

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# व्यष्टि - अर्थशास्त्र

( MICRO-ECONOMICS )

[ व्यष्टि-मूलक आर्थिक सिद्धान्तों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ]

लेखक

डा० आर० एन० सिंह  
व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

डा० जे० पी० श्रीवास्तव  
यूनिवर्सिटी कामर्स कॉलेज,

रमेश बुक डिपो  
जयपुर

प्रकाशक :

बृजमोहन लाल माहेश्वरी

रमेश बुक डिपो

जयपुर

© सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य पन्द्रह रुपये

मुद्रक

भूलेलाल प्रिन्टर्स,

जयपुर





अन्य ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर के संकेत भी दिए गए हैं।

जहाँ तक संभव हो सका है, विषय सामग्री को बोधगम्य एवं सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। लेखक उस सभी लेखकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं जिनकी कृतियों से इस पुस्तक के प्रणयन में सहायता मिली है। हमारा विश्वास है कि पुस्तक अपने वर्तमान रूप में विद्यार्थी वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लेखक उन अध्यापक बन्धुओं तथा पाठकों के प्रति अत्यन्त ही कृतज्ञ होंगे जो पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपने अमूल्य सुझावों से हमें अङ्गत करेंगे। लेखक उन बन्धुओं के प्रति अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित किया।

लेखक द्रष्टव्य

# अनुक्रमणिका

प्रश्नार्थ	पृष्ठ संख्या
1. आर्थिक प्रणाली के कार्य	1
2. अर्थशास्त्र की परिभाषा	16
3. अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र	46
4. आर्थिक विश्लेषण की शाखाएँ (i)	67
5. आर्थिक विश्लेषण की शाखाएँ (ii)	91
6. अर्थशास्त्र विधियाँ : निगमन व आगमन	102
7. अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति	113
8. उपयोगिता विश्लेषण	124
9. उपयोगिता विश्लेषण : उपभोक्ता की दृष्टि	166
10. उपयोगिता विश्लेषण : माग	181
11. लक्ष्यता वक्र विश्लेषण	199
12. माग की लोच	247
13. प्राचुर्य उपयोगिता विश्लेषण	274
14. उत्पादन तथा उसके साधन	292
15. भूमि व श्रम की कार्यक्षमता	306
16. धन व धर्म की कार्यक्षमता	313
17. जनसंख्या सिद्धांत (धन की पूर्ति)	331
18. पूँजी तथा पूँजी के कार्य	335
19. साहस तथा साहसी के कार्य	371
20. व्यापारिक संगठन के स्वरूप	379
21. लागत वक्र	395
22. पूर्ति अथवा समरूप	417
23. उत्पादन के नियम	433

अध्याय	पृष्ठ संख्या
(24) पैमाने के प्रतिकूल	457
25. उत्पादन-साधनों का श्रेष्ठतम संयोग	476
26. बाजार की अवस्थायें	481
27. कुल माग, सीमांत माग व लोच	500
28. मूल्य सिद्धांत तथा बाजार-मूल्य	511
(29) पूर्ण प्रतिस्पर्धा : मूल्य व उत्पादन निर्धारण	525
30. कीमत निर्धारण में समय तत्व	540
(31) एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण	558
(32) अपूर्ण स्पर्धा : मूल्य व उत्पादन निर्धारण [ (i) एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा 594 (ii) मत्पविक्त्रेताधिकार 603 ]	594
33. उत्पादन साधनों का मूल्य-निर्धारण (सीमांत उत्पादकता सिद्धांत)	619
(34) लगान	650
35. मजदूरी	672
36. व्याज	< 698
(37) लाभ की प्रकृति	718

नोट :— भूमि, श्रम तथा पूँजी आदि साधनों की माग व पूर्ति की विशिष्ट दशाश्री तथा सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त का विभिन्न साधनों के सदृश में विस्तार से सम्बन्धित विषय सामग्री, तद्सम्बन्धी मूल ग्रन्थों में सम्मिलित है ।

## आर्थिक प्रणाली के कार्य (Functions of the Economic System)

*"Every economy must somehow solve the three fundamental economic problems What kinds and quantities shall be produced of all possible goods and services How economic resources shall be used in producing these goods For whom the goods shall be produced—i.e. What the distribution of income among different individuals and classes is to be"*

Paul A Samuelson

### 1 आर्थिक समस्या (The Economic Problem)

अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। आर्थिक समस्याओं का उदय चुनाव की समस्या के कारण होता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं का अंत नहीं है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को सतुष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की तुलना में उसके साधन सीमित होते हैं। साधनों के वैकल्पिक उपयोग (Alternative uses) हो सकते हैं अतः मनुष्य वैकल्पिक उपयोग वाले इन साधनों से अपनी आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए प्रयत्न करता है। इसके लिए उसके सामने चुनाव की समस्या खड़ी होती है— वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग, असिमित आवश्यकताओं में से कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे, जिससे उसे अधिकतम सतुष्टि मिल सके। वह आवश्यकताओं की सतुष्टि उनकी तीव्रता (Intensity) के आधार पर करता है। इस प्रकार प्रत्येक आर्थिक क्रिया के तीन मुख्य तत्व होते हैं

(1) मानवीय आवश्यकताएँ (2) साधन तथा (3) चुनाव की समस्या या उत्पादन की विधियाँ

**1 मानवीय आवश्यकताएँ (Human Wants)** जिन प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है उसी प्रकार आवश्यकताएँ सभी आर्थिक क्रियाओं की उद्गम हैं। मानव समाज का सम्पूर्ण अस्तित्व आवश्यकताओं पर आधारित है। मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है तथा किसी अवधि विशेष में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। मनुष्य के सामने आवश्यकताओं का ताता लगा रहता है। मनुष्य की आवश्यकताएँ (i) जीवन को बनाए रखने के तथा (ii) जीवन स्तर में सुधार के लिए होती हैं (iii) साथ ही साथ कुछ लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नयी आवश्यकताएँ जन्म लेती हैं।

**2. साधन (Means or Resources)** साधनों द्वारा आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की जाती है। एक अर्थ व्यवस्था में हजारों प्रकार के साधन पाये जाते हैं। इन सभी साधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है—(i) मानवीय साधन या श्रम (Human Resources) तथा (ii) मानवोत्तर साधन (Non Human Resources) मानवीय साधन का अन्विष्ट श्रम या सभी प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से है, जिसका उपयोग वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। मानवोत्तर साधन या धन का अन्विष्ट उन सभी मानवोत्तर वस्तुओं से है जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है जैसे—भूमि, खनिज पदार्थ, मशीन, भवन आदि।

साधनों के कई लक्षण होते हैं—(i) साधन सीमित होते हैं (ii) साधनों के कई उपयोग हो सकते हैं तथा (iii) किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों की विभिन्न अनुपातों में मिलाया जा सकता है।

**3 चुनाव की समस्या या उत्पादन की विधियाँ (The Problem of Choice or Techniques of Production)** आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं को पैदा करने के लिए साधनों का उपयोग किया जाता है। जिन विधियों से साधनों का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हें उत्पादन की विधियाँ कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आवश्यकताओं की सन्तुष्टि है। आवश्यकताओं की सन्तुष्टि मनुष्य के जीवन स्तर को निर्धारित करती है। ऊँचे जीवन स्तर के लिए अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य सर्वोत्तम उत्पादन विधियों को अपनाने का प्रयत्न करता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी समस्या को आर्थिक समस्या कहे जाने के लिए तीन तत्वों का पाया जाना आवश्यक है—(i) मानवीय आवश्यकताएँ (ii) साधन (iii) चुनाव की समस्या या उत्पादन की विधियाँ, इन तीनों तत्वों का एक ही साथ पाया जाना आवश्यक है। अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है अतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि

मनुष्य अपने सीमित साधनों का आवंटन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार करता है। (Economics is the study of how men allocate their limited resources to provide for their wants) आर्थिक समस्या का उदय दुर्लभता (Scarcity) के कारण होता है। यदि आवश्यकता एक ही है तो यह आर्थिक समस्या नहीं बल्कि प्राविधिक समस्या होगी। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि उद्देश्य (end) एक है तथा साधन अनेक हैं तो यह प्राविधिक समस्या (Technological Problem) होगी। यदि उद्देश्य तथा साधन दोनों अनेक हैं तो समस्या आर्थिक होगी। (Multiplicity of ends and multiplicity of means raises economic problem, if end is one then it is technological problem)

## 2. आर्थिक-प्रणाली (The Economic System)

आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय ऐसे संस्थात्मक ढाँचे (Institutional framework) से है जिनके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। ऐसे ढाँचे के अन्तर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय वितरण तथा राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं का संचालन होता है। आज कल आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक देश में कम या अधिक मात्रा में राज्य आर्थिक क्रियाओं पर नियन्त्रण रखता है तथा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में वैधानिक नियम बनाता है। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली के स्वरूप का निर्माण राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति तथा सीमा पर निर्भर है। राज्य द्वारा पारित विधानों के अतिरिक्त सामाजिक परम्पराएँ तथा नियम भी बहुत कुछ अंशों में आर्थिक प्रणाली का स्वरूप निर्धारित करते हैं। राज्य के हस्तक्षेप की सीमा व मात्रा तथा आर्थिक संगठन के ढाँचे के अनुसार अर्थ व्यवस्था कई प्रकार की हो सकती है, जैसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि।

अर्थव्यवस्था का जो भी स्वरूप हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है चाहे अर्थव्यवस्था पूँजीवादी हो या साम्यवादी या किसी अन्य प्रकार की। प्रोफेसर Frank. H. Knight ने यह मत प्रकट किया है कि प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली को किसी न किसी रूप में पाँच कार्य करने पड़ते हैं।<sup>1</sup> आगे हम इन पाँच मौलिक कार्यों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर सेम्युलसन ने कहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन मौलिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है।

<sup>1</sup>. Knight, Frank. H. "Social Economic organisation" Contemporary society . Syllabus and Selected Readings, Edited by Harry D Gideonse and others, 4th edition Chicago : The University of Chicago Press, 1935 PP. 125-137

“Every economy must some how solve the three fundamental economic problems What kinds and quantities shall be produced of all possible goods and services, How economic resources shall be used in producing these goods, For Whom the goods shall be produced—i.e. What the distribution of income among different individuals and classes is to be”

अर्थात् प्रत्येक आर्थिक संगठन को किसी न किसी प्रकार तीन मौलिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है—

(i) सभी सम्भावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किस प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का किम माना में उत्पादन किया जाए ?

(ii) इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए आर्थिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ?

(iii) वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाए ?

प्रोफेसर नाइट (Prof. Knight) ने आर्थिक प्रणाली की जिन पाँच समस्याओं का उल्लेख किया है वे निम्नलिखित हैं—

(i) किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ?

(ii) उत्पादन का संगठन क्या हो ?

(iii) उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए ?

(iv) जिन वस्तुओं की कमी है उनकी राशनिंग अल्पकाल में किस प्रकार की जाए ? तथा

(v) अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को किस प्रकार से कायम रखा जाए तथा उत्पादन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए ?

(1) वस्तुओं के उत्पादन का निर्धारण (What is to be Produced ?) :

प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए । इसके लिए उद्देश्यों की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है । अर्थव्यवस्था के साधन सीमित होते हैं । समाज की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति पूर्ण रूप से करना सम्भव नहीं होता है । अतः अर्थव्यवस्था को इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि समाज की सापेक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए । इसके लिए सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है ।

अतः अर्थ व्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि उत्पादन के साधनों का उपयोग उत्पादन के लिए किस प्रकार किया जाए । इस प्रकार विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न पड़तों का आवंटन किस प्रकार किया जाए ? (How the inputs should be allocated to different outputs ?)

एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान कीमत प्रणाली द्वारा किया जाता है। वस्तुतः मूल्यांकन की समस्या प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, परन्तु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली का प्रमुख स्थान है। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कीमतों के संदर्भ में किया जाता है। कीमत निर्धारण में उपभोक्ताओं का प्रमुख हाथ रहता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदा जाए इसका निर्णय उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। कीमत, वस्तुओं की पूर्ति की अवस्था तथा वस्तुओं को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं की तत्परता द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति, अन्य बातों के समान रहने पर, अधिक है, तो उसकी कीमत कम होगी। यदि उपभोक्ता की तत्परता अधिक है तो कीमत अधिक होगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं द्वारा जो आय विभिन्न वस्तुओं के खरीदने के लिए व्यय की जाती है उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है। उपभोक्ता-वस्तुओं के सम्बन्ध में जो बाग सागू होती है वह उत्पादन साधनों के भी सम्बन्ध में सही है। उत्पादन साधनों की कीमत माग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। हम कीमत प्रणाली का विवरण निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं—

(1) किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? इसका निश्चय उपभोक्ताओं के अधिमानों (Consumers' Preferences) द्वारा किया जाता है। उनके निरूपणों के निर्णयों के अनुसार उत्पादन की मात्रा तथा किस्म का निर्धारण होता है। उन्हें जो शुद्ध भी आय प्राप्त होती है वह उत्पादन का परिणाम होती है। वे उत्पादन के विभिन्न साधनों के स्वामी के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं तथा आय प्राप्त करते हैं। इस आय को वे उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यय करते हैं। इस प्रकार अर्जित आय पुनः उत्पादकों को हस्तान्तरित हो जाती है। आय का यह चक्राकार प्रवाह निरन्तर चलता रहता है।

(ii) वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए? इसका निर्णय विभिन्न उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धा द्वारा किया जाता है। न्यूनतम लागत की उत्पादन विधि, अधिकलागत की उत्पादन विधि का स्थान ग्रहण करती रहती है। प्रत्येक उत्पादक कार्य क्षमता में वृद्धि करने तथा लागत को न्यूनतम रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह कीमत को न्यूनतम रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कीमत प्रणाली द्वारा तीन प्रश्नों का हल प्राप्त होता है—क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए? प्रो० सैम्युएलसन ने ठीक ही कहा है<sup>1</sup> :

<sup>1</sup>. Paul A. Samuelson, Economics, An Introductory Analysis, 958, P. 40



"Like a master who gives his donkey carrots and kicks to coax him forward, the pricing system deals out profits and losses to get the What, How and For Whom questions answered."

(iii) उत्पादन किसके लिए किया जाए, इस बात का निर्धारण उत्पादक सेवाओं की बाजार में माग तथा पूर्ति द्वारा किया जाता है। मजदूरी, लगान, ब्याज लाभ आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। उपभोक्ताओं के अधिमानी तथा लागत व पूर्ति सम्बन्धी निर्णय द्वारा क्या पैदा किया जाए ? का निश्चय किया जाता है।

कीमत प्रणाली के मंचालन में स्पर्धा का प्रमुख हाथ होता है। परन्तु वास्तविक जगत में पूर्ण स्पर्धा नहीं पाई जाती है। फर्मों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन कब होगा। अतः किसी वस्तु के अधिक उत्पादन तथा कम उत्पादन की समस्या खड़ी होती है। इसी प्रकार बहुत से उत्पादक दूसरे उत्पादकों की उत्पादना विधियों के विषय में नहीं जानते। अतः लागत भी न्यूनतम नहीं होती है। एकाधिकार के कारण भी पूर्ण स्पर्धा की प्रवस्था नहीं पाई जाती। इन कारणों से साधनों का दोषपूर्ण आवंटन, अतः कीमती तथा एकाधिकारिक लाभ आदि समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं।

## (ii) उत्पादन का संगठन (Organisation of Production) :

एक प्रत्यक्षवस्था को दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय इस बात का करना पड़ता है कि साधनों का संगठन किस प्रकार से किया जाए जिससे इच्छित वस्तुओं का उत्पादन उचित परिमाण में किया जा सके। उत्पादन के संगठन के अन्तर्गत दो बातों पर ध्यान दिया जाता है—(i) साधनों का प्रयोग उन वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों में अधिक किया जाए जिन वस्तुओं को उपभोक्ता अधिक चाहते हैं तथा साधनों का प्रवेश उन उद्योगों में रोका जाए जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता कम चाहते हैं। (ii) फर्मों द्वारा साधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए, जिससे देश के साधनों का दुरुपयोग न हो सके।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुतः कीमत प्रणाली द्वारा उत्पादन का संगठन किया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिमानी तथा पसन्द का इस कार्य में महत्वपूर्ण हाथ रहता है। साधनों के स्वामी अपने साधनों के बदले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं। अधिक प्रतिफल, उत्पादन साधनों के स्वामियों को उन्हीं फर्मों से प्राप्त हो सक्ता है जो फर्में अधिक लाभ कमाती हैं। अधिक लाभ कमाना उन्हीं फर्मों के लिए सम्भव होता है जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसन्द किया जाता है। जिन वस्तुओं को उपभोक्ता अधिक पसन्द करते हैं उनके लिए वे अधिक कीमतें देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं इससे उत्पादन करने वाली फर्मों को अधिक लाभ होता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं को उपभोक्ता

कम पसन्द करत है उनकी कीमते कम होती हैं फलस्वरूप उत्पादन फर्म को कम कीमत प्राप्त हानी है तथा उनका नाम कम होता है। अतः वे उत्पादन साधनों के स्वामियों को अधिक प्रतिफल देने की स्थिति में नहीं होते हैं। उत्पादन के स्वामी अपने साधन उन्ही फर्मों को देते हैं जिनसे उन्हें अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पादन के साधन कम प्रतिफल देने वाली फर्मों से हटकर अधिक प्रतिफल देने वाली फर्मों के पास हस्तान्तरित होते रहते हैं। इस प्रकार साधनों का उपयोग उचित रूप से होता है।

प्रत्येक फर्म अपने लाभ का अधिकतम करना चाहती है। इसने लिए फर्म उत्पादन लागत को न्यूनतम करने का यत्न करती है। उत्पादन विभिन्न साधनों के सम्मिलित प्रयास का फल है। उत्पादक विभिन्न उत्पादन साधनों के उचित संयोग से उत्पादन करता है। वह प्रत्येक दृष्टि से उत्पादन लागत को कम करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह विभिन्न उत्पादन साधनों की लागत तथा उन्नत उत्पादन प्रविधि पर ध्यान देता है।

### (iii) उत्पादित वस्तुओं का वितरण (Distribution of produced commodities)

एक आर्थिक प्रणाली को उत्पादित वस्तुओं के वितरण की समस्या का समाधान करना पड़ता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली द्वारा वस्तुओं का वितरण किया जाता है। वस्तुएं भाय द्वारा खरीदी जाती हैं। अतः अर्थव्यवस्था में अधिक भाय वाले व्यक्तियों का उत्पादन की क्रिया में अधिक हाथ रहना है। किसी व्यक्ति की भाय दो बातों पर निर्भर है। (i) उत्पादन साधनों की उसके पास पाई जाने वाली मात्रा तथा (ii) उत्पादन साधनों के बदले प्राप्त होने वाले प्रतिफल की मात्रा।

जिन व्यक्तियों के पास उत्पादन के साधन अधिक मात्रा में होते हैं तथा इनके बदले जिन्हें अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है उनकी भाय अधिक होती है।

कीमत प्रणाली द्वारा अधिकांश अर्थों में भाय का यह अन्तर स्वतः दूर होता जाता है। उत्पादन की क्रिया में साधनों के उचित प्रयोग न करने से भाय में जो अन्तर होता है उसे कीमत प्रणाली द्वारा दूर किया जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—मान लीजिए श्रमिकों का एक समूह है जो समान रूप में किसी कार्य विशेष को करने के लिए कुशल है। इस समूह में से कुछ श्रमिक एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं तथा कुछ श्रमिक दूसरे प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए दूसरी प्रकार की वस्तु का मूल्य प्रथम प्रकार की वस्तु से अधिक है। इस वजह से दूसरी प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले श्रमिकों को ऊँची मजदूरी प्राप्त होगी तथा उनकी भाय अधिक होगी। प्रथम प्रकार की वस्तु

पैदा करने वाले धर्मिकों को, कीमत कम होने के कारण, कम राजदूरी प्राप्त होगी तथा उनकी आय कम होगी। यद्यपि उनकी कुशलता दूसरे प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले धर्मिकों के समान है। आय के इस भन्तर को देख कर प्रथम प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले धर्मिकों से कुछ धर्मिक दूसरे प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले उद्योग में चले जावेंगे। क्योंकि उन्हें बड़ा अधिक्त मजदूरी मिलती है इस प्रकार दूसरे प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति बढ़ने के कारण उस वस्तु की कीमत घटेगी। प्रथम प्रकार की वस्तु की पूर्ति घट जायेगी मतः उसकी कीमत बढ़ जायेगी। कीमतों में इस परिवर्तन के कारण दूसरी प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले धर्मिकों की आय घटेगी। इस प्रकार दोनों प्रकार की वस्तु पैदा करने वाले धर्मिकों की आय का भन्तर समाप्त हो जायेगा। यह याद रखना चाहिए कि उपर्युक्त विधि उसी समय क्रियाशील होगी जबकि (i) धर्मिकों को बाजार की अवधारणा का पूर्ण ज्ञान हो तथा (ii) उनकी गतिशीलता में कोई बाधा नहीं हो। परन्तु वास्तविक जगत में इन दोनों शर्तों का पालना जाना कल्पना मात्र है। यही कारण है कि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में व्यक्तियों की आय में पर्याप्त भन्तर बाधा जाता है तथा समाज में आर्थिक विषमता पायी जाती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में आय के भन्तर को दूर करने में कीमत प्रणाली असफल सिद्ध होती है। आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है अतः इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं।

#### (ii) अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था (Rationing in a Very short period)

प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली को यदि अल्पकाल में उन वस्तुओं के लिए, किसी न किसी प्रकार की राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है तबकी पूर्ति कम होती है। ऐसी वस्तुओं के आवंटन की व्यवस्था आर्थिक प्रणाली की करना पड़ता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह कार्य कीमत प्रणाली द्वारा किया जाता है। जिस वस्तु की कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है फलस्वरूप उपभोक्ता ऐसी वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। कीमत उस समय तक बढ़ती जाती है जब तक सभी उपभोक्ता स्थिर पूर्ति की देने के बिन्दु पर नहीं आ जाते। इसके विपरीत जिस वस्तु की अधिकता होती है उसकी कीमत उस बिन्दु तक घटती जाती है जिस बिन्दु पर क्रेताओं द्वारा खरीदे जाने वाली मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वे बाजार में उपलब्ध सगस्त पूर्ति को खरीद सकें। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के उपभोग को नियमित करने में सट्टा (Speculation) महत्वपूर्ण भूमिका धरा करता है। सट्टारिए भविष्य में होने वाली मूल्य की घट बढ़ का अनुमान लगाते हैं तथा क्रय-विक्रय द्वारा मूल्य व पूर्ति को प्रभावित करते हैं।

## (v) उत्पादन क्षमता का अनुरक्षण तथा विकास (Economic Maintenance and Growth) :

प्रत्येक आर्थिक प्रणाली अधिक से अधिक विकसित होने का प्रयत्न करती है। आर्थिक विकास के लिए पूँजी आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली किसी न किसी प्रकार से अधिक से अधिक पूँजी का संचय व विनियोजन करने का प्रयास करती है। आर्थिक साधनों की मात्रा में वृद्धि, उनकी किस्मों में सुधार तथा उत्पादन विधि में निरन्तर सुधार करने का प्रयत्न प्रत्येक आर्थिक प्रणाली करती रहती है। श्रम-शक्ति का विकास वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विकास द्वारा किया जाता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में दसता का बिकाम कीमत प्रणाली द्वारा प्रेरित होता है। अधिक कुशल व प्रशिक्षित व्यक्ति को कम कुशल व कम प्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा ऊँची दर पर पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अतः श्रमिक अपनी कुशलता में वृद्धि करने का प्रयत्न करते रहते हैं।

आर्थिक विकास के लिए पूँजी ईंधन के समान कार्य करती है। उत्पादन के लिए पूँजी आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली आर्थिक विकास के लिए पूँजी का अधिकाधिक प्रयोग करती है। उत्पादन की क्रिया में जिस पूँजी का प्रयोग किया जाता है उसमें मूल्य ह्रास (Depreciation) होता रहता है। आर्थिक प्रणाली इस बात का प्रयत्न करती है कि प्रति वर्ष कम से कम, जितना मूल्य ह्रास होता है उससे अधिक मात्रा में नई पूँजी का विनियोजन किया जाए जिससे पूँजी की मात्रा बढ़ती रहे तथा आर्थिक विकास होता रहे। उत्पादन प्रणाली में ज्यों ज्यों सुधार होता जाता है, उत्पादन की श्रेष्ठ विधियों का इस्तेमाल बढ़ता जाता है, उसके साथ ही साथ उत्तरोत्तर अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। विकास की आर्थिक समस्या में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए पूँजी का प्रयोग किया जाता है। इसे पूँजी प्रसार (Capital widening) कहते हैं। विकास के साथ ही साथ जब उद्योगों में पहले की अपेक्षा, श्रेष्ठ उत्पादन विधियों के कारण, उन्हीं उद्योगों में पहले की अपेक्षा अधिक पूँजी का इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसे पूँजी की गहनता (Deepening of Capital) कहते हैं।

पूँजी बचत का परिणाम है। अतः पूँजी में समाज का त्याग निहित है। प्रत्येक अर्थ व्यवस्था इस बात का प्रयत्न करती है कि वर्तमान उपभोग का त्याग कर अधिक से अधिक पूँजी का विनियोजन करे। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में कीमत प्रणाली तथा लाभ द्वारा पूँजी संचय तथा विनियोजन को प्रोत्साहन मिलता है।

आर्थिक विकास के साथ ही साथ उत्पादन प्रविधि में भी सुधार होता रहता है। उत्पादन प्रविधि में सुधार द्वारा साधनों की दी हुई मात्रा द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कारों द्वारा उत्पादन विधि में सुधार करने का प्रयत्न निरन्तर चला रहता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली को पाच प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ये पाचो समस्याएँ पूँजीवादी, समाजवादी आदि सभी प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं में पाई जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में अलग अलग ढंग तथा नीतियों द्वारा किया जाता है। इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। इसके लिए विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं में अलग-अलग तरीके अपनाये जाते हैं। तरीकों की विभिन्नता के कारण भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में मौलिक अन्तर पाये जाने हैं तथा एक आर्थिक प्रणाली दूसरे में भिन्न नजर आती है।

### 3 आर्थिक प्रणाली की कार्य विधि

(The Processes of Economic System)

आर्थिक प्रणाली का कोई भी रूप हो प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में आर्थिक नियमों का स्वरूप एकसा होता है तथा आर्थिक-जीवन मूल रूप में एक प्रकार से प्रवाहित होता है। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में आर्थिक-जीवन परिवार (Household) तथा फर्मों के बीच, चक्राकार रूप में प्रवाहित होता रहता है। (Whatever the form of economic organisation, the basic processes of economic life consists of a circular flow between households and firms)<sup>1</sup>

1. परिवार (Household) या उपभोक्ता (Consumer) : किसी भी अर्थ व्यवस्था में परिवार की भूमिका ईकाई माना जाता है। परिवार आर्थिक जीवन की मुख्य उपभोक्ता इकाई है। परिवार व्यक्तियों (Persons) का समूह है जो अपनी वर्तमान आय या भूतकाल की आय का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं को खरीद कर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्यय की गई राशि को 'उपयोग पर व्यय' कहते हैं।

2. साधन स्वामी (The factor owner) : आर्थिक प्रणाली में दूसरी प्रमुख इकाई साधन स्वामी होता है। बिना व्यक्ति या संस्था के पास साधन होता है वह उसका प्रयोग प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप से उत्पादन के लिए करता है। सामान्य रूप से प्रत्येक परिवार किसी न किसी साधन (भूमि, श्रम, प्रबन्ध, पूँजी आदि) का स्वामी होता है, जो उत्पादन के लिए साधन प्रदान करता है तथा साधन के बदले में आय प्राप्त करता है जिसका उपयोग वह उपयोग के लिए करता है।

3. व्यावसायिक फर्म (Business firm) : आर्थिक जीवन में फर्म मूल उत्पादक इकाई होती है। फर्म वैयक्तिक या सार्वजनिक (Private or Public)

<sup>1</sup> Sickles J. V. Van, and Rogge B. A. Introduction to Economics, 1968 P. 13

स्वामित्व की हो सकती है। फर्म एक दुकान के रूप में (व्यक्तिगत या सार्वजनिक), एक स्टील मिल के रूप में (व्यक्तिगत या सार्वजनिक), या कृषि फार्म (व्यक्तिगत या सामूहिक) या किसी अन्य रूप में कार्य कर सकती है। फर्म द्वारा उत्पादनकार्य किया जाता है। आर्थिक प्रणाली का कोई भी रूप हो, एक फर्म की मुख्य विशेषता यह है कि यह साधनों का एकत्रित रूप होती है जिन्हें वस्तुओं के उत्पादन के लिए एकत्रित किया जाता है। फर्म उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों का प्रयोग करती है तथा इसके लिए जो कुछ व्यय करती है, उसे लागत कहते हैं, उनके प्रतिफल रूप में वे लागतें साधन स्वामियों के लिए धाय होती हैं। फर्मों के समूह को (एक प्रकार का या मिलता जुलता उत्पादन करने वाली) उद्योग कहते हैं।

इस प्रकार परिवार तथा फर्म दोनों, दो प्रकार के बाजारों में कार्य करती हैं—(i) उपभोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजारों में तथा (ii) साधनों के बाजारों में।

**आर्थिक क्रियाओं का चक्राकार प्रवाह (The Circular flow of economic activities)** .

प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली में परिवारों तथा फर्मों के बीच आर्थिक क्रियाओं का चक्राकार प्रवाह चलता रहता है। यहां पर हम आर्थिक क्रियाओं के चक्राकार प्रवाह पर प्रकाश डालेंगे। आर्थिक क्रियाओं के चक्राकार प्रवाह का केन्द्र बिन्दु (परिवारों से फर्मों को) साधनों का प्रवाह तथा इसके विपरीत दिशा में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह (फर्मों से परिवारों की ओर) होता है। परिवार फर्मों को साधन प्रदान करते हैं तथा फर्म परिवारों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करती हैं।

इस मूलचक्र (Primary Circuit) का स्पष्टीकरण चित्र मध्या 1 द्वारा होता है।

चित्र स० 1



प्रत्येक अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के चक्राकार प्रवाह में एक दूसरा चक्र भी क्रियाशील होता है जिसे मौद्रिक चक्र (Monetary Circuit) कहते हैं। आज कल परिवार अपने साधनों का,

वस्तुओं तथा सेवाओं से वस्तु विनिमय (Barter) नहीं करते बल्कि वे साधनों के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं तथा इस मुद्रा का प्रयोग वे वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए करते हैं। इस प्रकार मौद्रिक चक्र के अन्तर्गत दो बातें सम्मिलित हैं—प्रथम फर्मों से परिवारों को मुद्रा का प्रवाह तथा द्वितीय, (प्रथम के विपरीत) परिवारों से फर्मों को मुद्रा का प्रवाह। परिवार आवश्यक वस्तुएँ तथा सेवाएँ फर्मों से ख़रीदते हैं तथा फर्मों को मुद्रा में भुगतान करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के इस दोहरे चक्र का स्पष्टीकरण चित्र संख्या 2 द्वारा होता है। फर्मों से परिवारों को जो मुद्रा प्रवाहित होती है वह फर्म की दृष्टि से लागत (cost) होती है तथा परिवार की दृष्टि से आय होती है। इसी प्रकार फर्मों को जो मुद्रा परिवारों से प्रवाहित होती है वह परिवारों के लिए उपभोग व्यय (Consumption expenditure) है तथा फर्मों के लिए कुल आय (gross revenues) होती है।

चित्र सं० 2



इस चक्राकार प्रवाह को 'धन चक्र' (Wheel of wealth) भी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का यह चक्राकार प्रवाह पूँजीवादी, समाजवादी आदि सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में पाया जाता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा आर्थिक निर्णय बाजार-तन्त्र या कीमत प्रणाली (Market Mechanism or price system) द्वारा लिये जाते हैं। समाजवादी अर्थ व्यवस्था में साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है तथा आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिये जाते हैं। साधनों का स्वामित्व चाहे जिस प्रकार का हो, आर्थिक निर्णय चाहे जिस प्रकार लिये जाते हों, आर्थिक क्रियाओं के उपर्युक्त चक्राकार प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह चक्राकार प्रवाह प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाया जाता है।

[आर्थिक क्रियाओं के इस चक्राकार प्रवाह को किसी भी आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है - विचार्य आर्थिक क्रियाओं के चक्राकार प्रवाह को या तो उपर्युक्त विधि द्वारा स्पष्ट करें या वे अग्र लिखित विधि का प्रयोग कर सकते हैं।]

## आर्थिक क्रियाओं का चक्राकार प्रवाह (द्वितीय विधि)

पहले व्यक्ति स्वावलम्बी था तथा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। वह उत्पादक तथा उपभोक्ता-दोनों ही था। परन्तु आधुनिक उत्पादन विनियमन के लिये किया जाता है। उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादन साधनों को एकत्रित किया जाता है तथा उनके सहयोग से उत्पादन-साधनों को प्रतिकूल देना आवश्यक होता है।

अतः लगान, मजदूरी, व्याज, वेतन व लाभान के रूप में विभिन्न उत्पादन-साधनों को भुगतान किया जाता है। विनियोजकों को व्याज व लाभान तथा कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन के रूप में आय प्राप्त होती है। इस आय का उपयोग वे वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। इस प्रकार उत्पादन द्वारा आय प्राप्त होती है, तथा आय द्वारा उत्पादन को खरीदा जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति दो रूपों में आर्थिक क्रियाओं में भाग लेता है—उत्पादन के साधन के रूप में वस्तुओं का उत्पादन करने में, तथा उपभोक्ता के रूप में उत्पादित वस्तुओं को क्रय कर उनका उपयोग करने में। इस दोहरी क्रिया में कर्मों भी भाग लेती हैं—वे उत्पादन-साधनों को आय के रूप में भुगतान करती हैं तथा सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम इस प्रकार होता है—उत्पादन द्वारा आय होती है। आय का उपयोग क्रय-शक्ति के रूप में व्यय करके किया जाता है। व्यय करने के कारण उत्पादन की माग होती है। इस प्रकार आय व्यय तथा उत्पादन चक्राकार चलते रहते हैं। इस चक्राकार क्रिया में न तो कोई आरम्भ बिन्दु होता है, न अन्तिम बिन्दु। अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह के रूप में निरन्तर निरन्तर बहती रहती है।

उत्पादन के साधनों की मात्रा, उनकी उत्पादन-शक्ति तथा वस्तुओं के माग-परिवर्तन के अनुसार राष्ट्रीय आय भी घटती-बढ़ती रहती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय स्थिर या निश्चित कोष नहीं है। यह एक निरन्तर बहने वाला प्रवाह है, जिसमें उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इसी राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधनों को हिस्सा प्रदान किया है।

अतः नागरिकों की आय = उत्पादन साधनों को मुद्रा के रूप में भुगतान = उत्पादन का विक्रय मूल्य।

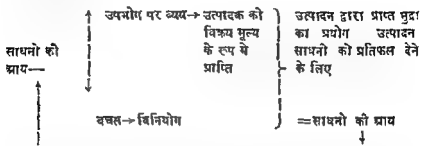
प्राप्त आय को उपयोग पर व्यय किया जाता है तथा कुछ भाग वचत के रूप में शेष रहता है अतः —

आय = उपयोग + वचत

वचत का उपयोग पूँजीगत वस्तुओं को खरीदकर विनियोजन के रूप में किया जाता है। इन पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे



पुनः प्राप्त होती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं द्वारा आय का एक चक्राकार प्रवाह बन जाता है।



आर्थिक क्रियाओं के इस चक्राकार प्रवाह से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि (1) यदि उत्पादन साधन कम है तो कुल उत्पादन भी कम होगा (2) उत्पादकों की विक्रय-मूल्य के रूप में प्राप्ति इस बात पर निर्भर है कि साधनों की कितनी मात्रा में भुगतान किया जाता है। उत्पादन-साधनों को किया गया भुगतान और विक्रय द्वारा प्राप्त धनराशि अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश में आय एवं रोजगार का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है।

साधनों को किया गया भुगतान उत्पादन लागत के बराबर होता है, इसे 'कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पूर्ति-मूल्य' (Aggregate supply price of the national output) कह सकते हैं। साधन, प्राप्त आय का उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं, अतः कुल खरीद-मूल्य को राष्ट्रीय उत्पादन का 'माग मूल्य' (demand price) कह सकते हैं। 'पूर्ति मूल्य' तथा 'माग मूल्य' एक दूसरे पर निर्भर है। इन दोनों का अस-तुलन देश की आय तथा रोजगार में परिवर्तन लाता है। राष्ट्रीय उत्पादन के माग-मूल्य को ऊँचा रखकर रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।

### संदर्भ-ग्रन्थ

- 1 Due and Clower, Intermediate Economic Analysis, 1963 Ed., Chap 1
2. Van Sickle, J. V, and Rogge, B A., Introduction to Economics 1968 Ed, Chap. 1.
- 3 Stigler, George J, Theory of Price, 1966 Ed Chap 2.
- 4 Samuelson, Paul A, Economics-An Introductory Analysis 1958 Ed., Chap 2
- 5 Leftwich Richard H, The Price System and Resource Allocation, 3rd Ed Chapter I & II

### अभ्यास प्रश्न

#### 1 आर्थिक समस्या किसे कहते हैं ?

(सकेत : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मानवीय आवश्यकताएँ, माधन तथा चुनाव की समस्या पर प्रकाश डालिए तथा स्पष्ट करिये कि जहाँ भी अनक आवश्यकताएँ तथा सीमित माधन होंगे उसे आर्थिक समस्या कहेंगे ।)

#### 2 आर्थिक प्रणाली के कार्यों का उल्लेख कीजिए ।

(सकेत : आर्थिक प्रणाली के पाँचों कार्यों को स्पष्ट रूप से समझाईए ।)

#### 3 आर्थिक त्रियासो के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट कीजिए ।

(सकेत : सत्तेप में परिवार तथा फर्म के सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए तथा हम अध्याय में दिये गये दोनों चित्रों की सहायता से चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट कीजिए या अध्याय के अन्त में दी गई विधि में चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट कीजिए ।)

#### 4 पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के महत्त्व पर प्रकाश डालिए ।

(सकेत : सबसे पहले यह स्पष्ट कीजिए कि कीमत प्रणाली का पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसके पश्चात् आर्थिक प्रणाली के पाँचों कार्यों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में इन पाँचों कार्यों का संचालन कीमत प्रणाली द्वारा किस प्रकार किया जाता है ।)

# 2

## अर्थशास्त्र की परिभाषा (Definition of Economics)

*"The rationale of any definition is to be found in the use which is actually made of it."*

—Robbins

अर्थशास्त्र का जन्म सन् 1776 में एडम स्मिथ (Adam Smith) की महान कृति 'राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जाँच' (*An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*) के प्रकाशन के साथ हुआ था। उस समय इसका नाम 'राज्य अर्थव्यवस्था' (*Political Economy*) रखा गया, जो उस समय से लगभग एक शताब्दी तक प्रयोग में लाया जाता रहा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इस विज्ञान को एक नया नाम देने के कई प्रयास किए गए। व्हेटली (Whately) ने यह सुझाव दिया कि इसका नाम 'राज्य अर्थव्यवस्था' से बदल कर 'विनिमय का विज्ञान' (*Catalitics or Science of Exchanges*) रख दिया जाय। हर्न (Hearn) ने इसे 'धन का विज्ञान' (*Plutology*) कहना उचित समझा था। इन्ग्राम (Ingram) ने इसे 'धन पैदा करने का विज्ञान' (*Chrematistics or the Science of money-making*) नाम देने पर जोर दिया था।

परन्तु नाम बदलने के इन सभी प्रयत्नों के बावजूद भी 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसका नाम 'राज्य अर्थव्यवस्था' ही प्रचलित रहा। प्रोफेसर मार्शल (Prof. Marshall) की विख्यात पुस्तक 'अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' (*Principles of Economics*) सन् 1890 में प्रकाशित हुयी। उस समय तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो जाने तथा 'धन के विज्ञान' के रूप में इस शास्त्र की कटु आलोचना होने के कारण मार्शल ने उसे 'अर्थशास्त्र' (*Economics*) नाम देकर उसे उसकी सही सीमाओं से मुक्ति प्रदान की। उस समय से आज तक यही नाम प्रयोग किया जाता रहा है, यद्यपि इधर कुछ वर्षों से इसे अधिक वैज्ञानिक

आधार प्रदान करने के लिए कुछ विद्वानों ने, जिनमें प्रोफेसर के० ई० बौलिंग (Prof K. E. Boulding) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है 'अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' (*Principles of Economics*) के स्थान पर 'आर्थिक विश्लेषण' (*Economic Analysis*) नाम का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है।

अर्थशास्त्र एक विकासशील एवं गतिशील विषय है। इस शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा देने की समस्या आज भी बनी हुयी है। अर्थशास्त्रियों में इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इन मतभेदों के आधार पर ही बारबारा वूटन (Barbara Wooton) ने यह कहा है कि "छ अर्थशास्त्रियों के एकत्रित होने पर मात्र मत होंगे।"<sup>2</sup> जे० एन० वुन्स का भी इस सम्बन्ध में यह कहना है कि 'राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है।'<sup>4</sup> जैकब वाइनर (Jacob Viner) ने तो यहाँ तक कहा है कि "जो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं, वह अर्थशास्त्र है।"<sup>3</sup> अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में भिन्नता तथा उसकी सर्वमान्य परिभाषा के सम्बन्ध में मतभेद इस बात को प्रोत्साहित करता है कि आर्थिक गतिविधियों में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में भी निरन्तर एवं क्रमिक विस्तार होता रहा है। ऐसी स्थिति में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इस शास्त्र की परिभाषाओं में कुछ सीमा तक भिन्नता होना स्वाभाविक है। इसकी सीमाएँ तथा विषय क्षेत्र या सामग्री न तो पहले ही निश्चित थी और न आज तक ही निश्चित हो पायी है। इसीलिए रिचार्ड जोन्स (Richard Jones) तथा कॉम्टे (Comte) ऐसे पुराने अर्थशास्त्री तथा जैकब वाइनर, मॉरिस डॉब (Maurice Dobb), गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) तथा वॉन माइजेस (Von Mises) ऐसे नवीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं समझते।

परन्तु परिभाषा न देने की विचारधारा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, क्योंकि किसी भी शास्त्र के क्षेत्र तथा इसकी विषय-सामग्री का ज्ञान, उसको परिभाषा के द्वारा बहुत कुछ प्रशो में हो जाता है। क्षेत्र परिभाषित न होने पर इसके अन्तर्गत उन बातों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिनका अर्थशास्त्र से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

### अर्थशास्त्र की परिभाषा

#### (Definition of Economics)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। अध्ययन की सुविधा एवं सरलता की दृष्टि से इन सभी परिभाषाओं को चार

<sup>1</sup> "Whenever six economists are gathered, there are seven opinions" — Barbara Wooton *Lament of Economics*.

<sup>2</sup> "Political Economy is said to have strangled itself with definitions" — J N Keynes

<sup>3</sup> 'Economics is what economists do' — Jacob Viner.

वर्गों में बाटा जा सकता है (1) धन सम्बन्धी परिभाषाएँ (Wealth Definitions), (2) कल्याण प्रधान परिभाषा (Welfare Definition), (3) दुर्लभता प्रधान परिभाषा (Scarcity Definition); तथा (4) आवश्यकता विहीनता सम्बन्धी परिभाषा (Wantlessness Definition)।

### 1. धन प्रधान परिभाषा (Wealth Definition)

अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ सत्या उनके अनुयायियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहकर परिभाषित किया था। उनके द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में धन पर ही विशेष बल दिया गया है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक "An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations" में इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति के स्वभाव तथा कारणों के अध्ययन का शास्त्र मानकर 'राजनैतिक अर्थ व्यवस्था' (Political Economy) की सत्ता दी उन्होंने इस विषय को ऐसा शास्त्र बतलाया जो राष्ट्रों के धन-सम्बन्धी कारणों एवं प्रयत्नों का ज्ञान कराता है।<sup>4</sup>

विवेचना कुछ आलोचकों का यह मत है कि एडम स्मिथ (Adam Smith) ने अपनी उपर्युक्त परिभाषा में धन को प्रभावता दी है तथा अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना है। परन्तु यह सकुचित मान्यता इस परिभाषा में कहीं पर स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है। वास्तव में एडम स्मिथ ने राजनैतिक अर्थ व्यवस्था के विषय के उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों तथा राष्ट्र को धनी तथा समृद्धिशाली बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के ही द्वारा धन की व्यवस्था करना आवश्यक है। अतः अर्थशास्त्र धन की व्यवस्था के लिए किए गए प्रयत्नों का अध्ययन है।

फ्रांस के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे० बी० से (J. B. Say) ने एडम स्मिथ के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है।"<sup>5</sup> वाकर (Walker), जो अमेरिका के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, का भी यह मत था कि "अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से सम्बन्धित है।"<sup>6</sup> जे० एस० मिल ने भी अर्थशास्त्र को 'मनुष्य से सम्बन्धित धन का विज्ञान' कह कर परिभाषित किया।<sup>7</sup> इन परिभाषाओं से अप्रलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

4. "Economics is concerned with enquiring into the causes of the wealth of nations." —Adam Smith

5. "Economics is the science which treats of wealth." —J. B. Say

6. "Economics is that body of knowledge which relates to wealth." —Walker

7. "Economics is the science of wealth related to man."

—J. S. Mill

(i) धन का विशेष महत्व - प्राचीन या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन या सम्पत्ति का विज्ञान माना है जिसका उद्देश्य स्वहित के लिए धन एकत्र करने के उपायों का अध्ययन करना है। अतः इन अर्थशास्त्रियों के विचार से अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री का केन्द्र-बिन्दु धन है।

(ii) आर्थिक मनुष्य की कल्पना - एडम स्मिथ तथा उनके समर्थकों की यह धारणा थी कि व्यक्तिगत समृद्धि बढ़ने पर ही राष्ट्रीय धन एवं सम्पत्तियों में वृद्धि सम्भव है। यही कारण है कि एडम स्मिथ ने एक ऐसे 'आर्थिक मनुष्य' (Economic Man) की कल्पना की जो केवल स्वहित की भावना से प्रेरित होकर धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा जिस पर नैतिक विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है।<sup>8</sup>

(iii) मनुष्य का गौण स्थान : धन को ही मानवीय सुखों का एक मात्र आधार एवं मापदण्ड मान कर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को प्रमुख स्थान प्रदान किया तथा मनुष्य को गौण। उनके विचार से धन से मनुष्य धनी अथवा निर्धन होता है। एडम स्मिथ ने इस विचार का समर्थन करते हुए लिखा है "प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक ही धनी या निर्धन है जहां तक कि वह मानव जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं तथा सुखों का आनन्द ले सकता है।"<sup>9</sup>

### आलोचना

1. धन पर अधिक जोर - 'धन के शास्त्र' के रूप में अर्थशास्त्र की कठु आलोचनाएँ की गयीं। धन पर जोर देने के कारण यह खाम तो अवश्य हुआ कि निजी तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हुई, परन्तु इस अपूर्ण एवं संकुचित विचार-धारा ने अनेक घातक, असामाजिक एवं आर्थिक अनैतिकताओं को जन्म दिया। सामान्य वर्ग की दशा बहुत ही हीन हो गयी। समाज सुधारकों ने उन समय के समाज की हीन दशा के लिए प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की परिभाषा को दोषी ठहराया। इन अर्थशास्त्रियों ने जीवन के उच्चतर मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मनुष्य को भौतिकता (Materialism) का पाठ पढ़ाया। इन अर्थशास्त्रियों ने धन को साध्य (end) माना, साधन नहीं। इंग्लैंड में कार्लाइल (Carlyle), रस्किन (Ruskin) तथा बिर्तलम मौरिस ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की कड़ी निन्दा की। कार्लाइल ने अर्थशास्त्र की प्राचीन परिभाषा की आलोचना करते

<sup>8</sup> "the mystical 'economic man' who is under no ethical influences and who pursue pecuniary gain warily and energetically but mechanically and selfishly" —Marshall

<sup>9</sup> "Every man is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessities, conveniences and amusements of life" —Adam Smith

हुए कहा कि 'धन के विज्ञान' के रूप में अर्थशास्त्र को 'कुबेर का अर्थशास्त्र' (Gospel of Mammon) कहना अधिक उपयुक्त होगा। रस्किन ने इसे 'अधम विज्ञान' (A bastard science) बताया। उनका विचार था—धन की अपेक्षा मनुष्य का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य अछड़ी तरह जीवन व्यतीत करने के लिए ही धन प्राप्त करता है न कि धनी बनने के लिए। अन्य विचारकों ने अर्थशास्त्र को 'रोटी-टुकड़े का विज्ञान' (Bread and Butter Science) तथा 'स्वार्थ विज्ञान' के नाम से सम्बोधित किया और इसकी कटु आलोचनाएँ की।

2 आर्थिक मनुष्य की कल्पना निराधार—इन अर्थशास्त्रियों ने एक आर्थिक मनुष्य (Economic Man) की कल्पना की जो निरन्तर स्वार्थ में प्रेरित होकर काम करता है तथा जिम पर नैतिकता, धर्म, आचार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्यों के हित में वृद्धि होने से समाज के हित में भी वृद्धि होनी है। परन्तु यह धारणा निर्मूल थी। सामाजिक मनुष्य 'आर्थिक मनुष्य' से भिन्न होता है तथा वह मानव मूल्यों (Human Values) से भी प्रभावित होता है।

जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा (Historical School) के अर्थशास्त्रियों ने 'स्वहित या स्वार्थ' की मान्यता की कटु आलोचना की और कहा कि सामाजिक हित केवल निजी स्वार्थों से ही सम्भव नहीं हो सकता। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों की मान्यताएँ कार्पनिक थीं। (इस दोष को दूर करने तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से ही ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक रोस्कर (Roscher) ने अर्थशास्त्र की एक नयी परिभाषा प्रस्तुत की। उनके अनुसार "राष्ट्रीय अथवा राजनैतिक अर्थ व्यवस्था से हमारा तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसका सम्बन्ध किसी राष्ट्र अथवा उसके आर्थिक राष्ट्रीय जीवन के विकास के नियमों से है।"<sup>10</sup>)

3 मनुष्य की अपेक्षा : इन अर्थशास्त्रियों ने 'धन' पर जोर दिया तथा मनुष्य की अपेक्षा की। वस्तुतः अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य में अधिक है। 'मनुष्य' की अपेक्षा कर 'धन' की महत्ता पर अधिक जोर देना उचित नहीं था।

4 अर्थशास्त्र के क्षेत्र का संकुचित होना—धन प्रधान परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर दिया। इन परिभाषाओं के अनुसार केवल धन सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री बन गयी जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र वस्तुतः बहुत विस्तृत है।

10 "By the science of national or Political Economy, we understand the science which has to do with the laws of development of the economy of nation or with the economic national life"

उपयुक्त 'धन प्रधान' परिभाषाओं की आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये परिभाषाएँ सन्तुलित, वास्तविकता से दूर तथा दोषपूर्ण हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने धन को ही केन्द्र बिन्दु मान लिया। एडम स्मिथ ने स्पष्ट रूप में लिखा है, 'Political Economy proposes to enrich both, the people and the sovereign' अर्थात् अर्थशास्त्र का उद्देश्य जनता तथा राज्य को धनी बनाना है। अर्थशास्त्र के इस उद्देश्य तथा धन की प्रधानता के आधार पर हम इन अर्थ-शास्त्रियों को कटु आलोचना कर सकते हैं, फिर भी हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा भविष्य के आर्थिक विचारों के लिए आधार प्रस्तुत किया। यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों तथा अर्थशास्त्र के प्रारम्भ पर ध्यान दें तो सम्भवतः हम इन अर्थ-शास्त्रियों को उतना दोष नहीं देंगे जितना दोषारोपण उन पर किया गया है। प्राधुनिक अर्थशास्त्र का प्रारम्भ, कम से कम प्राथमिक रूप में, वाणिज्यवादी लेखकों द्वारा किया गया जिन्हें "परामर्शदाता, प्रणामक तथा प्रचारक" (Consultants, administrators and pamphleteers) भी मजा दी गई है। ये लेखक व्यावहारिक परिणामों (Practical results) पर जोर दते थे। एडम स्मिथ तथा उनके समर्थक इस प्रभाव से बचत नहीं रह सके। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक व्यावहारिक विषय के रूप में देखा। वाणिज्यवादियों के प्रभाव के कारण ही एडम स्मिथ के विचार इस प्रकार के थे। एडम स्मिथ ने व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। यही कारण है कि उन्होंने 'धन' को अधिक महत्व दिया।

## 2 कल्याण-प्रधान परिभाषा (Welfare Definition)

इंग्लैंड के समाज सुधारकों की आलोचनाओं तथा जर्मन ऐतिहासिक विचार-धारा के अनुयायियों के नवीन विचारों से यह स्पष्ट हो गया कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार उपयुक्त नहीं थे।

यह विचार जोर पकड़ता गया कि धन साधन मात्र (Means) है, साध्य (End) नहीं है। वस्तुतः साध्य तो मानव-कल्याण (Human Welfare) है। अतः अब धन की अपेक्षा मनुष्य को अर्थशास्त्र में प्रधानता दी गई<sup>11</sup> तथा मानव का मौलिक कल्याण अर्थशास्त्र का केन्द्र बिन्दु हो गया। प्रो० मार्शल, पीगू, फेयर चाइल्ड, सीगर, रिचार्ड्स, पेन्सन, डेवरिज आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में अर्थशास्त्र का उद्देश्य 'मानव-कल्याण' की वृद्धि करना बतलाया गया। अतः इन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को 'कल्याण प्रधान' परिभाषा कहा जाता है।<sup>12</sup>

<sup>11</sup>. "The starting point and goal of our science is man" — Roscher

<sup>12</sup>. "Economic activities rather than economic goods form the subject matter of the science."  
— Carrier



## (क) मार्शल की परिभाषा :

अल्फ्रेड मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मन् 1890 में अपनी विख्यात पुस्तक 'Principles of Economics' द्वारा अर्थशास्त्र को तीव्र आलोचनाओं, निन्दाओं तथा अपयश से बचाकर एक सम्मानपूर्ण विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव-कल्याण (Human Welfare) माना। 'धन' को मानव कल्याण का साधन माना माना तथा अर्थशास्त्र को 'सामाजिक हित का एक यन्त्र' (an engine of social betterment) का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया।

मार्शल के समय में परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। औद्योगिक वि्वास के कारण नई आर्थिक समस्याएँ प्रकाश में आईं। अतः अर्थशास्त्र के स्वरूप में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। जर्मन अर्थशास्त्रियों द्वारा आत्मन प्रस्थानी पर तथा आन्ट्रियम स्कूल द्वारा 'वैयक्तिक हट्टिकोण' पर विशेष जोर देने के कारण आर्थिक सिद्धान्तों को आधुनिक रूप प्रदान करना आवश्यक हो गया था। अर्थशास्त्र धन-प्रधान परिभाषाओं के कारण बहुत बदनाम हो चुका था। अतः मार्शल ने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, अर्थशास्त्र के पुराने सिद्धान्तों का, तत्कालीन समस्याओं के प्रकाश में नए ढंग से विश्लेषण किया। इस बात का उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।<sup>13</sup>

मार्शल ने देखा कि अर्थशास्त्र की बदनामी का प्रमुख कारण 'धन' पर विशेष जोर देना है, इसलिए उन्होंने इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह कार्य बड़ी चतुराई और कुशलता से किया। उन्होंने धन से ध्यान हटाकर, आर्थिक-कल्याण पर जोर दिया, जो धन या वस्तुओं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार उन्होंने देश को समृद्ध बनाने के तरीकों (measures) पर जोर न देकर, देश के कल्याण पर जोर दिया जो उन तरीकों का ही परिणाम है। उन्होंने 'धन' को केवल साधन माना जिसकी कामना मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उनके विचार से आवश्यकताओं की समुष्टि ही मानव कल्याण है और मानव-कल्याण (Human Welfare) मनुष्य की क्रियाओं का लक्ष्य है। अतः मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव कल्याण का विज्ञान है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का केन्द्र बिन्दु है—'मनुष्य' तथा उसका आर्थिक कल्याण।

मार्शल ने तत्कालीन विचारों को समन्वित कर अर्थशास्त्र की एक नयी परिभाषा प्रस्तुत की। उनके अनुसार

<sup>13</sup> The present treatise is an attempt to present a modern version of old doctrines with the aid of new work and with reference to the new problems of our age."

“जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। यह जान करता है कि मनुष्य किस प्रकार धन प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका प्रयोग करता है... इस प्रकार एक ओर यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।”

“Political Economy or Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life, it enquires how he gets his income and how he uses it..... Thus, it is on one side the study of wealth and on the other and more important side, a part of the study of man”  
—Marshall, *Economics of Industry*

प्रो० मार्शल ने उपर्युक्त परिभाषा के उद्देश्य को अधिक विस्तृत करने के लिए उसमें सशोधन किया। यह सशोधित परिभाषा इस प्रकार थी :

“अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव-जाति का अध्ययन है, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिनका भौतिक कल्याण के साधनों की प्राप्ति तथा उनके प्रयोग से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है”

“Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being”

—Marshall, *Principles of Economics*.

**मार्शल की परिभाषा की व्याख्या.—**

1. मनुष्य का अध्ययन : अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अध्ययन का विषय ‘मनुष्य’ है। अर्थशास्त्र में मनुष्य का स्थान प्रमुख है तथा धन का गौण। एडम स्मिथ आदि ने धन को अर्थशास्त्र में प्रमुख स्थान प्रदान किया था। मार्शल ने धन के महत्व को स्वीकार किया, परन्तु उन्होंने धन को साधन मात्र माना तथा ‘मनुष्य’ पर अधिक जोर दिया। मार्शल ने स्पष्ट रूप से कहा है “एक ओर तो यह (अर्थशास्त्र) धन का अध्ययन है दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।” अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पशु-पक्षी आदि की क्रियाओं का नहीं।

2. सामाजिक (Social) वास्तविक (Real) तथा सामान्य (Normal) मनुष्य का अध्ययन : एडम स्मिथ तथा उसके समर्थकों ने एक ‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना की थी। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र “रहस्यपूर्ण आर्थिक मनुष्य” की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है जो हाड-मांस का सामान्य प्राणी होता है तथा जिसका सामाजिक जीवन होता है और वह नैतिकता तथा आचार-विचार से प्रभावित होता है तथा वह स्वार्थी-मात्र नहीं होता है। मार्शल ने स्पष्ट रूप से कहा है—

"Man is a normal being made of flesh and blood and he has his individual and social behaviour and not the mystical 'economic man'."

अर्थशास्त्र असामाजिक, (समाज से बाहर रहने वाले योगी सन्यासी आदि) तथा असामान्य व्यक्तियों (पागल आदि) की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है।

3. मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन - मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन करता है। 'सामान्य व्यवसाय' का अर्थ मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से है। एक मनुष्य के जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, आदि। अर्थशास्त्र मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। आर्थिक पहलू का तात्पर्य है, धन अर्जित करने की विधियाँ तथा धन का उपयोग ('it enquires how he gets his income and how he uses it')। आर्थिक पहलू के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाएँ आती हैं जो धन या आय के उत्पादन, उपभोग, विनिमय वितरण आदि से सम्बन्धित हैं।

4. भौतिक कल्याण का अध्ययन - अर्थशास्त्र में मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है, परन्तु 'मानव कल्याण' के भी सभी पक्षों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल आर्थिक या भौतिक कल्याण का ही अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने मानव समाज के भौतिक या आर्थिक कल्याण पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य भौतिक कल्याण के लिए साधनों को प्राप्त करना तथा उनका प्रयोग करना है। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का अन्तिम लक्ष्य मानव-कल्याण की वृद्धि है। अतः अर्थशास्त्रियों का कर्तव्य केवल आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करने के उपरान्त कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना ही नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य उन सिद्धान्तों का ज्ञान करना भी है जिनके द्वारा भौतिक कल्याण सम्भव हो सकता है। इस प्रकार मार्शल ने अपनी परिभाषा के अन्तर्गत मानव-कल्याण को अर्थशास्त्र का उद्देश्य निर्धारित करके 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' (Welfare Economics) के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है।

5. मुद्रा 'भौतिक कल्याण' का मापक : कौन सी क्रिया भौतिक या आर्थिक है तथा कौन सी निष्ठा अशैतिक है? इसका स्पष्टीकरण मार्शल की इस परिभाषा में नहीं मिलता है, परन्तु मार्शल ने अन्य स्थल पर यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि भौतिक कल्याण, मानव-कल्याण का वह भाग है जिसे मापा जा सकता है। अर्थशास्त्र का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में अस्तित्व केवल इसी कारण है कि इसका सम्बन्ध मुख्यतः मानवीय क्रिया के उस भाग से है जिसकी माप की जा सकती

है।<sup>16</sup> मार्शल ने मुद्रा को आर्थिक क्रियाओं तथा भौतिक-कल्याण का मापक माना है।

"In the world in which we live money, as representing general purchasing power, is so much the best measure of motives that no other can compete with it. But this is, so to speak, an accident."<sup>17</sup> —Marshall

इस प्रकार मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक-कल्याण का अध्ययन करता है तथा भौतिक-कल्याण, मानव-कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा नापा जा सकता है।<sup>18</sup>

पीगू, कैनन, चैप मैन, वेबरिज आदि ने भी मार्शल की परिभाषा का अनुमोदन किया है।

### मार्शल की परिभाषा की आलोचना :

यद्यपि मार्शल ने अर्थशास्त्र को 'मन के विज्ञान' के स्थान पर 'मानव विज्ञान' (Human Science) तथा 'सामाजिक विज्ञान' (Social Science) के रूप में प्रतिष्ठित किया, तथापि उनके द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना की गई। सन् 1932 में प्रोफेसर राबिन्स (Prof Lionel Robbins) ने अपनी पुस्तक "An Essay on the Nature and Significance of Economic Science" में मार्शल की परिभाषा के दोषों का उल्लेख करते हुए उसकी कटु आलोचना की :

1. 'जीवन के साधारण व्यवसाय' का अर्थ अस्पष्ट होता। राबिन्स ने 'जीवन के साधारण व्यवसाय' वाक्यांश की आलोचना करते हुए कहा कि मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जीवन के साधारण व्यवसाय कौन-कौन से हैं। यह भी कहीं पर स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो इस वर्ग में न आने के

<sup>16</sup>. "The *raison d'être* of economics as a separate science is that it deals chiefly with that part of man's action which is most under the control of measurable motives" —Marshall

<sup>17</sup>. Marshall's Inaugural lecture at Cambridge in 1885, Quoted by I M Kirzner in his book, *The Economic Point of View*, p. 94

<sup>18</sup>. कुछ लोगों का यह मत है कि भौतिक-कल्याण की मुद्रा द्वारा मापनीयता पर सर्वप्रथम पीगू ने प्रकाश डाला। परन्तु यह सत्य नहीं है। वास्तव में पीगू ने मार्शल के इस विचार को ग्रहण किया था। "Usually this formulation of economics is ascribed to Pigou. In fact Pigou seems to have simply taken over this definition from Marshall without much ado."

—I. M. Kirzner, op cit p 96.

कारण असाधारण मानी जायेंगी। ऐसी स्थिति में राबिन्स का यह विचार है कि यह वाक्यांश अस्पष्ट एवं भ्रामक है, क्योंकि सामान्यतः मानवीय क्रियाओं को साधारण तथा असाधारण वर्गों में रखना अत्यन्त कठिन है। अतः राबिन्स का यह मत है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिये जिनका सम्बन्ध मानवीय आवश्यकताओं की मनुष्टि से हो, ऐसी क्रियाएँ चाहे मनुष्य-जीवन में साधारण व्यवसाय में सम्मिलित हों या असाधारण व्यवसाय से।

2 भौतिक तथा अभौतिक साधनों में भेद भ्रामक प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में भौतिक साधनों तथा भौतिक कल्याण की बात की है। राबिन्स के विचार में भौतिक तथा अभौतिक साधनों में भेद करना अनुचित है, क्योंकि साधनों तथा मानवीय प्रयत्नों के वर्गीकरण के कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाता है तथा यह भेद करना समझ में नहीं है। अर्थशास्त्र को एक मानव विज्ञान मानने पर यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि अमृत क्रियाएँ और साधन तथा उनसे सम्बन्धित हित भौतिक हैं और शेष अभौतिक। राबिन्स का विचार है कि यदि एक व्यक्ति को मदिरा पान से ही अधिक सुख मिलता है या किसी व्यक्ति को मनोरंजन से ही अधिक मन-नोप का अनुभव होता है तो ऐसे सुख या ऐसी मनुष्टि को अभौतिक या अनाधिक कहकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित न करना उचित नहीं है। राबिन्स के अनुसार मानव कल्याण भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के पदार्थों या साधनों से सम्भव है, यदि वे पदार्थ या साधन सीमित अथवा दुर्लभ हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग हैं तथा मनुष्य उनसे किसी न किसी प्रकार की मनुष्टि प्राप्त करता है। अतः यह कहना भ्रामक होगा कि अर्थशास्त्र केवल भौतिक कल्याण का ही अध्ययन है।

वास्तविक जगत में हम 'भौतिक' व 'अभौतिक' के बीच रेखा नहीं खींच सकते हैं। इनका अन्तर सर्वत्र स्पष्ट नहीं होता है। मार्शल के अनुसार गायक, चित्रकार, अध्यापक आदि की सेवाएँ मानव कल्याण में वृद्धि करती हैं परन्तु ये सेवाएँ भौतिक नहीं हैं, अतः अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। राबिन्स ने इस तर्क का तीव्र विरोध किया है और कहा है

"Is it not misleading to go on describing Economics as the study of 'the causes of material welfare'? The services of the opera dancer are wealth. Economics deals with the pricing of these services, equally with the pricing of the services of a cook" <sup>19</sup> - Robbins

इसी प्रकार भौतिक तथा अभौतिक कल्याण के सम्बन्ध में, मजदूरी के सदर्थ में राबिन्स ने कहा है "मजदूरी का ऐसा कोई भी सिद्धांत असहनीय होगा, जो

<sup>19</sup> - L. Robbins, *An Essay on the Nature & Significance of Economic Science*, London, 1949, p. 9

भुग्नान के उस भाग पर जो अमौलिक उद्देश्यों पर व्यय किया जाता है या प्रमौलिक सेवाओं के लिए दिया जाता है, ध्यान नहीं देता हो ।”

“A theory of wages which ignored all those sums which were paid for immaterial services or were spent on immaterial ends, would be intolerable”

3. क्रियाओं का ‘आर्थिक’ तथा ‘अनार्थिक’ वर्गीकरण उचित नहीं मार्शल ने केवल उन मानवीय क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री माना है जिनका सम्बन्ध धन से है अर्थात् आर्थिक हैं । जिन क्रियाओं का सम्बन्ध धनोपार्जन तथा धन के व्यय करन से नहीं है, वे मार्शल द्वारा अनार्थिक क्रियाएँ मानी गयी हैं । राबिन्स ने मानव-क्रियाओं के इस प्रकार के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी क्रिया के धन से सम्बन्धित होने पर ही उसे आर्थिक क्रिया कहना तथा उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मानना अनुचित है । वस्तुतः उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं तथा दुर्लभ साधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं के रूप में अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मानना चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया का सम्बन्ध धन से ही हो । यदि उसका सम्बन्ध दुर्लभ साधनों से है और किसी व्यक्ति को उसका चुनाव करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्भव हो सकता है तो ऐसी क्रिया को आर्थिक क्रिया ही कहा जायेगा । उदाहरणार्थ, जब एक व्यक्ति अपने सीमित समय को अपने दैनिक कार्यक्रम में इस प्रकार विभाजित करता है कि उसे समस्त कार्यों को पूरा करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होती है तब सीमित समय और अनेक कार्यों में अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिये किया गया प्रयास आर्थिक क्रिया के वर्ग में ही रखा जायेगा । इसे अर्थशास्त्र की परिधि से बाहर रखना उसके क्षेत्र को संकुचित करना होगा ।

4 अर्थशास्त्र का सम्बन्ध कल्याण से जोड़ना अनुचित मार्शल ने अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भौतिक कल्याण से जोड़ा है । राबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भौतिक कल्याण से जोड़ना उचित नहीं है । बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कमो होती है (जैसे शराब या अश्व नशीली वस्तुएँ), फिर भी ऐसी वस्तुओं के उत्पादन विक्रय आदि क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है । इसी प्रकार ‘युद्ध’ द्वारा सामान्यतः मानव कल्याण में कमो होती है, फिर भी ‘युद्ध अर्थ-व्यवस्था’ का अध्ययन अर्थ-शास्त्र में किया जाता है । इसके अतिरिक्त ‘भौतिक कल्याण’ का सम्बन्ध मनुष्य की मनः स्थिति से है । इसे मुद्रा द्वारा नहीं नापा जा सकता है । इस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चाहे अन्य किसी भी वस्तु से हो, परन्तु, इसका सम्बन्ध भौतिक कल्याण से नहीं है ।

“Whatever Economics is concerned with, it is not concerned with the causes of material welfare as such” — Robbins

5 अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है बल्कि मानव-विज्ञान भी है। परन्तु मार्शल ने इसे केवल समाज-विज्ञान माना है। उनके अनुसार हमें केवल सामाजिक तथा वास्तविक व्यक्तियों की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। उन व्यक्तियों की क्रियाओं का जो सामाजिक नहीं है और जो एकान्तवास करते हैं अथवा जिनके कार्य समाज के अन्य सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, अर्थशास्त्र में कोई महत्व नहीं है।

राबिन्स का इस सम्बन्ध में यह मत है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों की ही आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करने का अर्थ उसके क्षेत्र को संकुचित तथा सीमित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह समाज में रहता हो या समाज से अलग रहता हो, जीवन-यापन के लिए प्रयत्न करता ही है। उसके शरीर प्रयत्नों का सम्बन्ध सीमित साधनों से है। अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन एकान्तवासी तथा समाज से अलग रहने वाले व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र के नियम समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।

6. उद्देश्यों के प्रति अर्थशास्त्र की तटस्थता : यदि मार्शल की परिभाषा को सही मान लिया जाए तो अर्थशास्त्री का कार्य यह भी होगा कि वह यह बतलाए कि कौनसा कार्य अच्छा है तथा कौनसा बुरा है। इस प्रकार नीति निर्देशन करना भी अर्थशास्त्री का कर्तव्य होगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान (Normative Science) हो जाएगा। राबिन्स का कथन है कि नीति निर्देशन करना — अच्छा या बुरा बतलाना — नीतिशास्त्र का कार्य है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है (Economics is neutral between the ends) अर्थशास्त्र का नीतिशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है।

7 मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। मार्शल तथा उसके समर्थकों द्वारा दी गई परिभाषाएँ वर्ग विभेदात्मक (Classificatory) हैं। उन्होंने क्रियाओं का वर्गीकरण आर्थिक तथा अनार्थिक, कल्याण का वर्गीकरण भौतिक तथा अभौतिक, मनुष्य का वर्गीकरण सामाजिक तथा असामाजिक के रूप में किया है। उनके अनुसार ‘आर्थिक’, ‘अभौतिक’ तथा ‘असामाजिक’ का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र सामान्यतः वस्तु विनिमय (Barter) की क्रियाओं का भी अध्ययन नहीं करता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यन्त ही संकुचित हो जाता है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर राबिन्स ने कहा है कि ‘कल्याण’ सम्बन्धी

परिभाषाएं दोषपूर्ण, सकुचित तथा अर्थशास्त्रिक हैं। फिर भी बहुत से अर्थशास्त्री अब भी मार्शल की परिभाषा में सहमत हैं।

(ख) प्रो० पीगू की परिभाषा :

प्रो० पीगू ने मार्शल की परिभाषा के मूल तत्वों को स्वीकार किया तथा उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यक्ति तथा समाज के भौतिक कल्याण के अतर्गत आर्थिक कल्याण के पक्ष को विशेष महत्व प्रदान किया। उनके अनुसार, "अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण का अर्थ सामाजिक कल्याण के उस पक्ष से है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मुद्रा के मापदण्ड से सम्बन्धित किया जा सकता है।"<sup>20</sup>

उपर्युक्त परिभाषा के द्वारा प्रो० पीगू ने मार्शल की परिभाषा को अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाने की चेष्टा की है। प्रो० पीगू की परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक कलदायरु शास्त्र एवं विज्ञान माना है। उनके विचार में यह शास्त्र एवं विज्ञान आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। उन्होंने इस आर्थिक कल्याण के माप को समव बनाने के लिए मुद्रा के मापदण्ड का समावेश किया तथा मानव-कल्याण में वृद्धि करने वाले उन सभी भौतिक तथा अर्थशास्त्रिक साधनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया है जो मुद्रा से नापे जा सकते हैं।

परन्तु प्रोफेसर पीगू की परिभाषा अस्पष्ट तथा सकुचित है। आलोचकों का यह मत है कि आर्थिक कल्याण की धारणा सम्भव नहीं है और मुद्रा द्वारा मापनीय भौतिक तथा अर्थशास्त्रिक साधनों का वर्गीकरण करना भी कठिन है। इस परिभाषा ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को महत्व प्रदान किया है जिसमें मुद्रा का ही अधिक महत्व है। मुद्रा रहित समाज में प्रो० पीगू की परिभाषा महत्वहीन है।

(ग) कल्याण प्रधान अन्य परिभाषाएं

प्रो० मार्शल तथा पीगू द्वारा दी गई परिभाषाओं का कल्याण-प्रधान परिभाषाओं में त्रिषिष्ट स्थान है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के उद्देश्य को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र को अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया, यद्यपि उनकी परिभाषाओं में भी मूल विचार वही हैं, जिन पर मार्शल तथा पीगू ने जोर दिया है।

<sup>20</sup>. Economics is a study of economic welfare, economic welfare being described as that part of welfare which can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money."



प्रो० कॅनन (Cannan) के अनुसार "अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों का स्पष्टीकरण करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण प्राधारित है।"<sup>21</sup>

फेयर चाइल्ड (Fair Child) ने मार्शल की कल्याण प्रधान परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'अर्थशास्त्र मानवीय आवश्यकताओं तथा उनको सन्तुष्ट करने के उन साधनों का विज्ञान है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने वाली वस्तुएं प्राप्त करते हैं।'<sup>22</sup>

पेंसन (Penson) ने इस सम्बन्ध में अपनी सूक्ष्मतम परिभाषा दी है, 'अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है।'<sup>23</sup>

### 3 दुर्लभता प्रधान परिभाषा (Scarcity Definition)

प्रोफेसर राबिन्स ने प्रो० मार्शल तथा उनके अनुयायियों की भौतिकवादी विचारधारा का सख्त विरोध किया। उन्होंने प्रो० मार्शल की परिभाषा की बहुत प्रलोचना की तथा अर्थशास्त्र को नयेन एव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया उनके अनुसार, 'अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राशियों और विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।'

'Economics is the science which studies human behaviour in a relationship between ends and scarce means which have alternative uses'<sup>24</sup>  
—Robbins

### राबिन्स की परिभाषा की व्याख्या

1 लक्ष्य या उद्देश्य (Ends) राबिन्स का कथन है कि मनुष्य के लक्ष्य अनेक तथा असीमित हैं। लक्ष्य का अर्थ आवश्यकताओं से है। इन आवश्यकताओं का अन्त जन्म से मरण तक भी नहीं होता और उनकी सन्तुष्टि की समस्या मनुष्य के सामने सदैव बनी रहती है। मनुष्य जीवन भर अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए प्रयत्न करता रहता है, परन्तु आवश्यकताओं का क्रम बना ही रहता है तथा वह सभी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण व कम

<sup>21</sup>. 'The aim of Political Economy is the explanation of the general causes on which the material welfare of human beings depends.'  
—Cannan

<sup>22</sup>. "Economics is the science of human wants and of the means by which men obtain the things that satisfy them."  
—Fair Child

<sup>23</sup>. "Economics is the science of material welfare"  
—Penson

<sup>24</sup>. L. Robbins, op cit. p. 16

महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है क्योंकि वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन अल्प है। उसके पास समय कम है तथा प्रकृति भी कृपण है अतः विभिन्न आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना आवश्यक है।<sup>25</sup>

2 साधनों का सीमित एवं दुर्लभ होना (Limited Means) असीमित आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की समस्या का कारण यह है कि व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि अथवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। यदि व्यक्ति के साधन भी आवश्यकताओं की तरह असीमित हो तो उसकी सभी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। यहां पर साधनों के सीमित या दुर्लभ होने का अर्थ यह है कि साधन मांग की तुलना में कम होते हैं।

3 साधनों के वैकल्पिक उपयोग (Alternative uses) साधन दुर्लभ हान के साथ साथ विभिन्न उपयोग वाले होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की तीव्रता के आधार पर ही उन साधनों का चुनाव करता है। साधनों की दुर्लभता मात्र ही आर्थिक समस्याओं का जन्म नहीं होता। यदि साधनों के वैकल्पिक उपयोग नहीं हो तो दुर्लभ होते हुये भी उनका "आर्थिक उपयोग"—प्रबलतम सन्तुष्टि की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि एक साधन के विभिन्न उपयोग हों। व्यक्ति के सामने यही समस्या रहती है कि वह सीमित साधन का उपयोग किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए करे। व्यक्ति आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर, उनकी सन्तुष्टि के लिए साधनों का उपयोग करता है। यदि किसी साधन का एक ही उपयोग किया जा सकता है तो आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होगा।

4. लक्ष्यों के महत्व में विभिन्नता साधनों के केवल वैकल्पिक प्रयोग से ही आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यह आवश्यक है कि लक्ष्यों की तीव्रता या महत्व समान नहीं हो। यदि दो लक्ष्य या आवश्यकताएँ समान महत्व की हैं तथा उनकी सन्तुष्टि के लिए एक साधन है तो व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर सकता है कि किस आवश्यकता की पूर्ति करे। आर्थिक समस्या के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता हो जिससे चुनाव करने में सुविधा हो।

उपयुक्त तथ्यों पर आधारित राबिन्स की परिभाषा अधिक व्यापक है। इस परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र में दुर्लभ साधन (Scarce means) तथा विभिन्न

<sup>25</sup> "We are sentient creatures with bundles of desires and aspirations. . . But the time is limited...Life is short Nature is niggardly"  
—Robbins, op cit p 13

महत्व की असीमित आवश्यकताओं एवं सद्य (ends) के बीच चुनाव के आधार पर मानव-व्यवहार के उस पक्ष का अध्ययन का विषय माना गया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोग वाले अपने दुर्लभ साधनों का चुनाव करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। यह स्मरणीय है कि राबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या का जन्म उसी समय होगा, जबकि उपरोक्त चारो शर्तों की पूर्ति एक ही साथ होती हो।

**राबिन्स की परिभाषा की विशेषतायें -**

1. अर्थशास्त्र विशुद्ध एवं वास्तविक विज्ञान है : प्रो० राबिन्स का कथन है कि अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है जिनका उद्देश्य आदर्शों का प्रतिपादन करना नहीं है और न तो कला के रूप में उसका उद्देश्य वास्तविकता तथा आदर्श के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना ही है। यह तो मानव-व्यवहारों की विवेचना उनके वास्तविक रूप में करता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति सटस्थ रहता है।

2. मानव व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है : प्रो० राबिन्स ने अर्थशास्त्र में साधनों की दुर्लभता का समावेश करके साधनों के भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण के प्रश्न को समाप्त कर दिया। उनका विचार है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की क्रियाओं के केवल उस पहलू का ही अध्ययन करता है जिसका सम्बन्ध दुर्लभ साधनों के चुनाव से है। अतः अर्थशास्त्र मानव की उस निर्णय प्रवृत्ति का अध्ययन है जिसका सम्बन्ध दुर्लभ साधनों तथा विभिन्न लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करने से है। यह आवश्यक नहीं है कि वे साधन भौतिक ही हों। यदि अभौतिक साधनों, जैसे समय और शक्ति, के प्रयोग में भी इस प्रकार के निर्णय या चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

राबिन्स ने आर्थिक तथा अर्थानैतिक क्रियाओं के भेद का पूर्णरूपेण स्पष्ट करते हुए कहा कि मानवीय क्रियाओं का इस प्रकार का वर्गीकरण सम्भव नहीं है। एक मनुष्य की एक ही प्रकार की क्रिया को दो विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक तथा अर्थानैतिक मानना उचित प्रतीत नहीं होता। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति आत्म-सन्तोष के लिए गाता गाता है तो भाषण के अनुसार वह अर्थानैतिक क्रिया कही जायेगी, क्योंकि इसका सम्बन्ध घनोपाजन से नहीं है। परन्तु यदि वही व्यक्ति गाना गाकर घनोपाजन करने लगे तो ऐसी क्रिया आर्थिक क्रिया कहलायेगी। राबिन्स का इस सम्बन्ध में यह विचार है कि ये दोनों ही कार्य सीमित समय और शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्णय लेने से इस प्रकार से सम्बन्धित हैं कि दोनों में भेद करना कठिन है। असीमित आवश्यकताओं तथा दुर्लभ साधनों के होने पर उसमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में मनुष्य अपनी

क्रियाओं में निर्णय या चुनाव पक्ष को अधिक महत्व देता है। राबिन्स के मतानुसार ऐसी समस्त क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ मानी जायेंगी और उन सबका ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जायेगा।

3. प्रवृत्तियों की मुद्रा द्वारा माप नहीं मानवीय प्रवृत्तियाँ धन के मापदण्ड से मापनीय हैं या नहीं? इस सम्बन्ध में राबिन्स ने मुद्रा या धन के मापदण्ड को कोई स्थान नहीं दिया है।

4. अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत है राबिन्स की परिभाषा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य का निर्णय पक्ष (Choice Making) सर्व-कालीन तथा सर्वव्यापी है। उनका विचार है कि साधनों के सीमित होने पर उनके चुनाव का प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष आता है, चाहे वह व्यक्ति समाज में रहे या समाज से बाहर रहे। इस आधार पर राबिन्स इसे केवल सामाजिक शास्त्र ही नहीं मानते। उनका कथन है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र इससे भी अधिक विस्तृत है। इस प्रकार राबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया है। राबिन्स के अनुसार,

"Our Economics holds good under barter as well as under money exchange, under individual as well as under social human conduct, under capitalist as well as under socialist society"

**राबिन्स की परिभाषा की आलोचना :** राबिन्स की परिभाषा अधिक तर्कमुक्त तथा उपयुक्त मानी जाती है, फिर भी उसकी भी आलोचनार्यों की गयी हैं

1. अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक होना प्रो० राबिन्स ने मानवीय क्रियाओं के आर्थिक तथा अनार्थिक भेद को समाप्त करके समस्त मानवीय प्रवृत्तियों के निर्णय करने के पक्ष को ही विशेष महत्व दिया है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत तथा व्यापक हो गया है कि यह समझना कठिन हो जाता है कि किन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए? फलस्वरूप बहुत से ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका सम्बन्ध सीमित साधनों के चुनाव से होता है, यह समस्या बनी रहती है कि इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए अथवा नहीं। राबिन्स के अनुसार इनको अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मानना चाहिए। उदाहरणार्थ राबिन्स के अनुसार जब किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी आराधना के सम्बन्ध में राम या कृष्ण में चुनाव करने (Choice making) की समस्या होती है या कोई विद्यार्थी शाँ के बदले शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ने के सम्बन्ध में चुनाव करे तो इस निर्णय प्रवृत्ति का अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना जा सकता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में इन समस्याओं का अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। इनके अतिरिक्त चुनाव या निर्णय का उद्देश्य अधिक मन्तोप है।

प्रति केवल इन निरुपेक्ष प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का आधार मान लेना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ।

2 उद्देश्यों के प्रति तटस्थता प्रो० राबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि "अर्थशास्त्र का सम्बन्ध केवल साधनों से है उद्देश्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है।"<sup>26</sup> उनका विचार है कि "अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है।" उन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है और इसी आधार पर उनका कथन है कि विभूत विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को वर्तमान वास्तविक तथ्यों के आधार पर 'जो है' (What is) से सम्बन्धित सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना चाहिए । अर्थशास्त्री का यह कतब्य नहीं है कि वह इन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते समय आदर्श पक्ष अर्थात् 'क्या होना चाहिए' (What ought to be) को ध्यान में रखे ।

आलापको वा यह विचार है कि राबिन्स का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है । साधनों का पूरा रूप से उपयोग करने तथा उनका पूर्ण लाभ उठाने का आधार अधिकतम सम्प्राप्त करना है । इस भावना के पीछे सामाजिक तथा मानवीय कल्याण के उद्देश्य भी निहित हैं । मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में आदर्श की भावना रहती है । यदि केवल वास्तविकता को ही ध्यान में रखा जाय तो बारबार वूडन (Barbara Wooton) के अनुसार अर्थशास्त्र एक शुष्क विज्ञान मात्र रह जायेगा । 'अर्थशास्त्रियों के लिए अपनी धिक्कता में से आदर्श पक्ष को पूर्णतः पृथक् कर देना बहुत ही कठिन है।'<sup>27</sup>

फ्रेजर (Fraser) के भी विचार से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है तथा उसका उद्देश्य केवल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना ही नहीं है । इसका क्षेत्र इससे भी अधिक विस्तृत है । उनके अनुसार 'अर्थशास्त्र (का क्षेत्र) मूल्य सिद्धान्त तथा साम्य विरलेषण से कहीं अधिक विस्तृत है।'<sup>28</sup> अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक आदर्श विज्ञान भी है जो सामाजिक समस्याओं के वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करता है ।

3 साधनों तथा लक्ष्यों का अस्पष्ट होना - प्रो० राबिन्स ने अपनी परिभाषा में प्रयुक्त 'लक्ष्य' तथा 'कुलम साधनों' शब्दों को स्पष्ट नहीं किया है । यह शब्द यह व्यक्त

<sup>26</sup> "Economics deals with means The study of ends lies outside its scope"

<sup>27</sup> "It is very difficult for economists to divest their discussions of all normative significance"  
—Barbara Wooton

<sup>28</sup> "Economics is more than a value theory or equilibrium analysis."  
—Fraser

करते हैं कि मनुष्य के समक्ष अनेक लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए उनके पास जो साधन होते हैं वे दुर्लभ होते हैं। उनके अनुसार जब किसी एक साधन द्वारा किसी एक लक्ष्य को पूर्ति कर ली जाती है, तब साधन और लक्ष्य का पारस्परिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।

परन्तु आलोचकों का मत इसके विपरीत है। उनका विचार है कि मनुष्य या समाज का एक ही लक्ष्य है—अधिकतम सन्तुष्टि या प्रसन्नता (Maximum satisfaction or happiness) प्राप्त करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अनेक साधन होते हैं, न कि अनेक साधन और अनेक लक्ष्य होते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय तो यह है कि इन दुर्लभ साधनों का प्रयोग किस विधि से किया जाये कि मनुष्य या समाज अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सके। अतः राबिन्स का यह निष्कर्ष कि अनेक दुर्लभ साधनों और लक्ष्यों के कारण एक निरन्तर बनी रहने वाली समस्या का अध्ययन ही अर्थशास्त्र का विषय है, भ्रष्ट तथा भ्रामक है।

4. साधनों के साथ वैकल्पिक प्रयोगों तथा दुर्लभ शब्दों का प्रयोग प्रो० राबिन्स ने अपनी परिभाषा में साधनों (means) के साथ दुर्लभ (scarce) तथा 'जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है' (which have alternative uses) शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ आलोचकों का यह मत है कि इन शब्दों के द्वारा साधनों की विशेषताएँ व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी साधन वैकल्पिक प्रयोग वाले ही होते हैं। ऐसे साधन दुर्लभ भी होते हैं। ये दोनों ही उपलब्ध साधनों की स्वाभाविक विशेषताएँ होती हैं। राबिन्स ने इन विशेषणों का प्रयोग करके साधनों के वर्गीकरण की समस्या खड़ी कर दी है जिससे अर्थशास्त्र एक अटिल विषय बन गया है।

5. आर्थिक निष्कर्षों के लिए निगमन प्रणाली की ही मान्यता अनुचित है प्रो० राबिन्स ने आर्थिक निष्कर्षों को ज्ञात करने के लिए केवल निगमन प्रणाली (Deductive Method) के प्रयोग को ही अधिक उपयुक्त माना है। परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करने तथा उचित निष्कर्षों को ज्ञात करने के लिए "भाषमन प्रणाली" (Inductive Method) की भी आवश्यकता पड़ती है।

6. मानव-कल्याण के साथ सम्बन्ध नहीं है प्रो० राबिन्स ने अपनी परिभाषा में मानव-कल्याण के उद्देश्य को कोई महत्व प्रदान नहीं किया है। परन्तु वस्तुतः समस्त आर्थिक क्रियाओं का अन्तिम लक्ष्य मानव-कल्याण में वृद्धि करना होता

है। यदि अर्थशास्त्र इस सम्बन्ध में तटस्थ रहे और यदि उसका सम्बन्ध मनुष्य या समाज के हित-अहित, सुख-दुःख तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक कल्याण से न रहे, तो यह शास्त्र मानव-समाज के लिए अनुपयोगी हो जायेगा। वह एक निश्चित सिद्धान्त-वादी शुष्क तथा भावनाहीन विज्ञान-मात्र रह जायेगा।

7 उचित निर्णय की प्रवृत्ति व्यापक नहीं है : प्रो० राबिन्स की यह मान्यता कि मनुष्य की यह सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए सर्वत्र दुर्लभ साधनों के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय लेता है तथा यह निर्णय पक्ष ही उसकी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करता है, गलत तथा अस्वाभाविक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में अधिकांश आवश्यकताएँ साधनों के सम्बन्ध में बिना किसी निर्णय या चुनाव के सन्तुष्ट कर ली जाती हैं। विवेकपूर्ण तथा व्यापक चुनाव और प्रतिस्थापन की प्रयत्नशीलता मानवीय प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं में यदा-वदा ही देखने को मिलती है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राबिन्स की परिभाषा में भी कई दोष हैं। राबिन्स की पुस्तक के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् ही, सन् 1933 में Prof. Souder ने अपने एक लेख द्वारा, राबिन्स की परिभाषा की कटु आलोचना की। उन्होंने इस परिभाषा के आधार पर राबिन्स को "Juggler with a static verbal logic" और 'Profane sunderer of form from substance' कहा। साउटर की इस तीव्र भर्त्सना का कारण यह था कि राबिन्स ने अपनी परिभाषा द्वारा अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से अन्य विषयों से अलग माना, ऐसे विषयों से भी सम्बन्ध नहीं रखता, जिनसे अर्थशास्त्र किसी न किसी रूप में अनिष्ट रूप से सम्बन्धित है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र (Sociology) तथा प्रविधि-शास्त्र (Technology)। अन्य विषयों से सम्बन्ध विच्छेद तथा उद्देश्यों के प्रति तटस्थता के कारण साउटर के अनुसार, राबिन्स ने अर्थशास्त्र को 'Purely formal science of implications' बना दिया। राबिन्स ने 'भागवतक तर्क' (Abstract reasoning) को अर्थशास्त्र का आधार माना। इस प्रकार साउटर के अनुसार राबिन्स का दृष्टिकोण पूर्णरूप से औपचारिक (formalistic) था। साउटर ने कहा कि यदि राबिन्स के मत को अन्य विषयों पर भी लागू किया जाए, अर्थात् यदि अन्य विषय भी एक-दूसरे से सम्बन्ध न रखें तो सभी विषयों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। ('each of which can be sealed in airtight receptacle only on the penalty of death') इस प्रकार राबिन्स के मत को यदि मान लिया जाए तो साउटर के अनुसार हमें अर्थशास्त्र के अन्तिम दिन देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।

## मार्शल तथा राबिन्स की परिभाषाओं की तुलना

(Comparison between Marshall's & Robbins' Definitions)

(क) समानताएँ यद्यपि राबिन्स ने अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री मार्शल की कटु आलोचना की है, तथापि दोनों ही विद्वानों ने इस विषय के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं माना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में अपनाये गये दृष्टिकोणों में कुछ भौतिक विभिन्नता अवश्य है, परन्तु उनके विचारों में निम्न-लिखित समानताएँ भी पायी जाती हैं।

(1) मार्शल तथा राबिन्स दोनों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है।

(11) मार्शल में 'अधिकतम कल्याण' (Maximization) पर जोर दिया है तथा राबिन्स ने 'मितव्ययिता' (Economizing) पर, परन्तु दोनों के द्वारा ही अधिकतम सन्तुष्टि होगी।

(111) मार्शल ने 'धन' तथा राबिन्स ने 'सीमित साधन' शब्द का प्रयोग किया है, परन्तु दोनों का अर्थ वास्तव में एक ही है।

(ख) असमानताएँ यद्यपि अर्थशास्त्र के अध्ययन के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रो० मार्शल तथा प्रो० राबिन्स एक मत हैं, फिर भी आर्थिक प्रयत्नों तथा साधनों के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए उनके विचारों में कुछ असमानताएँ हैं। दोनों की परिभाषाओं में अन्तर का अध्ययन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है :

(1) मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की धन-सम्बन्धी अर्थात् आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। जिन क्रियाओं का सम्बन्ध धन से नहीं होता, वे अनार्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता राबिन्स ने समस्त मानवीय कार्यों के उस पक्ष को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है जिनका सबंध असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों में समन्वय स्थापित करने से हो, चाहे उन कार्यों का सबंध धन से हो या न हो। राबिन्स की परिभाषा के अनुसार सभी आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाएँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित की जा सकती हैं।

(2) साधनों का वर्गीकरण मार्शल तथा उनके समर्थकों ने भौतिक कल्याण के आधार पर, केवल भौतिक साधनों को ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है। राबिन्स ने अपनी परिभाषा में उन समस्त साधनों को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है जो दुर्लभ होते हैं, चाहे वे साधन भौतिक हों या अमौलिक।

(3) अर्थशास्त्र के अध्ययन का लक्ष्य : मार्शल तथा उनके अनुयायियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मानव-कल्याण है। वह मानव-कल्याण की वृद्धि के लिए आदर्शवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी करता है परन्तु राबिन्स का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के सम्बन्ध में राबिन्स स्पष्ट है।



(4) अध्ययन का क्षेत्र : मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में एक ऐसे व्यक्ति को ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक, सामान्य तथा वास्तविक हो, अर्थात् वह एक औसत एवं सामान्य व्यक्ति की तरह वास्तविक रूप में मानव समाज में रहता हो। राबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में ऐसे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके समक्ष असंमित आवश्यकताओं तथा दुर्लभ साधनों के मध्य समन्वय की समस्या बनी रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति समाज में रहता हो। यदि वह मानव समाज के बाहर है तो भी उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जायेगा।

(5) मानवीय प्रवृत्तियों की माप : मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत केवल उन मानवीय क्रियाओं को ही सम्मिलित किया है जो मुद्रा के मापदण्ड द्वारा मापनीय होती हैं, क्योंकि इस मापदण्ड के द्वारा ही भौतिक कल्याण को नापा जा सकता है तथा उससे सम्बन्धित योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं। राबिन्स न आर्थिक तथा अनार्थिक, भौतिक तथा अभौतिक क्रियाओं के भेद को अस्वीकार करके, मानवीय प्रवृत्तियों की माप की आवश्यकता ही नहीं ममकी है। वह मानवीय क्रियाओं के उस आर्थिक पक्ष को ही इस विषय की सामग्री मानते हैं, जो दुर्लभ साधनों के चुनाव से सम्बन्धित होता है।

उपयुक्त असमानताओं को निम्न सारणी द्वारा प्रकट किया जा सकता है।

मार्शल	राबिन्स
1. अर्थशास्त्र मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है।	1. अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के उपयोग से सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन है।
2. अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है।	2. अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है।
3. अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है।	3. अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है।
4. अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भौतिकता से है।	4. अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की क्रियाओं से है।
5. मार्शल की परिभाषा वर्गीकरण (Classificatory) है। इसमें मनुष्य को सामाजिक व असा- माजिक, क्रियाओं को आर्थिक व	5. राबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक (Analytical) है। इसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं है।

अनाधिक, तथा कल्याण को भौतिक व अमौलिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6. मानवीय प्रवृत्तियों (Human-motives) को मुद्रा द्वारा नापा जा सकता है।

7. माशेल की परिभाषा व्यावहारिक है।

6. मानवीय प्रवृत्तियों को न तो नापने की आवश्यकता है और न मुद्रा द्वारा उन्हें नापा ही जा सकता है।

7. राबिन्स की परिभाषा संझा-न्तिक है।

#### 4 आवश्यकता-विहीनता-परिभाषा (Wantlessness Definition)

अर्थशास्त्र के पाश्चात्य दृष्टिकोण की मान्यता अधिकतम सन्तोष तथा भौतिक सुख एवं कल्याण पर आधारित है। इसके फलस्वरूप ही पाश्चात्य विद्वानों ने आवश्यकताओं के अन्तर्गत होने तथा उनकी सन्तुष्टि के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों को ही अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री माना है। भारतीय विचारक एवं अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे० के० मेहता का दृष्टिकोण पाश्चात्य दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। उनका कथन है कि "मानव व्यवहार का सर्वव्यापक उद्देश्य आवश्यकताओं को समाप्त करना है।"<sup>29</sup> उन्होंने आगे कहा है कि 'आवश्यकताओं से मुक्ति पाने की समस्या ही आर्थिक समस्या है।'<sup>30</sup> अतः उनके अनुसार "अर्थशास्त्र को मानव क्रियाओं के उस विज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जिसने आवश्यकता विहीनता की दशा को पहचानने का प्रयास किया जाता है।"

"Economics must, therefore, be defined as the science of human activities considered as an endeavour to reach the state of wantlessness"

—J. K. Mehta

प्रो० मेहता की परिभाषा भारतीय-दर्शन से प्रभावित है। "सादा जीवन उच्च विचार" (Simple living and high thinking) भारतीय सभ्यता का आधार है। महात्मा गांधी इस आदर्श में अटूट विश्वास रखते थे। उन्होंने भी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखने पर जोर दिया, क्योंकि आवश्यकताओं की वृद्धि से मनुष्य का असन्तोष बढ़ता है। महात्मा गांधी ने कहा है।

<sup>29</sup>. "It can, therefore, be maintained that elimination of wants is one universal of all behaviour."

—J. K. Mehta

<sup>30</sup> "The problem of gaining freedom from wants is regarded as an economic problem"

—J. K. Mehta

"The human mind is like a restless bird, the more it gets, the more it wants and still remaining unsatisfied"  
—Gandhi

प्रो० मेहता इस विचार के समर्थक हैं। उन्होंने भी आवश्यकताओं को कम करने पर जोर दिया है। उनका विचार है कि आवश्यकताओं का पूर्णतः लोप सम्भव नहीं है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का चुनाव इस प्रकार अवश्य कर सकता है कि उनको धीरे-धीरे कम करके भी वह अधिकतम सन्तुष्टि का अनुभव कर सके। उन्होंने आनन्द (Pleasure), कष्ट (Pain) तथा सन्तुष्टि (Satisfaction) के आधार पर 'आनन्द एवं कष्ट के सिद्धांत' (Pleasure and Pain Theory) का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि मनुष्य ऐसी आवश्यकताओं का सर्वथा त्याग कर दे जिनकी सन्तुष्टि साधनों के अभाव में असम्भव है तो उसका मानसिक असंतुलन से होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जायेगी। अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के सम्बन्ध में वह क्षणिक मानसिक असंतुलन अनुभव करेगा। वह अपने प्रयासों द्वारा थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति करके मानसिक सन्तुलन प्राप्त करने में सफल होता है, उस सीमा तक वह आनन्द (Pleasure) का अनुभव करता है। परन्तु वास्तविक सुख (real happiness) इस क्षणिक आनन्द में नहीं है, बल्कि उसके स्थायी मानसिक सन्तुलन की स्थिति में है, जिसे प्रो० मेहता 'इच्छा रहित अवस्था' (State of wantlessness) कहते हैं। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भ से ही असौमित्र आवश्यकताओं में से कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं का ही चुनाव किया जाये जिससे सीमित साधनों का अधिकाधिक उपयोग सम्भव हो सके तथा आनन्द मिल सके।

### प्रो० मेहता तथा प्रो० राबिन्स के दृष्टिकोणों की तुलना

प्रो० मेहता तथा राबिन्स द्वारा निर्णय पक्ष को अधिक महत्व देने के कारण इन दोनों विद्वानों द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि—

1 राबिन्स ने आवश्यकताओं की वृद्धि पर बल दिया है, जबकि प्रो० मेहता ने इन आवश्यकताओं को क्रमशः कम करने तथा अन्त में उनको समाप्त करने पर विशेष जोर दिया है।

2 राबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक परन्तु तटस्थ विज्ञान माना है, जबकि प्रो० मेहता ने अधिकतम सुख के चरम लक्ष्य को निर्धारित करके इसे एक प्रादर्श (Normative) विज्ञान माना है।

3 राबिन्स अधिकतम उपयोगिता में विश्वास रखते हैं। प्रो० मेहता अधिकतम सुख की स्थिति में विश्वास रखते हैं जो 'आवश्यकता विहीनता' की अवस्था में प्राप्त होता है। राबिन्स का दृष्टिकोण आवश्यकताओं का सन्तुष्टि तक ही सीमित है,

जबकि प्रो० मेहता का दृष्टिकोण दूरदर्शी है, क्योंकि उनका कथन है कि मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह पूर्ण मानसिक समतुलन की स्थिति के अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करे ।

प्रोफेसर मेहता के दृष्टिकोण की आलोचना यद्यपि दर्शन और नीतिशास्त्र (विशेषकर भारतीय दर्शन) के दृष्टिकोण से प्रो० मेहता के विचार उचित और तर्क युक्त प्रतीत होते हैं, फिर भी इस भौतिकवादी युग में वे यथार्थ एवं व्यावहारिक नहीं माने जा सकते । साधारण जीवन में असीमित आवश्यकताओं की समुष्टि से ही अधिकतम सुख प्राप्त किया जा सकता है, न कि उनको कम करने पर । ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को कम करने बरकरा आवश्यकता विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इस भौतिकवादी युग में एक काल्पनिक या समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति माना जायेगा । अतः प्रो० मेहता का विचार दार्शनिक, अव्यावहारिक एवं काल्पनिक है जो वास्तविकता से परे है । अर्थशास्त्र एवं वास्तविक विज्ञान है जिसमें वास्तविक स्थिति तथा वास्तविक मानवीय प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है । यदि अर्थशास्त्र प्रो० मेहता के आदर्शात्मक पहलू को मान्यता प्रदान करके आवश्यकता विहीनता के आदर्श को ही महत्व देने लगे तो वह एक अव्यावहारिक एवं काल्पनिक विज्ञान माना जायेगा ।

प्रो० मेहता ने उपलब्ध साधनों के सीमित होने के कारण आवश्यकताओं को कम करने पर विशेष जोर दिया है । उन्होंने इन साधनों में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील होने के पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने आवश्यकताओं से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य या वास्तविक सुख माना है । परन्तु इस भौतिकवादी युग में प्रो० मेहता के द्वारा बतलाए गए मानव जीवन के इस लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता । वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान युग में मनुष्य अधिक से अधिक सुखी रहना चाहता है । उसका यह विश्वास है कि भौतिक सुख आवश्यकताओं की वृद्धि तथा उनकी समुष्टि से ही सम्भव है । यही कारण है कि वह अपने सीमित साधनों में वृद्धि करने का प्रयास करता है । यदि वह प्रो० मेहता के कथनानुसार सांसारिक मोहमाया का परित्याग कर दे, तो देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की आवश्यकता ही नहीं होगी । इस विचार-धारा के अनुसार न तो किसी व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी और न ही देश के आर्थिक विकास की । यह एक ऐसी पलायनवादी तथा निराशावादी धारणा है जिसे स्वीकार कर लेने पर वह व्यक्ति, समाज तथा देश की आर्थिक प्रगति में बाधक होगी । इसका परिणाम यह होगा कि अर्थशास्त्र की नींव जो आवश्यकताओं की वृद्धि (Maximisation of wants) तथा उनकी समुष्टि के लिए किए जाने वाले आर्थिक प्रयासों पर आधारित है कमजोर हो जायेगी । ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता नहीं रहेगी ।

### सर्वोत्तम परिभाषा

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के विवेचन के पश्चात् यह ज्ञात करना आवश्यक है कि कौन सी परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त तथा व्यावहारिक है? स्पष्ट रूप से किसी भी परिभाषा को सर्वोत्तम कहना कठिन है। जैसा कि आलोचनाओं से स्पष्ट है, प्रत्येक परिभाषा में कोई न कोई दोष है। प्रो० बोल्डिंग (Boulding) ने भी यह कहा है कि अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएँ दी गई हैं, उन सब में कोई न कोई त्रुटि है। कुछ परिभाषाएँ संकुचित हैं तथा कुछ प्रत्यस्त ही व्यापक। बोल्डिंग ने कहा है, अर्थशास्त्र को 'मानव के सामान्य जीवन व्यवसाय का अध्ययन' कहना अर्थशास्त्र को बहुत ठगपक विषय बनाना है। इसे भौतिक कल्याण का अध्ययन' कहना अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित बनाना है। अर्थशास्त्र को 'मानवीय मूल्यांकन तथा चुनाव' से सम्बन्धित करना प्रत्यस्त ही व्यापक है। इसी प्रकार इसे मुद्रा द्वारा मापनीय मानवीय कार्यों का अध्ययन' कहना भी संकुचित दृष्टिकोण है।

"To define it as 'a study of mankind in the ordinary business of life is surely too broad To define it as the study of material wealth is too narrow. To define it as the study of human valuation and choice is again probably too wide, and to define it as the study of that part of human activity subject to the measuring rod of money, is again too narrow'" A. E. Boulding : *Economic Analysis* p 3

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर हम मोटे रूप में दो विचार-धाराएँ पाते हैं—कुछ अर्थशास्त्री मानस की परिभाषा को सर्वोत्तम बतलाते हैं तथा कुछ राबिन्स की परिभाषा को। राबिन्स ने स्वयं अर्थशास्त्र की उत्तम परिभाषा की कसौटी का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'किसी परिभाषा की सत्यता की अन्तिम कसौटी, साधारण बोल चाल में प्रयुक्त शब्दों से उसकी प्रत्यक्ष अनुरूपता न होकर, उस विज्ञान की अन्तिम विषय सामग्री से सम्बन्धित मुख्य सिद्धान्तों को सही रूप में प्रकट करने की क्षमता है।'<sup>31</sup>

हम आर्किस्ट की इस कसौटी से सहमत हैं। इस दृष्टि से स्पष्ट रूप से परिभाषा की जाँच करने पर यह ज्ञात होता है कि यह परिभाषा संबंधा भ्रष्टाचार-हारिक तथा अनुपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के स्थान पर धन को अधिक महत्व देकर मनुष्य तथा उसकी क्रियाओं की उपेक्षा की है। प्रो० मेहता की परिभाषा भी

31. "The final test of validity of any such definition is not its apparent harmony with certain usages of everyday speech, but its capacity to describe exactly the ultimate subject matter of the main generalisations of the science"

वास्तविकता से परे मानी जाती है। यह वास्तविक तथ्यों से दूर है तथा इस भौतिकवादी युग के लिए अनुपयुक्त है।

आधुनिक अर्थशास्त्री राबिन्स की परिभाषा को अधिक उपयुक्त मानते हैं। उनका विचार है कि राबिन्स की परिभाषा सैद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि राबिन्स ने आवश्यकताओं की बहुलता तथा उनकी अधिकतम सतुष्टि पर बल दिया है। राबिन्स की परिभाषा में अर्थशास्त्र के सभी मिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। अधिकांश अर्थशास्त्री राबिन्स की परिभाषा को पूर्ण, शुद्ध तथा वैज्ञानिक मानते हैं। Prof Macfie ने तो राबिन्स की परिभाषा को 'अन्तिम परिभाषा' मान लिया है।

"What he (Robbins) has said cannot be resaid To me it appears final within its chosen scope"

—Macfie, *An Essay on Economy and Value*

इसके साथ ही साथ उन्होंने सभी मनुष्यों की समस्त क्रियाओं के निरालंघ्य पक्ष को, जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित एवं दुर्लभ साधनों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। फिर भी राबिन्स की परिभाषा वैज्ञानिक है तथा वह अर्थशास्त्र की आत्मा व शरीर दोनों को प्रकट करने में अधिकांश अर्थों में सफल है। उनकी परिभाषा में यदि कोई दोष है तो यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है। परन्तु इसके सम्बन्ध में राबिन्स का विचार है कि यदि लक्ष्य अनेक हैं तो यह आर्थिक समस्या है। यदि लक्ष्य एक ही है तथा यह बतलाना है कि किस विधि से उस लक्ष्य को पूरा किया जाये तो यह प्राविधिक (Technological) समस्या है, आर्थिक नहीं। (Multiplicity of ends and multiplicity of means raises economic problem If end is one then it is technological problem)। इस प्रकार राबिन्स की परिभाषा शुद्ध है।

मार्शल ने केवल भौतिक साधनों तथा सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है अतः मार्शल की परिभाषा मरुचित तथा सीमित मानी जानी है। मार्शल की परिभाषा की सबसे अधिक आलोचना 'भौतिक' शब्द के प्रयोग के कारण की गई है।<sup>१३२</sup>

फिर भी व्यावहारिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि मार्शल अर्थशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक

१३२. "This fatal word 'material' is probably more responsible for the ignorant slanders on the 'dismal science' than any other economic description."

कल्याण में वृद्धि करना मानते हैं, जबकि राबिन्स अर्थशास्त्र के इस आदर्श पहलू की ओर से तटस्थ है। मार्शल ने मनुष्य जीवन के सामान्य व्यवहारों तथा भौतिक कल्याण की वृद्धि में अर्थशास्त्र के उपयोग को महत्व दिया है, जबकि राबिन्स आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के सम्बन्ध में मानवीय प्रवृत्तियों के निर्णय पक्ष की वास्तविकता पर विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट व्यक्त नहीं करते कि उसके माने मनुष्य को क्या करना चाहिये? यही कारण है कि कुछ विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र यदि वास्तविक विज्ञान (Positive Science) होने के साथ-साथ आदर्श विज्ञान (Normative Science) नहीं हो तो व्यावहारिक जीवन में उसका विशेष महत्व नहीं रहेगा। वह समाज विज्ञान के रूप में उपयोगी नहीं हो सकेगा। वर्तमान समाजवादी विचारधाराये भी मानव कल्याण तथा भौतिक कल्याण को अर्थशास्त्र के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करती हैं। ऐसी स्थिति में राबिन्स की परिभाषा एकपक्षीय मानी जाती है, क्योंकि वह मानव-कल्याण में वृद्धि करने के आदर्शात्मक तथ्य के प्रति शान्त हैं। राबिन्स के इस तटस्थ दृष्टिकोण के कारण ही उनकी परिभाषा की अपेक्षा मार्शल की परिभाषा की मान्यता बढ़ती जा रहा है।

### संकेत

1. अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह कर परिभाषित किया गया है। क्या यह परिभाषा पर्याप्त है? (Jodhpur, T.D C., Arts 1963)

[संकेत—प्रथम धन सम्बन्धी परिभाषाएँ देकर उनकी व्याख्या कीजिए और आलोचना देने हुए सिद्ध कीजिए कि ये परिभाषाएँ अपूर्ण तथा दोष पूर्ण हैं।]

2. "अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन व्यवसाय के सम्बन्ध में अध्ययन है।" अर्थशास्त्र की इस परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।]

(Ravishankar, B. Com. Pali, 1963)

[संकेत—मार्शल की परिभाषा की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उसकी परिभाषा की मुख्य आलोचनाएँ दीजिए।]

3. राबिन्स की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन उनकी परिभाषा के अन्तर्गत आता है?

[Ravi., B.A. Final, 1965, Lucknow, B.A. I, 1963]

[संकेत—राबिन्स की परिभाषा दीजिए तथा उसकी प्रमुख आलोचनाएँ दीजिए। इसके पश्चात् यह बताइए कि इस परिभाषा का सम्बन्ध, आर्थिक कल्याण से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है; यद्यपि आर्थिक कल्याण का विचार भी चयन की समस्या से सम्बन्धित है।]

4. “अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छारहित अवस्था में पहुँचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है।”—मेहता । इस कथन की विवेचना कीजिए ।

[संकेत—‘इच्छा रहित अवस्था’ के विचार की व्याख्या कीजिए तथा उप-युक्त कथन की विवेचना करते हुए बताइये कि यह विचार वर्तमान भौतिकवादी युग में कहाँ तक तक संगत है ?]

5. मार्शल तथा रोबिन्स द्वारा दी गयी परिभाषाओं का मूल्यांकन (evaluation) कीजिए । इन दोनों में से किसको आप पसन्द करते हैं और क्यों ?

[संकेत—दोनों की परिभाषाओं की समालोचना कीजिए तथा यह बताइए कि सैद्धांतिक दृष्टि से रोबिन्स तथा व्यावहारिक दृष्टि से मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त हैं ।]



# 3

## अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र (Nature and Scope of Economics)

*"The theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine an apparatus of the mind technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions"*

J. M. Keynes

प्रत्येक शास्त्र के अन्तर्गत कुछ निश्चित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अतः यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है? हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक गत्यात्मक विषय है। इस शास्त्र के विकास के साथ ही साथ इसके अन्तर्गत आने वाली विषय सामग्री (Subject Matter) भी विस्तृत होती गई। क्रमिक विकास के कारण अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई तथा परिभाषा की ही भांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विवाद उठ खड़े हुये।

किसी भी विषय के क्षेत्र का अभिप्राय उसके अन्तर्गत अध्ययन की जाने वाली विषय-सामग्री, उस विषय की प्रकृति व स्वरूप, तथा उसकी परिसीमाओं या मर्यादाओं से है। अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर है :

1. अर्थशास्त्र का विषय क्या है (Subject Matter) : यह एक सामाजिक शास्त्र है या मानव शास्त्र? इसके अन्तर्गत मनुष्य की क्रियाओं का सम्बन्ध केवल धन से है या वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों से?

2. अर्थशास्त्र की प्रकृति (Nature) क्या है? (i) क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? (ii) यदि वह विज्ञान है, तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? तथा (iii) क्या अर्थशास्त्र कला है?

3. अर्थशास्त्र की मान्यताएँ तथा सीमाएँ क्या हैं?

## 1. अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री (The Subject Matter of Economics)

एडम स्मिथ तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। एडम स्मिथ ने 'आर्थिक मनुष्य' (Economic Man) की कल्पना की थी। परन्तु अर्थशास्त्र के अन्तर्गत धन की ही अध्ययन का विषय मानना किसी भी विचारक के द्वारा उचित नहीं माना गया।

डा० मार्शल तथा उनके समर्थकों ने अर्थशास्त्र के उद्देश्य तथा उसके विषय के सम्बन्ध में निम्नलिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया

(अ) अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उसके भौतिक कल्याण से सम्बन्धित हैं;

(ब) भौतिक कल्याण का अर्थ भौतिक आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि से है;

(स) आर्थिक क्रियाओं का अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो धन से सम्बन्धित हैं, इस प्रकार मार्शल ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य की प्राथमिकता प्रदान की तथा यह स्पष्ट कर दिया कि अर्थशास्त्र में केवल ऐसे ही व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य होते हैं। मार्शल ने केवल उन्हीं क्रियाओं तथा साधनों को अर्थशास्त्र का विषय माना है जो आर्थिक तथा भौतिक हो।

राबिन्स ने मार्शल द्वारा निर्धारित अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को संकुचित तथा प्रबंधनानुसार माना। राबिन्स ने उन सभी मानवीय क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री माना जिनका सम्बन्ध असीमित आवश्यकताओं तथा दुर्लभ साधनों से है। असीमित आवश्यकताओं की सीमित साधनों द्वारा सन्तुष्टि के लिए चुनाव की समस्या उठती है। अतः राबिन्स ने चुनाव (Choice) या मूल्यांकन (Valuation) की समस्या को अर्थशास्त्र का मुख्य विषय माना है। (Valuation is the central problem of Economics' Robbins) राबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री निम्नलिखित है :

(1) अर्थशास्त्र में सभी व्यक्तियों का, चाहे वे समाज में रहते हों या समाज के बाहर, अध्ययन किया जाता है,

(2) इसके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों की समस्त क्रियाओं के उस निर्णय पक्ष का अध्ययन किया जाता है जिसका सम्बन्ध वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं से होता है, तथा

(3) दुर्लभ साधनों में उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं।

इस प्रकार राबिन्स ने सभी व्यक्तियों (सामाजिक तथा असामाजिक) समस्त क्रियाओं (आर्थिक तथा अनार्थिक) और समस्त साधनों (भौतिक तथा अभौतिक) को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है। आजकल राबिन्स का मत ही अधिक प्रचलित है।

**आर्थिक विभागों के विभाग :** अर्थशास्त्र को विषय सामग्री को निम्नलिखित विभागों में बाटा गया है।

1. उपभोग (Consumption) इसके अन्तर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं तथा उनकी सन्तुष्टि से सम्बन्धित निषेधों का अध्ययन किया जाता है।

2. उत्पादन (Production) मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने वाली वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण, विभिन्न साधनों की प्राप्ति, उपलब्ध पदार्थों में उपयोगिता का सृजन अथवा उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने से सम्बन्धित प्रयत्नों एवं प्रयासों को उत्पादन की विषय-सामग्री के अन्तर्गत रखा गया है।

3. विनिमय (Exchange) : वस्तुओं का उत्पादन सामूहिक रूप से होने के कारण उनके विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है। अतः उनके मूल्य-निर्धारण, त्रय-विक्रय, मुद्रा, बैंक-व्यवस्था आदि विषयों को विनिमय के अन्तर्गत रखा गया है।

4. वितरण (Distribution) : किसी वस्तु की उत्पत्ति विभिन्न साधनों के सहयोग का प्रतिफल है। अतः विनिमय द्वारा प्राप्त प्रतिफल का सहयोगी साधनों में वितरित करने की समस्याओं तथा तदुपलब्धी सिद्धांतों को वितरण का विषय माना गया है।

5. सार्वजनिक राजस्व (Public Finance) उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री में पाचवा विभाग सार्वजनिक राजस्व भी है। इस विभाग को सम्मिलित करने का कारण यह है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत राज्य की आय के स्रोतों, उसके व्यय की मूल्य तथा राजकीय वित्तीय व्यवस्था आदि का अध्ययन किया जाय।

**अर्थशास्त्र समाजशास्त्र है (Social Science) या मानव शास्त्र (Human Science) ?**

मार्शल ने अर्थशास्त्र को 'जीवन के साधारण क्रिया-वलाप में मानव जाति का अध्ययन' कहकर इसके समाज-शास्त्र होने पर बत दिया है। मार्शल के अनुसार

अर्थशास्त्र सामाजिक मनुष्य की आर्थिक गियाओं का अध्ययन करता है। समाज के बाहर रहने वाले साधु सन्यासी तथा राबिन्सन क्रूओ जैसे एकांतवासी अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री नहीं है। प्रो० राबिन्सन ने अर्थशास्त्र को मानव शास्त्र माना है। उन्होंने कहा है, 'अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन करता है।' असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के चुनाव की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष रहती है चाहे वह समाज के अन्दर रहता हो या समाज के बाहर।

इन दो विचारधाराओं के अतिरिक्त एक तीसरी विचारधारा भी है, जिसमें इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाया है। इस मध्यम मार्ग के समर्थक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र विनिमय, वितरण, तथा राजस्व विभागों के आधार पर एक समाज-शास्त्र है। परन्तु उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी मानव की क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र एक मानवशास्त्र प्रतीत होता है, क्योंकि उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी क्रियाएँ समाज के बाहर रहने वाले व्यक्ति को भी करनी पड़ती हैं। 'उपभोगिता ह्यम नियम' तथा 'प्रतिस्थापन का नियम' समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

75850

व्यावहारिक दृष्टि से अर्थशास्त्र 'समाज शास्त्र' प्रतीत होता है। इसको अधिकांश विषय-सामग्री समाज से ही सम्बन्धित है, यद्यपि यह सत्य है कि अर्थशास्त्र के उत्पादन तथा उपभोग के नियम समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के समष्टिक पहलू (Macro) पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जो समाज की आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थशास्त्र मानव शास्त्र है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से समाज शास्त्र है।

## 2 अर्थशास्त्र की प्रकृति ( Nature of Economics )

अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों ? अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के पूर्व यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान की दो शाखाएँ हैं—विज्ञान तथा कला। विज्ञान (Science) ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है जो कार्य और कारण के पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित करता है<sup>1</sup>। इस प्रकार विज्ञान वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य तथा परिणाम में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करता है।

<sup>1</sup> "Science is a systematised body of knowledge it is that knowledge which establishes a relationship between cause and effect."

उपर्युक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान का प्रथम उद्देश्य वास्तविक तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में एकत्र करना है। इसके पश्चात् वह एक निश्चित रूप में उनका वर्गीकरण करता है और परिणाम-सम्बन्धी नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है।

विज्ञान की दो शाखाएँ हैं—(1) वास्तविक विज्ञान (Positive Science) तथा (2) आदर्श विज्ञान (Normative Science)। वास्तविक या यथार्थ विज्ञान का उद्देश्य वस्तु स्थिति अर्थात् यथार्थ तथ्यों का ज्ञान कराना है। इसमें केवल हमी प्रश्न का उत्तर मिलता है कि यथार्थ वस्तु स्थिति या तथ्य 'क्या है' (What is)। अतः इसका कार्य वास्तविक तथ्यों से सम्बन्धित कारणों और परिणामों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना है। यह आदर्शों का प्रतिपादन नहीं करता। आदर्श विज्ञान का उद्देश्य आदर्शों को प्रस्तुत करना है। इसके द्वारा 'क्या होना चाहिये' (What ought to be) प्रश्न का समाधान मिलता है। यह किसी भी वस्तु स्थिति में क्या सत्य या उचित है और क्या असत्य या अनुचित है, इसका बोध कराता है। वास्तविक या अवास्तविक आदर्शों को स्पष्ट करते हुए यह उचित आदर्शों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है।<sup>2</sup>

क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है ?

(क) अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं :

1 अर्थशास्त्र में मानव व्यवहारों का अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य भी आर्थिक तथ्यों को एकत्रित तथा वर्गीकृत करके उनसे सम्बन्धित कारणों एवं परिणामों के पारस्परिक सम्बन्ध को ज्ञान करना है।

2 इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अर्थशास्त्र के अध्ययन की सम्पूर्ण विषय सामग्री पाँच भागों—उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में बाँट दी गयी है और इन विभागों में मनुष्य की क्रियाओं से सम्बन्धित आवश्यक नियमों का अध्ययन किया जाता है।

3 आर्थिक क्रियाओं की माप के लिए 'मुद्रा' का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री इस मापक के कारण आर्थिक निष्कर्षों में निश्चितता ला देता है।

<sup>2</sup> "Positive Science may be defined as a body of systematised knowledge concerning 'what is,' a Normative Science or a regulative science is a body of systematised knowledge relating to criteria of 'what ought to be', and concerned with the ideal as distinguished from the actual. The objective of a positive science is the establishment of uniformities, of a normative science, the determination of ideals."

—J. N. Keynes, *Scope and Method of Political Economy* p 16

इस प्रकार विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन ( Analytical and scientific study) की दृष्टि से अर्थशास्त्र विज्ञान है।

(ख) कुछ अर्थशास्त्री निम्नलिखित तर्कों के आधार पर अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं -

1. आर्थिक सिद्धांतों के विषय में अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में निश्चितता नहीं है, जबकि विज्ञान सुनिश्चित होता है, उसमें तथ्य के विषय में मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता है।

2 अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, अतः मानव-व्यवहार के सम्बन्ध में कारण-परिणाम के आधार पर जो नियम अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाये जाते हैं, वे पूर्ण रूप से सत्य नहीं सिद्ध होते हैं, जबकि वैज्ञानिक नियम पूर्ण रूप से सत्य होते हैं।

3. मुद्रा को आर्थिक क्रियाओं का मापक माना जाता है। परन्तु मुद्रा आर्थिक क्रियाओं का सही मापक नहीं है। विज्ञान में जिन मापकों का प्रयोग किया जाता है, वे सही स्थिति का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार उचित तथा शुद्ध मापक व अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता है।

4 वैज्ञानिक नियमों के निर्माण के लिये सही आकड़े ( Statistics ) आवश्यक हैं। आर्थिक-विषयों में सम्बन्धित परिस्थितियाँ जैसे तकनीक, संस्थाएँ आदि बदलती रहती हैं। अतः स्वरूप इनसे सम्बन्धित आकड़े भी बदलते रहते हैं। आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आकड़े भी नहीं मिलते हैं। 'आकड़े कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं' (Statistics can prove anything)। यह कथन आर्थिक आकड़ों के सम्बन्ध में अधिक नहीं है। इस प्रकार इन आकड़ों पर आधारित आर्थिक नियम भी सही नहीं होते हैं।

इन तर्कों के होते हुए भी अर्थशास्त्र को विज्ञान की कोटि में रखा जा सकता है। वस्तुतः कुछ आर्थिक नियम भी वैज्ञानिक नियमों की भाँति सही होते हैं। मानव व्यवहार परिवर्तनशील होते हुए भी एक सामान्य दिशा तथा एकरूपता की ओर सकेत अवश्य करते हैं।

**अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान ?**  
(Is Economics Positive or Normative Science ?)

हम पहले 'वास्तविक विज्ञान' तथा आदर्श-विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। प्रायः सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। मतभेद अर्थशास्त्र के 'आदर्श विज्ञान' होने के सम्बन्ध में है। अर्थशास्त्र का

आदर्शात्मक पहलू भी है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है ।

अर्थशास्त्री का कार्य उपदेश देना नहीं है, वर्तन वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना है । उसे एक वैज्ञानिक की तरह, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए । यह मन उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक काफी प्रचलित था । Myrdal के अनुसार प्रायः सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान माना गया ।

“Almost all leading economists, from N Senior and J. S. Mill onwards” had made pronouncement “that the science of economics should be concerned only with what is and not what ought to be”  
— G Myrdal *Value in Social Theory*, p. 437

परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के सम्बन्धों के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ । जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा (Historical School) के अर्थशास्त्रियों ने बड़े जोरदार ढंग से कहना प्रारम्भ किया कि अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू भी है तथा अर्थशास्त्र का नीतिशास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है । शुम्पीटर ने लिखा है कि सन् 1909 में Vienna की मीटिंग में ‘Werturteil’ (Value judgement) के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के बीच विवाद न इतना उग्र रूप धारण किया कि उनमें हाथा-पाई होते होते बची । उनके पश्चात् यह विवाद कई वर्षों तक शान्त रहा, परन्तु 1932 में राबिन्स की पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही यह विवाद पुनः चल पड़ा ।

अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों में सीनियर फ़ैरबैस, राबिन्स आदि प्रमुख हैं । इसी प्रकार वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू आदि प्रमुख हैं ।

## 1 अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है

अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों का मत है कि वास्तविक विज्ञान के रूप में इसका उद्देश्य आर्थिक समस्याओं के कारणों तथा परिणामों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना है । उनका कहना है कि एक वैज्ञानिक के रूप में किसी भी अर्थशास्त्री के लिए आर्थिक आदर्शों के सम्बन्ध में अपना मत देना उचित नहीं है । उचित-अनुचित ज्ञान कराने का कार्य नीतिशास्त्रियों का है । अर्थशास्त्रियों का कार्य केवल वास्तविकता के आधार पर वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति के कारणों एवं परिणामों को ज्ञात करना तथा उनका विश्लेषण करना है ।

इस विचारधारा के समर्थकों में जे० बी० से, सीनियर (Senior), कैरनेस तथा राबिन्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सम्बन्ध में जे० बी० से का कथन है "हम जनता को केवल यह बताने के लिए उत्तरदायी हैं कि अमुक तथ्य क्यों और कैसे किसी अन्य तथ्य का परिणाम है। चाहे यह निष्कर्ष स्वीकृत हो या अस्वीकृत इतना ही ध्येष्ट है कि अर्थशास्त्री द्वारा उसके कारणों को प्रदर्शित एवं व्यक्त कर दिया जाए परन्तु उसे इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं देना चाहिए। सीनियर का भी यही विचार था कि अर्थशास्त्री का कार्य परामर्श देना नहीं बल्कि उन सामान्य नियमों का उन्मेष कर देना है जिनकी उपेक्षा करना घातक सिद्ध हो सकता है। कैरनेस ने अर्थशास्त्रियों को यह सलाह दी है कि वे लक्ष्यों के प्रति उसी प्रकार तटस्थ रहें जिस प्रकार एक यांत्रिक (Mechanic) रेलवे निर्माण की प्रति स्पर्द्धात्मक योजनाओं के प्रति रहता है।<sup>3</sup>

राबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। उनके अनुसार अर्थशास्त्री का कर्त्तव्य वास्तविक तथ्यों का अनुमधान कर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देना मात्र है। उसका कार्य लक्ष्यों के औचित्य के सम्बन्ध में राय देना नहीं है। मानव कल्याण विषय पर सुझाव या उपदेश प्रस्तुत करना अर्थशास्त्री के कार्यक्षेत्र की परिधि से परे है। उसका कर्त्तव्य माधनों के अध्ययन तक ही सीमित है। वह केवल विशुद्ध अनुमधान कर्त्ता है, उपदेशक नहीं।<sup>4</sup> अर्थशास्त्री लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग निर्देशन नहीं करता। वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है।<sup>5</sup> उसे प्रादर्शों तथा नैतिक शिक्षा से परे रहना चाहिए।

‘वास्तविक विज्ञान’ होने के पक्ष में दिये गए तर्क .

(1) तर्क पर आधारित विज्ञान का काम ‘कारण’ तथा ‘परिणाम’ के सम्बन्ध को बतलाना है। अर्थशास्त्र भी अर्थ विज्ञानों की भांति कारण तथा परिणाम के सम्बन्ध को बतलाता है। विज्ञान का आधार तर्क होता है। अर्थशास्त्र केवल उन्हीं विषयों से सम्बन्धित है, जिनका निश्चय तर्क द्वारा किया जा सकता है। अच्छा या बुरा बतलाना अर्थशास्त्र का कार्य नहीं है। अर्थशास्त्री यह बतलाएगा कि ‘प्रत्यक्ष कर’ तथा ‘अप्रत्यक्ष कर’ की क्या हानियाँ तथा लाभ है, परन्तु इन दोनों में कौन अच्छा है ? यह बतलाना अर्थशास्त्री का कार्य नहीं है।

<sup>3</sup> "Political economy stood neutral as regards ends as mechanic stands neutral between rival schemes of railway construction"

—Cairness

<sup>4</sup> "The function of economists consists in exploring and explaining and not advocating and condemning".

—Robbins

<sup>5</sup> "Economics is neutral between ends"

—Robbins



(ii) **श्रम विभाजन :** राबिन्स के अनुसार मानव-ज्ञान में भी श्रम-विभाजन का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये। सभी विज्ञान एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार सब बुद्ध करने के चक्कर में अर्थशास्त्री कुछ नहीं कर सकेगा। अतः अर्थ-शास्त्री का कार्य आर्थिक समस्या के 'विश्लेषण तक ही सीमित होना चाहिए। नीति निर्देशन का कार्य 'नैति-शास्त्र' के लिए छोड़ देना चाहिए।

(iii) **उद्देश्य का पहले से ही निर्धारण :** राबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी राय नहीं दी जा सकती है। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य (Ends) पहले से ही निश्चित होता है तथा समस्या विशेष के अध्ययन के दौरान लक्ष्य बदलता नहीं है। इस प्रकार 'लक्ष्य' के सम्बन्ध में यदि अर्थशास्त्री उपदेश देता है तो वह अर्थशास्त्र की सीमा का उल्लंघन करता है।<sup>6</sup>

(iv) **धर्माथ तथा आदर्श की खाई को पाटना असम्भव** राबिन्स ने कहा है कि धर्माथ (Positive) तथा आदर्श (Normative) सम्बन्धी अध्ययन में पर्याप्त अन्तर है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों में अन्तर इतना अधिक है कि उस अन्तर को दूर करना असम्भव है। दोनों की सीमाएँ पूर्णरूप से भिन्न हैं। अर्थ-शास्त्र निश्चित किए जाने योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है, नीतिशास्त्र मूल्यों, कर्तव्यों का अध्ययन करता है। ('Economics deals with ascertainable facts, ethics with valuations and obligations') अर्थशास्त्री यदि उपदेश देता है तो वह अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र को मिलाने की अनाधिकार चेष्टा करता है। वास्तविक तथा आदर्श के नियमों के बीच इतनी चौड़ी खाई है जिसे मरन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।<sup>7</sup>

(v) **'सन्तुलन' के आधार पर भी अर्थशास्त्र धर्माथ विज्ञान है :** अर्थशास्त्री सन्तुलन (Equilibrium) की बातें करते हैं। सन्तुलन के शुद्ध सिद्धान्त द्वारा हमें यह ज्ञात करने में सहायता मिलती है कि वर्तमान प्राविधिक तथा वैधानिक वातावरण में, विभिन्न आर्थिक तथ्यों के मूल्यों में उन सम्बन्धों को कैसे स्थापित किया जा सकता है, जिनमें विचलन (Variation) की प्रवृत्ति सामान्यतः नहीं होती। सन्तुलन द्वारा यह ज्ञात होता है कि अधिकतम सन्तुष्टि के लिए साधनों का वितरण किस प्रकार किया जाय। परन्तु इसके द्वारा किसी आदर्श का ज्ञान नहीं होता। यह प्रदर्शित करना कि 'कुछ परिस्थितियों' में मार्ग की सन्तुष्टि अन्य वैकल्पिक परि-

<sup>6</sup>. I M Kirzner, op cit p. 138

<sup>7</sup>. "Between the generalisation of positive and normative studies there is a logical gulf fixed which no ingenuity can disguise and no juxtaposition in space or time bridge over." —Robbins

स्थितियों की अपेक्षा अधिक हो सकती है, यह नहीं सिद्ध करता कि वे 'कुछ परिस्थितियाँ' वाछनीय हैं। सन्तुलन अधिकतम कल्याण का प्रतीक नहीं है। सन्तुलन की स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। 'सन्तुलन सिद्धांत में अनुमोदन का बल नहीं है। संतुलन तो संतुलन मात्र है।'<sup>8</sup>

## 2. अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है :

राष्ट्रिय के उक्त विचार मार्शल, पीगू, फ्रेंजर, मून् तथा हार्ट्रे आदि विद्वानों में मिश्र हैं। इन विद्वानों ने अर्थशास्त्र की आदर्श विज्ञान माना है तथा यह कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में मानव-कल्याण से सम्बन्धित है। अतः इसे आदर्श से अलग नहीं रखा जा सकता। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मार्शल ने 'कल्याण की भौतिक आवश्यकताओं' पर जोर दिया है तथा पीगू ने धन का अध्ययन मानव-कल्याण की दृष्टि में किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं है बल्कि फलदायक भी है। यदि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध नीति-निर्धारण से नहीं होता तो प्राथमिक तन्त्र धनी धनियों को अधिक धनी तथा निर्धनो को अधिक निधन बना देता। परन्तु अर्थशास्त्र में नीति निर्देशन का प्रमुख स्थान होने के कारण ही मानवजाति पूर्ण शोषण तथा असमानता की विषम स्थिति से बचत रह सकती है। इस प्रकार यथार्थता के अतिरिक्त पर प्रकाश डालना तथा मार्ग-दर्शन कराना अर्थशास्त्री का कर्तव्य है। पीगू के विचार, इस सम्बन्ध में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं "अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हमारा दृष्टिकोण या हमारी भावना एक दार्शनिक की तरह 'केवल ज्ञान के लिए ज्ञान' प्राप्त करना ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उस विकसित का दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसका उद्देश्य अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के दुःखों को दूर करना है।"<sup>9</sup>

पीगू ने अपने विचारों को और भी स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा है "अर्थशास्त्र मुख्यतः न तो बौद्धिक व्यायाम के रूप में महत्वपूर्ण है और न ही सत्य के लिए सत्य के साधन के रूप में, बल्कि नीतिशास्त्र की दायी एवं व्यवहार का दाय बनने में है।"

"Economics is chiefly valuable neither as an intellectual

<sup>8</sup>. "There is no penumbra of approbation round the theory of equilibrium. Equilibrium is just equilibrium"

—Robbins op. cit p 143

<sup>9</sup>. "Our impulse is not the philosopher's impulse—knowledge for the sake of knowledge, but rather the physiologists' knowledge for the healing that knowledge may help to bring about."

—Pigou

gymnastic nor as a means of winning truth for its own sake but as a handmaid of Ethics and servant of practice." —Pigou

हाइडे ने आदर्श पक्ष को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है : "अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता.....अर्थशास्त्र को केवल मूल्यांकन तथा नैतिक मानदण्ड का एक दिये गए तथ्य के रूप में ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बरन् उसे इन मूल्यांकनों एवं आदर्शों की अन्तिम सत्यता के सम्बन्ध में अपना निष्णय भी देना चाहिए।"

बार्बेरा वूटन ने वयार्थवादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए कहा है कि "हम अपना अविद्याश समय सैद्धान्तिक उपकरणों के बनाने में लगाते हैं लेकिन उनका लाभ उठाने में बहुत ही कम समय देते हैं।" इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र के आदर्श पक्ष पर जोर दिया है।

अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क :

1. लक्ष्य की प्रकृति आदर्श-मूलक . राबिन्स यह मानकर चलते हैं कि उद्देश्य पूर्व निश्चित होते हैं। यदि यह सही मान लिया जाए तो अर्थशास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। Prof Parsons ने यह मत व्यक्त किया है कि राबिन्स ने भावात्मक लक्ष्य (abstract end) की जो कल्पना की है वह निराधार है। वस्तुतः लक्ष्य उद्देश्य तथा प्रयत्न से सम्बन्धित है जो वास्तव में आदर्श पहलू से सम्बन्ध रखते हैं। अतः जब भी हम 'लक्ष्य' की बात करेंगे, 'आदर्श' का तत्त्व स्वतः आ जाता है।<sup>10</sup>

2. मानव प्रकृति 'आदर्श' से प्रभावित : Veblen ने कहा है कि मनुष्य की प्रकृति प्रभावपूर्ण कार्य करने की तथा बेकार के प्रयत्नों से बचने की है। वह सेवादायकता या कार्यकुशलता का प्रशंसक तथा अयोग्यता, बर्बादी तथा व्यर्थता का विरोधी है। वह जीवन के निरर्थक कार्यों को पसन्द नहीं करता है। वह लक्ष्य की प्राप्ति या सफलता चाहता है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहारों का अध्ययन है, अतः वह आदर्श पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ऐसा करना मानव-प्रकृति की उपेक्षा करना है। कोई भी मानव-शास्त्र, मानव प्रकृति की उपेक्षा कर जीवित नहीं रह सकता है।<sup>11</sup>

3. श्रम विभाजन के आधार पर विभाजन चलता . यह कहना तर्कयुक्त नहीं है कि अर्थशास्त्री कारण व परिणाम का विश्लेषण मात्र कर दे तथा राय देने का

<sup>10</sup> J. M. Kirzner, op cit. p. 139

<sup>11</sup> "There is in the human character "a taste for effective work and a distaste for futile effort...Man is possessed of a discriminating sense of purpose...Economic theory must run back to this ubiquitous human impulse." —Veblen

कार्य नीतिशास्त्री पर छोड़ दे। ऐसा करना उचित नहीं है तथा समय की बर्बादी भी है। अतः अर्थशास्त्री को विशेषण के साथ ही साथ आदर्श के सम्बन्ध में भी राय देनी चाहिए।

4. 'संतुलन' केवल संतुलन के लिए सम्बन्धी तर्क उचित नहीं : राबिन्स के अनुसार संतुलन केवल संतुलन मात्र है। उसमें अनुमोदन का वल नहीं है। यदि यह सही है तो मजदूरी का निर्धारण मांग व पूर्ति के संतुलन द्वारा कराके अर्थशास्त्री को उचित मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं करनी चाहिए। परन्तु वास्तव में अर्थशास्त्री उचित मजदूरी की भी बात करते हैं जो 'आदर्श' का सूचक है।

5. अर्थशास्त्र एक उपयोगी विषय : कल्याणवादी अर्थशास्त्र . व्यावहारिक दृष्टि से हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में कल्याणवादी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) का विकास होता जा रहा है जो आदर्श पहलू का अध्ययन है। आज-कल 'राजस्व' तथा आर्थिक नियोजन (Economic Planning) का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये दोनों ऐसे विषय हैं, जिनमें अर्थशास्त्री आदर्श-पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र को 'सामाजिक प्रगति का इन्जिन' कहा जाता है। अर्थशास्त्र आदर्श-पहलू की उपेक्षा कर सामाजिक प्रगति में सहायक नहीं हो सकता है।

6. औद्योगिक प्रगति : वर्तमान युग औद्योगिक युग है। औद्योगीकरण के कारण नई समस्याएँ पैदा हो गई हैं। सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, श्रम-कल्याण, औद्योगिक विकास का स्वरूप आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिनके समाधान के लिए अर्थशास्त्री को 'क्या करना चाहिए' प्रश्न का भी उत्तर देना पड़ता है जो आदर्श का सूचक है।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का 'आदर्श' पहलू भी है। इस प्रकार यह आदर्श-विज्ञान भी है। वर्तमान समय में अधिकतर अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को यथार्थ विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों मानते हैं। व्यावहारिक रूप में हम जानते हैं कि आज व्यावसायिक तथा औद्योगिक फर्म भी अर्थशास्त्री को परामर्शदाता (Adviser) के रूप में रखती हैं तथा अर्थशास्त्री कर, उत्पादन, विनियोग, नियोजन आदि के सम्बन्ध में सलाह देता है। आज अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में 'Managerial Economics' का महत्व बढ़ता जा रहा है, जो व्यावहारिक समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार 'मानविक' तथा 'आदर्श' विज्ञान सम्बन्धी विवाद अब पुराना पड़ गया है। राबिन्स ने जो बात सन् 1932 में कही, वह व्यावहारिक दृष्टि से आज उपयुक्त प्रतीत होती है। अब तो यह निर्विवाद रूप से माना जाने लगा है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, तथा आदर्श के विषय में राय देना अर्थशास्त्री का कर्तव्य है। Prof Macfie (जो राबिन्स के समर्थक हैं) ने भी, राबिन्स की परिभाषा का समर्थन करते हुए भी, कहा है

“...economics is fundamentally a normative science, not merely a positive science like Chemistry”.

यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों विचारधाराओं के पक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों ही है। वास्तव में यह मानव विज्ञान है, अतः विज्ञान के रूप में वह न तो वास्तविक तथ्यों की उपेक्षा कर सकता है और न ही निश्चित आदर्शों के प्रतिपादन के उत्तरदायित्व में अपने आप को मुक्त कर सकता है। अतः अर्थशास्त्र न तो केवल वास्तविक या यथार्थ विज्ञान है और न आदर्श विज्ञान मान। वह एक ऐसा सामाजिक एवं मानव विज्ञान है जिसके अन्तर्गत यथार्थ आर्थिक तथ्यों के आधार पर आर्थिक आदर्शों का उल्लेख किया जाता है। उदाहरणार्थ, विनिमय के अन्तर्गत हम मांग और पूर्ति का अध्ययन करते हैं जिसमें यह ज्ञान होता है कि मूल्य का निर्धारण किम प्रकार किया जाता है, परन्तु हमें साथ ही साथ अर्थशास्त्र उचित मूल्य का भी अध्ययन करता है। उत्पादन में वास्तविक प्राक्कटो के आधार पर जन-संख्या के घनत्व का यथार्थ रूप में अध्ययन किया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या के विवेचन की भी उपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार वितरण में उचित मजदूरी, उचित लगान, उचित लाभ और उचित राज के सम्बन्ध में आदर्शों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः यह निष्कर्ष उचित है कि अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान दोनों है।

### 3. क्या अर्थशास्त्र कला भी है ? (Is Economics Art also ?)

अर्थशास्त्र कला है या नहीं ? इस सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। एडम स्मिथ, मिल, रिकार्डो, मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्र को कला भी मानते हैं। इनके विपरीत वालरस, सीनियर, मुम्पीटर, राबिन्स आदि अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते हैं। यह प्रश्न अधिक विवादग्रस्त इसलिए हो जाता है कि मार्शल तथा पीगू ने भी इस सम्बन्ध में ऐसे विचार दिये हैं जिनके यदि शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दिया जाए तो उनके अनुसार अर्थशास्त्र कला नहीं है परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके माध्यम पर ध्यान दिया जाए तो अर्थशास्त्र “कला” प्रतीत होता है। अतः इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए उपायों या विधियों का ज्ञान कराती है। विज्ञान से वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। कला सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की विधि बताती है। ‘ज्ञानता’ विज्ञान है तथा ‘करना’ कला है। विज्ञान आचरण का सिद्धान्त मात्र है। जब सिद्धान्तों का आचरण व्यवहार में होता है तब उसे कला कहते हैं। ‘वास्तविक विज्ञान’ द्वारा बतलाई गई वस्तु-स्थिति, तथा ‘आदर्श-विज्ञान’ द्वारा निर्दिष्ट

आदर्श या सर्वोत्तम उपाय द्वारा लक्ष्य तक पहुँचने की विधि क्या होगी ? इसका ज्ञान कला कराती है । कला एक ऐसा पुत है जो वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान को मिलाती है ।

‘अर्थशास्त्र कला नहीं है’ के पक्ष में तर्क .

1. कला तथा विज्ञान एक दूसरे में भिन्न कला तथा विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है । दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं । अतः अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो वह कला नहीं हो सकता ।

2 आर्थिक समस्याओं की प्रकृति कोई भी आर्थिक समस्या वास्तव में विशुद्ध आर्थिक समस्या नहीं होती है । आर्थिक समस्याएँ राजनैतिक, सामाजिक तथा सत्वागत परिस्थितियों में प्रभावित होती हैं । अतः केवल आर्थिक दृष्टि से ही अर्थशास्त्री समस्याओं के समाधान के लिए उचित विधि नहीं बता सकता है । यदि वह विधि या उपाय बताता है तो भी सफलता नहीं मिलेगी । अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत विवेचन कला का आधार तो हो सकता है, परन्तु स्वयं कला का रूप ग्रहण नहीं कर सकता है । मानव के शब्दों में,

“The type of science at the economist will endeavour to develop must be one adapted to form the basis of an art. It will not indeed itself be an art. It is a science pure and applied rather than a science and an art”  
—Marshall

मार्शल के अनुसार, अर्थशास्त्री का आर्थिक समस्या का अध्ययन करने के पश्चात् पीछे हट जाना चाहिए तथा अन्तिम निर्णय सम्बन्धी शायद सामान्य ज्ञान (Common Sense) पर छाड़ देना चाहिए ।

3 आर्थिक निष्कर्षों का नीति निर्धारण में तुरन्त उपयोग नहीं अर्थशास्त्री का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना है, नीति निर्धारण करना नहीं । अर्थशास्त्र के नियमों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से तुरन्त नीति-निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है । इतना अवश्य है कि आर्थिक विश्लेषण नीति निर्धारण में अन्य तत्वों के साथ, एक सहायक तत्व हो सकता है । जे एन केन्स के शब्दों में, “अर्थ शास्त्र ऐसे निश्चित नियम प्रदान नहीं करता है जिन्हें तत्काल ही किसी नीति के लिए प्रयोग में लाया जा सके । यह सिद्धान्त नहीं बल्कि विश्लेषण का एक ढग है । यह विचार करने की विधि तथा मस्तिष्क के लिए एक यन्त्र है, जिसको अपनाते धालों को सही निर्णय पर पहुँचने में सहायता मिलती है ।” जब नीति निर्धारण में आर्थिक नियमों का तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है तब अर्थशास्त्र को कला भी नहीं कह सकते हैं ।

‘अर्थशास्त्र कला है’, के पक्ष में तर्क

1. अर्थशास्त्र सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों अर्थशास्त्र के कला न होने

के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कला व विज्ञान की प्रकृति भिन्न है। अतः अर्थशास्त्र कला व विज्ञान दोनों नहीं हो सकता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ज्ञान की कोई शाखा या विषय ऐसा भी हो सकता है जो सैद्धान्तिक दृष्टि से विज्ञान हो तथा व्यावहारिक दृष्टि से कला भी हो। अर्थशास्त्र ऐसा ही विषय है।

2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) कला का ही प्रतीक है : आजकल व्यावहारिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र राजस्व आदि का महत्व अर्थशास्त्र में बढ़ता जा रहा है। Managerial Economics (जो आर्थिक सिद्धान्तों के व्यावहारिक उपयोग का अध्ययन है) का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल आर्थिक सलाहकार व्यावहारिक नीति के विषय में राय देते हैं। अतः अर्थशास्त्र की आधुनिक प्रवृत्ति का आधार पर इसे कला कहना अनुपम नहीं होगा।

अर्थशास्त्री को चाहिये कि वह प्रायिक समस्याओं का विश्लेषण करे तथा उनको दूर करने के उपाय बताए। एक दाशनिक के रूप में उसे मथार्यता की ओर सकेत करके तटस्थ नहीं हो जाना चाहिये। व्यक्ति तथा समाज से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं जिनका विश्लेषण मान ही लाभदायक नहीं होगा। यदि सरकार द्वारा लगाये गये करों की आलोचना की जाए, लेकिन एक आदर्श कर-प्रणाली को प्राप्त करने के उपाय न बताये जायें, तो अर्थशास्त्री मानव-कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सगता। उसका कार्य, पीगू के कथनानुसार, उसी प्रकार होगा जैसे कि एक डाक्टर किसी रोगी की बीमारी का निदान तो कर दे परन्तु उसका इलाज करने के लिये आवश्यक औपधियों को न बताये। यह सभी जानते हैं कि देश में बेकारी की समस्या है, व्यक्तिगत आय कम है, वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में कमी है। यदि अर्थशास्त्र में इन समस्याओं के कारणों का विश्लेषण ही किया जाय और इन समस्याओं को हल करने के उपायों को न बताया जाय, तो उसे एक फलदायक विज्ञान नहीं कहा जायेगा। इस प्रकार जब अर्थशास्त्र इन समस्याओं के वास्तविक पहलू का अध्ययन करने के उपरान्त निश्चित आदर्शों की प्राप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय भी बताता है तब इसे 'कला' की श्रेणी में रखा जाता है।

निष्कर्ष : उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में वास्तविक आर्थिक तथ्यों को एकत्र एवं संग्रह करता है और उनका विश्लेषण करने के उपरांत वह आर्थिक नियमों के रूप में उनके कारणों एवं परिणामों में सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके उपरांत मानव कल्याण के दृष्टिकोण से वह कुछ आदर्शों की ओर सकेत करता है और अन्त में उन प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आदर्शों की प्राप्ति में जो समस्याएँ आती हैं उनके समाधान के उपायों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान तथा कला, तीनों ही हैं।

## 2. अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (Significance of Economics)

अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है ? इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त ही जटिल है। कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना मात्र है। दूसरी ओर ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान (Applied Science) माना है तथा उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हल प्रस्तुत करना भी है। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र का उद्देश्य नीति-निर्धारण माना है। अर्थशास्त्रियों का एक तीसरा भी वर्ग है जिसने मध्यम मार्ग अपनाया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के द्वारा ऐसे सिद्धान्त निश्चित नहीं किए जाते जिनका व्यावहारिक दृष्टि से तुरन्त उपयोग किया जा सके। इन तीनों प्रकार के मतों के अध्ययन के पश्चात् ही हम अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व के सम्बन्ध में निर्णायक राय प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. अर्थशास्त्र का महत्व केवल सैद्धान्तिक है (Economics has only theoretical significance) : प्रोफेसर राबिन्स, शूम्पीटर, बालरस तथा कूर्नौ (Cournot) आदि अर्थशास्त्रियों ने यह मत प्रकट किया है कि अर्थशास्त्र का कार्य नीति निर्धारण करना नहीं है। अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। यदि अर्थशास्त्र का उद्देश्य नीति-निर्धारण तथा व्यावहारिक निर्देशन करना मान लिया जाय तो एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी। राबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्री का कार्य विभिन्न उद्देश्यों की उपयुक्तता (desirability) के सम्बन्ध में राय देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है—तब अर्थशास्त्र का क्या महत्व रह जायेगा ? राबिन्स ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है :

यदि हमारे समक्ष विभिन्न उद्देश्यों के बीच चुनाव करने की समस्या हो (किस उद्देश्य को पहले पूरा किया जाय ?) तो अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह बतलाता है कि अमुक उद्देश्य को प्राथमिकता देने के विभिन्न परिणाम क्या होंगे ? इसके द्वारा यह ज्ञात नहीं होगा कि कौन सा उद्देश्य श्रेष्ठतम है ? अतः चुनाव करने का कार्य सम्बन्धित व्यक्ति का है, अर्थशास्त्र का नहीं। किम्वस्तु या उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाय ? इस प्रश्न का उत्तर कोई भी विज्ञान नहीं दे सकता। विज्ञान का कार्य केवल विभिन्न सम्भावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना मात्र है। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि विभिन्न विकल्पों (alternatives) के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि चुनाव सम्बन्धी विवेकशीलता का अर्थ है कि चुनाव करने वाला विभिन्न विकल्पों के विषय में जानकारी रखता हो और वह यह जानता हो कि यदि उसने अन्य उद्देश्यों को छोड़कर किसी उद्देश्य-विशेष को चुना है, तो अन्य उद्देश्यों के



छोड़ने से उसे क्या हानि होगी ? यही पर अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्व प्रकट होता है । हमें अर्थशास्त्र द्वारा चुने गये विभिन्न उद्देश्यों के आशय तथा परिणाम का ज्ञान प्राप्त होता है । इन्हें द्वारा हमारे लिए ऐसे उद्देश्यों का चुनाव करना सम्भव हो पाता है जो परस्पर एक दूसरे से सगत (Consistent) हैं ।<sup>1</sup> इस प्रकार राबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का महत्व केवल सैद्धान्तिक है । अर्थशास्त्र द्वारा विभिन्न नीतियों की जांच करने में सहायता मिलती है । अर्थशास्त्र हमें नीति की वैकल्पिक सम्भावनाओं के महत्वपूर्ण परिणामों की जानकारी प्राप्त कराने में सहायक होता है ।<sup>2</sup> इसके द्वारा नीति-निर्देशन नहीं किया जाता । अर्थशास्त्र विवेक पूर्ण निर्णय पर पहुँचने में सहायक होता है । राबिन्स के शब्दों में, “अर्थशास्त्र विवेकपूर्ण कार्य करने की दिधि प्रदान करता है तथा हमारे साधनों तथा उद्देश्यों के बीच चुनाव की क्रिया का सगत ढंग से संपादन सम्भव बना देता है ।”

“Economics provides a technique of rational action and makes it possible to act more consistently in choosing out ends and our means for attaining them”  
—Robbins

2. अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्व भी है (Economics has practical importance also) . एडम स्मिथ, जे० एस० मिल, रिकार्डों तथा पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी माना है । इनके अनुसार कोई भी अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण करते समय सैद्धान्तिक रूप से तटस्थ नहीं रह सकता । अर्थशास्त्री का काम विभिन्न आर्थिक विषयों पर राय देना तथा नीति-निर्देशन करना भी है । अर्थशास्त्री एक दास्यनिक नहीं है, बल्कि एक चिकित्सक है “जिसे समाज के आर्थिक स्वास्थ्य के लिये निदान तथा चिकित्सा करनी है ।”<sup>3</sup> फ्रेजर ने कहा है, “एक अर्थशास्त्री, जो केवल अर्थशास्त्री है, केवल माधारण सुन्दर मछली है ।”<sup>4</sup> इस प्रकार अर्थशास्त्री का कार्य नीति-निर्धारण तथा नीति-निर्देशन दोनो है ।

अन्य वैज्ञानिक विषयों की भाँति अर्थशास्त्र भी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में मदद देता है । राबिन्स का यह कहना कि विज्ञान का कार्य नीति-निर्देशन

1 “Economics can make clear to us the implications of the different ends we may choose. It makes it possible for us to select a system of ends which are mutually consistent with each other”

—Robbins

2 “It enables us to conceive the far reaching implications of alternative possibilities of policy”  
—Ibid, p, 156

3 “He (the economist) should diagnose and prescribe for the economic health of the society.”  
—Smithies

4 “An economist who is only an economist is a poor pretty fish”  
—Fraser

करनी नहीं है, इसी राय से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यहाँ तक कि शुद्ध विज्ञान भी वास्तविक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए, एषोन विज्ञान (Astronomy) द्वारा नाविकों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये गए। चिकित्सा-विज्ञान का विनाश बीमारी दूर करने के लिए किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि विज्ञानों का विकास मानव-समाज की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही किया गया। अर्थ-अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान है, अतः इसके द्वारा विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। बेरोजगारी, मुद्रा-रफ़ीनि, मूल्य-स्तर विदेशी व्यापार, मजदूरी, लाभ, राष्ट्रीय करण, सम्पत्ति तथा आय का वितरण, कृषि, उद्योग, भादि से सम्बन्धित अन्य समस्याएँ हैं जिनका विश्लेषण अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित तथा आवश्यक मुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यापक दृष्टि से प्रत्यक्ष ही उपयोगी है। “अर्थशास्त्र मूल्य सिद्धान्त या सन्तुलन-विश्लेषण मात्र नहीं है, वह इससे अधिक है।”<sup>3</sup> इस कथन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र केवल सैद्धान्तिक विश्लेषण ही नहीं प्रस्तुत करता बल्कि आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित उपाय भी बताता है। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से यह एक उपयोगी विषय है।

3 अर्थशास्त्र विश्लेषण का एक ढंग है जो सही निर्णय पर पहुँचने में सहायक होता है (Economics is a method of analysis which helps to draw correct conclusions) : उपरोक्त दोनों विचारधाराएँ परस्पर विरोधी हैं। शक्ति-मतादि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के सैद्धान्तिक महत्व को मानते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर पीगू आदि इसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु मार्शल, जे० एम० केम्स आदि ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उपरोक्त दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित कर मध्यम मार्ग अपनाया है। मार्शल ने कहा है “अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद देना है।”<sup>4</sup> इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए मार्ग निर्देशन करे। यह कथन केवल इस सत्य की ओर संकेत करता है कि अर्थशास्त्री का कार्य सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना तथा विभिन्न नीतियों के सम्भावित प्रभावों का उल्लेख करना है। कौन सी नीति अपनाई जाय? यह बतलाना अर्थशास्त्री का कर्तव्य नहीं है। प्रो० वाउन के अनुसार, “आर्थिक सिद्धान्त

<sup>3</sup> “Economics is something more than mere value theory or equilibrium analysis”  
—Fraser

<sup>4</sup> “The dominant aim of Economics is to contribute to a solution of social problems.”  
—Marshall

स्वयं व्यावहारिक समस्याओं के समाधान नहीं प्रस्तुत करता; बल्कि यह एक यंत्र है जो उनकी खोज (व्यावहारिक समस्याओं) में प्रयुक्त होता है।”

वेन्स ने अर्थशास्त्र के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है ‘अर्थशास्त्र ऐसा निश्चित नियम प्रदान नहीं करता जिन्हें तत्काल ही किसी नीति के लिए प्रयोग में लाया जा सके। यह मिट्टात नहीं बरस विश्लेषण का एक ढग है। यह विचार करने की एक विधि तथा मस्तिष्क के लिए एक यंत्र है जिसको घुमाने वाली धी सही निर्णय पर पहुँचने में सहायता मिलती है।’ इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को तुरन्त नीति के रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र समस्याओं की जानकारी के लिए उपयोगी तथ्य प्रस्तुत करता है। उन तथ्यों का प्रयोग करना अथवा न करना व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। इसके अन्तर्गत ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो मानव-कल्याण को प्रभावित करते हैं। अतः मानव समस्याओं को समझने में अर्थशास्त्र मदद देता है। अर्थशास्त्री वर्तमान आर्थिक समस्याओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। उन समस्याओं में वह आमूल परिवर्तन करने के लिए भी सुझाव दे सकता है, यदि उसे इस बात का निश्चय हो जाय कि वे समस्याएँ मुधारों के बावजूद भी फुलतापूर्वक नहीं चलाई जा सकती। फिर भी, उसका प्रमुख कर्तव्य वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में मुधार लाना ही है, सर्वथा एक नई अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना नहीं। अर्थशास्त्री एक नई अर्थ-व्यवस्था के निर्माण करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता। वह उस यांत्रिक (Mechanic) की भाँति है जो पुरानी मोटरों की मरम्मत तथा उनका नवीनीकरण करता है। वह नई प्रकार की मोटरों की रूपरेखा (Design) तैयार नहीं करता। इस प्रकार अर्थशास्त्री एक तथ्य विश्लेषक, व्यावहारिक मार्गदर्शक तथा नीति निर्देशक है।

**क्या अर्थशास्त्र व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर सकता है ?**

**(Can Economics Solve Practical Problems ?)**

इस विषय में अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्री का कर्तव्य आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है। उसे समस्याओं के समाधान नहीं बतलाने चाहिये। उनका कहना है कि अर्थशास्त्री के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके द्वारा निर्देशित समाधान भी सही हो सकता है, परन्तु किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल आर्थिक आधार पर ही निर्णय नहीं दिया जा सकता है। व्यावहारिक समस्याएँ जटिल होती हैं तथा उनके राजनैतिक सामाजिक तथा नैतिक आदि पहलू भी होते हैं। इन सब पर विचार किए बिना, समस्या के समाधान के लिए राय देना उचित नहीं है। साथ ही साथ हम अर्थशास्त्री से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इन सभी विषयों का ज्ञाता है। सीनियर

(Senior) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अर्थशास्त्री के निष्कर्ष कितने ही सही हों, परन्तु उसे राय देने का अधिकार नहीं है। राय देने का अधिकार उस सिद्धांतवादी को प्राप्त नहीं होता जिसने एक दृष्टिकोण विशेष से विचार प्रस्तुत किया हो—

*"The economist's conclusions, whatever be their generality and their truth, do not authorise him in adding a single syllable of advice. That privilege belongs to the writer or to the statesman... not to the theorist who has considered only though among the most important of these causes"*

पीगू ने भी कहा है कि यद्यपि अर्थशास्त्री को सामाजिक उन्नति का लक्ष्य सदा सामने रखना चाहिये, परन्तु उसका कार्य आक्रमण की सीमा के सामने खड़े होने का नहीं है, बल्कि धर्म के साथ उस सीमा के पीछे खड़े होकर कुछ सामग्री तैयार करना है—

*"Though for the economist the goal of social betterment must be held ever in sight, his own special task is not to stand in the forefront of attack but patiently behind the lines to prepare the armament of knowledge"*

—Pigou

राबिन्स ने भी कहा है कि अर्थशास्त्री का कार्य समस्या का विश्लेषण करना मान है, उसे राय देने का अधिकार नहीं है। राबिन्स के विचार इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। परन्तु मार्शल तथा पीगू के विचार भ्रामक हैं। मार्शल तथा पीगू दोनों ने यह विचार व्यक्त किया है कि अर्थशास्त्री का कार्य समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करना नहीं है, परन्तु उन्होंने कुछ ऐसी भी बात कही है, जिसका परोक्ष रूप में वास्तविक अर्थ यह निकलता है कि अर्थशास्त्री का कार्य राय देना भी है या कम से कम समस्या के समाधान में सहयोग देना है। मार्शल ने कहा है

*"The aims of study are to gain knowledge for its own sake and to obtain guidance in the practical conduct of life and especially social life"* इसी प्रकार पीगू ने भी कहा है कि अर्थशास्त्री की स्थिति एक दार्शनिक की स्थिति नहीं है, बल्कि वह एक चिकित्सक की भांति है जो अपने ज्ञान का उपयोग रोग को दूर करने के लिए करता है। इन विचारों से स्पष्ट है कि मार्शल तथा पीगू ने भी किसी न किसी रूप में यह कहा है कि अर्थशास्त्री को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहयोग देना चाहिये।

कल्याणवादी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) इसी बात का प्रतीक है। प्रबन्धात्मक अर्थशास्त्र (Managerial Economics) आर्थिक नियोजन आदि अर्थशास्त्र की व्यावहारिक शाखाएँ हैं। आजकल अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योग देते हैं। अतः अर्थशास्त्री यदि व्यावहारिक समस्याओं

के समाधान के लिए राय देता है तो वह सर्वथा अपनी सीमा के ही अन्दर है। राय देना अर्थशास्त्री की अनाधिकार चेष्टा नहीं है, बल्कि उसका वर्तव्य है।

यह सही है कि अर्थशास्त्र के पास समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व निश्चित सुझाव नहीं हैं, परन्तु अर्थशास्त्र ऐसा विषय अवश्य है जिसका अध्ययन सही निर्णय पर पहुँचने में सहायक होता है। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के ज्ञान का उपयोग निर्णय या सुझाव देने के लिए कर सकता है।

### प्रश्न व सकेत

1 "The function of an economist is to explore and explain and not to advocate or condemn" Discuss (Agra BA, 1967)

“एक अर्थशास्त्री का कार्य खोज तथा व्याख्या करना है, न कि अनुमोदन करना या निन्दा करना।” विवेचना कीजिए

[सकेत—इस कथन का आशय समझाइए। रोबिन्स द्वारा सैद्धांतिक पहलू पर दिये गये जोर को स्पष्ट करते हुए सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थशास्त्री के कार्यों की समीक्षा कीजिए]

2 "Whatever economics is concerned with, it is not concerned with the causes of Material Welfare"—Robbins Discuss

“अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चाहे जिससे हो, पर उसका सम्बन्ध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है।” रोबिन्स। विवेचना कीजिए।

(Bihar, 1963, Indorc, B Com I, 1965)

[सकेत—भौतिक कल्याण सम्बन्धी रोबिन्स के विचार बताइए। रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चयन की समस्या से किम प्रकार है, समझाइये।

3 "अर्थशास्त्र ऐसे निश्चित तथा तैयार निष्कर्ष नहीं देता है जिनका नीति के लिए तत्काल प्रयोग हो सकता हो। यह तो एक रीति है न कि एक सिद्धांत मस्तिष्क का एक यन्त्र तथा सोचने की एक कला है जो इसके अधिकारी को सही निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता करती है।—" केंज। विवेचना कीजिए।

[सकेत—केंज के इस कथन की व्याख्या कीजिए। इससे पश्चात् केंज द्वारा अर्थशास्त्र के कलात्मक पक्ष पर दिये गये जोर का वर्णन कीजिए तथा अर्थशास्त्र के महत्व पर सविस्तार प्रमाण डालिए।]

4 "एक अर्थशास्त्री, जो केवल अर्थशास्त्री है वह केवल एक सुन्दर व असहाय मछली की तरह है।"—फैजर

[सकेत—प्रथम यह बताइए कि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक व व्यावहारिक, दोनों ही प्रकार का अध्ययन है। इसके पश्चात् यह बताइए कि अर्थशास्त्री का कार्य केवल विश्लेषण करना ही नहीं अपितु उसकी व्यावहारिक उपयोगिताएँ बताना भी है।]

# 4

## आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं (I) (Branches of Economic Analysis)

---

*"Macro-economics deals with economic affairs 'in large' It concerns the overall dimensions of economic life It looks at the total size and shape . . . it studies the character of the forest independently of the trees which compose it"*

—Gardner Ackley

आर्थिक-विश्लेषण के लिए विभिन्न विधियों (approaches) या दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए उन विधियों में से किसी एक विधि या कई विधियों द्वारा विश्लेषण करता है। सामान्य रूप से आर्थिक विश्लेषण के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं।

1. व्यष्टि तथा समष्टि आर्थिक विश्लेषण (Micro and Macro Economic Analysis)

2. आंशिक विश्लेषण तथा पूर्ण विश्लेषण (Partial Analysis and Total Analysis) तथा

3. साम्य विश्लेषण (Equilibrium Analysis) अगले पृष्ठों में, इन सभी पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

### 1. व्यष्टि व समष्टि आर्थिक विश्लेषण ✓ (Micro and Macro Economic Analysis)

अन्य विषयों की भांति अर्थशास्त्र भी कई शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं जो किसी आर्थिक समस्या के अध्ययन के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोणों (Approaches) सूक्ष्म विश्लेषण (Micro analysis), तथा व्यापक विश्लेषण (Macro analysis) पर आधारित हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किसी

अर्थव्यवस्था की इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था की किसी समस्या का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय-आय, देश में वचन, देश का कुल उपभोग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र 'विशिष्ट' (Particular) से सम्बन्धित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र 'सामान्य' (General) से सम्बन्धित है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्तिगत इकाइयों से है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रो० चेम्बरलिन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में माडल (Model) की दृष्टि से विभेद किया है। उनका अनुसार, "व्यष्टि माडल पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा अन्तर्बैयक्तिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है जबकि समष्टि माडल कुल सम्बन्धों की व्याख्या करता है।"

"The micro model is built solely on the individual and deals with inter personal relations only, the macro model, on the other hand, deals with aggregative relations" — Chamberlin

व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि ✓

(Historical Background of Micro & Macro Economics)

'व्यष्टि अर्थशास्त्र' तथा 'समष्टि अर्थशास्त्र' दोनों के ही अध्ययन-रीतियों में पुराने अर्थशास्त्री परिचित थे। परन्तु प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि दृष्टिकोण (Micro-approach) या सूक्ष्म विश्लेषण (Micro analysis) पर अधिक ध्यान दिया था। ऐतिहासिक दृष्टि में व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics) (Micro Economics) की अपेक्षा पुराना है। एडम स्मिथ के पूर्व, आर्थिक विचारधारा के लिए वाणिज्यवादियों (Mercantilists) तथा फिजियोक्रैट्स ने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वह समष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro) के जन्मदाता एडम स्मिथ थे। इस प्रकार समष्टि दृष्टिकोण की अपेक्षा पुराना है। वाणिज्यवादी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की समस्या में रूचि रखते थे। उनका मुख्य विषय 'राष्ट्रीय समृद्धि के लिये उचित सरकारी नीति थी। वे राष्ट्रीय समृद्धि के लिये सरकारी हस्तक्षेप में विश्वास रखते थे जिससे देश के ममस्त साधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। फिजियोक्रैट्स भी समष्टि दृष्टिकोण के समर्थक थे। प्रसिद्ध फिजियोक्रैट (Quesney) को अर्थ-व्यवस्था की तालिका (Tableau Economique) इस बात का प्रमाण है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ तथा उसके समर्थक 'स्वहित की भावना' (self interest) को सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का आधार मानते थे। उन्होंने वस्तु विशेष किस प्रकार पैदा की जाती है उसकी कीमत

का निर्धारण किम प्रकार किया जाता है, आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरण किस प्रकार किया जाता है, आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से अधिकांश ने सूक्ष्म विश्लेषण तथा व्यापक विश्लेषण दोनों का ही प्रयोग किया। एडम स्मिथ तथा उसके समर्थकों ने भी यह माना कि समस्त आर्थिक संगठन का संचालन व्यक्तियों की स्वहित भावना के कारण सुचारु रूप से होता है। मार्शल के समय में व्यष्टि या सूक्ष्म विश्लेषण का काफी विकास हुआ। मार्शल के समकालीन अर्थशास्त्रियों में से अधिकांश का ध्यान विश्लेषण की इस विधि पर ही केन्द्रित रहा।

माल्थस तथा सिसमंडो और मार्क्स ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपर्युक्त मत के प्रति असहमति प्रकट की। वे स्वहित पर आधारित स्व-सन्तुलनीय (Self adjusting) अर्थ-व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। एडम स्मिथ ने भी कुछ ऐसे विचार प्रकट किए—समाज की हित भावना, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार आदि—जो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक विश्लेषण के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु माल्थस प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक विश्लेषण सम्बन्धी विचार प्रकट किए। उन्होंने जनसंख्या की समस्या पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इसके पश्चात् मार्क्स ने सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं का विवेचन किया। नवीन प्रातिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Neo-classical economists) का ध्यान मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म विश्लेषण पर ही केन्द्रित रहा, यद्यपि मुद्रा, सामान्य मूल्य आदि के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रकट किए गये विचारों को समष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

सन् 1929-32 की विश्व आर्थिक मंदी (Great Depression) ने अर्थशास्त्रियों का ध्यान, सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम विधिवत वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का श्रेय लार्ड केन्स (E. M. Keynes) को प्राप्त है। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ, 'The General Theory of Employment, Interest and Money' जो सन् 1936 में प्रकाशित हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है। यद्यपि इसके पूर्व वात्सरस, शुम्पीटर, फिशर आदि ने व्यापक विश्लेषण के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था। पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, राजस्व, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास आदि विषय समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अङ्ग बन गए। आजकल व्यापक या समष्टि व विश्लेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है तथा सूक्ष्म या व्यष्टि विश्लेषण एक प्रकार से पृष्ठभूमि (Background) में चला गया है।



### व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के निश्चित समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अलग-अलग अध्ययन करते हैं। यह विशेष व्यक्तियों, फर्मों, उद्योगों, व्यक्तिगत मूल्यों, मजदूरी, आय आदि का अध्ययन है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, प्रेताओं तथा विक्रेताओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अतः व्यष्टिगत अर्थशास्त्र विशेष (Particular) का अध्ययन है। केना कब किस प्रकार करता है? एक फर्म उत्पादित वस्तुओं की कीमत किम प्रकार निश्चित करती है? विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में अन्तर क्यों है? आदि समस्याओं का अध्ययन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। बौलडिंग के अनुसार “व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक प्रदूतों (इकाइयों) तथा उनके पारस्परिक प्रभाव और विशिष्ट आर्थिक मानकों तथा उनके निर्धारण का अध्ययन है।”

“Micro-economics is the study of particular economic organisms and their interaction and particular economic quantities and their determination.”  
—K. E. Boulding

प्रो० जे० के० मेहता ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को वैयक्तिक इकाइयों से सम्बन्धित होने के कारण क्रुसो की अर्थ-व्यवस्था की सहायी है (A micro economic study is essentially the study of Cruso economy)। गार्डनर एक्ले (Gardner Ackley) के अनुसार “व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों और फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्द्धी उपयोग के लिए साधनों के वितरण का अध्ययन करता है। यह आय वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। यह विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित है।”<sup>1</sup> इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के निश्चित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है।<sup>2</sup> व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग (aggregates) का भी अध्ययन किया जाता है, परन्तु ये योग सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं होते हैं (Micro economics also uses aggregates, but not in a context

<sup>1</sup> “Micro-economics, on the other hand, deals with division of the total output among industries, products and firms, and the allocation of resources among competing use. It considers problems of income distribution. Its interest is in relating prices of particular goods and services.” Gardner Ackley, *Macro economic Theory*, p 4

<sup>2</sup> “Micro-economics is the study of economic actions of individuals and well defined groups of individuals.” *Henderson & Quandt Micro-economic Theory*, p. 2

which relates them to an economy wide total'-Ackley)। उपभोग सम्बन्धी नियम उपयोगिता हास नियम, उपभोक्ता की वृत्त, सम-सीमात उपयोगिता नियम आदि, उपादन में फर्मों, उद्योगों का उत्पादन विनिमय में इकाइयों द्वारा मूल्य निर्धारण, वितरण में विभिन्न साधनों में उत्पादन का वितरण आदि समस्याएँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमात विश्लेषण (Marginal analysis) का महत्वपूर्ण स्थान है।

### व्यष्टि विश्लेषण के प्रयोग (Uses of Micro-Analysis)

1. अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था की इकाइयों या अङ्गों का अध्ययन करता है। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं के अध्ययन में, अङ्गों या वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन सहायक सिद्ध होता है।

2. व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक आय, व्यय, वृत्त, आदि पर प्रकाश डालता है जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के विश्लेषण में भी सहायक होता है।

3. आजकल प्रबन्धात्मक अर्थशास्त्र (Managerial Economics) का महत्त्व बढ़ रहा है। प्रबन्धात्मक अर्थशास्त्र, आर्थिक विधियों (Economic Tools) के प्रयोग द्वारा किस प्रकार निर्णय लिए जाएँ? इस बात का ज्ञान कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों, फर्मों आदि का अध्ययन करता है। इस प्रकार इसका अध्ययन आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होता है।

4. व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारण तथा उत्पादन साधनों के अंश निर्धारण की विधि बतलाता है।

5. वैयक्तिक इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन कर, उनके लिए उचित निर्देशन में सहायक होता है।

### व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitations of Micro Economics) :

1. सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का ज्ञान नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल वैयक्तिक इकाइयों का ही अध्ययन करता है अतः इसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने नहीं आ पाता है।

2. वैयक्तिक स्थिति सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की प्रतीक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि वैयक्तिक निर्णयों का योग राष्ट्रीय निर्णय के अनुकूल हो। कभी-कभी व्यक्तिगत हित तथा राष्ट्रीय हित भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में उपभोक्ता उद्योगों में विनियोजन करना व्यक्तिगत साहसियों के लिए लाभदायक है, परन्तु यदि सभी उद्योगपति केवल उपभोक्ता उद्योगों में ही विनियोजन करने लगे तो देश के औद्योगीकरण में बाधा पड़ेगी।

3. कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिये अनुपयुक्त : व्यष्टि अर्थशास्त्र धीरे धीरे वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो रहा है। प्राजकल अधिकांश निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। रोजगार, प्रशुलक नीति, आय व धन का वितरण, आयात, निर्यात, राजस्व, औद्योगीकरण, आर्थिक नियोजन आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनसे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र सर्वथा उपयुक्त नहीं है।

**समष्टि अर्थशास्त्र (Macro-Economics) :**

समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समूहों का अध्ययन किया जाता है। समूहों (Aggregates) का अध्ययन करने के कारण ही इसे (Aggregative Economics) भी कहते हैं। इसमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल उपभोग, कुल आय, वचत तथा विनियोग आदि। किसी अर्थ-व्यवस्था के इन सभी तत्वों तथा उनकी समस्याओं एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धों और प्रभावों आदि का अध्ययन इसकी विषय-सामग्री है।

बोल्डिंग के अनुसार “समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग (या समूह) का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है।”

“Macro-Economics deals not with individual quantities as such but with aggregates of these quantities, not with individual incomes but with national income, not with individual prices, but with price-level, not with individual output but with national output.”

—K E Boulding, *Economic Analysis*, p 3

बोल्डिंग ने अपनी दूसरी पुस्तक *Reconstruction of Economic Theory* में समष्टि अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है—“समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के योगों व औसतों की प्रकृति, सम्बन्धों तथा व्यवहारों का अध्ययन है।” (Macro economics is the study of nature, relationship and behaviour of aggregates and averages of economic quantities)

प्रो० एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के वृहद् रूप का अध्ययन है। इसका सम्बन्ध आर्थिक जीवन के ‘संपूर्ण’ पहलुओं से है। यह कहा

जा सकता है कि यह जंगल की विशेषताओं का अध्ययन करता है, जंगल के अलग-अलग वृक्षों से इसका सम्बन्ध नहीं है।<sup>3</sup>

यह आवश्यक नहीं है कि समष्टि अर्थशास्त्र में केवल सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित योगों का ही अध्ययन किया जाए। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे भागों का भी अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु ऐसे छोटे योगों का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों का उप-भाग होना चाहिए।

“Macro economics uses aggregates smaller than for the whole economy, but only in a context which makes them sub divisions of an economy-wide total”  
—Ackley

समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक है। इसके अन्तर्गत कुल उत्पादन, अर्थव्यवस्था के साधनों की रोजगार स्थिति, सामान्य मूल्य-स्तर, मौद्रिक तथा बैंकिंग समस्याएँ, व्यापार-चक्र, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार व राजस्व आदि का अध्ययन किया जाता है।

#### 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना

Micro तथा Macro ‘ग्रोक’ भाषा के शब्द हैं। प्रथम का अर्थ ‘छोटा’ तथा द्वितीय का अर्थ ‘बड़ा’ है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग ओसलो विश्व-विद्यालय के प्रो० रैग्नर फ्रिश (Prof Ragnar Frisch) ने किया तथा ये शब्द अब अत्यधिक प्रचलित हो गए हैं। वस्तुतः व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद नया नहीं है। व्यष्टि तथा समष्टि के अन्तर्गत के प्रचलित होने के पूर्व कीमत तथा आय विश्लेषण रीतियाँ प्रचलित थीं। कीमत-विश्लेषण (Price Analysis) तथा आय विश्लेषण (Income Analysis) रीतियाँ क्रमशः व्यष्टि तथा समष्टि रीतियाँ हो गयीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का महत्व है। इसके अन्तर्गत कीमत-निर्धारण तथा साधनों के विशिष्ट उपयोग का अध्ययन किया जाता है, दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्यतया राष्ट्रीय आय तथा कुल साधनों के रोजगार का अध्ययन किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आय का अध्ययन तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन नहीं किया जाता। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों में व्यक्तियों के आय-निर्धारण का अध्ययन सामान्य कीमत-निर्धारण के

“Macro economics deals with economic affairs ‘in large’. It concerns the overall dimensions of economic life. It looks at the total size and shape and functioning of the ‘elephant’ of economic experience, rather than the working or articulation or dimensions of the individual parts. To alter the metaphor, it studies the character of the forest independently of the trees which compose it”

—Gardner Ackley, op cit p, 4

अन्तर्गत आ जाता है, जैसे उत्पादन साधनों के बदले व्यक्ति आय प्राप्त करते हैं तथा उत्पादन साधनों की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतों की भांति ही निर्धारित की जाती है।

### 5 व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की अन्तर्निर्भरता (Inter-dependence of Micro & Macro Economics)

‘व्यष्टि’ तथा ‘समष्टि’ एक ही विषय की दो शाखाएँ हैं। वे एक-दूसरे की सहयोगी तथा पूरक हैं। उन्हें एक-दूसरे से पूछनया भिन्न तथा स्वतन्त्र नहीं समझना चाहिए। आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं

#### 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता :

(क) मान लीजिए एक फर्म का अपने अधिकारी की मजदूरी दर का निर्णय करना है। यह एक व्यष्टिगत समस्या है, परन्तु मजदूरी दर का निर्धारण करते समय उस फर्म को अन्य फर्मों की मजदूरी दरों तथा राष्ट्रीय मजदूरी नीति को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भौद्धान्तिक दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है।

(ख) यदि फर्म अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करना चाहती है तो उसे अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी ध्यान देना होगा।

(ग) एक फर्म को अपनी उत्पादन मात्रा निश्चित करते समय, समाज की मांग, आय तथा रोजगार आदि पर ध्यान देना पड़ेगा जो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं।

#### 2 समष्टि अर्थशास्त्र भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर

(क) व्यक्तियों के योग से समाज बनता है। इसी प्रकार फर्मों के योग से, ‘उद्योग’ तथा विभिन्न उद्योगों के योग से अर्थ व्यवस्था बनती है। अतः सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके भूतलों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे ‘राष्ट्रीय आय’ समष्टिगत समस्या है, परन्तु राष्ट्रीय आय व्यक्तियों की आय का ही योग है।

(ख) सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की गतिविधियों का ज्ञान, अर्थ व्यवस्था के विभिन्न अवस्था के ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। यदि हम सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिए योजना बना रहे हैं तो व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों आदि की योजनाओं की भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार ‘समष्टि-अर्थशास्त्रीय विश्लेषण’ के लिए ‘व्यष्टि-अर्थशास्त्रीय विश्लेषण’ आवश्यक है।

इस प्रकार अर्थशास्त्र की ये दोनों शाखाएँ एक-दूसरे की सहयोगी हैं तथा वे परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों का ज्ञान आवश्यक है।

प्रो० सैमुयलसन (Prof Samuelson) के शब्दों में,

‘There is really no opposition between micro and macro economics Both are absolutely vital And you are only half educated, if you understand the one while being ignorant of the other’

### समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के कारण

#### (Contributory Factors of the Development of Macro-Economics)

आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्त्व बढ़ रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र ने आर्थिक सिद्धान्तों के ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है।<sup>4</sup> केन्स की पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात् समष्टि अर्थशास्त्र का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इस निरंतर विकास के निम्नलिखित कारण हैं

1. जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में लिखा जा चुका है, किजिगा नेटम ने ‘भुगतान के चक्राकार प्रवाह’ (Circular flow of payment) का जिक्र किया। इस सिद्धान्त ने समष्टि अर्थशास्त्र का गिना-गिनाम दिया। आगे चलकर वाल-स, शुम्पीटर, केन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया।

2. माशन तथा पीगू ने राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend) के सम्बन्ध में समष्टि मूलक विचार प्रस्तुत किया। पीगू के ग्रन्थ Economics of Welfare ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में बड़ी सहायता दी।

3. मौद्रिक अर्थशास्त्र (Monetary Economics) का विकास समष्टि के आधार पर ही हुआ। मुद्रा का परिमाण, सिद्धान्त आदि मौद्रिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन समष्टिगत पृष्ठभूमि में ही किया गया। केन्स ने मौद्रिक सिद्धान्त को सामान्य आर्थिक सिद्धान्त का एक अङ्ग माना तथा सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की मांग, आय, उपभोग, बचत, विनियोग आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया।

4. व्यापार चक्रों (Business Cycles) का विश्लेषण भी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में किया गया। वर्ष 1929-32 का विश्व आर्थिक मन्दी के कारण, अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस तरह अर्थिक अवस्था हुआ कि व्यापार चक्रों का विश्लेषण सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की एक इकाई मानकर किया गया।

5. धीरे धीरे आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता गया। अर्थ व्यवस्था के नियमन, नियंत्रण तथा संचालन के लिए विभिन्न दशों में सरकार ने उचित अधिक नीतियाँ अपनायीं। वृत्ति नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक

<sup>4</sup> Macro Economics has brought ‘a considerable upheaval in the structure of economic theory  
—R G D Allen

नीति तथा वित्तीय-नीति आदि का निर्माण सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के ही लिए किया जाता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र से सम्बन्धित है।

6. 'आर्थिक नियोजन' में भी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। राजकल आर्थिक नियोजन का महत्व बढ़ता जा रहा है। धीरे-धीरे सभी देश, किसी न किसी रूप में आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं। आर्थिक नियोजन में सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं जो समष्टिगत विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। आर्थिक विकास (Economic growth) सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण भी समष्टिगत होता है।

इनके अनिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र के अधिकाधिक प्रयोग का कारण, आर्थिक समस्याओं की जटिलता भी है। इन जटिल आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण, समष्टिगत दृष्टिकोण से करने में सुविधा रहती है। अर्थ-व्यवस्था के समय-एब गतिशील रूप को समझने के लिये समष्टिगत विश्लेषण अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

### समष्टि अर्थशास्त्र के भेद (Types of Macro-Economics)

समष्टि अर्थशास्त्र के सामान्यतया तीन भेद किये जाते हैं

1. समष्टि स्थैतिक (Macro Statics) इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन सतुलन अवस्था स्थायी स्थिति में किया जाता है। सतुलन की स्थिति में आय, उपभोग, विनियोग, आदि का अध्ययन करता है। अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों के कारण विभिन्न मौलिक (aggregates) क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा नए नए सतुलन स्थापित करते रहते हैं। इन विभिन्न सतुलन स्थितियों का अध्ययन, 'समष्टि-स्थिर विश्लेषण' कहलाता है।

2. तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक (Comparative Macro Statics) - अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन के कारण नए सतुलन बिन्दु स्थापित होते रहते हैं। तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक, इन विभिन्न सतुलन बिन्दुओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है।

3. समष्टि प्रवर्णिक (Macro Dynamics) : यह गतिशील अर्थ-व्यवस्था का निरन्तर अध्ययन है। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न घटक (Variables) जैसे उपभोग, विनियोग आदि परिवर्तित होते रहते हैं। यह अर्थशास्त्र इन निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है तथा उनके समायोजनों की भी व्याख्या करता है। प्रो० कुरिहारा (Prof. Kurihara) ने समष्टि प्रवर्णिक को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है

"Macro Dynamics studies changing relations and indicates step by step, what is cause and what is effect. It describes the changing universe as it is related to previous or subsequent adjustments.....the time paths of macro dynamic method enables one

to see a motion picture of the functioning of economy as a progressive whole."<sup>5</sup>

### समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग तथा गुण (Uses & Merits of Macro-Economics)

1. अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायता . आजकल अर्थ-व्यवस्था में जटिलताएँ (Complexities) बढ़ती जा रही हैं। समष्टि-अर्थशास्त्र द्वारा इन जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था के परिवर्तनों, अन्तर्सम्बन्धों तथा आर्थिक संगठनों पर प्रकाश डाला जाता है।

2. विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक . समष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण करता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार, जनसंख्या, पूँजी निर्माण तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का समाधान, समष्टि विश्लेषण द्वारा सम्भव हो जाता है।

3 उचित आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक : लोक कल्याणकारी राज्य, आर्थिक-निर्माण तथा आर्थिक समस्याओं को बढ़ती हुई जटिलता के कारण सरकार का महत्व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। सरकार अर्थ-व्यवस्था के संचालन के लिए उत्पादन, व्यापार, राजस्व, मूल्य आदि के सम्बन्ध में आवश्यक नीति बनाती है। समष्टि-आर्थिक-विश्लेषण, पूरी अर्थ-व्यवस्था का चित्र हमारे समक्ष रखता है, जिससे नीति-निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। प्रो० बोहिडन के शब्दों में, "आर्थिक नीति की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति से न होकर सभी व्यक्तियों के समूहों से होता है।"

4. व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ . कुछ आर्थिक समस्याएँ ऐसी हैं जिनका अध्ययन समग्र रूप में ही किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजस्व, सामान्य-मूल्य स्तर आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण तथा उनको परस्पर सी मेल-रूप में ही की जा सकती है। अतः व्यष्टि-अर्थशास्त्र की सीमाओं के कारण भी, समष्टि-अर्थशास्त्र उपयोगी सिद्ध होता है।

■ समष्टि-मूलक विरोधाभासों के कारण : कुछ आर्थिक मूल्य व्यक्तियों के सदस्य में तो सही होते हैं, परन्तु समाज के सदस्य में सही नहीं होते हैं, जैसे बचत, व्यक्तिगत दृष्टिकोण में उचित है, परन्तु यदि सभी लोग अधिक में अधिक बचत करने लगे तो देश में प्रभाव-पूर्ण मांग (effective demand) कम हो जाएगी जो

<sup>5</sup> Kurihara, *Introduction to Keynesian Dynamics*, p. 2.



विभिन्न आर्थिक संकटों का कारण बन सकती है। इन समष्टिगत आर्थिक विरोधाभासों (Macro economic paradoxes) के कारण, आर्थिक समस्या का समग्र रूप में अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रो० बोल्डविन ने इन विरोधाभासों को समष्टिगत विश्लेषण का कारण माना है।

### समष्टि-आर्थिक विश्लेषण की सीमाएँ (Limitations of Macro-Analysis)

आजकल समष्टि-आर्थिक विश्लेषण का अतिरिक्त प्रयोग होने लगा है तथा इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, परन्तु इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

1 व्यक्ति तथा छोटे समूहों के योग के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक: समष्टि प्रवृत्तियों का सम्बन्ध योगों (aggregates) से है। कमी-बसी व्यक्ति तथा समूहों से सम्बन्धित परिणामों के योगों को समष्टिगत-विश्लेषण का आधार मान लिया जाता है, क्योंकि समाज या अर्थ-व्यवस्था व्यक्तियों तथा समूहों का ही योग है। परन्तु ऐसे योगों पर आधारित निष्कर्ष भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तियों तथा समूहों की प्रकृति, अर्थ-व्यवस्था में भिन्न हो सकती है। बार्ड कार्य प्रवृत्ति या उद्देश्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के छोटे समूहों के लिए ठीक हो सकता है, परन्तु यदि हम उस कार्य या प्रवृत्ति को सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए ठीक मान लें तो ऐसा करना कठिनाई पैदा कर सकता है, जैसे बचत करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ठीक है परन्तु यदि सभी लोग बचत करने लगे तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है।<sup>6</sup> अधिक बचत के कारण प्रभाव पूर्ण मांग कम हो सकती है जिससे बेरोजगारी में, वृद्धि होगी तथा अर्थ-व्यवस्था मंदी के कुचक्र में फँस सकती है। अतः व्यक्तियों या समूहों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

अर्थशास्त्री अपनी व्यक्तिगत धारणा या निष्कर्ष को यदि समाज का निष्कर्ष मान ले अथवा अपने व्यक्तिगत अनुभव का समाज का अनुभव मानकर पूरे समाज के सम्बन्ध में वही निष्कर्ष सही मान ले तो ऐसा निष्कर्ष निराधार सिद्ध हो सकता है। प्रो० बोल्डविन ने स्पष्ट रूप से कहा है "समष्टि अर्थशास्त्र में हमको व्यक्तिगत अनुभव से कोई निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिये। अपने व्यक्तिगत अनुभव से निष्कर्ष निकालने की हममें सामान्य आदत होती है तथा हम इस आदत का अनुसरण करते हैं, परन्तु सामाजिक चिन्तन में त्रुटियों का यह एक बड़ा स्रोत है।

<sup>6</sup> While individual saving is a virtue, national saving may prove a calamity  
—J. M. Keynes

"In Micro Economics therefore, we must be on our guard against generalising from our individual experience. Generalising from our own experience is such a common habit that we constantly fall into it, it is however, one of the greatest sources of error in social thinking"

— K. E. Boulding

यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के सम्बन्ध में निष्कर्ष समस्त समाज के सम्बन्ध में भी ठीक हो।

2 समूह या समाज में पाए जाने वाले भेदों की उपेक्षा (The differences within aggregates or groups might be ignored) : समष्टि विश्लेषण में समूहों के योग का आधार पर अध्ययन करते हैं, परन्तु सभी समूहों में पाए जाने वाले अन्तर की उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रकार जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी देश में एक वर्ष विशेष में विकास दर (rate of growth) 5% है। दूसरे वर्ष भी विकास दर 5% है, परन्तु दूसरे वर्ष प्रकृति अनुकूल होने के कारण कृषि उत्पादन में पहले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दोनों वर्षों में विकास दर पांच प्रतिशत है या यह बनताती है कि अर्थ व्यवस्था का विकास ठीक ठग से हो रहा है। परन्तु वास्तव में यह निष्कर्ष ठीक नहीं है। कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होते हुए भी विकास दर पहले के ही समान है, इसका यह अर्थ है कि उद्योग आदि के उत्पादन में काफी गमी हुई है या यह बनताता है कि अर्थ-व्यवस्था का विकास ठीक नहीं हुआ है। यदि हम अर्थ व्यवस्था का समूह क्षेत्र के अनुसार (Sector-wise) अध्ययन करें तो यह दाप प्रकट हो जायगा। बाल्डिंग ने यह सुझाव दिया है कि हम समूह की अलग-अलग मंशों के स्वभाव पर भी ध्यान देना चाहिये। उनकी प्रशिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिये, तब निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये। समूह की अपेक्षा समूह की रचना महत्वपूर्ण है।

3. समूह की माप सम्बन्धी कठिनाई : समष्टि आर्थिक विश्लेषण में विभिन्न समूहों को नापते समय भी कठिनाई होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की माप के लिये मापक की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतया मुद्रा का प्रयोग मापक के लिए किया जाता है, परन्तु मुद्रा की भापक के रूप में अपनी सीमायें हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समष्टि विश्लेषण में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा इस विधि द्वारा निकाल गये निष्कर्ष भी सदैव सही नहीं होते हैं। दापपूर्ण निष्कर्ष वैयक्तिक इकाइयों के योग को आधार मानने कारण भी हो सकते हैं तथा समय के योग के अध्ययन के कारण भी। अतः सही निष्कर्ष के लिये व्यष्टि तथा समष्टि दोनों प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है।

## 2. आंशिक विश्लेषण एवं पूर्ण विश्लेषण (Partial Analysis and Total Analysis)

आर्थिक सिद्धान्तों या व्यवस्था का अध्ययन करने के दो अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी हैं जिन्हें आंशिक विश्लेषण (Partial Analysis) तथा पूर्ण विश्लेषण (Total Analysis) भी कहते हैं। यद्यपि आर्थिक व्यवस्था विश्लेषण की ये विधियाँ आर्थिक विश्लेषण की दो मुख्य शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics) तथा समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics) के समान ही हैं, फिर भी कुछ निश्चित पहलुओं में ये भूक्षम तथा व्यापक विश्लेषण की विधियों से भिन्न हैं।

### (1) आंशिक विश्लेषण :

आंशिक विश्लेषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है 'आंशिक विश्लेषण सापेक्षिक रूप से अन्य-व्यवस्था के छोटे क्षेत्रों में आर्थिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए लीजी गयी एक कुशल विधि है। इसमें गहन अध्ययन एक जाब के लिए परिवर्तनशील घटकों (Variables) को एक सीमित संख्या को ध्यान में रखा जाता है।'

ध्यातव्य : आर्थिक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय हम उन बाहरी घटकों पर ध्यान नहीं देते जो अर्थ व्यवस्था के आंशिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसका अन्तर्गत अन्य घटकों को स्थिर मानकर किसी भी आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी भी वस्तु विशेष का, मूल्य सिद्धान्त के अन्तर्गत, मूल्य निर्धारित करते समय अन्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर या यथावत् मान लिया जाता है। हमसे किसी वस्तु-विशेष के मूल्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना सरल हो जाता है। यदि अन्य घटकों, अर्थात् अन्य वस्तुओं के मूल्यों को, यथावत् नहीं माना जाये, तो समस्या विशेष का अध्ययन अधिक जटिल हो जायेगा। इस तथ्य को हम इस उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि हम अन्य वस्तुओं के मूल्यों तथा उपभोक्ताओं की आय को परिवर्तनशील मानकर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करना चाहे तो केवल मांग व पूर्ति के विश्लेषण के आधार पर मूल्य निश्चित करना सम्भव नहीं हो सकेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अन्य वस्तुओं के मूल्यों तथा उपभोक्ताओं की आय का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि इन सभी तथ्यों एवं घटकों का भी विश्लेषण किया जाए तो अनेक जटिलताओं के कारण आंशिक विश्लेषण करना कठिन हो जायेगा। इस प्रकार की जटिलताओं को दूर करने तथा किसी समस्या विशेष के विश्लेषण को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से आंशिक विश्लेषण का तरीका प्रयोग में लाया जाता है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र विशेष के आंशिक

विश्लेषण के परिणाम उसी स्थिति में ठीक निकलेंगे जबकि उसको प्रभावित करने वाले अन्य बाहरी घटकों को उचित मूल्य (Values) प्रदान कर दिये गये हों। यदि बाहरी घटकों के मूल्य आंशिक विश्लेषण के अन्तर्गत माने गये मूल्यों से भिन्न होंगे तो आंशिक विश्लेषण के निष्कर्ष सही नहीं होंगे।

प्रोफेसर कुम्पौटर के अनुसार आंशिक विश्लेषण सम्बन्धी प्रमाणित विधि कूरनो (Cournot) या मार्शल (Marshall) का 'बाजार माग वक्र' (Market Demand curve) है जो दिए हुए मूल्य पर केनाग्रो द्वारा किसी वस्तु विशेष की निश्चित मात्रा खरीदने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

अर्थशास्त्र के लिए आंशिक विश्लेषण का विचार नया नहीं है। इस प्रकार के विश्लेषण के तरीके की शुरुआत वस्तु विशेष के बाजार में प्रचलित मूल्य तथा उसकी स्थानीय उपलब्ध मात्रा के पारस्परिक सम्बन्धों में हुयी। बाद में मार्शल, कूरनो आदि अर्थशास्त्रियों ने आंशिक विश्लेषण विधि को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। वास्तव में मार्शल को आंशिक विश्लेषण के तरीके का निर्माण कहा जा सकता है। मार्शल ने मूल्य निर्धारण सिद्धान्त के अन्तर्गत एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय अन्य वस्तुओं के मूल्यों तथा उपभोक्ताओं की आय आदि घटकों को स्थिर एवं यथावत् माना था। आंशिक विश्लेषण के तरीके को सूक्ष्म एवं व्यापक विश्लेषण की विधियों के बीच का एक माप या तरीका कहा जा सकता है।

पूर्ण आंशिक विश्लेषण के तरीके को अपनाने पर आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना सरल हो जाता है। सभी परिवर्तनशील घटकों को ध्यान में रखते हुए किसी समस्या विशेष का अध्ययन व जांच करने में जो कठिनाई होती है, उसे आंशिक विश्लेषण विधि के अन्तर्गत कुछ निश्चित घटकों को स्थिर मानकर अधिक सरल बनाया जा सकता है। प्राप्त निष्कर्षों को अन्य घटकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार यह विधि किसी आर्थिक तथ्य का विश्लेषण करने की एक वैज्ञानिक विधि है।

टिप्पणी : इस विधि को अपूर्ण एवं अवास्तविक कहा जा सकता है। इसे अपूर्ण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत किसी समस्या विशेष के सभी घटकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह अवास्तविक इस अर्थ में है कि यह दृष्टिकोण विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियों अथवा अर्थ-व्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता पर ध्यान नहीं देता। कुछ निश्चित घटकों को स्थिर मानकर या अर्थ-व्यवस्था के किसी क्षेत्र (Sector) विशेष को अन्य क्षेत्रों (Sectors) से स्वतन्त्र मानकर अध्ययन व जांच करना वास्तविक विश्लेषण नहीं है। इन कमियों तथा दोषों के बावजूद भी इस प्रकार की विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता रहा है, यद्यपि बालरस, परेटो आदि अर्थशास्त्रियों ने इस विधि की कटु आलोचना की है।

## (2) पूर्ण या सामान्य विश्लेषण (Total Analysis) -

आर्थिक प्रवृत्तियों के अध्ययन व जाच में पूर्ण या सामान्य विश्लेषण विधि का प्रयोग नया है। आंशिक विश्लेषण के विपरीत सामान्य विश्लेषण विधि किसी आर्थिक प्रवृत्ति के अध्ययन व जाच की वह विधि है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों की अन्तर्निर्भरता के आधार पर उस आर्थिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है। अन्य शब्दों में, सामान्य विश्लेषण विधि के अन्तर्गत सभी परिवर्तनशील घटकों (Variables) के प्रभाव को एवं साथ ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह ठीक है कि इस विधि के द्वारा अध्ययन व जाच करने पर सम्पूर्ण विश्लेषण विधि अधिक जटिल हो जाती है, लेकिन वास्तविक आर्थिक निष्कर्ष निकालने के लिए इस दृष्टिकोण व तरीके को अपनाना आवश्यक है। सामान्यतया यह कहा जाता है कि सभी घटकों को एक साथ ध्यान में रखते हुए किसी समस्या का विवेचन करना इतना ही नहीं शक्ति सम्भव है। परन्तु आधुनिक काल में अर्थशास्त्र में गणितीय विधियों के प्रयोग ने विश्लेषण की इस पद्धति को अपनाता सरल बना दिया है।

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम बालरस (1834-1910) द्वारा किया गया था। उनके इस कार्य में उनके समकालीन परेटो (1843-1923) ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। वर्तमान काल में बालरस तथा परेटो की इस महत्वपूर्ण विधि को हिक्स, सैम्पुएलसन, ओहलिन आदि अर्थशास्त्रियों ने बहुत ही प्राय बढ़ाया है।

यद्यपि बालरस की इस विश्लेषण विधि को 'पूर्ण एवं वास्तविक' कहा जाता है, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है। अमेरिकन अर्थशास्त्री स्टिगलर (Stigler) के अनुसार कोई आर्थिक विश्लेषण इस अर्थ में सामान्य नहीं हो सकता कि उसमें सभी सम्बन्धित आर्थिक तथ्यों का समावेश किया गया है। पूरा या सामान्य विश्लेषण में व्यापार चक्र (Business Cycles), प्राविधिक सुधार (Technological improvements) आदि का समावेश नहीं किया गया है। इस आधार पर इसे पूर्ण विश्लेषण विधि न कहकर 'अधिक समाविष्ट' (More inclusive) विधि कहना अधिक उपयुक्त होगा।

## 3. साम्य विश्लेषण (Equilibrium Analysis)

### 1. परिभाषा :

साम्य का अर्थ विधान (Rest) की स्थिति है। 'Equilibrium' शब्द, दो लैटिन शब्दों से बना है *aequus* + *libra* पहले शब्द का अर्थ है समान तथा दूसरे का अर्थ है सतुलन अर्थात् समान सतुलन। 'साम्य' शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में इतना अधिक किया जाता है कि कुछ लोग अर्थशास्त्र को साम्य-विश्लेषण (Equilibrium

Analysis ) के नाम से पुकारते हैं। सामान्य रूप से साम्य का अर्थ विश्राम की स्थिति या 'संतुलन' है। उदाहरण के लिए यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो उसे हम साम्य की अवस्था में कहेंगे, क्योंकि पुस्तक अपनी स्थिति को बदल नहीं सकती है। इसके विपरीत यदि पुस्तक ऊपर से नीचे हवा में गिर रही है तो यह गिरती हुई पुस्तक साम्य की अवस्था में नहीं है, क्योंकि पुस्तक विश्राम की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार 'कई भी वस्तु साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि उस पर क्रियाशील शक्तियाँ इस प्रकार की हैं कि उन वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है।' ( 'Any thing is in equilibrium when the forces acting on it are such that it has no tendency to change its conditions' Boulding ) एक दूसरे उदाहरण द्वारा 'साम्य' को और भी स्पष्ट किया जा सकता है। यदि एक रस्सी में पत्थर का टुकड़ा बांधकर, दीवार में लगी हुई एक खूटी से लटका कर टांग दिया जाए तो शुरू में कुछ समय तक वह पत्थर इधर उधर रस्सी के सहारे हिलता रहेगा परन्तु कुछ समय पश्चात् पत्थर रस्सी के सहारे बिल्कुल विश्राम की स्थिति में आ जाएगा तथा उसका हिलना डुलना बन्द हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहेंगे कि रस्सी से बंधा पत्थर संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उस इधर-उधर हिलाने वाली विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे के ठीक बराबर हैं, जिससे कि पत्थर एक ही अवस्था में है।

उपयुक्त उदाहरण (रस्सी से बंधा पत्थर) साम्य के उस अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है, जिस अर्थ में उसका प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। गणित तथा भौतिक शास्त्र में साम्य का अर्थ 'विश्राम' होता है, विश्राम की स्थिति वह स्थिति है जो गतिहीन तथा निष्क्रिय है (motionless and inactive), परन्तु अर्थशास्त्र में साम्य का अर्थ 'गतिहीन तथा निष्क्रिय विश्राम' नहीं है, बल्कि सक्रिय विश्राम ( active rest ) है। यदि किसी अर्थ-व्यवस्था में सभी आर्थिक शक्तियाँ निष्क्रिय या क्रियाहीन हो जाएं तो यह स्थिति अर्थ व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। अर्थशास्त्र में साम्य का अर्थ निष्क्रियता (inactive) नहीं, बल्कि ऐसी सक्रियता है, जिसमें फलस्वरूप विभिन्न मूल्यों (Variables) की दरों में परिवर्तन न हो। उदाहरण के लिए अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोग दोनों घटते रहते हैं। साम्य की अवस्था वह अवस्था होगी जिसमें उत्पादन तथा उपभोग की मात्रा में तो परिवर्तन हो परन्तु उनकी वृद्धि की दरों में परिवर्तन नहीं हो। प्रो० जे० के० मेहता ने संतुलन को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है, "अर्थशास्त्र में साम्य 'गति परिवर्तन' की अनुपस्थिति बतलाता है जबकि भौतिक विज्ञानों में यह (साम्य) गति की ही अनुपस्थिति को बतलाता है।"

"equilibrium denotes in economics absence of change in movement while in the physical sciences it denotes absence of movement itself." J. K. Mehta

अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएँ सन्तुलित रहती हैं, उनकी शक्तियाँ इस प्रकार क्रियाशील होती हैं कि वे एक दूसरे को तटस्थ (Neutral) कर देती हैं, ऐसी स्थिति को साम्य की स्थिति कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण अर्थशास्त्र में साम्य की स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे :

(क) एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में उस समय होता है जबकि उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय उसे अधिकतम-संतुष्टि (Maximum Satisfaction) देता है। यदि वह विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन करता है (दी हुई आय से) तो उसे मिलने वाला सम्बोध निश्चित रूप से कम हो जाता है।

(ख) एक कर्म साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि उसका उत्पादन ऐसे बिन्दु पर होता है, जिस पर उसका लाभ अधिकतम हो जाता है। यदि उस माना से वह कम या अधिक उत्पादन करता है तो उसका लाभ कम हो जाएगा।

(ग) उत्पादन के साधनों का स्वामी उस समय साम्य की अवस्था में होता है जबकि उसे उन साधनों द्वारा अधिकतम आय प्राप्त होती है। यदि वह उन साधनों के रोजगार में परिवर्तन करता है तो उसकी आय कम हो जाएगी।

## 2 साम्य के प्रकार (Kinds of Equilibrium) :

अर्थशास्त्र में साम्य का वर्गीकरण विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है :

### साम्य के प्रकार

1	2	3	4	5
(i) स्थिर साम्य (Stable)	(i) अल्पकालिक साम्य (Short Term)	(i) आंशिक साम्य (Partial or Particular)	(i) एकाकी (Single or Unique)	(i) स्थैतिक (Static)
(ii) अस्थिर साम्य (Unstable)	(ii) दीर्घकालिक साम्य (Long Term)	(ii) सामान्य साम्य (General)	(ii) अनेक संख्यीय (Multiple)	(ii) गतिशील (Dynamic)
(iii) तटस्थ साम्य (Neutral)				

### 1. स्थिर अस्थिर और तटस्थ साम्य (Stable Unstable and Neutral) :

(i) स्थिर साम्य (Stable Equilibrium) : स्थिर साम्य की अवस्था अर्थ-व्यवस्था की वह अवस्था है, जबकि किसी कारण से अर्थ-व्यवस्था में कुछ हल-

चल (disturbance) या परिवर्तन होता है, परन्तु तुरन्त ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं जो अर्थ-व्यवस्था को पुनः पहले की स्थिति अर्थात् हलचल से पूर्व की स्थिति में ला देती हैं। इस प्रकार पहले जैसी स्थिति पुनः हो जाती है।

(ii) अस्थिर सन्तुलन (Unstable Equilibrium) - जब किसी स्थिति में इस प्रकार की हलचल या इस इस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो जाए कि अन्य परिस्थितियों में भारी परिवर्तन होने के कारण पूर्व स्थिति प्राप्त न हो सके तब ऐसी स्थिति अस्थिर सन्तुलन की स्थिति कही जाती है।

(iii) तटस्थ सन्तुलन (Neutral Equilibrium) - उस स्थिति को तटस्थ सन्तुलन कहते हैं जिसमें परिवर्तनकारी शक्तियाँ प्रभावहीन होती हैं जिससे प्रारम्भिक स्थिति नहीं हो पाती है और न तो वर्तमान स्थिति प्रारम्भिक स्थिति से काफी दूर हो हट पाती है।

प्रोफेसर शुम्पीटर ने सन्तुलन की उपर्युक्त स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए सन्तुलन-मूल्य का इस प्रकार विवेचन किया है। एक स्थायी सन्तुलन मूल्य वह मूल्य है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी ऐसी शक्तियाँ प्रवृत्त हो जाती हैं जो उसको पुनः प्रारम्भिक मूल्य पर ले आती हैं। एक तटस्थ सन्तुलन मूल्य यह मूल्य है जिसमें इस प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान ही नहीं होती। अस्थायी सन्तुलन मूल्य वह मूल्य है जिसमें ऐसी परिवर्तनकारी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे प्रारम्भिक सन्तुलन मूल्य से दूर ले जाती हैं।<sup>1</sup> आर्थिक विश्लेषण में स्थायी सन्तुलन का ही प्रयोग अधिक किया गया है।

पागू ने उपर्युक्त सन्तुलनों को इस प्रकार स्पष्ट किया है। भारी लोहे की पेंदी (Heavy keel) वासा जहाज स्थायी सन्तुलन की स्थिति में रहता है, एक और पड़ा हुआ अण्डा तटस्थ सन्तुलन की स्थिति में रहता है, और एक सिरे पर खड़ा सतोलित किया अण्डा अस्थायी सन्तुलन की स्थिति में रहता है। उपर्युक्त तीन प्रकार के साम्य में से प्रथम—स्थिर-साम्य व्यावहारिक रूप में पाया जाता है। अस्थिर तथा तटस्थ साम्य काल्पनिक स्थितियाँ हैं, व्यावहारिक दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है।

<sup>1</sup> "A stable equilibrium value is an equilibrium value that, if changed by a small amount, calls into action forces that will lead to reproduce the old value, a neutral equilibrium value an equilibrium value, that does not know any such forces, an unstable equilibrium value, is an equilibrium value, change in which calls forth forces which tend to move the system farther and farther away from the equilibrium value."



(ब) समय के आधार पर : समय के आधार पर सन्तुलन के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। मार्शल ने सर्वप्रथम कीमत सिद्धांत में समय तत्व पर जोर दिया।

1. अल्पकालिक सन्तुलन ( Short-term Equilibrium ) : अल्पकालिक सन्तुलन की स्थिति वह है जिसमें माग में परिवर्तन होने पर वर्तमान उत्पादन के साधनों की सहायता में ही पूर्ति का समायोजन कर लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में माग के बढ़ने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता।

2. दीर्घकालीन सन्तुलन ( Long-term Equilibrium ) : यह वह स्थिति है जिसमें माग बढ़ने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार घटी हुई माग के अनुसार, उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन कर, पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार माग और पूर्ति में जो नया साम्य स्थापित होता है, उसे दीर्घकालीन साम्य कहते हैं। दीर्घकालीन साम्य या सन्तुलन को दूसरे ढंग से भी स्पष्ट किया जा सकता है। दीर्घकालीन साम्य वह साम्य है जो लम्बे समय तक बना रहता है।

(स) अन्य भेद : सन्तुलन के अन्य भेद भी हैं—आंशिक सन्तुलन ( Partial Equilibrium ) और सामान्य सन्तुलन ( General Equilibrium )

1. आंशिक या विशिष्ट सन्तुलन ( Partial or Particular Equilibrium ) : आंशिक या विशिष्ट सन्तुलन का सम्बन्ध एक व्यक्ति, उपभोक्ता उत्पादक फर्म या उद्योग में होता है। उपभोक्ता के सन्तुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें वह दी गई परिस्थितियों में एक निश्चित मात्रा में धन व्यय करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। उत्पादन के सन्तुलन की स्थिति वह स्थिति मानी जाती है जबकि वह वर्तमान उत्पादन की परिस्थितियों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने में समर्थ होता है। एक फर्म उस समय सन्तुलन की स्थिति में होती है जबकि वह अपने उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ होती है तथा उसका लाभ अधिकतम होता है। अतः में जब किसी एक उद्योग की यह स्थिति आ जाती है कि उसने किसी अन्य उत्पादन इकाई के प्रवेश करने या उसमें किसी एक इकाई के निकलने पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना असम्भव हो जाना है, तब ऐसी स्थिति को उस उद्योग की सन्तुलन स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम यह देखने हैं कि आंशिक या विशिष्ट सन्तुलन का क्षेत्र किसी एक आर्थिक इकाई या क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका यह नाम अवश्य है कि किसी एक आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं का विश्लेषण करने में सुविधा में होती है।

आंशिक या विशिष्ट साम्य कुछ मान्यताओं पर आधारित है—(i) हम अन्य बातों को स्थिर मान लेते हैं, जैसे एक उद्योग की माग व पूर्ति की दशाओं का

विश्लेषण करते समय हम यह मान लेते हैं कि उस उद्योग की माग व पूर्ति की दशाएँ अन्य उद्योगों की माग व पूर्ति की दशाओं से प्रभावित नहीं होगी।

(ii) यह साम्य सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण नहीं करता है, बल्कि अर्थ-व्यवस्था के एक अंग या भाग का ही विश्लेषण करता है।

**2. सामान्य सन्तुलन (General Equilibrium)** - सामान्य सन्तुलन के अन्तर्गत किमी एक आर्थिक इकाई या क्षेत्र-विशेष वा अध्ययन नहीं किया जाता, बरन् देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में कार्यशील तत्वों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य सन्तुलन सम्पूर्ण आर्थिक तत्वों तथा उनके प्रभावों को दृष्टिगत रखता है, जबकि आंशिक या विशिष्ट सन्तुलन किसी एक तत्व का ही अध्ययन करता है।

सामान्य साम्य वास्तविकता के नजदीक है। यह अर्थ-व्यवस्था के सभी परि वर्तमान तत्वों का विश्लेषण करता है। यह अपने में आंशिक साम्य को भी सम्मिलित कर लेता है। यह अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न तत्वों या अंगों की अंतर्निर्भरता को भी ध्यान में रखता है। सामान्य साम्य के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ व्यवस्था की सभी इकाइयाँ, एक ही साथ आंशिक साम्य की अवस्था में हों। जिस प्रकार मानव शरीर को साम्य या सामान्य दशा में हम उसी समय कह सकते हैं, जबकि शरीर के सभी अंग साम्य अवस्था में हों अर्थात् किसी भी अंग में कोई कष्ट न हो। सामान्य साम्य के लिए आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था के सभी अंग या भाग साम्य की अवस्था में हों। लेफ्टविच के शब्दों में, “पूरी अर्थ व्यवस्था सामान्य-साम्य की स्थिति में उसी समय होगी जबकि अर्थ-व्यवस्था की सभी इकाइयाँ एक साथ ही आंशिक साम्य की स्थिति में हों। सामान्य का विचार सभी आर्थिक इकाइयाँ तथा अर्थ-व्यवस्था के सभी अंगों के पारस्परिक निर्भरता पर जोर देती है।”

“General equilibrium for the entire economy could exist only if all economic units were to achieve simultaneous particular equilibrium adjustments. The concept of general equilibrium stresses the interdependence of all economic units and of all segments of the economy on each other” *Richard H. Leftwich, (The Price System and Resource Allocation, 1966 p. 329)*

**सामान्य-साम्य विश्लेषण के रूप (Variants of General Equilibrium)**  
आजकल सामान्य साम्य विश्लेषण के दो रूप प्रचलित हैं।

(क) पहले प्रकार का विश्लेषण, वालरस (Walras) द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर आधारित है। इसे (Walrasian Version) कहते हैं। वालरस के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अर्थमन्बन्धों के विषय में सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किया जाता है। हम यह जानते हैं कि सामान्य

साम्य विश्लेषण में अर्थ-व्यवस्था के सभी अंगों के अर्थसम्बन्धों पर विचार किया जाता है। इसमें विश्लेषण अत्यन्त ही जटिल हो जाता है। वानरम के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण में गणित का अधिक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक इकाइयों की अन्तर्निर्भरता को युग्मपद समीकरणों (Simultaneous equations) द्वारा विभिन्न इकाइयों को आकार मानकर प्रकट करते हैं। इस विधि में समीकरणों की संख्या उतनी हो होती है, जितनी इकाइयों (Variables) का मूल्य ज्ञान करना होता है। इससे समीकरणों की एक लम्बी श्रृंखला खी बन जाती है जिन्हें हल करना सरल कार्य नहीं है।

(ख) दूसरे प्रकार का सामान्य साम्य विश्लेषण लियोनटिक (W. W. Leontief) द्वारा प्रस्तुत 'पड़त-उत्पादन' (Input-Output) विश्लेषण पर आधारित है। वस्तुतः लियोनटिक द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण बालरस के सिद्धान्तों का बनावट-रूप है। इस विधि में अर्थ-व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों या उद्योगों (परिवारों की भी सम्मिलितकर) तथा सरकार को अन्तिम मांग (final demand) में सम्बन्धित उद्योग मान लेते हैं। प्रत्येक उद्योग के विषय में यह मान लिया जाता है कि वह अन्य उद्योगों को अपना उत्पादन बेचता है। बेचा गया उत्पादन (output) खरीदने वाले उद्योगों के लिए पड़त (Input) मान लिया जाता है। प्रत्येक उद्योग, अन्य उद्योगों के उत्पादन का खरीददार भी मान लिया जाता है। इस प्रकार सभी उद्योग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस आधार पर आकड़ों का संग्रह किया जाता है जो एक उद्योग द्वारा दूसरे उद्योगों को दी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रकट करते हैं। इस आधार पर अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख हलचलों का विश्लेषण किया जाता है। [यह विधि अभी विकसित की जा रही है। इस विधि का विकास मुख्यतः प्रो० लियोनटिक, (जो रूसी अर्थशास्त्री थे, तथा अब वे अमेरिकी नागरिक हैं) और गोसने इन्स्टीट्यूट, पूना के प्रो० पी० एन० माथुर द्वारा किया जा रहा है। इस विधि से अर्थशास्त्र को बड़ी प्राप्ताएँ हैं]

सामान्य साम्य-सिद्धान्त के उद्देश्य तथा महत्व : सामान्य साम्य विश्लेषण सिद्धान्त दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए विश्लेषण का समग्र (Tools) प्रदान करता है। पहला, सैद्धान्तिक दृष्टि से इस प्रकार का विश्लेषण अर्थ-व्यवस्था के समस्त अंगों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे अर्थ-व्यवस्था का पूरा चित्र एक ही साथ हमारे सामने आ जाता है। अर्थ-व्यवस्था की काय विधि समझने में इससे बड़ी मदद मिलती है। दूसरा, हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आर्थिक हलचलों का सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर क्रमशः किस प्रकार तथा किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक हलचलों के अन्तिम प्रभावों का ज्ञान होता है। एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, भूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है।

हमें यह ज्ञात करना है कि इसका अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम 'विशिष्ट साम्य' की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। हम यह पाएंगे कि मांग बढ़ जाने के कारण, कपड़े की कीमत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तथा उत्पादक को अधिक माल प्राप्त होगा। परन्तु बढ़ी हुई मांग का प्रभाव यही तक सीमित नहीं होगा। कपड़े के उत्पादकों की आय तथा लाभ से वृद्धि होने के कारण उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की भी मांग बढ़ जाएगी। इसका प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ेगा। सूती कपड़ों की स्थानापन्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अन्य उद्योगों के उत्पादन साधनों का सूती-वस्त्र उद्योग में अधिक लाभ होने के कारण स्थानान्तर (Transfer) होगा। इस प्रकार पूरी अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होगी। यदि हमें पूरी अर्थ-व्यवस्था पर पड़े प्रभावों की जानकारी करनी है तो सामान्य साम्य विश्लेषण ही सहायक होगा।

4. एकाकी तथा अनेक तत्वीय साम्य (Single or unique and Multiple Equilibrium) :

(i) एकाकी साम्य (Single or unique) : जब साम्य की शर्तों की पूर्ति एक ही कीमतों तथा वस्तुओं की मात्राओं द्वारा हो जाती है, तो उसे एकाकी साम्य कहते हैं। ('A position of unique equilibrium arises if there is a single sets of prices and quantities which fulfil the conditions of equilibrium—Stigler')

(ii) अनेक तत्वीय साम्य (Multiple) : जब साम्य की शर्तों की पूर्ति कई बिन्दुओं पर विभिन्न कीमतों तथा वस्तु की मात्राओं द्वारा हो जाती है, तो उसे अनेक तत्वीय साम्य की स्थिति कहते हैं।

("Multiple positions of equilibrium exist when several different sets of prices and quantities will meet the equilibrium conditions"—Stigler )

अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि स्थिर साम्य की एक ही स्थिति हो सकती है। अर्थात् एक विशिष्ट कीमत तथा विशिष्ट मात्रा पर ही साम्य की स्थिति हो सकती है। मार्शल ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध किया तथा यह बतलाया कि मांग तथा पूर्ति में एक से अधिक साम्य-बिन्दु हो सकते हैं। (यद्यपि यह स्थिति व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कम पाई जाती है) यह स्थिति (अनेक तत्वीय साम्य) उस समय पाई जाती है जबकि मांग रेखा कुछ दूरी तक बेसोबदार होती है तथा तत्पश्चात् कुछ दूरी तक लोबदार हो जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से यह स्थिति उस समय पाई जाती है, जबकि बाजार उपभोक्ताओं के आय समूह (Income Group) के आधार पर विभाजित हो, यद्यपि यह स्थिति पूर्णतया काल्पनिक है।

### 5. स्थैतिक गतिशील साम्य\* (Static and Dynamic equilibrium) :

(i) स्थैतिक साम्य (Static) : जब अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग जनसंख्या, माग पूर्ति आदि को स्थिर मान लिया जाता है तो उसे स्थैतिक साम्य की स्थिति कहते हैं।

(ii) गतिशील साम्य (Dynamic) : इसका सम्बन्ध गतिशील अर्थ-व्यवस्था से है। जब किसी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न तत्त्वों में समान दर से परिवर्तन होता है तो उसे गतिशील साम्य कहते हैं। प्रो० मेहता के अनुसार जो साम्य एक निश्चित अवधि के बाद भी पूर्ववत् बना रहता है उसे स्थैतिक साम्य, तथा जो साम्य एक निश्चित अवधि के पश्चात् बदल जाता है उसे गतिशील साम्य कहते हैं। वस्तुतः अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न तत्त्वों में समान दर से परिवर्तन की बात, काल्पनिक तथा भ्रामक है।

#### साम्य की वास्तविकता

साम्य के सम्बन्ध में, एक प्रश्न उठाया जाता है—क्या साम्य वास्तविक जगत में पाया जाता है? (क) यद्यपि साम्य वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है, फिर भी वास्तविक जगत में साम्य की ओर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। साम्य की स्थिति को हम आदर्श स्थिति कह सकते हैं। (ख) यदि निश्चित मूल्य पर माग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है तो यह मानना पड़ेगा कि साम्य वास्तविक रूप में भी पाया जाता है। परन्तु यदि यह स्थिति वास्तविक जगत में पाई भी जाए तो वह क्षणिक या बहुत कम समय के लिए बनी रहेगी। 'साम्य (concept)' का सैद्धान्तिक रूप में ही अधिक महत्व है।

नोट :— इस अध्याय सम्बन्धी प्रश्न व सकेत अध्याय 5 के अन्त में देखिये।

---

\* 'स्थैतिक' तथा 'गतिशील' के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अध्ययन के लिए अध्याय 5 देखिए।

## आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं (II)

(Branches of Economic Analysis)

*"Dynamic economics is, as it were, a running commentary on static economics. The laws of static economics must, therefore, apply to dynamics"*

J. K. Mehta

### स्थैतिक तथा गतिशील अर्थशास्त्र ✓ (Static and Dynamic Economics) ✓

आधुनिक आर्थिक विद्वानों को समझने के लिए अर्थशास्त्र में प्रयोग में लाये जाने वाले स्थैतिक (Static) तथा गतिशील (Dynamic) शब्दों के अन्तर को समझना बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक विषयों के विश्लेषण में कुछ मान्यताओं का आधार मान लिया जाता है। ये मान्यताएँ कुछ दशाओं या परिस्थितियों से सम्बन्धित होती हैं। दशा सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर ही अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जाता है—स्थैतिक अर्थशास्त्र (Static Economics) तथा गतिशील अर्थशास्त्र (Dynamic Economics)। इन दो शब्दों के अर्थों के विषय में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री इन शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियों के रूप में करते हैं, जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का यह मन है कि ये शब्द अर्थशास्त्र की दो शाखाओं को व्यक्त करते हैं। प्रो० नाइट के अनुसार अर्थशास्त्र में "स्थैतिक तथा गतिशील शब्दों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग ने अनाश्वयक भ्रम पैदा हो गया है।" (Needless confusion has been caused by the unfortunate use of the terms 'Static' and 'dynamic')। परन्तु आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अर्थशास्त्र को 'स्थैतिक' तथा 'गतिशील' वर्गों में विभाजित करना उचित है।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> "The correct charting of a line of demarcation between them should have beneficial result on the progress of Economics"

Prof Harrod.

## 1. स्थैतिक अर्थशास्त्र (Static Economics)

1. स्थैतिक का अर्थ : सामान्य तौर पर स्थैतिक शब्द 'स्थिर', 'निष्क्रिय', 'विश्राम' की या 'गतिहीन' अवस्था या स्थिति का स्रोतक है। परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ 'स्थिर', 'निष्क्रिय' या 'गतिहीन' नहीं है। अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अर्थ प्रायः गतिहीन, निष्क्रिय या स्थिर अर्थ-व्यवस्था से नहीं है, अपितु ऐसी अर्थ-व्यवस्था से है जिसमें गति होती है, परन्तु गति की दर समान रहती है। आर्थिक वातावरण समय तत्त्व से सर्वथा अप्रभावित रहने के कारण, उसमें अनिश्चितता व उत्तार-चढ़ाव नहीं होते। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था एक निश्चित एवं निगमित गति में चलती रहती है। प्रो० हैरोड ने 'स्थैतिक' को इस प्रकार परिभाषित किया है, 'स्थैतिक सन्तुलन का अर्थ विश्राम की अवस्था नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जिसमें दिन-प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष कार्य चरुस्ती से निरन्तर हो रहा हो, परन्तु उसमें वृद्धि या कमी नहीं हो रही हो। इस सक्रिय परन्तु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाना चाहिए।'।

"Thus a static equilibrium by no means implies a state of idleness, but one in which work steadily is going forward day by day and year by year but without increase or diminution...that it is to this active but unchanging process that the expression static economics should be applied."

Sir R. Harrod.

इस शब्द के अर्थ के विषय में इतने भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं कि हम एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। अतः यहाँ पर इस शब्द के सम्बन्ध में प्रकट किए गए विचारों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

(i) मार्शल के अनुसार, "स्थैतिक अवस्था के सभी महत्वपूर्ण लक्षण ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं जहाँ जनसंख्या तथा धन दोनों बढ़ रहे हों तथा दोनों में वृद्धि की दर लगभग समान होती है, और भूमि की कोई कमी नहीं होती है। उत्पादन की दशाओं तथा विधियों में बहुत कम परिवर्तन होता है और जहाँ मनुष्य का चरित्र स्वयं स्थिर रहता है।"<sup>2</sup>

(ii) प्रो० मैकफाई के शब्दों में, "स्थैतिक दशा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वे साधन जा कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियंत्रित

<sup>2</sup> "Nearly all the distinctive features of a stationary state may be exhibited in a place where population and wealth are both growing, provided they are growing at about the same rate and there is no scarcity of land and, provided also, the methods of production and the conditions change very little and, above all, where the character of man himself is a constant quantity" — Marshall

करते हैं, स्थिर हो अथवा स्थिर मान लिए गये हों। जनसंख्या को न तो बढ़ती हुई मानने है न घटती हुई और उसके आयु के ढांचे में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन प्रणाली तथा कुल उत्पादन पूर्ववत् रहते हैं या कम से कम यदि जनसंख्या में वृद्धि हानी है तो यह मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन भी उसी दर से बढ़ रहा है।<sup>3</sup> प्रो० टिन बर्जिन (Tinbergen), स्टिग्लर (Stigler) तथा प्रो० क्लार्क (B. Clark) ने भी 'स्थैतिक' को मैकफार्ड की ही तरह, स्थिर अर्थ व्यवस्था माना है। स्टिग्लर ने ऐसी अर्थ-व्यवस्था को स्थैतिक कहा है जिसमें सीन बानो-रुचि, साधनो तथा प्रविधि (Technology) में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लार्क ने ऐसी अर्थ व्यवस्था को स्थैतिक माना है जिसमें पाच बातों—जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन प्रणाली, मनुष्य की आवश्यकताओं और वैयक्तिक इकाइयों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीगू ने 'स्थैतिक' स्थिति का स्पष्टीकरण एक उदाहरण द्वारा किया है। उनके अनुसार 'स्थैतिक' में भी परिवर्तन हावे है, परन्तु ये परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। पीगू ने इसका स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया है, 'जिम्मे धूँ से भरना बनता है वे सदा बदलते रहते हैं किन्तु भरना अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार 'स्थैतिक' की स्थिति में होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

(ii) प्रोफेसर जे० के० मेहता ने 'स्थैतिक' तथा 'गत्यात्मक' के सम्बन्ध में अपना मौलिक विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार स्थैतिक स्थिति वह है जो एक निश्चित समय या अवधि के पश्चात् भी उसी रूप में बनी रहती है। परन्तु यदि निश्चित समय के पश्चात् अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे गत्यात्मक स्थिति कहेंगे। उदाहरण के लिए हम एक सप्ताह की अवधि ले लें। यदि एक सप्ताह के पश्चात् भी सतुलन की स्थिति पूर्ववत् रहती है तो इसे स्थैतिक स्थिति कहेंगे, परन्तु यदि एक सप्ताह के पश्चात् सतुलन के परिवर्तन हो जाता है तो इसे गत्यात्मक स्थिति कहेंगे। इस प्रकार 'स्थैतिक' तथा 'गत्यात्मक' स्थिति के निर्धारण में एक निश्चित समय या अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है।

(11) जे० आर० हिव्स के अनुसार, "आर्थिक सिद्धान्त के उन भागों को 'आर्थिक स्थैतिक' कहा जाता है जिसमें हम तिथि का ध्यान नहीं रखते और ज्ञा-

<sup>3</sup> "The stationary state is an economic system in which the factors which control production and consumption, distribution and exchange are constant. Population is regarded as neither increasing nor decreasing and its age composition does not alter. Methods of production and the total output remain the same, or at least, if population grows, total output must be regarded as growing at the same rate"



त्मक उन भागो को कहते हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई या मात्रा का सम्बन्ध किसी तिथि से होता है।”

“We call economic statics those parts of economic theory where we do not trouble about dating, economic dynamics those parts where every quantity must be dated.” —J. R. Hicks, *Value and Capital*

इस प्रकार हिक्स के अनुसार ‘तिथिकरण’ (dating) महत्वपूर्ण है। हैरोड ने ‘तिथिकरण’ पर आपत्ति की है। हैरोड ने कहा है कि ‘गत्यात्मक’ के अन्तर्गत निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। परन्तु यदि एक निश्चित अवधि में होने वाले परिवर्तनों की तुलना किसी अन्य निश्चित अवधि के परिवर्तनों से की जाए तो इसे “तुलनात्मक स्थैतिक” (Comparative Statics) की सजा देनी चाहिए।

## 2 स्थैतिक विश्लेषण की सीमाएँ (Limitations of Static Analysis) :

1 स्थैतिक स्थिति काल्पनिक स्थैतिक ‘स्थिर’ अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण करता है, परन्तु वास्तविक सत्तार गतिशील है। अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुआ करते हैं। परिवर्तनशील सत्तार को स्थिर मानकर अध्ययन करना एक भ्रम है। इस आधार पर मार्क्स ने इसे ‘सैद्धांतिक कल्पना’ (Methodological Fiction) कहा है। प्रो० एडवर्थ ने कहा है, “परिवर्तनशील को स्थिर मान लेने के कारण अर्थशास्त्र में बहुत से काल्पनिक विचार भर गए हैं। (The treating as constant of what is variable is the source of most of the fallacies in Political Economy’ Edgeworth)

2. स्थैतिक की मान्यताएँ अवास्तविक : ‘स्थैतिक’ जिन मान्यताओं पर आधारित है, वे काल्पनिक हैं। जैसे पूर्ण प्रतिযোগिता, दी हुई रुचि, पूर्णज्ञान, जन-संख्या का निश्चित आकार, पूर्ण गतिशीलता, अनिश्चितता की अनुपस्थिति आदि मान्यताएँ वास्तविकता से बहुत दूर हैं। वास्तविक सत्तार की परिवर्तनशील दशाओं के विश्लेषण के लिए स्थैतिक विधि उपयुक्त नहीं है। प्रो० हिक्स ने ठीक ही कहा है, ‘स्थैतिक अवस्था अन्त में कुछ नहीं है, बल्कि वास्तविकता से दूर भागना है’ (‘Stationary state is in the end, nothing but an evasion’)

स्थैतिक विश्लेषण का क्षेत्र तथा महत्व (Scope and Importance of Static Analysis) - उपर्युक्त सीमाओं के हाते हुए भी स्थैतिक विश्लेषण का अर्थ-शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है।

1. अर्थशास्त्र की बहुत सी विषय सामग्री 'स्यैतिक' पर आधारित : कीमत-निर्धारण उत्पादन के साधनों का हिस्सा-निर्धारण, उपभोक्ता का सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार आदि विषय सामग्री तथा इनसे सम्बन्धित आर्थिक नियम स्यैतिक विश्लेषण पर आधारित हैं। इसी प्रकार 'व्यापार चक्रों' में सम्बन्धित भिद्धान्तों को भी 'स्यैतिक' से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता है। प्रो० हैरोड के अनुसार राधिनस की परिभाषा भी मुख्यतः स्यैतिक विश्लेषण पर आधारित है। केन्स के भी कुछ विचार 'स्यैतिक' पर आधारित हैं।

2 'परिवर्तन स्यैतिक' में पूर्णतया उपेक्षित नहीं है यह मानना कि 'परिवर्तन' स्यैतिक विश्लेषण की सीमा के पूरा रूप से बाहर है, निराधार है। स्यैतिक में भी एक बार परिवर्तन (Once over change) के कारण उत्पादन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। 'स्यैतिक' का अर्थ पूर्ण स्थिरता नहीं है।

3 परिवर्तनशील अध्ययनस्थिति का अध्ययन कठिन आर्थिक परिवर्तन बड़े ही जटिल (Complex) होते हैं। इन जटिल परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कठिन है। गतिशील अर्थ-व्यवस्थाओं का अध्ययन गतिशील अवस्थाओं को छोटी-छोटी स्यैतिक अवस्थाओं में विभाजित करने से सुविधाजनक हो जाता है। लगातार परिवर्तन में अनिश्चितता का तत्व अधिक होता है। इस प्रकार 'गतिशील' का अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है।

अतः विभिन्न स्यैतिक अवस्थाओं को 'गतिशील' की अलग-अलग अवस्थाएँ मानकर अध्ययन करना अधिक उपयुक्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रो० मेहता ने कहा है कि गतिशील अर्थशास्त्र स्यैतिक की 'लगातार टीका' है, अतः स्यैतिक के नियम 'गतिशील' पर भी लागू होते हैं।

"Dynamic economics is as it were, a running commentary on static economics. The laws of static economics must, therefore, apply to dynamics"

—J K Mehta

4 आशाओं व सम्भावनाओं (Expectations and Probabilities) का भी अध्ययन स्यैतिक विश्लेषण के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि आशाओं व सम्भावनाओं पर इसके द्वारा प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। परन्तु यह कथन पूर्णरूप से सही नहीं है। सीमित रूप से, कुछ परिस्थितियों में, वर्तमान तथा भूतकाल की कई स्यैतिक अवस्थाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालकर भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में भी सम्भावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं। फिर भी, आशा व 'सम्भावना' मुख्यतया गतिशील अर्थशास्त्र के विषय हैं।

4 'Such Theory (static theory) can be successful in predicting the behaviour of the price system in certain circumstances in which dynamic considerations are not critical'. Richard G. Lipsey, *An Introduction to Positive Economics*, p 531

5. उच्च-गणित का ज्ञान आवश्यक नहीं गतिशील विश्लेषण के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है, निरन्तर-प्रति होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, उच्च-गणित की सहायता के बिना करना संभव नहीं है। परन्तु 'स्थैतिक' विश्लेषण के लिए गणित का ज्ञान अनिवार्य नहीं है।

उपर्युक्त महत्त्व के होते हुए भी, यह मानना पड़ेगा की परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था की गतिविधियों के विश्लेषण के लिए स्थैतिक-विश्लेषण का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जा सकता है। स्थैतिक विश्लेषण की दो प्रमुख सीमाएँ हैं—(क) स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग उस मार्ग के विषय में अविवेकवाणी के लिए नहीं किया जा सकता, जिस पर बाजार एक सतुलन की अवस्था से दूसरे सतुलन की अवस्था की ओर बढ़ रहा हो, तथा (ख) स्थैतिक विश्लेषण द्वारा यह भी नहीं बताया जा सकता है कि एक दी गई सतुलन की अवस्था में पहुँचा जा सकता है या नहीं।<sup>5</sup> इन सीमाओं के होते हुए भी स्थैतिक, विश्लेषण के महत्त्व को प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

## 2. गतिशील अर्थशास्त्र (Dynamic Economics)

### 1. गतिशील अर्थशास्त्र का अर्थ .

गतिशील अर्थशास्त्र का सम्बन्ध परिवर्तन से है। स्थैतिक विश्लेषण अर्थ-व्यवस्था में दिन-प्रति-दिन होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। गतिशील अर्थशास्त्र द्वारा अर्थ-व्यवस्था में लगातार होने वाले परिवर्तनों, इन परिवर्तनों की प्रक्रिया (Process) तथा परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारणों का विश्लेषण किया जाता है। गतिशील अर्थशास्त्र का विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

(1) रिचार्ड लिप्से के अनुसार, "गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था की प्रणालियों, वैयक्तिक बाजारों या सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की असन्तुलित दशाओं का अध्ययन है।"

"Dynamic Analysis may be defined as the study of the behaviour of systems, single markets or whole economics, in disequilibrium situations"

<sup>5</sup> "First, it cannot be used to predict the path which the market follows when moving from one equilibrium to another, and, second, it cannot predict whether or not a given equilibrium position can ever be attained"

अर्थ-व्यवस्था सामान्यतया असंतुलन में नहीं रहती है। परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण असंतुलन पैदा होता रहता है। इन असंतुलित अवस्थाओं का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है।

(ii) जे० बी० क्लार्क के अनुसार गतिशील अर्थ-व्यवस्था में पांच विशेषताएँ पाई जाती हैं—(i) जनसंख्या, (ii) पूँजी, (iii) उत्पादन विधियाँ, (iv) औद्योगिक संगठनों के रूप में परिवर्तन तथा (v) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि। जिन अर्थ-व्यवस्थाओं में ये परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें 'गतिशील' तथा जिनमें ये परिवर्तन नहीं होते, उन्हें 'स्थैतिक' कहते हैं। गतिशील विश्लेषण इन परिवर्तनों की प्रक्रियाओं का विश्लेषण है।

(iii) हिक्स के अनुसार गतिशील अर्थशास्त्र वह है जिसमें प्रत्येक मात्रा का त्रयीकरण (Dating) किया जाता है। हिक्स ने त्रयीकरण पर बहुत जोर दिया है।

(iv) हैरेज ने गतिशील अर्थशास्त्र को अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कहा है। उनके अनुसार, "गतिशील का सम्बन्ध विशेषतया निरन्तर होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों तथा निश्चित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तनों की बरी में है।"

(v) बोमल ने गतिशील अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भूतकालीन तथा आगामी घटनाओं के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी से बतलाया है। उनके अनुसार,

"Economic dynamics is the study of economic phenomena in relation to preceding and succeeding events" —Baumol

'गत्यात्मक' के अन्तर्गत हम विभिन्न तरंगों (Variables) के सहसम्बन्धों के आधार पर किसी अर्थ व्यवस्था की भविष्य सम्बन्धी अवस्थाओं का अनुमान लगाते हैं। बोमल के अनुसार, 'गतिशील अर्थशास्त्र आर्थिक वातावरण की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन है।"

'स्थैतिक' तथा 'गतिशील' के विषय में उपरोक्त स्पष्टीकरण से ऐसा आभास होता है कि वे किसी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक स्थितियों के प्रतीक हैं। परन्तु वे किसी अर्थ-व्यवस्था की अवस्थाओं के प्रतीक नहीं हैं। 'अर्थ-व्यवस्था' के उदाहरण द्वारा केवल इन दोनों को समझाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः स्थैतिक तथा

\* "Dynamics will specially be concerned with the effects of continuing changes and with rates of change in the values that have to be determined" Harrod, *Towards a Dynamic Economics*, p. 8

व्यवहारिक आर्थिक विश्लेषण की दो रीतियाँ (approaches) हैं। प्रथमशास्त्र के विभिन्न विषयों का विश्लेषण इन दोनों रीतियों द्वारा किया जाता है।

## 2. गतिशील अर्थशास्त्र की उपयोगिता तथा महत्व :

‘गतिशील अर्थशास्त्र’ आर्थिक जगत की वास्तविकताओं का विश्लेषण करता है। इसके महत्व का अनुमान हम निम्नलिखित विवरण में लगा सकते हैं।

1. वास्तविकता के निकट : गतिशील अर्थशास्त्र, स्थैतिक अर्थशास्त्र की तुलना में वास्तविकता के अधिक नजदीक है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। स्थैतिक के अनुसार यदि किसी वस्तु के उत्पादन से हानि उठानी पड़ती है तो उस वस्तु का उत्पादन बन्द कर दिया जाएगा। परन्तु गतिशील अर्थशास्त्र यह बताता है कि अल्पकाल में स्थायी लागतों (Fixed costs) के बराबर हानि उठाते हुए भी अल्पकाल में लाभ की सम्भावनाओं के कारण उत्पादन जारी रहेगा। वास्तव में व्यवहार में ऐसा ही किया जाता है। (यह उदाहरण Timbergen ने दिया है)। गतिशील अर्थशास्त्र परिवर्तनों का अध्ययन करता है। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष समस्या में रजि, जनसंख्या, उत्पादन-विधि आदि में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। स्थैतिक इन परिवर्तनों का अध्ययन करने में असमर्थ है।

2. कुछ समस्याओं का अध्ययन ‘गतिशील’ द्वारा ही सम्भव। कुछ आर्थिक समस्याएँ ऐसी हैं, जिनका विश्लेषण गतिशील रीति द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे एक सदुत्पन्न की स्थिति से दूसरे सदुत्पन्न की स्थिति में बदलने के बीच से सम्बन्धित समस्याओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन, गतिशील रीति द्वारा ही किया जा सकता है। इसी प्रकार जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ आर्थिक विकास, व्यापार-चक्र वृद्धि, विनियोग, लाभ के विद्वान्त आदि का विश्लेषण गतिशील अर्थशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है।

3. मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित समस्याओं के विश्लेषण के लिए : जो आर्थिक क्रियाएँ मानव की प्रवृत्तियों पर अधिक आधारित हैं या ऐसे आर्थिक विषय जो मनोवैज्ञानिक तरीकों से प्रभावित होते हैं, उनका विश्लेषण गतिशील अर्थशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे व्यापार चक्र, विनियोजन आदि।

4. अल्पिक लचीला (Flexible) : गतिशील विश्लेषण काफी लचीला है, इसमें किसी प्रकार की हठधर्मिता (Rigidity) नहीं पाई जाती है। गतिशील अर्थशास्त्र अधिक से अधिक सम्भावनाओं तथा अधिक से अधिक उपयुक्त नमूनों (Model) पर विचार करता है। इस लचीलेपन के कारण, आर्थिक विकास तथा नियोजन सम्बन्धी जटिल समस्याओं के अध्ययन में गतिशील विश्लेषण विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है।

5 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा भी प्रयोग : प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सामान्य-तया स्थैतिक विश्लेषण में विश्वास रखते थे, परन्तु उन्होंने भी कुछ समस्याओं के अध्ययन के लिए गतिशील-विश्लेषण का सहारा लिया जिससे इसके महत्व का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए रिकार्डों की वितरण की समस्या तथा भाव्यस की जन-संख्या की समस्या का अध्ययन गतिशील विश्लेषण के ही अन्तर्गत होता है। मार्शल ने भी गतिशील-विश्लेषण की पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की।

6. अन्य महत्व . प्रो० राविन्स ने गतिशील-विश्लेषण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार गतिशील-विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है : (क) इसकी व्याख्या वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित होने के कारण, अधिक सही तथा उपयोगी होती है, (ख) आर्थिक-सिद्धान्तों की सत्यता की जाच में सहायक होती है, तथा (ग) यह उन तत्वों पर भी प्रकाश डालता है, जिनके सम्बन्ध में स्थैतिक अर्थशास्त्र मौन रहता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है।

### 3. गतिशील अर्थशास्त्र की सीमाएं (Limitations) :

1. गतिशील विश्लेषण के लिए उच्च गणित तथा इकोनोमेट्रिक्स का ज्ञान आवश्यक है। अतः विश्लेषण की यह रीति बहुत कठिन है।

2. वास्तविक जगत में परिवर्तन बड़ी तेजी से होते हैं। तेजी से होने वाले इन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, गतिशील विश्लेषण करना बहुत ही कठिन है। परिवर्तनों की तीव्रता के कारण, गतिशील विश्लेषण बड़ा जटिल तथा पेचीदा हो जाता है। अतः बहुत से अर्थशास्त्री इन पेचीदगियों से बचने के लिए स्थैतिक विश्लेषण का सहारा लेते हैं। स्टोनियर तथा हेग के विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं :

'In any case, the real world is a very complex place and the creation of a theory of economics which tries to take account of all or even most of that complexity would be beyond the capacity of any human brain'

3. गतिशील अर्थशास्त्र का सीमित विकास : गतिशील अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत अर्थशास्त्र की नई शाखा है। विश्लेषण के इस ढंग का अभी पूर्णरूप से विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि रूस (Roos), टिन्बर्जिन (Tinbergen), कैप (Kapp), हारोड (Harrod), मीरडल (Myrdal), ओह्लिन (Ohlin), हैन्सेन (Hansen), कुज़नेट्स (Kuznets) आदि अर्थशास्त्रियों ने इस शाखा का समृद्ध तथा पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी अर्थशास्त्र की यह शाखा पूर्ण विकसित नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में स्टिगलर ने ठीक ही कहा है, "In fact no very general theory of economic dynamics has yet been invented."

वस्तुतः आर्थिक समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए आर्थिक-विश्लेषण की इन दोनों रीतियों—स्थैतिक तथा गतिशील—की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में गतिशील विश्लेषण का महत्व बढ़ रहा है तथा निकट भविष्य में, यह रीति एक विकसित तथा पूर्ण रीति हो जाएगी।

### प्रश्न तथा सवैत

1. स्थैतिक तथा गतिशील के विचारों को व्याख्या कीजिए। आर्थिक विश्लेषण में उनकी क्या उपयोगिता है?

या

"वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों परस्पर आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ (Ignorant) रहते हैं तो आप केवल अर्द्ध शिक्षित हैं।" सेम्युवसन के इस कथन की विवेचना कीजिए।

[सकेत—सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के दृष्टिकोण से मुख्य समानताएँ बताइए तथा यह सिद्ध कीजिए कि आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए दोनों ही आवश्यक हैं।]

2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro economics) तथा व्यापक अर्थशास्त्र (Macro economics) का अन्तर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण के महत्व को समझाइए।

[सकेत—प्रथम भाग में सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अन्तर बताइए तथा द्वितीय भाग में व्यापक दृष्टिकोण की महत्ता स्पष्ट कीजिए।]

3. अर्थशास्त्री को आर्थिक व्यष्टिभाव तथा आर्थिक समष्टिभाव (Macro economics) दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक व्यष्टिभाव तथा आर्थिक समष्टिभाव रीतियाँ एक दूसरे की विकल्प (alternative) नहीं बल्कि पूरक हैं।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

(Vik, B. com. II, 1964)

[सकेत—आर्थिक व्यष्टिभाव तथा समष्टिभाव दोनों की परिभाषा दीजिए। इसके बाद इनके महत्व, प्रयोग तथा सीमाएँ बताते हुए दोनों की परस्पर निर्भरता स्पष्ट कीजिए।]

4. आंशिक विश्लेषण (Partial Analysis) तथा पूर्ण विश्लेषण (Total Analysis) का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या आंशिक विश्लेषण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी कहा जा सकता है?

5. सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बीच अन्तर बताइए । इनमें से आप किसे अधिक सामान्य तथा आधार-भूत (General and Fundamental) समझते हैं ?

[संकेत—प्रथम भाग में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक अर्थशास्त्र की बीच अन्तर बताइए । द्वितीय भाग में दोनों की महत्ता तथा प्रयोग स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिए कि दोनों ही आवश्यक हैं ।]

6. सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिए तथा दोनों की आवश्यकता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

7. 'साम्य' शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए । विभिन्न प्रकार की साम्य परिस्थितियों के बीच अन्तर बताइए ।

(Lucknow, B. A. I, 1961)

8. साम्य से आप क्या समझते हैं ? आर्थिक तथा साधारण साम्यों के विचारों की व्याख्या कीजिए । कारणों सहित बताइए कि सामान्य साम्य की जगह स्थिति बाध्यता है या नहीं ?

(Ravishanker, B. com. I, 1965)

9. "सामान्य साम्य एक मिथ्या नाम (Misnomer) है, कोई भी आर्थिक विश्लेषण इस अर्थ में सामान्य नहीं है कि वह सभी सम्बन्धित वस्तुओं पर एक साथ विचार कर सके ।" इस कथन की व्याख्या कीजिए । प्रो० स्टिंगलर

[संकेत—इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा सामान्य-साम्य विश्लेषण की सीमाओं को लिखिए ।]

10. सन्तुलन (Equilibrium) से आप क्या समझते हैं ? स्थिर तथा प्रायोगिक सन्तुलन (Static and Dynamic equilibria) को स्पष्ट रूप से समझाइए ।

(Lucknow, B. A. I, 1958)

[संकेत—साम्य के विचार को स्पष्ट कीजिए तथा स्थिर व प्रायोगिक दशाओं को उदाहरण द्वारा समझाइए, विशेषतः प्रो० मेहता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ।]



## अर्थशास्त्र की अध्ययन-विधियां (Methods of Economics)

*"There is not any one method of investigation which can properly be called the method of Economics but every method must be made serviceable in its proper place, either singly or in combination with others"*

—Marshall

विज्ञान का निर्माण नियमों द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है अतः अन्य विज्ञानों की भाँति, इसके द्वारा भी आर्थिक घटनाओं के अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा कारण तथा परिणाम के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धान्तों या नियमों की खोज के लिए विभिन्न रीतियों या विधियों (Methods) का प्रयोग किया गया है। रीति का अभिप्राय उत तक पूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग मन्त्रार्थ को खोजने या उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ('Method Means the logical Process used in discovering or in demonstrating the truth'—Luigi cossa) जिन विधियों द्वारा आर्थिक नियमों का निर्माण किया जाता है उन्हें अर्थ-शास्त्र की विधियाँ कहते हैं। रीति या अध्ययन-विधि का अर्थ उस विधि से है जिसके द्वारा सत्य या वस्तु स्थिति की खोज की जाती है। नियमों की सत्यता कुछ अंशों में उनके अध्ययन की उचित विधियों पर निर्भर है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियमों के निर्माण तथा आर्थिक अध्ययन के लिए सामान्यतया दो विधियों या रीतियों का प्रयोग किया है

- 1 निगमन या अनुमान रीति (Deductive or Abstract Method)
- 2 आगमन या ऐतिहासिक रीति (Inductive or Historical Method)

### 1. निगमन रीति (Deductive Method)

इसी रीति के अनुसार किसी पूर्व-कथित सामान्य, स्वर्यासिद्ध सत्य को आधार मानकर किसी विशिष्ट सिद्धान्त या नियम तक पहुँचा जाता है। इस रीति को अनु-

मान रीति ( Hypothetical Method ) भी कहते हैं, क्योंकि कुछ अनुमान या धारणायें तथ्यों से कभी-कभी भेल नहीं खाती, परन्तु वे तथ्यों के इतने निकट हा सन्ती हैं कि उन्हें आधार मानकर तर्क द्वारा परिणाम निवाले जा सकते हैं। पहले स्वयं सिद्ध बातों को आधार मान लेते हैं तथा उस आधार पर नियमों का निर्माण करते हैं तथा बाद में उस सामान्य कथन की जाच, व्यक्तिगत मामलों के सदर्थ में की जाती है। इस प्रकार, इस विधि के अनुसार हम सामान्य में विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। (from general to particular) सर्वप्रथम, अध्ययन की जाने वाली परिस्थिति या समस्या के वास्तविक सरल रूप का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके पश्चात् हम सम्बन्ध में पूर्व कथित सामान्य आधारभूत सिद्धान्त एवं धारणा की जाच जारी प्राप्त की जाती है। अन्त में, उनकी सहायता से न तर्कपूर्ण विधि द्वारा निश्चित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरणार्थ, "प्रत्येक व्यक्ति 'अधिकतम सन्तुष्टि' प्राप्त करना चाहता है" या प्रत्येक व्यक्ति वस्तुएँ सस्ती दर पर क्रय करना चाहता है, ये सर्वमान्य तथ्य हैं। समस्या यह है कि क्या ये सत्य सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। विभिन्न देशों तथा समयों में जाच करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना ही है तथा प्रत्येक व्यक्ति सस्ती दर पर क्रय करना चाहता है।

अधिकांश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस रीति को उपयुक्त माना है। एडम-स्मिथ, रिकार्डों, सीनियर, मिल, कर्नेस, (Cairness) आदि अर्थशास्त्री इस रीति के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने मानव-व्यवहारों के कुछ तथ्यों को सत्य मानकर उनके आधार पर कुछ आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया, जैसे मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी है मनुष्य की इच्छा अधिक से अधिक धन संग्रह करने की होती है, भूमि पर कृपागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, आदि। इन अर्थशास्त्रियों की बहुत सी धारणायें प्रवास्तविक थीं और यथार्थ वस्तु-स्थिति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। कार्सल, जेवन्स, फिशर आदि ने भी निगमन रीति का प्रयोग किया, परन्तु उन्होंने ज्ञात किए गए परिणामों की सहायता से निगमन प्रणाली के आधारभूत सत्य को सही बनाने के लिए भी प्रयत्न किया।

निगमन-रीति को श्रुत रीति ( Abstract Method ), काल्पनिक रीति ( Hypothetical Method ) तथा विश्लेषणात्मक रीति ( Analytical Method ) भी कहते हैं। गणितीय रीति ( Mathematical Method ) निगमन रीति का ही एक रूप है। Jevons, Edgeworth, Hicks आदि ने गणितीय रीति का काफी प्रयोग किया है। आजकल 'गणितीय निगमन रीति' का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

बोल्डिंग (Boulding) ने निगमन प्रणाली को 'Method of Intellectual Experiment' कहा है। वस्तुतः यह प्रणाली शुद्ध गणित के सिद्धान्तों से मिलती

जुलती है। जिस प्रकार गणित में हम कुछ सरल सिद्धान्तों या तथ्यों से प्रारम्भ करते हैं तथा उनमें धीरे-धीरे गूढ़ प्रश्नों का समावेश करते जाते हैं, उसी प्रकार कुछ सामान्य आर्थिक विचार धारार्यों के आधार पर गूढ़ आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए मिल ने अपने विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त को प्रतिष्ठा निगमन रीति द्वारा ही की है। उसने इस मान्यता से प्रारम्भ किया कि मुक्त व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय धन-विभाजन से सभी देश लाभान्वित होंगे। प्रारम्भ में अपने केवल दो वस्तुओं तथा दो देशों का उदाहरण लिया। बाद में विभिन्न देशों तथा विभिन्न वस्तुओं के उदाहरणों द्वारा इस मान्यता की पुष्टि की। इसी प्रकार मूल्य नियंत्रण-सिद्धान्त तथा वितरण के सिद्धान्त, माग तथा पूर्ति सिद्धान्त, उपयोगिता ह्रास नियम आदि निगमन रीति द्वारा ही निमित्त किए गये हैं।

**निगमन रीति के गुण (Merits of Deductive Method) :**

(1) सरलता यह रीति सर्वसाधारण के लिए सरल है। इस रीति के अनुसार जटिल घटनाओं का भी विश्लेषण सरलतापूर्वक कर लिया जाता है। यदि इनका अलग-अलग निरीक्षण करने के पश्चात् एक सामान्य सत्य की ज्ञात करना हो तो यह कार्य भव्यतः कठिन होगा। परन्तु एक सर्वमान्य सत्य को आधार मानकर तर्क-वितर्क द्वारा किसी विशिष्ट सत्य पर पहुँचना सरल है।

(2) निष्कर्षों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता निगमन रीति द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि इनमें त्रुटियों का निवारण एवं समाधान तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार सम्भव है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का यह मत है कि ज्ञात को आधार मानकर गणितशास्त्र की सहायता से अज्ञात का अनुमान लगाना सरल है। यह अनुमान प्रायः शुद्ध एवं स्पष्ट ही होता है। कौनेन ने कहा है कि अर्थ-विज्ञान के अध्ययन की यह रीति उसी समय उपयोगी हो सकती है जबकि इस प्रणाली को सावधानीपूर्वक काम में लाया जाये।

(3) तथ्यों और आकड़ों की श्रृंखला करने की आवश्यकता नहीं : इस रीति की उपयोगिता अर्थशास्त्र के उन विभागों के अध्ययन में अधिक है जिनमें आर्थिक तथ्यों एवं आकड़ों का संकलन कठिन एवं असम्भव है। विनिमय एवं वितरण विभागों में इन प्रणाली के प्रयोग द्वारा बिना आकड़ों के विशिष्ट निष्कर्षों को ज्ञात करने में अधिक सुविधा होती है।

(4) निष्कर्ष सर्वव्यापी तथा सार्वजनिक होते हैं : निगमन प्रणाली द्वारा निकाले गये निष्कर्ष सामान्य एवं सर्वमान्य सत्य पर आधारित होने के कारण सभी देशों तथा सभी वालों में सत्य होते हैं। सभी मनुष्यों की मर्यादाशीलता का निर्विवाद सत्य किसी भी काल में, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य

उतरेगा, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उपयोगिता ह्रास नियम प्रत्येक देश, प्रत्येक अवस्था तथा काल में सिद्ध होगा।

(5) पक्षपात का अभाव इस प्रणाली में तर्क-वितर्क द्वारा एक आधार-भूत सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य निकाला जाता है, घट उस निष्कर्ष पर व्यापकत विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह लाभ होता है कि आर्थिक घटनाओं का उचित तथा पक्षपात रहित विश्लेषण किया जा सकता है।

(6) भविष्यवाणी की सुविधा इस रीति से अध्ययन करने पर आर्थिक घटनाओं का अनुमान लगाना सरल होता है जिससे उनके सम्बन्ध में भविष्यवाणी सरलतापूर्वक की जा सकती है।

(7) आगमन प्रणाली द्वारा ज्ञात निष्कर्षों की जांच करने की दृष्टि से आगमन या अनुभव प्रणाली द्वारा निकाले गये निष्कर्षों अथवा प्रतिपादन नियमों की सत्यता की जांच निगमन प्रणाली द्वारा की जा सकती है। इस रीति के अनुसार उन निष्कर्षों की सामान्य सत्य मानकर उनसे विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि विशिष्ट निष्कर्ष सामान्य की पुष्टि करते हैं तो आगमन प्रणाली द्वारा प्रतिपादित नियमों को ठीक माना जा सकता है।

### निगमन रीति के दोष (Demerits of Deductive Method)

निगमन प्रणाली का उपयोग, यदि सावधानी पूर्वक नहीं किया जाए, तो वह एक दोषपूर्ण प्रणाली सिद्ध हो सकती है। इसके निम्नलिखित दोष हैं

(1) निष्कर्ष अवास्तविक एवं काल्पनिक होते हैं निगमन प्रणाली में एक काल्पनिक स्वयंमिद्ध सत्य को आधार मानकर तर्क द्वारा विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की विधि आमक है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर निकलसन का यह कथन है कि “निगमन प्रणाली का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सत्यता की जांच करने का अदृष्टिकरण काय कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता।”<sup>1</sup> यही कारण है कि इसके अनुसार निकाले गये निष्कर्षों की वास्तविक घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक नहीं कि निगमन प्रणाली के आदर्श तथ्य प्रत्येक देश, काल तथा अवस्था में उपस्थित हो। इसके साथ ही साथ सामान्य सत्य की सत्यता का पता लगाना अथवा उसके आदर्श स्वरूप को निर्धारित करना भी एक कठिन कार्य है। इन परिस्थितियों में ये आदर्श सार्वव्यापी तथा सार्वकालीन नहीं हो सकते। ये वास्तविकता के विपरीत होय और आधार नुतिपूर्ण होने पर निकाले गए निष्कर्ष भी गलत होंगे।

(2) तथ्यों और आंकड़ों के अभाव में सही निष्कर्ष निकलना कठिन है इस प्रणाली का एक दोष यह भी है कि आधारभूत सत्य की परखने तथा उसकी जांच

<sup>1</sup> “The great danger of the deductive method lies in the natural aversion of the labour of verification”

करने की कोई विधि नहीं है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने एक अमूर्त तथा काल्पनिक सत्य को वास्तविक मानकर उसके आधार पर विशिष्ट सत्य ज्ञात करने की चेष्टा की।<sup>2</sup> यदि वे तर्क के स्थान पर वास्तविक तथ्यों के आधार पर स्वीकार किए गये सामान्य सत्य की वास्तविकता को परख लेते, तो विशिष्ट निष्कर्षों में त्रुटियाँ होने की संभावनाएँ कम हो जानी।

(3) यह रीति अपूर्ण है निगमन रीति के समर्थकों ने सामान्य सत्य को ही विशिष्ट सत्य या निष्कर्ष निकालने के लिये निर्णायक माना है। वे उसको परिवर्तनशील नहीं मानते। अतः सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन तथा उनके प्रभाव का ज्ञान, इससे प्राप्त नहीं हो पाता। विशिष्ट निष्कर्षों को ज्ञात करने के लिए परिवर्तनशील सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो केवल अनुभव या आगमन रीति (Inductive Method) से ही सम्भव है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि निगमन रीति स्वयं में अपूर्ण एवं अपर्याप्त है।

(4) सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सम्भव नहीं : इस रीति द्वारा अर्थशास्त्र की सभी समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। आर्थिक-नियोजन, बेरोजगार, आर्थिक विषमता आदि के अध्ययन के लिये यह रीति उपयुक्त नहीं है। अतः केवल इसी रीति पर निर्भर रहने से, अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है।

इन दोषों के होते हुए भी, निगमन प्रणाली कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। यदि इस रीति का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाय तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। *Carnes* ने इन रीति के सम्बन्ध में कहा है :

“The method of deduction is incomparable when conducted under proper checks, the most powerful instrument of discovery ever wielded by human intelligence.” —*Carnes*

## 2. आगमन रीति (Inductive Method)

इनके प्रसृत तथ्यों के निरीक्षण, अध्ययन एवं प्रयोग करने के पश्चात् विशिष्ट निष्कर्ष निकालने जाते हैं और अन्त में इन विशिष्ट निष्कर्षों की एक रूपता की जाच करके सामान्य सिद्धान्तों या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार आगमन पद्धति के अनुसार हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य (from the particular to general) की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस पद्धति

<sup>2</sup> “The mistake of the Classical School did not consist in too frequent use of the abstract method, but having too often mistaken the abstract for reality.” —*Gide*

को प्रायोगिक पद्धति (Experimental Method) भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ जब हम माँग में वृद्धि के कारणों का अध्ययन करते हैं तब हमें यह ज्ञात होना है कि विभिन्न वस्तुओं का मूल्य कम होने पर पहले की अपेक्षा माँग बढ़ गई है। अतः इन विशिष्ट तथ्यों से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर हम सामान्य नियम का प्रतिपादन कर दिया गया है कि वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने पर उनकी माँग बढ़ जाती है।

जिन आर्थिक घटनाओं के सम्बन्ध में प्रयोग सम्भव है वहाँ प्रायोगिक विधि से अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसी भी घटनाएँ या आर्थिक तथ्य हैं जिनके सम्बन्ध में केवल ऐतिहासिक एवं वास्तविक घटनाओं को ही आधार मानकर विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनके अनुसार सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस रीति को ऐतिहासिक प्रणाली (Historical Method) कहने का एक कारण यह भी है कि निम्न प्रणाली का वर्णन करने वाले जर्मनी के ऐतिहासिक स्कूल (Historical School) के अनुयायी विद्वानों ने आर्थिक नियमों के निर्माण में इस रीति को अधिक महत्त्व प्रदान किया था। इन विद्वानों में रोसर, हिल्डब्रैंड (Hildebrand) तथा फ्रेडरिक लिस्ट के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक स्कूल के इन विद्वानों द्वारा अस्वीकार की गई इस प्रणाली के समर्थकों में इंग्लैंड के क्लिफ लीसली (Cliff Leslie) का नाम भी सम्मिलित किया जाता है। परन्तु इस प्रणाली का उपयोग पहले भी किया था। एडम स्मिथ ने कई स्थानों पर इस रीति का अनुकरण किया है और माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त इसी विधि पर आधारित है।

आगमन रीति को 'प्रायोगिक रीति' (Experimental Method), 'वास्तविक रीति' (Realistic Method) तथा 'सांख्यिकी रीति' (Statistical Method) भी कहते हैं।

### आगमन रीति के गुण (Merits of Inductive Method)

(1) निकाले गये निष्कर्षों का वास्तविक होना परीक्षण और प्रयोग के आधार पर आर्थिक घटनाओं और तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करने पर या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे सत्य होते हैं। दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का हल अनुभव के आधार पर सही रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इन विशिष्ट निष्कर्षों को लेकर स्थापित किया सामान्य सत्य भी वास्तविक से भिन्न नहीं होगा।

(2) निष्कर्षों की जाँच सम्भव है। आगमन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि किसी भी निष्कर्ष की सत्यता की जाँच प्रयोगों द्वारा की जा सकती है।

वर्तमान युग में 'आर्थिकी' ने इस कार्य को मुगम बना दिया है। तथ्यों का संग्रह कर यथार्थता की जांच कर तो जाती है जिसमें किसी भी निष्कर्ष के गलत होने की सम्भावना नहीं रहती।

(3) नियमन प्रणाली का पूरक होना : आगमन प्रणाली की अवलोकन एवं प्रायोगिक विधि से निगमन प्रणाली के सामान्य मूल्य की वास्तविकता एवं यथार्थता की जांच करके उसकी पुष्टि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आगमन प्रणाली द्वारा निगमन प्रणाली के आधारभूत मूल्यों में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके उनको प्रामाणिक बना सकते हैं तथा उनको उपयोग में ला सकते हैं।

(4) एक प्रारंभिक विधि आगमन रीति प्रारंभिक दृष्टिकोण (Dynamic Approach) पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि यह रीति इस मान्यता को मानती है कि आर्थिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अतः आर्थिक नियम बनाते समय इन परिवर्तनशील परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यह रीति आर्थिक-विषयों के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण प्रदानती है जो अर्थशास्त्र के विकास के लिए अग्रगण्य है।

**आगमन रीति के दोष (Demerits of Inductive Method) :**

(1) सरल नहीं है : इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि सर्व-साधारण इस प्रणाली का प्रयोग नहीं कर सकता। अवलोकन, प्रयोग एवं निरीक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। इसमें श्रम एवं समय का अप्रत्यक्ष भी होता है।

(2) नियमों के अस्तित्व होने की सम्भावना : इस प्रणाली का दूसरा दोष यह है कि सकलित सूचनाओं तथा आकड़ों के अपर्याप्त तथा अविश्वसनीय होने पर उनसे निकाले गये निष्कर्ष भी अशुद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का दोष भी है। यदि एकत्र किए गए आकड़ों अथवा तथ्यों की इच्छानुसार व्याख्या तथा विवेचना की जाये और उनसे मनमाने परिणाम निकाले जायें तो वे वास्तविकता से परे होंगे। इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सदैव मिथ्या नहीं होते हैं।

(3) आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में प्रायोगिक विधि की अनुपयोगिता : कई आर्थिक समस्याएँ अधिक जटिल होती हैं जिनको प्रभावित करने वाली ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो एक दूसरे से इतनी अधिक मिश्रित हैं कि उनका अनु-अनु अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये समस्याएँ सामाजिक होती हैं जिनका सम्बन्ध मनुष्य से होता है। चूंकि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील तथा सामाजिक वातावरण से प्रभावित होने वाली होती हैं, अतः आर्थिक समस्याओं

एव तथ्यों के प्रयोगों की सम्भावनायें न्यूनतम हैं। मनुष्य के भौतिक कल्याण सम्बन्धी जटिल आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए, जिनके सम्बन्ध में व्यापक निष्कर्ष निकालना कठिन है, आगमन प्रणाली अनुपयुक्त है। इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियमन प्रणाली ही सहायक सिद्ध हो सकती है।

(4) केवल आगमन रीति का प्रयोग अपर्याप्त अर्थशास्त्र का विकास केवल आगमन रीति द्वारा ही संभव नहीं है। किसी भी विज्ञान का विकास केवल तथ्यों के संग्रह तथा परीक्षण द्वारा ही नहीं होता है, जैसा कि जेवन्स ने कहा है।

“Though observation and induction must ever be the ground of all certain knowledge of nature, their unaided employment could never have led to the results of modern science” —Jevons

वस्तुतः विज्ञान के विकास के लिए आगमन के साथ ही साथ निगमन रीति की भी आवश्यकता पड़ती है।

### 3 अध्ययन की रीतियों के सम्बन्ध में विवाद (Controversy over the Methods of Study)

अर्थशास्त्र में समय-समय पर निगमन तथा आगमन रीतियों का प्रयोग किया गया है। परंतु यह प्रश्न उठता है कि कौन सी रीति अधिक उपयुक्त है? इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद रहा है। प्राचीन या प्रतिष्ठित अग्रज अर्थशास्त्रियों ने निगमन या अनुमान प्रणाली को ही अधिक महत्व दिया था, क्योंकि (i) उस समय वे आर्थिक तथ्यों के सम्बन्ध में निश्चितता (certainty) स्थापित करना चाहते थे, उनका मत था कि निश्चितता निगमन प्रणाली द्वारा ही संभव है, (ii) उस समय के विद्वानों का यह मत था कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुष्य होने के कारण उस पर प्रयोग संभव नहीं है। (iii) उस समय अर्थशास्त्र या सांख्यिकी (Statistics) का विकास नहीं हुआ था जिससे अवलोकन या निरीक्षण की विधि को अपनाया संभव नहीं था, (iv) निगमन प्रणाली के समर्थक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र तथा तर्कशास्त्र के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध मानते थे। यही कारण है कि वे निगमन प्रणाली के अनुसार निकाले गये निष्कर्षों की त्रुटियों (Fallacies) को दूर करने के लिए तर्कशास्त्र के नियमों को ही उपयोग में लाने की राय देते थे। परन्तु प्राचीन अंग्रेज अर्थशास्त्रियों द्वारा निगमन प्रणाली को अधिक महत्व देने का परिणाम यह हुआ कि अर्थशास्त्र एक अव्यावहारिक एवं अवास्तविक विज्ञान माना जाने लगा।

19वीं शताब्दी में जर्मनी के ऐतिहासिक स्कूल के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। उन्होंने प्राचीन अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों के इस विचार का खण्डन किया कि निगमन प्रणाली ही



आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त रीति है। ऐतिहासिक स्कूल के अर्थशास्त्रियों का मत था कि नियमन प्रणाली अर्थशास्त्र को औपचारिक तथा व्यवहारिक शास्त्र बनाने में सहायक हुई है। उसका अनुकरण करने पर निकाले गये निष्कर्ष या सत्य वास्तविकता से दूर होते हैं। उनका कथन था कि वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए आगमन विधि ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सामान्य सत्यता या स्वयं निश्चिन्तों को आधार मानकर निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक नहीं कहे जा सकते। यद्यपि जब तक आगमन या अनुभव प्रणाली के द्वारा विशिष्ट तथ्यों का निरीक्षण नहीं किया जायेगा, तब तक एक सामान्य सत्य की वास्तविकता परखी नहीं जा सकती। इस प्रकार आगमन या अनुभव प्रणाली द्वारा ज्ञात किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जाँच निगमन या अनुमान प्रणाली के सामान्य सत्य से भी करना आवश्यक है जिससे गहन धारणाओं और पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण के कारण होने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सके।

दोनों रीतियाँ आवश्यक तथा एक दूसरे की पूरक :

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन, उनके निष्कर्षों के प्रतिपादन तथा उन नियमों की जाँच करने के लिए निगमन तथा आगमन दोनों ही विधियों को साथ साथ अपनाना अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के तथ्यों अथवा उसकी समस्याओं में विभिन्नता होने के कारण उनको हल करने तथा निष्कर्षों के निकालने में दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों प्रणालियाँ वास्तव में प्रतिस्पर्द्धी (Rival) प्रणालियाँ न होकर एक दूसरे की पूरक हैं। इसी आधार पर वेगनर (Wagner) ने कहा है कि “इन विधियों में से किसी को चुनाव पाम ? इन प्रश्नों का वास्तविक हल आगमन तथा निगमन विधियों में किसी एक का चुनाव करने से नहीं, बल्कि दोनों को अपनाने से ही हो सकता है।”<sup>3</sup> मार्शल ने इस पूरक तत्व का स्पष्ट करते हुए शमोलर (Schmoller) के उस कथन का उल्लेख किया है जिसमें यह कहा गया कि “जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बाएँ दोनों पैरों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अर्थ विज्ञान के अध्ययन के लिए निगमन तथा आगमन दोनों ही रीतियों की आवश्यकता पड़ती है।”

“Induction and deduction are both necessary for scientific thought just as the right and the left foot, both are needed for walking”  
—Schmoller

<sup>3</sup> “The true solution of the contest about method is not to be found in the selection of deduction or induction, but in acceptance of deduction and induction”  
—Wagner

जिस घटना या समस्या के सम्बन्ध में आवश्यक आकड़े उपलब्ध होते हैं और जिनके निष्कर्ष पर मानव-स्वभाव या प्रकृति का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, (बल्कि उसके सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों एवं घटनाओं को ही विशेष महत्व देने की आवश्यकता पड़ती है) उसके अध्ययन के लिए आगमन या अनुभव प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। इसमें आकड़ों के प्रयोग एवं निरीक्षण द्वारा विशेष परिस्थितियों के अनुसार निकाले गए निष्कर्ष सत्य और वास्तविकता के अनुरूप होते हैं। उदाहरणार्थ, उत्पादन और राजस्व की समस्याओं के परीक्षण एवं प्रयोग द्वारा ही उत्पत्ति ह्रास नियम, जनसंख्या मिडान्त, नियोजन तथा कर सम्बन्धी नियमों का निर्माण सम्भव हो सका है। परन्तु जहाँ पर मानव प्रकृति या स्वभाव की ही प्रधानता है और जिसका प्रयोगात्मक अध्ययन किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, वहाँ निगमन प्रणाली के अनुसार स्वयं-सिद्ध तथ्यों को आधार मानकर आगे बढ़ना होगा और विशिष्ट निष्कर्ष ज्ञात करने होंगे, जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, सीमान्त उपयोगिता नियम उपभोक्ता की वृत्त आदि।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण विषय के अध्ययन के लिए कोई एक ही विधि उपयुक्त नहीं है। दोनों ही विधियों का उपयोग आवश्यक है। यदि निगमन विधि का प्रयोग विशिष्ट निष्कर्षों या सत्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो उसके सामान्य सत्य की परख आगमन विधि के द्वारा करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आगमन विधि से विशिष्ट निष्कर्ष निकालकर किसी सामान्य सत्य की स्थापना की गयी है, तो ज्ञात निष्कर्षों की सत्यता की परख निगमन विधि की स्वयं सिद्धियों से की जाती है। यही कारण है कि प्रोफेसर मार्शल ने दोनों विधियों का नाथ-नाथ प्रयोग करने को ही अधिक उपयोगी माना है। उनका कहना है कि “लोगों की कोई भी ऐसी रीति नहीं है जिसे हम अर्थशास्त्र की रीति कह सकें बल्कि समुचित स्थान पर प्रत्येक रीति का या तो व्यक्तिगत रूप में या अन्य रीतियों के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए।”

“There is not anyone method of investigation which can properly be called the method of Economics; but every method must be made serviceable at its proper place, either singly or in combination with others.”

Marshall

आधुनिक अर्थशास्त्री इसी विचारधारा के समर्थक हैं। शमोलर (Schmoller), केन्स और वेग्नर आदि ने भी अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इन दोनों विधियों को ही आवश्यक माना है।

## प्रश्न व सकेत

1. "अन्वेषण (Investigation) की कोई भी एक ऐसी रीति नहीं है जिसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की उचित रीति कहा जा सके, बल्कि प्रत्येक का यथा-स्थान या तो सकेले या मिश्रित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।" —मार्शल।  
व्याख्या कीजिए। (Raj, 1961)

[सकेत—अन्वेषण की दोनों विधियों आगमन व निगमन की कमियां बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि दोनों के प्रयोग का उचित क्षेत्र क्या है?]

2. अर्थशास्त्र के अध्ययन में निगमन तथा आगमन प्रणालियों के प्रयोग की व्याख्या कीजिए और बताइए कि अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में उनकी उपयोगिता में क्या परिवर्तन होता है? (Raj B A, 1961, Agra B A., 1953)

[सकेत—दोनों विधियों के प्रयोग बताइए तथा अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में उनकी उपादेयता का विवेचन कीजिए।]

3. आर्थिक नियमों को निकालने की रीतियां बताइए। क्या ये रीतियां एक दूसरे की सहायक होती हैं? (Raj B. A., 1964)

[सकेत—दोनों विधियों (आगमन व निगमन) का विवेचन कीजिए तथा दोनों की परस्पर भिन्नता बताइए।]

4. आगमन व निगमन विधि की सविस्तार आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

# 7

## अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति (Nature of Economic Laws)

*"The propositions of Economics are on all fours with the propositions of all other Sciences"*

—Robbins

प्रत्येक विज्ञान के कुछ नियम होते हैं, जिनके आधार पर उस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये नियम सामान्यतया कारण-परिणाम के सम्बन्धों को व्यक्त करते हैं (Law is a statement of a causal relationship between two sets of phenomena)। 'नियम सामान्य कथन या सामान्य प्रवृत्ति के प्रतीक होते हैं जो लगभग सत्य तथा निश्चित होते हैं।' <sup>1</sup> 'नियम' शब्द का प्रयोग भी विभिन्न अर्थों में किया जाता है।

खेलकूद में नियम बद्ध आचरण आवश्यक है, देश में शांति बनाये रखने के लिए सरकारी कानून अनिवार्य हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत सुख के लिए मानाजिक एवं नैतिक आदर्शों को मानना आवश्यक है। प्राकृतिक विज्ञानों में कुछ नियमों तथा निर्दिष्ट सूत्रों (Formulae) के होने से वैज्ञानिक परिस्थितियों का अध्ययन सरल हो जाता है। नियमों की इसी प्रकार की उपयोगिता के कारण ही अर्थशास्त्र के भी कुछ 'आर्थिक नियम' हैं। ये आर्थिक नियम आर्थिक घटनाओं एवं परिस्थितियों के 'कारण और परिणाम' के आधार पर उनके पारस्परिक एवं सापेक्षिक सम्बन्ध का उल्लेख करते हैं।

1 "The term 'law' means then, nothing more than the general proposition or statement of tendencies, more or less certain, more or less definite."

—Marshall

## 1. नियमों का वर्गीकरण

ज्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा वैज्ञानिक नियमों के अतिरिक्त 'आदेश भूतक', 'संस्थागत' तथा 'नैतिक' नियम भी होते हैं। इन नियमों की अपनी अलग विशेषताएँ होती हैं।

1. सरकारी कानून या नियम (Statutory Laws) : देश का शासन चलाने तथा नागरिकों के वर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम सरकारी नियम अथवा कानून कहलाते हैं। इन नियमों का क्षेत्र किसी एक देश तक ही सीमित रहता है। सरकार अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इनमें समय-समय पर परिवर्तन करती रहती है। प्रत्येक देश में कहा जा सकता है कि सरकारी कानून स्थायी नहीं रहते। देश के किसी भी नागरिक के लिए इन नियमों का पालन न करना अपराध माना जाता है और अपराधी व्यक्ति दण्ड का भागी होता है।

2. सामाजिक अथवा संस्थागत नियम (Social or Institutional Laws) : किसी संस्था या समाज-विशेष के द्वारा अपने सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों तथा संस्था या समाज के कार्यों को विधिवत् चलाने के लिए बनाए गए नियम, सामाजिक एवं संस्थागत नियम कहलाते हैं। इन नियमों में भी समाज या संस्था के सदस्यों की दृष्टानुसार परिवर्तन किया जाता है। इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है।

3. प्रभामूलक या नैतिक नियम (Moral or Religious Laws) : नैतिक नियम अर्थात् एक सदाचार पर आधारित होते हैं। इनका सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक तथा वैयक्तिक आचरण से होता है, क्योंकि ये मानव जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करते हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। नैतिक आदर्शों, देश, काल और समाज की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते। इनकी सत्यता सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन होती है।

4. वैज्ञानिक नियम (Scientific Laws) : वैज्ञानिक नियम दो घटनाओं और परिस्थितियों के कारण—परिणाम (Cause and Effect) के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या करते हैं। इसका प्रतिपादन परीक्षण एवं अवलोकन द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों (Natural Sciences) जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से सम्बन्धित नियम सर्वत्र तथा सर्वदा सत्य उत्तरते हैं। उदाहरणार्थ, गुरुत्वाकर्षण का नियम (Law of Gravitation) इस तथ्य का उल्लेख करता है कि यदि किसी वस्तु को ऊपर उड़ाया जाय तो वह पृथ्वी पर आ गिरती है। प्रथम घटना किसी वस्तु को ऊपर उड़ाया जाना है जिसके कारण ही पृथ्वी पर आ गिरती है। वस्तु का गिरना एक परिणाम के रूप में द्वितीय घटना है।

दोनों घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या गुह्यत्वाकर्षण नियम द्वारा की जाती है।

## 1 आर्थिक नियमों की परिभाषा

आर्थिक नियमों को भी वैज्ञानिक नियमों के वर्ग में रखा गया है। आर्थिक नियम आर्थिक घटनाओं तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण—परिणाम के पारस्परिक एवं आपेक्षिक सम्बन्ध का उल्लेख करने वाले सामान्य कथन होते हैं। मार्शल ने अनुसार, “आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन, वे सामाजिक नियम हैं जिनका सम्बन्ध आचरण की उन शालाओं से है जिन्हें सम्बन्धित मनो धृत्तियों की शक्ति की माप मुद्रा-मूल्य द्वारा की जा सकती है।”

“Economic Laws or statements of economic tendencies are those social laws relating to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by a money price”  
—Marshall

मार्शल ने ‘आर्थिक-प्रवृत्तियों’ पर जोर दिया है। राबिन्स ने ‘मानव व्यवहार’ की चुनाव प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। राबिन्स के अनुसार, “आर्थिक नियम मानव व्यवहार की एकरूपताओं से सम्बन्धित कथन हैं, जिन पर सीमित साधनों द्वारा, असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित मानव-व्यवहार निर्भर होता है”।

“Economic laws are statements of uniformities about human behaviour concerning the disposal of scarce means with alternative uses for the achievement of ends that are unlimited” —Robbins

वैज्ञानिक नियमों की भाँति आर्थिक नियम भी कारण-परिणाम के सम्बन्धों को प्रकट करते हैं। आर्थिक नियम आर्थिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हैं। ये नियम यह बतलाते हैं कि परिस्थिति विशेष में, अमुक कारण का क्या परिणाम होगा? जैसे मांग का नियम यह बताना है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर आर्थिक नियमों की परिभाषाओं से तीन मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं। (i) आर्थिक नियम सामाजिक नियम हैं, (ii) वे मानव प्रवृत्तियों पर आधारित हैं, तथा (iii) उनका सम्बन्ध उन्हीं प्रवृत्तियों में है, जिनके उद्देश्यों को मुद्रा द्वारा नापा जा सकता है। (ये लक्षण मार्शल की परिभाषा पर आधारित हैं।)

## 2 आर्थिक नियमों की प्रकृति या विशेषताएं

(Nature of Economic Laws)

कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र के नियमों पर कई आक्षेप लगाये हैं। उनका कथन है कि आर्थिक नियमों की सत्यता जब अन्य बातों के यथावत रहने पर ही

निर्भर है तब उनमें व्यावहारिकता एवं निश्चितता का अभाव है। उनके विचार में इन्हें काल्पनिक कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। आर्थिक नियमों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं •

1 आर्थिक नियम काल्पनिक हैं (Hypothetical) : आर्थिक नियम निश्चित परिस्थितियों में ही सत्य होते हैं। इनकी सत्यता सदैव और सर्वत्र प्रमाणित नहीं हो पाती। वैज्ञानिक नियमों के समान परीक्षण और अवलोकन द्वारा निश्चित एवं सही निष्कर्ष निकालना कठिन है। परिवर्तनशील मानवीय प्रवृत्तियों से सम्बन्धित सिद्धांत या अनुमान कभी भी निश्चित और पूर्ण नहीं हो सकते। इनमें 'अन्य बातों के समान रहने' (Other things being equal) की शर्तें लगी होती हैं। इस शर्त के जुड़े रहने के कारण ही सेल्सियस ने आर्थिक नियमों को काल्पनिक माना है।<sup>2</sup>

परन्तु यदि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की प्रकृति से आर्थिक नियमों की प्रकृति की तुलना की जाये तो यह ज्ञात होता है कि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों में भी अनिश्चितता, अपूर्णता तथा कल्पना का तत्त्व पाया जाता है।<sup>3</sup> वास्तव में वैज्ञानिक नियम 'यदि अन्य बातें ब्यावत रहे' की मान्यता पर ही आधारित हैं। उदाहरणार्थ, गुरुत्वाकर्षण का नियम (Law of gravitation) पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का उल्लेख करता है। यह इस तथ्य की व्याख्या करता है कि कितनी वस्तु की ऊपर उछालने पर वह नीचे गिरेगी। परन्तु यदि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दी जाय तो वह नीचे आने के स्थान पर ऊपर ही उठता जायेगा। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की परिधि या सीमा के बाहर चले जाने पर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। इससे यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक नियमों की सत्यता भी कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही प्रमाणित की जा सकती है। अतः वैज्ञानिक नियमों को भी काल्पनिक कहा जा सकता है। परन्तु इस दृष्टिकोण से दोनों विज्ञानों—प्राकृतिक तथा अर्थ-शास्त्र—के नियमों में केवल इतना ही अन्तर है कि वैज्ञानिक नियम उतने काल्पनिक नहीं होते जितने कि आर्थिक नियम। (अर्थशास्त्र के सभी नियम काल्पनिक नहीं हैं।)

2. अर्थशास्त्र के नियमों का कम निश्चित होना आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के नियम

<sup>2</sup> "Economic Laws are essentially hypothetical" —Seligman

<sup>3</sup> "They (Economic Laws) are hypothetical only in the same sense as are the laws of physical science, for these laws also contain or imply conditions. But there is more difficulty in making the conditions clear, and more danger in any failure to do so in economics than in physics"

—Marshall

व्यापक एवं निश्चित होते हैं, परन्तु आर्थिक नियम सर्वत्र तथा सदैव ही निश्चित रूप से लागू नहीं होते। रसायन शास्त्र का यह सिद्धांत कि आक्सीजन और हाइड्रोजन को यदि 2 और 1 के अनुपात में मिलाया जाय तो एक निश्चित दबाव और तापमान पर उनका मिश्रण पानी में परिवर्तित हो जायेगा यह परिणाम सर्वत्र और सभी समयों में निश्चित रूप से सही निकलेगा। परन्तु अर्थशास्त्र के 'माग के नियम' के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाये कि 'किसी वस्तु के मंहगे होने पर लोग उसे खरीदना बन्द कर देगे तो व्यावहारिक रूप में यह देखने को मिलेगा कि वास्तविकता यह नहीं है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी देश प्रेम की भावना में मस्ती विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा लोग देश में निर्मित मंहगी वस्तुओं को खरीदते हैं। इस उदाहरण में यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियमों की क्रियाशीलता में निश्चितता की कमी है।

3 आर्थिक नियम पूर्ण (Exact) नहीं हैं : आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह पूर्ण और सही (Exact) भी नहीं हैं। आर्थिक परिस्थितियों एवं घटनाओं और मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन होने के कारण उनके अनुमान निश्चित रूप से सही नहीं उतरते। इनमें गणितात्मक शुद्धता (Mathematical Exactness) का अभाव है। उदाहरणार्थ, रसायन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यदि आक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्राएं दुगुनी कर दी जायें तो प्राप्त पानी की मात्रा भी दुगुनी हो जायेगी। परन्तु इसके विपरीत यदि यह कहा जाये कि किसी वस्तु के मूल्य में दुगुनी वृद्धि हो जाने पर उसकी माग घटकर आधी रह जायेगी, तो यह कथन पूर्णतः सही नहीं होगा। इन दोनों परिस्थितियों में एक निश्चित एवं पूर्ण गणितात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। आर्थिक नियम केवल किसी एक विशेष कारण के होने वाले परिणाम या प्रभाव के स्वरूप, प्रकृति (Nature of Effect) तथा दिशा का अनुमान ही लगा सकते हैं,<sup>4</sup> जो व्यापक रूप में पूर्णतः सत्य नहीं होते।

4. आर्थिक नियम सापेक्षिक हैं (Economic Laws are Relative)  
आर्थिक नियमों को भी दो वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग ऐसे आर्थिक नियमों का है जिनमें सार्वभौमिक नियम (Universal Laws) आते हैं। अतः ये नियम सर्वत्र और सदैव एक ही प्रकार से क्रियाशील होते हैं। उदाहरणार्थ, 'माग और पूर्ति' का नियम सार्वभौमिक नियम है।

\* "They (economic laws) are qualitative rather than quantitative, they tell the kind or direction of change that is expected rather than the amount of change."



द्वितीय वर्ग उन आर्थिक नियमों का है जो सापेक्षिक (Relative) हैं। ये समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील हैं। ये सार्वभौमिक तथा सार्वजालिक नहीं होते। वैकिंग, बर्सेसी तथा व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले सभी आर्थिक नियम इसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयों में प्रचलित आर्थिक संगठन तथा व्यापार एवं उद्योग की भिन्न-भिन्न पद्धतियों पर आधारित होते हैं। अतः ये समय तथा स्थान के आधार पर सापेक्षिक मान जाते हैं। इन नियमों का प्रतिपादन 'अनुभव रीति' (Inductive Method) द्वारा किया जाता है और अधिकांश आर्थिक नियम इसी वर्ग में आते हैं।

### 3 आर्थिक नियमों की अपूर्णता के कारण (Why Economic Laws are Less Exact ?)

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति पूर्णतः निश्चित एवं सही नहीं होते, इसके निम्नलिखित कारण हैं -

1 अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील मानवीय प्रवृत्तियों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुष्य है और प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की सामग्री 'पदार्थ' (Matter) है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, जिसकी भावनाएँ परिवर्तनशील होती हैं। उसके व्यवहार केवल आर्थिक भावनाओं से ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उस पर धार्मिक भावनाओं जैसे वैश्व प्रेम, स्नेह, दया भक्ति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। वह एक स्वतन्त्र तत्त्व एवं वृद्धिशील प्राणी है। अतः मानवीय भावनाएँ और मानवीय प्रवृत्तियाँ सर्वत्र तथा सर्वदा एक सी नहीं रहती। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ अपरिवर्तनशील, जड़, निर्जीव और अचेतन होते हैं। इनका प्रयोग, परीक्षण एवं विश्लेषण करना सरल होता है। इन पर समय और स्थान की भिन्नता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः प्राकृतिक पदार्थों से सम्बन्धित नियम प्रामाणिक एवं सत्य उतरते हैं।

विषय-सामग्री में अन्तर होने के कारण आर्थिक नियमों तथा प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। आर्थिक नियमों का सम्बन्ध मनुष्य के उन व्यवहारों के आर्थिक पक्ष से है जो समय-समय पर और स्थान-स्थान पर अल्प और आर्थिक भावनाओं से भी प्रभावित होते रहते हैं, अतः ये नियम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होते।

2. आर्थिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशालाओं में सम्भव नहीं है - प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की सत्यता की जाँच प्रयोगशालाओं में प्रयोग तथा परीक्षण करके की जा सकती है। वैज्ञानिक तत्वों में समान प्रकृति पायी जाती है और इसकी खोज करके एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन किया जा सकता है। परन्तु आर्थिक

नियमों की सत्यता की जांच के लिए मानवीय क्रियाओं पर प्रयोग करना कठिन है और न उनके परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला ही है। समस्त मानव समाज की आर्थिक क्रियाएँ प्रयोग की सामग्री हैं, अतः उनकी सत्यता प्रमाणित करना एक कठिन कार्य है। यही कारण है कि आर्थिक नियम पूर्णतः प्रामाणिक तथा सत्य नहीं होते।

3. अर्थशास्त्र में मानव प्रवृत्तियों का मापदण्ड प्रामाणिक नहीं है : अर्थशास्त्र में मानव-प्रवृत्तियों की माप मुद्रा द्वारा की जाती है। मुद्रा को मापदण्ड के रूप में प्रयोग करने के कारण ही मनुष्य की आर्थिक प्रवृत्तियों की सही माप ज्ञात नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता उसके द्वारा खर्च की जाने वाली मुद्रा की मात्रा से ज्ञात की जाती है। परन्तु खर्च की जाने वाली मुद्रा की मात्रा का अनुमान लगाते समय एक धनी व्यक्ति की तुलना में एक निधन व्यक्ति के लिए सीमित मुद्रा की उपयोगिता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इसके अनिश्चित मुद्रा की क्रय-शक्ति अथ्य वस्तुओं के मूल्यों के सहज 'माग और पूर्ति' के नियम के अनुसार परिवर्तनशील है। अतः जब स्वयं मापदण्ड की क्रय-शक्ति अनिश्चित हो तो उसके द्वारा आर्थिक प्रवृत्तियों का माप करके निकाले गए निष्कर्ष या अनुमान भी निश्चिन्, सांख्यिक तथा पूर्ण नहीं हो सकते।

4. अर्थ तत्वों का प्रभाव : जैसा पहले कहा जा चुका है, अर्थशास्त्र में मानव प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है जो परिवर्तनशील होती हैं। साथ ही साथ मानव व्यवहार केवल सामान्य प्रवृत्तियों से ही प्रभावित नहीं होता है। कुछ मनो वैज्ञानिक तत्व आर्थिक क्रियाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। ये तत्व हैं मविष्य के प्रति आशा या निराशा की भावना। आशा व निराशा के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और न उन्हें मापा हो जा सकता है। मन्दी (Depression) के समय अर्थशास्त्री परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सोचता है कि आर्थिक-मविष्य ठीक नहीं है परन्तु किसी कारणवश यदि व्यापारी वर्ग में आशा का संचार हो जाता है तो मन्दी समाप्त होने लगती है। अर्थशास्त्र में ऐसे अनिश्चित तत्वों की जानकारी और माप के लिए कोई मापक नहीं है अतः इन तत्वों की जानकारी के न होने के कारण आर्थिक नियम सत्य नहीं सिद्ध होते हैं। मूर ने कहा है, "अर्थशास्त्र में कोई ऐसा सुविधानजनक मापक नहीं है जिससे व्यावसायिक कार्यों के प्रवाह को मापा जा सके क्योंकि व्यावसायिक कार्य भय एवं हास्यप्रद आशावाद के मोड़ों से भी प्रभावित होते हैं, जिनके विषय में भूकम्प की ही भांति मविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।"<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 'In Economics, there is no convenient yardstick by which to measure the currents in business affairs for these are subject to gusts of fear or perhaps of fantastic optimism as unpredictable as earthquakes' Moore & others Modern Economics

वास्तव में अब तक, आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले सभी तत्व ज्ञात नहीं हो पाए हैं। इन अज्ञात तत्वों की जानकारी के बिना की गई भविष्यवाणियाँ भी सतत सिद्ध हो जाती हैं।

#### 4 क्या अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान है ?

( Is Economics an Exact Science ? )

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र के नियम मानव-व्यवहारों, प्रवृत्तियों तथा अन्य अनिश्चित तत्वों पर आधारित होने के कारण पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध नहीं होत है। आर्थिक नियमों की इस सीमा (Limitation) के कारण क्या अर्थशास्त्र को एक निश्चित विज्ञान कहना चाहिए ? राबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक शुद्ध विज्ञान माना है तथा यह विचार प्रकट किया है कि अर्थशास्त्र के नियम, उन्ही प्रकार सत्य हैं जिस प्रकार विज्ञान के नियम। उन्होंने कहा है, 'अर्थशास्त्र के नियम अन्य विज्ञानों के नियमों के पूर्णतया समान हैं।' यदि पूर्णतया सत्य दिए हुए हों तो, उन पर आधारित परिणाम भी सत्य होते हैं।

"Economic laws are on all fours with the propositions of all other sciences. If the data they postulate are given, then the consequences they predict necessarily follow"

—Robbins

आर्थिक नियमों की सत्यता के आधार पर भी अर्थशास्त्र को निश्चित विज्ञान कहा जा सकता है।

1 अधिकांश आर्थिक नियम पूर्ण तथा सत्य हैं सभी आर्थिक नियम एक जैसे नहीं होते हैं। (1) Stable Laws : अर्थशास्त्र में कुछ नियम ऐसे हैं, जो प्रकृति पर अधिक निर्भर हैं, ऐसे नियम सार्वभौमिक तथा उसी प्रकार सत्य हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान के नियम जैसे उत्पादन हानि नियम। (2) Unstable Laws द्वितीय वर्ग में अर्थशास्त्र के वे नियम आते हैं जो मानव प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। ये नियम सापेक्षिक (Relative) हैं तथा समय व स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। वे पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि वे कुछ जतों पर आधारित होते हैं, जैसे 'भाग का नियम' (iii) {Laws dependent upon basic human nature} मानव प्रवृत्तियों पर भी आधारित सभी नियम कम सत्य नहीं होते हैं। मानव-प्रवृत्ति में भी कुछ मौलिक तत्व होते हैं, जो सभी स्थान व समय में समान रहते हैं। मानव प्रवृत्ति की इन मौलिक प्रवृत्तियों पर आधारित नियम भी सार्वभौमिक होते हैं, जैसे जेजम का उपयोगिता हानि नियम, आवश्यकताओं के बीच चुनाव सम्बन्धी नियम।

आर्थिक नियमों के उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रथम तथा तृतीय वर्ग के नियम पूर्णतया सत्य होते हैं उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार अन्य विज्ञानों के नियम।

2. सामूहिक व्यवहार के सम्बन्ध में भविष्यवाणी सभव (Group behaviour is predictable) ऊपर, द्वितीय वर्ग के नियमों के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि मानव प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण ये नियम सार्वभौमिक नहीं होते हैं। यद्यपि ये नियम प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में सही नहीं होते हैं परन्तु समूह (Group) पर ये नियम भी सत्य सिद्ध होते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति किसी नियम के विरुद्ध व्यवहार कर सकता है, परन्तु सामूहिक-व्यवहार, नियम के अनुकूल ही है। आर्थिक नियम सामान्य तथा औचित्य रूप से अवश्य लागू होते हैं। अतः समूह के सदस्यों में आर्थिक नियमों की सत्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान तथ्यों के आधार पर सही भविष्यवाणी करना, वैज्ञानिक नियमों की प्रमुख विशेषता है। अर्थशास्त्र के नियमों पर आधारित, समुदाय के विषय में की गई भविष्यवाणियाँ सामान्यतया सही नहीं होती हैं। अतः द्वितीय वर्ग के आर्थिक नियमों में भी वैज्ञानिक नियमों के तत्त्व मौजूद हैं।

3. वैज्ञानिक नियम भी शर्तों पर आधारित : आर्थिक विषयों की सबसे अधिक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वे सर्वत्र सत्य शर्तों पर आधारित होते हैं अतः उन्हें सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता है। परन्तु अन्य विज्ञानों के नियमों में भी शर्तें होती हैं। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी यह मान कर चलता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की कोई विरोधी शक्ति क्रियाशील नहीं है। इस प्रकार हम, केवल शर्त के आधार पर, आर्थिक विषयों को अनिश्चित नहीं कह सकते हैं। आर्थिक नियम भी अपनी शर्तों के सदस्यों में ही पूर्ण सत्य सिद्ध होते हैं।<sup>6</sup>

4. केवल भौतिक-शास्त्र व रसायन शास्त्र के नियमों से तुलना अनुचित अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना केवल भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के नियमों से ही करके, उन्हें कम सत्य प्रमाणित करना ठीक नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में भी अतिरिक्त विज्ञान (Meteorology) तथा जीवन-विज्ञान (Biology) के नियम भौतिक शास्त्र के नियमों की भाँति सत्य नहीं होते हैं, जैसे अतिरिक्त विज्ञान की मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। इससे केवल समाधान का ही ज्ञान होता है। जब समाधानों का विज्ञान (Science of Probabilities) होता है तो अतिरिक्त विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है तो अर्थशास्त्र को किस तर्क के आधार पर हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे ?

<sup>6</sup> "There is no difference whatsoever between the nature of economic laws and that of the laws of the physical science...and in so far as they follow logically or mathematically from their assumptions, they are both equally exact or accurate also in themselves" Mehta, Rudra & others, 'Fundamentals of Economics' P 16"

5 अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा आर्थिक नियम अधिक सत्य : अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अर्थशास्त्र के नियम अधिक पूर्ण, निश्चित और सही होते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की क्रियाओं के आर्थिक पहलू का मापदण्ड मुद्रा है, जबकि अन्य सामाजिक शास्त्रों में मानवीय क्रियाओं की मापने के लिए कोई भी मापदण्ड नहीं है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में प्रतिपादित नियमों की एक निश्चित सामान्य कवच के रूप में कार्य कारण के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करने में सुविधा होती है। मुद्रा सर्वत्र और सदैव प्रयुक्त होती है, मत. मुद्रा के मापदण्ड के आधार पर अनुमानित आर्थिक नियम अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं निश्चित माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में मार्शल का यह कथन उल्लेखनीय है : 'जिम प्रकार रसायनशास्त्री की शुद्ध तराजू ने रसायनशास्त्र को अन्य भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं शुद्ध बना दिया है उसी प्रकार अर्थशास्त्र को इस (मुद्रा रूपी) तराजू ने, चाहे वह कितनी ही भरी और अपूर्ण क्यों न हो, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की अन्य किसी भी शाखा की तुलना में अधिक पूर्ण एवं निश्चित बनाया है।'<sup>7</sup>

मार्शल द्वारा आर्थिक नियमों की वास्तविक प्रकृति पर प्रभाव प्रो० मार्शल का मत है कि आर्थिक नियमों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात करने के लिए, उनकी तुलना प्राकृतिक विज्ञान के मरल तथा निश्चित गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त से न करके, ज्वार-भाटे के नियम से करना चाहिए।

"The laws of economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact law of gravitation"  
— Marshall

आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार-भाटे के नियम से करने पर उनकी प्रकृति का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाता है। इसका कारण यह है कि ज्वार-भाटे का नियम होने यह ज्ञात करता है कि चन्द्रमा के आकार में वृद्धि होने से बहरो के चढ़ाव में वृद्धि होती जाती है और पूरा चन्द्र के दिन 'सम्भवतः' ज्वार सबसे अधिक ऊँचा होगा। परन्तु इस भविष्यवाणी में 'सम्भवतः' शब्द जुड़े रहने के कारण, यह स्पष्ट है कि यह नियम उन आकस्मिक प्राकृतिक परिवर्तनों जैसे आघी, तूफान, अत्यधिक वर्षा आदि का दृष्टिगत रहता है जिनके कारण पूर्ण चन्द्र के दिन भी अत्यधिक ज्वार रहने की सम्भावना निश्चित नहीं है। ठीक यही स्थिति आर्थिक नियमों की भी है। जिस प्रकार ज्वार भाटे के सम्बन्ध में भी कई भविष्यवाणी सामान्य

7 "Just as the chemist's fine balance has made chemistry more exact than other physical sciences, so this economist's balance, rough and imperfect it is, has made Economics more exact than any other branch of social sciences."  
— Marshall

परिस्थितियों तथा अन्य बातों के यथावत् रहने पर ही सही उत्तरनी है और प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर उसके सही होने की सम्भावना नहीं रहती, उसी प्रकार आर्थिक नियमों के अनुमान सामान्य परिस्थितियों में ही क्रियाशील होने हैं। मनुष्य के स्वभाव की स्वतन्त्रता के कारण मानव समाज की आर्थिक घटनाओं और परिस्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन होने की सम्भावनाएँ रहती हैं, अतः आर्थिक नियम आर्थिक व्यवहारों के सम्बन्ध में केवल अनुमान या सम्भावनाएँ ही व्यक्त कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के सीधे और निश्चित सिद्धान्त की तरह इसमें भी कोई भविष्यवाणी संबंध एवं सदैव ठीक नहीं होगी। अतः आर्थिक नियमों की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। इन नियमों में 'सम्भावना' का तत्त्व अधिक है और वह भी उस स्थिति में जबकि 'अन्य परिस्थितियाँ समान रहें' (Other things remaining the same)। अन शब्द का यह मत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार-भाटे के नियम से करना उचित है न कि सीधे और निश्चित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त में।

### प्रश्न व संकेत

1 आर्थिक नियमों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या ये नियम उसी प्रकार प्राप्त किये जाते हैं जिस प्रकार कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम ?

(Raj, B A. 1963)

(संकेत : आर्थिक नियमों की प्रमुख विशेषताएँ बताइए तथा आर्थिक व प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को प्राप्त करने के तरीकों में अन्तर बताइए।)

2. "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है परन्तु वह एक अनिश्चित विज्ञान (Inexact Science) है।" इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(Patna B. A, 1966 A)

(संकेत : प्रथम भाग में अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। दूसरे भाग में आर्थिक नियमों के कम निश्चित होने के कारण बताते हुए निष्कर्ष निकालिए। पृष्ठ 120-23 पर दिया गया वर्णन ध्यान में रखिए।)

3. "अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण जैसे सरल तथा सही नियमों की अपेक्षा ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिए।" विवेचना कीजिए।

(Bihar B A 1966 A)

(संकेत : आर्थिक नियमों का आशय स्पष्ट कीजिए तथा आर्थिक नियमों की विशेषताएँ बताइए। अन्त में निष्कर्ष दीजिए।)

4 आर्थिक नियमों के स्वभाव की व्याख्या कीजिए तथा उन रीतियों को भी बताइए जिनके द्वारा इन नियमों को निकाला जाता है।

(संकेत : आर्थिक नियमों का अर्थ बताइए तथा विशेषता का विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में आगमन व निगमन रीतियों का विवेचन कीजिए।)

# 8

## उपयोगिता-विश्लेषण (Utility Analysis)

*"The word 'utility' was defined, for the purposes of economic analysis, as the satisfaction, or pleasure, or benefit derived by a person from the consumption of wealth"*

—Edward Nelson

### 1. सामान्य परिचय (Introduction)

अर्थशास्त्र में उपयोगिता विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। उपयोगिता का सम्बन्ध उपभोक्ता से होता है। उपभोक्ता का अर्थ किसी भी व्यक्ति, इकाई या समूह से है, जिसके पास धन (बजट) होती है तथा जो वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग करता है। उपभोक्ता एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, परिवार, फर्म या संस्था हो सकती है। 'उपयोगिता' शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में बहुत पुराना है। 'उपयोगिता' के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों की धारणाएँ भी बदलती रही हैं। मुख्य रूप से हम उन धारणाओं को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

(1) उपयोगिता सम्बन्धी पुराने विचार सर्वप्रथम 'उपयोगिता का विचार' (utility concept) पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रकाश डाला। उन्होंने उपयोगिता को मनोविज्ञान से सम्बन्धित कर, आनन्द तथा कष्ट (Pleasure and pain) के सन्दर्भ में इसकी व्याख्या की। पुराने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को समझने की कोशिश की परन्तु वे किसी निर्याय पर नहीं पहुँच पाए। उन्होंने देखा कि बहुत सी वस्तुओं की कीमतें, उन वस्तुओं के उपयोग (usefulness) या लाभ-दायकता के अनुसार हैं, परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो बहुत उपयोगी नहीं हैं, परन्तु उनकी कीमत बहुत ऊँची है, जैसे पानी, मनुष्य के लिए प्रति आवश्यक तथा उपयोगी है, परन्तु उसकी कीमत सामान्यतया

कुछ नहीं है। इसके विपरीत 'हीरा' मनुष्य के लिए पानी की तुलना में बहुत ही कम उपयोगी है, परन्तु इसकी कीमत बहुत अधिक है। इस प्रकार के विरोधाभासों के कारण, उन्होंने कीमत सिद्धान्त की व्याख्या अन्य प्रकार से की तथा कीमत को उपयोगिता से सम्बन्धित नहीं माना। यदि उन्होंने पानी तथा हीरा की 'सीमांत उपयोगिता' पर ध्यान दिया होता (वे 'सीमांत उपयोगिता' के विषय में नहीं जानते थे) तथा 'पुनाब की समस्या' पर भी विचार करते तो विरोधाभास का उत्तर मिल जाता।

(2) आधुनिक विचार : वस्तुतः उपयोगिता के आधुनिक सिद्धान्त का प्रारम्भ सन् 1870-80 में जेवन्स (W. S. Jevons), मेन्जर (Carl Menger), तथा वालरस (Leon Walras) द्वारा हुआ। इन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की विस्तारपूर्वक व्याख्या की तथा 'सीमांत उपयोगिता' का स्पष्टीकरण कर उन्होंने पानी तथा हीरे सम्बन्धी विरोधाभास का कारण बतलाया। इन अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त मार्शल, पीगू आदि ने उपयोगिता का विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा यह माना कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। बीसवीं शताब्दी में उपयोगिता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए। सामान्य विचारधारा यह रही कि किसी वस्तु की उपयोगिता को मूल्या द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल उनके क्रम के अनुसार महत्व पर प्रकाश डाला जा सकता है। मार्शल आदि द्वारा बतलाए गए, उपयोगिता सम्बन्धी विचार ('Cardinal Approach') के नाम से जाने जाते हैं। उपयोगिता के क्रम सम्बन्धी विचार ('Ordinal Approach') के नाम से जाने जाते हैं (इस अध्याय में आगे 'उपयोगिता की माप' शीर्षक के अन्तर्गत इन्हें समझाया गया है)। इन सभी विचारों को, (विशेषतः जो बीसवीं शताब्दी में प्रकट किए गए) 'Neoclassical utility concept' के नाम से जाना जाता है।

3. वर्तमान विचार : सन् 1930 के पश्चात् हिक्स, अलेन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोगिता विश्लेषण नए ढंग से किया गया। उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के लिए उदासीनता वक्रों (Indifference Curves) का प्रयोग किया (जिनके सम्बन्ध में इस पुस्तक में एक अलग अध्याय है) तथा 'Ordinal Approach' पर जोर दिया। 'उपयोगिता की माप' के सम्बन्ध में कई अर्थशास्त्रियों ने नए विचार प्रस्तुत किए उनमें हिक्स, अलेन, सैम्पुएलसन, मोरगेनस तथा यूमेन के विचार प्रमुख हैं। (उपयोगिता सम्बन्धी इन आधुनिक विचारों के अध्ययन के लिए, उपभोग का अन्तिम अध्याय देखिए)

इस प्रकार 'उपयोगिता के सम्बन्ध' में सैद्धान्तिक दृष्टि से, अर्थशास्त्र में विचार बदलते रहे हैं।



## (क) उपयोगिता का अर्थ (Meaning of Utility)

आर्थिक क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा का महत्व केवल दुर्लभता के कारण ही नहीं होता है। बहुत सी वस्तुओं के दुर्लभ होने पर भी उनकी कोई इच्छा नहीं करता। उपयोगिता किसी वस्तु को इसलिए चाहता है कि उसमें उपयोगिता का तत्व निहित है और वस्तु के उपयोग से उपयोगिता को आनन्द, सन्तोष या लाभ (pleasure, satisfaction or benefit) प्राप्त होता है। अतः अर्थशास्त्र में 'उपयोगिता' का अर्थ 'आवश्यकता सन्तुष्ट करने की शक्ति' से लिया जाता है। (Utility is want satisfying power) वस्तु में 'अर्थशास्त्र में कोई भी वस्तु (या सेवा) उपयोगिता का सूचक है, इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति उसे चाहते हैं। वे उसे क्यों चाहते हैं? इससे अर्थशास्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं है।'<sup>1</sup> उपयोगिता की परिभाषा के आधार पर, हम निम्नलिखित विषयताएँ पाते हैं।

(1) अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु में निहित लाभदायकता तथा विकाशपन से नहीं है : आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा में निहित किसी आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की क्षमता या शक्ति से है। इसके कारण ही किसी वस्तु की माग होती है तथा उपयोगिता उसे प्राप्त या क्रय करने के लिए इच्छुक व तत्पर होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ 'लाभदायकता' नहीं है। उपयोगिता या सन्तुष्टि उन वस्तुओं में भी प्राप्त होती है, जो लाभदायक नहीं होती। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं (जैसे अफीम, शराब) जिनका उपयोग सामाजिक दृष्टि से अव्यवस्थायी तथा लाभदायकता की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है। परन्तु इनमें भी कुछ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने का गुण या शक्ति होने के कारण, वे व्यक्ति इनको क्रय करते हैं। उपयोगिता का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। (The concept of utility is ethically neutral) इस प्रकार अफीम और शराब में भी आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का गुण निहित है। अतः एडवर्ड नेविन के अनुसार, "आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता का अर्थ उस सन्तुष्टि या आनन्द या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या सम्पत्ति (Wealth) के उपयोग से प्राप्त होता है।"

(2) उपयोगिता और सन्तोष (Utility and Satisfaction) दोनों बातों का समान अर्थ नहीं होता उपयोगिता तो केवल किसी वस्तु विशेष के प्रति उप-

<sup>1</sup> "In economics the expression 'a commodity conveys utility' means merely that some people want it, why they want it, is not the concern of economists" —Edward Nevin

सामान्यतः आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता शब्द के लिए desiredness, satisfyingness, vendibility, opelimity, usefulness, serviceability आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

भोक्ता की इच्छा की तीव्रता (intensity or urgency) का संकेत मान है। प्रायः उपभोक्ता जितनी वृष्टि की आशा (expected satisfaction) रखता है, वह कमी कमी पूर्ण नहीं भी होती है। उदाहरणस्वरूप, उपभोक्ता किमी आम के रंग को देखकर उसके मोठा होने की आशा रखता है, किन्तु वास्तविक उपभोग से पता चलता है कि वह उतना मोठा नहीं था। अतः वृष्टि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले वास्तविक सुख या सतोष का द्योतक है।

(3) उपयोगिता वस्तुगत (Objective) नहीं बल्कि व्यक्तिगत (Subjective) होती है वस्तु की उपयोगिता का अनुभव या भाव व्यक्ति में निहित है, वह उस वस्तु में निहित नहीं होता जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता।<sup>2</sup> किसी वस्तु से व्यक्ति को क्या उपयोगिता मिलेगी? यह उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता, रुचि, आदत आदि पर निर्भर है। उपयोगिता व्यक्ति से सम्बन्धित है वस्तु से नहीं।

(4) उपयोगिता सापेक्षिक (Relative) होती है उपयोगिता की धारणा सापेक्षिक है। यह कहना कि कोई वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी है, इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

अर्थशास्त्र में जब भी उपयोगिता की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि किसी वस्तु विशेष में अन्य की हुई वस्तुओं की तुलना में अधिक उपयोगिता है। उपयोगिता की बात तुलना के ही सदर्भ में की जा सकती है अतः उपयोगिता की धारणा एक सापेक्षिक धारणा है।

<sup>2</sup> "Utility is something experienced within a person and is not inherent in the physical commodity with the aid of which he experiences it"  
— Edward Nevin

<sup>3</sup> उपयोगिता के सापेक्षिक तत्त्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अधिकांश भारतीय लेखकों ने 'सापेक्षिक' का दूसरे ढंग से अर्थ लगाया है, जो निराधार है। हम यहां पर क्रिज्जर के विचार उद्धृत कर रहे हैं, जो 'सापेक्षिक' को समझने में सहायक होगा।

"Utility reveals itself only in acts of choice when two or more goods are being compared. Thus it is quite meaningless to conceive of the utility of a loaf of bread as it were, in vacuum. All we can say is that a loaf of bread may have either more or less utility than a glass of beer, a news magazine or twenty cents.. Utility refers to position on a scale of values. Without other goods or services, there is no scale of values and hence no utility concept at all". J. M. Kirzner, Market Theory and the Price System ¶ 57.

## (ख) उपयोगिता की माप (Measurement of Utility)

उपयोगिता अथवा 'आवश्यकता-संतुष्टि की शक्ति' एक व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) तथा मनोवैज्ञानिक धारणा है। अतः 'उपयोगिता की माप' के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। उपयोगिता की माप के सम्बन्ध में प्रचलित विचार-धाराओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है :

(क) गणनावाचक विचारधारा (The Cardinalists) : मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि उपयोगिता को मोटे रूप से नापा जा सकता है। उन्होंने मुद्रा को उपयोगिता का मापक माना है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति, जब किसी वस्तु को खरीदता है तो उनका भुगतान मुद्रा द्वारा करता है। वह वस्तु की कीमत, उन वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक नहीं चुकाएगा। अतः कीमत वस्तु की उपयोगिता की माप है। जैसे एक पुस्तक की कीमत यदि दस रुपया दी जाती है तो उस पुस्तक की उपयोगिता दस रुपए के बराबर है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को सीधे संख्याओं जैसे 1, 2, 3... आदि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 1, 2, 3 आदि संख्याओं को गणित में Cardinal Numbers कहा जाता है। इन संख्याओं को एक दूसरे से अनुपातिक रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, जैसे दो, एक का दुगुना, तथा तीन एक का तीन गुना है। जब हम वस्तु की उपयोगिता को इस प्रकार की संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे Cardinal utility कहते हैं। इस प्रकार जब वस्तुओं की उपयोगिता का संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, तब इसका अर्थ यह है कि विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि पुस्तक की उपयोगिता 50 तथा फलम की उपयोगिता 25 है। अतः पुस्तक, फलम से दुगुनी उपयोगी है। उपयोगिता सम्बन्धी यह विचार धारा 'Neoclassical-school' की देन है।

(ख) क्रमवाचक विचारधारा (The Ordinalists) : उपयोगिता सम्बन्धी उपर्युक्त विचारधारा हमारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ लाती है। अतः पैरेटो, हिक्स आदि ने कहा है कि उपयोगिता को नापा नहीं जा सकता है। उसे इस प्रकार मापों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि उपयोगिता को न तो विभाजित किया जा सकता है और न इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है।<sup>4</sup> इन अर्थशास्त्रियों के मत में, वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों (Combinations) के आधार पर, उन्हें क्रमानुसार प्रकट किया जा सकता है जैसे हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक कप काफी की उपयोगिता 50 तथा एक गिलास दूध की

4. 'Utility as a magnitude does not possess the property of divisibility. Hence it is wrong to use numbers for utility, for that would suggest that we can add and subtract utilities' — Charles Kennedy

उपयोगिता 100 है। हम अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता काफी की तुलना में दूध को अधिक उपयोगी समझ रहा है। दूध तथा काफी से प्राप्त उपयोगिता की तुलना नहीं की जा सकती है। यह कदापि नहीं कहा जा सकता है कि दूध की उपयोगिता काफी से दुगुनी है या तीन गुनी। गणित में, पहला, दूसरा, तीसरा आदि को Ordinal Numbers कहा जाता है। ऐसी संख्याओं से क्रम का बोध होता है, सरया विशेष का नहीं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि 'दूसरा पहले' का दुगुना है या तीसरा पहले का तीन गुना है। पहला, दूसरा, तीसरा 10, 20 और 30 भी हो सकते हैं और 1, 100, 100,000 भी हो सकते हैं। इस प्रकार क्रम-वाचक विचारधारा उपयोगिता को मापनीय नहीं मानती है।

ध्या। वास्तव में उपयोगिता मापनीय है ? (Is Utility Measurable ?)

उपभुक्त दो विचारधाराएँ एक दूसरे की विरोधी हैं।

(क) उपयोगिता के परिमाण को मापनीय मानने वाले अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि उपयोगिता को अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। इसके लिए यह शात किया जाता है कि किसी वस्तु की इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता किम माना में धन या द्रव्य त्याग करने के लिए तत्पर है ? या धन देने के लिए तत्पर रहता है, उतना धन वह दूसरी इकाई के लिए त्याग नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी इकाइयों के लिए पहले की अपेक्षा और भी कम रकम देना चाहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए दी जाने वाली मौद्रिक इकाइयों द्वारा जा सकती है।

(ख) उपयोगिता मापनीय नहीं है। क्रमवादियों (Ordinalists) के विचार में उपयोगिता को नापा नहीं जा सकता है। क्योंकि (i) उपयोगिता स्वभावतः अमापनीय है—सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों के साथ ही साथ उपभोक्ता के व्यवहारों के बहुत से पक्षों का अध्ययन, उपयोगिता की माप के बिना भी किया जा सकता है। अतः न तो उपयोगिता मापनीय है और न उसे मापने की आवश्यकता है। (ii) उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार है। किसी भी मनो-वैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार को, सरयाओं या किसी अन्य पैमाने से नापा नहीं जा सकता है। (iii) विभिन्न व्यक्तियों तथा परिस्थितियों में कोई वस्तु उपयोगी हो सकती है तथा दूसरी परिस्थिति में अनुपयोगी। अतः ऐसी परिवर्तनशील तत्त्व की माप नहीं की जा सकती। (iv) किसी भी वस्तु की मापने के लिए किसी पैमाने की आवश्यकता होती है। उपयोगिता को मापने के लिए कोई निश्चित तथा सर्व-मान्य पैमाना नहीं है। मार्शल ने 'मुद्रा' को उपयोगिता का मापक माना है परन्तु मुद्रा निश्चित तथा विश्वसनीय मापक नहीं है।

पैरेटो, प्रलेन, हिक्स इत्यादि अर्थशास्त्री उपयोगिता को मापनीय नहीं मानते हैं, और न वे उपयोगिता की माप की आवश्यक ही मानते हैं। हिक्स ने तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण (Indifference curves Analysis) की नई विधि निकाली है, जिसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

### (ग) कुल उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता (Total Utility and Marginal Utility)

1 कुल उपयोगिता (Total Utility) किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से प्राप्त कुल सन्तुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा में से प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता मिलती है, उन सबके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रो० बिर्जनेर के शब्दों में "किसी वस्तु के स्टॉक से उपयोगिता का जो परिमाण प्राप्त होता है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं।" (Total utility refers to the Quantity of (Cardinal) utility afforded by a stock of a commodity")

सन्तुष्टि का योग वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होने पर बढ़ता ही जाता है, परन्तु इसके बढ़ने की गति इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान तीव्र नहीं होती।<sup>3</sup> इस प्रकार कुल या पूर्ण उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, किन्तु मन्द गति से। इसका कारण यह है कि किसी वस्तु के उपयोग की क्रिया में जैसे जैसे उसकी इकाइयों की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसकी प्रत्यक्ष अतिरिक्त इकाई (successive unit) से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है।

2 सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) का अर्थप्रायः उपयोगिता की उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई में प्राप्त होती है। शब्दों में, सीमान्त उपयोगिता उपयोग का अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में हुयी अतिरिक्त वृद्धि को कहते हैं। इस प्रकार की क्रमिक सम्पूर्ण उपयोगिताओं का अन्तर ही सीमान्त उपयोगिता है। शब्दों में कहा जा सकता है कि "सीमान्त उपयोगिता उस दर को प्रकट करती है, जिस दर पर, वस्तु के स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है।

3 "The total utility of a thing to any one increases with every increase in his stocks of it, but not, as fast as his stock increases"

—Marshall

4 Marginal utility is "the extra amount of satisfaction to be obtained from having an additional small increment of a commodity".

—J. L. Hanson

“Marginal utility refers to the rate at which total utility changes as the size of the stock of the commodity changes”.

—I. M. Kirzner

उपरोक्त दोनों प्रकार की उपयोगिताओं को निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस सारणी का निर्माण इस आधार पर किया गया है आवश्यकताओं की यह विशेषता है कि आवश्यकता-विशेष को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करने के लिए उपभोक्ता को किसी वस्तु की कई इकाइयों का उपयोग करना पड़ता है। वह प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ सन्तुष्ट होता जाता है जिससे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है।

सन्तरी की इकाइया	प्राप्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता
1	12	12	12
2	10	22	10
3	9	31	9
4	7	38	7
5	5	43	5
6	0	43 (अधिकतम)	0 शून्य सी०उ०
7	-4	39 (घटती हुयी)	-4 नकारात्मक

रेखाचित्रों द्वारा स्पष्टीकरण पूर्ण उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। उपर्युक्त सारणी में सन्तरी की इकाइयों से प्राप्त सीमान्त तथा पूर्ण उपयोगिताओं की सख्याओं को अंकित करने पर चित्र सख्या 1 में दो वक्र बनते हैं जिनसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का स्पष्टीकरण होता है

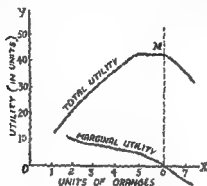
(1) पूर्ण उपयोगिता में वृद्धि तो होती है, परन्तु घटती हुयी दर से। एक निश्चित बिन्दु (M) पर पहुँचने के बाद उसमें भी ह्रास प्रारम्भ हो जाता है।

(2) सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है तथा शून्य की स्थिति में पहुँचकर नकारात्मक (Negative) हो जाती है।

(3) पूर्ण उपयोगिता M बिन्दु पर अधिकतम होती है जहाँ सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है।

(4) सीमान्त उपयोगिता के नकारात्मक होते ही पूर्ण उपयोगिता कम होने लगती है, अर्थात् जब तक सीमान्त उपयोगिता धनात्मक (Positive) है, पूर्ण उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। परन्तु जब सीमान्त उपयोगिता नकारात्मक (Negative) हो जाती है, तब पूर्ण उपयोगिता भी क्रमशः घटने लगती है।

(5) उपभोक्ता की संतुष्टि की चरमावस्था (Point of Satiation) पर पूर्ण उपयोगिता अधिकतम होती है और यहाँ सीमान्त उपयोगिता शून्य हो जाती है।

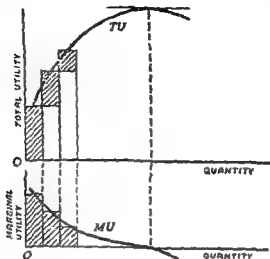


चित्र नं० 1

कुल उपभोगिता तथा सीमान्त उपभोगिता का सम्बन्ध : 'सीमान्त उपभोगिता' तथा 'कुल उपभोगिता' से सम्बन्धित बन्धों को दूधारे रूप से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की तीन इकाइयाँ हैं। वह सोचता है कि वह एक या दो या तीनों इकाइयों का उपयोग करे। भवतः उसके सामने उपयोग की ये तीन सम्भावनाएँ हैं। वस्तु की एक इकाई कुछ उपयोगिता देगी, दो इकाइयाँ और अधिक उपयोगिता देंगी, तीन इकाइयाँ उससे भी अधिक उपयोगिता देंगी। जैसे-जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाएगा, कुल उपभोगिता बढ़ती जाएगी। परन्तु साथ ही साथ उपभोक्ता की संतुष्टि भी बढ़ती जाएगी, इस प्रकार उत्तरोत्तर इकाइयों से उसे कम-कम उपभोगिता प्राप्त होगी। अर्थात्, कुल उपभोगिता में वृद्धि, घटती हुई दर पर होगी।

चित्र 2 में कुल उपभोगिता तथा सीमान्त उपभोगिता के सम्बन्ध को दिखलाया गया है। चित्र के ऊपरी भाग में बने तीन भाग, बढ़ती हुई कुल उपभोगिता प्रदर्शित कर रहे हैं। तीनों भागों के बाद भी कुल उपभोगिता वक्र (TU) स्तर उठता गया है, जो यह बताता है कि अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपभोगिता बढ़ती जाएगी। चित्र के नीचे का भाग केवल कुल उपभोगिता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है अर्थात् सीमान्त उपभोगिता को प्रकट करता है। किसी भी मात्रा की सीमान्त उपभोगिता, उस मात्रा की कुल उपभोगिता वक्र की ढाल (slope) कही जा सकती है। किसी भी बिन्दु पर कुल उपभोगिता वक्र की ढाल उस बिन्दु पर प्रतिरिक्त उपभोगिता को प्रकट करता है तथा सम्बन्धित मात्रा के लिए, सीमान्त उपभोगिता वक्र की ऊँचाई के बराबर होता है।

जब कुल उपयोगिता धक उच्चतम बिन्दु पर पहुँच जाता है, तब उसका ढलाव शून्य हो जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमान्त



चित्र न० 2

उपयोगिता शून्य होती है। इस चित्र के आधार पर कुल उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता के बीच निम्नलिखित सम्बन्ध स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं।

### कुल उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता में सम्बन्ध

जब कुल उपयोगिता (When Total is)	तब सीमान्त उपयोगिता (Then Marginal is)
1. समान दर से बढ़ रही है	1. पूर्ववत् या समान
2. बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है	2. बढ़ रही है।
3. घटती हुई दर से बढ़ रही है	3. घट रही है।
4. अधिकतम है	4. शून्य है।
5. घट रही है	5. ऋणात्मक है।

सीमान्त उपयोगिता सदैव सीमान्त इकाई की होती है। सीमान्त इकाई किसी वस्तु की वह इकाई है जो सबसे कम उत्कट इच्छा (least intense desire) को सन्तुष्ट करती है। इस प्रकार यदि सम्पूर्ण उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपयोग की इकाइयों की उपयोगिताओं का योग है, तो सीमान्त उपयोगिता निम्न विधि से भी ज्ञात की जा सकती है :

$$\text{सीमान्त उपयोगिता} = \frac{\text{कुल उपयोगिता में वृद्धि}}{\text{उस वस्तु की सख्या में वृद्धि}}$$

कुछ अर्थशास्त्रियों ने मास्ति या भारक्षील सीमान्त उपयोगिता (Weighted marginal utility) शब्द का भी प्रयोग किया है। प्रो० बोल्डिंग (prof.



Boulding) के अनुसार किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता में यदि उस वस्तु के मूल्य से भाग दिया जाता है, तो हमें मार्गशील सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होती है। इस हम निम्न रूप से प्रकट कर सकते हैं।

$$\text{भारित सीमान्त उपयोगिता} = \frac{\text{'अ' वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{'अ' वस्तु का मूल्य}}$$

सीमान्त विचार का महत्व \* (Importance of the Concept of Margins) :

(i) अर्थशास्त्र में सीमान्त विचार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रो० जे० के० मेह्रता के शब्दों में, "समस्त समस्त आर्थिक ढांचा सीमान्त उपयोगिता के विचार पर आधारित है" ("almost the entire economic structure is based on the conception of marginal utility".) 'सीमान्त' का प्रयोग अर्थशास्त्र के सभी विभागों में किया गया है। उपयोग के क्षेत्र में सीमान्त उपयोगिता, उत्पादन के क्षेत्र में सीमान्त लागत, विनिमय के क्षेत्र में सीमान्त प्राय तथा सीमान्त लागत, तथा वितरण के क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार राजस्व के क्षेत्र में भी 'सीमान्त' का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में किया जाता है।

उपयोग सम्बन्धी कई सिद्धान्त, जैसे क्रमागत उपयोगिता-ह्रास नियम, सम सीमान्त उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत आदि सीमान्त विचार पर आधारित हैं।

(ii) सीमान्त उपयोगिता की धारणाओं ने अर्थ के इस विरोधाभास (paradox) को समाप्त करने में सहायता की है कि "पानी, हीरो (diamonds) से क्यो कम मूल्यवान है?" पानी की पूर्ण उपयोगिता अनिश्चित है, परन्तु उसकी पूर्ण अधिक होने के कारण उसकी सीमान्त उपयोगिता शून्य के बराबर ही रहती है। इसके विपरीत हीरो की पूर्ण उपयोगिता अपेक्षाकृत कम होगी, परन्तु हीरो की पूर्ण स्वल्प तथा दुर्लभ होने के कारण, इसकी सीमान्त उपयोगिता अधिक होगी। यही कारण है कि दुर्लभ तथा स्वल्प वस्तुओं का मूल्य हाता है, जबकि असीमित मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं का कोई बाजार मूल्य नहीं होता। यदि किसी स्थान पर पानी में दुर्लभ एवं स्वल्प वस्तु ही जाय तो उसकी सीमान्त उपयोगिता अधिक होने पर उसका भी बाजार मूल्य होगा।

\*सीमान्त के विचार का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व है। यहां पर हम सविधा विवरण दे रहे हैं, जिसका सम्बन्ध 'सीमान्त उपयोगिता' से है। अन्य विभागों में भी 'सीमान्त' का महत्व है, परन्तु निवार्यो जब तक उनका अध्ययन न कर लें, सीमान्त का महत्व को समझना उनके लिए कठिन होगा। अतः हमने इस पुस्तक के अन्त में, सीमान्त के महत्व पर अलग से प्रकाश डाला है। देखिए परिशिष्ट—1।

(iii) सीमान्त उपयोगिता तथा मूल्य : प्रत्येक इकाई की सीमान्त उपयोगिता का अनुमान उस वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए दिए जाने वाले मूल्य से लगाया जा सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता उस वस्तु की अतिरिक्त इकाईयां उम इकाई तक खरीदता जायेगा, जब तक कि इकाई की सीमान्त उपयोगिता उसके लिए त्याग की जाने वाली रकम के बराबर न हो जाय। जब तक धन की सीमान्त उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर रहती है, वस्तु की सीमान्त उपयोगिता मूल्य के मूल्य ही होती है, जैसा कि नीचे दी गयी सारणी में स्पष्ट किया गया है :

संतरो की सीमान्त उपयोगिता

त्याग करने की तत्परता के आधार पर मूल्य धन की सीमान्त उपयोगिता			
इकाईया	(पैसे में)	(पैसे में)	(पैसे में)
1	75	25	—
2	62	25	25
3	56	25	25
4	40	25	25
5	25	25	25
6	10	25	25

उपयुक्त सारणी में यह स्पष्ट किया गया है कि धन या मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान तथा स्थायी रहने पर किसी भी वस्तु के बाजार में धन या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही वस्तु का मूल्य होता है। अतः प्रत्येक इकाई का मूल्य धन की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही है। उपभोक्ता संतरे की पाचवीं इकाई पर आकर हक जायेगा, क्योंकि उससे प्राप्त उपयोगिता का मूल्य त्याग किए जाने वाले धन के बराबर है। छठी इकाई की उपयोगिता 10 पैसे के बराबर है जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के तुल्य धन अर्थात् प्रचलित मूल्य—25—पैसे का त्याग करना होगा। अतः पाचवीं इकाई ही सीमांत इकाई है जिससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहा जायेगा।

मुद्रा के मापदण्ड द्वारा उपयोगिता के परिमाण की माप के सम्बन्ध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि ऐसी माप उसी समय सम्भव हो सकती है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थायी या समान रहे यदि इस मापदण्ड की सीमांत उपयोगिता स्वयं परिवर्तनशील है, तो समय तथा व्यक्ति की विभिन्नता के कारण किसी वस्तु की परिवर्तनशील उपयोगिता का मापना कठिन होगा। अतः मुद्रा के मापदण्ड द्वारा उपयोगिता उसी समय मापनीय हो सकती है, जबकि मोद्रिक इकाई की सीमान्त उपयोगिता समान रहे। परन्तु व्यावहारिक जगत में ऐसा न होने के कारण ही तटस्थता-वक्र (Indifference Curve) विधि के द्वारा उपयोगिता के परिमाण की माप करने में सुविधा होती है।

## 2. उपयोगिता ह्रास नियम (The Law of Diminishing Utility)

उपयोगिता विश्लेषण (Utility analysis) के अन्तर्गत 'उपयोगिता ह्रास नियम' का महत्वपूर्ण स्थान है। यह नियम माग-विश्लेषण का भी आधार है। यद्यपि इस नियम का उल्लेख बेन्थम (Bentham) के आर्थिक सिद्धान्तों में मिलता है, परन्तु आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के सम्बन्ध में सर्वप्रथम (सन् 1854 ई० में) इसका उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री एच० एच० गोसेन (H. H. Gossen) ने किया। यही कारण है कि इस नियम को 'गोसेन का प्रथम नियम' (The First Law of Gossen) या सन्तुष्टि का नियम (Law of Satiation) कहा जाता है। मूल्य निर्धारण की व्याख्या में इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम स्टैन्ली जेवन्स (William Stanley Jevons) ने किया।

1. उपयोगिता ह्रास नियम का आधार (Basis of the Law of Diminishing utility) : आवश्यकताओं के लक्षणों से यह स्पष्ट है कि आवश्यकताएं अनन्त हैं किन्तु उनमें से किसी एक आवश्यकता को पूर्णतया सन्तुष्ट किया जा सकता है। मार्शल के अनुसार "आवश्यकताओं की असीमित किस्म है, परन्तु प्रत्येक आवश्यकता विशेष की सीमा (Limit) है। मानव-प्रकृति की इस मौलिक प्रवृत्ति का उल्लेख 'सन्तुष्टि या पूर्ण योग्य आवश्यकताओं के नियम' (Law of satiable wants) अथवा ह्रासमान उपयोगिता के नियम के रूप में किया जा सकता है।" इस आधार के अतिरिक्त यह नियम इस तथ्य पर भी आधारित है कि किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया में किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई का उपयोग करने पर आवश्यकता की तीव्रता (intensity of wants) में कमी होती है तथा वस्तु विशेष की उपयोगिता भी कम होने लगती है।

मानव-प्रकृति की ये मानसिक तथा शारीरिक (psychological and physiological) प्रवृत्तियाँ दैनिक व्यवहारों में देखने को मिलती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस नियम का निर्माण किया गया है। वस्तुतः किसी वस्तु को रखने तथा उसकी प्रयोग करने में प्रसन्नता का अनुभव होता है।

2. नियम की परिभाषा उपयोगिता ह्रास नियम किसी वस्तु की मात्रा में घट-बढ़ तथा सीमान्त उपयोगिता में कमी तथा वृद्धि के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। यह ज्ञात होता है कि "किसी वस्तु की उपयोगिता इसकी मात्रा की विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है।" इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घट जाती है, तथा उसकी मात्रा में कमी होने पर, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

एडवर्ड नेविन के अनुसार, "किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है।"<sup>1</sup> इस तथ्य को सन् 1854 ई० में गोसेन ने इन शब्दों में व्यक्त किया था 'जब कि पूर्ण सन्तुष्टि का बिन्दु नहीं आ जाता तब तक एक ही और उसी सन्तुष्टि की मात्राओं में वृद्धि करने पर क्रमशः उसका हास होता जाता है।'<sup>2</sup>

(The amount of one and the same satisfaction declines as we proceed with that satisfaction, until satiety is reached)

प्रो० मार्शल ने इस नियम की व्याख्या इन शब्दों में की है 'अन्य बातों के समान रहने पर, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा पहले से है उसमें एक डी हुई मात्रा से वृद्धि करने पर जो अतिरिक्त लाभ मिलता है, वह प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है।'<sup>3</sup>

उपयोगिता हास नियमों को 'सीमान्त उपयोगिता हास नियम' (Law of Diminishing Marginal Utility) भी कहा जाता है। प्रो० बौलिंग (Prof Boulding) के अनुसार, "जैसे जैसे कोई उपभोक्ता, अन्य वस्तुओं के उपभोग को समान (constant) रखते हुए, किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाता है, वैसे-वैसे परिवर्तनशील वस्तु की सीमान्त उपयोगिता निश्चित रूप से कम होनी चाहिए।"<sup>4</sup>

3 स्पष्टीकरण यह नियम इस अनुभव पर आधारित है कि उपभोग की क्रिया में जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है अन्य बातों के समान रहने पर, उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई की अतिरिक्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है वहाँ उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाती है। उस स्थिति पर पहुँचने पर उपभोग की सभी अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता शून्य हो जाती है। यदि इस सीमा के बाद भी उपभोग की क्रिया चलती रहे तो अगली इकाइयों से उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता

<sup>1</sup> The extra satisfaction derived from the consumption of additional units of any commodity tends to decline as the quantity consumed increases"  
—Edward Nevin

<sup>2</sup> The additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of a thing diminishes, other things being equal, with every increase in the stock that he already has' —Marshall

<sup>3</sup> "As a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline."  
—Boulding

(disutility) मिलेगी, जिसे नकारात्मक उपयोगिता (negative utility) कहा जाता है, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में स्पष्ट किया गया है। क्रमशः उपभोग की गयी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता घटते हुए कम से बढ़ती है तथा प्रतिरिक्त इकाई की सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अतः चैंपमैन के अनुसार किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी ही कम हम उसकी प्रतिरिक्त मात्रा चाहते हैं अथवा प्रतिरिक्त वृद्धि की हम उतनी ही अधिक इच्छा नहीं रखते।<sup>4</sup> इस प्रकार वस्तु के स्टॉक में प्रत्येक प्रतिरिक्त इकाई की वृद्धि से सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है, परन्तु स्टॉक में प्रत्येक इकाई की कमी करने पर सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। स्टॉक में परिवर्तन होने से उपयोगिता में विपरीत क्रम में परिवर्तन होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन उसी अनुपात में हो।

4 उदाहरण द्वारा निम्न की व्याख्या इस नियम की व्याख्या अथवा स्पष्ट रूप से करने के लिए रोटीयों की इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को अधोलिखित तालिका में दिखलाया गया है

#### रोटी से प्राप्त उपयोगिता

उपभोग इकाइया (रोटी)	सीमान्त उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइया)	कुल उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइया)
1	20	20
2	14	34
3	10	44
4	8	52
5	6	58
6	0	58-सन्तुष्टि का प्रसिप्त बिन्दु
7	-2	56

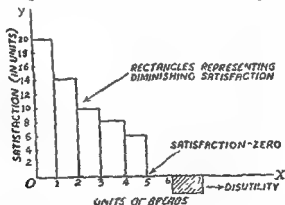
तालिका से स्पष्ट है कि पहली रोटी की उपयोगिता 20, दूसरी की 14, तीसरी की 10, चौथी की 8, पाचवी की 6, छठी की शून्य तथा सातवी की -2 इकाइयों के बराबर है। इससे यह ज्ञात होता है कि पहली रोटी उपभोग करने के बाद प्रत्येक अगली इकाई (दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी) की इकाई की उपयोगिता घटती जाती है। छठी रोटी का उपभोग करने पर पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त होती है, अतः इस रोटी की उपयोगिता शून्य के बराबर है। इसके पश्चात् की सातवी रोटी का

4 "The more we have of a thing the less we want additional increments of it, or the more we want not to have additional increments of it."  
—Chapman

उपभोग करने पर उपयोगिता मिलने के स्थान पर अनुपयोगिता मिलने लगती है, जो ऋणात्मक (-2) है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ह्रासमान उपयोगिता नियम सीमान्त उपयोगिता में घटने (ह्रास) की दर (the rate of decline of marginal utility) का उल्लेख नहीं करता। इस नियम के आधार पर यह तभी कहा जा सकता कि सीमान्त उपयोगिता तीव्र या धीमी गति से घट रही है प्रथवा ह्रास की दर परिवर्तनशील है या समान। इस नियम में केवल इतना ही पता चलता है कि किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घटती जाती है।

उपयुक्त तालिका की सहायता से रेखाचित्र बनाकर सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र 3 में OX अक्ष (axis) पर रोटी की इकाइयों को तथा OY पर उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों को अंकित किया गया है। प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता को अलग अलग आयतों द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को व्यक्त करने वाले आयत का आकार घटता जाता है, जो यह व्यक्त करता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सन्तुष्टि कम हो घटती जाती है। छठी रोटी से शून्य के बराबर सन्तुष्टि प्राप्त होती है और 7 वीं रोटी से सन्तुष्टि प्राप्त होने के

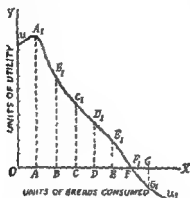


चित्र न० 3

स्थान पर उसमें नुकसान होने की सम्भावना है जिससे उससे सम्बन्धित आयत OX अक्ष के नीचे दिखलाया गया है।

अब यदि OX अक्ष के प्रत्येक बिन्दु (A, B, C, D, E, F तथा G) पर जो रोटियों की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करता है प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के बराबर ऊँची एक खड़ा रेखा (vertical line) खींच दी जाय तथा उनके ऊपरी

विन्दुओं को मिला दिया जाय तो उपयोगिता-वक्र चित्र 4 में दिए गए प्रकार का होगा :



चित्र नं० 4

OA इकाई की सीमान्त उपयोगिता  $AA_1$ , तथा AB की सीमान्त उपयोगिता  $BB_1$ , शीर्ष रेखाओं द्वारा मापी गयी है। इसी प्रकार प्रत्येक इकाई (BC, CD, DE, EF, FG) की सीमान्त उपयोगिता को  $CC_1$ ,  $DD_1$ ,  $EE_1$ ,  $GG_1$ , द्वारा व्यक्त किया गया है।

सीमान्त उपयोगिता को व्यक्त करने वाली  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ , आदि शीर्ष रेखाएँ क्रमशः छोटी होती गयी है।  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ , आदि विन्दुओं को मिलाने पर दायाँ ओर भुजता हुआ वक्र ( $UU_1$ ) बनता है जिसे उक्त वस्तु (रोटियो) का उपयोगिता वक्र (utility curve) कहते हैं। यह वक्र OX को कभी न कभी छेड़ने काटेगा। उपर्युक्त चित्र में  $UU_1$  वक्र OX को F या  $F_1$  विन्दु पर काटता है, जहाँ यह व्यक्त करता है कि EF इकाई की सीमान्त उपयोगिता शून्य के बराबर है। उपभोक्ता इस विन्दु पर पूर्ण समुष्टि प्राप्त कर लेता है। यदि वह इसके बाद भी FG घटिरहित इकाई का उपयोग करे, तो वक्र OX भक्ष के नीचे की ओर फुकता है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता उपयोगिता प्राप्त करने के बरने अनुपयोगिता प्रथवा त्वारात्मक उपयोगिता प्राप्त करने लगा है।

5. उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है ? इस सम्बन्ध में प्रो० बोल्डिंग (Prof Boulding) ने दो कारणों का उल्लेख किया है (1) वस्तुएँ एक दूसरे की पूर्ण स्वानापन्न (Perfect substitute) न होकर अपूर्ण स्वानापन्न (Imperfect substitutes) होती हैं, अर्थात् विभिन्न उपयोग वस्तुओं के उचित अनुपातों (appropriate proportion) में प्रयोग करने पर ही यह नियम लागू होता है, अदहरणार्थ, यदि कोई उपभोक्ता सिगरेट तथा चाय का उपभोग करता है तथा

उनकी मात्राओं का एक उचित अनुपात निर्धारित कर लेना है। मान लीजिए ये मात्राएँ X तथा Y है। यदि उचित अनुपातों में इन दोनों वस्तुओं का उपभोग करने के लिए यह सिगरेट की मात्रा स्थिर रखना है और चाय की मात्रा को क्रमशः बढ़ाता है तो चाय के प्रत्येक अणु प्याले (इकाई) से उसे घटती हुई उपयोगिता मिलेगी। तथा (2) आवश्यकता विशेष पूर्णतया सन्तुष्ट की जा सकती है, अर्थात् सन्तुष्टि के अन्तिम बिन्दु (point of satiety) पर पहुँचकर वस्तु की मात्रा बढ़ने पर भी तृप्ति नहीं बढ़ती क्योंकि उस बिन्दु पर भीमान्त उपयोगिता शून्य के बराबर होती है।

बोमोल (Baumol) के अनुसार इस नियम के लागू होने का कारण यह है कि हम पहला स्थान सबसे अधिक महत्व वाले उपयोग को देते हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए यदि उदाहरण दिया है, "यदि हमारे पास केक" (Cake) का एक ही टुकड़ा है तो हम उसे अपने बच्चे को खाने के लिए दे देंगे, यदि दो हैं तो द्वितीय टुकड़ा अपनी पत्नी को देंगे, यह तीसरा टुकड़ा हमें तो उसे अपने लिए रखेंगे और चौथा होने पर उसे अपने सास को देंगे।<sup>5</sup> ऐसा ही विचार प्रो० हैरोड (Harrod) ने भी व्यक्त किया है। कुछ दशाओं में वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है और कुछ में कम। उपभोक्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग को ही प्राथमिकता प्रदान करता है।

6. नियम की सीमाएँ तथा मान्यताएँ (Limitations and Assumptions of the Law) : उपयोगिता ह्यम नियम अग्य वानों के यथावत् या समान रहने पर ही लागू होता है। यह वाक्यांश इस नियम के सम्बन्ध में कुछ सीमाओं एवं मान्यताओं की ओर संकेत करता है जो निम्नलिखित हैं :

(1) उपभोक्ता की मानसिक स्थिति एक सी रहनी चाहिए : यह नियम उसी समय लागू होगा जबकि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो जैसे, यदि कोई उपभोक्ता किसी समय खाना खाने के दौरान में दो रोटियाँ खाने के बाद भाग या शराब का प्रयोग करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जायेगा। इसके परचाव्. हो सकता है कि तीसरी रोटी से उसे पहले उपभोग की गयी दो रोटियों की तुलना में अधिक सन्तुष्टि मिले। इस प्रकार मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(2) वस्तु की प्रत्येक इकाई का परिमाण उचित होना चाहिए : उपभोग्य-वस्तु की प्रत्येक इकाई का परिमाण उचित होना चाहिए (sizeable unit), अन्यथा

<sup>5</sup>... "because we give priority to more highly valued uses if we have only one cake, we feed it to our child, if we have two we give the second to our wife, a third we keep for ourselves, and a fourth we give to our mother-in-law."



प्रारम्भिक अवस्था में ही आवश्यकता की तीव्रता घटने के स्थान पर अधिक हो जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि एक प्यासे व्यक्ति को चम्मच से पानी पिलाया जाय, तो कुछ चम्मच पानी की इकाइयों तक उसकी उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती जायेगी।

(3) वस्तु की प्रत्येक इकाई का रूप, रंग, गुरुत्व समान होना चाहिए : उपभोग वस्तु की प्रत्येक इकाई का रूप, रंग एवं गुरुत्व समान होना चाहिए। यदि किसी भ्रगली इकाई का रूप परिवर्तित कर दिया जाये (सूखी राटी के स्थान पर पूरी दे दी जाए), तो भ्रगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटने की अपेक्षा बढ़ेगी।

(4) उपभोग के समय में अन्तर नहीं : किसी वस्तु के उपभोग का समय निश्चित होना चाहिए तथा उस समय में वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। यदि हम भोजन दो बार करते हैं तो प्रत्येक बार भोजन करने पर सन्तोष मिलेगा। परन्तु यदि दो बार भोजन के मध्य समय का कोई समान अन्तर न हो, तो दूसरी बार के भोजन से उपयोगिता कम प्राप्त होगी।

(5) उपभोक्ता की आदतों, रुचि, फंशान तथा व्यय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए : यह नियम उसी समय लागू होता है जब उपभोक्ता की आदतें, रुचियाँ तथा आय समान रहती हैं। इनमें से किसी में परिवर्तन होने पर वस्तु की उपयोगिता घटने का स्थान पर बढ़ जाती है।

(6) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं : यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु का उपभोग करते समय किसी भ्रगली इकाई का मूल्य बढ़ या घट जाता है तो सीमांत उपयोगिता कम या अधिक होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति भ्राम का उपभोग करता है तो 50 पैसे एक भ्राम का मूल्य होना पर वह अधिक से अधिक 3 भ्रामों का क्रमशः उपभोग करने के लिए उत्तर होगा। परन्तु यदि 2 भ्राम खाने के बाद प्रति भ्राम मूल्य 25 पैसे हो जाना है, तो वह अब 4 भ्रामों का उपभोग करना चाहेगा।

(7) स्थानापन्न (Substitute) का मूल्य समान रहना चाहिए : उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी पहले के समान रहना चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। चाय और काफी दो स्थानापन्न वस्तुएँ हैं। यदि चाय की कीमत घट जाती है, तो काफी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा बढ़ जायेगी।

(8) सुखमय मानसिक स्थिति का होना : पेट्टेन (Petten) के अनुसार इस नियम की कार्यशीलता सुखमय अर्थ व्यवस्था (Pleasure Economy) में ही सम्भव है, क्योंकि इस प्रकार की अव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करके आनन्द

एव सन्तोष का अनुभव करता है। विशेष रूचि के साथ किसी वस्तु का उपयोग करने पर ही उपयोगिता के क्रमशः घटने का नियम लागू होगा। परन्तु दुःखमय अर्थव्यवस्था (Pain Economy) में उपभोक्ताओं की अधिक असमर्थता के कारण उन्हें सभी वस्तुओं के उपयोग के अवसर उपलब्ध नहीं होते। अतः उन्हें अत्यन्त कष्ट का अनुभव होना है। जब तक उपभोक्ता दुःखमयी मानसिक स्थिति में रहेगा तब तक उपयोग की अगरी इकाइयाँ कम सन्तोष प्रदान करने के स्थान पर अधिक सन्तोष प्रदान कर सकती हैं।

(9) प्रदर्शन-प्रभाव न पड़ना उपभोक्ता पर प्रदर्शन-प्रभाव (demonstration or Dusenberry Effect) न पड़ने पर ही यह नियम लागू होगा। यदि निम्न आय-वर्ग के लोग उच्च-आय के व्यक्तियों का अनुकरण करने लगे तो वे सम्भवतः किमी वस्तु को अधिक मात्रा में रखना प्रारम्भ कर देंगे। उनके द्वारा प्राप्त की गई क्रमिक इकाइयाँ एक निश्चित सीमा तक घटती सीमान्त उपयोगिता प्रदान नहीं करती हैं।

7. नियम के तथाकथित अपवाद (Alleged Exceptions) : यह नियम अपनी मान्यताओं के अन्तर्गत सदैव सत्य उतरता है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इसके निम्नलिखित अपवादों का उल्लेख किया है।

(1) यदि किसी वस्तु की बहुत थोड़ी सी मात्रा की इकाई का उपयोग किया जाय, तो यह नियम लागू नहीं होगा। प्रो० जैम्स ने चाय बनाने के लिए कोयले के प्रयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए 100 ग्राम कोयले का प्रयोग करता है, तो यह इकाई इतनी कम मात्रा में है कि उपभोक्ता को कोयले की दूसरी 100 ग्राम मात्रा की इकाई से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। परन्तु यह अपवाद ठीक नहीं है, क्योंकि इस नियम की यह मान्यता है कि उपयोग की जाने वाली इकाई की मात्रा उपयुक्त तथा उचित होनी चाहिए।

(2) दुर्लभ वस्तुओं के सम्बन्ध में नियम का लागू न होना, यह नियम दुर्लभ वस्तुओं (rare articles) जैसे टाक-टिकट, दुर्लभ चित्र तथा प्रदर्शन-वस्तुओं, के सम्बन्ध में लागू नहीं होता इनकी मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ इनकी सीमान्त उपयोगिता में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। परन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि इन वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता के स्थान पर समूह (group or set) की उपयोगिता जात की जानी चाहिए। वस्तुतः टाक टिकट संग्रह करने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के टाक-टिकटों के 'सेट' के संग्रह में विरोध रचि रखता है। यदि वह एक ही प्रकार के टिकटों का पूरा 'सेट' सेता है, तो उसी प्रकार के टिकटों के दूसरे सेट की उपयोगिता निश्चय ही कम होगी। यही स्थिति अन्य दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तुओं की दशाओं में भी रहती है।

(2) शराब पीने तथा अच्छी कविता या मधुर संगीत की इच्छा का संतुष्ट न होना : कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि शराब पीने की इच्छा तथा अच्छी कविता या मधुर संगीत बार-बार सुनने की इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। परन्तु शराबी की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इस नियम की यह मान्यता है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होने पर ही यह नियम सत्य होगा। अतः यह अपवाद निराधार है। कविता तथा संगीत के सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि उसी कविता या गान को सुनने पर प्रत्येक बार समान संतुष्टि प्राप्त होती है। पहली बार उसे सुन लेने के पश्चात्, दूसरी बार उसके सुनने में उसकी रुचि नहीं होती। अतः यहाँ पर भी यह नियम लागू होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि परिस्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा।

(4) पूरक वस्तुओं के सम्बन्ध में नियम का लागू न होना : कुछ पूरक वस्तुओं (Complementary goods), जैसे चाय दूध चीनी, मोटर-पेट्रोल आदि, के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता। दूध और चीनी के मिलने पर चाय की उपयोगिता में वृद्धि होती है। परन्तु यहाँ पर पूरक वस्तुओं की सम्मिश्रित करके उनकी सामूहिक उपयोगिता की ध्यान में रखना तथा इस नियम की सत्यता की जाँच करना ठीक नहीं होगा। प्रत्येक पूरक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से क्रमशः बढ़ती हुयी उपयोगिता प्राप्त होगी।

(5) कञ्ज की धन की इच्छा का संतुष्ट न होना : एक कञ्ज व्यक्ति की धन की इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती और धन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से अधिक संतुष्टि प्राप्ता होती है। परन्तु अर्थशास्त्र में एक कञ्ज व्यक्ति असामान्य व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं होती, अतः कञ्ज द्वारा धन-संग्रह की इच्छा अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के बाहर है। इसे इस नियम का अपवाद मानना ठीक नहीं है। इसी प्रकार शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा को अपवाद मानना ठीक नहीं है।

(6) कुछ वस्तुओं का या सेवाओं का प्रयोग बढ़ने पर भी उनकी उपयोगिता नहीं घटती : कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता कुछ व्यक्तियों के पास उनकी अतिरिक्त इकाइयों के बढ़ने पर बाँधक होती है। जैसे टेलीफोन प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ने पर टेलीफोन-सम्बन्ध (telephonic connections) बढ़ने के साथ-साथ उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। परन्तु यह अपवाद निराधार है। यहाँ यदि एक व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के बाद अतिरिक्त टेलीफोन की वृद्धि की वाम तो उसकी उपयोगिता निश्चित ही कम होगी।

उपयुक्त अपवादों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस नियम का कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रो० टॉजिंग का यह विचार है कि "इस नियम की गति ऐसी है और यह इतना विस्तृत तथा इतना बड़ा अपवाद वाला है कि इसमें कोई विशेष गलती नहीं होगी, यदि इसे एक विश्वव्यापी नियम मान लिया जाय।"<sup>6</sup>

प्रो० टॉजिंग ने कुछ वास्तविक अपवादों (real exceptions) का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पहला अपवाद यह है कि यदि किसी धनी मर्माज में प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कारे हों, तो एक कार रखन वाला व्यक्ति दूसरी कार ले लने पर उस दूसरी इकाई से अधिक सन्तुष्टि पायेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि कार को दूसरी इकाई के पश्चात् तीसरी कार लेने पर उसे घटती हुयी उपयोगिता मिलेगी।

उनका दूसरा अपवाद अच्छी कविता सुनने के सम्बन्ध में है। उनके अनुसार एक अच्छी कविता को प्रत्येक बार सुनने पर पहलें की अपेक्षा अधिक आनन्द आता है। परन्तु इस स्थिति में भी एक बिन्दु (समय) ऐसा आयेगा जिसके बाद उस कविता को सुनने पर पहल जैसा आनन्द नहीं आयेगा।

## 8. नियम की आलोचना

(1) यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है, जो दैनिक अनुभव तथा व्यक्तिगत संवेदनशीलता पर आधारित है। व्यावहारिक नियम की संवेदनशीलता के आधार पर बनाने करने का अर्थ यह है कि नियम अस्पष्ट तथा गलत है।

(2) यह उपयोगिता को मापनीय मानता है। यह इस नियम की सबसे बड़ी त्रुटि है, क्योंकि उपयोगिता की प्रत्यक्ष माप सम्भव नहीं है। यह कहा जाना है कि परोक्ष रूप में, दिए जाने वाले मूल्य से उपयोगिता की माप सम्भव हो सकती है, किन्तु यह माप विश्वसनीय नहीं समझी जा सकती।

(3) यह सिद्धान्त उपभोक्ता के व्यक्तिगत विचारों को विनियमित करने का प्रयत्न करता है, परन्तु व्यक्ति मर्दव तक एक बुद्धि से ही कार्य नहीं करता। उसकी रुचि, इच्छा तथा भावनाएँ किसी न किसी रूप में अन्य बातों से प्रभावित होती रहती हैं। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध भावनाओं से नहीं, बल्कि सीमित साधनों के द्वारा संयोजित अविकलतम सन्तुष्टि की प्राप्ति से है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य इच्छाओं एवं भावनाओं का विरले-पण करना नहीं है।

\* "The tendency operates so widely and with so few exceptions that there is no significant inaccuracy in speaking of it as universal."  
—Taussing

(4) यह नियम व्यष्टि प्रधान है। आधुनिक अर्थशास्त्र समष्टिगत विरूपण पर अधिक बल देता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में वैयक्तिक सीमान्त उपयोगिता के विक्षेपण का कोई विशेष स्थान नहीं है।

(5) यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि आवश्यकता विशेष की पूर्ण सन्तुष्टि सम्भव है। परन्तु उपयोग की अवधि सम्बन्धी होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण सन्तुष्टि सम्भव नहीं हो सकती। उस अवधि में अन्य आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर उसके सीमित साधन और भी सीमित हो जाते हैं, जिससे आवश्यकता विशेष की सन्तुष्टि भी पूर्णरूप से नहीं हो पाती।

(6) यह नियम मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता के स्थिर रहने पर सत्य उतरता है, परन्तु यह मान्यता उचित नहीं है। अन्य वस्तुओं की तरह मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता भी परिवर्तनशील है। इसके आधार पर ही विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समाजवाद तथा प्रगतिशील कर व्यवस्था (Progressive Taxation) का समर्थन किया है। धनी व्यक्तियों से इसीलिए कर अधिक लिया जाता है कि उनके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है।

मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को स्थिर मानकर प्रतिष्ठित (Classical) अर्थशास्त्रियों ने पूँजीवाद तथा स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था (Free economy) को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु उन लोगों ने सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम का उल्लेख नहीं किया था। यदि वे इस नियम को सत्य मानते, तो वे स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था की नींव नहीं रख पाते, क्योंकि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था तथा सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम परस्पर विरोधी आर्थिक तथ्य हैं। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को स्थिर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने उपयोग-भोक्ता की सापेक्षिक पसन्दगी (relative preferences) के आधार पर नदृश्यता वक्र (Indifference Curve) द्वारा उपयोगिता का विश्लेषण किया है।

(7) उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ताओं के उपयोग करने की शारीरिक क्षमता को सीमित मानता है। उसकी यह मान्यता है कि उपभोक्ता शारीरिक इशार्ड का उपयोग करने के पश्चात् थक जाता है, फलस्वरूप उसकी उपयोग करने की क्षमता में कमी होती है। तत्पश्चात् वस्तु की प्रत्येक अगली इकाइयों के उपयोग में उसकी उपयोग करने की क्षमता में कमी आती जाती है, जिससे क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। परन्तु सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम यह स्थिति नहीं पर प्रकट नहीं करता।

(8) आलोचना का एक आधार यह है कि इस नियम की यह मान्यता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर है। व्यवहार

में सामान्यतया यह सत्य भी है कि वस्तु की उपयोगिता उसकी मात्रा पर ही निर्भर करती है, किन्तु उस वस्तु की उपयोगिता केवल स्वयं की मात्रा पर ही नहीं, बल्कि अन्य पूरक तथा स्थानापन्न (complementary and substitutes) वस्तुओं की मात्रा की पूर्ति पर भी, निर्भर है। अतः किसी भी वस्तु की उपयोगिता न केवल उस वस्तु की मात्रा, बल्कि अन्य पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं की मात्रा, का कार्य (function) है। सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम इन सम्बन्धित वस्तुओं के मिश्रित प्रभावों (cross effects) पर ध्यान नहीं देता।

### 9. नियम का महत्व (Importance) :

सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम मार्शल के आर्थिक विश्लेषण का केन्द्र बिन्दु है। इसके माध्यम से उपयोगिता को आधार मानते हुए, उन्होंने मान के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से इस नियम का, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों रूपों में महत्व है :—

(1) मूल्य-निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण : यह नियम इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पूर्ति में वृद्धि के साथ ही मूल्य में कमी क्यों आती है ? अतः यह मूल्य-सिद्धान्त के व्यक्तिगत तत्वों (subjective elements) की व्याख्या में सहायता प्रदान करता है। माग-वक्र मोड़ों की ओर बायीं तरफ (downward sloping to the right) क्यों झुकती है ? इसकी व्याख्या इस नियम द्वारा सम्भव हो पाती है। उपभोक्ता की समतुल्य की अवस्था (consumer's equilibrium) तथा उपभोक्ता की बचत (consumer's surplus) की व्याख्या में भी इस नियम से सहायता मिलती है। इस दृष्टि से यह नियम मूल्य-सिद्धान्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(2) आधुनिक कर-प्रणाली का आधार : मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था में इन नियम का महत्व और भी बढ़ गया है। व्यक्ति की मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ ही मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता उसके लिए घटती जाती है, अर्थात् धनी व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम और गरीब व्यक्तियों के लिए अधिक क्यों होती है ? इसका विश्लेषण इस नियम के आधार पर भी किया जा सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इसका महत्व सार्वजनिक वित्त (Public Finance) में प्रगतिशील कर-प्रणाली के सम्बन्ध में पाते हैं। प्रगतिशील कर-व्यवस्था के पक्ष में तर्कों के रूप में यह कहा जाता है कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अधिक आय वालों के लिए कम होती है। इसी दृष्टिकोण से न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त (Least aggregate sacrifice) आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है।

(3) वस्तुओं की उपयोगिता तथा विनिमय-सम्बन्धी मूल्यों के अन्तर को स्पष्ट करने में सहायक है : यह नियम उपयोगिता सम्बन्धी मूल्य और विनिमय

सम्बन्धी मूल्यो ( value-in-use and value-in-exchange ) की व्याख्या करने तथा उनमें अन्तर स्पष्ट करने में सहायक है। उपभोग-वस्तुओं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश आदि, का विनिमय मूल्य इतना कम क्यों है ? इसे यह नियम स्पष्ट करता है क्योंकि बहुलता के कारण इनकी सीमान्त उपयोगिता बहुत कम होती है और फलस्वरूप विनिमय मूल्य नाम मात्र का होता है। ठीक इसके विपरीत सीमित वस्तुएं आर्थिक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, जिनकी सीमान्त उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण उनका विनिमय-मूल्य अधिक होता है।

(4) यह नियम उपभोग तथा उत्पादन की जटिलता के कारणों पर प्रकाश डालने में सहायक है। आज के युग में उत्पादित वस्तुओं के रूप एवं मात्रा में इतनी विविधता (variety) क्यों उड़नी जाती है तथा उत्पादन एवं उपभोग इतना जटिल क्यों होता जा रहा है ? इनकी व्याख्या इस नियम की सहायता से सम्भव है। टॉजिंग ने भी यही विचार प्रकट किया है

"It is this fact of Diminishing Marginal Utility that explains the growing variety in the articles produced and the growing complexity of production and consumption"

(5) इस नियम पर आधारित अन्य नियमों की सहायता से उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का उचित प्रयोग करने में समर्थ 'सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' अथवा 'सर्वाधिक सन्तुष्टि का नियम' अथवा 'प्रतिस्थापन का विचार' इसी नियम पर आधारित है, जिससे उपभोक्ता अपने साधनों का सर्वाधिक लाभप्रद उपयोग करने में समर्थ होता है।

चूँकि यह नियम एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, इसलिए इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। फॉरनरॉस ने इसी तथ्य को बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा है, 'यह केवल रोटी एवं भोजन, रेतयात्रा, व्यक्ति के हेत आदि वस्तुओं पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अर्थशास्त्रियों के व्याख्यानो, राजनीतिज्ञों के भाषणों तथा जासूसी कहानियों के अनेक सदृश व्यक्तियों के सम्वाच में भी समान रूप से सत्य है।'" अतः यह स्पष्ट है कि इस नियम का व्यावहारिक महत्व अधिक है।

### 3. ह्रासमान सीमान्त प्रतिस्थापकता नियम

(Law of Diminishing Marginal Substitutability)

उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे 'ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता नियम' (Law of Diminishing Marginal Utility) भी कहते हैं, की चालोचना से यह स्पष्ट

---

"It can be applied not only to things like butter and bread, railway journeys, man's hats, and so on, but also to the lectures of economists, the speeches of politicians and even the number of suspects in detective stories."

—Carncross.

है कि यह नियम दो ऐसी धारणाओं पर आधारित है जो वास्तविक नहीं हैं। इस नियम के सम्बन्ध में मार्शल की यह धारणा है कि (1) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थायी है (marginal utility of money is constant) तथा जेवन्स की यह धारणा है कि (ii) वस्तु या सेवा की उपयोगिता की संख्या में व्यक्त किया जा सकता है (Utility can be expressed in quantities)। मार्शल तथा जेवन्स की ये धारणाएँ आधुनिक अर्थशास्त्रियों को मान्य नहीं हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ह्याममान सीमांत उपयोगिता नियम के स्थान पर 'ह्रासमान सीमान्त प्रतिस्थापकता नियम' का उल्लेख किया है। इस नियम को बनाने वाले प्रो० हिक्स तथा एलेन (Prof. Hicks and Allen) हैं।

ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें एक निश्चित समय में एक ही वस्तु के उपभोग पर ध्यान दिया जाता है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। सत्य तो यह है कि उपभोक्ता एक माय ही कई वस्तुओं की उपयोगिता पर एक साथ ही ध्यान देता है। चूँकि प्रत्येक उपभोक्ता के पास साधन सीमित होते हैं व उसकी आवश्यकताएँ अनन्त तथा कई प्रकार की होती हैं, अतः वह पूर्ण मनुष्य के बिन्दु तक किसी एक ही वस्तु के उपभोग की बात नहीं सोचता। वास्तव में वह उस बिन्दु तक विभिन्न वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिता पर विचार करता है। अतः उपभोक्ता की माग की सही व्याख्या करने के लिए एक ही वस्तु के उपभोग पर विचार न करके उसकी पसन्दगी के क्रम अथवा प्राथमिकता के क्रम (Scale of preferences) पर विचार करना होगा। प्राथमिकता के क्रम पर विचार करने पर ही उपभोक्ता की माग की सही व्याख्या की जा सकती है।

साधनों की कमी के कारण उपभोक्ता के सामने हमेशा यह कठिनाई बनी रहती है कि वह दो वस्तुओं, (मान लीजिए  $x$  तथा  $y$ ) में से किसको प्राथमिकता दे? इसका कारण स्पष्ट है। साधनों (धन) की कमी के कारण वह दोनों वस्तुओं को अपनी जरूरत के अनुसार नहीं खरीद सकता। अतः उसे एक वस्तु ( $x$ ) को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु ( $y$ ) का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व को ध्यान में रखकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित (Substitute) करता जाता है। इसका अर्थ यह है कि  $x$  तथा  $y$  वस्तुओं में यदि  $x$  वस्तु का अधिक महत्व है तो वह  $y$  वस्तु का त्याग करके  $x$  वस्तु प्राप्त करेगा। परन्तु इस प्रकार ज्यों-ज्यों एक वस्तु  $x$  की अधिक इकाइयों को वह ग्रहण या प्राप्त करता जाता है त्यों त्यों उसका महत्व उसके लिए घटता जाता है तथा दूसरी वस्तु  $y$  का, जिसका वह त्याग करता जाता है, महत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में उपभोक्ता किसी वस्तु के लिये किसी अन्य वस्तु या



मुद्रा को जितनी मात्रा का त्याग करता है, बाद में उतना त्याग नहीं करना चाहता। इस आधार पर ही यह कहा जाता है, "जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों को प्राप्त करता जाता है, त्यों-त्यों उस वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के लिए सीमान्त प्रतिस्थापन दर घटती जाती है।"

(The Marginal Rate of Substitution of one commodity for another decreases as an individual possesses increasing quantities of this commodity)

उदाहरण मान लीजिये एक व्यक्ति के लिए दो वस्तुओं, चाय तथा सिगरेट, के प्राथमिकता क्रम (Scale of preferences) नीचे की तालिका के अनुसार हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि सिगरेट के रूप में चाय की प्रतिस्थापन दर क्रमशः घटती जाती है, अर्थात् प्रारम्भ में उपरोक्ता 1 प्याला चाय के लिए 6 सिगरेटों का प्रो. बाद में दूसरे, तीसरे तथा चौथे प्याले के लिए क्रमशः 5, 4 तथा 1 सिगरेट ही

प्राथमिकता-क्रम

क्रम	उचित संयोग या अनुपात		सिगरेट के रूप में चाय की प्रतिस्थापन दर
	चाय के प्याले की संख्या	सिगरेटों की संख्या	
प्रारम्भ में	5	30	1 प्याला चाय के लिए 6 सिगरेटों का त्याग
दूसरी बार	6	25	1 प्याला चाय के लिए 5 सिगरेटों का त्याग
तीसरी बार	7	21	1 प्याला चाय के लिए 4 सिगरेटों का त्याग
चौथी बार	8	20	1 प्याला चाय के लिए 1 सिगरेट का त्याग

दना चाहता है। अतः यह स्पष्ट है कि "सीमान्त प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु की एक बहुत ही छोटी मात्रा को किसी दूसरी वस्तु की एक छोटी मात्रा के लिए, अपनी कुल सन्तुष्टि में परिवर्तन किए बिना, विनिमय कर सकता है।"<sup>8</sup> उपर्युक्त उदाहरण में सिगरेट के रूप में चाय की प्रतिस्थापन दर क्रमशः 1 6, 1 5, 1 4 1 1 है जो क्रमशः घटती गयी है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि ह्रासमान सीमान्त प्रतिस्थापकता

\* "A consumer's Marginal Rate of Substitution is the rate at which a consumer can exchange a very small amount of one commodity for a very small amount of the other without affecting the total utility."

नियम ह्रासमान सीमान्त उत्पादकता नियम का रूपान्तर है। प्रो० हिव्स इस विचार से सहमत नहीं हैं। वास्तविकता भी यही है कि ह्रासमान सीमान्त प्रतिस्थापकता नियम ह्रासमान सीमान्त उत्पादकता नियम का रूपान्तर नहीं हो सकता, क्योंकि

(i) यह नियम उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन (Quantitative measurement) पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके तुलनात्मक महत्व पर आधारित है।

(ii) इस नियम के अन्तर्गत मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को स्थिर नहीं माना जाता।

(iii) यह नियम एक वस्तु के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपयोगिता की आवश्यकताओं की दूसरी वस्तुओं को भी ध्यान में रखते हुए उनका तुलनात्मक महत्व पर आधारित है।

(iv) यह नियम दो वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं के आधार पर उनकी प्रतिस्थापन दर निर्धारित करने में सहायक होता है।

## (4) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-Marginal Utility)

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम उपभोक्ता की अधिकतम सन्तुष्टि से सम्बन्धित है। सर्वप्रथम इस नियम का उल्लेख सन् 1858 ई० में जर्मन अर्थशास्त्री एच० एच० गोसेन (H. H. Gossen) ने किया था। इसलिए इस नियम को 'गोसेन का दूसरा नियम' (Second Law of Gossen) भी कहा जाता है। गोसेन के नियम का आधार यह था कि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित हैं, कोई भी व्यक्ति उन सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह एक माय सन्तुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास माघन (घन) सीमित है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टि से उनमें चुनाव करना होता है। ऐसे चुनाव में वह कम उपयोगिता की वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता की वस्तु प्रतिस्थापित करता जाता है। इस प्रकार आचरण करने पर अन्त में उसको अधिकतम सन्तुष्टि मिल पाती है। गोसेन के अनुसार "यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण सन्तुष्टि के बिन्दु तक तृप्त करना सम्भव नहीं है, तो अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की सन्तुष्टि उस बिन्दु पर रोक दी जाय जिस बिन्दु पर उनकी तीव्रता समान हो जाय।"<sup>1</sup> इन तथ्यों के आधार पर ही इस नियम के कई नाम हैं, जैसे

<sup>1</sup> "If it is not possible to gratify all wants to the point of satiety, it is necessary, in order to obtain maximum satisfaction to discontinue the satisfaction of different wants at the want at which their intensity has become equal."

'अधिकतम सन्तुष्टि नियम' (Law of Maximum Satisfaction), प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution), तटस्थता नियम (Law of Indifference), 'व्यय की मितव्ययता का नियम' (Law of Economy of Expenditure) आदि।

### 1. नियम की परिभाषा -

प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। परन्तु वह तथा समय सीमित होने के कारण अधिकतम सन्तुष्टि पाने के लिए उसे विभिन्न सन्तुष्टियों का इस प्रकार चुनाव करना होता है कि उपयोग बन्द करते समय, उसे प्रत्येक चुनाव से समान सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। मार्शल ने इस नियम की इस प्रकार स्पष्ट किया है, "यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है, जिसका कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है तो वह उसे (वस्तु) विभिन्न उपयोग में इस प्रकार बाँटेगा जिससे प्रत्येक उपयोग से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो सके।" \* प्रो० मेहता ने इस नियम की परिभाषा में निम्नलिखित काल पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार, "यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है तो उनको एक निश्चित माध्य से अधिकतम संतोख प्राप्त करने के लिए, उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बाँटना चाहिए कि उस निश्चित काल में सभी दशाओं में उसकी सीमान्त उपयोगिता लगभग समान हो।" इस परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपयोगिता अधिकतम सन्तुष्टि उसी समय प्राप्त कर सकता है जबकि वह प्रतिस्थापन द्वारा अलग अलग वस्तुओं से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करे।

### 2. नियम का स्पष्टीकरण

उपयोगिता ठाम नियम यह बतलाता है कि यदि कोई उपयोगिता किसी वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता प्रत्यक्ष घटती जाती है। यत यदि वह उस वस्तु की अधिक मात्रा न खरीदकर उसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु खरीद ले तो उसे सम्भवतः अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। इस प्रकार वह कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु खरीदता है अर्थात् वह एक वस्तु का प्रतिस्थापन (Substitution) दूसरी वस्तु में करता है। विभिन्न वस्तुओं की समाप्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखकर वह अधिकतम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं की खरीदता। इस प्रकार खरीद बचन के पश्चात् यदि इस विधि द्वारा उसकी कुल मुद्रा वस्तुओं के खरीदने में व्यय कर दी जाती है तो उपयोगिता को यह मात्रा

\* "If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all."  
— Marshall

होगा कि उसे मुद्रा की प्रत्येक अन्तिम इकाई से खरीदी गई प्रत्येक वस्तु से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यय के सदम में यह कहा जा सकता है कि सम सीमान्त उपयोगिता नियम यह बतलाता है कि एक निश्चित आय में से विभिन्न वस्तुओं पर किए गए समस्त व्यय, सीमान्त पर, विभिन्न वस्तुओं की सीमान्त इकाई से समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। एक उदाहरण द्वारा इस नियम को और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुल दस रुपये हैं। वह नारंगी, सेब तथा मिठाई पर अपना रुपये व्यय करना चाहता है। मुद्रा की विभिन्न इकाइयों को इन तीनों वस्तुओं की खरीद पर व्यय करना से मान लीजिए उस निम्नलिखित उपयोगिताएँ प्राप्त हो सकती हैं

नारंगी, सेब तथा मिठाई से प्राप्त उपयोगिता

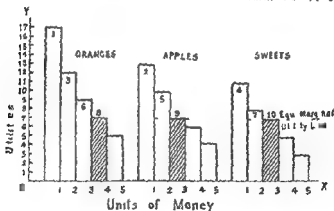
मुद्रा की इकाइया	नारंगी	सेब	मिठाई
1	17 (1)	13 (2)	11 (4)
2	12 (3)	10 (5)	8 (7)
3	9 (6)	7 (9)	7 (10)
		30	26
4	7 (8)	6	5
	45		
5	5	4	4

सारणी से स्पष्ट है कि यदि वह पहला रुपया व्यय करना चाहता है तो वह पाता है कि उसे नारंगी, सेब तथा मिठाई से क्रमश 17, 13 और 11 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अतः वह पहला रुपया नारंगी पर व्यय करेगा, क्योंकि नारंगी से उसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वह पहला रुपया नारंगी पर, दूसरा रुपया सेब पर, तीसरा नारंगी पर, चौथा मिठाई पर, पाचवा सेब पर, छठा नारंगी पर, सातवा मिठाई पर, तथा अन्तिम तीन रुपये में से एक रुपया नारंगी पर एक रुपया सेब पर तथा एक रुपया मिठाई पर व्यय करेगा। उपयोगिता की दृष्टि से इस प्रकार वह चार रुपये के सतरे, तीन रुपये के सेब तथा तीन रुपये की मिठाई खरीदेगा, तभी उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होगी। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तीनों वस्तुओं पर व्यय की गयी सीमान्त इकाई से प्राप्त उपयोगिताएँ समान हों। नारंगी, सेब तथा मिठाई पर क्रमश 4, 3, व 3 रुपये व्यय करता है। इन तीनों वस्तुओं पर व्यय किए गए रुपयों की सीमान्त इकाइयों से (चौथे तीसरे, व तीसरे रुपये से) उसे प्रत्येक वस्तु से समान उपयोगिताएँ प्राप्त हो रही है (प्रत्येक दशा में 7)।

उपयुक्त विधि से व्यय करने पर ही उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होगी। इन तीनों वस्तुओं की खरीदी हुई कुल इकाइयों से उपभोक्ता को  $45 + 30 + 26 = 101$  कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। मान लीजिए, वह नारंगी पर एक रुपया और अधिक (कुल पाच रुपए) व्यय करना चाहता है इसका फल यह होगा कि वह सेब पर एक रुपया कम (कुल दो रुपए) व्यय करेगा। ऐसी स्थिति में उसे कुल उपयोगिता 101 से कम प्राप्त होगी (नारंगी पर पाच रुपया व्यय करने से  $50 +$  सेब पर दो रुपया व्यय करने से  $23 +$  मिठाई पर तीन रुपए व्यय करने से  $26 = 99$  कुल उपयोगिता प्राप्त होगी)। विद्यार्थी भ्रम संयोग (Combinations) द्वारा या परीक्षण कर देख सकते हैं कि उपभोक्ता को प्रत्येक भ्रम दशा में कुल उपयोगिता 101 से कम प्राप्त होगी जैसे उपभोक्ता यदि चार नारंगी, चार सेब तथा दो मिठाइया खरीदता है तो भी उसे कुल उपयोगिता नारंगी से  $45 +$  सेब से  $36 +$  मिठाई से  $19 = 100$  प्राप्त होगी। इस प्रकार अधिकतम सन्तुष्टि उन्नीसवत्स में प्राप्त होगी, जबकि खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो।

### 3 रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण

(1) नीचे दिए गए चित्र में आधार रेखाओं OX पर नारंगी, सेब तथा मिठाई पर व्यय की गयी रुपया की इकाइया तथा छोटी रेखाओं OY पर उन

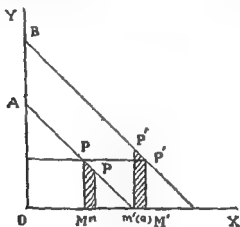


चित्र नं० 5

वस्तुओं की उपयोगिताएँ दिखायी गयी हैं। आधार रेखाओं पर बने आयत (rectangles) रुपये की प्रत्येक इकाई के व्यय से प्राप्त इन वस्तुओं की उपयोगिताओं को व्यक्त करते हैं। मढ़रे रूप के आयत तीनों वस्तुओं की समान सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। इन आयतों के ऊपरी भाग को धुँवाँ हुयी खींची गयी

रेखा सम सीमान्त उपयोगिता की रेखा (Equi-marginal Utility Line) है, जो आधार रेखा के समानान्तर होती है।

(ii) उपर्युक्त उदाहरण को चित्र स 6 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। दिए गए चित्र में,  $OX$  अक्ष पर वस्तुओं की मात्रा तथा  $OY$  पर सीमान्त उपयोगिताएँ प्रदर्शित की गई हैं। सुविधा की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुएँ — नारंगी तथा सेब खरीद रहा है। उपभोक्ता के पास  $OM + OM'$  मुद्रा है।  $A$  तथा  $B$  वक्र क्रमशः नारंगी तथा सेब की प्रकट कर रहे हैं, जो यह बताते हैं कि ज्यों-ज्यों नारंगी तथा सेब की अधिक मात्राएँ खरीदी जाती हैं, उनकी उपयोगिताएँ क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार घट रही हैं। यदि  $OM$



चित्र न० 6

मुद्रा नारंगी तथा  $OM'$  मुद्रा सेब को खरीदने में व्यय की जाती है तो नारंगी तथा सेब से प्राप्त सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हैं ( $MP = M'P'$ )। नारंगी तथा सेब की कुल उपयोगिताएँ क्रमशः  $OMPA$  तथा  $OM'P'B$  हैं। सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार ये उपयोगिताएँ अधिकतम होनी चाहिए। यदि मुद्रा किसी अन्य विधि से खर्च की जाती है तो कुल उपयोगिताएँ कम होनी चाहिए। जैसे, मान लीजिए उपभोक्ता नारंगी पर  $Mm$  मुद्रा अधिक खर्च करता है तो नारंगी की सीमान्त उपयोगिता  $MP$  से घटकर  $mp$  हो जाती है। मुद्रा एक निश्चित मात्रा में है, अतः नारंगी पर जितना अधिक व्यय किया जाएगा, सेब पर उतनी ही मात्रा में कम व्यय किया जाएगा। मान लीजिए, उपभोक्ता सेब पर  $M'm'$  मुद्रा कम व्यय करता है (या  $a$  के बराबर कम व्यय करता है, चित्र में  $M'm'$  की दूरी  $= a$  है) जो  $Mm$  के बराबर है (चित्र में  $Mm = M'm'$  प्रदर्शित किया गया है)। सेब पर  $M'm'$  कम व्यय करने से, सेब की सीमान्त उपयोगिता  $M'P'$  से बढ़कर  $m'P'$  हो

जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि जब इस नई स्थिति में नारंगी तथा सेब की सीमान्त उपयोगिताएँ समान नहीं हैं। (सेब की सीमान्त उपयोगिता नारंगी से अधिक है, दोनों की सीमान्त उपयोगिताएँ समान न होने का परिणाम यह हुआ है कि अब मुद्रा के इस नए वितरण से कुल उपयोगिताएँ कम हो गई हैं।

कुल उपयोगिताओं के घटने का प्रमाण यह है कि मुद्रा की  $Mm$  मात्रा नारंगी पर अधिक धन्य की जाती है तो नारंगी की कुल उपयोगिता में  $MmPP$  के बराबर वृद्धि होती है, तथा सेब पर  $M'm$  मुद्रा कम धन्य करने से सेब की कुल उपयोगिता में  $M'PP'm$  के बराबर कमी होती है। अतः नारंगी पर अधिक धन्य करने से कुल उपयोगिता जिस मात्रा से बढ़ती है, सेब पर कम धन्य करने से उससे अधिक मात्रा में कुल उपयोगिता कम हो जाती है (चित्र से, स्पष्ट है कि  $M'PP'm$  का क्षेत्रफल  $MmPP$  से अधिक है)। अतः उपभोक्ता धन्य में जिस प्रकार से भी परिवर्तन करे उसे कुल उपयोगिता पहुँच की अपेक्षा कम प्राप्त होगी। उसे अधिकतम सतुष्टि उसी समय प्राप्त होगी जबकि वह मुद्रा इस प्रकार से व्यय करे कि उसे नारंगी तथा सेब दोनों से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो सके।

#### 4 नियम की मान्यताएँ (Assumptions of the Law) :

यह नियम इन मान्यताओं पर आधारित है कि (i) उपभोक्ता अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, (ii) उपभोक्ता की आय सीमित होती है तथा वह अपनी आय का उपयोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए करता है, (iii) वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता मापी जा सकती है, अर्थात् हम विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं (iv) वस्तुएँ छोटी तथा विभाज्य हैं, (v) उपभोक्ता अपनी आय को मोच समझ कर विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, (vi) आय तथा व्यय की अवधि एक ही है, (vii) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है, तथा (viii) अन्य बातें—उपभोक्ता की आय, खर्चा तथा वस्तुओं के मूल्य आदि—पूर्ववत् रहती हैं।

नियम की आधुनिक व्याख्या—आधुनिक सीमान्त उपयोगिता नियम  
(Law of Proportional Marginal Utility) :

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि विभिन्न वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता की समानता के आधार पर इस नियम की व्याख्या करना ठीक नहीं है। इस आधार पर नियम की व्याख्या करने में वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता। किन्तु किसी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता की मापना स्वयं ही उसके मूल्य पर आधारित है, क्योंकि उपभोक्ता पहले किसी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता की उसके मूल्य के साथ तुलना करता है, उसके बाद वह यह निश्चित करता है कि

वह उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। इसके अतिरिक्त अविभाज्य तथा अधिक कीमत वाली वस्तु की सीमान्त उपयोगिता का किसी कम कीमत वाली वस्तु के बराबर करने में जो स्थिति उत्पन्न होगी वह अवास्तविक एवं अव्यावहारिक होगी। साइकिल तथा सन्तरे की सीमान्त उपयोगिताओं को बराबर करने के लिए कई साइकिलें खरीदनी पड़ेगी। उपभोक्ता केवल सीमान्त उपयोगिता को बराबर करने के विचार से कभी ऐसा नहीं करेगा।

अतः यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिताओं को समान नहीं बनाना चाहता, बल्कि वह उन वस्तुओं पर किये जाने वाले खर्च की सीमान्त उपयोगिता को समान बनाना चाहता है। इस सम्बन्ध में प्रो० वोल्टिंग ने भारयुक्त सीमांत उपयोगिता (Weighted Marginal Utility) का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उसके मूल्य से भाग द दिया जाय, तो उस वस्तु की भारयुक्त सीमांत उपयोगिता मासूम होगी। इस प्रकार मासूम की गयी भारयुक्त सीमान्त उपयोगिताएँ जहाँ पर बराबर होंगी, वही उपभोक्ता को अधिकतम सन्तोष प्राप्त होगा। प्रो० पी० सी जैन (Prof P C Jain) के अनुसार अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिए "एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना धन इस प्रकार खर्च करेगा कि उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएँ उनके मूल्यों के अनुपात में हों।"<sup>8</sup> इस आधार पर:

$$\frac{x \text{ वस्तु की सी० उ०}}{x \text{ वस्तु का मूल्य}} = \frac{y \text{ वस्तु की सी० उ०}}{y \text{ वस्तु का मूल्य}} = \frac{z \text{ वस्तु की सी० उ०}}{z \text{ वस्तु का मूल्य}} \text{ आदि}$$

$$\left[ \frac{\text{Marginal Utility of Commodity X}}{\text{Price of Commodity X}} = \frac{\text{Marginal Utility of Commodity Y}}{\text{Price of Commodity Y}} \right.$$

$$\left. = \frac{\text{Marginal Utility of Commodity Z}}{\text{Price of Commodity Z}} \dots \right]$$

मूल्यो तथा सीमान्त उपयोगिताओं के समान अनुपात के आधार पर सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या करने के कारण ही इसे आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम या आनुपातिक नियम (Law of Proportional Marginal Utility or Law of Proportionality) कहते हैं। इस नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिताओं के बराबर होने पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि कई वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिताओं और उनके पारस्परिक मूल्यों के अनुपात के बराबर

"A consumer will spend money on different commodities in such a way that the marginal utilities of the different commodities are proportional to their prices."  
—P. C. Jain



होने पर विचार किया जाता है। इस आधार पर ही यह कहा जाता है कि यदि उप-भोक्ता दो ऐसी वस्तुओं को खरीदना चाहता है जिनमें से एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य से दुगुना है, तो अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए उनकी सीमांत उपयोगिताओं को उनके मूल्यों का समानुपाती होना आवश्यक है। यदि पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य से दुगुना है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता से दुगुनी होनी चाहिए। इसका आधार यह है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके लिए दिए गए मूल्य के बराबर होती है। अतः मूल्य के दुगुने होने पर यदि सीमांत उपयोगिता MU तथा मूल्य P है तो,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{पहली वस्तु} \\ \text{की सी. उ. तथा} \\ \text{उसके मूल्य का} \\ \text{अनुपात} \end{array} \right\} \dots \frac{MU}{P} = \frac{2MU}{2P} \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{दूसरी वस्तु की} \\ \text{सी. उ. तथा} \\ \text{उसके मूल्य का} \\ \text{अनुपात} \end{array} \right\}$$

इसके विपरीत, मान लीजिए, दो वस्तुओं के मूल्यों में इस प्रकार का अन्तर है कि उनकी सीमांत उपयोगिताएँ उनके मूल्यों की समानुपाती नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधिकतम सन्तुष्टि पाने के लिए उपभोक्ता को एक वस्तु को दूसरी वस्तु से उस समय तक इस प्रकार प्रतिस्थापित करना होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा उनके मूल्यों में समानुपातिकता (proportionality) स्थापित न हो जाय। उदाहरण के लिए, माना कि उपभोक्ता X वस्तु की 10 इकाइयाँ तथा Y वस्तु की 7 इकाइयाँ खरीदना चाहता है, तथा

$$\begin{array}{ll} x \text{ वस्तु की सीमांत उपयोगिता} = 5 & y \text{ वस्तु की सीमांत उपयोगिता} = 3 \\ x \text{ वस्तु का मूल्य} = 2 & y \text{ वस्तु का मूल्य} = 4 \end{array}$$

उपभोक्ता को Y वस्तु खरीदने में रुकना है, क्योंकि इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से कम है, जबकि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक है। ऐसी स्थिति से वह Y वस्तु के स्थान पर x की प्रतिरिक्त इकाइयाँ उस समय तक खरीदना चाहेगा जब तक कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती हुयी उसके मूल्य (2) के बराबर न हो जाय। इस स्थिति तक उसे कोई हानि नहीं होगी। Y वस्तु में खरीदने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी और अन्त में वह बढ़कर 4 तक पहुँच जायेगी। इस स्थिति पर पहुँचने पर x तथा y वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएँ तथा मूल्यों के अनुपात बराबर होंगे।

$$\left[ \frac{X \text{ वस्तु की सी. उ. (2)}}{X \text{ वस्तु का मूल्य (2)}} = \frac{Y \text{ वस्तु की सी. उ. (4)}}{Y \text{ वस्तु का मूल्य (4)}} \right]$$

इन अनुपातों के बराबर होने पर उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होगी।

## 6. नियम का व्यावहारिक उपयोग या महत्व (Application or Importance)

सम सीमान्त उपयोगिता या प्रतिस्थापन नियम का उपभोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में किया जा सकता है। इसका प्रयोग आर्थिक विशेषण के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है

(i) उपभोग प्रत्येक बुद्धिमान उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता या सतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते समय, कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुएं खरीदी जाएं, अर्थात् कम उपयोगिता वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन (Substitution) अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं द्वारा किया जाए। अधिकतम सतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं के खरीदते समय इस प्रकार व्यय किया जाए कि खरीदी जाएं वाली समस्त वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ समान रहें। इसी प्रकार विभिन्न उपयोगों वाली किसी वस्तु को किस उपयोग में लाया जाए? इस प्रश्न का भी समाधान इसी नियम के पालन द्वारा किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में से प्राथमिकता दी जाए? इस बात का निर्णय भी इस नियम की सहायता से लिया जा सकता है।

(ii) उत्पादन यह नियम उत्पादन-साधनों को विभिन्न उत्पादन-क्रियाओं के बीच बांटने में सहायक होता है। उत्पादन के क्षेत्र में इस नियम के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि विभिन्न उत्पादन साधनों को किस अनुपात में प्राप्त तथा प्रयोग किया जाय कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन सम्भव हो सके। इसके लिए महंगे साधन को सस्ते साधन से प्रतिस्थापित करने में यह नियम सहायक होता है। इसीलिए इसको प्रतिस्थापन-नियम (Law of substitution) कहा जाता है। इस नियम के आधार पर विभिन्न साधनों की सीमान्त उपयोगिताओं तथा मूल्य के अनुपातों में समानता लाने में सहायता मिलती है। उत्पादन के साधनों के विभिन्न प्रयोगों की सीमान्त उत्पादकता में समानता स्थापित करने में भी यह नियम लागू होता है।

(iii) विनिमय यह नियम मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। वस्तु खरीदते समय कोई भी व्यक्ति वस्तु की सीमान्त उपयोगिता में अधिक मूल्य नहीं चुकाता। विनिमय करना एक वस्तु का दूसरे वस्तु द्वारा प्रतिस्थापन करना है। इसके द्वारा अधिक दुर्लभ वस्तु को दुर्लभ वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

4 "The application of the principle of substitution extends over almost every field of economic enquiry"  
—Marshall

(17) वितरण : वितरण के क्षेत्र में इस नियम को सम-सीमान्त उत्पादकता नियम ( Law of Equi-Marginal Productivity ) कहते हैं। प्रत्येक उत्पादन साधन की उसकी सीमान्त उत्पादकता के अनुसार हिस्सा प्राप्त होता है। उत्पादक मशीन साधनों का प्रयोग ऐसे अनुपात में करता हूँ, जिसके निम्न उनकी सीमान्त उत्पादकता समान रहे, अन्यथा वह एक साधन की प्रतिस्थापना दूसरे साधन द्वारा करता है। अतः यह सिद्धान्त उत्पादन साधनों का पुरस्कार निर्धारित करने में सहायक होता है। देश में आर्थिक विषमता की समस्या का समाधान भी इस नियम की सहायता में किया जा सकता है। यदि देश में युद्ध की सीमा-न उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान है तो प्रत्येक व्यक्ति यह होगा कि उस देश में आय व धन का वितरण समान है।

(18) राजस्व : राजस्व के क्षेत्र में 'अधिकतम सामाजिक लाभ' का सिद्धान्त (Maximum Social Advantage Principle) सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त पर ही आधारित है। सरकार कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि समाज के विभिन्न वर्गों पर उनकी आय का अनुसार कर का भार समान पड़े जिससे किसी वर्ग विशेष को कर देने में अधिक कष्ट न उठाना पड़े। इस प्रकार राजस्व के क्षेत्र में व्यापक रूप से इस सिद्धान्त का उपयोग होता है।

इस प्रकार 'सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त' का पालन प्रत्येक प्रकार के आर्थिक मामलों में किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस नियम का पालन करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। यद्यपि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस नियम का पालन अज्ञात नहीं करता फिर भी किसी न किसी रूप में वह इस सिद्धान्त का पालन करता ही है। चर्चमें के शब्दों में, 'हम प्रतिस्थापन नियम या सम-सीमान्त नियम के अनुसार अपनी आय को वितरित करने के लिए उस भागि बाध्य नहीं होते जिस प्रकार ऊपर हवा में फेंका गया कपड़ा पृथ्वी पर बिखर होकर आ जाता है फिर भी हम मोटे रूप में ऐसा ही करते हैं। अर्थात् इस नियम का पालन करते हैं। क्योंकि हम तर्कशील प्राणी हैं।'<sup>5</sup>

### 7 नियम की आलोचना (Criticism of the Law)

यह नियम किन मामलों में पर आधारित है, उनका उल्लेख पहले किया जा

<sup>5</sup> "We are not of course, compelled to distribute our income according to the Law of Substitution or Equi Marginal Expenditure as a stone thrown in air is compelled, in a sense, to fall back to the earth but, as a matter of fact, we do so in a certain rough fashion because we are reasonable."

मुद्रा है। वस्तुओं की विभाज्यता, आय तथा व्यय की अवधि का एक ही होना, मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता सदैव समान रहना, उपभोक्ता की आय, रुचि आदि पूर्ववत् रहती हैं, आदि इस नियम की मान्यताएँ हैं। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन मान्यताओं का वास्तविक जगत में पाया जाना संदेहपूर्ण है। सामान्यतः इस नियम की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं :

(i) वस्तुओं की विभाज्यता ( *Divisibility of goods* ) यह नियम यह मानकर चलता है कि वस्तु का विभाजन अपरिमित सीमा तक किया जा सकता है, परन्तु बहुत सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे घड़ी, मोटरकार आदि। अतः ऐसी अविभाज्य वस्तुओं की खरीदते समय उपभोक्ता इस नियम का पालन पूर्ण अर्थों में नहीं कर सकता।

(ii) आय तथा व्यय की अवधि का एक होना ( *Synchronization of the Period of Income and Expenditure* ) बहुत सी वस्तुओं के उपभोग का समय आय प्राप्ति के समय से भिन्न होता है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग उभी अवधि में होता है जिस अवधि में कुल भौतिक आय व्यय की जाती है। आय तथा व्यय के समय में विभिन्नता के कारण, वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः इस नियम के अनुसार व्यय करना कठिन होता है।

(iii) वस्तु की पूर्ति ( *Supply of goods* ) यह नियम यह मानकर चलता है कि वस्तुओं की पूर्ति अपरिमित है तथा अधिक उपयोगी वस्तु को उपभोक्ता किसी भी मात्रा में खरीद सकता है। परन्तु व्यवहार में कभी-कभी ऐसा सम्भव नहीं होता है। जैसे उपभोक्ता के लिए, मान लीजिए, चीनी, चाय की अपेक्षा, अधिक उपयोगी है, परन्तु राशनिंग के कारण वह अधिक चीनी नहीं खरीद सकता है अर्थात् चाय की प्रतिस्थापन चीनी द्वारा नहीं कर सकता है।

(iv) उपभोक्ता की लापरवाही तथा असमानता ( *Carelessness and Ignorance* ) बहुत से व्यक्ति खरीद करते समय वस्तु की उपयोगिता की माप नहीं करते। वे 'अधिकतम सतुष्टि' का विचार भी अपने मस्तिष्क में नहीं लाते। ग्रामीण भारतीय जनता इसका ज्वलंत उदाहरण है। अज्ञानता के कारण भी व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता का अनुमान नहीं लगा पाता है।

(v) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता परिवर्तनशील है ( *Fluctuating Marginal Utility of Money* ) यह नियम यह मानकर चलता है कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक दशा में समान रहती है। परन्तु यह मान्यता यथार्थ

से बहुत दूर है। अन्य वस्तुओं की माति मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता से परिवर्तनशील है।

### 8. नियम की सीमाएं (Limitations of the Law)

वास्तव में इस नियम की श्राम सभी सामान्यताएं वस्तु-स्थिति से दूर हैं। इसकी कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं

(1) धन में विवेकशीलता तथा हिसाब की अनुभाव 'सामान्यता' की ई की उपमोक्षा धन करते समय विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना नहीं करता, बल्कि वह स्वभाव के अनुसार व्यय करता है। एक अन्यन्त ही समझदार तथा गणना करने वाला व्यक्ति ही उतनी सावधानी से व्यय करता है, जितनी कि इस नियम के प्रतिपादकों ने कल्पना की है।

(2) उपयोगिता का मापनीय न होना : वास्तव में, उपयोगिता की मापनीयता ही एक विवादग्रस्त विषय है। उपयोगिता की माप का कोई उचित माप-दण्ड न होने के कारण हम उपयोगिताओं की माप नहीं कर सकते। अतः इस नियम के अनुसार व्यय करना भी अत्यन्त ही कठिन है। यह नियम उपयोगितावादी धर्म-शास्त्रियों के सामाजिक व्यापार का एक नमूना है।

(3) वजट अवधि (Budget Period) का अनिश्चित होना : प्रो० बोर्डिंग का यह कहना है कि सामान्यतया उपभोक्ता की वजट अवधि निश्चित नहीं होती। अतः श्राद यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वह एक निश्चित वजट-अवधि में ही कार्यशील हो सकता है। इसका कारण यह भी है कि एक उपभोक्ता किसी अवधि विशेष की सीमित आय उसी अवधि में सम्भावित आवश्यकताओं पर इस प्रकार बाटना चाहता है कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सके। परन्तु वजट-अवधि निश्चित नहीं होने से वह इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता।

(4) रीति-रिवाज, श्रादत आदि के प्रभाव : रीति रिवाजों, श्रादत, फैशन आदि, के कारण भी उपभोक्ता अपने धन में मितव्ययता नहीं कर पाता। रीति-रिवाजों से उसे मानना पड़ता ही है। उन पर उसे अपने सीमित धन के कुछ भाग को खर्च करना पड़ता है। इसी प्रकार उसे अपनी श्रादत वन अपनी आवश्यकताओं (बाय-निसगरेट आदि) को पूरा करने के लिए कुछ धन व्यय करना पड़ता है। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि उपभोक्ता समझदारी से ही अपनी आय को खर्च करता है। ये रीति-रिवाज, फैशन तथा उसकी श्रादतें उसकी विवेकशीलता से बाधक हैं।

5 पूरक वस्तुओं (Complementary Goods) के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता यह नियम उन वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होता जो किसी अन्य वस्तु की पूरक होती हैं। उदाहरणार्थ, मोटर पेट्रोल, फाउन्टेनपेन स्याही आदि वस्तुएँ एक निश्चित अनुपात में ही खरीदी जाती हैं। इनमें प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।

6 वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन किसी भी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता उसके मूल्य पर निर्भर करती है। मूल्य ज्यादातर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से सीमान्त उपयोगिता भी बदलती रहती है, जिस कारण विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा मूल्यों की अनुपातिकता में समानता नहीं होती।

### प्रश्न तथा संकेत

#### (क) उपयोगिता (मामान्य प्रश्न)

1 सीमान्त तथा कुल उपयोगिता विश्लेषण में महत्व की विवेचना कीजिए। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है ?

(Rajasthan B A 1964)

[ संकेत सर्वप्रथम उपयोग, उत्पादन विनिमय वितरण तथा राजस्व के क्षेत्र में सीमान्त तथा कुल उपयोगिता विश्लेषण की महत्ता बताइए, तत्पश्चात् उपयोगिता मापने के सम्बन्ध में मतभेद का विवेचन कीजिए । ]

2 'उपयोगिता एक क्रमवाचक (ordinal) विचार है न कि गणनावाचक' (cardinal) विचार।' विवेचना कीजिए।

(Bihar B A Hons, 1965 A)

[ संकेत प्रश्न को दो भागों में विभक्त कर प्रथम भाग में उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा द्वितीय भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता और इसलिए यह क्रमवाचक विचार है न कि गणनावाचक । ]

3 सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का अन्तर बताइए। यह सिद्ध कीजिए कि जब एक वस्तु की 'सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो उसकी 'कुल उपयोगिता' अधिकतम होती है।

(Agra B Com I 1965)

[ संकेत आरम्भ में संक्षेप में उपयोगिता का अर्थ बताइए। इसके पश्चात् सीमान्त तथा कुल उपयोगिता का स्पष्ट विवेचन कीजिए। अन्त में सीमान्त तथा कुल उपयोगिता का सम्बन्ध बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है । ]

4. अर्थशास्त्र में सीमान्त उपयोगिता के महत्व को बताइए। यह उपयोगिता ह्रास नियम से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

[ संकेत सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के पाचों विभागों में सीमान्त उपयोगिता का महत्व बनाइए। इसके बाद यह स्पष्ट कीजिए कि उपयोगिता ह्रास नियम सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण पर ही आधारित है। ]

### (ख) उपयोगिता-ह्रास नियम

1. उपयोगिता ह्रास नियम को बताइए और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इससे मांग का नियम निकाला जाता है।

(Jodhpur T.D.C, Arts, 1964)

[ संकेत - सर्वप्रथम उपयोगिता ह्रास नियम की विवेचना कीजिए। इसके बाद यह स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इससे मांग का नियम निकाला जाता है। ]

2. "किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होगी उतनी ही उस वस्तु की प्रतिरिक्त मात्रा के लिए हमारी आवश्यकता कम होगी।" इस कथन को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या यह हमेशा सत्य होता है ?

(Rajasthan T.D.C. Com, 1964)

[ संकेत - सर्वप्रथम उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके पश्चात् इसके नियम के प्रमुख अपवाद या सीमाएँ बताइए। ]

3. किन दशावस्था के अन्तर्गत उपयोग की वस्तु की मात्रा में कृद्धि होने पर भी सीमान्त उपयोगिता नहीं घटती, और क्यों ?

[ संकेत - संक्षेप में उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा देते हुए इसके अपवादों की पूर्ण विवेचना कीजिए। ]

### (ग) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम

1. उपभोग में प्रतिस्थापन के सिद्धान्त (Law of Substitution in Consumption) की व्याख्या कीजिए। यह किस प्रकार उपभोक्ता की संतुष्टि (equilibrium) की दशा तक पहुँचने में मदद करता है ?

(Allah., B A I, 1965)

[ संकेत - सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को रेखाचित्र व उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात् बताइए कि इसके प्रयोग से ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और वह संतुलन की स्थिति में होगा। ]

2. 'प्रतिस्थापन के नियम की व्याख्या कीजिए और बताइए कि वह अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है।

[ सकेत : सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की रेखाचित्र व उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और इसके पश्चात् अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के क्षेत्र में इस नियम के प्रयोग को बताइए । ]

3. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की विवेचना कीजिए और एक चित्र की सहायता से यह सिद्ध कीजिए कि उपभोक्ता को अधिकतम सतुष्टि प्राप्त होती है यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता है ।

(Indore, B Com. I, 1965)

4. अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन के नियम के प्रयोग की विवेचना कीजिए । यह नियम उपयोगिता ह्रास नियम से किम प्रकार सम्बन्धित है ?

(Agra B A. I, 1962)

[ सकेत सर्व प्रथम 'प्रतिस्थापन के नियम' का आशय स्पष्ट कीजिए : तत्पश्चात् सक्षेप में अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में इसके प्रयोग को बताते हुए उपयोगिता ह्रास नियम के साथ इसका सम्बन्ध बताइए । ]



## उपयोगिता-विश्लेषण (II) उपभोक्ता की वचत (Utility Analysis Consumers Surplus)

*"The difference between what we would pay and what we have to pay is called consumer's surplus"*

—Penson

‘उपभोक्ता का अतिरेक’ या ‘उपभोक्ता की वचत’ के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों ने कही-कही जिक्र किया है। प्रो० जेम्स ने इनके विषय में निश्चित विचार व्यक्त किया था, परन्तु फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्युपिट (Dupuit) पहले अर्थ-शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा रेखा चित्र द्वारा इसे समझाने का प्रयत्न किया। (मन् 1844 ई० में) प्रो० मार्शल ने सन् 1879 ई० में इस सिद्धांत के विषय में अपने मौलिक विचार व्यक्त किये तथा बाद में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘Principles of Economics’ में इसका सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रो० जे० आर० हिक्स ने उदासीनता या तटस्थता दलों की सहायता से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है तथा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डा० ए० के० बास गुप्ता ने इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं।

### 1. परिभाषा (Definition)

व्यवहारिक जीवन में हम बहुत सी ऐसी वस्तुएँ खरीदते हैं, जिनके प्राप्त होने पर शायद हम बहुत अधिक मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते या बहुत सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम सामान्यतः अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, नमक, पोस्टकार्डें, अखबार आदि हम क्रय करते हैं। यदि ये वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध नहीं हों, तो अत्यधिक उपयोगी एवं आवश्यक होने के कारण हम उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके सामान्य मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य देने को तैयार हो जायेंगे। इन वस्तुओं के लिए हम जो मूल्य देते हैं, उससे बहुत अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु का

जो मूल्य हम चुकाते हैं, तथा वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते, इन दोनों मूल्यों के अन्तर को 'उपभोक्ता का अतिरिक्त' कहते हैं। जैसे हम पोस्टकार्ड 10 पैसे में खरीदते हैं, परन्तु यदि पोस्टकार्ड आसानी से नहीं मिल पाता है, तो हम सम्भवतः (अन्य विरल्यो की अनुपस्थिति में) एक पोस्टकार्ड के लिए 15 पैसे देने को भी तैयार हो जाते। अतः  $15 - 10 = 5$  पैसे हमारे लिए 'उपभोक्ता का अतिरिक्त' है। मार्शल ने 'उपभोक्ता की बचत' को इस प्रकार परिभाषित किया है, "किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक व्यक्ति (उपभोक्ता) जो कीमत उस वस्तु के लिये देने को प्रस्तुत है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है, उनका अन्तर ही सन्तुष्टि की बचत वा आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत' कहा जा सकता है।"

"The excess of the price which one is willing to pay rather than go without the thing over which he actually pays is 'the economic measure of this surplus of satisfaction. It may be called the Consumer's Surplus'"  
—Marshall

प्रोफेसर जे० के० मेहता ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है "किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त सन्तुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग के अन्तर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं।" प्रो० पेन्सन के शब्दों में, "हम जो कुछ चुकाने को तैयार हैं और जो कुछ हमको चुकाना पड़ता है, इन दोनों के अन्तर को 'उपभोक्ता की बचत' कहते हैं।" अतः जो हम चुकाने को तैयार हो जाते तथा जो हम वास्तव में चुकाते हैं इनका अन्तर ही 'उपभोक्ता का अतिरिक्त' है।

## 2. 'उपभोक्ता की बचत' तथा 'उपयोगिता ह्रास नियम' का सम्बन्ध

ये दोनों सिद्धान्त घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। वस्तुतः 'उपभोक्ता की बचत' का सिद्धान्त 'उपयोगिता ह्रास नियम' के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने पर, अन्य बातों के समान रहने पर, उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तब उस वस्तु से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है और उस वस्तु के लिए चुकाए गये मूल्य के रूप में हम उपयोगिता का त्याग करते हैं। खरीदने की इस क्रिया में प्राप्त उपयोगिता, त्याग की गई उपयोगिता से अधिक होती है। परन्तु ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदते जाते हैं, उस वस्तु की इकाइयों की उपयोगिता हमारे लिए उत्तरोत्तर कम

<sup>1</sup> "Consumer's surplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and which he foregoes in order to procure that commodity"

—J. K. Mehta, *Groundwork of Economics*, P. 52

होती जाती है, तथा हम उस समय वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को खरीदना बन्द कर देते हैं जबकि मूल्य के रूप में त्याग की जाने वाली उपयोगिता, उस वस्तु की इकाई से प्राप्त उपयोगिता के बराबर हो जाती है। यदि इसके पश्चात् भी उस वस्तु का खरीदना जारी रखा जाय, तो त्याग की गई उपयोगिता प्राप्त की जाने वाली उपयोगिता से अधिक होगी जो हमारे लिए हानि की सूचक है। दम्प की निम्न इकाई को खरीदने से प्राप्त तथा उसके खरीदने के लिये त्याग की गई उपयोगिताएँ बराबर होती है, उस इकाई से पूर्व खरीदी गई समस्त इकाइयाँ से प्राप्त उपयोगिता, त्याग की गई उपयोगिता से अधिक होती है। इस प्रकार से प्राप्त अधिक उपयोगिताओं के योग को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में।

(i) उपभोक्ता की बचत = (कुल उपयोगिता) — (कीमत × खरीदी गई इकाइयाँ)

इसी प्रकार मार्शल के अनुसार सम्पूर्ण बाजार के लिए भी उपभोक्ता की बचत शत की जा सकती है।

(ii) बाजार-सम्बन्धी उपभोक्ता की बचत = माग-मूल्यों का योग — वास्तविक कीमत

Consumer's surplus for the whole market = Aggregate Market Demand prices — Actual Selling Price

माग-मूल्य का अर्थ वह मूल्य है, जिस उपभोक्ता बुकाने को तैयार है। इस प्रकार सभी उपभोक्ताओं के माग मूल्यों को जोड़कर, कुल-उपयोगिता ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार प्राप्त कुल उपयोगिता में से श्रेताओं द्वारा वास्तविक बुकाई गई कीमतों को घटा दिया जाता है। अतः शेष ही उपभोक्ता की बचत होती है। हम यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आप, रुचि आदि में विभिन्नता के कारण, उन्हें प्राप्त उपयोगिताओं का अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु मार्शल ने कहा है कि यह कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं के ये अन्तर, सामूहिक रूप से, एक-दूसरे से समायोजित (Cancel out) हो जायेंगे।

### 3. स्पष्टीकरण

उद्युक्त विवेचना के आधार पर 'उपभोक्ता की बचत' का स्पष्टीकरण एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार में अमरुद खरीदता है। प्रत्येक अमरुद की कीमत 2 पैसे है।

अप्रतिमित सारणी से अमरुदों की इकाइयाँ, उनसे प्राप्त उपयोगिता तथा उपभोक्ता की बचत का ज्ञान होता है :

## अमरूदों से प्राप्त उपयोगिता (पैसे में)

अमरूदों की इकाई	प्राप्त उपयोगिता या कीमत जो उपभोक्ता देता	कीमत	उपभोक्ता की वचत
1	10	2	$10 - 2 = 8$
2	8	2	$8 - 2 = 6$
3	6	2	$6 - 2 = 4$
4	5	2	$5 - 2 = 3$
5	3	2	$3 - 2 = 1$
6	2	2	$2 - 2 = 0$
कुल उपयोगिता		कुल कीमत	उपभोक्ता की कुल वचत
34		$6 \times 2 = 12$	22

वह व्यक्ति पहला अमरूद खरीदता है तो उसे 10 पैसे के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। परन्तु यह कीमत केवल 2 पैसे देता है। वह जो उद्यो अमरूद की अधिक इकाइया खरीदता है उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। छठवा अमरूद खरीदने पर उपयोगिता तथा त्याग की गई उपयोगिता घटती जाती है (2 पैसे)। अतः वह सातवा अमरूद नहीं खरीदेगा। इन छः अमरूदों से उसे कुल 34 पैसे के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है तथा वह दो पैसे प्रति अमरूद की दर से 12 पैसे के बराबर उपयोगिता का त्याग करता है। इस प्रकार उसे  $34 - 12 = 22$  उपयोगिता के बराबर उपभोक्ता की वचत प्राप्त होती है।

## 4. रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण :

उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर रेखाचित्र नं 7 तैयार किया गया है जो उपभोक्ता की वचत को स्पष्ट करता है। चित्र में OY रेखा पर अमरूदों की इकाइया तथा OX पर उनसे प्राप्त उपयोगितायें प्रदर्शित की गई हैं। OMNR, आयत अमरूदों की कीमतों को प्रकट करता है। इस आयत के ऊपर जो आयत बने हुए हैं वे उपभोक्ता की वचत को प्रकट करते हैं।

## 5 उपभोक्ता की वचत की मान्यताएँ (Assumptions) :

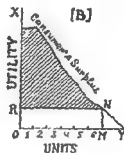
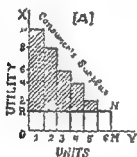
माशल द्वारा प्रस्तुत 'उपभोक्ता' की वचत का सिद्धान्त अग्रलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

(1) उपयोगिता की माप की जा सकती है, तथा मुद्रा उपयोगिता की माप का कार्य कर सकती है। इस प्रकार उपभोक्ता की वस्तु माप द्वारा मात की जा सकती है।

(2) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है। खरीदने की क्रिया में मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता है।

(3) वस्तु की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर है। अन्य वस्तुओं की पूर्ति से वस्तु विशेष की उपयोगिता प्रभावित नहीं होती है।

(4) हम जिस वस्तु के मूल्य में उपभोक्ता की वस्तु मात करते हैं, उस वस्तु की कोई स्तानापन (substitute) वस्तु नहीं होती है और यदि होती भी है तो हमें ऐसी वस्तुओं का मूल्य की वस्तु मान लेना चाहिए।



चित्र न० 7

## 6. उपभोक्ता की वस्तु की आलोचना . इसे मापने में कठिनाइयाँ

(Criticism and Difficulties in the measurement of Consumer's surplus)

उपरोक्त सांख्यिकी नया रेखाचित्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता की वस्तु की माप परसतापूर्वक की जा सकती है। परन्तु व्यावहारिक रूप से निम्नलिखित कारणों से इसकी माप करना व्यवस्त हो कठिन है। 'उपभोक्ता की वस्तु' की आलोचनाएँ मुख्यतः इसकी मान्यता के प्रश्न पर ही केंद्रित हैं।

(1) उपयोगिता मापनीय नहीं है - 'उपभोक्ता की वस्तु' इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता की माप जा सकता है, परन्तु हम यह जानते हैं कि उपयोगिता का सम्बन्ध मनुष्य की मानसिक स्थिति से है, इस प्रकार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, जिसे माप नहीं जा सकता है। माप ही माप उपयोगिता एक व्यक्ति निष्ठ (subjective) विचार है, अतः किसी भी विधि द्वारा उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है। उपभोक्ता की वस्तु, प्राप्त उपयोगिता,

तथा त्याग की जाने वाली उपयोगिता का अन्तर है, जब हम उपयोगिता को नाप नहीं सकते हैं, तब उपभोक्ता की वचन भी ज्ञात नहीं की जा सकती है।

(2) उपभोक्ता की रुचि में अन्तर सभी उपभोक्ताओं की अमिर्चि (Taste) समान नहीं होती है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु को बहुत चाहता है तथा दूसरा उसी वस्तु को उतना पसन्द नहीं करता है। यदि इस प्रकार के दोनो उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वे बाजार में समान मूल्य चुकायेंगे, परन्तु प्रथम उपभोक्ता की पसन्दगी अधिक होने के कारण, उस दूसरे उपभोक्ता की अपेक्षा अधिक उपयोगिता अर्थात् उपभोक्ता की वचन प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि उपभोक्ताओं की सरया बहुत अधिक है तो उनमें से कुछ की पसन्द किसी वस्तु के लिये अधिक होगी तथा कुछ की कम। इस प्रकार उन समस्त उपभोक्ताओं के सम्मेलन में उपभोक्ता की औसत वचन की माप की जा सकती है।

(3) आर्थिक स्थिति में अन्तर एक धनी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिक मूल्य चुकाने को तैयार हो सकता है जबकि एक निर्धन उपभोक्ता उतना अधिक मूल्य चुकाने को तैयार नहीं होगा। बाजार में धनी व निर्धन—दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं में समान मूल्य लिया जाता है, अतः उपभोक्ता की वचन की परिमाणा के अनुसार धनी उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता की वचन अधिक होगी तथा निर्धन उपभोक्ता के लिए कम। इस प्रकार आय में विभिन्नता के कारण उपभोक्ता की वचन में भी विभिन्नता होती है, अतः इसकी सही माप करना कठिन है। उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने पर औसत रूप से हम इस स्थिति में भी उपभोक्ता की वचन ज्ञात कर सकते हैं।

(4) कीमतों की सूची की अप्राप्यता हम उपभोक्ता की मांग-सूची, बाजार मूल्य के आधार पर तैयार करते हैं, परन्तु हम यह नहीं जान सकते हैं कि विभिन्न उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर कितना मूल्य देने को तैयार होगे। इस प्रकार इस मूल्य की जानकारी के अभाव में उपभोक्ता की वचन की माप अत्यन्त ही कठिन है।

(5) अनिवार्य आवश्यकताओं की उपभोक्ता की वचन अनिवार्य आवश्यकताओं की तीव्रता बहुत अधिक होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक है। ऐसी आवश्यकता से सम्बन्धित किसी वस्तु की प्रारम्भिक इकाइयों की उपयोगिता की माप करना कठिन है। इसी प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक वस्तुओं की उपयोगिता की माप भी अमापनीय होती है। ऐसी दशाओं में उपभोक्ता की वचन की माप करना बहुत कठिन है। प्रो० पैटन (Patten) ने

उपभोग की दो स्थितियों का वर्णन किया है—(i) दुःखमय धन्य-व्यवस्था (Pain Economy) तथा (ii) सुखमय धन्य-व्यवस्था (Pleasure Economy)। जीवन-रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति से उपभोक्ता केवल कष्ट निवारण करता है, सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त नहीं करता है। जब जीवन रक्षक अनिवार्यताओं की सन्तुष्टि हो जाती है, तब उपभोक्ता की स्थिति 'सुखमय' होती है। हम उपभोक्ता की वचत की माप सुखमय स्थिति में ही कर सकते हैं। प्रो० टास्सिग ने भी कहा है कि उपभोक्ता की वचत का प्रश्न उसी समय उठता है जब उपभोक्ता सुख का अनुभव करने लगता है।<sup>2</sup>

(6) प्रतिष्ठा भूतक वस्तुओं की उपभोक्ता की वचत : प्रतिष्ठा सम्बन्धी वस्तुओं जैसे होरा, प्राचीन मूर्ति व चित्र या वलाटमक वस्तुओं के सन्दर्भ में भी 'उपभोक्ता की वचत' बात की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं की ऊँची कीमत होने पर ही यही व्यक्ति उन्हें प्रतिष्ठा-भूतक तथा उपयोगी समझते है। यदि उनकी कीमत कम हो जाए तो उनके खरीददारों के लिए वे प्रतिष्ठा-भूतक नहीं रह जायेंगी तथा उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी। अतः ऐसी वस्तुओं की कीमत में कमी होने से, उपभोक्ता की वचत में वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की उपभोक्ता की वचत नहीं बात की जा सकती है।

(7) समाप्त पथ से प्रारम्भिक इकाइयों की उपभोक्ता का घटते जाना : उपभोक्ता ज्यों-ज्यों किसी वस्तु की अधिकारिक इकाइया खरीदता जाता है, धारम में क्रय की गई इकाइयों की उपभोक्ता घटती जाती है। उपभोक्ता की वचत की माप करते समय हम पहले खरीदी गई वस्तुओं की उपभोक्ता में हुए इस परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते हैं। परन्तु यह कठिनाई अव्यस्तविक है, क्योंकि उपभोक्ता की माप सारिणी भीषण नहीं बल्कि सीमान्त उपभोक्ता प्रवर्धित करती है। किन्तु वस्तु की अधिकारिक इकाइया खरीदने से वस्तु की विभिन्न इकाइयों की भीषण उपभोक्ता घटती जाती है सीमान्त उपभोक्ता मुक्त के अनुसार ही रहती है। अतः माप-सम्बन्धी यह कठिनाई वास्तविक नहीं है।

(8) मुद्रा की सीमान्त उपभोक्ता परिवर्तनशील : उपभोक्ता की वचत की माप करते समय मुद्रा की सीमान्त उपभोक्ता यथास्थिर मान ली जाती है, परन्तु उपभोक्ता ज्यों-ज्यों मुद्रा व्यय करता जाता है, उसके पास मुद्रा कम होती जाती है। अतः मुद्रा की समाप्त इकाइयों की सीमान्त उपभोक्ता में वृद्धि होती जाती है। इस

<sup>2</sup> "Only where the stage has been reached of possible comfort of some choice in the direction of expenditure, can there be anything in the form of a real surplus of satisfaction for the consumer."  
—Tassig

सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि एक वस्तु खरीदने में बहुत ही कम मुद्रा का प्रयोग किया जाता है (कुल आय की तुलना में)। अतः मुद्रा की इतनी थोड़ी मात्रा की उपयोगिता को यथा-स्थिर मान लेने से, उपभोक्ता की वचत के माप में अशुद्धि नगण्य होगी।

(9) स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता - यदि दो स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitutes) हैं तो उनकी अलग-अलग उपयोगिताओं का जोड़ उनकी सम्मिलित उपयोगिताओं से कम होता है, जैसे चाय और काफी दोनों ही अप्राप्य हो तो उपभोक्ता को अनुपयोगिता मान लीजिये 100 होगी। परन्तु केवल चाय अप्राप्य हो तो अनुपयोगिता (मान लीजिये) 30 तथा काफी के अप्राप्य होने पर 40 होगी। इस प्रकार अनुपयोगिता  $40 + 30 = 70$  होगी जो 100 से कम है। अतः स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता की मही माप नहीं की जा सकती है। मार्शल ने इस समस्या के समाधान के लिए यह सुझाव दिया है कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता समान मान लेनी चाहिए।

(10) अन्य आलोचना—यह सिद्धान्त काल्पनिक है (Other Criticism It is imaginary concept) : 'उपभोक्ता की वचत' की मापनीयता के सम्बन्ध में उपरोक्त तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी माप करना असम्भव है। परन्तु इसकी आलोचनाओं का अर्थ 'मापनीयता' तक ही नहीं है, बल्कि बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त को पूर्णतः कल्पना पूर्ण माना है। केनन, निकलसन, डेवेनपोर्ट आदि अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि 'उपभोक्ता की वचत' जिन मान्यताओं पर आधारित है, वे मान्यताएँ सर्वथा काल्पनिक एवं अव्यावहारिक हैं। जैसे यह सिद्धान्त इन मान्यताओं पर आधारित है : (1) उपयोगिता की माप की जा सकती है, (2) उपयोगिता को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। (3) वस्तु की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिताओं में विभिन्नता पाई जाती है। (4) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता यथास्थिर रहती है, आदि। परन्तु ये सभी मान्यताएँ अव्यावहारिक हैं। अतः मान्यताओं की अव्यावहारिकता के कारण यह सिद्धान्त काल्पनिक तथा अस्वाभाविक है।

प्रो० निकलसन ने व्यंगपूर्ण शब्दों में कहा है कि यह कहना अत्यन्त ही हास्यास्पद है कि 100 पाँड आय 1000 पाँड के बराबर है। 'उपभोक्ता की वचत' वस्तुतः यही बतलाती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त बारीक कल्पना मात्र है। परन्तु यह तर्क उतना सन्तोषजनक नहीं है जितना प्रतीत होता है। यह सम्भव है कि एक व्यक्ति 100 पाँड की आय से किसी ऐसे देश में अधिक सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है



गहा वस्तुयें सरसता से उपलब्ध हैं। इसके विपरीत 1000 गौद की आय वाला व्यक्ति, सम्भव है अपेक्षाकृत कम सन्तुष्टि प्राप्त करे, यदि वह ऐसे देश में रहता है जहाँ वस्तुयें बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती हैं।

इस सिद्धान्त की दूसरी प्रमुख आलोचना यह प्रस्तुत की गई है कि उपभोक्ता की वचत परिवर्तनीयता है। जैसा वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे प्राप्त उपभोक्ता की वचत कम हो जाती है। परन्तु हमका उत्तर यह दिया जा सकता है कि समाज में परिवर्तन हर दिशा में होते रहते हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है।

तीसरी प्रमुख आलोचना यह है कि उपभोक्ता की वचत का अनुमान प्रति-वार्मनसो के सन्दर्भ में नहीं लगाया जा सकता। ऐसी वस्तुओं की उपयोज्यता प्रतीत होती है।

उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'उपभोक्ता की वचत' एक काल्पनिक तथा अर्थज्ञानिक धारणा है, तथा इसकी माप नहीं की जा सकती, फिर भी इस धारणा का सैद्धान्तिक महत्व है। सैमुएलसन ने इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कहा है

"The subject is of historical and doctrinal interest with a limited amount of appeal as mathematical puzzle" —Samuelson

प्रत्येक उपभोक्ता व्यावहारिक रूप में उपभोक्ता की वचत मूल्यांकन करता है। वस्तुओं की खरीदते समय, उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है, वह कीमत नि सन्देह उस कीमत से कम रहती है, जो उस वस्तु के प्राप्त न होने की अवस्था में उपभोक्ता चुकाने के लिए तैयार होता है। हा, वह आलोचना सही है कि उपभोक्ता की वचत की सही माप नहीं की जा सकती।

## 7 उदासीनता वक्रों द्वारा उपभोक्ता की वचत की माप

(Measuring Consumer's Surplus with the Help of Indifference Curves)

प्रो० हिडस और ऐन्ग ने यह कहा है कि न तो उपभोक्ता की माप की जा सकती है और न मुद्रा की सीमात उपयोगिता ही स्थिर है। उनके अनुसार हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि व्यय की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा की सीमात उपयोगिता बढ़ती जाती है। यदि हम उपभोक्ता का वचत को आय की वचत (Saving of Income) की तरह मान लें तो मुद्रा की सीमात उपयोगिता को स्थिर मानना अनानुषंगिक हो जाता है। मुद्रा की सीमात उपयोगिता को यथास्थिर मानने का अर्थ यह होगा कि हम कीमत परिवर्तन के साथ प्रभाव (Income effect of

4 "Samuelson, Foundations of Economic Analysis, II 207

price changes) की उपेक्षा कर रहे हैं। प्रो० हिक्स ने (i) उपयोगिता को अमापनीय (ii) मुद्रा की सीमात उपयोगिता को परिगर्ननशील मानकर और (iii) स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उदासीनता वक्रों<sup>3</sup> की सहायता से उपभोक्ता की वचत को मापने का ढंग बतलाया है। इस प्रकार उन्होंने मार्शल द्वारा दत्ताए गए 'उपभोक्ता की वचत' के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। हिक्स ने 'उपभोक्ता की वचत' को नये दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि यदि वस्तु की कीमत गिरती है, तो उपभोक्ता के लिए इसके दो परिणाम हो सकते हैं। (i) उस मस्ती वस्तु (वस्तु जिसकी कीमत गिर गई है) की वह पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा खरीद सकता है, तथा इस प्रकार अधिक खरीदी हुई वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तु के स्थान पर कर सकता है, जिनकी कीमत गिरी नहीं है, तथा (ii) कीमत गिर जाने से वस्तु सस्ती हो जाएगी तथा पहले जितनी मात्रा खरीदने पर उपभोक्ता का खर्च अब कम होगा। इन दोनों बातों का प्रभाव यह होगा कि उपभोक्ता, कीमत गिर जाने के कारण, पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति में होगा अर्थात् कीमत गिरने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक-आय में जो वृद्धि हो जायेगी, वह वृद्धि उपभोक्ता की वचत है। हिक्स के शब्दों में, उपभोक्ता की वचत को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले लाभ को मौद्रिक आय के रूप में व्यक्त करना।<sup>4</sup> "The best way of looking at consumer's surplus is to regard it as a means of expressing in terms of money income, the gain which accrues to the consumer as a result of a fall in prices." (Hicks, Value and Capital, p 13) अतः हिक्स द्वारा प्रस्तुत व्याख्या अधिक वैज्ञानिक तथा उनके तर्क अधिक व्यावहारिक हैं। चित्र सं० 8 द्वारा हिक्स के विचारों को समझाने का प्रयत्न किया गया है।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण चित्र में तीन प्रकार की उपभोक्ता की वचतों का ज्ञान होता है।

(1) मार्शल की उपभोक्ता की वचत (The counterpart of Marshallian concept) उपभोक्ता की मौद्रिक आय (Money Income) OY अक्ष पर तथा वस्तु की मात्रा को OX पर दिखाया गया है। MP<sub>1</sub> कीमत रेखा है। बिन्दु

<sup>3</sup> उदासीनता वक्रों के अध्ययन हेतु अध्याय 11 देखिए।

<sup>4</sup> अधिकांश पुस्तकों में चित्र 8 के स्थान पर दूसरे चित्र दिए गए हैं, परन्तु यह चित्र अधिक स्पष्ट है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इस एक ही चित्र द्वारा हम तीन प्रकार की उपभोक्ता की वचत को माप सकते हैं। देखिए, 'A Survey of Contemporary Economics' Edited by Ellis, Vol I, Chapter I—Value and Distribution, an article by B E Haley



"Consumer's surplus is the compensating variation in income whose loss would just offset the fall in price, and leave the consumer no better off than before "

—Hicks

यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है अर्थात् वह अपनी आय द्वारा अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। अतः उपभोक्ता की बचत मौद्रिक आय में उस क्षति के बराबर होगी, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय पहले के समान रहती है। जैसे किसी व्यक्ति की दैनिक आय दो रुपये है। वह इन दो रुपये से एक गज कपड़ा खरीद सकता है। यदि कपड़े का भाव दो रुपये प्रति गज से घटकर एक रुपया प्रति गज हो जाए तो अब उपभोक्ता एक रुपया में ही एक गज कपड़ा खरीद सकेगा। यदि उसकी आय दो रुपया प्रति दिन से कम करके केवल एक रुपया प्रतिदिन कर दी जाए तो भी उसकी वास्तविक आय में कमी नहीं होगी, क्योंकि वह घटी हुई आय से भी, वस्तु सस्ती हो जाने के कारण, पहले जितनी मात्रा में वस्तु खरीद सकता है। इस प्रकार उसकी वास्तविक आय पहले जैसी ही रहेगी। अतः इस उदाहरण में उपभोक्ता की बचत एक रुपया हुई जो वस्तु की कीमत गिरने तथा मौद्रिक आय पहले के ही समान रहने के कारण प्राप्त होती है। चित्र में  $MP_2$  पहले की कीमत रेखा है। उपभोक्ता  $OX_2$  वस्तु की मात्रा +  $OA$  मुद्रा के संयोग पर है अर्थात् वह  $OX_2$  मात्रा के लिए  $FR$  मुद्रा देता है। अब यदि हम उपभोक्ता को ऊँचे तटस्थता वक्र से नीचे तटस्थता वक्र (From higher indifference curve to lower indifference curve) पर लाएँ, परन्तु उपभोक्ता को हम स्वतंत्रता दें कि वह वस्तु की जितनी मात्रा चाहे खरीद सके (कीमत कम होने के कारण) तो वह अब पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा खरीद सकेगा। यदि हम उसे पहले वाली ही तटस्थता वक्र पर रहने दें अर्थात् पहले जितनी मात्रा खरीदने दें तो वह पहले जितनी मात्रा अब कम आय से ही खरीद सकता है, अर्थात् यदि उसकी आय घटा दी जाए तो भी वह मूल्य कम होने के कारण, वास्तविक आय की दृष्टि से पहले की ही स्थिति में रहेगा। चित्र में स्पष्ट है कि यदि उसकी आय  $OM$  से घटाकर  $OA$  कर दी जाए तो भी वह कीमत कम होने के कारण ( $AP_1$  कीमत रेखा घटी हुई कीमत को प्रकट करती है) पहले की ही स्थिति में रहेगा। इस प्रकार  $OM - OA = MA$  उपभोक्ता की बचत हुई जिसे हम Compensating Variation कह सकते हैं।

(3) समान परिवर्तन (Equivalent Variation) : यदि उपभोक्ता को वस्तु खरीदने का मिल्कुल मौद्रिक न दिया जाए तो वह कीमत की कमी से लाभ नहीं उठा सकेगा। अतः वह इसके लिए क्षति पूर्ति चाहेगा। उसे इतनी मात्रा में क्षति पूर्ति मिलनी चाहिए जिसमें वह Higher Indifference curve पर रह सके। क्षति पूर्ति की इस मात्रा को Equivalent Variation कहते हैं। (Equivalent Variation

is the amount of added income that would compensate the consumer for the loss of the opportunity to purchase any of the commodity Haley, op cit p. 5) बिच से स्पष्ट है कि पहले आय OM थी। उसकी वह  $OX_1$  माना  $+OA$  मुद्रा के समोप पर था। अब यदि उसे वस्तु बिन्दु न सरीदने दिया जाय तो वह OM मुद्रा से ही संतुष्ट नहीं होगा।  $OX_2$  वस्तु के बढ़ते उतरे अब क्षतिपूर्ति चाहिए। अतः यदि हम उसे पहले जितना ही समुद्ध रररना चाहते हैं। (पहले के तटस्थता-वक्र पर रखना चाहते हैं, अर्थात् उसे वस्तु की शून्य माना  $+OK$  मुद्रा चाहिए) परन्तु वस्तु सरीदने नहीं देते हैं तो वह तटस्थता वक्र पर R बिन्दु से हट कर K बिन्दु पर जाएगा, K बिन्दु पर उसका समोप OK मुद्रा  $+X$  वस्तु की शून्य माना होगी। (उपकी आय में MK के बराबर वृद्धि होनी चाहिए) अर्थात् इस दशा में MK उपभोक्ता की वचत हुई।

Hicks ने इसे (MK मुद्रा वृद्धि की) quantity-equivalent variation in income' कहा है तथा I. M D Little ने 'quantity-compensating variation in income' कहा है। इस प्रकार बिच नं० 8 से तीन प्रकार की उपभोक्ता वचतों का ज्ञान होता है

(i) Marshall's Consumer's Surplus = RV

(ii) Compensating Variation = MA

(iii) Equivalent Variation = MK

(रनने अतिरिक्त भी उपभोक्ता की वचत के सम्बन्ध में अन्य विचार व्यक्त किए गए हैं। परन्तु स्नातक तथा धनार्न के विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त विवरण ही पर्याप्त है।)

## 8 उपभोक्ता की वचत का महत्व (Importance of Consumer's Surplus)

विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं तथा उपभोक्ताओं की वचत की सदैवपूर्ण मापनीयता के होते हुए भी यह विद्वान् अवश्य ही महत्वपूर्ण है

(1) सैद्धान्तिक महत्व उपभोक्ता की वचत द्वारा हमें इस तथ्य का ज्ञान होता है कि हम समाज या अर्थ व्यवस्था के ऐसे अवस्था में प्राप्त होते हैं जिनके विषय में हम जागरूक नहीं हैं या सामान्यतः हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। इससे हम बात का पता चलता है कि जिस देश में विभिन्न प्रकार की सरती वस्तुएं उपलब्ध माना में उपलब्ध होती हैं उस देश में उपभोक्ताओं को अत्यधिक माना में उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त प्राप्त होता है। हम अचेत रूप में सामाजिक कल्याण से जो लाभ प्राप्त होता है, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। यदि एक कुशल उत्पादक को प्राकृतिक साधन मज्जीन, धन तथा प्राविधिक ज्ञान (जो समाज से ही प्राप्त होते हैं) आदि से वंचित कर दिया जाए तो उसकी कुशलता का कुछ भी उप-

योग नहीं होगा। इन चीजों में उसे जो लाभ प्राप्त होते हैं, वे परोक्ष रूप में उसके लिए 'उपभोक्ता की बचत' के प्रतीक हैं : संयुक्तलसन के शब्दों में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कम मूल्यों पर खरीदने में समर्थ होना कम महत्वपूर्ण नहीं है ..... यह अत्यन्त ही स्पष्ट है कि हम एक ऐसे आर्थिक जगत की सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसका निर्माण हमने कभी नहीं किया था।<sup>4</sup>

(2) मूल्यों का अन्तर उपभोक्ता की बचत द्वारा हमें प्रयोग मूल्य (Value-in use) और विनिमय मूल्य (Value-in-Exchange) का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इन दोनों के अन्तर द्वारा उपभोक्ता की बचत जानी जाती है।

(3) आर्थिक तुलना इस सिद्धान्त की सहायता से हम दो देशों के आर्थिक विकास तथा उन्नति (Development and Progress) की तुलना कर सकते हैं। अधिक उपभोक्ता की बचत (अन्य बातों के यथावत् रहने पर) आर्थिक उन्नति का प्रतीक है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसके द्वारा हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभों का अनुमान लगा सकते हैं। सस्ती दर पर विदेशी वस्तुएं खरीदने से अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, जो उपभोक्ता की बचत का चातक है।

(5) मूल्य परिवर्तन का प्रभाव : इसकी सहायता से मूल्य परिवर्तन द्वारा उपभोक्ताओं पर पड़े प्रभाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्य-परिवर्तन से उपभोक्ता की बचत में हुई वृद्धि उपभोक्ता के लिए हितकर होती है।

(6) कर नीति : सरकार इसके द्वारा विभिन्न वर्गों पर पड़े कर-भार का अनुमान लगा सकती है। अतिरिक्त कर उपभोक्ता की बचत को कम करता है, अतः सरकार ऐसी कर नीति अपना सकती है, जिससे उपभोक्ता की बचत में न्यूनतम कमी हो।

(7) एकाधिकारी यह सिद्धान्त एकाधिकारी (Monopolist) के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखते हुए एकाधिकारी मूल्यों में इस प्रकार परिवर्तन करता है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके। यदि किसी वस्तु में उपभोक्ताओं को 'उपभोक्ता की बचत' बहुत अधिक प्राप्त होनी है, तो एकाधिकारी ऐसी वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ा सकता है। परन्तु मूल्य बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वही 'उपभोक्ता की बचत' पूर्णतया समाप्त न हो जाए। ऐसी मूल्य-वृद्धि से वस्तु की माग कम हो जाएगी।

<sup>4</sup> "The privilege of being able to buy a vast array of goods at low prices cannot be over-estimated. It is only too clear that all of us are reaping the benefits of an economic world we never made."  
— Samuelson

## प्रश्न तथा संकेत

1. 'उपभोक्ता वचन' के विचार की व्याख्या कीजिए। अर्थशास्त्र में इसका क्या महत्व है ?

(Jiwaji, B. A. I, 1967, Udaipur T D. C. Com. 1967)

[संकेत—सर्वप्रथम उपभोक्ता विचार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। इसके पश्चात् अर्थशास्त्र में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।]

2. संतुष्टता वक्र विज्ञापण (Indifference curve Technique) की सहायता से उपभोक्ता वचन के निर्धारण की विवेचना कीजिए।

(Ravishankar, B A., 1965)

3. उपभोक्ता की वचन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और इसके मापने की कठिनाइयों को समझाइए। (Raj., T. D. C. Com., 1964)

4. उपभोक्ता की वचन के सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यह कैसे मापी जा सकती है ? चित्र कीजिए। (Agra, B. Com. I, 1965)

[संकेत—प्रथम भाग में उपभोक्ता की वचन के आशय को रेखाचित्र व उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। द्वितीय भाग में उपभोक्ता की वचन को मापने की विधि बताइए। तृतीय भाग में इसकी मापने के सम्बन्ध में कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए।]

## उपयोगिता विश्लेषण (III) : मांग (Utility Analysis (III) : Demand)

*"The demand for anything, at a given price, is the amount of it, which will be bought per unit of time at that price."*

—Benham

समस्त उत्पादन-व्यवस्था 'मांग' पर आधारित है। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग, समाज की सामाजिक मांग, राष्ट्र की राष्ट्रीय मांग, यहाँ तक कि विभिन्न देशों की मांगों की मात्राओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय 'मांग' की पूर्ति करने के लिए ही किसी देश की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं।

### 1. मांग का अर्थ (Meaning of Demand)

अर्थशास्त्र में किसी इच्छा (desire) तथा आवश्यकता (need) मात्र को मांग (demand) नहीं कहा जाता, क्योंकि केवल इच्छा मात्र से ही कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं हो जाती। वस्तुतः जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की इच्छा-पूर्ति के लिए मूल्य के रूप में उचित प्रतिफल (Consideration) देने के लिए तत्पर तथा समर्थ होता है, तभी उसकी इच्छा प्रभावकारी मानी जाती है। अतः 'मूल्य से सम्बन्धित प्रभावकारी इच्छा (effective desire related to price)' को ही अर्थशास्त्र में मांग कहा जाता है। मूल्य के अतिरिक्त मांग का सम्बन्ध समय की एक निश्चित इकाई या अवधि (unit or period of time) से भी होता है। अतः बेनहम के अनुसार "एक दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी समय विशेष पर भ्रय की जाएगी।"

मांग के उपर्युक्त अर्थ से यह ज्ञात होता है कि मांग के अप्रलिखित तीन तत्व हैं :



(1) मांग का प्रभावोत्पादक इच्छा (effective desire) होना केवल प्रभावोत्पादक इच्छा ही मांग होती है। अन्य मांग में भी आवश्यकता की तरह (i) इच्छा (ii) पर्याप्त क्रय शक्ति या धन तथा (iii) क्रय शक्ति या धन व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक है।

(2) मांग का मूल्य से सम्बन्ध होना मांग का मूल्य से सम्बन्ध होना अनिवार्य है (Demand, in Economics, always means demand at a price)। किसी भी वस्तु या सेवा की मांग उसके मूल्य के सन्दर्भ में ही व्यक्त की जाती है। इसका कारण यह है कि बदलते हुए मूल्यों पर मांग, अर्थात् वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा बदलती करती है।

(3) समय की अवधि से सम्बन्ध होना मांग का हमेशा एक निश्चित समय की इकाई या अवधि, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने या प्रति वर्ष के सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है। अन्य यह कटा जाता है कि मांग किसी निश्चित मूल्य पर किसी विशेष समय में होती है (Demand is at a price and at a time)।

उपर्युक्त तत्वों पर बोबर (Bober) तथा मेयर्स (Meyers) की निम्नलिखित परिभाषाओं से अच्छा प्रज्ञा पड़ना है

बोबर के अनुसार "मांग से हमारा आशय एक ही दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता किसी एक बाजार में, किसी दिए गए समय में विभिन्न मूल्यों पर अथवा विभिन्न आयों पर अथवा सम्बन्धित वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों पर व्यय करेंगे।"<sup>1</sup>

मेयर्स के अनुसार, 'किसी वस्तु की मांग किसी निश्चित समय में सभी संभव मूल्यों पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जिन्हें खरीदने के लिए क्रेता तत्पर होंगे।'<sup>2</sup>

मांग तथा प्रभावकारी मांग (effective demand) में अन्तर मांग किसी मूल्य पर खरीदी जाने वाली किसी वस्तु की खरीदी जान वाली मात्राओं या वस्तुओं

<sup>1</sup> "By demand we mean the various quantities of a given commodity or service which consumers would buy in one market in a given period of time at various prices, or at various incomes, or at various prices of related goods." —Bober

<sup>2</sup> "The demand for a goods is a schedule of the amounts that buyers would be willing to purchase at all possible prices at any one instant of time." —Meyers

को घटाती है, जबकि प्रभावकारी मांग किसी व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की वास्तव में खरीदी गई सत्या या मात्रा को बतनाती है।

**मांग तथा आवश्यकता में अन्तर :**

अर्थशास्त्र में प्रभावकारी इच्छा को मांग तथा आवश्यकता दोनों ही कहा जा सकता है, किन्तु मांग का अर्थ आवश्यकता से भिन्न होने के कारण 'मांग' को ऐसी प्रभावकारी इच्छा कहते हैं जिसका सम्बन्ध मूल्य तथा समय-विशेष से होता है। वस्तुतः मांग को मूल्य से सम्बन्धित आवश्यकता (want related to price) भी कहा जा सकता है। मिल के अनुसार "मांग शब्द से हमारा अभिप्राय निश्चय ही मांग की मात्रा से होना चाहिए।" (We must mean by the word 'demand' the quantity demanded)। इस अर्थ में मांग उसी समय व्यक्त की जा सकती है, जबकि उसे मूल्य के साथ सम्बद्ध किया जाता है। अतः आवश्यकता केवल एक ऐसी प्रभावकारी इच्छा है जिसके पीछे क्रय-शक्ति तथा वस्तु को खरीदने की तत्परता मान ही रहती है।

## 2 मांग-सूची (Demand Schedule)

(i) व्यक्तिगत मांग-सूची : यह सूची, जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी दिए गए समय में एक काल्पनिक बाजार में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बतलाती है, व्यक्तिगत मांग-सूची (Individual Demand Schedule) कहलाती है। यह सूची किसी वस्तु या सेवा के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के फलनीय सम्बन्ध (functional relationship) को व्यक्त करती है।<sup>3</sup>

(ii) उद्योग या बाजार मांग सूची (Industry or Market Demand Schedule) : सभी उपभोक्ताओं की एक निश्चित समय व्यक्तिगत मांग सूचियों में दी गई वस्तु-विशेष की विभिन्न मूल्यों पर कुल खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं के योगों से तैयार की गई सूची उद्योग या बाजार-मांग सूची कहलाती है। मान लीजिए X, Y और Z तीन व्यक्तियों की मांग सूची अप्रलखित हैं :

<sup>3</sup> ... "Relationship between price and quantity bought is called the demand schedule or 'demand curve'.

## व्यक्तिगत और बाजार माग सूची

व्यक्तिगत माग-सूचियाँ (दैनिक)				बाजार माग-सूची (दैनिक)	
मूल्य (प्रति इकाई) ₹०	मागी गयी इकाइयों की मात्राएँ			मूल्य प्रति इकाई ₹०	कुल मागी गयी इकाइयों की मात्राएँ
	X	Y	Z <sub>1</sub>		
6	2	3	1	6	6
5	4	5	3	5	12
4	6	8	4	4	18
3	8	10	7	3	25
2	10	13	11	2	34
1	12	18	14	1	44

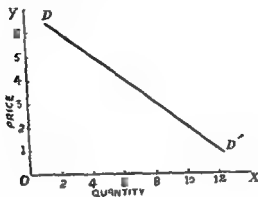
उपर्युक्त बाजार माग-सूची अनुमानों पर आधारित तथा काल्पनिक हैं क्योंकि वास्तविक जीवन में बाजार माग-सूची तैयार करना असम्भव है। इस सम्बन्ध में हम केवल यह ध्येय रखते हैं कि मूल्य के घटने पर वस्तु की माग की मात्रा बढ़ेगी तथा मूल्य-वृद्धि से माग की मात्रा घटेगी। माग को निर्धारित करने वाले तारों में परिवर्तन होने रहते हैं। इसके साथ ही ऐसी कोई यत्नोपज्जक विधि भी नहीं है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सके कि प्रचलित मूल्य पर कितनी अधिक प्रत्येक कितनी कम माग होगी? उस समय तक इस तथ्य को ज्ञात करने का प्रयत्न ही उपस्थित नहीं होता, जब तक कि अन्य परिस्थितियाँ (पैट्रिक अन्य स्तर सहित) समान रहती हैं। माग-सूची तो केवल इस बात की जानकारी प्रदान करती है कि किसी समय-विशेष पर एक ही बाजार में, 'पूर्ण बाजार (Perfect market) होने पर' केवल एक ही मूल्य प्रचलित होता है।

## 3 माग-वक्र (Demand Curve)

“माग सूची का चित्रोत्करण नाम वक्र कहलाता है।”<sup>4</sup> माग-वक्र द्वारा माग-सूची में दी गयी माग की मात्राओं को रेखा-चित्र द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी माग की जाने वाली मात्राओं के सम्बन्ध को व्यक्त करने वाले रेखाचित्र पर अंकित वक्र माग-वक्र कहलाता है। जैसा कि दिए गए चित्र व स्पष्ट है, शीर्ष (vertical)-अक्ष (Oy-axis) पर वस्तु-विशेष के विभिन्न मूल्यों (प्रति इकाई) को अंकित किया है तथा क्षैतिज (horizontal) अक्ष (Ox-axis) पर वस्तु की विभिन्न मात्राएँ प्रदर्शित की गई हैं। दिए गए चित्र

\* “.....Pictorialization of the demand schedule is called the demand curve.”  
—Samuelson

मे की माग सूची से एक माग वक्र खींचा गया है। इस वक्र को देखने पर यह ज्ञात होगा कि यह वक्र भी 'उपयोगिता वक्र' (Utility Curve) के ही स्वरूप है।



चित्र न० 9

ऊपर दिए गए चित्र में माग वक्र का रूप एक सीधी रेखा के समान है, किन्तु इसके कई अन्य रूप भी हो सकते हैं। वह उन्नतोदर (convex) अथवा नतोदर (concave) अथवा उसका आंशिक भाग एक रूप में तथा शेष भाग किसी अन्य रूप में हो सकता है। उसका चाहे जो भी रूप हो, अधिकांश माग वक्रों की ढाल (slope) सदैव दायीं तरफ ढाँचे की ओर होती है (always slope downward from left to the right)।

(i) मूल्य माग (Price Demand) किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित (hypothetical) मूल्यों पर किसी वस्तु या सेवा की खरीदी जाने वाली मात्राओं को 'मूल्य माग' कहा जाता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि उक्त समय में माग को प्रभावित करने वाले तत्वों, जैसे आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता की इस प्रकार की माग व्यक्तिगत माग (individual demand) कहलाती है। परन्तु वस्तुओं तथा सेवाओं की उपभोक्ताओं की सामूहिक या सम्मिलित माग को उद्योग या बाजार-माग (Industry or Market Demand) कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा की मात्रा की व्यक्तिगत अथवा बाजार माग को निर्धारित करते समय यह मान लिया जाता है कि उससे (वस्तु या सेवा से) सम्बंधित वस्तुओं या सेवाओं (related goods or services) के मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(ii) आय माग (Income Demand) : आय माग का अधिकांश वस्तुओं तथा सेवाओं की उन मात्राओं से है, जो एक निश्चित समय में, आय वृद्धि के पथावत् रहने पर, उपभोक्ता विभिन्न आय स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार है।

आय-माग को ज्ञात करते समय मूल्यों को अपरिवर्तित मानने के साथ साथ यह भी मान लिया जाता है कि उपभोक्ताओं की रुचि तथा आदतों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक बाजार में निश्चित समय में विभिन्न आय स्तरों पर किसी वस्तु की क्रिमांश की जाने वाली मात्राओं की सूची को आय-माग सूची (Income-Demand-Schedule) कहा जाता है। आय-माग, विभिन्न आय-स्तरों तथा वस्तु की कीमत की जाने वाली मात्राओं के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करती है। इस आय-माग सूची (Income Demand Schedule) के एक स्तंभ (column) में आय तथा दूसरे स्तंभ में विभिन्न आय-स्तरों पर वस्तु की मात्राएं उल्लेखित की जाती हैं। इस सूची से आय तथा माग की मात्राओं के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रदर्शित करने के लिए आय माग-वक्र (Income Demand Curve) खींचा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि आय-स्तर ऊंचा होने पर उच्चोत्पादनीय किस्म की वस्तुओं (economically inferior goods) के माग पर अप्रत्यक्ष क्रिया की वस्तुएं खरीदने लगती हैं। इन कारण अप्रत्यक्ष वस्तुओं की माग बढ़ जाती है और उसकी अधिक मात्राएं खरीदी जाती हैं। इसके विपरीत आय कम होने पर नीची किस्म की वस्तुओं की अधिक मात्राएं खरीदी जाती हैं।

(iii) तिरछी माग (Cross Demand) तिरछी माग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु के मूल्य तथा आय के समान रहने पर, वस्तु सम्बन्धित मूल्यों से परिवर्तन होने पर, खरीदने को तैयार है। इस प्रकार की माग वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं तथा उस वस्तु के सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के सम्बन्ध का ज्ञान कराती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित वस्तु प्रतिस्पर्धी (competing) या प्रतिस्थापक (substitute) हो, जैसे चाय और काफी, श्रवण सहयोगी (cooperating) या पूरक (complementary) हो, जैसे चाय और चीनी। यदि काफी का मूल्य कम हो चाय और चाय का मूल्य बढ़ाव रखे तो उपभोक्ता निश्चित रूप से चाय के स्थान पर काफी की अधिक मात्रा खरीदने को तैयार होगा। ऐसी स्थिति में चाय को प्रतिस्थापक वस्तु या माग-वक्र (Demand Curve) बायीं ओर नीचे से ऊपर की ओर जायेगा।

यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की पूरक है, जैसे चाय और चीनी, मोटर तथा पेट्रोल आदि, तो किसी एक आवश्यकता-विवेक की पूर्ति के लिए दोनों सहयोगी वस्तुएं आवश्यक होती हैं। उदाहरणार्थ, चाय के लिए चीनी पूरक वस्तु है। यदि चाय का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी अधिक मात्राएं खरीदने पर चीनी की अधिक मात्राएं खरीदने की जायेंगी। इस स्थिति में चीनी पर तिरछा-माग-वक्र

(Cross Demand Curve) का झुकाव चाय के मांग चक्र की तरह ही दायाँ तरफ ऊपर से नीचे की ओर होगा ।

उपयुक्त दोनों स्थितियों में किसी वस्तु की मांग की मात्राओं तथा उनकी प्रतिस्पर्धक अथवा पूरक वस्तुओं की मांग की मात्राओं के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए मांग-नूची के एक खान में प्रथम वस्तु के मूल्यों को तथा दूसरे खान में दूसरी वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्राओं को लिखते हैं ।

## 5. मांग का नियम (The Law of Demand)

### 1. परिभाषा .

किसी वस्तु के मूल्य तथा मांग की जाने वाली उसकी मात्रा के सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला नियम मांग का नियम कहा जाता है । यह नियम बतलाता है कि मांग मूल्य के विपरीत बदलती रहती है, अर्थात् अधिक मूल्य पर वस्तु-विरोध की कम मात्रा खरीदी जाएगी और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, बशर्ते कि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहें । सैमुएलसन (Samuelson) के अनुसार “.....यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाय, तो अन्य बातों के समान रहने पर, वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है ।”

मांग का नियम एक गुणात्मक ( qualitative ), न कि परिमाणात्मक ( quantitative ), वस्तु है । वह किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की दिशा का संकेत करता है, उसके वास्तविक परिमाण ( magnitude ) का नहीं । जैसे यह कहा जाय कि 100 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से किसी समय विज्ञेय में (प्रति सप्ताह) गेहूँ की मांगी जाने वाली मात्रा 500 क्विन्टल है, तो 80 रु० प्रति क्विन्टल मूल्य हो जाने पर गेहूँ की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी होगी ? यह जान करना कठिन होता । इस नियम के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गेहूँ 500 क्विन्टल से अधिक क्रय किया जायेगा । अतः यह स्पष्ट है कि मूल्य में वृद्धि या मूल्य में कमी होने पर मांग का नियम केवल मांग की मात्रा में क्रमशः कमी अथवा वृद्धि की ओर ही संकेत करता है, मांग की जाने वाली

<sup>5</sup> “When the price of a good is raised (at the same time that all other things are held constant), less of it will be demanded -- People will buy more at lower prices and buy less at higher ones”

Samuelson

<sup>6</sup> “Or, what is the same thing if a greater quantity of a goods is thrown on the market, then—other things being equal—it can be sold only at a lower price.”

—Samuelson

वास्तविक भावा का ज्ञान इसमें प्राप्त नहीं होता । भाग का नियम मूल्य में परिवर्तन होने के कारण भाग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को भी व्यक्त नहीं करता, क्योंकि यह अनुपात मूल्य में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम या अधिक था, उसके बराबर हो सकता है ।

भाग मूल्य से प्रभावित होता है । मूल्य के अनिश्चित कुछ अन्य तत्व भी हैं जो भाग को प्रभावित करते हैं, जैसे जनसंख्या, उपभोक्ताओं की रुचि तथा घाटों, उमदी आय, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएँ, सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य आदि । मूल्य-परिवर्तन के साथ यदि इन तत्वों में से किसी एक में भी परिवर्तन हो जाता है तो उसका भाग को भाग पर सामूहिक प्रभाव पड़ता करता कठिन होगा । उदाहरणस्वरूप, यदि गेहूँ का मूल्य कम होने के साथ ही साथ जनसंख्या में वृद्धि हो जाय, तो गेहूँ की भाग की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

## 2. भाग के सामान्य नियम के अपवाद (Exceptions to the General Law of Demand)

कुछ दशामों में मूल्य अधिक होने पर भाग अधिक और कम मूल्य होने पर कम हो सकता है । इस प्रकार जो भाग बढ़ जाय बनेगा, वह बाएँ से दाएँ ऊपर की ओरता हुआ होगा जैसा चित्र संख्या में दिखाया गया है । इस प्रकार के अपवाद के निम्नलिखित कारण हैं

(i) प्रदर्शन उपभोग की वस्तुओं का आकर्षण (Inducement to purchase goods of conspicuous consumption) : कुछ वस्तुएँ, जैसे आभूषण तथा प्रतिष्ठाभूषक प्रदर्शनकारी वस्तुएँ, महंगी होने पर भी सभी व्यक्तियों द्वारा अधिक मात्रा में खरीदी जाती है । इसके विपरीत मूल्य कम होने पर वे उन्हें खरीदना रुक कर देते हैं । इस प्रकार मूल्य-वृद्धि से भाग में वृद्धि तथा मूल्य-ह्रास से भाग में कमी हो सकती है ।

(ii) मूल्य वृद्धि की आशंका (When prices are expected to rise) : कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएँ, जिनकी मूल्य वृद्धि से उनकी भाग कम नहीं होती । तब वस्तु के बाजार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर यदि यह आशंका हो जाती है कि भविष्य में कट्टे या अधिक लाभ की भावना से विक्रेता वस्तु के मूल्य में और वृद्धि करेंगे, तो वेना प्रचलित अधिक मूल्य पर भी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने लगे हैं ।

(iii) निम्न वस्तुएँ (Inferior goods) : निम्न व्यक्ति द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु निम्न वस्तु कहलाती है । यदि उस व्यक्ति की आय में वृद्धि हो

जाती है, तो वह ऐसी वस्तु की कम मात्रा ही क्रय करेगा। उदाहरणार्थ, एक निर्धन व्यक्ति, गेहूँ का मूल्य अधिक होने के कारण, जो अधिक मात्रा में क्रय करता है। यदि जो का मूल्य कम हो जाए और वह जो की पूर्ववत् मात्रा ही क्रय करे, तो उसकी आय का कुछ भाग अपेक्षाकृत अच्छी स्थानापन्न वस्तुओं (Substitutes) को क्रय करने के लिए बच रहेगा। अतः उपभोक्ता निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने पर भी उनकी क्रय की जाने वाली मात्रा में वृद्धि नहीं करता। यह एक विरोधाभास है जिसे *Giffen's paradox* कहते हैं। परन्तु यह विरोधाभास एक व्यक्ति के सन्दर्भ में सत्य हो सकता है। सभी उपभोक्ताओं की भावनाएँ तथा स्थितियाँ समान नहीं होती। अतः बाजार-माग सूची इस प्रकार की प्रवृत्ति को व्यक्त नहीं करती।

### 3. माग के नियम की मान्यताएँ ( Assumptions of the Law of Demand )

माग का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) उपभोक्ता की आदतें तथा रुचियाँ अपरिवर्तित रहे : किसी वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा, उपभोक्ता की रुचि तथा आदतों पर निर्भर है। उसकी रुचि तथा आदतों में परिवर्तन होने पर उपभोग की मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है। अतः माग मूल्य तथा माग बन का निर्माण इस आधार पर किया जाता है कि उपभोक्ता के पसन्दगी मान (Scale of preferences) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

(2) आय यथावत रहे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर पसन्दगी-मान पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। वह उसी मूल्य पर किसी वस्तु को अधिक माना में क्रय कर सकता है। निर्धन व्यक्ति की आय में वृद्धि होने पर वह निकृष्ट वस्तुओं के स्थान पर अधिक अच्छी वस्तुएँ क्रय करने लगता है।

(3) अन्य वस्तुओं के मूल्यों का यथावत रहना . किसी वस्तु के सम्बन्ध में माग का नियम उभी समय लागू होगा जब कि अन्य वस्तुओं (स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं) के मूल्य यथावत् रहे। इन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाने पर वस्तु-विशेष की माग भी परिवर्तित हो सकती है।

(4) मूल्य में और परिवर्तन की आशंका न हो : वस्तु-विशेष के भावी मूल्य में परिवर्तन की आशंका भी वर्तमान माग को प्रभावित करती है। अतः नियम की सत्यता के लिए यह आवश्यक है कि भविष्य में मूल्य-परिवर्तन की सम्भावना न हो।

(5) वस्तु विशेष की किस्म समान हो : माग-सूची या माग-वक्र किसी वस्तु-विशेष से ही सम्बन्धित होता है। यदि वस्तु की किस्म में अन्तर होता है तो यह नियम चरितार्थ नहीं होगा।



## ७ अधिकांश मांग-वक्रों का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है ?

(Why most Demand Curves Slope downwards to the right ?)

इस प्रश्न का उत्तर मांग के नियम की व्याख्या द्वारा होती है। अधिकांश मांग की रेखाओं का ढाल दायाँ तरफ नीचे की ओर होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होने पर वस्तु का मूल्य बढ़ने पर कम तथा मूल्य कम होने पर उसकी अधिक मात्राएँ खरीदी जाएँगी। मूल्य तथा मांग की मात्रा में विपरीत सम्बन्ध होने के कारण ही मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

(1) ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता नियम का प्रभाव - किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य, मुद्रा के त्याग की मात्रा को व्यक्त करता है। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करते समय उसकी सीमान्त उपयोगिता से अधिक त्याग करने को तैयार नहीं होता। ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की जितनी ही अधिक मात्राएँ खरीदी जाती हैं, प्रत्येक प्रतिरिक्त इकाई की सीमान्त उपयोगिता उतनी ही घटती जाती है। इन दोनों विचारों में यह निष्कर्ष निरक्षता है कि सीमान्त उपयोगिता के समझ बढ़ने के त्याग की मात्रा भी कम हो जाती है, यानी कम मूल्य होने पर ही किसी वस्तु की अधिक मात्राएँ खरीदी जा सकती हैं। इसके विपरीत यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो वह केवल इतनी ही इकाइयाँ खरीदेगा जिनकी लागतमिता (सीमान्त) अधिक है। वह मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता तथा वस्तु की सीमान्त उपयोगिता के साम्य को हमेशा ध्यान में रखेगा। वस्तु की इकाई के रूप में प्राप्त की गयी कम सीमान्त उपयोगिता के लिए, वह मुद्रा की इकाई के रूप में कभी भी अधिक सीमान्त उपयोगिता का त्याग नहीं करेगा। यानी, अन्य बातों के समान रहने पर, उपभोक्ता कम कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदता है। इसका कारण उपयोगिता ह्रास नियम है। इस प्रकार इस तथ्य पर आधारित यदि मांग वक्र खींचा जाए तो उसका ढाल ऊपर के नीचे की ओर, दाहिनी तरफ मुड़ता हुआ होगा।

(2) घटते हुए मूल्य तथा केंद्रांशों को आकर्षित करते हैं : जब किसी वस्तु (मांस नीमिए गैर) का मूल्य घटता है, तब केवल अपनी धनिक ही उसे कब करेगा। निर्धन धनिक अन्य वस्तुओं (जो, वादरा आदि) से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। अतएव अधिक मूल्य पर निर्धन व्यक्ति गैर नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार गैर की कम मात्रा खरीदी जाएगी। इसके विपरीत घटते हुए मूल्यों पर अधिक मात्रा उस वस्तु को खरीदने लगेगे जिससे वे बहुत से गैर खेता होंगे। इस प्रकार कम मूल्य पर मांग बढ़ेगी। मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की कम मात्रा

खरीदी जाएगी। इन तथ्यों पर आधारित जो मांग वक्र बनाया जाएगा, वह नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ होगा।

(3) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) : यदि दो वस्तुओं का उपयोग एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए या एक ही प्रकार से किया जाता है तो ऐसी वस्तुओं को एक दूसरे की प्रतिस्थापक वस्तु कहा जाता है जैसे चाय और काफी। यदि चाय की कीमत कम हो जाये तथा काफी की कीमत पूर्ववत् रहे तो कुछ लोग चाय सस्ती होने के कारण काफी के स्थान पर चाय का इस्तेमाल करने लगे थे। इससे चाय की मांग बढ़ जायेगी। इस प्रकार काफी की चाय से प्रतिस्थापित किया जायेगा, इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण किसी वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत घटने पर मांग घट जाती है। इस प्रकार मांग के नियम के लागू होने का कारण प्राप्त होता है। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग वक्र का ढलाव ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकता हुआ होता है।

(4) आय-प्रभाव (Income Effect) : किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने का अर्थ यह है कि उस वस्तु की पहले जितनी मात्रा कम मुद्रा में खरीदी जा सकती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए एक उपभोक्ता बी की कीमत 12 ₹ प्रति किलो होने पर, 5 किलो की 60 ₹ में खरीदता था। यदि बी का मूल्य 10 ₹ प्रति किलो हो जाता है तो बी की उतनी ही मात्रा खरीदने पर उसे 50 ₹ खर्च करने पड़ेगे। इस प्रकार मूल्य में कमी होने पर उसका कुल व्यय, बी पर 10 ₹ कम हो गया। यह हम रुपए उसके लिए एक ऊपर से आय में वृद्धि की तरह है। इस वृद्धि या आय में वृद्धि का पूरा उपयोग या कुछ मांग का उपयोग वस्तु की प्रतिरिक्त मात्रा खरीदने के लिए कर सकता है इसे 'आय प्रभाव' कहते हैं। यदि कीमत घटती है तो उपभोक्ता पहले जितनी ही मुद्रा खर्च करेगा, इस प्रकार वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। बड़ी हुई कीमत आय घटने के समान है। कम मात्रा खरीदने में वस्तु की मांग कम हो जाएगी। अतः आय प्रभाव मांग के नियम को स्पष्ट करता है। अर्थात् यह बताता है कि कीमत कम होने पर, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, इस प्रकार मांग-वक्र का ढलाव बाएँ से दाहिने, नीचे की ओर होगा।

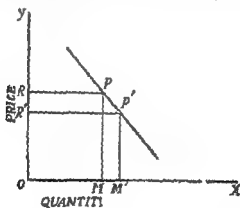
## 7. मांग का विस्तार तथा संकुचन; मांग में वृद्धि व कमी

(Extension and Contraction in demand; Increase and Decrease in demand) .

(1) मांग का विस्तार तथा संकुचन अन्य बातों के यथावत् रहने पर किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी अधिक मांग को मांग का विस्तार (extension or expansion in demand) तथा अधिक मूल्य होने पर कम मात्रा की मांग को मांग

का संकुचन (contraction in demand) कहते हैं। विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं की माग को उसी माग वक्र पर विभिन्न बिन्दुओं पर अंकित या प्रदर्शित किया जाता है। यह ध्यान रहे कि माग का विस्तार अथवा संकुचन मूल्य परिवर्तन के कारण होता है, न कि माग की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण। माग में इस प्रकार के परिवर्तन पर उपभोक्ता का कोई निजी प्रभाव नहीं पड़ता। वह मूल्य परिवर्तन के कारण अपना माग की मात्राओं को परिवर्तित करने को बाध्य होता है। अतः इस परिवर्तनों को उसी माग वक्र पर ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर की ओर जाकर स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि चित्र सं० 10 में दिखाया गया है।

मूल्य-परिवर्तन के परिणामस्वरूप माग की मात्राओं में विस्तार अथवा संकुचन माग-रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यह माग रेखा ही उपभोक्ता के पसंदी-मान (Scale of preferences) को व्यक्त करने वाले विभिन्न बिन्दुओं का पथ है।  $P'M'$  मूल्य पर उपभोक्ता वस्तु की  $OM'$  मात्रा क्रय करता है। वह  $(PM)$  निम्नतम मूल्य है, अतः इस वस्तु की अधिकतम मात्रा ( $OM'$ ) क्रय की जायेगी। यदि मूल्य  $M'P$  स बढ़कर  $PM$  हो जाय, तो उपभोक्ता वस्तु की  $OM$  मात्रा ही



चित्र सं० 10

क्रय करेगा। इस स्थिति में हमने मूल्य-रेखा पर दायी तरफ से ऊपर की ओर बायी ओर के झुकाव पर  $P'$  तथा  $P$  बिन्दुओं द्वारा बढ़ते हुए मूल्य पर वस्तु की मात्रा में कमी की दिशा को जान लिया है। अब यदि इसकी विपरीत स्थिति ले, तो हमें उसी मूल्य रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर चलना होगा।  $P$  बिन्दु पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु के लिए दिया जाने वाला मूल्य अधिक है, अतः वह वस्तु की  $OM$  मात्रा क्रय करेगा। परन्तु  $P$  पर वस्तु का मूल्य  $P'M'$  है जो  $PM$  की अपेक्षा कम है,

अतः उपभोक्ता वस्तु की OM' मात्रा क्रय करेगा। अतः यह स्पष्ट है कि मूल्य परिवर्तन से माग की मात्रा परिवर्तित होती है, उपभोक्ता पहले से अपनी पसन्दगी (preferences) निर्धारित कर लेता है और उसके बाद वह मूल्य द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है।

### (ii) माग में वृद्धि और कमी (Increase and decrease in demand)

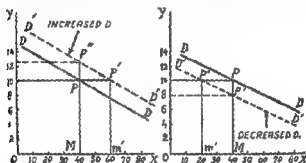
मूल्य के अतिरिक्त माग में अन्य कई निर्धारक तत्व (determinants) हैं। इनमें से किसी एक में होने वाले परिवर्तन का माग पर पड़ने वाले प्रभाव को ही 'माग में परिवर्तन' (change in demand) कहते हैं। माग में यह परिवर्तन माग में वृद्धि (increase in demand) अथवा माग में कमी (decrease in demand) के रूप में हो सकता है।

माग में वृद्धि का आशय यह है कि दिए गए मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय की जायेगी अथवा वस्तु की पूर्ण मात्रा ही मूल्य के अधिक होने पर भी क्रय की जायेगी। इस प्रकार की माग में वृद्धि कई कारणों से हो सकती है। उपभोक्ता की आय अथवा उसके परिवार में वृद्धि होने पर, उसे मूल्य को ध्यान में रखे बिना वस्तु की मात्रा या माग में वृद्धि करनी पड़ती है। अतः मूल्य में वृद्धि की दशा में वस्तु की माग का निर्धारक तत्व मूल्य नहीं होता, बल्कि व्यक्ति होता है। वही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी माग तथा पसन्दगी-मान (scale of preferences) निर्धारित करने में सक्रिय रहता है। इसके विपरीत माग में कमी का आशय यह है कि यदि मूल्य पूर्ववत् या अपरिवर्तित रहते हैं, तो माग की मात्रा कम होगी, और यदि माग की मात्रा पूर्ववत् रहती है तो मूल्य कम होंगे। इस प्रकार, माग में परिवर्तन होने पर नए पसन्दगी मान निर्धारित करने पर पहले की माग-सूची के स्थान पर एक नयी माग-सूची तैयार की जाती है। जब माग में वृद्धि होगी तो प्रत्येक मूल्य से सम्बन्धित माग की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक होगी। इसी प्रकार माग में कमी होने पर प्रत्येक मूल्य से सम्बन्धित वस्तु की मात्रा पहले से कम होगी। माग वृद्धि से एक नया माग-वक्र पहले के माग-वक्र की दायी तरफ हट कर एक ऊँची स्थिति पर पहुँच जाता है। माग में कमी प्रदर्शित करने वाला नया माग वक्र पूर्व स्थिति व्यक्त करने वाले माग वक्र की दायी तरफ नीची स्थिति पर अंकित होता है।

मूल्य में वृद्धि और कमी को प्रदर्शित करने वाली माँग-सूची

मूल्य	मूल माग	बढ़ी हुई माग	कम हुई माग
(प्र.वि.)-६.(Original Demand)	(Increased Demand)	(Decreased Demand)	
(i) मूल्य समान रहने पर			
10	40	60	20
(ii) मूल्य बढ़ने पर			
13	40	40	—
(iii) मूल्य घटने पर			
8	40	—	20

उपरोक्त तालिका के अनुसार माग में वृद्धि तथा माग में कमी की स्थितियों को नीचे दिए गए रेखाचित्रों (क्रमशः संख्या 11A और 11B) में प्रदर्शित किया गया है :



चित्र सं० 11 A व B

चित्र संख्या 11A में  $D'D''$  एक माग में वृद्धि की स्थिति को व्यक्त करता है। माग में परिवर्तन (वृद्धि) के पूर्व मूल माग-वक्र  $DD$  है जिस पर  $P$  बिन्दु यह बताता है कि 10 ₹ प्रति निवटल की दर (PM) से वस्तु की 40 निवटल माग (OM) क्रय की जाती है। अब यदि मूल्य समान रहे, लेकिन अन्य किसी तत्व के कारण उपभोक्ता 40 निवटल के स्थान पर 60 निवटल खरीदना चाहें तो उसे ऊँचे वक्र ( $D'D'$ ) के बिन्दु  $P'$  पर जाना होगा, क्योंकि उसी मूल्य, 10 ₹ ( $PM = P'M'$ ) पर  $D$  वक्र पर 60 निवटल की माग  $Om'$  नहीं प्राप्त की जा सकती। इसी प्रकार यदि मूल्य वृद्धि प्रयत्न मूल्य के 10 ₹ से बढ़कर 13 ₹ प्रति निवटल ( $P''M$ ) हो जाने पर 40 निवटल ही माग हो तो इस मूल्य पर माग की माग  $OM$  को व्यक्त करने वाला बिन्दु ( $P'$ )  $DD$  वक्र पर न होकर नए वक्र  $D'D'$  पर होगा। यह नयी माग-रेखा  $D'D'$  ही माग में वृद्धि (Increase in demand) को व्यक्त करती है, क्योंकि उपभोक्ता ने वस्तु-माग को व्यक्त करने वाले इस रेखा पर ही प्रतिक्रिया होगी।

चित्र सं० 11B माग में कमी का निदर्श-चित्र (Illustration) है। माग में परिवर्तन के पूर्व 10 रुपये पर (PM), माग की मात्रा 40 क्विन्टल (OM) है। माग में परिवर्तन होने पर यदि 10 रु० क्विन्टल की दर से (अर्थात्  $PM = P'm'$  मूल्य पर) 20 क्विन्टल ( $Om'$ ) की अथवा मूल्य की दर 8 रुपये प्रति क्विन्टल ( $P'M$ ) होने पर 40 क्विन्टल (OM) की माग की जाती है, तो ये दोनों ही स्थितियाँ माग की कमी (decrease in demand) को दर्शाती हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में समस्त मान को प्रदर्शित करने वाले बिन्दु  $P'$  तथा  $P''$  पूर्व माग-रेखा  $D'D'$  पर अंकित  $P'$  तथा  $P''$  बिन्दु माग की कमी को प्रदर्शित करते हैं।

### 8. माग में परिवर्तन के कारण (Causes of Changes in Demand)

स्टिगलर (Stigler) के अनुसार माग के चार निर्धारक तत्व हैं : (अ) वस्तु का मूल्य, (ब) उपभोक्ता की आय (स) प्रतिस्थापक तथा पूरक वस्तुओं के मूल्य, और (द) उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान (Preference)। माग का नियम यह बताता है कि वस्तु के मूल्य को छोड़कर यदि अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे तो मूल्य की विपरीत दिशा में माग की मात्रा में विस्तार या संकुचन होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य परिवर्तन के अनुपात में ही माग की मात्रा में भी विस्तार अथवा संकुचन होगा। परन्तु जब माग के किसी अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन होने के कारण स्वयं माग प्रभावित होती है, अर्थात् पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक या कम मात्राएँ ब्रय की जाती हैं, तब इसे माग में परिवर्तन कहते हैं।

विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माग में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है :

#### माग में परिवर्तन के कारण

माग में वृद्धि	माग में कमी
1. उपभोक्ता की इच्छाएँ तीव्र हो जाएँ।	1. उपभोक्ता की इच्छाएँ कम तीव्र हो।
2. उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएँ।	2. उपभोक्ता की आय कम हो जाएँ।
3. स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएँ।	3. स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएँ।
4. पूरक वस्तुओं के मूल्य गिर जाएँ।	4. पूरक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएँ।

यहां माय में इस प्रकार के परिवर्तनों के कारणों का ही वर्णन किया गया है :

(1) रुचि, आदत अथवा फैशन में परिवर्तन (*Changes in taste, habit or fashion*): लोगों की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तनों के फलस्वरूप तद्-सम्बन्धी वस्तुओं की माग भी परिवर्तित हो जाती है। चाय के स्थान पर काफी, घोड़ी के स्थान पर पैंट तथा सूती वस्त्रों के स्थान पर टेरीलिन के कपड़े का प्रयोग इनके उदाहरण हैं।

(2) मौद्रिक तथा वास्तविक आय में परिवर्तन (*Changes in the money and real incomes*): लोगों की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने का तात्पर्य उनके द्वारा अर्जित मुद्रा अर्थात् क्रय-शक्ति की मात्रा में परिवर्तन से है, जबकि वास्तविक आय में परिवर्तन का आशय पूर्व आय से ही न्य की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन से है। यदि पहले की अपेक्षा वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, तो उपभोक्ता उन वस्तुओं की पूर्व मात्रा को कम धन-राशि से क्रय करके, बची हुयी धनराशि से अन्य उत्तम वस्तुएं क्रय करता है। इसी प्रकार उसकी मौद्रिक आय बढ़ने पर, यदि वस्तुओं के मूल्य यथावत् रहे, तो उसके पसन्दगीय मान में निश्चय ही परिवर्तन होगा। अतः दोनों ही स्थितियों में माग-सूची तथा माग-वक्र को पुनः बनाने की आवश्यकता होगी।

(3) चलन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन (*Changes in the amount of money in circulation*): देश में जितनी मुद्रा चलन में होती है, उसके परिमाण में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव मुद्रा के मूल्य, वस्तुओं के मूल्यों तथा लोगों की क्रय-शक्ति पर पड़ता है। अतः लोगों को अपने व्यय को समायोजित करना पड़ता है। मूल्य वृद्धि के कारण कुछ वस्तुओं की माग कम हो जाती है और लोग कुछ नवीन वस्तुओं की अधिक मात्रा में क्रय करना प्रारम्भ कर देते हैं।

(4) जनसंख्या में परिवर्तन (*Changes in population*): जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी होने में केवल माग में ही परिवर्तन नहीं होता, बरन् माग की किस्म में भी परिवर्तन हो जाता है।

(5) धन एवं सम्पत्ति तथा आय के वितरण में परिवर्तन (*Changes in the distribution of wealth and income*): सामाजिक तथा आर्थिक समानता के लक्ष्य से जब सरकार अपनी कर नीति धनी वर्ग के लोगों की प्रतिरिक्त क्रय-शक्ति को कर के रूप में लेकर उच्च निर्धन वर्ग के व्यक्तियों में वितरित कर देती है, तब वे लोग भी उन वस्तुओं को क्रय करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें वे पहले क्रय नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनके अधिकारों में परिवर्तन होने से माग में परिवर्तन होता है।

(6) प्रतिस्थापक तथा पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन (Changes in the prices of other goods): किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी प्रतिस्थापक अथवा पूरक वस्तु की माग में भी परिवर्तन हो जाता है। चाय के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिस्थापक वस्तु काफी की माग में वृद्धि होगी। पूरक वस्तु के सम्बन्ध में, यदि मोटर-कार का मूल्य कम हो जाता है, तो उसकी माग बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु पेट्रोल की माग भी बढ़ जायेगी।

(7) व्यापार की दशा में परिवर्तन (Changes in the state of trade) व्यापारिक समृद्धि के काल (boom period) में मूल्य में वृद्धि होने पर भी कुछ वस्तुओं की माग अधिक होती है और मन्दी (depression) के समय अधिकांश वस्तुओं की माग कम होती है।

(8) बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन (Changes in the propensity to save): यदि लोगों में पहले की अपेक्षा बचत करने की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय हो जाती है, तो निश्चय ही लोगों के पास ऋण-शक्ति (मुद्रा) कम होगी। फलस्वरूप लोगों की माग के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि तरलता प्रसन्नगी (Liquidity Preference) को लोग अधिक महत्व देने लगते हैं, अर्थात् यदि वे तरल (नकद) सम्पत्तियों को अधिक प्रसन्न करते हैं, तो भी लोगों के पास वस्तुओं की ऋण करने के लिए मुद्रा कम होगी जिससे माग भी कम हो जायेगी।

(9) अन्तर्सम्बन्धित वस्तुओं की माग में परिवर्तन (Changes in the demand for inter-connected goods): कुछ वस्तुएं पूर्णतया अन्तर्सम्बन्धित होती हैं। इस आधार पर माग के निम्नलिखित तीन रूप हो सकते हैं

(i) व्युत्पन्न माग (Derived demand): किसी वस्तु या सेवा की माग उस समय व्युत्पन्न माग कहलाती है, जबकि किसी दूसरी वस्तु या सेवा की माग के परिणामस्वरूप उसकी माग उदय होती है। उदाहरणार्थ, रोटी की माग को सन्तुष्ट करने के लिए आटे की माग का होना स्वाभाविक है। अतः आटे की माग व्युत्पन्न माग कहलायेगी। एक की माग में वृद्धि से दूसरे की माग में वृद्धि होगी।

(ii) संयुक्त माग (Joint demand): जब दो या अधिक वस्तुएं एक साथ ही किसी वस्तु की माग की पूर्ति के लिए आवश्यक हों, तो उन सभी वस्तुओं की माग संयुक्त माग कहलाती है। उदाहरणार्थ, कंक्रीट (concrete) बनाने के लिए बालू (रेत), सीमेंट तथा बजरी (कंकड़-gravel) तीनों ही वस्तुएं आवश्यक हैं। अतः अन्तिम वस्तु कंक्रीट की माग में वृद्धि या कमी होने का प्रभाव सम्बन्धित वस्तुओं की माग पर भी पड़ेगा।



(iii) **समष्टिक मांग या मिश्रित मांग (Composite demand) :** विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु की कुल मांग को समष्टिक या सम्मिश्रित मांग कहते हैं। यह वास्तव में किसी वस्तु की विभिन्न भागों का योग है। उदाहरण के लिए, यदि कोयले की मांग घरेलू ईंधन, यातायात के साधनों तथा उद्योग-व्यव्यों में विद्युत् प्रकृत उत्पादित करने के लिए की जाती है, तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोयले का मांगों के योग को समष्टिक मांग कहेंगे। किसी भी उद्देश्य के लिए कोयले की मांग की मात्रा में संकुचन होने पर उसकी समष्टि भाग भी कम हो जायेगी, अथवा विस्तार होने पर बढ़ जायेगी।

### प्रश्न व सकेत

1. मांग की वृद्धि और मांग के विस्तार (Increase in demand and expansion of demand) और मांग में कमी तथा मांग में संकुचन (Decrease in demand and contraction of demand) का अन्तर बताइए। सब परिस्थितियों को समझाइये जिनके अन्तर्गत मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है।

(Raj., B. com., T.D.C., 1967)

[सकेत—सर्वप्रथम मांग में वृद्धि व विस्तार तथा मांग में कमी व संकुचन में अन्तर बताइये। इसके पश्चात् मांग के नियम के अन्वयात् को बताइये।]

2. अधिकतम मांग रेखाएँ दाईं की नीचे की ओर क्यों झुकती हैं ?

(Bihar, B.A. Hons., 1966 A)

[सकेत—सर्वप्रथम मांग रेखा का अर्थ बताइये। इसके पश्चात् कीमत तथा मांग के प्रतिस्तरों सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुये बताइये कि अधिकतम मांग रेखाएँ दाईं की नीचे की ओर क्यों झुकती हैं। अन्य कारणों पर भी प्रकाश डालिए।]

3. 'मांग में वृद्धि' तथा 'मांग में विस्तार' के अर्थ बताइये तथा रेखाचित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिये। क्या एक मांग रेखा उत्पन्न वक्र रेखाओं की सहायता से निर्वाली जा सकती है ?

(Luck., B. Com., 1962)

[सकेत—प्रथम भाग में मांग में वृद्धि तथा विस्तार का रेखाचित्रों की सहायता से स्पष्टीकरण कीजिये। द्वितीय भाग में उत्पन्न वक्र रेखाओं की सहायता से मांग रेखा निकालिये। देखिए पृष्ठ 234-37]

# 11

## तटस्थता-वक्र-विश्लेषण ( Indifference-Curve-Analysis )

*"Indifference-curve-analysis uses as its basis this fact that if a person has no especial preference as between a given amount of one commodity and a given amount of another—i.e. if he is indifferent as between these alternatives—then he derives an equal degree of satisfaction from the two sets of commodities"*

—Edward Nevins

### 1. उपयोगिता-विश्लेषण के दोष

मार्शल ने माग के नियम की व्याख्या उपयोगिता-विश्लेषण के आधार पर की थी। उन्होंने उपयोगिता की मात्रा को मापनीय (quantitatively measurable magnitude) माना था। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में मार्शल की मापनीयता का खण्डन किया है। उनके अनुसार उपयोगिता एक व्यक्तिगत (Subjective) घाटणा तथा मानसिक अवस्था का आभास मात्र (Mental phenomenon) है। सबसे पहले इटैलियन अर्थशास्त्री विलफ्रेड परेडो (Wilfred Pareto) ने सन् 1903 में अपनी पुस्तक '*Manuale*' *Economic Politique* में कहा था कि 'उपयोगिता अमाप्य होती है' (Utility is immeasurable)। इस कथन के आधार पर ही बाद में चल कर उपयोगिता-विश्लेषण के दोषों पर प्रकाश डाला गया।

(1) उपयोगिता विश्लेषण का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें स्वयं उपयोगिता की घाटणा स्पष्ट नहीं है। उपयोगिता व्यक्तिगत (Subjective) तथा सापेक्ष (relative) होने के कारण एक अस्थिर तत्व है। वस्तुतः वह उपभोग के पूर्व किसी उपभोक्ता की व्यक्तिगत मानसिक भावना है जो आवश्यकता की तीव्रता तथा उसके प्रभावकारी तत्वों पर निर्भर होती है। यही कारण है कि उपयोगिता उपभोग के बाद प्राप्त किये गये सन्तोष से भिन्न है। इसके अतिरिक्त फलन-फलन

व्यक्तियों के लिए किसी एक ही वस्तु की उपयोगिता समान नहीं होती; यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्न समयों में एक ही वस्तु की उपयोगिता भी भिन्न-भिन्न होती है। अतः ऐसी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक (psychological) या मानसिक भावना की सही माप किसी वस्तुगत प्रमाण (objective standard) के आधार पर सम्भव नहीं है।

(2) दूसरा बोध यह था कि मार्शल ने उपयोगिता के परिमाण की माप (quantitative measurement) का जो आधार माना था, वह ठीक नहीं है। उनके अनुसार किसी वस्तु के लिए दिया जाने वाला धन्य इस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का सूचक है, अतः किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता मुद्रा के रूप में माप्य है। इस धारणा पर ही उन्होंने उपयोगिता-विश्लेषण-विधि की इस तथ्य पर आधारित किया था कि उपभोक्ता जैसे-जैसे अधिक धन व्यय करता जाता है, वैसे-वैसे मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में समान रहने की प्रवृत्ति होती है। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। मुद्रा की जैसे-जैसे अधिक इकाइया व्यय की जायेंगी, स्थोन्व्यो भाव (धन) में कमी होने पर मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जायेगी। अतः यह स्पष्ट है मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता के समान रहने की धारणा ठीक नहीं है। अतः उसके आधार पर मापी गयी उपयोगिता भी ठीक नहीं होगी।

## 2. प्राथमिकता दृष्टिकोण (Approach) का महत्व :

मार्शल तथा उनके अनुयायियों की उपयोगिता-शास्त्र (Neo classical Utility Analysis) में सहायक दृष्टिकोण (Cardinal approach) अपनाया गया था। यह दृष्टिकोण भी इस ना-यता पर ही आधारित है कि उपयोगिता मापनीय है (Neo-classical cardinal utility carries with it the assumption of measurability)। इस आधार पर यह कहा जाता है कि यदि एक व्यापक चाय तथा एक व्यापक दूध की उपयोगिताओं की तुलना करनी हो, तो दोनों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को सहायक सूचक संकेत (cardinal numbers) (1, 2, 3) में व्यक्त करना उचित होगा। उदाहरणार्थ, यदि यह कहा जाय कि एक व्यापक दूध की उपयोगिता एक व्यापक चाय की उपयोगिता से दुगुनी है तो इस कथन से कुछ स्पष्ट अर्थ भी निकलता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सहायक दृष्टिकोण को गलत माना है। उनका कहना है कि उपयोगिता की मात्राएँ मैदान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों रूपों में स्वभावीतः मापनीय है (quantities of utility are inherently immeasurable theoretically and conceptually as well as practically)। इन प्रवृत्तियों की यह धारणा है कि मापनीय उपयोगिता पर विचार किए बिना भी

उपभोक्ता आचरण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की जा सकती है। अतः उन्होंने उपयोगिता-व्याख्या के लिए क्रम सूचक या स्थितिक दृष्टिकोण (ordinal approach) अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत उपयोगिता मापनीय नहीं होती, बल्कि तुलनीय होती है। क्रम सूचक दृष्टिकोण से यह ज्ञान होना है कि उपभोक्ता एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु चाहेगा या नहीं ?

उपभोक्ता वस्तुओं के महत्व के आधार पर अपने उपभोग क्रम में किस वस्तु की कितनी मात्रा को प्राथमिकता दी जाय, इस पर विचार करता है। इस विचार का आधार पर ही वह यह बता सकता है कि किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु की अपेक्षा वह किसी आग वस्तु की कितनी मात्रा में पसन्द करेगा। यही उसका क्रम सूचक दृष्टिकोण है। जिसे प्राथमिकता दृष्टिकोण (preference approach) कहा जाता है। उदाहरणार्थ, उपभोक्ता के सामने चाय और दूध की मात्राओं के चुनाव का प्रश्न है। प्राथमिकता दृष्टिकोण के अन्तर्गत उसे यह जानना आवश्यक नहीं होगा कि दूध की उपयोगिता चाय की उपयोगिता से कितनी अधिक या कम है। वह प्राथमिकता क्रम (Scale of preferences) के अनुसार दोनों में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव करेगा। वह यदि 1 प्याला दूध को पहला (first) तथा 2 प्याले को दूसरा (second) स्थान देना है तो ये क्रमसूचक संख्याएँ (ordinal numbers) कहलायेंगी। इन संख्याओं के आधार पर ही उपभोक्ताओं के विविध वस्तुओं के महत्व अथवा उसकी पसन्दगी के क्रम निर्धारित किये जाते हैं (Ordinal utility means that the consumer is assumed to order, or rank, the subjective utilities of goods)। इससे यह स्पष्ट है कि प्राथमिकता दृष्टिकोण के अन्तर्गत वस्तुओं की उपयोगिता की सटीक माप की जरूरत नहीं पड़ती। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि प्राथमिकता-क्रम निर्धारित करते समय भी उपभोक्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं बल्कि उनकी मात्राओं को भी निर्धारित करता है। बेनहम के अनुसार ‘किसी व्यक्ति का पसन्दगी मान या प्राथमिकता क्रम उसकी रुचियों की सटीक अभिव्यक्ति है (A person's scale of preferences is the quantitative expression of his tastes)।’

### 3 तटस्थता विश्लेषण सक्षिप्त परिचय

तटस्थता वक्र का प्रयोग नया नहीं है। एजवर्थ (F Y. Edgeworth) पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में ही मांग पर प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अपनी पुस्तक ‘Mathematical Physics’ (सन् 1881 ई०) में तटस्थता वक्रों (Indifference Curves) का प्रयोग किया था। इसके पश्चात् तटस्थता-वक्रों का प्रयोग योरोपीय देशों के अर्थशास्त्रियों

द्वारा अधिक किया गया। इटैलियन अर्थशास्त्री विलफ्रेडो परेटो ने तो एजदर्व की तटस्थता-वक्र प्रयोग विधि में कुछ सुधार करके उसका विस्तृत प्रयोग किया। वास्तव में परेटो ने ही सबसे पहले सन् 1903 में अपनी पुस्तक '*Manuale d' Economic*' में उपयोगिता की व्याख्या के लिए यह सूचक दृष्टिकोण (ordinal approach) का उल्लेख किया था। उन्होंने उपयोगिता को अमापनीय माना था। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं के बीच प्राथमिकता क्रम तैयार किया जा सकता है तथा उसे तटस्थता-वक्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद सन् 1915 में रूसी अर्थशास्त्री स्लुत्स्की (Slutsky) ने अपने एक लेख में परेटो की तटस्थता-विश्लेषण-विधि को स्पष्ट किया था।

सन् 1930 ई० में अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने पुनः इस विधि के महत्व एवं प्रयोग पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। उसके बाद से उपयोगिता के सस्यात्मक दृष्टिकोण की हमारा आलोचना की जा रही है। परिणामस्वरूप कमसूचक उपयोगिता आधुनिक उपयोगिता व्याख्या का आधार बन गया है तथा तटस्थता-वक्र उसके सहायक यन्त्र हैं (...Ordinal utility was set on a throne consisting of a box of tools containing indifference curves)। वास्तव में तटस्थता वक्र ने ह्रासमान सीमान्त-वक्र का स्थान ले लिया है। इसका श्रेय दो अंग्रेज अर्थशास्त्रियों, प्रो० जे० आर० हिक्स (Prof J R Hicks) तथा प्रो० आर० जी० डी० एलेन (Prof R G. D. Allen) को है। इन्होंने सन् 1934 ई० में अपने लेख '*A Reconstruction of the Theory of Value*' में इस बात पर विशेष जोर दिया था कि कमसूचक उपयोगिता का आधार पर उपयोक्ता-आचरण तथा मूल्य के मिथ्यात्वों का फिर से निर्माण किया जाय। इस निबन्ध में इन अर्थशास्त्रियों ने तटस्थता वक्र का बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया था। बाद में सन् 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक '*Value and Capital*' में प्रो० हिक्स ने तटस्थता-वक्रों का विवरण बड़े ही विस्तार से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् उन्होंने अपनी नई पुस्तक '*Revision of Demand Theory*' में इन तटस्थता-वक्रों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त आस्ट्रियन स्कूल के विचारकों, विकस्टीड (Wicksteed), वीजर (Wieser), चम्बरलिन (Chamberlin) आदि ने भी मांग-विश्लेषण के लिए तटस्थता-वक्रों का प्रयोग किया है।

#### 4. तटस्थता-वक्र विधि के आधार

तटस्थता वक्र विश्लेषण की विधि निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है।

(1) पसन्दगी के मान (Scale of Preferences) : 'उपयोगिता-वक्र' (Utility Curve) केवल एक ही वस्तु की ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता को व्यक्त

करता है। परन्तु प्रत्येक विवेकशील (rational) उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं के चुनाव के सम्बन्ध में अपनी पसन्दगी के मान होते हैं। वह उन वस्तुओं में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति के आधार पर उनके महत्व तथा अपनी मानसिक पसन्दगी एवं रुचि के रूप में एक सूची तैयार करता है।

(2) विभिन्न वस्तुओं के संयोग का निर्धारण (Desirability of Combinations of Goods) वस्तुओं में आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की शक्ति के क्रम में पसन्दगी मान की सूची तैयार कर लेने के पश्चात् उपभोक्ता उनमें माध्यम से यह निश्चित करता है कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों (Combinations) में से कौन सा संयोग किसी अन्य संयोग में अधिक, कम या समान सन्तुष्टि प्रदान करेगा? इन संयोगों को निश्चिन करने का कारण यह है कि उपभोक्ता की मांग केवल एक वस्तु तक ही सीमित नहीं रहनी। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखकर कई वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। विभिन्न आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की इच्छा से ही वह केवल यह निश्चय नहीं करता कि किसी एक समय-विशेष में यह कौन सी वस्तु क्रय करना चाहता है, बल्कि वह यह निश्चय करता है कि उस काल में विभिन्न वस्तुओं के किन संयोगों से (किन किन वस्तुओं को एक साथ क्रय करने पर) उसे समान सन्तुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होगी।

### 5. तटस्थता-वक्र विधि का अर्थ

तटस्थता वक्र विधि क्रमसूचक उपयोगिता की व्याख्या करने की एक ऐसी विधि है जिससे दो या दोसे अधिक वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को ज्ञात किया जा सकता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि मिलती है। इस विधि के द्वारा उपभोक्ता के पसन्दगी मान (scale of preferences) के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के उन संयोगों को ज्ञात करने में सुविधा होती है जिनसे प्राप्त पूर्ण उपयोगिता समान रहनी है। वृत्ति कि उपभोक्ता उनमें से किसी या संयोग के द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि या पूर्ण उपयोगिता प्राप्त कर सकता है, अतः वह इन संयोगों के चुनाव के सम्बन्ध में तटस्थ या उदासीन (Indifferent) रहता है। अतः एडवर्ड नेविन (Edward Nevin) के अनुसार, ‘तटस्थता-वक्र विश्लेषण का आधार यह है कि यदि किसी उपभोक्ता को दो विभिन्न वस्तुओं की दो गयी मात्रा के सम्बन्ध में कोई विशेष रुचि या पसन्दगी नहीं है, अर्थात् वह इन दो विकल्पों के प्रति तटस्थ या उदासीन है, तो वह इन दो वस्तुओं के संयोग से समान सन्तुष्टि प्राप्त करता है।’<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “An indifference schedule may be defined as a schedule of various combinations of goods that will be equally satisfactory to the individual concerned.”

अतः अब माग विश्लेषण के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से कितनी मात्रा में संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है। यद्यपि माग-व्याख्या में उपयोगिता तत्त्व अब भी मौजूद है फिर भी अब उसके परिमाण की माप आवश्यक नहीं है। तटस्थता वक्र-विश्लेषण इस तथ्य की जानकारी प्रदान करने में सहायक होता है कि एक दिए हुए समय में क्या विभिन्न वस्तुओं का एक संयोग (combination) उतना ही वाछनीय (desirable) है जितना कि दूसरा? अथवा दूखने की अपेक्षा अन्न है? यही कारण है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता विश्लेषण के लिए तटस्थता वक्र विधि का प्रयोग किया है। इस विधि के द्वारा उन्होंने उपयोगिता की सही एवं वैज्ञानिक माप करने की चेष्टा की है।

### 6 तटस्थता वक्र-विधि का स्पष्टीकरण

(1) तटस्थता सूची या तालिका द्वारा तटस्थता वक्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक तटस्थता सूची या तालिका (Indifference Schedule) तैयार की जाती है।

तटस्थता तालिका (दो या दो से अधिक) वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की तालिका होती है जो किसी व्यक्ति को समान रूप से संतोषजनक होते हैं। दो या अधिक उपयोग वस्तुओं की तटस्थता तालिका दो वस्तुओं के संयोगों की सूची है, यह सूची इस क्रम से तैयार की जाती है कि कोई उपभोक्ता किसी भी संयोग को कितना दूसरे की तुलना में प्राथमिकता नहीं देता तथा इस प्रकार सभी संयोगों के प्रति उदासीन रहता है।<sup>2</sup> सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित सूची में केवल दो वस्तुओं के ऐसे कई संयोग दिये गए हैं जिनमें प्रत्येक की पूर्ण उपयोगिता समान है:

माना कि एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं—सेब और संतरों—से समान पूर्ण उपयोगिता वाले संयोगों का निश्चित करना है। यह नौ संयोगों के निम्नलिखित क्रम निश्चित कर सकता है

#### तटस्थता सूची—1

संयोग क्रम	सेब	संतरा	सेब के स्थान पर संतरा के प्रतिस्थापन की दर		
पहला	12	+	0	सेब	संतरा
दूसरा	8	+	1	4	= 1
तीसरा	5	+	2	3	= 1
चौथा	3	+	3	2	= 1
पांचवा	2	+	4	1	= 1

<sup>2</sup> "An indifference schedule is a list of combinations of two commodities, the list being so arranged that a consumer is indifferent to the combinations preferring none of them to any of the others."

उपर्युक्त सूची से यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता को केवल 12 सेवो से जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उतनी ही उपयोगिता 8 सर्वो तथा 1 सन्तरे के संयोग से भी प्राप्त हो सकती है। मन वह सोचता है कि यदि 4 सेवो का त्याग करके उसके स्थान पर 1 सन्तरा प्राप्त किया जाय, तो उसको 8 सेव तथा 1 सन्तरे का नया संयोग उनना ही सतोषप्रद होगा जितना कि पहला अथवा अन्य कोई। यह उनकी केवल एक मानसिक धारणा है। इसी आधार पर वह सेवो की मात्रा को अनिश्चित सन्तरो की मात्रा से कई प्रकार से प्रतिस्थापित करने पर विचार करता है जैसे तीसरे (5+2) चौथे (3+3) तथा पाचवें (2+4) संयोगों में प्रत्येक समान रूप से सन्तोषप्रद होगा। ये सभी संयोग समान सन्तुष्टि के संयोग हैं। उनमें से न तो कोई संयोग किसी दूसरे से अच्छा है न ही खराब। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की धाँडी बहुत मात्राएँ चाहता है। परन्तु यहाँ पर प्रश्न उसकी इच्छाओं तथा वस्तुओं की मात्राओं के बीच सम्बन्ध का है। उपर्युक्त तालिका में सेव तथा सन्तरे की मात्राएँ इस क्रम से रखी गयी हैं कि उपभोक्ता सभी संयोगों के प्रति तटस्थ है। प्रत्येक संयोग समान रूप से वांछनीय (desirable) है वह उनमें से किसी भी संयोग का चुनाव करने पर उतना ही सुखी होगा जितना कि किसी दूसरे संयोग का चुनाव करने पर।<sup>3</sup>

(ii) तटस्थता वक्र या रेखा द्वारा तटस्थता सूची में दिये गए संयोगों को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस रेखाचित्र में तटस्थता-वक्र (Indifference Curve) खिंची दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है, जो किसी उपभोक्ता की दृष्टि से समान सन्तुष्टि के संयोग होते हैं। इस आधार पर ही यह कहा जाता है कि तटस्थता वक्र विधि दो या अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त करने की विधि है जिससे यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता किस क्रम से दो या अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को सामान्य रूप से पसन्द करता है।

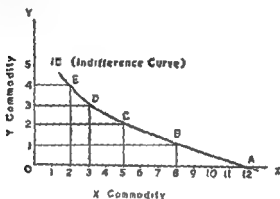
यदि OX आधार रेखा तथा OY सही रेखा पर हम क्रमशः सेव और सन्तरे के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने के लिए बिन्दु अंकित करें तो इन बिन्दुओं को मिलाने पर एक वक्र या रेखा (Curve) बनती है। वह कि उपभोक्ता इस रेखा पर खड़े बिन्दुओं द्वारा व्यक्त विभिन्न संयोगों को समान रूप से पसन्द करता है और वह उनमें चुनाव करने के प्रति तटस्थ रहता है अतः इस रेखा को उदासीनता रेखा

<sup>3</sup> "....the quantities of---are so arranged that the consumer is indifferent among the combinations. Each one is equally desirable; he considers himself equally well off in having any one of the combinations as in having any other."



(Indifference Curve) कहा जाता है। इस रेखा की रचना चित्र सं० 12 के अनुसार की जा सकती है :

नीचे दिए गए चित्र में A, B, C, D तथा E बिन्दु सेव तथा सन्तरे के विभिन्न नमूनों को व्यक्त करते हैं। A बिन्दु पर उसे केवल 12 सेवों से जितनी सन्तुष्टि मिलती है, उतनी ही बिन्दु पर उसे 8 सेवों तथा 1 सन्तरे से सन्तुष्टि मिलेगी, उतनी ही सन्तुष्टि C बिन्दु पर 5 सेवों व 2 सन्तरे को प्राप्त करने पर मिलेगी, अथवा C बिन्दु पर 3 सेव व 3 सन्तरे से, अथवा D बिन्दु पर 2 सेव व 4



चित्र सं० 12

सन्तरे से मिलेगी। B, C, D, व E बिन्दु उपभोक्ता को समान सम्बोध प्रदान करने वाले सेव तथा सन्तरे के संयोगों का अध्ययन करते हैं। इन बिन्दुओं को मिलाकर उनसे गुजरने वाली एक रेखा (Indifference curve) खींची जा सकती है। इस रेखा पर जिनके बिन्दु हैं, वे सेवों और सन्तरे के उन संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अतः इन बिन्दुओं के बिन्दु पथ (Locus) को ही उदासीनता वक्र (Indifference Curve) कहा जाता है।<sup>4</sup> उदासीनता-वक्र को 'समान उपयोगिता वक्र' (Iso-utility Curve) भी कहा जा सकता है।

इन सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि इस बिंदु से हम यह ज्ञात नहीं करते कि प्रत्येक वस्तु (सेव या सन्तरे) से अलग-अलग किस मात्रा में उपयोगिता या सन्तुष्टि प्राप्त होती है। हमें तटस्थता सूची तथा वक्र से केवल यह पता चलता है कि दो वस्तुओं के ऐसे कौन कौन से संयोग हैं जो किसी उपभोक्ता के लिए समान

<sup>4</sup> "It is the locus of the points representing pairs of quantities between which the individual is indifferent, so it is termed as indifference curve."

सन्तुष्टि के संयोग हो सकते हैं। वास्तव में तटस्थता-वक्र-विधि की यह विशेषता है कि हम उपयोगिता को मापनीय माने बिना मांग के नियम को व्याख्या कर सकते हैं।

## 7. तटस्थता-वक्र और प्रतिस्थापन की दर (Rate of Substitution) :

तटस्थता सूची-1 को देखने पर यह ज्ञात होता है कि जब उपभोक्ता सेवा के उपभोग की मात्रा को घटाकर 12 सेवा के स्थान पर 8 सेवा लेने का विचार करता है तो 1 सन्तरे के उपभोग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब वह 8 सेवा के स्थान पर 5 सेवा का उपभोग करने का विचार करता है, तब पुनः 1 अतिरिक्त सन्तरे के उपभोग की वृद्धि होती है, अर्थात् वह 5 सेवा के साथ 2 सन्तरो का उपभोग कर सकता है। चौथे संयोग में सेवा का उपभोग 5 से घटकर 3 के बराबर हो जाता है, जबकि सन्तरो की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। इस प्रकार दूसरे, तीसरे चौथे, पाचवें समान सन्तुष्टि वाले संयोगों को प्राप्त करने के लिए क्रमशः 4, 3, 2, व 1 सेवा के स्थान पर एक-एक सन्तरे की दर से प्रतिस्थापन किया जाता है। इसी दर को प्रतिस्थापन की दर (Rate of Substitution) कहा जा सकता है। सन्तरो की वह मात्रा जो सेवा की सीमान्त उपयोगिता की कमी की पूर्ति करती है, सेवा के स्थान पर सन्तरे की ‘सीमान्त प्रतिस्थापन-दर’ (Marginal Rate of Substitution) कहलाती है। अतः उपभोक्ता के लिए सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर वह दर है जिस पर वह दो वस्तुओं के संयोगों से प्राप्त पूर्ण उपयोगिता को बिना प्रभावित किए किसी एक वस्तु की ग्यूनतम मात्रा को किसी अन्य वस्तु की ग्यूनतम मात्रा से प्रतिस्थापित करता है। इसका कारण यह है कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर उसकी अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घटती है, तथा जिस वस्तु का त्याग किया जाता है, उसकी मात्रा में कमी होने पर उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार जैसे-जैसे सन्तरो की मात्रा में वृद्धि तथा सेवा की मात्रा में कमी की जाती है, वैसे वैसे सन्तरो की मात्रा में वृद्धि होने पर सेवा की तुलना में उसका सीमान्त महत्व कम होता जाता है और सेवा की मात्रा में कमी होने से उनका सीमान्त महत्व बढ़ता जाता है। इस सिद्धान्त को ही प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (Marginal Rate of Substitution-MRS) अथवा वस्तु प्रतिस्थापन-दर (Rate of Commodity Substitution) कहते हैं।

सीमान्त-महत्व की धारणा का मूलभूत आधार यह है कि उपभोक्ता उपभोग वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान उपयोगिता प्राप्त करने का विचार करता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह एक ही तटस्थता-वक्र पर बना रहना चाहता है। वह उस पर जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, प्राप्त की जाने वाली वस्तु का सीमान्त महत्व त्याग की जाने वाली वस्तु की तुलना में घटता जाता है। यही कारण है कि

रहा की जाने वाली वस्तु की एक इकाई के बदले में प्राप्त की जाने वाली वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों सेनी पड़ती है जिससे उन रेखा पर विभिन्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त संयोगों से समान उपभोगिता प्राप्त हो। फलस्वरूप तटस्थता-वक्र भूत बिन्दु उत्तमोत्तर (convex to the origin) होता है, अर्थात् उनका ढाल नीचे की ओर बायीं तरफ चौड़ा होता है परन्तु ऊपर की तरफ ढालू होता है।<sup>१५</sup> उदाहरणार्थ जैसे-जैसे वक्र पर ऊपर की ओर बढ़ना जायेगा, वक्र का ढाल (=Syn) भी बढ़ना जायेगा।<sup>१६</sup> अतः तटस्थता वक्र के ढाल का विशेष महत्व है क्योंकि इसके द्वारा ही यह निश्चित होता है कि किसी तटस्थता वक्र के विभिन्न बिन्दुओं पर समान महत्व बना होगा ?

8. पसन्दगी-मान या प्राथमिकता-क्रम (Scale of Preferences) में परिवर्तन का प्रभाव

उपभोक्ता के पसन्दगी-मान या प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन होने पर वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की एक नयी तटस्थता-सूची (Indifference Schedule) तैयार करनी होगी। इस सूची या तालिका में संयोग के रूप में बदलन के कारण तटस्थता-रेखा को स्थिति भी बदल जानी है। वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों के रूप को, जिनसे उपभोक्ता को प्रता प्रता समुष्टि या उद्देश्यिता प्राप्त होती है, प्रत्येक प्रता तटस्थता-रेखाओं द्वारा दिखाना जा सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि प्रत्येक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिन्दु एक निश्चित समुष्टि-स्तर के संयोगों को ही व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समुष्टि-स्तर/या तटस्थता-वक्र भी स्वभावतः भिन्न होता है। इस दृष्टि से यदि हम विभिन्न तटस्थता वक्रों के एक समूह को ले लें, जिसमें प्रत्येक वक्र एक प्रत्येक समुष्टि स्तर पर वस्तुओं के संयोगों को प्रतिनिधित्व करे, तो हमें एक तटस्थता मानचित्र (Indifference Map) प्राप्त होगा। अतः एक ऐसे बिन्दु को, जिसमें एक नहीं बरिच अनेक तटस्थता या उद्देश्यिता वक्र दिखनाए जाते हैं, तटस्थता मान-चित्र कहते हैं। तटस्थता रेखाओं की स्थिति जैसे-जैसे दायी ओर ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है वही वही के अधिक समुष्टि या उपभोगिता वाले संयोगों को बताती है। परन्तु जैसे-जैसे तटस्थता रेखाएँ बायीं ओर नीचे की तरफ उतरती जाती हैं,

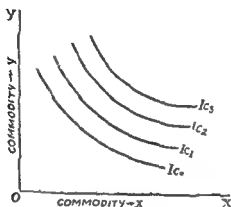
"Thus, as one moves along an indifference curve the assumption that it is convex to the origin, that it gets flatter to the right and steeper upwards implies that the marginal significance of the one good in terms of the other will always diminish progressively as one acquires more of the former good"

—Stanier and Hague, page 47.

"The slope of the indifference (=Syn) increases as the consumer moves upward along the curve....."

—Stigler.

रहो र्हो वे कम सन्तुष्टि या उपयोगिता के संयोग व्यक्त करती हैं। ऐसी तटस्थता रेखाओं का एक मानचित्र नीचे दिया जा रहा है :



चित्र सं० 13

माना कि उपर्युक्त तटस्थता मानचित्र में  $IC_1$  वह उदासीन वक्र है जो तटस्थता सूची—1 में दिए गए सेवा व सन्तरो के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। अब यदि उपभोगता की आय, रुचि आदि में परिवर्तन हो जाने पर सेवा व सन्तरे के अनुपात में भी परिवर्तन हो जायें और वह निम्नलिखित संयोगों से अधिक सन्तुष्टि प्राप्त करने लगे, तो निश्चय ही इन परिवर्तित संयोगों को अधिक पसन्द करेगा :

तटस्थता सूची—2

संयोग क्रम	सेवा		सन्तरे
पहला	12	+	2
दूसरा	8	+	3
तीसरा	6	+	4
चौथा	5	+	5

उपर्युक्त सूची के प्रथम संयोग से उपभोगता 12 सेवा के साथ 2 सन्तरे पाता है, जबकि सूची—1 के अनुसार उसे 12 सेवा के साथ शून्य सन्तरा मिलता है। इसी प्रकार अन्य संयोगों में भी सेवा और सन्तरो की मात्राएं अधिक हैं। अतः वह सूची—2 के संयोगों को अधिक पसन्द करेगा, क्योंकि इन परिवर्तित संयोगों से प्राप्त की गयी सन्तुष्टि का स्तर अधिक ऊँचा होगा। यही कारण है कि इस सूची के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करने वाले बिन्दु पहले वाले तटस्थता-वक्र पर स्थित नहीं हो सकते। वे पहली सूची के विभिन्न संयोगों के बिन्दुओं से ऊँचे स्तर पर स्थित

होंगे। अतः ये बिन्दु तटस्थता-वक्र  $IC_2$  पर होंगे। इसी प्रकार उपभोक्ता  $IC_2$  तटस्थता वक्र द्वारा व्यक्त दो वस्तुओं (सेब तथा सन्तरे) के विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन या तटस्थ रहेगा, लेकिन इन संयोगों को  $IC_2$  के समस्त संयोगों से अधिक पसन्द करेगा, क्योंकि  $IC_3$  उदासीन वक्र  $IC_2$  उदासीन वक्र की तुलना में ऊँचे स्तर के संयोगों को व्यक्त करता है। परन्तु  $IC_0$  उदासीनता वक्र  $IC_1, IC_2$  व  $IC_3$  तटस्थता वक्रों की तुलना में दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे प्राप्त सन्तुष्टि का स्तर नीचा होगा क्योंकि यह वक्र अन्य वक्रों की अपेक्षा नीचे स्तर पर है।

तटस्थता वक्र एक नक्शे की 'परिधि रेखा' (Contour Line) के समान होता है। जिस प्रकार परिधि-रेखा पर स्थित सभी स्थानों की ऊँचाई एक समान रहती है, उसी प्रकार एक दिए हुए तटस्थता वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदुओं वाले संयोगों से समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है। किन्तु परिधि रेखाओं और तटस्थता रेखाओं की यह तुलना उचित नहीं है। दोनों में कुछ अन्तर है। हम परिधि रेखाओं पर ऊँचाई 'फुट', 'मीटर' जैसी इकाइयों द्वारा माप सकते हैं, लेकिन तटस्थता वक्र के द्वारा प्राप्त हुई सन्तुष्टि परिमाण में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उपयोगिता या सन्तुष्टि भूमिगत (Subjective) होने के कारण प्रमापनीय है। उपयोगिता या सन्तुष्टि की ठीक-ठीक माप करने की कोई इकाई (Unit) नहीं है। हम इसका ही कह सकते हैं कि एक तटस्थता वक्र दूसरे तटस्थता वक्र की तुलना में एक ऊँच सन्तुष्टि स्तर के समान संयोगों को बताता है, किन्तु यह वही कह सकते कि यह सन्तुष्टि कितनी अधिक या कितनी कम है? हम तटस्थता वक्रों द्वारा व्यक्त विभिन्न सन्तुष्टि स्तरों के संयोगों को इकाइयों द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते।<sup>7</sup> तटस्थता वक्र  $IC_0, IC_1, IC_2, IC_3$  इत्यादि केवल विभिन्न सन्तुष्टि स्तरों (levels of satisfactions) को व्यक्त करते हैं।

### 9 तटस्थता वक्र की प्रकृति (Nature & Properties of Indifference Curve)

तटस्थता वक्र यह नहीं बताता कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को कितनी सन्तुष्टि मिलती है। वह केवल इतना ही बताता है कि विभिन्न

<sup>7</sup> "An indifference curve is thus like a contour line on a map which shows all places at the same height above level, instead of representing height, each indifference curve represents a level of satisfactions. It is, however, quite impossible to measure levels of satisfactions in the way that one can measure heights above sea level. There are obviously no units of measurement" — *Stoner and Hague*

संयोगों से उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि मिलती है। तटस्थता-वक्र में एक वस्तु को OY (axis) पर तथा दूसरी को OX अक्ष (axis) पर दिखलाते हैं। हम एक त्रिअक्षीय चित्र (Three-dimensional diagram) के द्वारा तीन वस्तुओं को भी ले सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे तटस्थता वक्र न कह कर तटस्थता-तल (Indifference Surface) कहा जाएगा। इसके द्वारा तीन वस्तुओं के अन्य विभिन्न संयोगों को व्यक्त किया जा सकता है, जो उपभोक्ता के लिए समान महत्व के होंगे। ऐसी दशा में तटस्थता-वक्र का स्वरूप अधिक जटिल हो जाता है। फलस्वरूप तटस्थता-वक्र बनाते समय दो ही वस्तुओं पर विचार करना ठीक होगा, क्योंकि जो बात दो या तीन वस्तुओं के सम्बन्ध में ठीक है, वही अनेक वस्तुओं के विषय में भी समान रूप से सही होगी, और उपभोक्ता द्वारा बहुत सी वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर विचार करने से भी हमारे निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

## 10. विशेषताएं :

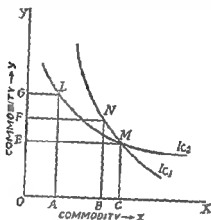
तटस्थता-वक्र के स्वरूप के सम्बन्ध में उसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) तटस्थता वक्र पर सभी बिन्दु समान उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं। (All points on an indifference-curve reflect equal utility-yielding combinations of goods) : यह विशेषता इस तथ्य की घोषणा है कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान पूर्ण उपयोगिता मिलने के कारण ही उपभोक्ता उनके प्रति तटस्थ रहता है। वक्र पर इन संयोगों के बिन्दुओं से विभिन्न संयोगों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

(2) किसी तटस्थता-वक्र की बायीं ओर का तटस्थता वक्र उसकी बायीं तरफ के तटस्थता-वक्र की अपेक्षा अधिक सन्तुष्टि वाले संयोगों को व्यक्त करता है (An indifference curve to the right of another indicates combinations—each of which yields a higher total satisfaction than any combination on a curve to the left)। जैसा कि पिछले चित्र में स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी तटस्थता वक्र की बायीं तरफ जितने भी वक्र होंगे वे अपेक्षाकृत उससे अधिक सन्तुष्टि के सूचक होंगे। इसके विपरीत उसकी बायीं ओर के तटस्थता वक्र कम सन्तुष्टि के सूचक होंगे।

(3) विभिन्न तटस्थता-वक्र एक दूसरे को नहीं काटते (Indifference Curves cannot intersect) : विभिन्न तटस्थता-वक्र विभिन्न मात्राओं में दो वस्तुओं के संयोगों को दिखलाते हैं। अतः दो तटस्थता-वक्र न तो एक दूसरे को स्पर्श

ही करते हैं और न ही वे एक दूसरे को काटते हैं। यदि वे एक दूसरे को काटने लगे तो फल यह होगा कि एक तटस्थता-वक्र पर वह बिन्दु उत्तमो ही सन्तुष्टि प्रदान करेगा, जितना कि दूसरे तटस्थता-वक्र का वह बिन्दु जिस पर वे एक दूसरे को काटते हैं। इस तथ्य को निम्न चित्रों से स्पष्ट किया जा सकता है :



चित्र सं० 14

इस चित्र में दो तटस्थता-वक्र  $IC_1$  व  $IC_2$  एक दूसरे को  $M$  बिन्दु पर काटते हैं। इन वक्रों से निम्नलिखित संयोगों को ज्ञात किया जाता है :

$IC_1$  वक्र के समान पूर्ण उपयोगिता वाले संयोग :

$$OC_x + OE_y = OB_x + OF_y$$

इसी प्रकार  $IC_2$  वक्र के समान पूर्ण उपयोगिता वाले संयोग :

$$OC_x + OE_y = OA_x + OG_y$$

∵  $M$  बिन्दु  $IC_1$  तथा  $IC_2$  दोनों ही तटस्थता वक्रों पर है। अतः इनसे व्यक्त होने वाले  $IC_1$  व  $IC_2$  पर संयोग  $(OC_x + OE_y)$  एक ही है। परन्तु प्रत्येक वक्र पर संयोगों के बिन्दु समान पूर्ण उपयोगिता के संयोगों को व्यक्त करते हैं—

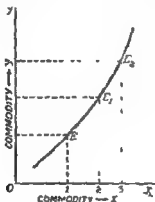
$$\therefore OB_x + OF_y = OA_x + OG_y, \text{ क्योंकि } OF_y = OG_y$$

परन्तु ऐसा होना निराधार एष असम्भव है, क्योंकि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है  $OG$  मात्रा  $OF$  मात्रा से अधिक है। अतः दो संयोगों की पूर्ण उपयोगिता को समान बनाने के लिए एक ही वस्तु की अधिक मात्रा दूसरे संयोग में कम मात्रा के बराबर नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट है कि दो उदासीन-रेखाएँ एक दूसरे को नहीं काट सकती।

(4) तटस्थता-वक्र सर्वत्र ऊपर से नीचे की ओर झुकता जाता है (Always slopes downwards to the right) : ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक

वस्तु (X) की मात्रा में वृद्धि होती है, तब दूसरी वस्तु (Y) की मात्रा में कमी होनी चाहिये, अन्यथा संयोग समान पूर्ण उपयोगिता वाले नहीं हो सकते। यदि तटस्थता वक्र नीचे की तरफ बाएँ से दाएँ न झुके तो उसके दो और सम्भव रूप हो सकते हैं :

(1) नीचे से ऊपर की तरफ दायीं ओर मुड़ सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अगले बिन्दु से अधिक सतुष्टि की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रत्येक अगले बिन्दु  $E, E_1, E_2$  पर X और Y की मात्राएँ बढ़ती जाती हैं। प्रत्येक अगला बिन्दु इन वस्तुओं की अधिक इकाइयों वाले संयोगों को प्रकट करता है। चित्र स० 15 से स्पष्ट है कि E बिन्दु पर Y और X दोनों की एक-एक इकाई का संयोग प्राप्त होता है,  $E_1$  बिन्दु पर दो-दो इकाइयाँ मिलती हैं और  $E_2$  पर तीन-तीन इकाइयाँ। इन



चित्र स० 15

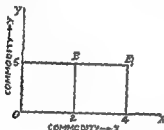
तीनों बिन्दुओं में सबसे नीचे के बिन्दु E पर अवश्य ही ऊपर के बिन्दुओं की तुलना में कम सतुष्टि मिलेगी। परन्तु यह स्थिति तटस्थता वक्र की परिभाषा के विपरीत है तथा अस्वाभाविक है क्योंकि एक तटस्थता-वक्र के सभी बिन्दुओं पर समान सतुष्टि मिलना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि तटस्थता वक्र कभी भी दाहिनी ओर ऊपर की ओर नहीं उठ सकता। यह स्थिति उसी समय सम्भव है जबकि दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु से प्राप्त सतुष्टि नकारात्मक (negative) हो जाय।

(ii) आधार रेखा (OX) के समानान्तर (Horizontal) या लंबी रेखा (OY) के समानान्तर (Vertical) यदि तटस्थता वक्र आधार रेखा (OX) के समानान्तर है तो उपभोक्ता को X वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, जबकि Y की मात्रा पूर्ववत् रहेगी। चित्र 16 (1) में उपभोक्ता E बिन्दु पर  $2X + 5Y$  से सतुष्टि प्राप्त करता है। परन्तु  $E_1$  बिन्दु पर X वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि होती है, पर्याप्त वह 4 के बराबर हो जाती है, लेकिन Y की इकाइयाँ 5 ही रहती हैं। अतः स्पष्ट है कि

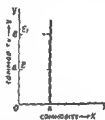


समोचना  $E_2$  के संयोग को अधिक बसन्द करेगा। यह स्थिति भी अस्वानाविक है, अतः तटस्थता-वक्र कभी भी आधार रेखा के समानान्तर नहीं हो सकता।

इसी प्रकार तटस्थता-वक्र (चित्र-16-2)  $OY$  खड़ी रेखा के समानान्तर भी नहीं हो सकता। तटस्थता-वक्र एक खड़ी रेखा के रूप में एक होने पर  $X$  वस्तु की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन  $Y$  वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। फलस्वरूप प्रत्येक प्रगता संयोग ( $E_1$ ) अधिक वांछनीय होगा। यह स्थिति भी अस्वानाविक मानी जाती है। अतः तटस्थता-वक्र कभी भी खड़ी रेखा  $OY$  के समानान्तर भी नहीं हो सकता।



(1) चित्र सं० 16



(2)

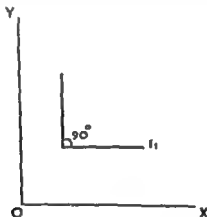
(5) सभी तटस्थता वक्र मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर होते हैं (All indifference curves are convex to the origin): तटस्थता-वक्र के उन्नतोदर (Convex) होने का अर्थ यह है कि यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु की सुलना में सीमान्त महत्व (Marginal Significance) स्पष्ट करता है।<sup>6</sup> जैसे-जैसे हम किसी तटस्थता वक्र पर नीचे की ओर बढ़ते हैं, उपभोग की गई एक वस्तु ( $X$ ) की मात्रा में वृद्धि होती है, परन्तु दूसरी वस्तु ( $Y$ ) की मात्रा में कमी होती है। इस प्रकार  $X$  की सीमांत उपयोगिता घटती है, जबकि  $Y$  की सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि  $Y$  वस्तु की कमी पूर्ति  $X$  वस्तु की मात्रा में पूर्ति करके ही की जा सकती है। केवल ऐसा वक्र जो अपने मूल बिन्दु से उन्नतोदर (convex to the origin) होता है, इस स्थिति को व्यक्त कर सकता है। ऐसे वक्र का ढाल सदैव नीचे की ओर बायें से दायें की ओर होता है जो प्रतिस्थापन की घटती सीमान्त दर को व्यक्त करता है। वस्तुतः तटस्थता-वक्र की यह प्रकृति प्रतिस्थापन की सीमान्त दर की वृद्धि (increasing marginal rate of

\* "The slope of an indifference curve at any point indicates the terms at which a consumer is prepared in exchange one commodity for another i. e. what is usually called his marginal rate of substitution.

substitution) अथवा X वस्तु के लिए ह्रासमान प्रतिस्थापन सीमात दर (decreasing marginal rate of substitution) व्यक्त करती है।

### 11. अपवाद (Exceptions) :

(i) पूरक वस्तुओं का तटस्थता वक्र : एक निश्चित अनुपात में प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं (Perfectly complementary goods), जैसे प्याला तथा प्लेट के लिए तटस्थता-वक्र का आकार भिन्न होता है। ऐसे तटस्थता वक्र का आकार दो सीधी रेखाओं के रूप में होता है। इनमें से एक रेखा आधार रेखा (OX) के समानान्तर तथा दूसरी रेखा छड़ी रेखा (OY) के समानान्तर होती है। दोनों रेखाएँ एक दूसरे से  $90^\circ$  के कोण पर मिलती हैं।



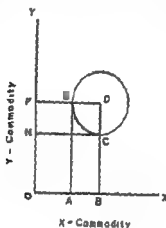
चित्र सं० 17

जैसा कि चित्र सं० 17 में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि दो पूर्ण पूरक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्राएँ बढ़ा दी जाती हैं तथा दूसरी में उसी अनुपात में वृद्धि न की जाय, तो पहली वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ बेकार हो जायेंगी। अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ण पूरक वस्तुएँ एक साथ एक निश्चित अनुपात में ही खरीदी जाती जाती हैं। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में प्रतिस्थापित करके पूर्ण सन्तुष्टि का संयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(ii) तटस्थता-वक्र का गोलाकार होना : \*\* किसी एक वस्तु की निरन्तर अधिक मात्राएँ प्रयोग करने पर एक सीमा पर उपभोक्ता पूर्ण सन्तुष्टि के बिन्दु पर

\*\*प्रो० जे० के० मेहता ने कहा है, ‘तटस्थता वक्र’ गोलाकार भी हो सकते हैं। परन्तु इसे सिद्ध करना अत्यन्त ही कठिन है तथा इसके लिए गणित का बहुत उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक है। देखिये, R. G. D. Allen, Mathematical Analysis 1962 p 357-58

पहुँच जाता है। उसके पश्चात् भी यदि वह उस वस्तु की प्रतिरिक्त इकाइया प्रयोग में लाना है तो उसे उपयोगिता या मनुष्य के स्थान पर अनुपयोगिता या ऋणात्मक उपयोगिता (Negative utility) प्राप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में वह किसी अन्य वस्तु की मात्रा में, प्रतिस्थापन नियम के आधार पर कमी करने के बजाय वृद्धि करने लगता है, जिससे उस वस्तु से भी उसे ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है।



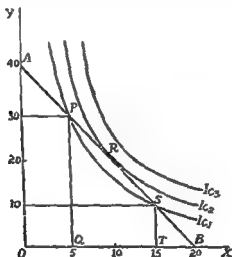
चित्र सं० 18

इस प्रकार दूसरी वस्तु की ऋणात्मक उपयोगिता पहली वस्तु से प्राप्त हुयी अनुपयोगिता की पूर्ति करती है। ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र दोनों वस्तुओं की इकाइयों में पूर्ण सतुष्टि के बाद भी वृद्धि होने के तथा उनके ऋणात्मक उपयोगिता मिलने के कारण, गोलाकार (circular) या अण्डाकार (elliptical) हो जाता है, जैसा कि चित्र सं० 18 से स्पष्ट है।

चित्र सं० 18 में EC सामान्य तटस्थता वक्र (IC) है। इस वक्र पर C बिन्दु पर X वस्तु की OB मात्रा तथा Y वस्तु की ON मात्रा का संयोग उनकी ही मनुष्य के देना जितनी E बिन्दु पर X की OA मात्रा तथा Y की OF का संयोग। CE वक्र पर किसी बिन्दु पर समान सतुष्टि के संयोग प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी वस्तु (X या Y) की अधिक मात्राएं उपयोग करण पर अनुपयोगिता प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में D पूर्ण सतुष्टि का बिन्दु तथा CE (IC) क्षेत्र प्रभावोत्पादक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रभावित क्षेत्र से निकलकर यदि उपयोगिता X वस्तु की प्रतिरिक्त मात्राओं का प्रयोग करता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए उस Y वस्तु की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। फलस्वरूप सामान्य तटस्थता वक्र EC गोलाकार होता आयेगा।

## 12. तटस्थता तथा मूल्य रेखा (Price Line) \*

मूल्य-रेखा वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों के विषय में ज्ञान कराती है जो विभिन्न बिन्दुओं पर उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी उपभोक्ता की आय सीमित होने पर वह उसे दो वस्तुओं, X और Y, पर व्यय करना चाहता है। नीचे दिए गए चित्र सं० 19 में X वस्तु को OX पर आघार रेखा तथा Y वस्तु को OY खड़ी रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। यदि उपभोक्ता अपनी आय Y वस्तु खय करने में व्यय करना चाहता है, तो वह Y वस्तु की OA मात्रा प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि वह X वस्तु पर ही अपनी समस्त आय व्यय करना चाहे तो उसे X की OB मात्रा प्राप्त हो सकेगी। यदि A और B बिन्दु को मिला कर AB रेखा खींची जाय, तो AB रेखा को ‘मूल्य रेखा’, ‘बजट रेखा’ या ‘सम्भावित उपभोग रेखा’ कहा जायेगा। इस रेखा पर प्रत्येक बिन्दु उपभोक्ता की आय का X और Y वस्तुओं के खय पर सम्भावित बटवारा (allocation) व्यक्त करेगा। माना



चित्र सं० 19

कि उपभोक्ता के पास X और Y अथवा X या Y को खय करने के लिए 200 रुपये हैं। यह मान लेने पर कि यदि बाजार में X वस्तु की प्रति इकाई का मूल्य 10 रु० प्रति इकाई है तो उपभोक्ता X वस्तु की अधिक से अधिक 20 इकाइया खरीद सकता है। यह स्थिति B बिन्दु पर व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में वह Y वस्तु की एक

\* Price Line को Price ratio Line या Price Opportunity Line भी कहते हैं। इसे Stigler ने Budget Line तथा Samuelson ने Consumption Possibility-Line कहा है।

इकाई भी क्रय नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि Y वस्तु की प्रति इकाई का मूल्य 5 रु० प्रति इकाई हो तो वह केवल Y वस्तु को ही 40 इकाइयाँ क्रय कर सकता है और X वस्तु को बिलकुल नहीं खरीदेगा। इस स्थिति को OY पर A बिन्दु द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

अब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय—200 रुपये—को निम्नलिखित तीनों विकल्पों में से किसी एक पर भी व्यय करके सामान्य सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है :

- (i) केवल Y वस्तुओं को क्रय कर सकता है और Y की OA मात्रा प्राप्त करता है, या
- (ii) केवल X वस्तुओं को क्रय करके उसकी OB मात्रा प्राप्त कर सकता है, अथवा
- (iii) वह दोनों ही वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा क्रय करके उनके मध्य से उतनी ही सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है, जितनी कि Y वस्तु की OA मात्रा से अथवा X वस्तु की OB मात्रा से प्राप्त होती है।

यदि उपभोक्ता तीसरे विकल्प के अनुसार अपनी निश्चित आय को व्यय करता है तो उसे AB रेखा पर प्रदर्शित किसी भी बिन्दु के संयोग से समान सन्तुष्टि मिलेगी। उदाहरणार्थ, S बिन्दु पर X और Y वस्तुओं के संयोग  $OT_x + ST_y$  अथवा P बिन्दु पर  $OQ_x + PQ_y$  संयोग से समान पूर्ण सन्तुष्टि मिलेगी।

∴ Total Utility =  $(OT_x + ST_y) = (OQ_x + PQ_y) = OA = OB$   
निश्चित धन-राशि के वितरण द्वारा स्पष्टीकरण

X वस्तु की प्रत्येक इकाई का मूल्य 10 रु० तथा Y वस्तु की प्रति-इकाई-मूल्य 5 रु० है

अतः  $OA = \frac{200}{5} = 40$  इकाइयाँ → Y वस्तु पर → कुल व्यय = 200 रु०

$OB = \frac{200}{10} = 20$  इकाइयाँ → X वस्तु पर → „ „ = 200 रु०

S बिन्दु पर X और Y वस्तुओं की इकाइयों के संयोग पर कुल धनराशि के व्यय को ज्ञात करने के लिए X तथा Y वस्तु की प्रति इकाई की दर से संयोजित इकाइयों का मूल्य ज्ञात करना होगा।

∴  $OT = X$  वस्तु की 15 इकाइयाँ ∴ OT पर किया गया व्यय  $15 \times 10 = 150$

∴  $ST = Y$  वस्तु की 10 इकाइयाँ ST „ „ „  $10 \times 5 = 50$

∴  $OT_x + ST_y$  पर कुल व्यय की गयी धनराशि = 200

इसी प्रकार पुनः AB रेखा पर P बिन्दु द्वारा प्रदर्शित संयोग का चुनाव करने पर उपभोक्ता X तथा Y वस्तुओं के निम्नलिखित संयोग से समान सन्तुष्टि प्राप्त करेगा :

$$OQ_x + PQ_y$$

X और Y वस्तुओं के इस परिवर्तित संयोग पर भी उपभोक्ता अपनी 200 रु० की निश्चित धन राशि हो व्यय करेगा, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है •

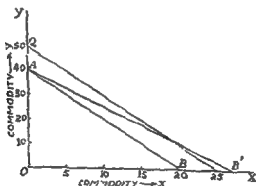
∴  $OQ = X$  वस्तु को 5 इकाइयाँ ∴  $OQ$  पर किया गया व्यय  $5 \times 10 = 50$

∴  $PQ = Y$  वस्तु को 30 इकाइयाँ ∴  $PQ$  पर किया गया व्यय  $30 \times 5 = 150$

∴  $OQ_x + PQ_y$  पर कुल व्यय  $\approx 200$

उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्य-रेखा यह ज्ञात करने में सहायक होती है कि प्रचलित मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदने का कौन सा प्रवृत्ति प्राप्त होगा ? इसलिए इसे ‘मूल्य-अवसर रेखा’ (Price-Opportunity-Line) भी कहा जाता है । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहना चाहिए कि तटस्थता-वक्र अर्थात् पसन्दगी-मान और मूल्य रेखा एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं । उपभोक्ता अपने पसन्दगी-मान तथा मूल्य-रेखा को अपनी आय के अनुसार ही समायोजित करता है ।<sup>10</sup>

मूल्य-रेखा में परिवर्तन सम्भव है । यदि वस्तुओं के मूल्य के पूर्ववत् रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, तो वह प्रतिगति क्रय क्षक्ति में X प्रयत्न



चित्र सं० 20

Y वस्तुओं की प्रतिरिक्त इकाइयाँ क्रय करने में समर्थ होगा । नीचे दिए गए चित्र को

<sup>10</sup> "The price line, thus, represents the opportunities open to the consumer in the market, given prices and his income, whereas the indifference curves show his tastes independently of market conditions. It is extremely important to remember that the indifference map and the price line are quite independent of one another.

—Stoner and Hague.

देखने पर ज्ञात होगा कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 250 रुपये हो जाय तो प्रति इकाई मूल्य में परिवर्तन न होने पर वह X वस्तु की 25 इकाइया या Y वस्तु की 50 इकाइया ख़र्च कर सगता है। मूल्यों में परिवर्तन न होने के कारण ही नयी OR मूल्य रेखा AB के ऊपर उसके समानान्तर होगी।

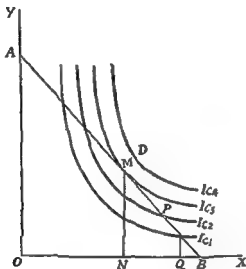
इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की आय में तो वृद्धि नहीं होती, परन्तु X वस्तु के मूल्य में परिवर्तन (कमी) हो जाता है, तो उपभोक्ता अपनी निश्चित आय (200 रु०) से Y वस्तु की तो पूर्ण मात्रा (40 इकाइया) प्राप्त कर सकता है। परन्तु यदि वह केवल X वस्तु को ख़र्च करना चाहता है तो उसे इसकी अधिक इकाइया प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में मूल्य रेखा AB से हटकर AB' हो जायेगी।

### 13 उपभोक्ता का संतुलन (Consumer's Equilibrium)

उपयोगिता विश्लेषण-विधि यह ज्ञात करने में सहायक होती है कि कोई उपभोक्ता 'सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धांत' (Law of Equi marginal Utility) के द्वारा किस प्रकार अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। सटस्थता वक्र द्वारा किसी उपभोक्ता को दो विभिन्न वस्तुओं के उत वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनमें उसे समान सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। परन्तु वस्तुतः उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर कुछ ही आवश्यक वस्तुएं खरीदकर अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सटस्थता वक्र विधि की सहायता से यह बिन्दु या सन्तुलन स्थिति ज्ञात की जा सकती है जिन पर उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा

- ( i ) उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली धन की मात्रा निश्चित एवं सीमित है।
- ( ii ) उपभोक्ता को सभी बाजार मूल्य ज्ञात हैं,
- ( iii ) सभी वस्तुएं समरूप (homogeneous) और विभाजनीय (divisible) हैं,
- ( iv ) उपभोक्ता विवेक से कार्य करता है, अर्थात् वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, तथा
- ( v ) उपभोक्ता को दो वस्तुओं के उन सभी विभिन्न उपयोगों को ध्यान करने वाले समभाव-मानचित्र (Indifference Map) का ज्ञान है जिनसे उसे समान सन्तुष्टि मिलेगी।

इन मान्यताओं के आधार पर उपभोक्ता के लिए नीचे दिये गये तटस्थता वक्र खींचे गये हैं और उपभोक्ता की निश्चित आय के आधार पर सम्भावित उपभोग की रेखा (Consumption Possibility Line) या मूल्य रेखा AB खींची गई है। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर हम यह मानकर चलते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करना चाहता है। अतः यदि उपभोक्ता  $IC_1$  तटस्थता वक्र पर बिंदु P (जो भलनी से  $IC_1$  रेखा पर दिलाया गया है) के संयोग के अनुरार X तथा Y वस्तुओं को क्रय करता है तो उसे अपनी आय व्यय करने पर X वस्तु की OQ मात्रा तथा Y वस्तु की PQ



चित्र सं० 21

मात्रा प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि P बिन्दु AB मूल्य रेखा पर है, अतः दली रेखा पर M बिन्दु द्वारा प्रदर्शित संयोग के अनुमार उतनी ही आय से X तथा Y वस्तुओं की क्रयण ON तथा MN मात्राएँ प्राप्त होगी। M बिन्दु  $IC_3$  तटस्थता-वक्र पर है। उपभोक्ता अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिए वस्तुओं के अपेक्षाकृत प्रच्छे संयोगों को पसन्द करता है। किन्ती तटस्थता-वक्र से ऊँचे वक्र अच्छे संयोगों को प्रदर्शित करते हैं; अतः यह उपभोक्ता  $PQ + OQ$  संयोग जो  $IC_1$  पर है, की अपेक्षा  $IC_3$  के  $MN + ON$  संयोग को अधिक पसन्द करेगा। इसके साथ ही माय निश्चित आय से समान सन्तुष्टि उन्हीं तटस्थता वक्रों से प्राप्त हो सकती है जिनको आय-मूल्य रेखा या तो काटती है या स्पर्श करती है। उपभोक्ता का संतुलन बिन्दु वह होता है, जहाँ आय-मूल्य-रेखा तटस्थता रेखा को स्पर्श करती है [या स्पर्श-रेखा (tangent) बनती है]। उपरोक्त चित्र में AB रेखा  $IC_1$  व  $IC_2$  तटस्थता वक्रों को काटती



है, परन्तु  $IC_3$  तटस्थता वक्र को  $M$  बिन्दु पर स्पर्श करती है।  $IC_3$  वक्र वू कि  $IC_1$  व  $IC_2$  तटस्थता-वक्रों से उच्च स्थिति पर है, अतः  $IC_3$  तटस्थता-वक्र के संयोग का चुनाव ही उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। परन्तु  $IC_3$  तटस्थता वक्र भी  $AB$  मूल्य रेखा को केवल  $M$  बिन्दु पर ही स्पर्श करता है, अतः  $AB$  मूल्य-रेखा  $IC_3$  तटस्थता-वक्र की  $M$  पर स्पर्श रेखा है ( *Price Line is a tangent to an Indifference Curve* )। इस स्पर्श बिन्दु के प्रतिरिक्त  $AB$  मूल्य-रेखा  $IC_3$  को किसी अन्य बिन्दु पर नहीं काटती। अतः उपभोक्ता  $M$  बिन्दु के द्वारा  $X$  तथा  $Y$  वस्तुओं के संयोग ( $ON_x + MN_y$ ) के प्रतिरिक्त उस आय से अन्य किसी संयोग से सन्तुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः  $M$  बिन्दु पर प्राप्त सर्वोत्तम एवं वांछनीय है, जो उपभोक्ता सन्तुलन ( *Consumer's Equilibrium* ) का संकेत करता है। अन्य कोई भी संयोग सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि  $IC_3$  की बायीं ओर ( जैसे  $P$  पर ) वह नहीं जाना चाहिये, क्योंकि वह निम्न स्तरीय तटस्थता वक्र  $IC_2$  के संयोग को व्यक्त करता है। उसकी दायी ओर ( जैसे  $IC_4$  तटस्थता-वक्र के  $D$  बिन्दु पर ) वह नहीं जाना चाहिये क्योंकि उसकी निश्चित आय की सम्भावित उपभोग-रेखा या मूल्य-रेखा ( *Consumption Possibility Line* )  $AB$  न तो  $IC_4$  को स्पर्श ही करती है और न उसकी कहीं पर काटती ही है। यह बिन्दु उसकी मूल्य-रेखा की पहुँच के बाहर है, क्योंकि वह उच्च-स्तरीय उपभोग पर अधिक आय के वितरण को व्यक्त करता है। इस स्तर ( $IC_4$ ) पर स्थित संयोग क्रय करने के लिए इस उपभोक्ता की आय पर्याप्त नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि जिस बिन्दु पर मूल्य रेखा किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, वह उपभोक्ता के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। इसी बिन्दु पर उपभोक्ता सन्तुलन की स्थिति में होता है। सन्तुलन की अवस्था प्राप्त कर लेने पर उपभोक्ता उस समय तक किसी वस्तु की मात्रा अधिक नहीं खरीदेगा जब तक कि उसकी आय प्राप्ति में परिवर्तन न हो जाय।

सन्तुलन-बिन्दु ( *Point of tangency or equilibrium point* )  $M$  पर मूल्य-रेखा ( $AB$ ) तथा तटस्थता-वक्र ( $IC_3$ ) दोनों का ढाल ( *Slope* ) समान है। तटस्थता-वक्र के ढाल का बिन्दु दो वस्तुओं के मध्य 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर' ( *Marginal rate of substitution* ) या 'प्रतिस्थापन अनुपात' ( *ratio of substitution* ) को मापता है। परन्तु मूल्य-रेखा का ढाल प्रारम्भ से अन्त तक समान रहता है जो  $\frac{OA}{OB}$  ( $X$  वस्तु के मूल्य तथा  $Y$  वस्तु के मूल्य के अनुपात) से स्पष्ट है। अतः सन्तुलन की स्थिति में दो वस्तुओं के मूल्य के मध्य अनुपात उन वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन के अनुपात के बराबर होता है। अतः उपभोक्ता ने सन्तुलन का

अभिप्राय यह है कि अधिकतम सन्तुष्टि उमी बिन्दु पर प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर वस्तुओं की सन्तुष्टि उनके मूल्य के बराबर हो। इस तथ्य को इस प्रकार भी दिखाया जा सकता है :

$$\begin{aligned}\text{उपभोक्ता का संतुलन}^8 &= \frac{X \text{ की सीमान्त उपयोगिता}}{Y \text{ की सीमान्त उपयोगिता}} \\ &= \frac{X \text{ का मूल्य}}{Y \text{ का मूल्य}}\end{aligned}$$

ऐसी स्थिति उस बिन्दु पर, जहाँ मूल्य-रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करे, सम्भव हो सकती है। तटस्थता वक्र की मापा में सीमान्त उपयोगिताएँ और मूल्यों का आनुपातिक सम्बन्ध क्या है ? यह इस तथ्य से प्रदर्शित होना है कि मूल्य की रेखा तटस्थता-वक्र को स्पर्श करती है। एक मूल्य रेखा एक ही तटस्थता-वक्र को स्पर्श कर सकती है, इससे अधिक को नहीं तथा मूल्य-रेखा पर स्पर्श-बिन्दु केवल एक ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि कोई भी दो तटस्थता-वक्र एक दूसरे को काटते नहीं तथा तटस्थता-वक्र मूल-बिन्दु से उन्नतोदर (Convex to the origin) होते हैं। इसीलिये आधुनिक अर्थशास्त्र किसी भी उपभोक्ता के संतुलन की बगलवा तटस्थता-वक्र के आद्यम से करते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार अधिकतम सन्तुष्टि तटस्थता-वक्र के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। मूल्यों के आधार पर तटस्थता-वक्र का निर्माण नहीं होता तथा उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के प्रत्येक संयोग को नहीं लेता। एक दिए हुए मूल्य पर कुछ संयोगों को ही वह लेता है और कुछ को छोड़ देता है। बिन्दु जिस संयोग को वह लेता है उसी से उसको अधिकतम सन्तुष्टि मिलने की धाशा की जाती है और उपभोक्ता का वही संतुलन बिन्दु होता है। अतः स्पष्ट है कि तटस्थता-वक्र की विधि द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि दी हुई दशाओं के अन्तर्गत किम प्रकार उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है। तटस्थता-वक्र बहुत स्पष्ट रूप से उपभोक्ता के प्रत्येक सम्भव संयोगों को प्रदर्शित करता है तथा यह बतता है कि उपभोक्ता एक विशेष संयोग को क्यों पसन्द कहता है ? परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा चुनाव का सिद्धांत तटस्थता वक्र की विधि के द्वारा और भी अधिक स्पष्ट तथा सुटहीन बन जाता है।

अपवाद : परन्तु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में तटस्थता-वक्र मूल-बिन्दु के उन्नतोदर (Convex) होने के बजाय नतोदर-(Concave) होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को ऊँच करते हुए सभी उदासीनता-वक्र के

\* “Tangency between the price-line and the indifference curve of the proportionality between marginal utilities and prices.”

किसी बिन्दु पर स्थायी सन्तुलन की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तटस्थता वक्र बिन्दु पर नतोदर है उस स्थिति पर क्रय की जाने वाली वस्तु का सीमान्त महत्व बढ़ रहा हो, परन्तु वह कभी भी उपभोक्ता के सन्तुलन की स्थिति व्यक्त नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त वह स्थिति क्रमागत सीमान्त उपयोगिता द्वारा नियम के विपरीत है। अतः तटस्थता-वक्र का स्वरूप भूल बिन्दु के उत्तमोदर (Convex to the origin) होना आवश्यक है। नतोदर की स्थिति कुछ समय तक रह सकती है, परन्तु लाभ की धारणा में वस्तु की अप्रिकाधिक इकाइयाँ खरीदते रहने पर, पुनः उसका सीमान्त महत्व घटने लगता है और वह अपने मूल बिन्दु से उत्तमोदर होने लगता है।

#### 14. उपभोक्ता सन्तुलन के परिवर्तनकारी तत्व \*

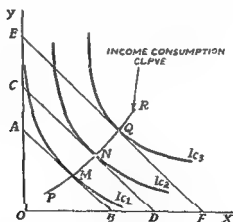
उपभोक्ता के सन्तुलन का यह विश्लेषण कुछ मान्यताओं पर आधारित है, किन्तु यदि उपभोक्ता की आय या वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाय तो सन्तुलन बिन्दु भी बदल जाएगा। उपभोक्ता के सन्तुलन में कौनसे परिवर्तन होंगे? इस तथ्य की स्पष्ट करने के लिए हम अपने विश्लेषण की तीन विभिन्न भागों में विभाजित करना होगा। ये तीन विभिन्न परिवर्तन ये हैं : (i) आय प्रभाव (Income effect) (ii) मूल्य-प्रभाव (Price effect) और (iii) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect)। अब इनका विश्लेषण हम अलग अलग करेंगे।

#### (1) आय-परिवर्तन का प्रभाव (Effects of Changes in Income) :

अन्य बातों के समान रहते हुए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है (i) आय में वृद्धि द्वारा अथवा (ii) आय में कमी द्वारा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप भाग में जो वृद्धि या कमी होती है, उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता का सन्तुलन (Consumer's Equilibrium) बदल जाता है प्रथम उसकी सन्तुष्टि पहले की तुलना में अधिक या कम हो जाती है। किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी मूल्य रेखा (Price Line) बायें से दायी ओर ऊँचे स्तर पर खींची जाती है, क्योंकि दो वस्तुओं के मूल्यों के तथा उपभोक्ता की रुचियों में बिना कोई परिवर्तन हुए अब, वह X या Y वस्तु की पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। अन्य बातों के समान रहने के कारण ही तटस्थता वक्र का ढाल पहले के तटस्थता-वक्रों की तरह रहेगा और मूल्य रेखाएँ एक दूसरे के समानान्तर रहेंगी। उपभोक्ता का उपभोग-स्तर ऊँचा उठने के कारण प्रत्येक मूल्य रेखा ऊँचे तटस्थता वक्र की स्पर्श-रेखा बन जायेगी जो अपने स्पर्श बिन्दु पर उपभोक्ता की अधिकतम सन्तुष्टि या उपभोक्ता सन्तुलन को व्यक्त करेगी। उदाहरणार्थ, उपभोक्ता की निश्चित आय पर, (दिये गए विषय

स० 22 में) मूल्य-रेखा AB है और सन्तुलन-बिन्दु M है, जिस पर मूल्य-रेखा AB तटस्थता वक्र  $IC_1$  को स्पर्श करती है।

यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, तो वह X और Y वस्तुओं की अधिक मात्राएँ क्रय कर सकता है। अतः मूल्य-रेखा बायें से दायें ऊपर की तरफ़ तिसकेगी जो AB के समानान्तर होगी। यह मूल्य रेखा CD है। यह मूल्य रेखा (CD) दूसरे तटस्थता वक्र  $IC_2$  को N पर स्पर्श करती है। यदि आय में पुनः वृद्धि होती है तो मूल्य-रेखा पुनः आगे उठकर AB व CD के समानान्तर EF की स्थिति में पहुँच जाती है। यह रेखा तटस्थता-वक्र  $IC_3$  को Q बिन्दु पर स्पर्श करती है। M, N तथा Q स्पर्श-बिन्दु उपभोक्ता-सन्तुलन की स्थितियाँ व्यक्त करते हैं। उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तरों पर इन बिन्दुओं द्वारा व्यक्त X तथा Y वस्तुओं के संयोगों से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। आय में वृद्धि होने से उपभोग पर पड़ने वाले परिवर्तनों को M, N, Q बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा PR व्यक्त करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक तटस्थता मानचित्र पर दिए गए विभिन्न तटस्थता-वक्रों के सन्तुलन बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा को आय उपभोग-वक्र (Income Consumption Curve) या व्यय-उपभोग वक्र (Expenditure Consumption Curve) कहते हैं। यह वक्र आय में परिवर्तन होने पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।



चित्र स० 22

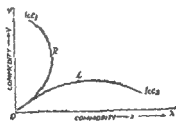
आय उपभोग वक्र का स्वरूप (slope) तटस्थता वक्र के स्वरूप पर निर्भर

’ “Any line drawn through the equilibrium points for all the possible levels of income is known as an income-consumption-curve.”

—Stoner and Hague

है। सामान्यतया यदि दो वस्तुओं के सापेक्ष मूल्यो (relative prices) और उपभोक्ता की रुचियो में परिवर्तन न हो तथा आय में वृद्धि हो, तो आय उपभोग वक्र का ढाल ऊपर की ओर दायी तरफ होता है (most income consumption curves slope upwards to the right), जैसा कि चित्र सं० 22 में दिखलाया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अतिरिक्त मात्राओं का उपयोग कर सकता है। अतः सामान्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आय-प्रभाव धनात्मक (Positive) होता है, परन्तु घटिया किस्म की वस्तुओं (inferior goods) के सम्बन्ध में आय-प्रभाव ऋणात्मक (Negative) होता है। इसका अर्थ यह है कि आय में वृद्धि के बावजूद भी, उपभोक्ता घटिया वस्तुओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है।

यदि हम  $ICC_1$  वक्र पर हैं तो  $X$  वस्तु, एक सीमा के बाद ( $R$  के बाद), घटिया वस्तु होगी, क्योंकि  $R$  बिन्दु के बाद  $X$  वस्तु की मात्रा पहले की तुलना में कम खरीदी जाएगी। किन्तु ठीक इसके विपरीत यदि हम  $ICC_2$  पर हैं, तो एक निश्चित सीमा, अर्थात्  $L$  के बाद,  $Y$  वस्तु घटिया वस्तु रही जाएगी, क्योंकि  $L$



चित्र सं० 23

बिन्दु के बाद  $Y$  वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। चित्र में दिए गए इन दो असामान्य वक्रों की देखने पर ज्ञात होता है कि  $ICC_1$  का ढाल पीछे की ओर  $ICC_2$  का ढाल नीचे की ओर जाता है। इसका यह अर्थ है कि एक बिन्दु पर पहुँचने के बाद आय में वृद्धि का प्रभाव कुछ वस्तुओं के लिए ऋणात्मक (Negative) हो जाता है। परन्तु आय उपभोग-वक्र का ऐसा स्वरूप (जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं) सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता। भारत जैसे घटती-बिकसित देश में निधनता के कारण उपभोक्ता घटिया वस्तुओं का अधिक उपभोग करता है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तब वह घटिया वस्तुओं के स्थान पर अच्छे वस्तुओं का उपभोग प्रारम्भ कर देता है।

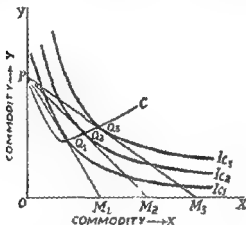
(ii) मूल्य-प्रभाव (Price Effect)

वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तनों का प्रभाव भी उपभोक्ता के सन्तुलन-बिन्दु (equilibrium position) पर पड़ता है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न होने पर, यद्यपि उपभोक्ता की मौद्रिक आय के स्थायी (constant) रहने पर, वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करना आवश्यक है। मूल्य परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को मूल्य प्रभाव (Price Effect) कहते हैं। इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए मूल्य-उपभोग वक्र (Price Consumption Curve) का उपयोग किया जाता है। यह वक्र हमें यह बताता है कि मूल्य में कमी होने से किसी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रभाव को ज्ञात करने के लिए यह मान कर चलना होगा कि उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मौद्रिक आय पूर्ववत् रहते हुए यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होगा। मूल्य में वृद्धि होने पर वह उस वस्तु की कम मात्रा ही खरीद कर सकता है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि उसकी वास्तविक आय में कमी होती है। इसके विपरीत उस वस्तु का मूल्य कम होने पर, वह उसकी अधिक मात्रा खरीद कर सकता है अतः यह कहा जा सकता है कि उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। फलस्वरूप उपभोक्ता की सन्तुलन स्थिति बदल जाती है।

अन्य बातों के समान हान पर, तटस्थता वक्र को स्थिर मानने पर मूल्य-परिवर्तन से मूल्य रेखा बदल जाती है, जिसके कारण तटस्थता-वक्र का स्पर्श बिन्दु (Point of Tangency) भी बदल जाता है। इस स्थिति को हम चित्र सं० 24 के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं।

मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप स्वभावतः मूल्य-रेखा मूल-बिन्दु से ऊपर की ओर उठनी जाती है जिसमें हम एक उच्च तटस्थता वक्र पर पहुँच जाते हैं। इस चित्र में हम  $Q_1$  सन्तुलन-बिन्दु में प्रारम्भ करते हैं। यह बिन्दु मूल्य रेखा  $PM_1$  पर स्थित है। अनुमान कर कि X वस्तु की कीमत में कमी होती है तथा Y वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है। परिणामस्वरूप X वस्तु की माँग बढ़ती है। मूल्य रेखा  $M_1$  से  $M_2$  की ओर फिर  $M_3$  तक पहुँच जाती है, यद्यपि उत्तरोत्तर मूल्य-रेखा  $PM_1$  से ऊपर उठ कर  $PM_2, PM_3$  हो जाती है। ये सभी परिवर्तित मूल्य रेखाएँ उच्चतर तटस्थता वक्रों का स्पर्श करती हैं जिन्हें हम क्रमशः  $Q_2$  और  $Q_3$  बिन्दुओं द्वारा चिह्नित करते हैं। यदि हम सन्तुलन के इन उत्तरोत्तर उच्च बिन्दुओं को मिला दें, तो हमें उस मांग का ज्ञान प्राप्त होगा जिसका कि

उपभोगता मूल्य में परिवर्तन होने पर व्यवहार में साता है। यही रेखा मूल्य-प्राप को प्रदर्शित करती है तथा इसे हम मूल्य-उपभोग वक्र (Price Consumption



चित्र सं० 24

Curve) कहते हैं। यहां हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि X वस्तु उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है तथा मूल्य-रेखा का ढाल कम-कम होता जाता है (The slope of the price lines gets less and less steep)।

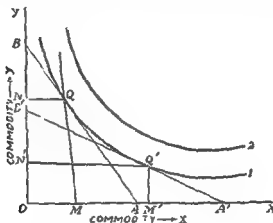
(iii) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) :

यह सम्भव है कि वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के साथ ही साथ उपभोगता की आय में भी इतना परिवर्तन हो, जिससे कि उसकी स्थिति पूर्ववत् ही बनी रहे। वस्तुओं के मूल्यों तथा उपभोगता की आय में समकाली परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप उपभोगता की स्थिति न तो पहले से सुधरती है और न बिगड़ती ही है। ऐसी स्थिति में उपभोगता उन वस्तुओं की अधिक मात्रा लेता जिनके मूल्य कम हैं, तथा उन वस्तुओं को कम मात्रा में खरीदेगा जिनके मूल्य अधिक हैं, क्योंकि उपभोगता अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुएं लेता है। उनकी मात्रा में इस प्रकार के परिवर्तन को प्रतिस्थापन-प्रभाव (Substitution Effect) कहते हैं।

यह नियम दो मापदंडों पर आधारित है। (अ) मूल्यों में इस प्रकार का परिवर्तन होता, जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक सस्ती हो जाय, तथा (ब) उपभोगता की मौद्रिक आय में इस प्रकार का परिवर्तन होना कि उसकी स्थिति पहले के ही समान रहे। इस दोनों मापदंडों का आधार यह है कि जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है, तो उपभोगता को उसकी कुल मात्रा खरीदने पर जो ध्यान देना पड़ेगा, वह मौद्रिक आय में वृद्धि द्वारा पूरा हो जाती है। मूल्य और आय में इस

प्रकार समकारी परिवर्तन को ‘आय में क्षतिपूरक परिवर्तन’ (Compensating Variation in Income) कहते हैं।

नीचे दिए गए चित्र सं० 25 में हम उस बिन्दु से प्रारम्भ करते हैं जहाँ उपभोक्ता Q बिन्दु पर सन्तुलन की दशा में है। इस सन्तुलन की दशा में उपभोक्ता के पास X वस्तु की OM मात्रा तथा Y वस्तु की ON मात्रा रहती है। यहाँ हम मान ले कि किसी कारण Y वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और X वस्तु के मूल्य में कमी। फलस्वरूप अब Y वस्तु की अपेक्षा X वस्तु सस्ती पड़ती है। ऐसी दशा में Y के मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो कमी हुई है, उस



चित्र सं० 25

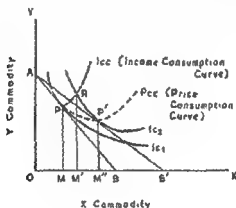
क्षति की X वस्तु के मूल्य में कमी होने के कारण पूर्ति हो जाती है। अतः दोनों वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन इस प्रकार हुए हैं कि उपभोक्ता का स्थिति पूर्ववत् रहती है और उपभोक्ता एक वस्तु के मूल्य में कमी तथा दूसरे के मूल्य में वृद्धि के कारण उसी स्थिति में बना रहता है जिसमें कि वह पहले था। तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता का सन्तुलन पहले वाले तटस्थता वक्र पर ही बना रहता है। किन्तु यहाँ यह स्पष्ट रखना चाहिए कि उपभोक्ता का सन्तुलन-बिन्दु बदल जाता है। Y वस्तु के मूल्य में वृद्धि के कारण वास्तविक आय में हुई कमी (क्षति) X वस्तु के मूल्य में कमी के द्वारा पूरी हो जाती है।<sup>10</sup>

10 "This compensating variation is just large enough to cancel out the change in his circumstances caused by the rise in the relative price of Y. He remains at exactly the same position in his scale of preferences (on the same indifference curve), the rise in the price of Y having been compensated for by the rise in his income."



अतः इन परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिस्थापन प्रभाव की उत्पत्ति होती है।  $Y$  और  $X$  वस्तु के मार्गेशिक मुक्त्यो में परिवर्तन हुआ है, किन्तु उपभोक्ता की स्थिति पूर्ववत् ही रहती है।<sup>11</sup>  $X$  वस्तु  $Y$  वस्तु की अपेक्षा अब सस्ती पड़ती है। इसलिए उपभोक्ता  $Y$  वस्तु के स्थान पर  $X$  की खरीद की मात्रा में वृद्धि करता है और वह अपनी आय का ज्यादा भाग  $X$  पर व्यय करता है तथा  $Y$  पर पहले की अपेक्षा कम व्यय करता है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता की समुचित पूर्ववत् बनो रहती है, क्योंकि वह परिवर्तित स्थिति में भी उन्हीं तटस्थता वक्र पर बना रहता है, जहाँ कि वह पहले था। केवल भण्डन बिन्दु का स्थान बदल जाता है।  $Q$  के स्थान पर अब उपभोक्ता  $Q_1$  पर चला आता है।  $Q$  और  $Q_1$  दोनों एक ही तटस्थता वक्र पर हैं और इस पर चलना प्रतिस्थापन प्रभाव का सूचक है। उपभोक्ता  $Y$  के स्थान पर  $X$  का अधिक उपभोग करता है, क्योंकि  $X$  वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती है। प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रवर्तन सर्वत्र एक ही तटस्थता वक्र पर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु पर चल कर दिया जा सकता है।<sup>12</sup>

15 आय तथा प्रतिस्थापन का द्विप्रभाव (The Dual Effect) : यह एक तत्कालीन तथ्य है कि सभी मूल्य-परिवर्तनों को आय-प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उदाहरणार्थ, मूल्य में वृद्धि होने पर यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता



की वास्तविक आय में वृद्धि हो गयी है, जबकि मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होती है। इन कारण-परिणाम के तथ्य को सत्य मानने पर यह कहा जा सकता है कि मूल्य परिवर्तन को सर्वप्रथम आय परिवर्तनों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्य तथा आय में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को चित्र सं० 26 में स्पष्ट किया गया है।

किसी एक वस्तु की कीमत का प्रत्येक परिवर्तन दोनों वस्तुओं के उपयोगों का अनुपात बदल कर मूल्य रेखा को ढाल बदल देता है। इसका कारण स्पष्ट है जब किसी वस्तु (X वस्तु) की कीमत गिरती है तो इसकी मांग की मात्रा एक तरफ आय प्रभाव की शक्ति और दिशा पर निर्भर करता है और दूसरी तरफ प्रतिस्थापन प्रभाव पर निर्भर करती है। X वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता के लिए उसकी मांग बढ़ेगी। साथ ही X वस्तु के मूल्य के गिरने के कारण मूल्य-रेखा का ढाल भी AB से बदल कर AB' हो जाता है। अतः X वस्तु का मूल्य गिरने पर उपभोक्ता प्रारम्भिक संतुलन स्थिति P में नवीन संतुलन स्थिति P' पर चला जाता है। लेकिन इसका आय उपभोग वक्र (Income Consumption Curve) पर P से R तक एक मिश्रित गति के रूप में देवना अधिक उचित होगा। आय उपभोग-वक्र पर P से R तक जाना आय प्रभाव कहना सकता है, तथा उदासीनता वक्र IC, पर R से P' तक जाना प्रतिस्थापन-प्रभाव कहना सकता है। जब उपभोक्ता का कीमत-उपभोग वक्र (Price Consumption Curve) P से P' तक जाता है तो X वस्तु की मांग OM से OM'' हो जाती है। वास्तव में X वस्तु की मांग में OM से MM की वृद्धि तो आय-प्रभाव का परिणाम है और शेष MM' प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम है। ऐसा होने का कारण यह है कि सामान्यतया प्रतिस्थापन-प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों ही धनात्मक (Positive) होते हैं। ये दोनों इस तरह कार्य करते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी खरीद बढ़ जाती है।

अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आय प्रभाव अथवा मूल्य-प्रभाव में से किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इन दोनों प्रवृत्तियों का सापेक्ष महत्व उन अनुपातों पर निर्भर है जिनमें उपभोक्ता अपने व्यय को इन दोनों वस्तुओं को खरीदने पर बाँटेगा। X वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता की स्थिति किस सीमा तक अच्छी हो जाती है, यह इस बात पर निर्भर है कि मूल्य परिवर्तन के पहले वह X वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करता था। यदि उसकी सम्बन्धित आय के अन्तर्गत X वस्तु का उपभोग अधिक था, तो अब उसकी स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी होगी। ऐसी स्थिति में आय-प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगा। परन्तु यदि पहले X वस्तु के उपभोग की मात्रा

कम थी, तो उपभोक्ता को लाभ कम होगा, और प्रतिस्थापन-प्रभाव आय-प्रभाव को शक्तिहीन बना देगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामान्यतः घटिया वस्तुओं (inferior goods) को छोड़कर, अन्य वस्तुओं की दशा में, प्रतिस्थापन प्रभाव आय-प्रभाव से प्रबल (Predominant) होता है।

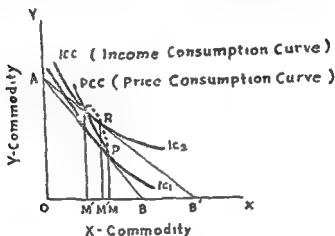
16. घटिया वस्तुएं (Inferior Goods) तथा गिफेन का विरोधाभास (Giffen's Paradox) सामान्य रूप से आय-प्रभाव तथा प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है। प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण हमें सा कितनी भी वस्तु की कीमत बिरने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाने की प्रवृत्ति होगी। परन्तु आय-प्रभाव हमें सा धनात्मक (Positive) नहीं हो सकता, अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य कम होने तथा आय बढ़ने पर उपभोक्ता कम कीमत वाली वस्तु की अधिक मात्रा खरीदे। वह उस वस्तु की वास्तव में कम मात्रा भी खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में आय-प्रभाव ऋणात्मक होता है।

उपयुक्त स्थिति प्रायः घटिया वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि कुछ घटिया वस्तुओं की खरीद, उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर भी बढ़ने में स्थान पर घट जाती है। वास्तव में आय बढ़ने पर उपभोक्ता की अधिक स्थिति में सुधार होता है। वह घटिया वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुएँ खरीदने लगता है, जिनमें मुख्य बढ़ने पर घटिया वस्तु कम मात्रा में खरीदी जाती है। ऐसी स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक कहा जावेगा। परन्तु इस स्थिति में भी यदि वह इतना कमजोर हो कि प्रतिस्थापन-प्रभाव को जो धनात्मक होता है, नहीं मिटा सके, तो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जावेगी।

परन्तु कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी खरीद के सम्बन्ध में ऋणात्मक आय-प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसको कम मात्रा में तथा कीमत के अधिक होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार की स्थिति उसी समय आती है जबकि वस्तु विशेष पर व्यय किया जाने वाला उपभोक्ता की आय का अंश बहुत बड़ा हो। ऐसी दशा में वस्तु-विशेष के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है।

ऐसी विशेष किस्मों की वस्तुएँ, जिनकी माँग इनके सस्ते होने पर कम तथा मह्ये होने पर अधिक होती है, गिफेन वस्तुएँ (Giffen goods) कहलाती हैं। ये वस्तुएँ घटिया वस्तुएँ (inferior goods) होती हैं। ऐसी वस्तुओं का नाम सर राबर्ट गिफेन के नाम से बना आ रहा है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में रोटी का उदाहरण

देते हुए कहा या कि रोटी का मूल्य बढ़ने पर भी वे मांस तथा अन्य मांस वस्तुओं से मस्ती होगी। रोटी की कीमत बढ़ने से निर्वन उपभोक्ताओं की आय में अधिक गिरावट होगी, अतः खाद्य वस्तुओं में रोटी के सस्ते होने से वे उसे ही अधिक खरीदेंगे। इसके विपरीत रोटी की कीमत कम होने पर उनकी वास्तविक आय बढ़ जायेगी और वे रोटी के स्थान पर अन्य अच्छी खाद्य वस्तुओं को भी खरीदने लगेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनकी रोटी की खरीद की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जायेगी। किसी वस्तु विशेष के मूल्य में कमी होने पर उसकी खरीद की मात्रा में कमी तथा वस्तु विशेष का मूल्य बढ़ने पर उसकी खरीद की मात्रा में वृद्धि यही गिफेन का विरोधाभास (Giffen's Paradox) कहलाता है।



चित्र सं० 27

चित्र सं० 27 में गिफेन-विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है। जब X वस्तु की कीमत घटती है, तब आय में वृद्धि होने पर मूल्य-रेखा AB से AB' तो हो जाती है, परन्तु संतुलन बिन्दु P से R पर चला जाता है। इससे यह पता चलता है कि X वस्तु की OM की मात्रा घटकर OM'' हो जाती है। खरीद में M''M की कमी कुल परिणाम के रूप में है, क्योंकि अकेले अणुगतिक आय-प्रभाव के फलस्वरूप तो उपभोक्ता X वस्तु की M'M कम मात्रा खरीदता और अकेले घनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव के फलस्वरूप वह M''M मात्रा अधिक खरीदता। अतः इन सबका कुल परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता X वस्तु की कम मात्रा ही खरीदेगा (OM के स्थान पर OM''), परन्तु घनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण वह इतनी कम मात्रा नहीं खरीदेगा कि X वस्तु की मात्रा OM में घटकर OM' हो जाय। अतः यह कहा जाता है कि घनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव अणुगतिक आय-प्रभाव के कारण कम हो जाता है और उपभोक्ता X वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पहले की अपेक्षा

कम मात्रा खरीदता है। ऐसी दशाएँ असाधारण हैं, फिर भी ये कभी-कभी सम्भव होती हैं।

## 17. तटस्थता वक्रों से मांग वक्र का निर्माण

(The Derivation of Demand Curves from Indifference Curves)

तटस्थता वक्रों के द्वारा मांग वक्र (Demand Curve) की रचना की जा सकती है। मांग वक्र का घनिष्ठतया एक ऐसे वक्र से है जो किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा तथा उसके मूल्य के सम्बन्ध को व्यक्त करता है। मांग-वक्र के द्वारा हम यह ज्ञात होता है कि विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग होगी? अतः यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की रुचि तथा माय और अन्य वस्तुओं के मूल्य समान रहने पर किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की मांगी गई मात्रा पर पड़ता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का मांग वक्र (Demand Curve) उसके मूल्य उपभोग वक्र से (Price Consumption Curve) से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित है। वस्तुतः यदि उपभोक्ता की आय और तटस्थता वक्रों का मानचित्र (Indifference Map) दिया गया हो, तो मूल्य-उपभोग वक्र से मांग वक्र निर्मित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इन दोनों वक्रों में एक ही प्रकार की सूचना मिलती है। मांग वक्र यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांग क्या होगी? मूल्य उपभोग-वक्र में यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस वस्तु की उपभोग मात्रा क्या होगी? इन दोनों सूचनाओं में विषय भिन्न न होने का कारण ही कुछ सर्वसाधारण मूल्य-उपभोग-वक्र तथा मांग वक्र में कोई अन्तर नहीं मानते। परन्तु वास्तव में इन दोनों में कुछ निम्नलिखित अन्तर हैं।

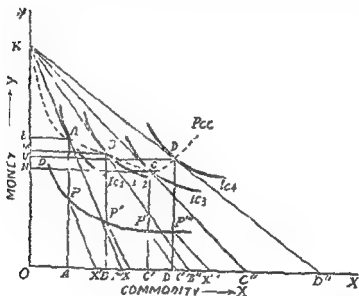
(i) मूल्य-उपभोग वक्र के द्वारा हम दो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनमें से एक वस्तु मुद्रा भी हो सकती है किन्तु मांग-वक्र का निर्माण वस्तु के विभिन्न मूल्यों के आधार पर होता है।

(ii) मूल्य उपभोग वक्र किसी वस्तु के मूल्य की मौद्रिक इकाइया (रूपयों-पैसे में) नहीं बताता। यह केवल दो वस्तुओं के मूल्यों के मध्य अनुपात को ही व्यक्त करता है। किन्तु मांग-वक्र में वस्तु के विभिन्न मूल्यों का व्यवहार किया जाता है। यही कारण है कि मांग वक्र से यह जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है कि दिए हुए मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जायेगी?

(iii) मूल्य उपभोग-वक्र यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कभी के कारण उसके आय प्रभाव (Income Effect) तथा प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) क्या होंगे? परन्तु मांग वक्र द्वारा इन प्रभावों की जानकारी सम्भव नहीं है।

(iv) किसी वस्तु के मूल्य की जानकारी मांग वक्र (Demand Curve) पर पूर्ति-वक्र (Supply Curve) बनाकर प्राप्त की जा सकती है, किन्तु मूल्य-उप-भोग वक्र की सहायता से किसी वस्तु का मूल्य-निर्धारण सम्भव नहीं है।

मांग वक्र का निर्माण करने के लिए नीचे दिए गए चित्र सं० 28 में OY खड़ी रेखा पर मुद्रा की तथा OX वस्तु की मात्रा की माप OX आधार रेखा पर की गयी है। KA', KB', KC', KD' मूल्य रेखाय खींची गई हैं जिनको तटस्थता वक्र 1, 2, 3, 4 क्रमशः A, B, C, D बिन्दुओं पर स्पष्ट करते हैं। इन चार विभिन्न सम्पत्तियों की स्थितियों में उपभोक्ता X वस्तु की क्रमशः OA, OB', OC',



चित्र सं० 28

OD' मात्राएं नेता है, यदि हम K, A, B, C तथा D बिन्दुओं को आपस में मिलायें तो मूल्य उपभोग-वक्र KD अर्थात् pcc प्राप्त होगा जिसे हम मूल्य-उपभोग-वक्र (Price-Consumption Curve) कहते हैं। OA' वस्तु के लिए उपभोक्ता KL मुद्रा देने की तत्पर है। इस प्रकार इन विभिन्न मात्राओं के लिए वह प्रति इकाई जो मूल्य देने की तैयार है, वह इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है,

$$\frac{KL}{OA'}, \frac{KM}{OB'}, \frac{KN}{OC'} \text{ और } \frac{KU}{OD'}$$

X वस्तु का मूल्य क्रमशः तेजी के साथ कम होता जाता है, जबकि उपभोक्ता X ने D बिन्दु पर चलता है। दूसरे शब्दों में, ये विभिन्न मूल्य KA', KB', KC'

और  $KJ''$  के झुकाव के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। चूंकि उपभोक्ता की आय  $OK$  निश्चित है, जिसे वह खर्च कर सकता है। जब वह  $A$  बिन्दु पर है और  $KL$  माना खर्च करता है तब वह  $OL$  माना बचा लेता है तथा उसे दूसरे उद्देश्यों के निमित्त रख लेता है। ठीक इसी प्रकार  $B$  बिन्दु पर  $KM$  माना खर्च करता है और  $OM$  माना अपने पास रखता है  $C$  बिन्दु पर  $KN$  तथा  $D$  बिन्दु पर  $KU$  व्यय करता है। इन सभी तथ्यों का संकलन  $Y$  अक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता की सम्पूर्ण आय  $OK$  निश्चित है।  $KA''$  मूल्य-रेखा पर किसी भी बिन्दु से, उदाहरणस्वरूप  $A$  बिन्दु से, यदि हम  $OX$  आधार-रेखा तथा  $OY$  लंबी रेखा पर लंब (Perpendiculars) डालें तो इस बात का ज्ञान हो जायेगा कि उपभोक्ता कितनी मात्रा खप करने को तैयार है तथा वह उसके लिए कितनी मुद्रा व्यय करने को तैयार है? यदि हम  $A$  बिन्दु से  $OX$  पर  $AA'$  खम्ब डालते हैं तो ज्ञात होता है कि उपभोक्ता  $OA'$  मात्रा खरीदना चाहता है तथा  $OY$  अक्ष पर  $AL$  खम्ब डालें तो पता चलता है कि उपभोक्ता  $X$  की  $OA'$  मात्रा के लिए  $KL$  मुद्रा व्यय करने को तैयार है। इसी प्रकार यदि  $KL$  को  $OA'$  मात्रा से भाग दें तो हमको जो मूल्य मिलेगा, वही होगा जो कि  $OK$  को  $OA''$  से भाग देने से प्राप्त होता है। इसीलिए हमने

$$\frac{KL}{OA'} = \frac{OK}{OA} \text{ तथा } \frac{KM}{OB'} = \frac{OK}{OB}, \text{ इत्यादि का प्रयोग किया है।}$$

मात्र वह हमसे अधिक कुछ भी नहीं कहता कि उपभोक्ता की आय निश्चित है। इससे यह भी पता नहीं चलता कि  $X$  वस्तु खरीदने के बाद उपभोक्ता के पास मुद्रा की कितनी रकम बच जाती है। मांग-वक्र केवल इतना ही कहता है कि दिए हुए मूल्य पर कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, किन्तु मूल्य-उपभोग-वक्र यह दिखाता है कि  $X$  वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए सम्पूर्ण व्यय क्या होगा? अतः हम  $X$  वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ व्यय में वस्तु की मात्रा से भाग देना होगा। जैसे जब उपभोक्ता  $OA'$  मात्रा की भाग करता है तब उसके लिए  $KL$  रूपरा व्यय करता है। इसीलिए प्रति इकाई मूल्य  $\frac{KL}{OA'}$  क्या हमें जो  $\frac{OK}{OA''}$  रूपरेखा के बराबर है। इसी प्रकार प्रत्येक संतुलन-बिन्दु का पता लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप,  $K$  बिन्दु पर  $X$  वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं खरीदी जाती तथा व्यय शून्य है। किन्तु जैसे ही उपभोक्ता  $K$  से  $B$  बिन्दु पर आता है, वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तथा उस वस्तु पर कुछ व्यय की मात्रा बच जाती है।  $C$  बिन्दु के बाद  $X$  वस्तु की खरीद की मात्रा बढ़ती ही जाती है, किन्तु सम्पूर्ण व्यय में कमी आती है। वास्तव में मूल्य-उपभोग-वक्र कुल व्यय-वक्र है, किन्तु यह ऊपर से नीचे की ओर आता है (The price consumption line is really only a total outlay curve, but it is upside down)।

एक माग-वक्र खींचने के लिये हम केवल यही जानने की आवश्यकता होगी कि X वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए उमका प्रति इकाई मूल्य क्या है ? इसका पता बहुत आसानी से लग जाता है । चिन स० 28 में दिए गये लम्ब AA', BB', CC', और DD' आधाग रेखा (OX) के क्रमशः A B C D बिन्दुओं से खींचे गये हैं । यदि हम AA' रेखा पर विचार करें तो X की मात्रा का ज्ञान होगा, अर्थात् OA इकाई, जो X वस्तु के एक दिये हुये मूल्य पर खरीदी जाती है,  $\frac{KL}{OA} = \frac{OK}{OA}$ , किन्तु X वस्तु की प्रत्येक इकाई का मूल्य क्या है ? इनकी जानकारी हमें  $\frac{KL}{OA} = \frac{OK}{OA}$  से होती है । किन्तु यह आसान नहीं है कि इसे चित्र पर दिखला सकें ।

वर्तमान विश्लेषण के लिए X वस्तु की प्रत्येक इकाई के मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए AA की दाहिनी ओर OX-पक्ष पर एक इकाई पर बिन्दु लगा लेते हैं, जैसे एक इकाई = A'X पर चिन्ह लगा लिया गया है ।

हम यह मान ले कि X की एक इकाई का प्रतिनिधित्व A'X' की दूरी से स्पष्ट है और यदि हम X' से KA' के समानान्तर X'P रेखा खींचें तो KA'' का ढाल X का मूल्य दिखलायेगा । चूंकि KA'' और X'P इन दोनों के ढाल समान हैं, अतः ये दोनों X वस्तु की वही प्रति इकाई मूल्य को सूचित करती हैं; जबकि X की एक इकाई का प्रतिनिधित्व A'X करता है तो A'P की दूरी X वस्तु की एक इकाई का मूल्य सूचित करती है और उपोक्ता X वस्तु OA' मात्रा खरीदता है । अतः P उपोक्ता के माग-वक्र पर एक बिन्दु है । यह बतलाता है कि उपोक्ता X की कितनी मात्रा खरीदता है जबकि उसकी लागत A'P  $\left( = \frac{OK}{OA'} \right)$  है । ठीक इसी प्रकार अगर हम X की एक इकाई के लिये B' की दायी ओर B'X'' दूरी ले लें तथा X'' से KB'' के समानान्तर X''P' खींचें तो X वस्तु की एक इकाई के मूल्य की जानकारी होगी, जबकि X वस्तु की OB' मात्रा खरीदी जाती है । यह मूल्य B'P'  $\left( = \frac{OK}{OB'} \right)$  होगा । अतः P' बिन्दु उपोक्ता के माग-वक्र का एक दूसरा बिन्दु होगा जो यह दिखलाता है कि यदि X वस्तु की एक इकाई की कीमत B'P' है, तो उसकी कितनी मात्रा खरीदी जायेगी ? इसी प्रकार हम P तथा P' बिन्दु निकाल सकते हैं जिससे उपोक्ता की X वस्तु की माग की मात्राओं का पता चलता है, जबकि उसकी एक इकाई की लागत क्रमशः CP'' और D'P'' है ।

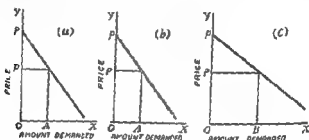
अब हम एक माग-वक्र DD' खींच सकते हैं । माग-वक्र (DD') X वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो कि उपोक्ता X के विभिन्न मूल्यों पर खरीदने



को तैयार है। यह माग-वक्र क्रमशः  $P, P', P''$  तथा  $P'''$  बिन्दुओं से गुजरता है जो इस तथ्य का प्रदर्शन करता है कि विभिन्न मूल्यों पर  $X$  वस्तु की वितनी मात्रा की माग होती है? जैसा कि हम देख चुके हैं, इस माग-वक्र को सामान्यी से उप-मोक्षा के गटस्थता वक्र के आधार पर खींच सकते हैं। अतः यदि हम  $P, P', P''$  तथा  $P'''$  बिन्दुओं को मिलाकर बायीं ओर  $D'$  तथा दायीं ओर  $D$  तक बढ़ा दें तो हमें उपमोक्षा का माग-वक्र प्राप्त होगा।

### 18. बाजार मांग वक्र (Market Demand Curve) :

अब तक हमारा यह विवरण केवल व्यक्ति के माग-वक्र से सम्बन्धित था। अतः यह व्यक्तिगत माग-वक्र हुआ। किन्तु अब हमें यह देखना है कि बाजार माग-वक्र का स्वरूप क्या होगा? बाजार-माग-वक्र का निर्माण सभी व्यक्तियों के माग वक्रों के योग से घटता है।



चित्र सं० 29

उपरोक्त चित्र में दो (a व b) व्यक्तिगत माग-वक्र हैं और इन दोनों का समुचित रूप (c) चित्र से स्पष्ट है। (a) व (b) व्यक्तिगत माग-वक्र एक समान हैं जो इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि  $OP$  या इससे अधिक मूल्य पर वस्तु की माग नहीं होगी। यही तथ्य इन दोनों चित्रों के योग से बने (c) रेखा चित्र से स्पष्ट है।  $OP$  से कम सभी मूल्यों पर कुल माग वक्र (aggregate demand curve) यह दिखाता है कि विचाराधीन मूल्य पर व्यक्ति की माग कितनी होती है? उदाहरण स्वरूप,  $OP'$  मूल्य पर माग की मात्रा, (a) और (b) दोनों ही चित्रों में,  $OA$  है तथा चित्र (c) में  $OP'$  मूल्य पर माग की मात्रा,  $OB$  है जो  $OA$  से दुगुनी है (demand at the Price  $OP'$  is  $OB$  which is twice  $OA$ ), क्योंकि दो व्यक्तिगत माग-वक्र एक समान हैं तथा किसी भी मूल्य पर बाजार माग-वक्र को मानाएँ व्यक्तिगत माग-वक्र की मात्राओं के दुगुने के बराबर होगा। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मूल्य पर मांग की खोज इन तीनों माग वक्रों में एक ही है। किसी वस्तु के व्यक्तिगत माग-वक्रों में किसी भी समूह को, चाहे व्यक्तिगत क

संख्या कितनी भी क्यों न हो, एक साथ जोड़ने से उस वस्तु के बाजार-भाग-वक्र का पता चलता है, अर्थात् व्यक्तिगत उपभोक्ता प्रत्येक मूल्य पर वस्तुओं की जितनी मात्रा खरीदना चाहता है, उसको जोड़ देने से उस वस्तु का बाजार-भाग-वक्र प्राप्त होता है। बाजार-भाग-वक्र सामान्यतः दायी ओर नीचे की तरफ भुज्जता है, जिस प्रकार व्यक्तिगत भाग-वक्र दायी ओर नीचे झुकता है।

### 19. तटस्थता-वक्र विधि की सीमाएँ या आलोचना :

(Criticism or Limitations of the Indifference-Curve-Technique)

तटस्थता-वक्र-विधि का सम्बन्ध क्रम सूचक अंकों (Ordinal Numbers) से होने के कारण, वह उपयोगिता की पुरानी धारणा से, जिसका सम्बन्ध सङ्ख्या-सूचक अंकों (Cardinal Numbers) से है, अपेक्षाकृत अच्छी है। आधुनिक अर्थ-शास्त्री माग तथा उपयोगिता विश्लेषण के सम्बन्ध में इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसका इतना महत्व होत हुए भी इस विधि की आलोचना की गयी है। ये आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं -

(1) सन्तुष्टि की परिमाणात्मक मापनीयता अधिक तर्ज संगत है। एफ० एच० नाइट (F. H. Knight) तथा अन्य अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि जब कोई उपभोक्ता अपनी आय को व्यय करने की योजना बनाता है, तब वह वस्तुओं के प्रतिस्थापन-प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं देता। वह यह नहीं सोचता कि किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने पर उसका क्या महत्व होगा? वास्तव में इस सम्बन्ध में वह यह सोचता है कि यदि प्रमुख वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाय, तो दूसरी वस्तु की तुलना में कितनी अधिक सन्तुष्टि प्राप्त होगी। वास्तव में वह सन्तुष्टि की गणना एक निश्चित परिमाण में करना चाहता है, तथा पूर्ण उपयोगिता (Total Utility) के आधार पर ही वस्तु की मात्रा में वृद्धि निश्चित करना चाहता है। अतः माग-सिद्धान्त को इन तथ्यों पर आधारित करना अधिक तर्क्युक्त प्रतीत होता है।

(2) अवास्तविक मान्यताएँ : डॉ० रूबी नॉरिस (Dr. Ruby Norris) ने प्रो० हिक्स (Prof J R Hicks) के माग सिद्धान्त के विश्लेषण की आलोचना करते हुए कहा है। तटस्थता-वक्र पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएँ स्वयं इसकी मान्यताओं में निहित हैं। आर्थिक सिद्धान्त व्यक्ति के गतिशील जीवन के तथ्यों का विश्लेषण बहुत ही सीख रूप में करता है।<sup>18</sup> डॉ० नॉरिस लिखती हैं कि उपज-

<sup>18</sup> “The most important criticisms of the Indifference Curve-System stem from the unreality of its assumptions. At best economic theory can approach only remotely the bewildering dynamics of daily life.”

विभेद (Product Differentiation) के कारण वस्तुओं की सरासरी कीमतें अधिक बढ़ी हो गयी है कि उपभोक्ता के लिए चुनाव करना कठिन हो गया है।

(3) संस्थागत मूल्य नियंत्रण की उपेक्षा प्रो हिंस की एक मांगता यह भी है कि मूल्य के सामान्य विनियमन में सरासरी मूल्य नियंत्रण (Institutional Price Controls), अर्थात् मूल्य पर सरकारी नियंत्रण की उपेक्षा की जा सकती है। परन्तु कुछ ज्ञान प्रबन्धन नियोजित समय व्यवस्था में इस प्रकार का विनियमन मांग और पूर्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

(4) उपभोक्ता के विवेकशील आचरण की धारणा काल्पनिक है। तद्व्यतिरिक्त वह विधि में उपभोक्ता के आचरण का विवेकशील माना गया है। यह मांगता कि उपभोक्ता वस्तुओं के विविध संयोगों में मिलने वाली सन्तुष्टि की कल्पना निरंतर कर सकता है उचित प्रतीत नहीं होती। तद्व्यतिरिक्त वह पर व्यक्त रायों की तद्व्यतिरिक्त सूची (Indifference Schedule) के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। ये वस्तुओं के बाजार मूल्यों पर ध्यान नहीं देते। अतः इनको कल्पित (hypothetical) तथा अज्ञात (unknown) कहा जा सकता है।

(5) उपभोक्ता की मान पर अथवा बातों के प्रभाव की उपेक्षा उपभोक्ता में विवेकशीलता की अपेक्षा भावुकता का पुट अधिक है। उपभोक्ता के व्यवहार पर परम्पराओं, रुचियों तथा संस्कृति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तद्व्यतिरिक्त वह विधि में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(6) वस्तुओं की सरासरी कीमतें बढ़ी होने पर वह विधि जटिल है। वास्तविक जीवन में उपभोक्ता के राग-रस केवल दो वस्तुओं प्रत्येक के संयोगों के चुनाव का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त विभिन्न संयोगों के लिए मूल्यों की ज्ञात तथा स्थिर मान लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए वस्तुओं की संख्या अधिक है वहाँ उपभोक्ता के पसंद की मान विश्वास कठिन है। अतः दो या तीन से अधिक वस्तुओं की मान के विश्लेषण के लिए तद्व्यतिरिक्त वस्तुओं का प्रयोग करना सरल नहीं है।

(7) तद्व्यतिरिक्त वह विशेष परिस्थितियों में पसंद की मान को व्यक्त नहीं करते। प्रो० के० ई० बोर्स्टेड के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व पसंद की सिद्धांत के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वे (तद्व्यतिरिक्त) बाहरी विस्तार में कहा अधिक बातों को व्यक्त करते हैं। हम लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में चुनाव करते हैं हम लोग अपने स्वतंत्र परिस्थितियों में चुनाव करने की कल्पना भी नहीं करते।<sup>14</sup>

<sup>14</sup> In seeking to cover the whole field of potential preference theory they (the indifference curves) seem to state more than what actually exists in the mind. We make choices in particular situation we do not contemplate making choices in an indefinitely large number of situations  
—Prof. A. E. Boulding

(8) आनुभाविak अध्ययन का आधार नहीं है तटस्थता वक्र विधि का प्रयोग आनुभाविak अध्ययन एवं शोध (Empirical Study and Research) के लिए नहीं किया जा सकता। सारियकी द्वारा इसके कार्यों की परीक्षा (Statistical Verification) भी सम्भव नहीं है।

(9) तटस्थता मानचित्र अल्पकालीन घटना है हाले (Hawley) के अनुसार किसी उपभोक्ता का तटस्थता मानचित्र अल्पकालीन घटना है जो बराबर परिवर्तित होता रहता है।<sup>15</sup>

निष्कर्ष . तटस्थता वक्र विधि की उपरोक्त आलोचनाओं एवं सीमाओं के बावजूद भी इस विधि के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वयं डॉ० नारिस ने प्रो० हिव्स की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रो० हिव्स ने एक ऐसे अर्थशास्त्र का विकास किया है जो पसन्दगी की स्थितियों को सख्या सूचक अंकों (Cardinal Numbers) के स्थान पर क्रम सूचक अंकों (Ordinal Numbers) से सम्बन्धित करता है। इस दृष्टि से प्रो० हिव्स ने माग विश्लेषण का मार्शल के उपयोगितावाद (Hedonism) से उद्धार किया है। डॉ० नारिस के विचार में तटस्थता वक्र की धारणा निश्चय ही परम्परावादी विश्लेषण से श्रेष्ठ है।<sup>16</sup>

कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का, जिनमें एरिक रोल (Eric Roll) का नाम प्रमुख है, यह विचार है कि तटस्थता वक्र विधि कोई नई नहीं है, अतः इसे पहले की विधियों से अच्छी विधि नहीं कहा जा सकता। एरिक रोल ने विचार से इस विधि में भी उपयोगिता का व्यक्तिगत तत्व (Subjective Element) मौजूद है। परन्तु उनका यह विचार सकुचित है। प्रो० राबर्टसन (Prof D H Robertson) के अनुसार, ‘तटस्थता वक्र विश्लेषण एक नई बोटल में पुरानी शराब मात्र ही है।’<sup>17</sup> प्रो० आर्मस्ट्रांग (Prof Armstrong) का यह कहना है कि मार्शल के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का उपयोग किए बिना हिव्स के प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमान्त दर के सिद्धान्त (MRS) का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। परन्तु इन आलोचनाओं का खण्डन करते हुए एडवर्ड नेविन ने लिखा है, “एक अर्थशास्त्री को यह भय नहीं होना चाहिए कि उसके सभी निष्कर्ष स्पष्ट और

<sup>15</sup> “The individual's map of indifference curves may be a short-run phenomenon, subject to frequent and possibly capricious changes”  
—Hawley

<sup>16</sup> “On the whole the indifference curve approach apart from its formal perfection as a mathematical system represents improvement along some lines and stagnation in others”  
—Dr Ruby Norris

<sup>17</sup> “Indifference curve analysis is an old wine in a new bottle”  
—Prof. D H Robertson

अमापनीय उपयोगिता के विचार पर आधारित हैं। तटस्थता वक्र-विश्लेषण सन्तुष्टि के मापनीय तथ्य पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ता द्वारा प्रदर्शित पसन्दगी का अध्ययन करता है।<sup>18</sup>

## 20. तटस्थता-वक्र का महत्व एवं उपयोगिता (Usefulness of Indifference Curve or Application of Indifference-Curve Technique) :

विभिन्न श्रुतियों के बावजूद भी आज मार्शल के माग वक्र-विश्लेषण से तटस्थता-वक्र-विश्लेषण को खेड़ समझा जाता है। आधुनिक युग में तटस्थता वक्र की पद्धति काफी लोकप्रिय है तथा इसका प्रयोग क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। इसकी सहायता से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तटस्थता-वक्र-विश्लेषण के माध्यम से माग की सोच एवं प्रतिस्थापन, उपभोक्ता की बचत आदि नियमों का सरलतापूर्वक अध्ययन सम्भव है। हिक्स ने उपभोक्ता की बचत को इस विधि के द्वारा स्पष्ट करने का सहायनीय प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं मूल्य विश्लेषण के सिद्धान्त में भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है।

वास्तव में तटस्थता-वक्र-विश्लेषण का प्रयोग अब आर्थिक क्षेत्र की प्रत्येक शाखा में होने लगा है। उपभोग के अतिरिक्त इस विश्लेषण का प्रयोग उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा कर-सिद्धान्त (Theory of Taxation) क्षेत्रों में भी किया जाता है। बोल्डिंग ने तटस्थता वक्र विधि को आर्थिक विश्लेषण का एक सबल अस्त्र माना है, जिसके माध्यम से विभिन्न समस्याओं का हल सम्भव है।<sup>19</sup>

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में तटस्थता-वक्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रयोग हैं :

(1) विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग तटस्थता-वक्र विश्लेषण का प्रयोग विनिमय-दर (Exchange Rate) निर्धारित करने में किया जाता है। दो वस्तुओं के मध्य निर्धारित विनिमय-दर सन्तुलन की दशा बतायेगी। इसे ही सन्तुलन-विनिमय-दर (Equilibrium Rate of Exchange) कहा जाता है। दो वस्तुओं

<sup>18</sup> "The economist need have no fear that all his conclusions are based on the vague and immeasurable concept of utility, indifference analysis does not require to attach a quantitative magnitude to the satisfaction derived by consumer from commodities, but simply accepts the preferences expressed in the market place."

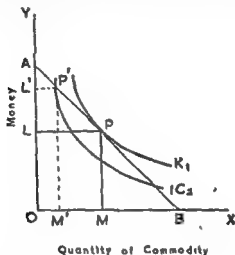
—Edward Nevil

<sup>19</sup> The Indifference Curve is a powerful weapon of economic analysis. Economics is ultimately the theory of human choices. As such it covers not merely a part of life, but the whole. And the Indifference curve is the map of human choices."

—Boulding

की प्रतिस्थापन-सीमान्त-दर (MRS) समान होने पर ही विनिमय सम्भव हो पाता है और इससे कोई भी उपभोक्ता अपने को ठगा जैसा महसूस नहीं करता।

(2) राशनिंग तथा उपभोक्ता की सन्तुष्टि के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग : राशनिंग ( Rationing ) से उपभोक्ताओं को अधिकतम सतोष नहीं मिल पाता। उपभोक्ताओं का सन्तोष सीमित तथा कम हो जाता है। राशनिंग के समय व्यक्ति को वस्तु की एक निश्चित (Fixed) मात्रा ही मिल पाती



चित्र सं० 30

है, अधिक मात्रा मिलना कठिन है। इस प्रकार उस वस्तु की मात्रा कम मिलती है। अतः राशनिंग का प्रभाव बहुत कुछ वैसा ही होता है जैसा कि मूल्य बढ़ने पर होता है। अभिप्राय यह है कि तटस्थता-वक्र-विश्लेषण के द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया जा सकता कि राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता को वस्तु विशेष की उचित मात्रा कम मिलने लगती है, जिससे उस वस्तु में उसको पूर्ण सन्तुष्टि नहीं मिल पाती, यद्यपि उसके पास द्रव्य या धन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तथ्य को तटस्थता-वक्र की सहायता से ऊपर दिये गये चित्र में व्यक्त किया गया है।

चित्र में तटस्थता वक्र  $IC_1$  राशनिंग के पहले का वक्र है जो उपभोक्ता के पूर्ण सन्तुलन या उसकी सन्तुष्टि को P बिन्दु पर व्यक्त करता है। इस बिन्दु पर उपभोक्ता के पास वस्तु तथा द्रव्य की मात्राओं का मयाग इस प्रकार है— $(OM_x + OL_y)$  इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु की OM मात्रा खरीदता है तथा द्रव्य की OL मात्रा अपने पास रखता है। परन्तु राशनिंग के बाद उसे वस्तु की OM मात्रा प्राप्त होने लगती है। वस्तु तथा द्रव्य के संयोग को व्यक्त करने वाला तटस्थता वक्र  $IC_2$  बजट

या मूल्य रेखा AB को P' पर काटता है। P' बिन्दु पर उपभोक्ता वस्तु की OM' मात्रा हो खरीद सकता है, जो OM मात्रा से कम है, यद्यपि उसके पास द्रव्य की मात्रा OL से बढकर OL' हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता के पास द्रव्य की मात्रा बढने पर वह वस्तु विशेष से अधिकतम सन्तुष्टि नहीं पा सकता और न ही वह सन्तुलन बिन्दु पर है। IC<sub>2</sub> तटस्थता-वक्र की स्थिति IC<sub>1</sub> तटस्थता-वक्र से नीचे की तरफ है। अतः इस वक्र पर मर्याद का कोई बिन्दु कम सन्तुष्टि स्तर का प्रयोग होगा।

(3) करारोपण (Taxation) में प्रयोग : उपभोक्ताओं पर कर लगाने समय तटस्थता-वक्र-विधि अधिक सहायक होती है। इसके जरिये यह पता लगाया जा सकता है कि प्रत्यक्ष (direct), आयकर (Income Tax), अथवा अप्रत्यक्ष (indirect) करों, बिक्री कर (Sales Tax) उत्पादन कर (Excise duty) का वस्तुओं के उपयोग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस प्रभाव को मापन करने सरकार ऐसे कर लगाती है जिनसे उपभोक्ताओं पर कर का भार अधिक न पड़े और ये वस्तुओं का उचित मात्रा में उपयोग कर सकें। तटस्थता-वक्र की सहायता से यह भी पता किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के करों से उपभोक्ता की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सरकारी कर्तव्य-प्रेरणा (inducives) देती है या नहीं?

(4) दो विकल्पों के बीच पसन्दगी या प्राथमिकता कम निर्धारण में सहायक : इसका प्रयोग यह पता लगाने में लिए भी किया जा सकता है कि उपभोक्ता प्रायः और विधाय, वर्तमान उपयोग तथा भविष्य के उपयोग, तरस सम्पत्तियों तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों में किसको अधिक पसन्द करेगा?

(5) उपभोक्ता की दक्षत ज्ञात करने में सहायक : तटस्थता वक्र-विधि की सहायता से सत्पा सूचक उपयोगिता (Cardinal utility) को जाने बगैर उपभोक्ता-दक्षत की व्याख्या की जा सकती है।

(6) सूचनांक (Index Number) की समस्या में प्रयोग : तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का जीवन स्तर तुलनात्मक दृष्टि से ऊँचा है अथवा नीचा, अच्छा है या खराब, इसका पता चल सकता है।

(7) उपभोक्ता-सन्तुलन की स्थिति ज्ञात करने में सहायक : तटस्थता वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता-सन्तुलन की स्थिति ज्ञान की जा सकती है। इस सन्तुलन की स्थिति में उपभोक्ता की अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है। जिस बिन्दु पर मूल्य-रेखा तटस्थता-वक्र की स्पर्श-रेखा होती है, उस बिन्दु पर उपभोक्ता दो वस्तुओं की मात्राओं के संयोग से अधिकतम सन्तुष्टि पा सकता है। तटस्थता-वक्रों की सहायता

से ही उपभोक्ता सतुलन पर आये, प्रतिस्थापन तथा मूल्य के प्रभावों को ज्ञात किया जा सकता है ।

(8) उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग - जिस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में समान सन्तुष्टि वाले संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्रों (Iso-utility Curves) का निर्माण करके किसी उपभोक्ता के लिए उपभोग्य वस्तुओं का प्राथमिक क्रम व्यक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में समान उत्पादन क्षमता वाले उत्पादन साधनों के संयोगों को ज्ञात करने के लिए समता-वक्रों (Iso quant Curves) का निर्माण किया जा सकता है ।

### प्रश्न एवं संकेत

1 तटस्थता वक्र रेखाएँ मूल बिन्दु ( origin ) की ओर उन्नतोदर (Convex) क्यों होती हैं ? इनकी सहायता से कीमतों में परिवर्तनों का उपभोक्ता की माग पर पड़े प्रभाव का विवेचन कीजिए ।

(Raj, B A , 1964)

[संकेत सव प्रथम अंति संक्षेप में तटस्थता वक्र रेखाओं का अर्थ स्पष्ट कीजिए । इसके पश्चात् तटस्थता-वक्र रेखा के मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर (convex) होने की विशेषता का विवेचन कीजिए । अन्त में कीमत प्रभाव की व्याख्या कीजिए ।]

2 तटस्थता वक्र रेखाओं से थाप क्या समझते हैं । उनकी सहायता से माग रेखा को निकालिए ।

(Raj II A 1963)

[संकेत देखिये पृष्ठ 234-237]

3 चिन्तों की सहायता से तटस्थता वक्र रेखाओं के विचार की व्याख्या कीजिए । उपयोगिता विचार के ऊपर यह कहा तक सुधार है ?

(Jodhpur T D C , Arts, 1963)

[संकेत प्रथम भाग में उदाहरण व रेखाचित्रों की सहायता से तटस्थता-वक्र रेखाओं को स्पष्ट कीजिए । द्वितीय भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि कहा तक यह उपयोगिता विश्लेषण के ऊपर सुधार है ।]

4. क्या उपयोगिता मापनीय ( Measurable ) है ? यदि यह मापनीय नहीं है, तो उपभोक्ता के चुनाव सिद्धान्त ( Theory of Consumer's choice ) में इस कठिनाई को कैसे दूर कर सकते हैं ?

(Allahabad, B A. I, 1964)

[संकेत सव प्रथम उपयोगिता की मापने में कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए । इसके पश्चात् स्पष्ट कीजिए कि तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से इस कठिनाई को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।]



5. किसी वस्तु के मूल्य में कमी पर आय व प्रतिस्थापन प्रभाव (Income and Substitution effect) का स्पष्ट उल्लेख कीजिए।

(Bihar, B. A. Hons 1966 A)

[सकेत देखिए पृ० 230 से 234]

6 उदासीनता वक्र-टेक्नीक की सहायता से उपभोक्ता की सामान्य मांग-वक्र का निर्माण कीजिए। मांग वक्र किन परिस्थितियों में 'पीछे की ओर गिरती' होगी।

(Raj. M. Com, 1969)

### समस्याएं

1. सिद्ध कीजिए कि यदि उदासीनता वक्र सीधी रेखा में या नतोदर (Concave) हो तो उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीदेगा, दोनो नहीं।

2. पृष्ठ 233 पर घटिया किस्म की वस्तुओं का चित्र है। ऐसा रेखाचित्र खींचिए जिनमें Y वस्तु को घटिया किस्म का दिखाया गया हो।

3. 'गिफेन-प्रभाव' (Giffen Effect) को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

4. बताइए कि परम्परागत मांग वक्र (Traditional Demand curve) को उदासीनता मान-चित्र (Indifference map) से किन प्रकार खींचा जा सकता है?

5 मांग विश्लेषण के सीमान्त उपयोगिता दृष्टिकोण की तुलना में उदासीनता वक्र दृष्टिकोण के लाभों को समझाइए।

## मांग की लोच (Elasticity of Demand)

*"The elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded which would result from one percent change in price"*

—Boulding

### 1 मांग की लोच का अर्थ (Meaning of Elasticity) ✓

मांग के नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है। मांग तथा कीमत में विपरीत सम्बन्ध होता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है, उसे मांग की लोच कहते हैं, अर्थात् कीमत परिवर्तन के कारण मांग की प्रतिकारिता को ही मांग की लोच कहते हैं (The responsiveness of demand to changes of price is called elasticity of demand)। प्रो० कैरनक्रॉस के शब्दों में, 'एक वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर क्रय की मात्रा में, कीमत के परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है।'<sup>1</sup> थोमस जोन रॉबिन्सन के अनुसार, "मांग की लोच, किसी कीमत या उत्पात्ति पर क्रय की गई मात्रा का वह आनुपातिक परिवर्तन है जो कीमत के अल्प परिवर्तन में, कीमत के आनुपातिक परिवर्तन में मांग देने पर प्राप्त होती है।"<sup>2</sup> अर्थात् यदि किसी बिन्दु पर हम मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो वह मांग के आनुपातिक परिवर्तन और मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात द्वारा ज्ञात की जा सकती है, अर्थात्

<sup>1</sup> "The elasticity of demand for a commodity is the rate at which the quantity bought changes as the price changes" —Cairncross

<sup>2</sup> "The elasticity of demand, at any price or at any output, is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price divided by the proportional change of price"

—Joan Robinson, op cit p 18

माग की लोच =  $\frac{\text{माग का आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{मूल्य का आनुपातिक परिवर्तन}}$

एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, किसी वस्तु की कीमत पांच रुपया प्रति इकाई होने पर उस वस्तु की 40 इकाइयों की माग होती है। यदि वस्तु का मूल्य घट कर चार रुपया प्रति इकाई हो जाता है तो उस वस्तु की 50 इकाइयों की माग होती है। ऐसी अवस्था में माग की लोच, उपरोक्त सूत्र के अनुसार, इस प्रकार ज्ञात की जाएगी।

कीमत	5 रुपए प्रति इकाई	4 रुपए प्रति इकाई
	↓	↓
माग	40 इकाइया	50 इकाइया

(i) माग का आनुपातिक परिवर्तन =  $\frac{\text{माग में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)}}{\text{पहले की माग}} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$

(ii) कीमत का आनुपातिक परिवर्तन =  $\frac{\text{कीमत में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)}}{\text{पहले की कीमत}} = \frac{-1}{5} = -\frac{1}{5}$

(iii) माग की लोच =  $\frac{\text{माग में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}} = \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{1}{5}} = -\frac{5}{4} \text{ या } 1.25$

उक्त उदाहरण में माग अधिक लोचदार है, क्योंकि कीमत के आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा, माग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हुआ है, अर्थात् कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर माग में आनुपातिक वृद्धि अधिक हुई है।

‘माग की लोच’ (Demand Elasticity) तथा ‘माग की मूल्य-लोच’ (Price elasticity of Demand) दोनों का प्रयोग एक ही वर्ष में किया जाता है।

## 2. माग की चप-लोच तथा बिन्दु लोच ✓

(Arc Elasticity and Point Elasticity)

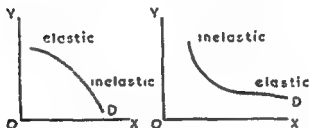
जब माग की लोच, माग-रेखा के दो बिन्दुओं के बीच ज्ञात की जाती है तो उसे माग की चाप लोच (Arc Elasticity) कहते हैं। जब माग रेखा के किसी एक बिन्दु पर लोच ज्ञात की जाती है तो उसे बिन्दु लोच (Point Elasticity) कहते हैं। इन दोनों प्रकार की लोचों की ज्ञात करने की अलग-अलग विविधा हैं।

(क) माग की चप-लोच (Arc Elasticity) :

(1) चाप लोच ज्ञात करने की आवश्यकता - सामान्य रूप से हम पूरे माग रेखा की लोच की ज्ञात करते हैं और यह ज्ञात करते हैं कि किसी वस्तु की माग पर मूल्य-परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है? परन्तु इससे विभिन्न दशाओं में पाई जाने वाली वास्तविक-स्थिति का पता नहीं चलता है। क्योंकि किसी वस्तु की माग कुछ

मूल्य-क्षेत्रों ( Price-Range ) पर लोचदार ( elastic ) हो सकती है तथा कुछ मूल्यों पर वेलोचदार ( Inelastic ) । इसी प्रकार लोच की मात्राएं ( degree of elasticity ) भी एक मूल्य-क्षेत्र व दूसरे मूल्य-क्षेत्र पर अलग अलग हो सकती हैं । चित्र सरदा 31 इन तथ्यों को प्रकाश में लाता है ।

### Elasticities and Price Ranges



चित्र सं० 31

प्रथम चित्र में ऊँचे मूल्यों पर मांग लोचदार है तथा कम-मूल्यों पर वेलोचदार है । दूसरे चित्र में ठीक इसके विपरीत स्थिति है । व्यावहारिक रूप से ये दोनों प्रकार की मांग रेखाएँ पाई जा सकती हैं । अतः एक ही मांग-रेखा के विभिन्न भागों की लोच अलग-अलग हो सकती है । इसलिए मांग रेखा के अलग-अलग भागों की लोच ज्ञान करना, व्यावहारिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है । मांग रेखा पर किसी दो बिन्दुओं के बीच की लोच को 'चाप-लोच' कहते हैं ।

(2) 'चाप-लोच क्या है ? चाप-लोच, मांग रेखा के एक चाप अर्थात् दो बिन्दुओं के बीच की दूरी के लिए ज्ञात करते हैं । जैसे चित्र सरदा 32 में DD मांग रेखा पर A व B के बीच मांग की लोच । चाप लोच, दो मूल्यों और मात्राओं के एक क्षेत्र (Range) से सम्बन्धित है । जैसे, यदि कीमत सी रुपये प्रति मन है तो चावल की मांग 1000 मन है । यदि कीमत घटकर 90 रुपये प्रति मन हो जाए तो मांग बढ़कर 1200 मन हो जाती है । यदि हम 90 — 100 रुपये (Price-Range) के लिए मांग की मात्राओं के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करें तो उसे चाप-लोच कहेंगे । चाप किसी वक्र के एक भाग को कहते हैं । अतः चाप-लोच का अर्थ है, मांग रेखा के एक भाग के सम्बन्ध में लोच ज्ञात करना । चाप लोच मांग रेखा पर दो बिन्दुओं के बीच, मध्य बिन्दु पर, मांग की लोच बताती है ( Arc elasticity is the elasticity at the mid point of an arc of a demand ) । जब हम मांग रेखा के दो बिन्दुओं के बीच चलते हैं (जैसे DD रेखा पर A व B बिन्दु) तो इनके बीच बहुत सी मांग रेखाएँ खींची जा सकती हैं, जिनकी वक्रता (Curvature) में विनिश्चयता होगी ।

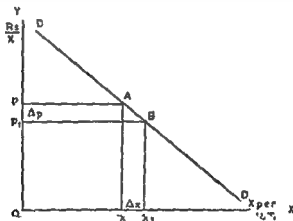
अतः जब हम दो बिन्दुओं के बीच लोच या चाप-लोच ज्ञात करते हैं तो लोच, समूचे चाप से गुजरने वाली मांग रेखाओं की लोचों की औसत होती है।

(3) चाप लोच ज्ञात करने के तरीके ( Methods of calculating Arc Elasticity ) : चाप-लोच ज्ञात करने के तीन निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।

(i) पहला सूत्र (First Formula) हम यह जानते हैं कि मांग की लोच, मांग में आनुपातिक परिवर्तन तथा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। बीज गणित (Algebra) की भाषा में हम कह सकते हैं।

$$e = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

( $e$  = मांग की लोच,  $\Delta X$  = मात्रा में परिवर्तन,  $\Delta P$  = कीमत में परिवर्तन)  
चित्र सं० 32 में  $OX$  अक्ष पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा, तथा  $OY$  पर कीमत प्रदर्शित की गई है।  $OP$  कीमत पर  $OX_1$  मात्रा खरीदी जा रही है। कीमत घट कर  $OP$  से  $OP_1$  हो जाती है, तब खरीद की मात्रा  $OX$  से बढ़कर  $OX_2$



चित्र सं० 32

हो जाती है।  $\Delta$  (डेल्टा) कमी या वृद्धि को प्रकट करता है। इस प्रकार  $\Delta X$  वस्तु की बढ़ी हुई मात्रा, तथा  $-\Delta P$  कीमत में हुई कमी को प्रकट करता है। इस प्रकार वस्तु की मात्रा में  $\Delta X$  परिवर्तन तथा कीमत में  $-\Delta P$  परिवर्तन हुआ है।  $DD$  मांग वक्र है।  $OP_1$  कीमत पर हम मांग वक्र के बिन्दु  $B$  पर हैं तथा  $OP$  कीमत पर बिन्दु  $A$  पर हैं। हम यह जानते हैं कि

माग की लोच =  $\frac{\text{माग में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$

$$\text{अतः माग की लोच या } e = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

एक उदाहरण द्वारा हम इस सूत्र को स्पष्ट कर सकते हैं।

मान लीजिए चित्र में सम्बन्धित सरयाए निम्नलिखित है :

$$P = (\text{कीमत रुपये में}) \quad X = (\text{मात्रा मनो में})$$

बिन्दु A पर 100 1000

बिन्दु B पर 90 1200

यदि कीमत 100 रुपए प्रति मन है तो चावल की 1000 मन मात्रा (माग) खरीदी जाती है। यदि कीमत घटकर 90 रुपए प्रति मन हो जाती है तो चावल की माग बढ़कर 1200 मन हो जाती है।

(क) यदि हम माग वक्र पर बिन्दु A से बिन्दु B पर आएँ तथा यदि हम सूत्र में प्रयुक्त अक्षरों के स्थान पर सरयाए लिख द तो :

$$e = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\frac{200}{1000}}{\frac{-10}{100}} = \frac{200}{1000} \times \frac{100}{-10} = -2$$

(ख) यदि हम बिन्दु B से A पर आएँ अर्थात् मान लें कि पहले 90 रु० प्रति मन कीमत पर माग 1,200 मन थी। कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो माग घटकर 1000 मन हो जाती है। ऐसी स्थिति में,

$$e = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\frac{-200}{1200}}{\frac{10}{90}} = \frac{-200}{1200} \times \frac{90}{10} = -1.5$$

पहली अवस्था में माग की लोच—2 तथा दूसरी अवस्था में —1.5 है। हम यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर, उदाहरण में सरयाए नहीं है, परन्तु जब हम A से B बिन्दु की ओर, तथा B बिन्दु से A बिन्दु की ओर जाते हैं तो इन दो दशाओं में माग की लोच में अन्तर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन दो दशाओं में मात्रा तथा कीमत के प्रतिशत परिवर्तनों में अन्तर है।

(ii) दूसरा सूत्र ( Second Formula ) उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दोनों दशायो में माग की लोच में पर्याप्त अन्तर है। दोनों बिन्दु, एक दूसरे से जितने ही दूर होंगे, Arc-elasticity में उतना ही अधिक अन्तर पाया जाएगा। अतः उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग उसी समय करना चाहिए, जबकि दोनों बिन्दु एक दूसरे के निकट हों। जब हम बिन्दु A से प्रारम्भ करते हैं तथा फिर बिन्दु B से प्रारम्भ करते हैं तो परिणाम में बहुत अन्तर पाया जाता है। यह उपर्युक्त सूत्र का दोष है। अतः पहले सूत्र के दोषों से बचने के लिए, अन्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है :

$$e = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P_2}} = \frac{200}{1000} - \frac{-10}{90} = \frac{200}{1000} \times \frac{90}{-10} = -1.8$$

यहाँ पर  $P_2$  दोनों सूत्रों में से कम मूल्य को तथा  $X$  दोनों मानाओं में से कम माना को प्रकट करता है। माग की लोच A और B बिन्दुओं के बीच ज्ञान की गई है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पहले सूत्र के अनुसार A से B बिन्दु तथा B से A बिन्दु के बीच माग की लोच क्रमशः—2 व—1.5 थी। दूसरे सूत्र के अनुसार A तथा B बिन्दुओं के बीच माग की लोच—1.8 है जो दोनों के औसत के जवम है। अतः दूसरा सूत्र अधिक विश्वसनीय है। ( विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि माग की लोच ऋण ( — ) में आती है, क्योंकि कीमत तथा माना में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होता है। परन्तु जब हम माग की लोच की मात्रा की बात करते हैं तो ऋणरहित चिह्न ( — ) पर ध्यान नहीं दिया जाता है। )

(iii) तीसरा सूत्र ( Third Formula ) : माग की चाप-लोच मानून करने के लिए एक अन्य सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है :

$$e = \frac{\frac{X - X_1}{X + X_1}}{\frac{P - P_1}{P + P_1}}$$

इस सूत्र द्वारा उपर्युक्त उदाहरण में दी गई संख्याओं के आधार पर यदि हम चाप-लोच ज्ञात करें तो उत्तर—1.7 जाएगा। इस सूत्र की भी यह विशेषता है कि यदि हम A से B तथा B से A की ओर चलें तो इस प्रकार जो माग की लोचें होंगी, उनका औसत जवम—1.7 होगा।

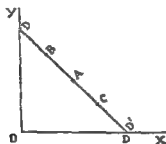
(ख) मांग की बिन्दु-लोच ( Point Elasticity of Demand ) :

व्यावहारिक जीवन में हम जानते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बड़ी कम मात्राओं से बढ़ती हैं। किसी वस्तु की कीमत, भाड़ा पैसा, एक पैसा, दो पैसा या

कुछ पैसों से बचना व घटना मागरेखा वात है। यदि मूल्य में इस प्रकार के परिवर्तन बहुत ही कम दर से होते हैं तो ऐसी दशा में हमें माग रेखा के किसी एक बिन्दु पर, माग की लोच ज्ञात करनी पड़ती है। यत्र कहा जा सकता है कि बिन्दु लोच एक प्रकार की चाप-लाच है जबकि चाप के दो बिन्दुओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। जब माग रेखा के एक बिन्दु पर, लोच ज्ञान की जाती है तब उसे बिन्दु लोच कहते हैं। माग रेखा भी प्रवृत्ति के अनुसार दो प्रकार की हो सकती है प्रथम सीधी माग रेखा (Linear Demand) तथा वक्र के रूप में (curve)। इन दोनों दशाओं में माग की बिन्दु लोच ज्ञान करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं, य विधियाँ मार्शल ने बतलाई हैं।

1. जब माग रेखा सीधी हो।

माग-रेखा के विभिन्न बिन्दुओं पर माग की लोच समान नहीं होती है। मार्शल ने माग-वक्र के विभिन्न बिन्दुओं पर लोच मानने की प्रत्येक विधि बतलाई है। इन विधियों में से एक विधि द्वारा स्पष्ट किया गया है। चित्र में DD' एक सीधी



चित्र सं० 33

माग-रेखा है, जो OX तथा OY पर D व D' बिन्दु पर मिलती है। DD' पर मध्य बिन्दु A है, अर्थात्  $DA = AD'$ । लोच ज्ञान करने के लिए इस मूल्य का प्रयोग किया जाता है

किसी बिन्दु पर माग की लोच =  $\frac{\text{वक्र पर किसी बिन्दु से D' तक की दूरी}}{\text{उसी बिन्दु से D तक की दूरी}}$

बिन्दु A वक्र के मध्य में है अतः A बिन्दु पर माग की लोच =  $\frac{AD'}{AD} = 1$  होगी। इसी प्रकार—

B बिन्दु पर माग की लोच  $\frac{BD'}{BD}$  तथा

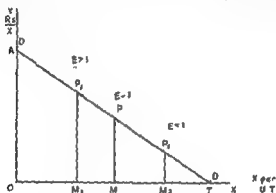
C बिन्दु पर माग की लोच =  $\frac{CD'}{CD}$

\*जिस बिन्दु पर हम माग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं।



यदि हम माग रेखा की सम्वर्द्ध को ध्यान में रखें तो मध्य-बिन्दु (A) से नीचे के प्रत्येक बिन्दु पर माग की लोच इकाई से कम होगी तथा मध्य-बिन्दु से ऊपर के प्रत्येक बिन्दु पर माग की लोच इकाई से अधिक होगी।

सामान्य परिमाण के आधार पर माग की लोच के तीन भेद किए जा सकते हैं : (i) जब लोच की मात्रा एक से अधिक होती है तब माग को लोचदार (elastic) कहते हैं। (ii) जब लोच की मात्रा एक होती है तब उसे इकाई लोच (unitary elastic) कहते हैं तथा (iii) जब लोच की मात्रा एक से कम होती है तब उसे बेलोच (inelastic) कहते हैं। चित्र स० 34 में इन्हें स्पष्ट किया गया है।



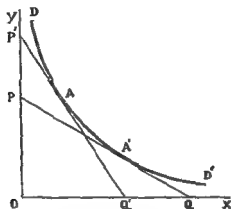
चित्र स० 34

DD माग रेखा है। P बिन्दु माग रेखा पर ऐसे स्थान पर स्थित है, जिससे  $PD = PD$  या  $OM = MT$  अतः बिन्दु P पर माग की लोच इकाई (unitary) होगी। माग रेखा पर P बिन्दु से ऊपर की ओर जितने भी बिन्दु लिए जाएं वे प्रत्येक बिन्दु पर माग की लोच एक से अधिक होगी—जैसे  $P_2$  बिन्दु पर। यदि ऊपर बढ़ते जाएं तो बिन्दु A पर, लोच infinity ( $\infty$ ) हो जाएगी। इसी प्रकार P बिन्दु से, माग बढ़ कर नीचे के सभी बिन्दुओं पर लोच एक से कम होगी जैसे  $P_1$  बिन्दु पर। यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो बिन्दु T पर, माग की लोच शून्य हो जाएगी।

## 2 माग रेखा सीधी न होने पर

रेखा चित्र स० 34 में माग-वक्र को  $DD'$  द्वारा प्रकट किया गया है। सामान्यतया माग-वक्र सीधी रेखा के रूप में नहीं होता है। यदि माग-वक्र सीधी रेखा के रूप में नहीं है तो भी हम उस मूल द्वारा माग वक्र के किसी बिन्दु पर लोच को नाप सकते हैं। ऐसी अवस्था में, हम जिस बिन्दु पर माग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, उस बिन्दु से माग वक्र पर स्पर्श रेखा (Tangent) खींचते हैं। अथवा पृष्ठ पर चित्र द्वारा यह विधि स्पष्ट की गई है।

चित्र में  $DD'$  माग वक्र है, जिसके  $A$  तथा  $A'$  बिन्दुओं पर माग की लोच ज्ञात करनी है।  $A$  तथा  $A'$  बिन्दुओं पर माग वक्र की स्पर्श रेखाएँ क्रमशः  $P'Q'$



चित्र सं० 35

तथा  $PQ$  खींची गई हैं।  $A$  बिन्दु की स्पर्श रेखा  $OX$  तथा  $OY$  को  $Q'$  व  $P'$  बिन्दु पर काटती है तथा  $A'$  बिन्दु की स्पर्श रेखा  $OX$  तथा  $OY$  को  $Q$  व  $P$  बिन्दुओं पर काटती है। सूत्र के अनुसार

$$A \text{ बिन्दु पर माग की लोच} = \frac{AQ'}{AP'}$$

$$A' \text{ बिन्दु पर माग की लोच} = \frac{A'Q}{A'P}$$

चित्र में स्पष्ट है कि  $A$  बिन्दु पर माग की लोच  $A'$  बिन्दु की अपेक्षा अधिक है।

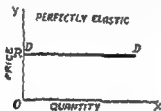
इन विधियों द्वारा लोच ज्ञात करने को ज्यामितिक विधि (Geometric technique) भी कहते हैं। इन्हें 'मार्शल की बिन्दु विधि' भी कहते हैं।

### 3 माग की कीमत लोच की मात्राएँ (Degrees of Price Elasticity of Demand)

माग की लोच सदैव समान नहीं होती है। कुछ वस्तुओं की माग की लोच परिस्थिति के अनुसार अधिक होती है तथा कुछ की कम होती है। यदि मूल्य परिवर्तन का किसी वस्तु की माग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस वस्तु की माग पूर्णतया बेलोच (Perfectly Inelastic) होती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की माग पर मूल्य-परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तो उस वस्तु की माग अत्यधिक लोचपूर्ण (Perfectly Elastic) होती है। व्यावहारिक रूप में सामान्यतः ये दोनों समस्याएँ नहीं पाई जाती। 'पूर्णतया बेलोच' तथा 'अत्यधिक लोचपूर्ण'

के बीच, लोच की कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार लोच की पाँच श्रेणियाँ हो सकती हैं :

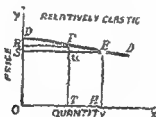
1. पूर्णतया लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand) : जब किसी वस्तु के मूल्य में अत्यन्त ही थोड़ी सी वृद्धि या कमी होने से, उस वस्तु की माँग की मात्रा में अत्यन्त कमी या वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में माँग की लोच पूर्ण-



चित्र स० 36

तया लोचदार होती है। सामान्यतः मूल्य में परिवर्तन हुए बिना भी माँग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। रेखा चित्र स० 36 में पूर्णतया लोचदार माँग वक्र प्रदर्शित किया गया है।

2. अत्यधिक या सापेक्षतया लोचदार माँग (Highly or Relatively Elastic Demand) : जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, उसकी माँग में मानुषानिक परिवर्तन अधिक होता है तो उस वस्तु की माँग की लोच अत्यधिक

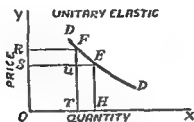


चित्र स० 37

लोचदार' कही जाती है। जैसे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने से, उसकी माँग में 25% वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की माँग अत्यधिक लोचदार बही जाएगी। चित्र स० 37 में 'अत्यधिक लोचदार माँग' वक्र दिखलाया गया है।

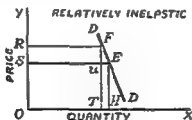
3. लोचदार या एकात्मक लोचदार माँग (Elastic or Unitary Elastic Demand) : जब किसी वस्तु की माँग में, मूल्य-परिवर्तन के अनुपात के अनुसार परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग की लोचदार माँग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने से उस वस्तु की माँग में ठीक 10% की वृद्धि हो

जाए। ऐसी माग की लोच इकाई के बराबर होती है, अतः इसे एकात्मक लोचदार माग भी कहते हैं। चित्र स० 38 में ऐसा माग वक्र प्रदर्शित किया गया है।



चित्र स० 38

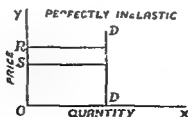
4. बेलोच या सापेक्षतया बेलोच माग (Inelastic or Relatively Inelastic Demand) : यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, उसकी माग में बहुत कम परिवर्तन होता है तो ऐसी माग को बेलोच माग कहते हैं। इसमें मूल्य-



चित्र स० 39

परिवर्तन की अपेक्षा, माग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होता है। जैसे मूल्य 50% कम हो जाए तथा माग की मात्रा केवल 10% ही बढ़े। चित्र स० 39 में सापेक्षतया बेलोच माग वक्र प्रदर्शित किया गया है।

5. पूर्णतया बेलोच माग (Perfectly Inelastic Demand) यदि किसी



चित्र स० 40

वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी माग की मात्रा में कोई

परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी मांग को पूर्णतया बेलोच मांग कहते हैं। चित्र सं० 40 में ऐसा मांग वक्र दिखाया गया है।

मांग की लोच की उपरोक्त मात्राओं या श्रेणियों को गणितीय सूत्रों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। मांग लोचदार हो सकती है, अर्थात् उसकी लोच 1 के बराबर हो सकती है या पूर्णतया लोचदार हो सकती है, अर्थात् 1 से अनन्त (Infinity) तक हो सकती है। दूसरी ओर बेलोच हो सकती है, अर्थात् एक से कम हो सकती है या पूर्णतया बेलोचदार हो सकती है अर्थात् उसकी लोच शून्य के बराबर हो सकती है। अतः हम गणित के सूत्रों के रूप में, उपरोक्त पाँच रूपों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट कर सकते हैं।

1. पूर्णतया लोचदार (Perfectly Elastic)  $(E \rightarrow \infty)$
2. अत्यधिक सापेक्षतया लोचदार (Highly Elastic)  $(\infty > E > 1)$
3. लोचदार या एलास्टिक लोचदार (Elastic)  $(E > 1)$
4. बेलोच या सापेक्षतया बेलोच (Inelastic)  $(0 < E < 1)$
5. पूर्णतया बेलोच (Perfectly Inelastic)  $(E = 0)$

#### 4. मांग की लोच मापने की विधियाँ

##### (Methods of Measurement of Elasticity)

मांग की लोच को मापने के लिए, मुख्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है

1. अनुपातिक या प्रतिशत रीति (Percentage Method or Proportionate Method)
2. कुल व्यय विधि (Method of Total Money Outlays)
3. मार्शल की बिन्दु रीति या ज्यामितीय रीति (Marshall's Point Method or Geometric Method)

##### 1. पलक्स की प्रतिशत रीति (Flux's Percentage Method) :

पलक्स के अनुसार मांग की लोच को माप के लिए, मांग के प्रतिशत परिवर्तन में मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से मांग देते हैं। पलक्स ने लोच की माप के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया है :

$$\text{मांग की लोच} = \frac{\text{मांग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन}}$$

उक्त सूत्र के अनुसार (i) यदि मांग तथा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन समान है तो मांग की लोच इकाई (unity) के बराबर होगी, जैसे मूल्य में 10% वृद्धि के कारण मांग में 10% की कमी हो जाए, (ii) यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन,

मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है तो माग की लोच इकाई से अधिक (More than unity) होगी, जैसे मूल्य में 20% कमी के कारण, माग की मात्रा में 25% वृद्धि हो जाए, (iii) यदि माग में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो तो माग की लोच इकाई से कम (Less than unity) होगी, जैसे मूल्य में 20% की कमी के कारण माग की मात्रा में 15% वृद्धि हो जाए।

वास्तव में यह रीति वही है, जिसे इस अध्याय के प्रारम्भ में 'लोच की परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उदाहरण द्वारा समझाया गया है। चाप लोच (Arc-elasticity) के अंतर्गत जो तीन सूत्र बतलाए गए हैं, वे सभी, आनुपातिक रीति के ही अन्तर्गत आते हैं। इसका सामान्य सूत्र निम्नलिखित है

$$\text{माग की लोच} = \frac{\text{माग में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

## 2 कुल व्यय विधि (Method of Total Money Outlays) .

इस विधि का प्रतिपादन माशल ने किया है। इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि माग की लोच इकाई है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है ? (इकाई के सदृश में लोच ज्ञात करने के कारण इस विधि को माशल की इकाई रीति (Marshall's Unitary Method) भी कहते हैं।) इस विधि द्वारा माग की लोच मापने के लिए वस्तु पर किए गए कुल व्यय (मूल्य परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात्) की तुलना की जाती है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इस विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है

### विभिन्न मूल्यों पर माग तथा कुल व्यय

प्रथम अवस्था      द्वितीय अवस्था      तृतीय अवस्था

मूल्य प्रति इकाई ₹०	माग की मात्रा	कुल व्यय (₹० में)	माग की मात्रा	कुल व्यय (₹० में)	माग की मात्रा	कुल व्यय (₹० में)
5	20	100	20	100	20	100
4	25	100	40	160	24	96
3	33 $\frac{1}{3}$	100	60	180	27	81

उपरोक्त सारणी में तीन अवस्थाएँ स्पष्ट हैं। तीनों अवस्थाओं में किसी वस्तु का प्रति इकाई मूल्य 5 ₹० है तथा इस मूल्य पर माग की मात्रा 20 है। इसके पश्चात् मूल्य घटकर क्रमशः 4 ₹० व 3 ₹० प्रति इकाई हो जाता है। फलस्वरूप

माग बढ़ती है। प्रत्येक अवस्था के दूसरे काल में कुल व्यय दिखाया गया है, (मांग  $\times$  मूल्य प्रति इकाई)। इन कुल व्ययों के आधार पर माग की लोच की माप इस प्रकार की जाएगी :

(i) मांग की लोच इकाई के बराबर (Elasticity of Demand equal to Unity) : यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण माग की मात्रा में इस प्रकार परिवर्तन हो कि कुल व्यय प्रत्येक वक्ता में समान रहे तो माग की लोच इकाई के बराबर होगी। उपरोक्त सारिणी के अनुसार, प्रथम अवस्था में मूल्य के घटने पर माग बढ़कर 25 तथा 33 $\frac{1}{3}$  हो जाती है। परन्तु कुल व्यय माग की प्रत्येक मात्रा पर 100 रु. रहता है। अतः यहाँ पर माग की लोच इकाई के बराबर है। (प्रथम बार कुल व्यय की गई रकम से अन्य बार कुल व्यय की गई रकमों में भाग देने से परिणाम 1 रहता है,  $\frac{100}{100}=1$ ,  $\frac{100}{100}=1$ )

(ii) माग की लोच इकाई से अधिक (Elasticity of Demand more than Unity) : यदि वस्तु के मूल्य में कमी से, माग इतनी अधिक बढ़ जाए कि कुल व्यय पहले की अपेक्षा अधिक होने लगे, तब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, जैसे द्वितीय अवस्था में कुल व्यय 100 रुपए में बढ़कर, 160 रुपए तथा 180 रुपए हो जाता है। यहाँ पर माग की लोच इकाई से अधिक है।

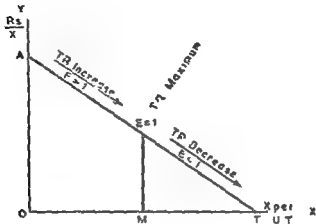
$$\left( \frac{160}{100} = 1.6 \quad \frac{180}{100} = 1.8 \right)$$

(iii) मांग की लोच इकाई से कम (Elasticity of Demand Less than Unity) : यदि वस्तु के मूल्य में कमी होने से माग में इस प्रकार वृद्धि हो, जिससे कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो जाए, तो ऐसी अवस्था में माग की लोच इकाई से कम होती है। जैसे तीसरी अवस्था में मांग बढ़ने पर कुल व्यय 100 रु. से घटकर 96 रु. तथा 81 रु. हो जाता है। यहाँ पर माग की लोच इकाई से कम है

$$\left( \frac{96}{100} = 0.96, \quad \frac{81}{100} = 0.81 \right)$$

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण : यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि खरीदार व्यय करता है। जो कुछ खरीददार व्यय करता है, विक्रेता की वही कुल आय (Total Revenue or T.R.) है। अतः हम कुल व्यय या कुल-आय की बात करें, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। उपर्युक्त विवरण के जो निष्कर्ष हैं, उन्हें रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। चित्र सस्या 41 में माग वक्र इस प्रकार का है जिससे OM=MT. यदि हम बिन्दु A से माग वक्र पर नीचे की ओर चलें तो बढ़ा पर ME रेखा, माग रेखा को स्पर्श करती है अर्थात् बिन्दु E तक, (यद्यपि माग की

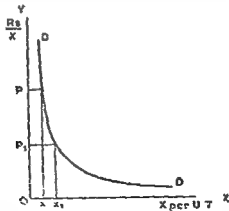
लोच घटती जा रही है) लोच एक से अधिक है अतः इस बिन्दु तक कुल आय (TR) बढ़ती जा रही है। यदि हम इससे भी नीचे की ओर चलें तो लोच घटती जाती है



चित्र सं० 41

सथा एक से कम रहती है। अतः कुल आय (TR) घटेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर लोच एक के बराबर है, वहाँ पर कुल आय अधिकतम है।

ऐसा भी माग वक्र हो सकता है, जिसके प्रत्येक बिन्दु पर, माग की लोच इकाई हो। ऐसी दशा में कीमत बढ़ाई जाए या घटाई जाए कुल-व्यय (या कुल



चित्र सं० 42

आय) समान रहेगा। ऐसा माग वक्र Rectangular hyperbola जैसा हो सकता है। चित्र संख्या 42 में इस तथ्य को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में DD माग वक्र ऐसा माग वक्र है जिसके प्रत्येक बिन्दु पर लोच इकाई है। चित्र से स्पष्ट है कि OP



कीमत पर  $OX$  मात्रा खरीदी जाती है। इस प्रकार कुल आय जैसे आयत के बराबर प्राप्त होती है। यदि कीमत घटाकर  $OP_1$  कर दी जाती है, तब  $OX_1$  मात्रा खरीदी जाती है। इस प्रकार जो आयत बनता है, उसका क्षेत्रफल, प्रथम मागत के विलुप्त बराबर है। इससे यह स्पष्ट है कि कीमत कुछ भी हो, कुल व्यय वही रहेगा।

### 3. रेखा भूमितीय या बिन्दु रीति (Point or Geometric Method)

माग वक्र दो प्रकार का हो सकता है, सीधी माग रेखा के रूप में और वक्र (Curve) के रूप में। इन दोनों रूपाओं में माग की लोच बिन्दु रीति द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे हम पहले 'माग की बिन्दु-लोच', धीरे-धीरे के अतःगत समझ चुके हैं (देखिए पृ० 252-254)

### 5 माग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Governing Elasticity)

(1) वस्तु की प्रकृति (Nature of the commodity) : सामान्यतया अनिवार्यताओं (Necessaries) की माग की लोच कम होती है तथा विलासिताओं (Luxuries) की माग की लोच अधिक होती है। आराम प्रदान करने वाली वस्तुओं (Comforts) की माग न तो अधिक लोचदार होती है और न लोचहीन। अनिवार्यताओं के बिना मनुष्य जीवन दुष्कर हो जाता है, उनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता। अतः उनके मूल्यों में वृद्धि होने पर भी माग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। विलासिताओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर उनकी माग बहुत कम हो सकती है क्योंकि उनके बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है तथा अपनी वांछना बनाए रख सकता है।

(2) समय (Time) : अल्प काल में, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का, उसकी माग पर कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ताओं की मूल्य परिवर्तन की जानकारी तुरन्त नहीं हो पाती। भविष्य में, मूल्य में और कमी की आशा के कारण भी उपभोक्ता मूल्य में कमी होने पर माग में वृद्धि नहीं करते।

(3) उपभोक्ता की आय (Income) एक निर्धन व्यक्ति की माग अधिकांश वस्तुओं के लिए अधिक लोचदार होती है। इसके विपरीत एक धनी व्यक्ति की माग कम लोचदार होती है। इसके साथ ही साथ यह भी स्मरणीय है कि यदि उपभोक्ता की आय का बहुत कम भाग किसी वस्तु के खरीदने में व्यय किया जाता है तो उस वस्तु की माग कम लोचदार होती है, इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की आय का बड़ा भाग किसी वस्तु के खरीदने के लिए व्यय किया जाता है तो उस वस्तु की माग अधिक लोचदार होगी।

(4) उपभोक्ता की आदत (Habit) : जिन वस्तुओं के उपभोग करने की

आदन पड़ जाती है उन वस्तुओं की माग कम लोचदार होती है जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब के मूल्य में वृद्धि का उसकी माग पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

(5) स्थानापन्न वस्तुएं (Substitutes) यदि किसी वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उस वस्तु की माग लोचदार होगी। जैसे चाय और काफी एक दूसरे की स्थानापन्न हैं। यदि काफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय द्वारा काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार मूल्य बढ़ने पर काफी की माग बहुत कम हो जाएगी।

(6) वस्तु के विभिन्न उपयोग (Different Uses) यदि कोई वस्तु विभिन्न कार्यों में लाई जा सकती है तो उसकी माग अधिक लोचदार होगी। जैसे बिजली यदि सस्ती दर पर दी जाने लगे तो उसका विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होने के कारण, बिजली की माग बहुत बढ़ जाएगी। जिस वस्तु का प्रयोग कबन एक कार्य के लिए किया जाता है उसकी माग कम लोचदार होती है।

(7) वस्तु के प्रयोग का स्थगन (Postponement of Consumption) : जिस वस्तु का प्रयोग भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, उसकी माग अधिक लोचदार होती है। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु वाले देश में ऊनी कपड़ों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उनकी माग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सूती कपड़े या पुराने ऊनी कपड़े से अपना काम चला लेंगे।

(8) संयुक्त माग (Joint Demand) : यदि किसी वस्तु का उपयोग अन्य वस्तु के साथ किया जाता है तो उस वस्तु की माग की लोच कुछ प्रशास्य उस अन्य वस्तु की माग की लोच पर निर्भर होगी। एक वस्तु की माग बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की माग स्वतः बढ़ जाएगी। जैसे माटरों की माग बढ़ने पर, पेट्रोल की माग स्वतः बढ़ जाएगी। अतः एक दूसरे की पूरक वस्तुओं की माग की लोच अधिक होती है।

(9) समाज में धन का वितरण (Distribution of Wealth) धन का समान वितरण होने पर वस्तुओं की माग अधिक लोचदार होगी तथा असमान वितरण से माग की लोच कम होगी। असमान वितरण होने से समाज में दो वर्ग होंगे—धनी तथा गरीब। धनी व्यक्तियों की माग (विलासिता-सम्बन्धी वस्तुओं की) कम लोचदार होती है; दूसरी ओर गरीब व्यक्ति केवल 'अनिवार्यताओं' को ही खरीदते हैं। अनिवार्यताओं की भी माग बहुत कम लोचदार होती है।

(10) समाज का जीवन-स्तर (Standard of Living) : समाज का जीवन-स्तर जितना ही ऊंचा होगा वस्तुओं की माग कम लोचदार होगी, क्योंकि उच्च जीवन-स्तर सम्पत्तिका प्रातीक है तथा धनी व्यक्तियों की माग पर मूल्य-परिवर्तन का बहुत कम असर पड़ता है।

(11) वस्तुओं का मूल्य (Price-level) : वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊँचा या बहुत कम होने पर भी उनकी मांग की लोच कम होती है। परन्तु मूल्य-स्तर का मांग की लोच पर प्रभाव 'पूरे समाज की मांग' तथा 'वर्ग-विशेष की मांग' पर अलग-अलग पड़ता है। (i) समाज की सामूहिक मांग : समूचे समाज की मांग, बहुत ऊँची प्रत्यक्ष कम कीमत वाली वस्तुओं के लिए कम लोचदार होती है, क्योंकि बहुत ऊँची कीमत की वस्तुएँ धन के योग्य खरीदने हैं, जो ऊँची कीमत पर भी वस्तुएँ खरीदेंगे। इसी प्रकार बहुत कम कीमत वाली वस्तुएँ सभी लोग खरीदेंगे। सस्ती वस्तुओं की मांग की लोच पर भी मूल्य में थोड़े परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ेगा, (ii) वर्ग-विशेष की मांग : कीमत का समाज के किसी वर्ग विशेष की मांग की लोच पर, मार्शल के अनुसार, इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा : "मांग की लोच ऊँचे कीमतों पर अधिक होती है, तथा मध्यम कीमतों पर अधिक या काफी अधिक होती है, परन्तु कीमत में गिरावट के साथ यह (लोच) कम होती जाती है। यदि कीमतें इतनी तेजी से गिरती हैं कि पूर्ण सन्तुष्टि की दशा प्राप्त जाए, तब यह (लोच) पूर्णतया समाप्त हो जाती है।"

## 6. मांग की लोच के प्रकार या प्रकृति (Kinds of Elasticity of Demand)

मांग की लोच की प्रकृति तीन प्रकार की हो सकती है। (i) मांग की कीमत-लोच (Price Elasticity of Demand) (ii) मांग की आय लोच (Income Elasticity of Demand) तथा (iii) मांग की साझे या तिरछी लोच (Cross Elasticity of Demand)

### (1) मांग की मूल्य लोच (Price Elasticity) :

मांग की मूल्य लोच के लिए 'मांग की लोच' या 'मांग की मूल्य लोच' दोनों में से किसी भी एक शब्द समूह का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, उस वस्तु की मांग घटती या बढ़ती है, तो मांग में परिवर्तन की सीमा के अनुपात को 'मांग की मूल्य लोच' कहते हैं।

### (2) मांग की आय लोच (Income Elasticity) :

किसी वस्तु की 'मांग की आय लोच' यह प्रश्न करता है कि किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी वस्तु के लिए, 'मांग की आय लोच' कम है तो इसका अर्थ होगा कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी का प्रभाव उस वस्तु की मांग की मात्रा पर बहुत कम पड़ेगा। उदाहरणार्थ, आय में वृद्धि या कमी का प्रभाव उपभोक्ता की चाय-सामग्रियों की मांग की मात्रा पर कम पड़ता है। उसकी आय में कमी हो जाय या वृद्धि हो जाए, चाय-शक्तानुसार उस एक निश्चित मात्रा में चाय-सामग्रियों खरीदनी पड़ेंगी। परन्तु कुछ

वस्तुओं के लिए 'आय लोच' अधिक हो सकती है, जैसे मोटर-कार। आय में परिवर्तन के कारण, मोटर-कार की माँग में बहुत अधिक परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार 'आय लोच' यह प्रकट करती है कि अन्य चीजें समान रहने पर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की माँग में क्या परिवर्तन होगा। माँग की आय लोच, निम्नलिखित प्रकार ज्ञात की जा सकती है :

$$e_1 \text{ या माँग की आय लोच} = \frac{\text{वस्तु की माँग में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{आय में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

माँग की आय-लोच ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है :

$$e_1 = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1 + Q_2} \div \frac{Y_2 - Y_1}{Y_1 + Y_2}$$

इस सूत्र में  $Y_2$  नई आय तथा  $Y_1$  पुरानी आय को प्रकट करते हैं।  $Q_2$  पुरानी मात्रा तथा  $Q_1$  नई मात्रा (वस्तु) का प्रकट करते हैं।

उपर्युक्त सूत्र द्वारा माँग की आय लोच ज्ञात की जा सकती है। सूत्र से स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु की माँग की आय लोच अधिक होगी तो उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की माँग में अधिक वृद्धि होती है। जैसे यदि उपभोक्ता की आय में 5% वृद्धि हो तथा इसके फलस्वरूप वस्तु का माँग में 10% वृद्धि हो तो माँग की आय लोच  $\frac{10}{5} = 2$  होगी, जो यह प्रकट करती है कि माँग की आय लोच ऊँची है। (यहाँ यह मान लिया गया है कि वस्तुओं की कीमतें पूर्ववत् हैं।) इसी प्रकार यदि उपभोक्ता की आय में 2% वृद्धि होती है तथा वस्तु की माँग में 1% वृद्धि होती है तो माँग की आय लोच  $\frac{1}{2} = 0.5$  होगी। अधिकांश वस्तुओं की माँग की आय लोच धनात्मक (Positive) होती है जो यह प्रकट करती है कि आय बढ़ने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जायेगी। जिन वस्तुओं की आय-लोच ऋणात्मक (Negative) होती है उन्हें घटिया वस्तुएँ (Inferior goods) कहते हैं। माँग की मूल्य लोच की ही तरह माँग की आय लोच भी पाँच प्रकार की हो सकती है :

(i) माँग की शून्य आय लोच (Zero income elasticity of demand)

इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाने पर भी वस्तु पर कुल व्यय पहले के समान रहता है अर्थात् यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि हो तो भी वस्तु की माँग में कोई वृद्धि नहीं होती है।

(ii) माँग की ऋणात्मक आय लोच (Negative income elasticity of demand) : यह उस स्थिति को प्रवर्णित करता है जबकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाने पर भी वस्तु पर बिखरे जाने वाले कुल व्यय में कमी होनी है अर्थात् यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि हो परन्तु वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा में घटती हो जाय। ऐसा घटिया वस्तुओं के सम्बन्ध में होता है।

(iii) माँग की इकाई आय लोच (Unitary income elasticity of demand) : इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता अपनी आय का जो भाग खर्च करने के पहले खर्च करता था, ठीक वही भाग खर्च करने के बाद भी खर्च करता है।

(iv) माँग की आय लोच इकाई से अधिक (Income elasticity of demand greater than unity) : यह स्थिति सामान्यतया प्रिलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू होती है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह पहले की अपेक्षा अपनी आय का अधिक प्रतिशत भाग किसी वस्तु पर खर्च करता है तो यह अवस्था माँग की इकाई से अधिक आय लाभ ही होगी।

(v) इकाई से कम माँग की आय लोच (Income elasticity of demand less than unity) : माँग की आय लोच सामान्यतया अनिवार्य आवश्यकता सम्बन्धी वस्तुओं में इकाई से कम होती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि होने से यदि वस्तु पर बिखरे जाने वाले व्यय में कम आनुपातिक वृद्धि हो तो ऐसी अवस्था में माँग की आय की लोच इकाई से कम होती है। उपभोक्ता पहले अपनी आय का जो प्रतिशत भाग एक वस्तु पर खर्च करता है, आय में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर कम प्रतिशत भाग खर्च करता है।

व्यावहारिक रूप में मुख्यतः तीन प्रकार की माँग की आय लोच का प्रयोग किया जाता है

1. माँग की धनात्मक आय लोच (Positive ei)।
2. माँग की शून्य आय लोच (Zero ei)।
3. माँग की ऋणात्मक आय लोच (Negative ei)।

### ✓ (3) माँग की तिरछी लोच (Cross Elasticity) :

यदि दो स्थापनाएँ (Substitute) वस्तुएँ हैं, तो उनको माँगें परस्पर प्रतिस्पर्धी (Competitive) होंगी। उनकी माँग प्रतिस्पर्धी होने के कारण, यदि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की माँग बढ़ जाएगी। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन या दूसरी वस्तु के माँग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे माँग की तिरछी लोच कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि देशों की माँग में 5% वृद्धि होने के

कारण वनस्पति धी की मांग में 10% वृद्धि होती है तो 'तिरछी लोच' इस प्रकार ज्ञात की जाएगी :

$$\frac{\frac{200}{5}}{\frac{10}{10}} = \frac{100}{5} \times \frac{10}{100} = 2$$

अतः 'तिरछी लोच' = 2 होगी जो यह प्रकट करती है कि धी के मूल्य में कुछ वृद्धि के कारण वनस्पति धी की मांग में दुगुनी वृद्धि होगी। यदि हम उपरोक्त दो वस्तुओं को क्रमशः X व Y मान ले तो तिरछी लोच ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित होगा :

$$\text{माग की तिरछी लोच} = \frac{X \text{ की मांग में आनुपातिक परिवर्तन}}{Y \text{ की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

'माग की तिरछी लोच' ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है

$$\text{माग की तिरछी लोच} = \frac{\frac{P_2 - P_1}{P_2 + P_1}}{\frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1}}$$

इस सूत्र में  $P_2$  तथा  $P_1$  स्थानापन्न वस्तु की नई तथा पुरानी कीमतों को प्रकट करते हैं।

तिरछी-लोच द्वारा स्थानापन्न वस्तुओं की निकटता (Closeness) का पता चलता है। किसी वस्तु की विलोम, उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत से भी प्रभावित होती है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम है तो विचारणीय वस्तु की कम मात्रा बेची जाएगी। यदि माग की तिरछी लोच ऊँची है तो इसका कारण यह है कि वस्तुएँ एक दूसरे की नजदीकी स्थानापन्न (Close Substitute) हैं। यदि तिरछी-लोच शून्य है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुएँ स्वतन्त्र हैं तथा स्थानापन्न नहीं हैं।

### प्रतिस्थापन लोच (Substitution Elasticity)

प्रतिस्थापन लोच, तटस्थता वक्र विश्लेषण से सम्बन्धित है। प्रतिस्थापन-लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

दिये हुए मूल्य अनुपात के परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस सीमा तक प्रतिस्थापित करता है उसे प्रतिस्थापन लोच कहते हैं। यदि उपभोक्ता पहले के समान संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। (Substitution elasticity expresses the extent to which one commodity can be substituted for another as a consequence of a given change in their price ratio, the consumer wants to enjoy the same amount of satisfaction) प्रति-

स्थापन की प्रक्रिया में वस्तुओं के अनुपात में परिवर्तन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए वनस्पति घी तथा शुद्ध घी की दरें 8 रुपये तथा 16 रुपये प्रति किलो ग्राम हैं। इन कीमतों पर उपभोक्ता 6 किलोग्राम वनस्पति घी तथा 4 किलो ग्राम शुद्ध घी खरीदता है। इस प्रकार वनस्पति घी तथा शुद्ध घी की खरीदी जाने वाली मात्रा का अनुपात  $\frac{6}{4}$  होगा तथा उनका कीमत अनुपात  $\frac{8}{16}$  होगा। इस प्रकार वस्तु अनुपात (Commodity ratio)  $\frac{3}{2}$  तथा कीमत अनुपात (Price ratio)  $\frac{1}{2}$  होगा। मान लीजिए शुद्ध घी की कीमत बढ़कर 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तथा वनस्पति घी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत में इस परिवर्तन के कारण उपभोक्ता शुद्ध घी का कम प्रयोग करेगा तथा इस कमी की पूर्ति वह अधिक वनस्पति घी खरीदकर करेगा अर्थात् वह शुद्ध घी को वनस्पति घी से प्रतिस्थापित करेगा। यह प्रतिस्थापन किस सीमा तक होगा यह इस बात पर निर्भर है कि शुद्ध घी को वनस्पति घी द्वारा किस सीमा तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए वह अब 8 किलोग्राम वनस्पति घी तथा 3 किलो ग्राम शुद्ध घी खरीदता है। अब वनस्पति तथा शुद्ध घी का अनुपात  $\frac{8}{3}$  होगा तथा नया मूल्य अनुपात  $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$  होगा।

ऐसी दशा में प्रतिस्थापन लोच की माप निम्न सूत्र द्वारा की जायेगी :

$$\text{प्रतिस्थापन लोच} = \frac{X \text{ व } Y \text{ वस्तुओं के समान-अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन}}{X \text{ व } Y \text{ वस्तुओं के कीमत-अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

इस सूत्र के अनुसार वनस्पति घी व शुद्ध घी में आनुपातिक परिवर्तन इस प्रकार हुआ है। पहले वनस्पति घी व शुद्ध घी का अनुपात  $\frac{3}{2}$  था तथा उनका नया अनुपात  $\frac{8}{3}$  है। इस प्रकार इन दोनों में आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात  $\frac{8}{3} - \frac{3}{2} = \frac{25}{6}$  है।

इसी प्रकार पहले का कीमत अनुपात  $\frac{1}{2}$  था तथा नया कीमत अनुपात  $\frac{1}{3}$  है। इस प्रकार कीमत अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन  $= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  होगा। सूत्र के अनुसार प्रतिस्थापन लोच  $= \frac{25}{6} \div \frac{1}{6} = 25 \times \frac{1}{1} = 25$  होगा। (लोच तथा सूत्र के अनुसार प्रतिस्थापन लोच का उत्तर ऋणात्मक होता है परन्तु मरलता की दृष्टि से ऋण निशान छोड़ दिया जाता है)।\*

### मूल्य प्रत्याशा लोच (Elasticity of price Expectations)

मूल्य प्रत्याशा (Price expectations) में मांग कितनी प्रभावित होगी, यह बात मूल्य प्रत्याशा लोच पर निर्भर करती है। लोच का यह विचार 1939 में ब्रिटेन

\* 'प्रतिस्थापन-लोच' का विचार (Concept) कठिन है। स्नातक बक्षीओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है अतः हमने केवल उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश की है। गणितीय सूत्र व रेखाचित्र का प्रयोग नहीं किया है।

अर्थशास्त्री हिक्स (J. R. Hicks) ने प्रस्तुत किया। मूल्य प्रत्याशा कई कारणों से प्रभावित होती है, जैसे-राजनैतिक निर्णय, वर्तमान तथा नवीन आर्थिक प्रवृत्तियाँ, प्रचलित धारणाएँ, मूल्यों में परिवर्तन सम्बन्धी अनुभव आदि। हिक्स ने मूल्यानुभव तथा मूल्य प्रत्याशा को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है।

‘मूल्य प्रत्याशा लोच’ वर्तमान मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन के साथ अनुमानित मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन का अनुपात है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी देखता है कि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% वृद्धि हुई है और इस आधार पर वह भविष्य में 20% वृद्धि की आशा करता है तो इस दशा में मूल्य प्रत्याशा लोच 2 हुई। आगे की तालिका किसी बाजार में क्रेताओं की मूल्य प्रत्याशा लोच की विभिन्न सीमाएँ प्रदर्शित करती है।

अगर मूल्य प्रत्याशा लोच इकाई से ज्यादा है तो मूल्यों में वर्तमान वृद्धि माग वक्र को दाहिनी तरफ स्थानान्तरित कर देगी। माग में वृद्धि इसलिए होगी, क्योंकि क्रेता भविष्य में और अधिक मूल्य देने की अपेक्षा वर्तमान में अधिक वस्तुएँ ख़रीदना चाहेंगे। अगर मूल्य प्रत्याशा लोच इकाई से कम या नकारात्मक है तो ऐसी अवस्था में माग कम हो जायेगी। अगर मूल्य प्रत्याशा लोच इकाई के बराबर है तो माग समान रहेगी, इसलिए ख़रीद योजना परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

### मूल्य प्रत्याशा लोच

(Elasticity of Price Expectations)

(वर्तमान मूल्य वृद्धि के प्रति क्रेताओं की धारणा)

लोच (elasticity)	गुणक (Coefficient) <sup>1</sup>	(Remarks) <sup>2</sup>
उच्च (High)	$>1$	नतीजा भविष्य में बढ़ते हुए मूल्यों की आशा रखते हैं।
इकाई (Unit)	1	क्रेता वर्तमान वृद्धि को अस्थायी मानते हैं।
निम्न (Low)	$<1 >0$	क्रेता वर्तमान वृद्धि को अस्थायी मानते हैं।
शून्य (Zero)	0	क्रेताओं का अनुमान है कि वर्तमान वृद्धि भविष्य में मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं रखती।
नकारात्मक (Negative)	$<0$	क्रेता वर्तमान वृद्धि की अपेक्षा भविष्य में मूल्यों में गिरावट की धारणा रखते हैं।

<sup>1</sup> माना कि अनुमानित मूल्य F है और चालू मूल्य C है तो मूल्य प्रत्याशा लोच का गुणक  $\frac{\Delta F}{F} - \frac{\Delta C}{C}$  होगा।

<sup>2</sup> यद्यपि विभिन्न क्रेताओं की अलग अलग मूल्य प्रत्याशा लोचें होती हैं। लेकिन उपर्युक्त तालिका इस मायना पर आधारित है कि बाजार में सभी क्रेताओं की मूल्य प्रत्याशा लोचें समान हैं।



### मांग की लोच का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक महत्त्व

मांग की लोच का विचार अर्थशास्त्र में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य उपयोगिताएँ निम्नलिखित हैं।

1. मूल्य निर्धारण में : किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तबकि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी पर वस्तु के मूल्य में किन्तनी वृद्धि या कमी होगी, यह बात मांग की लोच पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की मांग बलाबदार हुई तो पूर्ति में वृद्धि या कमी का मूल्य पर अनुपातिक प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार एकाधिकार (Monopoly) के अन्तर्गत बेलोबदार मांग वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में एकाधिकारी अधिक मूल्य चार्ज करने में सफल हो जायेगा।

2. सरकारी आर्थिक व वित्तीय नीतियों के लिए मांग की लोच का विचार सरकार को आर्थिक व वित्तीय नीतियाँ निर्धारित करने में सहायता पहुँचाता है। वैधानिक मूल्य नियंत्रण के समय सरकार को मांग की लोच के विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। कर लगाने समय सरकार को यह भी देखना पड़ता है कि उसका भार समाज के कौन से वर्ग पर पड़ेगा? अगर बेलोबदार मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाया गया तो सरकार को इच्छित आय प्राप्त हो जायेगी लेकिन लोचदार मांग वाली वस्तुओं की दशा में ऐसा सम्भव नहीं है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में : दो देशों के मध्य व्यापारित शर्तें निर्धारित करने में मांग की लोच का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। एक देश की वस्तु का दूसरे देश की वस्तुओं के साथ किस दर पर विनिमय किया जायेगा, यह बात दोनों देशों में उन वस्तुओं की पारस्परिक लोच (Mutual elasticity) पर निर्भर करती है।

4. विनिमय दर के निर्धारण में मांग की लोच का विचार सरकार को विनिमय दर के निर्धारण में सहायता पहुँचाता है। उदाहरण, के लिए अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) और पुनर्मूल्यीकरण (Revaluation) करते समय आयात व निर्यात की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है।

5. उत्पात्ति के साधनों का प्रतिकर निर्धारित करने में : मांग की लोच का विचार उत्पात्ति साधनों का प्रतिफल निर्धारित करने के निराय को भी प्रभावित करता है। अगर किसी उद्योग विशेष में श्रम (Labour) की मांग बेलोबदार है और स्वयं-संचालक (Automation) के लिए कोई क्षेत्र न हो तो ऐसी दशा में प्रतिक संघ (Trade Unions) अधिक मजदूरी तय करने में सफल हो जायेगे। यही बात अन्य प्रसाधनों के साथ लागू होती है।

6. कीमत विभेद के लिए : दो अलग-अलग बाजारों में एक ही वस्तु के अलग-अलग मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार राशिपातन के समय यह विचार बहुत सहायक सिद्ध होता है।

7. किसी उद्योग को सार्वजनिक महत्ता (Public utility) वाला उद्योग घोषित करना : कौन से उद्योग को सार्वजनिक सेवा घोषित किया जाए, यह निर्णय लेने में मांग की लोच का विचार सहायक सिद्ध होता है। यदि जीवनोपयोगी वस्तु, जिसकी मांग बेलोबदार है, किसी एकाधिकारी के नियंत्रण में है तो ऐसी वस्तु के उत्पादन या व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

8 मांग की लोच का सिद्धान्त सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता के विरोधाभास को स्पष्ट करता है। अधिक अच्छी फसल तुलनात्मक रूप में बुरा फसल की अपेक्षा कृषकों को कम द्रव्य प्रदान करती है। नष्ट होने वाली वस्तुओं (Perishable Commodity) के सम्बन्ध में यह बात अधिक अच्छी तरह स्पष्ट होती है।

इस प्रकार मांग की लोच का विचार सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है।

नोट—Elasticity of Demand, Total Revenue and Marginal Revenue के सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं। इनके पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में अध्ययन के लिए ? विनिमय के अग्रजंत 'आगत' शीर्षक अध्याय देखिए।

### प्रश्न व संकेत

1 मांग की लोच क्या है ? आप उसे कैसे मापेंगे ? बताइए कि विभिन्न आयों पर मांग की लोच किस प्रकार परिवर्तित होती है ?

(Allahabad, B. com. I, 1964)

[संकेत : सर्व प्रथम मांग की लोच के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात् इसके मापने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। अन्त में मांग की लोच पर आय के परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।]

2. मांग की लोच कैसे मापी जाती है ? एकाधिकारी मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का महत्व समझाइए।

[संकेत : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर के लिए 'एकाधिकार' सम्बन्धी अध्याय देखिए।]

3. कीमत लोच (Price elasticity) तथा आय लोच (Income elasticity) में अन्तर स्पष्ट कीजिए तथा कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियाँ बताइए।

(Bihar, B. A. Hons, 1967 A)

[सकेत : दोनों का अन्तर स्पष्ट करिए तथा लोच मापने की विधियों को समझाइए ।]

4. माग की लोच क्या है ? निम्न अरु तानिका की सहायता से तीनों परिस्थितियों में माग की लोच निकालिए तथा उनमें अंतर क्यों है ? समझाइए ।

	प्रति इकाई मूल्य (रुपये में)	माग की मात्रा (किलो ग्राम में)
परिस्थिति 1	10 8	30 36
परिस्थिति 2	10 8	30 35
परिस्थिति 3	10 8	30 38

(Gorakhpur, B. A I 1966)

[सकेत प्रथम भाग में माग की लोच के आशय को स्पष्ट कीजिए । द्वितीय भाग में माग की लोच को मापने की आनुपातिक रीति की व्याख्या कीजिए । अन्त में तीनों दशाओं में  $\frac{Q-Q_1}{Q+Q_1} \div \frac{P-P_1}{P+P_1}$  के प्रयोग से उत्तर निकालिए ।]

5. माग की लोच मापने के विभिन्न तरीकों का विवरण दीजिए । क्या माग वक्र का 'Steepness' इसकी लोच का सूचक है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(राज०, एम० काम० 1969)

### समस्याएँ (Problems)

1 अक्टूबर, 1967 को माउन्ट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने माल भाड़ा किसी निश्चित दूरी के लिए 25 रु० से 30 रु० कर दिया । एक महीने की अवधि में व्यापार की मात्रा ( Volume of business ) 20,58,000 रुपये से घटकर 19,25,000 रुपये हो गई ।

(अ) यह मानते हुए कि व्यापार की मात्रा में सम्पूर्ण गिरावट मूल्य वृद्धि के कारण हुई है—माग की लोच निर्धारित कीजिए ।

(ब) यह मान्यता अधिक वास्तविक क्यों नहीं है ?

2. क्या लोचदार वस्तु की दशा में किसी वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय मूल्य में वृद्धि या कमी से घटता बढ़ता है ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

3. किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से उसकी माग की लोच परिवर्तन के तुरन्त बाद की अपेक्षा दीर्घकाल में अधिक क्यों होती है ? स्पष्ट कीजिए ।

4. किन दशाओं में संकरण लोच ( Cross elasticity ) नकारात्मक, धनात्मक और बहुत अधिक ( Very high ) होती है ?

5. अगर किसी वस्तु की मूल्य लोच ( Price elasticity ) कम है तो इसकी आय की लोच ( Income elasticity ) भी कम होगी । क्यों ?

6. किसी वस्तु के मरिप्य में मूल्य गिरने की घाटणा का उस वस्तु की षालू माग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? विभिन्न प्रकार की लोचों की मान्यता के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए ।

7. एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय 1000 रुपये है, एक सप्ताह में 4 किलोग्राम घी खरीदता है । जब उसकी आय 1200 रुपये हो जाती है तो वह 5 किलोग्राम घी प्रति सप्ताह खरीदने लगता है तो आय की लोच क्या होगी ?

8. घाम का भाव 2 रुपये से बढ़कर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति अगूर का उपभोग 1 किलोग्राम से बढ़ाकर 1 50 किलोग्राम कर देता है तो बताइए संकरण लोच क्या होगी ?

# 13

## आधुनिक उपयोगिता-विश्लेषण (Modern Utility Analysis)

*"The Modern (Utility) Theory establishes a method of measuring utility under certain conditions, shows the possibility of the increasing marginal utility of money and creates a logical foundation for making certain kinds of rational decisions"*

Watson, D. S.

इस अध्याय के प्रथम भाग में हम उपयोगिता विश्लेषण सम्बन्धी कुछ समस्याओं जैसे उपभोक्ता की साम्य अवस्था अन्तर्भक्ति उपयोगिता की तुलना, आय का वितरण तथा कल्याण और उद्दंगमों पर व उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। इससे उपयोगिता की धारणा की व्यावहारिकता स्पष्ट होगी। यह सब विवरण नव प्रतिष्ठात्मक उपयोगिता विश्लेषण (Neo-classical Utility Analysis) पर आधारित है।

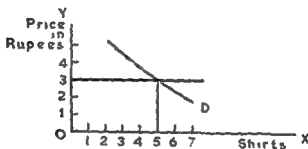
द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् 'उपयोगिता' के सम्बन्ध में कुछ नए विचार प्रकट किए गए हैं। ये विचार स्तानक वक्षा के विद्यार्थियों के लिए रुचिजनक हैं। फिर भी हमने उन विचारों का सार इस अध्याय में समझाने का प्रयत्न किया है।

### उपभोक्ता की साम्य अवस्था (Equilibrium of the Consumer)

जब उपभोक्ता किसी वस्तु की निम्न मात्राओं का उपभोग करता है तो उसे कमजोर घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी है (उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार) उनके लिए मुद्रा की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता उसकी कुल मौद्रिक आय पर निर्भर है। अतः वस्तु की इकाइयों की उपयोगिता को मुद्रा द्वारा नापा जा सकता है तथा वस्तु की एक इकाई, दो इकाइयों, तीन इकाइयों आदि के महत्व को मुद्रा के मूल्य में प्रकट किया जा सकता है। इसके आधार पर किसी वस्तु के लिए

उपभोक्ता का माग बक्र जाना जा सकता है। (इसे समझने के लिए विद्यार्थी माग वक्र तथा माग के नियम के अध्ययन के लिए भाग शीर्षक अध्याय को देखें) माग के विषय में अध्ययन करने से यह ज्ञात होगा कि माग वक्र का ढाल नीचे की ओर मुकता हुआ होता है। घटती हुई उपयोगिता माग रेखा के मुकने का प्रमुख कारण है। बाजार माग व्यक्तिगत भागों का योग होती है। यदि कीमते बढ़ती है तो कुछ उपभोक्ता वस्तु नहीं खरीदते क्योंकि ऊँची कीमतें उनकी व्यक्तिगत माग रेखा के ऊपर होती हैं। कम कीमतों पर उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। इसके दो कारण हैं 1. उपभोक्ता उपयोगिता ह्रास नियम के कारण कम कीमतों पर अधिक मात्रा खरीदता है। 2. कीमत कम होने से नये कर्ता भी खरीद करने लगते हैं जो अपनी रवि या आय के कारण ऊँची कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार

### Equilibrium of the Consumer



चित्र स० 43

नहीं थे। इस प्रकार माग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम तथा उपभोक्ताओं की रवि तथा आय के अन्तर पर आधारित है। चित्र सख्या 43 में उपभोक्ता की माग-रेखा कमीजों के लिए दिखाई गई है। कमीज की कीमत 3 रुपये हैं। 3 रुपये के बिन्दु में जो रेखा आधार रेखा के समानान्तर खींची गई है वह यह बतलाती है कि उपभोक्ता के लिए कीमत समान है चाहे वह कमीज की कितनी ही मात्रा खरीदे। उपभोक्ता पाँच कमीजें खरीदता है। यदि वह छ कमीजें खरीदेगा तो छठी कमीज की उपयोगिता उसके लिए दी गई कीमत से कम होगी अर्थात् छठी कमीज की लागत उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक होगी। अतः वह छठवी कमीज न खरीद कर किसी अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को खरीदेगा। इसके विपरीत यदि वह केवल चार कमीजें खरीदता है तो वह पाँचवी ऐसी कमीज के उपयोग के अवसर से वंचित रह जायेगा जिसकी उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है।

उपभोक्ता उस समय साम्य की अवस्था में होगा जबकि वह वस्तु की वह मात्रा खरीदेगा जिसकी सीमान्त उपयोगिता कीमत के रूप में दिये गये रुपये की

उपयोगिता के बराबर होंगे। उपभोक्ता के साम्य के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की उपयोगिता घटती रहे क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि सीमान्त उपयोगिता बढ़ रही है (ऐसा अभावधारण स्थिति में हो सकता है) तो भी उपभोक्ता कीमत के बराबर होंगे। यदि सीमान्त उपयोगिता = कीमत ( $MU = P$ ) है तथा सीमान्त उपयोगिता ( $MU$ ) बढ़ रही है तो उपभोक्ता साम्य की अवस्था में तभी पहुँचेगा क्योंकि वह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेगा।

हम यह पढ़ चुके हैं कि साम्य बिन्दु विरोधी शक्तियों का संतुलन बिन्दु होता है। यहाँ पर उपभोक्ता की शक्ति उसकी इच्छा है जो आय द्वारा सीमित होती है। दूसरी विरोधी शक्ति कीमत है जो वस्तु की उपलब्धता की दशा को प्रकट करती है। यदि कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता कम खरीदता है। यदि कीमत घटती है तो वह अधिक खरीदता है। यदि उसकी इच्छा तीव्र होती है तो वह ज्यादा खरीदता है। यदि उसकी इच्छा तीव्र नहीं होती है तो वह कम खरीदता है। यदि कीमत तथा इच्छा दोनों में परिवर्तन होता है तो नया साम्य बिन्दु इन दोनों शक्तियों को प्रकट करता है।

उपभोक्ता के साम्य का दूसरा पहलू भी है, जब वह वस्तु की साम्य मात्रा खरीदता है तो उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता या सन्तुष्टि अधिकतम होती है। 'अधिकतम' (Maximisation) वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतम सन्तुष्टि का प्रतीक है।

### अन्तर्ध्व्यक्ति उपयोगिता की तुलना

#### (Inter Personal Comparisons of Utility)

क्या एक वस्तु से दो व्यक्तियों को मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है? मान लीजिए राम तथा मोहन दोनों की आय समान है, वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तथा एक ही परिस्थितियों में रहते हैं। क्या यह कहना ठीक होगा कि 100 रुपया व्यय करने से या फुटबाल खेलने से या कोई अन्य कार्य करने से दोनों को समान आनन्द प्राप्त होगा? कोई भी व्यक्ति राम और मोहन के आनन्द की तुलना नहीं कर सकता। इस प्रकार किसी वस्तु से विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार उपयोगिताओं को जोड़ा नहीं जा सकता तथा किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिताओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता।

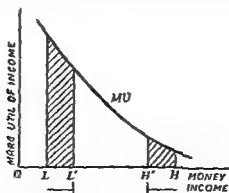
उपर्युक्त तर्क प्रकाट्य प्रतीत होता है। परन्तु इसे सही मान लेने पर हमें बहुत सी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्या के विषय में मौन रहना पड़ेगा। इन समस्याओं के सम्बन्ध में हम विचार भी नहीं कर सकते जब तक कि हम यह

मानकर न चले कि समाज के व्यक्ति लगभग एक ही प्रकार के हैं तथा उपभोग से उन्हें लगभग समान सतुष्टि मिलती है। यह सही है कि विभिन्न व्यक्तियों को किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की पूर्ण रूप से सही तुलना नहीं की जा सकती। परन्तु यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस तरह की तुलना पूर्ण रूप से सही नहीं होते हुए भी लगभग सही होगी। यह उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के शारीरिक अंग एक प्रकार के होते हैं, परन्तु फिर भी एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है।

### आय का पुनः वितरण तथा कल्याण (Redistribution of Income and welfare)

आय: सभी देशों में सरकार आयकर द्वारा आय प्राप्त करती हैं। कर की दरें आय की मात्रा के अनुसार ऊँची होती जाती हैं। इस प्रकार सरकार धनी नागरिकों से कर के रूप में आय प्राप्त कर, सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अधिक आय वाले लोगों की आय कम आय वाले (निर्धन) लोगों को हस्तांतरित की जाती है। प्रश्न है, क्या धनी-व्यक्तियों की आय को निर्धन-व्यक्तियों के पास हस्तांतरित कर देश के आर्थिक-कल्याण में वृद्धि की जा सकती है?

मान लीजिये (i) आय का हस्तान्तरण उत्पादन की प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता। यदि उपभोग से प्राप्त सतुष्टि, आर्थिक-कल्याण का प्रतीक है तो ऐसी दशा में हस्तान्तरण का आर्थिक-कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (ii) यह भी मान लीजिये कि सभी व्यक्ति उपभोग-वस्तुओं तथा सेवाओं से आनन्द प्राप्त करने की



चित्र सं० 44

समान क्षमता रखते हैं। इस मान्यता का परिणाम यह होगा कि हम प्रत्येक-व्यक्ति के लिए ही आय का एक ही ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता वक्र खींच सकते हैं। चित्र



सरया 44 में MU ऐसा ही वक्र है। OL गरीब व्यक्ति की तथा OH धनी व्यक्ति की आय है। मान लीजिए हम धनी व्यक्ति की आय HH' के बराबर कम करके, उसे गरीब व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देते हैं, इस प्रकार गरीब व्यक्ति की आय OL' तथा धनी व्यक्ति की आय OH' हो जायेगी। इस प्रकार धनी व्यक्ति की आय HH' के बराबर घट जाती है और गरीब व्यक्ति की आय LL' के बराबर बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप गरीब व्यक्ति की कुल उपयोगिता चित्र में दिखाये गये LL' के ऊपर के छायादार भाग से बढ़ जायेगी तथा धनी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता HH' के ऊपर दिखाये गये छायादार भाग से कम हो जायेगी। इसी आधार पर कुछ प्रर्थशास्त्रियों ने आय के पुनर्वितरण का समर्थन किया है।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह निष्कर्ष सही है? अधिकांश प्रर्थशास्त्रियों का उत्तर होगा 'नहीं'। अगर हम उपयोगिता की व्यक्तिगत तुलना कर सकें तो भी लोगों की रुचि आदि में विभिन्नता के कारण उनके आय-वक्रों की स्थिति अलग-अलग होगी। इस प्रकार यह विषय विवादग्रस्त है, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि धनी व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति की तुलना में भुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है, अतः धनी व्यक्तियों की आय का हस्तान्तरण यदि गरीब व्यक्तियों को किया जाए तो निश्चय ही गरीब व्यक्तियों को अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी।

**ऊर्ध्वगामी आय-कर (Progressive Income Taxation) :** ऊर्ध्वगामी आय कर भी विवादग्रस्त है। इस प्रकार के कर को उचित मानने का कारण यह है कि इसके द्वारा सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है, आर्थिक विषमता में कमी की जा सकती है तथा इसका कर भार व्यापपूर्ण होता है। प्रश्न है क्या ऊर्ध्वगामी आय-कर समानता (equity) की दृष्टि से उचित है? क्या सभी प्रकार के करों में इस प्रकार का कर अधिक व्यापपूर्ण है? इस कर की उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता में क्या सम्बन्ध है?

समानता (equity) का अर्थप्राम यह है कि व्यक्तियों पर कर उनकी कर-दान क्षमता (ability to pay) के अनुसार लगाया जाय। व्यक्ति की करदान क्षमता उसकी आय पर निर्भर है। उपयोगिता सिद्धान्त के विकास के साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह माना जाने लगा कि प्रत्येक करदाता को, आय में से कर का भुगतान करते समय समान रूप से त्याग (equal sacrifices) करना चाहिए। इसका अर्थ समान कर की राशि का भुगतान नहीं है बल्कि समान त्याग का अनिवार्य यह है कि करदाताओं को समान रूप से उपयोगिता का त्याग करना पड़े। परन्तु समान त्याग (equal sacrifice) का भी तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है

1. **समान सीमान्त त्याग (equal marginal sacrifice)** - इसका अर्थ यह है कि कर के रूप में प्रत्येक करदाता जो कर प्रदा करता है उसका अन्तिम रुपये के रूप में किया गया त्याग सबके लिए समान हो। यदि सीमान्त त्याग बराबर है तो सभी करदाताओं का सम्मिलित रूप से कुल त्याग न्यूनतम होगा। यहाँ पर सम-सीमान्त नियम (Equi Marginal Principle) का प्रयोग किया जाता है। परन्तु सीमान्त त्याग उभी समय बराबर हो सकता है जबकि कर के भुगतान के पश्चात् सभी करदाताओं की आय समान शेष बचे (यह मान लिया जाय कि सभी व्यक्तियों की आय की सीमान्त उपयोगिता समान है।)

2 **समान कुल त्याग (Equal absolute sacrifice)** - इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक करदाता द्वारा कर के रूप में जो कुल उपयोगिता का त्याग किया जाता है, वह समान है। इस प्रकार गरीब व्यक्ति उतनी ही कुल उपयोगिता का त्याग करता है जितना कि धनी व्यक्ति करता है।

3 **समान आनुपातिक त्याग (Equal proportional sacrifice)** - इसका अभिप्राय यह है कि गरीब तथा धनी व्यक्तियों को जो कुल उपयोगिता उनका आय से प्राप्त होती है वे कुल उपयोगिता का समान प्रतिशत भाग का त्याग कर। प्रश्न है : क्या समान कुल त्याग तथा समान आनुपातिक त्याग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत आय पर ऊर्ध्वगामी दर से कर लगाया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि आय की सीमान्त उपयोगिता जितनी तेजी से घटती है ? परन्तु सीमान्त उपयोगिता की घटने की गति का जानना कठिन है। अतः उपयोगिता सिद्धान्त के आधार पर इस सम्बन्ध में निश्चिन्त मत देना कठिन है।

स्वीडन के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनियल बर्नौली (Daniel Bernoulli, 1700-1782) ने यह विचार व्यक्त किया था कि एक न्यूनतम सीमा तक आय प्राप्त करने के पश्चात् आय की सीमान्त उपयोगिता आय में वृद्धि व अनुपात में घटती जाती है। (After some minimum income is attained the marginal utility of income declines by a rate equal to the relative (i.e. percentage) increase in income) चित्र मर्यादा 45 में आय की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता A रेखा की भाँति है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आय की लोक इकाई का बराबर है। मान लीजिये एक व्यक्ति की आय 10000 रुपये है तथा वह 2000 रुपये कर देता है। दूसरे व्यक्ति की आय 5000 रुपये है वह 1000 रुपये कर देता है। दोनों ही अवस्थाओं में त्याग समान है क्योंकि 10000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता, 5000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता की आधी है अर्थात्  $2000 \times \frac{1}{2} = 1000$ , यदि आय की सीमान्त उपयोगिता बर्नौली (Bernoulli) की मान्यता की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरती है तभी यह कहा जा सकता है कि ऊर्ध्वगामी दर समा-

संख्या 44 में MU ऐसा ही वक्र है। OL गरीब व्यक्ति की तथा OH धनी व्यक्ति की आय है। मान लीजिए हम धनी व्यक्ति की आय HH' के बराबर कम करके, उसे गरीब व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देते हैं, इस प्रकार गरीब व्यक्ति की आय OL' तथा धनी व्यक्ति की आय OH' हो जायेगी। इस प्रकार धनी व्यक्ति की आय HH' के बराबर घट जाती है और गरीब व्यक्ति की आय LL' के बराबर बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप गरीब व्यक्ति की कुल उपयोगिता बिना में दिखाये गये LL' के ऊपर के छायादार भाग से बढ़ जायेगी तथा धनी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता HH' के ऊपर दिखाये गये छायादार भाग से कम हो जायेगी। इसी आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने आय के पुनर्वितरण का समर्थन किया है।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह निष्कर्ष सही है? अधिकांश अर्थ-शास्त्रियों का उत्तर होगा 'नहीं'। अगर हम उपयोगिता की व्यक्तिगत तुलना कर सकें तो भी लोगों की रुचि आदि में विभिन्नता के कारण उनके आय-वक्रों की स्थिति अलग-अलग होगी। इस प्रकार यह विषय विवादग्रस्त है, परन्तु इतना प्रबल कहा जा सकता है कि धनी व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति की तुलना में मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है, अतः धनी व्यक्तियों की आय का हस्तान्तरण यदि गरीब व्यक्तियों को किया जाए तो निश्चय ही गरीब व्यक्तियों को अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी।

**ऊर्ध्वगामी आय-कर (Progressive Income Taxation) :** ऊर्ध्वगामी आय कर भी विवादग्रस्त है। इस प्रकार के कर को उचित मानने का कारण यह है कि इसके द्वारा सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है, आर्थिक विषमता में कमी की जा सकती है तथा इसका कर भार न्यायपूर्ण होता है। प्रश्न है क्या ऊर्ध्वगामी आय-कर समानता (equity) की दृष्टि से उचित है? क्या सभी प्रकार के करों में इस प्रकार का कर अधिक न्यायपूर्ण है? इस कर की उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता से क्या सम्बन्ध है?

समानता (equity) का अभिप्राय यह है कि व्यक्तियों पर कर उनकी कर-दान क्षमता (ability to pay) के अनुसार तय किया जाय। व्यक्ति की करदान क्षमता उसकी आय पर निर्भर है। उपयोगिता सिद्धान्त के विकास के साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह माना जाने लगा कि प्रत्येक करदाता को, आय में से कर का भुगतान करते समय समान रूप से त्याग (equal sacrifices) करना चाहिए। इसका अर्थ समान कर की राशि का भुगतान नहीं है बल्कि समान त्याग का अभिप्राय यह है कि करदाताओं को समान रूप से उपयोगिता का त्याग करना पड़े। परन्तु समान त्याग (equal sacrifice) का भी तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है

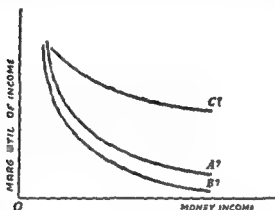
1. समान सीमान्त त्याग (equal marginal sacrifice) : इसका अर्थ यह है कि कर के रूप में प्रत्येक करदाता जा कर अदा करता है उसके अन्तिम रुपये के रूप में दिया गया त्याग सबके लिए समान हो। यदि सीमान्त त्याग बराबर है तो सभी करदाताओं का सम्मिलित रूप से कुल त्याग न्यूनतम होगा। यहाँ पर सम-सीमान्त नियम (Equi-Marginal Principle) का प्रयोग किया जाता है। परन्तु सीमान्त त्याग उसी समय बराबर हो सकता है जबकि कर के भुगतान के पश्चात् सभी करदाताओं की आय समान शेष बचे (यह मान लिया जाय कि सभी व्यक्तियों की आय की सीमान्त उपयोगिता समान है।)

2. समान कुल त्याग (Equal absolute sacrifice) : इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक करदाता द्वारा कर के रूप में जो कुल उपयोगिता का त्याग किया जाता है, वह समान है। इस प्रकार गरीब व्यक्ति उतनी ही कुल उपयोगिता का त्याग करता है जितना कि धनी व्यक्ति करता है।

3. समान आनुपातिक त्याग (Equal proportional sacrifice) : इसका अभिप्राय यह है कि गरीब तथा धनी व्यक्तियों को जो कुल उपयोगिता उनकी आय से प्राप्त होती है वे कुल उपयोगिता का समान प्रतिशत भाग का त्याग कर। प्रश्न है : क्या समान कुल त्याग तथा समान आनुपातिक त्याग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत आय पर ऊर्ध्वगामी दर से कर लगाया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि आय की सीमान्त उपयोगिता कितनी तेजी से घटती है ? परन्तु सीमान्त उपयोगिता की घटने की गति का ज्ञानना कठिन है। अतः उपयोगिता सिद्धान्त के आधार पर इस सम्बन्ध में निश्चित मत देना कठिन है।

स्वीडन के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनियल बर्नौली (Daniel Bernoulli, 1700-1782) ने यह विचार व्यक्त किया था कि एक न्यूनतम सीमा तक आय प्राप्त करने के पश्चात् आय की सीमान्त उपयोगिता आय में वृद्धि के अनुपात में घटती जाती है। (After some minimum income is attained the marginal utility of income declines by a rate equal to the relative (i. e. percentage) increase in income) चित्र संख्या 45 में आय की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता A रेखा की भाँति है जिसके प्रत्येक बिन्दु पर माँग की सोच इकाई के बराबर है। मान लीजिये एक व्यक्ति की आय 10000 रुपये है तथा वह 2000 रुपया कर देता है। दूसरे व्यक्ति की आय 5000 रुपये है वह 1000 रुपये कर देता है। दोनों ही अवस्थाओं में त्याग समान है क्योंकि 10000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता, 5000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता की आधी है अर्थात्  $2000 \times \frac{1}{2} = 1000$ , यदि आय की सीमान्त उपयोगिता बर्नौली (Bernoulli) की मान्यता की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरती है तभी यह कहा जा सकता है कि ऊर्ध्वगामी कर समा-

मता की दृष्टि से उचित है। इसके लिए चित्र में दी हुई रेखा II की भांति होनी चाहिए। तेज गति से गिरने से, 10000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता 5000 रुपये की सीमान्त उपयोगिता से कम होगी। अतः ऐसी दशा में कर की मात्रा 2000 रुपये से अधिक होने पर ही, 5000 रुपये पर दिये जाने वाले 1000 रुपये के त्याग के



चित्र सं० 45

समान होगी। यदि सीमान्त उपयोगिता उस प्रकार घटती है जैसा कि  $C_1$  रेखा से प्रकट है तो ऐसी दशा में समानता के सिद्धान्त के आधार पर व्यक्तिगत आय पर ऊर्ध्वगामी कर (Progressive Tax) नहीं लगेगा बल्कि अतिगामी कर (Regressive Tax) लगाता उचित होगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऊर्ध्वगामी आयकर समान त्याग के सिद्धान्त की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

### आधुनिक उपयोगिता सिद्धान्त (Modern Utility Theory)

पिछले अध्यायों में हमने उपयोगिता के विभिन्न पहलुओं तथा उससे सम्बन्धित नियमों पर प्रकाश डाला। उपयोगिता की धारणा (concept) एक विवादग्रस्त विषय रहा है तथा समय-समय पर, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर प्रकाश डाला है। इस धारणा की विकासक्रम के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है—

- (i) मार्शल का सीमांत उपयोगिता सिद्धान्त (The Marshallian Marginal-utility Theory)
- (ii) हिक्स का उदासीनता वक्र सिद्धान्त (Hicksian Indifference-curve Theory)
- (iii) सैमुएलसन का प्रकट अधिमान सिद्धान्त (Samuelson's Revealed Preference Theory)

- (iv) न्यूमैन-मॉर्गेन्सटर्न का सांख्यिकीय उपयोगिता सिद्धान्त (Neumann-Morgenstern Statistical utility Theory)  
 (v) आर्मस्ट्रांग का सीमान्त अधिमान सिद्धान्त (Armstrong's Marginal Preference Theory)

उपर्युक्त में से हम प्रथम दो का अध्ययन कर चुके हैं। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण दो मान्यताओं पर आधारित है : (i) उपयोगिता को नापा जा सकता है तथा इसकी नाप का गणनावाचक संस्थाओं 1, 2, 3 आदि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है (ii) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अपरिवर्तित (Constant) रहती है। उदासीनता वक्र विश्लेषण इन सन्देहपूर्ण मान्यताओं को परित्याग कर, नये ढंग से उपयोगिता का विश्लेषण करता है। अब हम उपयोगिता विश्लेषण के क्षेत्र में आधुनिक मतों पर विचार करेंगे।

आधुनिक उपयोगिता सिद्धान्त का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हुआ परन्तु आधुनिक उपयोगिता सिद्धान्त को (Bernoullian utility Theory) कहते हैं क्योंकि इसका प्रारम्भ स्वित्जरलैंड के गणितज्ञ डेनियल बर्नौली (Daniel Bernoulli)-1700-1782) ने किया था। आधुनिक उपयोगिता सिद्धान्त की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं— (i) आधुनिक उपयोगिता का सिद्धान्त कुछ परिस्थितियों में उपयोगिता की नाप की विधि पर प्रकाश डालता है (ii) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता के बढ़ने की सम्भावना को दिखलाता है तथा (iii) कुछ प्रकार के विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए नार्मिक आधार प्रस्तुत करता है।

सेंट पीटर्स बर्ग पैराडॉक्स (St. Petersburg Paradox) बर्नौली के नाम से एक समस्या आई जिसे उपर्युक्त नाम दिया गया है। समस्या यह थी कि मनुष्य किसी जुआ या मट्टे में  $\frac{1}{2}$  सम्भावना पर ही क्यों जोर देता है जबकि कुछ अवसरों में उसके जीतने की सम्भावना  $\frac{1}{2}$  से अधिक होती है? बर्नौली ने इस सम्बन्ध से जो कुछ कहा उसका अनिवाच्य यह था कि भौतिक प्राय में वृद्धि के साथ ही साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं तथा वह किसी शर्त (Bet) पर 100 रुपये हारने या जीतने की बाजी लगाता है तो इसे हम विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कह सकते क्योंकि यदि वह जीतता है तो उसके पास 1100 रु० हो जायेंगे। अर्थात् उसकी उपयोगिता 100 से बढ़ जायेगी। यदि वह हारता है तो उसके पास 900 रुपये रह जायेंगे अर्थात् 100 रुपये के बराबर उपयोगिता की हानि उठानी पड़ेगी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का यह अर्थ है कि हानि की अपेक्षा लाभ की उपयोगिता कम होती है। (Diminishing marginal utility means that the gain of utility is smaller than the loss even through the amounts of money are equal) इस तथ्य का स्पष्टीकरण चित्र सख्या 46 में किया गया है।

उपयोगिता माप की सम्भावनाओं की शुरुआत कर न्यूमैन मार्ग-सटर्न ने पुराने सत्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण के सिद्धांत को बल प्रदान किया है।

### (v) आर्मस्ट्रांग का सोमान्त अधिमान सिद्धान्त (Armstrong Marginal Preference Theory)

W B Armstrong विचार की दृष्टि से माशल की ही भांति सत्यावाचक उपयोगितावादी हैं। उन्होंने मर्यादावाद (cardinalism) को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उनका सिद्धांत दो अन्तर्निम्न विचारों पर आधारित है। ये विचार हैं, (i) अनिश्चिता (uncertainty) तथा (ii) उदासीनता (Indifference)। हम पहले देख चुके हैं कि न्यूमैन मार्ग-सटर्न का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है— (i) उपभोक्ता अपने चुनाव का उद्देश्य 'निश्चित आशा (Sure Prospects) नहीं मानता। उद्देश्य की प्रवृत्ति निश्चित होती है परन्तु उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाए इसके विषय में उपभोक्ता निश्चित नहीं होता (ii) दूसरी मान्यता यह है कि उपभोक्ता दो स्पष्ट उद्देश्यों के बीच साफ तरीके से भेद (Discrimination) नहीं कर पाता।

हिक्स की भांति आर्मस्ट्रांग ने भी उदासीनता वक्रों की ही सहायता ली है जो न्यून मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता दो अवस्थाओं में भेद करने में सफल नहीं होता। परन्तु हिक्स के विपरीत आर्मस्ट्रांग की उदासीनता या अधिमान (Preference) एक से दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता, जैसे उपभोक्ता X और Y या Z के बीच भेद नहीं कर सकता, यद्यपि X और Z का अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार आर्मस्ट्रांग ने 'अनिश्चिता' तथा 'उदासीनता' के सम्बन्ध में अपनी परिभाषाएँ दी हैं। उनके अनुसार उदासीनता का उदय कई प्रकार से हो सकता है—(i) क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त द्वारा अर्थात् एक दिशा में हुई हानि की पूर्ति दूसरी दिशा में हुए लाभ द्वारा की जा सकती है। (Principles of Compensation) या (ii) निकटतम सम्बन्धी विचार (idea of approximation) अर्थात् उपभोक्ता के सामने दो अवस्थाएँ समान होती हैं परन्तु वह उनमें भेद करने में समर्थ नहीं होता है अतः उनके सम्बन्ध में उदासीन या तटस्थ रहता है। आर्मस्ट्रांग का उदासीनता का विचार निकटतमता (approximation) पर आधारित है जबकि हिक्स का विचार क्षतिपूर्ति सिद्धांत पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि (i) किसी वस्तु के पक्ष तथा विपक्ष का परिणाम है तथा (ii) का उदय दो वस्तुओं में उपभोक्ता द्वारा अन्तर न देख सकने का परिणाम है। हिक्स का विचार प्रतिस्थापन पर आधारित है जबकि आर्मस्ट्रांग का विचार अधिमान पर आधारित है।

आर्मस्ट्रांग ने अधिमान गहनता (Preference intensity) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह गहनता उच्चतम व निम्नतम हो सकती है। आर्मस्ट्रांग के

अनुसार अधिमान सीमान्त उम समय होता है जबकि उपभोक्ता इसका पता लगाने में समर्थ हो। ऐसा उस समय होता है जबकि उपभोक्ता स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि वह दो वस्तुओं में से किसका प्राथमिकता देगा ? यह भी सम्भव है कि उपभोक्ता स्पष्ट रूप से इन निर्णय पर न पहुँच सके। इस दशा में वह उदामीनता की स्थिति में होगा। इस प्रकार आर्मस्ट्रान्ग के सिद्धांत में उदामीनता दो स्थितियों में निश्चित-तम समानता में पैदा होती है। उदामीनता का यह सम्बन्ध दो अन्य बिन्दुओं के बीच लागू नहीं होगा।

### फ्रिडमैन-सैवेज की परिकल्पना

(The Friedman — Savage Hypothesis)

क्या मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता हमेशा घटती है ? यदि घटती है तो व्यक्ति जुआ क्यों खेलता है ? इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति अधिक खतरा (Risk) लेने के लिए क्यों तैयार होते हैं ? यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जुआ आनन्द के लिए खेलता है। परन्तु यह उत्तर तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। अधिक खतरा लेने की प्रवृत्ति को ही अविवेकपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। जुआ खेलने में तब तक खतरा लेने में व्यक्ति बड़ी सावधानी तथा समझ-बूझ से काम लेता है ? यदि कोई व्यक्ति बीमा की माधारण पालिसी लता है तो ऐसा मान्य होता है कि उसके लिए आय की सीमान्त उपयोगिता घटती है। त्रिमियम का भुगतान करने के लिए मुद्रा अथवा उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग या हानि निश्चित होती है परन्तु उम सम्भावित हानि की तुलना में कम होती है जो बीमा न कराने पर तथा किसी घटना के घटित होने पर होती है। मिल्टन फ्रिडमैन (Milton Friedman) और एल जे सैवेज (L. J. Savage) ने एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जुआ के साथ ही साथ बीमा पॉलिसी लन जैसे विरोधी कार्यों को करने की प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि एक ही व्यक्ति कभी खतरा उठाता है तथा कभी नहीं उठाता है। एक ही मनुष्य के कार्यों में ऐसा विरोधाभास क्यों पाया जाता है ? Friedman तथा Savage ने यह विचार व्यक्त किया है कि अधिकांश व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि उनकी आय एक स्तर में नीचे है तो आय की सीमान्त उपयोगिता घटती है। उम स्तर तथा उममें कुछ ऊँचे स्तर के बीच आय की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती है और जब आय उस ऊँचे स्तर में अधिक होती है तो आय की सीमान्त उपयोगिता घटती है।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Friedman — Savage hypothesis is that for most people, the marginal utility of income diminishes when incomes are below some level, increases for incomes between level and some higher level, and diminishes again when incomes are above the high level.

[Watson, D.S. Op. cit. p 7]



चुनाव करता है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि वह 'क' को दृढ़ रुम प्रदान करता है। अगर वह 'ग' की अपेक्षा 'ख' का चुनाव करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह 'ख' को दृढ़ रुम प्रदान करता है। लेकिन 'क' संयोग (जिसमें कि 'ख' का कमी चुनाव नहीं किया जाता है) और 'ग' संयोग (जिसमें कि 'ख' का कमी परित्याग नहीं किया जाता) के बीच बहुत सी मध्य दशाएँ हो सकती हैं जिनमें 'ख' को स्वीकार किया जा सकता है और इसका परित्याग भी किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी दशाओं में हम उपरोक्त के चुनाव के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं दे सकते और कह सकते हैं कि उपरोक्त उदासीनता की दशा में है।

न्यूमैन मार्गेंसटर्न का सिद्धांत इस उदासीनता की स्थिति को स्वीकार करता है लेकिन एक ही घटना त्रम की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार यह कमजोर तथा नम्रताएँ अधिमानों की कसरना है। यह मुख्यतया दो मान्यताओं पर आधारित है—(1) कि उपरोक्त दो वस्तुओं में से किसी एक का चुनाव अधिक स्पष्ट आधार पर नहीं कर सकता और इन कारणों से वह चुनाव कमी-कमी अनुपयुक्त भी सिद्ध होना है (2) उपरोक्त अपने चुनाव की दोनों वस्तुओं को निश्चित सम्भावना (Sure Prospects) नहीं मानता और इसलिए इस चुनाव की प्रक्रिया में हमेशा जोखिम की उपस्थिति कमजोर रुम के विचार को स्पष्ट करती है।

न्यूमैन मार्गेंसटर्न विधि को निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) एक व्यक्ति से यह कहा जाता है कि वह शर्त लगाये। इस शर्त में उसे जीतने या हारने के लिये 50-50 अवसर है। वह इस शर्त से इन्कार कर जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि एक घड़े में 100 गैदे हैं जिनमें से 55 सफेद तथा 45 काली है। यदि वह सफेद गैद चुनता है तो वह जीत जायेगा। वह इस शर्त से भी इन्कार करता है। इसके पश्चात् उससे कहा जाता है कि उसके जीतने की सम्भावना 60-40 है। वह किसी प्रकार इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। प्रश्न है कि यह सूचना व्यक्ति के लिए मुदा सम्बन्धी उपयोगिता के ज्ञान को किस प्रकार प्रकट करती है? मान लीजिए हारने पर 100 रुपये की उपयोगिता 15 इकाइयों के बराबर है, उसके हारने की सम्भावना 40% है। इस प्रकार उसकी कुल उपयोगिता की हानि की सम्भावना  $0.4 \times 15 = 6.0$  इकाइया है। चूँकि वह जीतने की 60-40 की सम्भावना को स्वीकार करने को तैयार है अतः उसके लिए सम्भावित लाभ की उपयोगिता भी 6 इकाई होगी। इसका अर्थ यह है कि दूसरे 100 रुपये की उपयोगिता उसके लिए 10 होगी क्योंकि  $0.6 \times 10 = 6$  (यह स्थिति जीतने की 60-40 की सम्भावना पर आधारित है। इसे अग्रलिखित ढंग से भी प्रकट किया जा सकता है :

उपयोगिता से सम्भावित प्राप्ति = उपयोगिता से सम्भावित हानि

प्राप्ति की सम्भावना  $\times$  प्राप्त होने वाली उपयोगिता = हानि की सम्भावना

$0.6 \times$  प्राप्त उपयोगिता =  $0.4 \times 15$  अतः प्राप्त उपयोगिता (लाभ) =

$$\frac{6}{0.6} = 10$$

इसका परिणाम यह है कि 60-40 की सम्भावना पर यदि 100 रुपये की उपयोगिता को 1000 रुपये में जोड़ दिया जाए तो उपयोगिता का लाभ 1000 रु० में से 100 रुपये की उपयोगिता घटाने की हानि की अपेक्षा कम है। यदि वही व्यक्ति शर्त जीत जाता है तथा उन्हीं शर्तों पर दूसरी शर्त में भी बाजी लगाता है तो 100 रुपये की उपयोगिता को यदि 1100 रुपये में जोड़ दिया जाए तो उपर्युक्त तर्क के अनुसार उसकी उपयोगिता 6 $\frac{2}{3}$  से बढ़ जायेगी। अतः 900 रु० से प्रारम्भ कर यदि हम 100 रु० से वृद्धि करते जाएं तथा 900 रु० के पश्चात् प्रथम 100 रु० की उपयोगिता 15 मान लें, तो 60-40 की सम्भावना पर उस व्यक्ति की सीमान्त उपयोगिता का निर्देशांक 15, 10, 6 $\frac{2}{3}$  उपयोगिताएं आदि होंगे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उपयोगिता सम्बन्धी ये सरायाएँ पूर्णतया काल्पनिक हैं। हम कोई भी सख्या रख सकते हैं। यदि हम इन्हे चित्र पर अंकित करें तो बिजु सेन्ट पीटरस बर्ज (St. Petersburg Paradox) शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हैं, उन्हीं के समान होगा (देखिए चित्र सरया 46) चित्र में दिखा गया वक्र ऊँचा या नीचा हो सकता है। वक्र का प्रारम्भ बिन्दु ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है। इन सीमाओं के होते हुए भी न्यूमैन मार्गे-सटर्न (Neumann Morgenstern) विधि द्वारा उपयोगिता मापन के लिए सख्याओं के समूह पर प्रकाश अवश्य पड़ता है।

2 यदि हम मानले कि एक दूसरा व्यक्ति 50-50 की सम्भावना पर शर्त लगाता है तो उसकी शर्त पर यह माना जा सकता है कि उसकी उपयोगिता सम्बन्धी हानि उपयोगिता सम्बन्धी लाभ के बराबर होगा। 900-100 की सीमा में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान (Constant) रहेगी।

3 यदि एक तीसरा व्यक्ति चतुरा बने के लिए अधिक तैयार है तथा हानि की सम्भावना अधिक होने पर भी वह शर्त लगाने के लिए तैयार रहता है तो उसके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढती हुई होगी।

इस प्रकार न्यूमैन मार्गे-सटर्न विधि सख्यात्मक उपयोगिता के आधार प्रदान करती है जो या तो सैद्धांतिक या वास्तविक प्रयोगजनित हो सकते हैं। न्यूमैन मार्गे-सटर्न विधि पुरानी क्लासिकल सख्यात्मक विश्लेषण के समान नहीं है। यह विधि वस्तुओं व सेवाओं के प्रति भावना की दृढ़ता का माप नहीं करती। यह केवल जोखिम की उपस्थिति में व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। लेकिन

OX मुद्रा की मात्राओं को 100 में व्यक्त करती है। 9-10 तथा 10-11 के बीच की दूरी समान है। MU रेखा परती सीमान्त उपयोगिता को प्रकट करती है। जीतने पर उपयोगिता पर वृद्धि 10-11 के बीच का छायांकित क्षेत्र जीतने पर उपयोगिता में हुई वृद्धि को प्रकट करता है। इसके विपरीत 8-10 के



चित्र नं० 46

बीच का क्षेत्र हारने पर हानि को प्रकट करता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि उपयोगिता की हानि उसकी वृद्धि की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है। इसमें जुए से प्राप्त होने वाले आनन्द को ध्यान में नहीं रखा गया है। मागल ने कहा कि जुए से प्राप्त आनन्द व्यक्ति को जीवन के अन्य ऊँचे आनन्दों से वंचित करता है। व्यक्ति अन्य कार्यों में जुए की अपेक्षा अधिक आनन्द प्राप्त कर सकता है।

### (iii) सेम्युएलसन का प्रकट अधिमान सिद्धांत (Samuelson's Revealed Preference Theory)

इस सिद्धांत का 'Behaviourist ordinal utility Theory' भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता दृढ़ क्रम बोध (Strong ordering) है। इनके अनुसार दो प्रकार के क्रम निवारित किये जा सकते हैं—दृढ़ तथा कमजोर। दृढ़ क्रम में उपभोक्ता की श्रेय योजना में प्राथम्य मंद का एक निश्चित स्थान होता है या संख्या होती है। प्राथम्य मंदों के सामने एक मंद होती है। इस प्रकार उपभोक्ता अपने अधिमानों को निश्चित रूप से प्रकट करता है। कमजोर क्रम में कुछ मंद ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अधिमानों ने अनुसार क्रम से प्रकट नहीं किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उपभोक्ता का इस विषय में किस मंद के लिए क्या अधिमान है। कमजोर क्रम के अनुसार क्रम की मंदों को वर्गों में बांटा जाता है। वर्गों (groups) के क्रम दृढ़ हो सकते हैं जिनके द्वारा अधिमानों का निश्चित क्रम मातृय होता है। परन्तु समूह के अन्दर क्रम कमजोर होता है। दृढ़

क्रम के अन्तर्गत उपभोक्ता अधिमानों को प्रकट करता है तथा उसके द्वारा उसके चुनाव का ज्ञान होता है।

परम्परागत उदामीन वक्र कमजोर क्रम का उदाहरण है क्योंकि उसी उदामीन वक्र पर सभी संयोगों को समान अधिमान दिया जाता है। संयुगलसन का मिद्धान्त दृढ़ क्रम की मान्यता पर आधारित है। उदामीन वक्र विधि की यह मान्यता कि उपभोक्ता एक उदामीन वक्र पर सभी सम्भव विकल्पों का क्रम प्रदान करने में समर्थ है, अध्यात्मविक है।

इसीलिए संयुगलसन ने कमजोर क्रम की सम्भावना का परित्याग किया। वे उदामीन वक्र विधि को क्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार नहीं मानते। उनके अनुसार उपभोक्ता चुनाव प्रक्रिया में अपने अधिमानों को स्पष्ट करता है। प्रदर्शित अधिमान, निरीक्षित चुनाव व्यवहार तथा उसके कल्याण परिणामों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इस प्रकार उदामीन वक्र विधि को क्रियात्मक आधारों (operational grounds) पर अस्वीकार किया गया। लेकिन उपभोक्ता व्यवहार समान रहना चाहिए। जैसे यदि उपभोक्ता किसी समय चाय का अपेक्षा काफी को अधिक अधिमान देता है तो दूसरे समय वह काफी की अपेक्षा चाय का चुनाव नहीं कर सता। हिक्स ने इसे 'two term consistency' कहा है और यही संयुगलसन के सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण मान्यता है।

संयुगलसन का सिद्धान्त मार्शल के सिद्धान्त की तरह ही सामान्य सिद्धान्त है और उन मान्यताओं का परित्याग करता है जिनकी प्रत्यक्ष जांच सम्भव नहीं है। हिक्स के सिद्धान्त के विपरीत यह सिक्के विरोधाभास को स्पष्ट नहीं करता। आप की लोच शून्य या नकारात्मक होने पर संयुगलसन का मिद्धान्त मांग विश्लेषण करने में असमर्थ है। हम संयुगलसन के प्रकट अधिमान सिद्धान्त की अपेक्षा हिक्स का मिद्धान्त नियात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

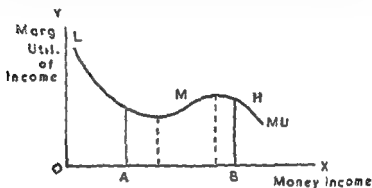
#### (iv) न्यूमैन मार्गेन्सटर्न का सांख्यिकीय उपयोगिता मिद्धान्त

(Neumann Morgenstern Statistical Utility Theory)

आधुनिक उपयोगिता विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 'उपयोगिता माप' विधि की प्राप्ति है। यह माप सैद्धांतिक होती है, न कि व्यावहारिक। आधुनिक सिद्धान्त में माप उन सम्भावित उपयोगिताओं, जिनमें जोखिम का तत्व भी होता है, तक ही सीमित है जो कि किसी निश्चित चुनाव संयोग को तय करती है। यह सांख्यिकीय सिद्धान्त है क्योंकि यह विभिन्न निरीक्षणों पर आधारित है न कि चुनाव के एक कार्य पर, जैसा कि हिक्स व संयुगलसन ने माना है।

सांख्यिकीय आधार पर हमारे दृढ़ व कमजोर दोनों ही क्रम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 'ध' की अपेक्षा 'र' संयोग का ही हमेशा

चित्र सख्या 47 द्वारा फिडमैन संवेज के विचारों का स्पष्टीकरण होता है। चित्र से स्पष्ट है कि आय की सीमान्त उपयोगिता वक्र (MU) के तीन भाग हैं— यह रेखा पहले घटती है, फिर बढ़ती है और फिर घटती है। इन तीनों स्थितियों को टूटी



चित्र सं० 47

हुई रेखाओं (Dashed line) द्वारा प्रकट किया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय OA है जो आय की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता वाले भाग में है। वह व्यक्ति बीमा पॉलिसी खरीदेगा क्योंकि प्रिमियम के रूप में सम्भावित हानि की तुलना में उसे बहुत कम व्यय करना पड़ेगा। यद्यपि बीमा की अनुपस्थिति में भी उसके लिए हानि की सम्भावना कम है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बीमा की अनुपस्थिति में भी हो सक्ता है उसे हानि बहुत अधिक उठानी पड़े। वही व्यक्ति जुआ भी खेल सकता है या साटरी टिकट भी खरीद सकता है क्योंकि जुआ खेलने या साटरी टिकट खरीदने में भुगतान कम करना पड़ता है जीतने की भी सम्भावना कम होती है। जुआ की सम्भावित उपयोगिता नकारात्मक होगी यदि M बिन्दु के पश्चात् सम्भावित लाभ की सीमान्त उपयोगिता अधिक नहीं होगी जैसा कि M बिन्दु के भाग ऊँची उठनी हुई MU रेखा द्वारा प्रकट है। यदि किसी व्यक्ति की आय OB है, जो अधिक आय को प्रकट करती है, तो वह सतरा कम मोल लेगा या जुआ खेलेगी की इच्छा नहीं रखेगा या सतरापूर्ण विनियोग नहीं करेगा, जब तक कि जीतने या साम की सम्भावना बहुत अधिक नहीं है। फिडमैन-संवेज ने यह कहा है कि चित्र में दिया हुआ वक्र विभिन्न आय समूहों के व्यक्तियों की मनोवृत्ति को प्रकट करता है। मध्यम वर्गीय लोग बिनकी मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती हुई होती है वे सतरा लेने के लिए अधिक तैयार रहते हैं क्योंकि वे अपने आर्थिक स्तर में वृद्धि करना चाहते हैं।

उपसंहार : उपयोगिता सम्बन्धी पिछले कई अध्यायों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपयोगिता धारणा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के विचारों में परिवर्तन होते

रहे हैं। नव-प्रतिष्ठावादी उपयोगिता सिद्धांत (Neo-classical theory of utility) या मार्शल तथा उसके अनुयायियों के विचारों का सारांश निम्नलिखित सार से स्पष्ट किया जा सकता है—(i) उपभोक्ता कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है (ii) उपभोग के साथ ही साथ अगली इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है (iii) उपभोक्ता की यह आदत होती है कि वह खतरा-हीन विकल्पों (Riskless alternatives) के बीच चुनाव करना है। नव-प्रतिष्ठावादी उपयोगिता सिद्धान्त उपभोक्ता के व्यवहार का स्पष्टीकरण करता है। उपभोक्ता की आय दी हुई होती है। वह विभिन्न वस्तुओं की कीमते जानता है। उसकी रुचि दी हुई होती है। इन सभी बातों की जानकारी रखते हुए वह चुनाव करता है तथा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। (iv) उपभोक्ता की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता घटती है अतः यह दूरदर्शी उपभोक्ता न तो जुमा खेल सकता है और न लाटरी टिकट खरीद सकता है।

आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत (i) कुछ परिस्थितियों में उपयोगिता की मांग की विधि बतलाता है (ii) मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की वृद्धि की सम्भावना भी बतलाता है (iii) कुछ विवेकपूर्ण चुनावों के लिए तार्किक आधार प्रस्तुत करता है (iv) खतरे की उपस्थिति में चुनाव की समस्या (choices subject to risk) पर प्रकाश डालता है (v) खतरे की उपस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए सम्भावित उपयोगिता (Expected utility) पर जोर देता है, सम्भावित मौद्रिक मूल्य पर नहीं।

उपयुक्त विकास के होते हुए भी उपयोगिता सम्बन्धी विचार दोषपूर्ण हैं ?

### उपयोगिता धारण की आलोचना

उपयोगिता की माप के सम्बन्ध में मार्शल तथा उनके अनुयायियों द्वारा जो धाराएँ प्रस्तुत की गई हैं, उनकी आलोचना निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की गई है।

(1) उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। एक भौतिक वस्तु को मापा जा सकता है। परन्तु एक काल्पनिक तथा अमौलिक वस्तु की माप किस प्रकार की जा सकती है।

(2) इसमें निश्चितता का अभाव है। कभी 'उपयोगिता' शब्द किसी वस्तु की 'इच्छा शक्ति' (desireness) को तो कभी 'सन्तुष्टि' (satisfaction) को व्यक्त करता है। अधिकतर पूर्ण उपयोगिता और पूर्ण सन्तुष्टि का एक ही अर्थ लगाते हैं, परन्तु वास्तव में उपयोगिता और सन्तुष्टि एक दूसरे में भिन्न हैं। किसी वस्तु के लिए दिया गया मूल्य उसकी इच्छा की तीव्रता को व्यक्त कर सकता है, परन्तु वह उस वस्तु से प्राप्त सन्तुष्टि का मापदण्ड नहीं माना जा सकता।

(3) उपयोगिता समान (constant) नहीं रहती । वह समय-समय पर बदलती रहती है । इन प्रकार की परिवर्तनशील वस्तु को मापना संभव नहीं हो सकता । परन्तु इस सम्बन्ध में दिया गया तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय किसी वस्तु की उपयोगिता को मापा जा रहा है, उस समय वह समान है । अतः उसकी मात्र उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार ताप, ऊँचाई और लंबाई की माप संभव है ।

(4) उपयोगिता की माप का कोई प्रमाण (standard) नहीं है, भौतिक वस्तुओं को किसी प्रमाणित मापदंड (जैसे अणु या तुला) से नापा तथा तोला जा सकता है । परन्तु उपयोगिता का कोई ऐसा मापदंड नहीं है, सर्वश्रेष्ठ में सन्तुष्टि का अनुमान त्याग की गई मुद्रा के आधार पर लगाया जा सकता है । अतः सन्तुष्टि को आधार मानकर उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है । इसमें यह मापना होगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक स्वामी शायद बाले व्यक्ति को मुद्रा की प्रत्येक अणु की इकाई की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, क्योंकि जैसे-जैसे वह धन की रकम को व्यय करता जाता है, उपलब्ध धन की मात्रा कम होने से शेष मुद्रा का मूल्य उसके लिए अधिक होता है ।

समकाल: Pareto सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता को अमापनीय (immeasurable) माना था । उनके विचार थे कि उपयोगिता मापनीय तो नहीं है, किन्तु तुलना योग्य है । बाद प्रो० हिक्टर तवा एलेन ने Pareto की मान्यता को स्वीकार करके वस्तुदली के आधार पर अर्थ-सिद्धान्त (Theory of Value) का निर्माण किया । उनके विचार में उपयोगिता अथवा सीमांत उपयोगिता अमापनीय है । अतः अर्थ-सिद्धान्त उपयोगिता के आधार पर निर्मित नहीं किया जा सकता । परन्तु उसकी प्रतिस्थापन की दर (rate of substitution) के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है । उसके अनुसार सीमांत उपयोगिता का चाहे कोई प्रपं न हो, किन्तु प्रतिस्थापन की सीमांत दर (marginal rate of substitution) का अवश्य कुछ प्रपं एक महत्व है ।

### प्रश्न व संकेत

1. आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत के मूलतत्त्व क्या हैं ?  
(संकेत : देखिए पृष्ठ 280-282)
2. न्यूमैन मार्गेंसटर्न उपयोगिता मापन विधि पर प्रकाश डालिए ।  
(संकेत : देखिए पृष्ठ 283-286)

3. मुद्रा की उपयोगिता के सम्बन्ध में फ्रिडमैन—सैम्युज के विचारों को स्पष्ट कीजिए । (संकेत : देखिए पृष्ठ 287-288)
4. क्या आय का पुनर्वितरण कल्याण में वृद्धि करता है ?  
(संकेत : देखिए पृष्ठ 277-280)

### समस्याएँ (Problems)

1. चित्र सरणी 47 में वक्र के तीन भाग हैं, प्रत्येक भाग तीन सामाजिक व आर्थिक (Socio-economic) वर्गों को प्रदर्शित करता है । पाच भागों सहित एक वक्र बनाइए और उसकी सामाजिक व आर्थिक विवेचना कीजिए ।
2. मान लीजिए एक सफल व्यापारी राजनीति में प्रवेश करने की सोच रहा है । वह जानता है कि राजनैतिक जीवन में उसे अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी । उसके लिए मुद्रा की सीमान्त-उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए ।



## उत्पादन तथा उसके साधन

(Production and its Factors)

*"Practically, man does nothing but pull, press, carry or otherwise mechanically force things into new forms or new places. All these activities result in the production of wealth"*

—Penson

उत्पादन आर्थिक प्रगति का प्रतीक है । किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के बढन की दर पर निर्भर है । मनुष्य की आर्थिक समस्याओं का केन्द्र-बिन्दु उत्पादन ही है । उत्पादन की मात्रा तथा उसका क्षेत्र मानव समाज के आर्थिक भाग्य के निर्णायक हैं । उत्पादन की मात्रा तथा प्रकृति, उत्पादन के मूल साधनों की पूर्ति द्वारा शासित होती है । विभिन्न प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना कुशल धर्म का होना, प्रचुर मात्रा में पूँजी की प्राप्ति, लोगों में प्रबन्ध व संगठन-योग्यता तथा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और उन्नत व वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की मात्रा एवं प्रकृति के निर्धारक तत्व हैं ।

### 1. उत्पादन का अर्थ ( Meaning of Production ) ✓

किसी वस्तु का निर्माण ही उत्पादन नहीं है । एडम स्मिथ तथा प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह मत कि उत्पादन का अर्थ भौतिक साधनों का निर्माण करना है, सङ्कुचित है । पदार्थ ( Matter ) प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं । मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना में उनकी पूर्ति भी सीमित होती है । मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों ( matters ) की उपयोगिता में विभिन्न प्रकार से वृद्धि ही कर सकता है, वह स्वयं किसी नए पदार्थ का सृजन या निर्माण नहीं कर सकता । अतः के अनुसार, 'मनुष्य भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता । मानसिक तथा नैतिक क्षेत्र में वह नये नये विचारों की जन्म ले ही दे सकता है, परन्तु जब भौतिक वस्तुओं का निर्माण की बात आती है, तो वह केवल उपयोगिता का ही सृजन

या निर्माण कर सकता है।<sup>1</sup> अतः उपयोगिता मूलन या वृद्धि करने को ही अर्थ-शास्त्र में उत्पादन कहा गया है ( *Production is the creation of utility* ) । फेयर चाइल्ड के अनुसार, 'धन में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है।' <sup>2</sup> एली के शब्दों में, 'उत्पादन का अर्थ आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना है' <sup>3</sup> । फ्रेजर के अनुसार, 'यदि उपयोग का अर्थ किसी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त करना है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उपयोगिता का सृजन करना है।' <sup>4</sup>

उदाहरण के लिए एक बड़ई एक लकड़ी के लठ्ठों में मैत्र बनाकर एन मए पदार्थ को जन्म नहीं देता, बल्कि केवल अपने श्रम तथा औजारों की सहायता से उस मैत्र का रूप बदर उसमें अनिरिक्त आर्थिक उपयोगिता का सृजन करता है । अतः उसका यह कार्य 'उत्पादन' कहा जायगा । इस उदाहरण को लेकर ही मार्शल ने उत्पादन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, "इस भौतिक संसार में मनुष्य अधिक से अधिक यह कर सकता है कि या तो वह पदार्थ की इस प्रकार पुनः व्यवस्था कर दे कि वह पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो जाय या इस सम्बन्ध में कुछ प्रावरणक कार्य करे, जिससे प्रकृति उसे अधिक उपयोगी बना दे, जैसे भूमि में बीज डालने पर प्राकृतिक शक्तियाँ उसे नया जीवन प्रदान करती हैं।" <sup>5</sup>

पेंसन (Penson) के अनुसार धन या सम्पत्ति के उत्पादन का अर्थ निर्मा पदार्थ का निर्माण करना नहीं है, बरन् किसी उपलब्ध पदार्थ में मानवीय प्रावरणकताओं को सन्तुष्ट करने की योग्यता, क्षमता अथवा शक्ति का निर्माण करना है । प्रो० जे० के० मेहता ने उपयोगिता में वृद्धि को उत्पादन कहा है ।

परन्तु व्यापक दृष्टि से अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ केवल सीमित मात्रा में प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं और साधनों में अतिरिक्त उपयोगिता का सृजन करना ही

<sup>1</sup> "Man cannot create material things. In the mental and moral world indeed he may produce new ideas, but when he is said to produce material things he really produces utilities" —Marshall

<sup>2</sup> "Production consists of creation of utility in wealth"

—Fairchild

<sup>3</sup> "Production means creation of economic utility" —Ely

<sup>4</sup> "If consuming means extracting utility from, producing means putting utility into"

—Fraser

<sup>5</sup> "All that man can do in this physical world is either to re-adjust matter so as to make it more useful, as when he makes a log of wood into a table or to put in the way of being made more useful by nature as when he puts seed where the forces of nature make it burst into life."

—Marshall

नहीं है, वरन् प्रोफेसर टामस ( Thomas ) के मतानुसार, उसका अर्थ इन साधनों और सेवाओं में 'मूल्य-वृद्धि' या उनकी 'विनिमय शक्ति' में वृद्धि में है। किसी वस्तु में मूल्य वृद्धि या उसकी विनिमय क्षमता में वृद्धि करने पर उसके बदले में पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। 'मूल्य-वृद्धि' या 'विनिमय-साध्यता में वृद्धि' आर्थिक वस्तुओं में ही होती है, क्योंकि ये वस्तुएं ही मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हैं। अतः उपयोगिता रखने वाली आर्थिक वस्तुओं का निर्माण ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अन्तर्गत उपयोगिता में वृद्धि तथा विनिमय-क्षमता या मूल्य-वृद्धि करने की दोनों ही क्रियाएँ एक साथ ही की जाती हैं।

## 2. उत्पादन के भेद (Forms of Production)

किसी भी वस्तु या पदार्थ में उपयोगिता सृजन करने अथवा उसकी उपयोगिता में वृद्धि करने की कई विधियाँ हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं।

(1) रूप परिवर्तन करके (Form Utility) : जब किसी पदार्थ के वर्तमान रूप, रंग और आकार को बदल कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है, तब इसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन करना या उपयोगिता में वृद्धि करना कहा जाता है। इस प्रकार के उत्पादन से पदार्थ पहले की अपेक्षा अधिक लाभदायक एवं उपयोगी हो जाता है और उसके मूल्य तथा उसकी विनिमय-साध्यता में बढ़ि हो जाती है।

(2) स्थान परिवर्तन करके (Place Utility) . जब किसी वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, तब इसे स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। स्थान-परिवर्तन से उपयोगिता की वृद्धि इसलिए होती है कि जिस स्थान से वह वस्तु भेजी जा रही है वहाँ अधिक मात्रा में होने के कारण उसकी उपयोगिता कम है, परन्तु जहाँ वह वस्तु भेजी जा रही है वहाँ उस वस्तु की उपयोगिता अधिक है। स्थान परिवर्तन से किसी वस्तु में स्थान मूलक उपयोगिता (Place Utility) का सृजन होता है। उदाहरण के लिए, खानों में पठा कोयला जब फैक्टरी में, या रेलों के इंजन चलाने के लिए ग्रन्थ स्थानों पर ले जाया जाता है, तब उसमें स्थान-मूलक उपयोगिता का सृजन होता है। इस प्रकार की उपयोगिता का सृजन करने में यातायात के साधनों का अत्यधिक महत्व है।

(3) समय-परिवर्तन करके (Time Utility) : कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पुरानी होने पर ही अधिक उपयोगी या मूल्यवान् मानी जाती हैं, जैसे पुराना चावल, पुरानी शराब। इनके अतिरिक्त वस्तुओं का संचय अथवा सग्रह करके भी

उनकी उपयोगिता अथवा उनके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल कटने पर, माग की तुलना में उसकी पूर्ति (Supply) अधिक होने पर उसका मूल्य कम होता है। परन्तु उसका मूल्य समय के व्यतीत होने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। उसको सयह करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य करके उसमें समय या काल-मूलक उपयोगिता (Time Utility) का सृजन किया जाता है।

(4) अधिकार परिवर्तन द्वारा (Possession Utility) : किसी वस्तु को हस्तान्तरित करके उस वस्तु में 'अधिकार-मूलक उपयोगिता' (Possession Utility) का सृजन किया जाता है। इस प्रकार की उपयोगिता के सृजन से हस्तान्तरित वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक ही वस्तु की उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, एक दुकानदार के लिये उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है। परन्तु क्रेता अर्थात् उपभोक्ता के अधिकार में आने पर उसी वस्तु की उपयोगिता अधिक हो जाती है।

(5) सेवा-द्वारा (Service Utility) : सेवा द्वारा उत्पन्न या प्रदान की गयी उपयोगिता 'सेवा मूलक उपयोगिता' कहलाती है। डाक्टर, शिक्षक, वकील, संगीतज्ञ अपनी सेवाओं को बेचकर अपने व्यक्तिगत गुणों की उपयोगिताओं में वृद्धि करते हैं। 'व्यक्तिगत गुण' या 'व्यक्तिगत सेवाएँ' दिखायी नहीं देती। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रदान की गयी इन सेवाओं का उत्पादन की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। परन्तु इन सेवाओं में उपयोगिता अर्थात् आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की क्षमता होने के कारण इनका विनिमय करना उत्पादन माना जाता है।

(6) ज्ञान द्वारा उपयोगिता (Knowledge Utility) : किसी वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान अन्य व्यक्तियों को कराना, ज्ञान-प्रसार द्वारा उत्पादन कहलाता है। ज्ञान-प्रसार द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न की गयी अतिरिक्त उपयोगिता, ज्ञान-मूलक उपयोगिता (Knowledge Utility) कहलाती है। जैसे, सनलाइट साबुन की विशेषता का ज्ञान न होने पर किसी व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता कम होगी। परन्तु यदि विज्ञापन द्वारा उसकी विशेषताओं का ज्ञान उसे करा दिया जाये, तो उसकी उपयोगिता उसके लिए अधिक हो जायेगी।

उपयुक्त विधियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं से उपयोगिताओं का सृजन या उसकी उपयोगिताओं में वृद्धि करने वालों को उत्पादक (Producer) कहा जाता है।

उत्पादन प्रविधियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है :

(i) निस्तरण उद्योग (Extractive Industries) : इनके अन्तर्गत कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन करना, भूमि के अन्दर से खनन करके अनेक प्रकार की धातुओं निकालना तथा मछली पकड़ना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ii) निर्माणकारी उद्योग (Manufacturing Industries) : इनके अन्तर्गत कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण-सम्बन्धी कार्य सम्मिलित हैं।

(iii) व्यापारिक सेवायें (Commercial Services) इनके अन्तर्गत निमित्त वस्तुओं के विपणन एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों में लगे व्यापारियों, बैंकों, मण्डल बैंक तथा परिवहन के साधनों, बीमा-कम्पनियों आदि की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।

(iv) प्रत्यक्ष सेवायें (Direct Services) : इनके अन्तर्गत वे सेवायें आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं, जैसे डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नौकर, सम्पादक आदि की सेवायें।

### 3 उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने वाले तत्व (Factors Determining Volume of Production)

उत्पादन की मात्रा अथवा कुशलता, अर्थात् उत्पादन की मात्रा में वृद्धि तथा अच्युती विस्म की वस्तुओं का उत्पादन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर है :

1. उत्पादन के साधनों का उपलब्ध होना किसी देश में एक निश्चित समय में उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन कुशलता को निर्धारित करने वाले प्राथमिक एवं आधारभूत तत्वों के अन्तर्गत तथा पर उपलब्ध (अ) प्राकृतिक साधन, जैसे—उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की धातुएँ, जल, वायु, तापक्रम आदि, (ब) श्रम—कुशल तथा परिश्रमी श्रमिक, (स) पूँजी तथा (द) उत्पादन के कुशल संगठन एवं इसकी कुशल व्यवस्था की योग्यता का सम्मिलित करते हैं। यदि य सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने हैं, तो देश में उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। परन्तु उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय इन साधनों की मात्रा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उनके गुणों तथा कार्य-कुशलता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि ये साधन अधिक कार्य-कुशल हैं तो उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तथा उत्पादित वस्तुओं की विस्म भी अधिक होगी। इसके साथ ही प्राप्त साधनों को अनुकूलतम (Optimum) तथा आदर्श (ideal) अनुपात में एकत्र तथा मनोयोगित करने पर ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि सम्भव हो सकती

है। अतः कार्य-कुशल साधनों की उचित व्यवस्था भी उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है।

2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का उपलब्ध होना उत्पादन की मात्रा वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की उन्नति तथा उसके प्रयोग पर निर्भर है। यदि किसी देश में उत्पादन के क्षेत्रों में नयी एवं आधुनिक उत्पादन-विधियों, यन्त्रों आदि का उपयोग किया जाता है, यदि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाता है, तो निश्चय ही उस देश की उत्पादन मात्रा प्राधिक होगी (जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में)। अतः किसी देश की उत्पादन मात्रा को निश्चित करते समय इस तत्व को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

3. सदेश-बहन तथा यातायात के साधनों का विकास उत्पादन मात्रा को निर्धारित करने में यातायात तथा सदेश-बहन के साधनों का भी महत्व है। यदि डाकघर और टेलीफोन की विस्तृत सुविधायें उपलब्ध हों तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने में सरलता होगी है तथा व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार होता है। यातायात के साधनों—रेल, सड़क, वायु तथा जल यातायात—का विकास होने पर उत्पादन को अनेक स्थानों और देशों में भेजने की सुविधायें उपलब्ध होती हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की योजनायें कार्यान्वित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यातायात के साधन उत्पादन के साधनों—कच्चा माल, धन तथा पूँजी—को गतिशील बनाते हैं। अनुत्पादक क्षेत्रों से उत्पादक क्षेत्रों में जाने पर उनकी कार्य-एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है जिससे देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है।

4. बैंकिंग तथा साख्त व्यवस्था का विकास बैंकिंग तथा साख्त संस्थाएँ सम्पूर्ण उत्पादन-प्रणाली के लिए धन एवं पूँजी की व्यवस्था में सहायक होती हैं। आधुनिक युग में साख्त अथवा ऋण-पूँजी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि नकद पूँजी। बैंकिंग तथा साख्त-संस्थाओं का समुचित एवं आवश्यक विकास सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक यन्त्र को चलाता है तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने में सहायक होता है। इन संस्थाओं का अधिक विकास होने तथा अधिक से अधिक मात्रा में पूँजी प्राप्त होने से ही इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य विकसित पश्चिमी देशों में औद्योगिक उत्पादन एवं आर्थिक विकास अधिक हुआ है।

5. राजनैतिक तत्व देश की सरकारी नीति उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है। यदि देश की सरकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षा, आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता, आवश्यक जानकारी आदि प्रदान करती है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी है। इसके विपरीत, सरकार का अनावश्यक हस्त-

हैं प आर्थिक एवं औद्योगिक विश्वास को रोक देना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राजनैतिक परिस्थितियाँ, जैसे आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा भी उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

6 अन्य प्राकृतिक तत्व : उत्पादन मात्रा पर कुछ अन्य प्राकृतिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ वर्षा का न हाना, बाढ़, भूकम्प, महामारी टिफ़ो का आक्रमण ऐसे दैवी प्रकापो से उत्पादन-मात्रा कम हो जाती है। प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण तथा मानव-हित और आर्थिक विकास में उनके उचित प्रयोग से ही उत्पादन-मात्रा में वृद्धि होती है।

प्रोफेसर बेनहम ने उत्पादन-मात्रा को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त तत्वों को निम्नलिखित तीनो वर्गों में रखा है।

(I) प्राकृतिक शक्तियाँ या घटक (Natural factors) : बाढ़, भूचाल, घनावृष्टि तथा अन्य दैवी एवं प्राकृतिक प्रकोप।

(II) वैज्ञानिक उन्नति - तकनीकी ज्ञान का विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कार एवं उनका प्रयोग।

(ii) उत्पादन के साधनों की उपलब्धता तथा उनकी उपयोग में लाने की विधिः भूमि, धन तथा पूँजी की अधिकाधिक मात्रा, यातायात के साधन, बैंकिंग तथा सात-यकस्या तथा इन साधनों का नियोजित उपयोग।

#### 4. उत्पादन के साधन (Factors of Production)

उत्पादन के साधनों का अविश्राय उन समस्त वस्तुओं (पदार्थों) और सेवाओं में है जो धन के उत्पादन में सहायक होती हैं। यदि कोई सेवा या वस्तु, धन के उत्पादन में सहायक नहीं होती है, तो उसे उत्पादन के साधनों के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता।<sup>1</sup> फोब्र ने उत्पादन के साधन को मौलिक उत्पादनकारी साधनों के एक समूह या वर्ग के रूप में माना है। उनके अनुसार उत्पादन के साधन शब्द का अविश्राय उत्पादनकारी तत्वों के वर्ग में है जिसके प्रत्येक तत्व को उस वर्ग की इकाई

<sup>1</sup> "Any thing that assists production is known as a factor of production. A thing that exists is not necessarily a factor of production, it becomes a factor of production only when it actually assists production"

(Unit) कहना ही उपयुक्त होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन विभिन्न उत्पादन-कारी इकाइयों को 'Inputs' तथा इससे उत्पादित वस्तुओं को 'Outputs' की संज्ञा दी है।

उत्पादन के साधनों की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद रहा है। परन्तु प्रचलित मत उत्पादन के पांच साधनों—भूमि (Land), श्रम (Labour), पूँजी (Capital) संगठन (Organisation) तथा साहस (Enterprise) के पक्ष में ही है। मतः यहाँ पर इन पांचों साधनों की व्याख्या की गई है।

(1) भूमि (Land) : भूमि उत्पादन का अनिवार्य एवं सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इसके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए इसको उत्पादन का अनिवार्य साधन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में भूमि का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। ऐसे समस्त पदार्थ जो बिना किसी मानवीय श्रम के पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा उसके नीचे पाये जाते हैं, भूमि के अन्तर्गत शामिल हैं। इस प्रकार पृथ्वी की मिट्टी, नदी, पहाड़, खनिज पदार्थ, वातुयें, हवा, पानी, प्रकाश, प्राकृतिक वन सम्पदायें, जीव-जन्तु आदि भूमि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। मनुष्य इन प्राकृतिक पदार्थों या साधनों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। प्रकृति स्वयं इन्हे उपहार-स्वरूप प्रदान करती है। वस्तुतः उत्पादन के साधनों में भूमि ही प्राकृतिक साधन है। आर्थिक के अनुसार, 'भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति से निःशुल्क एवं स्वतन्त्र उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं।' आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वे समस्त पदार्थ जो बिना किसी मानवीय श्रम के उत्पादन के लिए उपलब्ध हों, भूमि के अन्तर्गत आते हैं।

(2) श्रम (Labour) : उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन श्रम है। यह साधन ही वास्तव में सक्रिय साधन (Active factor) है, क्योंकि भूमि तो ऐसा साधन है जो निष्क्रिय है। भूमि को उत्पादन कार्य में लगाने तथा मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उसमें उपयोगिता का निर्माण करने का कार्य श्रम ही करता है। इसीलिए श्रम को उत्पादन का अनिवार्य (Inevitable) साधन माना गया है, परन्तु यह प्राकृतिक साधन न होकर मानवीय साधन है।

अर्थशास्त्र में श्रम का आशय मानवीय श्रम से है 'जिसके अन्तर्गत मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के श्रम सम्मिलित हैं। इस प्रकार श्रम के

\* "Land is a free gift of Nature"

—Ricardo

\* Land means "the materials and the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air and light and heat"

—Alfred Marshall



अन्तर्गत मनुष्य की वे सभी आर्थिक क्रियायें सम्मिलित की जाती हैं जिनका उद्देश्य पनोरपत्ति करना या भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है। यदि उत्पादन के लिए किए गए प्रयत्नों से किसी वस्तु या सम्पत्ति का उत्पादन न हो सके तो इसका अर्थ यह न होगा कि किये गये प्रयत्नों को धर्म के अन्तर्गत सम्मिलित न किया जाय। इस प्रवास को भी धर्म माना जायेगा। आर्थिक ने धर्म की परिभाषा इन शब्दों में दी है : किसी भी मानसिक प्रयत्न या शारीरिक कार्य को धर्म कहते हैं जो कार्य से प्राप्त प्रत्यक्ष आनन्द के अतिरिक्त पूर्णतः या आंशिक रूप से अच्छाई की दृष्टि से किया जाता है।<sup>१</sup>

(3) पूँजी (Capital) : आधुनिक युग में पूँजी को भी उत्पादन का अनिवार्य साधन माना जाता है। अर्थशास्त्र में पूँजी का अभिप्राय केवल नकद धन से ही नहीं है। पूँजी मनुष्य द्वारा पहले किए गए 'धर्म' से उत्पादित धन का वह भाग है जो उपभोग के पश्चात् खेप बच जाता है और जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने पूँजी को 'मानव निर्मित उत्पादन का साधन' (Man-made instrument of production) या 'उत्पादन का उत्पादित साधन' (Produced means of production) कहा है। इसके आधार पर कच्चे तया पक्के माल, पन्थ और औजार, इमारतें, विज्ञान के हल-बील, बीज, नकद धन आदि पूँजी के अन्तर्गत आंशिक हैं। इन सबका प्रयोग अतिरिक्त उत्पादन के लिए किया जाता है।

(4) संगठन (Organisation) : उपर्युक्त तीनों साधनों—भूमि, धर्म तथा पूँजी—के उपलब्ध होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन ठीक ढंग से होगा। उत्पादन के साधनों को उपयुक्त मात्रा में लगाकर उनमें समन्वय स्थापित करना तथा समय-समय पर उन्हें समायोजित करना भी आवश्यक है जिससे उत्पादित वस्तुओं की लागत कम हो सके तथा उत्पादन अधिकतम हो सके। इन सबके लिए संगठन एवं प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। अतः वर्तमान उत्पादन-प्रणाली में उत्पादन के साधन के रूप में संगठन या व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि संगठन-योग्यता विशिष्ट धर्म (Specialised Labour) या मानसिक धर्म है अतः इसे एक अलग साधन के रूप में न मानकर धर्म के अन्तर्गत ही मानना चाहिये। परन्तु वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था की वैज्ञानिक तरीके से चलाने में इसका अलग महत्वपूर्ण स्थान है।

(5) साहस (Enterprise) : उत्पादन कार्य में हानि की सम्भावनायें भी रहती हैं। रूपक द्वारा फल नो देने के पश्चात् यह निश्चित नहीं है कि यह उसे

<sup>१</sup> "Any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to good, other than the pleasure derived directly from the work,"  
—Marshall

काट लेगा। वर्षा न होने अथवा अधिक होने के कारण फसल नष्ट होने की भी सम्भावना बनी रहती है। इसी प्रकार वस्तुओं का उत्पादन भावी मांग के अनुमान के आधार पर किया जाता है। यदि ये अनुमान सत्य उत्तरते हैं तो लाभ होता है, परन्तु यदि मांग सम्बन्धी अनुमान, रुचि व फैशन में परिवर्तन हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से, गलत हो जाय, तो हानि भी सहन करनी पड़ सकती है। अतः उत्पादन-योजना में भावी हानि का डर बना रहता है। भावी हानि या जोखिम को सहन करने के लिए साहस का भी उत्पादन के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इस जोखिम को उठाने वाले व्यक्ति का, जिसे साहसी (Entrepreneur or Enterpriser) कहते हैं, होना आवश्यक है। साहस को उत्पादन के साधनों में एक अलग साधन के रूप में स्थान प्रदान करने का श्रेय जे०बी०से० तथा अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को है। पुराने अर्थशास्त्रों इसका व्यवस्था का ही एक अंग मानते थे।

**साधनों के वर्गीकरण की समीक्षा :**

उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने मतभेद है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्धारित उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन किए गये हैं। अतः इन परिवर्तनों का क्रमबद्ध विवेचन करना आवश्यक है।

(1) प्रारम्भिक वर्गीकरण—उत्पादन के दो मौलिक साधनों की मान्यता : प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कुल उत्पादन के विभाजन के आधार पर उत्पादन के तीन साधनों को स्वीकार किया था। उनका विचार था कि उत्पादन में प्राप्त फल तीन भागों में बांटा जाता है, प्रथम भाग भूमि को, दूसरा भाग श्रम को, और अन्तिम भाग पूँजी को प्राप्त होता है। उन्होंने भूमि को निष्क्रिय (Passive) साधन तथा श्रम को सक्रिय (Active) साधन माना था। परन्तु प्रोफेसर चैपमैन तथा जे०एस० मिल ने उत्पादन के दो ही साधनों पर विशेष धन दिया था। उनके अनुसार भूमि और श्रम ही उत्पादन के मौलिक साधन हैं (the absolutely indispensable agents of production are land and labour), क्योंकि भूमि अर्थात् प्राकृतिक साधनों के न होने पर उत्पादन नहीं हो सकता और भूमि के होने पर भी श्रम के न रहने पर उपयोगिता का सृजन असम्भव है। अतः इन दोनों साधनों के रहने पर ही उत्पादन-कार्य सम्भव हो पाता है। इनके अतिरिक्त पूँजी जो उत्पादन का महत्वपूर्ण, परन्तु गौण, साधन है, भूमि और श्रम की संयुक्त उपज (Joint Product) का वह शेष भाग माना गया है (Capital is the joint product of land and labour) जो उपयोग के पश्चात् उत्पादन के लिए बच रहता है। वह उत्पादन का मौलिक साधन नहीं है। भूमि और श्रम के रहने पर पूँजी प्राप्त हो सकती है, परन्तु पूँजी की कल्पना इन दोनों की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती।

इसी आधार पर इन अर्थशास्त्रियों ने सगठन को भी उत्पादन के एक अलग माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके विचार में सगठन विभिन्न भ्रम है जिसे भ्रम के अन्तर्गत ही सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु पेंसन (Penson) के विचार से "उत्पादन का प्रत्येक साधन आवश्यक है। हाँ, इतना अवश्य है कि अलग-अलग समय तथा औद्योगिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग साधनों का अलग अलग महत्व रहता है।"

(2) मार्शल द्वारा उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण—उत्पादन के पाँच साधनों के सम्बन्ध में मार्शल ने उत्पादन के चार साधन बनाए—भूमि, श्रम, पूँजी और सगठन। बाद में सगठन को भी दो भागों में उपविभाजित कर दिया गया—प्रबन्ध तथा साहस। इस प्रकार उत्पादन के पाँच साधन माने गए—भूमि, श्रम, पूँजी, सगठन और साहस। आधुनिक विचारधारा इस वर्गीकरण के ही पक्ष में है। इस वर्गीकरण अर्थात् उत्पादन के पाँच साधनों के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किये जाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं -

(1) आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में पूँजी, भूमि तथा श्रम से भी अधिक, महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान औद्योगिक युग में भूमि एवं श्रम जैसे उत्पादन के मूल साधनों का उपयोग पूँजी पर निर्भर है। श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करके श्रम के महत्व को कम किया जा सकता है और भूमि की कमी की पूर्ति उपलब्ध प्रकृति-दत्त वस्तुओं के समुचित प्रयोग द्वारा सम्भव हो सकती है।

(ii) उत्पादन के कार्य को नियन्त्रित करने तथा भूमि, श्रम और पूँजी की इकाइयों को व्यवस्थित करके कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उत्तरदायित्व की पूर्ति एक कुशल प्रबन्धक ही कर सकता है। इसे विभिन्न भ्रम के रूप में मानकर श्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करना उचित नहीं है।

(iii) प्रत्येक उत्पादन-कार्य में जोखिम तथा हानि की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। शायद सभी साधनों की प्रदान करने वाले साधकों—भूमिपति, श्रमिक, पूँजीपति तथा प्रबन्धक—में से प्रत्येक साधक उत्पादन-कार्य में भागी अनिश्चिन्ता एवं असुरक्षा से दूर रहना चाहता है। वह तो नुन उत्पादन में अपने अंश की ओर से निश्चिन्त हो जाना चाहता है। हानि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। साहसी इस अनिश्चितता, हानि की सम्भावनाओं तथा जोखिम का भार उठाता है। इस प्रकार वह उत्पादन को अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अतः साहस भी उत्पादन के एक स्वतन्त्र साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

3. आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपर्युक्त वर्गीकरण से सहमत नहीं हैं। इनमें विकस्टीड, वेनहम तथा डेवनपोर्ट के नाम उल्लेख-

नीय है। प्रोफेसर बेनहम ने भूमि का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि भूमि भी अनेक प्रकार से प्रयोग में लायी जाती है, जैसे कृषि योग्य भूमि, शहरी-भूमि जिसका प्रयोग मकान-निर्माण के लिए किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र की भूमि जिसका प्रयोग औद्योगिक मयनों के निर्माण के लिए ही होता है। विभिन्न प्रकार की भूमि को एक ही वर्ग में रखना उचित नहीं है। इसी प्रकार पूँजी में सम्मिलित रेल का इजन केवल रेल चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि सूती वस्त्र-उद्योग में प्रयुक्त मशीनों का प्रयोग केवल सूती वस्त्रों के बनाने के लिए ही किया जा सकता है। इन दोनों को एक ही वर्ग—पूँजी में सम्मिलित करना असंझान्तिक है। अतः इन विभिन्न विशेषताओं तथा उपयोगिता वाले साधनों को समान मानकर उन्हें कुछ विशेष वर्गों में रखना संझान्तिक रूप से गलत है। इन सभी साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी, साहम (जिसमें सगठन भी सम्मिलित है) की विभिन्न किस्मों को उत्पादन का अलग-अलग एक स्वतन्त्र साधन मानना अधिक वैज्ञानिक तथा यथार्थ होगा। प्रोफेसर बेनहम के मतानुसार कोई भी इकाई जो किसी भी स्तर पर उत्पादन विधि में प्रयोग में लायी जाती है, उत्पादन या एक साधन है।<sup>10</sup>

उपयुक्त विचार एवं मत के अनुसार उत्पादन के पांच साधन ही नहीं बरन् अनेक साधन हो सकते हैं। परन्तु जैसा कि बेनहम ने आगे स्पष्ट किया है, आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए इन उत्पादनकारी इकाइयों अथवा साधनों की सख्या में कुछ कमी की जा सकती है। यदि एक ही गुण एवं प्रकार वाले साधनों को एक ही श्रेणी या वर्ग में रख दिया जाये तो साधनों की सख्या कम हो सकती है।

परम्परागत वर्गीकरण के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी है कि कुछ साधनों को मौलिक मानकर उन्हें अन्य साधनों से पूर्वक कर देना उचित नहीं है। बेनहम का यह मत है कि मौलिकता के आधार पर भूमि को पूँजी से अलग एक साधन मानना उपयुक्त नहीं है। यह ठीक है कि भूमि प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है और पूँजी मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है। परन्तु भूमि की उत्पादकता तथा उपयोगिता में वृद्धि मानव-प्रयासों के द्वारा ही सम्भव हो पाती है। यदि भूमि का साफ करके उसको कृषि योग्य अथवा शहरी क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया जाये तो यह भूमि पूँजी कहलायेगी। परन्तु प्रकृति द्वारा दी गयी भूमि और मनुष्य द्वारा नया रूप देने पर उपलब्ध भूमि में भेद करना कठिन होगा। अतः दोनों में जो थोड़ा सा मौलिक अन्तर हो उसको ध्यान में रखकर भूमि को भी पूँजी के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उसे भी अधिक उप-

<sup>10</sup> "Any thing which contributes towards output is a factor of production.....any ingredient which goes into the productive process at any stage is a factor of production" —Benham

योगी बनाया जा सकता है। इस आधार पर केवल मौलिक या प्रकृति-दत्त उपहार होने के कारण भूमि और श्रम को प्रत्यक्ष श्रेणियों में रखना ठीक प्रतीत नहीं होता।

(4) नवीन वर्गीकरण . उपर्युक्त संतर्भेदों के कारण उत्पादन के पाच साधनों की सहाय को कम करने की दिशा में और भी गम्भीर प्रयत्न किए गए हैं। आस्ट्रियन अर्थशास्त्री वीजर (Wieser) ने उत्पादन के समस्त साधनों को दो विस्तृत श्रेणियों-विशिष्ट (Specific) तथा अवशिष्ट (Non-specific) में रखा है। जिन साधनों का उपयोग केवल किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए ही किया जा सकता है। तथा जो साधन गतिशील नहीं होते उन्हें विशिष्ट साधन (Specific factors) कहते हैं, जैसे रेल का इंजन केवल एक विशिष्ट कार्य—गाड़ी चलाने—के लिए ही उपयोगी माना जाता है। उसे लूट या चोरी मिल में भ्रान्तों को चलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। परंतु यह एक विशिष्ट साधन माना जाएगा। इसके विपरीत जिन साधनों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है तथा जो गतिशील होते हैं, उन्हें अवशिष्ट साधन (Non-Specific factors) कहते हैं, जैसे एक शक्ति यंत्र (विजली की मोटर), जिसका प्रयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। परन्तु दत्त सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि किसी साधन की विशिष्टता तथा अवशिष्टता उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। यह साधन का मौलिक गुण नहीं है। इस गुण को उत्पादन कार्य के लिए साधन के साथ जोड़ दिया जाता है। श्रम को चाहे मशीन चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाय और चाहे सफाई कार्य के लिए, वह श्रम ही कहलायेगा। इसके साथ ही साथ साधन विशिष्ट अथवा अवशिष्ट होते ही समय तक रह सकता है। जब तक कोई भूमि बेकार पड़ी है, तब तक वह निविश्ट है, क्योंकि उसका प्रयोग किसी भी कार्य यकान बनाने, दूकान बनाने, पार्क बनाने आदि के लिए किया जा सकता है। परन्तु जब उसका प्रयोग यकान बनाने के लिए कर दिया जाता है, तब वह विशिष्ट साधन माना जाता है।

**निष्कर्ष :** उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन के साधनों का पाच वर्ग-सम्बन्धी परम्परागत वर्गीकरण ठीक नहीं है, फिर भी इस व्यवहार करना उचित नहीं है। अर्थशास्त्र की वर्तमान विषय-सामग्री उत्पादन के साधनों के इस प्रकार के वर्गीकरण पर ही आधारित है। सभी उत्पादनकारी साधनों के उत्पादन को एक साथ सम्मिलित करके अथवा उनका सूक्ष्म वर्गीकरण करके अलग अलग अध्ययन करना कठिन एवं जटिल होगा तथा अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को पुनः नया रूप देने की आवश्यकता होगी।

### प्रश्न व संकेत

1. उत्पादन का अर्थ बताइए। वे कौन से तत्त्व हैं जो किसी समय में एक देश के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं ?

(Agra, B. A. 1956)।

(संकेत : सर्वप्रथम उत्पादन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात् उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।)

2. उत्पादन का आधिक क्या अर्थ है ? क्या उत्पादन तथा उपभोग के अन्तर्गत मनुष्य की सभी आधिक क्रियाएँ आ जाती हैं ?

(Alld; B Com. 1962)

(संकेत : प्रश्न के दूसरे भाग में उत्पादन व उपभोग के अन्तर्गत आने वाली आधिक क्रियाएँ बताइए।)

3. उत्पादन क्या है ? उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं ? इन साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कौन सा है ?

(Bhagalpur, 1966A)

(संकेत : प्रश्न के दूसरे भाग में उत्पादन के विभिन्न साधनों के तुलनात्मक महत्व का विवेचन कीजिए और बताइए कि कौन सा साधन अधिक महत्वपूर्ण है।)

---

## भूमि व भूमि की कार्यक्षमता (Land and its Efficiency)

*"By land is meant, not merely land in the strict sense of the word, but whole of materials and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat."*

—Marshall

### 1. भूमि का अर्थ (Meaning of Land)

भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन है। साधारण भाषा में भूमि का अर्थ भूमि की सतह तथा मिट्टी से है, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ अधिक व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ एवं अभिप्राय उन समस्त पदार्थों एवं शक्ति से है जो पृथ्वी की सतह पर, उसके नीचे तथा ऊपर, प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार-स्वरूप प्रदान की जाती है। इस विस्तृत अर्थ में भूमि के अन्तर्गत भूमि की सतह के प्रतिरिक्त अन्य सब प्राकृतिक साधनों, जैसे हवा, धूप, वर्षा, नदी, झरने, पहाड़, वन, समुद्र, जीव-जन्तु, वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ, आदि, भी सम्मिलित हैं। प्रोफेसर मार्शल ने भूमि के इसी अभिप्राय को अपनी परिभाषा में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है :

“भूमि का अर्थ, शब्द के वास्तविक अर्थ में केवल भूमि से ही नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति मनुष्य को सहायता के लिए पृथ्वी भूमि और पानी, वायु, प्रकाश और उष्णता के रूप में निःशुल्क प्रदान करती है।”

मैसन ने भी ‘भूमि’ के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत प्रकट किया है। परन्तु प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया था। इन अर्थशास्त्रियों में से कुछ का यह मत है कि प्रकृति की उदारता के कारण इसमें मिले उपहार (Gifts of Nature) ही भूमि है। रिकार्डो (Ricardo) ने भी इसे प्रकृति का निःशुल्क या स्वतन्त्र उपहार (Free Gift of Nature) ही माना है, परन्तु वह अपने पूर्ववर्ती विचारकों की इस बात से सहमत नहीं है कि प्रकृति उदार है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भूमि की मौलिक तथा नष्ट न होने वाली शक्तियों को ही भूमि माना था। बाद में उन्होंने कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में उसकी मिट्टी की उर्वरा-शक्ति, गैर-कृषि भूमि के सम्बन्ध में उसके स्थान (space) तथा उसके स्थिति मूल्य (site-value), वायु, जल और सूर्य के प्रकाश को भूमि के अन्तर्गत सम्मिलित किया। परन्तु मार्शल ने अपनी उपर्युक्त परिभाषा में 'भूमि' का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया। मार्शल तथा पैसन की परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि के अन्तर्गत केवल उन्हीं पदार्थों तथा शक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनको मनुष्य अपने श्रम द्वारा निर्मित नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं पूँजी के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती हैं।

### भूमि के लक्षण :

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर ही भूमि के निम्नलिखित लक्षणों की व्याख्या की गयी है :

1. भूमि प्रकृति की निःशुल्क दान है (Free Gift of Nature) . भूमि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक स्वतन्त्र उपहार है। इसका सृजन तथा निर्माण मनुष्य नहीं करता। मनुष्य इसे बिना किसी व्यय के प्रकृति से स्वतन्त्र रूप में प्राप्त करता है। मानव समाज को इसके लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। बाद में वह उसमें सुधार करके उसे अधिक उपयोगी बना लेता है। इस सम्बन्ध में मार्शल ने कहा है कि वे मौलिक पदार्थ, जो अपनी उपयोगिता के लिए मानवीय श्रम के ऋणी हैं, पूँजी के अन्तर्गत रखे जाते हैं, और वे पदार्थ, जो किसी प्रकार से उसके ऋणी नहीं हैं, भूमि के अन्तर्गत आते हैं।

(Those Material things which owe their usefulness to human labour being clas-ed under capital and those which owe nothing to it being classed as land.)

2. भूमि की मात्रा सीमित है (Limited in Quantity) : भूमि की मात्रा प्रयत्न उसका परिमाण सीमित है। उसकी मात्रा में किसी प्रकार वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती। जिस सीमा या परिमाण से प्रकृति ने अपने उपहार दे रखे हैं वे निश्चित हैं, जैसे पृथ्वी का क्षेत्रफल प्रकृति द्वारा निर्धारित एवं निश्चित कर दिया गया है। मनुष्य न तो उसको घटा सकता है और न ही उसको बढ़ा सकता है। यही कारण है कि भूमि की पूर्ति पूर्णतया अलोचदार (Perfectly inelastic) मानी जाती है। कुछ आलोचकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भूमि का क्षेत्रफल समुद्र, भोलो, तालाबों को सुखाकर बढ़ाया जा सकता है, परन्तु यह तर्क ठीक नहीं है। भूमि अर्थात् घरातल सो पट्टे से भी बड़ा वर्तमान है। मनुष्य उस स्थान के पानी को सुखाकर केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि ही करता है।



3. भूमि अविनाशी है (Indestructible) : भूमि कभी भी नष्ट नहीं होती। पृथ्वी की सतह पर कभी-कभी कुछ आवश्यक परिवर्तन होने रहते हैं, जैसे पहाड़ों के स्थान पर समतल भूमि का हो जाना, नदियों का सूख जाना, आदि। परन्तु इन परिवर्तनों का यह अर्थ नहीं है कि भूमि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार भूमि की उर्वरा-शक्ति में कमी होने पर यह कहना कि भूमि नष्ट हो गयी है, गलत है। प्रकृति स्वयं प्राकृतिक तरीकों से प्रदान करके उसकी उर्वरा-शक्ति में वृद्धि करती है।

4. भूमि अचल एवं स्थिर है (Immobile) : भूमि स्वभाव से ही स्थिर एवं अचल है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। अतः इसमें गतिशीलता (Mobility) का अभाव है। किसान के खेतों, रावों, वन, नदियों आदि का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

5. भूमि निष्क्रिय है (Passive) : भूमि का यह प्राकृतिक गुण है कि वह स्वामाधिक रूप से षट् एव निर्जीव है। यह उत्पादन कार्य में स्वयं सक्रिय भाग नहीं ले सकती। अन्न का सहयोग प्राप्त करने पर ही उत्पादन में उसका सहयोग मिलता है।

6. भूमि के गुणों में विभिन्नता (Variability) : स्थिति तथा उर्वरा-शक्ति के विचार से सभी भूमि एक सी नहीं हैं। कृषि-योग्य भूमि में ही कुछ पर्याधिक उपजाऊ, कुछ औसत दर्जे की तथा कुछ कम उपजाऊ होती हैं। स्थिति के विचार से भी भूमि में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे शहर के निकट की भूमि तथा शहर से दूर भूमि। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में कुछ खानों में अधिक खनिज पदार्थ होता है और कुछ में कम, वहाँ कहीं अधिक होती है तो कहीं पर कम। अतः विविधता भी भूमि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है।

7. भूमि का कोई पूँति मूल्य नहीं होता (Land has no supply price)। मार्शल के अनुसार, “भूमि का क्षेत्र निश्चित है, मनुष्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह पूर्णतया माँग से अप्रभावित रहती है। (अर्थात् इस पर माँग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता), इसका कोई उत्पादन व्यय नहीं होना, इसका कोई पूँति मूल्य नहीं होना जिस पर इसका उत्पादन किया जाय।” इस आधार पर ही कहा गया है कि भूमि का पूँति-मूल्य (supply price) इसके प्रचलित मूल्य को प्रभावित नहीं करता।

**भूमि के लक्षणों की समीक्षा :**

भूमि का नया अर्थ - आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भूमि के उपर्युक्त लक्षणों में

1 “The area of the earth is fixed, man has no control over these, they are wholly unaffected by demand, they have no cost of production, there is no supply price at which they can be produced.”  
—Marshall

से कुछ की कड़ी मालोचनाएँ की हैं। उनसे विचार से भूमि को प्रकृति का निमूल्य उपहार मानना, उसकी मात्रा सीमित मानना, तथा उसे अचल तथा अविनाशी समझना उचित नहीं है।

भूमि प्रकृति को देन है इस सम्बन्ध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि केवल इस आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों—मनुष्य द्वारा बनायी गयी तथा प्रकृति द्वारा प्रदान की गयी वस्तुओं—में बांट देना ठीक नहीं है। प्रत्येक पदार्थ मानव-श्रम तथा पूँजी द्वारा संचारने के बाद ही उपयोगी होता है। प्रत्येक वस्तु अपने मौलिक रूप में प्रकृति को देन ही है। अतः इस प्रकार का वर्ग भेद ठीक मालूम नहीं होता और भूमि को इस आधार पर पूँजी तथा उत्पादन के अन्य साधनों से अलग रखना ठीक नहीं है। भूमि के उपजाऊपन के अविनाशी होने के सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि किसी भी भूमि पर निरन्तर खेती करने पर उससे उत्पादन—मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि भूमि की कार्यक्षमता उसी प्रकार कम होती है जिस प्रकार मानव-श्रम या पूँजी की। अतः यह कहना कि भूमि अविनाशी है ठीक नहीं है।

भूमि की स्थिरता का लक्षण केवल इस तथ्य पर ही आधारित है कि भूमि का स्थान परिवर्तन सम्भव नहीं है। परन्तु गतिशीलता (Mobility) का अभिप्राय केवल स्थान परिवर्तन से नहीं है, बल्कि उसके विभिन्न प्रयोग से भी है। यदि किसी भूमि का प्रयोग कृषि से हटाकर स्कूल निर्माण में किया जाय, तो यह कहा जा सकता है कि भूमि स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। अतः उसे स्थिर मानना ठीक नहीं है।

भूमि की मात्रा में वृद्धि भी सम्भव है। आर्थिक दृष्टिकोण से उपलब्ध प्राकृतिक साधनों से उत्पादन-मात्रा में वृद्धि करने की भूमि की मात्रा में वृद्धि करना भी कह सकते हैं। भूमि पर गहन खेती करके तथा किसी एक भवन के ऊपर अनेक मजिल्लें खड़ी करके स्थान की न्यूनता दूर की जा सकती है तथा उपयोगिताओं या उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि की मात्रा में वृद्धि या कमी सम्भव नहीं है।

अतः, भूमि निःशुल्क प्राप्त नहीं होती है। वह उतनी ही मूल्यवान् तथा विनिमय-साध्य है जितने कि उत्पादन के अन्य साधन। यह कहना ठीक है कि मानव जाति को भूमि प्रकृति की ओर से निःशुल्क अर्थात् मूल्य चुकाये बगैर प्राप्त होती है। परन्तु उस पर एक बार अधिकार प्राप्त कर लेने पर उसका अविकारी बिना मूल्य लिए उसके प्रयोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देता। इसके अतिरिक्त यदि यह मान भी लिया जाय कि कोई भूमि बिना मूल्य दिए प्राप्त हो गयी है, तो भी उसमें विभिन्न प्रयोगों का गुण हानि के कारण उसमें 'अवसर-ध्वंस' (Opportunity Cost) तत्त्व मौजूद है। इस तत्त्व के आधार पर यह कहा जाता है कि

भूमि का प्रयोग किसी एक कार्य के लिए ही करने पर उसके दूसरे प्रयोग का त्याग करना पड़ता है।

**आधुनिक विचार :** उपर्युक्त आलोचनाओं के आधार पर ही आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों (जो के० मेहता भारतीय अर्थशास्त्री तथा बीजर, आस्ट्रियन अर्थशास्त्री) ने भूमि की उत्पादन का एक अलग साधन नहीं माना है। उनका यह विचार है कि भूमि की विशेषताएं प्रत्येक साधन में दृष्टिगोचर होती हैं, यदि हम इनको प्रयोग की विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत कर दें। यदि कोई साधन किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए ही प्रयोग में आये तो उसे विशिष्ट तथा अन्य उपयोग में आने वाले साधन भूमि कहे जा सकते हैं। इस आधार पर प्रत्येक साधन में भूमि का लक्षण या स्वरूप (Land Aspect) वर्तमान रहता है। यहां पर 'भूमि का पक्ष' होने का अर्थ यह है कि इस साधन के विभिन्न उपयोग न होने के कारण उसके 'वैकल्पिक उपयोग' (alternative uses) को ध्यान में नहीं रखा जाता और न ही उसमें कोई त्याग की भावना ही निहित होती है। यह तथ्य प्रत्येक साधन—पूजा, घम, सगठन प्रादि पर भी लागू हो सकता है। अतः 'भूमि नामक साधन' का क्या अलग नहीं बनाया जा सकता।

## 2 भूमि की कार्यक्षमता (Efficiency of Land) :

भूमि की उत्पादन शक्ति या उसकी उत्पादकता को ही भूमि की कार्यक्षमता कहते हैं। उसकी कार्यक्षमता किसी उत्पादन कार्य के लिए उसकी उपयुक्तता तथा उसके द्वारा उत्पादित मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि भूमि के एक टुकड़े से किसी अन्य टुकड़े की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जाता है तो यह कहा जायेगा कि भूमि के पहले टुकड़े में अधिक उत्पादकता है और दूसरे टुकड़े में कम। कार्यक्षमता के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि पहले टुकड़े में दूसरे टुकड़े की अपेक्षा अधिक कार्यक्षमता है।

भूमि के सम्बन्ध में कार्यक्षमता या उत्पादनशीलता शब्द को सापेक्षिक (Relative) अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में किसी भी साधन के सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग सापेक्षिक अर्थ में ही होता है, क्योंकि कार्यक्षमता बिना तुलनात्मक व्याख्या के ज्ञात नहीं की जा सकती। भूमि के विषय में भी जब तक हम इसके दो टुकड़ों से प्राप्त उत्पादन की मात्रा की तुलना नहीं करते, तब तक यह नहीं कह सकते कि भूमि का अधिक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से अधिक उत्पादक या कार्यक्षम है।

---

\* "A factor of production, therefore, appears in its land aspect when it is considered as rendering its service without any sacrifice or cost."

—J. K. Mehta

भूमि की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व . भूमि की उत्पादन-शीलता या कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं :

1. भूमि के मौलिक गुण (Natural Conditions) : भूमि की उत्पादन-क्षमता उसके मौलिक एवं प्राकृतिक गुणों पर निर्भर है । भूमि का यह मौलिक गुण उसकी उर्वराशक्ति है । यदि किसी भूमि में अधिक उर्वरा शक्ति है तो उसकी उत्पाद-कता अधिक होगी । यह उर्वरा शक्ति अनेक प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे भूमि-विशेष की प्रकृति, उसकी रचना, मिट्टी की विस्म, उसमें रासायनिक एवं सजीव तत्वों की उपस्थिति आदि ।

2. स्थिति (Location) : भूमि की कार्यक्षमता उसकी स्थिति से प्रभावित होती है । मात्रकल वस्तुओं का उत्पादन भाग की पूर्ति करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, यहां तक कि विदेशी भाग, की पूर्ति के लिए भी किया जाता है । अतः भूमि की कार्यक्षमता इस बात पर भी निर्भर है कि उसकी उत्पादन-लाभन में बिक्री, खर्च या वितरण व्यय किस मात्रा में सम्मिलित है । यदि भूमि रेल और यातायात के अन्य साधनों, राहों व मण्डियों से दूर है तो उत्पादित वस्तु की अन्य स्थानों पर ले जाने में व्यय अधिक होगा जिससे भूमि की कार्यक्षमता कम मानी जायेगी ।

3. भूमि सुधार (Improvements) भूमि की उत्पादकता पर उसके सम्बन्ध में मनुष्य द्वारा किए गए सुधारों का भी प्रभाव पड़ता है । मनुष्य इन सुधारों के द्वारा भूमि के दोषों तथा प्राकृतिक असुविधाओं, जैसे भूमि का क्षरण (soil-erosion), क्षेत्रों में अनावश्यक जल का एकत्र होना (water-logging) आदि, को दूर करके भूमि की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है । इसी प्रकार अच्छी खाद, अच्छे बीज का प्रयोग करके, फसलों के हेर-फेर से सिंचाई का प्रबन्ध करके भूमि के मौलिक गुणों में वृद्धि करके तथा वनाग्नेयण आदि द्वारा भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है । अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा भूमि में सुधार करके उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है ।

4. संगठन की कार्य कुशलता (Organisational Efficiency) . भूमि का उचित उपयोग ही भूमि को अधिक सक्रिय एवं उत्पादक बना सकता है । यह कार्य भूमि का संगठनकर्त्ता करता है । वह भूमि को उपयुक्त कार्य में लगाकर उसे अधिक उत्पादनशील बनाता है । यदि उसका उपयोग उचित ढंग से नहीं किया जाये अर्थात् जिस कार्य के लिए वह अधिक उपयुक्त है यदि उसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं होता है, तो यह निश्चित है, कि उसकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होगी । यदि भूमि का संगठनकर्त्ता भूमि का मालिक भी है, तो वह अधिक धन तथा

पूँजी लगा कर भूमि की उत्पादकता तथा कार्य क्षमता को बढ़ाने में अधिक रुचि लेगा ।

5. अन्य परिस्थितियाँ : किसी देश की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ भी भूमि की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं । समाज में भूमि पर कार्य करने वालों का स्थाव एव धातुर, उनकी धार्मिक दशा, सामाजिक नियम तथा सरकार की नीति—ये कुछ ऐसे प्रभावकारी तत्व हैं जो भूमि की कार्यक्षमता में कमी या वृद्धि करते हैं ।

### प्रश्न व संकेत

1. भूमि की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा तत्वों की विवेचना कीजिए जिन पर भूमि की उत्पादकता निर्भर करती है ।

(Vik. B. A. 1964)

(संकेत : प्रश्न के प्रथम भाग में भूमि की परिभाषा दीजिए तथा दूसरे भाग में उन तत्वों का, जिन पर भूमि की उर्वरता निर्भर करती है, विवेचन कीजिए ।

2. भूमि की परिभाषा दीजिए । क्या यह उत्पादन का एक साधन है ? यह पूँजी से किस प्रकार भिन्न है ?

(Ald. B. A. I, 1963)

3. अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है ? उत्पादन के साधन के रूप में भूमि की विशेषताएँ तथा महत्व बताइए ।

(Ravi Shankar, 1965)

(संकेत : उत्पादन का अर्थ बताइए तथा प्रश्न के द्वितीय भाग में भूमि की विशेषताएँ तथा महत्व बताइए ।)

# 16

## श्रम व श्रम की कार्य-क्षमता (Labour and its Efficiency)

*"The term labour must be held to include the very highest professional skill of all kinds, as well as the labour of all skilled workers and artisans and we must include also not only that results in the permanent form, but also that renders services which perish in the act"*

—Nicholson

उ पादन के साधनो मे श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक साधनो के उपलब्ध होने पर भी यदि किसी देश मे मानव श्रम का अभाव है, तो वहा आर्थिक विकास की योजनायें शीघ्र पूरी नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास की नयी विचारधाराओ के अनुसार आर्थिक विकास या तो श्रम के अधिक होने अथवा पूँजी निर्माण से ही सम्भव हो सकता है। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियो ने भी राष्ट्रीय समृद्धि के लिए 'श्रम के परिमाण में वृद्धि' पर विशेष बल दिया था। प्रत्येक आर्थिक विचारधारा में उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में श्रम विचारणीय विषय रहा है।

### 1 श्रम का अर्थ (Meaning of Labour)

मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय "किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक परिश्रम से है, जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से, कार्य से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष भानन्द के अतिरिक्त, किसी अच्छाई के लिए किया जाता है।"<sup>1</sup> टामस ने मार्शल की परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है। "वे समस्त शारीरिक तथा मानसिक कार्य जो किसी पुरस्कार की आशा में किए जाते हैं, श्रम के

<sup>1</sup> "Any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good, other than the pleasure derived directly from the work, is called labour"

—Marshall

अन्तर्गत आते हैं।<sup>1</sup> जेवन्स ने अपनी पुस्तक 'Theory of Political Economy' में श्रम के अन्तर्गत केवल मनुष्य के उसी शारीरिक एवं मानसिक श्रम को सम्मिलित किया है, जिससे मनुष्य को दुख एवं कष्ट का अनुभव होता है। जेवन्स की इस परिभाषा का समर्थन मार्शल ने भी किया है। उनके अनुसार, "श्रम का आशय मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से।" (By labour is meant the economic work of man, whether done with the hand or the head) प्रो० निकलसन ने सभी प्रकार के मानवीय परिश्रम को श्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया है—'श्रम शब्द में सभी प्रकार की उच्चतम व्यावसायिक कुशलताओं के साथ ही साथ प्रकुमन श्रमिकों तथा कारीगरों के परिश्रम को भी सम्मिलित करना चाहिए। हम इस अन्तर्गत केवल उन व्यक्तियों के परिश्रम को ही सम्मिलित करना चाहिए जो सामान्य रूप से व्यवसाय में रहते हैं, वरन् उन व्यक्तियों के परिश्रम का भी सम्मिलित करना चाहिए जो शिक्षा, कलित कलाओं, साहित्य विज्ञान, व्यायाम-प्रशिक्षण तथा अनेक प्रकार की राजकीय सेवाओं में रहते हैं। हम न केवल उन परिश्रम को सम्मिलित करना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी उत्पादन होता हो, बल्कि उस श्रम को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए जिसके फलस्वरूप ऐसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जो पूरी होत ही नष्ट हो जाती हैं।'<sup>2</sup>

श्रम की उपर्युक्त परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि श्रम के लिए निम्न लिखित बातों का होना आवश्यक है

(1) श्रम के अन्तर्गत केवल मनुष्य के परिश्रम को ही सम्मिलित किया जाता चाहिए। पशुओं तथा मशीनों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ श्रम के अन्तर्गत नहीं आती, (ii) सभी प्रकार के मानव परिश्रम का चाहे उनका सम्बन्ध मनुष्य के शरीर से हो अथवा मस्तिष्क से—श्रम कहा जाता है, तथा (iii) व्ययज्ञान से

<sup>1</sup> "Labour connotes all human effort of body or mind, which is undertaken in the expectation of reward" —Thomas

<sup>2</sup> "The term labour must be held to include the very highest professional skill of all kinds, as well as the labour of unskilled workers and artisans we must include not only the labour of those engaged in business in the ordinary sense of the term but that of those employed in education, in fine arts, in literature, in science, in the administration of justice and in governments in all its branches, and we must include also, not only that results in the permanent form, but also that renders services which perish in the act" —Nicholson

श्रम कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका उद्देश्य आर्थिक स्वार्थ भयवा लाभ की आशा हो। अत्यन्त आनन्द के लिए किया गया परिश्रम अर्थशास्त्र में श्रम नहीं माना जाता।

अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय उन व्यक्ति-समूहों की श्रम शक्ति से है जो उत्पादन कार्यों के लिए उपलब्ध होती है। श्रम जैसा कि बेनहम ने कहा है, "श्रम का आशय श्रमिकों की सेवाओं से है न कि शक्तियों से, क्योंकि उनकी सेवा की ही उत्पादन पद्धति (Input) का एक अंग माना जाता है। कोई भी निपेक्षित श्रमिकों की सेवाओं तथा कार्यशैली घटो की मांग करता है, न कि व्यक्तियों के रूप में श्रमिकों की।" वस्तुतः व्यक्तियों की सेवाएँ ही उत्पादन कार्य में सहायक होती हैं। इस प्रकार उत्पादन की सम्भावनाओं पर विचार करते समय श्रम के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों की कार्य शक्ति तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं अथवा काम करने के लिए इच्छुक हो। किसी भी देश की प्रमुख समस्या बड़ा पर उपलब्ध श्रम शक्ति के अधिकतम उपयोग की होनी है तथा इसी आधार पर बड़ा उत्पादन की मात्रा तथा आर्थिक विकास की योजनाएँ निर्धारित एवं निमित्त की जाती हैं।

## 2. श्रम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)

श्रम में कुछ ऐसी मौलिक एवं स्वामाविक विशेषताएँ हैं जिनके कारण वह उत्पादन के अन्य साधनों से भिन्न माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि श्रम करने वाला श्रमिक एक चेतन प्राणी है जबकि अन्य साधन जड़-पदार्थ हैं। श्रम उपकरणों का सृजन अपने (श्रमिकों) लिए ही करता है। अतः वह उत्पादन का माधन और माध्य दोनों ही माना जाता है। इस आधार पर श्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(1) श्रम और श्रमिक एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते (Inseparable) श्रम और श्रमिक एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। श्रमिक के छुट रहने पर ही उसका श्रम प्राप्त होता है। श्रमिक की अनुपस्थिति में उसकी सेवाएँ प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी स्थान पर कार्य करने के लिए तैयार होने पर मजदूर या श्रमिक को स्वयं बड़ा जाकर काम करना पड़ता है। अतः पृथक् और भूमि की तरह श्रम अपने मालिक (श्रमिक) से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता। यही कारण है कि श्रमिक को अपना श्रम बेचने के लिए कार्य स्थान पर स्वयं जाना पड़ता है तथा उसकी गतिशीलता में रुकावट आती है।

(2) श्रम स्वयं शीघ्र नाशवान है (Perishable) . श्रमिक का श्रम विलोप्य वायव्य वस्तु है। यदि हर रोज का श्रम बेचा न जाय तो वह धन की तरह इकट्ठा



नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में यदि कोई श्रमिक एक दिन काम न करे तो उस दिन का श्रम नहीं होता। समय के बीतते ही उस दिन काम में न लाया गया श्रम भी बेकार हो जाता है। यही कारण है कि श्रमिक अपना श्रम बेकार धर्दा नहीं होने देता। वह उसे किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से ही यह कहा जाता है कि श्रमिक का श्रम बहुत ही नाशवान है।

(3) मालिकों के मुकाबले में श्रम की सौदा करने की ताकत कमजोर होती है (Weak bargaining power)। काम में नहीं लेने पर श्रम के धर्दा हो जाने के कारण ही मालिक श्रमिकों में अपने श्रम को फौरन बेचने की मजदूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं और उनके श्रम को कम से कम कीमत या मजदूरी पर खरीद लेते हैं। श्रमिकों में संगठन की कमी होने की वजह से काफी समय तक इन्जाम भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्हें मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को स्वीकार करना पड़ता है। मालिक श्रम के इस दोष का फायदा उठाकर उनकी कम मजदूरी देना चाहते हैं तथा उनका शोषण करते हैं।

(4) श्रम की पूर्ति में बढ़ोतरी या कमी जल्दी हो नहीं की जा सकती : मजदूरी की पूर्ति की मात्रा जनसंख्या पर तथा उनके गुण उनकी कार्य-कुशलता पर निर्भर है। जनसंख्या तथा कार्य-कीर्जन में बढ़ोतरी जल्दी न हो सकने से थोड़े ही समय में श्रम की पूर्ति जल्दी ही नहीं बढ़ायी जा सकती।

(5) श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है (Active factor of production) : श्रम उत्पादन का सन्निध साधन है, क्योंकि श्रम ही दूसरे सभी साधनों को उत्पादन के कामों में लगाता है। श्रम के बिना हमारे साधन खुद उत्पादन नहीं कर सकते। खुद काम न करने वाले (निष्क्रिय) साधनों में भूमि, पूंजी इत्यादि शामिल हैं।

(6) श्रम में बुद्धि तथा निर्णय शक्ति का होना : प्रो० कैमरनक्रॉस (Prof Cairncross) का कहना है कि उत्पादन साधनों में श्रम ही एक ऐसा साधन है जिसमें बुद्धि (intelligence) तथा निर्णय शक्ति (power of judgement) है। यही कारण है कि वह हमारे सभी साधनों को संगठित करता है और मजदूर के रूप में उन पर काम करके उनकी उपयोगिता बढ़ाता है। यह यन्त्र की तरह नहीं है। अतः कोई दूसरा साधन उगरी जगह नहीं ले सकता।

(7) श्रमिक का श्रम ही बेचा जा सकता है, श्रमिक नहीं जैसा कि मार्शल ने कहा है, श्रमिक अपने श्रम को बेचता है, अपने आपको नहीं। इसका मतलब यह कि श्रमिक अपने शरीर तथा अपनी कार्य-कुशलता का हमेशा मालिक बना रहता है। वह अपने शरीर की मेहनत तथा कार्य-कुशलता को जिसे वह बिफ्री योग्य वस्तु समझता है, ही बेचता है। कार्य-कुशलता रूपी पूंजी वह अपना श्रम बेचकर धीरे-धीरे

वसूल करता है। इनके साथ ही साथ उसकी यह सम्पत्ति उससे अलग भी नहीं की जा सकती। वह उसके शरीर के साथ गतिशील रहता है।

(8) थम, भूमि और संपत्ति की तुलना में, गतिशील है (Mobile) : भूमि को स्थिर, परन्तु थम को गतिशील माना जाता है। इसका कारण यह है कि भूमि का स्थान नहीं बदला जा सकता है, परन्तु थम को स्वयं अपने काम की जगह पर जाना पड़ता है। वह व्यवसाय अथवा स्थान आसानी से बदल सकता है। परन्तु पूँजी की तुलना में थम को कम गतिशील माना जाता है।

(9) थम की पूर्ति पर अन्य वस्तुओं की पूर्ति की तरह, (मजदूरी) का प्रभाव नहीं पड़ता : अर्थशास्त्र में पूर्ति का नियम यह बतलाना है किसे वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उनकी पूर्ति बढ़ती है और उसका मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति कम हो जाती है। परन्तु थम के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता है। थमिकों की मजदूरी अधिक होने पर भी थमिकों की पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि बहुत से थमिक काफी मजदूरी कमा लेने पर कुछ दिन काम में गैर हाज़िर रहकर आराम करना चाहते हैं।

मजदूरी कम होने पर भी थम की पूर्ति बढ़ सकती है। थमिक अधिक से अधिक काम करके अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी, पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे थम की पूर्ति बढ़ जाती है। भारतीय थम की यह खास विशेषता है।

(10) थमिक एक साथ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है (Labour is both means and end of production) . भूमि तथा पूँजी उत्पादन के ऐसे साधन हैं जो केवल उत्पादन में ही सहायक होते हैं। इन साधनों की पूर्ति करने वाले उत्पादित वस्तु को बेचने पर मिनी कीमत का एक छोटे से छोटा भाग उपयोग के लिए प्रयोग में लाते हैं। परन्तु थमिक न केवल उत्पादन करता है, बल्कि साथ ही साथ उसका उपयोग भी करता है।

निष्कर्ष थम की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर ही उसके परिमाण सम्बन्धी पहलू (Quantitative Aspect) तथा गुण सम्बन्धी पहलू (Qualitative Aspect) पर विचार किया जा सकता है।

(1) परिमाण सम्बन्धी पहलू या पहलू (Quantitative Aspect) : थम थमिक से अलग नहीं है। अतः थम की मात्रा थमिकों की संख्या के बढ़ने पर ही सम्भव है। थमिकों की संख्या जनसंख्या के बढ़ने पर ही निर्भर करती है, परन्तु जनसंख्या में वृद्धि तथा थम की पूर्ति (Supply of Labour) धीरे धीरे ही कई वर्षों में सम्भव हो पाती है। थम की पूर्ति जनसंख्या के सिद्धांत पर आधारित है।

थमिकों की पूर्ति कार्य-क्षमता बढ़ाकर भी की जा सकती है। इस प्रकार

श्रम की तत्कालीन मांग की आंशिक पूर्ति सम्भव हो पाती है। परन्तु इसमें भी थोड़ा समय लगता है। श्रम की मांग शीघ्र न बढ़ सकने के कारण ही कभी-कभी जब इसकी मांग अधिक होती है, तब इसकी मजदूरी बढ़ जाती है। परन्तु मांग कम होने पर श्रम की तत्कालीन पूर्ति घटायी नहीं जा सकती अतः मजदूरी कम हो जाती है।

जहाँ तक श्रम की मांग का मवाल है यह एक व्युत्पन्न मांग (derived demand) है। इसका कारण यह है कि श्रम उत्पादक होने पर ही उपयोगिता गगता है। उसकी उत्पादकता की म्हायता से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उपभोग वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो पाता है। यदि उसमें उत्पादकता या कार्य करने की क्षमता नहीं हो, तो उसकी मांग नहीं होगी।

(ii) गुण सम्बन्धी पक्ष या पहलू (Qualitative Aspect) : यह पक्ष श्रमिकों की कार्य क्षमता से सम्बन्धित है। श्रमिकों की कार्यक्षमता उचित शिक्षा, अधिक मजदूरी, काम के कम घण्टों तथा आराम की सुविधायें देकर तथा श्रम में मानवीय तत्वों का विज्ञान करके बढ़ायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में भी श्रम को श्रमिक से अलग नहीं होने वाले लक्षणों की ध्यान में रखा जाता है।

### 3 श्रम का वर्गीकरण (Classification of Labour)

अर्थशास्त्र में श्रम को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है :

(1) उत्पादक श्रम (Productive Labour) और अनुत्पादक श्रम (Unproductive Labour) : किस प्रकार के श्रम को उत्पादक तथा किस प्रकार के श्रम को अनुत्पादक माना जाय ? इस बात पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों तरह के श्रम में जो भेद या भन्तर की रेखा निश्चित की है, वह इस प्रकार है :

वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों (Mercantilists) का मत : चूंकि इन अर्थशास्त्रियों का राय उर्द्ध्व देश में सोने (gold) की मात्रा को बढ़ाना था, इसलिए इनके अनुसार केवल वह श्रम जिसके द्वारा निर्यात के लिए वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उत्पादक श्रम कहलाता था और अन्य सभी प्रकार का श्रम अनुत्पादक था।

निर्वाहवादी (Physiocrats) का मत था कि वह श्रम जो प्राथमिक उद्योगों (Primary industries) तथा व्यवसायों के उत्पादन कार्यों में लगा हो वही उत्पादक श्रम है और बाकी कामों में लगा हुआ श्रम अनुत्पादक है। इन अर्थशास्त्रियों का कहना था कि कृषि, खानों से धातु निकालना, मछली पकड़ना आदि कुछ ऐसे उद्योग एवं व्यवसाय हैं जिनमें प्रकृति मनुष्य की मदद करती है और जगकी मेहरबानी की वजह से ही उत्पादन बढ़ता है। अतः इन उद्योगों में लगा श्रम उत्पादक है। परन्तु

अन्य प्रकार के कार्यों, जैसे सेवाएँ, व्यापार, अन्य औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, में प्रकृति मदद नहीं करती। उत्पादक उत्पादन के लिए अपनी मेहनत पर निर्भर है अतः इन कामों में लगा श्रम अनुत्पादक है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का मत : प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ तथा जे० एस० मिल ने केवल उसी श्रम को उत्पादक माना जो भौतिक और मूर्त पदार्थों (Material and tangible goods) का उत्पादन करता था। उनके विचार से अमौलिक तथा अमूर्त पदार्थों का उत्पादन करने वाला श्रम अनुत्पादक श्रम था। श्रम को इस आधार पर उत्पादक तथा अनुत्पादक वर्गों में रखने पर ऐसे लोगों के श्रम को, जो अन्न, वस्त्र, मेज, बर्तन मशीनों आदि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादक श्रम कहा जाता है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों के श्रम का बकील, डाक्टर, अध्यापक, गायक, घरेलू नौकर, पुजारी, कलाकार आदि क रूप में केवल अपनी सेवाएँ देते हैं, अनुत्पादक श्रम कहा जाता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्रम को एक वस्तु (Commodity) की ही तरह मानते थे। उनके विचार से किसी भी व्यक्ति की सेवा तथा श्रम को किसी वस्तु की तरह बेचा या खरीदा जा सकता है। इस प्रकार उनके अनुसार प्रतिमय की विशेषता के कारण श्रम का मूल्य मांग तथा पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित की जा सकता है। परन्तु यह विचारधारा गलत है। इस युग में दासों का क्रम विक्रय अवैध माना जाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के साथ वस्तु की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। श्रम के साथ स्वयं व्यक्ति विक्रि जाता है। उसका व्यक्ति-व समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार घटायी-बढ़ायी जा सकती है परन्तु अमिकों की मर्यादा अथवा श्रम की मात्रा आवश्यकतानुसार न तो सीधे ही बढ़ानी या सकती है और न ही वह घटायी जा सकती है। श्रम मशीनों तथा वस्तुओं की तरह किसी अन्य वस्तु से प्रतिस्थापित (Substitute) भी नहीं किया जा सकता वह वस्तुओं की तरह न तो गतिशील (mobile) है और न ही निष्क्रिय। उसकी भावनाएँ, उसकी परिस्थितियाँ तथा उसके विचार उसे गतिशील बनाते हैं। श्रम का प्रयोग ही उसे सक्रिय बनाना है। प्रयोग नहीं होने पर उसे संचय भी नहीं किया जा सकता। इन कारणों से श्रम को भी वस्तु मानना ठीक नहीं होगा।

वर्तमान विचारधारा (Modern concept) : आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत उपर्युक्त दोनों मतों से अलग है। उनका कहना है कि उत्पादन का उद्देश्य उपयोगिता का सृजन एवं निर्माण या उसमें वृद्धि करना है। अतः वह श्रम को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में उपयोगिता या आवश्यकता को पूर्ण करने की शक्ति का सृजन या उस वृद्धि करने के लिए किया जाता है उदाहरण श्रम कहना है। वह श्रम जिससे न तो उपयोगिता या आवश्यकता को पूर्ण करने की शक्ति का सृजन ही होता

है और न उपयोगिता में वृद्धि ही होती है, अनुपादक धर्म कहा जाता है। इस प्रकार वर्तमान मत के अनुसार, धर्मो धर्म उत्पादक धर्म कहा जा सकता है जिनके करने पर मनुष्य वास्तव में अपने उद्देश्य में सफल हो जाये। यदि वह धर्म करने पर भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, तो उसका धर्म अनुत्पादक होता है। यदि वह अपने परिश्रम में कुछ समय तक ही सफल हो जाता है, तो जिस सीमा तक वह सफल होगा, उस सीमा तक ही किया गया धर्म उत्पादक होगा और बाकी अनुत्पादक। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका धर्म न तो उत्पादक (Productive) होता है और न अनुत्पादक (Unproductive) बल्कि 'उत्पादन-विरोधी' (Disproductive) होता है। टासिज (Tassie) ने इस उत्पादक-विरोधी धर्म को भी अनुत्पादक माना है। इन तीनों प्रकार के धर्म को निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति दीर्घकाल तक परिश्रम करने के बाद एक पुस्तक लिख कर समाप्त करता है और उसकी पुस्तक प्रकाशित हो जाए, तो उसका धर्म उत्पादक कहलायेगा। परन्तु यदि पुस्तक प्रकाशित नहीं होती और उनके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाती है, तो उसका धर्म अनुत्पादक कहा जायेगा। टासिज के अनुसार चार, ठम, समाज-शोषकों तथा अन्य व्यक्तियों के धर्म पर पलने वाले व्यक्तियों को अनुत्पादक धर्मिक कहते हैं। परन्तु वास्तव में ये व्यक्ति समाज विरोधी हैं। मत इनके धर्म को उत्पादन-विरोधी धर्म कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

परन्तु वर्तमान विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं, (प्रो० बेहन्म आदि) जिनका मत है कि धर्म के क्षेत्र या उद्देश्य की सफलता के आधार पर उत्पादन तथा अनुत्पादक वर्गों में बांटना ठीक नहीं है। इन अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि यदि कोई काम करने पर धर्मिक की आय प्राप्त होती हो अर्थात् धर्मिक द्वारा मूल्य सृजन (Production of Value) हो, तो ऐसे धर्म को उत्पादक धर्म कहना चाहिए और यदि किसी कार्य के करने पर आय प्राप्त नहीं होती हो या मूल्य-सृजन नहीं हो, तो उसे अनुत्पादक धर्म मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर बेहन्म ने कहा है : "किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि उसका धर्म उसकी आय का साधन हो, तो वह उत्पादक धर्म है। यह धर्म कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उत्पादक है या नहीं, सामाजिक दार्शनिकों के लिए सोचने की बात है, न कि अर्थशास्त्रियों के लिए।"

4 'From the standpoint of the individual his work is productive, if it procures him an income. The question, whether a particular kind of work is productive from the standpoint of the community, is really a question for social philosophers, not economists'

## (ब) कुशल तथा अकुशल श्रम (Skilled and Unskilled labour) :

जिस मानसिक अथवा शारीरिक श्रम को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा तथा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है उसे कुशल श्रम कहते हैं। इसके विपरीत जो श्रम बिना किसी विशेष शिक्षा के किया जाता है, उसे अकुशल श्रम कहते हैं। डाक्टर तथा इन्जिनियर का श्रम कुशल श्रम है, लेकिन एक कुली और धरेलू नीकर का श्रम अकुशल श्रम है। कोई श्रम कुशल है अथवा अकुशल, यह देश अथवा काल पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देश का कुशल श्रम अमेरिका जैसे विकसित देश के लिए अकुशल श्रम हो सकता है।

श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण इसी वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। सामान्यतया एक कुशल श्रमिक एक अकुशल श्रमिक की अपेक्षा अधिक मजदूरी प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि कुशल श्रमिक की उत्पादकता (Productivity) अकुशल श्रमिक से अधिक होती है। परन्तु कुशल तथा अकुशल श्रम का अन्तर औद्योगिक विकास, शिक्षा-प्रसार तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण की विद्यमान सुविधाओं द्वारा दूर किया जा सकता है।

## (स) मानसिक तथा शारीरिक श्रम (Mental and Physical Labour) :

जब किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे श्रम को मानसिक श्रम कहते हैं। इसके विपरीत किसी कार्य करने में जब मस्तिष्क की अपेक्षा शरीर से अधिक काम लिया जाता है, तब यह श्रम शारीरिक कहलाता है। अध्यापक का श्रम मानसिक श्रम है, परन्तु एक कुली का श्रम शारीरिक श्रम है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है और कोई भी शारीरिक कार्य बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए सम्भव नहीं हो सकता। अतः पूर्ण शारीरिक श्रम सम्भव नहीं है।

### 1. श्रम की कार्य-कुशलता (Efficiency of Labour)

किसी देश में श्रम की पूर्ति दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है—प्रथम, जन-संख्या में वृद्धि द्वारा, तथा द्वितीय, उपलब्ध श्रम शक्ति की कार्य-कुशलता में वृद्धि द्वारा। श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर उनकी संख्या की कमी की पूर्ति हो जा सकती है। अतः वर्तमान 'आर्थिक विकास-नीति' में श्रम की कार्य-कुशलता में वृद्धि को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

#### (i) श्रम की कार्य-कुशलता का अर्थ -

एक निश्चित समय में, अन्य बातों के समान रहने पर, श्रम द्वारा अधिक

माना में अथवा उत्तम किस्म का या दोनों प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन करने की शक्ति, योग्यता तथा क्षमता को श्रम की कार्य-कुशलता कहते हैं। श्रम की कार्य-कुशलता एक सापेक्षिक और तुलनात्मक घाटणा है। हम समान दशाओं में दो श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करके ही यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा श्रमिक अधिक कार्य-कुशल है। यदि एक श्रमिक, समान परिस्थितियों में, दूसरे श्रमिक से अधिक वस्तुएं या उससे अच्छी किस्म की वस्तुएं उत्पादित करता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पहला श्रमिक दूसरे श्रमिक की तुलना में अधिक योग्य एवं अधिक कार्य-कुशल है। अतः समान परिस्थितियों में, एक निश्चित समय में किसी श्रमिक द्वारा माना में अधिक या किस्म में अच्छी प्रयत्ना मात्रा तथा किस्म दोनों में ही अधिक व अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करने की शक्ति को श्रम की कार्य-क्षमता कहा जाता है।

श्रम की कार्य-कुशलता की तुलना एक ही प्रकार के कार्य तथा समान परिस्थितियों में की जाती है। यदि सूती मिलों के श्रमिकों की कार्य-क्षमता की तुलना कोट्टे तथा इलाख के कारखानों के श्रमिकों की कार्य-क्षमता से की जाये, तो दोनों के कार्यों की प्रकृति तथा स्वभाव में अन्तर होने के कारण कार्य-क्षमता की तुलना करना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार श्रम की कार्य-कुशलता उसकी उत्पादनता या उत्पादनशीलता (Productivity) के आधार पर जानी जाती है। प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता की तुलना एक निश्चित समय तथा क्षेत्र में श्रमिक या सीमान्त उत्पादकता से की जाती है। यदि किसी श्रमिक द्वारा श्रमिक या सीमान्त उत्पादन में अधिक मात्रा में या उत्तम वस्तु या अधिक मात्रा में उत्तम वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे अधिक कार्य-कुशल श्रमिक कहा जाता है। यदि उसके द्वारा श्रमिक या सीमान्त उत्पादन के बराबर ही उत्पादन किया जाता है तो उसे श्रमिक या सीमान्त श्रमिक कहते हैं, परन्तु जब कोई श्रमिक श्रमिक उत्पादन से कम मात्रा में या श्रमिक किस्म से खराब वस्तुओं का उत्पादन करता है, तब उसे अयोग्य एवं अकुशल श्रमिक कहा जाता है।

श्रमिक या सीमान्त उत्पादकता का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है—  
उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर तथा लागत के आधार पर। उदाहरणार्थ, किसी एक समय-विशेष में उत्पादन के अन्य साधनों में परिवर्तन किए बिना, यदि 3 श्रमिकों के द्वारा 30 इकाइयां उत्पादित की जाती हैं और प्रत्येक श्रमिक प्रथम श्रमिक 8 इकाइयां, द्वितीय श्रमिक 10 इकाइयां तथा तृतीय श्रमिक 12 इकाइयां उत्पादित करता है, तो उनका श्रमिक उत्पादन 10 इकाई हुआ। इस स्थिति में पहला श्रमिक प्रमुख, दूसरा श्रमिक कार्यकुशल तथा तीसरा श्रमिक अन्य दोनों श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि अन्य उत्पादन साधनों में

परिवर्तन किये बिना चौथे श्रमिक को लगा लिया जाये और उसकी उत्पादकता 9 इकाइयों के बराबर हो तो कुल उत्पादन में 9 इकाइयों की वृद्धि होने पर सीमान्त उत्पत्ति 9 के बराबर होगी। इस स्थिति में दूसरा तथा तीसरा श्रमिक अधिक कार्य कुशल कहा जाएगा, चौथे श्रमिक की कार्य कुशलता सीमान्त कही जायेगी और पहला श्रमिक अकुशल माना जायेगा।

लाभ के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कितनी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले लाभ की तुलना श्रम की लागत से की जानी है। यदि उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मूल्य में से अन्य साधनों के पारितोषिक (rewards) घटाने के बाद शेष भाग श्रमिक को मजदूरी के बराबर ही रह जाती है अथवा कम हो जाती है तो श्रम को कार्यकुशल नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन कम होने से लाभ कम हुआ है। उत्पादन कम होने का अर्थ यह है कि श्रम की कार्य-क्षमता या कार्य कुशलता कम है। अन्य बातों के समान रहने पर लाभ में वृद्धि कार्य-क्षमता में वृद्धि को व्यक्त करती है तथा लाभ में कमी कार्य-क्षमता में कमी बतानी है। अतः श्रम की कार्य कुशलता उस पर किए जाने वाले व्यय से तथा उसमें प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना के आधार पर अन्य बातों के समान रहने पर ही निर्धारित की जाती है।

## (ii) श्रम की कार्य कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व :

श्रमिकों की उत्पादकता तथा कार्य कुशलता पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों के श्रम की कार्य-क्षमता को प्रभावित करने वाले कारण भी अलग अलग होते हैं। पैसन ने इस विभिन्नता के कारणों के सम्बन्ध में कहा है — “श्रम की कार्य कुशलता आंशिक रूप से मालिक या नियोक्ता पर तथा आंशिक रूप से श्रमिकों पर, आंशिक रूप से संगठन पर और आंशिक रूप से व्यक्तिगत प्रयत्न पर, अतः श्रमिक को प्रदान किए गए औजारों, यन्त्रों आदि पर और कुछ अंश तक श्रमिक द्वारा उन उपकरणों को प्रयोग करने की दक्षता तथा परिश्रम पर निर्भर है।”<sup>1</sup> श्रम की कार्य-क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों को चार वर्गों में रखा जा सकता है : (1) श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, (2) देश की परिस्थितियाँ, (3) कार्य करने की परिस्थितियाँ, (4) संगठन एवं प्रबन्ध की योग्यता, तथा (5) विविध।

<sup>1</sup> “Efficiency of labour depends partly on the employer and partly on the employed, partly on organisation and partly on individual effort, partly on tools, machinery etc, with which the worker is supplied and partly on his own skill and industry in making use of them.”



## (1) धर्मिकों के व्यक्तिगत गुण :

(i) पैतृक तथा जातीय गुण (Hereditary and Racial Qualities) : धर्मिक पर वंशगत परम्पराओं का भी प्रभाव पड़ता है। मां बाप के स्वस्थ, मेहनती, योग्य तथा बुद्धिमान होने पर उनके बच्चों में निस्सन्देह कार्य-क्षमता तथा कार्य करने की योग्यता अधिक होगी। जन्म से ही अच्छे वातावरण में रहने वाला धर्मिक अधिक कार्य-कुशल होगा। परन्तु आजकल धर्म की कार्य कुशलता का निर्धारित करने वाले तरीकों में जातीय तथा वंशगत गुणों को अधिक महत्व नहीं प्रदान किया जाता। उचित प्रशिक्षण द्वारा किसी भी जाति के व्यक्ति को योग्य एवं कुशल धर्मिक बनाया जा सकता है।

(ii) स्वास्थ्य (Health) : धर्मिक का स्वास्थ्य ही उसकी 'पूर्वी' है, क्योंकि उसकी कार्य-क्षमता उसी पर आधारित है यदि धर्मिक स्वस्थ है तो वह अधिक से अधिक कार्य करने पर भी नहीं थकता जिससे उनकी उत्पादनशीलता अधिक होती है।

(iii) सामान्य तथा विशेष शिक्षा (Education and Training) : धर्मिकों की कार्य-कुशलता पर उनकी शिक्षा-दीक्षा का अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से समझने तथा करने की क्षमता रखता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति किसी कार्य को समझने तथा करने में काफी समय लेता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य करने में विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए धर्मिकों का विशेष रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। अपनी योग्यता अनुसार तकनीकी (Technical Education) शिक्षा प्राप्त करने पर धर्मिक अधिक कार्य-कुशल होता है।

(iv) नैतिक गुण : देश के अन्दर नैतिकता का स्तर ऊँचा होने पर धर्मिक सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करता है। यदि देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार, वैईमानी और अनैतिक कार्यों का ही बोलबाला हो तो धर्मिक वर्ग धार्मिक-विरुद्ध खड़े होता है। उसमें उत्साह-परामर्शता की कमी होती है। यदि देश में गरीबी अधिक है तो धर्मिक अनैतिकता का शिकार हो जाता है। इससे उनकी कार्य-क्षमता कम हो जाती है। शिक्षित होने के साथ-साथ धर्मिक के स्वचरित होने पर भी उसकी कार्य-क्षमता अधिक होती है।

## (2) देश की परिस्थितियाँ :

(i) जलवायु (Climate) : देश या क्षेत्र की जलवायु धर्मिकों की कार्य-क्षमता को प्रभावित करती है। गर्म देश में रहने वाला धर्मिक सुलभ और आनंदी होता है, जबकि शीत जलवायु आनन्दप्रद और शक्ति-वर्धक होने के कारण धर्मिकों को अधिक परिश्रमी बनाती है।

(ii) सामाजिक वातावरण ( Social Conditions ) : जहाँ पर जातीय परम्पराओं के अनुसार कार्य के चुनाव के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध होते हैं तथा श्रमिक की गतिशीलता उनसे प्रभावित होती है और यदि सन्तुष्ट कुटुम्ब का बोझ उसे उठाना पड़ता है, तो ऐसे सामाजिक वातावरण में रहने वाला श्रमिक की कार्य-क्षमता कम होती है। पश्चिमी राष्ट्रों में 'व्यक्तिवाद' (Individualism) मान्यताओं का यह लाभ हुआ है कि श्रमिक व्यक्तिगत उत्थान के लिए अधिक प्रयत्न करता है।

(iii) राजनैतिक परिस्थितियाँ (Political Conditions) : श्रम की कार्य-क्षमता पर देश की राजनैतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश स्वतन्त्र है तो वहाँ के श्रमिक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से करते हैं। स्वतन्त्र होने पर वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझते हैं, अतः उनकी कार्य-क्षमता अधिक होती है। देश में राजनैतिक अस्थिरता तथा अव्यवस्था का प्रभाव भी श्रमिकों की कार्य-क्षमता पर पड़ता है। गान्धि जी की मुरदा का वातावरण रहने पर कार्य करने में श्रमिकों की रुचि अधिक होती है जिससे उनकी उत्पादना में वृद्धि होती है।

### (3) कार्य करने की परिस्थितियाँ

(1) कार्य में रुचि तथा कार्य करने की इच्छा : श्रमिक की कार्य-क्षमता उस समय अधिक होती है जब वह अपने कार्य में अधिक रुचि लेता है। उसकी रुचि के अनुसार कार्य होने पर वह उसे मन लगाकर करता है जिससे वह अधिक काम कर पाता है। इस प्रकार की इच्छा उसी समय उत्पन्न हो सकती है जबकि वह कार्य उसकी आन्तरिक योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। अतः श्रमिकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनकी मानसिक स्थिति का अध्ययन आवश्यक होता है। जहाँ पर औद्योगिक मनोविज्ञान ( Industrial Psychology ) के आधार पर श्रमिकों की मनोदशा का अध्ययन करके उनके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाता है, वहाँ श्रमिकों को अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुसार काम मिलने पर उनकी कार्य-क्षमता अधिक होती है।

(ii) उचित पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधायें (Fair wages and other Facilities) : यदि श्रमिक उचित मजदूरी प्राप्त करता है तो वह अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकता है। यदि उसे पौष्टिक भोजन, हवादार मकान तथा बीमारी के समय चिकित्सा आदि के लिए पर्याप्त मजदूरी मिलती है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। जहाँ पर धन, वेतन तथा सामाजिक सम्बन्धी योजनाएँ अपनायी जाती हैं, वहाँ श्रमिक अधिक कार्य-कुशल होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आने वाली बीमा योजनाएँ तथा

आर्थिक सहायता-योजनाओं की व्यवस्था होने पर श्रमिक को कार्य करने के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है तथा उसकी कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। मविप्य में उत्पत्ति की आशा भी उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। श्रमिक के स्वास्थ्य पर कार्य के घण्टों तथा कार्य-स्थान के वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि श्रमिक का कार्य स्थान स्वच्छ, हवादार व प्रकाश-युक्त नहीं है तो इनका श्रमिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उसकी कार्य-क्षमता कम होती है।

(iii) अच्छे औजार, उपकरण तथा उत्पादन की वैज्ञानिक प्रणाली : यदि श्रमिकों को अच्छे निस्म का बच्चा मात, अच्छे औजार तथा उपकरण प्राप्त हो और उत्पादन के अन्य साधनों के साथ श्रम का उचित सामञ्जस्य हो तो श्रमिक की कार्य क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी। उत्तम तथा वैज्ञानिक उत्पादन-प्रणाली भी श्रमिक की कार्य-क्षमता में वृद्धि करती है।

(iv) कार्य के घण्टे : श्रमिक कई घण्टे लगातार काम करने पर थक जाता है। इससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। यदि श्रमिकों को कुछ घण्टे काम करने के बाद थोड़ा आराम कर लेने दिया जाय तो उसने उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त यदि प्रति सप्ताह काम करने के घण्टों में कमी कर दी जाय, तथा सप्ताह के अन्त में मनोरंजन व आराम के लिए पर्याप्त समय दिया जाय, जैसा कि कई पश्चिमी देशों में किया गया है, तो भी श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

(v) श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था : मजदूरों की कार्य-क्षमता पर मालिकों तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण (Welfare) तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। किसी देश में इनकी पूर्ण व्यवस्था होने पर श्रमिकों की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता अधिक होती है। राज्य बीमा, नृदावस्था पेन्शन, बीमारी तथा दुर्घटना में आर्थिक सहायता, प्राविडेंट फण्ड तथा ग्रैजुइटी आदि के होने पर श्रमिक को मविप्य की चिन्ता नहीं रहती। वह अपने वर्तमान पारिवर्त्मिक से अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है।

(4) सफल एवं प्रयत्न की योग्यता :

(i) प्रयत्न योग्यता : यदि श्रमिकों को उनकी योग्यता तथा इच्छा के अनुसार काम पर लगाया जाता है। उत्पादन के अन्य साधनों के साथ श्रम का उचित अनुपात में समायोजन किया जाता है, श्रम विभाजन की वैज्ञानिक ढंग पर व्यवस्था की जाती है, उनको नियुक्ति उपयुक्त ढंग से की जाती है तो श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

(ii) श्रमिकों तथा मालिकों के बीच अच्छा सम्बन्ध : मालिक और श्रम के सम्बन्ध ठीक रहने पर लोकतन्त्रीय प्रणाली के माध्यम पर सह-अवन्ध, कार्य-समितियों

आदि की व्यवस्था को स्वीकार करने पर तथा धर्मिकों की रुचि तथा उनकी प्रति प्रियाओं पर विशेष ध्यान देने पर धर्मिक मालिक के हितों को ध्यान में रखते हैं तथा अधिक काम करते हैं। उनकी सघन शक्ति को उचित मान्यता प्रदान करने पर धर्मिकों की कार्यक्षमता नि सन्देह बढ़ती है।

#### (4) विविध

(1) धर्मिक संघों (Trade Unions) का प्रभाव धर्मिक संघों का भी धर्म की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ये संघ धर्मिकों को संगठित करके उनके मालिकों से उनकी भागों की पूर्ति कराने में सहायक होते हैं जिससे धर्मिक उस श्रम से निश्चित रह कर अपना कार्य करने में अधिक समय देता है। इन संघों द्वारा धर्मिकों की शिक्षा दीक्षा, उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। हड़तालें, तालाबन्दी आदि आन्दोलन के समय में धर्मिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार धर्मिक संघ धर्मिकों के मानसिक, नैतिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा रखने में सहायक होते हैं। इन गुणों का विकास होने पर धर्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

(ii) धर्मिकों में अधिक गतिशीलता यदि धर्मिक एक ही स्थान तथा व्यवसाय में स्थायी रूप से काम नहीं करते, बल्कि हमेशा व्यवसाय या पेशा बदलते रहते हैं, तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है।

उपरोक्त तत्वों एवं परिस्थितियों के अनुकूल होने पर धर्मिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। उचित मजदूरी, काम करने की अनुकूल दशाओं कारणों के अन्दर प्राप्त सुविधाओं, दश का सामान्य वातावरण, धर्मिक के सहकारी, उचित जीवन-स्तर, आवश्यक प्रशिक्षण अच्छी उत्प्रेरणा प्रणाली, अच्छा प्रबंधन सरकार तथा अन्य समस्याओं द्वारा किए गए धर्म कल्याण सम्बन्धी कार्यों और धर्मिकों को प्राप्त सुविधाओं तथा सम्मान आदि का धर्मिकों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। धर्मिकों की उच्च कार्य क्षमता राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्र को समृद्धिशील बनाती है।

#### भारतीय धर्म की कार्य-क्षमता (Efficiency of Indian Labour)

अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि के धर्मिकों से भारतीय धर्मिकों की तुलना कर यह कहा जाता है कि भारतीय धर्म की कार्यक्षमता अत्यन्त ही कम है। भारत, अमेरिका, तथा लक्जम्बर्ग (ब्रिटेन) में सूती वस्त्र उद्योग में प्रति एक हजार तन्तुओं पर काम करने वाले धर्मिकों की औसत सराया क्रम 22 4 5 तथा 6 7 है, लाह-इस्पात उद्योग में अमेरिका के धर्मिकों की उत्पादित भारतीय धर्मिक से दस गुनी है। इसी प्रकार कोयला उद्योग में भारतीय धर्मिक का उत्पादन अमेरिका के धर्मिक

के उत्पादन का केवल  $\frac{1}{3}$  तथा ब्रिटेन के श्रमिक के उत्पादन का केवल  $\frac{1}{5}$  भाग है। ये तथ्य सत्य हैं, परन्तु भारतीय श्रमिक को अन्य औद्योगिक देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत ही कम वास्तविक मजदूरी प्राप्त होती है, उसका जीवन स्तर निम्न है, काम करने की दशाएं आदर्श नहीं हैं, उसे वे सुविधाएं, वातावरण, मशीन तथा उपकरण प्राप्त नहीं हैं जो अन्य विकसित देशों के श्रमिकों को प्राप्त हैं। अतः भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता की तुलना, अन्य विकसित देशों के श्रमिकों की कार्यक्षमता से करना भारतीय श्रमिक के प्रति अन्याय करना है। मई 1946 में नियुक्त Labour Investigation Committee तथा द्वितीय विश्व-युद्ध काल में नियुक्त ग्रैडी मिशन (Grady Mission) ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय श्रमिक की कम कार्यक्षमता के सम्बन्ध में व्यक्त मत निराधार हैं। यदि भारतीय श्रमिक को काम करने की दशाएं, मजदूरी, उपकरण, अवश्य-व्यवस्था तथा सुविधाएं विकसित देशों के समान होतीं उसकी कार्यक्षमता किसी भी देश के श्रमिक से कम नहीं है। अनुकूल सुविधाएं प्रदान कर उसकी कार्यक्षमता में प्राकृतिक वृद्धि की जा सकती है।

परन्तु वस्तुतः भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता तथा कार्य-कुशलता कम है। इसके कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों पर नीचे प्रकाश डाला गया है :

(1) जातीय कारण : भारत में देशों तथा जातों का वर्गीकरण जाति के आधार पर किया गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार ही काम करता है। यह दोष शिक्षा के प्रसार से दूर होता जा रहा है।

(2) कर्त्तव्यपालन की इच्छा का अभाव - भारतीय श्रमिक गरीब है, उसकी मजदूरी बहुत ही कम है तथा अधिकांश श्रमिक अनिश्चित हैं। इन कारणों से भारतीय श्रमिक अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन रहता है।

उचित मजदूरी तथा शिक्षा के द्वारा यह दोष दूर किया जा सकता है। उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर उनमें कर्त्तव्यपालन की भावना उत्पन्न की जा सकती है।

(3) जलवायु तथा स्वास्थ्य : एक तरफ गरीबी के कारण भारतीय श्रमिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरी तरफ भारत की गर्म जलवायु अधिक श्रम के प्रति-कूल है। यदि श्रमिकों को समुचित योजन के लिए पर्याप्त वेतन मिले, वह हवादार मकानों में रहे तथा उसकी कार्य-कुशलता-रक्षक आवश्यकताएं पूरी होतीं रहे, तो उसकी कार्यक्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। गर्म जलवायु में भी यदि काम करने के स्थान का वातावरण गर्मी के दिनों में ठण्डा रखा जाय, तो कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

(4) शिक्षा तथा प्रशिक्षण : भारतीय थर्मिक अधिकतर अशिक्षित हैं। वे कार्य-सम्बन्धी विशेष शिक्षा के अभाव में अधिक कार्यकुशल नहीं होते।

यदि भारतीय थर्मिकों को सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाय तो वे भी अपनी कार्य-कुशलता को बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था की है, जिसमें थर्मिकों की कार्य-कुशलता बढ़ने की अपेक्षा बड़ी है।

(5) मजदूरी तथा कार्य करने की दशाएँ : अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय थर्मिकों की मजदूरी बहुत ही कम है। कार्य करने के स्थान उपयुक्त नहीं है। न तो वहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था है, और न ही वे हवादार तथा साफ-सुथरे हैं। कार्य के घण्टे भी यहाँ अधिक हैं। एक भारतीय थर्मिक को एक सप्ताह में 48 घण्टे काम करना पड़ता है जबकि पश्चिमी देशों में थर्मिकों को 36 से 40 घण्टे तक ही काम करना पड़ता है। आराम तथा मनोरंजन के अवसर नहीं मिलने के कारण, भारतीय थर्मिकों की कार्यक्षमता कम हो जाती है।

यदि सरकार मजदूरी मुक्तान, न्यूनतम मजदूरी, फैंडरी अधिनियमों की व्यवस्थाओं का पालन करने पर कड़ी नजर रखे तो इन दिशाओं में आवश्यक सुधार हो सकते हैं, जिससे थर्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है।

(6) अच्छी मशीनों का अभाव : भारत में अच्छी तथा आधुनिक मशीनों की कमी है। थर्मिकों को ऐसी मशीनों पर काम करने के अवसर नहीं मिलने से निश्चय ही उनकी कार्यक्षमता कम होगी।

यदि देश में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाय तथा थर्मिकों को उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाय तो भारतीय थर्मिकों की कार्यक्षमता तथा कुशलता में आवश्यक वृद्धि होगी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् नये-नये उद्योगों के विकास तथा अच्छी मशीनों तथा औजारों के प्रयोग से भारतीय थर्मिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है।

(7) थर्म-कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा : यद्यपि भारत में भी थर्मिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के लिए अनेक व्यवस्थाएँ की गयी हैं तथा सरकार द्वारा दुर्घटना क्षतिपूर्ति, थर्मिक राज्य बीमा नियम आदि पास भी किये गये हैं, फिर भी पश्चिमी देशों की तुलना में ये व्यवस्थाएँ कम हैं। यदि सामाजिक सुरक्षा की योजना में विस्तार कर दिया जाये तो थर्मिकों की ओर से निश्चिन्त होकर भारतीय थर्मिक भी अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाकर, अपनी कार्य-क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होगा।

(8) योग्य सगठनकर्त्ताओं का अभाव : भारत में ऐसे कुशल तथा योग्य सगठनकर्त्ताओं की कमी है, जो थर्मिकों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार

काम बाटकर उनकी उत्पादन मात्रा को बढ़ायें। वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा श्रमिकों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में उचित शिक्षा प्राप्त करने पर समझने के इस दोष को दूर किया जा सकता है। इससे श्रम-शान्ति के सम्बन्ध में समाप्त होया तथा श्रमिकों की मानवार्थ भी बदल जायेंगी। फलस्वरूप श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

(9) श्रम संघ (Trade Unions) : श्रम संघों (Trade Unions) का भारत में कम विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त इनकी मिस मानिकों की तरफ से कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। अधिकांश श्रम-संघ टूटकर टुकड़े में समाहित भी नहीं हैं। उन पर राजनीतिक प्रभाव अधिक है। अतः वे श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में किसी प्रकार से सहायक नहीं होते।

श्रम-संघों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए तथा राजनीति से दूर रहकर मिल-मालिकों को उनके साथ मिलकर पारस्परिक मतभेद दूर करने के उपाय करने चाहिए, जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।

### प्रश्न व संकेत

1. आधुनिक उद्योग में श्रमिक की कार्यक्षमता निर्धारित करने वाले मुख्य-तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।  
(Raj, II yr. T D C. Com. 1964)

(संकेत : प्रश्न में उन तत्वों का विस्तृत निवेदन कीजिए जिनसे श्रम की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और प्रत्येक के साथ भारतीय उदाहरण दीजिए।)

2. श्रम की कार्यक्षमता निर्धारित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? छेति-हर मजदूरी की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं?  
(Agra, B.A I. 1960)

(संकेत : प्रथम भाग में श्रम की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए तथा दूसरे भाग में भारतीय कृषकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के उपाय बताइए जैसे मजदूरी में वृद्धि, कार्य करने के घण्टे निर्धारित करना, श्रम सुविधाओं का विकास करना आदि।)

3. श्रम की गतिशीलता समझाइए। भारत में श्रम अधिक गतिशील क्यों नहीं है?  
(Ravi Shankar B.A., Pal, Comp I, 1965)

(संकेत : प्रथम भाग में श्रम की गतिशीलता का अर्थ बताइए और द्वितीय भाग में उन कारणों का स्पष्टीकरण कीजिए जिनके कारण यहाँ श्रमिक की गतिशीलता कम है।)

4. श्रम की विशेषताएँ बताइए तथा मजदूरी पर उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए।  
(Agra, B.A II, 1964)

(संकेत : प्रथम भाग में श्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा द्वितीय भाग में मजदूरी पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए।)

## जनसंख्या के सिद्धान्त (Theories of Population)

*"The relationship of population growth to economic development is interesting and complex. A growing population almost invariably leads to an increasing total output, but it also makes for a greater number of persons among whom the output must be divided... There are more productive hands, but there are also more mouths to feed"*

—Richard T. Gill

धर्म की पूर्ति का मात्रा सम्बन्धी पक्ष (Quantitative Aspect) जनसंख्या से सम्बन्धित है। यही कारण है कि समय-समय पर जनसंख्या की समस्या पर विभिन्न विद्वानों एवं अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। व्यापारवादी अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए अधिक से अधिक उत्पादन आवश्यक है। अधिक उत्पादन अधिक की संख्या में वृद्धि द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अतः उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि को अधिक महत्व दिया था। बाद में वे बढ़ती हुई जनसंख्या को ईश्वरीय वरदान मानने लगे (Increasing population was regarded as a blessing of the Almighty)। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या की वृद्धि को एक 'प्राकृतिक व्यवस्था' (natural order) कह कर यह विचार प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों के द्वारा अर्थात् प्रकृति द्वारा स्वयं सीमित कर दी जाती है, अतः उसकी वृद्धि एक गम्भीर समस्या नहीं है। एडम स्मिथ ने जनसंख्या के एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। उनकी यह धारणा थी कि जनसंख्या मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार स्वयं सामंजस्य की स्थिति में आ जाती है।

परन्तु माल्थस प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया। उन्होंने स्वयं अपने देश तथा अन्य देशों की जन



समस्या का विशेषणसाध्यक अध्ययन करने एक निश्चित सैद्धान्तिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप जनसंख्या के सम्बन्ध में एक नयी विचारधारा प्रारम्भ हुई।

### 1 माल्थस का जनसंख्या-सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)

जनसंख्या का प्रथम सिद्धान्त प्रतिपादित करने का श्रेय थॉमस रॉबर्ट माल्थस (Thomas Robert Malthus) को है जिसका विवरण सन् 1798 में प्रकाशित निबन्ध "An Essay on the Principles of Population as it affects the future Improvement of Society" में मिलता है। इस लेख में माल्थस ने अपने देशवासियों को तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के गम्भीर परिणाम के प्रति सचेत किया था। माल्थस स्वयं एक निराशावादी पावरी थे। उनको सामान्य लोगों के कष्टों एवं दुःखों को निवृत्त से देखन तथा उनका अध्ययन करने का अवसर मिला था। उस समय इंग्लैंड तथा मध्य योरोप की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। फ्रांस के साथ युद्ध के कारण खाद्यान्नों की कमी थी तथा उनके मूल्य निरन्तर बढ़ रहे थे। सभी जगह गरीबी और भुखमरी थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का पूरा-पूरा विकास नहीं हो पाया था, जिससे देश में व्यापक बेकारी फैली हुई थी। इन सब कारणों से लोगों का जीवन स्तर निरन्तर नीचे की ओर गिर रहा था। इन सब कष्टों के होते हुए भी जनसंख्या बराबर बढ़ रही थी।

माल्थस एक निराशावादी व्यक्ति थे। उन्हें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से मानव समाज पर घोर विपत्ति आने की आशंका होने लगी। उसी समय (सन् 1793 ई० में) विलियम गोडविन (William Godwin) की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें मानव समाज के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की गयी थी। माल्थस ने इस झूठी कल्पना का खण्डन करने के लिए अपना लेख प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण मानव समाज का भविष्य निराशासम तथा अन्धकारपूर्ण है, अतः आने वाली घोर विपत्ति से बचने के लिए जनसंख्या को तीव्र वृद्धि को रोकना आवश्यक है।

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की मुख्य बातें - माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त दो गान्धताओं पर आधारित है—(अ) मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, अतः किसी देश की जनसंख्या वही खाद्य पदार्थों की पूर्ति द्वारा सीमित है, और (ब) मनुष्य की प्रजनन शक्ति (Fecundity) अपार है। इन दोनों गान्धताओं के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धान्त को इन शब्दों में व्यक्त किया, "उत्पादन की विधियों की एक दी हूपी स्थिति के अन्तर्गत जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।" (In a given state of the arts of production, population tends to outrun subsistence)

जनसंख्या के इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए माल्थस द्वारा निम्न-लिखित तीन आधार प्रस्तुत किये गये -

(1) धम की माग या खाद्य सामग्री में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि होने पर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी है। उनको जीवित रखने के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होनी आवश्यक है। मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों के बदले में प्रकृति जो खाद्य सामग्री देती है, उसके आधार पर ही जनसंख्या (धम) की प्रभावकारी माग निर्धारित होती है (The produce which nature returns to the work of man is her effective demand for population.)। परन्तु भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित है तथा उस पर क्रमागत उत्पत्ति हानि नियम लागू होने के कारण भूमि से कम उत्पत्ति प्राप्त होगी है। अतः कई देशों में खाद्य पदार्थों के उत्पादन का अध्ययन करने के बाद माल्थस ने यह कहा कि खाद्य पदार्थों या जीवन निर्वाह के साधनों में इस गति से वृद्धि नहीं होती जिस गति से जनसंख्या बढ़ती है। उनका कहना था कि खाद्य पदार्थों में वृद्धि अरिथमेटिक या माध्य श्रेणी (Arithmetical Progression) अर्थात् 1, 2, 3, 4 के हिमाब होती है।

(2) धम की पूर्ति या जनसंख्या में वृद्धि की दर, यदि जनसंख्या को बढ़ने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये और उसकी तेजी से बढ़ने की दर में किसी प्रकार की रूकावट न हो तो जनसंख्या ज्यामिति या गुणोत्तर श्रेणी (Geometrical Progression) में अर्थात् 1, 2, 4, 8, 16 के अनुसार वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है। उनका कहना था कि मनुष्य में सन्तानोत्पत्ति की शक्ति अपार है। इस कारण यदि जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति में कोई रूकावट न हो, तो किसी देश की जनसंख्या वहां पर उपलब्ध जीवन निर्वाह के साधनों की मात्रा की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बहुत जल्दी बढ़ेगी। (There is a tendency of population to increase faster than means of subsistence).

माल्थस ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारणों को एक दूसरे से अलग रख कर गणितीय सहायता से यह सिद्ध किया कि जनसंख्या में बिना किसी रूकावट के ज्यामितिक गति से वृद्धि होने पर वह हर 25 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, परन्तु खाद्य पदार्थों का उत्पादन अकणिष्ठ श्रेणी में बढ़ने के कारण उसमें जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम वृद्धि होती है।<sup>1</sup> माल्थस ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 200 वर्षों में जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की पूर्ति के मध्य 256 : 9 का अनुपात होगा जबकि 300 वर्षों में यह

<sup>1</sup> By nature, human food increases in a slow arithmetical ratio, man himself increases in quick geometrical ratio unless want and vice stop him.

अन्तर बढ़ कर 4096 : 13 के अनुपात में हो जायेगा । 2000 वर्षों में तो दोनों के मध्य इतना अधिक अन्तर एव असन्तुलन हो जायेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ।

(3) जनसंख्या की वृद्धि पर प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध (Positive or Natural Checks) - माल्थस का विचार था कि जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की पूर्ति के बीच इस प्रकार के असन्तुलन (imbalance) की स्थिति आ जाने पर, प्रकृति स्वयं अवरोध (check) लगाना प्रारम्भ कर देती है । भूराज, महामारी, भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपत्तियों तथा दैवी प्रकोपों द्वारा प्रकृति जनसंख्या का समतुलन (balance) बनाए रखती है । माल्थस ने इन्हें प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध (positive checks) की संज्ञा दी है । इन अवरोधों के कारण जनसंख्या अपने पाप कम हो जाती है क्योंकि जन्म दर से मृत्यु दर घटिक होती है । कुछ समय बाद पुनः जनसंख्या बढ़ने लगती है । खाद्यान्नों की पूर्ति से जनसंख्या के पुनः बढ़ जाने पर नैसर्गिक प्रतिबन्ध पुनः लागू होते हैं । इस प्रकार जनसंख्या को समायोजित करने वाले प्राकृतिक चक्र (self adjusting Malthusian cycles of population) के द्वारा खाद्य पदार्थों की पूर्ति के अनुसार जनसंख्या समतुलित हो जाती है ।

परन्तु माल्थस का यह विचार था कि जनसंख्या घटाने की यह विधि भयंकर तथा अत्यधिक कष्टदायक है, क्योंकि प्राकृतिक विधियों से लोगों को अत्यधिक कठिनाइयाँ होती हैं । इसके अतिरिक्त इन अवरोधों से जनसंख्या में कमी केवल थोड़े समय के लिए ही होती है । कुछ समय के बाद वह पुनः तीव्र गति से बढ़ने लगती है । अतः माल्थस ने प्राकृतिक एव दैवी प्रकोप से बचने के लिए निवारक उपायों पर जोर दिया ।

(4) कृत्रिम या निवारक अवरोध (Preventive Checks) - माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए मनुष्य द्वारा अपनाए गए कृत्रिम उपायों की निवारक अवरोध (Preventive Checks) की संज्ञा दी । उनका मत था कि ब्रह्मचर्य, देर से विवाह करना, आत्म संयम आदि द्वारा मनुष्य जन्म-दर (Birth Rate) को कम कर सकता है, जिससे जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की पूर्ति का समतुलन बना रहे । परन्तु माल्थस ने निरोधक उपायों के अन्तर्गत आधुनिक सन्तति निरोधक कृत्रिम विधियों (Birth Control Measures) का उल्लेख नहीं किया था । उन्होंने पादरी होने के नाते आत्म-संयम और ब्रह्मचर्य पर ही जोर दिया था । सन्तति निरोधक कृत्रिम विधियों के सम्बन्ध में माल्थस के अनुयायियों (Neo Malthusians) ने बाद में विचार प्रस्तुत किया ।

## माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचना :

माल्थस के जनसंख्या-सिद्धान्त की आलोचना उनके लेख के प्रकाशित होने के बाद में ही प्रारम्भ हो गयी। उनके समकालीन विलियम गॉडविन (William Godwin) ने तो माल्थस के सिद्धान्त के निराशावादी दृष्टिकोण की तुलना एक भयानक राक्षस से की है जो मानव समाज की आशाओं का हमेशा गला घोटने को तैयार है। (That black and terrible demon that is always ready to stifle the hope of humanity)। उस समय से निरन्तर ही माल्थस की आलोचनाएँ की जाती रही हैं। उनके सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

(1) माल्थस ने भविष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों का अनुमान नहीं लगाया। माल्थस ने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अनुभव प्रणाली (Inductive Method) के आधार पर किया था। वे भविष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी प्रगति तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले आर्थिक एवं औद्योगिक विकास और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का अनुमान नहीं लगा सके थे। यही कारण था कि उन्होंने जमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को भूमि पर लागू करके उत्पादन की क्रमशः घटने वाली मात्रा के आधार पर भविष्य का एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया था। हार्प के प्राधुनिक वैज्ञानिक तरीकों द्वारा अब भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि सम्भव है, जिससे खाद्य-पदार्थों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने प्राधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के कारण माता-पिता के साधनों का विकास तथा फलस्वरूप खाद्यान्नों की पूर्ति की सुविधा का भी अनुमान नहीं लगाया था।

(2) माल्थस के निष्कर्ष तत्कालीन घटनाओं पर आधारित थे : माल्थस ने औद्योगिक क्रांति के तात्कालिक परिणामों को ही देखकर यह अनुमान लगाया था कि इसके भावी परिणाम आशाजनक एवं सुखमय नहीं हो सकते। परन्तु उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि औद्योगिक विकास होने पर बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याएँ दूर हो जायेंगी तथा खाद्य-पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का उत्पादन करके उनके बदले में खाद्यान्नों का आयात करके उनकी पूर्ति की जा सकेगी।

(3) माल्थस ने जनसंख्या का सम्बन्ध खाद्यान्नों के उत्पादन से स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि की तुलना खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि से ही की थी। मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा भी कर सकता है। उनकी पूर्ति या उत्पादन में भी उभो प्रकार वृद्धि होती है जिस प्रकार कि जनसंख्या में; अतः जनसंख्या की वृद्धि की तुलना केवल खाद्यान्नों की पूर्ति से करना गलत था। माल्थस को यह चाहिए था कि वे जनसंख्या की वृद्धि

की तुलना देश के कुल उत्पादन (खाद्यान्न के उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, आयात, अन्य साधन-सामग्रियों का उत्पादन) से करते, जिससे वह सही निष्कर्ष निकाल पाते।

(4) माल्थस का 'कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम के सर्वत्र लागू होने का आधार' यस्तथा। माल्थस ने कमलग्न उत्पत्ति ह्रास नियम भूमि पर तो लागू किया, परन्तु मनुष्य की प्रजनन शक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने इस नियम का प्रयोग नहीं किया। उनकी यह मान्यता थी कि मनुष्य को यह शक्ति यथा स्थिर तथा अनरिमित है और यदि मनुष्य किसी भी प्रकार एक बड़े परिवार को जीवित रखने में समर्थ हो जाये तो वह जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की प्रवृत्ति अधिक सन्तानोत्पादन करेगा। सम्भवतः उन्होंने यह धारणा उस समय के 'गरीबी कानूनों' (Poor Laws) के द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता के फलस्वरूप हो रही जनसंख्या में वृद्धि का आधार पर बनायी थी। परन्तु कालान्तर में उनकी ये दोनों ही धारणायें गलत सिद्ध हुईं। आर्थिकशास्त्र में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास होने पर मनुष्य की प्रजनन-शक्ति कम होती जाती है।

(5) जीवन-स्तर ऊँचा उठने पर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा कम होने लगती है; सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों ने भी अब यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य का जीवन-स्तर ऊँचा उठने पर वह अधिक भौतिक सुखों की कल्पना करता है, न कि अधिक सन्तानोत्पत्ति की। ऐसी स्थिति में निवारक अनुरोध—देर में विवाह करना, आरम्भ मय आदि—स्वयं कार्यशील होते हैं। उनकी अपवृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(6) माल्थस का गणितीय आधार ठीक नहीं है; माल्थस ने ज्यामितीय तथा अकण्ठित श्रेणियों के आधार पर जनसंख्या तथा खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। परन्तु विभिन्न देशों के जनसंख्या सम्बन्धी आकड़ों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी के आधार पर नहीं हुई। इस गणितीय आधार की अशुद्धता को स्वयं माल्थस ने अनुभव किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुस्तक के अन्य संस्करणों में जनसंख्या की तुलनात्मक वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए इन श्रेणियों (Progressions) का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यह बतसाया कि खाद्यान्न का उत्पादन में वृद्धि की गति से कहीं अधिक तबो से जनसंख्या में वृद्धि होती है।

(7) माल्थस की निराशावादी धारणाएँ असत्य सिद्ध हुयी हैं; परन्तु माल्थस को यह धारणा भी असत्य सिद्ध हुई। माल्थस ने मानव समाज का अंधकारमय चित्र प्रस्तुत किया था और नैतिक अवरोध के रूप में विश्व पर जिस घोर विपत्ति

की भविष्यवाणी की थी, वह आज तक किसी भी देश में सत्य नहीं हुई है। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य का जीवन स्तर ऊँचा उठा है। कुछ देशों में तो जनसंख्या को कम करने के लिए 'परिवार-नियोजन' (Family Planning) राष्ट्रीय योजना का एक अनिवार्य कार्यक्रम हो गया है। इस प्रकार आदर्श जनसंख्या के सिद्धान्त (Theory of Optimum or Ideal Population) तथा जनानुक्रमिक परिवर्तन सिद्धान्त (Theory of Demographic Transition) ने माल्थस की भविष्यवाणी को निराधार सिद्ध कर दिया है।

(8) मनुष्य केवल उपभोक्ता ही नहीं है, उत्पादक श्रम भी है। कैनन ने माल्थस के इस विचार (जनसंख्या की वृद्धि विपत्ति-सूचक है) की आलोचना करते हुए कहा है कि मनुष्य केवल उपभोक्ता के रूप में ही जन्म नहीं लेता बल्कि वह उत्पादक (श्रमिक) के रूप में भी आता है (वह मुँह ही लेकर नहीं आता, बल्कि दो हाथ भी साथ में लाता है)। इससे देश की श्रम-शक्ति बढ़ती है तथा देश की उत्पादन-मात्रा में भी वृद्धि होती है।

(9) माल्थस ने केवल जनसंख्या के आकार पर ही विचार किया था। इस सम्बन्ध में सेलिंगमैन (Seligman) का यह विचार है कि किसी देश की जनसंख्या समस्या वहाँ की जनसंख्या के आकार से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि उस देश के उत्पादन तथा व्यय सपन वितरण से सम्बन्धित है। यदि किसी देश में उत्पादन के साधनों की कुशलता अधिक है और उसका वितरण उचित रूप में किया जाता है तो निश्चय ही उत्पादन अधिक होगा जिससे जनसंख्या अधिक होने पर भी असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

"The problem of population is not merely of size but of efficient production and equitable distribution"

(10) माल्थस की यह धारणा कि नैसर्गिक अवरोधों (Positive Checks) का होना जनानुक्रम का सूचक है, गलत है। माल्थस की यह धारणा थी कि यदि भूकम्प, महामारी, भूकाल आदि देवी आपत्तियाँ आती हैं, तो यह मानना चाहिए कि वहाँ जनानुक्रम होने पर ही यह प्राकृतिक समायोजन चक्र (Self adjusting cycle) चलता है। परन्तु यह धारणा गलत है। जहाँ जनानुक्रम नहीं है, वहाँ भी ये देवी आपत्तियाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त जिन देशों में जनानुक्रम है, वहाँ इन आपत्तियों को नियंत्रित करने के उचित उपाय भी किये जा चुके हैं।

**माल्थस के सिद्धान्त की सत्यता**

माल्थस के सिद्धान्त की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। यद्यपि उन्होंने माल्थस के विचारों को अव्यावहारिक तथा असत्य सिद्ध करने का

प्रयत्न किया, फिर भी मासॉल, टाजिंग (Tassing), एली (Ely) पैटन (Patten) आदि अर्थशास्त्रियों ने उनके सिद्धान्त की सत्यता का समर्थन किया है। वास्तविकता तो यह है कि मानवस की यह चारणा कि यदि जनसंख्या का बढ़ने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वह नीच गति से बढ़ेगी, सत्य है। विश्व में जिन देशों में जनसंख्या की बढ़ने की गति रुकी है, उसमें मनुष्य द्वारा अपनाये गये निरोधक उपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे देश विशिष्ट तथा उन्नतिशील हैं। इन देशों में वैज्ञानिक जोशों के कारण उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। वहाँ जनसंख्या जीवन-निवाह के साधनों में उत्पादन वृद्धि से अधिक तीव्र गति से नहीं बढ़ी है। इसके प्रतिरिक्त इन देशों में शिक्षा, सामाजिक उन्नति तथा जीवन स्तर में अधिक उन्नति होने से भी जनमर्या कम हुई है। परन्तु अधिकसिक्त तथा पिछड़े देशों में जहाँ पर ये उपाय नहीं अपनाये गये हैं और जहाँ क्षमिता तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक सम्मानोत्पत्ति पर प्रनिबन्ध नहीं है, वहाँ माल्थस का सिद्धान्त अब भी लागू होता है जैसे भारत, चीन आदि देश। माल्थस की यह चारणा भी सत्य प्रतीत होती है कि जनसंख्या तथा खाद्य-पदार्थों की पूर्ति में असन्तुलन होने तथा निवारक उपायों को न अपनाने पर नैसर्गिक प्रचाराय कार्यशील होते हैं। प्रो० वाकर (Walker) तथा सैमुएलसन (Samuelson) का यह विचार है कि माल्थस का सिद्धान्त आज भी प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है<sup>2</sup> तथा एक जीवित प्रभाव है।<sup>3</sup>

## 2 सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त (Theory of Optimum Population)

माल्थस के जनसंख्या-सिद्धान्त की कड़ी आलोचनाओं ने जनसंख्या की समस्या पर एक नये सिद्धान्तिक दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। प्राबु निच अर्थशास्त्रियों ने माल्थस के इस विचार का खण्डन किया है कि अधिकतम जनसंख्या एक हानिकारक स्थिति है। ये अर्थशास्त्री जनसंख्या की वृद्धि को राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित करके यह देयते हैं कि अधिकतम आय के दृष्टिकोण से जनसंख्या का घातक सर्वोत्तम एवं आदर्श है या नहीं। इन अर्थशास्त्रियों ने माल्थस द्वारा प्रयुक्त अधिकतम शब्द के स्थान में आदर्श शब्द प्रतिस्थापित किया है।

अनुकूलतम सिद्धान्त का आधार सर्वप्रथम सिड्ग्विक (Sidgwick) ने अपनी पुस्तक 'Principles of Political Economy' में प्रस्तुत किया। इस सिद्धान्त में अधिकतम उत्पादन-क्षमता पर विचार किया गया था। इस आधार पर डॉ० एड्विन कैनन (Dr. Edwin Cannan) ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त (Theory of

<sup>2</sup> "Malthusianism has stood unshattered, impregnable amid all the controversy that has raged round it."

—Walker

<sup>3</sup> "It is still a living influence to day"

—Samuelson

Optimum Population) का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात् राबिन्स, डाल्टन (Dalton) तथा कार सौण्डर्स (Carr Saunders) ने इस सिद्धान्त को अधिक व्यापक बनाया।

### (1) अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ

अनुकूलतम का अभिप्राय 'आदर्श' (Ideal) से है। जनसंख्या के सदर्भ में अनुकूलतम या अभिप्राय जनसंख्या के आदर्श आकार (Ideal Size) से है। वह जनसंख्या जो किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग तथा अधिकतम उत्पादन के लिए प्रावश्यक हो आदर्श जनसंख्या मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समय तथा परिस्थिति में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त जनसंख्या में परिवर्तन तथा प्रति व्यक्ति आय के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है। यह बताता है कि जनसंख्या उन्नी समय आ आ या अनुकूलतम समझी जानी है जबकि किसी समय-विशेष में प्रति-व्यक्ति आय अधिकतम होती है। कार सौण्डर्स का शब्दों में, "आदर्श जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। यह आवश्यक नहीं कि अधिकतम आर्थिक कल्याण और प्रति व्यक्ति अधिकतम वास्तविक आय एक ही हो, परन्तु व्यावहारिक रूप में दोनों का अभिप्राय एक माना जा सकता है।" अनुकूलतम जनसंख्या का स्पष्टीकरण निम्न तालिका द्वारा किया जा सकता है।

#### निश्चित भूमि से उत्पादन (रूपों में)

जनसंख्या	कुल उत्पादन	प्रति व्यक्ति आय
20	400	20
25 आदर्श जनसंख्या	625	25 अधिकतम प्रति व्यक्ति आय
30	660	22

उपर्युक्त तालिका में यह सात होता है कि निश्चित भूमि का अधिकतम उपयोग उसी समय होता है जबकि जनसंख्या 25 है, क्योंकि इस जनसंख्या के रहने पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है। इससे कम जनसंख्या रहने पर प्रति व्यक्ति आय 25 रु० से कम है और इससे अधिक जनसंख्या होने पर भी प्रति व्यक्ति आय घट कर 22 रु० हो जाती है।

4 ".... The optimum population is that population which produces maximum economic welfare... Maximum economic welfare is not necessarily the same as maximum real income per head, but for practical purposes they may be taken as equivalent"

—Carr Saunders, *World Population*



अतः अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके रहने पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है।

डाल्टन (Dalton) के अनुसार, “आदर्श जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है।” (Optimum population is that which gives the maximum income per head) बौलिंग (Boulding) ने आदर्श जनसंख्या की व्याख्या जीवन स्तर (Standard of Life) के सम्बन्ध में की है। उनके अनुसार “वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है, आदर्श जनसंख्या कहलाती है। (The population at which the standard of life is a maximum is called the optimum population) रॉबिन्स (Robbins) ने डाल्टन के विपरीत अधिकतम उत्पादन के माफ-रूख के आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या की व्याख्या की है। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के अधिकतम होने तथा धन के न्यायोचित वितरण पर ही जोर नहीं दिया है। उनके अनुसार, “वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन को सम्भव बनाती है अनुकूलतम या सबसे अच्छी जनसंख्या है।” (The population which just makes the maximum return possible is the optimum or the best possible population.) इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या का स्तर अधिक ऊँचा है, क्योंकि इस स्तर पर जनसंख्या द्वारा उत्पादन तथा उसका उपयोग—दोनों ही बराबर होते हैं।

**अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की आधारभूत मान्यताएँ**

(1) उत्पादन साधनों में आदर्श समन्वय होना अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त उत्पादन के नियमों (Laws of Returns) पर आधारित है। उत्पादन के नियमों के अनुसार किसी भी उत्पादक इकाई में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और साहज) में आदर्श समन्वय होने पर ही अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है।

(2) एक बिन्दु के पश्चात् उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना : धन के अतिरिक्त यदि अन्य साधनों को अपरिवर्तनीय मान लिया जाय तो आदर्श समन्वय के बिन्दु के आने तक श्रमिकों की वृद्धि से धन की सीमान्त उत्पादित तथा प्रति श्रमिक औसत उत्पत्ति में वृद्धि होगी। आदर्श बिन्दु पर उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादन अधिकतम होगा। परन्तु अधिकतम उत्पादन के आदर्श बिन्दु के पश्चात् भी यदि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है तो श्रम की सीमान्त उत्पादकता तथा प्रति श्रमिक औसत उत्पादन—दोनों ही घटने लगते हैं। यह नियम उत्पादन की सभी इकाइयों पर लागू होता है। अतः इसको बैनन ने इस प्रकार व्यक्त किया है :

“किसी एक समय विशेष पर एक निश्चित बिन्दु तक श्रम की वृद्धि होने पर श्रानु-पातिक रूप में अधिक प्रतिकूल प्राप्त होते हैं, परन्तु यदि उस सीमा से अधिक श्रम की वृद्धि होती है तो श्रानुपातिक रूप में कम प्रतिकूल प्राप्त होने लगते हैं।”<sup>2</sup>

(3) श्रमिक के औसत उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में सीमा सम्बन्ध : इस नियम के आधार पर ही जनसंख्या की सर्वोत्तम या प्रादश सीमा निर्धारित की गयी है। श्रमिकों की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित है। किन्तु जनसंख्या की एक निश्चित सीमा तक वृद्धि ही प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहायक होती है। जिस बिन्दु पर जनसंख्या के पहुँचने के बाद प्रति व्यक्ति आय घटन लगती है, वह जनसंख्या की वृद्धि का प्रादश बिन्दु कहलाता है और इस बिन्दु पर जितनी जनसंख्या होती है, उसे प्रादश, सर्वोत्तम या अनुकूलनम जनसंख्या कहते हैं। इस प्रादश जनसंख्या के रहने पर ही उपलब्ध एवं वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो पाता है, अधिकतम आर्थिक वस्थाएँ की स्थिति उत्पन्न होती है और प्राग व्यक्ति प्राय अधिकतम होती है।

जनाभाव (Under-population) और जनाधिक्य (Over population) :

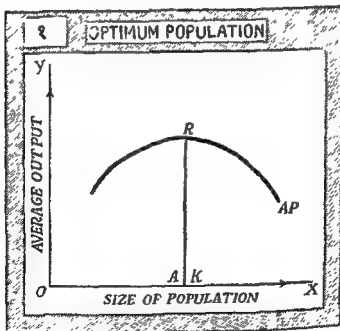
सर्वोत्तम या प्रादश जनसंख्या से कम जनसंख्या को जनाभाव कहा जाता है। किसी देश में जनाभाव की स्थिति रहने पर वहाँ वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता जिससे वस्तुओं और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन न होने के कारण प्रति व्यक्ति आर्थिक आय कम होती है। जब जनसंख्या अनुकूलनम जनसंख्या से अधिक होती है, तो वर्तमान साधन प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम बनाये रखने के लिए अपर्याप्त होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के रूप में औसत उत्पादन कम होने से प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही स्थितियाँ किसी देश के लिए सख्त नहीं मानी जाती।

अनुकूलनम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या अनुकूलनम जनसंख्या सिद्धान्त का स्पष्टीकरण अगले पृष्ठ पर दिए गए रेखाचित्र द्वारा किया गया है। इस चित्र में AP ‘प्रति व्यक्ति वास्तविक आय’ या ‘औसत उत्पादन’ बतलता है। OY अक्ष पर औसत उत्पत्ति या प्रति व्यक्ति आय तथा OX पर जनसंख्या का आकार दिखाया गया है। OK तक जनसंख्या की वृद्धि होने पर औसत उत्पादन में वृद्धि होती जाती है और जब जनसंख्या K बिन्दु पर पहुँच जाती है तब OK जनसंख्या होने पर औसत उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय KR होती है जो अधिकतम सीमा को व्यक्त करती है।

<sup>2</sup> “At any given time, increase of labour upto a certain point is attended by increasing proportionate returns and beyond that point further increase of labour is attended by diminishing proportionate returns.”

—Cannon, Dr. Edna : Wealth

अन  $OK$  अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या है, क्योंकि  $R$  की दायीं ओर बायीं ओर  $AP$  वक्र नीचे की तरफ झुका हुआ है जो यह व्यक्त करता है कि औसत उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय  $KR$  से कम है। जब तक जनसंख्या  $OK$  नहीं होती तब तक जनसंख्या की वृद्धि वाछनीय है, क्योंकि जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि से  $AP$  वक्र ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है जिससे यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या की दशा में जनसंख्या में वृद्धि होने पर औसत उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। परन्तु  $OK$  जनसंख्या होने पर जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम ( $KR$ ) हो जाती है तब  $OK$  के पश्चात् जनसंख्या में वृद्धि होने पर  $AP$  वक्र  $R$  की दायीं ओर झुकने लगता है जिससे यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या होने पर औसत उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है। अतः जनसंख्या तथा जनसंख्या दोनों ही ठीक नहीं है।



चित्र स० 48

जनसंख्या अथवा जनसंख्या का निर्धारण आ 1 जनसंख्या के बिन्दु से कोई भी विचलन (Deviation) जनसंख्या में समायोजन अभाव (Maladjustment) व्यक्त करता है। यह समायोजन अभाव जनसंख्या या जनसंख्या के रूप में हो सकता है। यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या में कम होती है तब यह

श्रृष्टात्मक समायोजन अभाव अथवा जनाभाव कहलाता है, क्योंकि इस जनाभाव को दूर करने के लिए जनसंख्या में वृद्धि वाछनीय होती है। परन्तु जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक होती है तब दोनों का अन्तर घनात्मक समायोजन अभाव (Positive Mal-adjustment) या जनाधिक्य कहलाता है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण की दृष्टि से वाछनीय नहीं है। अतः जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या के बराबर होती है तभी वह अधिकतम आर्थिक कल्याण प्रदान करती है।

समायोजन अभाव की मात्रा की माप (Measurement of the degree of mal-adjustment) . जनाभाव तथा जनाधिक्य मात्रा को नापने के लिए डाल्टन (Dalton) ने एक सूत्र (Formula) का निर्माण किया है जो इस प्रकार है :—

$$M = \frac{A - O}{O} \quad \text{अथवा} \quad या = \frac{व - अ}{अ}$$

यहाँ M या 'य' का अर्थ समायोजन अभाव (Mal adjustment) है, A या 'व' का अर्थ 'वास्तविक जनसंख्या' तथा O या 'अ' का अर्थ 'आदर्श जनसंख्या' से है। यदि किसी देश में वास्तविक तथा आदर्श जनसंख्या क्रमशः 1,20,000 तथा 1,00,000 मान ली जाय तो उपर्युक्त सूत्र के अनुसार समायोजन अभाव घनात्मक (Positive) होगा .  $\frac{1,20,000 - 1,00,000}{1,00,000} = + .2$ , जो .2 सीमा तक

'जनाधिक्य' (Over population) व्यक्त करता है। इसके विपरीत यदि आदर्श जनसंख्या 1,20,000 हो और वास्तविक जनसंख्या 1,00,000 तो

$$\frac{1,00,000 - 1,20,000}{1,00,000} = -.2 \quad \text{श्रृष्टात्मक समायोजन अभाव (Negative mal-adjustment)}$$

होगा जिससे यह ज्ञात होगा कि देश में 'जनाभाव' (Under-population) है। समायोजन अभाव की (जनाधिक्य तथा जनाभाव) ये दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति तथा समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण की दृष्टि से ठीक नहीं हैं।

डाल्टन तथा राबिन्स के विचारों की तुलना सर्वोत्तम एवं आदर्श जनसंख्या सिद्धान्त को अधिक व्यापक बनाने का श्रेय डाल्टन तथा राबिन्स को है। डाल्टन ने अपने सूत्र का प्रयोग करके आदर्श और वास्तविक जनसंख्या व समायोजन अभाव (Mal-adjustment) को नापने का आधार प्रस्तुत किया है, परन्तु आदर्श जनसंख्या के विषय में उनका दृष्टिकोण केवल प्रति व्यक्ति आय के अधिकतम होने तक ही सीमित है। राबिन्स ने आदर्श जनसंख्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण समाज को

प्राप्त होने वाले अधिकतम प्रतिफल (Maximum Return) को आधार माना है। इस प्रकार डाल्टन के विचार से किसी भी देश में किसी समय विशेष पर जनसंख्या के जिस आकार पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसी को आदर्श जनसंख्या कहा जा सकता है। राबिन्स के अनुसार जिस जनसंख्या के रहने पर अधिकतम राष्ट्रीय आय या प्रतिफल प्राप्त हो, वह जनसंख्या ही सर्वोत्तम या आदर्श जनसंख्या है।

राबिन्स प्रति व्यक्ति अधिकतम आय को महत्व नहीं देते। उनके विचार में सामाजिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय का अधिकतम होना अधिक आवश्यक है, जिससे देश में अधिकतम आर्थिक कल्याण की स्थिति उत्पन्न हो सके। उनका मत है कि यदि जनसंख्या के किसी विशेष आकार से केवल प्रति व्यक्ति आय ही अधिकतम होती है, परन्तु सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में अधिकतम प्रतिफल प्राप्त नहीं होते, तो उसे आदर्श जनसंख्या नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि उचित है, चाहे प्रति व्यक्ति आय अधिकतम सीमा से घटने ही क्यों न लगे। अतः राबिन्स के मतानुसार राष्ट्रीय आय-व्यवस्था के अधिकतम विकास की दृष्टि से जो जनसंख्या आवश्यक तथा वांछनीय हो, वही आदर्श जनसंख्या है। समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित, कल्याण या आय का कुछ न कुछ त्याग आवश्यक है। इस त्याग से देश तथा समाज को लाभ होने पर व्यक्तिगत क्षति की पूर्ति किसी न किसी रूप में अवश्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त राबिन्स का यह भी विचार है कि यदि देश की भ्रष्ट व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लाभप्रद कार्य में लगा हुआ है और समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में दयावृत्ति योगदान देता है, तो समाज उसके अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहता है।

सर्वोत्तम सिद्धान्त की माल्थस के सिद्धान्त से तुलना •

1 जनसंख्या की समस्या का खाद्य सामग्री के आधार पर नहीं बरन् देश की कुल उत्पत्ति के आधार पर अध्ययन माल्थस का सिद्धान्त जनसंख्या को केवल खाद्य सामग्री के सम्बन्धित करके ही किसी देश के लिए जनसंख्या को अधिकतम मानता है। परन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त जनसंख्या का सम्बन्ध देश के कुल उत्पादन में स्थापित करता है। अतः बड़ा जनसंख्या की अधिकतम सीमा के स्थान पर सर्वोत्तम जनसंख्या का उल्लेख करता है।

2. जनसंख्या की वृद्धि अबाधनीय नहीं है, बरन् कुछ सीमा तक बाधनीय भी है : माल्थस ने किसी भी देश के लिए खाद्य पदार्थों की पूर्ति तथा जनसंख्या की वृद्धि के मध्य असन्तुलन में धीरे-धीरे विपत्ति की कल्पना की है। परन्तु 'अनुकूलतम' सिद्धान्त

किसी देश के वर्तमान साधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि को उस सीमा तक बाधनीय मानता है जिस बिन्दु तक अधिकतम सामाजिक व आर्थिक कल्याण तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की स्थिति उत्पन्न होती है।

3. जनसंख्या के परिमाण सम्बन्धी पहलू (Quantitative Aspect) के साथ साथ गुण सम्बन्धी पहलू (Qualitative Aspect) को भी महत्व देना : “प्रत्येक व्यक्ति केवल स्वयं के लिए मृत ही लेकर नहीं आता, बरन् कार्य करने के लिए दो हाथों के साथ भी आता है।” इस मान्यता के आधार पर अनुकूलतम सिद्धान्त यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बनाये रखने के लिए पर्याप्तशील रहना है, बल्कि वह अधिकाधिक काम इसलिए करता है जिससे प्रति व्यक्ति आय तथा सामाजिक, आर्थिक कल्याण अधिकतम हो सके। जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में यह एक आशावादी दृष्टिकोण है।

माल्थस का सिद्धान्त मनुष्य के जीवित रहने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय पर ही जोर देता है। माल्थस के विचारों से जनसंख्या की वृद्धि में उपभोक्ताओं की वृद्धि होती है, परन्तु खाद्य-पदार्थों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था केवल निर्वाण-अर्थ व्यवस्था (Subsistence Economy) मान ही रह जाती है। इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर भविष्य कष्टमय हो जाता है। परन्तु बौलिंग (Boulding) आर० टी० बाई (R. T. Bye) आदि अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या के विचार में परिमाणान्तरक तथा गुणान्तरक दोनों पहलुओं पर जोर दिया है। इन अर्थशास्त्रियों ने ‘प्रति-व्यक्ति आय’ के स्थान पर जीवन प्रमाण पर जोर दिया है। इसका अर्थ है कि एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती ही है, परन्तु वृद्धि होने पर भी उसका आकार इतना ही हो जिसमें मानव समाज का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन उच्चतम (most wholesome) हो सके।

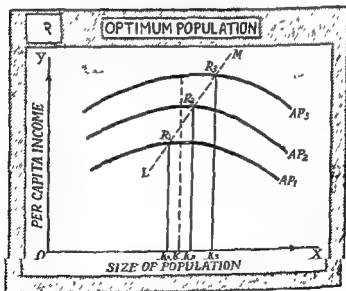
4. नैसर्गिक अवरोधों के न रहने पर भी जनअधिक्य हो सकता है। माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार किसी देश में जनअधिक्य की कभी भी महामारी, भूकाल, आदि दैवी विपत्तियाँ हैं। यदि ये नैसर्गिक अवरोध किसी देश में लागू हों, तो वहाँ जनअधिक्य अवश्य होगा। परन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त के अनुसार इन नैसर्गिक अवरोधों के न रहने पर भी, यदि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम न हो, तो यह कहा जा सकता है कि वहाँ जनअधिक्य है। इसमें जनअधिक्य की कसौटी प्रति व्यक्ति आय का अधिकतम सीमा में घटना है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचना :

1. यह एक सिद्धान्त नहीं है : अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त वस्तुतः कोई सिद्धान्त नहीं है। वस्तुतः यह जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में ‘क्यों और कैसे’

प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। यह तो केवल 'आदर्श' अथवा 'सर्वोत्तम' जनसंख्या के सम्बन्ध में एक निश्चित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धान्त किसी समय एक देश में जनाभाव है या जनाधिक्य, की स्थिति बताता है। इससे यह मालूम होता है कि जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम है या नहीं।

2. आदर्श बिन्दु या आदर्श जनसंख्या ज्ञात करना कठिन है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत आदर्श बिन्दु ज्ञात करना कठिन है। इसका कारण यह है कि अनुकूलतम सिद्धान्त, स्थैतिक (Static) सिद्धान्त है। यह धमिकों की मरणा म वृद्धि के प्रतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों को दिया हुआ या स्थिर मान कर जनसंख्या के आदर्श बिन्दु को ज्ञात करता है। परन्तु व्यावहारिक जीवन से समय के परिवर्तन के साथ अर्थ-व्यवस्था पहले जैसी नहीं रहती। नए नए प्राकृतिक साधनों की खोज, पूँजी, तकनीकी ज्ञान, धमिकों की कार्यकुशलता और उत्पादन के क्षेत्रों में विविध नयी विधियों को अपनाने पर देश का उत्पादन बढ़ता है। अधिकतम उत्पादन के लिए आग की आवश्यक जनसंख्या भविष्य में आदर्श या सर्वोत्तम नहीं भी हो सकती है, अर्थ-व्यवस्था का विकास एक गतिशील धारणा है (Dynamic Concept) है, अतः



चित्र सं० 49

अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन के साथ अनुकूलतम जनसंख्या भी परिवर्तित होती रहती है, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में स्पष्ट है।

उपरोक्त चित्र में  $AP_1$ ,  $AP_2$ , और  $AP_3$ , क्रमशः उत्पादन या प्रति व्यक्ति

आय रेखाएँ (Curves) हैं।  $AP_2$  और  $AP_3$ , रेखाओं पर  $R_2$  और  $R_3$  बिन्दु प्रति व्यक्ति अधिकतम आय व्यक्त करते हैं तथा ऐसा उसी समय सम्भव हुआ है जबकि नये नये उत्पादन साधनों तथा नवीन विधियों का प्रयोग करने के लिए आदर्श जनसंख्या भी  $OK_1$  तथा  $OK_2$  तक बढ़ी है। इन स्थितियों में ही प्रति व्यक्ति आय अधिकतम सम्भव हो सकी है। इस प्रकार आदर्श जनसंख्या में गतिशीलता का व्यक्त करने वाली रेखा LM यह प्रकट करती है कि गतिशील अर्थ व्यवस्था (Dynamic Economy) में आदर्श जनसंख्या स्थितिक (Static) नहीं रह सकती।

यदि वास्तविक जनसंख्या (OK), आदर्श जनसंख्या ( $OK_1$ ) से अधिक है, जैसा कि पीछे के चित्र से स्पष्ट है, अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन के पहले तथा बाद दोनों ही परिस्थितियों में आदर्श उस समय तक नहीं होगी, जब तक कि वह  $OK_2$  न हो जाये। परिवर्तन के पहले वास्तविक जनसंख्या OK आदर्श जनसंख्या ( $OK_1$ ) से अधिक थी। यह जनाधिक्य की स्थिति व्यक्त करती है। परिवर्तन के पश्चात् वास्तविक जनसंख्या OK अगली आदर्श जनसंख्या  $OK_2$  से कम है। अतः यह जनान्ध की स्थिति व्यक्त करती है। अर्थ व्यवस्था में अर्थ सभी भावी परिवर्तनों की स्थितिओं में यही कम चलता रहेगा।

3 यह सिद्धान्त राष्ट्रीय आय के वितरण-पक्ष पर ध्यान नहीं देता। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त केवल प्रति व्यक्ति आय तथा उत्पादन के अधिकतम होने से सम्बन्धित है। वह वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में प्राप्त प्रतिफल या आय के उचित वितरण पर ध्यान नहीं देता। यदि प्रति व्यक्ति आय या औसत उत्पादन के अधिकतम होने पर भी राष्ट्रीय आय कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाये, तो आर्थिक कल्याण की दृष्टि से जनसंख्या का आदर्श नहीं कहा जा सकता।

4. इस सिद्धान्त में जनसंख्या का अध्ययन केवल आर्थिक दृष्टि से किया जाता है; यह सिद्धान्त आदर्श जनसंख्या निर्धारित करते समय केवल उसके आर्थिक पक्ष को ही ध्यान में रखता है। इस प्रकार यह सिद्धान्त संकुचित दृष्टिकोण प्रकट करता है, क्योंकि आदर्श जनसंख्या केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बरन् सामाजिक, नैतिक तथा सुरक्षात्मक परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर निर्धारित की जानी चाहिए।

5. अधिकतम आय और अधिकतम प्रसन्नता का एक ही अर्थ नहीं है। यह सिद्धान्त राष्ट्रीय आय के अधिकतम होने को अधिकतम सुख एवं प्रसन्नता का सूचक मानता है। परन्तु प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होने पर भी देश में वास्तविक प्रसन्नता (Happiness) का अभाव हो सकता है। वास्तविक सुख एवं प्रसन्नता देश में स्वस्थ, शिक्षित, बुद्धिमान तथा अन्तर्भावनाशील (Conscientious) नागरिकों पर निर्भर है।



6. यह सिद्धान्त जनसंख्या की समस्या के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं करता : यह सिद्धान्त आदर्श जनसंख्या से कम व अधिक जनसंख्या को व्यक्त करके जनाभाव (Under population) और जनाधिक्य (Over population) की अवस्थानीयता का उल्लेख तो करता है, परन्तु इनको दूर करने के लिए कोई निश्चित निर्देश नहीं देता ।

### 3 जैवकीय जनसंख्या सिद्धान्त (Biological Theory of Population)

जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ खोज जीव शास्त्र के विद्वानों (Biologists) ने भी की है । उनके अनुसार जनसंख्या पहले धीरे-धीरे बढ़ती है, इसके पश्चात् बड़े वेग से बढ़ने लगती है । इसके पश्चात् वह स्थिर हो जाती है या घटने लगती है । कुछ समय के पश्चात् घटने की गति भी एक निश्चित बिन्दु तक तीव्र रहती है । उसके पश्चात् वह पुनः बढ़ना प्रारम्भ कर देती है । परन्तु इस प्रकार जनसंख्या के पुनः घटन की प्रवृत्ति जिस बिन्दु से प्रारम्भ होती है वही जनसंख्या पहले जितनी थी उससे अधिक हो रही है ।

इन सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिका के जीव शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रेमण्ड पर्ल (Prof Raymond Pearl) ने फल की मधिवर्षी की वृद्धि के अध्ययन के आधार पर किया था । उनका मत था कि प्रारम्भ में जीवन-निर्वाह के साधनों का अभाव होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि मंदी होती या खींची गति से होती है । उसके पश्चात् आर्थिक कठिनाइयों को दूर होने तथा जीवन-निर्वाह के साधनों और सम्पत्तियों का विकास होने पर जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है । परन्तु यह वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही सम्भव है । सम्पत्तियों की चरम सीमा पर पहुँचने पर उसके बढ़ने का क्रम समाप्त हो जाता है और वह स्थिर हो जाती है या घटने की प्रवृत्ति व्यक्त करती है ।

कुछ विद्वानों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की सत्यता का प्रमाणित करने के लिए यह बतलाया है कि योरोप के कई देशों में जनसंख्या में वृद्धि इसी क्रम से हुई है, फिर भी यह सिद्धान्त मंदेव और सबन लागू नहीं होता । इसके दो कारण हैं—प्रथम तो यह है कि इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में मनुष्यों तथा मानव समाज का अध्ययन नहीं किया गया है, अतः जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति का आधार किसी अन्य जीवधारी की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति को नहीं बनाया जा सकता । द्वितीय यह कि वानावरण के परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के विचारों, आचरण आदि पर भी पड़ता है जिससे परोक्ष रूप से जनसंख्या की वृद्धि भी प्रभावित होती है ।

#### 4 जनसंख्या की वृद्धि को ज्ञात करने की अन्य विधियाँ

जनसंख्या की वृद्धि को ज्ञात करने की अन्य विधियाँ भी प्रयोग में लायी जाती हैं जिनमें पर्ल का वाइटल इन्डेक्स (Pearl's Vital Index) तथा कुजिन्स्की की वास्तविक पुनरुत्पादन दर (Net Re-production Rate) की विधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

##### (अ) पर्ल का वाइटल इन्डेक्स (Pearl's Vital Index) :

इस विधि के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि या कमी को बच्चों के जन्म तथा उनकी मृत्यु की दरों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। प्रो० पर्ल के अनुसार जनसंख्या हमेशा बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है। यदि किसी देश में अधिक बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं परन्तु उसकी मृत्यु दर कम है तो निश्चित हो रहा जनसंख्या बढ़ेगी। परन्तु यदि बच्चों की जनन दर कम हो और उनकी मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घटेगी। यदि बच्चों की जनन दर तथा मृत्यु दर समान हो अर्थात् जितने बच्चे जन्म लेते हैं उतने ही मर जाते हैं, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। इस प्रकार इस सिद्धान्त के आधार पर जनसंख्या को यदि ग्राफ पर दिखाया जाये तो अंग्रेजी अक्षर 'S' के आकार की एक रेखा बनेगी जिसे लॉजिस्टिक रेखा (Logistic curve) कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक दृष्टि से श्रम की पूर्ति के सम्बन्ध में यह ज्ञात किया जा सकता है कि यदि जन्म लेने वाले बच्चे एक निश्चित आयु तक नहीं मरते, तो श्रम बाजार में एक निश्चित समय के पश्चात् नए श्रमिकों की वृद्धि किम सीमा तक हो सकती है? जब किसी देश में बाल्य-मरणशून्यता के विकास तथा औपधि-विज्ञान की प्रगति के कारण शिशु मरणशून्यता (Infantile Mortality) कम होती है, तब तब निश्चित अवधि के पश्चात् देश में जनसंख्या अधिक होगी।

आलोचना एवं दोष - जनसंख्या में कमी व वृद्धि को ज्ञात करने की यह विधि दोष पूर्ण है। इस विधि के अन्तर्गत जनसंख्या में कमी या वृद्धि के सम्बन्ध में निकाले गए निष्कर्ष निश्चित रूप से ठीक नहीं होते, क्योंकि यह सिद्धान्त इस पक्ष पर ध्यान नहीं देता कि कितने बच्चे शिशु-मरणशून्यता की आयु पार कर जाते हैं तथा वे उस आयु पर पहुँच जाते हैं जिस पर वे बच्चे उत्पन्न कर सकें। हो सकता है कि वे शिशु मरणशून्यता की आयु तो पार कर लें, परन्तु बच्चे उत्पन्न करने की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाये। वाइटल इन्डेक्स-विधि इस तथ्य पर ध्यान नहीं देती।

##### (ब) शुद्ध या वास्तविक पुनरुत्पादन दर (Net Re production Rate) :

किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है या स्थिर है? यह ज्ञात करने के लिए 'वास्तविक पुनरुत्पादन दर' विधि का प्रयोग अधिक प्रचलित हो गया है।

इस तरीके के अधिक व्यापक प्रयोग का श्रेय Kuczynski को है। उनके विचार से जिस दर से स्त्री-जानि अपने आपकी प्रतिस्थापित या अपने स्थान की पूर्ति करती है, वह वास्तविक पुनरुत्पादन दर कहलाती है।<sup>3</sup> यदि 1,000 औरतें 1,000 लड़कियों को जन्म देती हैं जो सन्तानोत्पादन आयु (15 वर्ष से 45-50 वर्ष) तक जीवित रहती हैं तो वास्तविक पुनरुत्पादन दर 1 होगी जो यह व्यक्त करेगी कि जनसंख्या स्थिर है। यदि 1,000 औरतें 1,000 लड़कियाँ पैदा करती हैं जिनमें से 800 ही सन्तानोत्पादन की आयु में जीवित रहती हैं तो यह दर 1 से घटकर  $\frac{800}{1000}=0.8$  हो जायेगी जो जनसंख्या के स्थिति को व्यक्त करती है। परन्तु यदि सन्तान पैदा करने वाली 1,000 औरतों की पूर्ति 1,200 औरतों द्वारा हो जाती है तो पुनरुत्पादन दर  $\frac{1200}{1000}=1.2$  हो जायेगी, जिससे यह ज्ञात होगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

इस विधि के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि या उसमें कमी की पुनरुत्पादन दर को ज्ञात करने के लिए कुछ माध्यमिक तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कितनी स्त्रियाँ किस दर पर अपने अपनी पूर्ति करती हैं, अर्थात् कितनी औरतें कितनी लड़कियों को जन्म देती हैं, इनमें से कितनी लड़कियाँ सन्तानोत्पादन आयु में जीवित रहती हैं, इनमें से कितनी लड़कियाँ विवाह करती हैं, विवाह करने वाली लड़कियों में से भी कितनी लड़कियाँ विधवा हो जाती हैं, तथा देश में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए गर्भ-निरोधक उपायों का प्रयोग किया जाता है या नहीं? इन तथ्यों और मापकों को ध्यान में रखकर ही वास्तविक पुनरुत्पादन दर ज्ञात की जा सकती है।

### 5 जनसंख्या तथा श्रम पूर्ति (Population and Labour Supply)

जनसंख्या के सम्बन्ध में नवीनतम विचारधारा के अन्तर्गत इस तथ्य एवं समस्या पर विचार किया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या से सक्रिय श्रम की पूर्ति किस सीमा तथा अनुपात में की जाती है और देश की अर्थ-व्यवस्था को किस सीमा तक विकसित किया जाय ताकि श्रम की उत्पादकता का अधिकतम किया जा सके? इसी आधार पर नियोजित अर्थ-व्यवस्था का ढांचा खड़ा किया जाता है, रोजगार के अधिक से अधिक साधनों का विकास किया जाता है तथा श्रम की सहायता में राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत आय को अधिकतम करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या की समस्या के अध्ययन में विशेष रुचि इसलिए दिलायी है कि वह श्रम शक्ति का स्रोत है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर ही एक निश्चित अर्थ के गश्चान् श्रमिकों की संख्या में वृद्धि सम्भव है। इसी तथ्य के

<sup>3</sup> "The net reproduction rate shows the rate at which the female population is replacing itself"

आधार पर जनसंख्या तथा अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन एवं समन्वय स्थापित करने के लिए जनसंख्या-नीति तथा आर्थिक नीति निर्धारित की जाती हैं। जनसंख्या का आर्थिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी समय-विशेष में एक देश की जनसंख्या पर वहाँ की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ उस देश के आर्थिक विकास की नीति को निर्धारित करने में सहायक होती हैं। इन दोनों ही दृष्टिकोणों का समन्वय जनान्विक परिवर्तन के सिद्धान्त (Theory of Demographic Transition) में किया गया है और इस सिद्धान्त के अनुसार ही अब जनसंख्या की समस्या का अध्ययन किया जाता है।

**अधिकसित अर्थ-व्यवस्था में जनसंख्या की समस्या।**

अधिकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए प्राथमिक उद्योग—कृषि को ही महत्व देता है। अर्थ-व्यवस्था के रुढ़िवादिता एवं पुरानी परम्पराओं व मान्यताओं को अधिक महत्व दिया जाता है और मनुष्य भाग्य-वादी होता है। वह कृषि के अनिश्चित अर्थ किसी उद्योग का विकास स्वयं करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। राष्ट्रीय आय कम होती है और प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम रहती है। बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास न होने के कारण शारीरिक श्रम द्वारा ही आय का वृद्धि सम्भव हो पाती है। पारिवारिक आय तथा सुरक्षा के लिए परिवार में अधिक सदस्यों का होना आवश्यक हो जाता है जिससे देश में जन्म दर अधिक होती है। परन्तु जीवन-स्तर नीचा होने के कारण तथा बड़े परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन-निर्वाह के साधन न होने के कारण नैसर्गिक अवरोध कार्यशील रहत हैं जिससे मृत्यु-दर भी अधिक रहती है। इस प्रकार अधिकसित अर्थ व्यवस्था में—

(1) जन्म दर तथा मृत्यु-दर दोनों ही अधिक होती हैं (2) पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए लोग कम उम्र से ही उत्पादन कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, (3) जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात अधिक होता है, क्योंकि जनसंख्या शीघ्र बढ़ती तो है, परन्तु मृत्यु दर अधिक होने के कारण कार्यशील आयु (15—60) वाले अधि लोग जातिन नहीं रहने बिना जनसंख्या में कार्यशील श्रम शक्ति का अभाव रहता है, (4) स्त्रियाँ अधिक विद्याओं में भाग नहीं लेती जिससे देश के उत्पादक श्रम का मात्र व्यर्थ चला जाता है (5) जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय और भी घटती जाती है जिसके फलस्वरूप बचत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। बचत न होने के कारण देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूँजी का निर्माण करना कठिन हो जाता है, तथा (6) मनुष्य का जीवन-काल कम होने के कारण देश में श्रम-शक्ति कम रहती है।

## प्रश्न व संकेत

1. माल्यस के सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा उसकी सीमाएँ बताइए।

(Raj, B A 1964)

[संकेत प्रश्न को तीन भागों में विभक्त कर प्रथम भाग में माल्यस का जनसंख्या विचार प्रस्तुत कीजिए। द्वितीय भाग में इसकी आलोचना कीजिए और तीसरे भाग में माल्यस के सिद्धान्त की व्यावहारिकता पर प्रकाश डालिए।]

2. अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त को बताइए तथा उसकी विवेचना कीजिए।

(Nagpur, B Com I, 1967, 1964)

[संकेत सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त का प्रर्थ बताइए। द्वितीय भाग में इसकी प्रमुख आलोचनाएँ बताते हुए निष्कर्ष दीजिए।]

3. "माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त निराशावादी है तथा अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त आशावादी है। परन्तु उनमें से कोई भी एक पूर्ण जनसंख्या का सिद्धान्त नहीं है।"

(Bihar, 1960, Indore, B, Com I, 1965)

[संकेत : सर्वप्रथम माल्यस के जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। द्वितीय भाग में अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तृतीय भाग में दोनों सिद्धान्तों की तुलना कीजिए। अन्त में निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि दोनों ही सिद्धान्त अपूर्ण हैं।]

4. एक देश की जनसंख्या के विकास तथा उसके आर्थिक विकास के बीच सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए।

(Delhi, B A Pass, 1961)

[संकेत प्रश्न में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।]

## पूँजी तथा पूँजी-निर्माण

(Capital & Capital Formation)

*"The proximate causes of economic growth are the effort to economize the accumulation of knowledge and its application, and the accumulation of capital"*

Arthur Lewis

पूँजी वर्तमान उत्पादन-व्यवस्था का आधार है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, नयी तथा आधुनिक तकनीकी विधियों का प्रयोग, विनिष्ठीकरण तथा उन्नत एवं वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली पूँजी के बिना सम्भव नहीं है। इसीलिए वर्तमान उत्पादन को पूँजी-मूलक उत्पादन कहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की भ्रम-व्यवस्था हा (पूँजीवाद या समाजवादी) पूँजी के अभाव में आधुनिक उत्पादन सम्भव नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आर्थिक विकास के लिए पूँजी ही सब कुछ है। पूँजी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है, परन्तु पर्याप्त तत्व नहीं है।

### 1. पूँजी का अर्थ (Meaning of Capital)

सामान्यतया लोग पूँजी शब्द का प्रयोग धन या सम्पत्ति के अर्थ में करते हैं, परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। पहले के अर्थ-शास्त्री पूँजी के स्थान पर स्टॉक (Stock)<sup>2</sup> शब्द का प्रयोग करते थे। एडम स्मिथ के अनुसार, पूँजी 'स्टॉक' का वह भाग है जिससे कोई व्यक्ति आय प्राप्त करने की आशा करता है। चैपमैन (Chapman) के अनुसार, "पूँजी धन का वह भाग है जिससे आम प्राप्त होती है अथवा जो आय प्राप्त करने में सहायक होता है अथवा

<sup>1</sup> "Capital is a necessary but not a sufficient condition of progress"

—Nurkse

<sup>2</sup> स्टॉक का अभिप्राय पुराने अर्थशास्त्रियों के अनुसार, उत्पादक के लिए उपयोग सम्बन्धी वस्तुओं, यन्त्र, औजार तथा मुद्रा से है।

ऐसा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।" प्रोफेसर बेनहम ने पूँजी शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है। उनके शब्दों में, "वर्तमान समस्त पूँजी (प्रकृति के मौलिक उपहार के अतिरिक्त) पिछले वर्षों की उत्पत्ति का भाग है। वह भूतकाल की उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति (Heritage) है। यह वह उत्पादन है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है जिसको बेकार समझकर परित्याग नहीं कर दिया गया है और जिसका अभी तक उपयोग भी नहीं किया गया है। सामाजिक उत्पादन में से सामाजिक उपयोग को घटाने के पश्चात् शेष श्रम की ही एक समान की निमित्त पूँजी अथवा बचत या उसका विनियोग कहते हैं।"<sup>3</sup> किशोर के अनुसार, "पूँजी वह सम्पत्ति है जो मनुष्य द्वारा किये गये पहले के श्रम का परिणाम है, परन्तु जिसका उपयोग साधन के रूप में अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाता है।" (Capital is the product of past labour, but which is used as means of further production) यहम बावर्क (Bohm Bawark) ने मनुष्य के श्रम द्वारा उत्पादित होने के कारण पूँजी का 'उत्पादन का उत्पादित साधन' (Produced means of production) माना है।

पूँजी की उपर्युक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि पूँजी के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व हैं

(1) पूँजी प्रकृति का निःशुल्क उपहार नहीं है। यह मनुष्य द्वारा निमित्त या उत्पादित होती है :

(ii) पूँजी मनुष्य के पूर्व श्रम का फल है जिसका प्रयोग अधिक धन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

(iii) सभी पूँजी सम्पत्ति है, परन्तु वे सभी वस्तुएँ, जो सम्पत्ति कहलाती हैं, पूँजी नहीं हैं। सम्पत्ति का वही भाग पूँजी है, जो अतिरिक्त सम्पत्ति या धन का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

## 2 पूँजी के भेद (Kinds of Capital)

पूँजी एक विस्तृत शब्द है, क्योंकि पूँजी का प्रयोग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। उत्पादन कार्य में ही इसका प्रयोग कई प्रकार से किये जाने के कारण इनके अन्वलिखित भेद किये गये हैं

"All our present capital (apart from any original gifts of nature formed part of the output of some former years. It is a heritage from the past. It is output which has not yet been used up, discarded, consumed. The capital formation or investment or saving of a community during any year is its output during that year minus its consumption during that year."

(i) स्थायी पूँजी (Fixed Capital) के अन्तर्गत ममस्त स्थायी, अचल तथा टिकाऊ सम्पत्तियाँ, जैसे फैक्टरी, गोदाम, कार्यालय, दुकान, यन्त्र एवं कल, औजार, कृषि-यन्त्र एवं उपकरण, परिवहन तथा सदेगवाहन के साधन आदि जो विभिन्न उद्योगों एवं व्यापारों में स्थायी रूप से प्रयोग में लाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। मिल (Mill) के अनुसार, "अचल या स्थायी पूँजी वह है जो टिकाऊ होती है तथा जिससे कुछ समय तक बराबर आय मिलती रहती है।" (Fixed capital is that which exists in durable shape and the return to which it spread over a period of corresponding duration)

(ii) चल पूँजी (Floating Capital) के अन्तर्गत उन समस्त वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए एक ही बार प्रयोग में आने के बाद अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, जैसे कच्चा माल, ईंधन, उत्पादन-विधियों में प्रयुक्त अर्द्ध-निर्मित वस्तुएँ, उत्पादकों तथा व्यापारियों के पास कच्चे माल, अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का स्टॉक आदि। इस प्रकार मिल (Mill) के अनुसार चल पूँजी वह है जो उत्पादन में एक ही बार के प्रयोग से उत्पादन में अपना सारा कार्य समाप्त कर लेती है। (Circulating capital is that which fulfils the whole of its office in production in which it is engaged by a single use)

(iii) कार्यशील पूँजी (Working Capital) का अभिप्राय उस मुद्रा में है जिसका उपयोग उत्पादक द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए किया जाता है।

(iv) उत्पादन तथा उपभोग पूँजी (Production and Consumption Capital) अतिरिक्त धन के उत्पादन में सहयोग देने वाली पूँजी उत्पादक पूँजी कहलाती है। धन वे सभी वस्तुएँ जो उत्पादन कार्य में धन की सहायता करती हैं, जैसे मशीन, कच्चा माल आदि, पूँजी के अन्तर्गत आती है (Production capital consists of all goods that aid labour in production)। इसके विपरीत श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएँ जो अप्रत्यक्ष रूप से (indirectly) उत्पादन कार्य में सहायक होती हैं, उपभोग पूँजी कहलाती हैं।

इनके अनिश्चित उपभोक्ताओं के पास की टिकाऊ वस्तुएँ तथा उपभोक्ताओं द्वारा संप्रदाय की गयी उपभोग-वस्तुओं को भी पूँजी कहा जा सकता है। वेनहून् का यह विचार है कि उपभोक्ताओं के पास की समस्त सम्पत्तियाँ, चाहे वे टिकाऊ एवं अचल हों या न हों, यदि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं और यदि उनका मूल्य मुद्रा के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है तो इनको धन या पूँजी की संज्ञा दी जा सकती है। इस आधार पर उपभोक्ताओं के मकान, मोटरकार, टेलीवीजन, फर्नीचर, यहाँ तक कि पहनने के



कपडों तथा संग्रहीत खाद्य पदार्थों को भी पूँजी के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है, परन्तु व्यापारिक दृष्टिकोण से इनको पूँजी कहना उचित नहीं है।

(v) भौतिक तथा व्यक्तिगत पूँजी (Material and Personal Capital) वह पूँजी जो मूर्त (Concrete) तथा स्थूल (tangible) रूप में मौजूद रहती है तथा जो विनिमयसाध्य होती है, अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित की जा सकती है, जैसे मशीन, औजार, माल आदि, भौतिक पूँजी कहलाती है। व्यक्तिगत पूँजी का अर्थ मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों से है, जो प्रमूर्त तथा अहस्तांतरणीय (non-transferable) होते हैं। इस पूँजी के अन्तर्गत श्रमिकों की कार्य कुशलता तथा व्यक्तियों की योग्यताएँ सम्मिलित की जाती हैं।

(vi) विशिष्ट तथा अविशिष्ट पूँजी (Specialised and Non Specialised Capital) वह पूँजी जो किसी कार्य विशेष के लिए ही प्रयोग न लायी जाती है, जैसे रेल का इंजन, विशिष्ट पूँजी (Specialised or sunk capital) कहलाती है। तब कि इस पूँजी को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इनको एक-अर्थी पूँजी भी कहा जाता है। परन्तु उस पूँजी को जो कई कामों में प्रयोग की जा सकती है, जैसे नकद रुपया बहु-अर्थी या अविशिष्ट पूँजी (Floating or non-specialised) पूँजी कहते हैं। अविशिष्ट पूँजी अधिक गतिशील होती है, क्योंकि इसको कहीं पर किसी भी काम में लगाया जा सकता है।

(vii) वेतन पूँजी तथा सहायक पूँजी (Remunerative Capital and Subsidiary Capital) श्रमिकों को दी गयी नकद मजदूरी, वेतन पूँजी (Remunerative Capital) कहलाती है। वह पूँजी जो उत्पादन कार्य में सहायक होती है, सहायक पूँजी (Subsidiary Capital) कहलाती है, जैसे मशीन, औजार आदि।

(viii) व्यक्तिगत पूँजी (Individual Capital), सामाजिक पूँजी (Social Capital), राष्ट्रीय पूँजी (National Capital) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी (International Capital) अधिकार के आधार पर वह पूँजी जिस पर किसी एक व्यक्ति, कर् अधिकार होता है, व्यक्तिगत पूँजी कहलाती है, जैसे मकान, फर्नीचर, आदि। उस पूँजी को जिस पर मारे समाज का अधिकार होना है जैसे सड़क, पार्क आदि, सामाजिक पूँजी, कहने हैं। राष्ट्र के अधिकार में रहने वाली सम्पत्तियाँ तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक पूँजी, राष्ट्रीय पूँजी कही जाती है। परन्तु जब किसी पूँजी पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, बल्कि सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है, जैसे एक निश्चित सीमा के बाद वायु मार्ग, समुद्री मार्ग आदि तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी कहते हैं।

अतः अर्थशास्त्र में उन समस्त सम्पत्तियों या उस धन को ही पूँजी कहना ठीक होगा जो वस्तुया तथा सेवाओं के उत्पादन में सहायक हों। इस प्रकार मशीन, भवन परिवहन के साधन, बच्चा माल, अर्द्ध निर्मित वस्तुएँ, ईंधन का स्टॉक तथा सार्वजनिक या सामाजिक उपयोग की सम्पत्तियाँ, जैसे अस्पताल, शिखर-सत्यायें, बाघ, नहरे, गंस, बिजली घर बन्दरगाह आदि, को पूँजी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये सम्पत्तियाँ पूँजी इसलिए कही जाती हैं क्योंकि यह सब भूमि और श्रम के सम्मिलित प्रयत्न से प्राप्त की गयी है तथा इनका प्रयोग उत्पादन के साधनों के रूप में किया जाता है। यह प्रतिकूल धर्मियों के श्रम के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त होता है। अतः कार्ल मार्क्स ने पूँजी का श्रम का ही फल माना है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी पूँजीगत सम्पत्ति (Capital Assets) का उत्पादन या निर्माण पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक एक निश्चित निरूपण के अनुसार ही किया गया है। श्रम और भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई पूर्व निर्धारित निर्णय नहीं होता। यही कारण है कि पूँजी को भूमि तथा श्रम से भिन्न माना गया है।

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने 'पूँजी' का प्रयोग निम्नलिखित व्यापक अर्थों में किया है :

(अ) पूँजी तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार-पत्र या विलेख (Title of Ownership or Deed) सामान्यतया पूँजी के अन्तर्गत उन अधिकार पत्रों या विलेखों (Titles of Ownership or Deeds) को शामिल किया जाता है जो किसी प्राय का उत्पादन करने वाली पूँजीगत सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं। इनके अतिरिक्त पूँजी का अतिप्राय ऋण-पत्रों (Bonds), अर्थात् एव स्टॉक (Shares and Stock), प्रतिभूतियों (Securities) आदि में भी है। पूँजीवादी देश में पूँजीगत सम्पत्तियों पर व्यक्तिगत अथवा कम्पनी के अन्तर्धारियों का अधिकार होता है। फर्म की सम्पत्तियों पर साझीदारों की पूँजी की मात्रा ही उनके स्वामित्व का परिचय करती है। साम्यवादी तथा ममजवादी दल में देश की समस्त सम्पत्तियों या पूँजी पर राष्ट्र का अधिकार होता है।

परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है - प्रथम तो यह कि उत्पादन के सम्बन्ध में केवल वास्तविक पूँजीगत सम्पत्तियों (Real Capital Assets) को ही पूँजी माना जाता है, क्योंकि उत्पादन के साधन के रूप में वास्तविक पूँजीगत सम्पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, न कि उनके अधिकार पत्रों का, द्वितीय, यह कि पूँजीगत सम्पत्तियों के अधिकार-पत्रों के हस्तान्तरण या अर्थात् एव ऋण-पत्रों के त्रय विक्रय का अन्तिम लक्ष्य उत्पादन के लिए पूँजीगत सम्पत्तियों को प्राप्त करना ही होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए

वैक से ऋण प्राप्त किया जाये तो प्राप्त धन को यन्त्र, मवन, कच्चा माल आदि में परिवर्तित कर लिया जायेगा। केवल ऋण-पूँजी से वस्तुओं का उत्पादन सम्भव नहीं हो सकेगा। पूँजी की गणना करते समय ऋण के लिए दी गयी स्वीकृति का अस्तित्व केवल हिमाय-किताब के लिए ही होता है। उत्पादन के लिए उस ऋण से प्राप्त की गयी पूँजीगत सम्पत्तियों को ही पूँजी माना जायेगा। इसी प्रकार अगो तथा ऋण-पनों का निर्बन्धन करने पर प्राप्त धन से कम्पनी स्थायी तथा कार्यशील सम्पत्तियाँ ऋण करती है और अपनी पूँजी को वास्तविक पूँजीगत सम्पत्तियों में परिवर्तित कर लेती है। इन वास्तविक सम्पत्तियों की सहायता से ही औद्योगिक उत्पादन अथवा बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्य किया जाता है।

(ब) मुद्रा और पूँजी : मुद्रा (Money) सम्पत्ति और धन (Wealth) का ही एक रूप है। व्यक्ति, व्यक्ति-समूह, कम्पनी अथवा राष्ट्र की पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किए जाते हैं, परन्तु उत्पादन के साधन के रूप में पूँजी और मुद्रा को एक नहीं माना जाता है। पूँजी का अर्थ वास्तविक पूँजीगत सम्पत्तियों से ही लगाया जाता है, क्योंकि उत्पादन के लिए नक़द धन या तरल सम्पत्ति (Liquid Asset) के रूप में मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। पूँजी के रूप में उसका वास्तविक प्रयोग तो उसे पूँजीगत सम्पत्तियों में परिवर्तित करके ही सम्भव हो पाता है।

(स) भूमि और पूँजी : कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि भूमि को पूँजी के अन्तर्गत ही सम्मिलित करना चाहिए। यह ठीक है कि भूमि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है, परन्तु उस पर समाज, राष्ट्र या व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके प्रयोग का अधिकार, उसका मूल्य चुकाय बिना प्राप्त नहीं होता। अतः उसका मूल्य होने का कारण उसे पूँजी ही मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि जिन रूप में प्राप्त होती है उसी रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसे उत्पादन के योग्य बनाने के लिए उस पर कुछ न कुछ धन व्यय करना पड़ता है। अतः वह मूल्यवान् सम्पत्ति के रूप में पूँजी की श्रेणी में रखी जाती है। परन्तु जिन विद्वानों का यह मत है कि भूमि पूँजी नहीं है, उनका यह कहना है कि भूमि प्रकृति की देन है जो नष्ट नहीं होगी जबकि पूँजी मनुष्य के श्रम द्वारा पैदा होती है तथा नष्ट हो जाती है। भूमि के स्थायित्व के कारण भी उसे पूँजी से भिन्न माना गया है, क्योंकि पूँजी में स्थान तथा उपयोग सम्बन्धी गतिशीलता दोनों ही हैं, जबकि भूमि में इस गुण का अभाव है।

(द) श्रम और पूँजी : पूँजी श्रमिकों के पूर्व परिश्रम का फल है। अतः उत्पादन के साधन के रूप में पूँजी की अपेक्षा श्रम का महत्व अधिक है। एक व्यक्ति का आजीवन अथवा मानसिक श्रम आय प्राप्त करने में सहायक होता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि मनुष्य के श्रम एवं गुण की व्यक्तिगत पूँजी की सहा

दी जा सकती है। परन्तु पूँजी की तरह श्रम में वृद्धि सम्भव नहीं होती। गतिशीलता का अभाव तथा क्षयशीलता के दोषों के कारण श्रम को पूँजी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। श्रम के सम्बन्ध में पूर्वं आयोजित निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। श्रमिकों के कार्य कौशल पर व्यय किए गए धन को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि पूँजी का विनियोजन करने के लिए पूर्वं निर्णय लेना सम्भव होता है तथा विनियोजित पूँजी उत्पादित वस्तुओं के रूप में पुनः वापस प्राप्त हो जाती है। इन कारणों के आधार पर ही पूँजी श्रम से निम्न होती है।

### 3. पूँजी की विशेषताएँ (Characteristics of Capital)

(1) निष्क्रियता पूँजी उत्पादन का एक निष्क्रिय माधन है। भूमि की तरह पूँजी के होने पर भी यदि 'श्रम' न हो तो पूँजी का कोई महत्व नहीं होगा यही कारण है कि वाल्टर मार्क्स मादि विद्वानों ने श्रम को अधिक महत्व प्रदान किया है।

(2) मनुष्य कृत माधन पूँजी उत्पादन का एक मनुष्य कृत माधन है। यह मनुष्य के पूर्वं श्रम का फल है, तथा उसके भूतकालीन उत्पादन का अंश है जो भविष्य में उत्पादन के लिए बचत के रूप में रखा जाता है।

(3) पूँजी में उत्पादकता होती है वह सम्पत्ति ही पूँजी है जो अतिरिक्त धन-सम्पत्ति का उत्पादन करती है। अतः पूँजी उत्पादक होती है। यही कारण है कि उत्पादन पूँजी की मांग करते हैं।

(4) अनिवार्य साधन नहीं है पूँजी को उत्पादन का अनिवार्य माधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूँजी के रहने पर भी यदि आधारभूत साधन भूमि और श्रम उपलब्ध नहीं हों तो उत्पादन-कार्य सम्भव नहीं हो सकता। परन्तु आज के युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा तकनीकी उत्पादन के लिए पूँजी को अनिवार्य साधन माना जाता है।

(5) पूँजी परिवर्तनशील है पूँजी की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी मरतता से की जा सकती है। उसके सम्बन्ध में पूर्व-निर्णयों के आधार पर पूँजी-निर्माण की योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक बचत को बढ़ाकर पूँजी भी बढ़ायी जा सकती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत उपभोग तथा सामाजिक उपभोग में वृद्धि करके पूँजी में आवश्यकतानुसार कमी भी की जा सकती है।

(6) पूँजी अस्थायी साधन पूँजी, भूमि की तरह स्थायी (Permanent) साधन नहीं है। एक निश्चित समय तक प्रयोग करने के बाद पूँजी, जैम मशीन, नष्ट हो जाती है। अतः उसका फिर से उत्पादन करना पड़ता है अथवा उसकी पूर्ति नये सिरे से करनी पड़ती है।

(7) पूँजी यतिशील साधन है : उत्पादन के साधनों में सबसे अधिक गतिशील साधन पूँजी है। उसको विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तथा विश्व के किसी स्थान पर मरलतापूर्वक भेजा जा सकता है। पूँजी के उपलब्ध होने पर देश का आर्थिक विकास सम्भव हो पाता है।

#### 4 पूँजी का महत्व (Importance of Capital)

वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में पूँजी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि पूँजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है फिर भी भूमि और श्रम को कार्य में लगाने में पूँजी ही सहायक होती है। पूँजी, मशीन आदि की सहायता से ही श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, मनुष्य भौतिक साधना का पूर्ण-लाभ उठा पाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन पूँजी की सहायता से ही सम्भव हो सका है तथा श्रम-विभाजन और तकनीकी विधियों के प्रयोग पूँजी की ही देन है। पूँजी ही उत्पादन की प्रक्रियाओं को जारी रगती है, क्योंकि वस्तुएँ निर्मित होने के फौरन बाद ही नहीं बिक जाती। ऐसी स्थिति में उत्पादित वस्तुओं में खरीदी पूँजी कुछ समय तक फसी रहती है। अन्तर्गत के रूप में पूँजी उत्पादन कार्य को निरन्तर बनाये रखने में सहायक होती है। उपभोक्ता को भी अपनी जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त होते रहते हैं। उत्पादन के साधन ही माध्यम वस्तुओं की विपरीत तथा कच्चे माल खरीदने के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। विक्री के लिए यातायात तथा मदेनवाहन के साधन आवश्यक हैं, जो पूँजी के ही रूप हैं। कच्चा माल भी पूँजी ही है और उसे प्राप्त करने के लिए भी पूँजी के रूप में तकद धन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था में पूँजी का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य स्थान है।

पूँजी की आवश्यकता प्रत्येक प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में पड़ती है। चाहे वह साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था हो या पूँजीवादी। दोनों ही अर्थ व्यवस्थाओं में प्रतिक्रम राष्ट्रीय उत्पादन का लक्ष्य पूँजी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति आने के लिए नए-नए उद्योग-धन्धों को स्थापित करना आवश्यक है। ये उद्योग धन्धे पूँजी के प्रभाव में स्थापित नहीं किये जा सकते। पूँजी के नहीं रहने पर न तो स्यात्तम आया हो बढ़ सकती है और न ही लोगों का जीवन स्तर ही ऊँचा उठ सकता है। कोई भी देश, चाहे वह विकसित (Developed) हो, अर्ध-विकसित (Under developed) हो या अविकसित (Underdeveloped) हो, पूँजी के बगैर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की योजनाएँ पूरी नहीं कर सकता।

#### 5. पूँजी-निर्माण तथा पूँजी-संचय

##### (Capital Formation and Accumulation)

आर्थिक विकास के लिए पूँजी-निर्माण एवं संचय अत्यन्त आवश्यक है।

पूँजी-निर्माण का अर्थ देश में अतिरिक्त उत्पादन के उत्पादित साधनों (Produced means of further production) अर्थात् 'उत्पादक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि से होता है। प्रो० नर्कसे (Prof Nurkse) के अनुसार, "पूँजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज अपनी वर्तमान उत्पादन क्रियाओं द्वारा तत्कालीन उपभोग की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो नहीं करता, बल्कि वह उनका एक अक पूँजीगत सम्पत्तियों के बनाने के लिए भी प्रयुक्त करता है। औजार तथा उपकरण, धातु तथा परिवहन की सुविधाएँ, कल और यन्त्र आस्तविक पूँजी के रूप हैं जो उत्पादन प्रयत्नों के प्रभाव में अधिक वृद्धि कर सकते हैं।" <sup>4</sup> यह उभी समय सम्भव हो सकता है तब कि समस्त वर्तमान राष्ट्रीय उत्पादन या आय का उपभोग न किया जाय और उसके एक भाग या अंश को बचत के रूप संचित किया जाये। परन्तु पूँजी निर्माण के लिए केवल बचत का संचय ही काफी नहीं है। उसका उचित विनियोजन (Investment) भी आवश्यक है जिससे प्रति वर्ष अतिरिक्त पूँजीगत सम्पत्तियों जैसे औद्योगिक मशीनों भूमि, कृषि यन्त्रों तथा बीजारों, मिचवाई तथा परिवहन के साधनों आदि का निर्माण एवं उत्पादन सम्भव हो सके। विकसित तथा विजासोन्मुख (Developed and Developing) दोनों प्रकार के देशों में, जहाँ पर पूँजी निर्माण तथा पूँजी-विस्तार या पूँजी की पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक होता है राष्ट्रीय उत्पादन के कुछ अंश को बचाना आवश्यक है, जिससे पूँजी-निर्माण तथा संचय की प्रक्रिया बराबर चलती रहे।

पूँजी-निर्माण (Capital Formation) तथा पूँजी के संचय (Accumulation of Capital) के सम्बन्ध में क्रमशः पूँजी गहन (deepening of Capital) तथा पूँजी विस्तार (Capital sparse or widening of capital) की विधियों का उल्लेख किया जाता है। 'पूँजी गहन विधि' का अतिप्राम्य पूँजी निर्माण से है। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति तथा समाज की बचत को एकत्र करके वर्तमान पूँजीगत सम्पत्तियों की महारत से अतिरिक्त पूँजी, मशीन, औजार आदि का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है जिससे न केवल पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों तथा पूँजीगत सम्पत्तियों के स्थान पर नयी पूँजीगत सम्पत्तियों का प्रयोग सम्भव हो पाता है, बल्कि नए नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी मशीनों

<sup>4</sup> "The meaning of 'capital formation' is that society does not apply the whole of its current productive activity to the needs and desires of immediate consumption, but directs a part of it to the making of capital goods tools and instruments, machines and transport facilities, plants and equipment—all the various forms of real capital that can greatly increase the efficiency of productive efforts."

आदि का उत्पादन सम्भव होता है। विकसित देशों में जहाँ पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, अर्थनवीकरण (Rationalisation) की योजनाएँ पूँजी-निर्माण द्वारा ही कार्यान्वित की जाती हैं। परन्तु एक विकसित (developing) देश में जहाँ औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी (basic) उद्योगों तथा औद्योगिक ढाँचे के आधार (infra-structure), परिवहन व शक्ति के माध्यम आदि, का निर्माण करना आवश्यक होता है, वहाँ पूँजी निर्माण का आशय इन समस्त उद्योगों के लिए नयी मशीनों तथा नये मायनों का निर्माण एवं उत्पादन से है। इन कार्यों के लिए पूँजी-विस्तार की विधि अपनायी जाती है। पूँजी विस्तार का अर्थ है पूँजी की कमी की पूर्ति करना। पूँजी की पूर्ति देश में वास्तविक वचन का निर्माण करके तथा लोगों की वचन की परत करके बढ़ायी जा सकती है। किन्तु देश में पर्याप्त मात्रा में वचन नहीं होने पर पूँजी की पूर्ति विदेशों तथा घनी राष्ट्रीय से ऋण एवं महापना लेकर बढ़ानी पड़ सकती है। इस प्रकार देश की आन्तरिक वचन (domestic savings) तथा विदेशी आर्थिक सहायता में पूँजी की मात्रा बढ़ती है। उसका प्रयोग पूँजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए किया जाता है। बाद में चक्कर ये पूँजीगत सम्पत्तियाँ ही पूँजी निर्माण, अर्थात् अतिरिक्त पूँजी का उत्पादन में सहायक होती हैं। इस प्रकार नयी औद्योगिक तथा व्यापारिक समस्याओं को हल करने, कृषि का आधुनिक तरीका में विकास करना, यानायात के मायनों को बढ़ाने, नदी नगी बन्दुबा का उत्पादन करना तथा रोजगार बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक अवस्था में पूँजी विस्तार की तथा बाद में पूँजी निमाण की विधियाँ अपनायी जाती हैं। वास्तव में एक विकसित देश के लिए पूँजी-विस्तार एक सञ्चालन प्रेरक शक्ति है जो पूँजी निर्माण की विधियों का शक्ति प्रदान कर आगे बढ़ती है।

पूँजी-विस्तार तथा पूँजी-निर्माण के सम्बन्ध में वचन का अर्थ वास्तविक वचन से है। वास्तविक वचन व्यक्तियों तथा फर्मों द्वारा आर से में बचाये गये उस धन को कहते हैं जो अतिरिक्त पूँजीगत सम्पत्तियों के उत्पादन के लिए अलग कर दी जाती है। इस वचन का समुचित विनियोजन आवश्यक है। इसके साथ ही माय लोगों में वचन करने की इच्छा एवं प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। वास्तविक वचन में पूँजी-निर्माण अभी समय सम्भव हो सकता है जबकि देश में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को पूँजी निर्माण के लिए वित्तिय तथा साधन की सुविधाएँ प्राप्त हो। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उपर्युक्त वचन का विनियोजन पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए ही किया जाये।

पूँजी निर्माण का अनुमान किसी भी देश में किसी एक निश्चित अवधि में कुल पूँजी-निर्माण का अनुमान केवल इस आधार पर ही नहीं लगाया जा सकता कि उस अवधि में कितनी अतिरिक्त पूँजीगत सम्पत्तियों का उत्पादन तथा निर्माण

हुआ है। उसमें आयात की गयी पूँजीगत परिसम्पत्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पूँजीगत सम्पत्तियों में वृद्धि का अनुमान निम्नलिखित विधि से ज्ञात किया जा सकता है :

$$\text{कुल पूँजी निर्माण} = \left\{ \begin{array}{l} \text{उत्पादित पूँजीगत सम्पत्तियाँ + आयात} \\ \text{की गयी पूँजीगत सम्पत्तियाँ} \end{array} \right\}$$

$$\text{Gross Capital formation} = \left\{ \begin{array}{l} (\text{Produced Means of Production} \\ + \text{Imports of Capital Assets} \end{array} \right\}$$

परन्तु वास्तविक पूँजी-निर्माण ज्ञात करने या पूँजीगत वस्तुओं में वास्तविक वृद्धि जानने के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त 'कुल पूँजी निर्माण' में से पूँजीगत सम्पत्तियों पर हानि के रूप में हुयी हानि को घटा दिया जाय। इस प्रकार वास्तविक पूँजी-निर्माण की गणना निम्नलिखित विधि में की जाती है।

$$\text{वास्तविक पूँजी निर्माण} = \left\{ \begin{array}{l} (\text{उत्पादित पूँजीगत सम्पत्तियाँ + आयात की गयी} \\ \text{पूँजीगत सम्पत्तियाँ) - वर्तमान पूँजीगत सम्प-} \\ \text{त्तियों में हानि} \end{array} \right\}$$

$$\text{Net Capital formation} = \left\{ \begin{array}{l} (\text{Produced Means of Production} + \\ \text{Imports of Capital Assets}) \\ \text{Depreciation on existing Capital} \\ \text{Assets} \end{array} \right\}$$

एक अधिकसिक्त देश में कुल उत्पादन में से कुछ प्रश्न बचाकर पूँजी निर्माण की प्रक्रिया सम्पादित करने पर यह आवश्यक नहीं है कि पूँजीगत सम्पत्तियों में वृद्धि हो। ऐसे देश में वर्तमान पूँजीगत सम्पत्तियों का अधिकतम तथा अकुशल प्रयोग होने पर मशीनों तथा पूँजीगत सम्पत्तियों में हानि और टूट-फूट अधिक होगी जिनके फल-स्वरूप वास्तविक पूँजी निर्माण कम होगा।

पूँजी निर्माण के सम्बन्ध में हम बचत और विनियोग का अध्ययन करने हैं। और इनके आधार पर ही पूँजी निर्माण की समस्त प्रक्रिया का अध्ययन एवं विवेचन करने हैं। पूँजी निर्माण के लिए बचत तथा विनियोग आवश्यक हैं। यहाँ पर बचत और विनियोग का अभिप्राय राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्रीय विनियोगों से है। कुल राष्ट्रीय विनियोग की गणना केवल उत्पादित पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों के योग के आधार पर ही नहीं की जाती। उसमें उन घन राशियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन के सहायक साधनों एवं पूँजीगत सम्पत्तियों (Capital Assets) को प्राप्त करने के लिए, लिए गए प्राप्त वित्तीय ऋणों एवं दायित्वों के शोधन तथा सरकारी एवं नागरिक विनियोग पर व्यय की जाती हैं।



कुल विनियोग =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{पूँजीगत सम्पत्तियों में वास्तविक वृद्धि (निजी क्षेत्र में)} \\ + \text{सामाजिक एवं सार्वजनिक पूँजीगत सम्पत्तियों में वृद्धि} \\ + \text{वित्तीय ऋणों एवं दायित्वों में वृद्धि} \end{array} \right\}$

परन्तु शुद्ध एवं वास्तविक विनियोग (Net Investment) को ज्ञात करते समय दो बातों पर ध्यान देना चाहिए (1) वर्तमान सम्पत्ति के क्षय विक्रय पर तथा (2) ऋणों द्वारा उत्पादित पूँजीगत सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित करने में वित्तीय दायित्वों की मौद्रिक राशि पर।

जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचता है तब यह देखना चाहिए कि वह उस प्राप्त राशि का उपयोग किस प्रकार करता है? यदि वह उस धन का प्रयोग उपभोग के लिए करता है तो पूँजीगत सम्पत्ति में वृद्धि नहीं होती। यह उसके लिए निर्वि-नियोग (Dis-investment) है। जब वित्तीय ऋण एवं दायित्वों के द्वारा पूँजीगत सम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है तब पूँजीगत सम्पत्तियों की वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए उनके मूल्य में इन दायित्वों को घटा देना चाहिए। अतः —  
 शुद्ध विनियोग = कुल विनियोग — (निर्विनियोग + वित्तीय ऋण एवं दायित्व)

## 6 पूँजी निर्माण तथा पूँजी संचय को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Affecting Capital formation and Capital accumulation)

किसी भी देश में पूँजी निर्माण पूँजी के संचय द्वारा ही सम्भव होता है। पूँजी-निर्माण के लिए वास्तविक बचत (Real savings) का होना आवश्यक है। वास्तविक बचत लोगों की आय और उपभोग पर निर्भर है। परन्तु किसी देश में बचत एवं विनियोग को प्रभावित एवं निर्धारित करने वाले कई तत्त्व होते हैं जिनके आधार पर पूँजी संचय के द्वारा पूँजी निर्माण सम्भव होता है। इन तत्त्वों को निम्न-लिखित तीन वर्गों में रखा जा सकता है (अ) बचत करने की शक्ति या क्षमता (Power or Capacity to save), (ब) बचत करने की इच्छा (Willingness to save), तथा (स) बचत करने की दशायें (Conditions to save or Opportunity to save)

(1) बचत करने की क्षमता (Capacity to save) बचत करने की क्षमता या शक्ति व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय आय पर निर्भर है। व्यक्तिगत उपभोग के नमान रहने पर यदि व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो, तो आय की अपेक्षा व्यय कम होने से व्यक्तिगत बचत की क्षमता अधिक होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय व्यय की अपेक्षा राष्ट्रीय आय अधिक होने पर देश में वास्तविक बचत की क्षमता अधिक होगी। अतः वास्तविक बचत में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही साथ व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हो। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना

आवश्यक है कि केवल आय में वृद्धि होने पर ही वचन की क्षमता में वृद्धि नहीं हो जाती। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत व्यय पर अन्य विकसित देशों के लोगों के श्रेष्ठतर उपभोग का 'प्रदर्शन-प्रभाव' (Demonstration effect) न पड़े, अन्यथा लोगों द्वारा नवीन वस्तुओं के उपभोग का अनुकरण करने पर आय में वचन का अंश भी अच्छी वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जायेगा।

व्यक्तिगत तथा सामाजिक वचन की क्षमता आय पर निर्भर रहने के कारण यह आवश्यक है कि प्रति-व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। यह वृद्धि पूँजीगत सम्पत्तियों तथा श्रमिकों के क़ाय-कौशल को बढ़ाकर अधिक उत्पादन द्वारा ही सम्भव हो सकती है। परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि लोगों के जीवन-स्तर तथा परिवार के आकार में अनुमान्य वृद्धि न हो। इसके अनिश्चित व्यक्तिगत आय कार्य की प्रकृति, आर्थिक विकास की सामान्य दशाओं, श्रम नियोजन की मजदूरी-वितरण-नीति, उपभोग—वस्तुओं के बाज़ार मूल्य तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर निर्भर है।

(2) बचत करने की इच्छा (Willingness to save) पूँजी संचय एवं पूँजी निर्माण के लिए देश में बचत करने की शक्ति का होना ही काफी नहीं है बल्कि लोगों में अपनी आय के एक अंश को बचाने की इच्छा का होना अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। बचत करने की इच्छा लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों तथा सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है :

(i) मानसिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत मनुष्यों की दूरदर्शिता तथा उनके स्वभाव को सम्मिलित किया जाता है। एक दूरदर्शी व्यक्ति अपनी वर्तमान आय का अधिक से अधिक भाग बचाकर रखना चाहता है जिससे वह भारी अनिश्चय एवं आकस्मिक व्ययों की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। यदि किसी देश में अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग बचाते रहते हैं, तो वहाँ पर वचन की मात्रा अधिक होगी। कुछ व्यक्तियों में अपनी आय के एक अंश को बचाने की आदत होती है। वे अन्य व्ययों की तरह अपनी आय में से एक निश्चित भाग बचाने को भी अधिक महत्त्व देते हैं। जिस देश के व्यक्तियों में बचत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, वहाँ वचन अधिक होगा और जहाँ लोग अधिक फ़िज़ूल-खर्ची होंगे, वहाँ वचन कम होगा।

(ii) सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियाँ : यदि किसी देश में सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों के पास एकत्र धन एवं ऐश्वर्य के आधार पर निर्धारित की जाती है तो यह स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों में धन-संचय करने की इच्छा बलवती होगी। इसके अनिश्चित लोग राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा देश के आर्थिक विकास की भावनाओं से प्रेरित होकर भी अपनी आय का कुछ भाग बचाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं।

## (3) बचत करने की दशाएँ (Conditions to save) :

(1) देश में शांति एवं सुरक्षा : बचत करने की क्षमता और इच्छा कुछ आधारभूत शर्तों पर निर्भर है। यदि देश में शांति और सुरक्षा होती है, व्यक्तिगत सम्पत्ति के सग्रह पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता तथा जन-जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार आवश्यक प्रबन्ध एवं व्यवस्था करने के लिए मजबूत तथा जागरूक रहती है तो लोगों में भी अपनी आय को बचाने की इच्छा होती है।

(2) विनियोजन की सुविधाएँ : देश में सुरक्षित विनियोग की सुविधाओं के होने पर लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इन सुविधाओं के न होने पर लोग अपनी बचत को अनुत्पादक सम्पत्तियों, जैसे, आभूषणों, उपभोग-वस्तुओं आदि में विनियोजित कर देते हैं। अतः बचत को प्रोत्साहित करने के लिए देश में वैकिंग व्यवस्था का समुचित विरास होना आवश्यक है। बीमा कंपनियाँ, जीवन-बीमा तथा सम्पत्तियों का बीमा करके लोगों की बचत को सग्रह करती हैं। प्राविडेंट फंड, अनिवार्य बीमा, अनिवार्य बचत, वापिकी जमा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध होने पर भी व्यक्तिगत बचत में वृद्धि होती है।

बचत की उपयुक्त सुविधाओं के होने के साथ-साथ ही देश में बचत को विनियोजित करने के लिए सुरक्षित व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाओं का भी होना आवश्यक है। यदि व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थान अपने लाभ का एक अंश स्वतः व्यापार अथवा उद्योग में विनियोजित करते हैं, तो ऐसे विनियोग को प्रत्यक्ष विनियोग कहा जाता है। परन्तु जब उद्योगपति तथा व्यापारी अन्य लोगों की बचत को प्राप्त करके अपने उद्योग तथा व्यापार का विकास व विस्तार करते हैं, तब लोगों की बचत के ऐसे विनियोग को अप्रत्यक्ष विनियोग कहते हैं। अप्रत्यक्ष विनियोग के लिए देश में मुद्रा तथा अन्न बाजारों, विनियोग-न्यासों, बीमा कंपनियों आदि का होना आवश्यक है। ये संस्थाएँ लोगों की बचत को सग्रह करके उसे गतिशील बनानी हैं जिससे पूँजी-निर्माण में सहायता मिलती है।

### 7. पूँजी-निर्माण में राज्य का योगदान (Government & Capital-Formation)

पूँजी निर्माण पर सरकार की व्यापारिक एवं औद्योगिक नीति का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। इस नीति में सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती है :

(1) विदेशी पूँजी : जिस देश में स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनायी जाती है वहाँ बचत की क्षमता कम होने पर पूँजी की कमी की पूर्ति विदेशी पूँजी के प्राप्ति द्वारा सम्भव हो जाती है। विदेशों से पूँजीगत सम्पत्तियों का आयात करके देश में पूँजी निर्माण किया जाता है। एक अविकसित राष्ट्र अपनी आर्थिक व्यवस्था के तब-

निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति में पूँजी निर्माण के लिए विदेशी पूँजी की सहायता की नीति अपनाता है।

(2) व्यावसायिक नीति : एक विकासोन्मुख देश अपनी व्यावसायिक नीति द्वारा विलासिता की वस्तुओं के उपभोग को कम करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिबन्ध लगाता है। इसके फलस्वरूप उपभोग की विदेशी वस्तुओं के स्थान पर पूँजीगत सम्पत्तियों के श्रय पर अधिक बल दिया जाता है जिससे देश में विलासिता की वस्तुओं का आयात बन्द हो जाता है और पूँजीगत सम्पत्तियों का आयात बढ़ जाता है।

(3) बचत योजनायें तथा कर नीति : पूँजी-संचय के लिए सरकार अल्प-बचत योजनाओं द्वारा ऐच्छिक बचत (voluntary savings) को प्रोत्साहन देती है। बचत की मात्रा में आवश्यकतानुसार वृद्धि न होने पर सरकार कभी कभी अनिवार्य बचत योजनाओं (compulsory saving schemes) को भी लागू करती है। इनके अतिरिक्त लोगों की आय में से कुछ अंश प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी वित्तीय एवं कर-नीतियों में भी आवश्यक परिवर्तन करती है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लगा कर लोगों के उपभोग का कम कर दिया जाता है जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो सके।

(4) घाटे की श्रय व्यवस्था द्वारा (Deficit Financing) : सरकार घाट की श्रय व्यवस्था द्वारा भी पूँजी-विस्तार या धन की व्यवस्था करती है। इससे मुद्रा प्रसार होता है। परन्तु ये दोनों ही स्थितियाँ सामान्य जनता के लिए ठीक नहीं हैं।

(5) वित्तीय तथा वैकल्पिक सस्थाओं का विस्तार : सरकार वैकल्पिक सस्थाओं को व्यवस्थित करके उनका विस्तार करती है जिससे बचत तथा विनिमय की सुविधायें सभी स्थानों पर मिल सकें। इनके अतिरिक्त सरकार औद्योगिक एवं कृषि वित्त की पूर्ति करने के लिए कई वित्तीय संस्थायें स्थापित करती है।

(6) औद्योगिक नीति : सरकार दश में पूँजी निर्माण के लिए सावजनिक क्षेत्र का विस्तार करती है जिससे देश का औद्योगिक विकास हो सके।

(7) पूँजी निर्माण में श्रम का उचित उपयोग : एक अविकसित देश में जहाँ पूँजी की तुलना में श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, वहाँ श्रम के अधिकतम सहयोग से पूँजी का विस्तृत प्रयोग करके पूँजी का निर्माण सम्भव हो सकता है। बेरोजगार व्यक्तियों का काम देकर अनेक प्रकार की सामाजिक पूँजीगत सम्पत्तियों का निर्माण किया जा सकता है। उनकी आय बढ़ने पर देश में श्रम शक्ति बढ़ती है, अनेक उद्योग-धन्धे पनपते हैं, लोगों की आय में वृद्धि होती है और इस प्रकार पूँजी निर्माण में सहायता मिलती है। अविकसित तथा अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रोफेसर नर्से (Prof Nurkse) ने आर्थिक विकास की योजनाओं में श्रम द्वारा पूँजी निर्माण विधि को अधिक महत्व दिया है।

### 8. भारत में पूँजी-निर्माण (Capital Formation in India) :

भारत तथा अन्य अल्प विकसित देशों में पूँजी की कमी के साथ-साथ पूँजी-निर्माण की गति भी बड़ी धीमी है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें श्रम की मात्रा अधिक होती है और कुछ में पूँजी का आधिक्य। पूँजी का आधिक्य होने पर उसका उचित उपयोग आवश्यक है। यदि उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाये उन संस्थाओं को स्थापित किया जाये जो इस दिशा में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें, तो निश्चय ही पूँजी के निर्माण तथा संचय में सहायता मिलेगी। परन्तु अधिकांश अल्पविकसित देशों में पूँजी की कमी होती है। इस कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(i) लोगों का निचंन होना : भारत में पूँजी संचय करने की इच्छा के सभी तत्वों के रहते हुए भी, पूँजी के संचय की दर बहुत ही कम है। यहाँ के लोग दूरदर्शी हैं, उनमें पारिवारिक स्नेह के कारण धन बचाने की इच्छा भी है, ध्यान की दर भी ऊँची है तथा लोग यह भी जानते हैं कि धन-संचय से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी परन्तु इतना होसे हुए भी आय कम होने के कारण वे धन बचा नहीं पाते। अतः भारत में वचत की दर कम होने से पूँजी संचय तथा निर्माण की गति भी धीमी है।

(ii) बचत करने की शक्ति : बचत करने की शक्ति कई बातों से प्रभावित होती है। यदि लोगों की आय कम है, तो उनकी बचत करने की शक्ति नहीं के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के कारण प्रादुर्भावक वस्तुओं के मूल्य अधिक होने से लोगों की बचत करने की शक्ति कम हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि आय का बहुत बड़ा हिस्सा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ही खर्च हो जाता है। आय के कम होने का प्रमुख कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि है। राष्ट्रीय उत्पादन में इसकी तुलना में वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय आय कम होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय बचत पर भी पड़ता है। ये सब दशाएँ भारत में पायी जाती हैं। इन कारणों के परिणाम-स्वरूप ही भारत में बचत की शक्ति बहुत ही कम है।

(iii) बचत करने की सुविधायें : स्वतन्त्रता के पहले भारत में बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की कमी के कारण बचन करने की सुविधाओं का अभाव था। स्वतन्त्रता के पश्चात्, विवेक कर आर्थिक नियोजन काल के प्रारम्भ होने के बाद से, इन संस्थाओं को व्यवस्थित करके इनका विस्तार किया गया। आन्तरिक बचन को एकत्र करने के लिए कुछ अनिवार्य बचत योजनाएँ चालू की गयीं, बैंकों की बहुत सी शाखाएँ खोली गयीं हैं, जीवन बीमा का विस्तार किया गया है सरकारी वित्तीय संस्थायें स्थापित की गयी हैं। अधिक व्याज वाले सरकारी ऋण पत्र, बांड्स आदि

जारी करके लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। परन्तु इतना होतें हुए भी भारत जैसे विज्ञान देश के लिए ये सुविधायें एवं प्रोत्साहन कम हैं, ग्रामीण क्षेत्र अब भी अविकसित हैं जिससे वहाँ की जनता को बचत की सभी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

(iv) धन का असमान वितरण : भारत तथा अन्य अल्प विकसित देशों में बचत की दर कम होने का एक कारण यह भी है कि समाज में धन का असमान वितरण है। समाज का एक वर्ग तो अधिक धनी है तथा अधिकांश लोग गरीब हैं। धनी वर्ग ही बचत करने में समर्थ है, परन्तु यह वर्ग भी उपभोग वस्तुओं तथा अनुत्पादक सम्पत्तियों जैसे मकान, भूमि, धातुएँ तथा विनाशिता की वस्तुओं पर अपनी बचत खर्च कर देता है। इसका प्रसार राष्ट्रीय बचत की दर पर पड़ता है।

(v) निर्धनता के अग्र्य प्रभाव : भारत जैसे अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र (Vicious circle of poverty) न केवल बचत की इच्छा तथा बचत की शक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा कार्य कुशलता को भी कम करता है। निर्धन लोग न तो उचित शिक्षा ही प्राप्त कर पाते हैं और न ही अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाकर कार्य कुशल हो पाते हैं। गरीबी के अग्र्य प्रसार प्रभावों (spread effects) में वस्तुओं की माग कम होना, माग कम होने से उत्पादन मात्रा कम होना, उत्पादन-मात्रा कम होने में औद्योगिक विकास का रुक जाना, रोजगार के स्रोतों का न होना, पूँजी-निर्माण में रुकी होना, आदि प्रभाव गिनाये जा सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है गरीबी का कुचक्र ही पूँजी संचय तथा निर्माण के लिए बाधक है।

अतः राष्ट्रीय सरकार को आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को लागू करना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने किया है। प्रारम्भ में उसे विदेशों में ऋण एवं वित्तीय सहायता लेकर औद्योगिक विकास का ढांचा खड़ा करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कर नीति के द्वारा लोगों की आय का थोड़ा भाग पूँजी-निर्माण के लिए प्राप्त करना चाहिए। बीमा, बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का विकास करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जनता के दृष्टिकोण, आचरण, भावनाओं तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए जिससे लोग भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत करने की इच्छा से प्रेरित होकर वर्तमान आय में से कुछ न कुछ भ्रवश्य बचाये। इनके अतिरिक्त सरकार को देश में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए एवं आधार (Infra structure) तैयार करना होगा। यह ढांचा, यद्यपि आय देने वाला नहीं है फिर भी इस ढांचे के बन जान से राष्ट्रीय आय बढ़ाने वाले कई उद्योग धन्य पनपने लगते हैं। यातायात, शक्ति आदि की सुविधायें उद्योग धन्यो तथा व्यापार के विकास एवं विस्तार में सहायक होती हैं।

## साहस तथा साहसी के कार्य (Enterprise and the Entrepreneurial Function)

*"Engaging in risky ventures is an essential characteristic of entrepreneurship, even though in contemporary large corporation this function is not typically combined with managerial activities"*

—William Fellner

प्रत्येक उत्पादन कार्य तथा व्यवसाय में जोखिम (Risk) का तत्व निहित है। उत्पादक छोटा हो या बड़ा, उसे अनिश्चितता (Uncertainty) का सामना करना पड़ता है। उत्पादन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की मांग का पूरा करना है। किसी भी उत्पादन इकाई को स्थापित करने से पहले सम्भावित मांग का अनुमान लगाना पड़ता है। आधुनिक औद्योगिक संगठन का कार्य इतना जटिल है कि उत्पादन के उद्देश्य को निश्चित करने, उद्योग को स्थापित करने तथा उत्पादन का काम शुरू करने में कुछ 'समय' लगना निश्चित है। 'समय तत्व' के कारण उत्पादन सम्बन्धी जोखिम बँ बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। हो सकता है कि उस 'समय' में मांग में परिवर्तन हो जाए या नए प्रतियोगी उसी वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ कर दें, जिससे लाभ कम होने या हानि होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यदि उत्पादक का मांग सम्बन्धी अनुमान गलत सिद्ध हुआ। (मान लीजिए मांग कम हो गई) तो उसे हानि उठानी पड़ सकती है। अतः व्यवसाय में अनिश्चितता एवं जोखिम का तत्व प्रत्येक दशा में मौजूद है। अतः व्यवसाय में अनिश्चितता एवं जोखिम का तत्व प्रत्येक दशा में मौजूद है। जो भी व्यक्ति या संस्था इस जोखिम को उठाता है या अनिश्चितता का सामना करता है, उसे साहसी या उद्यमी (Entrepreneur) कहते हैं।

### 1 उद्यमी कौन है ? (Who is an Entrepreneur ?)

साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति उत्पादन सम्बन्धी जोखिम और अनिश्चितता को उठाता है या सहन करता है, उसे उद्यमी, उपजमी या

साहसी की सजा दी जा सकती है। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों (वित्तपतया शुम्पीटर) ने उद्यमी को केवल 'जोखिम उठाने वाला' या 'अनिश्चितता वहन करने वाला' मात्र ही नहीं माना है, बल्कि उसे नवीन विधियों का प्रयोगकर्ता (Innovator) भी माना है। प्रश्न उठता है—कौन सी उत्पादन-प्रणाली नवीन है? यदि किसी नयी खोज की गयी मशीन या उत्पादन-विधि द्वारा पहली बार उत्पादन किया जाय तो निश्चित रूप से यह कार्य Innovation माना जाएगा। अतः उत्पादन-कार्य को नये तरीके से करने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थों में साहसी माना जाएगा। परन्तु यदि किसी प्रत्यक्ष विकसित देश में एक व्यक्ति अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली प्राधुनिकतम मशीन को मगाता है और पहली बार उत्पादन के लिए घपन देश में उसका प्रयोग करता है तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को 'उपक्रमी' कहेंगे? किसी व्यक्ति को उपक्रमी कहे जाने के लिए निश्चित माप-दण्ड नहीं है। यह देश तथा काल पर निर्भर है। एक व्यक्ति को किसी उद्यम-विशेष के कारण एक पिछड़े हुए देश में शुम्पीटर के अनुसार, 'साहसी' कहा जा सकता है (Innovator के रूप में) तथा उसी व्यक्ति को एक विकसित देश में 'साहसी' नहीं भी कहा जा सकता है। अतः 'साहस' सम्बन्धी मान-दण्ड विभिन्न प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न हैं।

“एक विकसित देश में उपक्रमी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अर्थ-व्यवस्था में किसी नयी विधि का सबसे पहले प्रयोग करता है, जैसे निर्माण के किसी क्षेत्र में ऐसी उत्पादन-विधि अपनाया जिसे पहले नहीं अपनाया गया है, किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करना जिससे उपभोक्ता पूर्व परिचित नहीं है, कच्चे माल के नए स्रोत का उपयोग करना, तथा नए बाजार की खोज, आदि।”<sup>1</sup> अतः विकसित अर्थ-व्यवस्था में वही व्यक्ति उपक्रमी कहा जा सकता है जो सर्वथा नयी विधि, वस्तु, बाजार या कच्चे माल के स्रोत का उपयोग करता है। परन्तु 'उपक्रमी' सम्बन्धी इस परिभाषा को प्रत्यक्ष विकसित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में सामान्यतः उस व्यक्ति को उपक्रमी कहा जाता है जो किसी भी प्रकार के उद्योग या व्यवसाय (नया या पुराना) की स्थापना करता है तथा जोखिम व अनिश्चितता का भार उठाता है। ऐसे देशों में उद्योगधन्धे की परम्परावादी (traditional) होती हैं, साहसी सामान्यतया नए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना नहीं करते। अतः एक अल्प विकसित देश में वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ साहसी कहा जाएगा जो

<sup>1</sup> “The entrepreneur in an advanced economy is an individual who introduces something new into the economy—a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacture concerned, a product with which consumers are not yet familiar, a new source of raw-material or of new markets and the like.”  
—Joseph A. Schumpeter.



किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करता है, या पूँजी का विनियोजन परम्परागत उद्योगों में न करके ऐसे उद्योग में करता है जो देश के लिए अधिक उपयोगी हैं (जैसे उपभोक्ता-उत्पादों के स्थान पर उत्पादक-उद्योगों या आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना)। इस प्रकार उत्पादन के साधनों को एकत्र कर, उत्पादन के काम या व्यवसाय को प्रारम्भ करने वाला व्यक्ति ही, जो अन्तिम रूप से जोखिम उठाता है, उपक्रमी है। उद्योग या विधि नहीं है या पुरानी, इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। उपक्रमी का सम्बन्ध जोखिम से ही है। पूँजी के अभाव, संकुचित बाजार, नए विनियोजन पर कम लाभ-प्राप्ति, परिवहन के साधनों तथा अन्य सुविधाओं (Infra-structures) की कमी के कारण अल्प विकसित देशों में, उद्योग स्थापित करने में जोखिम का तत्व अधिक रहता है।

## 2. साहसी उत्पादन साधन के रूप में (Entrepreneur as a Factor of Production)

पुराने अर्थशास्त्री 'साहस' को उत्पादन का अलग तथा स्वतन्त्र मानन नहीं मानते थे। एडम स्मिथ की मान्यता थी कि पूँजी का स्वामी प्रबन्धक तथा साहसी (Owner-Manager Entrepreneur) वस्तुतः एक ही व्यक्ति था। स्मिथ ने साहसी को उत्पादन का स्वतन्त्र साधन नहीं माना। जे० बी० से प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस विषय पर अपना विचार प्रकट किया तथा यह कहा कि 'साहसी' उत्पादन का स्वतन्त्र साधन है। 'से' ने कहा कि साहसी की सेवाओं द्वारा ही उत्पादन तथा वितरण संभव होते हैं। भूमि, श्रम, पूँजी तथा वस्तु की मांग होती हुई भी, यदि कोई साहसी उद्योग प्रारम्भ नहीं करता है, तो न तो उत्पादन साधनों की मांग होगी और न उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति ही की जा सकेगी। इस प्रकार 'साहसी' वह मध्यस्थ है जो आय का सृजन तथा वितरण दोनों ही कार्य करता है। 'से' के इन विचारों को समुचित मान्यता मिली। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में तथा बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास बड़ी तेजी से हुआ। बड़े पैमाने के उत्पादन तथा जटिल श्रम-विभाजन के कारण प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्य; स्वामित्व एवं उपक्रम सम्बन्धी-कार्यों में अलग होता गया। अतः अब 'साहस' को उत्पादन का एक स्वतन्त्र तथा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। भूमि का लगन, श्रम की मजदूरी, पूँजी पर व्याज तथा प्रबन्ध के लिए वेतन देकर, मूल्य हानि आदि की व्यवस्था करने के पश्चात् उत्पादन से प्राप्त जो भी आय बचती है, वह (लाभ) साहसी को प्राप्त होती है। इस प्रकार लाभ वह आय है जो साहसी को प्राप्त होती है।

सम्पीटर ने 'साहस' को उत्पादन का अत्यन्त ही प्रमुख साधन माना है। उनके अनुसार किसी भी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए 'साहस' का होना आवश्यक

है। साहसी वह व्यक्ति है जो सदा नवीनतम वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विधियों का प्रयोग समाज के लिए करता है तथा व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबन्धन में सम्बन्धित वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। इस प्रकार साहसी, आर्थिक विकास का जनक है। शूम्पीटर के विचारों से अब सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं। इस प्रकार 'साहस' को अब उत्पादन के स्वतन्त्र साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

### 3. साहसी तथा सगठनकर्त्ता में अन्तर (Entrepreneur and Organiser) :

'साहसी' तथा 'सगठन' का कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है इसीलिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इनमें भेद नहीं किया या; परन्तु प्राधुनिक विचारधारा के अनुसार 'साहस' तथा 'सगठन' उत्पादन के दो स्वतन्त्र साधन माने जाते हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर स्मरणीय हैं

(1) जोखिम तथा अनिश्चितता का भार उठाना : साहसी का कार्य जोखिम तथा उत्पादन सम्पत्ती अनिश्चितता बहन करना है, जबकि सगठनकर्त्ता का कार्य विभिन्न उत्पादन-साधनों में उचित समन्वय स्थापित करना तथा प्रादर्य अनुपात में उनका प्रयोग करना है। उसका सम्बन्ध जोखिम तथा व्यावसायिक अनिश्चितताओं से नहीं है।

(2) पारिश्रमिक या पुरस्कार : दोनों के पारिश्रमिक या पुरस्कार में भी अन्तर है। सगठनकर्त्ता 'वेतन' और साहसी 'लाभ' का अधिकारी है। सगठनकर्त्ता की वेतन मिलना अनिवार्य है जब कि साहसी का 'लाभ' अनिश्चित है। हानि होने की अवस्था में लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) साहसी तथा सगठनकर्त्ता का दायित्व : साहसी तथा 'सगठनकर्त्ता' छोटे व्यवसाय में एक ही व्यक्ति हो सकता है, परन्तु उसे एक ही समय दो प्रकार की विशिष्ट सेवाएँ—जोखिम तथा 'प्रबन्ध-सम्बन्धी'—प्रदान करनी पड़ेंगी। 'एकाकी उत्पादक' वस्तुतः 'साहसी' तथा प्रबन्धक दोनों होता है (मामान्यतः)। सांकेदारी फर्म में भी ये दोनों कार्य उचित विभाजन द्वारा किए जा सकते हैं। परन्तु 'संयुक्त पूँजी कम्पनी' में साहसी तथा सगठनकर्त्ता अलग अलग होते हैं। वहाँ अग्राधारी, कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तथा जोखिम का दायित्व उन्हीं का होता है, परन्तु प्रबन्धक का कार्य नियुक्त कर्मचारी करते हैं। कम्पनी का स्वामित्व प्रबन्ध से अलग होता है।

### 4. साहसी तथा पूँजीपति में अन्तर (Entrepreneur and Capitalist) :

यह आवश्यक नहीं कि साहसी व्यवसाय को चलाने के लिए पूँजी भी दे। ऐसी स्थिति में साहसी और पूँजीपति दो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। साहसी पूँजी-

पति से पूँजी लेता है तथा उसको पूँजी पर व्याज देता है। पूँजीपति का जोखिम में कोई मतलब नहीं है, अतः व्याज के रूप में उसकी आय निश्चिन्त होती है, जबकि साहसी की आय अनिश्चित है। एक छोटा व्यवसाय में साहसी ही पूँजीपति और पूँजीपति ही साहसी होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी साहसी पूँजीपति हों, या सभी पूँजीपति साहसी भी हों। एक बड़े व्यवसाय में, विशेषकर एक कंपनी में, पूँजीपति साहसी से सदा भिन्न होते हैं।

## 5 साहसी या उद्यमी के कार्य (Functions of Entrepreneur)

साहसी उद्योग का आधार-स्तम्भ है। उत्पादक इकाई की सफलता प्रमुखतः साहसी की दूरदर्शिता, निर्णय लेने की योग्यता तथा क्षमता और उसके नामान्य बौद्धिक स्तर पर निर्भर है। वह उद्योग के प्रमुख निर्णायक, उत्पादन-मात्राओं के समन्वयकर्ता तथा जोखिम वाहक के रूप में कार्य करता है। उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(1) जोखिम सम्बन्धी कार्य (Risk taking Functions) : जोखिम वहन करना साहसी का सबसे प्रमुख कार्य है। उद्योग की सफलता या असफलता का प्रतिशत शायद साहसी पर ही पड़ता है। यह कार्य अत्यन्त ही कठिन है तथा इसका भार उठाने के कारण ही उसे पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त होता है।

(ii) निर्णय तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य (Decision making and Co ordination) . निर्णय तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य, उद्योग की स्थापना के पूर्व तथा जब उद्योग स्थापित हो रहा हो, उस समय करने पड़ते हैं। ये कार्य निम्न-लिखित हैं

(क) उद्योग का चुनाव उद्यमी को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि वह किस प्रकार के उद्योग का स्थापना करे? हम सम्बन्ध में निर्णय लेते समय उद्यमी उपभोक्ताओं की भावी मांग, आवश्यक पूँजी, उत्पादन साधनों का उपलब्ध तथा भावी लाभ की सम्भावनाओं में प्रभावित होता है।

(ख) वस्तु का चुनाव : उद्योग का चुनाव करने के अलावा उद्यमी को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना पड़ता है कि वह चुने हुए उद्योग से सम्बन्धित किमी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करे अथवा उद्योग से सम्बन्धित किम उत्पादन-क्रिया को अपनाए? जैसे यदि वह सोहा उद्योग में प्रवेश करना चाहता है तो उसे यह निर्णय लेना पड़ेगा कि वह खान से लौह पदार्थ (Iron ore) निकालने का काम करेगा या केवल सोहा-निर्माण कार्य करेगा या इस्पात बनाएगा या ये सभी कार्य करेगा?

(ग) उत्पादन केन्द्र का चुनाव : उद्योग की स्थापना किन स्थान पर की जाए ? यह भी निर्णय साहसी को लेना पड़ता है। सामान्यतः बच्चे भाल की निकटता, बाजार की उपलब्धि, परिवहन एवं अन्य सेवाएं तथा सुविधाएं, शक्ति के साधन और कुशल यम की प्राप्ति आदि बातों को ध्यान में रखकर उत्पादन-स्थान के सम्बन्ध में साहसी निर्णय लेता है।

(घ) उत्पादन इकाई का आकार तथा उत्पादन पैमाना : साहसी बड़े औद्योगिक मस्या की स्थापना करेगा या छोटे ? उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा या छोटे पैमाने पर ? इस सम्बन्ध में भी पूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में निर्णय लेते समय सम्भावित मांग, उपलब्ध पूँजी, लान तथा मस्या के अनुकूलतम आकार आदि को ध्यान में रखना पड़ता है।

(च) उत्पादन साधनों का संप्रह तथा समन्वय : साहसी उत्पादन के आवश्यक साधनों को आवश्यक माना में एकत्रित करता है तथा उनका प्रयोग ऐसे अनुपात में करता है जिससे उत्पादन साधनों की समता का अनुकूलतम उपयोग हो सके तथा उत्पादन-व्यय न्यूनतम हो सके।

(iii) प्रबन्ध-कार्य (Managerial Functions) : साहसी उद्योग की आधारशिला एवं प्राण श्मोन है। वह प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में भी निर्णय लेता है तथा महत्वपूर्ण कमचारियों की नियुक्ति करता है। वह स्वयं भी एक प्रबन्धक के रूप में कार्य कर सकता है। एकाकी स्वामित्व होने पर सामान्यतः प्रबन्ध व्यवस्था साहसी ही करता है। समुक्त पूँजी व्यवस्था में स्वामित्व एवं प्रबन्ध एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वामित्व प्रसाधारियों का होता है तथा प्रबन्ध एवं नीति सम्बन्धी निर्णय तथा उनका कार्यान्वयन मंचालन-मण्डल करता है।

(iv) वितरण कार्य (Distributive Functions) : उत्पादन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। अतः उत्पादित वस्तु उत्पादन मानकों के समुक्त प्रयास का परिणाम है। इस समुक्त-उत्पादक (Product) का विभिन्न-साधनों में किन अनुपात में वितरण किया जाय ? यह कार्य भी साहसी को ही करना पड़ता है। सामान्यतः उत्पादन-साधकों को दिया जाने वाला पुरस्कार या पारिश्रमिक उसी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है।

## 5. साहसी के गुण (Qualities) .

साहसी के उपर्युक्त कार्यों में स्पष्ट है कि उत्पादन में उसका सबसे ऊँचा स्थान है। वह केवल जोखिम तथा अनिश्चितता का उठाने वाला ही नहीं है, बल्कि एक प्रबन्धक, दूरदर्शी, आर्थिक-निर्माता तथा नई उत्पादन-विधियों का प्रयोग करने वाला (Innovator) भी है। साहसी का कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं उत्तर-

दायित्वपूर्ण है। इन समस्त कार्यों का सफलतापूर्वक सम्पादन वही साहसी कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक गुण हो :

(i) उच्च बौद्धिक स्तर : साहसी का बौद्धिक स्तर ऊँचा होना चाहिए जिससे वह व्यवसाय-सम्बन्धी सभी बातों को अच्छी तरह समझ सके।

(ii) सामान्य योग्यता : साहसी को शिथिल होना चाहिए जिससे उसे व्यवसाय सम्बन्धी साधारण जानकारी के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा न लेना पड़े।

(iii) उद्योग एवं व्यवसाय सम्बन्धी बातों का विस्तृत व गहरा ज्ञान तथा अनुभव : साहसी को व्यवसाय का चुनाव करने के बाद से उसको स्थापित करने के समय तक तथा उसके बाद भी जोखिम तथा अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। अतः यदि उसको व्यवसाय-सम्बन्धी बातों का गहरा ज्ञान होगा, या उसने अनुभव द्वारा उन बातों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तभी उस सफलता मिलेगी।

(iv) दूरदर्शिता साहसी का दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। दूरदर्शी होने पर वह ही व्यवसाय के भविष्य के बारे में पहले से ही आवश्यक अनुमान लगा सकता है।

(v) नेतृत्व की क्षमता साहसी ही व्यवसाय का सर्वोच्च निर्णायक तथा मार्गदर्शक है। यदि उसमें नेतृत्व करने के गुण हैं, तो वह सम्पूर्ण सगठन को उत्पादन-कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित मार्ग पर लगाने में सफल होगा।

(vi) शीघ्र एवं उचित निर्णय लेने की क्षमता . अन्तिम निर्णायक के रूप में साहसी में शीघ्र एवं उचित निर्णय लेने का गुण होना चाहिए। यदि वह निर्णय लेने में देरी करता है, तो सम्पूर्ण हानि उसे ही उठानी पड़ेगी।

(vii) प्रभावशाली व्यक्तित्व . साहसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसमें, ईमानदारी, गम्भीरता, आत्मविश्वास तथा धैर्य आदि गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों से वह अपने कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न कर सकता है और बाहरी व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है।

(viii) आधुनिकतम परिवर्तनों का ज्ञान : उसे व्यवसाय तथा उद्योग सम्बन्धी आधुनिकतम परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह उन्हें सबसे पहले अपने व्यवसाय तथा उद्योग में प्रयोग करके लाभ वगा सके।

### प्रश्न व सकेत

1. साहसी के कार्य बताइए। एक कुशल साहसी में कौन कौन से आवश्यक कुशल गुण होने चाहिए ?

[सकेत : प्रश्न में सर्वप्रथम साहसी के प्रमुख कार्य बताइए और इसके बाद एक साहसी के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए।]

2. संगठन की परिभाषा दीजिए और एक कुशल संगठन के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए।

[सकेत : प्रश्न में सर्व प्रथम संगठन का वाक्य स्पष्ट कीजिए और द्वितीय भाग में कुशल संगठन के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए।]

3. 'यह साहसी ही है जो उद्योग की अधिवास जोखिम उठाता है।' इस कथन की स्पष्ट कीजिए तथा उद्योग के संगठन में साहसी के प्रमुख कार्य बताइए।

[सकेत : प्रथम भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि साहसी ही उद्योग की अधिकांश जोखिम उठाता है इसके पश्चात् संगठन में इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।]

## व्यापारिक संगठन के स्वरूप (Types of Business Organisation)

*'Organisation is a harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes'*

—Haney

### अ संगठन तथा संगठनकर्ता (Organisation and Organiser)

#### 1 अर्थ तथा महत्व (Meaning and Importance)

(1) अर्थ उत्पादन कार्य केवल उत्पादन के तीन प्रमुख साधनों—भूमि श्रम तथा पूँजी से अपने आप पूरा नहीं हो जाता। इन साधनों को एकत्र करके उनका सर्वोत्तम एवं अनुकूलतम अनुपात (optimum proportion) में समायोजन (adjustment) या संयुक्त (combine) करना आवश्यक होता है। इसी कार्य को संगठन अथवा व्यवस्था (Organisation) कहा जाता है। हैने (Haney) के अनुसार, 'किसी निश्चित उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उत्पादन के प्राप्त साधनों को सर्वोत्तम विधि से संयोजित करने के कार्य को संगठन कहते हैं।' इससे यह स्पष्ट है कि उत्पादन के काम का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य है—न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन (maximum production at minimum cost)। यह उद्देश्य विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम संयोग तथा सहयोग स्थापित करने पर ही पूरा किया जा सकता है।

अतः यह कहा जाता है कि उत्पादन-कार्य में संगठन का विशेष महत्व है। संगठन एवं व्यवस्था भी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। वास्तव में यह सम्पूर्ण उत्पादन कार्य की संचालन शक्ति है, क्योंकि यह मनुष्य की वह कुशल मानसिक तथा शारीरिक धर्म शक्ति है जो उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन तथा निर्देशन करती है। Bye के अनुसार, "एक व्यापारिक संस्था (उपक्रम) का यह

सारा कार्य वास्तव में श्रम का ही रूप है, क्योंकि यह आय अथवा धन पाने के लिए किया गया मानसिक प्रयास है। परन्तु यह अन्य प्रकार के श्रम से भिन्न एक ऐसा श्रम है जिसके लिए विशेष गुणों तथा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि यह स्वयं से उत्पादन का एक साधन माना जाता है।<sup>1</sup> इस प्रकार की विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति व्यवस्थापक, प्रबन्धक या संगठनकर्त्ता (Organiser) कहलाता है, क्योंकि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रभावपूर्ण महयोग द्वारा समस्त उत्पादन कार्य को सु-व्यवस्थित ढंग से संगठित करता है।

(ii) संगठन का महत्व (Importance) : आधुनिक उत्पादन व्यवस्था श्रम विभाजन, विभागीयकरण, यन्त्रीकरण तथा विशिष्टीकरण पर आधारित है। कार्यों का प्रत्येक अलग व्यक्तियों में विभाजन होने पर उनमें प्रभावपूर्ण सामंजस्य एवं सहयोग का होना आवश्यक है। कुशल संगठन द्वारा ही विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को श्रमिकों की योग्यता अनुभव तथा कार्य-शक्ति के अनुसार संगठित करके श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। वस्तुतः संगठन का उद्देश्य उत्पादन कार्य तथा उत्पादन सुविधाओं को उचित रूप से संगठित करना है। हेनरी फेयोल् ने इस सम्बन्ध में कहा है, “एक व्यापार को संगठित करने का अभिप्राय उसको कार्यशील बनाने के लिए उसको प्रत्येक उपयोगी साधन प्रदान करने से है - कच्चा माल, उपकरण, पूँजी, श्रम।”<sup>2</sup>

संगठन उत्पादन के साधनों को अधिक प्रभावकारी बनाता है श्रूततम साधन पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है तथा उत्पादन प्रक्रियाओं को निश्चितता तथा कार्य क्षमता प्रदान करता है। कुशल संगठन उत्पादन-संस्था की समस्याओं को मुलका कर उसका विकास तथा विस्तार करता है। आधुनिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण उसकी समस्याओं तथा कठिनाइयों को दूर करने का श्रेय कुशल संगठन को ही है। संगठन प्रत्येक उत्पादन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वह पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था हो अथवा समाजवादी या साम्य-

1 “All this work of business enterprise is really a form of labour, for it is mental effort devoted to the acquisition of wealth or income. But it is a labour of a type so distinct from other kinds and calls for such unique qualities that it is usually regarded as a factor of production in itself”

—Bry

2 “To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw materials, tools, capital, personnel”

—Henri Fayol, General and Industrial Management.



वादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था से इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था नियोजित ढंग से संचालित की जाती है। पूँजीवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन उभी समय लाभकारी हो सकता है, जबकि संगठनकर्त्ता उत्पादन के साधनों में प्रभावकारी सहभाग स्थापित कर। मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) में सावजनिक तथा निजी क्षेत्रों (Public and private sectors) की उत्पादन-नीति में समन्वय कुशल संगठनकर्त्ता ही बनाये रख सकता है। समाजवादी तथा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार स्वयं संगठनकर्त्ता एवं व्यवस्थापक का कार्य करती है। अतः आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था में आन्तरिक तथा बाह्य मितव्ययिताओं (Internal and External Economies) का लाभ उठाने के लिए संगठन तथा कुशल व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संगठन के महत्त्व की स्वीकार किया या परन्तु वे इसको धर्म का ही एक अंग मानते थे। उनके अनुसार उत्पादन-कार्य को संचालित करने के लिए किया जाने वाला कुशल मानसिक धर्म उत्पादक धर्म था। उन्होंने इसको उत्पादन का एक अलग साधन नहीं माना था। इसका कारण यह था कि प्राचीन उत्पादन-व्यवस्था का कन्द्र-बिन्दु एक ही व्यक्ति होता था। चूँकि उसे भी अपने उत्पादन-कार्य को संगठित करने के लिए एक योजना क अनुसार कार्य करना पड़ता था, अतः उसकी संचालन शक्ति को उसका अन्य कार्यों का ही एक पहलू माना जाता था। परन्तु औद्योगिक क्रांति के पश्चात् उत्पादन-व्यवस्था में नातिकारी परिवर्तन हुए। फलस्वरूप उत्तम उत्पादन व्यवस्था के लिए विभिन्न साधनों के प्रभावकारी सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता पड़ी। उद्यमी या साहसी की भूमि के लिए भूमिपति पर, धर्म के लिए श्रमिकों पर तथा पूँजी के लिए पूँजीपति पर आश्रित होना पड़ा। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन साधनों को एकत्र करने तथा उनमें प्रभावकारी सहयोग स्थापित करने के लिए उचित व्यवस्था, संगठन तथा प्रबन्ध की आवश्यकता महसूस हुयी। साहसी केवल उत्पादन का उद्देश्य ही निर्धारित करता था परन्तु उस उद्देश्य का पूरा करने के लिए कुशल संगठन एवं व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके पहले एक ही व्यक्ति संगठन-सम्बन्धी कार्य करता था तथा जोखिम भी उठाता था। परन्तु धीरे धीरे उद्यमी (entrepreneurs) ने यह महसूस किया कि उत्पादन-साधनों में मजदूरों सहयोग एवं समायोजन स्थापित करने का कार्य वे नहीं कर सकते। अतः व्यवसाय संगठन का कार्य संगठनकर्त्ता को सौंप दिया गया। इस प्रकार संगठन एक महत्वपूर्ण साधन बन गया।

## 2. संगठनकर्त्ता का कार्य (Functions of an Organiser) :

संगठनकर्त्ता एक व्यवस्थापक तथा प्रबन्धक होता है। व्यापारिक अथवा उत्पादन इकाई का स्वामी, साहसी और संचालक दोनों ही हो सकता है या वह एक

कुशल वेतन-भोगी (Salaried) व्यक्ति को संगठनकर्त्ता या प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में उत्पादन-व्यवस्था के संगठन के लिए संगठन को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं :

(i) निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना : संगठनकर्त्ता सबसे पहले साहसो द्वारा निश्चित किये गये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन व्यवस्था की भावी रूपरेखा तैयार करता है। इसके अन्तर्गत वह वस्तु की सम्भावित मांग के अध्ययन के आधार पर वस्तु की किस्म तथा मात्रा निर्धारित करता है तथा उत्पादन सम्बन्धी कार्यों में योजना बनाता है।

(ii) उत्पादन के साधनों को एकत्र करना : वस्तु की किस्म तथा उत्पादन-माना निश्चित कर लेने के बाद वह भूमि, श्रम तथा पूँजी की मात्राएँ आवश्यकता-नुसार कम से कम लागत पर खरीदने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करता है। वे साधन जिन व्यक्तियों तथा मस्यामों से खरीदे जा सकते हैं, उनसे वह सौदा करता है। इसके बाद सौदे के अनुसार निश्चित किये गये मूल्य का भुगतान करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध वही करता है।

(iii) विभिन्न साधनों में प्रभावकारी सहयोग स्थापित करना : उत्पादन के आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर लेने के बाद संगठनकर्त्ता उनमें अनुकूलतम सहयोग स्थापित करने की नीति निर्धारित करता है। प्रतिस्थापन के नियम (Law of substitution) के आधार पर विभिन्न साधनों के समन्वय का सर्वोत्तम अनुपात निर्धारित करता है। इसके लिए वह बाजार में वस्तु की मांग तथा तुलनात्मक मूल्य का अध्ययन करता है। इसके बाद वह अपनी उत्पादन-लागत ज्ञात करके अनुपातों में हेरफेर करता है तथा कम से कम लागत पर वस्तु के उत्पादन की व्यवस्था करता है।

(iv) आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा कच्चे माल को कय करना : वह उत्पादन कार्य को चलाने के लिए आवश्यक मा-यंत्रियों, यन्त्र-कय तथा उपकरणों को खरीदने का प्रबन्ध करता है। इन सम्बन्ध में वह इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि खरीदी जाने वाली सामग्रियाँ अच्छी हों तथा यन्त्र एवं कल उत्पादन-कार्य के लिये उपयोगी हों और उनकी कार्य क्षमता अधिकतम हो।

(v) श्रम संगठन : संगठनकर्त्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य श्रम को संगठित करना भी है। उसे श्रमिकों की रुचि, योग्यता तथा कार्यक्षमता के अनुसार कार्य विभाजन करना पड़ता है। उसे यह भी देखना पड़ता है कि 'श्रम-पटत उत्पादन-अनुपात, ( Labour input-output-ratio ) तथा 'पूँजी पटत-उत्पादन-अनुपात'

(Capital input-output-ratio) में क्या अन्तर है ? दोनों अनुपातों में जिन अनुपात से उसे लाभ होता है, उसी के अनुसार वह अपनी उत्पादन व्यवस्था को संगठित करता है। श्रमिक वर्ग को संगठित करना तथा उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वह प्रेरणादायक योजना की रूपरेखा भी तैयार करता है।

(6) उत्पादन व्यवस्था का प्रशासन : उत्पादन-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वैज्ञानिक प्रबन्ध (scientific management) के सिद्धांतों के आधार पर वह विभागीयकरण (Departmentalisation) पारस्परिक सम्पर्क (communication) तथा अधिकारियों की सुपुर्वी (delegation of authority) के नियमों को कार्यान्वित करने की योजना बनाता है। इन नियमों को कार्य रूप में लागू करके वह सभी कर्मचारियों में सत्ता के प्रति हवि एवं उत्साह को जन्म देकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होना है। विभिन्न सत्ताओं—बैठ बीमा कम्पनियों राज्य तथा स्थानीय सरकारों आदि—से सम्पर्क बनाये रखना भी संगठन-कर्ता का उत्तरदायित्व है।

(7) वितरण व्यवस्था : उत्पादन के पश्चात् संगठनकर्ता का कार्य उत्पादित वस्तु की बिक्री की व्यवस्था करना भी है। बाजार तथा सागत के आधार पर वह अपनी संस्था के माल का मूल्य निर्धारित करता है। इसकी विभिन्न क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था करता है। उनकी पैकिंग, माल भेजने की विधि, मूल्य भुगतान आदि के सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित करता है। बिक्री में सम्बन्धित सभी समस्याओं जैसे विज्ञापन, वितरण-नीति, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, हवि, फौज आदि के परिवर्तनों से माग में परिवर्तन आदि का अध्ययन करना तथा व्यवसर से लाभ उठाने वाली नीति निर्धारित करना भी संगठनकर्ता का ही कार्य है।

(8) अन्य कार्य : संगठनकर्ता को उपर्युक्त कार्यों के अनिर्दिष्ट उत्पादन सम्बन्धी नई नई विधियाँ, नवीनतम यन्त्रों, नये बाजार क्षेत्रों, प्रौद्योगिक उत्पादन तथा बिक्री नीतियों का भी ज्ञान रखना पड़ता है जिससे वह अपनी सत्ता के विकास तथा लाभ की वृद्धि करने में सफल हो सके।

संगठन के स्वरूप (Forms of Organisation) : व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों के वर्गीकरण के दो आधार हैं—(1) उनका आकार तथा (2) उनका स्वामित्व। आकार के आधार पर वे बड़े पैमाने के, छोटे पैमाने के अथवा माध्यम पैमाने के हो सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के वर्गीकरण का कोई सामान्य पैमाना या माप न होने से यह कहना कठिन है कि किसी सत्ता को किस वर्ग में रखा जाय। अतः विभिन्न व्यावसायिक सत्ताओं में उनके स्वामित्व के आधार पर

भेद करना सरल है। यहाँ पर उत्पादन-कार्य में सलग्न विभिन्न सगठित सस्थाओं का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया है।

प्राचीन काल में प्रायः उत्पादन के समस्त साधनों की व्यवस्था करने वाला एक ही व्यक्ति होता था जिसे हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। परन्तु वर्तमान युग में उत्पादन करने वाली इकाई का सगठन तथा संचालन एक व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्ति समूहों द्वारा सम्मिलित रूप से भी किया जाता है। इन व्यावसायिक सगठनों को निजी व्यवसाय (private enterprise) के वर्ग में रखा जाता है : ये व्यावसायिक सगठन निजी लाभ के उद्देश्यों से सगठित तथा संचालित किये जाते हैं। इन व्यावसायिक सगठनों के अतिरिक्त भाजकन सरकार द्वारा भी सार्वजनिक हित के लिए सार्वजनिक उपक्रम तथा सस्थाएँ स्थापित की जाती हैं। इस प्रकार के सगठन के तरीकों और उद्देश्यों में भी विभिन्नता होती है। कुछ सस्थाओं का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना होता है और कुछ का पारस्परिक लाभ या सार्वजनिक सेवा। उद्देश्यों और लाभों में विभिन्नता होने के कारण स्वामित्व के आधार पर सगठन के कई स्वरूप होते हैं, जैसे (1) एकाकी उत्पादन व्यवस्था, (2) साझेदारी, (3) कम्पनी, (4) सहकारिता, तथा (5) सार्वजनिक सस्थान।

### 1. एकाकी उत्पादन-व्यवस्था (The Single Entrepreneur System)

एकाकी उत्पादन व्यवस्था का अभिप्राय व्यक्तिगत स्वामित्व के सस्थान से है। इस सस्था का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है जो उत्पादन के समस्त साधनों की व्यवस्था करता है, उत्पादन-कार्य को सगठित तथा संचालित करता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि मस्या का स्वामी एक ही व्यक्ति हो। एक ऐसी पारिवारिक सस्था भी जिसका संचालन, सगठन तथा प्रबंध संयुक्त रूप से किया जाता है तथा सस्था के लाभ व हानि का विभाजन नहीं होता, व्यक्तिगत या एकल स्वामित्व की सस्था कहलाती है।

एकाकी साहसी अपनी सस्था की समस्त व्यावसायिक क्रियाओं की धुरी होता है। वह उत्पादन कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध कार्य-क्रम बनाता है, उसके अनुसार धन, भूमि तथा पूँजी की व्यवस्था करता है, उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय लेता है तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करता है। इस प्रकार उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के विचार करने के समय से लेकर अब तक कि माल का उत्पादन नहीं हो जाता तथा माल की बिक्री नहीं हो जाती तब तक सम्पूर्ण कार्य संचालन का भार एकाकी व्यक्ताधी या उत्पादक पर ही रहता है। अतः इस एक व्यक्ति में ही माहमी, निर्देशक, सगठनकर्ता तथा प्रबन्धक के उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध होता है।

साम एकाकी व्यावसायिक संगठन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :

(1) मितव्ययिता (Economy) : उत्पादनकारी संस्था का स्वामी स्वयं समस्त उत्पादन कार्यों का निर्देशक, संचालक एवं सगठक होता है अतः समस्त कार्य-व्यवस्था मनुष्योचित रूप से चलती है। अप्रत्यय और क्षति होने की सम्भावनाएं न्यूनतम हो जाती हैं।

(2) शीघ्र निर्णय (Quick Decision) : एक व्यक्ति स्वयं अपनी संस्था की कार्य-भरणा तथा कुशलता अथवा संचालन के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले सकता है। उसको किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पत्ती।

(3) अच्छी वस्तुओं का उत्पादन (Quality Production) : एकल उत्पादक प्रत्येक वस्तु का उत्पादन अपनी देखरेख में करवाता है, जिसमें उत्पादित वस्तु की किस्म अच्छी बनी रहती है। वह उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तुओं की किस्मों में शीघ्र परिवर्तन करने में समर्थ होता है तथा कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है।

(4) श्रमिकों के साथ अच्छा सम्बन्ध (Good Labour Relations) : एकल उत्पादक का अपने श्रमिकों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। अतः वह उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रख सकता है।

दोष : इस प्रकार की उत्पादन-व्यवस्था के निम्नलिखित प्रमुख दोष हैं :

(1) अपर्याप्त पूँजी (Inadequate Capital) : वर्तमान उत्पादन अथवा व्यावसायिक व्यवस्था के लिए अधिक मात्रा में पूँजी आवश्यक है। एकल उत्पादक न तो स्वयं अधिक पूँजी लगा सकता है और न ही वह अकेले अपनी व्यक्तिगत जमानत पर अधिक पूँजी प्राप्त कर सकता है।

(2) अधिक जोखिम (Great Risk) : एकल व्यावसायिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके स्वामी का उत्तरदायित्व असीमित होता है। व्यापार में हानि होने पर न केवल व्यावसायिक पूँजी ही डूबती है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्तिप्राप्ति भी हानि को पूरा करने में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की जोखिम होने के कारण ही उद्यमी कभी-कभी पूर्णतया दिवालिया हो जाता है।

उपरोक्त दोषों के कारण ही बड़े पैमाने के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यों का संगठन एकाकी साहसो नहीं कर पाता है। परन्तु इन दोषों के होने हुए भी इस प्रकार का व्यावसायिक संगठन कृषि-उत्पादन, घरेलू उद्योग, तथा कम लागत वाले उत्पादनकारी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अब भी जोड़ित है। कृषि, मुद्राकर व्यापार, होजरी तथा चावल-दाल की मिलें, त्रिन्म कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, एकाकी व्यवस्था के उदाहरण हैं।

## 2. साझेदारी (The Partnership)

*"The partnership of fellow travellers is an example of the difficulty in men living together and having things in common for they generally fall out by the way and quarrel about any trifle which turns up"*

—Hans

साझेदारी संगठन का जन्म वास्तव में पूँजी, कुशल-निरीक्षण एवं नियंत्रण तथा अधिक विशिष्टीकरण और धन विभाजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। इस प्रकार के संगठन का प्राथमिक रूप में *Societas* नामक व्यक्तियों के मध्य के रूप में हुआ था। कालान्तर में पारिवारिक सम्बन्ध के आधार पर भी साझेदारी संगठन स्थापित किए गए। साझेदारी संगठन का वह रूप है जो पारस्परिक समझौते के आधार पर कुछ व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य से संगठित किया जाता है। इस संगठन का स्वामित्व व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में रहता है। भारतवर्ष में एक व्यावसायिक अथवा औद्योगिक संस्थान में अधिक से अधिक बीस साझेदार हो सकते हैं। 20 से अधिक व्यक्तियों का संगठन होने पर उसका पंजीयन कम्पनी के रूप में किया जाता है।

व्यवस्था : साझेदारी के अन्तर्गत उत्पादन व्यवस्था समुचित रूप से संचालित एवं संगठित की जाती है। प्रत्येक साझेदार को प्रबन्ध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। वे पारस्परिक समझौते के अनुसार साधनों की पूर्ति करते हैं।

दायित्व : साझेदारी संगठन के स्वामियों का दायित्व (हानि तथा श्रृंखला को पूरा करने का दायित्व) असीमित होता है। प्रत्येक साझेदार का अधिकार समान होने के कारण, कोई भी साझेदार संगठन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।

सामान साझेदारी संगठन के अन्तर्गत उत्पादन व्यवस्था को कई सामान प्राप्त होत हैं। साझेदारी फर्म एकाकी उत्पादक की अपेक्षा अधिक मात्रा में वित्तीय साधन (Financial Resources) प्राप्त कर सकती है। कई साझेदारों के रहने पर साझेदारी फर्म का संचालन एवं प्रबन्ध अधिक कुशल होता है। साझेदार विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य विभाजन करके फर्म की कार्य व्यवस्था को अधिक कुशलतापूर्वक संचालित करने में सफल होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के आधार तथा कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नया साझेदार भी लिया जा सकता है। इन साझेदारों का दायित्व असीमित होने के कारण साझेदारी फर्म की साख्त अधिक होती है जिसके कारण व्यवसाय तथा उत्पादन के विकास के लिए सरलतापूर्वक आवश्यक साधनों की पूर्ति सम्भव हो जाती है।

दोष : परन्तु साझेदारी संगठन में भी कई दोष हैं। 'बहुमत जोगी न

उजाड़' ( Too many cooks spoil the broth ) की कटावत इस प्रकार की उत्पादन सस्या पर पूर्ण हा से लागू होती है। सामीदारो मे पारस्परिक मतभेद होन पर उत्पादन व्यवस्था का कुशल संचालन असम्भव हो जाता है। इसके प्रतिरिक्त इसका जीवन काल अनिश्चित तथा अल्पकालीन होता है। किसी भी सामीदार की मृत्यु होने पर या उसके अवकाश ग्रहण कर लेने पर अवका उसके दिवालिया हो जाने पर सामेदारी का वैधानिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख दोष सामीदारो का असमीमित दायित्व है। चू कि फम प्रत्येक सामीदार के फर्म-सम्बन्धी बायों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, अत एक अकुशल सामीदार अन्य सभी सामीदारो का बर्बाद कर देता है। अन्न में, प्राय सामेदारी संगठन की उत्पादन-मान को बढाने मे अरने की असमर्थ पाता है। पूंजी की अर्याप्तता सामेदारी तस्थान का प्रमुख दोष है। सामीदार पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था न कर सकने के कारण व्यावसायिक विकास नहीं कर पाते।

सामेदारी संगठन मे उपर्युक्त दोषो के कारण ही इसका स्थान धीरे धीरे कम्पनी संगठन लेता जा रहा है।

### 3 कम्पनी (The Company or Corporation)

*"An artificial being, invisible, intangible and existing only in the contemplation of the law. Being a mere creation of the law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it among the most-important of which are immortality and individuality"*

—Chief Justice Marshall

परिभाषा सामान्यत कम्पनी या निगम (Corporation) शब्द का प्रयोग तमे संगठन के सम्बन्ध मे प्रयुक्त किया जाता है जो कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो। यह सामान्य उद्देश्य अधिकतम उत्पादन अथवा व्यापार द्वारा लाभ उपाजित करना होता है। इसकी स्थापना राज्य-प्राप्ता, विशेष कानून अथवा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार संगठित सस्या को वैधानिक रूप से निर्मित, कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त व्यक्ति कहा जाता है। Joint Stock company अथवा Corporation शब्द का प्रयोग भी कम्पनी के लिए ही किया जाता है। कम्पनी का निर्माण पूंजी को निश्चित मूल्य वाले अंको मे बाट कर तथा उनको बेच कर किया जाता है। इन अंशो को क्रय करने वाले अक्षपारी (Shareholders) कम्पनी के सदस्य (Members) तथा स्वामी कहलाते हैं। कम्पनी की संगठन विधि तथा उसके सम्बन्धित पक्षो के अधिकारो तथा कर्तव्यो का नियमन कम्पनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। वेधा-

निक दृष्टिकोण से कम्पनी, निजी (Private) अथवा सार्वजनिक (Public) हो सकती है। कम्पनी संगठन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

1. कानून की दृष्टि से कम्पनी एक व्यक्ति के समान है। यह एक विधि निर्मित व्यक्ति (a legal person) है।

2. कम्पनी पर अशधारियों का स्वामित्व होता है, परन्तु वे प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के प्रबंध में भाग नहीं लेते। कम्पनी का अस्तित्व अशधारियों से पृथक् होता है।

3. प्रायः कम्पनी का प्रबंध सचालकों द्वारा किया जाता है। सचालक अशधारियों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। कभी-कभी कम्पनी का प्रबंध कुछ व्यक्तियों प्रबंध अभिकर्ताओं (Managing Agents) को सौंप दिया जाता है।

4. कम्पनी के अश कई प्रकार के होते हैं। भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार एब भारतीय कम्पनी साधारण (Equity) तथा पूर्वाधिकार (Preference) अशों का निगमन करती है। पूर्वाधिकार अशों के धारकों को कम्पनी के लाभ में हिस्सा (लाभांश Dividends) प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है।

5. सीमित दायित्व वाली कम्पनी के प्रत्येक अशधारी का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अशों के निर्धारित मूल्य तक ही सीमित रहता है। वह कम्पनी के ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता।

6. कम्पनी के अशधारी अपने अशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। यह सुविधा एक निजी कम्पनी के अशधारियों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक कम्पनी पर स्वामित्व बदलते हुए व्यक्ति समूहों का रहना है। परन्तु इससे कम्पनी के व्यक्तिगत अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि कम्पनी को 'सतत उत्तराधिकार वाला विधि-निर्मित कृत्रिम व्यक्ति' (An artificial person created by law with a perpetual succession) कहा जाता है।

कम्पनी संगठन के लाभ साझाकारी संगठन में असीमित जोखिम तथा अपर्याप्त पूँजी के दोषों के कारण कम्पनी-संगठन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। बड़े पैमाने की उत्पादन-व्यवस्था कम्पनी-संगठन के अंतर्गत ही सम्भव हो पाती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के संगठन से उत्पादकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं :

(1) बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव होना : सार्वजनिक कम्पनी में अशधारियों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जमता में अशों की बिक्री होने से



कम्पनी अधिक से अधिक व्यक्तियों को अपने अंश बेचकर अधिक मात्रा में पूँजी एकत्र कर लेती है। अतः एक कम्पनी के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की व्यवस्था करना सरल है।

(2) पूँजी तथा व्यावसायिक योग्यता का सहयोग कम्पनी का प्रबन्ध तथा स्वामित्व अलग अलग होने के कारण कुशल तथा योग्य व्यवस्थापकों द्वारा पूँजी पतियों की पूँजी का सदुपयोग, कम्पनी संगठन के अनुगमन ही सम्भव है। इस प्रकार की संगठन व्यवस्था में ही व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों तथा पूँजी पतियों को एक स्थान पर एकत्रित करके 'पूँजी' तथा 'संगठन' साधनों को मिलाया है। अकुशल तथा व्यवस्था की क्षमता न रखने वाले अशुद्धारी भी पूँजी प्रदान करते हैं तथा पूँजीपति न होने पर भी योग्य एवं कुशल संचालक तथा प्रबन्धक व्यावसायिक योग्यता की पूर्ति करते हैं।

(3) अशुद्धारियों के जोखिम में कमी कम्पनी संगठन ने व्यावसायिक क्षेत्र में यत्तिगत जोखिम को न्यूनतम कर दिया है। एकाकी तथा साभेदारी संगठन में अनिमित उत्तरदायित्व होने के कारण एकाकी उत्पादक व्यवसाय साभेदारी व्यावसायिक ऋणों तथा हानियों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। साभेदारी मर्यादा में प्रत्येक साभेदारी अन्य साभेदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी समझा जाता है। कम्पनी के अशुद्धारी का दायित्व खरीदे गए अंशों के लिखित मूल्य तक ही सीमित रहता है और कोई भी अशुद्धारी किसी अन्य अशुद्धारी के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक अशुद्धारी की जोखिम की मात्रा सीमित तथा न्यूनतम होती है। यही कारण है कि विनियोजक अपनी पूँजी को कम्पनियों में विनियोजित कर पाते हैं।

(4) विभिन्न रुचि वाले विनियोजकों की इच्छा को एकत्र करना : कम्पनी विभिन्न प्रकार के अंशों का निर्गमन करके विभिन्न प्रवृत्ति तथा रुचि वाले विनियोजकों को अपना धन विनियोजित करने की सुविधाएं प्रदान करती है। निश्चित् प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति पूर्वाधिकार अंशों में अपना धन विनियोजित करने की सुविधा प्राप्त करते हैं, सट्टे की प्रवृत्ति रखने वाले विनिगोषणों की रुचि के अनुकूल कम्पनी साधारण तथा अन्य प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है। इस प्रकार कम्पनी Mr. Wise, Mr. Medium तथा Mr. Speculator की दृष्टान्त के अनुसार अंशों का निर्गमन करके न केवल जनता की रुचि को आकर्षित करती है, बल्कि उनके जोखिम भार को भी विकेंद्रित कर देती है।

(5) अंशों के हस्तान्तरण की सुविधा : एक अशुद्धारी अपने अंशों के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने अपने विनियोजित धन को वापस प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पूँजी गतिशील रहती है।

(6) पूँजी का उत्पादन-कार्यों में सदुपयोग • कम्पनी संगठन ने पूँजी को अधिक कार्यशील तथा गतिशील बनाया है। कम्पनी संगठन के विकास के साथ ही साथ, अनेक वित्तीय संस्थाओं—बैंक, बीमा-कम्पनियों, विनियोग-ट्रस्टों आदि का विकास होने से सामाजिक धन को एकत्रित करने तथा उसे अनुत्पादक क्षेत्रों से उत्पादक क्षेत्रों में विनियोजित करके देश की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने में सुविधा हुई है।

कम्पनी-संगठन के दोष • परन्तु कम्पनी संगठन पूर्णतया दोष मुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :

(1) निगमन का केन्द्रीकरण : यद्यपि कम्पनी-संगठन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है यह पूँजीपतियों का प्रजातन्त्र है, जो अपनी अतिरिक्त पैसे अपने मनोनीत प्रतिनिधि-मण्डल को सौंप देते हैं तथा इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं कि उनकी पैसे का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?<sup>4</sup> तथापि, व्यावहारिक तथ्य यह है कि कम्पनी-संगठन-व्यवस्था में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता। सम्पूर्ण व्यवस्था तथा प्रबन्ध संचालक-मण्डल में केन्द्रित होता है। प्रशासिकों की कम्पनी में दिलचस्पी भी केवल अपने लाभार्थ के लिए होती है, वे कम्पनी के प्रबन्ध में रुचि नहीं लेते तथा असंगठित होने के कारण शक्तिहीन तथा प्रभावहीन होते हैं।

(2) अधिकारों का दुरुपयोग कुछ व्यक्तियों के हाथों में कम्पनी-संचालन तथा प्रबन्ध केन्द्रित होने से, वे अपने लाभ के लिए ही कम्पनी की नीति निर्धारित करते हैं। इस प्रकार सामान्य प्रशासिकों के हितों की उपेक्षा की जाती है।

(3) स्वार्थिता तथा प्रबन्ध प्रयुक्त होने से हानि : कम्पनी का प्रबन्ध दैनिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। उनका हित केवल वेतन तक ही सीमित होता है। वे न तो व्यावसायिक जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हैं और न नव प्रवर्तन (Innovations) के लिए ही तैयार होते हैं, फलस्वरूप व्यावसायिक संगठन का विकास नहीं हो पाता।

(4) प्रबन्ध में शिथिलता कम्पनी के अधिकारी (executives) प्रशासिकों के लाभ की अपेक्षा अपने लाभ में अधिक रुचि रखते हैं। इन दोनों हितों में सामंजस्य होना कठिन है। कभी-कभी कम्पनी की सम्पूर्ण व्यवस्था अत्यन्त अप्रसन्न होती है।

<sup>4</sup> "The company system is a democracy of capitalists, entrusting their surplus funds to a cabinet of their choosing and retaining an active interest in the use in which their capital is put"

(5) अच्छे धर्म सम्बन्ध का अभाव : कम्पनी-संगठन इतना बृहद् एव विस्तृत होता है कि धर्मियों तथा प्रबन्ध के मध्य व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता । फल-स्वरूप दोनों के हितों में विरोध होने के कारण औद्योगिक-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस सम्बन्ध में यह कहा जाना है कि एक पूर्ण अधिकारी वाली कम्पनी अनुभूतिहीन तथा आत्मा-विहीन है (a corporation sole, has no soul) ।

(6) अच्छे वर्मचारियों का अभाव : कम्पनी के मन्त्रिक तथा प्रबन्धक योग्यता के आधार पर नियुक्त नहीं किए जाते हैं । वे प्रायः कम्पनी पर नियन्त्रण रखने वाले अथवा कम्पनी की अर्थिक पूर्तता पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धी या प्रतिनिधि होते हैं, जो कम्पनी के हितों की अपेक्षा अपने निजी हितों के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं ।

इन दोषों के होने हुए भी कम्पनी संगठन योग्य एव उद्यमी व्यक्तियों की उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति करने के अवसर प्रदान करता है । संगठन की इस व्यवस्था का विकास होने से ही औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा ग्रामीण विकास सम्भव हो सका है ।

#### 4 सरकारी व्यवस्था (State Enterprises)

*"The means of production should be socially owned and controlled for the benefit of society as a whole"* —Jawahar Lal Nehru

स्वतन्त्र तथा निर्बाध पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में (Laissez-faire Capitalism) सरकार अधिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती । परन्तु ग्रामीण कल्याण तथा समाजवादी विचारवागमों के विकास के साथ साथ अधिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है । यही कारण है कि वर्तमान युग में किसी भी देश में निर्बाध पूँजीवाद का अस्तित्व नहीं दिखता । पूँजीवादी देशों में भी सरकार विभिन्न विधियों से अर्थ-व्यवस्था का नियन्त्रण व नियन्त्रण करती है ।

सरकारी व्यवस्था के उद्देश्य : औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप तथा प्रवेश करने के कई कारण हैं । कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें निजी लाभ के तत्व के स्थान पर लोक-सेवा का तत्व निहित होता है । इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता । अतः राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन क्षेत्रों का समुचित विकास करे । कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता अवांछनीय है । इन क्षेत्रों पर राज्य अपना पूर्ण अधिकार रखता है जिनमें वह सम्पत्ति उद्योगों का समुचित विकास कर सके तथा सामान्य उद्योगों की वस्तु तथा सेवाएँ न्यूनतम मूल्य पर प्रदान कर सके । सरकार ऐसे उद्योगों पर अपना पूर्ण अधिकार एवं नियन्त्रण रखती है ।

देश के आर्थिक विकास, उत्पादन-शक्ति, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए भी सरकार अपनी संस्थाएं खोलती है। एक विकसित राष्ट्र में पय-प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। राज्य नवीन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को सहयोग प्रदान करके समुक्त रूप से नये उद्योगों को स्थापित करता है। देश में सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए भी राज्य का औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक माना जाता है। वितरण तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सरकार प्रवेश करती है जिससे वह व्यापारिक चक्रों (तेजी-मन्दी की सम्भावनाओं) को नियन्त्रित कर सके। सरकार प्रतिस्पर्धी संस्थाएं स्थापित करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं विनिर्गत करने की व्यवस्था भी करती है।

**लाभ :** सरकारी संगठन का चाहे जो भी रूप हो, उससे देश का आर्थिक बरबाद होता है। राज्य दम की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से अनेक उद्योगों तथा उत्पादन-इकाइयों का संगठन करके देश का सर्व-मुन्वी विकास करने में सफल हुआ है। इस प्रकार के औद्योगिक संगठनों के स्थापित होने पर लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त-होते हैं। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के हान पर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का विकास होने से उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रों में सरकार भी सक्रिय भाग लेने लगी है। राज्य ने निगमों (Corporations) या प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित किया है जिन्हें सरकारी उपक्रम (State enterprises) कहा जाता है। इन सरकारी संगठनों के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं :

(1) सार्वजनिक सेवा-संस्थानों (Public Utility Concerns) : ऐसे उद्योगों को जो अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा ऐसी सेवाओं को जो देश के जनजीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होती हैं सरकार अपने एकाधिकार में रखती है, जैसे विद्युत-शक्ति, रेल विभाग, डाक-तार आदि।

(2) वैधानिक निगम (Statutory Corporations) : इस प्रकार के निगम की स्थापना विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इस निगम का प्रबन्ध एक वैधानिक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके कार्य तथा अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित कर दिये जाते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation), जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) आदि वैधानिक निगम हैं।

(3) संयुक्त-पूँजी कम्पनी (Joint Stock Company) - एक सरकारी उपक्रम का पञ्जीयन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भी किया जा सकता है। ऐसी संस्था में वे समस्त शुल्क होते हैं जो एक वैधानिक निगम में पाये जाते हैं। अन्तर केवल इतना है कि इसकी स्थापना विशेष अधिनियम द्वारा नहीं की जाती। भारत

मे इस प्रकार की सस्यायें State Trading Corporation, The Ashoka Hotel आदि हैं।

(4) विविध सस्याएं सरकारी संगठन के अन्य कई रूप हैं, जैसे उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सहकारी समितियां, स्थानीय स्वायत्त सस्यायें, म्युनिसिपल तथा जिला परिषद्, नगर-निगम, सरकार तथा निजी उद्योगपतियों के संयुक्त स्वामित्व तथा प्रबन्ध में संचालित सस्यायें आदि।

सार्वजनिक सस्यानों के कई लाभ हैं। उनमें उत्पादन की वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय बढ़ती है जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। सरकारी सस्याओं का उद्देश्य केवल लाभ-प्राप्ति न होने के कारण इन सस्याओं द्वारा उत्पादन तथा वितरित वस्तुओं के मूल्य प्रायः कम होते हैं। सरकार की आय के कई स्रोत होने के कारण राजकीय उद्योगों एवं सस्यानों में पूंजी का अभाव भी नहीं होता। नवीन तथा प्रच्छेदी मशीनों का प्रयोग सम्भव होने से सरकारी उत्पादक इकाइयों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है।

सरकारी संगठन की इकाइयों का प्रबन्ध कुशल तथा अनुभवी सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि ये उत्पादन की कुशल इकाइयां होती हैं। सरकारी सस्याओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों में सेवाओं की सुरक्षा, उचित वेतन, पशन आदि का विशेष आकर्षण होने के कारण वे विघ्न रहित से काम करते हैं।

दोष परन्तु सरकारी उत्पादन-व्यवस्था में वे समस्त दोष वर्तमान होते हैं जो एक सरकारी कार्यालय में पाये जाते हैं। काम विलम्ब, सातफीताशाही (red-tapism) तथा पक्षपातपूर्ण नीति के कारण कार्य कुशलता अधिक नहीं होती है। प्रबन्धकों तथा अधिकारियों में उत्तरदायित्व-हीनता की भावना रहती है, क्योंकि वे केवल वृत्तनिक कर्मचारी होते हैं। लाभ का तत्व न होने के कारण उन्हें अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इनके अनिश्चित सरकारी अधिकारियों में औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठन क्षमता तथा प्रबन्ध करने की विशेष तकनीकी योग्यता का अभाव होता है। यही कारण है कि वे नव प्रवर्तन तथा उत्पादन की नई तकनीकी विधियों के प्रयोग तथा वैज्ञानिक संगठन का समावेश करने के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहते। फलस्वरूप सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था स्थिर तथा मन्द गति से संचालित होती है और निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

परन्तु उपर्युक्त दोष सरकारी उत्पादन इकाइयों के नहीं बल्कि प्रबन्धकों के हैं। उनमें ईमानदारी तथा कर्तव्य-निष्ठा का अभाव होने के कारण ये इकाइयां सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। राजकीय स्वामित्व में कोई दोष नहीं है। इंग्लैंड, ग्रम

रिका तथा आस्ट्रेलिया में इन दोषों को दूर करके राजकीय उत्पादन-व्यवस्था को अधिक लोकप्रिय बनाया गया है। लोकतन्त्रीय देशों में इस प्रकार की समस्याओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

### प्रश्न व संकेत

1. एकाकी स्वामित्व का अर्थ बताइये। इसकी विशेषताओं, गुण एवं दोषों का विस्तृत उल्लेख कीजिये।

[संकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में एकाकी स्वामित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिये तथा द्वितीय भाग में इसकी विशेषताओं, गुण एवं दोषों को विस्तृत रूप में समझाइये।]

2. निम्न में से आप कौन से उपक्रम को सर्वोत्तम समझते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिये।

(अ) व्यक्तिगत (ब) सरकारी (स) सहकारी।

[संकेत—प्रारम्भ में तीनों प्रकार के उपक्रमों के गुण दोषों की विवेचना कीजिये। इसके बाद यह स्पष्ट कीजिये कि प्रत्येक में गुण एवं दोषों की उपस्थिति के कारण यह कहना कठिन है कि तुलनात्मक रूप में कौन सा उपक्रम सर्वोत्तम है। अलग अलग प्रकार के उपक्रम अलग-अलग परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं।]

3. संयुक्त पूँजी कम्पनी की विशेषताएँ क्या हैं? इसके गुण दोष बताइये।

4. साझेदारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके गुण दोष स्पष्ट कीजिये।

## लागत-वक्र (Cost Curves)

*"Costs curves are geometrical illustrations of the relationship between the rate of output of a firm and the rate of expenditure on various inputs."*

Stigler, G. J.

किसी वस्तु की कीमत, उस वस्तु की 'माग' तथा 'पूर्ति' द्वारा निर्धारित की जाती है। माग का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। किसी वस्तु की 'पूर्ति' उस वस्तु की उत्पादन लागत द्वारा शासित होती है। अतः 'पूर्ति' का अध्ययन करने के पूर्व, उत्पादन लागत का विश्लेषण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन सभी तत्वों को, जो पूर्ति में निहित हैं, हम एक शब्द—'लागत' द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। किसी वस्तु की जो मात्रा (पूर्ति) बाजार में बेची जाती है, उस मात्रा का निर्धारण, उत्पादक द्वारा लागत के ही आधार पर किया जाता है।

### 1. लागत-सम्बन्धी विचार (The Concepts of Cost)

अर्थशास्त्र में 'लागत' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। 'लागत' शब्द का अर्थ व्यापारी, लेखाक तथा अर्थशास्त्री के लिए भिन्न भिन्न होता है। अर्थशास्त्री भी 'लागत' शब्द का प्रयोग विभिन्न मदों में करते हैं। अतः सदमं के अनुसार इस शब्द के कई अर्थ लगाये जा सकते हैं। विभिन्न आर्थिक विषयों के विश्लेषण में, लागत के विभिन्न विचारों (Concepts) का प्रयोग किया जाता है। लागत सम्बन्धी ये विचार तीन प्रकार के हैं—मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत तथा भ्रवसर लागत :

#### 1. मौद्रिक लागत (Money Costs) :

भारत ने 'लागत' का अर्थ स्पष्ट करते समय 'मौद्रिक लागत' तथा 'वास्त-

विक लागत' (Real Cost) शब्दों का प्रयोग किया है। किसी वस्तु की लागत, उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की लागत के बराबर होती है। साधनों की लागत का अनुमान हम उनके बाजार मूल्य द्वारा लगाते हैं। उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के बाजार मूल्यों के योग को साधनों की मौद्रिक लागत कहते हैं। अतः किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की 'मौद्रिक लागत' का अर्थ उसे पैदा करने में प्रयुक्त उत्पादन साधनों के बाजार मूल्यों के योग से है। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक लागत वह लागत है जो मुद्रा के रूप में किसी वस्तु के उत्पादन में व्यय की जाती है। जैसे एक उत्पादक एक वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदता है, मजदूरों को मजदूरी देता है, पूँजी पर ब्याज तथा सगठनकर्त्ता को वेतन देता है, साहसी के लिए लाभ की व्यवस्था करता है, सरकार को कर देता है, बीमा तथा मूल्य ह्रास (Insurance and Depreciation) के लिए व्यवस्था तथा भुगतान करता है। इन सभी खर्चों को हम किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में सम्मिलित करते हैं।

किसी वस्तु की 'मौद्रिक लागत' ज्ञात करते समय, हमें उन लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यय नहीं किया जाता है। सम्भव है, उत्पादक ने सभी उत्पादन साधनों को बाजार में नहीं खरीदा हो—उसने अपने कुछ निजी साधनों का प्रयोग किया हो। ऐसे साधनों का मूल्य भी मौद्रिक लागत में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मौद्रिक लागत में सामान्यतः दो प्रकार की लागतें—व्यक्त लागत तथा अव्यक्त लागत सम्मिलित की जाती हैं :

(i) व्यक्त लागत (Explicit Costs) व्यक्त लागत उन मौद्रिक लागतों को कहते हैं जिनका भुगतान साधन के स्वामियों को उत्पादक द्वारा किया जाता है, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, कच्चा माल सम्बन्धी व्यय, विज्ञापन-व्यय आदि। इन सबका भुगतान उत्पादक द्वारा किया जाता है।

(ii) अव्यक्त लागत (Implicit Costs) 'अव्यक्त लागत' उन समस्त लागतों को कहते हैं जिनका भुगतान, उत्पादक द्वारा किसी 'बाहरी व्यक्ति' (outsider) को नहीं किया जाता, बल्कि स्वयं उत्पादक अपने निजी साधनों तथा सेवाओं के बदले अपनी ही फर्म से लागत वसूल करता है (या उत्पादन व्यय की गणना करते समय ध्यान में रखता है), जैसे निजी पूँजी पर ब्याज, निजी सम्पत्ति पर भू-मूल्य ह्रास (जिस सम्पत्ति का उपयोग 'फर्म' ने किया है), फर्म में विनियोजित निजी पूँजी पर प्रतिफल (Return), निजी वेतन आदि। इस प्रकार

कुल मौद्रिक लागत = कुल व्यक्त लागत + कुल अव्यक्त लागत

## 2. वास्तविक लागत (Real Costs)

उत्पादन व्यय का अर्थ वास्तविक लागत से भी लिया जाता है। वास्तविक लागत का अर्थ उस व्यय किए गए 'समय' तथा 'शक्ति' से लगाया जाता है जो कि



एक वस्तु के उत्पादन में वास्तविक लागत व्यय होने हैं। इस प्रकार व्यय होने वाले समय और शक्ति को वास्तविक लागत कहते हैं प्रो० मार्शल के अनुसार "किसी वस्तु को बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगने वाले विभिन्न प्रकार के मजदूरी का परिश्रम, साथ में उसके उत्पादन में प्रयुक्त पूँजी की बचत के लिए आवश्यक त्याग या प्रतीक्षा, य सब प्रयत्न और त्याग मिलकर उस वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हैं।"<sup>1</sup> इस प्रकार जिस कार्य में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे कार्यों की वास्तविक लागत अधिक पड़ती है। ऐसा सम्भव है कि दो कार्यों की मौद्रिक लागत समान हो परन्तु उनकी वास्तविक लागत में अन्तर हो। वास्तविक लागत सिद्धान्त का सामाजिक दृष्टि से महत्व है। परन्तु यह शब्द पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। इसके लिए कोई मापदण्ड भी नहीं है, क्योंकि इसे विषयगत रूप (Subjective term) में ही प्रकट कर सकते हैं।

### 3 अवसर लागत (Opportunity Cost)

मौद्रिक तथा वास्तविक लागत के अतिरिक्त लागत के एक तीसरे सिद्धान्त—अवसर लागत—का भी प्रयोग किया जाता है। अवसर लागत का प्रयोग तबीन ग्रंथ शास्त्री, विशेषतया अमेरिकी ग्रंथशास्त्री, करते हैं। श्रीमती जोन रॉबिन्सन ने 'Opportunity cost' के स्थान पर 'Transfer earnings—स्थानांतर अर्जन' शब्द का प्रयोग किया है। कुछ ग्रंथशास्त्री 'Imputed cost' शब्द का भी प्रयोग करते हैं।

(1) अवसर लागत का अर्थ अवसर नाशित उस लागत का कहते हैं जो एक उत्पादन के साधन का किसी वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है।

उत्पादन के साधनों के कई प्रयोग (alternative uses) हो सकते हैं परन्तु एक साधन विशेष का प्रयोग एक ही कार्य के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार जब एक साधन का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस साधन को उन अन्य अवसरों (opportunities) का त्याग करना पड़ता है, जिनमें उस

<sup>1</sup> "The exertions of all the different kinds of labour that are directly or indirectly involved in making it together with the abstinences or rather the waitings required for saving the capital used in making it, all these efforts and sacrifices together will be called the real cost of production of the commodity."

—Marshall, *op cit* p 339

<sup>2</sup> "The imputed cost (opportunity cost) of a productive input in any given business is the value that input would have the price it would get if employed in its best alternative use"

—Burns, Neal and Watson, *Modern Economics* p 21]

साधन का प्रयोग किया जा सकता था। अतः उस साधन को इस प्रयोग (कार्य) में लगाए रखने के लिए कम से कम इतना पुरस्कार या पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए जितना वह अन्य वैकल्पिक कार्यों में प्राप्त कर सकता था। यदि वैकल्पिक कार्य में प्राप्त किया जा सकने वाला पुरस्कार उस साधन को नहीं दिया जाता है तो वह साधन वर्तमान कार्य को छोड़कर वहाँ चला जाएगा जहाँ पर उसे अधिक पुरस्कार मिलेगा, जैसे एक प्रबन्धक को, मान लीजिए, एक मिल में दो हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, यदि वह मैनेजर अन्य मिल में काम करता तो भी उसे दो हजार रुपये मिलते (यदि किसी अन्य मिल में उसे दो हजार रुपये से अधिक रुपये मिलते, तो वह इस मिल में दो हजार रुपये पर काम नहीं करता)। अतः उस प्रबन्धक की अवसर लागत दो हजार रुपये हुई। इस मिल में उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसे कम से कम दो हजार रुपये दिए जाए, क्योंकि वह दो हजार रुपये अन्य मिल में भी प्राप्त कर सकता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में “वह कीमत जो किसी साधन की एक इकाई को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तान्तर अर्जन या हस्तान्तर कीमत कहलाती है।”

“The price which is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry may be called its transfer earnings or transfer price”  
—Mrs Joan Robinson.

उदाहरण के लिए एक पुस्तक मण्डार का प्रबन्धक पुस्तक मण्डार का प्रबन्धकर्ता है। मान लीजिए, वह प्रबन्धक यदि एक कपड़े की दुकान का प्रबन्ध करता तो उस समय भी उसे वेतन के रूप में कुछ प्राप्त होता। इस प्रकार कपड़े की दुकान पर वह जो वेतन प्राप्त कर सकता था वह वेतन पुस्तक मण्डार के प्रबन्धक की अवसर लागत हुई है।

किसी भी उद्योग में एक साधन को जो पुरस्कार दिया जाता है, वह उस पुरस्कार के बराबर होता है, जिसे वह साधन अन्य उद्योग से प्राप्त कर सकता है। यदि हम उस साधन को उद्योग में बनाए रखना चाहते हैं तो उसे कम से कम इतना पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए, जितना कि वह अन्य वैकल्पिक उद्योग में प्राप्त कर सकता है। प्रो० बेनहम के शब्दों में, “मुझे वह मात्रा जो कि कोई इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे हम हस्तान्तर अर्जन कह सकते हैं।”

“The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings”  
—Benham

कुछ उदाहरणों द्वारा ‘अवसर लागत’ को स्पष्ट किया जा सकता है :

1. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने निजी-व्यापार में पूँजी लगा रखी है। इस

पूँजी की 'अवसर लागत' उस ब्याज के बराबर होगी, जो उस पूँजी को दूसरे स्थानों पर लगाने में बचाया जा सकता है।

2. किसी मशीन की 'अवसर लागत' एक वस्तु को पैदा करने में, उस त्यागी गई आय के बराबर है जो उस मशीन द्वारा किसी अन्य वस्तु को पैदा करने से प्राप्त होती।

3. किसी वस्तु का निर्माण करने वाले धर्मिक की 'अवसर लागत' उस मजदूरी के बराबर है जो वह अन्य वस्तु को या उसी वस्तु का किसी दूसरी फर्म में निर्माण कर प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अवसर लागत ज्ञात करने के लिए, त्याग (sacrifice) को जानना या नापना आवश्यक है। यदि किसी साधन का इस्तेमाल करने में किसी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता है, तो उस साधन की अवसर लागत शून्य होती है। (If there is no sacrifice, there is no cost).

हेंडरसन (Henderson) ने अवसर लागत को इस प्रकार परिभाषित किया है, "उत्पादन के साधनों का मूल्य सर्वोत्तम स्थानापन्न प्रयोग के मूल्य से नापा जा सकता है, जिसमें वे (उत्पादन के साधन) लगाये जाते, यदि इस विशेष इकाई का उत्पादन नहीं होता।<sup>3</sup> ऐसे सर्वोत्तम स्थानापन्न प्रयोग के मूल्य को ही अवसर लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में लगे हुये किसी साधन की लागत वह अधिकतम राशि है जिसे वह साधन दूसरी वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त कर सकता है।

## (II) अवसर लागत की विशेषतायें

(i) अवसर लागतें मौद्रिक लागतें हैं (Opportunity Costs are Money Costs) अवसर लागत उस मुद्रा का योग है जिसे उत्पादन के साधन एक फर्म या उद्योग में निरन्तर प्रयोग होने के कारण प्राप्त करते हैं तथा जिसके कारण वे दूसरे उद्योगों से नहीं जाते। उदाहरण के लिए यदि एक मोटर-निर्माता कार बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में उसे कार बनाने वाले मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी देनी बाहिए, जिससे वे मोटर उद्योग में लगे रहे। यदि उन्हें कम मजदूरी दी जाती है तो वे हवाई जहाज बनाने के कारखाने में जा सकते हैं। यहाँ पर यह भ्रम इस तथ्य से हो सकता है कि मोटर के कारखाने में तथा हवाई जहाज के कारखाने में मजदूरी समान है, परन्तु इस भ्रम का प्रभाव अवसर लागत के सिद्धान्त पर नहीं

<sup>3</sup> "The value of the factors of production is measured by the best alternative use to which they might have been put had this particular unit of commodity not being produced."

पड़ेगा। मान लीजिए ये मजदूर मोटर के कारखाने में नहीं लगाये जाने, ऐसी अवस्था में उनकी स्पर्धा नौकरी के लिए, उन मजदूरों के साथ होती है जो जहाज बनाने के कारखाने में लगे हुये हैं। इस प्रकार जहाज के कारखाने का मालिक मजदूरों में स्पर्धा के कारण उन्हें कम मजदूरी देता है। इसी प्रकार यदि कार की माग बढ़ जाती है और जहाज की माग पूर्ववत् रहती है तो मोटर कारखाने का मालिक मजदूरी और बढ़ा देगा जिससे जहाज के कारखाने से अधिक मजदूर आयेगे। अतः कारखाना चलाने के लिए जहाज के कारखाने में भी मजदूरी बढ़ा दी जावेगी।

(2) अवसर लागत का सिद्धान्त सभी प्रकार के उद्योगों में, उत्पादन के सभी स्तरों पर लागू होता है। यह नियम सभी उद्योगों में लागू होता है, जैसे उत्पादन सम्बन्धी संस्थापन व्यापार गृह, बैंक व्यवसाय आदि। यदि कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएँ खरीदने के लिये बैंक से कर्षण उधार लेता है तो उसे बैंक को इतना व्याज देना होगा जिससे बैंक किसी दूसरे को कर्षण न देकर उसे ही दे सके।

(3) अवसर लागत का अर्थ सर्वत्र नकद ही नहीं होता (Opportunity Costs are not always Cost Expenditures) एक व्यक्ति अपना व्यापार चलाता है। ऐसी अवस्था में उसे अपने लिए कम से कम उतना वेतन अवश्य रखना चाहिए जितना वह अन्यत्र काम करने से प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपने लिए वेतन नहीं रखता है तो व्यापार का वास्तविक लाभ नहीं जान सकता। यहाँ पर यह प्रश्न नहीं उठता कि वेतन का भुगतान नकद दिया जाता है या नहीं। यह बात अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी लागू हो सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने कर्षणों से व्यापार आरम्भ करता है और अपने ही मकान में व्यापार करता है तो उसे कमरा व्याज और किराया लेना चाहिए जिसे वह दूसरे से प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार अवसर लागत यदि वास्तव में प्राप्त की जाती है तो वह वास्तविक आय का रूप ग्रहण कर लेती है।

## 2 अल्पकाल में लागत (Costs in the Short Run)

उत्पादक माग के अनुसार उत्पादन करता है। अधिक माग होने पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। उत्पादन वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में त्रिस प्रकार के परिवर्तन होंगे ? इस प्रश्न का उत्तर विचाराधीन समय या अवधि पर निर्भर है। (समय के अतिरिक्त अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है)। अतः हम यहाँ विभिन्न अवधि में लागत के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। हम अवधि को तीन समूहों में विभाजित कर सकते हैं—(1) बाजार काल (2) अल्पकाल तथा (3) दीर्घकाल।

(1) बाजार काल (Market Period) : बाजार काल उस काल या अवधि को कहते हैं, जिसमें उत्पादक को इतना कम समय मिलता है कि वह माग में परिवर्तन के अनुरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः इस अवधि में मूल्य निर्धारण में माग का प्रमुख स्थान रहता है। पूर्ति निश्चिन्त होती है। माग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ती है, तथा माग में कमी होने से कीमत घटती है।

(2) अल्पकाल (Short Period) अल्पकाल, बाजार की अपेक्षा, अधिक दीर्घ होता है। फिर भी अल्पकाल इतनी कम अवधि को कहते हैं, जिसके अन्दर किसी फर्म की उत्पादन शक्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।<sup>4</sup> इस काल में केवल इतना ही सम्भव है कि फर्म की वर्तमान उत्पादन का अधिकाधिक उपयोग कर लिया जाए। अतः इस काल में वर्तमान उत्पादन शक्ति का अधिक उपयोग कर उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, परन्तु न तो फर्म के आकार में ही परिवर्तन किया जा सकता है, और न किसी उद्योग में फर्मों की संख्या में ही वृद्धि की जा सकती है। लिप्से के अनुसार, 'अल्पकाल उस अवधि को कहते हैं जिसमें उत्पादन के कुछ माघन—मामान्यतः प्लांट तथा उपकरण तथा कभी कभी भूमि—की पूर्ति निश्चिन्त होती है, और उत्पादन में वृद्धि या कमी केवल स्थायी साधन के कम या अधिक गहन प्रयोग द्वारा ही की जा सकती है।'<sup>5</sup>

(3) दीर्घकाल (Long Period) दीर्घकाल उस अवधि को कहते हैं जिस अवधि के अन्तर फर्म की उत्पादन शक्ति में परिवर्तन सम्भव होता है। अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि फर्म की उत्पादन शक्ति, प्लांट, मशीन और प्रबन्ध आदि, में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत दीर्घकाल में फर्म की उत्पादन शक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दीर्घकाल में सभी लागत परिवर्तनशील होती है, अर्थात् दीर्घकाल में फर्म की उत्पादन शक्ति तथा उत्पादन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अल्प काल में समस्या होती है—कौन सी वस्तु फर्म की वर्तमान उत्पादन शक्ति के उपयोग की दर में परिवर्तन करती है? दीर्घकाल में इस प्रश्न का रूप यह होता जाता है—कौन सी वस्तु फर्म की उत्पादन शक्ति में परिवर्तन (change in capacity) या उत्पादन के पैमाने (scale of production) में परिवर्तन निश्चित करती है?

<sup>4</sup> "The short run is a period short enough to preclude any change in the firm's productive capacity" —Burns and others

<sup>5</sup> "The short run is defined as a period of time over which some factors of production—usually, plant and equipment, but sometimes land is fixed in supply and production can be raised or lowered only by using the fixed factor more or less intensively."

लिप्से के शब्दों में, “दीर्घकाल इतनी लम्बी अवधि को कहते हैं, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, प्लांट, उपकरण आदि, की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।”<sup>6</sup>

### (i) कुल लागत

#### (Total Costs)

कुल उत्पादन व्यय को ‘कुल लागत’ कहते हैं। इस प्रकार किसी दी हुई उत्पादन-मात्रा के उत्पादन में जो व्यय होता है, उसे ‘कुल लागत’ कहा जाता है। कुल लागत (Total Cost) को दो भागों में बाटा जा सकता है—(i) कुल निश्चित लागत (Total Fixed cost) तथा (ii) कुल परिवर्तनशील लागत (Total Variable Cost)। मार्शल ने इन लागतों को क्रमशः पूरक लागत (Supplementary Cost) तथा प्रमुख लागत (Prime Cost) कहा है।

(1) कुल निश्चित लागत (Total Fixed Costs) : इन लागतों को कहते हैं जिनको प्रत्येक अवस्था में व्यय करना पड़ता है, चाहे कर्म उत्पादन कर रही हो या नहीं। इसे स्थायी लागत भी कहते हैं। इस लागत का उत्पादन की मात्रा से विशेष सम्बन्ध नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा कम हो या अधिक, उत्पादक को यह लागत ठठानी पड़ती है। अतः स्थायी लागतों वे लागतें हैं जो उत्पादन के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, यद्यपि वे समान रहती हैं, उत्पादन की मात्रा चाहे एक इकाई हो या एक लाख इकाई। यदि उत्पादन कुछ समय के लिए शून्य के बराबर हो जाए तो भी इन लागतों का भार उत्पादक को ठठाना ही पड़ता है।<sup>7</sup> ऐसी लागत में व्यापार में लगी ईंजी पर ध्याज, पूँजी सम्बन्धी सुविधाओं का हान, सम्पत्ति कर, प्रबन्ध तथा ग्राफिम सम्बन्धी वेतन, मशीन का बीमा शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि सम्मिलित हैं। इन व्ययों को ऊपरी खर्च (overhead expenses) भी कहते हैं। ये व्यय प्रत्येक कारखाने में मंदव होते रहते हैं और उसी समय रुकते हैं जब कारखाना अग्निम रूप से बन्द कर दिया जाता है।

(2) कुल परिवर्तनशील लागत (Total Variable Costs) : इन्हें प्रमुख लागत (Prime Costs) भी कहते हैं। परिवर्तनशील लागत उन लागतों को कहते हैं जो पैदा की गई इकाइयों की संख्या के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती रहती

<sup>6</sup> “The long run is defined as a period of time sufficiently long to allow all factors of production, including plant and equipment to be varied in quantity,”  
—Lipsey

<sup>7</sup> “Fixed costs are those which are unrelated to the volume of output, they are the costs of firm when its output is temporarily zero.”  
—Burns and others Modern Economics, P. 113

हैं।<sup>1</sup> प्रमुख लागत में कच्चे माल का मूल्य, प्रत्यक्ष श्रम पर व्यय, उत्पादन कर, ईंधन आदि खर्च सम्मिलित है। ये खर्च उसी समय किये जाते हैं जब उत्पादन का कार्य चलता रहता है। इनकी मात्रा का उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यदि किसी कारणवश कारखाना बन्द कर दिया जाय तो ये खर्च नहीं होते।

(3) कुल लागत (Total Costs) : कुल निश्चित और कुल परिवर्तनशील लागत के योग को 'कुल लागत' कहते हैं। इस प्रकार :

कुल लागत = कुल निश्चित लागत + कुल परिवर्तनशील लागत

कुल लागत-वक्र (Total Cost Curves) : उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए इन लागतों को एक सारिणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

कुल लागत (रूपों में)

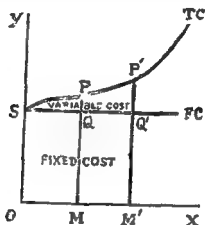
उत्पादन मात्रा इकाइया	कुल निश्चित-लागत (Fix costs)	कुल परिवर्तनशील लागत (Variable costs)	कुल लागत (Total costs)
0	2,000	0	2000
100	2,000	150	2150
200	2,000	275	2275
300	2 000	385	2385
400	2,000	495	2495
500	2 000	650	2650

सारिणी से स्पष्ट है कि कुल निश्चित लागत सदैव समान है। शून्य उत्पादन पर भी कुल निश्चित लागत उतनी ही उठानी पड़ती है, जितनी अधिक उत्पादन पर। शून्य उत्पादन पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ ही साथ परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती गई है।

'कुल लागत', 'कुल निश्चित लागत' तथा 'कुल परिवर्तनशील लागत' को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र सं० 50 में कुल लागत रेखा (Total cost curve) जिसमें प्रमुख लागत तथा पूरक लागत सम्मिलित हैं, दर्शायी गई है। इस रेखा के दो भाग—प्रमुख लागत तथा पूरक लागत—जिनके योग में कुल लागत बनती है, दिखाया गया है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि स्थाई लागत रेखा (Fixed cost curve) एक सीधी रेखा है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा चाहे कुछ भी हो, स्थायी लागत समान रहती है। स्थायी लागत की कुल लागत रेखा तथा

<sup>1</sup> "Variable costs are those which vary directly as a total with the number of units produced"

कुल परिवर्तनशील रेखा (Total variable cost) के बीच के लम्बवत् अन्तर (vertical distance) को नाप कर जाना जा सकता है। कुल प्रमुख लागत रेखा (Total variable cost curve) आरम्भ में शून्य से शुरू होती है तथा ज्यों-ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती है यह रेखा ऊपर उठती जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि



चित्र सं० 50

आरम्भ में वह कम शीघ्रता से ऊपर उठती है। परन्तु कुछ दूरी के बाद वह शीघ्रतापूर्वक ऊपर उठती है। कुल लागत रेखा (Total cost curve) आरम्भ से ही धनात्मक मूल्य (positive value) रखती है, जबकि उत्पादन शून्य रहता है। आरम्भ में उत्पादन के शून्य रहने पर इसका मूल्य fixed cost के बराबर होगा। इसके पश्चात् यह रेखा कुल प्रमुख लागत (Total Prime cost) के साथ लगभग समानान्तर रूप से ऊपर उठती है तथा उन दोनों के बीच की लम्बवत् दूरी स्थायी लागत के बराबर होती है।

**निश्चित तथा परिवर्तनशील लागत की प्रकृति (Nature of Fixed and Variable Costs) :**

(1) उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रमुख लागत उत्पादन के साथ परिवर्तित होती रहती है, जबकि पूरक लागत का उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे हर हानत में व्यय करना पड़ता है। ज्यों-ज्यों उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है यह लागत भी बढ़ती जाती है। आरम्भ में परिवर्तनशील लागत तेजी से बढ़ती है, परन्तु जब उत्पादन में काफी वृद्धि कर दी जाती है, तब बड़े पैमाने के उत्पादन में लाभ प्राप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती। दीर्घावधि (In the long run) में उत्पत्ति हाव



नियम लागू होता है। अतः परिवर्तनशील लागत उत्पादन की अपेक्षा प्राचुपातिक रूप से अधिक बढ़ती है।

(2) इन लागतों तथा समय का घनिष्ट सम्बन्ध है। यह कहना असम्भव है कि कोई लागत सदैव स्थायी है या परिवर्तनशील है। यह समय पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रमुख तथा पूरक लागत का अन्तर अल्पकाल (short run) तथा दीर्घकाल (long run) से पूरातया सम्बन्धित है। दीर्घावधि में सभी लागत परिवर्तनशील होती हैं परन्तु अल्प अवधि में बहुत सी लागतों में परिवर्तन नहीं होता उत्पादन की मात्रा चाहे कुछ भी क्या न हो।

(3) मूल्य निर्धारण में प्रमुख लागत और पूरक लागत का अधिक महत्व है। अल्पकाल में यह सम्भव है कि किसी दिए हुए समय पर जबकि मूल्य पर मांग का प्रभाव अधिक पड़ता है तो उत्पादन के लिए यह सम्भव हो सकता कि वह प्रमुख लागत व पूरक लागत दोनों को प्राप्त कर ले। अल्पावधि में यदि उत्पादक को केवल प्रमुख लागत में मूल्य के रूप में प्राप्ति हो जाती है तो वह उत्पादन जारी रखेगा। ऐसी परिस्थिति मुख्यतः आर्थिक मंदी या डम्पिंग (depression or dumping) के समय में होती है। उत्पादक ऐसा इसलिए करता है ताकि उत्पादन काय बंद करना पड़े। इस प्रकार जो भी मूल्य प्राप्त होता है उस पर बेच कर वह उत्पादन कार्य जारी रखता है।

(4) केवल प्रमुख लागत को मूल्य के रूप में प्राप्त कर उत्पादक उत्पादन का कार्य दीर्घावधि में नहीं चला सकता। ऐसा वह केवल अल्प समय के लिए ही कर सकता है, क्योंकि अल्प समय में उत्पादन को बन्द करने से फिर उत्पादन काय प्रारम्भ करने में कठिनाई उठानी पड़ती है। अल्पावधि में वह कम से कम इतना मूल्य स्वीकार करेगा जिससे यदि वस्तु की कुल लागत न घटती हो सके तो कम से कम प्रमुख लागत व पूरक लागत का कुछ भाग अवश्य प्राप्त हो जाय। बहुत ही कम समय में यदि असाधारण परिस्थिति आ जाय तो उत्पादक सविष्य की प्रार्थना में केवल प्रमुख लागत प्राप्त हो जाने पर भी उत्पादन जारी रखता है।

(5) दीर्घावधि में यह आवश्यक है कि उत्पादक को मूल्य के रूप में प्रमुख लागत तथा पूरक लागत दोनों प्राप्त हों। यदि दीर्घावधि में उसे प्रमुख लागत तथा पूरक लागत दोनों के बराबर मूल्य नहीं प्राप्त होता तो वह उत्पादन कार्य बन्द कर देगा।

**निश्चित लागत तथा परिवर्तनशील लागत में सम्बन्ध (Relationship between Fixed and Variable Costs) :**

निश्चित लागत तथा परिवर्तनशील लागत की विवेचन के बाद अब हम उनसे

सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे। ये बातें निश्चित लागत तथा परिवर्तनशील लागत के अन्तर से सम्बन्धित हैं :

(1) सर्वप्रथम दोनों लागतें साथ-साथ चलती हैं। किसी एक उत्पादन के माधन से उत्पादन नहीं किया जा सकता, बल्कि स्थायी तथा परिवर्तनशील साधनों (fixed and variable factors) दोनों के सहयोग से ही उत्पादन होता है।

(2) प्रमुख लागत तथा पूरक लागत में कुल लागत का जो विभाजन किया जाता है, वह उत्पादक इकाई की अवधि (duration) से पूर्णतया सम्बन्धित है। यह बात मजदूरी तथा वेतन के सम्बन्ध में मुख्यतया लागू होती है। जैसा कि प्रो० मार्शल ने कहा है कि प्रमुख लागत दीर्घकाल में अल्पकाल की अपेक्षा पूरक लागत का रूप ले लेती है।<sup>9</sup> दूसरे शब्दों में अल्पावधि में कुछ साधन उत्पादन के कार्य में निश्चित तथा पूरक होते हैं (Fixed and Supplementary) परन्तु दीर्घावधि में वही साधन (variable) हो जाते हैं।

(3) प्रो० मार्शल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रमुख तथा पूरक लागत में विशेष प्रकार का अन्तर नहीं है, बल्कि उनका अन्तर केवल मात्रा तक ही है (The distinction between prime and supplementary costs is one of degree and not kind) उदाहरण के लिए एक क्लर्क को वेतन दिया जाता है। यदि उत्पादन के बन्द होने के साथ ही साथ उसकी नौकरी भी समाप्त कर दी जाती है तो यह लागत प्रमुख लागत (Prime Cost) होगी और यदि उसकी नौकरी नहीं समाप्त की जाती तो यह लागत पूरक लागत (Supplementary) होगी।

## (ii) इकाई-लागत (Unit Cost)

'कुल उत्पादन लागत' का विभाजन 'कुल निश्चित लागत' तथा 'कुल परिवर्तनशील लागत' में किया जा सकता है। इन लागतों पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। 'कुल लागतों' की जानकारी उत्पादक के लिए अति आवश्यक है। परन्तु प्रति इकाई लागत (per unit cost) की जानकारी कुल लागतों की जानकारी की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। अतः हम अब इकाई लागतों का अध्ययन करेंगे।

प्रति इकाई लागत ज्ञात करना (Finding Unit Cost) :

प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दे देते हैं। अग्रनिश्चित माहिती द्वारा विभिन्न प्रकार की 'इकाई लागतों' को ज्ञात करने की विधि पर प्रकाश पड़ता है :

<sup>9</sup> "Prime costs relatively to long periods becomes supplementary costs relatively to short periods."  
— Marshall

प्रति इकाई अल्पकालीन लागतें (रूपयों में)

उत्पादन	कुल निश्चित लागत	परिवर्तनशील लागत	औसत निश्चित लागत	औसत परिवर्तन लागत	औसत कुल लागत	सीमान लागत
(output)	(TFC)	(TVC)	(AFC)	(AVC)	(ATC)	(MC)
1	100	20	100	20	120	
2	100	38	50	19	69	18
3	100	53	33	18	51	15
4	100	64	25	16	41	11
5	100	75	20	15	35	11
6	100	86	16	16	32	21
7	100	128	14	18	32	32
8	100	172	12	21	34	44
9	100	233	11	26	37	61
10	100	300	10	30	40	67

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार की प्रति इकाई लागतें किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। इन इकाई लागतों का विवरण निम्नलिखित है

(1) औसत निश्चित लागत (Average Fixed Cost) :

उपरोक्त सारिणी में औसत निश्चित लागत हमारे खाने में दिखायी गई है। यह कुल निश्चित लागत में उत्पादन इकाइयों से भाग देने में प्राप्त होती है। चूँकि कुल निश्चित लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देते हैं इसलिए उत्पादन के बढ़ने के साथ ही साथ औसत निश्चित लागत घटती जाती है। यही कारण है कि आरम्भ में जब उत्पादन कम होता है तो औसत निश्चित लागत अधिक होती है। उत्पादन के बढ़ने के साथ ही आरम्भ में यह लागत शीघ्रता से घटती है। बाद में धीरे धीरे घटती है।

(2) औसत परिवर्तन लागत (Average Variable Cost) :

यह लागत कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन का भाग देने में प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ता जाता है, यह लागत कम होती जाती है। यह वही उस बिन्दु तक होती है जहाँ तक फर्म सबसे अधिक कार्यशील होती है। उसके पश्चात् यह ऊपर उठना आरम्भ होती है। इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का आकार घरेलू के 'U' की भाँति होता है।

### (3) कुल औसत लागत (Average Total Cost) ।

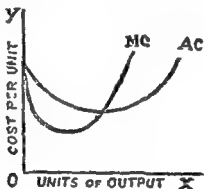
जैसा बतलाया जा चुका है, यह लागत कुल लागत में उत्पादन की कुल इकाइयों में विभाजित करने से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में यह लागत औसत निश्चित लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। कुल औसत लागत में औसत निश्चित लागत और औसत परिवर्तनशील लागत सम्मिलित रहती है। 'कुल औसत लागत' को 'औसत लागत' (Average Cost) भी कहते हैं। उद्योगों उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, औसत निश्चित लागत कम होती जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत में भी पारस्म में कमी होती है, परन्तु जब उत्पादन एक निश्चित सीमा तक पहुँच जाता है तब औसत परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हो जाती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब उत्पादन उस सीमा तक पहुँच जाता है जबकि औसत परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होने लगती है, तब कुल औसत लागत में कमी होती है।

### (4) सीमांत लागत (Marginal Cost)

यह वह लागत है जिस पर उत्पादक वस्तु की एक इकाई कम या अधिक उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में उत्पादित वस्तुओं की अंतिम इकाई की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक उत्पादक किसी वस्तु की 20 इकाइयों का उत्पादन करता है तो 20वीं इकाई का जो उत्पादन-व्यय होगा उसे सीमांत उत्पादन व्यय कहेंगे। सीमांत उत्पादन व्यय को हम एक दूसरे प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं। सीमान्त लागत वह अतिरिक्त लागत है जिसके द्वारा एक अतिरिक्त इकाई के पैदा करने से कुल व्यय में वृद्धि होती है, जैसे एक व्यक्ति 20 वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा उनके उत्पादन में 200 रु० व्यय होता है। अब यदि वह 51 वस्तुओं का उत्पादन करे और कुल लागत व्यय 205 रु० होती है तो यह अतिरिक्त 5 रु० सीमांत लागत है।

मूल्य निर्धारण में 'सीमांत लागत' का अत्यन्त ही महत्व है। उत्पादक को बाजार मूल्य की ध्यान में रखते हुए यह निश्चय करना पड़ता है कि उत्पादन की मात्रा कितनी रखी जाय। जिस समय तक वस्तु का मूल्य 'सीमांत लागत' से अधिक है उस समय तक उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। वह उत्पादन वृद्धि उस समय तक करता जाएगा, जब तक कि वस्तु का बाजार मूल्य 'सीमांत लागत' के बराबर नहीं हो जाता। जिस सीमा पर बाजार मूल्य तथा 'सीमांत उत्पादन व्यय' बराबर हो जायेंगे उस सीमा के बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि उत्पादक इसके बाद भी वृद्धि करता है तो उसे हानि होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादक की मात्रा निश्चित करने में सीमांत उत्पादित लागत का प्रभुत्व है।

‘औसत लागत’ तथा ‘सीमान्त लागत’ में सम्बन्ध (Average and Marginal Cost relationship) - औसत लागत तथा सीमान्त लागत में सम्बन्ध है, जिसे निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है (i) आरम्भ में औसत लागत तथा सीमान्त लागत दोनों गिरती हैं, परन्तु सीमान्त लागत औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति में गिरती है, (ii) उत्पादन में कोई ऐसा बिन्दु अवश्य आता है, जहाँ पर औसत लागत सीमान्त लागत के बराबर होती है, (iii) जहाँ पर औसत लागत और सीमान्त लागत बराबर होती है उसके बाद दोनों बढ़ना प्रारम्भ करती हैं परन्तु सीमान्त लागत, औसत लागत की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ती है। सीमान्त तथा औसत लागत का यह सम्बन्ध निम्नलिखित रेखाचित्र में स्पष्ट है



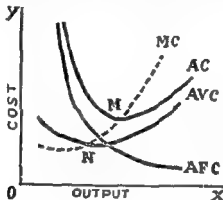
चित्र सं० 51

प्रस्तुत चित्र में AC औसत लागत रेखा है और MC सीमान्त लागत रेखा है। जिस बिन्दु पर दोनों रेखाएँ मिलती हैं उसके पश्चात् सीमान्त लागत रेखा औसत लागत रेखा की अपेक्षा अधिक तेजी से उठती है।

(iii) इकाई लागतों का रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण

‘औसत लागत’, ‘औसत निश्चित लागत’, ‘औसत परिवर्तनशील लागत’ तथा ‘सीमान्त लागत’ के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन रेखा चित्र सं० 51 द्वारा किया जा सकता है। (चित्र के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि कोई भी प्रति इकाई लागत रेखा Y-अक्ष को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उत्पादन शून्य होने की समस्या में प्रति इकाई लागत का प्रश्न ही नहीं उठता)। OX—अक्ष पर उत्पादन की विभिन्न मात्राएँ तथा OY—अक्ष पर प्रति इकाई लागत दिखालाई गयी है। AFC औसत स्थायी लागत (Average Fixed Cost) रेखा है जो उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ नीचे गिरती गई है। AVC औसत परिवर्तनशील लागत (Average Variable Cost) रेखा है। यह रेखा प्रारम्भ में गिरती और बाद में उठना प्रारम्भ

करती है।  $AC$  औसत लागत रेखा है जो पहले गिरती है, तदपश्चात् वह ऊपर उठना प्रारम्भ होती है। इस रेखा पर निम्नतम बिन्दु ( $M$ )  $AVC$  के निम्नतम बिन्दु ( $N$ ) की दायी ओर पड़ता है। निम्नतम बिन्दु के पश्चात्  $AVC$  उठना प्रारम्भ होती है, परन्तु  $AFC$  गिरती है। इसके पश्चात्  $AVC$  लगातार बढ़ती गयी है तथा  $AFC$  के गिरने की गति धीमी होती गयी है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि  $AVC$  की वृद्धि दर से  $AFC$  की गिरने की गति की दर अधिक है।



चित्र सं० 52

फलस्वरूप  $AC$  ऊपर उठती गई है।  $MC$  सीमान्त लागत रेखा है। प्रारम्भ में सीमान्त लागत घटती है, उसके बाद उसमें वृद्धि होना प्रारम्भ होती है। यही कारण है कि  $MC$  रेखा प्रारम्भ में नीचे की ओर गिरती है, उसके पश्चात् वह ऊपर की ओर उठती है। यह रेखा  $AC$  तथा  $AVC$  (Average Cost तथा Average Variable Cost) की रेखाओं को उनके निम्नतम बिन्दुओं (Lowest points) ( $M$  तथा  $N$ ) पर काटती है।

उपरोक्त रेखाचित्र के आधार पर, हम सीमान्त-लागत-सम्बन्धी निम्नलिखित विशेषताओं को पाते हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है।

(1) सीमान्त लागत का स्थायी लागत (Fixed Cost) से कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थायी लागत में कोई वृद्धि नहीं होती। सीमान्त लागत का सम्बन्ध कुल लागत में वृद्धि से है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने पर कुल लागत में वृद्धि होती है।

(2) एक ही सीमान्त लागत का सम्बन्ध कुल परिवर्तनशील लागत (Total Variable Cost) तथा कुल लागत में होता है। इसका कारण यह है कि कुल परिवर्तनशील लागत की अपेक्षा कुल लागत में वृद्धि स्थायी लागत में वृद्धि के द्वारा होती है। परन्तु इस वृद्धि के द्वारा सीमान्त लागत में वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप

उत्पादन की इकाई में वृद्धि के साथ जब कुल लागत में वृद्धि होती है, तब यह वृद्धि परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। अतः सीमान्त लागत कुल प्रमुख लागत तथा कुल लागत के आकार पर निर्भर करती है।

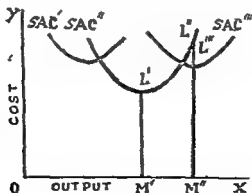
(3) सीमान्त लागत और औसत प्रमुख लागत तथा औसत कुल लागत का सम्बन्ध भी स्पष्ट है। इसमें प्रमुख सम्बन्ध यह है कि जब  $MC$  (Marginal Cost)  $AVC$  (Average Variable cost) तथा  $ATC$  (Average Total Cost) से कम रहती है, तो अन्तिम दो ( $AVC$  तथा  $ATC$ ) को अक्ष करने वाली रेखाएँ नीचे की ओर गिरती हैं, तथा जब  $MC$ ,  $AVC$  और  $ATC$  से अधिक रहनी है तो  $AVC$  और  $ATC$  रेखाएँ ऊपर की ओर उठती हैं।

### 3 दीर्घकाल में लागत (Costs in the long run)

अल्पकालीन लागतों के अध्ययन के पश्चात् अब हम दीर्घकाल के संदर्भ में लागतों का अध्ययन करेंगे। फर्म अल्पकालीन लागतों पर विशेष ध्यान देती हैं, क्योंकि फर्मों के आर्थिक कार्य मुख्यतः अल्पकाल से सम्बन्धित होते हैं। कीन्स ने कहा है कि 'दीर्घकाल' में हम सभी मर जाएंगे (In the long run, we will all be dead)। फिर भी उत्पादक व्यवस्था की आशाओं तथा सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर ही निर्णय लेता है (विशेषतः फर्म के आकार के सम्बन्ध में)। इस प्रकार यदि अल्पकाल का सम्बन्ध आर्थिक कार्यों (Economic actions) से है, तो दीर्घकाल का सम्बन्ध आर्थिक निर्णयों (Decisions) से है। अतः यहाँ पर 'दीर्घकाल में लागतों' का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा।

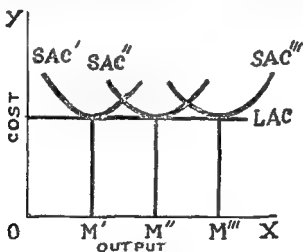
#### 1. दीर्घकालीन औसत लागत वक्र (Long Run Average Cost Curves) :

दीर्घकाल में फर्म के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादक विभिन्न मानाओं में उत्पादन कर इस बात का पता लगाता है कि उत्पादन की किस



मात्रा पर उत्पादन लागत न्यूनतम होगी। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि दीर्घकाल में उत्पादन के निश्चित साधनों (Fixed factors) में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अतः दीर्घकाल में उत्पादन से सम्बन्धित साधन परिवर्तनशील (Variable) होते हैं। दीर्घकाल की अवधि जितनी ही अधिक लम्बी होगी 'निश्चित लागतें' 'परिवर्तनशील साधनों' में परिवर्तित होती जाएंगी। दीर्घकाल में उत्पादन-साधनों के अपेक्षित संयोग से उत्पादन करना सम्भव होता है, अर्थात् 'उत्पादन मान' (Scale of Production) में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा में जितनी बार परिवर्तन किया जाएगा, उतनी ही बार फर्म के लिए नए अल्पकालीन लागत-वक्र प्राप्त होंगे। देखा चित्र सं० 54 इस तथ्य को स्पष्ट करता है :

चित्र में फर्म का अल्पकालीन लागत वक्र  $SAC''$  है,  $M'L'$  लागत पर उत्पादन की अनुकूलतम मात्रा  $OM'$  है। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर  $OM'$  कर दी जाए (अल्प काल) तो औसत लागत  $M''L''$  होगी ( $SAC''$  लागत-वक्र पर)। (इसका कारण यह है कि अल्पकाल में उत्पादन मान निश्चित है, तथा प्लाट आदि की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है)। परन्तु दीर्घकाल में प्लाट आदि की



चित्र सं० 54

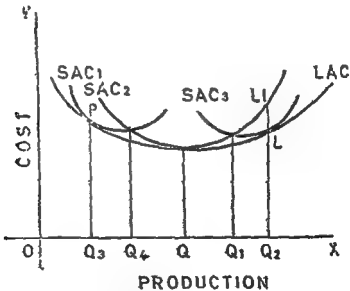
संख्या तथा क्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः उत्पादन-मान बढ़ाने पर नया अल्पकालीन औसत वक्र  $SAC''$  प्राप्त होगा ( $OM''$  मात्रा में उत्पादन के लिए)। अब  $OM''$  अनुकूलतम उत्पादन पर लागत  $M''L''$  होगी। (फर्म के आकार में परिवर्तन करने से लागत  $M''L''$  से घटकर  $M''L''$  हो जाएगी) अतः स्पष्ट है कि विभिन्न उत्पादन मानों पर फर्म को बढ़ती हुई तथा घटती हुई लागतें



का सामना करना पड़ेगा। दीर्घकाल में फर्म के आकार में परिवर्तन के कारण औसत लागत कम होगी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल में औसत लागत में परिवर्तन होता रहता है। यह सम्भव है कि दीर्घकाल में उत्पादन समता नियम (Constant Returns) के अनुसार उत्पादन हो, अर्थात् विभिन्न मात्राओं में उत्पादन के लिए प्लांट के आकार में परिवर्तन किया जाए तथा इस परिवर्तन के फल-स्वरूप, औसत लागत समान रहे।

चित्र सं० 55 में उपरोक्त तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है  $SAC'$ ,  $SAC''$ , तथा  $SAC'''$  अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से इन लागत वक्रों पर उत्पादन की मात्राएँ क्रमशः  $OM'$ ,  $OM''$  तथा  $OM'''$  हैं। तीनों अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की स्पर्श रेखा (Tangent) खींचने पर 'दीर्घकालीन औसत लागत वक्र' LAC प्राप्त होता है। यह एक सीधी रेखा है, जो यह प्रकट करती है कि उत्पादन-मान में परिवर्तन करने से औसत लागत में परिवर्तन नहीं होगा।

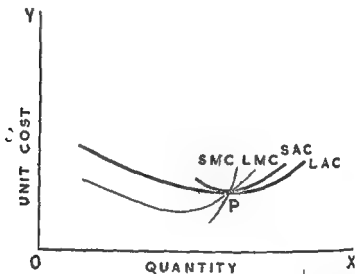


चित्र सं० 55

परन्तु औसत लागत को सदैव समान मान लेना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। व्यवहार में उत्पादन-साधनों की लागतों में परिवर्तन (variation) होता रहता है। अतः 'दीर्घकालीन औसत लागत वक्र' को एक सीधी रेखा मान लेना कारी कल्पना मात्र है, अर्थात् 'अल्पकालीन औसत लागत वक्रों' की स्पर्श-रेखाएँ एक सीध

प नहीं हो सकती है। 'दीर्घकालीन औसत लागत वक्र' भी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की भांति U के सदृश होगा। रेखा चित्र स० 56 में 'अल्पकालीन औसत लागत वक्रों ( $SAC_1, SAC_2, SAC_3$ ) की एक स्पर्श रेखा (सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के निम्नतम बिन्दुओं को स्पर्श करती हुई) खींची गई है, इस प्रकार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC बनता है।

चित्र से स्पष्ट है कि  $SAC_1, SAC_2$ , तथा  $SAC_3$ , अल्पकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न उत्पादन मान की प्रवस्थाओं को प्रकट करते हैं।  $OQ_3, OQ_2$  तथा  $OQ_1$  मात्राएँ विभिन्न औसत लागतों पर पैदा की जा रही हैं।  $OQ_3$  मात्रा निम्नतम लागत पर पैदा की जा रही है। ये तीनों मात्राएँ 'दीर्घकालीन औसत लागत वक्र' (LAC) पर भी हैं। उत्पादन-मान में परिवर्तन करने से, तीनों प्रवस्थाएँ



चित्र स० 56

पाई गई हैं जो तीनों अल्पकालीन औसत लागत वक्रों द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। चित्र स० 56 से स्पष्ट है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की भांति U की श्रृंखला का है, परन्तु इसका फैलाव अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को 'Envelope Curve' भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी 'अल्पकालीन औसत लागत वक्रों' को प्रपन में समाहित कर लेता है। 'दीर्घकालीन औसत लागत' को ये विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं -

(i) दीर्घकालीन औसत लागत कभी भी अल्पकालीन औसत लागत से अधिक नहीं हो सकती है, (ii) दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन

प्रोपत लागत वक्रों को कभी भी काटता नहीं है, (iii) दीर्घकालीन औपत लागत वक्र का न्यूनतम बिन्दु निम्नतम लागत तथा फर्म के अनुकूलतम आकार को प्रकट करता है।

## 2. दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र (Long-run Marginal Cost Curve) :

‘दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र’ तथा ‘अल्पकालीन सीमान्त लागत वक्र’ में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। अल्पकाल में, कुल परिवर्तनशील लागत (AVC) की परिवर्तित मात्रा में उत्पादन की परिवर्तित मात्रा से माप देने पर सीमान्त लागत ज्ञात की जाती है। परन्तु दीर्घकाल में ‘निरिश्चित लागत’ तथा ‘परिवर्तनशील लागत’ का भेद समाप्त हो जाता है। अतः दीर्घकाल में सीमान्त लागत उत्पादन की मात्रा में एक इकाई वृद्धि करने से, कुल लागत में हुई वृद्धि के बराबर होती है। दीर्घकाल में भी औपत लागत तथा सीमान्त लागत में वही सम्बन्ध रहते हैं जो अल्पकाल में होते हैं। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र—दोनों U शक्ल के होते हैं। दीर्घकालीन औपत लागत के निम्नतम बिन्दु पर, दीर्घकालीन सीमान्त लागत, औपत लागत के बराबर होती है। इस निम्नतम बिन्दु पर दीर्घकालीन औपत लागत, अल्पकालीन औपत लागत, दीर्घकालीन सीमान्त लागत तथा अल्पकालीन सीमान्त लागत—सभी बराबर होती हैं। बिन्दु सं० 56 इस तथ्य को प्रकट करता है।

चित्र से स्पष्ट है कि बिन्दु P पर अल्पकालीन, व दीर्घकालीन सीमान्त तथा औपत लागतें समान हैं।

### प्रश्न व सकेत

1 लागतों की प्रकृति की सन्क्षेप में व्याख्या कीजिए तथा दिखनाइए कि अल्प काल में औपत लागत, सीमान्त लागत, औपत आय तथा सीमान्त आय का व्यवहार कैसा होता है ?

(Sagar B Com Part I, 1964)

[सकेत प्रथम भाग में लागतों की प्रकृति समझने के लिए मौद्रिक लागत, तथा सन्क्षेप में परिवर्तनशील और स्थिर लागतों का आशय स्पष्ट कीजिए। द्वितीय भाग में औपत लागत, सीमान्त लागत तथा औपत आय तथा सीमान्त आय का अर्थ बतनाइए और अल्प काल में इनकी रेखाओं के आकार का स्पष्टीकरण कीजिए।]

2 एक फर्म के औपत तथा सीमान्त आगमों के बीच अन्तर बताइए। पूर्ण प्रतिप्रोशिता के अन्तर्गत इनका वस्तु के मूल्य से क्या सम्बन्ध होता है ?

(Agra B A., II 1960)

[सकेत . मर्व प्रथम औपत तथा सीमान्त आय का आशय रेखाचित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद समझाइए कि पूर्ण प्रतिप्रोशिता में औपत आय सीमान्त आय के बराबर होती है।]

3. वास्तविक लागत तथा अवसर लागत में अन्तर बताइए तथा अवसर लागत के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

(Raj, T. D. C Com., 1967; Agra, B. Com. I, 1960)

[सकेत : सर्व प्रथम प्रतिष्ठावादी ग्रंथशास्त्रियों के वास्तविक लागत के विचार को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसकी कमियां बताते हुए प्राधुनिक ग्रंथशास्त्रियों के विचार बताइए। इसके पश्चात् अवसर लागत का आशय स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व और सीमाओं का विवेचन कीजिए।

### समस्याएँ (Problems)

1 निम्न में से बताइए कि अल्पकाल में ये निश्चित लागतें होगी या परिवर्तनशील लागतें होगी—

(i) बिक्री कर (ii) सम्पत्ति कर (iii) कारखाने का किराया (iv) प्रतिरिक्त वस्तुएं खरीदने हेतु लिये गये ऋण पर व्याज (v) अग्नि बीमा (vi) माल की विक्रय लागत (vii) कम्पनी के अध्यक्ष का वेतन

2 एक फर्म के किसी विशेष प्लान्ट पर 4000 रुपये प्रतिदिन स्थायी लागत आती है। कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों पर (प्रतिदिन) इस प्रकार है—

उत्पादन इकाइयाँ	परिवर्तनशील लागत	उत्पादन इकाइयाँ	परिवर्तनशील लागत
1	2000 रु०	6	4000 रु०
2	2500 रु०	7	4500 रु०
3	2750 रु०	8	5500 रु०
4	3000 रु०	9	7500 रु०
5	3500 रु०	10	15000 रु०

उपरोक्त से औसत स्थायी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमान्त लागत निश्चित कीजिए और उन्हें ग्राफ पर चित्रित कीजिए।

3 एक फर्म में परिवर्तनशील उत्पादन साधनों जिनकी लागत 50 रु० प्रति इकाई है, अतिरिक्त इकाइयां लगाने पर उत्पादन मात्रा में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है—

उत्पादन साधन की इकाई	कुल उत्पादन	उत्पादन साधन की इकाई	कुल उत्पादन
1	8	5	60
2	20	6	63
3	45	7	64
4	54		

उपरोक्त सूचना के आधार पर उत्पादन की प्रति इकाई औसत परिवर्तनशील लागत निश्चित कीजिए।

# 22

## पूर्ति अथवा संभरण (Supply)

*"The behaviour of producers (businessmen) in making available quantities of want-satisfying goods and services assumes a vital economic significance."*

—A. L. Gifford

### 1. पूर्ति का अर्थ (Meaning of Supply)

पूर्ति का अर्थ किसी वस्तु अथवा सेवा की उस मात्रा से है जो उत्पादकों द्वारा एक समय विशेष में विभिन्न मूल्यों पर बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। Meyers के अनुसार, "हम पूर्ति को किसी वस्तु की उन मात्राओं की सूची के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो किसी समय विशेष पर अथवा किसी अवधि-विशेष; जैसे एक दिन, एक सप्ताह आदि में, जिसमें पूर्ति की दशाएँ व्यापक रहती हैं, सभी सम्भव मूल्यों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएँगी।"<sup>1</sup>

पूर्ति की उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि माग की गयी मात्रा की तरह पूर्ति की मात्रा भी मूल्य का फलन (function) है। माग की तरह यह भी समय तथा मूल्य के साथ परिवर्तित होती है। वस्तुतः पूर्ति माल के स्टॉक से भिन्न है। पूर्ति का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो बाजार में बिक्री के लिए वास्तव में लायी जाती है, परन्तु स्टॉक का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जो बिक्री के लिए उत्पादकों की सूचना पर बाजार में प्रस्तुत की जा सकती है।

<sup>1</sup> "We may define supply as a schedule of the amount of a goods that would be offered for sale at all possible prices at any one instant of time, or during any one period of time, for example a day, a week and so on, in which the conditions of supply remain the same."

—Meyers

## 2 पूर्ति का नियम (The Law of Supply)

माग के सामान्य नियम की तरह पूर्ति का सामान्य नियम भी वस्तु तथा पैसा की मात्रा तथा उसके मूल्य के फलनीय सम्बन्ध (functional relationship) का प्रकट करता है। माग तथा पूर्ति के सामान्य नियमों में आधारभूत अन्तर यह है कि जबकि मूल्य कम होने पर माग की मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति की मात्रा मूल्य में वृद्धि होने पर बढ़ती है। इस प्रकार पूर्ति का सामान्य नियम यह बतलाता है कि मूल्य अधिक होने पर पूर्ति की मात्रा अधिक होगी, तथा मूल्य कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम होगी।

पूर्ति का नियम मूल्य तथा मात्रा के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध (Positive Relation) निर्धारित करता है। इसका कारण यह है कि किसी वस्तु की पूर्ति उस मूल्य पर निर्भर है जो उत्पादक उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादकों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन किए जाने पर उत्पादन-लागत बढ़ती है (सामान्यतः)। अतः अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही उत्पादक अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। यदि मूल्य में वृद्धि होती है, तो उत्पादन अधिक लाभकारी होता है और पूर्ति में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मूल्य में कमी होती है तो अनिश्चित उत्पादन-लागत न मिलने के कारण उत्पादन-मात्रा कम हो जाती है, जिनके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में भी कमी आ जाती है।

### 3. पूर्ति के निर्धारक तत्व (Determinants of Supply)

लिप्से (Lipsey)<sup>1</sup> के अनुसार किसी वस्तु की वह मात्रा, जिसका उत्पादक उत्पादन तथा विक्रय करना चाहेंगे, निम्नलिखित बातों पर निर्भर है :

(1) वस्तु विशेष के मूल्य का प्रभाव : अन्य बातों के समान रहने पर, किसी वस्तु का मूल्य जितना ही अधिक होगा, उस वस्तु का उत्पादन उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। अतः मूल्य अधिक होने पर पूर्ति भी अधिक होती है।

(2) अन्य वस्तुओं के मूल्यों का प्रभाव : किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं के मूल्यों से प्रभावित होती है। सामान्यतः अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन के लिए पहले की तरह प्रोत्साहित नहीं होते जिनके मूल्य में वृद्धि नहीं होती। अतः अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर, किसी ऐसी वस्तु की पूर्ति (जिसका मूल्य अपरिवर्तित है) कम होगी।

(3) उत्पादन-साधनों के मूल्यों का प्रभाव : उत्पादन के किसी साधन के मूल्य में वृद्धि होने पर, यदि वस्तु-विशेष के उत्पादन में उस साधन का अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, तो उस वस्तु की उत्पादन-लागत में अधिक वृद्धि है।

<sup>1</sup> Richard G. Lipsey, *An Introduction to Positive Economics*, pp 58-69.

जाती है। इसके विपरीत यदि उस साधन का प्रयोग कम होता है, तो उत्पादन लागत में कम वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, भूमि के मूल्य में वृद्धि होने पर उसका प्रभाव गेहूँ के उत्पादन पर अधिक पड़ेगा, जबकि मोटर गाड़ियों की उत्पादन-लागत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार उत्पादन के किसी एक साधन का मूल्य-परिवर्तन उत्पादन की विभिन्न दिशाओं की सापेक्ष लाभदायकता (Relative Profitability) में भी परिवर्तन लायेगा। परिणामस्वरूप उत्पादक एक उत्पादन दिशा से किसी अन्य दिशा की ओर अग्रसर हान लगेंगे। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति में भी परिवर्तन हान लगेंगे।

(4) उत्पादन की तकनीकी विधि में परिवर्तन - उत्पादन की वर्तमान विधियों में तकनीकी विकास होने पर, चाहे उत्पादित वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित ही क्यों न रहे, उत्पादक उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा उसे बेचने के लिए प्रेरित हात हैं।

(5) उत्पादकों की रुचियों का प्रभाव - किसी वस्तु की उत्पादन-मात्रा उत्पादकों की रुचियों पर निर्भर है। यदि उत्पादक किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन में ही विशेष रुचि लेते हैं तथा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के प्रति अनिच्छुक होते हैं, तो यह स्वभाविक है कि उत्पादकों द्वारा प्रथम वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जायगा।

#### 4 पूर्ति की सूची (Supply Schedule)

एक ऐसी तालिका, जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को व्यक्त करती है, पूर्ति की सूची कहलाती है। इस सूची का निर्माण करते समय यह मान लिया जाता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व अपरिवर्तित रहते हैं। यदि इस प्रकार की तालिका एक विक्रेता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्राओं से तैयार की जाती है, तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति सूची (Individual's Supply Schedule) कहा जाता है। किसी वस्तु बाजार में विभिन्न उत्पादक विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गयी मात्राओं के योग से तैयार की गयी तालिका बाजार की पूर्ति-सूची (Supply Schedule of the Market) कहलाती है। एक व्यक्तिगत पूर्ति सूची नीचे दी जा रही है :

##### पूर्ति सूची

मूल्य (प्रति इकाई) र०	पूर्ति (अतिरिक्त विक्रेता द्वारा) इकाइयाँ	समस्त विक्रेताओं द्वारा
6	12	1,200
5	10	1,000
4	■	800
3	6	600
2	4	400
1	2	200

उपयुक्त सूची में स्पष्ट है कि जब प्रति इकाई मूल्य ४ रु० है तो व्यक्ति उत्पादक अथवा बिजनेस बाजार में 12 इकाया बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। बाजार-पूति को व्यक्त करने वाले खाने (Column 3) को देखने पर भी यह स्पष्ट है कि अधिनतम मूल्य (6 रु०) पर अधिकतम उत्पादक अधिकतम मात्रा में (1,200 इकाया) वस्तु की पूति करने हैं। इनमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे उत्पादक जो अभी तक इस वस्तु विशेष के उत्पादन में सलग्न नहीं थे, अब लाभ प्राप्त करने की भाशा में उनके उत्पादन एवं पूति में सलग्न हो गए हैं। उपयुक्त सूची से यह ज्ञात होता है कि मूल्य के गिरने पर पूति की मात्रा घटती जाती है। मरा ठक कि जब मूल्य घटकर 1 रुपया हो जाता है तब पूति की मात्रा ग्यूनतम, अर्थात् 2 अथवा 200 इकाया, ही रह जाती है। इसका अर्थ यह है कि बहुत से उत्पादक इस मूल्य पर अपने उत्पादन व्यय को पूति करने में भी असमर्थ हैं। अतः उन्होंने इस वस्तु विशेष का उत्पादन करना त्यागित कर दिया है, जिससे बाजार से उस वस्तु की मात्रा कम हो गयी है।

### 5 पूर्ति-वक्र (Supply Curve)

पूति के मध्य निर्धारक तत्वों के समान रहने पर, मूल्य और पूति की मात्रा के मध्य सम्बन्ध को प्रदर्शित करने वाला वक्र पूति वक्र कहलाता है।<sup>4</sup> समुच्चयन के अनुसार, 'पूति सूची' या 'वक्र' का तात्पर्य उस सम्बन्ध से है जो बाजार मूल्य तथा उन मात्राओं के, जिनकी पूति उत्पादक करने के लिए तत्पर हैं, मध्य होता है।<sup>5</sup> पूति सूची संश्लेषणों को रेखाचित्र में प्रकट करने पर पूति-वक्र SS पृष्ठ 421 पर निरूपण के अनुसार होगा। OX-अक्ष वस्तु की मात्राएं तथा OY-अक्ष प्रति इकाई मूल्य व्यक्त करता है। पूति-वक्र को देखने पर ज्ञात होता है कि सामान्यतः उसका ढाल (slope) ऊपर की ओर दक्षिण पश्चिम में उत्तर-पूर्व की दिशा में बढ़ता है (normally rises upward and to the right, from south west to north east)। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे वस्तु की प्रति इकाई (Quantity) के बाजार मूल्य में वृद्धि होती जाती है, उत्पादक बैसे-बैसे पूति की मात्राओं की बढ़ावा जाता है। एक रुपया प्रति इकाई मूल्य पर वह केवल वस्तु की दो इकाया बेचने के लिए तत्पर होता है, परन्तु जब बाजार-मूल्य 4, 5 अथवा ६ रुपया प्रति इकाई हो

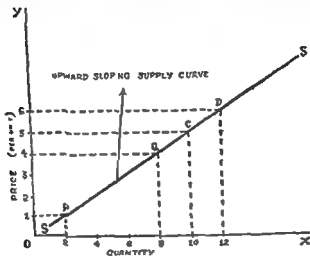
4 "The supply curve shows the relationship between price and quantity supplied under the assumption that the other determinants of supply are constant."  
—Ferguson Kreps

5 "By the supply schedule or curve is meant the relation between market prices and the amounts that producers are willing to supply."  
—Samuelson



जाता है तब वह बाजार में क्रमशः 8, 10 या 12 इकाइया प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होगा है।

व्यक्तिगत उत्पादक फर्म का पूति वक्र यह प्रदर्शित करता है कि वह विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मागाए बेचने के लिए तत्पर है। बाजार पूर्ति वक्र (Market Supply Curve or Supply Curve of an industry) यह प्रदर्शित



चित्र सं० 57

करता है कि विभिन्न मूल्यों पर किसी उद्योग में लगी उत्पादक फर्मों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गयी वस्तुओं की कुल मागाए क्या होगी। दोनों ही स्थितियों में, यदि बाजार मूल्य के अतिरिक्त पूति के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे, तो पूति-वक्र समान स्वरूप वाले होने हैं।

### 6 पूति तथा माग वक्रों का पारस्परिक सम्बन्ध

पूति मूल्य उत्पादन लागत पर आधारित है। कोई भी उत्पादक सामान्यतः इस लागत से कम मूल्य पर अपनी वस्तु बिक्री के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार प्रत्येक उत्पादक एक आरक्षित मूल्य (Reserve Price) निश्चित कर लेता है, जिसको निर्धारित करते समय उत्पादक वस्तु की प्रकृति—नाशवान अथवा स्थायी, भविष्य की लागतों, वस्तुओं के परिवहन व्यय, उनको सफा करने का व्यय, अपनी तरलता-असन्धशी (वस्तु को शीघ्र बेच कर नकद धनराशि में परिवर्तित करने की इच्छा) आदि तन्त्रों को ध्यान में रखता है। यदि वह आरक्षित मूल्य के स्थान पर उत्पादन लागत पर ही वस्तु की पूति करने के लिए तत्पर हो जाता है, तो पूति-वक्र को लागत वक्र कहा जा सकता है। परन्तु यदि उत्पादक आरक्षित मूल्य पर ही वस्तु की पूति करना चाहे, तो लागत वक्र और पूति-वक्र भिन्न होय। इसीलिए यह

कहा जाता है कि एक दृष्टि से प्रत्येक पूर्ति-वक्र लागत-वक्र है, किन्तु प्रत्येक लागत-वक्र पूर्ति वक्र नहीं है।

## 7 पूर्ति पर अवधि का प्रभाव (The effect of time upon supply) :

किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा पर उसकी उत्पादन-अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ :

(i) अल्पतम अवधि में (Very Short Period) : अल्पतम अवधि में, माग में चाहे जितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाय, पूर्ति की निश्चित मात्रा में वृद्धि सम्भव नहीं है, जैसे बाजार में मछली की माग में अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर भी उसकी पूर्ति नहीं बढ़ायी जा सकती।

(ii) अल्प अवधि में (Short Period) : अल्प अवधि में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन विस्तार प्रथवा संकुचन सम्भव है। इस अवधि में यद्यपि उत्पादन के स्थायी साधनों में विस्तार सम्भव नहीं है, फिर भी परिवर्तनशील साधनों (Variable Factors) में वृद्धि करके वर्तमान मयत्र (Plant) की उत्पादन-क्षमता का प्रयोग कर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि सम्भव हो पाती है। परिवर्तनशील साधनों की प्रतिरिक्त इकाइयाँ लगाने के कारण उत्पादन-लागत बढ़ जाती है, जिससे पूर्ति-मूल्य भी अधिक हो जाता है।

वास्तविकता तो यह है कि किसी दिए गए समय में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन कई उत्पादनकारी इकाइयों (Producing units) द्वारा किया जाता है। ये इकाइयाँ समान रूप से उत्पादन-कार्य में जुड़ती नहीं होती। समान मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पादनकारी इकाइयों द्वारा उत्पादन-साधनों पर किए जाने वाले कुल व्यय की घनराशियाँ भी अलग-अलग होती हैं। उत्पादन-लागत भिन्न होने के कारण ही प्रति इकाई औसत कुल लागत तथा सीमान्त लागत भी भिन्न होती हैं। उत्पादन मूल्य (product price) कम होने पर अकुशल इकाइयाँ उत्पादन करना बन्द कर देती हैं, क्योंकि मूल्य सीमान्त लागत के मूल्य अधिक होने पर अकुशल इकाइयाँ भी अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करने में समर्थ हो पाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कुल उत्पादन तथा जिसके लिए प्रस्तुत की गयी उत्पादन की मात्रा और उत्पादन-मूल्य में परिवर्तनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। पूर्ति का नियम भी इसी तथ्य का स्रोत है, क्योंकि यह स्थिति सामान्यतया अलावधि पूर्ति के सम्बन्ध में पायी जाती है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अल्प-अवधि में कुल पूर्ति में विस्तार उभी समय सम्भव हो सकता है जबकि प्रत्येक फर्म अविवर्तमान लाभ की माग में

अपनी उत्पादन-मात्रा का विस्तार करे। यही कारण है कि अल्प-अवधि में व्यक्तिगत फर्म का सीमान्त लागत वक्र (marginal cost curve) उसका पूर्ति वक्र (supply curve) भी होता है। अतः सम्पूर्ण उद्योग-विवेचन के अल्पावधि पूर्ति-वक्र (short-run supply-curve) उद्योग में सलग्न समस्त फर्मों द्वारा प्रत्येक सीमान्त-लागत पर वस्तु की उत्पादन मात्राओं को जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः पूर्ति वक्र के सम्बन्ध में यह स्थिति अल्प अवधि तथा पूर्ण स्पर्धा में पायी जाती है, क्योंकि लाभ में अधिकतम वृद्धि के अन्तर्गत यह सिद्धान्त निहित है कि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर होती है। चूँकि एक पूर्ण-प्रतिस्पर्धी फर्म (perfectly competitive firm) को असीमित लोचदार मांग-वक्र (infinitely elastic demand curve) के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित करना पड़ता है, सीमान्त आय बाजार-मूल्य के बराबर होती है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करनी है, तो सीमान्त लागत भी मूल्य के बराबर होगी।

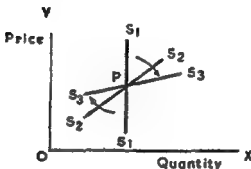
(ii) दीर्घ अवधि में (in the long run) : दीर्घ अवधि में उत्पादन-मान (scale of production) में परिवर्तन करना सम्भव होता है। मितव्ययिताओं प्रथवा अमितव्ययिताओं के कारण पूर्ति-मूल्य ह्रासमान (decreasing), वृद्धिमान (increasing) या समान (constant) हो सकता है। निर्माणकारी उद्योगों को आन्तरिक तथा बाह्य मितव्ययिताओं की सुविधाएं उत्पादन-मात्रा में विस्तार के कारण प्राप्त होती हैं। ऐसे उद्योगों के दीर्घकालीन पूर्ति-वक्र का झुकाव दायी ओर नीचे की तरफ होगा। कृषि-उद्योग में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने पर अनेक अमितव्ययिताओं के कारण पूर्ति-वक्र का झुकाव ऊपर की ओर दायी तरफ होगा। कुछ अन्य उद्योगों में मितव्ययिताओं तथा अमितव्ययिताओं के संतुलित हो जाने पर उनका पूर्ति-वक्र उत्पाद अक्ष (Output-axis) के समानान्तर होगा।

दीर्घकाल में उद्योग में सलग्न फर्म उत्पाद की मांग को पूर्ति करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत रूप में अपने उत्पादन-मान तथा उपकरणों में वृद्धि करती हैं। यदि वस्तु का बाजार मूल्य अधिक होता है तो नयी फर्म उस उद्योग में प्रवेश करती हैं। विपरीत स्थिति में अर्थात् बाजार-मूल्य कम होने पर, कई फर्म उत्पादन-कार्य स्थगित कर देती हैं। वस्तुतः दीर्घकाल के पूर्ति-वक्र का आकार फर्मों की संरचना में आवश्यक समायोजनाओं के पश्चात् लागत परिवर्तनों पर निर्भर है।

चित्र संख्या 58, विभिन्न अवधि में पूर्ति-रेखा का स्वरूप प्रकट करता है। अवधि जितनी ही लम्बी होगी, पूर्ति उतनी ही लोचदार होगी (1) चित्र में  $S_1$ , पूर्ति रेखा पूर्णतया लोचदार है जो अत्यन्त ही अल्प-काल (Very short-period) में सम्बन्धित है।

ऐसी दशा में कीमत में वृद्धि होने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ेगी । (ii)  $S_2 S_2$  पूर्ति-रेखा अल्पकाल (Short Period) से सम्बन्धित है । कीमत में वृद्धि होने पर, पूर्ति में वृद्धि होगी । (iii)  $S_3 S_3$  दीर्घकाल (Long Period) से सम्बन्धित है । कीमत में वृद्धि होने पर, दीर्घकाल में पूर्ति में और भी अधिक वृद्धि होगी ।

### Time and Elasticity of Supply



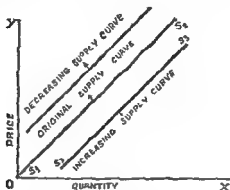
चित्र सं० 58

### 8. पूर्ति में परिवर्तन (Changes in the Supply)

मूल्य-परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तनों को, मूल पूर्ति-वक्र पर ही प्रदर्शित किया जाता है । इसका कारण यह है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से बिना के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा में वृद्धि में होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि हो गई है । इसी प्रकार मूल्य-हास से होने वाली पूर्ति की मात्रा में कमी का अर्थ भी पूर्ति की कमी नहीं है । ये परिवर्तन पूर्ति के नियम में अन्तर्निहित (inherent) हैं । इन परिवर्तनों से केवल यह संकेत मिलता है कि वर्तमान अल्प अवधि की पूर्ति में उत्पत्ति और प्रदाय (offerings) में वृद्धि के कारण विस्तार या संकुचन हुआ है या नहीं ।

वस्तुतः पूर्ति में परिवर्तन उस समय होता है, जब मूल्यों के क्रम में प्रत्येक मूल्य पर वस्तु की प्रस्तुत की गई मात्राएं आगे या पीछे की ओर सरक जाती हैं । जब दिए हुए मूल्यों पर अपेक्षाकृत अधिक मात्राएं अथवा दो हुई मात्राएं अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर प्रस्तुत की जाती हैं, तब पूर्ति बढ़ जाती है । जब दिये हुए मूल्यों पर अपेक्षाकृत कम मात्राएं अथवा दो हुयी मात्राएं अपेक्षाकृत अधिक मूल्यों पर प्रस्तुत की जाती हैं, तब पूर्ति घट जाती है । इन परिवर्तनों को नयी पूर्ति-वृत्ति तथा नए पूर्ति वक्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है । पृष्ठ 425, के चित्र में  $S_1 S_1$  मूल पूर्ति वक्र (Original Supply Curve) है । पूर्ति में वृद्धि होने पर यह दायी ओर

विचलित (shift) होकर,  $S_3$   $S_2$  की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तथा पूति की कमी (decrease) होने पर यह स्थिति मूल-वक्र  $S_1$   $S_2$  की बायी ओर एक नये वक्र  $S_2$   $S_2$  रूप में निर्मित होता है।



चित्र सं० 59

पूति में परिवर्तन के कारण . पूति में वास्तविक परिवर्तन, जिनके फलस्वरूप पूति-सूची तथा पूति-वक्र में भी परिवर्तन होते हैं, दीर्घ-अवधि में ही होते हैं, क्योंकि एक सम्भी अवधि में ही नयी उत्पादन-साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं। उत्पादक को वर्तमान सयन्त्रों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने का समय मिल जाता है। दीर्घ अवधि में ही उत्पादकों को अप्रचलित तथा प्रकुशल सयन्त्रों को हटाने तथा समाप्त करने का अवसर मिलता है। पूति में परिवर्तन होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) तकनीकी परिवर्तन (Technological changes) उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी विकास होने से पूति कई प्रकार से प्रभावित होती है : (i) इसके द्वारा पुरानी वस्तु की अपेक्षा एक अच्छी नयी वस्तु का उत्पादन होने से, पुरानी वस्तु की तुलना में नयी वस्तु की माग तथा तदनुसार पूति में वृद्धि हो जाती है, (ii) किसी वस्तु के उत्पादन की तकनीक में विकास एवं सुधार होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पादकों को दिये हुए मूल्यों पर पहले की अपेक्षा पूति की मात्राओं में घटिक वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिलता है।

(2) युद्ध (War) तथा अन्य दैवी आपत्तियाँ (Other Natural Calamities) : युद्ध-काल में अर्थ-व्यवस्था सैनिक सेवाओं तथा युद्ध सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन पर केन्द्रित हो जाती है। फलस्वरूप उपभोग-सामग्रियों तथा सेवाओं की पूति कम हो जाती है। दैवी आपत्तियों, जैसे अनावृष्टि, अग्निवृष्टि, बाढ़ आदि के फलस्वरूप भी उत्पादन-मात्रा कम हो जाती है।

(3) प्राकृतिक साधनों का ह्रास अथवा उनकी खोज (Depletion or Discovery of Natural Resources) नए प्राकृतिक व भौतिक साधनों की खोज के कम मूल्य पर उनके सुलभ होने से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत कम होती है जिससे इन वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत प्राकृतिक साधनों के नष्ट हो जाने पर पूर्ति कम हो जाती है।

(4) उत्पादन साधनों के मूल्यों में वृद्धि उत्पादन साधनों के मूल्यों में वृद्धि होने पर उत्पादन के साधनों की पड़त (resource inputs) महंगी पड़ती है जिसके फलस्वरूप वस्तु की प्रति इकाई लागत भी बढ़ जाती है। मूल्य के वयावृद्ध होने पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है।

(5) सरकार की कर तथा व्यापारिक नीतियाँ यदि सरकार उत्पादकों तथा व्यवसायियों पर कई प्रकार के कर तथा प्रतिबंध लगाती है तो निश्चय ही सम्बंधित वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जायेगी। किसी वस्तु पर आयात कर में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति कम हो जायेगी।

(6) परिवहन एवं सन्देश वहन के साधनों में विकास इन साधनों में विकास होने पर बाजार का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है जिससे न केवल आयात में ही वृद्धि होती है बल्कि उत्पादकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है।

### 9 पूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)

(1) अथ पूर्ति का नियम किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के प्रति उसके (उस वस्तु के) उत्पादक की प्रतिक्रिया की दशा को स्पष्टतः बतलाता है। अधिक मूल्यों पर अधिक उत्पादन तथा कम मूल्यों पर कम उत्पादन किया जाता है। परन्तु पूर्ति का नियम उत्पादक की प्रतिक्रिया के अंश या सीमा (degree) को व्यक्त नहीं करता। अतः पूर्ति की लोच यह बात कराती है कि अधिक मूल्य पर कितनी अधिक मात्रा अथवा कम मूल्य पर कितनी कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

(2) लोच की किस्में पूर्ति की लोच पाँच प्रकार की हो सकती हैं

1 इकाई लोच या सम लोच (unit elasticity) पूर्ति की इकाई लोच (unit elasticity) उस समय होती है जब किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तन होने पर उत्पादित तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा में परिवर्तन प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। सम लोच उत्पादक की अनुप्रियाशीलता की लोचदार (elastic) तथा वेलोच (inelastic) अथवा एव सीमाओं (degree) की विभाजन रेखा है।

2 लोचदार पूर्ति (Elastic Supply) पूर्ति उस समय लोचदार होती है जब अधिक मूल्य परिवर्तन के कारण उत्पादक की अनुप्रियाशीलता सम लोच की पूर्ति वक्र (C) अनुप्रियाशीलता से अधिक होती है अर्थात् जब मूल्य परिवर्तन के कारण

वस्तु की उत्पादित तथा प्रस्तुत की गयी मात्रा में प्रत्यक्ष अनुपाती परिवर्तन अधिक होता है।

3. बेलोच पूर्ति (Inelastic Supply) : जब उत्पादक की अनुकिया-शीलता के अंश में इकाई लोच (unit elasticity) के विपरीत परिवर्तन होता है, तब इसे बेलोच पूर्ति कहते हैं। बेलोच पूर्ति होने पर मूल्य-परिवर्तन के कारण वस्तु की उत्पादित तथा प्रस्तुत की गई मात्रा में प्रत्यक्ष अनुपाती परिवर्तन कम होता है।

4. पूर्णतया लोचदार पूर्ति (Perfectly Elastic Supply) : पूर्ति पूर्णतया लोचदार उस समय होती है, जब वर्तमान मूल्य पर वस्तु की असीमित मात्रा की पूर्ति की जाती है।

5. पूर्णतया बेलोच पूर्ति (Perfectly Inelastic Supply) : जब मूल्य में किसी परिवर्तन का बिक्री के लिए प्रस्तुत की गयी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है।

(iii) पूर्ति की लोच की माप (Measurement of Supply Elasticity) : अर्थशास्त्र में पूर्ति की लोच  $\epsilon$  (e) द्वारा व्यक्त की जाती है। [  $\epsilon$  एक ग्रीक अक्षर है जिसे 'Epsilon' कहा जाता है जो 'पूर्ति की लोच' को व्यक्त करता है ]। पूर्ति की लोच को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र (Formula) का प्रयोग किया जाता है जो पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन की माप करता है।

$$\text{मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन} = \frac{\Delta \phi}{\phi}$$

$$\text{पूर्ति की लोच} = \frac{\text{मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}} = \frac{\frac{\Delta \phi}{\phi}}{\frac{\Delta \sigma}{\sigma}}$$

$$= \frac{\Delta \phi}{\Delta \sigma} \times \frac{\sigma}{\phi}$$

$$\text{लोच} = \left( \frac{\text{मात्राओं में अन्तर}}{\text{मात्राओं का योग}} \right) \left( \frac{\text{मूल्यों का योग}}{\text{मूल्यों में अन्तर}} \right)$$

$$\left[ \epsilon = \left( \frac{\text{difference in quantities}}{\text{sum of quantities}} \right) \left( \frac{\text{sum of prices}}{\text{difference in prices}} \right) \right]$$

इस सूत्र के द्वारा आवश्यक गणना करने पर निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं

(अ) जब  $\epsilon = 1$ , पूर्ति इकाई लोचदार होती है।

(ब) जब  $\epsilon > 1$  (लोच 1 से अधिक होने पर), पूर्ति लोचदार होती है, क्योंकि उत्पादित तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा में मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष अनुपाती परिवर्तन होता है।

(म) जब  $\epsilon < 1$  (लोच 1 से कम होने पर) हो तो पूर्ति बेसोच होती है, क्योंकि उत्पादित तथा विनी के लिये प्रस्तुत की गई मात्रा में मूल्य-परिवर्तन के अनुपात में कम परिवर्तन होता है।

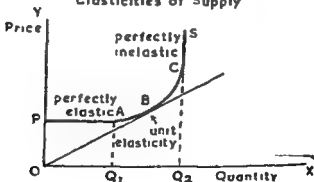
नीचे दी गई तालिका से विभिन्न प्रकार की लोच का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है :

बाजार-पूर्ति-सूची

मूल्य प्रति इकाई ₹०	उत्पादित तथा विनी के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा	लोच
1	50	लोच $\rightarrow \epsilon = 2.3$ $\rightarrow [\epsilon = \frac{350}{50} \times \frac{5}{1} = 2.3]$
2	400	
3	600	$\rightarrow$ समलोच $\rightarrow \epsilon = 1.0$ $[\epsilon = \frac{200}{600} \times \frac{6}{1} = 1.0]$
4	700	
5	775	$\rightarrow$ बेसोच $\rightarrow \epsilon = 43$ $[\epsilon = \frac{50}{775} \times \frac{10}{1} = 43]$
6	825	
7	850	

पूर्ण वक्र भी पूर्ति की लोच में परिवर्तन का व्यक्त करता है। पूर्ति लोचशर होने पर वक्र का ढाल सरल होना है, बेसोच होने पर उसका ढाल सीधा या खड़ा (steep) होता है, परन्तु समलोच होने पर उसका ढाल साधारण होता है।

Elasticities of Supply



चित्र सं० 60

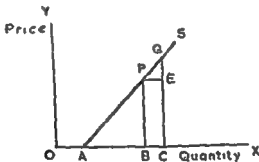
चित्र संख्या 60 में पूर्ति की लोच पर प्रकाश पड़ता है। PS पूर्ति वक्र है, जिसके ढलाव (slopes), अल्पकाल में पूर्ति की लोच को प्रदर्शित करते हैं। इस वक्र



पर विभिन्न प्रकार की लोच सत्याओं में व्यक्त की गई हैं। मांग-रेखा की ही तरह (i) यदि पूर्ति रेखा पड़ी (Horizontal) रेखा के रूप में है तो पूर्ति 'पूर्णतया लोचदार' (ii) यदि पूर्ति रेखा खड़ी रेखा (Vertical) के रूप में है तो पूर्ति 'पूर्णतया बेलोच' है। साधारण ढलान, जैसा AB चाप (Arc) में है, यह प्रकट करता है कि पूर्ति लोचदार है (iii) गहरी-ढलान (steep slope) जैसा कि चाप BC में है, लोचहीनता (inelasticity) को प्रकट करता है। (i) OP से कम कीमत पर, विक्रेता कुछ भी नहीं बेचेंगे। (ii) OP कीमत पर वे  $OQ_1$  मात्रा बेचेंगे (iii)  $OQ_1$  से अधिक मात्रा बेचने के लिए, कीमत OP से अधिक होनी चाहिये। (iv) कीमत कितनी ही ऊँची हो, विक्रेता  $OQ_2$  में अधिक मात्रा नहीं बेचेंगे।

पूर्ति की लोच की ज्यामिति मांग की लोच से कुछ भिन्न होती है : नीचे के चित्र में बिन्दु B पर इकाई-लोच है, इस बिन्दु पर बिन्दु O से खींची गई सीधी रेखा 'Tangent' है। यदि बिन्दु O में रेखा खींची जाये तब यह एक सीधी रेखा के रूप में हो तो पूर्ति वक्र का ढाल कुछ भी हो, उसकी लोच इकाई होगी (पूरी रेखा पर)।

चित्र सख्या 61 में बेलोच पूर्ति वक्र को प्रकट करता है। मान लीजिये पहले कीमत PB है तथा बाद में बढ़ कर कीमत QC हो जाती है। अतः



चित्र सं० 61

पूर्ति की लोच =  $\frac{\text{मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$  या

$$E_s = \frac{BC}{OB} \div \frac{QE}{PB} = \frac{PE}{OB} \times \frac{PB}{QE}$$

अन्तिम अक्षरों को हम  $\frac{PE}{QE} \times \frac{PB}{OB}$  भी लिख सकते हैं। चूँकि PBA तथा QEP

त्रिभुज एक ही प्रकार के हैं, अतः

$$\frac{PE}{QE} = \frac{AB}{PB}, \text{ इसलिए } E_s = \frac{AB}{PB} \times \frac{PB}{OB} = \frac{AB}{OB}$$

चूँकि AB, OB से छोटा है, अतः  $\frac{AB}{OB}$  इकाई (एक) से कम है। इस प्रकार पूर्ति बेलोच है। यदि  $AB=OB$  के हो जिससे  $E=1$  हो तो पूर्ति-वक्र प्रारम्भ बिन्दु O म गुजरना चाहिए। यदि AB, OB से लम्बा है जिससे  $E_s > 1$  तब पूर्ति वक्र मूल्य-अक्ष (Price Axis) को काटेगा।

यदि पूर्ति रेखा एक वक्र (curve) के रूप में है तो पूर्ति वक्र के किसी भी बिन्दु पर लोच ज्ञान करने के लिये, उस बिन्दु पर स्पर्श रेखा (Tangent) खींच कर लोच ज्ञात करते हैं।

(iv) पूर्ति की लोच और अवधि का सम्बन्ध : पूर्ति की लोच की उपर्युक्त व्याख्या अल्प अवधि के सन्दर्भ में की गई है। परन्तु पूर्ति की लोच की माप दीर्घ अवधि के सन्दर्भ में भी की जा सकती है। वस्तुतः दीर्घ अवधि में पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इस अवधि में उत्पादकों को अपने उत्पादन साधनों, सम्पत्ति, उपकरण आदि में परिवर्तन करने के लिये अधिक समय मिल जाता है।

(v) पूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व अल्प अवधि में पूर्ति-लोच का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व वह प्रतिशत है जो 'स्थायी लागत' व 'कुल लागत' का होता है। (fixed cost as a percent of total cost)। यदि सापेक्ष रूप से स्थायी लागत पूर्ण लागत से अधिक होती है तो उत्पादक को हानि पर भी उत्पादन करने का प्रलोभन रहता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन करने से उनकी हानि न्यूनतम हो जाती है। कम मूल्यों से परिवर्तनशील लागतों के अधिकांश भाग की पूर्ति हो जाती है। यदि उत्पादन निरन्तर होता रहता है, तो स्थायी लागतों के कुछ प्रश्न की पूर्ति सम्भव हो जाती है, क्योंकि उत्पादन कार्य स्थगित करने पर स्थायी लागत पूर्ण हानि के रूप में परिवर्तित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्ति के बेलोच होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। यदि स्थायी लागत कुल लागत की तुलना में कम होती है, तो पूर्ति लाचदार होती है।

दीर्घ अवधि में पूर्ति की लोच को निम्नलिखित करने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व हैं

(1) उत्पादन साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के अवसरों का होना (The alternative opportunities available to the productive factors) • यदि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन साधनों के उपयोग के लिये अन्य आकर्षक अवसर वर्तमान होते हैं तो उस वस्तु के मूल्य के कम होने तथा प्राप्त आय में कमी होने पर स्थान परिवर्तित कर देते हैं। वे साधन उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किये जाते हैं, जिसका मूल्य अधिक होता है तथा साधनों के विचलन (shifts) से उनकी

धाय बँट जाती है। अतः किमी वस्तु के उत्पादन साधनों के प्रयोग के जितने अधिक विस्तृत अवसर वतमान रहते हैं, वस्तु की पूर्ति उतनी ही अधिक लोचदार होती है। इस प्रकार के अवसरों में कमी होने पर पूर्ति अधिक बेरोच होती है।

(2) उत्पादन साधनों की गतिशीलता (Mobility of productive factors) : वैकल्पिक प्रयोग के अवसरों के होने के साथ ही साथ उत्पादन साधनों की गतिशील होना भी आवश्यक है। साधनों में जितनी अधिक गतिशीलता होगी, उतनी ही अधिक लोचदार उस वस्तु की पूर्ति होगी जिसके उत्पादन एवं निर्माण में उन साधनों को प्रयुक्त किया जाता है।

### पूर्ति के अन्य प्रकार

(घ) संयुक्त पूर्ति (Joint Supply) सामान्यतः कई वस्तुएँ एक साथ उत्पादित की जाती हैं। किसी एक वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव किमी अन्य वस्तु की पूर्ति पर पड़ना स्वाभाविक है, जैसे कोयल की गैस और कोयला। इस प्रकार की पूर्ति संयुक्त पूर्ति कहलाती है। संयुक्त पूर्ति का दशा में किसी एक वस्तु की माग में वृद्धि होने पर संयुक्त उत्पाद (Joint Product) की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे संयुक्त उत्पाद का मूल्य गिरने लगता है।

(ब) सम्मिश्रित या संप्रयुक्त पूर्ति (Composite Supply) किमी एक माग की पूर्ति कई वस्तुओं की पूर्ति द्वारा की जा सकती है। उदाहरणार्थ चाय काफ़ी दूध आदि की पूर्ति पेय पदार्थों की माग को सन्तुष्ट करने के लिए सम्मिश्रित या संप्रयुक्त पूर्ति कही जायेगी।

### प्रश्न व सकेत

1. पूर्ति की लोच का आशय स्पष्ट कीजिये। पूर्ति की लोच को मापने की विधि बताइये।

[सकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में पूर्ति की लोच का आशय स्पष्ट कीजिये और द्वितीय भाग में इसको मापने की प्रमुख विधियाँ बताइये।]

2. पूर्ति में भाव क्या सम्भक्त है? निम्न में अन्तर स्पष्ट कीजिये—

(घ) 'पूर्ति में वृद्धि' तथा 'पूर्ति में विस्तार' (ब) 'पूर्ति में कमी' तथा 'पूर्ति में संकुचन'।

3. पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिये और इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का स्पष्टीकरण कीजिये।

[सकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिये तथा द्वितीय भाग में इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण कीजिये।]

## समस्याएं (Problems)

1. निम्न तथ्यों के आधार पर अल्पकाल में एक फर्म की पूर्ति सूची तैयार कीजिये—

उत्पादन इकाइया	परिवर्तनशील लागत	उत्पादन इकाइया	परिवर्तनशील लागत
1.	Rs 22	6.	Rs 85
2.	„ 32	7.	„ 11
3.	„ 40	8.	„ 155
4.	„ 50	9.	„ 205
5.	„ 65	10.	„ 310

2. निम्न लागत समको के आधार पर दीर्घकाल में एक उद्योग का पूर्ति-बक बताइये—

उद्योग का कुल उत्पादन (इकाइया)	प्रत्येक फर्म के लिए निम्नतम अधिकतम लागत
1. 5,00,000	Rs. 470
2. 10,00,000	„ 520
3. 15,00,000	„ 550
4. 20,00,000	„ 590
5. 25,00,000	„ 630
6. 30,00,000	„ 660

# 23

## उत्पादन के नियम (Laws of Returns)

---

*'While the part which nature plays in production shows a tendency to diminishing returns the part which man plays show a tendency to increasing returns If the action of the law of increasing and diminishing returns are balanced we have the law of constant returns'*

Marshall

### 1 The Production Function

किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कई साधनों के सहयोग या संयोग (combination) की आवश्यकता पड़ती है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसे हम उत्पाद (out put) तथा जिन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाना है उन्हें हम पदार्थ (Input) कहते हैं। किसी फर्म के उत्पाद तथा पदार्थ के सम्बन्धों की Production Function कहा जाता है। (The production function is the name for the relation between the physical inputs and the physical outputs of a firm) Production Function का वास्तव हम किसी अवधि के समय में करते हैं। (It is a flow of inputs resulting in a flow of outputs during some period of time)

किसी भी फर्म के Production Function का निर्धारण प्राविधिक स्थिति (State of Technology) द्वारा किया जाता है। जब प्राविधिक प्रगति होती है तो नये Production Function का जन्म होता है। सामान्य रूप से पहलू संश्लेषण प्रविधि का प्रयोग करने में, उन्हीं पदार्थों द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। (उत्पादन में कमी भी हो सकती है जैसे भूमि की ख़तरनाक कम हो जाने के कारण भू-पदार्थ (Input) में वृद्धि करने पर भी उत्पादन में कमी हो सकती है) अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकीय विधियाँ द्वारा पदार्थों तथा उत्पाद के सम्बन्धों के परिवर्तन (relations between changes in physical inputs and physical outputs) का व्याव-

हारिक रूप से अध्ययन किया है। इन अध्ययनों में Paul H. Douglas तथा C.W. Cobb द्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रसिद्ध है। इसे Cobb-Douglas Production Function कहते हैं। इसके द्वारा उत्पादन समता नियम पर प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम Production Function में उत्पाद पड़त के दो प्रकार के सम्बन्धों पर ध्यान देते हैं। पहला, यदि कुछ पड़तें (Inputs) स्थिर हैं तथा कुछ पड़तें परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, यदि सभी पड़तें परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर हम उत्पाद तथा पड़त की मात्रा (Physical Quantity) की ही बात करते हैं, उनकी कीमतों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी फर्म के उत्पादन की मात्रा (निश्चित अवधि में) दो बातों पर निर्भर है।

(i) उत्पादन की विधि (Technology) तथा (ii) उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाली पड़तों (Inputs) या साधनों की मात्रा। यदि हम उत्पादन विधि को पूर्ववत् (Constant) मान लें तो उत्पादन मात्रा उत्पादन के साधनों की मात्रा पर निर्भर करेगी। यदि एक या अधिक साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें उत्पत्ति के नियमों (Laws of Returns) द्वारा मिलता है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु यह भी सम्भव है कि उत्पादन में वृद्धि, पड़त (Inputs) प्रत्येक साधनों की वृद्धि के अनुपात में न हो। उत्पत्ति के तीन नियमों का उल्लेख किया जाता है

1. कुछ समय हम यह पाते हैं कि उत्पादन की मात्रा में, साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर, आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होती है। प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसे 'उत्पत्ति ह्रास नियम' या 'लागत वृद्धि नियम' कहते हैं।

2. कभी कभी उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से, कुल उत्पादन में अधिक अनुपात से वृद्धि होती है, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है, इसे 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' या 'लागत ह्रास नियम' कहते हैं।

3. उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर, जब उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तब इसे 'उत्पत्ति समता नियम' या 'लागत समता नियम' कहते हैं।

### 1. उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (Law of Diminishing Returns or Law of Variable Proportions)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की व्याख्या केवल भूमि के सन्दर्भ में की थी, परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस नियम की व्याख्या व्यापक रूप से करते हैं।

अतः हम इस नियम की दो प्रकार की व्याख्याएँ पाते हैं, (1) पुराने अर्थ-

रास्त्रियो द्वारा प्रस्तुत व्याख्या तथा (ii) नियम के विषय में आधुनिक मत । हम यहाँ पर इन दोनों दृष्टिकोणों से इस नियम पर प्रकाश डालेंगे ।

### (1) उत्पत्ति ह्रास नियम की मार्शल द्वारा प्रस्तुत व्याख्या (Marshallian Version of the Law of Diminishing Returns)

I परिभाषा उत्पादन क्रिया में जब उत्पादन साधनों की कमागत इकाइयों द्वारा उत्पादन में वृद्धि होता जाता है तो इसे उत्पादन-ह्रास नियम कहते हैं । मार्शल के अनुसार, “यदि कृषि ज़मीन में कोई सुधार न हो तो सामान्यतः कृषि में प्रयुक्त श्रम और पूँजी की वृद्धि से कुल उत्पादन में वृद्धि आनुपातिक रूप में कम होगी ।”

‘An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the arts of agriculture’ —Marshall

इस परिभाषा का अर्थ यह है कि यदि भूमि के एक टुकड़े पर कृषि उत्पादन के लिए श्रम और पूँजी की मात्राओं में वृद्धि की जाये तो उनकी प्रत्येक वृद्धि की इकाई में प्राप्त सीमान्त उपज, अपने पूर्व की इकाई द्वारा प्राप्त सीमान्त उपज से कम होगी अर्थात् यदि धम तथा पूँजी की मात्रा दुगुनी या तीन गुनी कर दी जाय तो कुल उत्पादन दुगुना या तीन गुना नहीं होगा, बल्कि उत्पादन में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होगी । इस तथ्य का स्पष्टीकरण निम्नलिखित सारणी से किया जा सकता है—

(श्रम की विभिन्न इकाइयों द्वारा उत्पादन मनो में)

भूमि (एकड़)	श्रम की इकाइया	कुल उत्पत्ति Total Product	सीमांत उत्पत्ति Marginal Product	औसत उत्पत्ति Average Product
10	1	100	100	100
10	2	230	130	115
10	3	360	130	120
10	4	480	120	120
10	5	560	80	112
10	6	600	40	100
10	7	620	20	88
10	8	620	0	77.5
10	9	610	-10	68

मान लीजिए हम एकड़ भूमि है। उत्पादन के लिए इस भूमि पर उद्गादन साधन लगाए जाते हैं। भूमि निश्चित मात्रा में है केवल धन व पूँजी ऐसे साधन हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। पहले कॉलम में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइया दूसरे कॉलम में 'कुल उत्पत्ति', तीसरे में 'सीमान्त उत्पत्ति' तथा अन्तिम कॉलम में 'औसत उत्पत्ति' दिखाई गई है।

✓ 2 नियम की अवस्थाएँ (Stages of Law) : उत्पादन ह्रास नियम की तीन अलग अलग अवस्थाएँ हैं, जैसा कि पीछे दी गई सारिणी से प्रकट है :

1. कुल उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Total Diminishing Returns) : सारिणी से स्पष्ट है कि सातवें धमिक तक कुल उत्पादन में कुछ न कुछ वृद्धि होगी है। परन्तु नवें धमिक को लगाने से 'कुल उत्पत्ति' 620 मन से घट कर 610 मन हो जाती है। इस प्रकार नवें धमिक को काम पर लगाना हानिप्रद है। अतः उसी सेवाम्री का उपयोग करना किसान के हित में नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि यदि उत्पादन के एक साधन में वृद्धि की जाए, तो आरम्भ में 'कुल उत्पत्ति' घीरे-घीरे बढ़ती है, परन्तु एक बिन्दु के पश्चात् उस साधन की अधिक इकाइयों को लगाने से 'कुल उत्पादन' भी घटने लगता है। इस अवस्था को 'कुल उत्पत्ति ह्रास नियम' कहते हैं।

2. सीमान्त उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Marginal Returns) : 'सीमान्त उत्पत्ति' तीसरे धमिक तक बढ़ रही है। किसान यह जानता है कि यदि वह अतिरिक्त धमिकों को काम पर लगाएगा तो 'सीमान्त उत्पत्ति' बढ़ेगी क्योंकि नव धमिकों से भूमि की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा। परन्तु यदि चौथा धमिक लगाया जाता है, तो 'सीमान्त उत्पत्ति' 130 से घट कर 120 मन हो जाती है। नव धमिक के लगाने पर 'सीमान्त-उत्पत्ति' -10 हो जाती है, अर्थात् अतिरिक्त धमिक अन्य धमिकों के काम में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। सारिणी में पीछे धमिक से लेकर नव धमिक तक सीमान्त उत्पत्ति घटती रहती है। इस अवस्था को 'सीमान्त उत्पत्ति ह्रास नियम' कहते हैं।

3. औसत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Average Returns) : तीसरे धमिक तक 'औसत उत्पत्ति' अधिकतम है 120 मन। चौथे धमिक से 'औसत उत्पत्ति' घटना प्रारम्भ होती है और नव धमिक तक प्रति धमिक औसत उत्पादन घटकर 68 मन हो जाता है। सारिणी से स्पष्ट है कि तीसरे धमिक के पश्चात् 'सीमान्त उत्पत्ति' भी तेजी से घटने लगती है। चौथे धमिक पर औसत उत्पत्ति तथा 'सीमान्त उत्पत्ति' समान होगी। उत्पादन का सर्वोत्तम बिन्दु वह होगा, जिस पर औसत तथा सीमान्त उत्पादन बराबर होंगे, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से



श्रीतत व सीमान्त उत्पादन को समान रखना कभी कभी सम्भव नहीं हो पाता । औसत उत्पादन, एक सीमा (तीसरे धर्मिक) के पश्चात् घटता जाता है, अतः इसे 'औसत उत्पत्ति हानि नियम' कहते हैं ।

3. नियम की सीमाएँ (Limitation's of the Law) : 'उत्पादन हानि नियम' की जो परिभाषा मार्शल ने दी है उसके अनुसार इस नियम की निम्नलिखित सीमाएँ हैं :

(1) सामान्यतया (In General) यदि भूमि पर अपेक्षित मात्रा में धर्म, पूँजी आदि साधन पहुँचने से नहीं लगाए गए हैं तो आरम्भ में यह नियम नहीं लागू होगा । परन्तु अपेक्षित सीमा तक पूँजी आदि लगान के पश्चात् यदि उत्पादन-साधनों की अनिश्चित इकाइयाँ लगाई जायगी तो यह नियम लागू होना प्रारम्भ हो जायगा ।

(2) कृषि-प्रणाली में सुधार (Improvement in the art of Agriculture) इन नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि-प्रणाली पूर्ववत् हो, उसमें कोई सुधार न किया जाए । यदि पहुँचने की अपेक्षा अधिक किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, उत्तम खाद, फसल-चक्र (Crop Rotation), मशीनें, उत्तम मिचवाई आदि की सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी । वैज्ञानिक कृषि द्वारा इस नियम के लागू होने की अवधि आगे बढ़ायी जा सकती है । परन्तु दीर्घकाल में इन सुधारों के होते हुए भी यह नियम लागू होगा ।

(3) नयी भूमि (New Soil) : यदि परती भूमि पर कृषि प्रारम्भ की जाती है तो यह नियम प्रारम्भ में लागू नहीं होगा । पूँजी व धर्म के न्यूनतम प्रयोग से प्रारम्भ में उत्पादन में वृद्धि होगी । अतः नयी भूमि के सर्वप्रथम आरम्भिक अवस्था में नियम लागू नहीं होगा ।

(4) अपर्याप्त पूँजी (Inadequate Capital) : यदि अपर्याप्त पूँजी का प्रयोग किया है तो अनिश्चित पूँजी लगाने पर उत्पादन में वृद्धि होगी ।

इस नियम की उपरोक्त सभी सीमाओं का सम्बन्ध अल्पकाल से है । यह नियम स्थैतिक (Static) अवस्था में सम्बन्धित है । यदि कृषि-कला में आवश्यक सुधार हो जायेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा । फिर भी दीर्घकाल में यह नियम अवश्य लागू होगा है ।

5 नियम की अन्य विशेषताएँ (Other Features of the Law) .

(1) नियम की त्रियासीयता यह नियम उत्पादन साधनों के सर्वोत्तम संयोग (Optimum Combination) की अनुपस्थिति में ही लागू होता है । व्यावहारिक रूप से उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम संयोग बनाये रखना असम्भव हो कठिन है,

क्योंकि कुछ साधन ऐसे हैं जिनकी पूर्ति सीमित है तथा उन्हें प्रतिस्थापित (substitutable) करना मनुष्य के अधिकार से परे है। उदाहरण के लिए, 'भूमि' ऐसा ही साधन है। अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है परन्तु 'भूमि' की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जिन उत्पादन क्रियाओं में 'प्रकृति' का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें यह नियम अवश्य लागू होगा। यही कारण है कि यह नियम कृषि पर विशेष रूप से लागू होता है। कृषि में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि का क्षेत्रफल, वर्षा, मौसम आदि पर मनुष्य का प्रतिकार नहीं है, वह इनकी मात्रा व अनुकूलता को नियन्त्रित नहीं कर सकता है। अतः कृषि तथा अन्य ऐसे उद्योगों पर जो प्रकृति पर निर्भर है यह नियम शीघ्र लागू होता है।

इसके विपरीत उन उद्योगों में जिनमें मनुष्य की प्रधानता है, यह नियम शीघ्र लागू नहीं होगा। आधुनिक उत्पादन-प्रणाली, विशिष्टीकरण, नवीन आविष्कार, श्रम विभाजन आदि द्वारा मनुष्य उत्पादन में प्राशस्त वृद्धि कर सकता है। ऐसे उद्योग में मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा उत्पादन-साधनों का अनुकूलनम साधन बनाये रखन में सफल होता है। अतः इस नियम के लागू होने की प्रवृत्ति को भविष्य के लिए टाल दिया जा सकता है। परन्तु मानव-प्रधान उद्योगों पर भी अत्यन्त दीर्घकाल में यह नियम अवश्य लागू होगा। इस प्रकार 'उत्पादन हास नियम' सभी उद्योगों पर लागू होता है। मनुष्य केवल इनके लागू होने की तिथि को भविष्य के लिए टाल सकता है। इसी आधार पर Wicksteed ने कहा है, "This law is as universal as the law of life itself"

(2) नियम का सम्बन्ध उपज की मात्रा से हो है : 'उत्पादन हास नियम' का सम्बन्ध उपज की मात्रा से है उसके मूल्य से नहीं। हो सकता है, मूल्य-स्तर में वृद्धि होने के कारण, पहले की अपेक्षा कम उपज होने पर भी, उपज का मूल्य पहले की अपेक्षा अधिक हो। अतः हम उपज की मात्राओं की ही तुलना करते हैं।

### (ii) उत्पत्ति हास नियम—आधुनिक मत ✓

#### (Law of Diminishing Returns—Modern View)

1. परिभाषा . आधुनिक अर्थशास्त्री 'उत्पत्ति हास नियम' को एक व्यापक नियम मानते हैं। उनके अनुसार यह नियम केवल 'कृषि' ही नहीं, बरब सभी उद्योगों पर लागू होता है। उन्होंने इस नियम को 'परिवर्तनशील अनुपात नियम' (Law of variable proportions or Law of Proportionality) की संज्ञा दी है। यह नियम यह प्रकट करता है कि [उत्पादन के साधनों के समूह (Combination) में यदि एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाए तथा अन्य साधनों की मात्राएँ स्थिर हो तो कुल उपज एक सीमा के परचाय कम हो घटती जाएगी]।

"When total output, or production of a commodity is increased by adding units of a variable input while the quantities of other inputs are held constant, the increase in total production become, after some point, smaller and smaller"  
—Donald S. Watson

बेनहम ने इस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है : "उत्पादन साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों ज्यों बढ़ाया जाए, एक सीमा के पश्चात् त्यो-त्यो उस साधन की सीमान्त तथा औसत उपज घटती जाएगी" <sup>1</sup> श्रीमती जाने रॉबिन्सन द्वारा दी गयी इस नियम की परिभाषा इस प्रकार है : क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसा सामान्यतः कहा जाता है, यह बतलाता है कि किसी एक उत्पादन साधन की मात्रा निश्चित (यथास्थिर) रखने पर, एक सीमा के पश्चात् अन्य साधनों की क्रमागत वृद्धि करने से, उत्पत्ति में घटती हुई दर पर वृद्धि होगी <sup>2</sup> ये दोनों परिभाषाएँ उपयुक्त तथा वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार 'क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम' एक सार्वभौमिक (Universal) नियम है, तथा यह किनी भी उद्योग पर लागू किया जा सकता है। बेनहम तथा श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषाओं में कुछ भ्रम है। जोन रॉबिन्सन के अनुसार यदि एक साधन-विशेष को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उत्पत्ति की वृद्धि दर कम होनी जाती है। बेनहम के अनुसार यदि अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तथा एक साधन विशेष की मात्रा बढ़ा दी जाए तो प्राप्त उत्पत्ति की वृद्धि दर कम होनी जाएगी। दोनों के विचारों में दूसरा भ्रम यह है कि जोन रॉबिन्सन के अनुसार 'सीमान्त-उत्पत्ति के घटने के प्रारम्भ के साथ ही 'क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम' लागू होना प्रारम्भ हो जाता है, जबकि बेनहम के अनुसार 'सीमांत' व औसत उत्पत्ति—दोनों के घटने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर यह नियम लागू होता है। वस्तुतः बेनहम व रॉबिन्सन के विचारों में मौलिक भ्रम नहीं है। हम एक साधन को स्थिर रखें तथा अन्य साधनों की परिवर्तनशील रखें, या एक साधन को परिवर्तनशील तथा अन्य साधनों को स्थिर रखें, दोनों ही अवस्थाओं में यह नियम लागू होगा। इसके साथ ही साथ एक बिन्दु के पश्चात् 'सीमान्त' तथा 'औसत उत्पत्ति' दोनों में ही ह्रास प्रारम्भ हो जाता है, यद्यपि उनके घटने की गति या दर में भ्रम होना है तथा उनके घटने की प्रक्रिया के

<sup>1</sup> "As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point, the marginal and average product of that factor will diminish"  
—Benham

<sup>2</sup> "The Law of Diminishing Returns, as is usually formulated, states that with a fixed amount of any one factor of production, successive increases in the amount of others will, after a point, yield a diminishing increment of output"  
—Joan Robinson,

प्रारम्भ होने के समय में भी अन्नर हो सकता है। प्रो० लिप्से<sup>3</sup> तथा डोनाल्ड स्टीवेन्सन वाटसन<sup>4</sup> ने इस नियम की परिभाषा बेनहम की ही भाँति दी है। इन्होंने भी एक साधन को परिवर्तनशील तथा अन्य साधनों को यथास्थिर मानकर इस नियम की जाँच की है।

2. नियम का स्पष्टीकरण . इस नियम का स्पष्टीकरण निम्न सारिणी तथा रेखा चित्रों द्वारा किया जा सकता है :

अन्न द्वारा उत्पादन (मनो में)

अन्न की मात्रा	कुल उत्पाद	औसत उत्पाद	सीमान्त उत्पाद
प्रथम 1	6	6	6
अवस्था 2	18	9	12
3	33	11	15
द्वितीय 4	40	10	7
अवस्था 5	45	9	5
6	48	8	3
7	49	7	1
तृतीय 8	40	5	-9
अवस्था			

रेखाचित्र में (पृष्ठ 441) सारिणी के समक मन्त्रित किए गए हैं। चित्र में तीन अवस्था (Phases) प्रदर्शित की गई हैं।

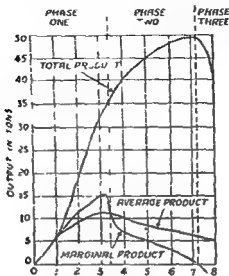
प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन (अन्न) की 'औसत उत्पाद' (Average Product) बढ़ रही है। इस अवस्था का अन्त अधिकतम औसत उत्पाद बिन्दु (highest average product point) पर होता है। इस बिन्दु पर 'औसत उत्पाद' तथा 'सीमान्त उत्पाद'—दोनों बराबर हैं।

द्वितीय अवस्था में 'औसत उत्पाद' कम हो रही है। इस अवस्था का अन्त अधिकतम कुल उत्पाद बिन्दु तथा अन्य 'सीमान्त उत्पाद' बिन्दु पर होता है। यह

<sup>3</sup> "If increasing amounts of a variable factor are applied to a fixed quantity of the other factors, the amount added to the total product by each additional unit of the variable factor will eventually decrease, after this point has been reached, additional unit of the variable factor will add less to the total product than did previous unit".

<sup>4</sup> Richard G. Lipsey, op cit, p 18

स्मरणीय है कि इस अवस्था में भी 'कुल उत्पत्ति' (Total Product) में वृद्धि हो रही है, तथा 'औसत उत्पत्ति' 'सीमान्त उत्पत्ति' से अधिक है।



चित्र सं० 62

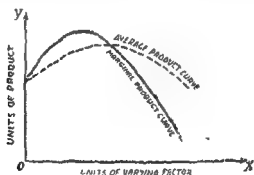
तृतीय अवस्था : में 'कुल उत्पत्ति' भी गिरनी प्रारम्भ हो जाती है, 'औसत उत्पत्ति' भी कम होती रहती है तथा 'सीमान्त उत्पत्ति' ऋणात्मक (Negative) हो जाती है।

(1) औसत उत्पत्ति (Average Product) : सारिणी से स्पष्ट है कि भूमि के एक टुकड़े पर धम की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तीन धमिकों को लगान पर प्रति धमिक 'औसत उत्पत्ति' अधिकतम है। प्रथम से तीसरे धमिक तक औसत उत्पत्ति बढ़ रही है तथा 'कुल उत्पत्ति' भी बढ़ रही है। इसे हम उत्पादन की प्रथम अवस्था कह सकते हैं। दूसरी अवस्था चौथे धमिक से सातवें धमिक तक है। इसमें 'कुल उत्पत्ति' में वृद्धि हो रही है, यद्यपि प्रति धमिक उत्पत्ति घट रही है। तीसरी अवस्था आठवें धमिक के लगाने पर प्रकट होती है। भूमि के टुकड़े पर अधिकतम कुल उत्पत्ति 49 घन प्राप्त की जा सकती है। आठवां धमिक लगाने पर अन्य धमिकों के कार्य में भी बाधा पड़ती है तथा कुल उत्पादन भी कम हो जाता है। इस प्रकार तृतीय अवस्था अव्यावहारिक है। केवल दूसरी अवस्था ही व्यावहारिक है। दूसरी अवस्था से स्पष्ट है कि यदि धम के अनुपात में भूमि की उपजावट बढ़ी की जानी है तो प्रति धमिक औसत उत्पत्ति घटती है। (इसी प्रकार यदि धम की अपेक्षा भूमि के अनुपात में वृद्धि की जाए तो प्रति एकड़ औसत उत्पत्ति कम होगी।) इससे स्पष्ट है कि यदि एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक

सीमा के पश्चात् उस साधन की त्रमागत इकाइयों की 'मौसत उत्पत्ति' घटती जाएगी। यदि एक साधन की मात्रा में 20% वृद्धि की जाए (अन्य साधनों को दयास्थिर रखकर) तो 'कुल-उत्पत्ति' में 20% से कम वृद्धि होगी।

(ii) सीमान्त उत्पत्ति (Marginal Product) : 'सीमान्त उत्पत्ति', कुल उत्पत्ति में वृद्धि की मात्रा को कहते हैं जो किसी साधन की अतिरिक्त इकाई के लगाने में प्राप्त होती है। सारिणी के अन्तिम कॉलम में श्रम की इकाइयों की 'सीमान्त उत्पत्ति' दिखाई गई है। यदि श्रमिकों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी जाती है तो 'श्रम' की 'सीमान्त उत्पत्ति'  $33-18=15$  हो जाती है। (यहाँ पर यह स्मरणयोग्य है कि उत्पादन में 15 की वृद्धि केवल तीसरे श्रमिक के ही कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी श्रमिकों की क्षमता समान है।)

(iii) 'मौसत' व 'सीमान्त-उत्पत्ति' में सम्बन्ध : सारिणी के आधार पर यदि हम 'मौसत-उत्पत्ति' और 'सीमान्त-उत्पत्ति' को रेखाचित्र द्वारा प्रकट करें तो उनकी रूप रेखा चित्र सं० 63 के अनुसार होगी :



चित्र सं० 63

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि (1) प्रारम्भ में श्रम की इकाइया बढ़ाने पर 'सीमान्त-उत्पत्ति' 'मौसत-उत्पत्ति' की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। (2) बाद में 'सीमान्त-उत्पत्ति' 'मौसत उत्पत्ति' की अपेक्षा अधिक तेजी से घटने लगती है। (3) एक ऐसा बिन्दु आता है जहाँ पर 'मौसत उत्पत्ति' 'सीमान्त उत्पत्ति' के बराबर होती है। यह बिन्दु अधिकतम 'मौसत-उत्पत्ति' का बिन्दु होता है। (4) इस बिन्दु के पश्चात् 'सीमान्त-उत्पत्ति' और 'मौसत उत्पत्ति' दोनों नीचे गिरने प्रारम्भ होती हैं तथा 'सीमान्त-उत्पत्ति' के नीचे गिरने की गति तीव्रतर होती है।

'मौसत' व 'सीमान्त उत्पत्ति' का उपरोक्त पारस्परिक सम्बन्ध सर्वत्र सत्य होता है (यदि 'मौसत उत्पत्ति' पहले बढ़ रही हो तथा बाद में घट रही हो)। उपरोक्त द्विवर्ण को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि एक उत्पादन-साधन

का अनुपात, अन्य साधनों के संयोग में बढ़ा दिया जाए तो एक सीमा के पश्चात् उस साधन की 'औसत' तथा 'सीमान्त-उत्पत्ति' कम होनी प्रारम्भ होगी ।

'क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम' के आधुनिक रूप की विवेचना के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि यह नियम समस्त उत्पादन-क्रियाओं पर लागू होता है । अतः प्रतिष्ठित आर्थशास्त्रियों का यह मत भ्रामक तथा नुट्टिपूर्ण है कि यह नियम कृषि पर ही लागू होता है । 'उत्पत्ति ह्रास नियम' की प्रवृत्ति प्रत्येक उद्योगों में विद्यमान है । इसके लागू होने के लिए केवल एक शर्त है कि 'ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन न हो' ।

**3. नियम की मान्यताएँ (Assumptions)** उत्पत्ति ह्रास नियम निम्न-लिखित मान्यताओं पर आधारित है ।

**1. उत्पादन विधि अपरिवर्तनीय :** यह मान लिया जाता है कि उत्पादन-विधि में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् प्राविधिक ज्ञान की व्यवस्था दी हुई होती है । साथ ही साथ यह भी मान लिया जाता है कि उत्पादन-वैधाने की मितव्ययिताएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं । प्रो० बेनहम के शब्दों में, "This assumes that the state of technical knowledge is given and that there are no economies of scale,"

**2. उत्पादन के मूल्य से सम्बन्ध नहीं :** इस नियम में हम उत्पादन की मात्रा पर ध्यान देते हैं, उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं ।

**3. साधनों का विभाजन सम्भव** यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन साधनों—कम से कम परिवर्तनशील साधनों (Variable factors) को छोटी छोटी समान इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है ।

**4. साधनों का पहले से ही उत्तम संयोग :** यह नियम यह मानकर चलता है कि उत्पादन साधनों का संयोग पहले से ही सर्वोत्तम है । यदि किसी साधन की मात्रा, आवश्यक मात्रा से कम है तो उस साधन की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में कमी के स्थान पर वृद्धि हो सकती है (अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखने पर) ।

**5. एक साधन स्थिर :** यह नियम उसी समय लागू होगा जबकि एक साधन स्थिर तथा अन्य साधन परिवर्तनशील हो या कम से कम एक साधन परिवर्तनशील हो ।

**4. नियम के लागू होने के कारण :** उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के निम्नलिखित कारण हैं

**1. अल्पकाल में फर्म की लागत** अल्प-काल में यदि कोई फर्म अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है तो यह नियम लागू होगा । हम यह जानते हैं कि अल्पकाल में फर्म का औसत लागत वक्र अग्रजों के U (यू) की शक्ति का होता है । औसत लागत वक्र का निम्नतम बिन्दु न्यूनतम लागत को प्रकट करता है । यदि

कोई फर्म इस बिन्दु की दाहिनी बिन्दु पर उत्पादन कर रही है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ती है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। दीर्घकाल में इस नियम के लागू होने के कारण निम्नलिखित हैं।

2 एक या कुछ साधनों का स्थिर होना : इस नियम के लागू होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन के एक या कुछ साधनों को स्थिर मान लिया जाता है। यदि उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है, तब उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होगी तथा यह नियम लागू नहीं होगा।

3 साधनों की कमी : कुछ साधनों की पूर्ति सीमित होती है। अतः उत्पादन में जब वृद्धि की जाती है तब फर्म के संगठन में परिवर्तन करते समय सीमित साधनों को ध्यान में रखना पड़ता है। कृषि-व्यवसाय में भूमि सीमित होती है अतः यह नियम लागू होता है। अन्य उद्योगों में भी यदि कोई कच्चा-माल या मशीन सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो यह नियम लागू होने लगता है।

4 उत्पादन साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना (Imperfect substitution of Factors) : उत्पादन के सभी साधन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते हैं। यदि हम उन्हें स्थानापन्न मान लें तो उन्हें एक सीमा तक ही, एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। श्रीमती जोन रॉबिन्सन ने कहा है कि यदि एक साधन स्थिर हो तथा अन्य साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो यह विल्कुल संभव है कि उत्पादन का कुछ भाग, स्थिर साधन की सहायता से पैदा किया जाय (अन्य परिवर्तनशील साधनों की सहायता से)। जब स्थिर साधन का अन्य साधनों के साथ अनुकूलतम प्रयोग कर लिया जाए तब स्थिर साधन के स्थान पर स्थानापन्न (Substitute) साधन का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार स्थिर लागत पर उत्पादन में वृद्धि संभव है, तथा यह नियम लागू होगा। परन्तु व्यावहारिक रूप में, साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, अतः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। श्रीमती जोन रॉबिन्सन के शब्दों में,

“..... Law of Diminishing Returns really states that there is a limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another, or in other words the elasticity of substitution between different factors is not infinite. If this were not true it would be possible... to substitute some other factor for it and to increase output at constant cost.” —Mrs Joan Robinson

## 2. उत्पत्ति वृद्धि नियम

### (Law of Increasing Returns)

पुराने ग्रंथकारों ने यह विचार प्रकट करते थे कि किसी देश के उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के नियमों के आधार पर किया जा सकता है। माशल के अनुसार



जो उद्योग प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं (जैसे कृषि) उनमें उत्पत्ति ह्रास नियम तथा जो उद्योग मनुष्य के प्रयत्नों पर आधारित होते हैं। (जैसे मशीन निर्माण) उनमें उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस धारणा का खंडन किया है तथा यह विचार व्यक्त किया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम एक ही प्रकार के तथ्यों पर आधारित नहीं है। उत्पत्ति ह्रास नियम में हम कुछ साधनों को स्थिर (constant) तथा कुछ साधनों को परिवर्तनशील मानकर व्याख्या करते हैं, इसके विपरीत उत्पत्ति वृद्धि नियम उस स्थिति की व्याख्या करता है, जबकि उत्पादन के सभी साधनों (All Inputs) में परिवर्तन होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम साधनों के दोष पूर्ण सयोगों (incorrect factor proportions) की व्याख्या करता है जबकि उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन मान की मितस्वयंप्रतिताओं (economies of scale) की व्याख्या करता है। इस प्रकार आधुनिक मत के अनुसार ये दोनों नियम एक दूसरे से भिन्न हैं। ये दोनों नियम दो विभिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं।

1. परिभाषा 'क्रमागत-उत्पत्ति वृद्धि-नियम', 'क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम' के पूर्णतया प्रतिकूल है। यदि किसी उद्योग में धन, पूँजी आदि साधनों की अतिरिक्त अधिक इकाइयाँ लगायी जाएँ तो सम्भव है उत्पादन में लगाए गए साधनों के अनुपात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो। जैसे यदि साधनों का मात्रा में 10% की वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन में 10% से अधिक वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' यह बतलाना है कि यदि उद्योग का विस्तार किया जाए तो 'सामान्य उत्पादन लागत' कम होनी जाएगी। प्रो० मार्शल ने इस नियम को नियामकता का सम्बन्ध उद्योगों के साथ (कृषि के साथ नहीं) स्थापित किया है। उनके अनुसार इस नियम की क्रियाशीलता का प्रमुख कारण धन व पूँजी की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप संगठन का श्रेष्ठतर होना तथा श्रेष्ठ संगठन के फलस्वरूप उत्पादन साधनों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होनी है। सैपमैन के अनुसार, "एक उद्योग का विस्तार करने पर, यदि योग्य उत्पादन साधनों का अभाव नहीं है, तो अन्य बातों के समान रहने पर, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।" श्रीमती जीन एडिन्गटन के अनुसार, "यदि किसी साधन के अतिरिक्त अन्य साधनों में अभाव नहीं है तो सामान्य संगठन में ऐसे सुधार सम्भव हो जाते हैं जिसमें उत्पादन साधनों की इकाई, मनुष्य, एकड़, या मुद्रा-पूँजी की कार्य-कुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन साधनों की मौलिक मात्रा में अनुपात-

\* "The expansion of an industry, provided that there is no dearth of suitable agents of production, tends to be accompanied, other thing being equal, by increasing returns." — Chapman

तिक वृद्धि नहीं करती पड़ती है।”<sup>6</sup> अर्थात् उद्योग में संगठन की कुशलता उत्तम होने पर उत्पादन में, उत्पादन साधनों की मात्रा की आनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है।

2 नियम का स्पष्टीकरण : इस नियम का स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। स्पष्ट है कि उत्पादन साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने पर ‘सीमान्त उत्पत्ति’ तथा ‘औसत उत्पत्ति’—दोनों में क्रमशः वृद्धि हो रही है :

#### उत्पादन साधनों की इकाइयों द्वारा उत्पादन

श्रम व पूँजी की इकाइया	कुल उत्पत्ति	सीमान्त उत्पत्ति	औसत उत्पत्ति
1	■	—	8
2	18	10	9
3	32	14	10.6
4	49	17	12.2
5	69	20	13.8

उपर्युक्त तालिका में ‘सीमान्त उत्पत्ति’ ‘औसत उत्पत्ति’ की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। ‘क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम’ को लागत ह्रास नियम (Law of Decreasing Costs) भी कहते हैं, क्योंकि साधनों की मात्रा बढ़ने पर प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती जाती है।

### 3. नियम लागू होने के कारण

(1) आन्तरिक मितव्ययिताएँ : इस नियम के लागू होने का प्रमुख कारण आन्तरिक मितव्ययिताएँ (Internal Economies) का पाया जाना है जो अधिकांश अंगों में अविभाज्यताएँ (indivisibilities) के कारण प्राप्त होती हैं। उत्पादन की मात्रा में उद्यो-उद्यो वृद्धि की जाती है, अविभाज्य साधनों का स्थो-स्थो अधिक उपयोग होने लगता है, अतः उत्पादन लागत प्रति इकाई कम होने लगती है।

<sup>6</sup> “When an increased amount of any factor of production is devoted to a certain use, it is often the case that improvements in organisation can be introduced which will make natural units of the factor (men, acres, or money capital) more efficient, so that an increase in output does not require a proportionate increase in the physical amount of the factor.”

—Joan Robinson, *op. cit.*, p 333

उत्पादन मान का विस्तार करने पर 'बाह्य मित-यथिताए' ( External Economies ) भी प्राप्त होती है, जो उत्पादन लागत को कम कर देती है ।

(2) प्राविधिक मित-यथिताए उत्पादन मान का विस्तार करने पर, Technical Economies प्राप्त होने लगती हैं, अतः उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होने लगती है ।

(3) 'श्रम विभाजन' एवं 'विशिष्टीकरण' की योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं । इससे भी उत्पादन लागत कम होती है ।

(4) अनुकूलतम आकार उत्पादन मान बढ़ाने पर कम अनुकूलतम आकार (Optimum size) की ओर प्रसरण होती है । अतः अनुकूलतम बिन्दु पर पहुँचने तक उत्पादन लागत कम होती है (यह स्मरणीय है कि 'अनुकूलतम उत्पादन बिन्दु' के पश्चात् फर्म का विस्तार करने पर उत्पादन लागत बढ़ती है) ।

(5) साधनों की पूर्ति यदि उत्पादन के साधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो तो उनका प्रयोग आवश्यक अनुपात में किया जा सकता है । ऐसा होने पर, उत्पादन मान में परिवर्तन द्वारा, लागत को कम करने का प्रयत्न किया जाता है तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है ।

उपरोक्त कारणों के संयोग से उत्पादन-लागत में कमी होती है तथा उत्पादन वृद्धि नियम लागू होने लगता है । जोन राबिन्सन के अनुसार इस नियम के लागू होने के प्रमुख कारण—उत्पादन विधि में सुधार, साधनों की कुशलता में वृद्धि, अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग तथा विशिष्ट उत्पादन प्रणाली का अपनाया जाना है ।

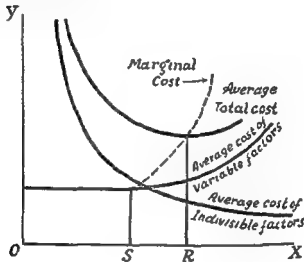
*'In every case increasing returns arise from improvements in productive technique. As output increases the efficiency of the factors can be increased by the fuller utilization of indivisible units of the factors or by the adoption of more specialised methods of production.'*

—Joan Robinson

#### 4 रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण .

'क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम' के लागू होने के कारणों से स्पष्ट है कि यह नियम मुख्यतः 'अविभाज्यताओं' ( Indivisibilities ) के कारण लागू होता है । मान लीजिए कोई एक उत्पादन साधन अविभाज्य (Indivisible) है तथा अन्य साधन विभाज्य हैं । विभाज्य साधनों में, छोटे-छोटे परिमाण में, समान लागत पर वृद्धि की जा सकती है । उत्पादन लागत ज्ञात करने समय, यदि हम 'अविभाज्य साधन' की लागत की गणना न करें, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत, कुछ सीमा

तक समान ( constant ) रहेगी । ज्यो-ज्यो उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाएगी, अविभाज्य साधन की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग होने लगेगा । अब यदि हम अविभाज्य साधन की लागत को भी उत्पादन व्यय में सम्मिलित कर लें, तो उत्पन्न लागत प्रति इकाई कम होगी । अविभाज्य साधन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के पश्चात् भी यदि उत्पादन मात्रा बढ़ाया जाता है तो 'क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम' लागू होना प्रारम्भ हो जाएगा ।



चित्र सं० 64

चित्र सं० 64 में इस तथ्य को प्रदर्शित किया गया है । OX पर उत्पादन तथा OY पर लागत प्रदर्शित की गई है । चित्र से स्पष्ट है, कि अविभाज्य साधन के उत्पादन की प्रति इकाई लागत (Average Cost of Indivisible Factor) को प्रदर्शित करने वाली रेखा एक आयतनकार 'अतिपरवलय' (a rectangular hyperbola) की शक्ति में है, जो उत्पादन की मात्रा से वृद्धि के साथ साथ नीचे गिर रही है । अन्य साधनों की औसत लागत OS तक समान है, इनके पश्चात् 'क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम' लागू होना प्रारम्भ हो जाता है तथा इन साधनों की औसत लागत वक्र (Average Cost Curve of Variable Factors) ऊपर उठना प्रारम्भ हो जाता है । कुल लागत वक्र (Average Total Cost Curve) OR तक नीचे गिरता है (यह स्मरणीय है कि  $\text{Average Total Cost} = \text{Average Cost of Indivisible factors} + \text{Average Cost of Variable factors}$ ) तथा OR के पश्चात् ऊपर उठने लगता है । सीमान्त लागत वक्र OS तक समान (constant) है, उसके पश्चात् ऊपर उठता है तथा Average Total Cost Curve को निम्नतम बिन्दु पर पार करता है (उत्पादन की OR मात्रा के लिए) । यदि लागत में वृद्धि

एक सीमा तक पहुँच गई है, तो दूसरे अविभाज्य साधक का प्रयोग करना लाभदायक होगा, तथा पुनः उपरोक्त प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।

‘क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम’ विशेषतया उद्योगों पर लागू होता है, क्योंकि :

1. उद्योगों में श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण, मशीनों का प्रयोग निरन्तर अनुसन्धान द्वारा नवीन उत्पादन विधियों की खोज तथा उनका उत्पादन क्रिया में उपयोग और आन्तरिक एवं बाह्य मितव्ययिताओं की प्राप्ति अपेक्षाकृत सरल होती है।

2. उद्योगों पर इस नियम के लागू होने का दूसरा प्रमुख कारण, उनमें उत्पादन साधनों की पूर्ति का सोचदार होना है। उत्पादक आवश्यकतानुसार, उत्पादन साधनों के अनुपात में परिवर्तन कर सकता है, इस प्रकार वह साधनों के सर्वोत्तम संयोग द्वारा उत्पादन करता है, तथा बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ उठाता है। कृषि में, एक साधन (भूमि) की सोच बहुत कम होती है, अतः सभी साधनों को सर्वोत्तम अनुपात में संयुक्त करना कठिन होता है। इस प्रकार यह नियम सामान्यतया उद्योगों पर ही लागू होता है।

यह स्मरणीय है कि यह नियम उद्योगों पर भी अनिश्चित काल तथा अनिश्चित सीमा तक लागू नहीं होगा। उत्पादन साधनों की अविभाज्यता में लाभ, और आन्तरिक एवं बाह्य मितव्ययिताएँ एक सीमा तक ही प्राप्त की जा सकती हैं। अन्त में, एक सीमा के पश्चात् ‘उत्पत्ति ह्रास नियम’ अनिवार्य रूप से लागू होने लगता है।

### 3. उत्पत्ति समता नियम

#### (Law of Constant Returns)

उत्पत्ति-वृद्धि नियम की अवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। कुछ समय तक साधनों की मात्रा में आवश्यक वृद्धि से उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है, परन्तु अधिक दीर्घकाल में उत्पत्ति-समता नियम लागू होता है। अर्थात् जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे यदि उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाकर दुगुनी कर दी जाए तो उत्पादन की मात्रा भी दुगुनी हो जाती है। इस नियम के लागू होने की व्याख्या प्रबंधशास्त्रियों द्वारा दो दृष्टिकोणों से की जाती है।

1. पहला दृष्टिकोण : जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तब यह संभव है कि कुछ अंशों में मितव्ययिताएँ (Economies) तथा कुछ अंशों में अमितव्ययिताएँ (Diseconomies) प्राप्त हों। यदि मितव्ययिताएँ तथा अमितव्ययिताएँ एक-दूसरे के बराबर होती हैं तो उत्पत्ति-समता नियम की स्थिति पाई जाती है।

निर्माणवागी उद्योगों में, विस्तार (expansion) द्वारा मिनव्ययिताए हमेशा प्राप्ति नहीं होती रहती। कुछ समय पश्चात् फर्म अनुकूलतम आकार की हो जाती है। यदि अनुकूलतम आकार के पश्चात् भी उनका विस्तार किया जाए तो उनकी कार्य क्षमता में कमी होगी। परन्तु यदि उद्योग इस प्रकार का है जिसमें नई फर्मों का प्रवेश संभव है, तथा सभी फर्मों का प्राविधिक ढांचा (Technical Structure) एक-सा है तो ऐसी दशा में उद्योग के उत्पादन में वृद्धि, नई फर्मों के प्रवेश के कारण होगी (वर्तमान फर्मों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा नहीं)। इस प्रकार कुल उत्पादन, अनुकूलतम आकार की एक जैसी फर्मों द्वारा किया जाएगा तथा उन फर्मों की (इस प्रकार उद्योग की) लागत, लागत समता नियम से शासित होगी।

2 दूसरा दृष्टिकोण कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह व्यक्त किया है कि उत्पत्ति नियम बहुत ही कम समय तक लागू होता है, परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यावहारिक अध्ययन (empirical studies) द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि इस नियम का शत्रु तथा लागू होना की अवधि काफी लम्बी हो सकती है। यदि बहुत ही घाट पैमाने के उत्पादन की अकुशलताओं को दूर करने के बाद, किसी फर्म के उत्पादन में बहुत ही कम मात्राओं में वृद्धि होगी रहती है तथा दूसरी ओर प्रति-प्रतिताप के कारण बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन क्लाम नियम भी लागू होता है तो यह कहा जा सकता है कि, ऐसी स्थिति में वास्तव में उचित-क्षमता नियम लागू हो रहा है। इस प्रकार की कल्पना में सैद्धान्तिक विश्लेषण सरल हो जाता है तथा यह कल्पना प्रावहारिक दृष्टि में भी सरल है। प्रो० वाटसन के विचार इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं :

"Though some theorists are inclined to look upon constant returns with jaundiced eyes, empirical evidence suggests that the phase of constant returns is long, that it typically covers a wide range of output. And if after overcoming the inefficiencies of too small scale a firm has return that increase only by the tiniest degrees and if the decreases in decreasing returns are exceedingly small then it can be assumed that returns to scale are constant. Such an assumption has great practical convenience, and it introduces a welcome simplification of theoretical analysis."

नियम का स्पष्टीकरण :

'रुपागत उत्पत्ति समता नियम' यह प्रकट करता है कि यदि उत्पादन क्षमता में उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो 'सीमान्त उत्पत्ति' ठीक उनी अनुपात में बढ़ेगी, जिस अनुपात में उत्पादन साधनों में वृद्धि की गई है। मागत न

इस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है, “जब समस्त उत्पादन सेवाओं में एक दिए हुए अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो उत्पत्ति उसी अनुपात में बढ़ जाती है।”

“When all of the productive services are increased in a given proportion, the product is increased in the same proportion”

— Marshall

उदाहरणार्थ, यदि उत्पादन साधनों में 10% वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन भी 10% से बढ़ जायगा। इस नियम के अनुसार उत्पादन-साधनों में वृद्धि करने पर ‘सीमान्त लागत’ सदैव समान रहती है। अतः इस नियम को ‘क्रमगत-लागत-समता-नियम’ (Law of Constant Costs) की भी संज्ञा दी गई है।

इस नियम को ‘अनुकूलतम आकार’ (Optimum size) के सदर्थ में भी स्पष्ट किया जा सकता है। यदि कोई फर्म ‘अनुकूलतम आकार’ प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है तो वह ‘क्रमगत उत्पत्ति-वृद्धि’ प्राप्त करेगी। यदि फर्म ‘अनुकूलतम आकार’ की सीमा को पार कर जाती है तो ‘क्रमगत-उत्पत्ति-ह्रास’ प्राप्त करेगी। परन्तु जब तक वह अनुकूलतम-बिन्दु पर उत्पादन कर रही है, उस समय तक ‘क्रमगत उत्पत्ति समता’ प्राप्त करेगी। निम्नलिखित सारिणी द्वारा इस समय को स्पष्ट किया जा सकता है

उत्पादन साधनों की इकाइयों द्वारा उत्पादन (मनों में)

उत्पत्ति-साधनों की इकाइया	कुल-उत्पत्ति	सीमान्त-उत्पत्ति
1	20	—
2	40	20
3	60	20
4	80	20

सारिणी से स्पष्ट है कि उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर भी सीमान्त उत्पादन सदैव समान रहता है। सामान्यतया यह नियम उन उद्योगों पर लागू होता है जिनमें उत्पादन के कई विभाग होते हैं। ऐसा सम्भव है कि एक विभाग में ‘उत्पादन-वृद्धि नियम’ के अनुसार उत्पादन हो रहा हो तथा दूसरे विभाग में ‘उत्पादन ह्रास नियम’ के अनुसार और इन दोनों नियमों की परस्पर व विपरीत प्रवृत्ति एक दूसरे को सन्तुलित कर ले, जिससे कुल-उत्पादन समता-नियम के अनुसार होने लगे।

‘क्रमगत-उत्पत्ति-समता-नियम’ उत्पादन-साधनों के अनुकूलतम तथा सर्वोत्तम संयुक्तीकरण का दायक है। उत्पादन क्रिया के आरम्भ में सामान्यतः ‘क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम’ लागू होता है (जब तक विभिन्न साधनों की उत्पादन-समता का पूर्ण

उपयोग नहीं कर लिया गया है)। साधनों की क्षमता के पूर्ण उपयोग के बिन्दु पर 'उत्पत्ति-समता नियम' लागू होता है। यदि उस बिन्दु (सीमा) के पश्चात् भी फर्म का विस्तार किया जाए तो 'क्रमागत-उत्पत्ति ह्रास नियम' लागू होना प्रारम्भ हो जाएगा अतः 'उत्पत्ति-समता-नियम' उद्यमी के लिए इस तथ्य के सूचक का काम करता है कि यदि फर्म का अधिक विस्तार किया गया तो 'उत्पत्ति-ह्रास-नियम' लागू होना प्रारम्भ हो जायगा। अतः 'उत्पत्ति-समता नियम' फर्म के 'अनुकूलतम आकार' का प्रतीक है। यह नियम फर्म का अनुकूलतम आकार निश्चित करने में सहायक होता है।

'उत्पत्ति समता नियम' के क्षेत्र में गणितीय-भाषा (mathematical language) का प्रयोग कई अर्थशास्त्रियों ने किया है। Production Function पर गणित की सहायता से प्रकाश डाला गया है। जो Production Function उत्पत्ति समता नियम को दर्शाता है उसे 'Linear and homogeneous' या 'homogeneous of the first degree' कहते हैं। Cobb Douglas production Function इसी प्रकार का है।

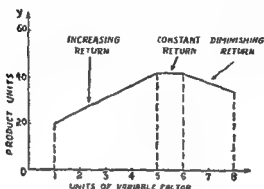
कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया है कि उत्पत्ति समता नियम बहुत दीर्घकाल में उन्नीसवीं सदी में लागू होगा जबकि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हों, परन्तु 'साहस' (entrepreneur) एक ऐसा साधन है जो परिवर्तनशील नहीं है अतः उत्पत्ति समता नियम लम्बे समय तक लागू नहीं हो सकता। परन्तु ऐसा कहना बाल की खाल निकालने के समान है।

#### 4 उत्पादन नियमों में परस्परिक सम्बन्ध

उत्पादन के ये तीनों नियम एक दूसरे से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। वस्तुतः वे एक ही नियम—'प्रतिस्थापन नियम'—के तीन विभिन्न दशाओं में प्रकट करते हैं। उत्पादन उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन करने का प्रयत्न करता है तथा उन संयोगों (Combinations) में से सर्वोत्तम 'संयोग' में विभिन्न साधनों के अनुपात होता है, उसी अनुपात में वह उत्पादन साधनों को समुक्त कर उत्पादन करता है, जिससे उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके। जब उत्पादक उत्पादन प्रारम्भ करता है तो सामान्यतः आरम्भ में उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर 'क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम' के अनुसार उत्पादन होता है, क्योंकि आरम्भ में साधनों की पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। ज्यों ज्यों उत्पादन मान बढ़ाया जाता है, प्रति इकाई लागत कम होती जाती है (जब तक कि 'अविभाज्यताओं' का पूरा लाभ न उठा लिया जाए)। यह अवस्था एक सीमा तक ही रहती है। जब 'अविभाज्यताओं' का पूरा लाभ उठा लिया जाता है, तब उस बिन्दु पर अत्यन्त प्रत्यक्ष रूप से लिए 'उत्पत्ति समता नियम' लागू होता है, जो फर्म के अनुकूलतम आकार



का प्रतीक है। उसके पश्चात् यदि उत्पादन की मात्रा में और वृद्धि की गई तो 'उत्पत्ति ह्रास मान' लागू होना प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार सामान्यतया, वृद्धि मान, समता मान तथा ह्रास मान, की अवस्थाएँ प्रत्येक उत्पादन क्रिया में पाई जाती हैं।



चित्र सं० 65

इन तीनों अवस्थाओं का निरूपण उपरोक्त रेखा चित्र में किया गया है।

### 5 उत्पादन का प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution in Production)

उत्पादन के उपरोक्त नियमों का प्रभाव उद्यमी के उत्पादन साधनों के सम्बन्ध में निर्णय पर पड़ता है। वह विभिन्न उत्पादन साधनों को सर्वोत्तम अनुपात में मिलाकर उत्पादन करने का प्रयत्न करता है। वह विभिन्न साधनों को ऐसे अनुपात में मिलाने का प्रयत्न करता है जिससे साधन न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम हो सके। उत्पादन प्रक्रिया में यह सर्वथा सम्भव है कि एक साधन या उसके कुछ अंश के स्थान पर दूसरे साधन या उसके कुछ अंश को काम में लाया जा सके। उदाहरणार्थ, अधिक पूँजी व कम श्रम का प्रयोग किया जा सकता है या अधिक पूँजी व कम भूमि अथवा अधिक श्रम व कम भूमि का उत्पादन कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यद्यपि एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता, तथापि अब उद्यमी को कुछ अंशों में इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग किम अनुपात में करें? व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव है, किसी साधन की एक इकाई के स्थान पर किसी अन्य साधन की इकाई का प्रयोग न किया जा सके, परन्तु एक साधन की इकाई के एक अंश वा दूसरे साधन की इकाई के एक अंश के स्थान पर प्रयोग करना सामान्यतया सम्भव होता है। किसी एक उत्पादन साधन की इकाई के स्थान पर अन्य साधन

या साधनों की इकाइयों का उपयोग करने को साधनों का प्रतिस्थापन (Substitution of Factors) कहते हैं।

1. परिभाषा : उत्पादन में 'प्रतिस्थापन' का अत्यधिक महत्व है। उत्पादक सहो माधनों के स्थान पर मरते तथा अधिक उत्पादक माधनों का प्रयोग करता है। 'अनुकूलतम अनुपात' में माधनों को समुक्त करने या 'न्यूनतम-लागत' पर उत्पादन करने के लिए उत्पादक 'प्रतिस्थापन सिद्धान्त' का सहारा लेता है। प्रतिस्थापन नियम यह बतलाना है कि, "न्यूनतम लागत पर उत्पादन हेतु, उत्पादन साधनों का प्रादुर्भाव सयोग जब समय प्राप्त होता है जबकि विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे अनुपात में किया जाए जिससे प्रत्येक साधन की 'सीमान्त उत्पत्ति' समान (साधनों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए) रहे।" समस्त माधनों की सीमांत उत्पादकता समान होने के कारण इसे सम सीमांत उत्पत्ति नियम (Law of Equi marginal Productivity) भी कहते हैं।

2 नियम का स्पष्टीकरण उत्पादन के एक साधन की प्रतिस्थापना (substitution) दूसरे साधन द्वारा की जा सकती है। यदि उत्पादक  $x$  तथा  $y$  साधनों में से प्रत्येक पर बत बत रूप से व्यय करता है और उसे यह ज्ञात होता है कि  $x$  साधन द्वारा उत्पादन अधिक होना है, तो उत्पादक  $y$  साधन की प्रतिस्थापना  $x$  द्वारा करेगा अर्थात् वह  $x$  साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा और  $y$  साधन की कम इकाइयों का। उत्पादक, साम्य (Equilibrium) की अवस्था में उस समय होगा जबकि  $x$  साधन पर किए गये 'सीमान्त व्यय' से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन  $y$  साधन पर किए गए सीमान्त व्यय से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के बराबर हो। उत्पादक उस समय तक  $y$  साधन के स्थान पर  $x$  साधन का प्रयोग करता जाएगा, जब तक दोनों ( $x$  और  $y$ ) पर किए गए सीमान्त व्यय में प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन बराबर न हो जाए।

हम यह जानते हैं कि किसी साधन की 'सीमान्त उत्पत्ति' उस साधन की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उत्पत्ति को कहते हैं। व्यावहारिक रूप से हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न साधनों की इकाइयों का मूल्य समान नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि भूमि की एक इकाई का मूल्य, श्रम या पूँजी की एक इकाई के मूल्य के बराबर हो। अतः विभिन्न साधनों की 'सीमांत उत्पत्ति' की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उन साधनों की सीमान्त इकाई को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को भी ध्यान में रखें। अतः यदि हम  $x$  साधन पर किए गए 'सीमान्त व्यय' से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि  $x$  साधन की सीमान्त उत्पत्ति में, साधन के मूल्य से मांग दें। उदाहरणार्थ, यदि एक साधन की 'सीमान्त उत्पत्ति' 50 इकाइयाँ हैं तथा उस साधन

की इकाई का मूल्य 5 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में उस साधन पर किए गए सीमान्त व्यय (अन्तिम एक रुपया) से  $50 - 5 = 10$  रु० का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

अतः उत्पादक 'साम्य अवस्था' (न्यूनतम लागत की अवस्था) में उस समय होगा जबकि<sup>१</sup>

साधन 'x' की सीमान्त उत्पादकता = साधन y की सीमान्त उत्पादकता

x का मूल्य

y का मूल्य

यदि उपरोक्त समीकरण में प्रथम (बाईं तरफ का) का मूल्य द्वितीय (दाईं तरफ) से अधिक है तो साधन x की अधिक तथा साधन y की कम इकाइयों का इस्तेमाल करना लाभदायक होगा। उत्पादक x तथा y की इकाइयों की मूल्य में उस समय तक परिवर्तन करना जाएगा, जब तक कि उपरोक्त समीकरण की शर्तें पूरी न हो जाए।<sup>२</sup>

इस प्रकार 'प्रतिस्थापन नियम' साधनों के अनुकूलतम संयोग में सहायक होता है। साधनों को विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार वितरित (Allocation) किया जाता है जिससे उनकी सीमान्त उत्पत्ति प्रत्येक उद्योग में समान रहे। यदि सूती वस्त्र उद्योग में इस्पात उद्योग की अपेक्षा, थर्म की सीमान्त उत्पादकता अधिक है तो थर्म इस्पात उद्योग से हटकर सूती वस्त्र उद्योग में लगेगा। थर्म के स्थानान्तर (transfer) की प्रक्रिया उस समय तक चलनी रहेगी जब तक कि दोनों उद्योगों में उसकी 'सीमान्त उत्पादकता' समान न हो जाए। इस प्रकार उत्पादन साधनों का विभिन्न उद्योगों में वह वितरण आदर्श होगा, जिसमें किसी साधन को, एक उद्योग का छोड़कर दूसरे उद्योग में जाने के लिए प्रोत्साहन (inducement) न मिले। बेनहम के शब्दों में, "साम्य अवस्था इस अर्थ में प्राप्त हो चुकी है कि किसी भी साधन को एक उद्योग में दूसरे उद्योग में स्थानान्तर के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। ऐसी अवस्था में एक साधन की सीमान्त उत्पादकता का मूल्य, प्रत्येक उद्योग में समान होगा।"<sup>३</sup>

१ इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है

$$\frac{MP_x}{P_x} = \frac{MP_y}{P_y} = \frac{MP_n}{P_n} \text{ जबकि } MP_x = \text{साधन } x \text{ की सीमान्त उत्पादकता } MP_y = \text{साधन } y \text{ की सीमान्त उत्पादकता, } P_x = \text{साधन } x \text{ का मूल्य तथा } P_y = \text{साधन } y \text{ का मूल्य।}$$

२ यह स्मरणीय है कि उत्पादक विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पत्ति को समान रखने का प्रयत्न नहीं करता बल्कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न साधनों की 'सीमान्त उत्पत्ति' में साधनों के मूल्यों का योग देता है। इस प्रकार योग देने में प्राप्त परिणामों को वह बराबर रखने की चेष्टा करता है।

३ यह स्मरणीय है कि उत्पादक विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पत्ति को समान रखने का प्रयत्न नहीं करता बल्कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न साधनों की 'सीमान्त उत्पत्ति' में साधनों के मूल्यों का योग देता है। इस प्रकार योग देने में प्राप्त परिणामों को वह बराबर रखने की चेष्टा करता है।

## प्रश्न व संकेत

1. परिवर्तनशील लागत सिद्धान्त को समझाइए। दिन परिस्थितियों में उत्पादन, ह्रासमान लागत द्वारा शासित होता है ?

[संकेत—प्रश्न के प्रथम भाग में परिवर्तनशील समुपात के नियम का उदाहरण व रेखाचित्र सहित विवेचन कीजिए तथा दूसरे भाग में इस नियम के लागू होने की दशाओं को बताइए।]

2. एक सामान्य उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था में एक साधन की कुल उत्पत्ति, प्रोसत उत्पत्ति और सीमान्त उत्पत्ति का क्या गतिित्र होता है ? किसी एक साधन की मांग का निर्धारण फलन की दूसरी अवस्था में ही क्यों होता है ?

(Raj. M. A 1969)

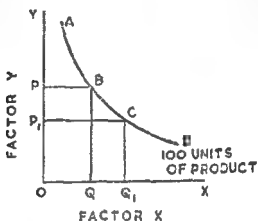
3. "वृद्धि तथा म्यूर नियम केवल ह्रास नियम के ही धस्यादी रूप (Temporary Phases) हैं।" इस कथन को समझाइए। (Vikram, B A I, 1964)

[संकेत—रेखाचित्र द्वारा उत्पत्ति ह्रास नियम को समझाइए तथा उपर्युक्त कथन की उपयुक्तता पर विचार करते हुए आधुनिक प्रयंशास्त्रियों का मत लिखिए।]

4 (अ) बर्द्धमान उत्पादन-खर्च और (ब) ह्रासमान उत्पादन खर्च नियमों के लागू होने के कारणों को समझाइये। क्या आप सोचते हैं कि एक उद्योग के लिए ये दोनों नियम पूर्णरूप से Symmetrical हैं ?

(एम० काम०, राज०, 1969)

यदि इसे एक रेखाचित्र द्वारा प्रकट किया जाए तो चित्र सख्या 66 की भाँति चित्र बनेगा। OX पर X साधन की मात्रा तथा OY पर Y साधन की मात्रा प्रदर्शित की गई है। AD सम उत्पादन वक्र (Equal Product curve) है। यह वक्र साधनों के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनके द्वारा वस्तु की 100



चित्र स० 66

इकाइया पैदा की जा सकती है। उदाहरण के लिए बिन्दु C यह प्रदर्शित करता है कि साधन X की  $OQ_1$  मात्रा तथा साधन Y की  $OP_1$  मात्रा द्वारा वस्तु की 100 इकाइया पैदा की जा सकती है। इसी प्रकार बिन्दु B यह प्रदर्शित करता है कि साधन X की  $OQ$  मात्रा तथा साधन Y की  $OP$  मात्रा द्वारा 100 वस्तुएँ पैदा की जा सकती हैं। AD वक्र पर हम कोई भी बिन्दु ले स वह बिन्दु यह प्रदर्शित करेगा कि दो साधनों के संयोग से उत्पादन समान होगा। इसीलिए इस वक्र को समोत्पत्ति वक्र कहते हैं। यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि उत्पादन की प्राविधिक अवस्थाएँ (Technical Conditions) दा हुई हैं।

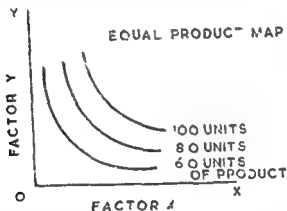
**समोत्पत्ति वक्र तथा उदासीनता वक्र में अन्तर**

समोत्पत्ति वक्र को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वह उदासीनता वक्र की ही भाँति है। परन्तु दोनों में अन्तर होता है। प्रथम, समोत्पत्ति वक्र का उत्पादन की मात्रा द्वारा प्रकट किया जा सकता है। परन्तु उदासीनता वक्र को किसी मापन द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। समोत्पत्ति वक्र को हम सरयाओं द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जैसे चित्र में समोत्पत्ति वक्र AD उत्पादन की 100 इकाइयों को प्रकट करती है। इसके द्वारा हम उत्पादन की मात्रा को निवटल, टन आदि द्वारा प्रकट कर सकते हैं। परन्तु उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का प्रवर्त करती है जिनके द्वारा एक निश्चित स्तर का सन्तोष प्राप्त होता है। उपभोक्ता की सन्तुष्टि को सरयाओं

द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। इमीलिए उदासीन वक्रों को  $IC_1$ ,  $IC_2$  आदि द्वारा प्रकट करते हैं क्योंकि सतुष्टि को भौतिक सख्याओं द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता। दूसरा, प्रमुख अन्तर यह है कि हम नीचा समोत्पत्ति वक्र या ऊँचा समोत्पत्ति वक्र बना सकते हैं तथा यह बतला सकते हैं कि एक समोत्पत्ति वक्र पर उत्पादन दूसरे समोत्पत्ति वक्र की तुलना में कितना अधिक है, जैसे चित्र सख्या 67 में तीन समोत्पत्ति वक्र हैं जो 100, 80 तथा 60 उत्पादन की मात्रा को प्रकट करते हैं। हम चित्र को *Equal Product Map* कहते हैं, उदासीनता वक्र के चित्र द्वारा हम यह नहीं कह सकते कि एक बिन्दु पर उत्पादन दूसरे बिन्दु की तुलना में कम है या अधिक है क्योंकि सतुष्टि को सख्याओं द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता।

**समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएँ (Properties of Equal Product Curves):**

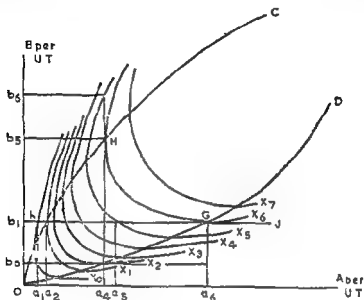
1. ये वक्र नीचे की ओर बाहिनी तरफ झुके हुए होते हैं (These Curves slope downwards to the right) : अधिकांश समोत्पत्ति वक्र नीचे की ओर बाहिनी तरफ झुकते हैं। ऐसा उस समय तक होता है जब तक कि किसी साधन की



चित्र सं० 67

अतिरिक्त इकाइयाँ आणविक उत्पादन नहीं करने लग जाती। कुछ दशाओं में आणविक उत्पादन हो सकता है जैसे कृषि कार्य में यदि श्रमिकों की अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जाएं तो एक सीमा के बाद श्रमिकों की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन घट सकता है। अतः यह आवश्यक होगा कि भूमि की मात्रा में भी वृद्धि की जाए। समोत्पत्ति वक्र यदि ऊपर की ओर बाहिनी तरफ झुकते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि  $X$  तथा  $Y$  साधनों की मात्रा में कमी वृद्धि करने पर भी उत्पादन समान रहेगा अर्थात् यदि  $X$  तथा  $Y$  की अधिक मात्राओं का प्रयोग किया जाए या उनकी कम मात्राओं का उपयोग किया जाए तो उत्पादन समान रहेगा। परन्तु ऐसा कहना

के लिए फर्म साधन B की b5 इकाइया और साधन A की a4 इकाइया प्रयुक्त कर सकती है, अथवा साधन B की b1 इकाइयों का उपयोग साधन A की a6 इकाइयों



चित्र म० 68

के माप कर सकती है, अथवा उस समोत्पत्ति वक्र पर दिखलाये गये A और B के किसी अन्य संयोग का उपयोग कर सकती है।

उत्पत्ति की अपेक्षाकृत अधिक मात्राएँ ऊँचे समोत्पत्ति वक्रों से सूचित की जाती है। समोत्पत्ति वक्र A और B के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो X वस्तु की X- की मात्रा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं, जहाँ X<sub>7</sub> मात्रा X<sub>6</sub> से अधिक होती है। इसी तरह X<sub>8</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>2</sub>, और X<sub>1</sub> मात्राएँ X- वस्तु की अपेक्षाकृत कम मात्राओं के लिए नीचे के समोत्पत्ति वक्र हैं।<sup>1</sup>

## 2 पैमाने के प्रतिफल

(Returns to Scale)

समोत्पत्ति वक्र की सहायता से उत्पादन नियमों को मकमा जा सकता है। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ यह है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उनके प्रतिफल में क्या परिवर्तन होते हैं? साधारण रूप में यह कहा जा

1. रिचर्ड, एच०, सेफ्टविच, 'कीमत प्रणाली एवं साधन आवंटन' (अनुवादक श्री सहमोनारायण नापूरामका) p 131

सकता है कि यदि सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में वृद्धि की जाए तो उत्पादन में उन्हीं अनुपात से वृद्धि होगी। जैसे यदि सभी साधनों की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो उत्पादन की मात्रा दुगुनी हो जायेगी। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। एक फर्म यदि सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करती है तो शुरू में उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि अधिक दर पर होती है परन्तु धीरे-धीरे वृद्धि दर में कमी होने लगती है। जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन में अधिक आनुपातिक वृद्धि होती है तो उसे Increasing returns to scale कहते हैं। यदि सभी साधनों की मात्रा में अनुपातिक मात्रा में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि होती है तो इसे Decreasing returns to scale कहते हैं। इन दोनों अवस्थायों के बीच में काफी समय तक एक ऐसी अवस्था पाई जाती है जिसमें सभी साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है ठीक उन्हीं अनुपात में कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था को Constant returns to scale कहते हैं।

अब हम समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से पैमाने के प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे। अब तक हमने समोत्पत्ति वक्रों को समझने के लिए केवल दो साधनों का प्रयोग किया है। परन्तु वास्तव में उत्पादन के माधन कई होते हैं। दो से अधिक माधनों को चित्र में प्रदर्शित करना कठिन होगा है तथा उनके बिना पुस्तक में देना अत्यन्त ही कठिन है। अब हम दो माधनों की ही सहायता से पैमाने के प्रतिक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे परन्तु माध ही साध आवश्यकतानुसार, विश्लेषण करते समय निष्कर्षों को दो से अधिक माधनों पर भी लागू करने का प्रयत्न करेंगे। हम यह मान कर चलेंगे कि माधनों के जेनाओं के बीच पूर्ण स्पर्धा है।

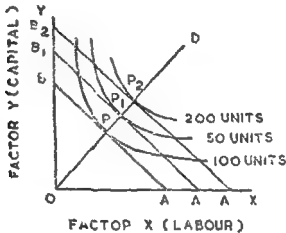
यदि एक फर्म दो माधनों का प्रयोग करती है तथा दोनों साधनों की मात्रा बढ़नी है तो दीर्घकाल में वह उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन लायेगी? माध में परिवर्तन के कारण दीर्घकाल में उत्पादन में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस परिवर्तन को जानने के लिए साधनों की कीमतों पर भी विचार करना होगा क्योंकि साधनों की मात्रा उनके माधन मूल्यों तथा प्राविधिक दक्षताओं पर निर्भर है। यदि समोत्पत्ति वक्र चित्र मर्यादा 69 का अनुसार हैं तो वर्तमान समय में—

$$\frac{X \text{ साधन की कीमत}}{Y \text{ साधन की कीमत}} = \frac{OB}{OA} = \frac{OB_1}{OA_1} = \frac{OB_2}{OA_2}$$

फर्म कम से कम लागत पर उत्पादन करना चाहती है। यदि फर्म 100 इकाइयाँ पैदा करना चाहती है तो वह P बिन्दु पर साम्य अवस्था में होगी। इसी बिन्दु पर BA Iso-cost line, समोत्पत्ति वक्र को स्पर्श-रेखा है। इस बिन्दु पर 100 इकाइयाँ पैदा करने की लागत न्यूनतम होगी। इसी प्रकार 150 तथा 200



इकाइया पैदा करने के लिए फर्म  $P_1$  तथा  $P_2$  बिन्दु पर साम्य अवस्था में होंगे। यह याद रखना चाहिए कि  $P_1, P_2$  तथा  $P_3$  आदि बिन्दु  $Y$  साधन के सदस्य में  $X$  साधन का सीमान्त महत्व प्रवृत्त करते हैं। यदि साम्य के इन सभी बिन्दुओं— $P, P_1$  तथा  $P_2$  को मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो वक्र  $OD$  बनता है उसे पैमाना रेखा (Scale line) कहते हैं। पैमाना रेखा यह बतलाती है कि यदि दो साधन  $X$  तथा  $Y$  परिवर्तनशील हैं तथा उनकी तुलनात्मक कीमत बाजार में निश्चित हैं तो न्यूनतम लागत पर उत्पादन की विभिन्न मात्राएँ पैदा की जायेंगी। कम उत्पादन का पैमाना



चित्र सं० 69

$OD$  रेखा पर निश्चित करेंगे। इस पैमाना रेखा को Expansion Path भी कहते हैं। यह रेखा उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर साधनों के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। पैमाना रेखा का ढलान दो बातों पर निर्भर है—(i) मशीन साधनों की कीमतें तथा (ii) समोत्पत्ति वक्रों का स्वरूप। पैमाना रेखा द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि यदि साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन में बढ़ती हुई दर से, घटती हुई दर से, या समान दर से परिवर्तन होगा?

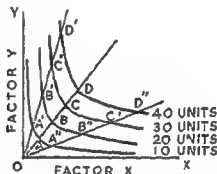
साथ ही साथ यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि पैमाना रेखा पर आगे बढ़ने से उत्पादन के दोनों साधनों की मात्राओं का अनुपात पूर्ववत् रहेगा या बदल जायगा?

### (i) समता पैमाना प्रतिफल

#### (Constant Returns to Scale)

अब हम समोत्पत्ति वक्र को सहायता से यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रभाव पैमाना रेखा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यदि दो साधनों के दिये हुए संयोग से उत्पादन प्रारम्भ किया जाए तथा यदि प्रत्येक साधन

की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो उत्पादन भी दुगुना होगा अर्थात् जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जायेगी उन्ही अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह है कि समोत्पत्ति चित्र में समी पैमाने की रेखाएँ मूल बिन्दु से प्रारम्भ होने वाली सरल रेखा के रूप में होंगी। चित्र की विभिन्न पैमाने की रेखाओं पर पैमाने का प्रतिफल (Return to scale) स्थिर रहता है। चित्र सरणी 70 में इस तथ्य को प्रदर्शित किया गया है।



चित्र स० 70

यदि समोत्पत्ति मानचित्र पर उत्पादन के दोनों साधनों की मात्रा में प्रानुपातिक परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन में भी प्रानुपातिक परिवर्तन हो जायेगा। इसीलिए समोत्पत्ति मानचित्र पर पैमाने की प्रत्येक रेखा पर उत्पादन समान होगा। उपरोक्त चित्र में पैमाने की प्रत्येक रेखा पर उत्पादन स्थिर रहता है।

प्रतिफल की स्थिरता इस बात में स्पष्ट होती है कि O, A, B, C, D, तथा A'', B'', C'', D'' पर विभिन्न सम उत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी सर्वत्र समान रहती है। उदाहरणार्थ उपरोक्त चित्र में  $OA=AB=CD$ ,  $OA'=A'B'=B'C'=C'D'$ ,  $OA''=A''B''=B''C''=C''D''$  इत्यादि। यह कहा जा सकता है कि दैकल्पिक रूप से दिये हुए साधनों के मूल्यों पर मूल्यों का द्वाव द्वाव व्यय के प्रतिफल के साथ स्थिर रहते हैं। अगर उत्पादन साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं और अगर उत्पादन साधन की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो कुल व्यय भी दुगुना हो जायेगा। इस प्रकार विशेष प्रकार के समोत्पत्ति मानचित्र में व्यय के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

चित्र सख्या 70 में समोत्पत्ति वक्र मानचित्र के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जो उत्पादन फलन (Production function) उत्पादन की मात्रा तथा इसके लिए प्रयुक्त साधनों की मात्रा में सम्बन्ध स्थापित करता है उसमें प्रथम श्रेणी की एकरूपता होती है। किसी भी उत्पादन फलन (Production function) को

हम इस प्रकार लिख सकते हैं,  $P=f(X,Y)$ , जहाँ  $P$ =उत्पादन की मात्रा और  $X$  तथा  $Y$  उत्पादन के साधन हैं। इस प्रकार यदि उत्पादन प्रसाधन  $X$  एवं  $Y$  में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन हो जायेगा।

प्रथम ध्रेणी की समरूपता सरलता के कारण अध्ययन की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन साधनों की कीमतों के स्थिर रहने पर उनका अनुपात एक सा बना रहता है, चाहे उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो। लेकिन इस मान्यता का सही होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी पैमाने की रेखा पर व्यय के प्रतिफल (Returns to outlay) स्थिर रहते हैं और उत्पत्ति के साधनों के दिये गये सापेक्ष मूल्यों पर व्यय को दुगुना कर देने से उत्पादन भी दुगुना हो जाता है तो उत्पत्ति के साधनों का अनुपात स्थिर रखना आवश्यक नहीं होता।

यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है तो पैमाने के प्रतिफल के स्थान पर व्यय के प्रतिफल (Returns to outlay) का विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा के बदलने पर जब किसी पैमाने की रेखा पर उत्पत्ति के पैमाने को दुगुना करके हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक साधन की मात्रा दुगुनी कर दी गई है। दोनों उत्पादन के साधनों को एक ही मात्रा में बढ़ाने का अभिप्राय यह होगा कि हम पैमाने की दूसरी रेखा पर चले गये हैं। लेकिन इस स्थिति में भी उत्पत्ति साधनों पर किये गये व्यय में परिवर्तन की तुलना, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से कर सकते हैं। जैसे यदि उत्पादन के साधनों पर किये गये व्यय की मात्रा को दुगुनी कर दी जाए और उत्पादन की मात्रा भी दुगुनी हो जाये तो व्यय के प्रतिफल समान रहेंगे।

यह भी कल्पना की जा सकती है कि उत्पत्ति के पैमाने में परिवर्तन से प्रयुक्त साधनों के अनुपात में भी परिवर्तन हो सकता है।

## (ii) पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल (Increasing returns to scale)

इस अवस्था का आशय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के साधनों की लगाई गई अतिरिक्त इकाइयों से उत्पादन (output) में सापेक्षिक रूप से अधिक वृद्धि हो। ऐसी स्थिति पैदा होने के मुख्य कारण दो हैं—(i) बुद्ध उत्पत्ति साधनों की अविभाजिता और (ii) विशेषीकरण (Specialisation) के लाभ।

(i) अविभाजिताएँ (Indivisibilities) : छोटे पैमाने पर उत्पादन की दशा में कुछ उत्पादन साधनों के छोटे भागों में विभक्त न हो सकने के कारण उत्पादन

प्रति इकाई कम होता है। उदाहरण के लिए कुछ पूँजी सम्पत्तियाँ उचित प्रयोग में नहीं आ सकती यदि उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है। सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न साधनों के सम्बन्ध में यह सत्य है। कुछ पूँजीगत सम्पत्तियों से छोटी इकाइयाँ पैदा की जा सकती हैं लेकिन ऐसी अवस्था में भी उत्पादन (प्रति इकाई) कम होगा। पूँजीगत सम्पत्तियों के समान धन भी पूर्णरूप से विभाज्य नहीं है। किसी भी उद्योग में धनिक से उसकी अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना कठिन होता है।

(ii) **विशिष्टीकरण (Specialisation)** बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल का दूसरा महत्वपूर्ण कारण विशेष दक्षता है। किसी छोटे पैमाने के उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो उनको वे कार्य करने को दिये जा सकते हैं जिनमें वे अधिक दक्ष हैं। इससे दक्षता में वृद्धि होगी और अधिक उत्पादन प्राप्त होगा।

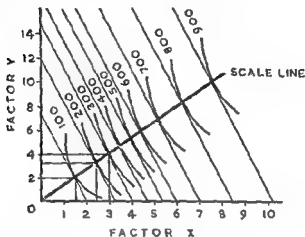
इस प्रकार यदि किसी उद्योग में प्रारम्भ में उत्पादन के कुछ साधनों में समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उत्पादन वृद्धि के प्रारम्भिक प्रयास में नए लगाये गये साधनों में सापेक्षिक रूप से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा।

### (iii) पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल (Decreasing Returns to Scale)

यदि कोई फर्म निश्चित सीमा से आगे उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पत्ति के साधनों की अतिरिक्त इकाइयाँ लगानी जाती हैं तो इन अतिरिक्त इकाइयों से सापेक्षिक रूप से कम उत्पादन प्राप्त होगा। इसी स्थिति को पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। वास्तव में उत्पादन के साधनों के सर्वोत्तम संयोग की स्थिति के बाद यदि अतिरिक्त इकाइयाँ लगायी जाती हैं तो उत्पादन प्रति इकाई कम प्राप्त होगा। इसका प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनेक जटिलताएँ (Complexities) तथा समस्याएँ (Problems) हैं। उदाहरण के लिए धन साधन में वृद्धि से उनकी क्रियाओं में समन्वय एवं नियन्त्रण के लिए अधिक प्रबन्धकीय व्यक्तियों (Administrative Personnel) की आवश्यकता होती है। प्रबन्धकों को निरुपेक्ष लेने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चित्र सं० 71 में पैमाने के घटते हुए, बढ़ते हुए तथा स्थिर प्रतिफल को स्पष्ट किया गया है।

चित्र में पैमाने की रेखा बिल्कुल सीधी (Straight) है इसलिए साधन X और साधन Y का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए, साधन Y की 4 इकाइयाँ और साधन X की तीन इकाइयाँ। इस प्रकार जब उत्पादन 100

इकाइयों से बढ़कर 200 इकाइयाँ हो जाता है तो साधन Y में 1.2 इकाइयों की और X में 0.9 इकाइयों की वृद्धि होती है। 200 इकाइयों से 300 इकाइयों का



चित्र सं० 71

उत्पादन करने पर साधन Y में 8 इकाई की और साधन X में 6 इकाई की वृद्धि होती है। दोनों साधन एक ही अनुपात में बढ़ते हैं।

यह स्पष्ट है कि उत्पादन 100 से 300 इकाइयाँ करने पर उत्पादन के साधनों की अतिरिक्त मात्रा प्रत्येक 100 इकाइयों के साथ घटती जाती है—वे बिन्दु जहाँ पर स्थिर उत्पादन वक्र है मूल्य रेखा अधिक नजदीक होती जा रही है। साधनों पर किया जाने वाला व्यय प्रत्येक अतिरिक्त 100 इकाइयों के साथ घटता जा रहा है। इस प्रकार फर्म पैमाने का बढ़ना हुआ प्रतिफल प्राप्त कर रही है क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त 100 इकाइयों पर सापेक्षिक रूप से कम व्यय होता है।

उत्पादन 300 इकाइयों से बढ़ा कर 600 इकाइयाँ कर देने पर प्रत्येक 100 इकाइयों के लिए लगाये जाने वाले साधनों की मात्रा स्थिर रहनी है। वे बिन्दु, जहाँ पर उत्पादन वक्र मूल्य रेखा को काटते हैं, समान दूरी पर हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि फर्म स्थिर पैमाने का प्रतिफल प्राप्त कर रही है।

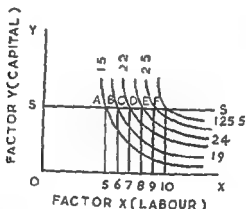
उत्पादन में 600 इकाइयों से अधिक वृद्धि करने पर उत्पादन की प्रत्येक 100 इकाइयों के लिए सापेक्षिक रूप से उत्पादन के साधनों की अधिक मात्राएँ लगानी पड़नी है। इस प्रकार फर्म घटती हुई दर पर उत्पादन का प्रतिफल प्राप्त करती है।

उपसंहार : "पैमाने का प्रतिफल सिद्धान्त वह महत्व शायद नहीं कर सकता है जो महत्व ह्रासमान उत्पादन नियम प्राप्त कर सका है। व्यावहारिक रूप में इस

वान से सभी सहमत हैं कि एक फर्म प्रारम्भ में यदि उत्पादन पैमाने का विस्तार करनी है तो प्रति-माघन-इकाई के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अन्त में पैमाने की मितव्ययिताएँ (Economies of scale) धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं परन्तु (i) क्या अन्त में प्रति इकाई पड़त (input) का उत्पादन कम होता है? या (ii) ऐसा केवल कृषि जैसे व्यवसाय में ही होता है जिसकी प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याएँ विशिष्ट हैं? इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एकमत-नहीं हैं।" (देखिए इस अध्याय के प्रारम्भ का कोटेशन)।

### सीमान्त भौतिक उत्पादकता (Marginal Physical Productivity)

अब तक हमने यह माना था कि किसी उत्पादन इकाई द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले उत्पादन के साधनों की मात्रा परिवर्तनशील है। अब हम यह मानेंगे कि



चित्र सं० 72

फर्म द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले उत्पादन साधनों में एक साधन की मात्रा स्थिर रहती है। चित्र सं० 72 में Y साधन (पूँजी) की मात्रा स्थिर है जबकि X साधन (धन) की मात्रा परिवर्तनशील रहती है। साधन Y, OS पर स्थायी दिखाया गया है जबकि साधन X (धन) 5 से 6, 6 से 7 और इसी तरह परिवर्तित होता रहना है। संतति रेखा SS साधन X और Y के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए A पर OS की Y की मात्रा और 5 इकाइयों, X साधन [धन] का संयोग है। समोत्पत्ति वक्र उत्पादन की विभिन्न मात्राएँ जैसे 15, 19, 22, 24, 25, 25.5 इकाइयाँ प्रदर्शित करते हैं। जब Y साधन की OS मात्रा का X साधन की 6 इकाइयों का संयोग किया जाता है तो उत्पादन 19 इकाइयाँ होता है जो कि बिन्दु

Q के द्वारा स्पष्ट है। इस प्रकार छठी इकाई द्वारा उत्पादन में की गई वृद्धि 4 इकाइया है या छठी इकाई की सीमांत उत्पादकता 4 इकाइया है। इसी प्रकार X साधन की 7वीं इकाई से 3 इकाइयों और 10वीं इकाई से 5 इकाई से उत्पादन में वृद्धि होती है।

इस प्रकार जब कोई फर्म एक साधन पूँजी को स्थिर रख कर दूसरे साधन [थम] की मात्रा में परिवर्तन करती जाती है तो दूसरे साधन (थम) की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। इस घटती हुई सीमान्त भौतिक उत्पादकता को हम वक्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र (MPPC) इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी एक उत्पादन साधन की मात्रा स्थिर रखने तथा दूसरे साधन की मात्रा को परिवर्तनशील रखने पर उस दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। उत्पादन प्रमापनों के मूल्य निर्धारण में यह वक्र बहुत लाभदायक है। नीचे दिये गये चित्र में 6 श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 4 इकाइयाँ, 7 श्रमिकों की 3 इकाइया, 8 श्रमिकों की दो इकाइया 9 श्रमिकों की एक इकाई और 10 श्रमिकों की 5 इकाई है। इस तथ्य को हम निम्न प्रकार चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं—

चित्र संख्या 73 में MPPC सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे थम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता



चित्र सं० 73

है तो सीमांत भौतिक उत्पादकता घटती जाती है। यही कारण है कि MPPC वक्र नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकता चला गया है। MPPC का साधारणतया यही ढाल होता है क्योंकि उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखने पर तथा दूसरे साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर उनकी सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। इसी साधारण पर हम औसत उत्पादकता वक्र [APPC] भी बना सकते हैं।

इसके लिए हमें कुल उत्पादन को धर्म की इकाइयों से विभाजित करना पड़ेगा। इसी प्रकार कुल भौतिक उत्पादकता वक्र, [TPPC] समोत्पत्ति मानचित्र या सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र तथा सीमांत सीमांत उत्पादकता वक्र [APPC] को सहायता से बनाया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है किमी परिवर्तनशील उत्पादन साधन से साथ किसी स्थिर साधन का मिलाव किया जाए तो सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। भूतकाल में इसी प्रवृत्ति को उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) का नाम दिया जाता था। वर्तमान में इसे अधिक उचित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (Law of variable Proportions) का नाम दिया जाता है।

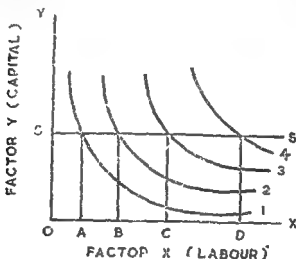
यह ध्यान में रखना चाहिये कि किसी परिवर्तनशील (Variable) उत्पादन साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कुछ दशाओं में बढ़ भी सकती है। सीमांत उत्पादकता वक्र (MPPC) में बहुत कुछ सीमाएं ऐसी सीमाएं भी हो सकती हैं जहां सीमांत उत्पादकता घटने के बजाय बढ़ती है। इसीलिए इसे कुछ अर्थशास्त्री 'घटनात्मक सीमांत उत्पादकता ह्रासमान' (Eventually diminishing marginal productivity) की संज्ञा देते हैं लेकिन दीर्घकाल में निश्चिन्त रूप से सीमांत उत्पादकता घटती है।

परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता, समोत्पत्ति वक्र मानचित्र से अन्य प्रकार से भी निकाली जा सकती है। अब हम यह मानकर कि उत्पादन क्रिया (Production function) समरूप है, विभिन्न परिवर्तनशील साधनों के अनुपातों का अध्ययन करेंगे जिनमें कि एक साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन या साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। पूर्व चित्र में साधन X (धर्म) की सम इकाइयां स्थिर साधन Y के साथ प्रयुक्त की जाती हैं। परिणामस्वरूप साधन X की सीमांत भौतिक उत्पादकता घटती जाती है। लेकिन अब हम दूसरे प्रकार का चित्र प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि यह समरूप उत्पादन क्रिया (Homogeneous production function) की दशा है।

चित्र 74 में सम उत्पाद चित्र (equal product map) चार वक्रों की सहायता से उत्पादन की 1, 2, 3, 4 इकाइयों के साथ दिखाया गया है। यहाँ साधन Y स्थिर है जबकि साधन X परिवर्तनशील है। संतुलित रेखा SS, OX के समानान्तर है। यह दो साधनों X और Y का X की परिवर्तनशील इकाइयों के साथ समान दिखाती है। एक इकाई के उत्पादन के लिए फर्म Y साधन को OS मात्रा और X की OA मात्रा का संयोग करती है। दो इकाइयों के उत्पादन के लिए फर्म Y साधन की OS मात्रा और X की OB मात्रा का संयोग करती है।



इसका तात्पर्य यह हुआ कि अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए  $X$  साधन की  $AB$  अतिरिक्त मात्रा लगानी पड़नी है। इसके पूर्व एक इकाई के उत्पादन के लिए  $Y$  साधन की  $OS$  मात्रा के साथ  $X$  साधन की  $OA$  मात्रा का संयोग करना पड़ता था। अब उत्पादन की एक इकाई श्रम या  $X$  साधन की  $AB$  मात्रा और  $Y$  साधन की  $OS$  मात्रा के संयोग से उत्पादित की जाती है। इस प्रकार  $OS$  पूँजी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रम की अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता घट गई है। इसके बाद दो से तीन इकाइयों के उत्पादन के लिए  $OS$  पूँजी के साथ श्रम की  $BC$  इकाइयाँ लगायी जाती हैं।  $BC$ ,  $AB$  से अधिक है। इस प्रकार अतिरिक्त इकाई के

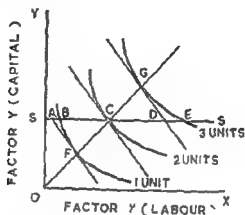


चित्र सं० 74

उत्पादन के लिए श्रम की आनुपातिक रूप से अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 3 व 4 इकाइयों के उत्पादन के लिए हमें तुलनात्मक रूप से श्रम की और अधिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार किसी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों के संयोग पर सीमांत भौतिक उत्पादकता क्रमिक रूप से घटती जाती है। प्रथम श्रेणी (First degree) के समरूप उत्पादन क्रिया (Homogeneous Production function) में सीमांत उत्पादकता हमेशा घटती जाती है। इसी तथ्य को प्राग चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

चित्र मध्या 75 में तीन सम उत्पादन वक्र हैं जो क्रमशः उत्पादन की 1, 2, और 3 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं।  $OFCG$  पैमाना रेखा है जो दो उत्पादन प्रसाधनों  $X$  (श्रम) तथा  $Y$  (पूँजी) का संयोग दिखाती है।  $F$ ,  $C$ ,  $G$  विभिन्न

संयोगों को प्रदर्शित करती है।  $OF=FC=CG$  इसका अर्थ यह हुआ कि पैमाने के प्रतिकूल सम (Constant) हैं। FCG बिन्दुओं पर सम उत्पाद वक्रों के साथ स्पर्श रेखाएँ (Tangent lines) बनाई गई हैं। क्योंकि ये सभी स्पर्श रेखाएँ सम



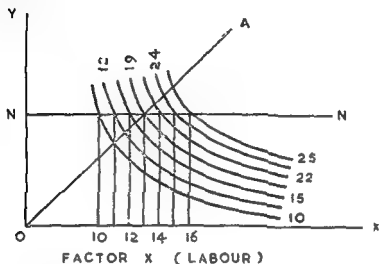
चित्र नं० 75

उत्पाद वक्रों को उस स्थान पर पैमाने की रेखा इनको काटती है, इसलिए ये एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। सीमांत भौतिक उत्पादकता हमेशा निरती है यदि उत्पादन क्रिया (Production Function) समरूप है तथा पैमाने का प्रतिकूल स्थिर है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि परिवर्तनशील उत्पादन साधन (Variable factor) की सीमांत भौतिक उत्पादनता उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था (initial stage) में बढ़ती मकनी है यदि कुल उत्पादन (Total outlay) का प्रतिकूल स्थिर (constant) नहीं रहता है। पृष्ठ 473 के चित्र द्वारा यह स्पष्ट है

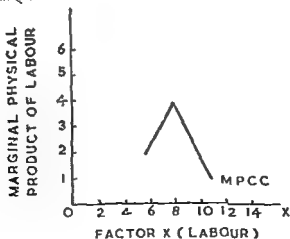
चित्र में समीपस्थ वक्र मानचित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक नए साधन X तथा साधन Y की विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। OP पैमाना रेखा है जो X व Y साधनों के विभिन्न संयोगों के साथ उत्पादन के विस्तार को स्पष्ट करती है। SS क्षैतिज रेखा Y स्थिर साधन का X की परिवर्तनशील मात्रा के साथ संयोग को प्रदर्शित करती है। चित्र में हम देखते हैं कि साधन Y की स्थिर मात्रा के साथ साधन X की बढ़ती हुई इकाइयों का संयोग किया जाए तो कुछ सीमा तक उत्पादन बढ़ता है अर्थात् साधन X (धन) की सीमांत उत्पादकता कुछ सीमा तक बढ़ती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कुल उत्पादन 10 से 12 12 से 15, 15 से 19 इकाइयाँ हो जाता है, यदि धन की इकाइयों में 10 से 11, 11 से 12,

12 से 13 की वृद्धि की जाती है। श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता 2 इकाइया, 12 श्रमिकों की 3 इकाइया, 13 श्रमिकों की 4 इकाइया है। इस प्रकार 13वें श्रमिक को लगाने तक सीमान्त उत्पादकता बढ़ती जाती है।



चित्र सं० 76

इसके पश्चात् सीमान्त उत्पादकता क्रमशः घटती जाती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिवर्तनशील उत्पादन इकाई को लगाने पर सीमान्त भौतिक उत्पादक प्रारम्भिक अवस्था में कुछ समय बढ़ती जाती है और इसके पश्चात् घटने लग जाती है।

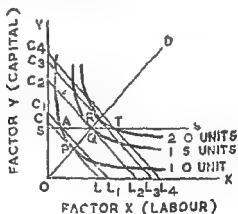


चित्र सं० 77

इन मध्यम श्रम की सीमात उत्पादकता को सीमान्त मूल्य उत्पादन वक्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र में तीसरी इकाई तक सीमात उत्पादकता बढ़ती जाती है और उसके पश्चात् क्रमशः घटना चालू हो जाती है।

बढ़ती हुई सीमात भौतिक उत्पादकता को दूसरे प्रकार के चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र सं० 78 में समोत्पत्ति वक्र मानचित्र में तीन वक्र हैं जो कि 1.0, 1.5 और 2 इकाइया उत्पादन की जाती हैं। पहली समस्या में श्रम और पूँजी दोनों की इकाइयाँ परिवर्तित की जाती हैं तथा पूँजी को स्थिर रखा जाता है। यह क्षैतिज रेखा SS से स्पष्ट है। पैमाना रेखा OP के बिन्दु A पर उत्पादन एक इकाई है, B पर उत्पादन 1.5 इकाई है तथा C पर उत्पादन 2 इकाई है। इस प्रकार यदि पैमाना रेखा पर P बिन्दु की ओर बढ़ें तो कुल उत्पादन प्रत्येक स्थिति में 0.5 इकाइयों से बढ़ता है। जब A से B की ओर बढ़ते हैं तो दोनों साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है। B से C की ओर बढ़ते हैं तो कुल साधनों की मात्रा घटाई जाती है और उत्पादन भी बढ़ता है। इस प्रकार फर्म पैमाना रेखा OP पर आगे बढ़ती है और बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है।



चित्र सं० 78

उपरोक्त निवेदन से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन यह तो कहा जा सकता है कि जब तक बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और उत्पादन की इकाइयों को पूर्ण साम्य की अवस्था में रहना है तो उत्पादकता किसी न किसी स्तर पर अवश्य घटनी आरम्भ हो जायेगी। सीमात उत्पादन वक्रों की आवृत्ति उल्टे U की तरह होती है। इसका आशय यह है कि एक स्थिर साधन के साथ किसी भी परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने पर उत्पत्ति अन्त में घटती जाती है।

### प्रश्न व सकेत

1 समोत्पत्ति वक्र रेखाओं को स्पष्ट कीजिये तथा उनकी विशेषतायें बताइये।

[सकेत—समोत्पत्ति वक्र रेखायें तथा उदासीन वक्र रेखायें समान (Counterpart) होती हैं। काल्पनिक उदाहरण देकर एक समोत्पत्ति वक्र बनाइये तथा उसकी चारों प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।]

2 समोत्पत्ति वक्र रेखायें किन्हे कहते हैं? ये उदासीन वक्र रेखाओं से किम प्रकार भिन्न हैं?

3 पैमाने के प्रतिफल' (Returns to Scale) को समोत्पत्ति वक्रों द्वारा स्पष्ट कीजिये।

[सकेत—पहले समोत्पत्ति वक्र का स्पष्टीकरण कीजिये। फिर उनकी सहायता से पैमाने के प्रतिफल को स्पष्ट कीजिये।]

4 उत्पादन ह्यम नियम की समोत्पत्ति वक्र विधि से व्याख्या कीजिये।

[सकेत—काल्पनिक उदाहरण देकर समोत्पत्ति वक्र मानचित्र बनाइये और उसकी सहायता से उत्पत्ति ह्यम नियम को व्याख्या कीजिये।]

5 'सीमान्त आगम उत्पाद' (MRP) तथा सीमान्त भौतिक उत्पाद (MPP) में अन्तर स्पष्ट कीजिये। यह भी बताइए कि किम प्रकार जब तक प्रत्येक साधन की कीमत उसके सीमान्त आगम उत्पाद के बराबर नहीं होगी तो लाभ अधिकतम नहीं होगी।

[सकेत—MRP तथा MPP में अन्तर बताइए तथा दूसरे भाग में बताइये कि यदि MRP साधनों की कीमत से कम है तो फर्म को घाटा होता है।]

### समस्याएँ (Problems)

1 यदि कृषक के अनुमान के विपरीत मौसम अच्छा हो जाता है तो श्रमिक के सीमान्त भौतिक उत्पाद वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

2 एक समोत्पत्ति वक्र पर निम्नलिखित को चित्रित कीजिये—

- (a) श्रम वचन नव प्रवर्तन (innovation) (b) पूँजी वचन प्रवर्तन
- (c) श्रम तथा पूँजी की क्षमता को बढ़ाने हेतु तकनीकी परिवर्तन।

3 समोत्पत्ति वक्र पर पूँजी की ह्यममान सीमान्त उत्पत्ति प्रदर्शित कीजिये जबकि श्रम की मात्रा स्थिर है।

4 सुपर बाजार और अल्पाहार गृह की स्थिति में परिवर्तनशील आनुपातिक तथा स्थिर आनुपातिक पैमाने के विचार को प्रकट कीजिये।

## उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम संयोग (Optimum Factor Combination)

*"A major task of the business firm is the selection of the factor combination which is the optimum in the sense of allowing lowest cost of producing a given output"*

Due and Clower

उत्पादक, उत्पत्ति के संयोग (combination) से उत्पादन करता है। पूर्व पृष्ठों में हमने उत्पादन फलन (Production function) का विश्लेषण समोपत्ति वक्रों की सहायता से दो साधनों की माध्यता के आधार पर किया है। लेकिन व्यवहार में उत्पादन के लिए दो से अधिक साधनों का संयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक फर्म की हुई मात्रा के उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का उचित मात्रा में संयोग करती है। इस अवस्था में फर्म के सामने समस्या होती है कि विभिन्न साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके।

यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विभिन्न उत्पादन के साधनों का मूल्य तथा मान्त्रिक ज्ञान दिया हुआ है। फर्म का उद्देश्य कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। स्पष्टतया फर्म इस उद्देश्य की प्राप्ति उत्पादन के विभिन्न साधनों के श्रेष्ठतम संयोग से ही प्राप्त कर सकती है। उत्पादक श्रेष्ठतम संयोग के लिए उत्पादक विभिन्न साधनों को इस प्रकार मिलाता है कि एक साधन के सीमांत भौतिक उत्पाद और उसके मूल्य का अनुपात दूसरे साधनों के सीमांत भौतिक उत्पाद और उनके मूल्यों के अनुपात के बराबर हो ॥

$$\frac{\text{साधन A का सीमान्त भौतिक उत्पाद}}{\text{साधन A का मूल्य}} = \frac{\text{साधन B का सीमान्त भौतिक उत्पाद}}{\text{साधन B का मूल्य}}$$

$$= \frac{\text{साधन C का सीमान्त भौतिक उत्पाद}}{\text{साधन C का मूल्य}} = \frac{\text{साधन Z का सीमान्त भौतिक उत्पाद}}{\text{साधन Z का मूल्य}}$$

उपरोक्त विश्लेषण से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण विचार सीमांत भौतिक उत्पाद और साधन का मूल्य है। कम से कम लागत पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधन का सीमान्त भौतिक उत्पाद इसका मूल्य के बराबर होना चाहिए। अगर किसी साधन के सीमांत भौतिक उत्पाद और उसके मूल्य का अनुपात दूसरे साधन के इसी अनुपात के बराबर नहीं है तो कम से कम लागत पर उत्पादन प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायेगी। ऐसी दशा में कम के लिए किसी एक साधन का कम या दूसरे साधन का अधिक मूल्य देकर उनके अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। जिस समय तक साधनों की सीमांत भौतिक उत्पाद और इनके मूल्यों का अनुपात बराबर नहीं होगा तब तक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन नहीं किया जा सकेगा।

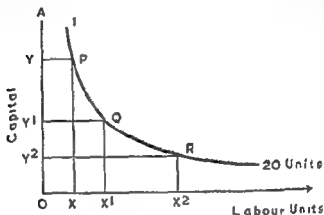
मान लीजिए 5 एकड़ भूमि 500 रुपये पर किराये पर ली जाती है और श्रम 1200 रुपये प्रतिवर्ष पर लगाया जाता है और भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता 500 kg और श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता 1400 kg है तो उपरोक्त फार्मूले का प्रयोग करने पर

$$\frac{\text{श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता (1400 kg)}}{\text{श्रम का मूल्य (Rs 1200) या } \frac{7}{6} > \frac{1}{2}} = \frac{\text{भूमि की सीमांत उत्पादकता (500 kg)}}{\text{भूमि का मूल्य (Rs, 500)}}$$

दोना साधन का अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए कम को अपना कुछ व्यय भूमि से श्रमिकों को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रकार साधनों के अधिकतम संयोग के लिए उत्पादक एक दूसरे साधन का प्रतिस्थापित करेगा। उत्पादक विभिन्न साधनों के संयोगों की लागत के दृष्टिकोण में तुलना करता है और जिस संयोग की लागत सबसे कम होती है वही संयोग अपनाया जाता है। मान लीजिए उत्पादक किसी वस्तु की 20 इकाइयों का उत्पादन श्रम व पूँजी के निम्नलिखित संयोगों द्वारा किया जा सकता है।

श्रम इकाइयाँ	पूँजी इकाइयाँ	उत्पादन इकाइयाँ	पूँजी तथा श्रम के मध्य तकनीकी सीमांत स्थानापत्ति दर
1	+	10	20
2	+	8	20
3	+	6	20
4	+	4	20
5	+	2	20
			1 4 ( $\frac{1}{2}$ )
			1 2 ( $\frac{1}{2}$ )
			1 1 (1)
			1 2 ( $\frac{2}{3}$ )

इस प्रकार 20 इकाइयों का उत्पादन थम व पूँजी की उपरोक्त इकाइयों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ यह मान लिया गया है कि थम तथा पूँजी के मध्य स्थानापत्ति सम्भव है। पीछे दी गई तालिका के आधार पर समोत्पत्ति वक्र भी प्राप्त किया जा सकता है :



चित्र सं० 79

उपरोक्त चित्र में  $X$  थम पर थम की इकाइया तथा  $Y$  थम पर पूँजी की इकाइया व्यक्त की गई हैं। दोनों साधनों के विभिन्न इकाइयों से संयोग से 20 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। ये विभिन्न संयोग समोत्पाद (Equal Product Curves) द्वारा व्यक्त किये गये हैं। उत्पादक इन संयोगों में से किसी एक का चुनाव करते समय लागत को ध्यान में रखता है और जिस संयोग (combination) से लागत कम से कम होती है वही संयोग उसके द्वारा चुना जाता है। किसी भी उत्पादक के लिए इस प्रकार के अनेक वक्र होते हैं जो निम्न-निम्न उत्पादन स्तरों पर विभिन्न संयोग (combination) प्रदर्शित करते हैं।

उत्पत्ति के साधनों की घटती हुई सीमान्त दर (The principle of Diminishing Marginal Rate of Factor Substitution) : उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों थम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है त्यों-त्यों पूँजी की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस अधिक सीमा तक पूँजी का थम के साथ प्रतिस्थापन किया जाता है, प्रतिस्थापन (Substitution) की सीमान्त दर घटती जाती है। इसी सम्बन्ध को घटती हुई सीमान्त दर की सहा दी जाती है। इस नियम को अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है - किसी एक उत्पत्ति साधन की मात्रा बढ़ाने पर उस संयोग से दूसरे साधन की क्रमशः कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जिस दर पर दूसरे साधन द्वारा पहले साधन को प्रतिस्थापित किया जाता है वह दर घटती जाती है।



**श्रेष्ठतम संयोग :** — केवल प्रतिस्थापन की सीमान्त दर ही साधनों के प्रयोग की श्रेष्ठतम मात्रा निर्धारित नहीं करती। प्रत्येक साधनी इस चुनाव में इन संयोगों की लागत कर भी ध्यान में रखना है। इसलिए कोई भी संयोग उसी हालत में निश्चित किया जा सकता है जबकि विभिन्न साधनों की लागत के बारे में ज्ञान हो तथा जिस दर पर एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापन किया जा सके, वह दर ज्ञात हो। मान लीजिए घुलाई की मशीनों की निश्चित दबावों के उत्पादन के लिए अल्युमिनियम और स्टील की निम्न मात्राओं के विभिन्न संयोग दिये हुए हैं और अल्युमिनियम की लागत 60 रुपये प्रति टन तथा स्टील की लागत 30 रुपये प्रति टन है। निम्न तालिका से इन मशीनों के निर्माण के विभिन्न संयोगों की लागत स्पष्ट है —

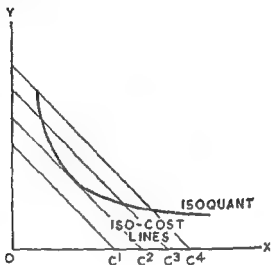
विभिन्न संयोगों की दशा में 200 घुलाई की मशीनों के उत्पादन से सम्बन्धित लागत

अल्युमिनियम (टनों में)	स्टील (Steel) (टनों में)	अल्युमिनियम की लागत (रुपयों में)	स्टील की लागत (रुपयों में)	अन्य लागत (रुपयों में)	कुल लागत
0	10	0	300	9000	9300
1	6	60	180	9000	9240
2	3	120	90	9000	9210
3	1	180	30	9000	9210
4	$\frac{1}{2}$	240	$7\frac{1}{2}$	9000	$9247\frac{1}{2}$
5	0	300	0	9000	9300

उपरोक्त तालिका में साधनों का श्रेष्ठतम संयोग उस हालत में प्राप्त किया जाता है कि जबकि अल्युमिनियम की मात्रा 2 टन और स्टील की 3 टन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगर लागत का भिन्नो में लिया जाता तो ये तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इस दशा में हम पूर्णतया निम्न लागत ज्ञात कर सकते हैं।

समोत्पत्ति लागत वक्रों की समलापन रेखा के साथ स्पर्शता (Tangency of the Isoquants with an Iso cost line) साधनों के श्रेष्ठतम संयोग को, समोत्पत्ति वक्र (Isoquants) के साथ समलापन रेखाओं का आइकर, रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक सम्भव संयोग के लिए सम लागत रेखाएँ बनाई जा सकती हैं। ये रेखाएँ एक दूसरे के समानान्तर होती हैं। विभिन्न वक्रात्मक संयोगों की दशा में उस संयोगों की दशा में उस संयोग का चुनाव कर जिसकी लागत सबसे कम है श्रेष्ठतम संयोग प्राप्त कर सकते हैं। रेखाचित्र में जहाँ निम्नतम सम

लागत रेखा (Lowest isocost line) जिस बिन्दु पर समोत्पत्ति वक्र को स्पर्श करती है वह बिन्दु साधनों के श्रेष्ठतम संयोग या बिन्दु होता है। यह निम्न चित्र से स्पष्ट है।



चित्र सं० 80

उपरोक्त चित्र में  $C_1, C_2, C_3, C_4$  विभिन्न समलागत रेखाएँ हैं। समोत्पत्ति वक्र, बिन्दु P पर निम्न समलागत रेखा को स्पर्श करता है। यही बिन्दु साधनों के श्रेष्ठतम संयोग का बिन्दु है। इस बिन्दु से निम्न लागत पर आवश्यक उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधन नष्ट नहीं किये जा सकेंगे जबकि इसके ऊपर की रेखा पर अधिक लागत होगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि समोत्पत्ति वक्र दो हुई मात्रा के उत्पादन के लिए दो साधनों की विभिन्न मात्राएँ प्रदर्शित करता है जबकि समलागत रेखाएँ दो साधनों की दिये हुए व्यय पर श्रम की जाने वाली मात्राएँ प्रदर्शित करते हैं।

## बाजार की अवस्थाएं (Types of Markets)

*'We must therefore define a market as any area over which buyers and sellers are in such close touch with one another, either directly or through dealers, that price obtainable in one part of the market affect the prices paid in other parts'*

Benham

'विनिमय' में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अपना कुछ विशेष अर्थ होता है। अतः यह आवश्यक है कि 'विनिमय' के सिद्धांतों का विवेचन करने के पूर्व उन शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय, जिनका प्रयोग विनिमय में किया जाता है।

### 1 बाजार (Market)

1 अर्थ 'विनिमय' के लिए बाजार का होना आवश्यक है। जहाँ विनिमय होता है उसे बाजार कहते हैं। माघारण बोलचाल की भाषा में 'बाजार' शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। परन्तु अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ कोई स्थान अथवा क्षेत्र नहीं है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है। इसका अभिप्राय उस सम्पूर्ण क्षेत्र से है जहाँ वस्तु-विशेष के क्रयकर्ता तथा विक्रेताओं में स्पर्धा तथा सम्पर्क रहता है जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु का मूल्य लगभग समान रहता है।

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर बाजार की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :  
(i) वस्तु के विक्रेताओं का होना, (ii) वस्तु के क्रयकर्ताओं का होना, (iii) क्रयकर्ता तथा विक्रेताओं में पारस्परिक सम्बन्ध होना, (iv) उनमें स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होना, तथा (v) वस्तु की किस्म का एक होना।

कुछ अर्थशास्त्री 'एक मूल्य' का होना भी बाजार की एक विशेषता मानते हैं। परन्तु जहाँ पर उपरोक्त विशेषताएँ पायी जाती हैं, वहाँ यह स्वाभाविक है कि एक

बाजार मूल्य ही पाया जायेगा, अथवा एक ही बाजार-मूल्य होने की प्रवृत्ति होगी। यह ध्यान रहे कि एक वस्तु के विभिन्न मूल्य हो सकते हैं, परन्तु एक वस्तु के जितने ही मूल्य होंगे, उसके उतने ही बाजार होंगे। यदि एक वस्तु की विभिन्न किस्में हैं, तो पृथक्-पृथक् वस्तुएं मानी जायेंगी तथा उन किस्मों के अनुसार उतने ही पृथक् बाजार भी होंगे।

**अन्य परिभाषाएँ :** यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं पर विचार कर लेना भी आवश्यक है। कूर्नो (Cournot) के अनुसार, 'बाजार' का अर्थ "किमी स्थान-विशेष से नहीं है जहाँ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, किन्तु उन पूरे प्रदेश से है जिसमें क्रेता व विक्रेता एक दूसरे से ऐसे सम्बन्ध संबंध में होते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में शीघ्रता और सरलता से समान होने की प्रवृत्ति होती है।"<sup>1</sup> सिडग्विक (Sidgwick) के अनुसार बाजार 'व्यक्तियों का कोई समूह है जिसमें ऐसे पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध हों कि प्रत्येक व्यक्ति उन दलों से अवगत हो सके जिन पर दूसरे व्यक्ति समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया करते हैं।"<sup>2</sup>

जेवन्स (Jevons) ने अपनी पुस्तक "Theory of Political Economy" में यह मत प्रकट किया है कि बाजार शब्द 'इस प्रकार साधारणकृत कर दिया गया है कि उसका तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है जिनमें व्यापारिक सम्बन्ध होते हैं और जो किसी वस्तु का विस्तृत व्यापार करते हैं।"<sup>3</sup> चैपमैन (Chapman) के अनुसार, "बाजार शब्द आवश्यक रूप से स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि वस्तु अथवा वस्तुओं तथा क्रेताओं और विक्रेताओं का ज्ञान कराता है जिनमें पारस्परिक स्पर्धा रहती है।"<sup>4</sup>

<sup>1</sup> "Economists understand by the term market not any particular market place in which things are bought and sold but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly"  
—Cournot

<sup>2</sup> "... as a body of persons in such commercial relations that each can easily acquaint himself with the rates at which certain kinds of exchange of goods or services are from time to time made by the others"  
—Sidgwick

<sup>3</sup> "... but the word has been generalised so as to mean any body of persons who are in intimate business relations and carry extensive transactions in any commodity."  
—Jevons

<sup>4</sup> "The term refers not necessarily to a place but always to a commodity or commodities and the buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another."  
—Chapman

इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाजार की विभिन्न विशेषताओं पर जोर दिया है। उपरोक्त परिभाषाओं में कौनों एक प्रदेश की बात करते हैं जबकि जेवन्स ने केवल क्रेताओं तथा विक्रेताओं के पारस्परिक सम्बन्ध पर विशेष बल दिया है। इसी प्रकार अन्य अर्थशास्त्रियों में सीगर ने भी स्थान शब्द पर जोर दिया है जबकि एली (Ely) के मत में बाजार के लिए पारस्परिक स्पर्धा का होना अति आवश्यक है।

## 2. विस्तृत बाजार की दशाएँ : (Conditions for a Wide Market) :

आधुनिक युग में किसी भी वस्तु के बाजार का विस्तृत बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में ऐसी दशाओं का वर्णन किया है, जो किसी वस्तु के विस्तृत बाजार होने के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि प्रो० मेहता के मत में ये दशाएँ अनावश्यक हैं, क्योंकि उनके अनुसार बाजार “एक दशा-विशेष है तथा किसी दशा को विस्तृत या सकीर्ण कहना वास्तव में निरर्थक है।” उनके अनुसार “बाजार शब्द एक स्थिति का बोध कराता है जिसमें किसी वस्तु की माग उस स्थान पर होनी है जहाँ वह वह बिक्री के लिए प्रयुक्त की जानी है।”<sup>5</sup> फिर भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी वस्तु का बाजार विस्तृत या सकुचित हो सकता है। व्यावहारिक जगत् में हम यह देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का बाजार संसार-व्यापी है तथा कुछ का केवल स्थानीय (local)। किसी वस्तु-विशेष के बाजार के विस्तृत होने के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। इन दशाओं को दो भागों में बाटा जा सकता है। (i) बाह्य परिस्थितियाँ, तथा (ii) वस्तुगत गुण।

### (i) बाह्य परिस्थितियाँ (Conditions within a Country) :

(1) देश में शांति सुरक्षा तथा अच्छे शासन का होना : यदि देश के अन्दर शांति और सुरक्षा नहीं है, तो कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलतापूर्वक नहीं भेजी जा सकती। किसी देश में शांति, सुरक्षा तथा अच्छी शासन-व्यवस्था रहने पर, वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है।

(2) परिवहन तथा संचार बहन के साधनों का विकास (Developed means of Transport and Communications) : संचार-वहन तथा परिवहन के साधनों के विकसित होने पर, वस्तुओं के सौद करने तथा उनके स्थानान्तरण में सुविधा होती है। फलस्वरूप वस्तुओं का बाजार किसी राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं रहता, बरन् वह अन्तर्राष्ट्रीय हो जाता है।

### (3) मुद्रा तथा साख-प्रणाली (Currency and Credit System) :

<sup>5</sup> “The word market signifies a state in which a commodity has demand at a place where it is offered for sale.”— J K. Mehta

उपयुक्त मुद्रा नीति, विक्रमित बैंक तथा साख-व्यवस्था बाजार के विकास में सहायक होते हैं। यदि सरकारी साख एवं मुद्रा नीति स्थायी है तथा उसमें जनता का पूर्ण विश्वास है तो वस्तुओं का क्रय-विक्रय दूर-दूर के स्थानों में बड़ी मरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है।

(4) सरकारी नीति (The Government Policy) : सरकारी नीति भी बाजार के क्षेत्र को सीमित तथा विस्तृत बनाती है। सरकार नियंतात्मक कर लगाकर तथा कोटा (Quota) निश्चित करके किमी भी वस्तु के बाजार को सीमित कर सकती है।

(5) श्रम-विभाजन (Division of Labour) : आधुनिक युग में श्रम-विभाजन का अत्यधिक महत्व है। जहां पर जितना ही अधिक श्रम विभाजन होगा, वहां पर वस्तुएं उतनी ही मस्ती होगी। परिणामस्वरूप उनकी मांग अधिक होगी और बाजार विस्तृत होगा।

(6) विज्ञापन, प्रदर्शनी आदि (Advertisement, Exhibitions etc.) : उत्पादन प्रणाली में ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक साधनों का अधिकधिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है, त्यो-त्यो विज्ञापन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। जिन वस्तुओं का व्यवस्थित विज्ञापन होता है, उनकी मांग अधिक होती है। इस प्रकार विज्ञापन तथा प्रचार के अन्य साधनों की सहायता से बाजार को विस्तृत बनाया जा सकता है।

(ii) वस्तुगत गुण (The Character of the Commodity) :

किमी वस्तु के बाजार के विस्तृत होने के लिए केवल बालू वातावरण का अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बिस्तार पर वस्तु के भौतिक गुणों का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। ये गुण निम्नलिखित हैं।

(1) वहनीयता (Portability) : जो वस्तुएं कम व्यय पर तथा मरलतापूर्वक स्थानान्तरणीय होती हैं, उनका बाजार विस्तृत होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वस्तु का भार व आकार उसके मूल्य के अनुपात में कम हो।

( ) मांग की प्रकृति (The Nature of Demand) : किमी वस्तु की मांग अधिक हान पर उसका बाजार भी विस्तृत होगा। इसके विपरीत मांग के सीमित होने पर बाजार संकुचित होगा। मांग में वृद्धि नियमित रूप से होनी चाहिए। परिवर्तनशील मांग होने पर, अर्थात् मांग के घटते बढ़ते रहने पर बाजार अधिक विस्तृत नहीं होता।

(3) टिकाऊपन (Durability) : शीघ्र न नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। उन वस्तुओं की अधिक दिनों तक रखा जा सकता है तथा उन्हें दूर-दूर के स्थानों का भेजा जा सकता है। शीघ्र नष्ट होन वाली वस्तुओं, जैसे साग, सब्जी, फल, दूध, मछली आदि का बाजार विस्तृत नहीं होता।

(4) **अनुसंधान तथा प्रमाणीकरण के योग्य होना (Suitability for Grading, Sampling etc)** : यदि किसी वस्तु के नमूने अच्छी प्रकार के बनाये जा सकते हैं तो उन्हें दूर के व्यवसायियों के पास भेजा जा सकता है और वे उन्हें घासानी में क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका वितरण सरलतापूर्वक किया जा सके। इन मुद्दियों के होने से क्रेता को वस्तु का चुनाव करने के लिए उसके उत्पादन-स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। नमूने भेज कर तथा वस्तुओं के व्यापारिक चिन्ह (Trade Marks) निर्धारित करके, ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी करायी जा सकती है।

(5) **अधिक मात्रा में पूर्ति (Large Supply)** : यदि किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार शीघ्र बढ़ायी जा सकती है, तो उसका बाजार विस्तृत होगा। इसके विपरीत स्थिति में उसका बाजार सीमित होगा।

### 3 बाजार का वर्गीकरण (Types of Markets)

बाजार कई प्रकार के होते हैं। मुविद्या की दृष्टि से बाजार को चार मुख्य शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। (i) स्थान या क्षेत्र के अनुसार, (ii) समय के अनुसार, (iii) कार्य के अनुसार, तथा (iv) परिस्थितियों या प्रतिभेदों के अनुसार।

(i) **स्थान या क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण (According to Place or Region)** स्थान या क्षेत्र के अनुसार बाजार के वर्गीकरण का उसका भौगोलिक विकास (Geographical Evolution) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत जब वस्तुओं का विनिमय किसी परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है, तब इसे कौटुम्बिक बाजार (Family Market) कहा जाता है। परन्तु यदि किसी वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं के विनिमय-कार्य या उनकी व्यापारिक क्रियाएँ किसी एक स्थान विशेष नगर या ग्राम तक ही सीमित हो तब उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार (Local Market) कहा जायेगा। ऐसे बाजार के क्रेता व विक्रेता उन्हीं स्थान के होते हैं। राष्ट्रीय बाजार (National Market) उस बाजार को कहा जाता है, जब कि किसी वस्तु का क्रय-विक्रय किसी स्थान, प्रान्त या राज्य तक सीमित न होकर देश-व्यापी होता है। परन्तु इसका विस्तार देश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। इसके अन्तर्गत भी जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय किसी नगर या ग्राम की सीमाओं को पार कर, किसी प्रान्त (Province) या राज्य (State) के सीमाओं तक ही सीमित रहता है, तब इसे प्रान्तीय या राज्य बाजार (Provincial or State Market) कहा जायेगा। अन्त में, जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता है तथा उसके क्रेता तथा विक्रेता सम्पूर्ण समार में फैल होते हैं, तब ऐसी वस्तु का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी (International Mar-

ket) कहलाता है। ऐसे बाजार में विश्व के सभी जेनाओं तथा विजेनाओं में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है।

(ii) समयानुसार वर्गीकरण (According to Time) : समय के अनुसार बाजारों या वर्गीकरण दैनिक (Daily), अल्पकालीन (Short Period) तथा दीर्घकालीन (Long Period) बाजारों में किया जा सकता है। दैनिक बाजार में किसी वस्तु के खय-विक्रय की क्रियाएँ कुछ ही घंटों या एक या दो दिनों तक ही की जाती हैं। ऐसा बाजार वास्तव में अति अल्पकालीन होता है। इसमें माग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती। अल्पकालीन बाजार (Short Period Market) का समय दैनिक बाजार के समय से कुछ अधिक लम्बा होता है। प्रायः इसका समय कुछ महीनों या एक वर्ष तक रहता है। अल्पकालीन बाजार में दैनिक बाजार की अपेक्षा पूर्ति में वृद्धि कुछ सीमा तक ही की जा सकती है। परन्तु अधिक समय न होने के कारण उपलब्ध उत्पादन साधनों का अधिकतम प्रयोग तथा विदेशों में वस्तुओं का आयात करने सामर्थ्य माग की पूर्ति कर दी जाती है। परन्तु इस काल में पूँजी-निर्माण सम्भव न हो सकने के कारण निरन्तर बढ़ती हुयी माग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती। इसीलिए यह कहा जाना है कि अल्पकालीन बाजार में, यद्यपि माग और पूर्ति का सम्बन्ध कुछ समय के लिए सम्भव हो पाता है फिर भी बाजार मूल्य निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा माग का अधिक महत्व होता है। इस बाजार में प्रायः वस्तु का बाजार-मूल्य उत्पादन-लागत के लगभग बराबर या कम होता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन बाजार (Long period market) में समय सीमित नहीं होता। यह महीनों तथा वर्षों तक चलता रहता है। इस काम में उत्पादन साधनों की अधिक विस्तार करके तथा पूँजी निर्माण द्वारा पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। फलस्वरूप ऐसे बाजार में माग की अपेक्षा पूर्ति, मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। वस्तु के बाजार में उत्पादन की, बढ़ती हुयी माग से लाभ होता है, क्योंकि इसमें जब तक उत्पादन साधना तथा पूँजी का स्थायी रूप से विकास नहीं हो जाता, तब तक वस्तु का मूल्य ऊँचा रहेगा। कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है। दीर्घकालीन बाजार मूल्य को ही 'सामान्य मूल्य' (Normal Price) कहते हैं।

(iii) कार्यानुसार वर्गीकरण (According to Functions) :

(अ) सामान्य अथवा मिश्रित बाजार (General or Mixed Market), इस प्रकार के बाजार में विविध प्रकार की वस्तुओं का खय-विक्रय किया जाता है।

(ब) विशिष्ट बाजार (Specialized Market) : प्रत्येक वस्तु के बाजार को विशिष्ट बाजार कहा जाता है, क्योंकि उसमें उस वस्तु विशेष के ही विभिन्न प्रकारों का खय-विक्रय किया जाता है। उदाहरणार्थ, सरसिया या सोन चादी का बाजार, अनाज मण्डी, अथवा बाजार आदि।



(त) नमूनों द्वारा बिक्री (Marketing by Samples) : वस्तुओं के प्रमापित होने पर जब उनके नमून तैयार करने में सुविधा होती है, तब उनका क्रय विनय नमूनों के आधार पर ही किया जाता है। अतः ऐसे बाजार नमूनों द्वारा बिक्री के बाजार कहलाते हैं।

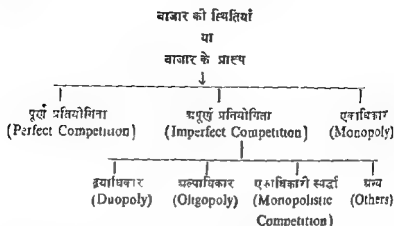
(द) श्रेणियों के आधार पर बिक्री (Marketing by Grades) : जिन वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करके उनके गुणों तथा उनकी किस्मों के आधार पर वर्गीकृत करने तथा किस्मा और श्रेणियों के आधार पर उनके नामों या चिह्नों के आधार पर हो होता है। इस विधि द्वारा खरीद व बिक्री होने पर केना वस्तु के नमूने नहीं देयता।

(iv) परिस्पर्धित तथा प्रतियोगिता के आधार पर (On the Basis of Competition) - प्रतियोगिता के आधार पर किसी बाजार को पूर्ण बाजार (Perfect Market) तथा अपूर्ण बाजार (Imperfect Market) में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूर्ण बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार में है जिसमें केना तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं तथा उनमें पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होती है, जिनके फलस्वरूप बाजार में एक वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। इसके विपरीत अपूर्ण बाजार में ये दम्राएँ नहीं पायी जाती। एहम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों ने पूर्ण बाजार की कल्पना की थी, परन्तु व्यावहारिक रूप से पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं पायी जाती। अतः यह कहा जाता है कि पूर्ण बाजार का अस्तित्व काल्पनिक है।

### बाजार की स्थितियाँ

#### (Market Situations)

कोई फर्म किसी वस्तु का कितना उत्पादन करेगी तथा बाजार में वह वस्तु किस मूल्य पर बेची जायेगी, ये बातें बाजार के रूप या उसकी स्थितियों (situations) पर निर्भर करती हैं। वस्तुओं की प्रकृति, केना तथा विक्रेताओं की संख्या तथा उनमें पारस्परिक सहयोग एवं निर्भरता आदि अनेक बातें बाजार के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। बाजार के स्वरूपों को दो सम्राएँ हैं। एक और पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) तथा दूसरी और एकाधिकार (Monopoly)। इन दोनों स्थितियों के बीच अन्य कई अवस्थाएँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से बाजार की तीन स्थितियाँ होती हैं जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है।



बाजार की उपर्युक्त विभिन्न स्थितियों में मुख्य किस प्रकार प्रभावित होता है ? इस बात की जानकारी के पूर्व यह आवश्यक है कि 'स्पर्धा' या 'प्रतियोगिता' (Competition) शब्द का आर्थिक अभिप्राय जान लिया जाय। स्पर्धा के लिए स्टिगलर (Stigler) ने तीन चीजें दी हैं (1) प्रत्येक आर्थिक इकाई इतनी छोटी होती है कि उसका प्रभाव मूल्य पर बहुत कम पड़ता है, (2) सरकार या व्यक्तिगत संस्थाएँ उत्पादन के साधनों के पूर्ण उपयोग पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जाता है, तथा (3) इसी प्रकार प्रत्येक माहूमी की वस्तु के मूल्य का पूर्ण ज्ञान रहना है और उसे अपने नाम की जानकारी रहती है। बाजार के रूप स्पर्धा या प्रतियोगिता की इन जतों पर निर्भर करते हैं जैसा कि बाजार की विभिन्न स्थितियों के निम्नलिखित विवेचन में स्पष्ट है।

### पूर्ण स्वधा या प्रतियोगिता (Pure Competition) :

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है बाजार के रूपों की दो सीमाओं में एक और 'पूर्ण प्रतियोगिता' की स्थिति है। 'पूर्ण स्पर्धा या प्रतियोगिता' शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा पूर्ण स्पर्धा तथा शुद्ध स्पर्धा (Pure Competition) में भेद किया है और वे 'पूर्ण स्पर्धा' की अपेक्षा 'शुद्ध स्पर्धा' शब्द का प्रयोग करना अधिक पसन्द करते हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि 'पूर्ण स्पर्धा' में 'शुद्ध स्पर्धा' की भावना पूर्णतया निहित है। फिर भी इन दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिए इनकी निम्नलिखित परिभाषाएँ एवं विशेषताओं का उल्लेख किया गया है :

### पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा (Definition of Perfect Competition) :

पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु का एक ही मूल्य होता है, क्योंकि कोई भी नेता या विजेता व्यक्तिगत रूप से

बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। श्रीमती जोन राबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के शब्दों में, “पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उस समय पायी जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक का उत्पादन की मात्रा पूर्णतया लोचदार होती है। इसका तात्पर्य यह प्रथम, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे कि किसी एक विक्रेता (उत्पादक) का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा अंश होता है, तथा द्वितीय, सभी क्रेता, प्रतिभागी विक्रेताओं के मध्य चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है।”

### पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ

पूर्ण प्रतियोगिता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है

(1) स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं तथा विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है। उनके व्यवसाय का आकार बहुत ही छोटा होता है। यही कारण है कि उनके द्वारा किये गये उत्पादन की मात्रा कुल उत्पादन का इतना थोड़ा भाग होता है कि वह उसमें कमा या वृद्धि करके भी वस्तु के बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रत्येक क्रेता बाजार में कुल पूर्ण का इतना कम भाग खरीदता है कि उसके द्वारा क्रय की गयी मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर भी बाजार मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें यह स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में मूल्य निर्धारण सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं की व्यापारिक क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव से होता है तथा ‘एक मूल्य’ के निश्चित हो जाने पर उसमें परिवर्तन कठिन हो जाता है।

स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अभिप्राय यह है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं में कोई पारस्परिक सम्बन्धता या गुप्त सन्धि नहीं होती। यही कारण है कि व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते हुए बाजार मूल्य का प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि यद्यपि न तो क्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु

\* “Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails first that the number of sellers is large, so that the output of any one seller is negligibly small proportion of the total output of the commodity, and second, that buyers are all alike in respect of their choice between rival sellers, so that the market is perfect.”

—Mrs Joan Robinson.

की कुल माग या पूर्ति में कमी या वृद्धि करके उसके मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता फिर भी एक प्रतियोगी उद्योग में समस्त उत्पादक सामूहिक रूप से कुल उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि करके बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रेता भी एक समूह के रूप में वस्तु की कुल माग की मात्रा में कमी या वृद्धि करके बाजार मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं।

(ii) विषय की जाने वाली वस्तु का प्रमाणित तथा एक रूप होना : (Standardised and Homogenous Commodity) उत्पादित या विक्रय की जाने वाली वस्तु प्रमाणित तथा एक सी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि विक्रेताओं अथवा उत्पादकों में एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात् वस्तु विभेद अथवा उनके स्थान उनकी रगति अथवा उनके व्यक्तित्व में अन्तर होने के कारण क्रेता को एक विक्रेता की अपेक्षा दूसरे विक्रेता को पसन्द करने का अवसर मिल सके। वस्तु की इकाइयों के एकरूप होने पर तथा विक्रेताओं की स्थिति समान होने पर वस्तु विभेद (Product differentiation) का प्रारण नहीं उठता तथा क्रेता वस्तु की सभी इकाइयों तथा सभी विक्रेताओं को समान महत्त्व देते हैं। इस प्रकार क्रेता के दृष्टिकोण से सभी विक्रेताओं अथवा फर्मों की वस्तुओं की इकाइयाँ एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी वस्तु का मूल्य किसी विक्रेता के द्वारा यदि थोड़ा सा भी बढ़ा दिया गया तो उसके सभी ग्राहक किसी अन्य विक्रेताओं के पास चले जायेंगे। विक्रेता प्रचलित मूल्य पर ही अपनी वस्तु का बेच कर लाभ कमाता है, अतः यह उसके मूल्य को कम भी नहीं करता।

(iii) बाजार का पूर्ण ज्ञान क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए। यह उसी समय सम्भव हो सकता है जबकि क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट सम्पर्क होता है। निकट सम्पर्क होने पर ही यह भी ज्ञात हो सकता है कि क्रेता तथा विक्रेता किस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदने अथवा बेचने के लिए तत्पर हैं।

(iv) फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व वृद्धिमान पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में नये उत्पादकों या फर्मों का उद्योग में प्रवेश करने अथवा उससे हटने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि फर्मों या उद्योगपतियों को उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार प्राप्त करके वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है। इससे साथ ही फर्मों के आगमन व निवर्तन का प्रभाव लाभ पर भी पड़ता है। दीर्घकाल में फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है।

(१) नियंत्रण एवं प्रतिबन्ध का अभाव किसी भी फर्म की व्यावसायिक क्रियाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। उत्पादन साधना में गतिशीलता होनी चाहिए।

(ii) सभी उत्पादकों या फर्मों का निकट होना स्टोनियर व हेग (Stonier and Hague) ने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के लिए यह माना है कि समस्त उत्पादक एक दूसरे के काफी समीप होना चाहिए जिससे उनकी कोई परिवहन लागत न हो। इससे बाजार मूल्य एक ही रहेगा।

**शुद्ध स्पर्धा या परमाणुवादी प्रतियोगिता (Pure Competition or Atomistic Competition)**

चैम्बरलिन (Chamberlin) ने शुद्ध स्पर्धा तथा पूर्ण स्पर्धा में भेद किया है। शुद्ध स्पर्धा उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एकाधिकार (monopoly) का कोई लक्षण या तत्व कहीं पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री इस प्रकार की स्पर्धा या प्रतियोगिता के लिए 'परमाणुवादी प्रतियोगिता' (atomistic Competition) शब्द का प्रयोग करते हैं।

शुद्ध प्रतियोगिता के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की तीन दशाओं का होना ही आवश्यक है। इन दशाओं को शुद्ध स्पर्धा की विशेषताएँ कहा जा सकता है। ये दशाएँ हैं

(i) स्वतन्त्र रूप में कार्य करने वाले जेताओं तथा विजेताओं की संख्या अधिक होती है, (ii) विजय की जाने वाली वस्तु प्रमाणित एवं एकसूत्र होती है तथा वस्तु विभेद नहीं होता, तथा (iii) उद्योग में फर्मों का आगमन अथवा उन्मेष उनका निगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। वे उद्योग में प्रवेश करने अथवा उससे बाहर चले जाने के लिए स्वतन्त्र होती हैं।

पूर्ण स्पर्धा तथा शुद्ध स्पर्धा में अन्तर पूर्ण स्पर्धा तथा शुद्ध स्पर्धा की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि शुद्ध स्पर्धा तथा पूर्ण स्पर्धा में कोई विशेष मौलिक अन्तर नहीं है। शुद्ध स्पर्धा में भी पूर्ण स्पर्धा की तीन दशाएँ निहित हैं। यही कारण है कि दोनों की मात्रा में अन्तर है, अर्थात् शुद्ध स्पर्धा की स्थिति अधिक सरल एवं कम विस्तृत है जबकि पूर्ण स्पर्धा अधिक विस्तृत है। पूर्ण स्पर्धा की ही तरह नया तथा विजेता व्यक्तिगत रूप से मूल्य प्रभावित नहीं कर सकते।

\* "An absence of friction in the sense of an ideal fluidity or mobility of factors such that adjustment to changing conditions which actually involve time are accomplished instantaneously in theory"

—Chamberlin

दोनों ही स्थितियों में उत्पादक या फर्म की कोई मूल्य नीति नहीं होती। उत्पादक या विनैता प्रचलित मूल्य के अनुसार ही अपनी उत्पादन-मात्रा का समायोजन करता है। वह मूल्य निर्धारक न होकर 'मूल्य ग्रहण करने वाला' ही होता है।

चेम्बरलिन (Chamberlin) ने पूर्ण स्पर्धा उत्त स्थिति को बतलाया है जिसमें घर्षण (Friction) का अभाव होता है, अर्थात् उसमें साधनों का ऐसा बहाव होता है या ऐसी गतिशीलता होती है कि परिवर्तनशील दशाओं के साथ सैद्धांतिक रूप से तत्क्षण ही समायोजन हो जाता है जिसमें कि वास्तव में काफी रागव लगता है। ऐसे बाजार में अपूर्णताओं (Imperfections) का अभाव रहता है। बाजार सम्बन्धी अपूर्णताएँ दो प्रकार की होती हैं।

(अ) बाजार के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव : बाजार सम्बन्धी ज्ञान का अभाव सामान्य उत्पादकों में होता है। वे अपने साधनों के उचित तथा अनुकूलतम अनुपात में उपयोग के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखते।

(ब) उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव : नये साधनों के प्रवेश पर रोक लगाने में उनकी गतिशीलता समाप्त हो जाती है। इसके प्रतिरक्त कुछ उत्पादक विशेष प्रकार के साधनों के नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी नहीं रखते, जिससे उत्पादन अधिक मात्रा में सम्भव नहीं होता।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्ण स्पर्धा में उत्पादन के साधनों की स्वतंत्र गतिशीलता होती है, जबकि शुद्ध स्पर्धा में इस प्रकार की गतिशीलता का अभाव होता है। पूर्ण स्पर्धा में किसी विनैता की अपनी मूल्य नीति नहीं होती। एक व्यक्तिगत फर्म की विक्रय की तात्कालिक या माय रेखा बिल्कुल सीधी होती है। इसका अर्थ यह है कि फर्म किसी भी मात्रा में अपनी वस्तु को बाजार मूल्य पर बेच सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से क्रेता भी केवल मूल्य से प्रभावित होता है। क्रेता का सम्बन्ध किसी विनैता विशेष से नहीं होता, क्योंकि सभी वस्तुएँ समान होती हैं।

## 2. एकाधिकार (Monopoly)

एकाधिकार (Monopoly) में दो शब्द हैं—Mono + poly'. Mono का अर्थ है 'एक' और 'Poly' का अर्थ है 'उत्पादक' अतः Monopoly का शाब्दिक अर्थ है—'एक उत्पादक'। इस प्रकार एकाधिकार में एक ही उत्पादक होता है या वस्तु की पूर्ण उत्पादकों के एक समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। इस आधार पर ही एकाधिकार पूर्ण स्पर्धा से भिन्न है। एकाधिकार की स्थिति में फर्म तथा उद्योग एक ही होता है। ऐसे एकाधिकार को 'पूर्ण' (Absolute) या शुद्ध (Pure) एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार को दूसरी

विशेषता यह होती है कि एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी स्थानापन्न वस्तु (Substitute) नहीं मिलती। एकाधिकारी के अधिकार बहुत से होते हैं। पूर्ति या मूल्य पर उमका पूर्ण नियन्त्रण होता है। उत्पादन के साधन भी उसके अधिकार में होते हैं। इस प्रकार वह दूसरी फर्मों को उद्योग में आने से रोकता है।

### 3. अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition)

वास्तविक जगत में न तो पूर्ण स्पर्धा पाई जाती है और न पूर्ण एकाधिकार ही। पूर्ण एकाधिकार के स्थान पर थोमसी जोन रॉबिन्सन के अनुसार 'अपूर्ण' प्रतियोगिता (Imperfect Competition) तथा चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार-प्रतियोगिता (Monopolistic Competition) की स्थिति अधिक व्यापक है। पूर्ण स्पर्धा तथा पूर्ण एकाधिकार के मध्य बाजार की अन्य कई अवस्थाएँ हैं। अपूर्ण स्पर्धा (Imperfect Competition) के विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत एकाधिकारी स्पर्धा (Monopolistic Competition), द्व्याधिकार या द्वि-अल्पाधिकार तथा अल्पाधिकार (Oligopoly) की स्थितियाँ सम्मिलित होती हैं।

अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ पूर्ण स्पर्धा की दशाओं में किसी दशा के अभाव में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है पूर्ण स्पर्धा में अपूर्णताओं (Imperfections) का अभाव रहता है परन्तु बाजार में अपूर्णताओं के उपस्थित होने पर, वहाँ अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पायी जाती है। यदि (i) केनाओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होती, या (ii) वस्तुएं प्रमापित या एकरूप नहीं होती या (iii) केनाओं व विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान नहीं होता तो स्वाभाविक है कि बाजार में एक मूल्य नहीं होता। बाजार की ऐसी स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहा जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में व्यक्तिगत फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार (Perfectly elastic) नहीं होती।

जैसाकि ऊपर बताया गया है अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे (1) केनाओं व विक्रेताओं की संख्या कम होना इस स्थिति में वे व्यक्तिगत रूप से मांग अथवा पूर्ति में कमी व वृद्धि करके बाजार मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, (ii) वस्तुओं की इकाइयों का एकरूप न होना - विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों में समानता न होने पर उनके मूल्यों में अन्तर होना स्वाभाविक है। विक्रेताओं के व्यक्तिगत गुणों, उनके व्यापार स्थानों, वस्तुओं की इकाइयों के गुणों में विभिन्नता, विज्ञापन एवं प्रचार का प्रयोग आदि कारणों से भी वस्तु के बाजार मूल्य में भिन्नता हो जाती है। (iii) केनाओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान न

उत्पादों तथा विक्रेताओं को बाजार में वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा तथा उनके मूल्यों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी नहीं रहने पर भी बाजार मूल्य में निम्नता होगी। (iv) वस्तुओं में अस्थिरता (immobility) : पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में उत्पादों में गतिशीलता होती है, परन्तु जब उत्पाद अपनी गुणों के कारण बाजार में प्रचलित कम मूल्यों पर वस्तु नहीं गरीदते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि बाजार में कई मूल्य प्रचलित होंगे। (v) यातायात व्यय का ऊँचा होना : यदि उत्पादक या फर्म समीप नहीं हैं तो वस्तुओं को लाने व लाने पर यातायात लागत ऊँची पड़ेगी जिससे वस्तुओं के मूल्य घटाने नहीं होंगे।

### (i) द्वयाधिकार या द्वि-अल्पाधिकार (Duopoly)

जब किसी वस्तु की कुल पूर्ति दो फर्मों या व्यक्तियों द्वारा की जाती है तब इसे द्वयाधिकार कहते हैं। यह बाजार की वह व्यवस्था है जिसमें दो फर्मों या तो एक प्रमाणित वस्तु का उत्पादन करती हैं या ऐसी दो वस्तुएँ उत्पादित करती हैं जिनमें बहुत कम अन्तर होता है। सामान्यतया दो वस्तुएँ एक ही प्रकार की होती हैं। यदि ये फर्म दो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करें तो दोनों फर्मों को अलग अलग एकाधिकारी फर्म कहा जायेगा। यह स्थिति द्वयाधिकार की स्थिति नहीं होगी।

### (ii) विक्रेता अल्पाधिकार (Oligopoly)

अल्पाधिकार (Oligopoly) एक ग्रीक (Greek) शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ विक्रेता (a few sellers) यदि किसी वस्तु की कुल पूर्ति कुछ फर्मों या कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही की जाती है तो ऐसी स्थिति को अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। इस अवस्था में पूँजी विरुद्ध बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वे माल की पूर्ति तथा उनके मूल्यों के प्रति मजबूत रहते हैं, क्योंकि एक विक्रेता का व्यावसायिक नीति का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। इस प्रकार सभी विक्रेताओं में मूल्य तथा उत्पादन की नीति के सम्बन्ध में अन्तर्सम्बन्ध होता है।

द्वयाधिकार की अवस्था में दो विक्रेताओं के होने से उनमें अत्यधिक स्पर्धा होती है। उनमें किसी एक के द्वारा मूल्य उत्पादन-नीति में परिवर्तन किये जाने पर उस का प्रभाव दूसरे विक्रेता पर पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक परिवर्तन अन्य परिवर्तन को जन्म देता है।

यदि दोनों उत्पादक या विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तु (Identical goods) बेचते हैं तो इस वस्तु को 'समान उत्पाद वाला द्वयाधिकार' (Duopoly with homogeneous Products) कहते हैं। यदि दोनों फर्मों में कोई पारस्परिक समझौता नहीं है तो ग्राहक दोनों को समान समझते हैं, दोनों की अन्तःविषय की नीति



कोई अन्तर नहीं है तथा दोनों के उत्पादन व्यय बराबर हैं, तो ऐसी अवस्था में बाजार में एक ही मूल्य होगा तथा दोनों फर्मों कुल विक्रय में समान रूप में भागीदार होंगी।

अल्पाधिकार के कई रूप हो सकते हैं जैसे—(अ) शुद्ध अल्पाधिकार (Pure Oligopoly)। इसमें सभी फर्मों द्वारा समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, (ब) उपज विभेद अल्पाधिकार (Differentiated Oligopoly) : इसमें प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु एक दूसरे में भिन्न होती है, (स) सामूहिक अल्पाधिकार (Collective Oligopoly) : इसमें विक्रेताओं में पारस्परिक पूर्ण सम्बन्ध होता है, (द) आंशिक अल्पाधिकार (Partial Oligopoly) इसमें विक्रेताओं के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध टूट नहीं होता, तथा (घ) पूर्ण अल्पाधिकार (Complete Oligopoly) : इसमें विक्रेताओं में पारस्परिक समझौते के आधार पर पूर्ण सम्बन्ध होता है। अल्पाधिकार की इन विभिन्न अवस्थाओं में मूल्य तथा पूर्ति का निर्धारण अलग-अलग होता है।

### (iii) एकाधिकारिक प्रतियोगिता (Monopolistic Competition)

सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग Chamberlin ने अपनी पुस्तक 'The theory of Monopolistic Competition' में किया था। व्यावहारिक जगत् में न तो हम पूर्ण प्रतियोगिता या स्पर्धा की श्रिति पाते हैं और न ही पूर्ण एकाधिकार की। बहुत से उत्पादक जो अपूर्ण स्पर्धा की भावना रखते हैं (Imperfectly competitive producers) उनमें से अधिकांश ऐसा हैं जो लगभग समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। फलस्वरूप ये उत्पादक इस बात का मद्देन द्यान रखते हैं कि उनके प्रतियोगियों की उत्पादन तथा व्यावसायिक नीति क्या है? इस अवस्था को ही एकाधिकारी स्पर्धा (Monopolistic Competition) या समूह सन्तुलन (Group Equilibrium) कहते हैं। इस अवस्था में तीव्र स्पर्धा (Keen competition) होती है, परन्तु यह स्पर्धा पूर्ण नहीं होती। इन प्रकार एकाधिकारिक स्पर्धा की दो विशेषताएँ हैं (अ) विक्रेताओं का अधिक होना तथा (ii) विभिन्न उत्पादकों की वस्तुओं के में असमानता होने के कारण कौन अपनी रचि के अनुसार वस्तु-विशेष को पसन्द करते हैं, यद्यपि एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूरक या प्रतिस्थापक होती है।

वस्तुओं में विभिन्नता होने के कारण उत्पादक अथवा विक्रेता विज्ञापन पर अधिक ध्यान देता है। जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु के लिए अपनी रचि रखते हैं, तो उस वस्तु के उत्पादक का अपना वस्तु के बाजार पर एकाधिकार होता है। परन्तु वह एकाधिकार की नीति नहीं अपना सकता, क्योंकि बाजार में अन्य उत्पादकों द्वारा उसकी उत्पादित वस्तु की प्रतिस्पर्धी पूरक वस्तुएँ वर्तमान रहती हैं। इस प्रकार एकाधिकारिक स्पर्धा वह अवस्था है जिसमें स्पर्धा तथा एकाधिकार दोनों का ही

स्पर्धा के प्रकार (Types of Competition)

स्पर्धा के प्रकार (Kinds of competition)	फर्मों की संख्या No of Firms	वस्तु का रूप (Nature of Product)	मूल्य नियन्त्रण सीमा (Degree of Control over Price)	अन्य फर्मों का प्रवेश (Entry of other Firms)
पूर्ण स्पर्धा (Perfect Competition)	अनेक (Many)	एक रूप (Identical Product)	विरुद्ध नहीं (None)	बहुत सरलता पूर्वक (Easy entry)
एकाधिकृत स्पर्धा (Monopolistic Competition)	अनेक (Many)	वर्गीकृत, पर कुछ भेद (Differentiated similar but not the same)	थोड़ा (a little)	सरलता से (Entry with no Difficulty)
अल्पाधिकार (Oligopoly)	कुछ (a few)	एक-रूप या विभिन्न (same or with difference in product)	प्रतिस्पर्द्धियों में समझौता होने पर अधिक (More on agreement)	बहुत कठिन (Very Difficult)
द्वयाधिकार (Duopoly)	दो (Two)	सामान्यतया एकरूपता (Generally the same)	कुछ (Some)	कठिन (Difficult)
पूर्ण एकाधिकार (Complete Monopoly)	एक (One)	एक वस्तु बिना निकट स्थापना वस्तु के (Single product without close substitutes)	अधिक (Considerable)	असम्भव (Impossible)

सम्बन्ध होता है। इस अवस्था में स्पर्धा के कारण कीमतों की प्रवृत्ति समान होने की होती है। परन्तु इसके साथ ही साथ प्रत्येक फर्म का अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है तथा वस्तुओं में उपज असमानता (product differentiation) भी पाई जाती है। अतः विभिन्न फर्मों की उत्पादित वस्तुओं के मूल्य भी असम-अलग होते हैं।

### विभिन्न बाजार स्थितियों में अन्तर

विशेषताएँ (Characteristics)	पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect competition)	एकाधिकार (Monopoly)
1 कृता व विक्रेताओं की संख्या	बहुत अधिक	एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह
2 वस्तु का प्रकार	एक रूप (Homogeneous)	सबसे सख्त जितका कोई निकट स्मानापन्न नहीं होता
3 फर्म की माग की रीति	पूर्ण सोचदार	पूर्ण सोचदार से कम
4 कृताओं व विक्रेताओं में जानकारी की प्राप्ति	है	नहीं
5 फर्मों का प्रवेश या वृद्धिमान	स्वतन्त्र	पूर्णतया निषिद्ध
6 मूल्य पर नियन्त्रण की मात्रा	कुछ नहीं	पर्याप्त
7 अन्य प्रतिपदार्थ	कुछ नहीं	जनता से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए विभाजन आदि पर विशेष जोर

कुछ अर्थशास्त्रियों ने बाजार की इन अवस्थाओं के अनिश्चित कुछ अन्य अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है जैसे—(i) पूर्ण परन्तु एकाधिकारी (Perfect but monopolistic) (ii) शुद्ध परन्तु अपूर्ण (Pure but imperfect) तथा (iii) शुद्ध तथा पूर्ण (Pure and perfect)

कृता एकाधिकार का वर्गीकरण (Monopoly) केना एकाधिकार एकाधिकार की विपरीत स्थिति है। प्रायः एकाधिकार का अधिप्राय बाजार पर विक्रेताओं के पूर्ण अधिकार में लगाया जाता है, परन्तु कभी कभी किसी वस्तु विशेष के बाजार में बड़े विक्रेता हो और एक ही क्रेता हो तो ऐसी स्थिति में बाजार में एकमात्र क्रेता का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। केना एकाधिकारी (monopsonist) वस्तु विशेष के सम्पूर्ण बाजार पर इस प्रकार अपना नियन्त्रण रखता है कि वह कम मूल्य पर वस्तु विशेष ख़र करने में सफल होता है। 'विक्रेताओं को सब एकाधिकारी क्रेता के इच्छानुकूल मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

प्रो० मेहता ने ऐसे क्रेता एकाधिकारी को वस्तु विशेष के एकाकी क्रेता की सजा दी है। क्रेता-एकाधिकार की स्थिति एक व्यक्ति या फर्म अथवा उपभोक्ताओं के समूहों के द्वारा स्थापित की जा सकती है। कभी कभी सरकार भी वस्तु विशेष के बाजार पर क्रेता एकाधिकार स्थापित कर लेती है। जिस प्रणाली एकाधिकार की स्थिति में विक्रेता नेताओं का शोषण करते हैं, उसी प्रकार क्रेता एकाधिकार की स्थिति में क्रेता द्वारा विक्रेताओं का शोषण किया जाता है।

**द्विक्रेता-अल्पाधिकार (Duopsony)** - द्वि-क्रेता अल्पाधिकार की स्थिति में किसी वस्तु विशेष के बाजार में एकाकी क्रेता के स्थान पर दो क्रेता तथा कई विक्रेता होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों क्रेताओं को बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिये (i) एक ही प्रकार की वस्तु रहने पर पारस्परिक समझौते द्वारा मिलकर बाजार पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लें, या (ii) अपना-अपना अलग बाजार क्षेत्र निर्धारित कर लें, जिस पर प्रत्येक का पूर्ण नियन्त्रण हो। उपर्युक्त (product differentiation) की स्थिति में दोनों वस्तुओं के बाजार अलग अलग होते हैं।

**क्रेता अल्पाधिकार (Oligopsony)** : इस स्थिति में बाजार में छोटे क्रेता तथा कई विक्रेता होते हैं।

### प्रश्न व सकेत

1. 'पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या बात है।' इस कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए। [धकेत : पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास कीजिए कि व्यावहारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये मान्यताएँ प्रवास्तविक हैं।]

2. उन तत्वों को बताइए जो कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के कार्य कारण में बाधाएँ डालते हैं।

(Jabalpur, B, com II, 1963, Agra B, com I, 1960)

[संकेत : सर्व प्रथम बहुत संक्षेप में पूर्ण प्रतियोगिता का आशय स्पष्ट कीजिए और इसके पश्चात् पूर्ण प्रतियोगिता का आशय स्पष्ट कीजिए और इसके पश्चात् पूर्ण प्रतियोगिता के कार्य कारण में बाधा डालने वाले या अपूर्ण प्रतियोगिता के कारणों का विवेचन कीजिए।]

3. निम्न के अन्तरो को स्पष्ट रूप से बताइए -

(i) पूर्ण बाजार तथा अपूर्ण बाजार (Perfect market and imperfect Market)

(11) एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता (Monopoly and Monopolistic competition (Ravishankar, B, com. I, 1965)

4 "अतः अर्थशास्त्री कहते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में, प्रत्येक फर्म प्रतिस्थापन के बिन्दु तक एक एकाधिकारी की भाँति होती है, परन्तु इस बिन्दु के आगे बाजार स्पर्धात्मक होता है।" विवेचना कीजिए।

[सकेत सर्व प्रथम एकाधिकारी प्रतियोगिता का आशय स्पष्ट कीजिए और इनके परवात् उसकी विशेषताओं की पूर्ण विवेचना कीजिए।]

5 अल्पाधिकारी (oligopolist) की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताओं का पूर्ण विवेचन कीजिए।

6 पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता में अन्तर बताइए। इनमें से कौन सा स्वरूप अधिक व्यावहारिक है ?  
(Bihar, B A Hons 1966 E)

[सकेत उपर्युक्त बाजारों के प्राप्ति में अन्तर बताइए और फिर प्रत्येक स्वरूप की व्यावहारिकता बताते हुए निष्कर्ष दीजिए।]

# 27

## कुल आगम, सीमान्त आगम व लोच (Total Revenue, Marginal Revenue & Elasticity)

कोई वस्तु इसलिये बेची जाती है कि बाजार में उसकी माग होती है। जो कुछ बाजार में खरीदा जाता है, वही बेचा भी जाता है, अर्थात् एक ही सोदा केता के लिए खरीद तथा विप्रेता के लिए बिक्री होता है। माग-मूची यह बनताती है कि विक्रेता विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा में बेच सकता है ? बिक्री द्वारा विक्रेता जो कुछ प्राप्त करता है, वह उसकी आगम या भाय होती है। किसी उत्पादक की भाय का निर्धारण माग द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार 'कुल लागत' 'औसत लागत' तथा 'सीमान्त लागत' शब्दों का प्रयोग लागत के सम्बन्ध में किया जाता है, उसी प्रकार 'कुल आगम', 'औसत आगम' तथा 'सीमान्त आगम' शब्दों का प्रयोग भाय के सम्बन्ध में किया जाता है।

1. कुल आगम (Total Revenue) उम राशि को कहते हैं जो फर्म अपनी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त करती है। इस प्रकार

कुल आगम = प्रति इकाई कीमत  $\times$  बेची गई इकाइयों की मय्या।

2. औसत आगम (Average Revenue) : किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को कुल बेची गई मात्रा से विभाजित करने पर औसत आगम प्राप्त होती है, अर्थात् औसत आगम =  $\frac{\text{कुल आगम}}{\text{कुल बिक्री की मात्रा या इकाइया}}$

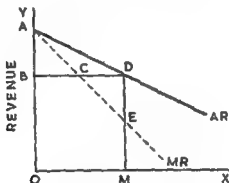
3. सीमान्त आगम (Marginal Revenue) : यह राशि, जिससे फर्म की कुल आगम में, एक प्रतिरिक्त इकाई बेचने से, वृद्धि होती है, सीमान्त आगम कहलानी है, अर्थात् सीमान्त आगम =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{कुल पूर्व आगम तथा एक प्रतिरिक्त इकाई बेचने से} \\ \text{प्राप्त कुल आगम का अन्तर।} \end{array} \right.$

प्रति इकाई कीमत प्रकट करता है। चूंकि CB एक इकाई प्रगट करती है इसलिए BD रपदा (8 रुपये) प्रति इकाई कीमत प्रकट करती है। अतः D फर्म के सीमांत आगम वक्र पर वह बिन्दु है जो OB उत्पादन पर प्रति इकाई कीमत प्रकट करता है। इसी प्रकार औसत आगम वक्र (AR) पर अन्य बिन्दु जान किए जा सकते हैं। जैसे OF उत्पादन (सात इकाइयां) पर GF वस्तु की एक इकाई प्रगट करता है।

अब हम औसत आगम वक्र तथा उससे सम्बन्धित सीमान्त आगम वक्र के ज्यामितीय सम्बन्ध पर प्रकाश डालेंगे—

(1) जब औसत आगम वक्र गिरता है तब सीमांत आगम औसत आगम के कम रहता है। स्वयं सीमांत आगम वक्र भी ऊँचा उठ सकता है, गिर सकता है या परिस्थितियों के अनुसार सीधी रेखा के रूप में (Horizontal) रह सकता है। परन्तु सामान्य रूप से यह गिरता है।

(2) सीमान्त आगम और औसत आगम के पारस्परिक सम्बन्धों को उस समय सरलता से ज्ञात किया जा सकता है जबकि औसत तथा सीमान्त आगम वक्र सीधी रेखाओं के रूप में हों। यदि ये दोनों सीधी रेखाओं के रूप में हैं तो सीमांत आगम वक्र  $Oy$  अक्ष पर डाली गयी लम्बी रेखा को औसत आगम वक्र को आधी दूरी पर काटेगा, जैसा कि चित्र स० 82 से प्रकट है।



चित्र स० 82

चित्र स० 82 में  $AR$  तथा  $MR$  सम्बन्धित औसत तथा सीमान्त आगम वक्र हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि सीमांत आगम वक्र हमेशा  $Oy$  अक्ष तथा औसत आगम वक्र के ठीक बीच में होता है।

$DB$  तथा  $DM$ ,  $OY$  तथा  $OX$  अक्ष पर क्रमशः लम्ब हैं। औसत आगम वक्र पर  $D$  बिंदु से  $DB$  सीमान्त आगम वक्र को  $C$  पर काटती है और  $DM$  सीमान्त आगम वक्र को  $E$  पर काटती है। हमें यह सिद्ध करना है कि  $BC = CD$  होगा।

$BDMO$  का क्षेत्रफल  $AEMO$  के बराबर है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक  $OM$  उत्पादन के कुल आगम को प्रकट करता है। ( $BDMO$  आयत औसत आगम तथा उत्पादन के गुणनफल, अर्थात् कुल आगम को प्रकट करता है।  $AEMO$  क्षेत्रफल  $O$  तथा  $M$  के बीच में उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर सीमांत आगम का जाड़

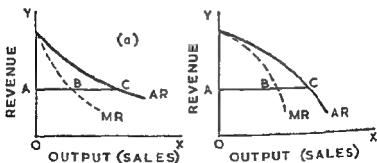


वतलाना है, अर्थात् यह दम दूरी पर उत्पादन की सभी वृद्धियों का जोड़ वतलाता है तथा इस प्रकार OM उत्पादन के कुल आगम को प्रकट करता है।) परन्तु  $BDMO$  आयत  $= BCEMO +$  त्रिभुज  $CDE$  का क्षेत्रफल। इसी प्रकार  $AEMO$  का क्षेत्रफल  $= BCEMO +$  त्रिभुज  $ABC$  का क्षेत्रफल। इस प्रकार त्रिभुज  $CDE$  का क्षेत्रफल  $=$  त्रिभुज  $ABC$  का क्षेत्रफल। परन्तु कोण  $ABC =$  कोण  $CDE$ , क्योंकि दोनों समानांतर हैं और कोण  $ACB =$  कोण  $DCE$ , क्योंकि दोनों शीर्ष एक ही मध्यमरेखा पर (Vertically Opposite) हैं। इस प्रकार  $ABC$  तथा  $CDE$  त्रिभुज प्रत्येक प्रकार से बराबर हैं। अतः  $BC = CD$ । इससे यह निश्चित होता है कि शीर्षत आगम वक्र के D बिन्दु से OY अक्ष पर डाला गया BD लम्ब सीमान्त आगम वक्र से C बिन्दु पर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि मीथी रेखा के रूप में सीमान्त आगम वक्र का ढलाव  $\frac{AB}{BC} =$  मीथी रेखा

के रूप में शीर्षत आगम वक्र के ढलाव  $\frac{AB}{BD}$  का दुगुना। क्योंकि

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AB}{CD} = 2 \frac{AB}{BD}$$

यदि शीर्षत आगम वक्र ऊपर की ओर नतोदर (Concave) होता है, तो सीमान्त आगम वक्र OY अक्ष पर डाली गयी। किसी भी लम्ब रेखा को शीर्षत आगम वक्र को आधी से कम दूरी पर काटना है, जैसा कि चित्र सं० 83 में प्रदर्शित किया गया है।



चित्र सं० 83

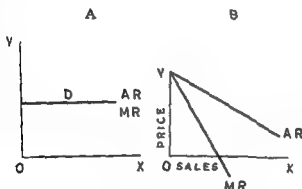
परन्तु जहाँ शीर्षत आगम वक्र ऊपर की ओर उन्नतोदर (Convex) होता है, वहाँ OY अक्ष पर डाले गये किसी भी लम्ब को शीर्षत आगम वक्र के आधे से अधिक दूरी पर काटता है, जैसा कि ऊपर के चित्र में प्रकट है।

# (1) पूर्ण स्पर्धा में औसत तथा सीमांत आगम (Average and Marginal Revenue in Perfect Competition)

पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत फर्म की वस्तुओं की माग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्म की उत्पादन-मात्रा का कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम (सीमांत आगम) सदैव समान रहता है। इस प्रकार सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। साथ ही साथ वह 'औसत आगम' के भी बराबर होता है। इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत :

$$\text{कीमत} = \text{सीमांत आगम} = \text{औसत आगम (या } P = MR = AR)$$

इन तीनों के समान होने के कारण कुल आगम में भी समान दर वृद्धि होती है। चूंकि पूर्ण स्पर्धा में औसत आय सीमान्त आय के बराबर होती है, अतः सीमान्त आय और औसत आय की रेखाएँ अलग-अलग न होकर एक सीधी क्षैतिज (Horizontal) रेखा के रूप में होती हैं, जैसा कि नीचे दिये गये रेखाचित्र में स्पष्ट किया गया है।



चित्र सं० 84

पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक को न तो लाभ होता है और न हानि। मूल्य औसत उत्पादन व्यय के बराबर होता है तथा इस मूल्य पर उत्पादक वस्तु की मात्राएँ बेचता है। प्रत्येक इकाई के लिए उसे एक ही दर से मूल्य प्राप्त होता है, इसलिए औसत आय और सीमान्त आय में कोई अन्तर नहीं होता। यही कारण है कि औसत आय और सीमान्त आय की रेखा भी एक ही होती है।

इस सन्दर्भ में यह भी याद रखना चाहिये कि एक फर्म की औसत आय रेखा फर्म की वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की माग रेखा (Demand Curve) भी होती है। अतः फर्म की औसत आय रेखा को माग-रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेखा इस तथ्य को व्यक्त करती है कि विभिन्न मूल्यों पर फर्म की कितनी वस्तुओं की

माग होगी ? कुछ प्रयोज्यशक्ति औसत आय वक्र (Average Revenue Curve) को विपणन वक्र (Sales Curve) भी कहते हैं। इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा में माग-वक्र (Demand Curve), औसत आय-वक्र (Average Revenue Curve) तथा सीमान्त आय वक्र (Marginal Revenue Curve) का रूप एक सीधी रेखा की तरह होता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि माग पूर्णतया लोचदार हो।

## 2. एकाधिकारी के आयम वक्र (Revenue Curves For Monopolist) :

चूंकि एकाधिकारी एकमात्र उत्पादक होता है। अतः उसकी माग की सोच, बाजार-माग की सोच के समान होती है। यदि वह अपने उत्पादन में 20% परिवर्तन करता है तो उद्योग के उत्पादन में भी 20% परिवर्तन होगा। एकाधिकारी, उत्पादन की विभिन्न मात्राएँ अलग-अलग कीमतों पर बेचता है। उसके औसत तथा सीमांत आयम, माग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकाधिकारी के औसत तथा सीमांत आयम में अन्तर होता है। एकाधिकारी के लिए माग वक्र नीचे की ओर झुका होता है (downward sloping demand curve) तथा यदि वह अतिरिक्त इकाइया बेचना चाहता है तो कुल उत्पादन बेचने के लिए, उसे कीमत कम करनी पड़ती है। कीमत (या औसत आयम) के नीचे गिरने पर सीमांत आयम औसत आयम की अपेक्षा तेजी से गिरता है। सीमांत आयम ऋणात्मक (Negative) भी हो सकता है, यद्यपि कीमत धनात्मक (Positive) ही हों। निम्न सारिणी द्वारा इन तथ्यों को स्पष्ट किया गया है :

एकाधिकारी का आयम			
कीमत या औसत आयम (₹० में)	विक्रय इकाइया (संख्या)	कुल आयम (₹० में)	सीमांत आयम (₹० में)
10	5	50	10
9	6	54	4
8	7	56	2
7	8	54	0
6	9	54	-2
5	10	50	-4
4	11	44	-6

सारिणी में स्पष्ट है कि (i) बिजो की मात्रा में वृद्धि के लिए कीमतें कम करनी पड़ती हैं, (ii) कुल आयम घटते हुए दर से वृद्धि होती है तथा कुछ समय पश्चात् कुल आयम भी घटने लगता है तथा (iii) सीमान्त आयम, औसत आयम से मंद्रव कम है तथा कुल आयम के अधिकतम होने के पश्चात्, सीमान्त आयम ऋणात्मक होन लगता है।

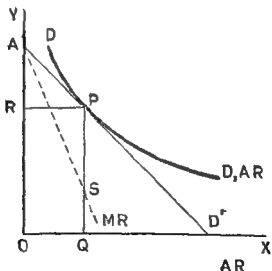
रेखाचित्र : अपूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार की अवस्थाओं में सीमान्त आयम तथा औसत आयम की रेखाएँ नीचे की ओर झुकी हुयी होती हैं तथा सीमांत आयम

रेखा औसत आगम रेखा के नीचे होती है। इसका कारण यह है कि सामान्यतया माँग की रेखा पूर्ण लोचदार नहीं होती है। ऐसी अवस्था में मूल्य तथा औसत आगम की रेखाएँ ही एक-ही होती हैं, परन्तु सीमांत आगम रेखा भिन्न होती है। सीमांत आगम रेखा औसत आगम रेखा की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गिरती है, क्योंकि एकाधिकारी को अधिक मात्रा में वस्तुओं के विक्रय के लिए सभी इकाइयों का मूल्य घटाया पड़ता है। इस प्रकार उसे केवल सीमांत आगम (प्रतिरिक्त बेची गयी इकाई पर आय) की ही हानि नहीं होती बल्कि औसत आगम (सभी बेची गयी इकाइयों पर आय) की मात्रा में कमी होने से हानि उठानी पड़ती है। यही कारण है कि एकाधिकार की अवस्था में यदि एकाधिकारी अधिक वस्तुओं को विक्री करता है तो सीमांत आय औसत आय की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गिरनी है।

रेखा-चित्र सं० 84 (पृ० 505 पर) AR औसत आगम रेखा तथा MR सीमांत आगम रेखा है जो AR के नीचे हैं, क्योंकि अपूर्ण स्पर्धा में सीमांत आय मूल्य में सदैव कम होती है। सीमांत आय उम समय ऋणात्मक (Negative) होती है जब माग बेलोचदार (Inelastic) होती है। ऐसी अवस्था में अधिक मात्रा में वस्तुओं का बेचन पर कुल आय में भी कमी होती है।

### 3. औसत व सीमांत आगम तथा लोच (Average Revenue, Marginal Revenue and Elasticity)

औसत व सीमांत आगम तथा लोच के पारस्परिक गणितीय-सम्बन्ध



चित्र सं० 85

[ध्यान रखें MR रेखा RP रेखा को दो समान भागों में बांटती है।]

(Mathematical Relationship) को ज्ञात किया जा सकता है। चित्र सं० 85 में DD माग वक्र या औसत-आगम वक्र है। इसके बिन्दु P पर स्पर्श रेखा (Tangent) AD खींची गई है। इसे भी हम माग वक्र मान सकते हैं। बिन्दु की OQ मात्रा के लिए P बिन्दु पर इन दोनों (DD or AD') की लोच समान होगी। AD' के नीचे की रेखा (MR) सीमान्त आगम रेखा है। अतः OQ मात्रा के लिए माग की लोच

$$\begin{aligned} &= \frac{PD'}{PA} = \frac{OR}{RA} = \frac{PQ}{SP} \text{ (क्योंकि } SP=AR) \\ &= \frac{PQ}{PQ-SQ} = \frac{\text{औसत आगम}}{\text{औसत आगम} - \text{सीमान्त आगम}} \end{aligned}$$

यदि माग की लोच =  $e$ , औसत आगम =  $A$ , सीमांत आगम =  $M$ , तो समीकरण के रूप में हम इन सम्बन्धों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :

$$e = \frac{A}{A-M}, \text{ प्रर्थात् } eA - eM = A \text{ अतः } -eM = A - eA$$

$$\text{अतः } M = \frac{eA - A}{e} = A \frac{e-1}{e}$$

इसी प्रकार, चूँकि  $eA - eM = A$ , अतः  $eA - A = eM$ ,

$$A(e-1) = eM, \quad A = \frac{M}{e-1} \therefore A = M \left( \frac{e}{e-1} \right)$$

$$\text{या } M = A \left( 1 - \frac{1}{e} \right) = A \left( \frac{e-1}{e} \right)$$

अतः सामान्य नियम के रूप में कहा जा सकता है कि यदि  $e$  = औसत आगम पर, माग की बिन्दु लोच हो तो किसी भी उत्पादन के लिए,

$$\text{औसत आगम} = \text{सीमांत आगम} \times \frac{e}{e-1} \text{ तथा}$$

$$\text{सीमांत आगम} = \text{औसत आगम} \times \frac{e-1}{e} \text{ और सीमांत आगम} = \text{कीमत} - \frac{\text{कीमत}}{\text{लोच}}$$

सीमान्त आगम, औसत आगम तथा लोच के उपरोक्त सम्बन्ध स्मरणीय हैं।

**सीमांत आगम कीमत व माग की लोच (Marginal Revenue, Price and Elasticity of Demand)**

सीमांत आगम, कीमत तथा माग के पारस्परिक सम्बन्धों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु की  $X$  इकाइयों की  $P$  कीमत पर बेचा जा सकता है तथा  $X + X_1$  इकाइयों को  $P - P_1$  कीमत पर बेचा जा सकता है (जबकि  $X_1$  तथा  $P_1$  बहुत ही छोटी मात्रा हैं)। ऐसी अवस्था में सीमांत आगम (MR)।

$$= \frac{\text{कुल आगम में वृद्धि}}{\text{बिक्री में वृद्धि}} = \frac{(X+X_1)(P-P_1)-XP}{X_1}$$

$$= \frac{XP + X_1P - P_1X - X_1P_1 - XP}{X_1} = P - \frac{XP_1}{X_1} - P_1$$

$$\therefore \frac{MR}{P} = 1 - \frac{X}{X_1} \times \frac{P_1}{P} - \frac{P_1}{P}$$
 हम यह मान चुके हैं कि  $P_1$  बहुत ही

छोटी मात्रा है अतः  $\frac{P_1}{P}$  को छोड़ा जा सकता है (Neglected) और,

$$\frac{X}{X_1} \times \frac{P_1}{P} = 1 - \left( \frac{X_1 - P_1}{X} \right) = \frac{1}{e} \text{ यहाँ पर } e \text{ माँग की लोच है।}$$

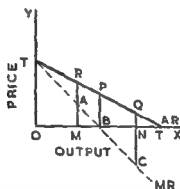
इससे यह स्पष्ट है कि,  $MR = P \left( 1 - \frac{1}{e} \right)$  इस प्रकार सीमांत आगम,

कीमत तथा माँग की लोच पर निर्भर है।

### परिशिष्ट

यदि किसी फर्म के औसत आगम वक्र की लोच किसी भी दी हुई उत्पत्ति पर एक के बराबर होती है, तो

$$\text{सीमांत आगम} = \text{औसत आगम} \times \frac{1-1}{1} = \text{औसत आगम} \times 0 = 0$$



चित्र सं० 86

अतः जब औसत आगम वक्र की लोच एक के बराबर होती है, सीमांत आगम शून्य होता है। इसे चित्र सं० 86 में प्रदर्शित किया गया है :

चित्र सं० 86 औसत आगम वक्र पर P बिन्दु पर लोच एक के बराबर है, महा उत्पत्ति OB है, क्योंकि  $PT = P_1$ , अतः  $\frac{PT}{P_1} = 1$ । इस उत्पत्ति पर सीमांत

आगम शून्य है। इसी प्रकार जब माग की लोच 2 के बराबर होती है चिन स० 86 में बिन्दु R पर), जहाँ  $RT=2R_1$ ,

$$M=A \times \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}A$$

अन्य शब्दों में  $AM=\frac{1}{2}RM$ । सीमांत आगम औसत आगम के घापे के बराबर होगा। जब भी औसत आगम वक्र से अधिक होगा, तो किसी भी उत्पत्ति पर सीमांत आगम सदैव धनात्मक (Positive) हो जाएगा। चिन स० 86 में औसत आगम वक्र की ॥ से P तक की दूरी पर ऐसा ही होता है। इसी प्रकार, P से T तक की दूरी पर लोच के एक से कम होने पर, सीमान्त आगम सदैव ऋणात्मक (negative) होता है।

Q बिन्दु पर लोच एक से कम यद्यपि  $\frac{1}{2}$  मान लेने पर, उदात्त फार्मूले को स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ  $QT=\frac{1}{2}Q_1$  और

$$M=AX \times \frac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}} = A \times \frac{-\frac{1}{2}}{1/4} = -3A$$

सीमान्त आगम ऋणात्मक है और औसत आगम का तिगुना है। चिन स० 86 में  $NC=3QN$ । इसलिए सीमान्त आगम औसत आगम वक्र के लोचदार होने पर सदैव ऋणात्मक होता है। औसत आगम वक्र पर माँग की बिन्दु लोच मान होने पर इन फार्मूलों की सहायता में किसी भी उत्पत्ति के औसत आगम से उसी उत्पत्ति का सीमांत आगम ज्ञात करना सम्भव होगा।

### प्रश्न व सकेत

1. फर्म की औसत तथा सीमांत आगमों के बीच अन्तर बताइए, पूर्ण प्रति-योगिता के अस्तित्व में उनका वस्तु क मूल्य से क्या सम्बन्ध होता है ?

[सकेत—MR व AR का अर्थ समझाइए तथा यह सिद्ध कीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अस्तित्व में अन्वय शक्तों के साथ ही साथ  $P=AR=MR$ ]

2. औसत व सीमान्त आगम तथा लोच में क्या सम्बन्ध है ?

[सकेत—पृष्ठ 507 के चित्र की सहायता से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।]

# 28

## मूल्य-सिद्धान्त तथा बाजार-मूल्य (Theories of Value and Market Price)

*"The real price of anything, what everything really costs to the man who wants to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it what is brought with money or with goods is purchased by labour as much as what we acquire with the toil of our body."*

Adam Smith

'मूल्य' अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। मूल्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रतिदिन हम साधन-सामग्री का मूल्य, कपड़ों का मूल्य, माहिर्य का मूल्य आदि जड़ों का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र में मूल्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है—(i) उपयोगिता मूल्य (Value-in-use) तथा (ii) विनिमय मूल्य (Value-in-Exchange)। आधुनिक अर्थशास्त्री इन शब्दों के अर्थ पर 'उपयोगिता' (utility) तथा 'मूल्य' (value) शब्दों का प्रयोग करते हैं। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शक्ति से लिया जाता है, जबकि मूल्य का अर्थ किसी वस्तु की विनिमय-शक्ति से होता है। मूल्य या बाजार में विनिमय मूल्य का जिक्र करती है जिस मुद्रा के सन्दर्भ में मापा जा सकता है।<sup>1</sup>

### 1 मूल्य के सिद्धान्त (Theories of Value)

मूल्य निर्धारण के आधुनिक सिद्धान्तों के पहले विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कई सिद्धान्त प्रस्तुत किये थे। यहाँ पर हम मध्ये में देने के मूल्य के सिद्धान्त बतायेंगे।

<sup>1</sup> "Price indicates the value in Exchange as measured in terms of money." —H A. Silverman, The Substance of Economics, p. 59.



## 1. मूल्य का श्रम सिद्धांत (Labour Theory of Value) :

श्रम-सिद्धांत विभिन्न समय में तथा विभिन्न रूपों में एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा बतलाया गया, परन्तु इस सिद्धांत का पूर्ण विकास कार्ल मार्क्स ने दिया। अतः इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक मार्क्स माने जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु को पैदा करने में लगे हुए श्रम के बराबर होगा है। इस प्रकार श्रम को मूल्य का स्रोत (Source) तथा मूल्य का मापक (Measure) मानते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले 'पूँजीगत वस्तु' (capital goods) की आवश्यकता का भी स्वीकार करते हैं। परन्तु उनका कहना है कि पूँजी भूतकाल के श्रम का परिणाम है, इसलिए वे पूँजी सम्बन्धी वस्तुओं को 'Crystallised' श्रम कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन पूँजीवाद अर्थ-व्यवस्था की कटु आलोचना के लिए किया था। उनका कहना था कि श्रम के द्वारा सभी प्रकार के मूल्यों का सृजन होता है। परन्तु श्रमिक को कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा सा भाग निर्वाह-मजदूरी (subsistence wage) के रूप में मिलता है। इस प्रकार श्रम के वास्तविक उत्पादन तथा उसके लिए दी गई मजदूरी का अन्तर अति-मूल्य (surplus value) है जिसे पूँजीपति व्याज, लाभ, लगान, आदि के रूप में प्राप्त करते हैं।

कुछ अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि मार्क्स ने उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में मार्क्स ने उपयोगिता पर ध्यान दिया था, परन्तु उन्होंने उपयोगिता को मूल्य-निर्धारण के सिद्धांत में महत्व नहीं दिया था, क्योंकि उपयोगिता अत्यधिक बदलती रहती है और इसका मूल्य से विशेष सम्बन्ध नहीं होता।

## 2. उत्पादन-व्यय सिद्धांत (Cost of Production Theory) :

यह सिद्धांत एक प्रकार से श्रम-सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप है। इसके अन्तर्गत श्रम के अतिरिक्त अन्य लागतों पर भी ध्यान दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधनों की लागत से निर्धारित होता है। श्रम-सिद्धांत की तरह इसमें भी पूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया गया है, परन्तु इसमें उत्पादन के सभी साधनों की लागत को ध्यान में रखा गया है, न कि केवल श्रम की। पूर्ण स्पर्धा में इस सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि मूल्य तथा लागत में यदि अन्तर अधिक होता है तो लाभ की मात्रा बढ़ती है। यही कारण है कि उद्योग में अधिक प्रतियोगी आते हैं जिससे पूर्ति में वृद्धि होती है और मूल्य कम होकर लागत व्यय के बराबर हो जाता है।

श्रम सिद्धांत तथा उत्पादन-व्यय सिद्धांत दोनों को लागत-व्यय-सिद्धांत (Cost Theories of Value) कहते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में पूर्ति पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है तथा उपयोगिता और मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है।

### 3 उपयोगिता-सिद्धान्त (Utility Theory) :

इस सिद्धान्त के मानने वाले वस्तु की उपयोगिता पर अधिक ध्यान देते हैं। इनके अनुसार वस्तु का मूल्य उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से निर्धारित होता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त को मानने वाले माग पक्ष पर ध्यान देते हैं। जर्मन अर्थ-शास्त्री Gossen के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य का उससे प्राप्त होने वाली सतुष्टि में घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ समय बाद W. S. Jevons ने इस सिद्धान्त को वास्तविक रूप में रखा।

कुछ अर्थशास्त्री उपयोगिता सिद्धान्त को दूसरे रूप में भी रखते हैं। उनके अनुसार मूल्य निर्धारण में दुर्लभता (scarcity) व माग का हाथ रहता है। कोई वस्तु उत्पादन की अधिक मागत तथा अन्य कारकों से दुर्लभ होती है। इसलिए उपयोगिता अथवा उत्पादन के दुर्लभ साधनों की प्रतियोगी मांगों के आधार पर उत्पादन लागत की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार मूल्य के उपयोगिता सिद्धान्त को लागत सिद्धान्त का मुँधरा हुआ रूप माना जा सकता है।

### 4. सीमात उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility Theory) :

पहले सिद्धान्तों में मूल्य-सिद्धान्त की सर्वोपजनक व्याख्या न की जा सकी। अतः विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के नये सिद्धान्त की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। इस सिद्धान्त को 'सीमात उपयोगिता सिद्धान्त' (Marginal Utility Theory of Value) कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य माग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें वस्तु की सीमात उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात् वस्तु की दुर्लभता (scarcity) से सम्बन्धित माग द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ति का सम्बन्ध उत्पादन-लागत से होता है। उत्पादन लागत किसी वस्तु की दुर्लभता निर्धारित करती है। मूल्य में दुर्लभता का अत्यधिक महत्व है, इसी के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का बड़ा हुआ मूल्य उसके बड़े दूबे माग-मूल्य का ही दूसरा रूप है। माग-मूल्य उपयोगिता की सीमात उपयोगिता पर निर्भर है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीमात उपयोगिता ही मूल्य निर्धारित करती है।

इस व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य के सीमात उपयोगिता सिद्धान्त तथा लागत सिद्धान्त लगभग एक में ही हैं, क्योंकि उत्पादन लागत सिद्धान्त में भी उत्पादन लागत द्वारा पूर्ति निर्धारित होती है और पूर्ति द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है, परन्तु दोनों सिद्धान्तों में मौलिक अन्तर है। सीमात उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन लागत किसी वस्तु की न्यूनता पर प्रभाव डालती है। और यह प्रभाव भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। उस प्रकार सीमात उपयोगिता सिद्धान्त में उत्पादन

लागत द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं होता है। किसी वस्तु के दुर्लभ होने में जितना हाथ उत्पादन व्यय का होता है उसमें बहुत अधिक हाथ उस वस्तु की मांग का होता है। अतः कोई वस्तु उसकी मांग के अनुसार दुर्लभ होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके उत्पादन व्यय से नहीं, बल्कि परस्पर प्रतियोगी मांगों (competing demands) द्वारा होता है। मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति बदलती रहती है और पूर्ति के अनुसार उत्पादन व्यय। किसी वस्तु की लागत उस वस्तु के विकल्पों (Alternatives) का त्याग है। विकल्पों के मूल्यों को उनकी उपयोगिता द्वारा प्रकट दिया जाता है। इसलिए लागत का सिद्धांत उपयोगिता पर निर्भर है।

उपयोगिता सिद्धांत की यह व्याख्या एकात्मक (Monistic) है। प्रो० मार्शल ने मूल्य निर्धारण का जो सिद्धांत दिया उसे हम दुर्लभ व्याख्या (dual analysis) कहते हैं। मार्शल के अनुसार उपयोगिता तथा लागत दो अलग अलग वस्तुएं हैं तथा इन दोनों का मूल्य निर्धारण में समान रूप में महत्व है। अतः मूल्य केवल उपयोगिता में ही नहीं बल्कि उपयोगिता और लागत दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। उपयोगिता का सम्बन्ध मांग से है और लागत का सम्बन्ध पूर्ति से है। अतः न केवल मांग तथा न केवल पूर्ति से ही मूल्य निर्धारित होता है, बल्कि मांग और पूर्ति दोनों से ही निर्धारित होता है। मार्शल ने मांग और पूर्ति को तुलना एक कैंची के दो पातों (blades) से की है। जिस प्रकार कैंची के दोनों पातों की सहायता से ही कागज का एक टुकड़ा काटा जा सकता है, उसी प्रकार मूल्य निर्धारण में उपयोगिता और लागत दोनों का हाथ रहता है। किसी एक के द्वारा ही मूल्य निर्धारित नहीं होता है<sup>2</sup> यद्यपि इन दोनों का महत्व समय के अनुसार बदला रहता है। मार्शल ने कहा है कि अल्पावधि में मूल्य पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है तथा दीर्घावधि में उत्पादन व्यय या पूर्ति का।<sup>3</sup>

“एत उपयोगिता सिद्धांत के मानने वाल इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं—  
उत्पादन लागत (पूर्ति) तथा उपयोगिता [मांग] दोनों को स्वतन्त्र वगैरह नहीं माना

---

<sup>2</sup> “We might as reasonably dispute whether it is the upper or under blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper as whether value is governed by utility or cost of production”

— Marshall Principles of Economics

“As a general rule, the shorter period which we are considering the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on value and longer the period, the more important will be the influence of cost of production on value”

Marshall : Principles of Economics, 291

जा सकती, क्योंकि उत्पादन लागत भी उपयोगिता का एक अंग है। लागत वैकल्पिक उपयोगिता (alternative utility) प्रकट करती है। इसीलिए उपयोगिता पर केवल मांग ही नहीं निर्भर करती, बल्कि पूर्ति भी निर्भर करती है। इस प्रकार मांग तथा पूर्ति दोनों उपयोगिता पर निर्भर करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मूल्य के निर्धारण में उपयोगिता विशेषतया सीमात उपयोगिता का हाथ रहता है।

वर्तमान समय में सीमात उपयोगिता सिद्धांत मूल्य का सर्वमान्य सिद्धांत है। यद्यपि इस सिद्धांत का प्रतिपादन Jevons तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया था, परन्तु इसको आधुनिक रूप देने में Wicksteed, Wicksell, Davenport तथा Cassel का प्रमुख स्थान है। सीमात उपयोगिता-सिद्धांत, मूल्य का सर्वमान्य सिद्धांत है क्योंकि (i) यह अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में सम्बन्धित मूल्यों की व्याख्या करता है, (ii) मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का स्पष्टीकरण भी करता है। (iii) दुर्लभ, खराब तथा शीघ्र नाशवान वस्तुओं के मूल्य की एक मात्र व्याख्या इसी सिद्धांत में मिलती है। यह सिद्धांत पानी, धूप आदि ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भी स्पष्टीकरण करता है जो अधिक उपयोगी होते हुए भी मूल्यवान नहीं होती हैं।

### मूल्य-निर्धारण . सामान्य सिद्धांत (Price Determination . General Theory)

किसी वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? मूल्य-निर्धारण का सामान्य सिद्धांत यह है कि वस्तु का मूल्य उस बिन्दु पर निश्चित किया जाता है, जिस बिन्दु पर उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होती है।

बाजार मूल्य मांग तथा पूर्ति के सम्मिलित प्रभाव से निर्धारित होता है। बाजार में जिस कीमत पर वस्तु की मांगी हुई मात्रा तथा वस्तु की पूर्ति की मात्रा बराबर होती है वही पर मूल्य निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित की हुई कीमत को साम्य कीमत (Equilibrium Price) कहते हैं तथा इस कीमत पर बेची गई वस्तु की मात्रा को साम्य राशि (Equilibrium Amount) कहते हैं। मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित इस प्रकार की कीमत का अध्ययन नीचे प्रस्तुत है :

(i) वस्तु की मांग (Demand for Commodity) : वस्तु की मांग बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा होती है। मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो कम मूल्य पर उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं। इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता कम खरीदना चाहते हैं।

(ii) वस्तु की पूर्ति (Supply of Commodity) : बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति सभी विक्रेताओं की पूर्ति का योग होती है। विभिन्न मूल्यों पर विक्रेता

अपनी वस्तुओं की विभिन्न मात्रा बेचने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की विभिन्न मात्रा की तालिका को बाजार पूर्ति तालिका (Market Supply Schedule) कहते हैं। वस्तु की कितनी मात्रा प्रत्येक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचेगा, यह उसके आरक्षित मूल्य (Reservation Price) पर निर्भर करता है। इससे कम पर विक्रेता माल को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। यह आरक्षित मूल्य (Reservation Price) कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे :

1. वस्तु की प्रकृति : यदि वस्तु नाशवान [Perishable] है तो विक्रेता उसे शीघ्रतापूर्वक बेचना चाहेगा। इसलिए वस्तु का आरक्षित मूल्य [Reservation Price] कम होगा।

2. भविष्य की मांग : यदि भविष्य में मूल्य गिरने की आशा है तो वह कम कीमत पर ही अपनी वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में बेचना चाहेगा।

3. उत्पादन व्यय : टिकाऊ तथा अर्ध-टिकाऊ (durable and semi-durable) वस्तुओं पर उत्पादन व्यय का प्रभाव पड़ता है। साधारणतया विक्रेता उत्पादन व्यय से कम कीमत पर अपनी वस्तु को नहीं बेचेगा। विक्रेता की कई कीमतें आरक्षित कीमतें (Reservation Price) हानी हैं।

बाजार कीमत माग तथा पूर्ति के सम्मिलित प्रभाव से निर्धारित होती है। बाजार पूर्ति तालिका यह दिखाती है कि विभिन्न कीमतों पर विक्रेता अपनी वस्तु की कितनी मात्रा बेचेगा तथा बाजार माग तालिका [Market Demand Schedule] उपभोक्ताओं की यह तैयारी (Willingness) दिखाती है कि वे विभिन्न मूल्यों पर कितनी मात्रा खरीदेंगे। इस प्रकार जिस कीमत पर बाजार में वस्तु की माग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है वही वस्तु का बाजार मूल्य होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

विभिन्न कीमतों पर गेहूँ की माग तथा पूर्ति

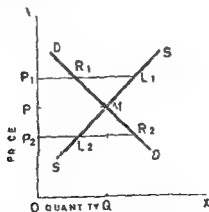
कीमत प्रति मन	(माग)	(पूर्ति)
30	200	0
31	180	20
32	170	40
33	140	70
34	100	100
35	75	135
36	25	170

उपराक्त तालिका में गेहूँ की कीमत प्रति मन दी गई है तथा बाजार में विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली तथा बेची जाने वाली मात्राएँ दी गई हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जब गेहूँ का मूल्य 34 रु० प्रतिमन है तो उसकी मांग तथा पूर्ति दोनों 100 मन हैं। इस प्रकार बाजार मूल्य 34 रुपये प्रति मन होगा, क्योंकि इसी मूल्य पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होती है।

(iii) रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण बाजार मूल्य बाजार की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार जहाँ पर मांग तथा पूर्ति रेखाएँ एक दूसरे की काटती हैं वही पर मूल्य निर्धारित होता है। जैसा कि आगे के पृष्ठ पर दिये गये रेखाचित्र स 71 में दर्शाया गया है।

इस रेखाचित्र में DD बाजार की माँग रेखा है तथा SS पूर्ति रेखा है। दोनों एक दूसरे की M बिन्दु पर काटती हैं। अतः OP (MQ=OP) बाजार मूल्य अथवा साम्य कीमत हुई तथा OQ साम्य मात्रा (Equilibrium Quantity) हुई।

प्रत्येक अवस्था में यही मूल्य होगा। एक पक्ष स्पर्धा वाला बाजार में जिसमें श्रेता तथा विभ्रता की बाजार की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है वहाँ पर साम्य कीमत अधिक समय तक बदल नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में वास्तविक विक्रय कीमत (Selling Price) तथा बाजार साम्य कीमत (Equilibrium Market Price) दोनों एक ही होती हैं।



चित्र स० 87

बाजार मूल्य की यह विशेषता होती है कि यदि वास्तविक मूल्य साम्य मूल्य से कम या अधिक होता है तो बाजार में ऐसी शक्तियाँ काम करती हैं जिन्होंने पाठे ही समय में वास्तविक मूल्य पुनः साम्य मूल्य के बराबर हो जाता है जैसा, यदि

विशेष मूल्य साम्य मूल्य से अधिक है तो बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ेगी। इस प्रकार विक्रेताओं में स्पर्धा होगी। क्रान्ताओं की सहायता पहले की ही भाँति रहेगी। अतः विक्रेताओं में स्पर्धा के कारण बाजार मूल्य पुनः साम्य मूल्य पर आ जायेगा। इसके विपरीत यदि विशिष्ट मूल्य साम्य मूल्य से कम है तो बाजार की मांग (Market Demand) बाजार की पूर्ति से अधिक होगी। इस प्रकार क्रान्ताओं में स्पर्धा होगी जिससे विशिष्ट मूल्य बढ़ेगा और पुनः साम्य मूल्य के बराबर हो जायेगा।

इस तथ्य को ऊपर रेखाचित्र में दर्शाया गया है जिसमें OP कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर है (OQ मात्रा)। मूल्य बढ़कर  $OP_1$  हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर  $P_1L_1$  हो जाती है। मूल्य बढ़ने के कारण मांग घटकर  $P_1R_1$  हो जाती है जिससे यह प्रकट होता है कि विक्रेता बेचने के लिए उत्सुक है, परन्तु क्रान्ता खरीदने को तैयार नहीं हैं। अतः कीमत गिरेगी और पुनः OP के बराबर होगी। दूसरी परिस्थिति में मूल्य कम होकर  $OP_2$  हो जाता है तो पूर्ति तथा मांग क्रमशः  $P_2L_2$  व  $P_2R_2$  हो जाती है। यहाँ पर क्रान्ताओं का दबाव रहेगा, अतः कीमत पुनः बढ़कर OP हो जायेगी।

**बाजार कीमत की विशेषताएँ (Characteristics of Market Price) :**

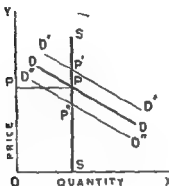
(1) बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर बाजार की मांग व पूर्ति बराबर होती है।

(2) साम्य बाजार कीमत (Equilibrium Market Price) में घट-बढ़ होते रहते हैं, क्योंकि बाजार की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। बाजार की पूर्ति व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति का योग होती है तथा यह पूर्ति बहुत कुछ प्रयोग में भविष्य में कीमत में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार बाजार की मांग भी परिवर्तित होती रहती है। अतः मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण अत्यन्त ही अल्प काल में बाजार साम्य-मूल्य बदलता रहता है।

**शीघ्र नाशवान वस्तुओं (Perishable Commodities) का मूल्य-निर्धारण :**

शीघ्र नाशवान वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, फण्डा आदि के मूल्य निर्धारण में 'पूर्ति' का महत्व नहीं रहता। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का मूल्य उनकी मांग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मांग में वृद्धि होने से उनके मूल्य में वृद्धि तथा मांग में कमी होने से मूल्य में कमी होती है। विक्रेता के पास जो भी स्टॉक होता है, उसे वह बेचना चाहता है, क्योंकि बाद में ये वस्तुएँ खराब हो जाती हैं, तथा उन्हें बेचना कठिन हो जाता है। अतः ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत का ध्यान नहीं रखा जाता है, मांग ही मूल्य का निर्धारक तत्व है। दिये गये चित्र सं० 88 में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। पूर्ति रेखा SS है जो एक ऊर्ध्व रेखा के

रूप में है। DD मांग-वक्र है, कीमत OP है। मांग में वृद्धि होने में ( $D'D'$ ) कीमत बढ़कर  $P'$  हो जाती है, तथा मांग में कमी होने से ( $D''D''$ ) कीमत घट कर  $P''$  हो जाती है।



चित्र सं० 88

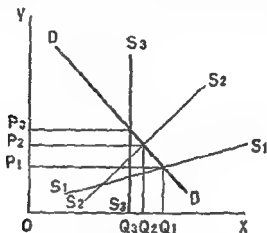
### मात्रा का समयानुसार विभाजन (Rationing over Time) :

कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन वर्ष में एक बार किया जाता है, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा उनका प्रयोग वर्ष पर्यन्त किया जाता है, जैसे खाद्यान्न। ऐसी वस्तुओं की बाजार-अवधि सामान्यतः एक वर्ष होती है। अतः उपभोक्ताओं की वर्ष भर की मांग की पूर्ति एक ही बार उत्पादित वस्तु में करनी पड़ती है। मरलना की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि एक वर्ष में चार माह की तीन अवधि हैं। आरम्भ में स्टॉक अधिक होने के कारण कीमत कम रहेगी तथा ज्यों-ज्यों स्टॉक घटना जाएगा, कीमत ऊँची होती जायेगी। आरम्भ में (प्रथम बार माह) पूर्ति की मात्रा कीमत पर निर्भर होगी। यदि नेता अधिक कीमत वेत को तैयार होंगे तो विक्रेता अधिक मात्रा में वस्तुओं को बेचेंगे। (अन्यथा स्टॉक को अपने पास रखे रहेंगे परन्तु वे स्टॉक रखने पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखेंगे)। अतः प्रथम बार माह के लिए पूर्ति-वक्र अधिक लोचदार होगा, तथा यह नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होगा (चित्र सं० 89 में  $S_1S_1$  देखिये)।

दूसरे चार महीने की अवधि में पूर्ति अपेक्षाकृत कम लोचदार होगी तथा इस अवधि का पूर्ति-वक्र प्रथम पूर्ति-वक्र के ऊपर रहेगा ( $S_2S_2$ ) क्योंकि विक्रेता अधिक ऊँची कीमत लेना चाहेंगे (स्टॉक रखने से सम्बन्धित व्यय, ऋण मूल्य पर व्याज आदि को भी वसूल करना चाहेंगे)। इस अवधि में पूर्ति-वक्र  $S_2S_2$  पर पूर्ति की मात्रा  $OQ_2$  तथा कीमत  $OP_2$  होगी। तीसरे चार महीने में, विक्रेता कुछ स्टॉक को किसी



प्रकार बेचना चाहेंगे अतः पूर्ति कुल स्टॉक के बराबर होगी। यही कारण है कि पूर्ति-वक्र  $S_3S_3$  सम्भवतः प्रदर्शित किया गया है। अब पूर्ति सवमग लेवहीन हो जाएगा।



चित्र सं० 89

ऐसी अवस्था में कीमत मांग पर निर्भर करेगी। यदि मांग अधिक होती है तो कीमत बढ़ेगी यदि मांग अधिक होती है तो कीमत घटेगी।

चित्र सं० 89 से स्पष्ट है कि तीनों अवधियों में कीमत क्रमशः बढ़ती गई है, क्योंकि स्टॉक सम्बन्धी अध्ययन बढ़ती जायेंगे तथा विनिर्देशक उन व्यक्तियों को भी केंद्रों से प्राप्त करने का प्रयत्न किया करेंगे। परन्तु यदि विनिर्देशक का मांग सम्बन्धी अनुमान गलत सिद्ध होता है अर्थात् बाद में मांग बहुत कम हो जाती है तो उसे कम कीमत पर भी वस्तु बेचना पड़ेगी, क्योंकि तीसरी अवधि की समाप्ति के समय गया स्टॉक आ जाएगा। उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतया आरम्भ में अधिक मात्रा बेची जायगी तथा कीमत कम रहेगी, तथा बाद में कीमतें बढ़ती जायेंगी।

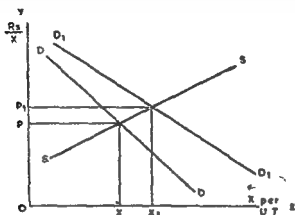
### मांग में परिवर्तन तथा बाजार मूल्य (Changes in Demand & Market Price)

1. मांग में वृद्धि होने पर बाजार-अवधि में साम्य कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति द्वारा किया जाता है। यदि मांग में वृद्धि हो जाए तो बाजार-कीमत में परिवर्तन आएगा। इस दशा का स्पष्टीकरण चित्र संख्या 90 में किया गया है।  $DD$  प्रथम मांग वक्र है, मान लीजिये मांग में वृद्धि हो जाती है।  $D_1D_1$  वक्र वही नया मांग को प्रकट करता है \* मांग बढ़ी हुई मांग के कारण कीमत  $OP$  में बढ़कर

\* "Total supply cannot be changed during the market period but it is possible for sellers to decide to offer more or less out of given non perishable stocks"

—Robinson, Adams and Dillan, An Introduction to Modern Economics, p. 328.

$OP_1$  हो जाएगी। बड़े हुए मूल्य पर विक्रेता अधिक वस्तु बेचना चाहेंगे इस प्रकार बेची जाने वाली मात्रा  $OX$  से बढ़कर  $OX_1$  हो जाएगी। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि माग में वृद्धि होने पर बाजार मूल्य ऊँचा उठता है तथा पूर्ति में भी वृद्धि होती है (वर्तमान उत्पादन की सीमा तक)।



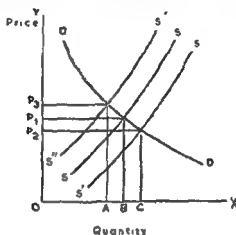
चित्र सं० 90

2. माग के घटने पर मान लीजिये  $D_1D_1$  मूल माग वक्र है तथा  $OP_1$  मूल बाजार मूल्य है।  $OP_1$  मूल्य पर वस्तु की  $OX_1$  मात्रा बेची जा रही है। यदि माग घटती है तो  $DD$  नया माग वक्र होगा इस प्रकार बाजार में  $OP_1$  कीमत पर वस्तु का आधिक्य हो जाएगा, क्योंकि खरीद कम हो गई है। इस आधिक्य के कारण विक्रेता कीमत में कमी करेगे इस प्रकार कीमत  $OP$  हो जाएगी तथा बेची जाने वाली मात्रा  $OX$  हो जाएगी।

### पूर्ति में परिवर्तन तथा बाजार मूल्य (Changes in Supply and Market Price)

1. पूर्ति में वृद्धि होने पर : यदि माग-वक्र दिया हुआ हो तो, पूर्ति में परिवर्तन होने में कीमत तथा वस्तु की मात्रा दोनों में परिवर्तन होंगे। चित्र संख्या 91 में  $DD$  माग वक्र तथा  $SS$  पूर्ति वक्र हैं।  $OP_1$  कीमत तथा  $OB$  विन्य-मात्रा को प्रकट करते हैं। मान लीजिए पूर्ति में परिवर्तन होता है\* (यह याद रखना चाहिये कि बाजार-अवधि में पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परन्तु विक्रेता अनाश्रयान वस्तुओं के स्टॉक में से विक्रय के लिए कम या अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं) मूल्य में परिवर्तन के अनुसार विक्रेता वस्तु की कम या अधिक मात्रा बेचने के लिए अपने वर्तमान स्टॉक में से प्रस्तुत करेंगे। चित्र में इसी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। माग (माग-पूत्री) में कोई परिवर्तन

नहीं हो रहा है तथा पूर्ति-मूची में कमो ब वृद्धि हो रही है। यदि पूर्ति बढ़ती है तो  $S_1$   $S_2$  नया पूर्ति-वक्र होगा इस प्रकार कीमत घटकर  $OP_2$  हो जाएगी। तथा बेची जाने वाली मात्रा  $OB$  से बढ़कर  $OC$  हो जाएगी।



चित्र स० 91

2 पूर्ति में कमी होने पर - मान लीजिये बिनेता दिए गए मूल्य पर कम मात्रा बेचना चाहते हैं। इस प्रकार  $S''S'$  घटी हुई पूर्ति-मूची को प्रकट करता है। पूर्ति घटाने से कीमत घटकर  $OP_2$  हो जाएगी तथा बेची जाने वाली मात्रा  $OB$  से घटकर  $OA$  हो जाएगी।

### माग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन तथा बाजार मूल्य (Changes in Demand & Supply)

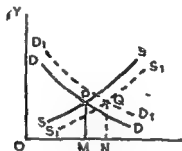
व्यावहारिक रूप में यह सम्भव है कि बाजार काल में माग तथा पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो। यदि माग तथा पूर्ति में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं तो बीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु विक्रय-मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

"it is conceivable that changes in both demand and supply will occur during the market period. To the extent that such changes cancel each other out, no change in price will occur. The quantity bought and sold will, however, change considerably".

*Robinson, Adams and Dillin.*

चित्र स० 91 A से इस स्थिति पर प्रकाश पड़ता है,  $DD$  माग वक्र तथा  $SS$  पूर्ति वक्र है।  $MP$  कीमत तथा  $OM$  वस्तु की विक्रय मात्रा है। मान लीजिये पूर्ति बढ़ जाती है,  $S_1S_2$  नया पूर्ति वक्र होगा। इसी प्रकार माग में वृद्धि के कारण

$D_1, D_1$  नया माग वक्र होगा। मान लीजिए, माग तथा पूर्ति दोनों में आनुपातिक वृद्धि समान हुई है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। चित्र में हम देख रहे हैं कि कीमत



चित्र सं० 91 A

पहले के ही समान है :  $PM = PN$ , परन्तु विक्रय मात्रा  $OM$  से बढ़कर  $ON$  हो गई है। इसी प्रकार यदि माग तथा पूर्ति दोनों में समान आनुपातिक कमी होती है। तो कीमत पूर्ववत् रहेगी, परन्तु विक्रय मात्रा घट जाएगी। माग तथा पूर्ति में परिवर्तन का अन्तान समान न रहने पर कीमत तथा विक्रय मात्रा दोनों में परिवर्तन होंगे। (जमन उदाहरणार्थ माग व पूर्ति के परिवर्तन सम्बन्धी ऊपर एक चित्र दिया है विद्यार्थी स्वयं माग तथा पूर्ति में अवमान आनुपातिक परिवर्तन मानकर तथा माग व पूर्ति में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन मानकर, स्वयं रेखा चित्र बनाकर जात कर सकते हैं कि माग व पूर्ति में परिवर्तन होने पर, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है।)

### प्रश्न व संकेत

1 सतुलन-मूल्य की परिभाषा देते हुए बताइये कि माग तथा पूर्ति में परिवर्तन होने में सतुलन मूल्य किस प्रकार प्रभावित होता है। [संकेत : पहले सतुलन मूल्य की परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग में रेखा चित्रों की सहायता से माग, पूर्ति के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एवं सामूहिक परिवर्तन से मूल्य सतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को दिखाइये।]

2 'हम यह विवाद कर सकते हैं कि बँची का ऊपरी फलका या नीचे का फलका (blade) बागज को काटता है जिस प्रकार कि मूल्य उपयोगिता से या उत्पादन व्यय से नियंत्रित होता है।' इस वचन की विवेचना करिए। [संकेत : जेवन्स व मार्शल के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइये कि माग शक्ति व पूर्ति शक्ति दोनों का ही मूल्य निर्धारण में महत्व है। इन शक्तियों की व्याख्या कीजिए तथा सतुलन मूल्य के निर्धारण को सोदाहरण समझाइये।]

## पूर्ण प्रतिस्पर्धा : मूल्य व उत्पादन निर्धारण (Perfect Competition Price & Output Determination)

*"Short run price output analysis treats situations in which the firm is free to vary its output but does not have time to change its scale of plant in the long run firms have time to increase or decrease their scales of plant and there is ample time and opportunity for new firms to enter or for existing firms to leave the industry"*

Leftwich

सागत तथा घागम के अध्ययन के पश्चात् अब हम पूरा स्पर्धा के अन्तर्गत 'मूल्यकाल' तथा 'दीघकाल' मे 'मूल्य' तथा 'उत्पादन' के निर्धारण के प्रश्न पर विचार करेगे । यहा पर यह बन्सा देना आवश्यक है कि मूल्य निर्धारण की समस्या की पूरा जानकारी के लिए 'उत्पादन लागत', 'उत्पादक का घागम' तथा 'भाग' का सम्पक् अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि मूल्य निर्धारण इन्ही तत्वो पर निर्भर है । (अत इन विषयो से सम्बन्धित अध्यायो का अध्ययन करने तथा उन्हें सली भाति समझ लेने के पश्चात् ही विद्यार्थी इस अध्याय का अध्ययन कर ।) मूल्य निर्धारण के साथ ही राग फर्म तथा उद्योग की साम्यावस्था (Equilibrium of the Firm and Industry) की भी जानकारी आवश्यक है अत इस अध्याय से इन पर भी प्रकाश डाला गया है । यहा पर 'फर्म' तथा 'उद्योग' का अर्थ भी समझ लेना चाहिए ।

(1) फर्म (Firm) जिस सस्थान द्वारा उत्पादन किया जाना है उसे उत्पादन इकाई (production unit) कहते हैं जैसे कोई कारखाना । फर्म एक या अधिक उत्पादन इकाइयो को कहते है जो कि एक ही स्वामित्व (same ownership) के अन्तर्गत हा । संयुक्त्सन के अनुसार पूरा स्पर्धा के अन्तर्गत फर्म उसे कहते हैं,

<sup>1</sup> Leftwich, Richard H, Price System and Resource Allocation, pp 160-167

‘जो जितनी मात्रा में चाहे, प्रचलित बाजार मूल्य पर बेच सकती है, परन्तु उस बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करने की क्षमता उसमें नहीं होती है।’<sup>2</sup>

(ii) उद्योग (Industry) बहुत सी ऐसी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, जो उसी बाजार (same market) के लिए किसी वस्तु का उत्पादन कर रही हो। परन्तु E.A.G. Robinson ने ‘उसी बाजार’ तथा वस्तु शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है। उन्हीं के शब्दों में ‘इसे (बाजार को) उत्पादित वस्तु अथवा बाजार जिनके लिए यह (वस्तु) पैदा की जाती है के सदृश में परिभाषित करना बहुत सी अवस्थाओं में या तो असम्भव है या कम से कम असतोषजनक। व्यावहारिक रूप में, हम अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि हम उनका उदाहरण सामने रखें जो वास्तविक रूप से उद्योगों में लगे हुए हैं। कुछ नियोजक (employers) अपने को एक उद्योग से सम्बन्धित केवल इसलिए मान लेते हैं कि उनके हित समन्वित (common) होते हैं। एक ही प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करने वाले (जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग में) या एक ही प्रकार की मशीनों का प्रयोग करने वाले या उत्पादन की एक ही प्रणाली अपनाने वाले भी अपने को एक ही उद्योग के प्रतिनिधि मान सकते हैं।<sup>3</sup> कोई ऐसी फर्म भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण कई उद्योगों से सम्बन्धित हो। संमूलसन के अनुसार “पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत बहुत सी प्रतिस्पर्धी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं।”

### 1. फर्म की साम्य-अवस्था (Equilibrium of the Firm)

फर्म की साम्य अवस्था उस अवस्था को कहते हैं, जिसमें फर्म का लाभ अनुकूलतम हो (when profit is optimised)। साम्य-अवस्था में फर्म का लाभ सामान्यतया अधिकतम होता है। उत्पादन की जिस मात्रा पर, लाभ अधिकतम होता है, उस मात्रा को साम्य उत्पादन (Equilibrium Output) कहते हैं। यह माना वह मात्रा होती है, जिसमें कम या अधिक उत्पादन करने से फर्म के कुल लाभ में कमी होती है।

साम्य का अर्थ परिवर्तनशीलता की अनुपस्थिति भी होता है (Equilibrium as *position of no change* or ‘stage of no change’ or ‘position of balance’) अर्थात् फर्म साम्य की स्थिति में उस समय होती है, जबकि कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा यदि परिवर्तन किया जाता है तो कुल लाभ में कमी

<sup>2</sup> “One who can sell all he wishes at the going market price, but is unable in any appreciable degree to raise or depress that market price”  
—Samuelson, *P. A. op.*, cit., p. 454

<sup>3</sup> “Robinson E. A. G., *The Structure of Competitive Industry*.”

होती है। फर्म परिवर्तन हीनता की स्थिति में उभे समय पहुँचती है जबकि न्यूनतम लागत पर उसका उत्पादन ऐसी मात्रा पर पहुँच जाता है जिस मात्रा पर उभरा लाभ अधिकतम होता है। यह वह अवस्था होती है, जिसमें फर्म परिवर्तन करना नहीं चाहती है। फर्म में, इस अवस्था में न तो विस्तार की प्रवृत्ति होती है और न संकुचन की। एक प्रकार में मान्यताएँ, मनुष्य या स्थिरता की अवस्था होती है। साम्य अवस्था में फर्म के उत्पादन की मात्रा ऐसी मात्रा होती है, जिस पर उसका लाभ अधिकतम होता है।

**साम्य-अवस्था की मान्यताएँ (Assumptions)**

साम्य-अवस्था का विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

1 फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इस प्रकार फर्म का व्यवहार विवेकपूर्ण (rational) होता है। फर्म कम लाभ से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाती है।

2 उत्पादक या फर्म उत्पादन-लागत को न्यूनतम करने के लिए प्रयत्नशील रहती है।

3 यह मान लिया जाता है कि विभिन्न पड़नों (Inputs) की कीमतें ज्ञात होती हैं। उत्पादन साधनों की सभी इकाइयाँ समान रूप से कार्य-कुशल होती हैं तथा उनकी पूर्ण बढ़त की ओर अनन्त (infinitely elastic) होती है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादक, वनमान कीमत या पुरस्कार देकर उत्पादन साधनों की जितनी मात्रा चाहे, काम में लगा सकता है।

## 2 अधिकतम लाभ (Profit Maximization)

फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। अधिकतम लाभ किस स्थिति में प्राप्ति होगा ? इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। सामान्य रूप से अधिकतम लाभ की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है।

1 कुल आगम तथा कुल आगम द्वारा तथा 2. सीमान्त व औसत लागत तथा आगम द्वारा

**1. अधिकतम लाभ : कुल आगम तथा कुल लागत द्वारा ज्ञात करना (Maximisation of Profits . through Total Revenue and Total Cost)**

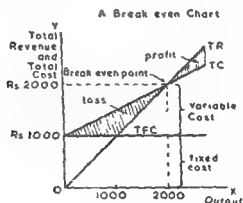
उत्पादन की निम्न मात्रा पर कुल आगम तथा कुल लागत का अन्तर अधिकतम होता है, उस बिन्दु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है ( Profit is maximised when the difference between Total Revenue and Total Cost is maximum )। इसके लिए 'कुल लागत वक्र' (Total Cost Curve) तथा कुल आगम वक्र (Total Revenue Curve) का प्रयोग किया जाता है। इन वक्रों की सहायता से जो चार्ट बनता है उस Break-even Chart कहते हैं।

**Break-even Chart तैयार करना :** यह चाट कुल आगम तथा कुल लागत रेखाओं द्वारा तैयार किया जाता है। मान लीजिए किसी फर्म की 'अल्पकालीन-लागत सूची' अधोलिखित सारणी के अनुसार है -

**फर्म की अल्पकालीन लागत तालिका (रुपये में)**

उत्पादन (इकाइयों)	कुल निश्चित लागत (TFC)	कुल परिवर्तनशील लागत (TVC)	कुल लागत (TC)
0	1 000	0	1,000
1,000	1 000	500	1,500
2,000	1,000	1,000	2,000
3,000	1,000	1,500	2,500

मान लीजिए फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का बिक्रय-मूल्य एक रुपया प्रति इकाई है (भाग की मात्रा चाहे जितनी भी हो)। उपर्युक्त मांगों के आधार पर Break-even Chart निम्न चित्र के अनुसार होगा। चित्र में TR तथा विभिन्न उत्पादन-मात्राओं (बिक्री) पर कुल आगम प्रदर्शित करती है। TFC रेखा कुल निश्चित-लागत को प्रकट करती है जो आधार रेखा के समानान्तर है, क्योंकि कुल निश्चित



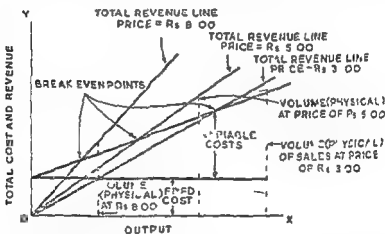
चित्र न० 92

लागत प्रत्येक अवस्था में 1,000 रुपए है। TC रेखा कुल लागत का प्रकट करती है (TFC + TVC)। TR तथा TC रेखाएँ जिस बिन्दु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस Break-even point कहते हैं। यह बिन्दु यह प्रकट करता है कि उत्पादन की मात्रा 2,000 इकाइया होने पर कुल-आगम तथा कुल-लागत बराबर होगी। (कुल लागत 2 000 रुपए तथा कुल आगम 2,000 रुपए) 2,000 इकाइया से कम उत्पादन होने पर फर्म की हानि उठानी पड़ेगी। इसमें अधिक उत्पादन होने पर फर्म को लाभ होगा। Break-even Chart द्वारा फर्म की दशा का ज्ञान सरलता से हो जाता है।



साधारणतया यह चार्ट सीधी रेखाओं द्वारा तैयार किया जाता है, यद्यपि वक्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। सीधी रेखाएँ यह मानकर चलती हैं कि कुल-लागत में परिवर्तन उत्पादन में परिवर्तन के आनुपातिक होते हैं (Straight lines mean the linear assumption that changes in total costs are proportional to changes in output)।

उपर्युक्त चार्ट में यह मान लिया गया है कि कीमत एक रुपया प्रति इकाई दी हुई है। दूसरे शब्दों में यह मान लिया गया है कि माग दी हुई है। परन्तु कीमत में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए कई मूल्यों से सम्बन्धित कुल-आयम रेखाएँ खींची जाती हैं। प्रत्येक मूल्य पर उत्पादन तथा विपणन की मात्राएँ चाट द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। चित्र सं० 93 से इस प्रकार के चार्ट (कई अनुमानित कीमतों पर आधारित) का ज्ञान होता है। चित्र में 3 5 तथा 8 रुपये प्रति इकाई मूल्यों से सम्बन्धित कुल आयम रेखाएँ (TR) खींची गई



चित्र सं० 93

हैं। कुल लागत रेखा, भी साथ में दी गई है। चित्र में तीन Break even points हैं, जो इन मूल्यों पर उत्पादन की मात्रा का प्रकट करते हैं। इन कीमतों में से, 5 रुपए कीमत सबसे अधिक लाभ प्रदान करती। अतः पांच रुपए कीमत पर जो उत्पादन होगा वह साम्य उत्पादन होगा।

## 2 अधिकतम लाभ - सीमांत तथा औसत वक्रों द्वारा ज्ञात करना (Profit Maximisation - From Marginal and Average Curves)

Break even चार्ट द्वारा लाभ की मात्रा ज्ञात करना एक जटिल तथा महंगा तरीका है, क्योंकि कुल आयम तथा कुल लागत वक्रों का रूप जटिल होने पर, अधिकतम लाभ सरलता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः अधिकतम लाभ या फर्म

की साम्य अवस्था ज्ञात करने के लिए 'सीमांत' तथा 'औसत' वक्रों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया उत्पादन की जिस मात्रा पर सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं, उत्पादन की वह मात्रा अधिकतम लाभ प्रदान करती है (when  $MR = MC$  profit is maximised)। फर्म का लाभ औसत आय (AR) तथा औसत लागत (AC) के अन्तर से जाना जा सकता है। (यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दशा में  $MR = MC$  होने से लाभ की मात्रा अधिकतम नहीं होगी, यह अवस्था न्यूनतम हानि की भी अवस्था हो सकती है, विशेष विवरण अगले पृष्ठों पर देखिए।) इस अध्ययन में हमने फर्म की साम्य अवस्था का अध्ययन सीमांत तथा औसत वक्रों की ही सहायता से किया है।

### 3. पूर्ण स्पर्धा • उत्पादों में मूल्य तथा उत्पादन

(Perfect Competition • Price And Output in The Short Run)

पूर्ण स्पर्धा की विशेषताओं का पहले उल्लेख किया जा चुका है। यहां पर मध्ये में उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक है (1) वस्तु में एकव्यता (Homogeneity) होती है, (2) क्रान्तियों तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे उनमें से कोई भी मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है तथा माग पूर्ण लोचदार होती है, (3) वस्तु की माग, पूर्ति तथा मूल्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है, तथा (4) फर्मों के प्रवेश करने या छोड़ने की स्वतन्त्रता होती है।

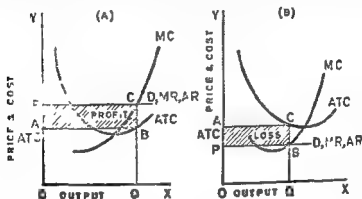
उत्पादों में उस अवधि को कहते हैं जिसमें फर्म अपने वर्तमान साधनों द्वारा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है, परन्तु उत्पादन साधनों की मात्रा में या आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। प्रत्येक फर्म उद्योग के कुल उत्पादन की तुलना में, इतना कम उत्पादन करती है कि वह मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। फर्म केवल अपनी उत्पादन की मात्रा के सम्बन्ध में ही निर्णय ले सकती है।

#### (1) फर्म की साम्य अवस्था •

फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना या न्यूनतम हानि उठाना होता है। लाभ की मात्रा अधिकतम या हानि की मात्रा न्यूनतम उस समय होती है, जबकि सीमान्त लागत सीमांत आय के बराबर होती है (when  $MC = MR$ )। यदि सीमान्त लागत सीमांत आय से अधिक है तो उत्पादक उत्पादन की मात्रा कम कर देता है। यदि सीमान्त लागत सीमांत आय से कम है तो उत्पादक उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर लाभ में वृद्धि कर सकता है। परन्तु यदि सीमांत लागत सीमान्त आय के बराबर है तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादक को कोई लाभ नहीं होगा। अतः यह स्मरण रखना चाहिए कि लाभ की मात्रा अधिकतम तथा हानि की मात्रा न्यूनतम उस समय होती है जबकि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर हो

(Profit is maximum or loss is minimum when Marginal Revenue is equal to Marginal Cost) : इस तथ्य का स्पष्टीकरण चित्र नं० 94 में किया गया है :

पूर्ण स्पर्धा में माग पूर्णतया लोचदार होती है, जो PD द्वारा प्रदर्शित की गई है। साथ ही माघ पूर्ण स्पर्धा में माग-वक्र, सीमान्त आय वक्र तथा औसत आय वक्र एक ही वक्र के रूप में होते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि OQ मात्रा का उत्पादन



चित्र नं० 94

करने से सीमान्त लागत, सीमान्त आय के बराबर होती है ( $MC = MR$ )। ATC कुल उत्पादन लागत वक्र है, MC सीमान्त लागत वक्र है तथा MR सीमान्त आय वक्र है। OQBA कुल उत्पादन लागत तथा ABCP लाभ की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं (चित्र A)।

चित्र नं० 94 [B] में OQ मात्रा का उत्पादन करने से हानि की मात्रा न्यूनतम होती है। इस स्थिति में भी सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर है ( $MC = MR$ )। OQCA कुल उत्पादन लागत तथा PBCA हानि की मात्रा को व्यक्त करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि उस समय होती है जबकि सीमांत लागत सीमान्त आय के बराबर हो। चित्र से स्पष्ट है कि इस स्थिति में प्रतिस्पर्धी हथकौड़ी की अवस्था स्थिति के हैं, उत्पादन को अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि नहीं प्राप्त होगी। अन्य स्थितियों में या तो उसका लाभ कम हो जाएगा, या हानि बढ़ जाएगी।

उपरोक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत, उत्पादन की जिस मात्रा पर सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय बराबर होगी, उत्पादन की वह मात्रा फर्म के लिए साम्य उत्पादन (Equilibrium output) होगी तथा ऐसी दशा में फर्म साम्य अवस्था में होगी, क्योंकि फर्म की साम्य-अवस्था का अर्थ उस अवस्था में है, जिसमें फर्म लाभ की अधिकतम मात्रा

को कायम रख सके। यदि डम मात्रा से कम या अधिक उत्पादन किया जाता है तो फर्म का लाभ कम हो जाएगा या हानि की मात्रा बढ़ जाएगी।

अल्पकाल में, पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत, फर्म की साम्य अवस्था को सूत्र रूप में निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। फर्म साम्य-अवस्था में उस समय होगी जब कि कीमत या औसत आय = सीमान्त लागत = सीमान्त आय

$$P \text{ or } AR = MC = MR$$

यह वह अवस्था होगी जिसमें फर्म का लाभ अनुकूलतम होगा।

क्या फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है ?

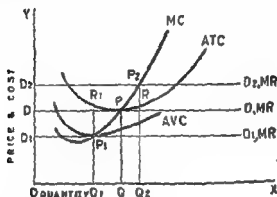
(Can a firm continue to produce even at a loss ?)

फर्म की साम्य अवस्था के उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि फर्म साम्य अवस्था में उस समय होगी, जबकि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर होगी, परन्तु सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत के बराबर होने पर फर्म को हानि भी सहन करनी पड़ सकती है। प्रश्न है—क्या फर्म हानि सहन करके भी उत्पादन जारी रख सकती है ? यदि फर्म को हानि हो रही है तो फर्म को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उत्पादन जारी रखा जाए या बन्द कर दिया जाए। हम यह जानते हैं कि फर्म की कुल लागत में निश्चित लागत (Fixed Costs) तथा परिवर्तनशील लागत (Variable Costs) सम्मिलित होती हैं। सामान्यतया फर्म के कुल औसत उत्पादन व्यय के बराबर कीमत प्राप्त होती चाहए, परन्तु अल्पकाल में उत्पादक कुल उत्पादन व्यय से कम कीमत प्राप्त करने पर भी उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि उत्पादक यह जानता है कि उत्पादन बन्द कर देने पर भी उसे निश्चित लागत का भार सहन करना पड़ेगा। अतः अल्पकाल में यदि उत्पादक को केवल परिवर्तनशील लागत के बराबर भी कीमत प्राप्त हो जाती है तो वह उत्पादन जारी रखेगा। यदि उसे परिवर्तनशील लागत के बराबर भी कीमत नहीं मिलती तो वह उत्पादन बन्द कर देगा।

अतः अल्पकाल में उत्पादन जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि फर्म को कम से कम कुल औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर कीमत प्राप्त हो। इस तथ्य का स्पष्टीकरण चित्र न० 95 में किया गया है :

चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन तथा OY अक्ष पर कीमत प्रदर्शित की गई है। ATC, AVC तथा MC क्रमशः 'कुल औसत उत्पादन लागत', 'औसत परिवर्तन लागत' तथा 'सीमान्त लागत वक्र' हैं।  $D_1D_1$ ,  $D_2D_2$  तथा DD मांग रेखाएँ हैं जो मांग की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती हैं।  $P_1$  बिन्दु पर MC तथा AVC एक दूसरे को काटती हैं। उत्पादक को उत्पादन जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे कम से कम  $Q_1P_1$  प्रति इकाई कीमत प्राप्त हो। यदि कीमत इससे कम है तो वह उत्पादन बन्द कर देगा, क्योंकि उसे परिवर्तनशील लागत के बराबर भी

कीमत प्राप्त नहीं हो रही है। यदि माग बढ़कर  $DD$  हो जाती है तो कीमत  $QP$  हो जाएगी। इस कीमत पर 'सीमान्त आय' 'सीमान्त लागत' के बराबर है। इस कीमत पर उत्पादक  $OQ$  मात्रा का उत्पादन करेगा। यदि माग घटकर  $D_2D_3$  हो जाती है तो ऐसी अवस्था में  $MC$ ,  $D_2D_3$  को  $P_2$  बिन्दु पर काटती है तथा उत्पादन



चित्र सं० 95

की मात्रा  $OQ_2$  हो जाती है। ऐसी अवस्था में उत्पादक को  $P_2R$  के बराबर अधिक लाभ प्राप्त होगा। अधिक लाभ की अवस्था में तब तक प्रवेश करेगी तथा पूर्ति में वृद्धि होगी। इस प्रकार लाभ की मात्रा कम हो जाएगी तथा कीमत  $PQ$  के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस बिन्दु पर उत्पादन करने से न तो हानि होगी न लाभ।

अब स्पष्ट है कि उत्पादक  $P_1Q_1$  से कम कीमत प्राप्त करने पर उत्पादन गरी करेगा, परन्तु यदि उत्पादक का अनुमान है कि माग में कमी अल्पकालीन है तथा लक्ष्य में माग बढ़ेगी तो वह  $Q_1P_1$  कीमत पर भी उत्पादन जारी रखेगा क्योंकि उसे शीघ्रत परिवर्तनशील लागत के बराबर कीमत प्राप्त हो रही है। सामान्यतः यदि उत्पादक को शीघ्रत परिवर्तनशील लागत तथा निश्चित लागत का कुछ भाग प्राप्त हो जाता है तो वह उत्पादन जारी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि यदि उसे कुछ समय के लिए केवल शीघ्रत परिवर्तनशील लागत के बराबर भी कीमत प्राप्त हो जाती है तो भी वह उत्पादन जारी रखेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्पकाल में यदि उत्पादक को केवल शीघ्रत परिवर्तनशील लागत (AVC) के बराबर भी कीमत प्राप्त हो जाती है तथा लक्ष्य में यदि माग बढ़ने की सम्भावना है तो भी वह उत्पादन जारी रखेगा अर्थात् वह  $ATC-AVC$  के बराबर अल्पकाल में हानि सहन कर सकता है। इससे अधिक हानि होने पर वह उत्पादन बन्द कर देगा। (यह याद रखना चाहिए कि  $AVC$  के ऊपर  $MC$  वक्र का जो भाग पड़ता

है, वह फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र भी है। AVC के नीचे किसी भी बिन्दु पर पूर्ति शून्य होगी। माग रेखा फर्म की सीमांत आय रेखा भी है।)

## (ii) उद्योग की साम्यावस्था (Industry equilibrium)

फर्मों के समूह को 'उद्योग' कहते हैं। अब तक हमने अल्पकाल में फर्म की साम्यावस्था का वर्णन किया है। परन्तु अब देखना है कि अल्पकाल में उद्योग की संतुलन स्थिति क्या होगी? तथा अल्पकाल में मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा? यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कीमत का सम्बन्ध सम्पूर्ण उद्योग से है किसी फर्म विशेष से नहीं। अतः कीमत का निर्धारण सम्पूर्ण उद्योग की माग तथा पूर्ति से किया जाता है। चूंकि उद्योग की परिस्थितियाँ उद्योग से सम्बन्धित फर्मों की कुल परिस्थितियों की प्रतीक होती हैं, तथा फर्मों की ही कीमत, आय के रूप में प्राप्त होती है, अतः माय ही साय फर्म (प्रतिनिधि के रूप में) का भी जिक्र किया जाएगा। उद्योग का मूल्य निर्धारण माग तथा पूर्ति के सामांय नियमों पर ही आधारित है।

(1) उद्योग का माग वक्र या अल्पकाल में वस्तु का माग वक्र (Short run Demand Curve of the Industry) किसी वस्तु की माग (सम्पूर्ण उद्योग के लिए) उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत माग का योग होती है। माग वक्र यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहेंगे। अतः सभी उपभोक्ताओं की मागों का योग उद्योग की वस्तु के लिए 'माग' को प्रकट करेगा।

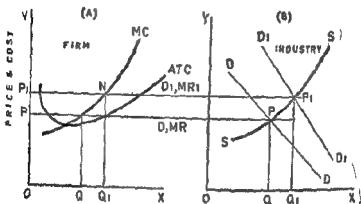
(2) उद्योग का अल्पकाल में पूर्ति वक्र (Short Run Supply Curve of the Industry) उद्योग का पूर्ति वक्र सभी फर्मों के पूर्ति वक्रों का योग है। यह अल्पकालीन पूर्ति वक्र यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न कीमतों पर एक उद्योग की समस्त फर्म कुल कितनी मात्रा बचने को प्रस्तुत है।

(3) उद्योग की साम्यावस्था (Industry Equilibrium) उद्योग के माग तथा पूर्ति वक्र जिस बिन्दु पर एक दूसरे को काटेंगे, उसी बिन्दु पर अल्पकालीन मूल्य निर्धारित होगा। इसका स्पष्टीकरण चित्र सं० 96 में किया गया है।

चित्र में  $Q$ -अक्ष पर मूल्य निर्धारण फर्म (केवल एक फर्म प्रतिनिधि के रूप में) तथा उद्योग का उत्पादन निर्धारण प्रदर्शित किया गया है। MC तथा ATC वक्र क्रमशः सीमांत लागत तथा कुल औसत लागत वक्र हैं। SS 'उद्योग पूर्ति वक्र' (सभी फर्मों का पूर्ति का योग) है। प्रत्येक फर्म लाभ की मात्रा को अधिकतम करने के लिए सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय को समान रखेगी। DD उद्योग माग वक्र है। DD तथा SS एक दूसरे का P बिन्दु पर काटते हैं। अतः PQ अल्पकालीन मूल्य होगा तथा उद्योग द्वारा OQ मात्रा बेची जाएगी (फर्मों के उत्पादन

का योग)। चित्र से स्पष्ट है कि  $P$  ऐसा बिन्दु है जहाँ पर उद्योग संतुलन की स्थिति में है। इसी बिन्दु पर फर्म का माग-वक्र तथा सीमान्त आय वक्र क्षैतिज (Horizontal) होगा।

यदि माग बढ़कर  $D_1 D_1$  हो जाती है तो कीमत बढ़कर  $OP_1$  (या  $P_1 Q_1$ ) हो जाएगी क्योंकि अल्पकालीन साम्य कीमत तथा उत्पादन बढ़ जाएँगे। इस मूल्य पर फर्म का माग-वक्र तथा सीमांत आय-वक्र  $D_1 MR_1$  हो जाएँगे। प्रत्येक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए सीमांत लागत सीमांत आय को बराबर रखने का



चित्र नं० 96

प्रदान करेगी। चित्र से स्पष्ट है कि  $N$  बिन्दु पर फर्म की सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है तथा यह बिन्दु  $P_1$  बिन्दु के बिल्कुल सीध में है। इस कीमत पर फर्म (प्रतिनिधि फर्म) का उत्पादन  $OQ_1$  तथा उद्योग की पूर्ति  $OQ_1$  होगी।

#### 4 दीर्घकाल में उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण

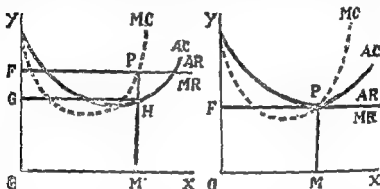
(Determination of Output and Price in the Long Run)

दीर्घकाल में निश्चित सामान तथा 'परिवर्तनशील साधन' का भेद गमयाप्त हो जाता है। दीर्घकाल में सभी सामानों 'परिवर्तनशील साधन' हो जाती हैं साथ ही साथ फर्म के प्रकार तथा उत्पादन पैमाने में भी परिवर्तन किया जा सकता है। उद्योग में फर्मों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। माग में परिवर्तन के अनुरूप पूर्ति में भी कमी या वृद्धि की जा सकती है।

##### (1) फर्म की साम्यावस्था (Firm's Equilibrium)

हम यह जानते हैं कि उत्पादों में यदि फर्म को परिवर्तनशील लागत (Variable Cost) के बराबर कीमत प्राप्त हो जाती है तो फर्म सामान्य उत्पादन बढ़ नहीं करती है। दीर्घकाल में निश्चित लागत तथा परिवर्तनशील साधन का भेद

OM उत्पादन की मात्रा तथा MP कीमत को व्यक्त करते हैं। प्रथम प्रवस्था में फर्म साम्य की अवस्था में नहीं है, क्योंकि उसे GHPF के बराबर असामान्य Abnormal Profit प्राप्त हो रहा है। द्वितीय अवस्था में फर्म साम्यावस्था में है, क्योंकि कीमत, सीमांत प्राय, औसत प्राय, सीमांत लागत तथा औसत लागत सभी बराबर हैं। यह स्मरणीय है कि अधिलाभ ध्वजित करके भी फर्म साम्यावस्था में



चित्र सं० 97

होगी जैसाकि प्रथम चित्र से स्पष्ट है कि फर्म की  $P = MC = AC = AR = MR$ , परन्तु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकती है। नई फर्मों के प्रवेश में अधिलाभ समाप्त हो जाएगा।

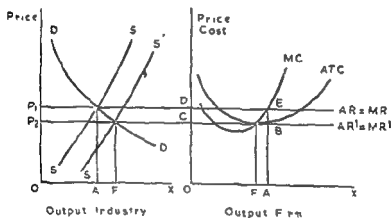
### (B) उद्योग की साम्यावस्था (Industry's Equilibrium) :

दीर्घकाल में पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत, उद्योग को पूर्ण साम्य की अवस्था में उस समय कहते हैं जबकि फर्मों की संख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसी अवस्था में फर्मों द्वारा ध्वजित लाभ सामान्य होता है।<sup>1</sup> यदि किसी फर्म को अधिक लाभ प्राप्त होता है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी और कीमत कम हो जाएगी। इस प्रकार अधिलाभ समाप्त हो जाएगा। सभी फर्में न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पादन करने लगगी तथा कीमत उत्पादन-लागत के बराबर होगी। उद्योग के दीर्घकालीन साम्यावस्था में होने के लिए यह आवश्यक है कि सभी फर्में न्यूनतम लागत पर उत्पादन करेंगी, तथा उनका प्रकार अनुकूलतम होगा। जो फर्म अकुशल होगी उसे उद्योग छोड़ देना पड़ेगा। अतः दीर्घ काल में उद्योग के साम्यावस्था में होने के लिए उन्हीं शर्तों का पाया जाना आवश्यक

<sup>1</sup> "An industry is said to be in full equilibrium when there is no tendency for the number of firms to alter. The profits earned by the firms in it are then normal."



इस है, जो कि फर्म के लिए आवश्यक है। अन्तर केवल इतना ही है कि उद्योग के दीर्घकालीन सन्तुलन के लिए, उसकी सभी फर्मों का दीर्घकालीन सन्तुलन की स्थिति में होना आवश्यक है, जबकि इसकी विपरीत दशा सही नहीं है। एक फर्म लाभ अर्जित करते हुए भी दीर्घकालीन साम्यावस्था में हो सकती है, परन्तु इस अवस्था में उद्योग सन्तुलन की स्थिति में नहीं होगा। उद्योग के सन्तुलन की स्थिति में होने के लिए यह आवश्यक है कि सभी फर्म व्यक्तिगत रूप से साम्यावस्था में हो तथा उन्हें न लाभ हो रहा हो और न हानि, अर्थात् सभी फर्मों के लिए कीमत ब्रीसत लागत के बराबर हो।<sup>१०</sup>



चित्र सत्या 99

फर्म तथा उद्योग की दीर्घकालीन साम्यावस्था से सम्बन्धित समायोजन चित्र स० 99 में प्रदर्शित की गई है। अल्पकालीन कीमत  $= AR = MR$  (चित्र के दाहिने भाग में) जो  $OP_1$  के बराबर है। फर्म का उत्पादन  $OA$  है।  $OA$  उत्पादन पर सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय समान है।  $AB$  इस उत्पादन की लागत है तथा  $AE$  इस उत्पादन का आगम (Revenue) है।  $BE$  शुद्ध लाभ की मात्रा को प्रकट करता है।

गान के कारण अन्य फर्मों का प्रवेश होगा। अतः पूर्ण-रेखा (उद्योग की) निम्नकर  $SS'$  हो जाएगी अर्थात् पूर्ण बढ जाएगी तथा बाजार-मूल्य  $OP_1$  से घट

<sup>१०</sup> "An individual firm could be in long run equilibrium while making profits. But in this case the industry would not be in equilibrium. The existence of long-run industry equilibrium requires long run individual firm equilibrium at a no profit no loss level of operation."

कर  $OP_2$  हो जाएगा। इस कीमत पर फर्म का औसत-आगम तथा सीमांत-आगम वक्र, औसत लागत वक्र पर (Tangent) होगा और फर्म का उत्पादन अनुकूलतम (Optimum) होगा। यह अवस्था साम्य की अवस्था होगी।

(‘पूर्ण स्पर्धा की अवस्था में अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण’ के अध्ययन हेतु आनर्स के विद्यार्थी इसी अध्याय को पढ़ें।)

### प्रश्न व संकेत

1. पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का उत्पादन कैसे निर्धारित होता है ?

(Luck, II A I., 1962)

[संकेत—पहले ‘पूर्ण प्रतियोगिता’ का आशय समझाइये तथा फिर (i) कुल आगम व कुल लागत रेखाओं एवं (ii) सामान्त और औसत रेखाओं की रीतियों द्वारा साम्य-स्थिति की व्याख्या करिये।]

2 एक उपयुक्त चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये कि वस्तु की कीमत सीमान्त लागत और औसत लागत के समान होती है।

(Alld. B. Com, I, 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में संक्षेप में पूर्ण प्रतियोगिता को समझाइये। तत्पश्चात् चित्र की सहायता से सीमांत और औसत लागत रेखाओं द्वारा सिद्ध कीजिये कि कीमत सीमान्त लागत तथा औसत लागत के बराबर ( $P=AC=MC$ ) होती है।]

3 पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्थाओं (conditions) की व्याख्या करिये। इसके अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण को समझाइये।

(Raj. II A., 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षणों को समझाइये। दूसरे भाग के अन्तर्गत संक्षेप में दोनों विधियों—कुल आगम व कुल लागत विधि तथा सीमांत व औसत रेखा विधि की सहायता से मूल्य निर्धारण को स्पष्ट करिये। उत्तर में यथा आवश्यक चित्र भी दीजिये।]

4. पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएँ बताइये। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य किस प्रकार स्थापित होगा ?

(Delhi, B Com, 1956)

[संकेत—प्रथम भाग में पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा देकर उसके लक्षणों को बताइये और दूसरे भाग में रेखा चित्रों द्वारा फर्म के साम्य की विवेचना करिये। प्रश्न व संकेत सं० 3 भी देखिये।]

### समस्याएँ (Problems)

1 कृषि वस्तुओं का उत्पादन अनियमित प्रवृत्ति का होता है। चूंकि कृषि वस्तुओं की उत्पत्ति प्रतिस्पर्धी दशाओं में (under competitive conditions) होती

है अतः यह आशा की जाती है फसल के समय कृषि पदार्थों की अधिकतम पूर्ति होने के कारण उनके मूल्य न्यूनतम होने की आशा (expectation) की जाती है। यह विचार सामान्यतया सही क्यों नहीं उतरता ?

2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म सीमान्त लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग पर ही उत्पादन क्यों करती है, गिरते हुए भाग पर क्यों नहीं ?

3 एक फर्म के लिए सीमांत लागत कीमत का निर्धारण करती है अथवा कीमत से सीमांत लागत निर्धारित होती है ?

4 कल्पना कीजिये कि एक प्रतिस्पर्धी उद्योग को उसकी फर्मों द्वारा उत्पादित प्रत्येक इकाई के सुगतान के लिए स्थायी सहायना (permanent subsidy) दी जाती है। एक रेखाचित्र खींचकर बताइये कि मूल्य (कीमत) पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

5 नीचे एक फर्म के सम्बन्ध में ये सूचनार्थ उपलब्ध हैं—

उत्पाद	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल मागम (₹०) —	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
कुल लागत (₹०)	110	140	162	175	180	185	194	219	260	325

(i) क्या फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत उत्पादन कर रही है ?

(ii) इसकी सीमांत मागम (M.R.) क्या है ?

(iii) इसकी स्थिर लागतें (F.C.) क्या हैं ?

(iv) सीमांत लागतों की सभी उत्पादन स्तरों पर पणना कीजिये।

(v) दीर्घकाल में फर्म कितना उत्पादन करेगी ?

(vi) इसके लाभ क्या हैं ?

(vii) वह न्यूनतम कीमत क्या है जिस पर फर्म अल्पकाल तथा दीर्घकाल में अपनी उत्पत्ति देव सकती है ?

6 नीचे एक फर्म के सम्बन्ध में ये सूचनार्थ दी गई हैं—

उत्पादन (इकाइया)	सीमांत लागत (₹०)
1	6
2	5
3	4
4	5
5	8
6	12
7	18

फर्म अधिकतम लाभ चाहती है तो बताइये वह कितनी मात्रा उत्पन्न करे यदि विनय मूल्य 4 ₹०, 5 ₹० व 18 ₹० प्रति इकाई हो ?

## कीमत निर्धारण में समय-तत्व (Time Element in Price Determination)

*"As a general rule, the shorter the period which we are considering the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on value, and the longer the period the more of production on value"*

—Marshall

कीमत निर्धारण में समय का बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम मार्शल ने 'समय तत्व' पर ध्यान आकर्षित किया। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण माग तथा पूर्ति के सम्मिलित प्रभाव में किया जाता है। परन्तु समय के अनुसार माग तथा पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है, अतः कीमत निर्धारण में भी अन्तर पाया जाता है। कीमत पर माग व पूर्ति के सापेक्षिक प्रभाव का अध्ययन समय के ही सन्दर्भ में किया जा सकता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि समय जितना ही कम होगा, कीमत पर माग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा तथा समय जितना ही अधिक होगा, कीमत पर पूर्ति का प्रभाव उतना ही अधिक होगा।

मार्शल ने समय या अवधि को चार भागों में बाटा है :

1. अति अल्पकालीन अवधि (Very Short Period) : यह अवधि अत्यन्त ही अल्प समय के लिए होती है। कुछ घण्टे, एक दिन या एक सप्ताह। इसमें पूर्ति निश्चित (Fixed) होती है। इसे बाजार अवधि (Market period) भी कहते हैं। बाजार मूल्य, माग तथा पूर्ति के समुच्चन द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है, अतः मूल्य निर्धारण में माग का प्रमुख हाथ रहता है।

2. अल्पावधि (Short Period) : अल्पावधि में पूर्ति में वृद्धि, उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता का ही उपयोग कर की जा सकती है। इस अवधि में प्लांट के उत्पादन मान (Scale of Plant) में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस

अवधि में पूर्ति ■ कुछ वृद्धि की जा सकती है, अतः अति अल्पकालीन समय की अपेक्षा इस अवधि में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। फर्मों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। सामान्यतया कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है परंतु मांग की दृष्टि से यदि उत्पादन को परिवर्तनशील लागत तथा निश्चित लागत के कुछ भाग के बराबर भी कीमत प्राप्त हो जाती है तो वह उत्पादन जारी रखता है। इस अवधि से सम्बंधित सतुलन मूल्य को अल्पकालीन सामान्य मूल्य (Short Run Normal Price) कहते हैं।

**3 दीर्घावधि (Long Period)** दीर्घावधि उस अवधि को कहते हैं जिसमें फर्मों के प्रकार तथा उद्योगों में फर्मों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह अवधि ज्ञानी लम्बी होती है कि इसमें निश्चित साधन (Fixed Factors) भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस अवधि में पूर्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस अवधि में सम्बंधित कीमत को सामान्य मूल्य या दीर्घकालीन सामान्य मूल्य (Normal Price or Long Run Normal Price) कहते हैं। दीर्घावधि में कीमत अनुकूलनम फर्म की औसत उत्पादन लागत के बराबर होती है।

**4 अति दीर्घावधि (Very Long Period)** यह अवधि इतनी लम्बी होती है कि इसमें उत्पादन के साधनों के उत्पादक साधनों (Factors of production) में भी परिवर्तन हो जाता है। पूँजीगत उपकरण (Capital equipment) की लागत में कमी या वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र का रूप बदल जाता है। मांग में भी आदत या रुचि में परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो जाता है। इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं, माछल ने उन्हें *Secular changes in value* कहा है।

उपयुक्त चार प्रकार की अवधि में से कीमत निर्धारण में प्रथम तीन का महत्त्व है। आजकल चौथी अवधि को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। यह याद रखना चाहिये कि ये समय घड़ी (Clock) पर आधारित नहीं है बल्कि ये *Operational Time* है। अर्थात् मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन करने से सम्बंधित है। (निश्चित साधनों में समायोजन द्वारा) (The time required to alter supply by adjusting the fixed equipment to the conditions of demand)। तात्पर्य यह है कि —

1 अति अल्पकालीन या बाजार काल में पूर्ति निश्चित होती है।

2 उत्पादकों में पूर्ति में परिवर्तन, वर्तमान उत्पादन क्षमता की सीमा तक किया जा सकता है। फर्मों की संख्या अपरिवर्तित रहती है।

3 दीर्घावधि में उत्पादन मापना तथा उत्पादन में परिवर्तन कर पूर्ति में आवश्यक समायोजन किया जा सकता है। फर्मों की संख्या भी बदल सकती है।

पिछले पृष्ठों में उन तत्वों (concepts) पर प्रकाश डाला गया है जिनके द्वारा मूल्य-विश्लेषण (price analysis) में सहायता मिलती है। यहाँ पर हम विभिन्न अवधि (different time periods) के सदर्भ में पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण पर विचार करेंगे। पूर्ण स्पर्धा की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है तथा उनकी विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है। यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है कि पूर्ण स्पर्धा में मूल्य निर्धारण पुरे उद्योग के द्वारा किया जाता है, किसी एक विशेष द्वारा नहीं। पूर्ण स्पर्धा में कीमत (Price) सभी केनाओं तथा बिक्रेताओं की सम्मिलित माग और पूर्ति का परिणाम होती है। किसी एक फर्म का प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता।

कीमत का निर्धारण माग तथा पूर्ति पर निर्भर है तथा पूर्ति समय के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि फर्मों को अपनी प्रबन्ध व्यवस्था, उत्पादन के पैमाने तथा उत्पादन के टग में समायानुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। पूर्ति में समायोजन (adjustment) करने के दृष्टिकोण से समय तीन प्रकार के हो सकते हैं : (1) बाजार समय (Market Period) (2) अल्पकाल (Short Period) तथा (3) दीर्घकाल (Long Period)।

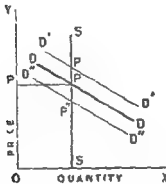
कृषि पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले कारण विभिन्न समयों में अलग-प्रलग होते हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि कीमत निर्धारण का अध्ययन इन तीनों समयों में अलग-अलग किया जाए।

### 1 बाजार मूल्य (Market Price)

किसी वस्तु का बाजार मूल्य वह मूल्य है जो बाजार में अल्प समय के लिए (एक दिन या एक सप्ताह) बाजार में पाया जाता है। बाजार समय उस अल्प समय को कहते हैं जिसके अन्दर उत्पादन की दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा जिसमें विक्रेता के पास वस्तुओं का निश्चित स्टॉक (Fixed Stock) रहता है। इसमें समय इतना कम रहता है कि अनिश्चित इकाइयों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान स्टॉक में से ही बिक्री की जाती है। वस्तु की पूर्ति उसके स्टॉक तक ही सीमित रहती है। वस्तु की माग अधिक हो जाने पर कम समय होने के कारण उसकी पूर्ति में कृत्रिम नहीं की जा सकती तथा माग कम हो जाने पर उनकी पूर्ति में कमी भी नहीं की जा सकती। बाजार समय को स्पष्ट करना कठिन है। उदाहरण के लिए उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं के लिए बिजली की पूर्ति, उत्पादन लगातार होने से, सीमित से बढ़ाई जा सकती है, बाजार समय बहुत कम होता है। यह कुछ दिनों का या कुछ घण्टों का भी हो सकता है परन्तु कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं के लिये बाजार समय कुछ महीनों का हो सकता है।

‘बाजार-काल’ को ‘अति अल्पकाल’ (Very Short Period) या ‘तत्कालिक समय’ (Immediate Period) भी कहते हैं। यह अवधि इतनी कम होती है कि

उत्पादन की दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माग बढ़ने पर, केवल वर्तमान स्टॉक से ही पूर्ति स्थिर या निश्चित (Fixed) होती है। कीमत मुख्यतः माग द्वारा निर्धारित होती है। माग अधिक होने पर कीमत ऊँची उठती है तथा माग कम होने पर कीमत नीचे गिरती है। इस तथ्य को चित्र सख्या 100 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। SS पूर्ति रेखा है, जो एक खड़ी रेखा के रूप (Vertical) में है, जो इस बात का सूचक है कि पूर्ति स्थिर है। DD माग रेखा है जो पूर्ति रेखा को बिन्दु P



चित्र सख्या 100

पर काटती है मत मूल्य PS होगा। यदि माग बढ़कर  $D'D'$  हो जाए तो कीमत  $SP$  होगी तथा यदि माग घटकर  $D''D''$  हो जाए तो कीमत घटकर  $P''S$  हो जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि अति-अल्पकाल में, कीमत माग द्वारा निर्धारित होती है, पूर्ति का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत कम पड़ता है। माग में परिवर्तन के अनुसार कीमत बदलती रहती है। इस मूल्य को बाजार-मूल्य या अति अल्पकालीन सामान्य मूल्य (Very Short Period equilibrium-Price) कहते हैं।

## 2. अल्पकालीन सामान्य-मूल्य (Short Run Nomral Price)

अल्पकालीन सामान्य-मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका सम्बन्ध अल्पकाल से होता है। हम यह जानते हैं कि अल्पकाल उम अवधि को कहते हैं जिसमें फर्मों माग में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि केवल अपने वर्तमान साधनों का अधिक उपयोग करके कर सकती है। फर्मों की सख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फर्मों को वतना ही समय मिलना है जिससे बड़ी हुई माग की पूर्ति वर्तमान प्लांट मशीनरी आदि को उत्पादन-क्षमता का अधिकारिक उपयोग कर सकें। इस प्रकार अल्पकाल में उत्पादक, पूर्ति की मात्रा में कुछ सोमा तक समायोजन कर सकते हैं।

अतः अल्पकाल में माग परिवर्तन के कारण पूर्ति में कुछ सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। अल्पकाल में माग में वृद्धि का अर्थ है, पूर्ति में भी कुछ सीमा तक वृद्धि का पाया जाना। इसी प्रकार माग घटने का अर्थ है, पूर्ति को माग में भी कमी करना। परन्तु अल्पकाल में माग के साथ पूर्ति का पूर्ण समायोजन सम्भव नहीं होता है। यदि माग में अधिक वृद्धि हो जाए, तो पूर्ति में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, अतः मूल्य ऊँचा उठेगा तथा उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि माग में कमी होती है तो कीमत नीचे गिरेगी, अतः उत्पादकों को हानि उठानी पड़ेगी। परन्तु लाभ व हानि की मात्रा उतनी अधिक नहीं हो सकती है, जितनी कि 'बाजार अर्थाथ' में सम्भव होती है।

अल्प काल में भी उत्पादक इस बात का प्रयत्न करता है कि कीमत सीमात सागत में बराबर हो। परन्तु यदि उसे केवल परिवर्तनशील लागत (variable costs) के बराबर भी कीमत प्राप्त होती है तो भी वह उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि उत्पादन बन्द कर देने पर भी उसे 'निश्चित लागत' (fixed costs) वहन करनी पड़ेगी। (मार्शल ने variable cost को prime cost तथा fixed cost को supplementary cost कहा है।)

अल्पकाल में भी मूल्य निर्धारण बाजार-काल की भांति माग तथा पूर्ति के साध्य द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात् जिस कीमत पर वस्तु की माग तथा पूर्ति परावर होती है वही कीमत निर्धारण होता है।

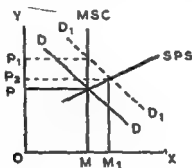
(क) वस्तु की माग : कीमत अधिकारण अर्थों में वस्तु की माग पर निर्भर करेगी। यदि माग में वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ेगी, यदि माग में कमी होती है तो कीमत घटेगी।

(ख) वस्तु की पूर्ति : उत्पादक इस बात की चेष्टा करता है कि उसे सीमात सागत के बराबर कीमत प्राप्त हो। अतः अल्पकाल में पूर्ति वक्र का स्वरूप फर्म के सीमान लागत वक्र की भांति होगा (उद्योग का पूर्ति-वक्र कर्मों के पूर्ति-वक्रों का योग होगा)। अल्पकाल में पूर्ति वक्र की स्थिति निश्चित होगी, क्योंकि परिवर्तन उसी वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर होगा (अर्थात् पूर्ति की मारियों की परिवर्तन नहीं किया जा सकता है) अर्थात् पूर्ति वक्र स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता (There can't be shifts in supply curve)। परन्तु यदि परिवर्तनशील साधन में भी परिवर्तन होता है और परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर, वर्तमान मशीन आदि का अधिक उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो कर्मों की सीमात लागत में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में दूसरा पूर्ति वक्र बनाना पड़ेगा। अल्पकाल में, बाजार काल की भांति पूर्ति पूर्ण स्थिर नहीं होती है। वर्तमान साधनों



का अधिक उपयोग कर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान उत्पादन क्षमता तक पूर्ति की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। वस्तु के मूल्य-निर्धारण में, पूर्ति की अपेक्षा माग का अधिक प्रभाव पड़ेगा।

(ग) मूल्य निर्धारण : अल्पकालीन सामान्य-मूल्य-निर्धारण का स्पष्टीकरण चित्र मर्या 101 में होता है। चित्र में MSC बाजार-पूर्ति-रेखा (Market Supply Curve) है। (यह मान लिया गया है कि पूर्ति पूर्ण स्थिर है तथा सम्पूर्ण स्टॉक वर्तमान मूल्य पर खेचने के लिए प्रस्तुत है)। DD माग वक्र है बाजार-मूल्य OP है। वस्तु की माग में वृद्धि होने पर  $D_1D_1$  नया माग-वक्र है। उत्पादक वर्तमान



चित्र सं० 101

उत्पादन क्षमता का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करेंगे जिससे बड़ी हुई माग की पूर्ति की जा सकेगी। पूर्ति में परिवर्तन होगा SPS अल्पकालीन पूर्ति (Short Period Supply) वक्र है। इस प्रकार कीमत  $OP_2$  होगी। यह याद रखना चाहिए कि यदि केवल वर्तमान स्टॉक तक ही पूर्ति सीमित है तो माग बढ़ने के कारण बाजार मूल्य  $OP_1$  हो जाएगा। परन्तु अल्पकाल में वर्तमान क्षमता के उपयोग द्वारा पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है अतः अल्पकालीन पूर्ति-वक्र, बाजार पूर्ति वक्र के दाहिने होगा। पूर्ति में वृद्धि होगी, अतः अल्पकालीन सामान्य-मूल्य बड़ी हुई माग पर, बाजार-मूल्य से कम होगा ( $OP_1$  बाजार मूल्य तथा  $OP_2$  अल्पकालीन सामान्य मूल्य होगा।)

अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण में 'निश्चित लागतों' पर ध्यान नहीं दिया जाता है। J. M. Keynes ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया है। उनका कहना है कि अल्पकालीन सीमांत लागत में 'निश्चित लागत' का भी प्रश्न वर्तमान रहता है, अर्थात् निश्चित उपकरणों (Fixed equipments) के जिस माग का प्रयोग साहसी वर्तमान उत्पादन के लिए करता है तथा उन्हें बेकार नहीं पड़ा रहने देगा, उसकी लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने ऐसी लागत को 'प्रयोगक

लागत' (user cost) कहा है। इस प्रकार अल्पकालीन सीमात लागत में सम्पूर्ण परिवर्तनशील लागत तथा निश्चित लागत के कुछ भाग को सम्मिलित करना चाहिए।

### 3. दीर्घकालीन सामान्य मूल्य (Long Run Normal Price)

1. परिभाषा : दीर्घकालीन सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका सम्बन्ध दीर्घकाल से होता है। दीर्घकाल में उत्पादक को इतना समय मिल जाता है कि वह उत्पादन साधनों तथा फर्म के आकार व उत्पादन मान में परिवर्तन कर उत्पादन की मात्रा में भाग के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल में भाग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को पूरा समय मिल जाता है। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य वास्तविक दीर्घकालीन सामान्य मूल्य होता है, क्योंकि इसी मूल्य द्वारा उत्पादन तथा उपभोग का प्रवाह समायोजित होता है। बाजार-मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य के बराबर होने की होती है, अतः बाजार-मूल्य सामान्य मूल्य के इद-गिद घबकर लगाता है। एडम स्मिथ ने सामान्य-मूल्य के लिए प्राकृतिक कीमत (Natural Price) तथा मार्शल ने Normal Price शब्दों का प्रयोग किया है। मार्शल ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है : "एक वस्तु की प्राकृतिक या सामान्य कीमत वह है जिसे आर्थिक शक्तियाँ दीर्घकाल में लाने के लिए प्रवृत्त होती हैं। यह औसत मूल्य है जिसे आर्थिक शक्तियाँ लाती हैं, यदि जीवन की सामान्य दशाएँ, इतने लम्बे समय तक स्थैतिक हों जिसमें उनका (आर्थिक शक्तियों का) पूरा प्रभाव पड़ सके।"<sup>7</sup>

(2) दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण : हम यह जानते हैं कि अल्पकालीन सामान्य मूल्य सीमात लागत द्वारा निर्धारित होता है (यदि भाग की तालिका दी हुई है)। दीर्घकाल में यदि भाग बढ़ जाती है तो फर्म उत्पादन मान में परिवर्तन करती है। फर्म अतिरिक्त पूँजी तथा साधन लगाकर भाग के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि करेगी। परन्तु फर्म ऐसी अवस्था में करेगी जबकि औसत लागत सीमात लागत से कम है, क्योंकि ऐसी दशा में फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त होता रहता है। एक फर्म के लाभ की मात्रा, व्यक्तिगत रूप से, उस समय अधिकतम होती है जबकि उसकी सीमात लागत तथा सीमात भाग समान हों, जिस प्रकार एक फर्म के लिए सामान्य उत्पादन, उत्पादन की वह मात्रा होगी जिस पर सीमात लागत, कीमत

<sup>7</sup> "Normal or natural value of a commodity is that which economic forces would tend to bring about in the long run. It is the average value which economic forces would bring about if the general conditions of life were stationary for a run of time long enough to enable them all to work out their full effects."

के बराबर हो। परन्तु सम्पूर्ण उद्योग की साम्य अवस्था में होने के लिए यह आवश्यक है कि कीमत औसत लागत के बराबर हो। इस प्रकार दीर्घकाल में कीमत उत्पादन-लागत के बराबर होती है। (Price in the long run is equal to cost of production)

अल्पकाल में उत्पादक अपनी वस्तु को कुल औसत लागत से कम पर भी बेच सकता है। यदि उसे औसत प्रमुख लागत (AVC) के बराबर कीमत प्राप्त हो जाती है, तो भी अच्छे मबिष्य की आशा में वह उत्पादन जारी रखेगा। परन्तु दीर्घकाल में वह ऐसा नहीं कर सकता है। दीर्घकाल में यह आवश्यक है कि उसे कुल औसत उत्पादन लागत के बराबर कीमत प्राप्त हो। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि कीमत सीमात लागत के बराबर हो अतः

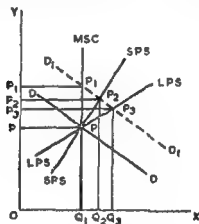
दीर्घकालीन सामान्य मूल्य = औसत लागत = सीमात लागत

इस प्रकार दीर्घकाल में उत्पादक को न तो हानि होती है, न लाभ (केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, जो उत्पादन व्यय का ही एक भाग माना जाता है) यदि फर्म अधिक लाभ प्राप्त कर रही है तो अन्य उत्पादक फर्म उस उद्योग की ओर आकर्षित होगी। इस प्रकार उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी तथा वस्तु की कीमत नीचे गिरेगी। कीमत उम समय तक नीचे गिरती जाएगी, जब तक कि वह औसत लागत तथा सीमात लागत के बराबर नहीं हो जाती है।

यदि उत्पादक को हानि हो रही है, अर्थात् उसे औसत लागत से कम कीमत प्राप्त हो रही है, तो वह दीर्घकाल में उद्योग छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा। अतः उत्पादन तथा पूर्ति—दोनों में कमी हो जाएगी और इस प्रकार कीमत बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कीमत औसत लागत तथा सीमात लागत के बराबर नहीं हो जाती। अतः दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन-लागत के बराबर होती है।

चूंकि दीर्घकाल में कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, अतः पूर्ण स्पर्धा के सन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि सभी फर्मों की समान रूप से कुशल होना पड़ेगा, अन्यथा अकुशल फर्म को उद्योग छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि सभी फर्मों की औसत लागत समान होगी। यद्यपि व्यावहारिक रूप में सम्भव है कि कुछ फर्मों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशल उत्पादक सेवाएँ उपलब्ध हों—जैसे अधिक कुशल प्रबन्धक, फर्म की अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थिति आदि, परन्तु इनका प्रभाव औसत उत्पादन लागत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अधिक कुशल साधनों को उनके सामान्य पारिथ्रमिक के अतिरिक्त पारिथ्रमिक मिलेगा, अतः सभी फर्मों की औसत लागत समान होगी।

3 रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण : दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की सख्या में वृद्धि कर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। नई फर्मों का भी प्रवेश हो सकता है। मांग के अनुसार पूर्ति में पूर्ण समायोजन (Adjustment) किया जा सकता है। इस काल में मूल्य मांग की अपेक्षा पूर्ति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। चित्र सख्या 102 में  $DD$  मूल मांग वक्र है।  $MSC$  बाजार पूर्ति रेखा, तथा  $SPS$  अल्पकालीन पूर्ति रेखा है।  $LPS$  दीर्घकाल पूर्ति रेखा (Long Period Supply) है, जो  $SPS$



चित्र सख्या 102

की दाहिनी ओर है और यह प्रकट करती है कि दीर्घकाल में, अल्पकाल की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि की जा सकती है। साथ ही माय उत्पादन लागत (Cost of Production) भी कम होगी।  $D_1 D_1$  बढ़ी हुई मांग रेखा  $LPS$  को  $P_3$  बिन्दु पर काटती है। इस प्रकार  $OP_3$  सामान्य मूल्य या दीर्घकालीन सामान्य मूल्य होगा तथा  $OQ_3$  मात्रा बेची जाएगी। यह स्वरणीय है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य ( $OP_3$ ) अल्पकालीन सामान्य मूल्य ( $OP_2$ ) से कम है, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति बढ़ेगी तथा सामान्यतया उत्पादन लागत घटेगी। दीर्घकालीन उत्पादन मात्रा ( $OQ_3$ ) अल्पकालीन उत्पादन मात्रा ( $OQ_2$ ) से अधिक होगी। चित्र से बाजार-मूल्य ( $OP_1$ ) अल्पकालीन सामान्य मूल्य ( $OP_2$ ) तथा सामान्य मूल्य ( $OP_3$ ) का अन्तर जाना जा सकता है।

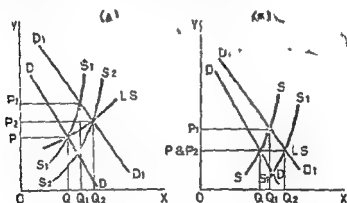
(4) मांग में परिवर्तन तथा दीर्घकालीन मूल्य : अब तक हमने मांग का जिक्र नहीं किया। दीर्घकाल में भी मांग में परिवर्तन होते हैं क्योंकि मांग पर प्रभाव डालने वाले तत्व — आय, रुचि, प्रथा आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। मांग में परिवर्तन का प्रभाव कीमत पर पड़ता है। यदि पूर्ति की अवस्थाएँ पूर्ववत् हैं तो मांग में वृद्धि होने पर साम्य बिन्दु ऊपर उठेगा तथा मांग में कमी होने से साम्य बिन्दु नीचे गिरेगा।

(5) पूर्ति में परिवर्तन तथा सामान्य मूल्य (Changes in Supply and Long Run Price) दीर्घकाल में पूर्ति, माग में अनुसार समायोजित की जाती है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का अर्थ है उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करना। चूंकि दीर्घकाल में कीमत, उत्पादन व्यय के बराबर होती है, अतः यह स्वामाविक है कि उत्पादन-व्यय में परिवर्तनों का प्रभाव कीमत पर पड़ेगा। उत्पादन व्यय में किस प्रकार या किस सीमा तक परिवर्तन होंगे, यह हम बात पर निर्भर है कि उत्पादन, लागत वृद्धि समान लागत या मागत ह्रास नियम के अनुसार किया जा रहा है।

**उत्पादन के नियम तथा दीर्घकालीन सामान्य मूल्य •**

(Laws of Returns and Long Run Normal Price)

(1) लागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Costs) इस क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम को कहते हैं। यदि किसी वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अनुसार हो रहा है तो माग कम होने पर, उत्पादन की मात्रा कम कर दी जाएगी, फलस्वरूप उत्पादन लागत कम होगी तथा मूल्य नीचे गिरेगा। माग के बढ़ने पर, उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार उत्पादन लागत बढ़ेगी तथा मूल्य ऊंचा उठेगा। चित्र स० 103 A, में इसका स्पष्टीकरण किया गया है।



चित्र स० 103

चित्र 103 A में DD माग वक्र है।  $S_2 S_1$  अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, उसी बिन्दु पर कीमत निर्धारित होगी। इस प्रकार OP कीमत तथा OQ उत्पादन मात्रा होगी। यदि माग बढ़कर  $D_1 D_1$  हो जाए तो, कीमत बढ़कर  $OP_1$  हो जाएगी तथा साम अधिकतम करने के लिए उत्पादन मात्रा  $OQ_1$  हो जाएगी। इस प्रकार माग में वृद्धि के कारण कीमत ऊँची उठती है तथा उत्पादन की मात्रा में कुछ वृद्धि होती है। (वर्तमान साधनों का अधिक उपयोग कर)

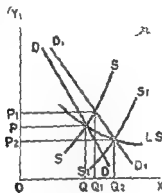
दीर्घकाल में, ताम देखकर अन्य फर्मों उद्योग में प्रवेश करेंगी। नई फर्मों के आने से उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होगी, इस प्रकार अल्पकालीन पूर्ति वक्र दाहिनी ओर हटेगी, अर्थात् पूर्ति बढ़ेगी ( $S_2S_2$  पूर्ति वक्र) पूर्ति के बढ़ते हुए भी कीमत बढ़ने का कारण यह है कि 'उद्योग लागत वृद्धि नियम' के अनुसार चलाया जा रहा है, अतः उत्पादन बढ़ाने पर लागत बढ़ेगी, इस प्रकार अधिक मात्रा की पूर्ति, ऊँची कीमत पर हो की जा सकती है। LS दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा, जो अल्पकालीन पूर्ति का योग है। दीर्घकालीन मूल्य  $OP_2$  होगा।

(2) लागत समता नियम (Law of Constant Costs) : यदि कोई वस्तु लागत समता नियम के अनुसार पैदा की जा रही है तो उत्पादन बढ़ने से प्रति इकाई उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यदि माग में वृद्धि होती है तो सामान्य कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चित्र स० 103 II में DD माग-वक्र तथा SS अल्पकालीन पूर्ति-वक्र है। अतः PQ कीमत तथा OQ उत्पादन की मात्रा हुई। यदि माग बढ़कर  $D_1D_1$  हो जाती है तो अल्पकाल में कीमत भी बढ़कर  $OP_1$  हो जाएगी, क्योंकि अल्पकाल में कीमत सीमान्त लागत के बराबर होगी। कीमत बढ़ने से फर्मों के प्रवेश या फर्मों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि के कारण नया अल्पकालीन पूर्ति वक्र  $S_1S_1$  होगा जो नए माग-वक्र  $D_1D_1$  को  $P_1$  की सीध में काटता है। दीर्घकालीन पूर्ति-वक्र LS होगा जो एक क्षैतिज (Horizontal) रेखा के रूप में होगा। हमसे स्पष्ट है कि दीर्घकाल में कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। नया मूल्य  $OP_2$  या  $OP$  होगा।

(3) लागत ह्रास नियम (Law of Decreasing Costs) : जिन वस्तुओं का उत्पादन 'लागत ह्रास नियम' के अनुसार होता है, उनकी उत्पादन लागत, अधिक मात्रा में उत्पादन करने से, प्रति इकाई घटती जाती है। अतः ऐसी वस्तुओं की माग में वृद्धि होने के कारण यदि पूर्ति में वृद्धि की जाए तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होने के कारण, उनकी कीमत भी घटती जाएगी। इसी प्रकार माग कम होने पर उत्पादन कम किया जाएगा तथा उत्पादन में वृद्धि होगी, फलस्वरूप कीमत बढ़ जाएगी। चित्र स० 104 में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया गया है :

DD माग वक्र तथा SS अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। अतः OQ उत्पादन-मात्रा तथा OP कीमत हुई।  $D_1D_1$  बढ़ी हुई माग का प्रतीक है, अतः अल्पकाल में कीमत बढ़कर  $P_1O$  हो जाएगी। फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त होगा, तथा नई फर्में प्रवेश करेंगी। अतः नया पूर्ति वक्र  $S_1S_1$  होगा (पूर्ति बढ़ जाएगी)। इस प्रकार कीमत घटकर  $P_2O$  हो जाएगी। LS दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा जो बाए

से दाये नीचे की ओर गिरता गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि अधिक पूँति, घटती हुई कीमतों पर की जाएगी।\*



चित्र सरवा 104

#### 4. सामान्य मूल्य किस फर्म की उत्पादन-लागत के बराबर होगा ?

दीर्घकालीन सामान्य मूल्य, औसत उत्पादन लागत के बराबर होता है। एक उद्योग में बहुत सी फर्में उत्पादन का काम करती हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण, सभी फर्मों की समान दर पर कीमत प्राप्त होती है, अर्थात् सम्पूर्ण उद्योग के लिए एक ही कीमत होती है। अतः प्रश्न है—किस फर्म की औसत लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाएगा ? मार्शल ने इस समस्या का समाधान 'प्रतिनिधि फर्म' का विचार (concept) प्रस्तुत करके किया है।

##### 1 प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm)

पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत विकास की दृष्टि से फर्मों की विभिन्न अवस्थायें होती हैं। कुछ फर्में नई होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। मार्शल ने उद्योग की दशा की तुलना एक वन (Forest) से की है। जिस प्रकार वन में कुछ वृक्ष प्रचुरित व पतपित होने रहते हैं, कुछ प्रचुर विकसित होते हैं तथा कुछ पुराने होकर जोशों शीशों हो जाते हैं, इसी प्रकार कुछ फर्म विकासामुख, कुछ विकसित तथा कुछ पुरानी फर्में हामोमुख होती हैं। अतः उद्योग में कुछ फर्में लाभ पर चलती हैं, कुछ न हानि न लाभ पर चलती हैं, और कुछ हानि उठाकर उत्पादन करती हैं। यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण विकसित फर्मों की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाए तो नई फर्मों (कम कुशल) को हानि होगी तथा वे उद्योग छोड़ देंगी। इसी प्रकार यदि

\* 'वाजार मूल्य व सामान्य मूल्य में अन्तर' के लिए इसी अध्याय के अन्तिम पृष्ठ देखिए।

ह्रासोन्मुख फर्म की उत्पादन लागत को आधार मान लिया जाए तो अन्य फर्मों को बहुत लाभ होगा, जिससे बहुत सी नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेगी। इस प्रकार समस्या यह है कि किस फर्म की उत्पादन लागत को आधार माना जाए? मार्शल के अनुसार 'दीर्घकालीन सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होता है।'

प्रतिनिधि फर्म क्या है? मार्शल के शब्दों में, "प्रतिनिधि फर्म वह है जो काफी समय से चालू है, जिसे अच्छी सफलता मिलती है, जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा जिसमें वे बाह्य एवं आन्तरिक मितव्ययिताएँ सामान्य रूप से प्राप्त हों जो उत्पादन की कुल मात्रा के कारण होती हैं, जिसमें उत्पादित वस्तुओं का वजन, उनकी विपणन की स्थिति तथा आर्थिक वातावरण का विचार रक्खा जाना है।"

इस प्रकार प्रतिनिधि फर्म न तो बहुत खराब व्यवस्था वाली और न बहुत अच्छी व्यवस्था वाली होती है यह फर्म न तो नई होती है और न बहुत पुरानी। अपने ढंग की यह एक विशेष फर्म होती है जो बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन का साधारण लाभ उठाती है। हम यह देखते हैं कि एक उद्योग में कई प्रकार की फर्में होती हैं : (1) कुछ फर्में बिल्कुल नई होती हैं जिनका आकार बढ़ना रहता है,

(2) कुछ फर्में मध्यम धरोणी की होती हैं जिन्हें हम परिपक्व फर्म कह सकते हैं। ऐसी फर्में नई होती हैं, न पुरानी, तथा (3) जीर्ण फर्में हैं जो क्षमता की सीमा पार कर चुकी हैं।

इन सभी प्रकार की फर्मों में कुछ अधिक क्षमता वाली फर्में होती हैं, कुछ कम क्षमता वाली और कुछ सामान्य क्षमता वाली। मार्शल की प्रतिनिधि फर्म सामान्य क्षमता वाली फर्म है।

प्रतिनिधि फर्म सिद्धांत की आलोचना : अर्थशास्त्रियों ने प्रतिनिधि फर्म की काफी आलोचना की है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

(1) यह सिद्धांत एक कल्पना मात्र है। प्रतिनिधि फर्म का सिद्धांत एडम के आर्थिक व्यक्ति की भाँति किसी व्यावहारिक उपयोगिता के योग्य नहीं है। व्यावहारिक जगत में यह नहीं पाया जाता है। राबिन्स ने इस सिद्धांत को व्यर्थ तथा

---

5. "Our representative firm must be one, which has had a fairly long life, and fair success, and which is managed with normal ability and which has a normal access to economies, external and internal, which belong to that aggregate volume of production, account being taken of the class of goods produced, the conditions of marketing them and the economic environment generally."

—Marshall : Principles of Economics, p 65



तत्त्वहीन बतलाया है। उनके शब्दों में, 'प्रतिनिधि फर्म या प्रतिनिधि उत्पादक की बात सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे लिए सोचने की वस्तुएँ हैं प्रतिनिधि रूप में धरती का एक टुकड़ा, प्रतिनिधि रूप में एक मशीन या एक प्रतिनिधि रूप में एक मजदूर। प्रतिनिधि फर्म का सिद्धांत अमान्य है, अनावश्यक तथा बेकार है। यह अनावश्यक ही नहीं, बल्कि गलत दिशा में ले जाने वाला है।'<sup>9</sup>

(2) इस धारणा को वास्तविक मान लिया जाय तो भी हमारे नर्व में जान नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म के मागन के बराबर होता है। यह ऐसी फर्म है जिसकी सामान्य सामान्य मूल्य के बराबर होती है। इस प्रकार मार्शल ने जो सिद्ध करना चाहा वहाँ उन्होंने गान भी दिया है।

(3) प्रतिनिधि फर्म विस्तार बनानी है या मागन? उन दोनों में से वह किसका प्रतिनिधि बनानी है? कहीं-कहीं मार्शल ने बिन्दुओं को महत्व दिया है, परन्तु उनके विचार से यह पता चल जाता है कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग की सामान्य लागत प्रकट करनी है। रॉबर्टसन की यही धारणा है। उनके शब्दों में, 'मेरे विचार से (प्रतिनिधि फर्म को) पूरे उद्योग की पूर्ण देना के एक छोटे प्रतिनिधि से अधिक मानने की आवश्यकता नहीं है।'<sup>10</sup> प्रो० निकोलस कैलडोर ने भी उसकी स्वाभाविक उपयोगिता को पूर्णतया बेकार माना है।<sup>11</sup>

## 2. प्यू की संस्थित फर्म (Pigou's Equilibrium Firm)

मार्शल की प्रतिनिधि फर्म साम्य की वजह एक स्थिति नहीं सम्बन्धित है। साम्य की दृष्टि में परिवर्तन हान पर, दूसरी प्रतिनिधि फर्म की तलाश करनी पड़ती है। इस प्रकार साम्य-परिवर्तन के साथ प्रतिनिधि फर्म भी बदलती रहती है।

<sup>9</sup> "There is no more need for us to assume a representative firm or a representative producer, than there is for us to assume a representative piece of land, a representative machine or a representative worker. The concept of representative firm is illusory, unnecessary and superfluous. It is yet unnecessary, but misleading."—Robbins *The Representative Firm* *Economic Journal*, Sept., 1928

<sup>10</sup> "In my opinion it is not necessary... to regard it as anything other than a small scale replica of the supply curve of the industry as a whole."—Robertson *Increasing Returns and Representative Firm*, *Economic Journal* March 1930

<sup>11</sup> "A representative firm is a tool of mind rather than an analysis of the concrete."—N. Kaldor, *Equilibrium of the Firm*, *Economic Journal*, March 1930.

इस प्रकार हम किसी फर्म विशेष को ही सदैव प्रतिनिधि फर्म नहीं कह सकते हैं। प्रो० पीगू ने इस दोष को दूर करने के लिए 'संस्थित-फर्म' या 'साम्य-फर्म' का विचार (concept) प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, यदि सम्पूर्ण उद्योग साम्य की अवस्था में है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्मों में साम्य-अवस्था में हो। व्यावहारिक दृष्टि में कुछ फर्मों का विस्तार हो रहा होगा तथा कुछ का संकुचन। ऐसी दशा में भी हम एक ऐसी फर्म की कल्पना कर सकते हैं जो उद्योग के विभिन्न साम्य-स्तरों पर फर्मों की साम्य-अवस्था में हो। छत वह फर्म जो उद्योग की विभिन्न साम्य-अवस्थाओं में, स्वयं भी साम्य-अवस्थाओं में रहती है, साम्य फर्म कहलाती है। पीगू के ही शब्दों में, साम्य का "अर्थ है कि एक ऐसी फर्म हो सकती है, जो जब कभी सम्पूर्ण उद्योग इस अर्थ में साम्य की अवस्था में है कि वह सामान्य पूर्ति कीमत P पर F उत्पादन की नियमित मात्रा Y पैदा कर रहा है, स्वयं नियमित उत्पादन मात्रा X पर साम्य की अवस्था में हो।"<sup>12</sup> इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये किसी उद्योग में दस फर्में हैं, उनका कुल उत्पादन एक वर्ष में दस हजार टन है। दूसरे वर्ष फर्मों के उत्पादन में परिवर्तन होता है अर्थात् कुछ फर्में पहले की अपेक्षा कम उत्पादन करती हैं तथा कुछ फर्में अधिक उत्पादन करती हैं परन्तु पूरे उद्योग का उत्पादन दस हजार टन ही रहता है। उनमें एक ऐसी फर्म है जो एक वर्ष में 500 टन उत्पादन तथा दूसरे वर्ष में 500 टन ही उत्पादन करती है, तो ऐसी फर्म 'साम्य फर्म' कही जाएगी उद्योग का पूर्ति मूल्य (Supply Price), साम्य फर्म के ही पूर्ति मूल्य के बराबर होगा, तथा साम्य फर्म की कीमत, सीमांत लागत के बराबर होगी। इतना ही नहीं वल्कि उद्योग का पूर्ति मूल्य साम्य-फर्म की श्रौतत लागत के भी बराबर होगा।

पीगू की साम्य-फर्म की भी आलोचना की गई है। जोन रॉबिन्सन का कहना है कि यदि वास्तविक फर्म साम्य की अवस्था में नहीं हैं तो उनकी लागतें उन काल्पनिक फर्म की लागतों से सम्बन्धित नहीं होगी। प्रो० जे० के० मेहता ने यह शिष्टार व्यक्त किया है कि पीगू की साम्य फर्म माध्यम की प्रतिनिधि फर्म का किसी भी प्रकार सुझाव हमारा रूप नहीं है। वस्तुतः दोनों ही विचार अवतः एक हैं उन्होंने प्रतिनिधि के विचार को उपयुक्त माना है तथा यह कहा है कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग का

<sup>12</sup> Equilibrium firm "implies that there can exist some one firm, which, whenever the industry as a whole is in equilibrium in the sense that it is producing a regular output in response to a normal supply price, will itself individually be in equilibrium with a regular output." —Pigou A. C., Economics of Welfare, p 720

पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है तथा "उसमें उद्योग की हो भाति उसी रूप में प्रसार या संकुचन की प्रवृत्ति होती है।"<sup>13</sup>

### 3 अनुकूलतम फर्म (Optimum Firm)

आधुनिक अर्थशास्त्री 'प्रतिनिधि फर्म' तथा 'साम्य फर्म' के विचार को निरर्थक तथा अ-व्यावहारिक मानते हैं। इन अर्थशास्त्रियों में रॉबिन्सन तथा जोन रॉबिन्सन के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिक समय में यह माना जाता है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य 'अनुकूलतम फर्म' की उत्पादन लागत के बराबर होता है। अनुकूलतम फर्म उस फर्म को कहते हैं जिसमें उत्पादन साधना का अनुकूलतम समन्वय होता है। ऐसी फर्म की औसत लागत न्यूनतम होती है, औसत तथा सीमाना लागतें बराबर होती हैं तथा फर्म का आकार ऐसा होता है कि उनकी औसत लागत न्यूनतम बिन्दु पर पहुँच जाती है तथा उससे अधिक औसत लागत के न गिरने की सम्भावना होती है न ऊपर उठने की। रॉबिन्सन के शब्दों में "वह फर्म अनुकूलतम फर्म कहलाती है जिसमें वर्तमान तकनीकी विधियों तथा संगठन योग्यता की दृष्टि से, प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, जबकि वे सभी लागतें सम्मिलित कर ली जाती हैं, जिन्हें दीर्घकाल में सम्मिलित करना आवश्यक होता है।"<sup>14</sup>

अनुकूलतम फर्म की धारणा व्यावहारिक है। यह किसी फर्म का वह आदर्श आकार है, जिस पर पहुँचने के लिए सभी फर्म प्रयत्न करती हैं। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य अनुकूलतम फर्म की औसत उत्पादन लागत के बराबर होता है।

सारांश रूप में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य अनुकूलतम फर्म की औसत उत्पादन लागत के बराबर होता है।

### 6 बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य<sup>1</sup> में अन्तर (Distinction between Market Price and Normal Price)

(1) समय बाजार मूल्य का सम्बन्ध अत्यन्त ही अल्पकाल—कुछ घंटे एक दिन, सप्ताह आदि—से होता है जबकि सामान्य मूल्य का सम्बन्ध दीर्घकाल से है।

<sup>13</sup> Representative firm is the firm, "that shows the tendency to expand or contract with industry in the same manner"

Mehra J K Studies in Advanced Economic Theory, p 181

<sup>14</sup> "That firm which in existing conditions of technique and organising ability has the lowest average cost of production per unit when all those costs which must be covered in the long run are included is called an optimum firm." —E.A G Robinson

<sup>1</sup> यहाँ पर सामान्य मूल्य का प्रयोग दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के लिए किया गया है।

(2) परिवर्तन बाजार मूल्य में परिवर्तन तेजी में होते हैं जबकि सामान्य मूल्य में स्थायित्व होता है।

(3) वशा बाजार मूल्य वह वास्तविक मूल्य होता है, जिस पर क्रय विपणन किया जाता है परन्तु सामान्य मूल्य एक प्रकार का आन्तरिक मूल्य होता है। बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य के बराबर होने का होती है।

(4) कीमत निर्धारण बाजार मूल्य के निर्धारण में माग का प्रमुख हाथ रहता है जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ण या प्रमुख स्थान रहता है तथा माग स्थान गौण रहता है।

(5) उत्पादन लागत बाजार मूल्य कीमत उत्पादन लागत के बराबर— उससे कम या अधिक हो सकता है परन्तु सामान्य मूल्य सदैव औसत उत्पादन लागत के बराबर होता है।

(6) वस्तु की प्रकृति बाजार मूल्य प्रत्यक्ष प्रकार की वस्तु का होता है— पुनरुत्पादनीय वस्तु निरुत्पादनीय वस्तु। परन्तु सामान्य मूल्य का सम्बन्ध उत्पादन लागत में होता है, अतः केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही सामान्य मूल्य होता है।

(7) पूर्ति बाजार मूल्य सम्बंधित पूर्ति स्थिर (fixed) होती है अर्थात् पूर्ति स्टाक तक ही सीमित होती है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है अतः प्लॉट के आकार में परिवर्तन द्वारा तथा कमों की दरों में परिवर्तन द्वारा पूर्ति घटाई बढ़ाई जा सकती है।

### प्रश्न व संकेत

1 मूल्य निर्धारण में समय के महत्व की व्याख्या कीजिए। अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए चित्र दीजिए।

(Jodhpur, II yr T D C Arts 1964)

[संकेत—सबप्रथम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में माशुल द्वारा दिया गया वर्गीकरण व इसे और यह स्पष्ट कीजिए कि समय का यह विभाजन न्यायिक समय (operational time) पर आधारित है। इसके बाद प्रति प्रत्येकाल प्रत्येक काम तथा दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पर समय के प्रभाव का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए और अंत में निष्कर्ष दीजिए।]

2 सीमा वह बिंदु है जिस पर (जिसका द्वारा नहीं) मूल्य का निर्धारण होता है। विवेचन कीजिए।

(Agra B A Part II 1967)

[संकेत—प्रश्न में सबप्रथम समय के महत्व को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए और दूसरे भाग में मूल्य निर्धारण में सीमा के महत्व की व्याख्या कीजिए।]

3 किसी वस्तु की माग में स्थायी वृद्धि का मूल्य पर निम्न समभावधियों में प्रभाव बताइये - (अ) अति अल्पकाल, (ब) अल्पकाल तथा (स) दीर्घकाल ।  
(Agra B A. II, 1962)

[सकेत—प्रश्न में अति अल्पकाल, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में माग में स्थायी वृद्धि का मूल्य पर प्रभाव बताइये ।]

4 (अ) वस्तु के बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के बीच अन्तर को समझाइये । (ब) मूल्य सिद्धान्त में समय के महत्व को बताइए ।  
(Agra, B A 1964)

[सकेत—प्रश्न के अ भाग में बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के अन्तर को स्पष्ट कीजिए तथा अ भाग में समय के महत्व को बताइए ।]



# 31

## एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण

(Price and Output Determination Under Monopoly)

*"The prima-facie interest of the owner of a monopoly is clearly to adjust the supply to the demand, not in such a way that the price at which he can sell his commodity shall just cover its expenses of production but in such a way as to afford him the greatest total net revenue"*

—Marshall

### 1 अर्थ (Meaning)

शुद्ध एकाधिकार पूर्ण स्पर्धा की ठीक विपरीत स्थिति है। इसमें तीन बातों का होना आवश्यक है (i) एकाधिकार के अन्तर्गत केवल एक उत्पादक होता है जो वस्तु की पूर्ति या कीमत पर नियन्त्रण रखता है। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग वस्तुतः एक ही होते हैं (ii) उद्योग में एकाधिकारी व अनिश्चित अन्य उद्योग प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अन्य फर्मों के प्रवेश में कई प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं, तथा (iii) एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकट स्थापान (Close substitute) वस्तु भी नहीं होती है अर्थात् उसके द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य उत्पादकों की वस्तुओं से पूर्णतया भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी वस्तु की मांग की आजी लोच शून्य होती है।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। चेंडरलिन ने अनुसार एकाधिकारी वह है जो पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है, "एक एकाधिकारी उसे सम्भनना चाहिए कि जो किसी वस्तु पर नियन्त्रण रखता है, अविनाशित, वह प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति द्वारा कार्य नहीं करता, बल्कि कीमत द्वारा

करता है।<sup>1</sup> स्नॉर के अनुसार, “एकाधिकारी उस विक्रेता को कहते हैं जिसको वस्तु का माग बंद गिरता हुआ होता है अर्थात् उसकी फर्म का विक्रय-वक्र लाचहीन होता है।” स्टोमियर और ह्यू (Stoner & Hague) ने एकाधिकारी की व्याख्या इस प्रकार की है “एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जोकि किसी एक वस्तु की पूर्ण पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा उस वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होता है।”

## 2 वर्गीकरण (Classification)

अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार को अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत किया है

(1) पूर्ण या शुद्ध तथा अपूर्ण एकाधिकार (Perfect or Pure and Imperfect Monopolies) शुद्ध एकाधिकार उस कहते हैं जिसमें स्पर्धा का तत्त्व लेनामात्र भी नहीं होता है अर्थात् एक ही फर्म का पूर्ण पर पूर्ण नियन्त्रण होता है, स्नॉर के अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह अवस्था है, जिसमें सभी वस्तुओं की पूर्ण पर एक ही फर्म का नियन्त्रण होता है। शुद्ध एकाधिकारी को मरिचक भी स्पर्धा का भय नहीं रहता है। अपूर्ण एकाधिकार उन्हे कहते हैं जिसमें नवी फर्मों के प्रवेश, सरकारी नियन्त्रण आदि का भय रहता है।<sup>2</sup>

(2) साधारण एकाधिकार व विवेचनात्मक एकाधिकार (Simple and Discriminating Monopolies) साधारण एकाधिकार उसे कहते हैं, जबकि एकाधिकारी सभी क्रयार्थी से समान कीमत बना है। विवेचनात्मक एकाधिकार के अन्तर्गत विभिन्न ग्राहकों से एक ही वस्तु की एक ही वस्तु अवस्थाओं में विभिन्न दर पर कीमत ली जाती है।

(3) व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक एकाधिकार [Private and Public Monopolies] व्यक्तिगत एकाधिकार उस अधिकार का कहते हैं, जिसमें फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या मण्डल व अधिकार में होता है। सार्वजनिक एकाधिकार उन एकाधिकार को कहते हैं जिसमें स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक निकायों का होता है। प्रथम का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना तथा द्वितीय का उद्देश्य

<sup>1</sup> “A monopolist must be thought of as some one who simply controls the supply of something, in most cases he operates directly not on supply but on the price”

—Chamberlin, Towards a More General Theory of Value p 62

<sup>2</sup> “The producer who controls the whole supply of a single commodity which has no close substitutes” —Stoner & Hague

<sup>3</sup> “Imperfect monopoly is one which is threatened by new-comer's competition, Government sanctions and organised public reaction”

—Fritz Machlup

सार्वजनिक हित सर्वपक्ष होता है। जैपमैन ने एकाधिकार को (i) प्राकृतिक [Natural] (ii) सामाजिक (Social), (iii) कानूनी (Legal), तथा ऐच्छिक (Voluntary), वर्गों में विभाजित किया है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार पूर्ण स्पर्धा वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती, उसी प्रकार शुद्ध एकाधिकार की अवस्था भी एक काल्पनिक अवस्था है। शुद्ध एकाधिकार का केवल सैद्धांतिक महत्व है।

### 3. मान्यताएँ :

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य तथा उत्पादन के निर्धारण के सम्बन्ध में अध्य-  
यन करते समय हमें कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा। प्रथम, आर्थिक  
विवेकशीलता (economic rationality), जो पूर्ण प्रतियोगिता को आधारभूत  
मान्यता है, एकाधिकार के सम्बन्ध में भी इस बात को प्रकट करती है कि एक  
एकाधिकारी अन्य उत्पादकों की तरह अपने लाभ को अधिकृतम करेगा, द्वितीय,  
एकाधिकार की स्थिति में फर्म तथा उद्योग के एक हो रहने के कारण प्रतियोगिता  
का पूर्णतया अभाव रहना है, अर्थात् प्रतियोगिता नहीं होती है। परन्तु क्रेताओं  
तथा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण उनमें प्रतियोगिता होती है। इस  
सम्बन्ध में भी यह ध्यान रह कि कोई भी क्रेता या उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से वस्तु  
के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि एक क्रेता के लिए वस्तु का  
मूल्य पूर्व निर्धारित होता है। तृतीय, एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए विभिन्न  
मूल्यों पर प्रत्येक उपभोक्ता का व्यक्तिगत माग की मात्राओं या माग रेखाओं के  
आधार पर अपनी वस्तु की कुल माग का अनुमान लगा सकता है। उपभोक्ता विवे-  
कशील होने के कारण किसी वस्तु को अपने अधिमान या पसन्दगी (Scale  
of preference) के क्रम में खरीदता है। इस आधार पर विभिन्न मूल्यों पर उसके  
द्वारा वस्तु की मागी गई मात्राओं का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रत्येक  
उपभोक्ता की व्यक्तिगत माग रेखाएँ खींची जा सकती हैं, जिनकी सहायता से  
एकाधिकारी अपनी वस्तु की कुल माग की रेखा खींच सकता है।

4 एकाधिकारी एक साथ मूल्य तथा पूर्ति दोनों की मात्रा निश्चित नहीं कर  
सकता (A monopolist cannot fix both Price and Output Simulta-  
neously) :

एकाधिकार की मान्यताओं के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि एक-  
धिकारी का वस्तु की पूर्ति पर ही एकाधिकार या पूर्ण नियन्त्रण होता है। क्रेताओं  
तथा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण उनकी माग पर जो पसन्दगी  
के क्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है, एकाधिकारी का कोई नियन्त्रण सम्भव



नहीं हो सकता। यही कारण है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु के मूल्य तथा उसकी उत्पादन मात्रा दोनों को एक साथ निवारित नहीं कर सकता। उसे इन दोनों में से किसी एक को निश्चित करके दूसरे को उसके अनुसार समायोजित करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि यदि वह अपनी वस्तु का मूल्य निश्चित करता है तो उस मूल्य पर क्रेताओं तथा उपभोक्ताओं द्वारा माँगी गयी वस्तु की कुल मात्रा के अनुरूप उसे अपनी पूर्ति की मात्रा निश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे शुद्ध एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके विपरीत यदि वह पहले पूर्ति की मात्रा निश्चित कर लेता है तो उसे माग के अनुसार उस वस्तु का मूल्य निश्चित करना होगा। परन्तु माग का दत्ता अनिश्चित तथा क्रेताओं तथा उपभोक्ताओं की माग पर उसका कोई नियन्त्रण न होने के कारण से यह सम्भव हो सकता है कि उसकी कुल पूर्ति का मात्रा न बिके। ऐसी स्थिति में उसे हानि हो सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी के लिए पहले मूल्य निश्चित करना ही उचित है। उस निश्चित मूल्य पर कुल माग का अनुमान लगाकर वस्तु का उत्पादन एवं पूर्ति करने पर ही उस अधिकतम लाभ या शुद्ध एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सकता है।

### 5 एकाधिकार के अन्तर्गत लागत व आय

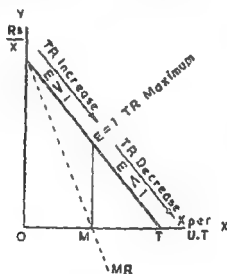
एकाधिकार के अन्तर्गत लागत उसी प्रकार तथा प्रकृति की होती है जिस प्रकार पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत। हम यह मानकर चलेंगे कि एकाधिकारिक उत्पादक, उत्पादन माधन्य का कीमतों को प्रभावित नहीं करता है।

**आय (Revenues)** पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत बिक्री वर्तमान कीमत पर जितनी मात्रा चाहे बच सकता है। अतः उसकी कीमत तथा सीमान्त आय (MR) बराबर होती है। परन्तु एकाधिकारी माग से प्रभावित होता है, अतः अधिक बिक्री के लिए उसे कीमत कम करनी पड़ती है यह तथ्य कि एकाधिकारी का अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए मूल्य कम करना पड़ता है उत्पादन के प्रथम स्तर (इकाई) को छोड़ कर, सीमान्त आय (MR) को औसत आय या कीमत (AR) से कम रखता है। इस वजह से एकाधिकारी की कीमत तथा सीमान्त आय का सम्बन्ध बदल जाता है। बिना किसी विभिन्न मात्राओं पर एकाधिकारी की सीमान्त आय सामान्यतया कीमत से कम होती है। हम यह जानते हैं कि प्रथम की औसत आय तथा, उसकी मात्रा भी होती है। कीमत का हम औसत आय (AR) भी कहते हैं। सीमान्त आय औसत आय से कम होती है (एकाधिकार में), अतः सीमान्त आय तथा माग रेखा (या AR) को नीचे हाँकी है। निम्न सारणी से इन तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है।

## एकाधिकारी की कुल आय सीमान्त आय रूपों में

कीमत (AR)	विक्रय मात्रा	कुल आय (TR)	सीमान्त आय (MR)
100	1	100	100
90	2	180	80
80	3	240	60
70	4	280	40
60	5	300	20
50	6	300	0
40	7	280	-20
30	8	240	-40
20	9	180	-60
10	10	100	-80

सारणी से स्पष्ट है कि केवल पहली इकाई के अतिरिक्त सभी विक्रय मात्राओं पर सीमान्त आय औसत-आय से कम है। यदि इन संस्थाओं की सहायता से रेखा-



(b)

चित्र सं० 105

चित्र बनाया जाए तो सीमान्त आय रेखा औसत आय रेखा (या मांग रेखा) के नीचे होगी।

उपर्युक्त सारणी की सहायता से यह तथ्य अधिक स्पष्ट करने के लिए कि सीमान्त आय की कीमत से कम होता है एक अन्य उदाहरण लिया जा सकता है। माना कि एकाधिकारी 4 इकाई 70 रु० की दर से बेचता है। यदि वह 4 इकाई

न बेचकर 5 इकाइया बेचना चाहता है तो उसे कीमत कम करनी होगी। या वह कीमत 70 रु० में घटाकर 60 रु० कर देता है। अतः सीमान्त आय (MR) = 5वीं इकाई में प्राप्त आगम पिछली 4 इकाइयों पर 10 रु० प्रति इकाई की दर से कीमत की कुल कटौती।

$$\begin{aligned} &= 60 \text{ रु०} - 40 \text{ रु०} \\ &= 20 \text{ रु०} \end{aligned}$$

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अनिश्चित इकाई को बेचने पर कुल आय (TR) में जो वृद्धि होती है, उसे सीमान्त आय (MR) कहा जाता है। इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है।

$$5 \text{ इकाइयों को बेचने पर कुल आय} = 5 \times 60 = 300 \text{ रु०}$$

$$\text{यदि 4 इकाइया बेची जाती तो कुल आय} = 4 \times 70 = 280 \text{ रु०}$$

अतः 5वीं इकाई के बेचने से कुल आगम

$$(\text{अर्थात् सीमान्त आय}-MR) \text{ में वृद्धि} = 20 \text{ रु०}$$

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि सीमान्त आय (MR), जो 20 रु० है, कीमत (AR) से, जो 60 रु० है, कम है।

माग की लोच का एकाधिकारी मूल्य पर प्रभाव :

एकाधिकारी को अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय माग की लोच को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

विक्रय की किसी भी मात्रा पर प्रत्येक अवस्था में सीमान्त आगम (MR) कीमत तथा माग की लोच में निम्नलिखित सम्बन्ध होता है :

सीमान्त आगम = कीमत - कीमत का माग की लोच से अनुपात

$$MR = P - \frac{P}{e}$$

(at any given level of sales by the firm, marginal revenue equals Price minus the ratio of price to elasticity of demand at that sales level)

(i) पूर्ण स्पर्धा में, माग रेखा आघार रेखा के समानान्तर होती है। इसका अर्थ यह है कि विक्रय की सभी मात्राओं पर माग की लोच अपरिमित (infinity or  $\infty$ ) होती है।

चूँकि  $MR = P - \frac{P}{e}$  और  $e \rightarrow \infty$ ,  $\frac{P}{e}$  शून्य तक पहुँचती है तथा

MR, P तक पहुँचता है इसका अर्थ यह हुआ कि विक्रय की सभी मात्राओं पर  $MR = P$  (विद्यार्थी यह याद रखें कि पूर्ण स्पर्धा में माँग रेखा, औसत आगम रेखा (AR) या कीमत तथा सीमान्त आगम रेखा (MR) एक ही रेखा द्वारा प्रकट किए जाते हैं, तथा यह रेखा आघार रेखा के समानान्तर होती है।)

**एकाधिकार** • एकाधिकार के अन्तर्गत माग रेखा या सीमांत माग रेखा, आधार रेखा के समानांतर नहीं होती है, बल्कि नीचे झुकती जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एकाधिकारी, कीमत कम करके ही अधिक मात्रा बेच सकता है। पिछले चित्र में एकाधिकारी की माग रेखा पर ध्यान दें (जो रेखा T बिन्दु पर आधार रेखा को छूती है)

उत्पादन की OM मात्रा पर (M बिन्दु O व T के ठीक मध्य में है), माग की लोच इकाई (1) के बराबर है • OM से कम उत्पादन पर, माग की लोच इकाई से अधिक है ( $e > 1$ ) तथा OM से अधिक उत्पादन पर माग की लोच इकाई से कम है ( $e < 1$ )।

हम माग की लोच, कुल आगम, सीमांत तथा सीमान्त आगम के सम्बन्धों से जानते हैं कि यदि  $e > 1$ , बिजली की मात्रा में वृद्धि करने से कुल आगम (TR) में वृद्धि होगी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि  $e > 1$ , सीमान्त आगम धनात्मक (Positive) होना चाहिए।

उत्पादन की वह मात्रा जिस पर माग की लोच इकाई है ( $e = 1$ ), कुल आगम (TR) अधिकतम है। इस बिन्दु पर कुल आगम अधिकतम है, उस बिन्दु पर सीमान्त आगम शून्य है। यदि  $MR = P - \frac{P}{e}$  तथा  $e = 1$  है तो  $MR = P - P = 0$  यदि  $e < 1$ , तो बिजली की मात्रा बढ़ाने से कुल आगम (TR) में कमी होगी। ऐसी अवस्था में सीमान्त आगम ऋणात्मक (Negative) होगा।

## 6. एकाधिकार तथा पूर्ण स्पर्धा (Monopoly and Perfect Competition) :

हम पूर्ण स्पर्धा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। सागत तथा आगम और एकाधिकारी के आगम (Monopolist's Revenue) पर भी प्रकाश डाला जा चुका है। अब हम यहां पर 'एकाधिकार' तथा पूर्ण स्पर्धा में साम्यावस्था तथा मूल्य निर्धारण-सम्बन्धी कुछ तत्वों का सामान्य रूप से विवेचन करेंगे, जिससे एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य तथा उत्पादन-मात्रा के निर्धारण को समझने में काफी सहायता मिलेगी।

समानता पूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार दोनों के अन्तर्गत उत्पादन का उद्देश्य लाभ की मात्रा अधिकतम करना होता है। अधिकतम लाभ दोनों ही अवस्थाओं में उस समय प्राप्त किया जाएगा जबकि सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर हों ( $MR = MC$ )। एकाधिकारी भी साम्य अवस्था में उस समय होगा जबकि सीमांत आगम तथा सीमांत लागत बराबर हों।

विभिन्नताएं • परन्तु दोनों अवस्थाओं में, मूल्य-निर्धारण में कुछ प्रमुख विभिन्नताएं पाई जाती हैं :

(1) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत उत्पादक एक ही मूल्य पर जितनी मात्रा चाहे, उतनी बेच सकता है, अर्थात् उसकी वस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार होनी है। अतः उसकी माँग रेखा या औसत आय रेखा (Demand or AR) एक क्षैतिज सीधी रेखा (Horizontal Straight Line) होनी है। परन्तु एकाधिकारी का आय वक्र (माँग रेखा) नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, (देखिए 'लागत तथा भागम विज्ञापण' शीर्षक अध्याय) अर्थात् वह कीमत घटा करके ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है।

(2) पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक की सीमांत आय तथा सीमांत लागत कीमत के बराबर होती है ( $MR=MC=P$ )। वह कीमत तथा सीमान्त लागत को बराबर कर लाभ की मात्रा को अधिकतम कर सकता है (Profit is maximised when  $P=MC$ )। इसी प्रकार उसकी सीमांत आय, औसत आय के बराबर होती है तथा सीमांत व औसत आय वक्र एक ही होते हैं ( $MR=AR$  and  $MR$  curves coincide with the  $AR$  curve), परन्तु एकाधिकारी की सीमांत आय, कीमत या औसत आय से सदैव कम होती है, इसलिए उसका सीमांत आय वक्र, औसत आय वक्र के नीचे होता है।

(3) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत फर्मों की संख्या अधिक होती है तथा दीर्घकाल में उद्योग अनुकूलतम फर्मों का समूह हो जाता है, परन्तु एकाधिकार के अन्तर्गत फर्म व उद्योग वस्तुतः एक ही होते हैं। नई फर्मों के प्रवेश की सम्भावना भी नहीं रहती है।

(4) पूर्ण स्पर्धा में जब कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तब उद्योग साम्य की अवस्था में होता है, औसत आय वक्र, औसत लागत वक्र के निम्नतम बिन्दु पर स्पर्श रेखा (Tangent) के रूप में होता है। परन्तु एकाधिकार की साम्य अवस्था में, औसत लागत वक्र के निम्नतम बिन्दु तक पहुँचने की पूर्व ही उत्पादन का विस्तार रोक दिया जाता है। स्पर्धा न होने के कारण, एकाधिकारी न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। एकाधिकारी न्यूनतम लागत बिन्दु पर न पहुँचने का कारण यह है कि (i) उत्पादन विस्तार करने से लागत-व्यय बढ़ता जाता है तथा (ii) पूति की मात्रा बढ़ने अथवा उत्पादन में वृद्धि करने से कीमतें कम हो जाती हैं। एकाधिकारी अधिकतम शुद्ध आय (maximum net revenue) प्राप्त करना चाहता है तथा इस उद्देश्य का पूति उसी समय हो जाती है जबकि सीमांत लागत सीमान्त आय के बराबर हो जाती है।

(5) पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक सीमांत लागत के बराबर कीमत प्राप्त कर साम्य की अवस्था में हो जाता है। औसत लागत तथा कीमत में समानता नई फर्मों के प्रवेश या प्रवेश की सम्भावना के कारण हाँ पाती है। परन्तु एकाधिकार के अन्तर्गत नई फर्मों के प्रवेश की सम्भावना ही नहीं रहती है।

(6) पूर्ण स्पर्धा : मे उत्पादन का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है, उसके लिए कामत पूर्व निश्चित होता है। परन्तु एकाधिकारी का कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। फिर भी वह मनमाने ढंग से ऊँचा कीमत नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि वस्तुओं की माग शायद ही कभी पूर्णतया बेतोच होती है।

## 7. एकाधिकारी का उद्देश्य (The aim of the monopolist) :

प्रत्येक उत्पादन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में भी उत्पादक या विक्रेता लाभ की मात्रा को अधिकतम करना चाहता है परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता में माग तोषदार होने के कारण साम्य बिन्दु पर औसत लागत भी औसत प्राय एवं सीमांत प्राय के बराबर होती है। अन्य शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सीमान्त लागत (marginal cost of production) के बराबर होने की होती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में बिनेना का केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, जो उत्पादन लागत (सीमांत लागत) का ही एक भाग होता है।

यद्यपि एकाधिकार की स्थिति में भी साम्य बिन्दु पर सीमान्त लागत तथा सीमांत आम बराबर होती है, फिर भी एकाधिकार की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के विपरीत होती है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी अपनी एकाधिकारिक शक्ति का प्रयोग करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। वह अपनी वस्तु की कीमत का उत्पादन लागत से काफी ऊँचा रख कर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। एकाधिकारी का कोई प्रतियोगी नहीं होता, अतः वह बाजार में अपनी वस्तु अधिक से अधिक मूल्य पर बचकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। एकाधिकारी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले लाभ को प्रो० मार्शल ने एकाधिकारी लाभ (Monopoly gain) कहा है। श्रीमती जोन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) ने इस अतिरिक्त लाभ को शुद्ध एकाधिकारी आय (Net Monopoly Revenue) की संज्ञा दी है।

प्रत्येक एकाधिकारी अपनी 'शुद्ध एकाधिकारी आय' को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। वह अधिकतम समाज कल्याण की भावना में प्रेरित नहीं होता। यही कारण है कि अधिकतम सन्तुष्टि का सिद्धान्त एकाधिकारी वस्तुओं की माग व पूर्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है। अधिकतम कुल शुद्ध एकाधिकारी आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही एकाधिकारी केवल प्रत्येक इकाई लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि वह पूर्ति की मात्रा के साथ इस प्रकार व्यवस्था करता, कि वह अपनी वस्तु की अधिकतम अधिक मात्रा अधिक से अधिक मूल्य पर बेच सके। मूल्य निर्धारण वह अपनी वस्तु की पूर्ति के आधार पर ही कर सकता है। अतः वह माग

को ध्यान में रखकर पूर्ति को इन प्रकार समायोजित करता है कि उसकी वस्तु का इतना मूल्य हो जाये कि वह उन मांग पर अधिकतम लाभ कमा सके।

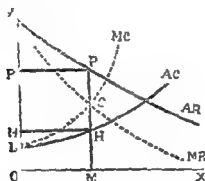
### एकाधिकारी का सतुलन : सामान्य विवेचन

(Equilibrium of the Monopolist General Discussion)

एकाधिकारी, सतुलन की स्थिति में उस समय होगा है जबकि उसके द्वारा अर्जित लाभ अधिकतम हो, अर्थात् कुल आय तथा कुल लागत का अन्तर अधिकतम हो (When Aggregate Revenue - Aggregate Cost is maximum)। इन अन्तर को सीमान्त आय वक्र के नीचे के क्षेत्र तथा सीमान्त लागत वक्र के नीचे के क्षेत्र द्वारा ज्ञान किया जा सकता है। अतः, एकाधिकारी का कुल लाभ -

कुल लाभ = अधिकतम आय - अधिकतम लागत  $\times$  उत्पादन की मात्रा  
(Total Profit = AR - AC  $\times$  Quantity Produced)

इसका स्पष्टीकरण देखा बिज स० 106 द्वारा किया गया है।



चित्र न० 106

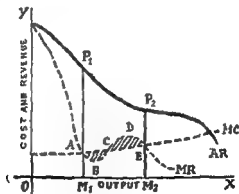
एकाधिकारी का लाभ YCL क्षेत्र के बराबर है। उनकी अधिकतम लागत HM है। कीमत PM है। यदि P तथा H बिन्दुओं से OY पर लम्ब डाले जाएं तो एक आयत बन जाएगा। एकाधिकारी का लाभ इसी आयत के बराबर होगा (PP'HH के बराबर)। यह एकाधिकारी का अधिकतम लाभ है। आयत PP'HH का क्षेत्रफल ACL क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा।

अधिकतम लाभ की उपरोक्त सैद्धान्तिक विधि नहीं है, परन्तु कोई भी एकाधिकारी व्यावहारिक रूप में मांग के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता है। नई, बड़े कारखानों तक मांग तथा पूर्ति की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सीमान्त आय को बराबर कर, लाभ को अधिकतम कर सकता है। जब तक सीमान्त आय सीमान्त लागत से अधिक है तब तक वह उत्पादन में वृद्धि कर लाभ में वृद्धि कर सकता है। इनके

विपरीत यदि सीमांत आय सीमांत लागत से कम है तो वह उत्पादन की मात्रा में कमी कर अपने लाभ में वृद्धि कर सकता है। अतः एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा में कमी तथा वृद्धि कर उस मात्रा का पता लगाता है जिस पर उसका लाभ अधिकतम हो।

**बहुविध सतुलन (Multiple Equilibrium) :** अधिकतम लाभ के बिन्दु का पता लगाने में यह सम्भव है कि सतुलन के कई बिन्दु प्राप्त हों, अर्थात् उत्पादन की कई निम्नित मात्राओं पर एकाधिकारी सतुलन की स्थिति में हो सकता है। इन विभिन्न सतुलन स्थितियों को बहुविध सतुलन (Multiple Equilibrium) कहते हैं। यह स्थिति उस समय होती है जबकि माग वक्र के ढाल में परिवर्तन होते हैं—अर्थात् माग कुछ समय तक लोचपूर्ण तथा कुछ समय तक अपेक्षाकृत कम लोचपूर्ण, और पुनः लोचपूर्ण हो जाती है।<sup>3</sup> इस प्रकार की अवस्था का पाया जाना उस समय सम्भव है, जबकि उपभोक्ताओं के विभिन्न आय समुदाय हों, जिनमें कीमत में कमी होने पर कम आय के उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदने लगेंगे, इस प्रकार माग अधिक लोचपूर्ण हो जाएगी। ऐसी माग से सम्बन्धित सीमांत आय वक्र नीचे गिरकर फिर ऊपर उठता है, तथा पुनः नीचे गिरता है, अतः एकाधिकारी के कई सतुलन बिन्दु होने हैं जिन पर उसका लाभ अधिकतम होता है। चित्र सं० 108 बहुविध सतुलन की स्थिति को प्रकट करता है।

चित्र सं० 107 में  $OM_1$ ,  $OM_2$  एकाधिकारी की उत्पादन मात्रा को प्रकट करते हैं।  $P_1M_1$ ,  $P_2M_2$  क्रमशः कामती का व्यक्त करते हैं। चित्र में सीमांत लागत



चित्र सं० 107

<sup>3</sup> "Cases of multiple equilibrium may arise when the demand curve changes its slope being highly elastic for a stretch, then perhaps becoming relatively inelastic, then elastic again"



वक्र लगभग सीधी रेखा के रूप में ऊपर उठना हुआ है। यह वक्र भी नीचे गिरकर पुन ऊपर उठ सकता है और फिर नीचे गिर सकता है। इस अवस्था में भी MR तथा MC जिन जिन बिन्दुओं पर एक दूसरे को काटगी, वे बिन्दु सतुलन की स्थिति को व्यक्त करेंगे। ऐसी दशा में उपर्युक्त चित्र में MR वक्र की भाँति MC वक्र भी टेढ़ा मेढ़ा होगा।

### एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण (Determination of Price and Output under monopoly)

जिस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक रूप से नहीं पायी जाती है, उसी प्रकार एकाधिकार की अवस्था भी वास्तविक रूप से नहीं पायी जाती है। फिर भी मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त का अध्ययन करने के लिए हम एकाधिकार की अवस्था की कल्पना करते हैं। व्यावहारिक रूप में तो हम पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था और न एकाधिकार की अवस्था पाते हैं। वास्तव में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच का अन्तर स्पष्ट नहीं है।

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण की दो विधियाँ हैं—प्रथम की कुल आय तथा कुल लागत रेखाओं की विधि तथा दूसरी की सीमांत तथा सीमांत रेखाओं की विधि कहते हैं। प्रथम विधि मार्शल द्वारा तथा दूसरी विधि भीमती जोन राबिन्सन द्वारा बतलाई गई है।

#### 1 कुल आय तथा कुल लागत विधि (Total Revenue and Total Cost Method)

एकाधिकारी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त होता है उसे प्रो० मार्शल ने 'एकाधिकार लाभ' (Monopoly gain) कहा है। मार्शल ने अपने सिद्धान्त को जांच तथा भूल का सिद्धान्त (Trial and Error Method) बतलाया है। एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अतः वह मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने का प्रयत्न करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रो० मार्शल के ही शब्दों में, 'स्पष्टतः एकाधिकारी का उद्देश्य पूँति को भाग के साथ इस प्रकार समायोजित करना है जिस मूल्य पर वह अपनी वस्तु को बेचे, वह न केवल उत्पादन लागत निराने के लिए पर्याप्त हो अपितु उसे अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो सके।' इस आय को अधिकतम करने के लिए एकाधिकारी जांच तथा भूल सिद्धान्त का पालन करता है। इस नियम के अनुसार एकाधिकारी वस्तु का एक मूल्य निर्धारित करता है और देखता है कि उसे कुल कितनी आय प्राप्त होती है। तदुपश्चात् वह मूल्य में परिवर्तन करता है और देखता है कि अब उसे परिवर्तित मूल्य पर कुल कितनी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार वह कई बार मूल्य में परिवर्तन करता

है और अपनी कुल आय ज्ञात करता रहता है। जिस मूल्य पर उसे अधिकतम आय प्राप्त होती है, वही मूल्य वह निर्धारित करता है।

प्रश्न है—एकाधिकारी, एकाधिकारिक लाभ' (Monopoly gain) को किस प्रकार अधिकतम करता है? 'एकाधिकारिक लाभ' को अधिकतम करने के लिए एकाधिकारी को वस्तु की माग की लोच तथा पूर्ति पक्ष पर ध्यान देना पड़ता है।

(1) माग की लोच . यदि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की माग लोचदार है तो कीमत बढ़ने पर कुल आय घटती है क्योंकि मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की माग में एक बड़ी कमी आ जायेगी। इसमें विपरीत कीमत घटने पर कुल आय बढ़ती है क्योंकि उससे माग उठ जाती है। यदि माग विलोच है तो कीमत बढ़ने पर कुल आय बढ़ती है तथा कीमत घटने पर कुल आय कम होती है। यदि माग की लोच इकाई के बराबर हो तो मूल्य परिवर्तन का कुल आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

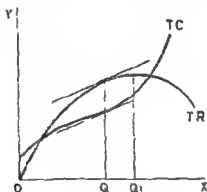
(2) वस्तु की पूर्ति . वस्तु की पूर्ति इस बात पर निर्भर है कि उसका उत्पादन, उत्पादन के किम नियम के अनुसार किया जा रहा है? यदि उत्पादन 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' के अनुसार हो रहा है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर, कम कीमत पर बचने से कुल आय में वृद्धि होगी। यदि उत्पादन 'उत्पत्ति ह्रास नियम' के अनुसार हो रहा है तो उत्पादन की मात्रा कम करके ऊँची कीमत पर बेचने से लाभ होगा। 'उत्पत्ति समता नियम' के अनुसार उत्पादन होने पर उत्पादन की मात्रा माग की लोच पर निर्भर होगी।

अतः माग तथा पूर्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक उत्पादन की मात्रा बढ़ा घटा कर इस बात का पता लगाएगा कि कितनी मात्रा में उत्पादन करने से उसका 'एकाधिकारिक लाभ' अधिकतम होगा। उत्पादन की जिस मात्रा तथा कीमत पर 'एकाधिकारिक लाभ' अधिकतम होगा, एकाधिकारी द्वारा उसी ही मात्रा का उत्पादन किया जाएगा तथा उसी ही कीमत निश्चित की जाएगी।

(3) रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण : चित्र स० 108 में TC वक्र कुल लागत वक्र है तथा TR कुल आय वक्र है। यदि एकाधिकारी OQ मात्रा का उत्पादन करता है तो उसकी कुल आय अधिकतम होती है। इससे अधिक उत्पादन करने पर TR वक्र नीचे गिरता है, परन्तु OQ<sub>1</sub> मात्रा पर 'एकाधिकारिक लाभ' अधिकतम नहीं है। अतः वह उत्पादन की मात्रा कम करेगा। चित्र स० 108 से स्पष्ट है कि OQ मात्रा का उत्पादन करने से TR तथा TC का अन्तर अधिकतम है।

अतः, एकाधिकारी उस मात्रा का उत्पादन करेगा जिस मात्रा पर कुल आय

तथा कुल लागत का अन्तर अधिकतम होगा। उसी उत्पादन पर एकाधिकारिक लाभ अधिकतम होगा। (नोट : यह ध्यान में रखना चाहिए कि TC वक्र का ढाल slope 'सीमांत लागत' तथा TR वक्र का ढाल 'सीमांत आय' को प्रकट करता है। जिस



चित्र न० 108

उत्पादन पर TC तथा TR के ढाल समान है अर्थात् TR व TC की स्पर्श रेखाएँ (Tangents) जिस बिन्दु पर सामानांतर (Parallel) हैं, उसी बिन्दु पर उत्पादन करने से TR व TC का अन्तर अधिकतम होगा, क्योंकि अधिकतम लाभ उस बिन्दु पर होगा है, जिस पर सीमांत लागत = सीमांत आय है।)

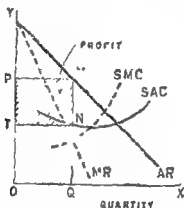
## 2. सीमांत तथा औसत-रेखाओं की विधि (Marginal and Average Curves Method)

श्रीमती जोन राबिन्सन के अनुसार एकाधिकार 'शुद्ध एकाधिकार आय' (Net Monopoly Revenue) को अधिकतम करने का प्रयत्न करना है। उनके अनुसार, शुद्ध एकाधिकार आय = कुल आय—कुल लागत (सामान्य लाभ को सम्मिलित कर) [Net Monopoly Revenue = Total Revenue—Total Cost (including Normal Profit)]। इस उद्देश्य की पूर्ति उस समय होती है, जबकि एकाधिकार की सीमांत आय, सीमांत लागत के बराबर हो। अतः एकाधिकारी लाभ की स्थिति के लिए यह चेष्टा करता है, कि उत्पादन प्रक्रिया में उसकी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। उत्पादन की जिस मात्रा व कीमत पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, एकाधिकारी वही मात्रा व कीमत निर्धारित करता है।

अल्पकाल तथा दीर्घकाल में एकाधिकारी द्वारा मूल्य निर्धारण :

अब हम अल्पकाल तथा दीर्घकाल में दून् विधि द्वारा एकाधिकारी द्वारा मूल्य निर्धारण का अध्ययन करेंगे।

1. अल्पकाल (Short Run) : अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। अल्पकाल में भी उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अधिकतम लाभ उस बिन्दु पर होता है जित पर आप्रवालीन सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है ( $SMC=MR$ ) इस तथ्य का स्पष्टीकरण चित्र सं० 109 द्वारा किया गया है। AR मांग वक्र या औद्योगिक मांग वक्र है। SMC व SAC क्रमशः अल्पकालीन सीमान्त लागत वक्र व अल्पकालीन औद्योगिक लागत वक्र है। MR सीमांत आय वक्र है। उत्पादन का OQ मात्रा पर MR तथा SMC समान है, अतः वह OQ मात्रा का ही उत्पादन करेगा। इस उत्पादन के लिए उसे प्रति इकाई OP



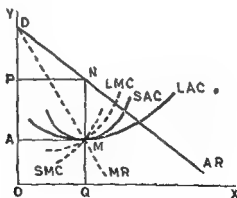
चित्र सं० 109

कीमत प्राप्त होगी। मांग अधिक होने के कारण इस उत्पादन की प्रति इकाई औद्योगिक लागत (SAC) OT है। इस प्रकार एक निवार्य का प्रतिरिक्त लाभ प्रति इकाई PT होगा,  $(OP-OT)$ । कुल अनिरिक्त लाभ  $TN \times MP$  होगा। यदि वह OQ से कम मात्रा का उत्पादन करता है तो सीमांत आय (MR) अल्पकालीन सीमांत लागत (SMC) में अधिक होगी। यदि OQ से अधिक उत्पादन करता है तो MR, SMC से कम होगा, अतः इस मात्रा में अधिक उत्पादन करने पर उसकी कुल लागत में कुल लाभ की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी, अतः उसका लाभ कम होगा। यह याद रखना चाहिए कि एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत सीमान्त आय से सदैव अधिक होती है, जबकि पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत सीमांत आय के बराबर होती है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल में एकाधिकारी उस मात्रा का उत्पादन करेगा जिस पर उसकी सीमांत आय व सीमांत लागत बराबर हो क्योंकि उसी मात्रा पर उसका लाभ अधिकतम होगा। कीमत मांग के स्वरूप व प्रकृति पर निर्भर करेगी।

यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकारी को सदैव लाभ ही हो। लाभ वस्तु की माग तथा उत्पादन लागत के सम्बन्धों पर निर्भर है। यदि उसकी उत्पादन लागत बहुत अधिक तथा उसकी वस्तु की माग कम है तो वह कीमत द्वारा औसत लागत भी बमूल नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में वह 'हानि' को न्यूनतम करने का प्रयत्न करेगा तथा पूर्ण स्पर्धा की ही भांति उत्पादन जारी रखेगा, यदि उसे परिवर्तनशील लागत (variable cost) से कुछ अधिक कीमत के रूप में प्राप्त हो जाता है। अतः यह धारणा निम्न है कि एकाधिकारी सदैव लाभ ही प्राप्त करता है।

(2) दीर्घकाल (Long Run) : पूर्ण स्पर्धा की ही भांति एकाधिकार की अवस्था में भी दीर्घकाल में उत्पादन साधनों की मात्रा में 'परिवर्तन' कर अर्थात् फर्म व आकार में परिवर्तन कर, उत्पादन-मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत दीर्घकाल में कीमत उत्पादन-लागत के बराबर होती है, परन्तु एकाधिकार की अवस्था में कीमत उत्पादन लागत से अधिक होती है, अर्थात् दीर्घकाल में भी एकाधिकारी अतिरिक्त लाभ अर्जित करता है, क्योंकि उसे नई फर्मों के प्रवेश का भय नहीं रहता है।

नई फर्मों के प्रवेश का भय न रहने के कारण एकाधिकारी अपनी उत्पादन-क्षमता में अधिकतम लाभ को ही दृष्टि में रखकर परिवर्तन करता है। वस्तु का



चित्र स० 110

आकार तथा दीर्घकालीन औसत लागत के सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए वह अनुकूलनम आकार से कम आकार की, अनुकूलनम आकार की तथा अनुकूलनम से अधिक आकार की फर्म चला सकता है (यह याद रखना चाहिए कि पूर्ण स्पर्धा में दीर्घकाल में फर्म अनुकूलनम आकार की होती है या होने का प्रयत्न करती है)। सामान्यतः एकाधिकारी इस बात की चेष्टा करेगा कि उसकी फर्म का आकार इतना बड़ा हो कि

सीमान्त आय वक्र (MR), दीर्घकालीन लागत वक्र (LAC) को निम्नतम बिन्दु पर काटे। इस संध्य का स्पष्टीकरण रेखाचित्र स० 110 में किया गया है। OQ मात्रा का उत्पादन करने से दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा सीमांत आय बराबर होती है। (LMC=MR)। यह दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) का निम्नतम बिन्दु है। इस बिन्दु पर अर्थात् OQ मात्रा का उत्पादन करने पर  $MR = SMC = LMC = SAC = LAC$ । फर्म इस बिन्दु पर अल्पकालीन व दीर्घकालीन—दोनों अवस्थाओं में—सन्तुलन की स्थिति में है। कीमत OP, लागत OA तथा लाभ AP के बराबर है। कुल प्रतिरिक्त लाभ  $= AP \times PN$  अर्थात् AMNP के बराबर होगा।

जिस बिन्दु पर MR, LAC को काटना है (M बिन्दु), यदि उस बिन्दु से बाईं तरफ वे किसी बिन्दु पर एक दूसरे को काटें तो फर्म का आकार अनुकूलतम नहीं होगा (अर्थात् अनुकूलतम से छोटा होगा)। इसी प्रकार यदि MR, LAC को बिन्दु M के दाहिनी ओर काटना है तो फर्म का आकार अनुकूलतम से बड़ा होगा।<sup>4</sup>

निरूपण मूल्य निर्धारण सम्बन्धी उपरोक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एकाधिकार की समस्या में कीमत सीमांत आय से अधिक होती है तथा सीमांत लागत, कीमत के बराबर होने के पूर्व ही, सीमांत आय के बराबर हो जाती है। (पूर्ण स्पर्धा में सीमांत आय तथा कीमत बराबर होती हैं)। जहाँ पर सीमांत आय व सीमांत लागत बराबर हो जाती है उसी बिन्दु पर उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है, क्योंकि उसी परिस्थिति में लाभ अधिकतम होता है। (एकाधिकारी पूरा स्पर्धा का अपक्षय कम उत्पादन करता है तथा ऊँची कीमत पर उसे बँचता है। देखिए पृष्ठ 586-87)

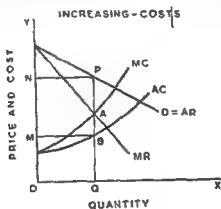
#### उत्पादन के नियमों का एकाधिकारी के उत्पादन पर प्रभाव

दीर्घकाल में एकाधिकारी अपनी वस्तु का मुख्य अधिक या कम निर्धारित करेगा, यह निर्णय उस वस्तु की लागत की दशाओं पर निर्भर करता है। दीर्घकाल में एकाधिकारी उद्योग का विस्तार या संकुचन क्रिय जाने पर उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि या कमी हो सकती है जिसका अर्थ यह है कि फर्म के उत्पादन की औसत लागत उत्पादन के नियमों-घटती हुई, बढ़ती हुई या स्थिर लागत द्वारा प्रभावित होता है।

<sup>4</sup> यहाँ पर सरलता की दृष्टि से केवल अनुकूलतम प्रकार के सन्दर्भ में ही मूल्य निर्धारण की व्याख्या की गई है। अनुकूलतम से छोटी तथा बड़ी आकार की फर्मों के सन्दर्भ के लिए देखिये *Leftwich op. cit., pp., 190-311* डिग्री तथा स्तम्भ नक्षाओं के विधानियों के लिए उपरोक्त विवरण ही पर्याप्त है।

(1) उत्पत्ति ह्रास नियम या बढ़ती हुई लागत नियम (Law of Increasing Cost)

यदि उत्पादन में बढ़ती हुई लागत का नियम क्रियाशील हो रहा है, अर्थात् जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने पर औसत लागत बढ़ रही है, तो एकाधिकारी के लिए कम मात्रा में उत्पादन करना ही हितकर है। ऐसा करने पर ही वह औसत लागत की वृद्धि को रोक सकता है तथा सीमान्त लागत कम करके अपनी वस्तु का मूल्य अधिक निर्धारित कर सकता है। चित्र सं० 111 में एकाधिकारी फर्म लागत वृद्धि के अन्तर्गत कार्य कर रही है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है औसत तथा सीमान्त लागत रेखाएँ (AC तथा MC) ऊपर की ओर जा रही हैं। A बिन्दु



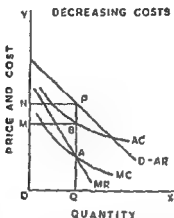
चित्र सं० 111

सीमान्त लागत (MC) = सीमान्त आय (MR) के। इस बिन्दु से होती हुई एक खड़ी रेखा तीचन पर वह कीमत रेखा (AR) को P बिन्दु पर तथा OX अक्ष को Q बिन्दु पर काटती है। अतः OQ उत्पादन मात्रा के लिए PQ कीमत हुई। एकाधिकारी के लाभ के लिए AR तथा AC की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि AR (सीमान्त आय रेखा) AC (औसत लागत रेखा) के ऊपर है। इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी PB प्रति इकाई लाभ प्रदर्शित करती है तथा कुल लाभ PBMN क्षेत्रफल के बराबर है। अतः कीमत—PQ, उत्पादन की मात्रा OQ, प्रति इकाई लाभ PB तथा कुल लाभ =  $PB \times BM$  या PBMN आयत व क्षेत्रफल के।

(ii) जबकि उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत के घटने का नियम (Law of Diminishing Costs) क्रियाशील हो रहा हो।

इस नियम व अन्तर्गत कार्य करने वाले एकाधिकारी द्वारा अधिक उत्पादन करने पर औसत लागत (AC) घटती चली जायगी। ऐसी स्थिति में औसत लागत को कम करने के लिए उत्पादन की मात्रा बढ़ाना एकाधिकारी के

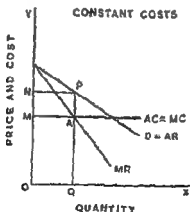
हित में होगा उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर सीमान्त लागत (MC) भी कम होगी जिससे एकाधिकारी की आय में वृद्धि होगी।



चित्र सं० 112

चित्र सं० 112 में AC तथा MC को के की प्रारंभिक गिरती हुई दिखाई गई है। A बिंदु पर सीमान्त आय (MR)=सीमान्त लागत (MC) के। इस बिंदु से होती हुई खड़ी रेखा खींचने पर PQ रेखा कीमत बताती है। AR तथा AC के मध्य लंब रेखा PB प्रति इकाई लाभ व्यक्त करती है। OQ कुल उत्पादन मात्रा है। अतः वस्तु का मूल्य=PQ, उत्पादन की मात्रा OQ कुल लाभ=PB×BM या PBMN के क्षेत्रफल के।

(iii) जबकि उत्पत्ति स्थिरता नियम या लागत स्थिरता नियम (Law of Constant Costs) लागू होता हो



चित्र सं० 113

उत्पादन लागत स्थिर रहने पर वस्तु की मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा।



वह एकाधिकारी को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता। जैसा कि चित्र सं० 113 से स्पष्ट है 'लागत स्थिरता नियम' के अन्तर्गत औसत लागत (AC) = सीमान्त लागत (MC) के। A बिन्दु पर सीमाव आय (MR) = सीमान्त लागत (MC) के। A से होनी हुई लंबी रेखा AR को P बिन्दु पर तथा OX अक्ष को Q पर काटती है जिससे यह सात होता है कि PQ कीमत है, OQ उत्पादन की मात्रा है तथा  $PA \times AM$  या  $OQ \times PAMN$  आय के क्षेत्रफल के बराबर एकाधिकारी का कुल लाभ है।

### विवेकात्मक या विवेचनात्मक एकाधिकार (Discriminating Monopoly)

1 प्रकृति : एकाधिकारी का उद्देश्य 'एकाधिकारिक लाभ' को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के समूहों से एक ही प्रकार की वस्तु के लिए निम्न-निम्न दरों पर कीमते लेता है। इस स्थिति को 'विवेचनात्मक एकाधिकार' कहा जाता है। विवेचनात्मक एकाधिकार विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न प्रयोगों के बीच सम्भव है। अन्तर् कीमतों के विवेचन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं

(i) व्यक्तिगत विवेचन (Personal Discrimination) : जब विभिन्न व्यक्तियों से अलग-अलग दरों पर कीमते वसूल की जाती हैं तो इसे व्यक्तिगत विवेचन कहते हैं। वस्तुओं के मूल्य उनकी मांग की तीव्रता (Intensity) के आधार पर लिये जाते हैं।

(ii) स्थान विवेचन (Place Discrimination) : जब विभिन्न बाजारों में अलग-अलग दरों पर कीमतें ली जाती हैं तो उसे स्थान विवेचन कहते हैं, जैन विदेशी बाजार में राशि-पातन (Dumping) के उद्देश्य में अत्यन्त ही कम मूल्य पर वस्तु बेची जाये तथा देश के अन्दर वस्तु का मूल्य बहुत ऊँचा रखा जाय।

(iii) व्यवसाय विवेचन (Trade Discrimination) : जब किसी वस्तु के प्रयोग के आधार पर विभिन्न दरों पर कीमतें ली जाती हैं तो उसे व्यवसाय विवेचन कहते हैं, जैसे दिक्कती के इन्फेन्सल के लिए औद्योगिक उपयोग (Industrial use) के लिए कम दर पर कीमतें ली जाती हैं तथा रोजाना आदि के लिए ऊँची दर पर कीमतें वसूल की जाती हैं। एक ही गुरा की वस्तु को विभिन्न लेवल लगाकर भी अलग-अलग दरों पर उद्धे बेचा जाता है।

### 2. मूल्य-विवेद की शर्तें (Conditions for Price Discrimination) :

एकाधिकारी द्वारा मूल्य विवेचन कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत ही सम्भव है :

(1) मांग की तीव्रता में विभिन्नता : विवेचनात्मक एकाधिकार उन्हीं समय

सकल हो सकता है, जबकि ग्राहकों की मांग की सोच में विभिन्नता हो। जिन ग्राहकों की मांग लाचरी है उनमें ऊँचा मूल्य तथा जिनकी मांग सोनपूरा है उन्हें कम मूल्य दिया जाता है।

(2) बाजारों का पृथक् होना : जिन बाजारों में मूल्य-विभेद किया जाए, वे बाजार पृथक्-पृथक् तथा एक दूसरे से दूर होने चाहिये, अन्यथा ग्राहक समूह मूल्य वाले बाजार में जाकर वस्तु को खरीदेंगे।

(3) नय शक्ति में विभिन्नता : ग्राहकों की नय शक्ति में विभिन्नता होने पर मूल्य-विभेद सम्भव होता है। एक डाक्टर अपनी व्यक्ति में शक्ति तथा गरीब व्यक्ति में कम शक्ति होता है।

(4) बाह्य पर विचार : यदि जन्तु ग्राहकों के मादम पर देखी जाती है तो विभिन्न ग्राहकों से भ्रमण चलकर वह न कीमत प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ग्राहकों की कीमतों की जानकारी नहीं होती है।

(5) समान सेवा : यदि विभिन्न वस्तुओं के लिए एक ही प्रकार की सेवा की आवश्यकता है तो भी मूल्य विभेद सम्भव हो सकता है, जैसे ग्राहकों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ खरीदने द्वारा भेजी जाती हैं, परन्तु खरीदने वाले समान दूरी के लिए भी विभिन्न वस्तुओं पर खर्च नाहें की अनन्य-अनन्य दूरें वस्तु की जाती हैं। अतः रेलवे द्वारा भी आवश्यकता विभिन्न वस्तुओं के लिए समान है, परन्तु उन वस्तुओं के साथ खर्च मूल्य विभेद करती है।

(6) परिवहन व्यय : वस्तुओं के एक स्थान में दूसरे स्थान पर पहुँचाने में परिवहन-व्यय उठाना पड़ता है। इस व्यय के कारण भी विभिन्न बाजारों में एक ही वस्तु विभिन्न दूर पर देखी जाती है। परिवहन-व्यय के कारण बाजारों का एक प्रकार में भौगोलिक विभाजन हो जाता है।

(7) सरकारी नियमन : कभी कभी सरकार ऐसे प्रतिबंध लगाती है या वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाती है जिनके कारण एक ही प्रकार की वस्तु विभिन्न मूल्यों पर देखी जाती है।

प्रो० पीगू ने मूल्य विभेद के निम्न दो शर्तों का उल्लेख किया है। प्रथम, वस्तु के अलग-अलग विभिन्न बाजार हो तथा एक बाजार से सम्बन्धित मांग

“The first of these (conditions) is that no unit of the commodity sold in one market can be transferred to another market. The second is that no unit of demand, proper to one market, can be transferred to another market”

का स्थानान्तर (Transfer) दूसरे बाजार में नहीं किया जा सकता हो। द्वितीय, एक बाजार में सम्बंधित पूर्ति का स्थानान्तर दूसरे बाजार में नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सेवाओं का विन्य उभवा उदाहरण है जैसे डाक्टर की सेवा। यदि एक डाक्टर एक निश्चित व्यक्ति से कम शुल्क लेता है तो निश्चित व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह डाक्टर में प्राप्त लाभ (पूर्ति) को अपनी व्यापक को हस्तांतरित कर सके या बच सके। अतः डाक्टर बना व्यक्ति में अधिक श्रुक्त न मकता है। अतः यहाँ पर मूलतः विभिन्न डेमण्ड सम्भव हो सका है कि पूर्ति का स्थानान्तर मूलतः बाजार से मझे बाजार का नहीं हो सका है। इस प्रकार इस उदाहरण में मूलतः विभेद इसलिए सम्भव हो सका है कि माग का भी स्थानान्तर सम्भव नहीं है जैसा अपनी व्यक्ति डाक्टर की सेवा सम्बंधी छपनों माग का भी स्थानान्तर नहीं हो सकता है, अर्थात् वह निश्चित बनकर अपनी माग को निश्चित व्यक्ति की साथ नहीं बना सकता है।

### 3 वर्गीकरण

प्रो० पीगू ने मृत्यु विवेचन का वर्गीकरण तीन धोरणों में किया है।<sup>6</sup>

(1) प्रथम धरा का मृत्यु विवेचन (Discrimination of the first order) उस अवस्था का कहते हैं जिसमें विभिन्न अनामों में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कामन होता है। इतना ही नहीं बल्कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कामन भी हो जाता है (एक ही विविधता से)। (श्रीमती जोन राबिन्सन का कहना है कि पूर्ण विवेचन उनी समय सम्भव है जबकि एक रज्जा एक दुकाई बय कर तथा उसके लिए वह अतिरिक्त कामन देने को प्रमत्त हो)।

(ii) द्वितीय धरा का मृत्यु विवेचन उस अवस्था में पाया जाता है जबकि बाजार का विभिन्न वर्गों में मृत्यु दुकान की क्षमता के आधार पर बांट दिया जाता है।

(iii) तृतीय धरा का मृत्यु विवेचन यह विवेचन दूसरा धरा के विवेचन का ही एक रूप है। इसमें विभिन्न अनामों में विभिन्न मृत्यु लिए जाते हैं तथा उनमें विभिन्न विभिन्न बाह्य निर्देशक (External Indices) द्वारा किया जाता है, जैसे रेलवे विभिन्न धरा के यात्रियों में अलग प्रत्यक्ष दरा पर किया जाता है परन्तु धरा के अनाम का स्वतंत्रता यात्रियों का होती है।

<sup>6</sup> 'We may distinguish three degree of discriminating power, which a monopolist may conceivably wield though all theoretically possible are not, from a practical point of view of equal importance'

मूल्य विभेद के रूपों का ज्ञान, निम्न सारिणी द्वारा किया जा सकता है :

मूल्य विभेद के प्रमुख रूप

मुख्य प्रकार	विभेद के आधार	उदाहरण
1. व्यक्तिगत (Personal)	पैसा की आय कमा की व्ययन की क्षमता	डायर वा शुल्क पेटेन्टेड मशीन की रायट्टी
2. समूह (Group)	(i) पैसा की आय, लिंग उत्पादि (ii) पैसा का स्थान (iii) पैसा का स्तर (Status) (iv) वस्तु का प्रयोग	बच्चों की वास्तु कटाई, सिनेमा गृह में विद्यार्थियों का प्रवेश-शुल्क डम्पिंग, सेन के अनुसार कीमतें नए याहू से कम की कीमत लेना, अधिक मात्रा में खरीदने वाली को छूट देना । रेलवे किराया, बिजली की अलग दरें,
3 वस्तु (Product)	(i) वस्तु के गुण (ii) वस्तु के मूल्य (iii) वस्तु की मात्रा (Size) (iv) सेवा के प्रयोग का समय (Peak and off peak period)	पुस्तक के डिलीवरी सस्करण की कीमत, विना बांध की वस्तुओं की कम कीमत बड़े पैक के दुश्पेस्ट की कम कीमत रेलवे द्वारा गर्मी के दिनों में नाइले में छूट, परिवहन सेवाओं द्वारा या हाटलों द्वारा अवधि विरोध में कम दरें वसूल करना ।

#### 4 विभेदात्मक एकाधिकार में मूल्य निर्धारण :

(Price Determination Under Discriminating Monopoly)

1 मूल्य निर्धारण विधि : एकाधिकारी का उद्देश्य एकाधिकारिक लाभ को अधिकतम करना होता है । विवेचनात्मक एकाधिकार के अन्तर्गत वह मांग की लोच के अनुसार, विभिन्न बाजारों में, विभिन्न दर पर कीमत वसूल करेगा । हम यह जानते हैं कि जब बाजार एक ही होता है तब शुद्ध एकाधिकारी सीमांत मांग को सीमांत लागत के बराबर कर अपना लाभ अधिकतम करता है । परन्तु विवेचनात्मक एकाधिकार की स्थिति में लाभ को अधिकतम किस प्रकार किया जाता है ? क्या (1) प्रत्येक बाजार में सीमांत आय को सीमांत लागत के बराबर कर लाभ अधिकतम किया जाए ? अथवा (2) सभी बाजारों की सीमांत आय के कुल योग को कुल सीमांत लागत के बराबर किया जाए ? श्रीमती जोन राबिन्सन का मत है कि (1) कुल उत्पादन की सीमांत लागत को प्रत्येक बाजार की सीमांत आय के बराबर कर विवेचनात्मक एकाधिकारी लाभ को अधिकतम कर सकता है । अर्थात् प्रत्येक बाजार

मे उसकी सीमात आय समान होनी चाहिए परन्तु साथ ही साथ प्रत्येक बाजार मे प्राप्त सीमात आय कुल उत्पादन की सीमात लागत के बराबर होनी चाहिए। कीमत प्रत्येक बाजार मे माग के अनुसार होगी।<sup>7</sup> विभेदात्मक एकाधिकारी द्वारा कीमत-निर्धारण की विधि का स्पष्टीकरण दो विधियों से किया जाता है—(1) जब एक बाजार मे उसका एकाधिकार हो तथा दूसरे बाजार मे उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तथा (2) जब उसे प्रतिस्पर्धा का सामना किसी भी बाजार मे नहीं करना पड़ रहा हो, अर्थात् प्रत्येक बाजार मे उसका एकाधिकार हो। इन दोनों दशाओं मे कीमत निर्धारण विधि का स्पष्टीकरण किया गया है

### 1. सुरक्षित देशी बाजार तथा प्रतिस्पर्धा पूर्ण विदेशी बाजार

(*Protected Home Market and Competitive Foreign Market*)

मूल्य-विवेचन की एक विशेष परिस्थिति उस समय होती जबकि एकाधिकार का ऐसे बाजारों में बचनी वस्तु बेच रहा हो जिनमें से एक में उसका एकाधिकार हो तथा दूसरे में उसे अथ प्रतिस्पर्धियों का मुकाबला करना पड़ रहा हो। जैसे, देश के मंदर तो उसे एकाधिकार प्राप्त हो परन्तु विदेशों में उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता हो। ऐसी परिस्थिति में सामान्यतया एकाधिकारी देश के अन्दर वस्तु का अधिक मूल्य तथा विदेश में कम मूल्य वसूल कर एकाधिकारिक लाभ को अधिकतम करता है।

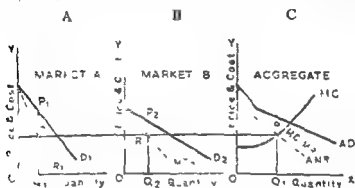
मान लीजिए बाजार 1. सुरक्षित देशी बाजार तथा बाजार 2 प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार है। विदेशी बाजार में कीमत सीमात आय के बराबर होगी ( $P=MR$ ) एकाधिकारी किसी भी इस प्रकार का समायोजन करेगा जिससे देशी बाजार की सीमात आय विदेशी बाजार की कीमत के बराबर हो। क्योंकि ऐसी समायोजना करने से ही दोनों बाजारों की सीमात आय समान होगी जिनमें कुल उत्पादन की सीमात लागत विदेशी बाजार के मूल्य के बराबर हो सकेगी। इसका स्पष्टीकरण रेखा चित्र मर्यादा 111 में किया गया है।

कुल उत्पादन  $OQ_2$  है।  $AR_1$  तथा  $AR_2$  क्रमशः देशी तथा विदेशी बाजार में माग वक्र हैं।  $MR_1$  तथा  $MR_2$  क्रमशः देशी तथा विदेशी बाजार में सम्बन्धित

<sup>7</sup> The monopoly output under price discrimination is determined by the intersection of the monopolist's marginal cost curve with aggregate marginal revenue curve. This total output is made up of the amounts sold in the two markets, in each of which marginal revenue is equal to the marginal cost of the whole output. The price in each market will be the demand price for the amount of output sold there".  
Joan Robinson, op. cit., p. 182



मांग की लोचें मिलती हैं। चित्र C दोनों बाजारों का योग है। बाजार A ऊँची आय प्रकट करता है जब मान तथा सीमांत आयम रेखाएँ (क्रमशः  $D_1$  तथा  $MR_1$ ) ऊँचे में प्रारम्भ होती हैं (चित्र B की अपेक्षा)। चित्र B में भी  $D_2$  तथा  $MR_2$  उच्च मान तथा सीमांत आयम को प्रकट करते हैं। चित्र C में A तथा B बाजारों का योग (Total) दिखाया गया है इस चित्र में  $AMR = MR_1 + MR_2$  को



चित्र म० 115

प्रकट करता है। चित्र C में सीमांत-लाभ भी दिखाई गई है। बिन्दु R पर (चित्र C) सीमांत लाभ, कुल सीमांत आयम (दोनों बाजारों की) के बराबर है। बिन्दु R से आगार-रेखा के समानान्तर रेखा खींची गई है। बिन्दु  $R_1$  तथा  $R_2$  पर  $MR_1$  तथा  $MR_2$ , MC (सीमांत लागत) के बराबर हैं।

$R_1$  तथा  $R_2$  बिन्दुओं से लम्बे डाले गये हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की कीमतों को ज्ञान किया जाता है।

चित्र C में स्पष्ट है कि उत्पादन की मात्रा  $OQ$  होगी। इस उत्पादन पर फर्म मनुजन की स्थिति में होगी क्योंकि इस उत्पादन पर सीमांत लागत तथा सीमांत आयम समान हैं। उत्पादन की यह मात्रा दोनों बाजारों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक बाजार का सीमांत आयम चित्र C के सीमांत आयम ( $Q_1R$ ) के बराबर हो। बाजार A में  $OQ_1$  मात्रा बेची जाएगी। इस मात्रा पर बाजार A में सीमांत आयम  $QR$  के बराबर है। उस बाजार में कीमत  $Q_1P_1$  होगी। इसी प्रकार बाजार B में  $OQ_2$  मात्रा  $Q_2P_2$  कीमत पर बेची जाएगी। यहाँ पर भी सीमांत आय (बाजार B में)  $RQ$  के बराबर है। चित्र C में R बिन्दु के बाएँ का क्षेत्र (AMR तथा MC द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं R बिन्दु के बाईं तरफ का घिरा हुआ क्षेत्र) एकाधिकारी के लाभ को प्रकट करता है।

पहले हम उल्लेख कर चुके हैं कि विभेदात्मक एकाधिकारी को लाभ अधिक-तम करने के लिए दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है : (1) सभी बाजारों में उसकी सीमान्त आय समान होनी चाहिए तथा (2) उसकी सीमान्त आय, सीमान्त लागत के बराबर होनी चाहिए हमारे प्रश्नों में प्रथम बाजार की सीमान्त आय = दूसरे बाजार की सीमान्त आय = सीमान्त लागत होनी चाहिए। चित्र से इन तीनों शर्तों की पूर्ति होती है।

**भाग की लोच का प्रभाव :**

मूल्य विभेद किन दशाओं में लाभदायक होता है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक साधारण एकाधिकारी फर्म के बजाय दो या अधिक फर्मों पर एक साधारण फर्म का निद्वैत लागू करना होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि समस्त बाजारों में सीमान्त आय समान रहनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें भाग की लोच पर भी विचार करना होगा क्योंकि सीमान्त भाग तथा औसत आय भाग की लोच से प्रभावित होती है। यदि हम यह मानते कि मूल्य-विभेद यस्तुतः सम्भव होता है तो एकाधिकारी के लिए दो बाजारों में वह उभी समय हितकर होगा जबकि एक ही एकाधिकार मूल्य (Single monopoly price) उनमें भाग की लोचें भिन्न भिन्न हों। इसका कारण यह है कि यदि दोनों बाजारों में एक ही एकाधिकार मूल्य पर भाग की लोचें बराबर होती हैं, तो दोनों बाजारों में सीमान्त आय बराबर होगी। इसको निम्न फार्मूला द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

$$\text{सीमान्त आय} = \text{औसत आय} \times \frac{e-1}{e}$$

यहां  $e$  भाग का विन्दु लोच है। यदि प्रत्येक बाजार में औसत आय (अर्थात् एक ही एकाधिकार मूल्य) समान है तथा भाग की लोचें भी समान हैं, तो उक्त फार्मूले से यह ज्ञात किया जा सकता है कि दोनों बाजारों में सीमान्त आय बराबर रहती है। दोनों बाजारों में सीमान्त आय के बराबर रहने पर एकाधिकारी को मूल्य-विभेद से कोई श्रेयशा नहीं मिलती, क्योंकि यदि मान ऊँचे मूल्य वाले बाजार से कम मूल्य वाले बाजार में स्थानान्तरित भी कर दिया जाता है तो कम मूल्य वाले बाजार का लाभ ऊँचे बाजार की हानि से मिट जाने के कारण उसकी कुल आय में कोई वृद्धि नहीं होगी।

अब यदि यह कल्पना की जाये कि एक ही एकाधिकार मूल्य पर प्रत्येक भाग की लोच भिन्न-भिन्न होती है। माना कि बाजार A में भाग की लोच या वेलोच (demand is inelastic) है तथा बाजार B में भाग की लोच बहुत ही



अधिक है (अर्थात् माग लोचदार है demand is elastic)। उक्त फार्मूले में यह मासूम किया जा सकता है कि यदि दोनों बाजारों में माग की लोच भिन्न भिन्न हैं, तो एक ही एकाधिकार मूल्य पर मागत आय भी भिन्न भिन्न होगी। बाजार A में माग की लोच नीची होने पर मूल्य एक ही एकाधिकार मूल्य से ऊपर जा मकेगा। इसका कारण यह है कि मूल्य के बढ़ने का माग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और मूल्य वृद्धि से माग में अधिक कमी नहीं आती। इसके विपरीत बाजार B में माग की लोच अधिक होने पर, मूल्य परिवर्तन का माग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाजार B में वस्तु के मूल्य को एक ही एकाधिकार मूल्य से नीचे रखना लाभप्रद होगा। इससे यह स्पष्ट है बाजार A में माग की लोच नीची होने से बिजली की कमी से आय में बहुत घावभी कमी आती है और बाजार B में माग की लोच ऊँची होने से मूल्य की कमी से आय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक ही मूल्य लेने वाले एकाधिकारी के लिए बेचोच माग वाले बाजार (A) से वस्तुओं को, लोचदार माग वाले बाजार (B) में को हस्तांतरित करना लाभप्रद होगा। बेलोच माग वाले बाजार (A) में एक (सीमांत) इकाई की बिजली कम होन पर आय में जो हानि होगी, वह लोचदार माग वाले बाजार (B) में एक (सीमांत) इकाई की बिजली की वृद्धि से होने वाली आय में जो वृद्धि होती है उससे कम होगी। जब दोनों बाजार में औसत आय समान होती है, तब उन बाजार में, जहाँ माग की लोच अधिक ऊँची होती है, सीमांत आय अपेक्षाकृत अधिक होती है। बाजार B में, जहाँ लोच ऊँची है, बाजार A की अपेक्षा सीमांत आय अधिक होगी, क्योंकि दोनों में औसत आय प्रारम्भ में समान है।

### 5 मूल्य-विवेचन का औचित्य (Justification of Price Discrimination)

आर्थिक या सामान्य-जीवन में किसी भी प्रकार का विवेचन सामान्यतः उचित नहीं है। मूल्य विवेचन उचित है या नहीं? यह इस बात पर निर्भर है कि मूल्य-विवेचन किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, तथा किस उद्देश्य में किया जा रहा है।

(1) मूल्य-विवेचन द्वारा, शुद्ध एकाधिकार की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह सम्भव है कि यदि मूल्य-विवेचन द्वारा लाभ न प्राप्त किया जाए तो उत्पादन या सेवा बन्द कर दी जाए। उदाहरणार्थ, यदि रेलवे बिजली कम्पनी (जो सार्वजनिक सेवा प्रदान करती है) आदि मूल्य-विवेचन की नीति न अपनाए तो उन्हें घाटा होगा तथा उत्पादन बन्द करना पड़ेगा। अतः ऐसी सेवाओं को जारी रखने के लिए मूल्य विवेचन पूर्णतया उचित है।

(2) यदि दो बाजारों में मूल्य विवेचन किया जा रहा है तो यह बनलाना कठिन है कि मूल्य-विवेचन उचित है या अनुचित। यदि मूल्य-विवेचन द्वारा निर्धनो

की कम मूल्य तथा धनी व्यक्तियों को अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची जा रही हैं तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से मूल्य-विवेचन उचित है।

(3) यदि नियमित व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से विदेशों में कम मूल्य पर तथा देश में अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची जा रही हैं तथा देश में बहुत अधिक ऊँचा मूल्य नहीं बटूल किया जा रहा है तो मूल्य-विवेचन उचित है।

(4) यदि मूल्य विवेचन द्वारा देश के कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है तो देश के कुल आर्थिक कल्याण की दृष्टि से मूल्य-विवेचन उचित है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणयोग्य है कि मूल्य-विवेचन द्वारा उत्पादन-साधनों का वितरण (maldistribution) होता है, अतः इस दृष्टि से मूल्य विवेचन हानि-प्रद है।

**क्या एकाधिकार मूल्य सदैव स्पर्धात्मक मूल्य से ऊँचा होता है ?**

**(Is Monopoly Price Always Higher than Competitive Price ?)**

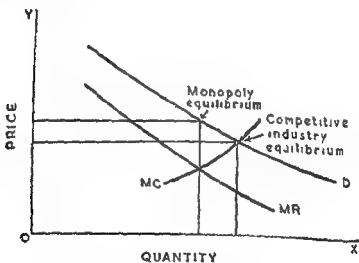
हम यह जानते हैं कि पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत सीमान्त लागत के बराबर होती है तथा एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत सामान्यतः सीमान्त लागत से अधिक होती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत, पूर्ण स्पर्धा की अपेक्षा सदैव ऊँचा होगी। पूरी परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान सम्भव है, जिनमें एकाधिकार मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से कम हो।

अधिक मात्रा में उत्पादन तथा विह्वलताओं में बिना-बिक्री के कारण यह सम्भव है कि एकाधिकारी की शोषण लागत अपेक्षाकृत कम हो। अतः यदि एकाधिकारी अपनी सीमान्त लागत से अधिक भी कीमत वसूल करे तो भी यह सर्वथा सम्भव है कि उसकी सीमान्त लागत प्रतिस्पर्धी विक्रेता की लागत से कम हो। इस प्रकार एकाधिकारी की कीमत पुनः-स्पर्धी की कीमत से कम हो सकती है।

सामान्यतया एकाधिकारी-कीमत पूर्ण स्पर्धी कीमत से ऊँची होती है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह कीमत सदैव ऊँची हो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तथा तत्त्व हैं जो एकाधिकारी को अधिक कीमत रखने से रोकते हैं : (1) स्थानावस्था वस्तुओं का भय, (2) सरकारी नियमन तथा विधिवश, (3) उपभोक्ताओं का प्रबल विरोध, (4) प्रतिযোগिता का भय, (5) अधिक मात्रा में उत्पादन द्वारा उत्पादन व्यय में कमी कर विक्रय की मात्रा में वृद्धि करके अधिक लाभ अर्जित करने की इच्छा, (6) और कभी-कभी जन-कल्याण की भावना, आदि कारणों से एकाधिकारी मनमाने ढंग में ऊँची कीमत निर्धारित नहीं कर सकता है।

अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादन करने वाले उद्योग की अपेक्षा कीमत ऊँची रखता है तथा उत्पादन कम करता है, यदि माग तथा लागत की दशाएँ समान हों।

चित्र सं० 116 में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की स्थितियों की तुलना की गयी है। यहाँ पर यह मान लिया गया है कि एकाधिकारी के पास भी उतने ही प्लांट (plants) हैं जितने कि पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में उत्पादन करने वाले उद्योग के पास। दोनों के लिए लागत समान है तथा उद्योग में प्रत्येक पड़त का थोड़ा अंश प्रयोग में लाया जाता है। एकाधिकारी की प्रेरणा का आधार अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। अतः जहाँ पर भी सम्भव होगा वह पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कार्य करने वाले फर्मों की तरह लागत कम करने का प्रयत्न करेगा। वह ही गयी उत्पादन-मानों को विभिन्न प्लांटों में उन्ही प्रकार बाँटगा जिस प्रकार कि उत्पादन का बंटवारा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किया जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा, तो विभिन्न प्लांटों में सीमान्त लागतों में अन्तर होगा और इस प्रकार वह ऊँची सीमान्त लागत वाले प्लांट द्वारा एवं इससे अधिक उत्पादन करके अथवा कम सीमान्त लागत वाले प्लांट द्वारा एवं इससे अधिक उत्पादन करके कुल लागत कम करने का प्रयत्न करेगा। चित्र सं० 116 में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता के कुल सीमान्त लागत एक ही हैं। उपयुक्त मान्यता के आधार पर ही दोनों प्रकार की संस्थान्त स्थितियों के लिए माँग वक्र भी एक ही है।



चित्र सं० 116

प्रो० जैतब्रेथ (John Kenneth Galbraith) ने 'Theory of Countervailing Power' का विचार प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि एकाधिकारी आती प्रतिस्पर्धा के समय से अधिक ऊँची कीमत नहीं रखता

है। साथ ही साथ सरकारी प्रतिबन्धों का भी उसे भय रहता है। प्रो० गैलब्रेथ का कहना है कि एकाधिकारी उपभोक्ताओं की प्रतिस्पर्धा से अधिक डरता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे Theory of Countervailing Power कहते हैं। उन्होंने 'फुटकर उपभोक्ता वस्तु बाजार' तथा 'उत्पादक वस्तु बाजार' का अध्ययन कर यह बनलाया है कि एकाधिकारी की अनामाजित नीतियों के विरोध में उपभोक्ता भी 'जैसा एकाधिकारी' के रूप में संगठित होते हैं। इस प्रकार उनकी एकाधिकारिक शक्ति, उत्पादक एकाधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत आर्थिक शक्ति को उन व्यक्तियों द्वारा रोका जाता है जो इन शक्तियों के शिकार होते हैं। आर्थिक सत्ता के कन्द्रीयकरण ने केवल मजबूत विक्रेताओं को ही नहीं, बल्कि मजबूत क्रयकर्ताओं को भी जन्म दिया है। कुछ विक्रेताओं के विविष्ट आधुनिक बाजार में क्रियात्मक प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धियों द्वारा नहीं बल्कि बाजार के दूसरे पक्ष विक्रेताओं द्वारा किया जाता है।<sup>1</sup> अतः एकाधिकारी की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतिरोधक तत्त्व स्वयं क्रय ही है। (प्रो० गैलब्रेथ ने विक्रेता के Countervailing Power का भी उल्लेख किया है।)

### एकाधिकार का नियमन (Regulation of Monopoly)

कभी कभी एकाधिकार के परिणाम बड़े घातक सिद्ध होते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण, कृत्रिम ढंग से वस्तुओं की पूर्ति कम कर देना, उत्पादन की नवीन विधियों के प्रति एकाधिकारी की उबासीनता, एकाधिकारी द्वारा अर्थ व्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति पैदा कर देना आदि ऐसे दोष हैं, जिनके आधार पर एकाधिकार को कटु निन्दा की जाती है। इन दोषों को दूर करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, एकाधिकार का नियमन किया जाता है नियमन के निम्नलिखित रूप हैं

#### (1) एकाधिकार विरोधी सन्निधिम (Anti-Monopoly Legislation)

एकाधिकार पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। ऐसे अधिनियमों का उद्देश्य (1) एकाधिकारिक संस्थाओं की स्थापना न होने देना या (2) पूर्व स्थापित एकाधिकारिक संस्थाओं को समाप्त कर उन्हें छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त करना होता है। परन्तु यह विधि किसी भी देश में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध नहीं हुई है। नियमों की

1 "—Private economic power is held in check by the countervailing power of those who are subject to it. The first begets the second. The long trend towards concentration of industrial enterprise in the hands of a relatively few firms has brought into existence not only strong sellers, but also strong buyers. In the typical modern market of few sellers, the active restraint is provided not by competitors but from the other side of the market by strong buyers."

कमियों से एकाधिकारी अनुचित रूप में लाभ उठाते हैं तथा किसी न किसी प्रकार वे उन नियमों की छिपे रूप में अवहेलना करते रहते हैं।

(2) अनुचित व्यवहारों पर प्रतिबन्ध ( Control of Mal practices ) : ऐसे नियम बनाए जाए जो एकाधिकारी मम्बाग्रो की अनुचित कामवाहियों पर रोक लगा सकें। वस्तु का गुण (Quality) निश्चित करने, बिनाशकारी रागिपातन (Dumping) को रोकने तथा मम्बाग्रिन प्रतियोगी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नियम बनाए जा सकते हैं। प्रो० पोषू का विचार है कि इस प्रकार के नियमों को भी प्राणिक संकलना ही मिलनी है। अतः निष्पक्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण की नीति ही श्रेयस्कार है।

(3) मूल्य तथा उत्पादन पर नियन्त्रण (Control of Prices and Output) सरकार द्वारा एकाधिकारी के मूल्य तथा उत्पादन पर नियन्त्रण रखा जाता है। सरकार यात्राग की नियुक्ति कर, उसके सुझावों के अनुसार उचित कीमत निर्धारित कर सकती है तथा उत्पादन की मात्रा निश्चित कर सकती है। परन्तु उचित कीमत निर्धारित करने में कुछ बावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे उत्पादन व्यय का अनुमान किस प्रकार लगाया जाए तथा लाभ की किस दर को उचित माना जाए। स माग्यतया कीमत तथा उत्पादन पर निम्नलिखित ढंग से नियन्त्रण लागू किया जा सकता है।

(क) कीमत इस प्रकार से निश्चित की जाए की सीमान्त आय सीमान्त व्यय के बराबर हो।  $(P=M=MC)$ ।

(ख) कीमत उस बिन्दु पर निश्चित की जाए जिस पर सीमान्त उत्पादन लागत कीमत अथवा औसत आय के बराबर हो  $(P=MC=AR)$ । ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को अधिक लाभ होगा, परन्तु यह स्थिति अनियन्त्रित एकाधिकार की स्थिति में, उपभोक्ताओं की दृष्टि, में श्रेष्ठतर है। इस प्रकार के नियन्त्रण के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सीमान्त लागत (MC) उत्पादन में प्रयुक्त माधनों की कीमत को व्यक्त करनी है तथा कीमत उपभोक्ताओं का वस्तु से प्राप्त मूल्य को प्रकट करती है, अतः सामाजिक दृष्टि में यह उचित है कि उत्पादन में वृद्धि उस सीमा तक होने दिया जाए, जहां पर साधनों का मूल्य उनकी सीमात लागत के बराबर हो।

(ग) कीमत इस प्रकार निश्चित की जाए कि औसत उत्पादन लागत, औसत आय के बराबर हो। इसके साथ ही उत्पादन को न्यूनतम मात्रा भी निश्चित कर दी जाए। ऐसी परिस्थिति में एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा।

(4) सार्वजनिक स्वामित्व ( Public Ownership ) एकाधिकारिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करना, एकाधिकार पर नियन्त्रण रखने का अन्तिम शस्त्र

है। सामान्यतः रेलवे तथा परिवहन के माधनों, विद्युत उत्पादन तथा बि-रण, जल-व्यव-या, आदि मावजनिक हिन में सम्बन्धित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जनहित की दृष्टि में मावजनिक स्वामित्व व्यक्तिगत स्वामित्व से श्रेष्ठतर है। राष्ट्रीयकरण द्वारा उत्पादन माधनों का विभिन्न उपयोगों के बीच उचित वितरण सम्भव होता है। राजकीय स्वामित्व अनिवार्यतः निम्न स्वामित्व से बहुत अच्छा है।

**एकाधिकार की आर्थिक कुशलता (Economic Efficiency of Monopoly)**

(1) एकाधिकारी फर्म सामान्यतया माधनों का उपयोग अधिकतम कुशलता के साथ नहीं करती है। हम यह जानते हैं कि पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत, दीर्घकाल में, फर्म अनुकूलतम आकार की होती है तथा उनका उत्पादन भी अनुकूलतम (Optimum) होता है। परन्तु दीर्घकाल में, जिस उत्पादन पर एकाधिकारी का साम्य अधिकतम होता है, यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन की वह मात्रा अनुकूलतम हो तथा फर्म का आकार अनुकूलतम हो, (ii) ऐसा हावे हुए भी हम यह याद रखना चाहिए कि कोई ऐसा उद्योग, जिसमें बाजार संतुलन होने के कारण उत्पादन अनुकूलतम उत्पादन में कम किया जा रहा हो, अभी दशा में एकाधिकार की व्यवस्था में उत्पादन लागत अथवा अधिक कुशलता का प्रतीक हो सकता है। इस दशा में यदि फर्मों की संख्या अधिक है अथवा पूर्ण स्पर्धा की दशा है तो प्रत्येक फर्म अपनी प्वाट का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर सकती, इस प्रकार आर्थिक कुशलता कम होगी। परन्तु यह स्मरणाय है कि ऐसा दशा में अधिक कुशल होने हुए भी, एकाधिकारी फर्म सामान्यतः अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग नहीं कर सकती है।

### प्रश्न व संकेत

1. एकाधिकारी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित करता है ?

(Nagpur B Com I 1964)

[नकद सत्य में एकाधिकार का अर्थ लिये और उसका उद्देश्य बनाये। तत्पश्चात् रक्षाचिन्ता द्वारा कुल मागम व कुल लागत वक्रों की रीति व सीमाद और सीमागत वक्रों का रीति (अल्पकाल में तथा दीर्घकाल में) द्वारा एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण का समझाये।]

2. एकाधिकारी किन विधानों के आधार पर अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है ? क्या एकाधिकारी का मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से सदैव अधिक होता है ?

(Agra B Com I, 1963)

[संकेत—'अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु एकाधिकारी कम उत्पादन की संख्या पर बेचता है', इसे समझाये। दूसरे भाग में उदाहरण सहित स्पष्ट

कीजिए कि एकाधिकारी द्वारा लिया जाने वाला मूल्य प्रतिस्पर्धामूलक मूल्य से सामान्यतः अधिक होता है, सदैव नहीं चित्र सख्या 116 का प्रयोग कीजिए।]

3. "एकाधिकारी के स्वामी की स्वार्थ पूर्ति मांग का इस प्रकार से समायोजन करने में नहीं है कि वस्तु की विक्रय कीमत केवल उसकी उत्पादन लागतों को ही पूरा कर सके, बल्कि उसका स्वार्थ इस प्रकार के समायोजन में है कि उसे अधिकतम शुद्ध आगम प्राप्त हो।" मार्शल के इस कथन के संदर्भ में एकाधिकारी मूल्य निर्धारण को समझाइये।

(संकेत—एकाधिकारी के उद्देश्यों को समझाते हुए कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए तथा मूल्य-निर्धारण की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या कीजिए।]

4. एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण के अन्तर को पूर्णतया स्पष्ट कीजिए।

(Ravishankar, B Com I, Compant., 1965, Agra II Com I, 1961)

(संकेत—एकाधिकार व प्रतियोगिता का संक्षेप में समझाइये और दोनों अवस्थाओं में मूल्य निर्धारण के मूल तरीकों का वर्णन करके उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए। यथास्थान चित्र भी दें।)

5. मूल्य विभेद की परिभाषा दी। विभेदकारी एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? क्या मूल्य विभेद सदैव हानिकारक होता है?

(संकेत—मूल्य विभेद की परिभाषा लिखिए और उसे स्पष्ट करिए। रेखाचित्र द्वारा इस बाजार अवस्था में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। अन्त में उन दशाओं को समझाइये जिनमें विभेदात्मक एकाधिकार उपयोगी हो सकता है।)

6. एकाधिकार को किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता? इस नियन्त्रण की क्या सीमाएँ हैं?

(Ravi. B A (F) Comp., 1965)

(संकेत—एकाधिकार पर लगाये जाने वाले विभिन्न नियन्त्रणों को बताइये तथा इनकी सीमाएँ लिखिए।)

### समस्याएँ (Problems)

1. क्या एक एकाधिकारी अपने उत्पाद का मूल्य-विभेद (Price discrimination) करके बेच सकेगा, यदि दो अलग-अलग बाजारों में मांग सूची निम्न प्रकार हो। कारण सहित समझाइये।

$$Q_1 = 72,000 - 1,000,000P$$

$$Q_2 = 108,000 - 1,500,000P$$

2. अनेक वायुयान 'मूल्य विभेद' का प्रयोग करते हैं। बताइये इनके संदर्भ में मूल्य-विभेद का क्या आधार है—ट्यूरिस्ट बनाम प्रथम श्रेणी के किराये व परिवार वायुयान।

3. यूनाइटेड एयर लाइन्स ने 'प्रथम-श्रेणी' के वायुयानों के आरम्भ करने की सूचना दी जो 'ट्यूरिस्ट तथा प्रथम श्रेणी' की प्रणाली (System) को प्रतिस्थापित करने हेतु चलाये गये। उदाहरणार्थ डम विधि के अन्तर्गत "एकमार्गी-बिना रुकने वाले जेट" (One-way non stop jet) की प्रथम-श्रेणी की सेवा का व्यय 160 65 या जबकि पहले 'प्रथम श्रेणी' व 'ट्यूरिस्ट श्रेणी' का किराया-व्यय क्रमशः \$196.25 तथा \$152.36 था। बताइये यूनाइटेड एयरलाइन्स द्वारा पहले की दोनों प्रणालियों को समाप्त करने के क्या कारण थे ?

4. कारण सहित बताइये कि एक एकाधिकारी के समस्त लाभों पर कर लगा दिया जाय तो वह क्या प्रयत्न करेगा ?

5. माना एक एकाधिकारी के उत्पाद की माग की लोच 1.50 से 1.25 रह जाती है। यदि लागते स्थिर रहती हैं तो कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ?

6. एक तेल-उत्पादक एकाधिकारी के सम्मुख निम्नलिखित माग-मूची है। मान लीजिए कि उसकी सीमान्त लागतें शून्य हैं :—

- (i) किस सीमा के पश्चात् वह उत्पादन की मात्रा बढ़ाना बन्द कर देगा ?
- (ii) अधोलिखित उत्पादन पर उसकी माग लोच क्या होगी ?

मूल्य	तेल की माग (टनो में)
6	250
5	900
4	1,500
3	2,000
2	2,500
1	3,800

7. निम्न में से मूल्य-विभेद के उदाहरण दीजिए—

- (i) बस-यात्रा (ii) देशी बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कार की बिक्री (iii) रेलवे द्वारा वसूल विया गया किराया, तथा (iv) टेलिफोन काल्म (Telephone Calls)



8 मान लीजिए एकाधिकारी दो भिन्न भिन्न बाजारों में निम्नलिखित माग-सूचियाँ हैं, तथा उसके पास विन्य हेतु 1 400 इकाइयाँ हैं, तो बताइये कि वह इस मात्रा को दोनों बाजारों में प्रस्तुत करने हेतु उसे कितनी कीमत लेनी चाहिए और क्यों ?

माग सूचियाँ	बाजार I		बाजार II	
	कीमत (₹०)	मात्रा (इकाइयाँ)	कीमत (₹०)	मात्रा (इकाइयाँ)
	50	400	60	600
	40	600	50	800
	30	900	40	1,100
	20	1,000	30	1,400

9 मान लीजिए प्रथम बाजार में  $e=2.0$  तथा द्वितीय बाजार में  $e=1.5$  है तो उत्पादक (एकाधिकारी) किस बाजार में अपनी उत्पाद बेचेगा ? उसके द्वारा बमूल की गई कीमतों का आनुपातिक प्रतिशत (Percentage ratio of the Prices) क्या होगा ?

## अपूर्ण प्रतिस्पर्धा : मूल्य व उत्पादन निर्धारण (Imperfect Competition Price and Output Determination)

*"The terms monopolistic and imperfect competition describe a situation similar to perfect competition with the single important difference that each producer sells a product that is somewhat differentiated from that sold by his competitors"*

—Lipsey, Richard G

अब तक हमने बाजार की दो चरम सीमाओं—पूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार के विषय में अध्ययन किया है। इस अध्याय में विशेष में हम उन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे जो इन दोनों के बीच पाई जाती है। व्यावहारिक अणत में न तो पूर्ण स्पर्धा पाई जाती है और न शुद्ध एकाधिकार। वस्तुतः इन दोनों के बीच की अवस्थाएँ पाई जाती हैं। इन बीच की अवस्थाओं को 'मध्यम बाजार की अवस्थाओं' (Intermediate Market Situations) की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तुतः हम किसी एक स्थिति को अपूर्ण स्पर्धा की स्थिति नहीं कह सकते हैं। अपूर्ण स्पर्धा की कई स्थितियाँ होती हैं। अपूर्ण स्पर्धा की सभी अवस्थाओं के वर्णन को इस पुस्तक की अध्ययन सामग्री नहीं बताया जा सकता, अतः यहाँ पर हम केवल अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के दो रूपों 'एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा' (Monopolistic Competition) तथा अल्प विक्रेताधिकार या अल्पाधिकार (oligopoly) के अन्तर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण का अध्ययन करेंगे।

### 1 एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition)—

1 अर्थ 'एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा' शब्द के प्रणेत चैम्बरलिन थे। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग बाजार की दो अवस्थाओं के लिए किया है—प्रथम, बहुत से उत्पादक प्रवेश की स्वतन्त्रता के साथ तथा द्वितीय कुछ उत्पादक प्रवेश को सीमित

स्वतन्त्रता के साथ । परन्तु आजकल एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा का अर्थ प्रथम अवस्था से है, तथा द्वितीय का अग्रिमार्थ Oligopoly से है । एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा का अग्रिमार्थ उस अवस्था से है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं परन्तु उनकी वस्तुओं में इतना विभेद (Differentiation) पाया जाता है कि वे एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न (Imperfect Substitutes) सिद्ध होती हैं । प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक का अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार होता है, परन्तु उसे लगभग अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । अतः प्रत्येक उत्पादक एकाधिकारी होता है, परन्तु साथ ही साथ उसे प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है । उदाहरण के लिए, विभिन्न ब्रांड की कारों तथा सिगरेटों के बीच जो स्पर्धा होती है, उसे एकाधिकृत स्पर्धा कह सकते हैं । स्टोनियर तथा हेग के शब्दों में, “अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में अधिकांश उत्पादकों की वस्तुएँ उनके प्रतिद्वन्द्वियों की वस्तुओं से बहुत मिलती जुलती होती हैं । परिणामस्वरूप इन उत्पादकों को हमेशा इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि प्रतिद्वन्द्वियों की क्रियाएँ उनके लाभ को कैसे प्रभावित करेंगी । अधिक सिद्धांत में इस तरह की स्थिति का विश्लेषण एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition) अथवा समूह-संतुलन (Group Equilibrium) के अन्तर्गत किया जाता है । इसमें एच सी वस्तुएँ बनाने वाली अनेक फर्मों में प्रतिस्पर्धा पूर्ण न होकर तीव्र होती है ।” एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं : (i) फर्मों की संख्या का अधिक होना, (ii) उद्योग में किसी भी फर्म के प्रवेश की स्वतन्त्रता, (iii) सभी के द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना, परन्तु वस्तुओं का समान न होना, (iv) वस्तु-विभेद का पाया जाना, (v) फर्म का अपनी वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार (vi) विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा का पाया जाना । (vii) क्रेता विभिन्न विक्रेताओं में से किसी एक की वस्तु को अधिक पसन्द कर सकते हैं । यह पसन्दगी वास्तविक अथवा काल्पनिक आधार पर हो सकती है, तथा (iii) क्रेताओं की पसन्द के आधार पर एकाधिकृत प्रतिस्पर्धी, अपने प्रतिस्पर्धी की वस्तुओं की तुलना में अधिक कीमत ले सकता है, परन्तु अधिक कीमत की सीमा स्थानापन्न वस्तुओं द्वारा निश्चित होती है, अतः “एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा...एकाधिकृत उसी बिन्दु तक है जहाँ स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग प्रारम्भ होता है तथा इस बिन्दु के पश्चात् वह प्रतिस्पर्धी हो जाती है ।”<sup>1</sup>

पूर्ण स्पर्धा में सम-रूप वस्तु एक ही होती हैं, एकाधिकृत-प्रतिस्पर्धा में वस्तुओं में अन्तर पाया जाता है । परन्तु वस्तुएँ ऐसी भी नहीं होती हैं जो एक दूसरे से

<sup>1</sup> “Monopolistic competition is.....monopolistic only up to the point where substitution take place and competitive only beyond that point.”  
—Clair Wilcox

पूर्णतया भिन्न हो। वस्तु एक ही प्रकार की होती है, परन्तु उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। वस्तुएँ समान (Identical) या लगभग समान होते हुए भी, ट्रेड-मार्क, भिन्न पैकिंग या भिन्न ब्राड के प्रयोग से अलग तथा भिन्न प्रतीत होती हैं। वस्तु की बनावट से भी कुछ भिन्नता दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में न तो वस्तुएँ समरूप होती हैं और न एकाधिकार की तरह दूर की स्थापनापन्न। एकाधिकृत-प्रतिस्पर्धा में कई 'एकाधिकारी' पाये जाते हैं जो एक दूसरे के तीव्र प्रतिस्पर्धी होते हैं। उनमें गम्भीर प्रतिस्पर्धा होती है।

**2 वस्तु विभेद (Product Differentiation) :** वस्तु-विभेद एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा का मूल आधार है, अर्थात् प्रत्येक फर्म की वस्तु किसी न किसी प्रकार अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न होती है। सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ अधिकांश अर्थों में एक दूसरे की स्थापनापन्न होती हैं, परन्तु वे एक जैसी नहीं होती हैं। यदि वस्तु-विभेद नहीं हो, अर्थात् वस्तुओं में एकरूपता हो तो एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतिस्पर्धा का रूप ग्रहण कर लेगी। इसी प्रकार यदि पूर्ण वस्तु-विभेद हो, अर्थात् वस्तुएँ एक दूसरे की स्थापनापन्न (Substitutes) न हो तो एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार का रूप ग्रहण कर लेगी।

एकाधिकृत प्रतिस्पर्धी वस्तु-विभेद के विभिन्न तरीके अपनाता है। यह विभेद (i) वस्तु की विशेषताओं पर आधारित हो सकता है, जैसे ट्रेडमार्क, पैकिंग में विभिन्नता, रंग तथा रूप में विभिन्नता, डिजाइन का अलग होना आदि, (ii) वस्तु विभेद विक्रय की दशाओं पर भी आधारित हो सकता है, जैसे विक्रय स्थान का सुविधाजनक होना, विज्ञान की रचना, विक्रय की आवश्यक शर्तें—जैसे वस्तु की मरम्मत की सुविधा, पराब हान की अवस्था में वस्तु की वापसी, साख-सुविधा, वस्तु को जेता के घर पर पहुँचाने की सुविधा आदि आदि, (iii) विज्ञापन तथा अन्य विक्रय-वृद्धि-विधियों द्वारा भी वस्तु-विभेद सफलतापूर्वक किया जाता है। मुख्य रूप से वस्तु विभेद की दो विधियाँ हैं : (1) वस्तु-विभिन्नता (Product Variation) तथा (2) विक्रय-विस्तार (Sales Promotion)।

**3. एकाधिकृत प्रतिस्पर्धी की माँग :** हम यह जानते हैं कि पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत वस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार होती है, अर्थात् वर्तमान कीमत पर फर्म जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। परन्तु एकाधिकृत स्पर्धा के अन्तर्गत माँग—एक फर्म की माँग, पूर्ण लोचदार नहीं होती है। यदि फर्म अधिक मात्रा बेचना चाहती है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, ताकि दूसरी फर्मों के ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। इस प्रकार विक्रेता का कीमत पर अधिकार अपेक्षाकृत कम होता है। उसकी वस्तु की माँग-वक्र का ढाल (slope) नीचे की ओर होता है, जो यह प्रकट

करता है कि कम मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेची जा सकती है। स्थानापन्न वस्तुओं के उपलब्ध होने के कारण भी कीमत कम रखकर ही अधिक मात्रा बेची जा सकती है।

4. एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा की पूर्ति : (1) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत उत्पादक को 'उत्पादन-लागत' ही वहन करना पड़ता है, परन्तु एकाधिकृत स्पर्धा में उत्पादन-लागत के साथ ही साथ 'विक्रय-सम्बन्धी लागतों' (selling costs) को भी वहन करना पड़ता है, (2) पूर्ण स्पर्धा में दीर्घकाल में असंख्य अनुकूलतम फर्म होती हैं, जो न्यूनतम 'उत्पादन लागत' पर उत्पादन करती हैं, परन्तु एकाधिकृत स्पर्धा के अन्तर्गत दीर्घकाल में भी फर्म अनुकूलतम से छोटे आकार (less than optimum) की होती है।

#### 5 फर्म का सन्तुलन तथा कीमत-निर्धारण (Equilibrium of Firm and Price):

1 अल्प-काल (Short Run) एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा की माग तथा पूर्ति का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसका माग-वक्र नीचे झुका हुआ होता है। (अर्थात् उसका प्रीसल आय वक्र नीचे झुका हुआ होता है)। फर्म अनुकूलतम आकार से छोटी होती है। फर्म अपना विस्तार उम समय भी रोक देती है जबकि उसकी प्रीसल लागत घट रही हो। इसका कारण यह है कि फर्म सन्तुलन की स्थिति में उसी समय हो जाएगी, जिस समय सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय समान हो जाएगी ( $MR=MC$ )। फर्म की प्रीसल आय अधिक या कीमत सीमान्त आय से कम होगी। (Price is less than marginal revenue)। यदि फर्म इस बिन्दु के पश्चात् भी (where  $MR=MC$ ) बड़े पैमाने के उत्पादन से लाभ उठाने के लिए अपना विस्तार करती जाती है तो उसकी सीमान्त आय ऋणात्मक (Negative) हो जाएगी। चूंकि सन्तुलन की स्थिति उम समय होती है जबकि सीमान्त आय सीमान्त लागत के बराबर हो, (Profit is maximum when  $MR=MC$ ), अतः इस बिन्दु के पश्चात् एकाधिकृत स्पर्धा फर्म अपना विस्तार रोक देगी।

एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत फर्म को विक्रय-व्यय भी वहन करना पड़ता है। फर्म बिजली में वृद्धि केवल मूल्य घटाकर ही नहीं, बल्कि विज्ञापन आदि द्वारा भी करती है। अतः फर्म विक्रय-व्यय भी कीमत द्वारा समूह करना चाहती है। इस प्रकार फर्म जिस शुद्ध आय (Net Revenue) को अधिकतम करना चाहती है, उसे निम्नलिखित प्रकार प्रकट किया जा सकता है:

$$[\text{कीमत} \times \text{उत्पादन}] - [\text{उत्पादन लागत} + \text{विक्रय व्यय}]$$

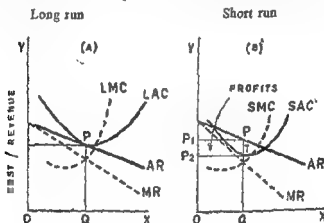
उपरोक्त दोनों के अन्तर को फर्म अधिकतम करना चाहती है। अतः फर्म की सन्तुलन स्थिति का अध्ययन कर उम समय विक्रय-व्यय का भी ध्यान रखना होगा।

विक्रय-व्यय को सीमांत तथा औसत लागत में सम्मिलित करना पड़ेगा। इसमें कठिनाई बढ जाती है। एक सामान्य नियम यह हो सकता है कि फर्म 'विक्रय-व्यय' में वृद्धि को उस समय रोक देगी, जबकि अतिरिक्त विक्रय-व्यय के कारण प्राप्त अतिरिक्त आय, अतिरिक्त विक्रय व्यय के बराबर हो जाए। जैसे दम रूपा विक्रय-व्यय करने से यदि अतिरिक्त आय भी दम रूपया होती है, तो फर्म इसके बाद विक्रय व्यय में वृद्धि नहीं करेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि फर्म सन्तुलन की स्थिति में उस समय होगी जबकि उत्पादन लागत तथा विक्रय-लागत को सम्मिलित कर:

सीमान्त आय = सीमांत लागत,  $MR = MC$ ।

सन्तुलन की स्थिति का स्पष्टीकरण चित्र सख्या 108 में किया गया है।

चित्र सं० 108 में SMC, SAC प्रत्यक्ष अल्पकालीन सीमांत लागत तथा प्रत्यवालीन औसत लागत वक्र हैं। AR तथा MR वक्र क्रमशः औसत तथा सीमान्त



चित्र सं० 108

आय वक्र हैं। MR तथा SMC वक्र एक दूसरे को OQ उत्पादन-मात्रा पर काटते हैं। अतः इस उत्पादन-मात्रा पर फर्म सन्तुलन की स्थिति में है। इस उत्पादन मात्रा के लिए कीमत PQ (या  $OP_1$ ) है। QT औसत उत्पादन लागत है तथा PQ औसत आय है। इस प्रकार फर्म को  $P_1P_2$  TP के बराबर अधिक-लाभ (Super-normal profit) प्राप्त हो रहा है। (इससे यह स्पष्ट होता है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन सन्तुलन पूर्णतया एकाधिकारी फर्म के सन्तुलन की ही भांति है<sup>2</sup>)

<sup>2</sup> "The Short Run equilibrium of the firm (under monopolistic competition) is exactly the same as that of a monopolist."

३ उद्योग की साम्य अवस्था अथवा 'सामूहिक-संतुलन-स्थिति' :

(Equilibrium of the Industry or Group Equilibrium):

एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत वस्तु-विभेद पाया जाता है, अतः यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या 'उद्योग' शब्द का प्रयोग ऐसी स्थिति में उपयुक्त है? हम यह जानते हैं कि इस अवस्था में वस्तु विभेद होने पर भी वस्तुएँ एक-दूसरे की स्थानापन्न होती हैं। 'हिन्द', 'हरक्यूजिस', 'ईस्टर्न स्टार' आदि साइकिलों में अन्तर हो सकता है, परन्तु उद्योग विभिन्न उत्पादक-समूहों का एक वृहद् समूह होता है। इसी कारण एकाधिकारिक स्पर्धा का स्थिति में उद्योग से संतुलन की सामूहिक या 'समूह-संतुलन' भी कहते हैं। इस समूह में प्रत्येक उत्पादक एकाधिकारी है (जहाँ तक उसकी वस्तु का सम्बन्ध है), साथ ही साथ उसे भीमत् प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। 'समूह-संतुलन' की स्थिति का वर्णन अत्यन्त ही कठिन है। वस्तुओं में विभिन्नता कीमतों तथा उत्पादन-लागतों में विभिन्नता, केन्द्रों की भाँति में विभिन्नता आदि कारणों से कठिनाई उपस्थित होती है। फिर भी हम 'उद्योग-संतुलन' की कल्पना कर सकते हैं।

उद्योग की संतुलन स्थिति वह स्थिति है, जिसमें फर्मों की सहाय में परिवर्तन न हो तथा फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा हो। पूर्ण-स्पर्धा की भाँति एकाधिकारिक स्पर्धा की स्थिति में भी उद्योग संतुलन की स्थिति में उस समय होगा जबकि (i) फर्मों की सहाय निश्चित होगी, (ii) कीमत औसत उत्पादन लागत के बराबर होगी, तथा (iii) फर्मों को लेबल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। परन्तु अन्य बातों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे :

(1) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत, दीर्घकाल में, प्रत्येक फर्म अनुकूलतम आकार की होगी तथा कीमत न्यूनतम उत्पादन लागत के बराबर होगी। परन्तु एकाधिकारिक स्पर्धा के अन्तर्गत प्रत्येक फर्म न्यूनतम उत्पादन लागत-बिन्दु पर पहुँचने के पूर्व ही संतुलन की स्थिति में होगी। उद्योग की संतुलन स्थिति में कीमत औसत उत्पादन-व्यय के बराबर होगी, परन्तु औसत उत्पादन व्यय न्यूनतम नहीं होगा।

(2) नेताओं के लिए पूर्ण स्पर्धा की स्थिति लाभदायक है, क्योंकि उन्हें न्यूनतम उत्पादन लागत के बराबर कीमत देनी पड़ती है। एकाधिकारिक स्पर्धा के अन्तर्गत न्यूनतम लागत का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत फर्मों को विक्रय-सामर्थ्यी व्यय (Selling cost) वहन नहीं करना पड़ता है। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत 'विक्रय-व्यय' बहुत अधिक होता है, जो उपभोक्ताओं से ही ऊँची कीमत के रूप में वसूल किया जाता है। अतः कीमत, पूर्ण स्पर्धा की अपेक्षा सामान्यतया अधिक होती है।

## 7. विक्रय-लागत (Selling Costs):

विनय-लागत उन समस्त व्ययों को कहते हैं जो खेनाओं को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जिससे क्रेता अन्य फर्मों की वस्तुओं को न खरीद कर, फर्म-विशेष की ही वस्तुओं को खरीद सके। विज्ञापन, प्रचार, विक्रय कला आदि पर किए गए व्यय इस श्रेणी में आते हैं। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन लागतों से उपभोक्ता की मांग प्रभावित होती है तथा विक्रेता की औसत आय में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी अधिक मूल्य देना पड़ता है। पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत सभी पक्षों को बाजार की दशाओं का ज्ञान रहता है अतः विक्रय-व्ययों की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(1) विक्रय व्यय का अभाव विज्ञापन तथा समुचित प्रचार द्वारा, फर्म की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, अतः उत्पादन में वृद्धि की जाती है। यदि वस्तु का उत्पादन 'अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि नियम' के अनुसार हो रहा हो तो उत्पादन लागत कम पड़ती है अतः वस्तु की कम कीमत निर्धारित की जाती है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ हाता है। परन्तु आजकल स्पर्धा अधिक होने के कारण विज्ञापन आदि पर इतना अधिक धन व्यय किया जाता है कि उत्पादन लागत में जो कमी होती है उससे अधिक विनय-व्यय में वृद्धि होती है, अतः सामान्यतः इन व्ययों के कारण कीमतें ऊँची उठती हैं।

प्रचार का विक्री की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि कीमत में परिवर्तन किसे प्रभावित करेगा, विक्रय की मात्रा में वृद्धि की जाए (प्रचार द्वारा)। चूंकि विक्री, कीमत तथा प्रचार का परिणाम है, अतः उक्त विधि द्वारा 'विनय व्यय' के प्रभाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 1 कमी कभी उपभोक्ता के विशिष्ट अधिमानों के कारण विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः विज्ञापन व्यय व्यर्थ जाता है। 2 जब एक फर्म विज्ञापन करती है तो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्में भी विज्ञापन करती हैं अतः किसी फर्म विशेष की विक्री पर विज्ञापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 ऐसा होते हुए भी विक्री की वर्तमान मात्रा बनाए रखने के लिए विज्ञापन करना आवश्यक होता है। 4 यदि विज्ञापन द्वारा खराब किस्म की वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता है तो यह सामाजिक दृष्टि में अव्याप्तनीय है। 5. विज्ञापन के कारण स्पर्धा में और वृद्धि होती है, परन्तु कभी-कभी इससे एकाधिकारिक प्रवृत्ति को बल मिलता है, क्योंकि छोटी फर्में विज्ञापन व्यय को बड़े पैमाने पर वहन नहीं कर पाती तथा उन्हें उद्योग छोड़ना पड़ता है।

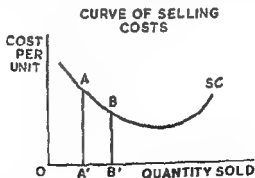
(2) विक्रय व्यय तथा मूल्य सिद्धान्त 'विक्रय लागत' के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त को प्रभावित किया है। इन व्ययों के कारण मांग के स्वरूप में परिवर्तन हो



जाता है, दूसरी ओर पूर्ति का स्वरूप भी प्रभावित होता है, क्योंकि इन व्ययों का प्रभाव कुल उत्पादन-लागतों पर पड़ता है। मूल्य-निर्धारण के पुराने सिद्धान्तों में विक्रय-व्ययों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परन्तु आधुनिक युग में इन व्ययों का महत्व बढ़ गया है, अतः मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त भी व्याख्या करते समय इन पर भी ध्यान दिया जाता है। चैम्बरलिन न, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण-सिद्धान्त का विश्लेषण करते समय विक्रय-व्ययों को भी ध्यान में रखता है। अतः उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्य-निर्धारण-सिद्धान्त अधिक उपयुक्त तथा तर्क-संगत है।

विक्रय-व्यय (Selling Costs) के अन्तर्गत विज्ञापन व्यय के अतिरिक्त सेल्समेन पर किया गया व्यय, फुटकर-बिजनेसों द्वारा प्रदर्शन आदि के लिए किया गया व्यय तथा विक्री बढ़ाने के लिए, किए गए सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन खाने के लिए, किए गए सभी प्रकार के व्यय विक्रय-लागत माने जाते हैं (The Costs of Changing consumers wants are Selling costs) 'Selling Costs' के स्थान पर 'Advertising expenditures' शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि चैम्बरलिन ने किया है।

हम यह मानकर चलेंगे कि कीमत, वस्तु का गुण तथा केनाओं की प्राप समान रहने पर, विज्ञापन से विक्री में वृद्धि होती है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि विज्ञापन व्यय तथा फर्म के विक्री में क्या सम्बन्ध है? इनके सम्बन्धों को 'विक्रय लागत वक्रों' द्वारा जाना जा सकता है। चित्र सं० 109 में विक्रय लागत



चित्र सं० 109

वक्र प्रदर्शित किया गया है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रय-लागत वक्र (SC) अन्य लागत वक्रों की ही तरह U की तरह होता है, परन्तु विक्रय-लागत

धन का अर्थ मित्र होना है। यह वक्र किसी वस्तु की दी हुई मात्रा के बेचने पर प्रति इकाई विक्रय-व्यय को प्रदर्शित करती है। चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की  $AO'$  मात्रा बेचने पर प्रति इकाई  $AA'$  विक्रय लागत है। इसी प्रकार  $OB'$  मात्रा बेचने पर यह लागत प्रति इकाई  $BB'$  है। प्रारम्भ में विक्रय लागत वक्र नीचे गिरता है जो पैमाने की मितव्ययिताओं का परिणाम है। परन्तु बाद में यह वक्र ऊपर उठता है जो यह बतलाता है कि बिना की मात्रा में अधिक विस्तार होने पर, विक्रय लागतों में अधिक वृद्धि होती है। अतः यह वक्र एक खड़ी रत्ता (Vertical) के रूप में हो जाना है, जो यह बतलाता है कि विक्री चरम सीमा (Saturation) पर पहुँच गई है तथा विक्रय व्यय में वृद्धि करने पर भी, विक्रय मात्रा पूर्ववत् रहेगी।

एक फर्म के विक्रय व्यय वक्र का स्वरूप तथा स्थिति यह बतलाता है कि, दिए हुए समय में अन्य बातों का नया प्रभाव पड़ता है? अर्थात् हमें द्वारा विचारणीय वस्तु तथा उस वस्तु की स्थापनापत्र वस्तुओं (Substitutes) की कीमतों तथा गुण, ज्ञेयता की आय, तथा नेताओं का नियंत्रण के प्रति प्रतिक्रिया पर प्रकाश पड़ता है। इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन होने से, विक्रय लागत वक्र का आकार तथा स्थिति बदल जाता है। कीमत ऊँची होने पर यह वक्र ऊपर उठता है जिसका अर्थ यह है कि वस्तु की किसी भी प्रतिरिक्त मात्रा को बेचने के लिए विक्रय-व्यय अधिक करना पड़ता है। यदि वस्तु का किस्म (Quality) में सुधार किए जाएँ तो यह वक्र नीचे गिरता है।

चैम्बरलिन, बोल्डिंग आदि अर्थशास्त्रियों ने विक्रय व्यय, माग तथा पूति के सम्बन्धों की व्याख्या करने का प्रयास किया है, परन्तु वे किसी निष्कर्षपरिणाम पर नहीं पहुँच सका हैं। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा ने अन्तर्गत कीमत उत्पादन-व्यय तथा विक्रय व्ययों के सम्मिलित योग द्वारा निर्धारित की जाती है। माग पूर्ण तथा विक्रय व्ययों के पारस्परिक सम्बन्धों का दयाचित्र द्वारा सही प्रदर्शन लगभग असम्भव है।

### ■ अल्प विक्रेताधिकार या अल्पाधिकार (Oligopoly)

एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की ही भाँति अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। जब केवल दो फर्मों ही उत्पादन करती हैं तथा वे किसी प्रमाणित वस्तु (Standard Product) का उत्पादन करती हैं तो ऐसी स्थिति को शुद्ध द्वयाधिकार (Pure Duopoly) कहते हैं। 'अशुद्ध द्वयाधिकार' (Impure Duopoly) उस स्थिति को कहते हैं जबकि दो फर्मों एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं, परन्तु कुछ सीमा तक वे वस्तु विभेद (Product Differentiation) अपनाती हैं अर्थात् उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ एक ही प्रकार की नहीं होती हैं।

(1) परिभाषा अल्पाधिकार, उन स्थिति को कहते हैं जब फर्मों की संख्या दो से अधिक होती है (परन्तु बहुत अधिक फर्म नहीं होती हैं) अल्प विक्रेताधिकार की दो स्थितियाँ हो सकती हैं—(i) जबकि विभिन्न अल्प-विक्रेताधिकारी एक ही वस्तुएँ बनाते हैं। इसे वस्तु-समता रहित अल्प-विक्रेताधिकार (Oligopoly without product differentiation) कह सकते हैं तथा (ii) जबकि फर्मों की वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है, परन्तु वे वस्तुएँ एक-दूसरे की निकट की स्थानापन्न वस्तुएँ होती हैं। (Oligopoly with product differentiation, where commodities are close substitutes, but not perfect substitutes) किसी भी एक उत्पादक के उत्पादन तथा मूल्य नीति का प्रभाव अन्य उत्पादकों पर निश्चित रूप से पड़ता है।

उपरोक्त दो प्रकार के अल्प-विक्रेताधिकार की अवस्थाओं को दूसरे नामों से भी पुकारते हैं जैसे

(i) Homogenous Oligopoly जिसके अन्तर्गत वस्तु प्रमाणित (standardized) होती है। इस्पात और सीमेंट उद्योग इस अवस्था के प्रतीक हो सकते हैं। केना इस दिशा में हम बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उत्पादक कौन हैं, वे मूल्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वस्तु लगभग एक समान होती है। इस अवस्था को पूर्ण अल्पविक्रेताधिकार (Perfect oligopoly) भी कहा जाता है।

(ii) Differentiated Oligopoly : यह अवस्था कई उद्योगों में पाई जाती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, यमस, सिलाई की मशीन, मोटर कार आदि उद्योग। इस अवस्था में वस्तु का रूप प्रकार आदि में विभिन्नता पाई जाती है। विज्ञापन, कुशल विक्रय-कला ट्रेड मार्क आदि द्वारा भी एक फर्म की वस्तु दूसरे से भिन्न प्रतीत होती है। इसे अपूर्ण अल्प-विक्रेताधिकार (Imperfect oligopoly) भी कहते हैं।

## 2 अल्पविक्रेताधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण

अल्पविक्रेताधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसके में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। इसके अन्तर्गत कीमत निर्धारण की समस्या बड़ी जटिल है। कीमत तथा उत्पादन अन्य प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया (Reaction) पर निर्भर करती है। प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना अत्यन्त ही कठिन है अतः अल्पाधिकार के अन्तर्गत फर्मों की सन्तुलन स्थिति तथा मूल्य-निर्धारण का अध्ययन एक जटिल समस्या है। मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

(1) अल्प विक्रेताधिकार के अन्तर्गत विक्रेता एक-दूसरे की नीतियों से प्रभावित होते हैं। अल्प विक्रेताधिकारी का मांग वक्र केवल कीमत पर ही नहीं निर्भर

करता है, बल्कि अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों की विन्य-नीति से भी प्रभावित होता है। क्या फर्म A द्वारा कीमत वर देने पर फर्म B भी अपनी वस्तु की कीमत घटा देगी? या फर्म B अपनी ख्याति या वस्तु विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए कीमत नहीं घटाएगी। क्या यदि B फर्म कीमत घटा देती है तो फर्म A अपनी वस्तु की कीमत पुनः घटा देगी? अल्पविक्रेताधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण के उठने ही तरीके हैं, जिनका कि कोई व्यक्ति मान्यताएं मान सकता है तथा वहन भी मान्यताएं, विशेषतः वे जो वास्तविकता के निकट होती हैं, कीमत अनिश्चित भी रहेंगे।

जैसा कि कहा जा चुका है, अल्पविक्रेताधिकार दो प्रकार का होता है।

(1) पूर्ण अल्पविक्रेताधिकार जिसमें वस्तुओं में एकत्वता होती है तथा यदि एक फर्म कीमत घटानी है तो दूसरी प्रतिस्पर्धी फर्म कीमत अवश्य घटाएगी। (ii) अपूर्ण अल्पविक्रेताधिकार जिसमें अनेक वस्तु विभिन्नता पाई जाती है तथा एक फर्म द्वारा कीमत घटाने पर यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी फर्म भी तुरन्त कीमत घटा दे।

**पूर्ण अल्पविक्रेताधिकार (Perfect oligopoly)**

इस अवस्था में एक फर्म का विन्य वर, पूर्ण सावधान नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म द्वारा कीमत में परिवर्तन करने में, दूसरी फर्म भी कीमत में परिवर्तन कर देती है। अतः फर्म की विन्य नीति शून्य होगी न ही और न अयोग्य। यदि फर्म A कीमत घटाती है तो B, C अन्य फर्म भी कीमत घटा देंगी। कीमत कम होने पर कुल विन्य में वृद्धि होगी तथा प्रत्येक फर्म की विन्य कुर विक्री बढ़ाने के कारण बढ़ेगी। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा कीमत में वृद्धि करने पर अन्य फर्म भी कीमतें बढ़ाएंगी। परन्तु सामान्यतया एक फर्म द्वारा कीमत घटाने पर अन्य फर्म कीमतें तुरन्त घटा देती हैं, परन्तु एक फर्म द्वारा कीमत बढ़ाने पर अन्य फर्म तुरन्त कीमतें नहीं बढ़ाती हैं। अतः विन्य वर वर्तमान मूल्य से ऊंचे मूल्य पर अधिक लोचदार होगा, तथा वर्तमान मूल्य में कम मूल्य पर कम लोचदार। ऐसे माद वर को Kinked demand curve कहा जाता है।

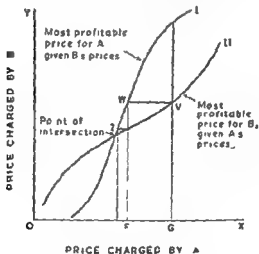
फर्म की साम्य अवस्था इस बात पर निर्भर करेगी कि हम प्रतिस्पर्धी फर्मों द्वारा मूल्य परिवर्तन होने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया (Reaction) की अपेक्षा रखते हैं? विक्रेता मिलकर (Collective) निर्णय ले सकते हैं तथा वे एकाधिकारी की भांति व्यवहार कर सकते हैं। इनका परिणाम यह हो सकता है कि कुल उत्पादन तथा कीमतें इस प्रकार की हो सकती हैं जिसमें कुल-लाभ (Aggregate Profit) अधिकतम हो। एनी दशा में, प्रत्येक फर्म की कीमत औसत लागत से अधिक होगी।

इसके विपरीत, फर्मों में नोत्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है तथा कीमत मूल्यम हो सकती है। इस दशा में कीमत औसत लागत के बराबर होगी। फर्म वस्तु-विभेद का सहारा लेकर (ब्रैंड या विज्ञापन आदि द्वारा) तथा उपभोक्ताओं को भ्रमनात सम्बन्धी

सुविधायेँ देखर बिन्दी बढाने का प्रयत्न करेगी। फर्मे कीमत कम करने की प्रेरणा इन तरीकों की प्राथिक अपनाती है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्ण अर्थ बिनेना-पिनार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण के सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है। उन्मादको के बीच प्रतिस्पर्धा या सहयोग के सम्बन्ध में हम कई प्रकार की मान्यताओं के आधार पर कीमत निर्धारण के विषय में विभिन्न कल्पनाएँ कर सकते हैं। जितनी ही मान्यताएँ (Assumptions) होंगी, उतने ही प्रकार से कीमत निर्धारित होगी। इस प्रकार कीमत निर्धारण के विषय में निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है। इसका प्रवरन कहा जा सकता है कि पूर्ण अर्थ बिनेनापिनार के अन्तर्गत कीमत एनापिनार-कीमत तथा पूर्णस्पर्धा कीमत के बीच में होंगी।

अपूर्ण अर्थ बिनेनापिनार (Imperfect Oligopoly) -

यदि अस्तु-बिनेद दो बिबि है तो यह आवश्यक नहीं है कि एक फर्मे द्वारा कीमत कम करने पर, अन्य फर्मे भी तुरन्त कीमत घटा देंगी। फर्मे इस मान्यता पर निर्णय न सकती है कि अन्य फर्मे तुरन्त बदला नहीं देंगी (will not retaliate)। ऐसी दशा में प्रतिबिबिनता उनी रहती। फर्मे A कीमत कम देती है क्योंकि उसकी सीमांत आय (MR), न मान लागन (MC) न अधिक है। ऐसा करना उनी समय



चित्र न० 110

उचित होगा, यदि फर्मे B कीमत न घटाए। हम मान लेते हैं कि फर्मे B की अस्तु निम्न है तथा वह तुरन्त कीमत कम नहीं करती है। परन्तु बाद में फर्मे B फर्मे A से भी प्राथिक कीमत कम कर सकती है B की कम कीमत, A को कीमत पुन घटाने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी विचार्य तथा प्रतिविचार्य चलती रहती हैं।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण : चित्र न० 110 में उपर्युक्त बात को स्पष्ट

निया गया है। यदि I वक्र में बिन्दु U में OX पर एक लम्ब डाला जाए तो OG, फर्म A के लिए अधिक लाभदायक (most profitable) कीमत होगी, जबकि फर्म II की कीमत VG है। (I वक्र पर जहाँ से लम्ब डाला गया है, वहाँ बिन्दु U मानिए)। परन्तु यदि फर्म A की कीमत OG है तो फर्म B के लिए VG कीमत उपयुक्त होगी जो वक्र II द्वारा दिखाई गई है। यदि फर्म B अब VG कीमत निश्चित कर, जो WF के बराबर है तो वक्र I से स्पष्ट है कि फर्म A के लिए अधिक लाभ सम्बन्धी कीमत OF होगी। यदि कीमत का घटना (Price Cutting) जारी रहता है तो अन्त में हम बिन्दु Z पर पहुँचेंगे। इस परेशान कीमत घटाना किसी भी फर्म के लिए लाभदायक मिश्र नहीं होगा।

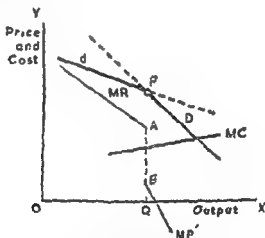
यह अवस्था स्थायी (Stable) है या नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि दोनों फर्म कम से कम सामान्य लाभ अर्जित कर रहें ह या नहीं? यदि ऐसा नहीं है तो एक फर्म उद्योग छोड़ देगी तथा अल्प विक्रेताधिकार के स्थान पर एकाधिकार (Monopoly) की दशा हा जाएगी। फर्म आपस में गमभीरता द्वारा कीमतें बढ़ा सकती हैं परन्तु यह अवस्था भी एकाधिकार की अवस्था होगी। वे अपनी वस्तुओं में धीरे अधिक विभेद के लिए भा कदम उठा सकती हैं। इसका विागन यदि साम्य बिन्दु पर दोनों असामान्य लाभ (Abnormal Profit) अर्जित कर रही हैं तो अन्य फर्मों में प्रवेश द्वारा, इस साम्य-कीमत में परिवर्तन होगा।

ii) Kinky or Kinked Demand Curve : अल्पविक्रेताधिकार के अन्तर्गत माग रेखा की प्रकृति (Shape) या लोच के सम्बन्ध में सामान्य-नस्बों का उल्लेख करना कठिन है। परस्पर प्रतिस्पर्धी फर्मों की कीमत-नीति एक दूसरे से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः कीमत की इस अन्तर्निर्भरता (Interdependence) के कारण एक सामान्य माग रेखा बनाना कठिन होता है। अर्थशास्त्रियों ने इस अन्तर्निर्भरता का विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किया है। फर्मों की माग वक्र दूसरी प्रतिस्पर्धी फर्मों से प्रभावित होती है। Homogenous oligopoly की दशा में, Differentiated oligopoly के अंशक फर्मों की माग एक दूसरे से अधिक प्रभावित होती है। सन् 1930-40 की अवधि में अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पविक्रेताधिकारी माग कोनेदार (Kinked) होती है, यद्यपि यह विषय अत्यन्त ही विवादग्रस्त है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि एक फर्म मूल्य में वृद्धि करती है तो अन्य फर्म भी अपनी वस्तुओं के मूल्य घटा देंगी, परन्तु यदि एक फर्म मूल्य में वृद्धि करती है तो अन्य फर्म मूल्य में वृद्धि नहीं करेंगी। इस प्रकार अलाधिकारियों को मूल्य परिवर्तन से लाभ नहीं होता है, अतः वे एक ही कीमत पर टिके रहने हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अलाधिकार के अन्तर्गत, वस्तु के माग वक्र में एक कोना (Kink or

corner) होता है जो वर्तमान मूल्य में सम्बन्धित होता है। उसी बिन्दु पर कीमतें स्थिर रहती हैं, न घटती हैं न बढ़ती हैं। अतः उत्पादितार के अन्तर्गत कीमतों में स्थिरता होती है। उत्पादन लागत में परिवर्तन भी उत्पादितार के उत्पादन तथा मूल्य को बहुत कम प्रभावित करत है। जैसे यदि मजदूरी की दरें कम हो जाती हैं तो उत्पादन लागत कम होगी, परन्तु फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं करेंगी, क्योंकि वे अपने प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा सकती हैं। इस प्रकार मांग तथा लागत में परिवर्तन हा मरुत हैं, परन्तु उनका प्रभाव मूल्य पर नहीं पड़ेगा (या बहुत कम पड़ेगा) अतः अर्थव्यवस्था में मूल्यों को अपरिवर्तनीयता के लिए बहुत कुछ अनी में उत्पादितारी उत्तरदायी हैं।

बानेदार मांग वर इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादितारों की फर्मों में मांग यन्त्रा न तो कीमत बढ़ाती हैं और न घटाती हैं। यदि कोई फर्म कीमत घटानी चाता अरु फर्मों भी कीमत घटाएगा। अतः कीमत कम करने में फर्म को लाभ नहीं होगा। कीमत घटाने से बिक्री और भी कम होगी। अतः कीमत में परिवर्तन उस समय तक नहीं किया जाता है जब तक कि मांग या लागत की दशाओं में अत्यधिक परिवर्तन या अमूल्य परिवर्तन न होना हो।



चित्र १०१११

चित्र मरुता १११ में 'कनेदार मांग' को प्रदर्शित किया गया है। मांग का कोना (Kink) बिन्दु P पर है। इस बिन्दु पर फर्म OQ मात्रा का उत्पादन व विक्रय कर रही है। P बिन्दु से ऊँची कीमत पर, कम यह मूल्यना करती है कि उसका मांग वर PP की नाति होगा। P बिन्दु की बाईं ओर मांग वर बहुत तीव्रता है।

क्योंकि फर्म यह मानती है कि यदि वह कीमत को बढ़ावे तो उसके प्रति-स्पर्धी कीमत नहीं बढ़ाएंगे जिससे बिक्री कम होगी।  $dP$  मांग रेखा में सम्बन्धित, सीमांत आगम (MR) घना-मव (Positive) है। PD उमी मांग रेखा का दूसरा भाग है। PD भाग कम लोचदार है। कम कीमत पर PD वक्र बेलाच है जैसा कि MR सीमांत आगम वक्र से प्रकट है, एक बिन्दु के पश्चात् सीमांत आगम ऋणात्मक (Negative) हो गया है। इसका अर्थ यह है कि फर्म यह सोचती है कि यदि उसने कीमत में P में कमी की तो अन्य फर्म भी अपनी कीमतें घटा देंगी।

P बिन्दु से ऊँची कीमत पर मांग-वक्र लोचदार है तथा इस बिन्दु से कम कीमत पर कम लोचदार है, इसका परिणाम यह होता है कि सीमांत आगम वक्र में Break आ जाता है। इस Break या Gap का कारण यह है कि मांग वक्र में P बिन्दु के बाद अचानक परिवर्तन आ जाता है। इस गैप को AB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सीमांत लागत वक्र (MC), इस गैप से गुजरती है।

Kinked Demand यह प्रकट करती है कि कीमतें स्थिर (Sticky) रहेगी। कोनेदार मांग वक्र के सम्बन्ध में यह स्पष्ट रहता कि चाहिए यह पूरातया काल्पनिक होती है, जो प्रत्यक्ष के बिचार में कीमत-परिवर्तन के सम्भावित परिणामों को प्रकट करती है। उसका वास्तविक मांग वक्र भिन्न हो सकता है। (The kinked demand curve is often called subjective—it exists in the decision maker's mind. His actual demand curve, the objective one, might be different) (WATSON)

कीमत की स्थिरता (Rigidity) की कल्पना लागत के कारण होती है। यदि सीमांत लागत बढ़ती है (परन्तु बिन्दु A से ऊपर नहीं) या घटती है, उत्पादन मात्रा तथा कीमत परिवर्तित नहीं होती। क्योंकि MC अब भी MR के लंबे हिस्से (Vertical Part) को पार कर रही है।

इस प्रकार कोनेदार मांग, कीमत-स्थिरता के कारणों पर प्रकाश डालती है। परन्तु यह स्थिर-कीमत (Rigid Price) किस प्रकार निश्चित की जाती है, इसके सम्बन्ध में कोनेदार मांग प्रकाश नहीं डालती। साथ ही साथ इसके द्वारा इस बात पर भी प्रकाश नहीं पड़ता कि नई कीमत पर नया कोना कैसे बनता है। (The model has a serious flaw. There is nothing in the model to show how the rigid price is established. Nor does the model explain how a new kink forms around a new price." watson)

(iii) कीमत पर नेतृत्व (Price Leadership) कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि उत्पादिकार के अन्तर्गत कोई एक फर्म अनुग्राहक के रूप में कार्य करती है तथा



उस फर्म द्वारा जो कीमत निश्चित करदी जाती है, अन्य फर्में उसी का अनुकरण करती हैं। सामान्यतः वही फर्म धनुषा के रूप में कार्य करती है जिनकी उत्पादन लागत अन्य सभी फर्मों से कम है, तथा जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों से स्पर्धा में विजय प्राप्त कर ली है।

(iv) पूर्व निश्चित मूल्य (Mark-up pricing) : कुछ अल्पाधिकारी कीमत निर्धारण औसत उत्पादन लागत के आधार पर करते हैं। उत्पादक लागत में कुछ प्रतिशत लाभ को सम्मिलित करके एक कीमत निश्चित करते हैं, तथा वे उसी ही मात्रा का उत्पादन करते हैं, जितनी मात्रा को इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर बेचा जा सकता है।

(v) Collusion कीमत निर्धारण की एक विधि यह भी हो सकती है कि प्रतिस्पर्धी फर्म आपस में समझौता कर लें तथा कुल मांग को आपस में बांट लें।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अल्पाधिकार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। अल्पाधिकारी की सन्तुलन स्थिति की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया का ज्ञान हो परन्तु ऐसी जानकारी प्राप्त करना असम्भव ही है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर, अल्पाधिकार के अन्तर्गत उत्पादन तथा मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त का निर्माण करने का प्रयत्न किया है। मान्यताओं (Assumptions) में विभिन्नता के कारण वे किसी एक नियम पर नहीं पहुँच सके हैं। अल्पाधिकार के अन्तर्गत मूल्य के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि विक्रेता का अपेक्षाकृत बाजार पर अधिक प्रभिकार रहता है। अतः वह पूर्ण-स्पर्धा तथा एकाधिकारिक स्पर्धा की अपेक्षा अधिक ऊँची कीमत नहीं प्राप्त कर सकता है। परन्तु कुछ प्रतिस्पर्धियों की उपस्थिति के कारण वह उतनी अधिक कीमत नहीं प्राप्त कर सकता है, जितनी कि एकाधिकारी प्राप्त कर सकता है। फर्मों के प्रवेश का मय कम होने के कारण कीमत उत्पादन लागत से अधिक होती है।

निष्कर्ष : यद्यपि हमने अपूर्ण-स्पर्धा (Imperfect Competition) की कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण विधि का अध्ययन किया। एकाधिकार, एकाधिकारिक-स्पर्धा, अल्पाधिकार आदि सभी अपूर्ण स्पर्धा का ही स्थितिमा है। एकाधिकार अपूर्ण स्पर्धा की चरम सीमा है। पूर्णस्पर्धा तथा एकाधिकार के बीच विभिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं।<sup>4</sup> उन सभी स्थितियों को 'अपूर्ण-प्रतिस्पर्धा' की संज्ञा दी जा सकती है।

<sup>4</sup> "There is no single case of imperfect competition, but a whole range or series of cases representing progressively more and more imperfect competition"  
Stonier and Hague

अतः शुद्ध एकाधिकार तथा पूर्ण-प्रतिस्पर्धा की भांति हम हम, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत एक निश्चित मूल्य-सिद्धान्त की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की विभिन्न स्थितियों में, मूल्य निर्धारण के अलग अलग सिद्धान्त हैं, जिनमें से कुछ एक परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण की विधि का अध्ययन हमने गत पृष्ठों में प्रस्तुत किया है। अपूर्ण-स्पर्धा के अन्तर्गत मूल्य के सम्बन्ध में हम केवल कुछ सामान्य निष्कर्षों की ही बात कर सकते हैं, जैसे :

(1) अपूर्ण-स्पर्धा के अन्तर्गत एक ही वस्तु के विभिन्न मूल्य होते हैं। मूल्यों में यह विभिन्नता मांग तथा क्रान्ति के अनुसार होती है। यह स्थिति केताओं की अन्तर्निष्ठा के कारण हो सकती है।

(2) मूल्य में विभिन्नता विदेशों की सदा कम होने के कारण होती है। विदेशों का बाजार पर अधिक अधिकार रहता है। वह पूर्ति को मात्रा को नियंत्रण कर, मूल्य ऊँचा रख सकता है।

(3) वस्तु विभेद के कारण भी मूल्य ऊँचा होता है।

(4) औसत माय वक्र (AR) मंदी नीचे गिरता हुआ होता है, परन्तु विभिन्न प्रकार की अपूर्ण स्पर्धाओं में औसत माय वक्र के नीचे गिरने की गति में विभिन्नता पाई जाती है।

### 3 सम्बन्धित मूल्य (Related Values)

कुछ वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति में अन्तर्मुख्य होता है। व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं कि कई उत्पादन-स्थान एक दूसरे में सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता भी एक एक साथ कई ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं, जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग संयुक्त होती है। उपभोक्ता की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कई वस्तुओं द्वारा की जा सकती है। अतः एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसी प्रकार की अन्य किसी दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धी वस्तुओं (जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति करती हैं) के मूल्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की वस्तुओं की मूल्य-निर्धारण-विधि का अध्ययन किया जाय।

#### 1 संयुक्त माग (Joint Demand)

जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की मांग की जाती है, (पूरक वस्तुओं की) तब ऐसी मांग को संयुक्त माग कहते हैं, जैसे कार के साथ पेट्रोल, चाय के साथ चीनी तथा कलम के साथ स्याही की मांग होती है। ऐसी वस्तुओं को पूरक वस्तुएँ (complementary goods) कहते हैं। पूरक वस्तुओं की कीमतें

परस्पर विरोधी होती है। यदि एक वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है। उदाहरणार्थ, यदि कलम की कीमत कम हो जाए तो उसकी बिक्री बढ़ जायेगी, परिणामस्वरूप स्याही की अधिक मांग होगी तथा स्याही की कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार एक दूसरे की पूरक वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन दो बातों पर निर्भर करते हैं—(i) प्रथम वस्तु (मान लीजिए कलम) की मांग की लोच तथा द्वितीय वस्तु (स्याही) की पूर्ति की लोच तथा (ii) दो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की खरीद के अनुपात में किस सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है ?

इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई का प्रमुख कारण यह है कि (i) उनकी मांग मूल्य एक दूसरे से सम्बन्धित होती है। यदि स्याही की पूर्ति होनी कठिन है तो इससे कलम की मांग प्रभावित होगी, (ii) दूसरी प्रमुख कठिनाई है पूरक वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना। हम यह जानते हैं कि कोई भी नतीजा किसी खरीदी जाने वाली वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देता कि। इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत=उत्पादन लागत=सीमान्त उपयोगिता। पूरक वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की जानकारी के बिना मूल्य निर्धारण कठिन होगा। सामान्यतया पूरक वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता ज्ञात करने के लिए (नम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है

(क) यदि दो वस्तुएँ एक दूसरे की पूरक हैं तो उनमें से एक वस्तु की मात्रा को स्थिर रखकर दूसरी की मात्रा में कुछ वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार कुल-उपयोगिता में जितनी वृद्धि होगी वही उस वस्तु (जिस वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाएगी) की सीमान्त उपयोगिता होगी।

(ख) दूसरी विधि के अनुसार मान लीजिए कलम तथा स्याही दो पूरक वस्तुएँ हैं। यदि कलम की मात्रा में कुछ वृद्धि कर दी जाए तथा आवश्यक मात्रा में स्याही का भी उपयोग बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार उपयोगिता में जो वृद्धि होगी यदि उसमें से स्याही की बढ़ी हुई मात्रा का मूल्य घटा दिया जाय तो जो शेष बचेगा वह कलम की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक माप होगा। इसी सीमांत उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाएगा।

उत्पादन साधनों की संयुक्त मांग उपरोक्त विधियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करना कठिन है, क्योंकि उपयोगिता की मांग करना कठिन है। (इस कठिनाई को उदासीनता वक्रों की गह्रायता से दूर कर सकते हैं।) संयुक्त मांग का महत्व उत्पादन साधनों का मांग की अवस्था में अत्यधिक है। उत्पादन साधनों की मांग पर विचार करते समय हम सीमांत उपयोगिता के स्थान पर साधनों की सीमांत उत्पादन (Marginal Productivity) पर विचार करते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन

करने के लिए उत्पादन के कई साधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक साधन की माग अन्य साधनों की माग से सम्बन्धित होती है। साथ ही साथ यह भी स्मरणीय है कि उत्पादन साधनों की माग 'व्युत्पादित माग' (Derived Demand) होती है, क्योंकि उत्पादन साधनों की माग उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाती है। अतः साधनों की कीमत उन उपभोग-वस्तुओं पर निर्भर है, जिनका उत्पादन उनके द्वारा किया जाता है। मार्शल ने 'मकान निर्माण' का उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा यह कहा है कि मकान के निर्माण के लिए काँगीर, बड़ई इ. जीनियर, तथा अकुशल श्रमिकों आदि की सेवाओं का भुगतान माग पूर्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर किया जा सकता है। यह सम्भव है कि इनमें से कोई एक साधन बाजार में प्रचलित पारिथमिक से अधिक पारिथमिक की माग करे। मार्शल ने चार शर्तों का उल्लेख किया है जिनमें एक साधन-विशेष को अधिक पारिथमिक दिया जा सकता है।

(i) वह साधन अन्यावश्यक हो तथा स्थानापन्न साधन कम कीमत पर उपलब्ध नहीं हो,

(ii) जिस वस्तु का उत्पादन ऐसे साधनों में करना हो, उसकी माग लोचनीय हो जिससे वस्तु को उसके मूल्य पर बेचा जा सके,

(iii) पैदा की जाने वाली वस्तु की कुल उत्पादन लागत में उस साधन की कीमत का भाग बहुत कम हो, तथा

(iv) उस साधन की माग में थोड़ा भी अवरोध करने पर अन्य साधनों के मूल्य पूर्ति में पर्याप्त कमी हो जाए, जिससे उस साधन का भुगतान के लिए अधिक धनराशि बच सके।

### सयुक्त पूर्ति (Joint Supply)

उन वस्तुओं की पूर्ति को सयुक्त पूर्ति कहते हैं जिनका उत्पादन साथ ही साथ तथा एक ही उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है, जैसे ऊन और मास चावल तथा छिनका, चीनी तथा शीरा आदि। सयुक्त पूर्ति वाली वस्तुओं की कीमतों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यदि एक की कीमत से वृद्धि होता है तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी, अतः दूसरी वस्तु की कीमत कम होगी।

इस प्रकार के सयुक्त उत्पादों (Joint Products) के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या होती है—उनकी अलग-अलग सीमान्त लागत ज्ञात करना, क्योंकि यदि उनकी सीमान्त लागतों को ज्ञात कर लिया जाये तो उनका मूल्य निर्धारण भी सरल हो

जाएगा (प्रत्येक की कीमत उसकी सीमान्त लागत के बराबर होगी) : समुक्त पूर्ति वाली वस्तुओं की अवस्था के अनुसार दो श्रेणियाँ में विभाजित किया जा सकता है—

(i) वह अवस्था जिसमें वस्तुओं की उत्पादन मात्रा का अनुपात निश्चित है (cases where proportion is fixed), तथा (ii) वह अवस्था जिसमें उनकी उत्पादन-मात्रा का अनुपात निश्चित नहीं है (cases where proportions vary) ।

(1) जब अनुपात निश्चित हो कई तथा कपास का बीज इनके उदाहरण हैं। जब विभिन्न उत्पादों के अनुपात निश्चित हो तो उनकी सीमांत लागत पृथक् पृथक् ज्ञात करना सम्भव नहीं है। जैसे कई और कपास के बीज कपास की किसी भी मात्रा में एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हों, अतः कई तथा बीज की अलग-अलग सीमांत लागत ज्ञात नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उनसे प्राप्त कुल आय (TR) उनके कुल उत्पादन व्यय (TC) के बराबर हो। उत्पादक समुक्त उत्पादों में से प्रत्येक की कीमत उनकी मांग की शोच के अनुसार निर्धारित करेगा तथा वह यह प्रयत्न करेगा कि कुल आय कुल लागत से बराबर हो।

(ii) जब उत्पादन मात्रा के अनुपात में परिवर्तन हो सकता हो ऊन तथा गास, चीनी व शिरा इस परिस्थिति के प्रतीक हैं। ऐसी भेदे पाली जा सकती हैं जिनमें या तो अधिक मात्रा प्राप्त हो सकता हो या अधिक ऊन। ऐसी स्थिति में समुक्त उत्पादों की पृथक् पृथक् सीमांत लागत करना सरल है। जैसे, यदि दस रुपये व्यय करने में एक उत्पादन विधि द्वारा 3 किलो चीनी तथा 4 किलो शिरा का उत्पादन होता है। उत्पादन विधि में आवश्यक संपादित कर यदि बारह रुपये व्यय होता है तो 4 किलो चीनी तथा 4 किलो शिरा प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में एक किलो चीनी की मात्रा में लागत का व्यय होगा। इस प्रकार शिरा की भी सीमांत लागत स्वतः ज्ञात हो जाएगा। ऐसी वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित प्रकार निश्चित किया जाएगा

(क) पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत = सीमांत लागत ( $P = MC$ )

(ख) अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत = सीमान्त आय ( $P = MR$ )

उपरोक्त विधि सैद्धांतिक दृष्टि से उद्भूत है। एक ही विधि द्वारा कई वस्तुएँ एक ही साथ पैदा की जाती हैं, अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक की सीमांत लागत ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाता है। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में वे एक वस्तु की तो प्रमुख उत्पाद (Main Product) मानते हैं तथा उसका मूल्य-निर्धारण उचित रूप से करते हैं अन्य वस्तुओं का उप-उत्पाद (By Product) मानकर मांग तथा पूर्ति के अनुसार जो भी मूल्य मिल जाता है उसे लेते हैं। परन्तु यदि 'उप-

उत्पाद' के निर्माण के लिए कोई 'विशेष व्यय' करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक 'उप उत्पाद' को बचने समय कम में कम 'विशेष व्यय' को कीमत के रूप में प्राप्त करना चाहता है ।

### 3. मिश्रित माग (Composit Demand) •

एक वस्तु की माग को मिश्रित-माग' उस समय कहते हैं जबकि उस वस्तु की माग विभिन्न प्रयोगों (different uses) के लिए होती है । ऐसी वस्तु की कुल माग जान करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न उपयोगों से सम्बन्धित मागों का जोड़ दिया जाए । मिश्रित माग वाली वस्तु की माग यदि एक उपयोग के लिए बढ़ जाती है तो अन्य उपयोगों के लिए भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी । मिश्रित माग वाला वस्तु का विभाजन विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार किया जाएगा कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता विभिन्न उपयोगों में समान हो । ऐसी वस्तु की मूल्य निर्धारण निम्न प्रकार है । विभिन्न उपयोगों में सम्बन्धित मागों का योग तथा उस वस्तु की पूर्ति व सन्तुलन द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है ।

### 4 मिश्रित पूर्ति (Composite Supply) ।

उन वस्तुओं की पूर्ति को मिश्रित पूर्ति कहते हैं जिनके द्वारा किसी एक आवश्यकता की सन्तुष्टि होती हो । ऐसी वस्तुएँ एक दूसरे की स्थानापन्न (Substitutes) होती हैं जैसे चाय और काफी । स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में समान दिशा में परिवर्तन होते हैं, अर्थात् एक कीमत कम होती है तो दूसरे की भी कीमत कम हो जाती है । जैसे यदि काफी की कीमत कम हो जाए तो लोग चाय के स्थान पर काफी का प्रयोग करने लगेंगे । इस प्रकार चाय की माग कम होगी तथा उसकी कीमत स्वतः कम हो जाएगी । परन्तु स्थानापन्न वस्तुओं की माग सूची बनाना अत्यन्त ही कठिन है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन चारों परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है । उपरोक्त सभी परिस्थितियों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण माग तथा पूर्ति के सन्तुलन द्वारा निर्धारित होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि माग तथा पूर्ति में परिवर्तनों के प्रभाव तथा प्रति-प्रभाव (effects and counter effects) कुछ जटिल हो जाते हैं तथा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता या उत्पादन-साधन की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करना सम्भव नहीं होता है तो मूल्य निर्धारण का सिद्धांत बतलाना भी सम्भव नहीं होता है ।

## कीमत निर्धारण के परम्परागत सिद्धांत की समीक्षा (Traditional Theory of Price Determination : Its Review)

यह अध्याय हमने पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार तथा अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत कीमत-निर्धारण सिद्धांतों का अध्ययन किया। ये सभी सिद्धान्त सामान्यतया सीमान्तवाद (Marginalism) के अन्तर्गत आते हैं (अल्प विप्रेणाधिकार के अतिरिक्त)। विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत, हमारा अध्ययन इस मान्यता पर आधारित रहा है कि उत्पादक की लागत या लाभ, कीमत निर्धारण पर निर्भर है। कीमत निर्धारण का यह सिद्धान्त माग की दशाओं (Demand Conditions) तथा लागत की दशाओं (Cost Conditions) को पूर्णतया ध्यान में रखता है। माग तथा लागत में परिवर्तन होने पर कीमत में भी परिवर्तन होता है।

परम्परागत कीमत निर्धारण बाजार की शक्तियों तथा लागतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, फर्म की कीमतों में आवश्यक समायोजन पर प्रकाश डालता है। परम्परागत सिद्धान्त, फर्म के प्रबंधक को एक दूरदर्शी, विचार-शील तथा विवेक पूर्ण व्यक्ति मानता है जो परिस्थिति सम्बन्धी परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। प्रो० हेन्स के शब्दों में,

“They (Price theories) picture the manager, not as a simple minded automation who rigidly follows mechanical rules of thumb, but rather as a rational human being who can analyse the implications of changes in conditions”

—IV H' Haynes, Managerial Economics

कीमत के ये सभी सिद्धान्त सीमान्तवाद (Marginalism) पर आधारित हैं।

इन विशेषताओं के होते हुए भी परम्परागत कीमत निर्धारण सिद्धान्त की कुछ सीमाएँ हैं जो फर्म के व्यवहार का विश्लेषण करते समय प्रकट होती हैं, ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

1. लाभ को अधिकतम करना (Profit Maximisation) परम्परागत सिद्धान्त का मूल आधार है। परन्तु व्यावहारिक जगत् में हम जानते हैं कि उत्पादक अन्य तथ्यों से भी प्रभावित होता है। उत्पादक कभी कभी, लाभ में अधिक बिनी को अधिकतम करने की सोच सकता है। कोई उत्पादक व्यक्तिगत शक्ति तथा खर्च बढ़ाने की भी सोच सकता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा अन्य नैतिक भावों से भी उत्पादक प्रभावित हो सकता है। उच्च-कीमत के लिए ‘लाभ’ का त्याग भी किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन केवल ‘अधिकतम लाभ’ से ही प्रभावित नहीं होता है।

2. परम्परागत सिद्धान्त-कीमत परिवर्तन के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावों में स्पष्ट भेद नहीं करता है। यह सिद्धान्त यह नहीं बतलाता है कि वर्तमान कीमतों का भविष्य के लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्पकालीन कीमत से सम्बन्धित चित्र वर्तमान माग वक्र (और सीमान्त आय वक्र) तथा वर्तमान लागत-वक्रों (सीमान्त लागत वक्रों को सम्मिलित कर) को प्रदर्शित करते हैं तथा यह बतलाते हैं कि उत्पादक सीमान्त लागत व सीमान्त आय को बराबर करने का प्रयत्न करता है। परन्तु उत्पादक भविष्य की भाशा में हमेशा ऐसा नहीं भी कर सकता है। भविष्य के लाभ की भाशा में वह वर्तमान लाभ का त्याग भी कर सकता है। परम्परागत कीमत सिद्धान्त इस तथ्य की उपेक्षा करता है।

3 परम्परागत सिद्धान्त सामान्यतया एक वस्तु पैदा करने वाली फर्म (a single product firm) की मान्यता पर आधारित है, परन्तु व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं कि एक फर्म कई वस्तुओं (Product Mix) का उत्पादन करती है, यह तथ्य कीमत निर्धारण को बहुत कुछ अंश में प्रभावित करता है, परन्तु परम्परागत कीमत सिद्धान्त इस तथ्य की भी उपेक्षा करता है।

4. यह सिद्धान्त अनिश्चितता की समस्या (Problem of uncertainty) की भी उपेक्षा करता है। यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादक लागतों तथा माग के विषय में पूर्ण जानकारी रखता है। परन्तु वास्तविक जगत में यह मान्यता निराधार सिद्ध होती है।

इन सीमाओं के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि परम्परागत कीमत-सिद्धान्त, कीमत निर्धारण के लिए नैदान्तिक आधार प्रस्तुत करता है तथा व्यावहारिक रूप से मूल्य निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है।

### प्रश्न व संकेत

1. पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच अन्तर बताइए। अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होता है। चित्रों की सहायता से पूर्णतया समझाइए।  
(जोधपुर, द्वितीय वर्ष, वाणिज्य, 1963)

(संकेत—पहले दोनों का अन्तर बतलाइए, फिर यह स्पष्ट कीजिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता की कई अवस्थाएँ होती हैं, उन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था की प्रतिनिधि अवस्था मानकर (एकाधिकृत प्रतियोगिता) मूल्य निर्धारण की विधि समझाइए।)

2 एकाधिकृत प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? इसके अन्तर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है?



(संकेत—एकाधिकृत प्रतिभोगिता का अर्थ समझाइए तथा इसके अन्तर्गत मूल्य निर्धारण की विधि समझाइए—अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में)

3. अल्प-विक्रेताधिकार के अन्तर्गत कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है।

(संकेत—अल्प विक्रेताधिकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए, कीमत निर्धारण विधि पर प्रकाश डालिए।)

4. 'संयुक्त पूर्ति' तथा 'संयुक्त माग' के बीच अन्तर बताइए। संयुक्त पूर्ति के अन्तर्गत मूल्य किन प्रकार निर्धारित होता है ?

(लखनऊ, बी० काम० प्रीवियस, 1971)

5. निम्न दशाओं में मूल्य किस प्रकार प्रभावित होते हैं ?

(i) जब दो वस्तुएँ संयुक्त रूप में मागी जाती हैं ?

(ii) जब दो वस्तुओं की संयुक्त रूप से पूर्ति की जाती है ?

### समस्याएँ (Problems)

#### एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा

1. बताइये कि किन प्रकार एक फर्म अपने उत्पाद (Product) को मर्यादा बनाने की उपेक्षा सस्ता करके लाभ में वृद्धि कर सकती है ?

2. एक गणितीय सारिणी बनाइये जिसमें एक फर्म के विभिन्न मूल्य संयोगों, विज्ञापन-व्ययों तथा लाभों को प्रदर्शित करिये।

#### अल्पविक्रेताधिकार

1. मूल्य सिद्धान्त अल्पविक्रेताधिकार की कीमतों तथा उत्पाद के आधार पर जाचना है। क्या अन्य प्रमाण (Standards) भी ध्यान में रखने चाहिए ? यदि हाँ तो वे कौन से प्रमाण हो सकते हैं ?

2. एक किन्कड माग-वक्र (Kinked Demand Curve) खींचिए और तब एक 'माग में कमी' (Decrease in demand) रेखा बनाकर निदिध करिये कि मूल्य में कमी उपस्थित नहीं होगी।

3. एक रेखाचित्र बनाइये और बताइये कि एक अल्पविक्रेताधिकारी-उद्योग में प्रवेश करने पर किस प्रकार मूल्य पूर्व-स्तर से नीचे गिर जाना है ?

## उत्पादन के साधनों का मूल्य-निर्धारण ( Factor Price Determination )

*"The firm will increase production upto the point at which the last unit of the variable factor employed adds just as much to revenue as it does to costs."*

—Lipsey, R. G.

19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्रियों ने भूमि, धन तथा पूँजी को ही उत्पादन के प्रमुख मापनों के रूप में महत्व प्रदान किया था। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पादन के साधनों में 'साहस' का भी समावेश किया गया। उस समय अर्थशास्त्रियों का केवल इस समस्या में ही अधिक दिलचस्पी थी कि कृषि व उद्योग का कितना भग्न उत्पादन के उक्त मापनों की प्राप्ति होता है? इसका प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय उत्पादन माधना के स्वामी—भूमिपति, श्रमिक पूँजीपति तथा माहूनी—पिन्ह लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लान के रूप में आय प्राप्त होती थी, आर्थिक समूह (economic group) से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में थे। राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से व विभिन्न सामाजिक उच्चवर्गीय, मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय समूह थे जिनकी सांकेतिक आय निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आय में उनके प्रलग-प्रलग हिस्से का अध्ययन किया जाता था। परन्तु आजकल विगुद्ध आर्थिक विवेचण में अधिक मिद्वान्त का सम्बन्ध जब कबन इस बात से नहीं है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन मापना का अवगणन हिस्सा क्या है, बल्कि इन तथ्य में है कि उत्पादन के माधना की कीमते कैसे निर्धारित हानी है? अतः हम इस अध्ययन में इन विधि का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा उत्पादन साधनों के मूल्य निर्धारित होने हैं।

साधनों के मूल्य निर्धारण मिद्वान्त के टाचे के चार प्रमुख भाग हैं :

(1) प्रत्येक फर्म साधनों की इतनी मापाए प्रयोग में लाती है कि उनकी सीमान्त भौतिक उत्पादकता के मूल्य फर्म के लिए उनकी इच्छा लागतों के बराबर होते हैं।

(ii) प्रत्येक फर्म के लिए उत्पादन साधनों का एक माग वक्र होता है। इस वक्र का साधनों की घटती हुई सीमान्त मौलिक उत्पादकता के कारण ढाल नीचे की ओर होता है। जब फर्मों की व्यक्तिगत माग को जोड़ दिया जाता है, तब प्रत्येक बाजार तथा सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में साधनों के माग फलन (demand functions) ज्ञात हो सकते हैं।

(iii) विभिन्न मूल्यों पर साधनों की पूर्ति की मात्रा उनके स्वामियों द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर निश्चित होती है। साधन के मूल्य माग तथा पूर्ति नियम के आधार पर निर्धारित होते हैं।

(iv) उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारण सिद्धान्त तथा उत्पादन साधनों का मूल्य सिद्धान्त एक ही सिद्धान्त के अंग हैं।

इस सम्बन्ध में इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं की माग उनकी रुचि तथा उम्र आदि पर निर्भर करती है जो वे अपने उत्पादन साधनों, अर्थात् अपने उत्पादन सेवाओं (productive services), को बेचकर प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं की माग तथा उत्पादन विधि में तकनीकी प्रगति उत्पादन साधनों की सीमान्त उत्पादकता निर्धारित करती है। इस प्रकार उत्पादन तथा साधनों के मूल्य सिद्धान्त, तकनीकी विधि तथा उपभोक्ताओं की रुचि की सीमाओं के अन्तर्गत, इस तथ्य को व्यक्त करने हैं कि उत्पादन साधन किस प्रकार अपने मूल्यों के कारण कई प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं।

उत्पादन साधनों का मूल्य सिद्धान्त सामान्यतया उत्पादन की 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' (Marginal Productivity Theory) कहा जाता है। परन्तु यह सिद्धान्त पूर्णतया साधनों के मूल्य सिद्धान्त का विवेचन नहीं करता, क्योंकि इसके अन्तर्गत सीमान्त उत्पादकता की धारणा माग पक्ष पर आधारित है जबकि प्रत्येक मूल्य सिद्धान्त में पूर्ति पक्ष का उतना ही महत्व है जितना कि माग पक्ष का। यही कारण है कि उत्पादन-साधनों के मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त में उनकी माग व पूर्ति, दोनों ही, पक्षों का अध्ययन करना पड़ता है। परन्तु जैसा कि स्टोनियर व हैग (Stonier & Hague) का कहना है 'उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त का मार यह है कि प्रत्येक उत्पादन के साधन की कीमत इसकी सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर करती है।' अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत के निर्धारण की प्रक्रिया को सीमान्त-उत्पादकता सिद्धान्त के आधार पर समझा जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों पर यह सिद्धान्त समान रूप से लागू होता है।

## सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory)

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त वितरण का सामान्य सिद्धान्त है जो इस बात की व्याख्या करता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है ? इसके अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को उस साधन की सीमान्त उत्पादकता के बराबर हिस्सा दिया जाता है। वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एक सामान्य सिद्धान्त नहीं था, अतः अर्थशास्त्री वितरण के एक सामान्य सिद्धान्त की खोज करते रहे, जिससे एक ही सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन-साधनों का हिस्सा निर्धारित किया जा सके। वितरण के सिद्धान्त 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' का निर्माण विकस्टीड (Wicksteed), वालरस (Walras) तथा क्लार्क (J. B. Clark) के स्वतन्त्र प्रयत्नों द्वारा हुआ। बाद में श्रोमती जोन राबिन्सन ने इन अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों में महत्वपूर्ण संशोधन किया।

'सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार साम्य अवस्था में प्रत्येक उत्पादन-साधन का पारिणोपिक या मूल्य उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक साधन का मूल्य उसकी 'उत्पादकता' पर निर्भर करता है तथा उसकी यह उत्पादकता उसकी सीमान्त उत्पादकता द्वारा निर्धारित की जाती है।

(1) सीमान्त उत्पादकता क्या है प्रो० हिक्स के अनुसार "सीमांत उपज जिसके द्वारा साम्य अवस्था में उत्पादन के एक साधन को प्राप्त होने वाले हिस्से को ज्ञात करते हैं, एक फर्म का अनिश्चित उत्पादन है जो उत्पादन-साधन के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के कारण प्राप्त होता है, जबकि उद्योग का शेष संगठन अपरिवर्तित रखा जाए।"<sup>1</sup> मूल्य निर्धारण का अध्ययन करते समय हम यह देख चुके हैं कि फर्म अपने उत्पादन का विस्तार उस बिन्दु तक करती है, जिस पर उत्पादन की अन्तिम इकाई की लागत तथा उस इकाई से प्राप्त आय बराबर होती है अर्थात् फर्म का विस्तार उस समय तक होता है जब तक सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं हो जाती है। उत्पादन साधनों के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है, 'फर्म उत्पादन में वृद्धि उस बिन्दु तक करेगी जिस पर परिवर्तनशील साधन की अन्तिम इकाई द्वारा आय में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की लागत में।'

<sup>1</sup> "The marginal product which measures the actual return which a factor of Production must get in a state of equilibrium is the addition which is made to the product of a firm when a small unit is added to the supply of that factor available to that firm and the rest of the organisation of the industry remains unchanged,"

इस प्रकार सरल शब्दों में, सीमान्त उत्पादकता की परिभाषा इस प्रकार है :  
 "अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है, वही उस साधन की सीमान्त उत्पादकता है।"

(2) सीमान्त उत्पादकता की मांग : एक साधन की अतिरिक्त इकाई द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन में वृद्धि अर्थात् सीमांत उत्पादकता की माप तीन प्रकार से की जा सकती है :

उपर्युक्त तोगों तरीकों की व्याख्या निम्नलिखित है :—

(i) सीमांत भौतिक उत्पाद (Marginal Physical Product or MPP)  
 किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल भौतिक उत्पादन (Total Physical Product) में वृद्धि को उस साधन की सीमान्त भौतिक उत्पाद कहते हैं, जबकि अन्य साधन पूर्ववत् या स्थिर रखे जाते हैं। सीमांत भौतिक उत्पादकता रेखा चरट 'यू' (U) आकार (∩) की होती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात नियम के अनुसार प्रारम्भ में सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ती है, एक बिन्दु पर यह अधिकतम हो जाती है और उसके बाद गिरने लगती है।

(ii) सीमांत आय उत्पाद (Marginal Revenue Product or MRP)  
 किसी उत्पादक या फर्म के लिए सीमांत भौतिक उत्पादकता का उनका महत्त्व नहीं है जितना कि उस भौतिक उत्पाद को बेचने से प्राप्त आय का। सीमांत आय उत्पाद का अतिमात्र वस्तु आय में उस द्रव्य या प्राय की वृद्धि से है जो कि अन्य साधनों को पूर्ववत् रखने पर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से होती है। सीमांत आय उत्पाद को ज्ञात करने के लिए सीमांत भौतिक उत्पाद को सीमांत आय से गुणा किया जाता है अर्थात्,

$$MRP = MPP \times MR$$

(iii) सीमांत भौतिक उत्पाद का भौतिक मूल्य (Marginal Value Product or MVP) या सीमान्त उत्पादक का मूल्य (Value of Marginal Product or VMP) सीमांत भौतिक उत्पादकता की वस्तु की कीमत से गुणा करने पर सीमान्त भौतिक उत्पाद का मूल्य ज्ञात होता है। अर्थात्,

$$MVP \text{ or } VMP = MPP \times Price$$

परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय (AR) सीमान्त आय (MR) के बराबर होती है तथा औसत आय (AR) को ही मूल्य (Price) कहा जाता है अतः

$$MVP \text{ or } VMP = MPP \times MR \\ = MRP$$

उक्त भमीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमात भौतिक उत्पाद का मूल्य (MVP) या सीमात उत्पाद का मूल्य (VMP) तथा सीमान्त आय उत्पाद (MRP) एव ही होते हैं ।

इन तीनों का स्पष्टीकरण एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है । मान लीजिए एक फर्म (पूर्ण स्पर्धा में) 20 श्रमिक उत्पादन-कार्य में लगाती है तथा वे वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं । यदि एक श्रमिक और बगा दिया जाता है तो उत्पादन 106 इकाई हो जाता है । फर्म दम रुपये प्रति इकाई की दर से वस्तु बेच रही है । अतः प्रथम अवस्था में फर्म की कुल आय 1,000 रुपये तथा द्वितीय अवस्था में 1 060 रुपये होगी । ऐसी परिस्थिति में :

$$\text{सीमात भौतिक उत्पाद (MPP)} = 106 - 100 = 6 \text{ इकाइया}$$

$$\text{सीमान्त मूल्य उत्पाद (VMP)} = 6 \times 10 = 60 \text{ रुपये}$$

$$\text{सीमात आय उत्पाद (MRP)} = 1\ 060 - 1,000 = 60 \text{ रुपए}$$

पूर्ण स्पर्धा में अतिरिक्त इकाइया भी उनी कीमत पर बेची जाती हैं, अतः MVP तथा MRP समान होंगे । जैसा कि आगे दी गयी तालिका से स्पष्ट है ।

## MPP, MRP तथा MVP के माप की तालिका

नियुक्त श्रमिकों की संख्या	कुल भौतिक उत्पाद	उत्पाद का मूल्य (Price)	कुल आय (Total Revenue)	सीमान्त भौतिक उत्पाद (MPP इकाईयाँ)	सीमान्त आय उत्पाद (MRP) ₹०	सीमान्त भौतिक उत्पाद का मौद्रिक मूल्य (MVP) ₹०
20	इकाईयाँ 100	₹० 10	$10 \times 100 = 1000$	—	—	—
21	106	10	$10 \times 106 = 1060$	$(106 - 100) = 6$	$(1060 - 1000) = 60$	$6 \times 10 = 60$

अपूर्णा स्वर्धा में प्रतिरिक्त इकाईयाँ कम मूल्य पर बेची जाती हैं। ऐसी स्थिति में सीमान्त आय उत्पाद (MRP) सीमान्त भौतिक उत्पाद के मौद्रिक मूल्य (MVP) से कम होना है, जैसा कि प्रति इकाई 10 ₹० के मूल्य के 9.90 ₹० हो जाने पर निम्न तालिका में MRP तथा MVP में हुए परिवर्तनों से स्पष्ट है।

## अपूर्णा स्वर्धा में MPP, MRP तथा MVP के माप की तालिका

नियुक्त श्रमिकों की संख्या	कुल भौतिक उत्पाद	उत्पाद का मूल्य (Price)	कुल आय (Total Revenue)	सीमान्त भौतिक उत्पाद (MPP)	सीमान्त आय उत्पाद (MRP)	सीमान्त भौतिक उत्पाद का मौद्रिक मूल्य (MVP)
20	इकाईयाँ 100	₹० 10	$10 \times 100 = 1000$	इकाईयाँ —	—	—
21	106	9 90	$9 90 \times 106 = 1049 40$	$(106 - 100) = 6$	$(1049 40) - (1000) = 49 40$	$6 \times 9 90 = 59 40$

औसत सम्पूर्ण आगम उत्पादकता तथा औसत शुद्ध आगम उत्पादकता (Average Gross Revenue Productivity i.e. AGRP and Average Net Revenue Productivity i.e. ANRP) :—

सीमान्त आगम उत्पादकता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि MRP वक्र उल्ट 'U' के आकार का होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि उसकी ऊपर उठती हुयी ढलान सीमान्त आगम उत्पाद में वृद्धि तथा उसकी नीचे की ओर गिरती हुयी ढलान सीमान्त आगम उत्पाद में कमी को व्यक्त करती है। सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र की तरह ही हम औसत आगम उत्पादकता वक्र को भी बीच मारते हैं। साधन के किसी प्रयोग के स्तर पर कुल आगम (Total Revenue) को साधन की इकाइयों से भाग देने पर औसत आगम उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात्

$$\text{औसत आगम उत्पाद} = \frac{\text{कुल आगम}}{\text{साधन की इकाइयाँ}}$$

$$\text{Average Revenue Product at any level of employment} = \frac{\text{Total Revenue}}{\text{Total number of units of the factor}}$$

उक्त समीकरण की सहायता से ज्ञात आकड़ों के आधार पर औसत आगम उत्पादकता वक्र खींचा जा सकता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित तालिका की सहायता से खींचे गये सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र (MRPC) तथा औसत आगम उत्पादकता वक्र के आकार चित्र स० 117 में दिए गये वक्रों के अनुरूप होंगे।

सीमान्त आगम उत्पादकता की तालिका

नियुक्त श्रमिकों की संख्या	धम की सीमान्त भौतिक उत्पादकता (किलो ग्राम में)	धम की सीमान्त आगम उत्पादकता (MPP × Price)
		₹०
1	5	25
2	7	35
3	12	60
4	20	100
5	25	125
6	30	150
7	27	135
8	25	125
9	18	90
10	10	50



चित्र न० 117 से सीमान्त आगम उत्पादकता तथा औसत आगम उत्पादकता वक्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—“जब सीमान्त



चित्र स० 117

आगम औसत आगम में अधिक होता है, तब सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र औसत आगम उत्पादकता वक्र के ऊपर होता है। परन्तु सीमान्त आगम औसत आगम से कम होता है तब सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र औसत आगम उत्पादकता वक्र के नीचे होता है। सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र आगम उत्पादकता वक्र को सर्वम ऊँचे बिंदु पर काटता है।”

चित्र स० 117 में औसत आगम उत्पादकता वक्र कुल या ‘सम्पूर्ण औसत आगम उत्पाद’ (Gross Average Revenue Product) का प्रकट करता है। परन्तु हम लोगों का अस निश्चयन कि विवेचन में सम्पूर्ण आगम उत्पाद की प्रकृति ‘निष्ठा औसत आगम उत्पाद’ (Net Average Revenue Product) पर विचार करना है।

इस सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि उत्पादन का कोई साधन स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। उस अन्य साधनों के साथ मिलाने पर ही किसी वस्तु का उत्पादन सम्भव हो सकता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है औसत आगम उत्पाद कुल या सम्पूर्ण आगम का मापन (माना कि धन की कुल इकाईयाँ से ना दकर ज्ञान किया जाता है। परन्तु कुल आगम धन के प्रतिरिक्त अन्य साधनों जैसे भूमि, पूँजी तथा साहम के अक्षयन के कारण प्राप्त होता है। धन की औसत पुँज आगम उत्पादकता को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे प्रथम कुल आगम में से भूमि, पूँजी तथा साहम के मापन के आगम के हिस्से को निहालना होगा। उसके बाद शेष आगम की श्रमिका की संस्था से माप देना होगा। इस प्रकार

तब स्पष्टित फर्म के लिए श्रम के प्रतिबन्ध का प्रश्न है, यह बरक चित्र स 118 में WW रेखा की तरह एक पड़ी हुयी सीधी रेखा (Horizontal Straight Line) के आकार का होगा, क्योंकि यह मान लिया गया है कि साधन (श्रम) बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है।

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म श्रम के प्रचलित मूल्य अर्थात् मजदूरी (जो श्रम की कुल माग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है) पर श्रम की मिलनी इकाइया चाहे उत्पादन कार्य में लगा सकती हैं। इसमें यह ज्ञात होता है कि फर्म के लिए श्रम की औसत लागत या औसत मजदूरी [जिसे किसी भी साधन के लिए 'साधन की औसत लागत' (Average Factor Cost-AFC) या 'औसत पारिश्रमिक' (Average Remuneration) कहा जा सकता है] का बरक एक पड़ी हुयी रेखा के आकार का होता है जो यह प्रकट करता है कि फर्म के लिये औसत मजदूरी श्रम की मजदूरी (अर्थात् साधन का औसत पारिश्रमिक साधन के सीमान्त पारिश्रमिक (Marginal Factor Cost या MFC) के बराबर होती है। निच स० 118 की WW रेखा को AFC या MFC भी कहा जा सकता है, क्योंकि  $AW \text{ or } AFC = MW \text{ या } MFC$ ,

पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत एक फर्म अधिकतम लाभ उसी समय प्राप्त करेगी जबकि उस श्रम साधन की एक प्रतिरिक्त इकाई का प्रयोग उम बिन्दु तक करे जिस बिन्दु पर श्रम की सीमान्त आगम उत्पादकता (MRP) [अर्थात् प्रतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल आगम में वृद्धि] श्रम की प्रतिरिक्त इकाई की सीमान्त मजदूरी [अर्थात् सीमान्त साधन लागत (MFC)] के बराबर न हो जाये। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फर्म उस समय सन्तुलन प्राप्त करती है जबकि उसके लिए एक साधन की सीमान्त आगम उत्पादकता (MRP) उसकी सीमान्त लागत (MFC) के बराबर हो जाती है। इसी स्थिति में लाभ अधिकतम होते हैं। अतः श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने पर एक फर्म की सन्तुलन की दशा इस प्रकार होगी

श्रम की सीमान्त उत्पादकता = सीमान्त मजदूरी = औसत मजदूरी

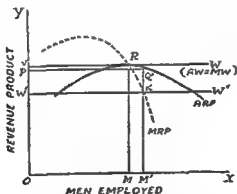
$MRP \text{ of Labour} = \text{Marginal Wage} = \text{Average Wage}$

अर्थात्  $MRP = MFC$

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किसी भी साधन का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से श्रम के पारिश्रमिक अर्थात् मजदूरी निर्धारण की विधि की रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। हमने इस सम्बन्ध में यह भी मान लिया है कि वस्तु और श्रम दोनों के ही बाजारों में पूर्ण स्पर्धा है। ऐसी स्थिति में आगम साधनों को स्थिर रखते हुये यदि श्रम की मात्रा में एक इकाई से वृद्धि की जाती है, तो मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (MVP) के बराबर

होगी। यदि श्रम की MVP के बराबर मजदूरी नहीं मिलेगी तो वह किसी अन्य फर्म में चला जायेगा क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में श्रम गतिशील होता है। श्रम की गतिशीलता ही मजदूरी और सीमान्त उत्पादकता में समानता लाती है। श्रमिकों के गतिशील हान के कारण सीमान्त उत्पादकता और मूल्य बराबर हो जायेंगे, क्योंकि श्रम की माग का प्रकट करन वाला सीमान्त आगम उत्पादकता (MPP) वक्र नीचे दाहिनी तरफ मुड़ता है और वह 'श्रोत आगम उत्पादन' (ARP) वक्र को उनके उनके उच्चतम बिन्दु पर काटता है जैसा कि चित्र स० 118 में दिखलाया गया है। मजदूरी की समान दर पर किसी फर्म का इच्छानुसार श्रम की इकाइया प्राप्त होगी। फलस्वरूप श्रम की पूर्ति प्रकट करने वाला सीमान्त मजदूरी (MW) वक्र एक पट्टी हुयी रेखा (Horizontal) के रूप में होगा। इस प्रकार श्रोत मजदूरी (AW) वक्र तथा 'सीमान्त मजदूरी' (MW) वक्र दोनों एक ही होंगे, अर्थात् पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमान्त मजदूरी और श्रोत मजदूरी एक ही होगी।

चित्र स० 118 से स्पष्ट है कि कोई फर्म अपने लाभ को सर्वाधिक करन के लिए एक दी हुयी मजदूरी की दर पर कितने श्रमिकों को कार्य पर लगायेगी। WW रेखा सीमान्त मजदूरी और श्रोत मजदूरी दोनों को प्रदर्शित करती है। श्रम की प्रत्येक इकाई को OW मजदूरी मिलती है। अतः श्रम की एक अनिश्चित इकाई को भी इतनी ही रकम मजदूरी के रूप में प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में फर्म का लाभ



चित्र स० 118

वही सम्भव होगा जहां श्रम का सीमान्त आगम उत्पादन (MRP) श्रम की सीमान्त लागत (सीमान्त मजदूरी) के बराबर है और ऐसा सम्भव होना है जबकि उत्पादक OM श्रमिकों को कार्य पर लगाता है। यदि इससे कम माना में श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो श्रम की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादक, लागत की अपक्षा अपनी आय को अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि 'सीमान्त आय उत्पादन (MRP)' उनकी

लागत की तुलना में अधिक होगा। ठीक इसके विपरीत यदि OM से अधिक मात्रा में श्रम को लगाया जाना है तो श्रम का 'सीमान्त आय उत्पादन' (MRP) उसकी सीमान्त लागत से कम होगा, परिणामस्वरूप फर्म अपनी कुल आय की अपेक्षा कुल लागत में ही अधिक वृद्धि करेगी। अतः स्पष्ट है कि फर्म के लिये OM मात्रा में श्रम की नियुक्ति ही सर्वाधिक लाभप्रद होगी। इस प्रकार जब धन बाजार में पूर्ण प्रति प्रयोगिता हो तो फर्म के लिए सन्तुलन की यह स्थिति होगी :

$$\text{श्रम की सीमांत आय उत्पादन (MRP)} = \text{श्रम की सीमांत मजदूरी (MW)} \\ = \text{श्रम की सीमांत मजदूरी (AW)}^2$$

पूर्व प्रविष्टि में, पूर्ण सन्तुलन की अवस्था में, इसका यह भी मान्य निकलता है कि मजदूरी श्रम की शुद्ध आय उत्पादकता के बराबर हो जाती है।

यह स्थिति OW से स्पष्ट है अर्थात् जब मजदूरी OW हो है तो श्रम का सीमांत आय उत्पादन (MRP) उसकी मजदूरी के बराबर है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि फर्म सन्तुलन की अवस्था में है तथा उत्पादक केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर रहा है। सन्तुलन की अवस्था में प्रत्येक फर्म का सीमांत आय-उत्पादन-वक्र (MRP) मजदूरी की रेखा को स्पष्ट करता है। अवस्था में मजदूरी की रेखा WW से ऊपर या नीचे हो सकती है, जिसके कारण उत्पादक को कमश. हानि या लाभ होगा, किन्तु दीर्घकाल में ऐसी स्थिति नहीं होगी तथा उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही मिलेगा। चित्र सं० 110 के अनुसार यदि मजदूरी WW से कम है अर्थात् W'W' है तो OM अधिक मात्रा पर लगाया जायेगा। फलस्वरूप असामान्य लाभ WP होगा ऐसी स्थिति में फर्म तो सन्तुलन की स्थिति में रहता है, किन्तु उद्योग सन्तुलन की स्थिति में नहीं रहता। लेकिन जब नई फर्म प्रवेश करेगी तो मूल्य में कमी आयगी तथा असामान्य लाभ कम होता जायेगा। फलस्वरूप 'सीमान्त आय उत्पादन वक्र' (MRP) तथा 'सीमांत आय उत्पादन वक्र' (MRP) नीचे की तरफ गिरगा। किन्तु ठीक इसके विपरीत, श्रम की माग में वृद्धि होगी, क्योंकि श्रम की माग में वृद्धि के कारण मजदूरी का बढ़ना स्वाभाविक होगा और श्रम का मूल्य बढ़ेगा और सीमांत आय उत्पादन वक्र नीचे की तरफ आयेगा। लेकिन मजदूरी की रेखा ऊपर आयगी और निम्नी स्तर पर दोनों एक दूसरे को स्पष्ट करेंगे। इस बिन्दु के कारण पुनः उत्पादकों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि फर्मों की सामान्य लाभ नहीं मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो वे उद्योग छोड़ सकती हैं और फिर सन्तुलन की स्थिति आ जायेगी।

<sup>2</sup> "The firm will be in equilibrium—profits will be maximised when the marginal revenue productivity of the factor is equal to the marginal cost of the factor—the marginal wage"

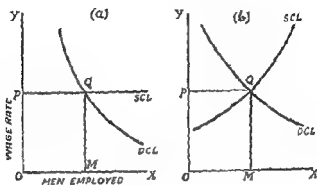
उक्त विश्लेषण में स्पष्ट है कि कोई फर्म श्रम की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग उसी सीमा तक करेगी जहां श्रम का भीजान आय उत्पादन (MRP) उसकी भीजान मजदूरी के बराबर होगा। पूर्ण अनिरुद्ध तथा सन्तुलन की स्थिति में मजदूरी श्रम के औसत आय उत्पादन के बराबर होती है। स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के लिये श्रम का पूर्ण वक्र प्रचलित मजदूरी की दर पर पूर्ण रूप से लोचदार होगा।

#### 4. उद्योग का सन्तुलन (Equilibrium of Industry) :

इस प्रकार किसी एक फर्म के लिये तो मजदूरी निश्चिन् और दी हुई होनी है किन्तु पूरे उद्योग के लिए ऐसा नहीं होता। पूरे उद्योग की दृष्टि से श्रम की पूर्ति पूर्ण रूप से लोचदार नहीं होती, क्योंकि यदि कोई उद्योग अधिक मजदूरी को कार्य पर लगाना चाहता है तो उसे मजदूरी में वृद्धि करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही एक विशिष्ट प्रकार का श्रमिक विभिन्न प्रकार के उद्योग में कार्य भी नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप वह एक उद्योग छोड़कर किसी दूसरे उद्योग में ग्रामानी सजा भी नहीं सकता, किन्तु यह स्थिति रचना चाहित कि समान पैसे वाले उद्योगों में मजदूरी में वृद्धि होने से अधिक श्रमिक उस तरफ जाने के लिए प्रवृत्त होंगे, जिसके कारण उस उद्योग में श्रम की पूर्ति बढ़ जायेगी। श्रम की पूर्ति में वृद्धि एक अल्प दृष्टि में भी सम्भव है। जब किसी उद्योग में मजदूरी बढ़ती है तो उस उद्योग के श्रमिक अतिरिक्त काल (over-time) तक काम करना प्रारम्भ कर देते हैं, ऐसी दशा में उद्योग के श्रम का पूर्ति वक्र बायीं ओर ऊपर (slopes upward from left to right) की तरफ बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी-दर में वृद्धि होने पर अधिक मजदूर बायें करने को तैयार होंगे और मजदूरी-दर बदल जायेगी। अतः पूरे उद्योग की दृष्टि में सन्तुलन उसी दशा में सम्भव है, जब सभी फर्मों के लिये श्रम की मांग एवं पूर्ति बराबर होती है।

फर्म और उद्योग में श्रम की पूर्ति और मांग का क्या स्वरूप होगा तथा मजदूरी दर क्या होगी, यह चित्र सं० 119 द्वारा और भी सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है :

किसी फर्म के लिये तो मजदूरी दर दी हुई है तथा श्रम के पूर्ति-वक्र (SCL) का स्वरूप समानांतर है, जिसका तात्पर्य यह है कि उत्पादक अपने व्यवहार में मजदूरी दर का प्रभावित नहीं कर सकता। फर्म की सन्तुलन की स्थिति में (OM) श्रम की इकाई कार्य करती है तथा OP मजदूरी की दर है। यह स्थिति बिन्दु (a) द्वारा स्पष्ट है किन्तु पूरे उद्योग में श्रम का पूर्ति वक्र (SCL) का स्वरूप (चित्र b में) बदल जाता है तथा वह बायें से दायें ऊपर की ओर उठता है तथा पूरे उद्योग की दृष्टि में सन्तुलन बिन्दु Q होगा। जिस स्थिति में सभी फर्मों में OM माना में श्रमिक कार्य पर लगाने जाते हैं तथा उनको OP मजदूरी प्राप्त होती है।



चित्र सं० 119

धर्म की मरिणीलता भाग एवं पूर्ति को प्रभावित करती है। धर्म के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने का प्रम उस सीमा तक चलता रहेगा। जब तक कि पूरे उद्योग में केवल एक मजदूरी दर कायम न हो जाये तथा मजदूरी दर सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (MVP) के बराबर न हो जाये। ऐसी स्थिति में माग एवं पूर्ति की प्रतिक्रिया के द्वारा पूरे उद्योग में मजदूरी धर्म की सीमान्त उत्पादकता (MVP) के बराबर होगी तथा धर्म की सीमान्त उत्पादकता के समान रहेगी।

(i) साधनों की मांग (Demand of the Factors) - जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसकी माग व पूर्ति पर निर्भर करता है। उत्पादन साधनों के मूल्य-सिद्धांत के सम्बन्ध में प्रतीत उनके पारिधमिक को निर्धारित करते समय सीमान्त उत्पादकता पर विचार करते समय साधनों की माग पर विचार करना आवश्यक है। वस्तुतः साधनों की माग उनकी 'उत्पादकता' पर निर्भर करती है, परन्तु किसी भी उत्पादन साधन की माग प्रत्यक्ष नहीं होती, बल्कि व्युत्पादित माग (derived demand) होती है। इसके साथ ही साथ साधन की माग उत्पादन की प्राविधिक दशा पर भी निर्भर करती है। प्राविधिक दशा का अर्थसाधन की सीमान्त उत्पादकता, कुल उत्पादन लागत में साधन का महत्व तथा एक साधन का दूसरे साधन के प्रयोग से है। साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की माग बढ़ने पर साधन की भी माग बढ़ती है, अर्थात् किसी साधन की माग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की माग की लोच पर निर्भर करती है। इससे यह निष्कर्ष निवाला जा सकता है कि किसी भी साधन की उत्पादकता अधिक होने पर उसकी माग अधिक होगी तथा उसका मूल्य भी अधिक होगा। इसके विपरीत उत्पादकता कम होने पर उसका मूल्य कम होगा।

किसी साधन का सीमान्त आय-उत्पादकता-वक्र (MRP) कर्म के लिए उस

साधन का माग-वक्र भी है। इस माग वक्र का ढाल सीमांत भौतिक उत्पाद (MPP) पर निर्भर करता है। किसी साधन के लिए उद्योग का माग वक्र नीचे की ओर ढलता हुआ (downward sloping) होता है, क्योंकि साधन की जितनी ही अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, अमागत इकाइयों का 'सीमांत भौतिक उत्पाद' (MPP) धीरे-धीरे कम होता जाता है।

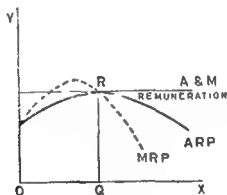
पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली उत्पादक परिवर्तनशील उत्पादन-साधन को उस सामा या बिन्दु पर उत्पादन कार्य में लगाता है, जिस बिन्दु पर उत्पादन-साधन की सीमांत लागत (साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लागत में वृद्धि) हम साधन द्वारा उत्पादित 'सीमांत माय उत्पाद' के बराबर होती है। उत्पादक इस 'सीमांत माय उत्पाद' के बराबर उस साधन की कीमत निर्धारित करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है साधनों का मूल्य सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होता है।

उक्त विवेचन से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि फर्म का लाभ अधिकतम उस स्थिति में होता है जबकि परिवर्तनशील साधन की सीमान्त लागत (MC) साधन की सीमान्त माय (MRP) के बराबर होती है। इसके लिए फर्म या उद्योग अपना लाभ अधिकतम करने के लिए साधन की सीमांत उत्पादकता तथा साधन की सीमान्त लागत (MC or MFC or Marginal Factor Cost) को बराबर करती है। यही कारण है कि साधन के मूल्य निर्धारण में सीमान्त उत्पादकता को महत्व दिया जाता है, न कि औसत उत्पादकता (Average Productivity) को। सीमान्त उत्पादकता ही साधन की सीमान्त लागत (Marginal Factor Cost) अर्थात् 'साधन की सीमान्त माय या उसका पारिश्रमिक (Marginal Remuneration of the Factor) निर्धारित करती है।

(ii) साधनों की पूर्ति पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत (क) उत्पादक अधिकतम लाभ उसी समय प्राप्त कर सकता है जबकि वह प्रत्येक उत्पादन साधन का उपयोग उस बिन्दु तक करे जिस बिन्दु पर साधन की 'सीमांत माय उत्पाद' (MRP) उस साधन के बाजार मूल्य के बराबर हो। (ख) इसके साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार उत्पादक, साधनों का 'न्यूनतम लागत संयोग' (Least Cost Combination) उस अवस्था में प्राप्त करता है, जब कि वह प्रत्येक साधन की इकाइयों का प्रयोग उस बिन्दु तक करे, जिस बिन्दु पर 'सीमांत माय उत्पाद' (MRP) तथा साधन के मूल्य का अनुपात, सभी उत्पादन साधनों के लिए समान हो। उपरोक्त दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाता है। अब हम यह देखना है कि साधनों की पूर्ति की क्या दशा होगी? एक फर्म के लिए साधन का पूर्ति वक्र क्षैतिज (Horizontal) होगा।

आय उत्पाद' से अधिक होगी। अतः उत्पादक किसी साधन की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करेगा जितनी मात्रा का प्रयोग करने से साधन की 'सीमान्त आय उत्पाद' उम साधन की कीमत के बराबर हो। इस तथ्य का स्पष्टीकरण निम्न रेखाचित्र द्वारा दिया जा सकता है।

चित्र में MRP तथा ARP वक्र उत्पादन-साधन के क्रमशः 'सीमान्त आय उत्पाद' तथा 'औसत आय उत्पाद' वक्र हैं जो R बिन्दु पर एक दूसरे के बराबर हैं। यह वह बिन्दु है जहाँ पर 'औसत आय उत्पाद' अधिकतम है। QR साधन की कीमत हुई या उसका पारिश्रमिक हुआ। उत्पादक की आय उम समय अधिकतम है, जबकि वह साधन की OQ मात्रा का प्रयोग करता है। साधन की OQ मात्रा का



चित्र सं० 120

प्रयोग करने पर साधन की कीमत = 'सीमान्त आय उत्पाद' = 'औसत आय उत्पाद'। MRP वक्र उत्पादक वा साधन के लिए माग-वक्र भी है। A & M-Remuneration एक सीधी रेखा के रूप में है जो यह प्रकट करता है कि इस पारिश्रमिक (RQ) पर साधन की पूर्ति इच्छित मात्रा में की जा सकती है। अतः R वह बिन्दु है जहाँ पर माग (MRP) तथा पूर्ति में भी संतुलन है।

### अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत पारिश्रमिक (Remuneration Under Imperfect Competition)

अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत भी उत्पादक वा लाग उस बिन्दु पर अधिकतम होगा जिन बिन्दु पर साधन वा 'सीमान्त आय उत्पाद' उमकी कीमत के बराबर होगा (When  $MRP = MC$  of the factor), परन्तु पूर्ण स्पर्धा की स्थिति से अपूर्ण स्पर्धा की स्थिति में एक विभिन्नता पाई जाएगी। पूर्ण स्पर्धा में उत्पादक को एक ही कीमत पर साधन की अपेक्षित मात्रा प्राप्त हो जाएगी, परन्तु अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत



साधन की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, उत्पादक को उत्तरेतर अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

उपयुक्त से स्पष्ट है कि सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक साधन को वह पारिश्रमिक मिलता है जितना उस साधन द्वारा उत्पत्ति में हिस्सा (Contribution) प्रदान किया गया है (साधन-विशेष के प्रति पक्ष को ध्यान में रखते हुए)। साधन का उत्पादित वस्तु में कितना हिस्सा होगा? यह उस वस्तु के बाजार मूल्य पर निर्भर है। यदि साधन (श्रम) की पूर्ति घटता है तो पारिश्रमिक बढ़ जायेगा तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी पारिश्रमिक बढ़ेगा। इसकी विपरीत दशा में उपयुक्त के विपरीत परिणाम होंगे। यहाँ पर यह यदि रखना चाहिए कि सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का सम्बन्ध केवल साधनों के मूल्य निर्धारण-विधि से है। पारिश्रमिक उचित है या नहीं, इस बात से इस सिद्धान्त का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सिद्धान्त द्वारा इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि साधनों की भाग क्यो बढ़ती है।

व्यवहारिक अंश में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं पायी जाती। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा व्यवहारिक स्थिति है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत यह सम्भव है कि साधन को उसके सीमान्त उत्पाद (Marginal Product) के बराबर पारिश्रमिक न मिले। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दो प्रकृतियाँ हो सकती हैं - (1) उत्पादित वस्तु के विषय से सम्बन्धित अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, तथा (2) साधन (श्रम) की माग से सम्बन्धित पूर्ण प्रतिस्पर्धा।

### (1) घटत बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा

#### (Imperfect Competition in the Product Market) :

मान लीजिए कि कोई साधन (श्रम) ऐसे उत्पादक की सेवा में है जो एकाधिकारी है। इस दशा में भी वह श्रम को उस बिन्दु तक संग्रहीत जायेगा जिन बिन्दु पर मजदूरी सीमान्त आय उत्पादकता (MRP) के बराबर होगी। परन्तु ऐसी स्थिति में मुख्य अन्तर यह होगा कि सीमांत आय उत्पाद (MRP) सीमान्त भौतिक उत्पाद (MPP) तथा कीमत के गुणनफल के बराबर नहीं नहीं होगा ( $MRP \text{ no longer equals } MPP \times P$ )। इसका कारण यह है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर एकाधिकारी बेची जाने वाली वस्तु की सभी मात्राओं पर कम कीमत प्राप्त करता है (देखिए एकाधिकार सम्बन्धी अध्याय)। अतः एकाधिकारी साधन को प्रतिरिक्त इकाइयों का लगाते समय केवल सीमान्त भौतिक उत्पाद (MPP) की मात्रा पर ही ध्यान नहीं देगा, बल्कि वह इस बात पर भी ध्यान देगा कि बड़ा हुआ उत्पादन किस कीमत पर बेचा जायेगा। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए श्रम की MPP तथा MPP की दशाएँ यद्यपि पृष्ठ पर दी गयी सारणी के अनुसार हैं।

श्रमिक को सत्या	कुल उत्पाद (TP)	सीमांत भौतिक उत्पाद (MPP, (किलो में)	सीमांत आय उत्पाद (MRP) (पैसे में)
1	1	1	20
2	■	7	140
3	27	19	380
4	40	13	260
5	47.5	7.5	150
6	54	6.5	130
7	60	6	120
8	65	5	100
9	69	4	80
10	71	2	40
11	71	0	—

वस्तु 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। यदि 3 श्रमिक लगाये जाते हैं तो वस्तु की 47.5 किलो ग्राम मात्रा पैदा की जाती है। इस मात्रा को उत्पादक 20 प्रति किलो की दर से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में बेचता है। यदि छठवा श्रमिक लगाया जाय तो कुल उत्पादन बढ़कर 54 किलोग्राम हो जाता है। इस प्रकार छठवे श्रमिक की MRP 130 ( $6.5 \times 20 = 130$ ) पैसे होगी। मान लीजिए मजदूरी की दर 130 रु० है। इसका अर्थ यह है कि छठवें श्रमिक को लगाना लाभप्रद होगा, क्योंकि अतिरिक्त लागत उत्पादन द्वारा पूरी हो जाती है।

अब मान लीजिए उत्पादक एकाधिकारी है तथा उसकी विक्रय मात्रा कीमत को प्रभावित करती है। उसका मान तालिका निम्नलिखित है :

कीमत (पैसे में)	माँगी गयी मात्रा (कि० ग्राम में)
23	■
22	23
21	37
20	47.5
19	54

इस प्रकार यदि वह 47.5 कि० ग्राम वस्तु की मात्रा बेचता है तो उसे 20 पैसे प्रति कि० ग्राम कीमत मिलती है। यदि वह 54 कि० ग्राम बेचता है तो उसे 19 पैसे प्रति कि० ग्राम कीमत प्राप्त होती है। छठवें श्रमिक की MRP 76 पैसे होगी, जबकि मजदूरी 130 रु० होगी। अतः केवल 5 श्रमिक लगाये जायेंगे। इस प्रकार यदि वस्तु विक्रय के सम्बन्ध में एकाधिकार की स्थिति है तो श्रम की माग पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में कम होगा तथा मजदूरी की दर भी कम होगी।

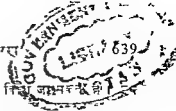
## (ii) साधन बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा

(Imperfect Competition in the Factor Market)

एक उत्पादक समूहों का एकाग्रता के हो सकता है यद्यपि उनकी स्थिति ज़रूरी एकाधिकारी (Monopsony) की हो सकती है। ऐसी स्थिति में उत्पादक द्वारा की जाने वाली मापन (भ्रम) की माप मजदूरी दर को प्रभावित करेगी। यदि अधिक भ्रम लगाया जाय तो सभी श्रमिकों को ऊँची मजदूरी देने पड़ेगी। इसका परिणाम यह होगा कि मजदूरी का भ्रम का भ्रम लागत वक एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होगा। भ्रम का माना बढ़ाने के लिए मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी अर्थात् वक दाहिना ओर ऊपर की तरफ उठना होगा, परन्तु उत्पादन यदि अधिक श्रमिक लगता है तो उस सभी श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने पड़ेगी। भ्रम अतिरिक्त भ्रम (मापन) की सीमात लागत मजदूरी (पारिस्थितिक) या भ्रम लागत से अधिक होगी।

इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिए माना कि उत्पादक अथवा फर्म उत्पाद बाजार (product market) में एकाधिकारी है तथा साधन बाजार (factor market) (भ्रम बाजार) में ज़रूरी एकाधिकारी (Monopsonist) है। इसका अर्थ यह है कि साधन बाजार में फर्म भ्रम का एक मात्र निरोधक (employer) है। ऐसी स्थिति में भ्रम की कुल माप केना एकाधिकारी फर्म की माप के समान होगी। भ्रम भ्रम की मजदूरी ज़रूरी एकाधिकारी फर्म की भ्रम की माप तथा बाजार में भ्रम की पूर्ति द्वारा निर्धारित होगी।

(1) माप पक्ष (Demand Side) पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह 'एकाधिकारी ज़रूरी अधिकारी (monopolist or monopsonist) की भ्रम की माप सीमात माप उत्पादकता (MRP) वक पर निर्भर करती है। उत्पाद बाजार में, जहाँ हमने एकाधिकार का स्थिति माना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति की तरह फर्म की वस्तु का मूल्य वक दया हो रहेगा और वही निश्चित होगा। इसके विपरीत, फर्म के एकाधिकारी हान के कारण वस्तु का मूल्य उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर बदलता रहेगा। अधिक उत्पादन होने पर, वस्तु कम मूल्य पर बिकेगी तथा कम उत्पादन होने पर वस्तु अधिक मूल्य पर बिकेगी। एकाधिकार की स्थिति में वस्तु का मूल्य वक दया रहने के कारण भ्रम के सीमात माप उत्पाद (MRP) को गणना करना ज़रूरी हो जाता है। वास्तव में एकाधिकार की स्थिति में भ्रम की MRP की गणना करना सरल नहीं है। एकाधिकार की स्थिति होने पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर जब उत्पाद का मूल्य कम हो जाता है तब पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह भ्रम का सीमात माप उत्पाद (MRP) सीमात भौतिक उत्पाद (MPP) को उत्पाद के मूल्य से गुणा करने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भ्रम का सीमात माप उत्पाद (MRP) सीमात भौतिक उत्पाद (MPP) की



भौतिक उत्पाद की सीमान्त आय में गुणा करने पर ज्ञात किन्हीं जलमय  $\times 50$  की है।  
तथ्य को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :

$$\left[ \begin{array}{l} \text{पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत} \\ \text{श्रम की सीमान्त आय उत्पादकता} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} \text{श्रम का सीमान्त भौतिक उत्पाद} \times \text{उत्पाद} \\ \text{का मूल्य} \end{array} \right]$$

या

$$\left[ \begin{array}{l} \text{MRP of Labour} \\ \text{(Under Perfect Competition)} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} \text{MPP of Labour} \times \text{Price of the} \\ \text{Product} \end{array} \right]$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{एकाधिकार के अन्तर्गत} \\ \text{श्रम की सीमान्त आय उत्पादकता} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} \text{श्रम का सीमान्त भौतिक उत्पाद} \times \text{भौतिक} \\ \text{उत्पाद के सीमान्त आय} \end{array} \right]$$

या

$$\left[ \begin{array}{l} \text{MRP of Labour} \\ \text{(Under Monopoly)} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} \text{MPP of Labour} \times \text{Marginal Revenue} \\ \text{from the Physical Product} \end{array} \right]$$

उक्त मर्म कारणों को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माननीय कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत एक फर्म में एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से किन्हीं वस्तु की 5 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन कम है जबकि मूल्य रु० 45 इकाइया उत्पादन की जाती थी। अतिरिक्त श्रमिक का लगाने पर कुल उत्पादन बढ़कर 10 इकाइया हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त या सीमान्त श्रमिक का उत्पादन 5 इकाइयों के बराबर है। अतः फर्म में श्रम की सीमान्त भौतिक उत्पादकता (MPP) वस्तु की 5 इकाइया है। माना कि वस्तु का प्रति-इकाई मूल्य 5 रुपये है। अतः श्रम के सीमान्त भौतिक उत्पाद का द्रव्य में मूल्य अर्थात् श्रम की सीमान्त आय उत्पाद  $5 \times 5 = 25$  रु० होगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य 5 रु० पर स्थिर रहता, चाहे फर्म वस्तु की 50 इकाइया उत्पादन कर अथवा 500।

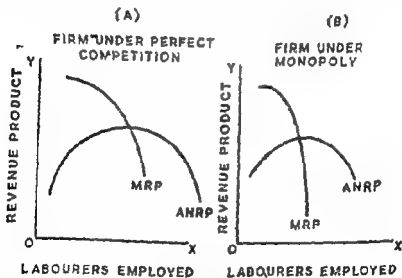
परन्तु एकाधिकार के अन्तर्गत फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य स्थिर नहीं रहता। वह उत्पादन-मात्रा में वृद्धि होने पर घटता है तथा उमम कम होने पर बढ़ता है। इसी कारण श्रम की MRP की गणना जटिल हो जाती है। मरका एम उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एकाधिकार फर्म वस्तु की 50 इकाइया उत्पादन करती है तथा प्रत्येक इकाई का मूल्य 5.25 रु० है। अब फर्म एक अतिरिक्त (सीमान्त) श्रमिक लगाती है जिसके फलस्वरूप फर्म के उत्पादन की मात्रा बढ़कर 55 इकाइया हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि श्रम का सीमान्त भौतिक उत्पाद (MRP) वस्तु की 5 इकाइयों के बराबर है। चूंकि फर्म की उत्पादन-मात्रा 50 इकाइयों से बढ़कर 55 इकाइया हो गयी है, इसलिए वस्तु का प्रति इकाई मूल्य 5.25 रु० पर स्थिर नहीं रहेगा। मान लीजिए कि वह

घटकर 5 रु० हो जाता है। ऐसी दशा में श्रम के सीमान्त आय उत्पाद (MRP) को इस प्रकार ज्ञात किया जायेगा।

$$(53 \times 5\text{रु०}) - (50 \times 5.25\text{रु०}) = 275 \text{ रु०} - 262.50 \text{ रु०} = 12.50$$

उक्त गणना से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा श्रम की सीमान्त इकाई को लगाने पर उसकी आय 12.50 रु० की शुद्ध (net) वृद्धि होती है। उस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे कि फर्म की उत्पादित वस्तु के मूल्य में कमी इस आधार पर की गयी है कि एकाधिकारी फर्म का औसत आय वक्र का ढाल एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के औसत आय वक्र की तरह एक पड़ी रेखा (horizontal) के रूप में न होकर नीचे की तरफ होता है।

इसका परिणाम यह होता है कि केवल एकाधिकारी फर्म का 'श्रम का सीमांत आय उत्पादकता (MRP) वक्र' (श्रम का मांग वक्र) पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के MRP वक्र की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है (Slopes downwards more rapidly) जैसा कि चित्र सं० 121 (a) और (b) में दिखाया गया है।



चित्र सं० 121

चित्र सं० 121 (a) तथा (b) से यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी फर्म का MRP वक्र पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के MRP वक्र की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि पूरा प्रतिस्पर्धी फर्म का औसत आय वक्र एक पड़ी रेखा (horizontal) के आकार का होता है, जबकि एकाधिकारी फर्म के औसत आय वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है।

(ii) पूर्ति पक्ष ( Supply Side ) : एकाधिकारी-नेता एकाधिकारी (monopolist monosonist) फर्म के श्रम का पूर्ति वक्र भी पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के श्रम के पूर्ति वक्र से मिलता होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के श्रम का पूर्ति वक्र एक सीधी पड़ी रेखा के आकार का होता है तथा उसकी मजदूरी रेखा भी क्षैतिज (horizontal) होती है। ऐसी फर्म के लिए मजदूरी की दर निश्चित रहती है तथा फर्म का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। परन्तु 'एकाधिकार-क्रेता-एकाधिकार' की स्थिति में यह स्थिति नहीं रहती। नेता एकाधिकारी होने के कारण फर्म ही श्रम का एक मात्र नेता होता है, जिस कारण वह श्रम के मूल्य (मजदूरी) को श्रम की खरीदी गयी मात्राओं को कम या अधिक करके प्रभावित कर सकता है। यदि वह अधिक श्रमिक लगाकर श्रम की मांग बढ़ा देता है तो मजदूरी बढ़ जायेगी। इसके विपरीत यदि वह कम श्रम में श्रमिक लगाता है और इस प्रकार श्रम की मांग को कम कर देता है तो मजदूरी कम हो जायेगी। इस प्रकार नेता एकाधिकारी के लिए मजदूरी घटती व बढ़ती रहती है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए, चाहे वह कितनी ही सत्यान श्रम लगाये, मजदूरी स्थिर रहती है।

पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए औसत मजदूरी तथा सीमान्त मजदूरी में कोई अन्तर नहीं होता, क्योंकि  $AW = MW$  तथा दोनों ही एक ही पड़ी हुयी रेखा (horizontal line) या मजदूरी रेखा (Wage line) द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परन्तु एक नेता एकाधिकारी के लिए औसत मजदूरी तथा सीमान्त मजदूरी में विशेष अन्तर होता है। दोनों ही एक-दूसरे में भिन्न होती हैं, तथा दोनों अलग-अलग वक्रों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इसका कारण यह है कि मजदूरी की कुल रकम को लगाये गये श्रमिकों की कुल सत्यान से भाग देन पर औसत मजदूरी ज्ञात होती है। इसके विपरीत सीमान्त मजदूरी एक अतिरिक्त मजदूरी को लगाने पर पूर्ण मजदूरी की कुल रकम में वृद्धि के बराबर होती है। इसको इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है :

$$\text{औसत मजदूरी (AW)} = \frac{\text{मजदूरी की कुल रकम (Total Wage-bill)}}{\text{लगाये गये श्रमिकों की सत्यान (Number of workers employed)}}$$

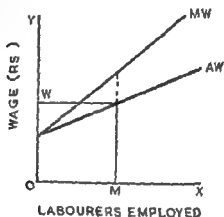
$$\text{सीमान्त मजदूरी (MW)} = \text{मजदूरी की कुल रकम में अतिरिक्त श्रमिक को नियुक्त करने पर वृद्धि}$$

(Addition to the Wage-bill when another labourer is employed)

सीमान्त मजदूरी औसत मजदूरी से अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह स्थिति उस स्थिति की ही तरह है जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर औसत लागत घटने लगती है तब सीमान्त लागत औसत लागत से अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है।

नेता-एकाधिकारी फर्म के लिए श्रम की पूर्ति की स्थिति चित्र स० 122म प्रदर्शित की गयी है।

औसत मजदूरी द्रव्य की उस मात्रा को व्यक्त करती है जो प्रत्येक श्रमिक को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर दी जाती है। उदाहरण के लिए जब  $OP$  श्रमिक लगाये जाते हैं तब प्रत्येक को मजदूरी के रूप में  $OW$  देने होंगे। अतः जब  $OM$



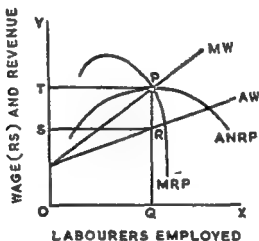
चित्र मस्या 122

श्रमिक रखे जाते हैं तब  $OM$  औसत मजदूरी प्रकट करता है। परन्तु जैसा कि चित्र स० 122 म दिखाया गया है रोजगार के इस स्तर पर सीमान्त मजदूरी औसत मजदूरी से अपेक्षाकृत अधिक है।

परन्तु यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि सीमान्त मजदूरी का अर्थ उग मजदूरी से नहीं है बल्कि सीमान्त श्रमिक को दी जाती है (चूंकि सभी श्रमिकों को एक समान मजदूरी दी जाती है)। इसका अभिप्राय एक प्रतिरिक्त श्रमिक लगाने पर कुल मजदूरी में वृद्धि से है। नेता-एकाधिकार के अंतर्गत, एक प्रतिरिक्त श्रमिक उसी स्थिति में लगाया जा सकता है, जबकि सभी श्रमिकों को ऊँची दर से मजदूरी दी जाती है। इसलिए फर्म द्वारा रखे जाने पर सीमान्त श्रमिक की मजदूरी कम मजदूरी में वृद्धि से अपेक्षाकृत कम होगी। अतः नेता-एकाधिकार के अंतर्गत, सीमांत मजदूरी वह औसत मजदूरी वह के ऊपर होगा, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत मजदूरी वह तथा सीमान्त मजदूरी वह एक ही होते हैं।

(iii) एकाधिकारी-नेता एकाधिकारी फर्म का समुत्पन्न (Equilibrium of the Monopolist-Monopsonist Firm) : 'एकाधिकारी-नेता एकाधिकारी' फर्म की समुत्पन्न की स्थिति ज्ञात करने के लिए श्रम के माँग तथा पूर्ति दोनों का चित्र स०

123 में एक माप मिलाकर प्रदर्शित किया गया है। श्रम की माग व पूर्ति में फर्म उस समय संतुलन प्राप्त करती है, जब कि श्रमिकों की OQ सत्या काम में लगायी जाती है, क्योंकि रोजगार के इस स्तर पर श्रम की MRP सीमान्त मजदूरी MW के बराबर होती है। ये दोनों PQ के बराबर हैं। रोजगार के OM स्तर पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। परन्तु लाभ को अधिकतम करते समय फर्म असामान्य लाभ (abnormal profit) भी अर्जित करती है, क्योंकि रोजगार के इस स्तर पर औसत शुद्ध आय उत्पाद (ANRP) औसत मजदूरी से ऊँची है। OQ



चित्र सख्या 123

रोजगार स्तर पर ANRP, PO है तथा औसत मजदूरी RQ है, जिससे प्रति मजदूर PR के बराबर अधिकार्य (Surplus) है। इस प्रकार OQ श्रमिकों से कुल अधिकार्य (Total Surplus) PR  $\times$  OQ या SR अथवा PRST आय के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह आयत उस असामान्य लाभ को प्रकट करता है जो केना एकाधिकारी फर्म का श्रम में उत्पन्न अधिकार्य के कारण प्राप्त होता है। इसके विपरीत पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म को इस प्रकार का असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी मजदूरी रखा (जो औसत मजदूरी रखा भी है) ANRP वक्र की स्पर्श रखा होती है, जिससे उनकी औसत मजदूरी उसके ANRP के बराबर होती है।



पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म तथा एकाधिकारी-क्रेता-एकाधिकारी फर्म में अन्तर

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत	एकाधिकार-क्रेता एकाधिकार के अन्तर्गत
1. बस्तु का मूल्य दिशा रहता है।	1. मूल्य उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। उत्पादन मात्रा में कमी होने पर मूल्य बढ़ता है, जबकि वृद्धि होने पर मूल्य कम हो जाता है।
2. सीमान्त आय उत्पाद में तंत्र गति में कमी नहीं आती।	2. उक्त कारण से इस स्थिति में $MRP$ अघातन तंत्रों में नीचे की ओर गिरता है।
3. सीमान्त मजदूरी वक्र तथा सीमान्त मजदूरी वक्र एक ही होते हैं। वेना एक ही क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है।	3. सीमान्त मजदूरी वक्र सीमान्त मजदूरी वक्र से पूर्णतः अलग होता है। सीमान्त आय वक्र ऊपर बाहिनी ओर ऊपर की तरफ उठता हुआ होगा तथा सीमित मजदूरी वक्र के ऊपर होगा।
4. फर्म के मनुष्य की स्थिति में श्रम का $MRP =$ सीमान्त मजदूरी, तथा $MW = AW$	4. सीमान्त मजदूरी सीमान्त मजदूरी से ऊंची होती है, अतः श्रम का $MRP$ भी सीमान्त मजदूरी से अधिक होता है।
5. उत्पाद बाजार में $MW =$ श्रम का $MRP$ [चूंकि श्रम का सीमान्त आय उत्पाद श्रम के सीमान्त मौलिक उत्पाद के मूल्य के बराबर होता है, इसलिए सीमान्त मजदूरी भी श्रम के सीमान्त मौलिक उत्पाद के मूल्य के बराबर होती है।]	5. उत्पाद बाजार में (एकाधिकार की स्थिति में) श्रम का सीमान्त आय उत्पाद श्रम के सीमान्त मौलिक उत्पाद के मूल्य से कम होता है।

### एकाधिकृत शोषण (Monopolistic Exploitation) :

उपयुक्त विवेचन में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक ऐसी फर्म जो उत्पाद बाजार में एकाधिकारी है तथा साधन बाजार में क्रेता-एकाधिकारी है दो तरीकों से लाभ उठाती है। वह उत्पाद-बाजार में उन्मुखताओं का तथा माघन-बाजार में साधनों का पापण कर सकती है। उत्पाद बाजार में एकाधिकारी फर्म सीमान्त लागत से कहीं अधिक उच्च सीमान्त आय (या मूल्य) निर्धारित कर सकती है तथा अनामत लाभ प्राप्त कर सकती है। साधन (घन) बाजार में क्रेता-एकाधिकारी फर्म द्वारा श्रमिकों को दी गयी मजदूरी श्रम के सीमित शुद्ध मान उत्पाद ( $ANRP$ ) से कम होती है। इस प्रकार श्रम बाजार में भी फर्म दो लाभ ही होता है। यदि यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी-क्रेता एकाधिकारी फर्म को उत्पाद या माघन, दोनों ही बाजारों में लाभ प्राप्त होता है। ऐसी फर्म की इस विशेषता को ही अर्थ-शास्त्रियों ने 'एकाधिकृत शोषण' कहा है।

## सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की मान्यताएं (Assumptions of the Marginal Productivity Theory) :

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

(1) उत्पादक साधनों की उत्पादकता का अनुमान लगा सकता है तथा उत्पादकता की माप भी कर सकता है।

(2) उत्पादन-साधनों के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है तथा अधिकतम लाभ बिन्दु ज्ञात करने के लिए साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है।

(3) इस सिद्धान्त को पूर्ण स्पर्धा की दशाओं को मानकर प्रतिपादित किया गया है। पूर्ण स्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादन साधन को सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है।

(4) उत्पादन साधनों तथा उनकी विभिन्न इकाइयों के एक रूप होने के कारण वे इकाइया समान रूप से कुशल होती हैं तथा पूर्ण रूप में स्थानापन्न (Substitutes) होती हैं और उन्हें एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(5) उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील है।

(6) यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से दीर्घकाल में लागू होता है, अर्थात् साधनों का पारिश्रमिक उनकी सीमान्त उत्पादकता से कम या अधिक नहीं हो सकता है।

(7) दीर्घकाल में उत्पादन-प्रक्रिया में उत्पादन समता नियम लागू होता है।

(8) पूर्ण रोजगार (Full employment) सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार के कारण ही साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त होता है।

(9) यदि साधनों को उनकी 'सीमांत उत्पादक' के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए, तो 'कुल उत्पाद' उनमें पूर्णतया बंट जाता है।

## सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचनाएं (Criticisms of the Marginal Productivity Theory) :

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की कई आलोचनाएं की गई हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

(1) उत्पादन विभिन्न साधनों के सम्मिलित सहयोग एवं प्रयोग का परिणाम है, अतः प्रत्येक साधन तथा उसकी इकाइयों की उत्पादकता ज्ञात करना अशक्य है फिर भी 'सीमांत विश्लेषण' तथा 'सीमांत आय उत्पाद' विश्लेषण द्वारा सीमान्त उत्पादकता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(2) यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक साधन की मात्रा में अपरिवर्तनीय सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। परन्तु उत्पादन के बड़े तथा अविभाज्य (Lumpy and Indivisible) माध्यमों के सम्बन्ध में यह मान्यता गलत सिद्ध होना है।

(3) यह सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि उत्पादक का उद्देश्य केवल लाभ को अधिकतम करना होता है, परन्तु प्रत्येक उत्पादक का यही उद्देश्य नहीं होता है। व्यावहारिक दृष्टि से उत्पादक विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखता है।

(4) इस सिद्धान्त को पूर्ण-स्पर्धा की दशाओं को मानकर बनाया गया है, परन्तु वास्तविक जीवन में पूर्ण स्पर्धा नहीं पाई जाती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त काल्पनिक है। (चेम्बरलिन ने यह मत व्यक्त किया है कि यह सिद्धान्त अपूर्ण स्पर्धा में भी लागू होता है। अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत प्रत्येक साधन का पारिस्थितिक 'सीमान्त आय उत्पाद' का बराबर होना है।)

(5) यह सिद्धान्त पूर्ण पक्ष की उपस्था करता है (सिद्धान्त के प्राचीन रूप में)। साधन की मात्रा उनकी सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर है, परन्तु मूल-निष्पाद्य मान गया पूर्ण दानों के सम्मिलित प्रभावों से होता है।

(6) सिद्धान्त की 'उत्पादन समता नियम' सम्बन्धी मान्यता भी दोषपूर्ण है। यह सिद्धान्त 'उत्पादन वृद्धि नियम' तथा 'उत्पादन ह्रास नियम' की अवस्था में लागू नहीं होता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में उत्पादन इन्हीं अन्तर्गत दो नियमों के अनुसार किया जाता है। 'उत्पादन समता नियम' एक प्रकार में अपवाद के रूप में ही लागू होता है। 'उत्पादन वृद्धि नियम' के अनुसार आ रहे उत्पादन की अवस्था में यदि साधनों का उसकी 'सीमान्त उत्पादकता' के अनुसार पारिस्थितिक दिया जाए तो उत्पादक का हानि उठानी पड़ेगी। धीमेरी जोन रॉबिन्सन ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन की मित्यन्विताएँ प्राप्त हो रही हैं तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में धर्म की 'सीमान्त भौतिक उत्पादकता' (MPP) फर्म की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि एक फर्म द्वारा रोजगार में की गई वृद्धि से दूसरी की कार्यक्षमता बढ़ती है।<sup>4</sup> इस प्रकार उद्योग में 'सीमान्त उत्पादकता' फर्म से अधिक होती है (उत्पादन वृद्धि नियम की अवस्था में) तथा यदि साधनों को उद्योग की सीमान्त उत्पादकता के अनुसार नुस्तान किया जाता है तो भुत्तान की दूरी में विभिन्नता होगी तथा साधनों का वाजार अक्षान्त हो जाएगा।

<sup>4</sup> When there are economies of large scale industry the marginal physical productivity of labour to a competitive industry will be greater than the individual firms, since an increment of employment given by one firm will enhance the efficiency of others."

(7) हॉब्सन (Hobson) ने कहा है कि विभिन्न साधनों के प्रयोग का अनुपात प्राविधिक दशाओं के अनुसार निश्चित किया जाना है, तथा उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परन्तु यह आलोचना निराधार है। साधनों के अनुपात में वस्तुतः परिवर्तन किया जाता है।

(8) आर्थिक विपमता को उचित ठहराने के लिए इस सिद्धान्त की शरण ली जाती है तथा यह कहा जाता है कि साधनों की सीमान्त उत्पादकता में विभिन्नता के कारण उनकी माँग में विभिन्नताएँ पैदा होती हैं, परन्तु यह धारणा 'व्यक्तिगत वितरण' तथा 'क्रियात्मक वितरण' में भेद नहीं करती है। आर्थिक विपमता का कारण योग्यता का अन्तर नहीं अपितु सम्पत्ति तथा शोषण भी है। आर्थिक विपमता को उत्पादकता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त एक अपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त की आलोचना जोन रॉबिन्सन, टाजिग, पीगू, जे० आर० हिब्स, हॉब्सन तथा फ्रेजर आदि प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा की गई है। फ्रेजर ने कहा है, "कोई भी अर्थशास्त्री यह दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकता है कि सिद्धान्त अब भी पूर्ण है। चूँकि यह परल और दृढ़ है, अतः यह अनूत तथा अव्यक्तिक है। यह अपूर्ण है, इसकी मान्यताएँ अनावश्यक रूप से दृढ़ तथा संकुचित हैं।"<sup>5</sup>

यह सिद्धान्त बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अत्यन्त ही मान्य था परन्तु अब यह सिद्धान्त अपूर्ण माना जाता है। यह दृष्टिगत (Micro) परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसे समष्टियुक्त बनाने की आवश्यकता है।

### वितरण का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Distribution)

वितरण व आधुनिक सिद्धान्त को 'माग व पूर्ति सिद्धान्त' भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन साधनों का पारिस्थानिक वस्तुओं के मूल्य की नाति माग व पूर्ति की सम्मिलित शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न साधनों की माग तथा पूर्ति की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं अतः मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के सम्बन्ध में भ्रम-भ्रम सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। फिर भी कुछ सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं।

(1) साधनों की माग - किसी भी साधन की माग उसकी सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर है। जब तक किसी साधन की सीमान्त उत्पादकता उसके मूल्य से

<sup>5</sup> "No economist would claim that the theory is as yet complete.....Being simple and self consistent it is abstract and impersonal. It is guilty of both omission and commission, its postulates are unduly rigid and narrow."

अधिक है, उत्पादन उस साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाएगा। कुल उत्पादन उस बिन्दु पर अधिकतम होता है, जिस पर साधन का मूल्य उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा। कोई भी उत्पादक किसी भी साधन को उसकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक परिधमिक नहीं देगा। अतः पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत साधन का पारिधमिक उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा।

(ii) साधनों की पूर्ति : वस्तुओं की पूर्ति उनकी उत्पादन लागत पर निर्भर होती है। उत्पादन साधनों की पूर्ति भी उनकी लागत पर निर्भर है, परन्तु यहाँ पर 'लागत' का अभिप्राय 'मौद्रिक लागत' या 'वास्तविक लागत' से नहीं है, बल्कि अवसर लागत से है। उत्पादन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, अतः साधनों को पारिधमिक के रूप में कम से कम उनकी आय प्राप्त होनी चाहिए जितनी वह वैकल्पिक प्रयोगों में प्राप्त कर सकता है। इससे कम पारिधमिक देने पर साधन अन्यत्र चला जाएगा। अतः किसी भी साधन का पूर्ति मूल्य उसे वैकल्पिक प्रयोगों में प्राप्त होने वाली आय के बराबर होना चाहिए।

(iii) पारिधमिक वितरण : वितरण के 'माग-पूर्ति' सिद्धान्त के अनुसार, पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत किसी उत्पादन साधन का पारिधमिक उसकी माग तथा पूर्ति पर निर्भर है। माग, साधन की सीमान्त उत्पादकता (MP) तथा पूर्ति उस साधन की 'अवसर लागत' निर्भर है। माध्य की अवस्था में सीमान्त उत्पादकता तथा अवसर लागत समान होती हैं तथा इसी बिन्दु पर साधन का पारिधमिक निश्चित होता है।

(vi) साम्यताएं वितरण का 'माग व पूर्ति' सिद्धान्त निम्नलिखित सान्य-ताओं पर आधारित है — (1) प्रत्येक उत्पादन-साधन पूर्णतया विभाजनीय है। (2) साधनों के सम्बन्ध में 'प्रतिस्थापन नियम' पूर्ण रूप से लागू होता है। (3) उत्पादन-साधन की विभिन्न इकाइयों में एकरूपता पाई जाती है तथा वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न (Substitutes) होते हैं।

### प्रश्न व संकेत

1. वितरण के सीमांत उत्पादनशीलता सिद्धान्त की सभ्यताएं। इन सिद्धान्त के मुख्य दोषों को बताइये। (Raj. T.D.C. Arts, Final, 1966)

[संकेत पढ़ने माग में सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए और उसकी व्याख्या करें। द्वितीय भाग में इस सिद्धान्त की आलोचनाएं लिखिए।]

2. किसी साधन का मूल्य एवं और तो उसकी सीमांत उत्पादकता तथा दूसरी ओर साधन के रमाण द्वारा निर्धारित होता है। इस कथन की विवेचना करें।

(Agra B. Com. II, 1962)

[संकेत—इस कथन को समझाने के लिए साधन के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियों अर्थात् 'माग' और 'पूर्ति' के प्रभावों को समझाये और अन्त में निष्कर्ष लिखिए ।]

3 "वितरण का सिद्धान्त मूल्य के सिद्धान्त की ही एक विशेष दशा है," विवेचना करिये ।

[संकेत—प्रथम भाग में समझाइये कि साधन का मूल्य भी वस्तु के मूल्य के सिद्धान्तों पर ही निर्धारित होता है—(देखिए प्रश्न संकेत 2) तथा इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए रेखाचित्र देकर सिद्ध कीजिए कि वितरण का सिद्धान्त मूल्य के सिद्धान्त की ही एक विशेष दशा है ।]

### समस्याएँ (Problems)

1. किसी फर्म के उत्पादन (Product) तथा एक उत्पादन साधन (Factor of Production) की मात्राओं का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाली एक ग्राहिका बनाइये जिसमें सीमांत मूल्य उत्पाद (M. P P.) दर की गणना करिए । इस उत्पाद की माग रेखा खींच कर सीमांत मागम उत्पाद (M.R.P.) की गणना करिए । वस्तु व साधन के मूल्य काल्पनिक मानते हुए बताइये कि फर्म इसमें अधिक या कम उत्पादन साधन की माग प्रयुक्त नहीं करेगी ?

2. मान लीजिए एक एकाधिकारी किसी श्रम सघ के कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु निर्धारित दर से अधिक दर पर पारिश्रमिक प्रदान करता है । साथ ही, यह भी मान लीजिए कि उत्पादक साम्य मात्रा (Equilibrium Quantity) से अधिक मात्रा में श्रमिका का लगाता है । इन पूर्व धारणाओं (assumptions) के आधार पर बताइये कि :

(अ) अल्पकालीन स्थिर लागतों, परिवर्तनशील लागतों तथा सीमांत लागतों पर इस नीति का क्या प्रभाव होगा ?

(ब) फर्म के अल्पकालीन 'उत्पाद व कीमत साम्य' पर क्या प्रभाव होगा ?

(स) यदि फर्म प्रतियोगी फर्म ही एवं अन्य फर्म भी प्रतियोगी फर्मों के रूप में श्रम सघ से व्यवहार करें तो अल्पकाल व दीर्घकाल में इस फर्म के 'उत्पाद' व 'कीमत साम्य' पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(द) यदि प्रतियोगी फर्म अकेली ही उद्योग में हो (उद्योग की यह फर्म श्रम सघ से सम्पर्क रखे हुए हो) तो अल्पकालीन व दीर्घकालीन व दीर्घकाल 'उत्पाद कीमत साम्य' पर क्या प्रभाव होगा ?

# 34

## लगान (Rent)

*"The difference between price and cost of production on infra marginal land is the Ricardian rent the present way of interpreting the rent concept leads to regarding rent as a surplus accruing to any unit of a factor of production over and above the income just necessary for keeping that unit in its occupation"*

—William Fellner

### 1 लगान का अर्थ (Meaning of Rent)

साधारण बोल चाल की भाषा में लगान (Rent) शब्द का अन्वय उस भुगतान से है जो किसी मकान, दुकान, खेत, यंत्र आदि के प्रयोग के बदले में उनका स्वामी को दिया जाता है। परन्तु अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय में केवल भूमि (Land) के प्रयोग के बदले में किय गये भुगतान को लगान कहते हैं।

लगान सम्बन्धी विचार सबसे पहले निर्वाधावादी (Physiocrats) अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था। उनका अनुसार लगान एक ऐसी वस्तु है जो कृषि उत्पादन से प्रकृति को दया के कारण प्राप्त होती है। एडम स्मिथ ने भी इस विषय पर कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया था। उन्होंने इसे एक ईश्वरीय दान बताया था। माल्थस ने भी लगान को प्रकृति की उदारता का परिणाम माना था। रिकार्डो (Ricardo) प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान के सम्बन्ध में अपना निश्चित तथा व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया। उनका अनुसार "लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले में दिया जाता है।" <sup>1</sup> मीनियर के अनुसार "किसी प्रकृति दान साधन के प्रयोग से

<sup>1</sup> "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"

—David Ricardo

प्राप्त की गयी अतिरिक्त उपज ही लगान है (Rent is the surplus arising from the use of an appropriated natural agent) । कार्वर (Carver) ने भी भूमि के प्रयोग के बदले में दिये जाने वाले मूल्य को लगान माना है (Rent is the price paid for the use of land) । मार्शल के अनुसार भी "भूमि तथा अन्य प्रकृति-दत्त उपहारों के स्वामित्व के कारण प्राप्त आय को लगान कहते हैं।"<sup>2</sup>

लगान की उपर्युक्त परिभाषाओं में इन शब्द का प्रयोग भूमि (Land) तथा अन्य प्रकृति-दत्त उपहारों (free gifts of nature) में प्राप्त आय के सम्बन्ध में ही किया गया है । परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री लगान शब्द का प्रयोग इस संकुचित अर्थ में नहीं करते । उनके अनुसार लगान उत्पादन के किसी भी साधन (factor) को, यदि उनकी पूर्ति पूर्ण रूप से लोचदार (perfectly elastic) नहीं है, प्राप्त हो सकती है । आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान की सही व्याख्या 'अल्पता के सिद्धान्त' (Principle of Scarcity) पर आधारित होनी चाहिए । उत्पादन का प्रत्येक साधन अल्प (scarce) है और उसकी भाग अलग-अलग उपयोगों के लिए की जा सकती है । स्वयं भूमि का प्रयोग कृषि, मकान बनाने, उद्योग-वन्धे स्थापित करने, दूकान खोलने आदि के लिए किया जा सकता है । परन्तु भूमि की पूर्ति सीमित एवं अल्प तथा पूर्णतया बेलोचदार होने के कारण, उसे उत्पादक कार्य में बनाये रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से जो अधिक आय प्राप्त होती है, उसे लगान कहते हैं । प्रो० बौलडिंग (Prof Boulding) के अनुसार "किसी भी उत्पादन के साधन की एक इकाई को उसे वर्तमान उत्पादन-कार्य में बनाये रखने के लिए जो न्यूनतम रकम देना आवश्यक होता है, उससे अधिक जो भी भुगतान किया जाता है, उसे लगान कहा जाता है।"<sup>3</sup> श्रीमती जोन राबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार, 'लगान की धारणा का तत्त्व उस आधिपत्य की धारणा से है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई को उस उत्पादन-कार्य में बनाये रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से अधिक है।'<sup>4</sup> इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का तत्त्व उत्पादन के सभी

<sup>2</sup> 'The income derived from the ownership of land and other free gifts of nature is called rent' —Marshall.

<sup>3</sup> "Economic rent may be defined as any payment to a unit of any factor of production which is in excess of the minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation"

—Boulding.

<sup>4</sup> "The essence of the conception of the rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earning necessary to induce it to do its work"

—Mrs Joan Robinson.



साधनो के पुरस्कार-मजदूरी, व्याज, लाभ-मे माना है और भूमि के लगान को एक बड़ी जाति की उप-जाति माना है (*Rent is a species of a large genus*) ।

## 2 लगान के सिद्धान्त (Theories of Rent)

लगान-निर्धारण के दो प्रमुख सिद्धान्त है : (i) प्रतिष्ठित या रिकार्डों का लगान सिद्धान्त (Classical or Ricardian Theory of Rent) तथा (ii) लगान का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Rent) ।

### (1) रिकार्डों का लगान-सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent) :

डेविड रिकार्डो (David Ricardo) प्रथम प्रयोज्ञात्मी थे जिन्होंने लगान के सम्बन्ध मे निश्चित एवं व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया । लगान का क्या और कैसे उदय होता है ? इसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपने लगान के सिद्धान्त मे किया है । उन्होंने उत्पादन के साधन के रूप मे भूमि की विशेषताओं को ध्यान मे रखकर लगान के सिद्धान्त का प्रतिपादन भूमि के सदस्र मे ही किया है । उन्होंने अपने सिद्धान्त मे यह निष्कर्ष निवाला है कि लगान एक प्रकार का अन्तरभूतक लाभ या आधिक्य है (*Rent is a differential surplus*) । यह लाभ या आधिक्य भूमि की कुछ विशेषताओं के कारण ही उदय होता है । ये विशेषताएँ हैं : (i) भूमि का सीमित होना : भूमि की उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा बढ़ायी नहीं जा सकती । अधिक से अधिक, गहरी खेती द्वारा भूमि की बड़ी हुयी मांग की आर्थिक पूर्ति की जा सकती है । (ii) भूमि गतिशील नहीं है । भूमि का एक टुकड़ा अपने स्थान से हटाकर कहीं और नहीं भेजा जा सकता । (iii) भूमि की उर्वराशक्ति मे भिन्नता होती है । भूमि के सभी टुकड़े एक ही तरह उपजाऊ नहीं होते ।

सिद्धान्त की व्याख्या . रिकार्डों ने लगान की परिभाषा इस प्रकार दी है . 'लगान भूमि के उत्पादन का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है ।' इस प्रकार रिकार्डों ने अपने सिद्धान्त मे निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला :

(1) लगान एक प्रकार का अन्तरभूतक लाभ है (*Rent is a differential gain*) . रिकार्डों के अनुसार, 'लगान अधिकतमोत्पन्न तथा सीमान्त भूमि की उपजो का अन्तर है' (*Rent is the excess of the yield of a superior piece of land, i.e. super-marginal land over that of a marginal land*) । रिकार्डों का कहना था कि सीमान्त भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमि पर आय तथा उत्पादन-लागत का अन्तर अधिक होगा तथा यह अन्तर ही 'आर्थिक लगान' (Economic Rent) कहा जायेगा ।

उदाहरण : रिकार्डों ने उक्त तथ्य को स्पष्ट करन के लिए एक ऐसे द्वीप का

उदाहरण प्रस्तुत किया है जहाँ अभी तक कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। वहाँ भूमि का प्रयोग न होने के कारण भूमि निशुल्क होगी। अब यदि कुछ लोग उस द्वीप पर आकर बसने लगे तो वे सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि के टुकड़े, जो प्रथम श्रेणी की भूमि (A-Grade land) कहें जायेंगे, पर कृषि करना प्रारम्भ करेंगे। कुछ समय के बाद जनसंख्या में वृद्धि होने पर जब खाद्यान्न की मांग में वृद्धि होगी, तब प्रथम श्रेणी की भूमि से कम उपजाऊ, द्वितीय श्रेणी (B Grade land) की भूमि पर खेती की जाने लगेगी। इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के साथ निम्न से निम्न कोटि की (द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी) की भूमि पर खेती की जाने लगेगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि लगान किन स्थितियों में किस प्रकार उदय होता है? उक्त उदाहरण में एक नये द्वीप में लोगों के द्वारा खेती के लिए भूमि का प्रयोग किये जाने पर प्रारम्भिक अवस्था में लगान के उदय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु जनसंख्या के बढ़ने पर द्वितीय श्रेणी की भूमि का प्रयोग उसी समय किया जायगा जबकि उत्पादन से प्राप्त आय उत्पादन की लागत (श्रमिकों की सहाय्य मजदूरी तथा पूँजी के माध्यम से लाभ) के बराबर होगी। यदि इस श्रेणी की भूमि के उत्पादन से उत्पादन लागत प्राप्त हो जाती है, तो वह सीमान्त भूमि (Marginal or no rent land) कहें जायेंगी। चूँकि वस्तु बाजार में भूमि में प्राप्त एक प्रकार की उपज का एक ही मूल्य होता है, अतः प्रथम श्रेणी की भूमि से प्राप्त उत्पादन की आय में से उत्पादन लागत की पूर्ति करने के पश्चात् कुछ आय या लाभ अवश्य रहेगा। यह लाभ या आधिक्य ही प्रथम श्रेणी की भूमि का अन्तरमूल्य लाभ या लगान है।

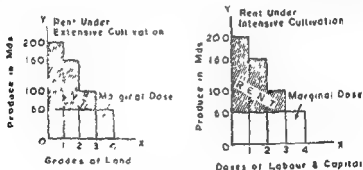
इसी प्रकार तीसरी, चौथी और उनके बाद की श्रेणी की भूमि से प्राप्त उत्पादन की आय तथा उन पर उत्पादन लागत की तुलना करके यह देखा जायगा कि किस श्रेणी की भूमि से प्राप्त उत्पादन की आय उत्पादन लागत से कम होती है। जिस श्रेणी की भूमि से प्राप्त उपज द्वारा उत्पादन लागत का भुगतान भी नहीं किया जा सकता, उस भूमि पर खेती नहीं की जायगी। माना कि ऐसी भूमि पाँचवीं श्रेणी की है। अतः चौथी श्रेणी की भूमि ऐसी होगी जिसकी उपज में प्राप्त आय उत्पादन लागत के बराबर होगी तथा वह सीमान्त या लगान-हीन भूमि होगी। इस श्रेणी की भूमि के ऊपर तीसरी, दूसरी तथा पहली श्रेणी की भूमि यदि सामान्य (Super marginal or superior piece of land) भूमि होगी, क्योंकि उनकी उपज से प्राप्त आय में से उत्पादन लागत की पूर्ति करने के बाद कुछ लाभ या आधिक्य बच रहेगा, जैसा कि पृष्ठ 654 पर दायाँ तालिका में स्पष्ट किया गया है।

## विस्तृत खेती में लगान

भूमि की श्रेणी	प्रति एकड़ उत्पादन	लगान
पहली	200 मन	$200-60=140$ मन
दूसरी	160 मन	$160-60=100$ मन
तीसरी	100 मन	$100-60=40$ मन
चौथी	60 मन	$60-60=0$ सीमान्त भूमि
पाचवी	40 मन	$40-60=-20$ मन

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि पाचवी श्रेणी की भूमि पर खेती नहीं की जायेगी, क्योंकि उत्पादन लागत 60 मन के बराबर है जबकि उपज 40 मन ही है। चौथी श्रेणी की भूमि पर उपज (60 मन) उत्पादन लागत (60 मन) के बराबर है, अतः यह सीमांत भूमि होगी। इसके पहले की भूमि तीसरी, दूसरी तथा पहली श्रेणियाँ अधिकीकृत हैं जिन पर क्रमशः 40, 100 और 140 मन का प्रतिरिक्त या अन्तर मूलक लाभ (differential gain) प्राप्त हो रहा है।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण : उपर्युक्त मन्थनों को नीचे दिये रेखाचित्र में भी स्पष्ट किया गया है। OX—आधार रेखा पर भूमि की श्रेणियाँ (units) दिखलायी गयी हैं तथा OY—बड़ी रेखा पर भूमि से प्राप्त उपज। प्रत्येक आयत प्रत्येक श्रेणी



चित्र संख्या 124

की भूमि की उपज को व्यक्त करता है। चौथी श्रेणी की भूमि सीमान्त भूमि है, क्योंकि उसकी उपज उत्पादन-लागत के बराबर है। चूँकि प्रत्येक श्रेणी की भूमि की उपज की उत्पादन-लागत समान होगी, अतः प्रत्येक की उपज में से सीमान्त भूमि से बराबर उपज निम्नलिखित देने पर प्रत्येक श्रेणी की उपज को व्यक्त करने वाले आयत में जो वाला भाग (shaded portion) शेप रहता है, वही उस श्रेणी की भूमि का लगान है।

2. गहरी खेती के अन्तर्गत लगान रिफार्डों के अन्तर्मूलक लाभ या लगान की उपर्युक्त व्याख्या विस्तृत खेती के सम्बन्ध में की थी। परन्तु इसका अध्ययन गहरी खेती के अन्तर्गत भी किया जा सकता है। गहरी खेती के अन्तर्गत अन्तर्मूलक लाभ या लगान को Rent under intensive cultivation or Rent with intensive margin कहा है।

गहरी खेती के अन्तर्गत विस्तृत ही घटिया किस्म की भूमि पर खेती नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में गहन खेती द्वारा अच्छी भूमि के टुकड़े पर ही श्रम तथा पूँजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करके, कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है। परन्तु भूमि को स्थिर रखकर, अन्य साधनों में वृद्धि करके उत्पादन करने से उत्पादन हानि नियम लागू होना लगता है। पूँजी तथा श्रम की मात्राओं में वृद्धि करने पर प्रारम्भ में सीमांत उपज बढ़ती। बाद में एक बिन्दु ऐसा आएगा जिस पर सीमांत उपज उत्पादन लागत के बराबर होगी। इस बिन्दु में पहले की श्रम तथा पूँजी की प्रत्येक इकाई में उत्पादन लागत की अपेक्षा अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, अर्थात् श्रम व पूँजी की सीमांत इकाई के पहले की सभी इकाइयों रिफार्डों के अनुसार लगान प्रदान करेंगे, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका तथा चित्र सं० 124 में स्पष्ट है :

गहन खेती में लगान

श्रम व पूँजी की इकाइयाँ	प्रति एकड़ उत्पादन	लगान
पहली इकाई (dose)	200 मन	$200-60=140$
दूसरी " "	160 मन	$160-60=100$
तीसरी " "	100 मन	$100-60=40$
चौथी " "	60 मन	$60-60=0$
		सीमांत इकाई

3. खेतों की स्थिति तथा लगान (Location of fields and rent) : खेतों की स्थिति में अन्तर होने के कारण भी लगान उदय होता है। कुछ खेत, गांव, शहरों व उपज बाजारों के निकट तथा कुछ उनसे दूर होते हैं। जो खेत गांव, शहर या बाजार के नजदीक होते हैं, उनकी उपज को ढाने आदि पर किया गया व्यय (transport charges) कम होता है, तथा जो खेत बाजार से दूर होते हैं, उन पर किया गया मार्ग-व्यय अधिक होता है। ऐसी स्थिति में बाजार के निकट स्थित खेत से प्राप्त उदज से अन्तर्मूलक लाभ या लगान प्राप्त होता है, जबकि बाजार से अपेक्षाकृत दूर स्थित खेतों से कम लाभ प्राप्त होगा अथवा उपज का मूल्य मार्ग व्यय तथा उत्पादन-व्यय के योग के बराबर होने पर वह भूमि लगान हीन भूमि होगी।

उदाहरण माना कि तीन खेत A, B व C हैं। A खेत बाजार से 2 मील और B तथा C खेत क्रमशः 8 और 12 मील की दूरी पर स्थित हैं यह भी मान लिया गया है कि प्रत्येक खेत की उपज का उत्पादन-व्यय 110 रु० है तथा प्रति मन उपज का मूल्य 40 रु० है। अब यदि प्रत्येक खेत पर क्रमशः 10, 8 तथा 4 मन उपज प्राप्त होती है तथा मार्ग व्यय क्रमशः 20 रु०, 30 रु० व 50 रु० है, तो स्थिति के अन्तर के कारण अन्तरमूलक लाभ नीचे दी गयी तालिका के अनुसार ज्ञात किया जायगा।

स्थिति के अन्तर के कारण लगान

खेत	दूरी मील	उपज मन म	उपज का मूल्य रु०	कुल व्यय			अन्तरमूलक लाभ या लगान रु०
				उत्पादन व्यय	मार्ग व्यय	योग	
				रु०	रु०	रु०	
A	2	10	400	110+	20=	130	400-130=270
B	8	8	320	110+	30=	140	320-140=180
C	12	4	160	110+	50=	160	160-160= 0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि C खेत बाजार से अपेक्षाकृत दूर होने के कारण लगानहीन भूमि है, क्योंकि उत्पादन व्यय+मार्ग-व्यय (160 रु०) उपज मूल्य (160 रु०) के बराबर है, जबकि A व B खेतों के बाजार के अपेक्षाकृत निकट होने के कारण उनसे प्राप्त उपज का मूल्य कुल व्यय (उत्पादन व्यय+मार्ग व्यय) से अधिक है (क्रमशः 270 रु० तथा 180 रु०)। यह आधिनय ही A व B खेतों का अन्तरमूलक लाभ या लगान है।

## (ii) सिद्धान्त के मुख्य तत्व

रिकाडों के लगान सिद्धान्त के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं

1. लगान प्रकृति की कृपणता के कारण उत्पन्न होता है (Rent is due to the niggardliness of Nature) : 'अन्तरमूलक लाभ' उभी समय प्राप्त होता है जबकि निम्न कोटि की भूमि पर खेती की जाए। यदि सभी भूमि एक ही प्रकार की तथा उत्तम थोड़ी की हो तो लगान का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मन लगान की समस्या इसलिए उठती है कि अच्छी विस्म की भूमि यथेष्ट सीमा तक उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार लगान प्रकृति की उदारता नहीं बल्कि उसकी कृपणता के कारण उत्पन्न होता है।

2. लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों का प्रतिफल है। रिकाडों ने लगान की परिभाषा में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भूमि की मौलिक

तथा अविनाशी शक्तियों अर्थात् भूमि के विभिन्न टुकड़ों के उपजाऊपन में भिन्नता होने के कारण ही लगान उत्पन्न होता है। यदि भूमि के सभी टुकड़ों पर पूँजी और श्रम की समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तो जो भूमि जितनी ही अधिक उपजाऊ होगी उस भूमि का लगान उतना ही अधिक होगा।

3 लगान अनुपाजित आय है (Rent in Unearned Income) : लगान भूमि के प्रयत्नों का फल नहीं है। लगान, उपज का बाजार मूल्य उत्पादन लागत से अधिक होने के कारण प्रकट होता है। अतः यह एक अनुपाजित आय है। लगान कम होने पर, भूमि की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

4 वास्तविक लगान की प्रवृत्ति आर्थिक लगान के बराबर होने की होती है (Actual Rent tends to equal Economic Rent) रिकार्डों के अनुसार लगान अन्तरमूलक लाभ है। ऐसी स्थिति में भूमि का स्वामी किसान से इस अन्तरमूलक लाभ, अर्थात् कुल उपज से प्राप्त आय तथा कुल उत्पादन व्यय के अन्तर, की मांग कर सकता है। पूर्ण स्पर्धा में किसान को इस अन्तर के बराबर लगान देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका भुगतान कर देने पर किसान को कोई हानि नहीं होती है। लगान का भुगतान कर देने के बाद भी उसका पास उत्पादन लागत के बराबर आय बच रहती है, जिसमें उसका सामान्य लाभ भी सम्मिलित रहता है। अतः वास्तविक लगान की प्रवृत्ति आर्थिक लगान के बराबर होने की होती है।

### (iii) रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की आलोचना (Criticism to the Ricardian Theory)

(1) भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों को ज्ञात करना कठिन है। रिकार्डों के अनुसार भूमिपति को लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के कारण प्राप्त होता है। परन्तु यह ज्ञात करना अत्यन्त ही कठिन है कि भूमि का कौन सा गुण मौलिक तथा कौन सा अर्जित (acquired) है? एक पुराने देश में 'मौलिक गुण' तथा 'अर्जित गुण' में भेद करना अत्यन्त ही कठिन है। इसके साथ ही साथ भूमि की 'अविनाशी शक्तियों' का पता लगाना भी असम्भव है। किसी भी भूमि में 'अविनाशी उपजाऊपन' नहीं होता है। प्रयोग के साथ उपजाऊपन घटता जाता है, जब तक कि उसे यथावत् बनाए रखने के लिए प्रयत्न न किए जाएं।

(2) भूमि के प्रयोग का क्रम अव्यावहारिक है। रिकार्डों द्वारा वर्णित भूमि के प्रयोग का क्रम भी अव्यावहारिक है। रिकार्डों के अनुसार सर्वप्रथम सर्वोत्तम भूमि का प्रयोग किया जाता है, तत्पश्चात् उससे निम्न कोटि की भूमि का प्रयोग किया जाएगा। परन्तु व्यावहारिक रूप में हम जानते हैं कि भूमि की स्थिति का

उसके उपभोक्ताओं में अधिक महत्व है। भूमि का प्रयोग उसके उपजाऊपन के क्रम में नहीं बल्कि उसकी स्थिति के अनुसार या सुविधाजनक भूमि के क्रम में किया जाता है।

(3) लगान रहित भूमि का न होना रिकार्डों द्वारा वर्णित 'लगान रहित भूमि' व्यावहारिक दृष्टि से नहीं पाई जाती है। इस आलोचना का यह उत्तर दिया जा सकता है कि लगान के नाम पर भुगतान की राशि में पूर्णता पर ध्यान भी सम्मिलित रहता है। यद्यपि लगान का भुगतान किया जाता है, फिर भी यह सम्भव है कि 'आधिक लगान' शून्य हो। अतः यहाँ पर लगान रहित भूमि का अर्थ प्रायः ऐसी भूमि से है जिसकी उपज से प्राप्त प्रायः उपज के व्यय के बराबर हो। इस दृष्टि से सीमान्त या लगान होत भूमि का अर्थ लगान कठिन या अव्यावहारिक नहीं है।

(4) पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ठीक नहीं है। रिकार्डों ने मसी प्रकार की भूमि के दुबड़ों की उपज की एक ही कीमत मानकर पूरा प्रतियोगिता की कल्पना की थी। परन्तु इस प्रकार की मान्यता अव्यावहारिक है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वास्तव में कहीं भी नहीं पायी जाती, अतः उस पर आधारित होने से कारण रिकार्डों का लगान सिद्धान्त प्रसृत्य एक काल्पनिक है।

(5) लगान मुख्य से सम्मिलित नहीं होता, यह विचार भी अशुभ है। रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार सीमान्त भूमि लगान हीन भूमि होती है अर्थात् इसकी उपज से प्राप्त मूल्य से लगान जामिन नहीं होता है। परन्तु आलोचकों का यह कहना है कि रिकार्डों का यह विचार अशुभ है। व्यावहारिक जीवन में लगान कुछ विशेष परिस्थितियों में अवसर या वैकल्पिक व्यय (opportunity or alternative costs) के रूप में मुख्य में सम्मिलित रहता है।

उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की पूर्णतया व्यावहारिक माना जाता है, परन्तु वस्तुतः उनका लगान सिद्धान्त पूर्णतया व्यावहारिक नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डों के लगान सिद्धान्त का परित्याग नहीं किया है, बल्कि उसे एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है जो उत्पादन के किसी भी साधन के मन्दम या लागू किया जा सकता है। रिकार्डों ने लगान का कारण भूमि की 'मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों' को बताया है, आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन साधन की पुष्टि के बेलोच होने, अर्थात् उत्तम प्रकार के उत्पादन साधनों की कमी, को लगान का कारण मानते हैं। इस प्रकार रिकार्डों का लगान सिद्धान्त आधारहीन नहीं है, उसमें कुछ तथ्य हैं। अतः राबर्टसन का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, "The Classical Theory of Rent has by no means lost its validity and instructiveness".

## लगान तथा कीमत (Rent and Price)

रिकाडा व अनुमार किमी भी वृषि वस्तु की कीमत सीमात भूमि पर पैदा की गई उस वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर होती है, अर्थात् कीमत से मान्य लगान के बराबर होती है। रिकार्डों के अनुसार लगान एक प्रकार का आधिक्य है जो कीमत तथा लगान के अन्तर को प्रकट करता है। अतः उनका अनुसार लगान द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि कीमत द्वारा लगान का निर्धारण होता है। अतः लगान कीमत का परिणाम है। *Corn is not high because rent is paid, but rent is paid because corn is high*”

लगान कीमत में प्रवेश नहीं करता (Rent does not enter into price) लगान कीमत में प्रवेश नहीं करता है। इसके पक्ष में तक इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पूर्णतया के अन्तर्गत किमी वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त उत्पादन लागत के बराबर होता है। यहाँ पर सीमान्त उत्पादन लागत का अभिप्राय सीमान्त भूमि पर उत्पादन लागत में है। लगान एक प्रकार का ‘अन्तर’ (Differential) है, अतः सामान्य भूमि का कोई लगान नहीं होता है। चूँकि लगान सीमात उत्पादन लागत का कोई अंश नहीं है, अतः लगान कीमत में प्रवेश नहीं करता है।

लगान कीमत का परिणाम है। ऊँची सीमान्त उत्पादन-लागत के कारण यदि कीमत ऊँची है तो ऐसी परिस्थिति में उत्तम भूमि पर अपेक्षाकृत कम उत्पादन-लागत के कारण आधिक्य प्राप्त होगा। यह आधिक्य सीमान्त भूमि की ऊँची उत्पादन लागत तथा उत्तम भूमि की कम उत्पादन-लागत के अन्तर के बराबर होगा। अतः खेती की सीमा निम्नतर होने पर उत्पादित वस्तु की कीमत अधिक होगी, इस प्रकार उत्तम भूमि अधिक लगान अर्जित करेगी। इसी प्रकार यदि किसी भूमि पर गहन खेती की जाती है, तो सीमान्त लागत अधिक होगी जिससे घासत लागत तथा सीमात लागत में अन्तर होगा अतः लगान उत्पन्न होगा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि ऊँची सीमान्त लागत के कारण कीमत बढ़ती है तो उत्तम भूमि द्वारा ऊँची दर पर लगान अर्जित किया जाएगा।

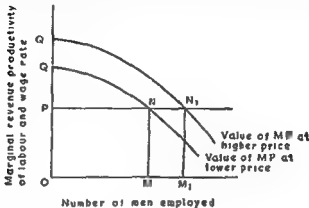
भूमि के सदस्य में उपर्युक्त विश्लेषण तर्कमग्न है। भूमि की पूर्ति निश्चित है, अतः उनके लिए दी जाने वाली कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसकी पूर्ति पर नहीं पड़ेगा (यदि हम पूरे समाज के सदस्यों में बात करते हैं)। यदि लगान शून्य भी हो जाय तो भूमि की पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि हम किसी एक फर्म के सदस्य में बात करें, तो ‘लगान’ उत्पादन-लागत का एक अंश होगा। यदि उत्पादक की कुल आय लगान को प्राप्त नहीं करती है तो उत्पादन बन्द कर दिया जाएगा। अतः अन्य व्ययों की भाँति, उत्पादक को कीमत द्वारा, लगान का अंश भी प्राप्त होगा।



चाहिए। उद्योग की दृष्टि से 'अवसर लागत' (opportunity cost) भी उत्पादन लागत का अंग होता है। हम यह जानते हैं कि वस्तु की कीमत सीमांत फर्म की सीमांत लागत क बराबर होती है। अतः सीमांत भूमि की अवसर लागत भी उत्पादन लागत का एक अंग होगा। सीमांत भूमि अधिकतम लागत वाली भूमि है जिसे उद्योग का अपन पास रखना होगा, यदि उद्योग कुल माग की पूर्ति करना चाहता है। परन्तु कुछ फर्मों के पास कम अवसर लागत वाली भूमि भी होगी। वे फर्मों भी अपने उत्पादन को उभी कीमत पर वचेंगी जिस कामन पर सीमांत फर्मों। अतः सीमांत फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों का 'आधिक्य' प्राप्त होगा। उद्योग के अन्तर्गत इस आधिक्य को आर्थिक लगान कहा जा सकता है। माग में ज्यों ज्यों वृद्धि होगी, त्यों-त्यों अधिक अवसर लागत वाली भूमि का भी प्रयोग किया जाएगा, अतः वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार पूँव की भूमि की इकाइयों की अवसर लागत तथा सीमांत भूमि की अवसर लागत का अंतर बढ़ता जाएगा। उद्योग के अंतर्गत आधिक्य या लगान बढ़ता जाएगा, जो कम अवसर लागत वाली भूमि द्वारा अर्जित किया जाएगा। यह लगान उत्पादन की सीमांत लागत का भाग नहीं है। अतः यह कीमत में प्रवेश नहीं करेगा बल्कि कीमत का परिणाम होगा, परन्तु अवसर लागत उत्पादन लागत का ही अंग है। सीमांत भूमि की अवसर लागत सीमांत लागत का अंग है, अतः यह कीमत में प्रवेश करती है।

कुछ भी हा, रिकार्डों ने एक सत्य की ओर संकेत किया है—यदि किसी साधन की पूर्ति पूर्ण विलोम है अर्थात् पूर्ण निश्चिन्त है तो उस साधन द्वारा किया गया उत्पादन उन्मादिन वस्तु की कीमत के अनुसार बदलेगा। (The return to a factor fixed in supply that is whose supply is absolutely inelastic, will vary directly with variations in the price of the goods produced by it) इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भूमि का एक ऐसा टुकड़ा है, जिस पर केवल गेहूँ पैदा किया जा सकता है, (i) केवल भूमि का अंग का प्रयोग किया जाता है। (ii) अंग की पूर्ति पूर्ण लोचदार है। हम यह देखें कि इस भूमि की उपज (Return) गेहूँ के मूल्य पर निर्भर करेगी, जैसा कि चित्र सं० 125 द्वारा स्पष्ट होता है।  $Q_1N_1$  अंग की सीमांत माय उत्पत्ति (MRP) को दर्शाती है। OP मजदूरी पर OM यन्त्रिक काम पर लगाए जाते हैं। कुल उत्पादन (TP) OMNQ है। मजदूरी विल OMNP है तथा उत्पादन (Return) PNQ है। यदि गेहूँ की कीमत बढ़ जाती है तो अंग की MRP ऊपर खिसक जाएगा, जैसा कि चित्र सं० 125 में दिखाया गया है। अंगिक  $Q_1N_1$  मजदूरी विल पर काम करते हैं। प्रत्येक अंगिक अंग भी वही मजदूरी, OP, प्राप्त करता है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि अंग की पूर्ति पूर्ण लोचदार है। परन्तु भूमि का उत्पादन (Return) बढ़कर

$PN_1Q_1$  हो गया है। यदि गेहू की कीमत गिर जाए तो उपर्युक्त विवरण की विपरीत स्थिति पाई जाएगी। उपर्युक्त विवरण में हम कुछ व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। चूँकि भूमि पर केवल गेहू पैदा किया जा सकता है, अतः गेहू की खेती उस समय तक की जानी रहेगी, जब तक कि उत्पादन की कीमत मजदूरी विल का भुगतान



चित्र सस्या 125

करने के लिए पर्याप्त है। अर्थात् कीमत कम रहने पर भूमि पर  $QPN$  मात्रा तक उत्पादन को प्रभावित किए बिना, खर लगाया जा सकता है। परिवर्तनशील साधन की पूर्ति में वृद्धि (यदि उत्पादित वस्तु की उत्पादकता तथा कीमत अपरिवर्तित रहे) स्थिर साधन की उत्पत्ति में वृद्धि करेगी। 3. लगान का यह सिद्धान्त कि भूमि के स्थिर (fixed) हान के कारण, लगान एक प्रकार का माघिक्य (Surplus) है और अधिक सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। आधुनिक प्रयत्नास्त्री रिकार्डों के भूमि सम्बन्धी विचार को उत्पादन के पन्थ साधनों पर भी लागू करते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण में स्पष्ट है कि रिकार्डों का कथन (लगान कीमत का अर्थ नहीं है) उसी समय सही होगा जबकि अधिक लगान को 'अन्तर्उद्योग लगान' (intra-industrial rent) के रूप में परिभाषित किया जाए। यदि 'लगान' शब्द का प्रयोग भूमि के उपयोग के बढ़ने में किए गए ममस्त भुगतानों (भूमि की अवसर लागत को सम्मिलित कर) के लिए किया जाता है तो भूमि के लगान का वह भाग, जो अवसर लागत को प्रकट करता है, उत्पादन लागत का एक अंश माना जाएगा तथा वह कीमत में प्रवेश करेगा। अतः रिकार्डों का कथन उन्ही समय सत्य माना जाएगा, यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक भूमि का टुकड़ा एक विशिष्ट प्रयोग के ही लिए है, अर्थात् उनकी अवसर लागत शून्य है। यदि भूमि की अवसर लागत होती है (निश्चित रूप से होती है) तो 'लगान' का अर्थ कीमत में अवश्य प्रवेश करेगा। अतः रिकार्डों का कथन पूर्णतया सत्य नहीं है।

## 2. लगान का आधुनिक सिद्धान्त (The Modern Theory of Rent)

1. लगान की परिभाषा : आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण केवल भूमि के ही मन्दर्भ में नहीं करते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार आर्थिक लगान किसी भी उत्पादन साधन को लिए गए उस अतिरिक्त भुगतान को कहते हैं, जो उस स धन का उपयोग में लाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक होता है। (Economic rent is any payment to a unit of factor of production, which is in excess of the minimum amount necessary to keep that factor in its present use)। इस प्रकार लगान एक सामान्य घुसकार है जो किसी भी उत्पादन साधन का दिया जा सकता है। हम यह जानते हैं कि किसी भी उत्पादन-साधन को वर्तमान व्यवस्था में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है उसे कम से कम उतना भुगतान आवश्यक किया जाए, जितना कि वह अल्पतः प्राप्त कर सकता है। अब एक साधन की आय के लिए हम दो राशियों का प्रयोग कर सकते हैं—(i) वर्तमान आय या वास्तविक आय (Present or actual earning), (ii) विस्थापन आय (Transfer earning)। माधन की जो कुछ प्राप्त होता है, वह उसकी वास्तविक आय है। विस्थापन आय वह आय है जिसे साधन अन्य वैकल्पिक प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है। साधन की वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसे कम से कम 'विस्थापन आय' के बराबर भुगतान किया जाए, अन्यथा वह माधन दूसरे उद्योग में चला जाएगा। मागम्य साधनों की वर्तमान आय या वास्तविक आय विस्थापन आय से अधिक होती है। अतः वास्तविक आय तथा विस्थापन आय के अन्तर को आर्थिक लगान कहते हैं (Rent = Actual Earning—Transfer Earning)।

आधुनिक अर्थ के अनुसार, ऐसे माधन के स्वादिशों को प्राप्त होत बाकी आय को निम्नो साधनों की पूर्ण पूर्ण लाभदार से कम होती है, लगान कहा जाता है। प्रो. वाटसन के अनुसार, "The income of owners of factors in less than perfectly elastic supply are called 'rents'. In this sense, the word 'rent' is not confined to land, nor does it have anything to do with leasing things or hiring them. The factor owner can receive rent from land or from capital under certain conditions, or from labour under certain conditions."

(D. S. Watson, Price Theory and its Uses, p. 462)

2. लगान क्यों दिया जाता है ? (i) साधन की पूर्ण : किसी उत्पादन साधन की दशाओं की विकल्प आय से अधिक भुगतान क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर माधनों की माग तथा पूर्ण में निहित है। यदि किसी साधन की पूर्ण पूर्णता लाभदार है तो इसका अर्थ यह होगा कि एक दिए हुए मूल्य पर उन साधन की

आवश्यक मात्रा में पूर्ति उपलब्ध होगी। ऐसी अवस्था में उम साधन की कोई भी इकाई लगान अर्जित नहीं कर पाएगी। परन्तु यह स्मरणीय है कि उम दिए हुए मूल्य से कम मूल्य पर उस साधन की पूर्ति विन्मुक्त नहीं उपलब्ध होगी।

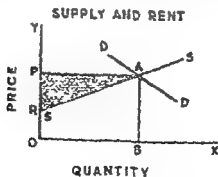
यदि साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार में कम है (less than perfectly elastic) तो उमकी उन इकाइयों को पहले काम में लगाया जाएगा जिसका पूर्ति-मूल्य न्यूनतम है। परन्तु यदि माग में वृद्धि होती है तो साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग अधिक मूल्य पर किया जाएगा जिसमें साधन वैकल्पिक व्ययसाधनों को छोड़कर अधिक माग वाले उद्योग में आ सकें। चूँकि साधन की समस्त इकाइयों को एक ही दर पर कीमत दी जाएगी, अतः पूर्ण की अन्तर-सीमान्त इकाइया (Intra marginal unit) जिसका पूर्ति-मूल्य कम है, उम कीमत से अधिक अर्जित करेगी, जितनी की उन्हे उद्योग में बनाये रखने के लिए देना आवश्यक है। अतः ऐसी अन्तर-सीमान्त इकाइयों को लगान प्राप्त होगा।

(ii) साधन की गतिशीलता : लगान की मात्रा साधन की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन-माधनों में कोई भी एक अन्तर नहीं होता है, परन्तु माधनों की गतिशीलता के कारण उनके गुणों में अन्तर पाया जाता है। प्रत्येक साधन को उमकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर पुरस्कार मिलाने के लिए यह आवश्यक है कि साधन पूर्ण गतिशील हो। परन्तु यदि कोई साधन कम गतिशील है तो उसे उम उमकी सीमान्त उत्पादकता से कम परिश्रम मिलेगा। आस्ट्रिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वॉन वीजर (Von Wieser) ने गतिशीलता के आधार पर साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है—(i) पूर्ण विशिष्ट (Perfectly Specific), तथा (ii) पूर्ण अविशिष्ट (Perfectly non specific)। पूर्ण विशिष्ट साधन वे हैं जिनका प्रयोग केवल एक कार्य के ही लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत पूर्ण अविशिष्ट साधन वे हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यदि पूर्ण अविशिष्ट साधनों को उनकी सीमान्त उत्पादकता से कम पारिश्रमिक दिया जाता है तो वे उद्योग छोड़कर अन्यत्र चले जाएँगे। परन्तु वैकल्पिक प्रयोग की उपलब्धि न होने के कारण पूर्ण विशिष्ट साधन उसी उद्योग में बने रहेंगे, यद्यपि उन्हे पारिश्रमिक सीमांत उत्पादकता में भले ही कम दिया जा रहा हो यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि (i) साधनों का उल्लेख दो श्रेणियों में स्थायी और परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता है। 'विशिष्टता' साधनों का एक मुख्य मान है, (ii) मात्रा जो साधन विशिष्ट है वह अवस्थिति में अविशिष्ट भी हो सकता है, (iii) व्यावहारिक रूप में कोई भी साधन न तो पूर्ण विशिष्ट होता है और न पूर्ण अविशिष्ट। (प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह भूल की थी कि वे भूमि का ही सदैव विशिष्ट साधन

मानते थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समय-विशेष में भूमि, श्रम, पूँजी आदि कोई भी साधन विशिष्ट हो सकता है।)

(iii) लगान निर्धारण चूंकि भूमि, श्रम, पूँजी आदि में कोई मौलिक भेद नहीं है, अतः भूमिगत साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर किया जाता है। अतः सतुल्य की स्थिति में भूमि का पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। किसी भी साधन का उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह साधन पूर्यतया अविशिष्ट हो। किसी भी साधन का उनकी अविशिष्टता की सीमा तक ही सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलना है। किसी भी साधन को उनकी (विशिष्टता के आधार पर) सीमांत उत्पादकता से अधिक जिस मात्रा में पारिश्रमिक मिलना है, वही मात्रा उस साधन का लगान है। अतः लगान विशिष्टता के लिए किया गया भुगतान है (Rent is a payment for specificity)। कोई भी साधन लगान अर्जित कर सकता है, यदि वह विशिष्ट (Specific) है। वह साधन भूमि, श्रम, पूँजी आदि कोई भी हो सकता है। इस प्रकार केवल भूमि ही नहीं, कोई भी साधन लगान अर्जित कर सकता है।

(iv) रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण चित्र सं 126 द्वारा लगान के आधुनिक सिद्धान्त को समझाया गया है। चित्र में SS दीर्घकाल पूर्ण वक्र है जो पूर्ण लोचदार पूर्ण वक्र से कम लोचदार है। मान लीजिए यह पूर्ण वक्र किसी उद्योग में मैनवर की पूर्ण को प्रकट करता है। मैनवरों की मात्रा उनकी योग्यता व कुशलता (उत्पादकता) पर निर्भर होगी। यदि बाजार का पूर्ण ज्ञान है तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई



चित्र संख्या 126

जाती है तो दीर्घकाल में सभी मैनवर OP वेतन प्राप्त करेंगे। पूर्ण वक्र से यह पता चलता है कि एक मैनवर के अतिरिक्त सभी मैनवर OP वेतन से कम वेतन पर नौकरी करने का तैयार हैं। परन्तु कोई भी व्यक्ति OR से कम वेतन पर काम

करने को तैयार नहीं होगा। चित्र में दिखाया गया छायांकित भाग, मनेजरो के वेतन में कुल लगान के भाग (Total Rent element) को प्रदर्शित करता है। लगान अवमर-लगान के ऊपर आधिक्य को प्रकट करता है। OPAB आयन का छायांकित भाग लगान को तथा जेप भाग अवमर लगान को प्रकट करता है। यदि पूर्ण वक्र पूर्ण लोचदार हो जाए, अर्थात् एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में (आधार रेखा OX के समानान्तर) हो जाए, तो छायांकित भाग (लगान) समाप्त हो जाएगा। अतः पूर्ण पूर्ण लोचदार (Perfectly elastic) होने पर लगान शून्य हो जाता है।

निष्कर्ष : यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने 'लगान' शब्द का प्रयोग भूमि के सदन में ही किया था, परन्तु आधुनिक विचारधार के अनुसार 'लगान' कोई भी साधन अर्जित कर सकता है, अतः हम लगान के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना नहीं करते ? वास्तव में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मस्तिष्क में 'भूमि' शब्द गतिहीनता के ही लिए था, जिसे हम अब विशिष्टता (Specificity) कहते हैं। उन्होंने केवल यही गलती की कि वे केवल भूमि को ही 'विशिष्ट' मान बैठे थे। यदि वे इन निष्कर्ष पर पहुँचें होते कि भूमि के अनिश्चित अन्य साधन भी विशिष्ट हो सकते हैं तथा यह आवश्यक नहीं है कि भूमि सदैव 'विशिष्ट' ही रहे तो वे सही निष्कर्ष पर पहुँच सकते थे। आजकल लगान शब्द का प्रयोग 'विशिष्टता' के लिए किए गए भुगतान के लिए किया जाता है। 'विशिष्टता' को 'भूमि पहलू' (Land Aspect) भी कहते हैं। प्रत्येक साधन में 'विशिष्टता' तथा 'अविशिष्टता' के तत्त्व विद्यमान रहते हैं, अतः प्रत्येक साधन में 'भूमि-पहलू' पाया जाता है। लगान का भुगतान 'भूमि-पहलू' के लिए ही किया जाता है। अतः आधुनिक निष्कर्ष में भी 'लगान' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार मूलन सही थे। उन्होंने केवल साधारण भी भूल की थी।

### 3 अर्द्ध-लगान या आभास लगान (Quasi-Rent)

'अर्द्ध-लगान' का विचार सर्वप्रथम मार्शल ने प्रस्तुत किया था। मार्शल ने 'अर्द्ध-लगान' शब्द का प्रयोग उन उत्पादन-साधनों की आय के लिए किया है जिनकी पूर्ण अल्प समय में निश्चिन होती है, जैसे निश्चिन प्लाट, भवन आदि की आय। प्रो० मार्शल ने अर्द्ध-लगान की परिभाषा इस प्रकार दी है - "अर्द्ध-लगान प्रमुख (मौद्रिक) लागत पर कुल आय के आधिक्य को कहते हैं जो कम या अधिक उस समय की माग और पूर्ति के घटनावस्था सम्बन्धों से प्रभावित होती है।"

(Quasi-Rent is a surplus of total receipts over 'prime (money) cost' governed by more or less accidental relations of demand and supply for that time.)

प्रो० सिचरमैन के अनुसार 'अर्द्ध'-लगान उत्पादन के उन साधनों से प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर, परन्तु दीर्घकाल में परिवर्तनशील होती है।

(The additional payment for those agents of production, the supply of which, though alterable in a long period, is fixed in a short period, is technically known as Quasi-rent)

प्रो० लिप्से के अनुसार, साधनों के वे भुगतान जो अल्पकाल में प्राथमिक लगान तथा दीर्घकाल में हस्तान्तरण भुगतान होते हैं, आभास लगान कहे जाते हैं।

('Factor payments which are economic rents in the short run and transfer payments in the long-run are called Quasi Rents')

आधुनिक अर्थशास्त्री 'अर्द्ध' लगान' के विषय में एक मत नहीं है। प्रो० लेस्टर-विच ने यह कहा है कि अस्पष्टता के कारण, अर्द्ध-लगान के विचार का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्पकाल में—

कुल अर्ध लगान = कुल आय — कुल परिवर्तनशील लागत (TR—TVC) या प्रति इकाई उत्पादन पर अर्ध लगान = औसत आय — औसत परिवर्तनशील लागत (AR—AVC)

अर्ध-लगान को अवसर लगान के सदृश में भी व्यक्त किया जा सकता है। अल्पकाल में अवसर लागत के ऊपर जो भी आधिक्य प्राप्त होता है, उसे अर्ध लगान कहते हैं। स्टोनियर तथा हेग ने मशीन के सदृश में, आभास-लगान को इस प्रकार परिभाषित किया है — 'मशीन का आभास लगान इसकी कुल अल्पकालीन आय में से इनक साय प्रयुक्त किए गए परिवर्तनशील साधनों की लागत एवं अल्पकाल में मशीन की चालू अवस्था में बनाए रखने के व्यय को घटावे के बराबर होता है। दीर्घ-कालीन मतुलन में आभास लगान मशीन की (स्थिर) सामान्य आय के बराबर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आभास लगान अपने दीर्घकालीन 'सामान्य' स्तर पर आ जाएगा जहाँ यह मशीन के अस्तित्व को निरन्तर बनाए रखने के व्यय के बराबर हो जाएगा।' इस प्रकार स्टोनियर तथा हेग के अनुसार मशीन का आभास लगान = [कुल आय] — [कुल परिवर्तनशील लागत + अल्पकालीन रखरखाव लागत]

"Quasi-rent of the machine = TR—TVC + Short Run maintenance cost."

अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार Quasi Rent = TR—TVC होता है। यह स्मरणीय है कि इन अर्थशास्त्रियों ने 'अल्पकालीन रखरखाव लागत' को TVC के अन्तर्गत माना है। स्टोनियर तथा हेग ने भी नहीं-नहीं परोक्ष रूप से 'अल्पकालीन रखरखाव लागत' को 'परिवर्तनशील लागत' के ही अन्दर शामिल माना है।

लगान व आभास लगान में अन्तर

लगान या आर्थिक लगान उन साधनों से प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति दीर्घ-काल तक बचाव हाती है या स्थिर होती है। यह अवसर लगान के ऊपर ऐसा आधिक्य है जो दीर्घकाल तक प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार लगान स्थायी प्रकृति का होता है। परन्तु आभास लगान अल्पकाल में कुल आय तथा परिवर्तनशील लागत के अन्तर का प्रकट करता है।

आधुनिक अर्थशास्त्री आभास लगान का अवसर लागत (Opportunity Cost) के ऊपर आधिक्य मानते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने लगान का भी अवसर लागत के ऊपर का आधिक्य माना है। इस प्रकार आभास लगान व लगान के अन्तर के सम्बन्ध में भ्रम हो जाता है। दोनों में बहुत बारीक अन्तर है। आभास लगान अवसर लागत के ऊपर आधिक्य है तो अल्पकाल में साधन की पूर्ति में अस्थायी कमी के कारण उत्पन्न होता है जो दीर्घकाल में पूर्ति का भविष्य ठीक हो जाने पर समाप्त हो जाता है। लगान के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

(1) स्थिर साधनों के सदर्भ में आभास लगान भूमि के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ ऐसे साधन हैं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर या अपरिवर्तनशील रहती है। मांग में वृद्धि होने पर उनकी पूर्ति केवल दीर्घकाल में ही बढ़ायी जा सकती है। अल्पकाल में ऐसे साधनों की मांग बढ़ जाने पर उनका मूल्य (आय) बढ़ जाता है। इस मूल्य वृद्धि तथा पूर्ति के स्थिर रहने के कारण इन साधनों की सामान्य आय से अधिक आय प्राप्त होना लगता है। इस स्थिति में सामान्य आय के ऊपर जिनकी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसे अर्द्ध या आभास लगान कहा जायगा। मान लीजिये किसी कारणवश भूमि या मशीन का मांग बढ़ जाती है, परन्तु उनकी पूर्ति स्थिर एवं अपरिवर्तित रहती है। यदि पहले उसका लगान 500 रु० था तो अब मांग बढ़ जाने के कारण 600 रु० हो जायगा। अब मासिक व अनुसार सामान्य आय से 100 रु० अधिक आय प्राप्त होगी। यह अतिरिक्त आय ही अर्द्ध-लगान कही जायगी। अर्द्ध लगान के रूप में यह आय उस समय तक मिलनी जायगी जब तक कि दीर्घकाल में भूमि या मशीन की पूर्ति मांग के अनुपात में बढ़ नहीं जायगी। पूर्ति में वृद्धि होने पर अर्द्ध-लगान स्वतः समाप्त हो जायगा।

(ii) निर्माणकारी उद्योग के सदर्भ में आभास लगान एक उत्पादन की निश्चित तथा परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें वहन करनी पड़ती हैं। निश्चित लागतें (Fixed or Supplementary Costs) उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि से सम्बन्धित नहीं होती हैं जैसे भवन, मशीन आदि। परन्तु प्रमुख या परिवर्तनशील लागत (Prime or Variable Cost) उत्पादन की मात्रा के अनुपात में



घटती या बढ़ती है, जैसे थम, कच्चा माल आदि से सम्बन्धित लागतें। एक उत्पादक को, अल्पकाल में, यदि परिवर्तनशील लागत के बराबर भी कीमत प्राप्त हो जाती है तो वह उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि उत्पादन बन्द करने पर भी उसे निश्चित लागत का भार वहन करना पड़ेगा। यदि उत्पादन को अल्प-काल में परिवर्तनशील लागत से आय प्राप्त होती है तो आय के इस आधिक्य को 'अर्ध-लगान' कहेंगे, क्योंकि यह आधिक्य (Surplus) एक प्रकार से निश्चित तथा स्थायी साधनों का प्रतिफल है। घट —

**अर्ध-लगान = कीमत परिवर्तन लागत (Quasi Rent = Price AVC)**

दीर्घकाल में निश्चित तथा परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतों के बराबर कीमत प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा हानि होने के कारण उत्पादक उद्योग को छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा। दीर्घकाल में कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है कि कुछ फर्मों अत्यन्त ही अधिक कार्यकुशल हो तथा उनकी उत्पादन लागत उद्योग की उत्पादन-लागत से कम हो। ऐसी अवस्था में इन फर्मों को उत्पादन लागत से अधिक कीमत प्राप्त होगी। कीमत तथा उत्पादन लागत का अन्तर, अर्थात् 'आधिक्य', इन फर्मों के लिए 'अर्ध-लगान' होगा। अतः दीर्घकाल में भी कुछ फर्मों कुछ समय तक अर्ध-लगान अर्जित कर सकती हैं, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं हो सकती है। उद्योग में लाभ से आकर्षित होकर नई फर्म प्रवेश करेंगी तथा कीमत उत्पादन-लागत के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार 'अर्ध-लगान' स्वतः समाप्त हो जाएगा।

कभी कभी ऐसी भ्रान्ति हो जाती है कि हम अर्ध-लगान को नकारात्मक (Negative) मान लेते हैं जैसे कि पारिश्रमिक का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। यदि वास्तविक प्रतिकूल अनुमानित प्रतिकूल से कम होता है तो इनके अन्तर को नकारात्मक अर्ध लगान कहने लगते हैं, परन्तु यह धारणा पूर्णतया निर्मूल है। अर्ध लगान कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। यदि मूल्य (अल्पकाल में) परिवर्तनशील लागत के बराबर है तो अर्ध लगान शून्य होगा, परन्तु ऋणात्मक किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है। [प्रो० फ्लक्स (Flux) ने ऋणात्मक 'अर्ध लगान' शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार यदि वास्तविक आय कुल लागत से कम है (सामान्य लाभ को सम्मिलित कर) तो यह अन्तर ऋणात्मक अर्ध लगान होगा, परन्तु इस धारणा को ठीक नहीं माना जाता है।

**निष्कर्ष :** (i) आभास लगान के सम्बन्ध में दिए गए उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि माशेल के अनुसार अल्पकाल में पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति स्थिर होने के कारण, आभास लगान का उदय होता है। (ii) माशेल ने यह भी कहा है कि मजदूरी व लाभ में भी आभास लगान का अर्थ विद्यमान रहता है। (iii) आधुनिक

अर्थशास्त्री कुल आय तथा परिवर्तनशील लागत के अन्तर को आभास लगान मानते हैं। (iv) वस्तुतः मार्शल का 'आभास लगान' सम्बन्धी विचार, रिकार्डों के लगान सिद्धान्त तथा लगान के आधुनिक सिद्धान्त के बीच एक कड़ी (Link) के समान है। (v) आधुनिक मत के अनुसार ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति भी आभास लगान अर्जित करते हैं, जिनकी पूति अल्पकाल में बेरोच होती है। (vi) स्थानान्तरण आय का जिन प्रकार प्रयोग लगान के विश्लेषण के लिए किया जाता है, उन्ही प्रकार आभास लगान के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है।

#### 4 अवसर आय या स्थानान्तरण आय (Opportunity Earnings or Transfer Earnings)

हस्तांतरण आय, जिसे अवसर आय भी कहते हैं, मुद्रा की वह रकम है जो उत्पादन के किसी साधन की इकाई विशेष के द्वारा अपने सर्वोत्तम पुरस्कार वाले वैकल्पिक प्रयोग में अर्जित की जा सकती है।<sup>5</sup> श्रीमती जोन राबिन्सन के अनुसार "किसी साधन की विशेष इकाई को एक विशेष उद्योग में ही बने रहने के लिए जो मूल्य देना आवश्यक होता है, उसे हस्तान्तरण आय अथवा हस्तांतरण मूल्य कहते हैं।"

"The price which is necessary to retain a given unit of a factor in certain industry may be called its transfer earnings or transfer price"

स्थानान्तरण आय की धारणा अधिक लगान के सिद्धान्त को पूर्णतया प्रभावित करती है। इस धारणा के अन्तर्गत उत्पादन के किसी साधन की इकाई-विशेष के वर्तमान उपयोग से प्राप्त आय की तुलना उसके वैकल्पिक प्रयोग से सम्भावित अवसर आय से की जाती है। वर्तमान उपयोग की आय में से अवसर आय को कम कर देने पर यदि शेष आय धनात्मक (positive) है तो उस शेष आय को ही लगान कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक भूमि के टुकड़े पर मकान बनाने पर 300 रु० आय होती है परन्तु उसका प्रयोग खेती के लिए किए जाने पर आय 350 रु० हो तो, ऐसी स्थिति में उस भूमि पर अवसर या हस्तांतरण आय  $(350 - 300) \text{ रु०} = 50 \text{ रु०}$  होगी।

स्थानान्तरण-आय भूमि के अतिरिक्त उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकती है। परन्तु इसके उत्पन्न होने की शर्त यह है कि वह साधन किसी अज्ञ तक विशिष्ट (specific) होना चाहिए। चूंकि उत्पादन का प्रत्येक साधन किसी अज्ञ तक विशिष्ट होना है अतः सभी साधनों में स्थानान्तरण आय या लगान उत्पन्न

<sup>5</sup>. "The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings."  
— Benham.

होना है। इसके विपरीत यदि कोई माधन पूर्णतया विशिष्ट है तथा उसका उपयोग किसी भी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता तो उसकी अवसर लागत न होने के कारण, उसकी हस्तान्तरण लागत नहीं होती, या उसका कोई लगान हो नहीं होता।

### 5 लगान तथा आर्थिक उन्नति (Rent and Economic Progress)

किसी भी भूमि के टुकड़े का लगान उस पर लगाई गई उत्पादन लागत तथा सीमान्त भूमि पर लगाई गई उत्पादन लागत के अन्तर के बराबर होता है। अतः यदि आर्थिक विकास सेती सीमावर्तीता (Margin of cultivation) को प्रभावित करता है तो इसमें लगान भी प्रभावित होगा। विभिन्न परिस्थितियों में इसका प्रभाव निम्नलिखित प्रकार पड़ेगा

(1) जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि-पदार्थों की मांग बढ़ती है। अतः सराव किसम की भूमि पर भी खेती की जाती है तथा अधिकाधिक सीमा तक गहन कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रकार लगान में वृद्धि होती है।

(2) जीवन स्तर में सुधार - आर्थिक विकास के कारण आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर ऊँचा उठता है, परन्तु अन्य वस्तुओं के व्यय में जिस अनुपात से वृद्धि होती है, खाद्य पदार्थों पर किए जाने वाले व्यय में उस अनुपात से कम अनुपात में वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक विकास के कारण आय के व्यय स्रोतों—मजदूरी, लगान तथा ऋण आदि—में जिस अनुपात से वृद्धि होती है, कृषि आय में उस अनुपात में कम दर पर वृद्धि होती है।

(3) परिवहन में सुधार - परिवहन के साधनों का विकास न होने पर भूमि की स्थिति-सम्बन्धी लाभ (जैसे बाजार की निकटता आदि) कम मिल पाते हैं, अतः लगान घटता है। विकसित परिवहन के साधनों के कारण खाद्य पदार्थों का आयात भी सरल हो जाता है, अतः देश में सराव किसम की भूमि पर खेती बन्द कर दी जाती है। इस प्रकार सेती की सीमावर्तीता (Margin of cultivation) ऊपर उठती है तथा लगान कम हो जाता है।

(4) कृषि कला में सुधार - कृषि कला में उन्नति के कारण भूमि की सीमावर्ती उत्पादकता में वृद्धि होती है। यदि कृषि वस्तुओं की माँग पूर्ववत् हो तो उनकी कीमत गिरेगी तथा सराव किसम की भूमि पर खेती नहीं की जाएगी। इस प्रकार लगान में कमी होगी।

### प्रश्न व सकेत

1. रिकार्डों के लगान सिद्धांत को बताइये एवं उसकी व्याख्या करते हुए सिद्धान्त की सीमाएं लिखिए। (Agra III A. II, 1960)

[सकेत : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम भाग में रिकार्डों के लगान की परिभाषा दी जाए और उसकी मूल विशेषताएं लिखिए। दूसरे भाग में इस सिद्धान्त की प्रमुख सीमाएं बताइये।]

2. "अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं होता है क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि ऊंचे लगान इसलिए दिये जाते हैं, क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा होता है।" आलोचनात्मक ढंग से कथन को समझाइये। (Vik. B. Com II, 1964)

[सकेत : प्रश्न के उत्तर में यह बताना है कि क्या लगान मुख्य में प्रवेश करता है? इसकी व्याख्या के लिए रिकार्डों एवं प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार लिखिए और 'लगान-कीमत सहसम्बन्ध' को समझाइये। देखिये पृष्ठ 659-61]

3. लगान के प्राधुनिक सिद्धांत की विवेचना करिये। रिकार्डों के सिद्धांत से यह सिद्धांत किम प्रकार भिन्न है? (Sagar, B Com I, 1964)

[सकेत : पहले आधुनिक अर्थशास्त्रियों के लगान सम्बन्धी विचार लिखिए और तत्पश्चात् इस सिद्धान्त की विशेषताओं की तुलना करके रिकार्डों के सिद्धांत से भिन्नताओं को समझाइये।]

4. "लगान विनिश्चितता के लिए भुगतान है।" समझाइये।

[सकेत : इस कथन की सार्थकता को सिद्ध करने हेतु प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित लगान के सिद्धान्त को समझाइये और अन्त में निष्कर्ष लिखिए।]

5. आभास लगान को समझात हुए बताइये यह आर्थिक लगान व ब्याज से किस प्रकार भिन्न है।

[सकेत : आभास लगान का तात्पर्य बताइये और बाद में आर्थिक लगान व ब्याज से यह किस तरह भिन्न है, समझाइये।]

# 35

## मजदूरी (Wages)

*"The market will tend toward that equilibrium pattern of wages differentials at which the total demand for each category of labour exactly matches its competitive supply"*

—Samuelson

### मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत (Theories of Wage Determination)

मजदूरी राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में प्रतिफल स्वरूप दिया जाता है। मजदूरी निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। प्राचीन काल में जनसंख्या की कमी तथा सामान्यतः सामाजिक तथा अधिकाधिक व्यवस्था के कारण मजदूरी-निर्धारण को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। उस समय 'न्यायपूर्ण मजदूरी पर विचार अवश्य व्यक्त किए गए थे, परन्तु न्यायपूर्ण मजदूरी का आधार निर्धारित नहीं किया गया था। औद्योगिक क्रांति के पूर्व धरेलू उद्योग धंधों के काल में अधिकांश निश्चोक्ता स्वयं अपने अधिक होते थे। ऐसी स्थिति में मजदूरी निर्धारित करने के सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् श्रम विभाजन, बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा फॅक्टरी व्यवस्था ने वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया। पूँजीपतियों तथा श्रमिकों के वर्ग विभेद के कारण ही उत्पादन से प्राप्त आय के उपयुक्त विभाजन की समस्या उठ खड़ी हुयी। समाज सुधारकों तथा अर्थशास्त्रियों ने श्रमिकों के शोषण तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करने के विचार से समय-समय पर निम्न मजदूरी-निर्धारण के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। परन्तु आधुनिक सिद्धांत की तुलना में अब उन सिद्धान्तों का केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है।

(1) जीवन-निर्वाह अथवा मजदूरी का लोह सिद्धान्त (The Subsistence Theory or the Iron Law of Wages), (2) जीवन स्तर सिद्धान्त (The Standard of Living Theory), (3) मजदूरी कोष सिद्धान्त (The Wage Fund Theory) (4) मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (The Residual Claimant Theory), (5) सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory) (6), अप्रहृत सीमांत उत्पादकता नियम (Discounted Marginal Productivity of Wages)

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्राधुनिक सिद्धांत कि तुलना में अब उक्त सिद्धांतों में से अधिकांश सिद्धान्तों का केवल सैद्धान्तिक महत्व है, अतः यहां पर उत्पादन-साधन श्रम, के मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त की दृष्टि से सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त, अप्रहृत सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त तथा प्राधुनिक सिद्धांत की ही व्याख्या की गई है।

### 1. सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory)

मजदूरी का 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' वितरण के सामान्य सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है।<sup>1</sup> इसका अर्थ यह है कि नियोक्ता श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर जितनी उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करता है, मजदूरी उन्ही के बराबर होने को प्रवृत्त होती है। उदाहरणार्थ, एक फर्म 20 श्रमिकों को नियुक्त करके अन्य साधनों की सहायता से किमी वस्तु की 50 इकाइयां उत्पादित करती है। यदि अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किए बिना यह एक और श्रमिक नियुक्त करता है तथा उसके फर्म का उत्पादन 50 इकाइयों से बढ़कर 52 इकाइयों के बराबर हो जाता है तो उसके फर्म में श्रम की सीमान्त उत्पादकता 2 इकाइयों के बराबर कही जायेगी। यदि प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 रुपया है तो अतिरिक्त श्रम की सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य 2 रुपया होगा। अतः नियोक्ता श्रम को 2 रुपये में अधिक मजदूरी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि यह मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर है। जब तक मजदूरी की दर 2 रुपये से कम होगी, तब तक नियोक्ता के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करना लाभप्रद होगा, परन्तु श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर 'सीमान्त

<sup>1</sup> (a) "Demand for labour to this theory is based on the final or marginal utility of the labour to the entrepreneur" —S. B. Thomas

(b) "The only wage at which equilibrium is possible is a wage which equals the value of the marginal product of the labourers."  
—J. R. Hicks

उत्पादकता ह्रास नियम लागू होने लगेगा जिससे श्रम की सीमान्त उत्पादकता भी कम होने लगेगी। इस प्रकार श्रमिकों की सख्या में वृद्धि करते रहने पर एक ऐसी स्थिति या आयेगी जबकि मजदूरी की बाजार दर श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जायेगी। इस बिन्दु पर पहुँचने पर निषेक्ता अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करना बन्द कर देगा। अतः सन्तुलन की स्थिति में मजदूरी दर सदैव श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। यह स्थिति पूर्ण स्पर्धा में पायी जाती है। अपूर्ण स्पर्धा में मजदूरी की दर श्रम की सीमान्त आय उत्पत्ति के बराबर होगी।

मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के विश्लेषण के सम्बन्ध में प्रो० जे० आर० हिक्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'सीमान्त उत्पादकता के परम्परागत विचार का स्पष्ट करना बहुत ही सरल है, क्योंकि यह मूल रूप में सीमान्त उत्पादन ह्रास नियम से निकलता है।' <sup>2</sup> इस सिद्धान्त के अन्तर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना। श्रम की सख्या से एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होनी है। एडम स्मिथ ने भी यह सकेन किया था कि मजदूरी श्रम की उत्पादकता पर ही निर्भर है। उनके विचार से श्रम को मजदूरी इस कारण दी जाती है कि वह ऐसी उपयोगी वस्तु का उत्पादन करता है या ऐसी वस्तु के उत्पादन में सहायता पहुँचाना है जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य होता है। इस आधार पर ही कोई भी उत्पादक श्रमिक की उत्पादकता के मूल्य से अधिक मजदूरी नहीं देता। अन्य शब्दों में, उत्पादक अतिरिक्त श्रम की इकाइयों को उस समय तक नियुक्त करता जायेगा जब तक उनकी उत्पादकता (प्राप्त लाभ) उनकी मजदूरी (उन पर खर्च) में अधिक होती है।

साराण रूप में सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी श्रम की माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तथा सन्तुलन की दशा में मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। यदि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के बराबर नहीं होगी तो सन्तुलन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सन्तुलन प्राप्त करने के लिए श्रम की माग एवं पूर्ति में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। यह सम्भव है कि वास्तविक जगत् में मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से विचलित हो जाय। ऐसी परिस्थिति में सन्तुलन की स्थिति नहीं आ पायेगी। अतः व्यवहार में सन्तुलन प्राप्त करने की प्रवृत्ति सदैव वर्तमान रहती है।

मान्यताएँ यह सिद्धान्त कुछ मान्यताओं (Assumptions) पर आधारित है, (1) श्रम की सभी इकाइयाँ एकसु हैं, (2) श्रम तथा निषेक्ता दोनों की

<sup>2</sup> "The conventional proof of the marginal productivity proposition is simple enough. It follows from the most fundamental form of the law of diminishing returns"

मोन जोल करने की क्षमता बराबर है तथा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वर्तमान है, (iii) दीर्घकाल में भी अन्य दशायें स्थिर हैं, (iv) उत्पादन कार्य में लगे सभी उत्पादन के साधन, श्रम को छोड़कर, स्थिर हैं। श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। (v) श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग (derived demand) है, क्योंकि वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी होने पर ही उसकी मांग बढ़ती या घटती है। (vi) इस सिद्धांत के अन्तर्गत उत्पादन ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है तथा साहसी श्रम की सीमान्त उत्पादकता का पता लगाने के लिये प्रतिस्थापन के नियम को जानना है।

**प्रालोचनायें** - अन्य सिद्धान्तों की तुलना में सत्य के अधिक निकट होते हुए भी मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत की कड़ी प्रालोचना की जाती है :

(1) पूर्ण प्रतियोगिता तथा श्रम की गतिशीलता की मान्यता प्रथावहारिक है यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता तथा श्रम की गतिशीलता की मान्यता को स्वीकार करना है, जबकि व्यवहार में न तो श्रम गतिशील है और न पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ही पायी जाती है। इन कारणों से मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के बराबर नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई नियोजित प्रतियोगिता के कारण ही अधिक मजदूरी देगा। व्यवहार में विभिन्न प्रकार के उद्योगपति होते हैं। अच्छे उद्योगपति अधिक मजदूरी देते हैं और बुरे उद्योगपति कम मजदूरी देते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की उत्पादकता के मूल्यों में अन्तर होगा तथा मजदूरी भी अलग-अलग होगी। परन्तु दीर्घकाल में श्रम की गतिशीलता पूर्ण होने पर सभी व्यवसायों में मजदूरी एक ही होगी।

(2) उत्पादकता का सङ्कुचित अर्थ - “उत्पादकता” का प्रयोग सङ्कुचित अर्थ में किया गया है। अतिरिक्त उत्पादन के कारण सम्भव है कि वस्तु के मूल्य में कमी आ जाये। वस्तुतः उत्पादन से प्राप्त आय ही श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित करती है, तथा उत्पादित वस्तु का मूल्य बाजार की दशाओं पर निर्भर करता है। फलस्वरूप श्रमिकों की कुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि का यह अर्थ नहीं है कि नियोजित की मजदूरी देने की क्षमता में भी आनुपातिक वृद्धि हुई है।

(3) अपूर्ण सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के समर्थक भी इसे एक पूरा सिद्धान्त नहीं मानते। मार्शल का यह कथन कि श्रमिक की मजदूरी उसके शुद्ध उत्पादन के बराबर होगी, अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि शुद्ध उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये हमें श्रमिक की मजदूरी के अतिरिक्त, उत्पादन के उन सभी व्ययों को भी सम्मिलित करना पड़ता है जो उत्पादन में व्यय किए जाते हैं। स्वयं मार्शल ने भी इस बात पर बल दिया है कि हम मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियों का अध्ययन करने के लिए ‘सीमान्त’ पर विचार करना ही पड़ता है,



तथा सीमान्त उत्पादकता मिथ्यान्त मजदूरी-निर्धारण के कम से कम एक तथ्य पर प्रकाश डालता है<sup>10</sup> । वास्तविक जगत में मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता के बराबर होना आवश्यक नहीं है, किन्तु मजदूरी की प्रवृत्ति सदैव सीमान्त उत्पादकता के बराबर होने की रहती है ।

(4) अतिरिक्त मजदूरी के अतिरिक्त उत्पादन की माप असम्भव है : अतिरिक्त मजदूरी से व्युत्पन्न अतिरिक्त उत्पादन की माप सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में टाजिग तथा डेबनपोर्ट का यह कहना है कि उत्पादन सभी साधनों की संयुक्त घेष्टा का परिणाम है । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन की ठीक-ठीक माप नहीं हो सकती । यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि सभी साधनों को स्थिर रख कर यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया जाता, तो अतिरिक्त उत्पादन का होना सम्भव नहीं होता । उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि अतिरिक्त मजदूर को लगाने का ही फल है, तथा इसे श्रम की सीमान्त उत्पादकता कहना पूर्णतः सही होगा । अतः श्रम की अतिरिक्त इकाई द्वारा किये गये कार्य, अर्थात् उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि की मात्रा, को जानना सम्भव है और इस दृष्टि से श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है ।

(5) सिद्धान्त एक पक्षीय है : यह सिद्धान्त एक पक्षीय एवं अपूर्ण है क्योंकि इसमें श्रम की पूर्ति को ध्यान में नहीं रखा गया है । हम जानते हैं कि श्रम की पूर्ति सीमित है । यदि श्रम की पूर्ति सीमित है तो निश्चय ही मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से अधिक होगी । मजदूरी-निर्धारण का कोई भी सिद्धान्त तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता, जब तक कि मांग तथा पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में न रखा जाये ।

(6) श्रम की सीमान्त उत्पादकता श्रमिक की कार्यकुशलता पर ही निर्भर नहीं है : श्रम की सीमान्त उत्पादकता न केवल श्रमिक की कुशलता, बल्कि कच्चे-माल, यन्त्र तथा औद्योगिक संगठन आदि की कुशलता पर निर्भर करती है । फल-स्वरूप एक ही उद्योग के श्रमिक की सीमांत उत्पादकता में अन्तर पाया जाता है । तात्पर्य यह है कि श्रम द्वारा प्राप्त उत्पादन केवल श्रम की कुशलता पर ही नहीं, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों के कुशल प्रयोग पर भी निर्भर है । इन साधनों में परिवर्तन के कारण भी श्रमिक की उत्पादनशीलता बदल जाती है । स्पष्ट है इस सिद्धान्त में औद्योगिक व्यवस्था के महत्व को रचीकार नहीं किया गया है जो कि बहुत सीमा तक मजदूरी को बढ़ाने में सहायक होता है ।

(7) उत्पादन साधनों के अनुपात में परिवर्तन सम्भव नहीं है : यह मान्यता

<sup>10</sup> "One has to go to the margin to study the action of these forces which govern the value of the whole," and that the marginal productivity theory throws into clear light the action of one of the sources that govern wages."

वि उत्पादन के विभिन्न साधनों के अनुपात में इच्छानुसार परिवर्तन करना सम्भव है, ठीक नहीं है यदि किसी फर्म के अन्दर का आकार निश्चित है तो उत्पादन के साधनों में मनमाना परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। फलस्वरूप धर्म के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का प्रयोग भी सम्भव नहीं है। दीर्घकाल में इस तर्क का विशेष स्थान नहीं है। स्थिर उत्पादन-इकाई (plant) को बदला जा सकता है। निश्चित आकार वाली इकाई की धारणा में भी दीर्घकाल में परिवर्तन का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

(8) अन्य साधनों के स्थिर रहने पर धर्म की एक इकाई में वृद्धि करना सम्भव नहीं है : यह सिद्धान्त इस मान्यता को स्वीकार करता है कि अन्य सभी साधनों को स्थिर रखते हुए धर्म की मात्रा में एक इकाई में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु यदि उत्पादन की तकनीकी प्रगति निश्चित हो तो इस प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्म की मात्रा में एक इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन के अन्य साधनों में भी परिवर्तन करना होगा।

(9) सीमान्त उत्पादकता के सम्बन्ध में उत्पादक की अज्ञानता व्यवहार में प्रायः उत्पादकों या नियोक्ताओं को धर्म की सीमान्त उत्पादकता के विषय में जानकारी नहीं होती। परन्तु वास्तविकता यह है कि उत्पादक सीमान्त उत्पादकता को ध्यान में अवश्य रखता है। वह सदा इस बात पर विचार करता है कि एक अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाने से उसे कितना लाभ होगा या कितनी हानि उठानी पड़ेगी। वास्तुतः उत्पादक द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने की भावना की व्याख्या सीमान्त उत्पादकता के विचार के द्वारा ही सम्भव है।

उपर्युक्त आलाचनाओं के आधार पर ही यह कहा जाता है कि यह एक स्थिर (static) सिद्धान्त है, किन्तु व्यावहारिक समारम्भशील है जिसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है। यह सत्य है कि सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त अपूर्ण है, किन्तु यह मजदूरी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व की ओर सकल करता है। धर्म की कुशलता में वृद्धि का अर्थ सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि है जिसके कारण मजदूरी में भी वृद्धि सम्भव है। एक उद्योग दूसरे उद्योग की तुलना में अधिक मजदूरी इस कारण देता है कि इसकी सीमान्त उत्पादकता (बाजार मूल्य की दृष्टि से) अधिक है इसी कारण एक देश दूसरे देश की तुलना में अधिक वास्तविक मजदूरी अदा कर सकता है।<sup>11</sup>

<sup>11</sup> 'Through the doctrine is thus incomplete, it offers useful indications of the influences on wages. A rise in efficiency means an increase in the marginal worth and therefore makes a possible rise in the wage. One industry pays a higher wage than another because the marginal productivity is higher (i.e. in terms of market value).'

मजदूरी में वृद्धि उद्योगपति की संगठन-कुशलता एवं निपुणता के कारण तथा नये साधनों की खोज एवं आविष्कार के द्वारा भी सम्भव है।

मार्शल तथा अन्य पुराने अर्थशास्त्रियों ने यह नहीं कहा कि मजदूरी का निर्धारण सीमान्त उत्पादकता के द्वारा ही होना चाहिए। उनका केवल इतना ही कहना था कि दी जाने वाली मजदूरी की दर सीमान्त उत्पादकता तथा काम पर लगाये जाने वाले श्रमिकों के बीच एक फलन सम्बन्ध (functional relation ship) है, अतः इस दृष्टि से सीमान्त उत्पादकता मजदूरी की दर की माप है, निर्धारक नहीं।

### बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त

(Discounted Marginal Productivity Theory of Wages)

प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० टॉजिंग (Prof. Taussig) ने सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त को ही एक नये सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हम मजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Discounted Marginal Productivity Theory of Wages) कहते हैं। टॉजिंग के अनुसार मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं होगी, क्योंकि मजदूरी का भुगतान तो उत्पादन के पहले ही कर दिया जाता है। प्रो० टॉजिंग (Prof. Taussig) का कहना है कि उत्पादन में समय लगता है। अतः श्रम की सीमान्त उत्पादकता को प्राप्त करने में भी समय लगता है तथा कुछ समय बाद ही श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता को जाना जा सकता है। परन्तु श्रमिक उस समय तक मजदूरी पाने के लिये प्रतीक्षा नहीं करता तथा उत्पादक को उत्पादन की बिक्री के पूर्व ही मजदूरी देनी पड़ती है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादक श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उत्पादन के पहले ही कर देता है। इस पेशगी मजदूरी की रकम उत्पादक अपने पास से या उधार के रूप में दूसरों से प्राप्त करता है और इस राशि पर उसे व्याज चुकाना पड़ता है। फलस्वरूप वह मजदूरी में से उतने दिनों का व्याज काट लेता है जितने दिन पहले वह मजदूरी चुकाता है। इसका फल यह होता है कि अन्ततः मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर नहीं हो पाती। अतः मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादकता में से इस कटौती (कटौती वर्तमान व्याज की दर पर निर्भर करती है) को निकाल देने पर जो शेष बचता है उसी के बराबर होती है। इसीलिये प्रो० टॉजिंग का कहना है कि मजदूरी श्रमिक की बट्टायुक्त (discounted) सीमान्त उत्पादकता द्वारा निर्धारित की जाती है। इस सम्बन्ध में बॉम बावर्क (Bohm-Bawerk) का भी यही विचार है।

### 3 मजदूरी-निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त (The Modern Theory)

मजदूरी-निर्धारण के सम्बन्ध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति के सामान्य नियम द्वारा निर्धारित

रिया जाता है। उसी प्रकार श्रम की मजदूरी भी, जो उसी मेवाघो का मूल्य है, श्रमिकों की माग और पूर्ति के नियम के आधार पर ही निर्धारित हो जानी चाहिए। परन्तु श्रम अन्य वस्तुओं से भिन्न है तथा उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। यही कारण है कि मजदूरी-निर्धारण के लिए मान तथा पूर्ति के सिद्धान्त को एक सशोधित एवं विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सशोधित सिद्धान्त का आधार यह है कि “श्रम का मूल्य ही उसकी मजदूरी है। प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बाजारों में यह मूल्य अवैयक्तिक रूप से श्रम की माग तथा पूर्ति की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है।” इन पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप श्रम की माग देखा उसकी पूर्ति देना को जिस बिन्दु पर वाज्यो है, उस बिन्दु पर ही मजदूरी निर्धारित होती है। अन्य शब्दों में, जिस मूल्य पर उत्पादक श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत की गयी सेवाओं की खरीदने तथा श्रमिक अपनी सेवाएँ उत्पादकों को प्रेषण के लिए तैयार हो जाते हैं, वही मूल्य श्रमिकों की मजदूरी है। मजदूरी निर्धारित करने वाले सिद्धान्त की व्याख्या करने के पहले, श्रम की माग तथा पूर्ति की विवेचना आवश्यक है।

### पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण (Determination of Wage under Perfect and Imperfect Competition)

सीमान्त उत्पादक सिद्धान्त की सहायता से माघनों की पूर्ण निर्धारण विधि की विवेचना करते समय हमने श्रम तथा मजदूरी का उदाहरण लिया था। उस उदाहरण में यह स्पष्ट किया गया था कि एक कर्म में उस समय तक श्रम की अधिक से अधिक इकाइया नियुक्त की जाती हैं जब तक कि श्रम की सीमान्त आय उत्पादकता सीमान्त मजदूरी के बराबर नहीं हो जाती। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उत्पाद बाजार तथा माघन बाजार में प्रत्येक कर्म में श्रम का मूल्य (अर्थात् मजदूरी) सीमान्त मूल्य (अर्थात् मजदूरी) एक तरफ श्रम के सीमान्त उत्पादकता वक्र (अथवा माग वक्र) द्वारा तथा दूसरी तरफ श्रम के पूर्ति वक्र द्वारा निर्धारित होता है। अन्य शब्दों में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत बाजार में श्रमिकों की मजदूरी श्रम की माग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ अब हम सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के आधार पर श्रम बाजार की विभिन्न स्थितियों पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा—में मजदूरी निर्धारण की विधियों का विवेचन करेंगे।

परन्तु उक्त दोनों स्थितियों में मजदूरी निर्धारण सिद्धान्त की विवेचना करने के पूर्व हमें उत्पादन साधन के रूप में श्रम की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनके आधार पर हमें सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की मजदूरी पर लागू करते समय उसमें कुछ आवश्यक सशोधन करने होंगे। पहली विशेषता यह है कि श्रमिक सामूहिक रूप से श्रम सध बना सकते हैं तथा प्रचलित मूल्य से भिन्न

मजदूरी के लिए सोदेगाजी कर सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिक की काम करने के सम्बन्ध में स्वतन्त्र इच्छा होती है। वह पूँजी तथा भूमि की तरह जीवनहीन नहीं है। वह अपनी इच्छानुसार किसी दिन या किसी क्षण काम करता है या काम करने के लिए अतिचतुर्क रहता है। ये दोनों विशेषताएँ भूमि और पूँजी में नहीं पायी जाती। इसी कारण श्रम की मजदूरी निर्धारित करते समय उसको इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

### पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण :

पूर्ण प्रतिस्पर्धा की वजहों में निम्नी उद्योग में मजदूरी मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत मजदूरी-निर्धारण का अध्ययन करने के लिए दो बाजार—माग बाजार तथा पूर्ति बाजार—को देखना पड़ेगा। यहाँ यह मान लिया गया है कि उत्पाद-बाजार तथा साधन-बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे कि आक्रान्त औद्योगीकरण के इस युग में साधन बाजार (यथा श्रम बाजार) में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति शायद ही कभी पायी जाती है। ऐसा पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार केवल अविकसित तथा कृषि प्रधान देशों में ही पाया जा सकता है।

(1) उद्योग के लिए श्रम का माग वह जैसा कि सीमान्त उत्पादकता के अनुपात में स्पष्ट किया जा चुका है श्रम के लिए किसी फर्म का सीमान्त माग उत्पादकता (MRP) वह फर्म द्वारा विभिन्न मजदूरी दरों पर लगाय गये श्रमिकों की विभिन्न मात्राओं (इकाइयों) को इकट्ठा करता है। फर्म श्रम की अनिश्चित इकाइयाँ उस समय तक प्रयोग में लाता जायगा जब तक कि श्रम की सीमान्त माग उत्पादकता प्रचलित मजदूरी दर के बराबर नहीं हो जाती है। इस प्रकार फर्म का MRP वह फर्म के लिए श्रम की माग प्रदर्शित करता है। वही कारण है कि फर्म का MRP वह उनके लिए श्रम का माग वह भी है। एक उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न फर्मों के लिए प्रत्येक-प्रत्येक MRP वह श्रम के लिए माग-वक्र होते हैं। यदि हम पड़ोसी रेखा के रूप में (horizontally) उद्योग में लगी सभी फर्मों के MRP या श्रम के माग वक्रों को जोड़ दें तो हमें सम्पूर्ण उद्योग के लिए श्रम का माग-वक्र प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रम के लिए उद्योग का माग वक्र  $A, B, C, \dots$  फर्मों के MRP वक्रों का योग है।

(2) उद्योग के माग वक्र को प्रभावित करने वाले तत्त्व : किसी उद्योग का माग-वक्र कई बातों से प्रभावित होता, जैसे

(1) श्रम की माग व्युत्पन्न माग है : श्रम की माग उस वस्तु की माग द्वारा निर्धारित होती है जिसका उत्पादन करने में श्रम सहायक होता है उत्पादित वस्तु की

जितनी ही अधिक माग होगी, उद्योग के लिए श्रम की माग में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी।

(ii) उत्पादन फंक्शन (Production Function) से सम्बन्धित प्राविधिक दशाओं का प्रभाव फर्म में उत्पादन-फलन अर्थात् पदत-उत्पादन के सम्बन्धी (input output relations) को प्रभावित करने वाली तकनीकी दशाएँ भी श्रम की माग निर्धारित करती हैं। यदि स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के अनुपात बेलोचदार (inflexible) है तथा परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं तो श्रम का MRP तेजी से कम हो जायेगा। ऐसी स्थिति में श्रम का MRP वक्र नीचे की ओर अधिक गिरता हुआ होगा। इस कारण श्रम की अतिरिक्त इकाइयों को प्रयोग में लाने के लिए मजदूरी दर को घटाना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि मजदूरी में बहुत अधिक कमी नहीं कर दी जाती है। तो फर्म की श्रम के लिए माग में अधिक तेजी से कमी आयेगी, इसके विपरीत यदि स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों (जैसे श्रम) से अनुपात लोचदार है तो परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप श्रम के MRP में तेजी से कमी नहीं आयेगी। ऐसी स्थिति में श्रम का MRP वक्र धीरे-धीरे नीचे की ओर गिरेगा तथा मजदूरी में थोड़ी सी कमी होने पर भी फर्म को श्रम का अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उक्त स्थिति में फर्म की श्रम की माग अपेक्षाकृत अधिक होगी।

(iii) स्थानापन्न साधनों का प्रभाव श्रम की माग केवल स्वयं के मूल्य (मजदूरी) से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि अन्य साधनों के मूल्यों से भी प्रभावित होती है। यहाँ तक कि श्रम तथा अन्य साधनों के एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापना (Substitution) की सम्भावना का भी श्रम की मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि पूँजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग सम्भव है तो पूँजी का मूल्य (व्याज) बढ़ने पर उसके स्थान पर श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग में लायी जा सकती हैं।

एक उद्योग के लिए श्रम का माग वक्र बायें, से दायें नीचे की गिरता हुआ होता है, जो यह प्रकट करता है कि मजदूरी तथा श्रम की माग में उल्टा सम्बन्ध है, अर्थात् मजदूरी की दर अधिक होने पर श्रम की माग कम होगी तथा मजदूरी दर कम होने पर श्रम की माग अधिक होगी। एक उद्योग में श्रम के लिए माग वक्र अल्पकाल में बेलोचदार होता है, तथा दीर्घकाल में लोचदार होता है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल की तुलना में अल्पकाल में श्रम के स्थान पर पूँजी अथवा पूँजी के स्थान पर श्रम के प्रयोग करने के अवसर सीमित होते हैं।

(3) उद्योग के लिए श्रम का पूर्ण दत्त : किसी उद्योग के लिए श्रम के पूर्ण दत्त के आधार के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाना कठिन है। इस वाटिन्ता पर विचार करने के पहले यह जानना आवश्यक है कि 'श्रम की पूर्ति' का वास्तव में अर्थ क्या है। 'श्रम की पूर्ति' का अन्विष्टार्थ उन् घटते तथा दिनों से है जो विभिन्न मजदूरी-दरों पर किये विशेष प्रकार के श्रमिक अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। सामान्यतः मजदूरी दर ऊँची होने पर अधिक श्रम घण्टे अर्पित किये जाते हैं, अर्थात् श्रमिक श्रमिक काम करने को तत्पर होते हैं। इसके विपरीत कम मजदूरी दर पर कम श्रमिक काम करने का तत्पर होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मजदूरी दर तथा श्रमिकों की पूर्ति में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। परन्तु कभी-कभी श्रम की पूर्ति को अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि अन्य साधनों के विपरीत विभिन्न मजदूरी दरों पर श्रमिकों की कार्य करने की अपनी इच्छा या प्रवृत्ति भी श्रम की पूर्ति निर्धारित करती है। इस आधार पर श्रम की पूर्ति में वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण यह है कि श्रमिक अपने श्रम के बदले में कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह कर सके। यह मजदूरी की दर न्यूनतम दर है जिसे श्रमिकों का सीमांत त्याग (marginal sacrifice) बचा जा सकता है। यदि उसे इस सीमांत त्याग या न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है तो वह काम करने को तैयार नहीं होता। अतः जिस प्रकार उत्पादक के लिए श्रम की सीमांत उत्पादकता (मजदूरी की अतिरिक्त सीमा) श्रम की मात्रा निर्धारित करती है उसी प्रकार श्रमिकों के लिए उन्नी सीमांत त्याग (मजदूरी की न्यूनतम सीमा) श्रम की पूर्ति की मात्रा निर्धारित करता है।

श्रम की पूर्ति निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व भी हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है

(1) व्यावसायिक स्थानान्तरण (Occupational Shifts) : श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक तत्व व्यावसायिक स्थानान्तरण है। यदि किसी उद्योग विशेष में मजदूरी की दर ऊँची है तो उसमें अधिक अन्य उद्योगों से प्राने लोगों की ओर उन उद्योग विशेष में श्रम की पूर्ति बढ़ने लगेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मजदूरी दर ऊँची होने पर श्रम की पूर्ति अधिक होगी है और मजदूरी दर नीची रहने पर श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। इस कारण ही उद्योग का श्रम पूर्ति बरक ऊपर की ओर दायी तरफ उठना हुआ होता है।

(2) श्रमिकों की कार्यकुशलता : किसी उद्योग में श्रम की पूर्ति श्रमिकों की कार्यकुशलता पर भी निर्भर करती है। श्रमिकों के कार्यकुशल होने पर उत्पादन मात्रा में उसी प्रकार वृद्धि होती है, जिस प्रकार कि श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने पर।

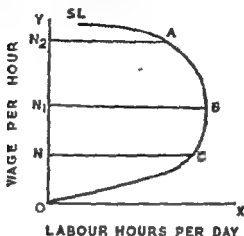
अकुशल श्रमिक की तुलना में एक कुशल श्रमिक की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इससे यह स्पष्ट है कि उद्योग की उत्पादन मात्रा पर श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि का बड़ी प्रभाव पड़ता है जो कि श्रम की पूर्ति में वृद्धि का ऊँची मजदूरी होने पर श्रमिकों का जीवनस्तर ऊँचा उठता है तथा जीवन स्तर ऊँचा रहने पर उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है जिससे श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। नीची मजदूरी-दर रहने पर जीवन स्तर नीचा रहता है जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाती है और श्रम की पूर्ति घट जाती है। इसके फलस्वरूप भी उद्योग का श्रम-पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर दायी तरफ उठता हुआ है।

(iii) कार्य-आराम अनुपात (Work-leisure Ratio) श्रम की पूर्ति कार्य-आराम-अनुपात से भी प्रभावित होती है। मजदूरी-दर में वृद्धि श्रम की पूर्ति को दो प्रकार से, परन्तु विपरीत दिशाओं में, प्रभावित करती है। पहला प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) कहलाता है। मजदूरी में वृद्धि होने पर श्रमिक अधिक कार्य करना पसन्द करेंगे तथा आराम के स्थान पर कार्य का प्रतिस्थापन करेंगे। इस दशा में श्रम पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर दायी तरफ उठता हुआ होगा, क्योंकि ऊँची मजदूरी मिलने पर श्रमिक अतिरिक्त कार्य करने के लिए तत्पर होगा। ध्यान रहे कि प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक (positive) होता है। इसके विपरीत मजदूरी में वृद्धि होने पर जब श्रमिक की आय बढ़ जायेगी तब वह आय में वृद्धि के कारण कम काम करना तथा अधिक आराम करना चाहेंगे। यह मजदूरी में वृद्धि के कारण 'आय प्रभाव' (income effect) कहा जाता है। इस स्थिति में श्रम पूर्ति-वक्र का ढाल आय की कुछ सीमाओं पर पीछे की तरफ झुकता हुआ होगा, जो यह प्रकट करता है कि 'आय प्रभाव' ऋणात्मक (negative) होता है, क्योंकि मजदूरी दर अधिक होने पर भी श्रमिक आराम अधिक पसन्द करते हैं। इन दोनों प्रभावों को चित्र सं० 127 में स्पष्ट किया गया है।

चित्र संख्या 127 में OSL श्रम-घटो का पूर्ति वक्र है। प्रति घंटा मजदूरी दर बढ़ने पर जब वह  $ON$  से  $ON_2$  हो जाती है, श्रमिक की श्रम घटो की पूर्ति भी  $NC$  से बढ़कर  $NB$  हो जाती है।  $B$  बिन्दु पर श्रम घटो का पूर्ति वक्र एक सड़ी रेखा के रूप में है, परन्तु  $II$  के बाद ऊपर की तरफ वह पीछे की तरफ झुका हुआ है। यदि मजदूरी दर  $ON_1$  से बढ़कर  $ON_2$  हो जाती है श्रम घटो की पूर्ति  $N_1 II$  से घटकर  $N_2 A$  हो जाती है। पूर्ति-वक्र के प्रारम्भ की स्थिति, जो ऊपर की ओर दायी तरफ चढ़ती हुई  $N_1$  यह व्यक्त करती है कि मजदूरी में वृद्धि के कारण श्रमिक आराम के स्थान पर अधिक घण्टा कार्य करने को तत्पर होंगे। OSL पूर्ति वक्र पर  $OB$  तक की स्थिति प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यक्त करती है परन्तु  $II$  बिन्दु के



वाद 'प्रत्य-प्रभाव' की स्थिति है, क्योंकि मजदूरी  $ON_2$  होने पर भी श्रमिक के कार्य घण्टों की पूर्ति  $OA$  के बराबर ही है जिनमे यह स्पष्ट है कि श्रमिक कम घण्टे कार्य करना चाहते हैं और श्रमिक आराम चाहते हैं।



चित्र सहा 127

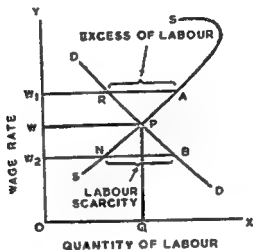
**3 मजदूरी निर्धारण (Wage Determination)** श्रम की माग तथा पूर्ति की शक्तियां श्रम बाजार की उन दशाओं को व्यक्त करती हैं जिनके आधार पर मजदूरी तथा रोजगार में संतुलन स्थापित होता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ति-सीमा की स्थिति में मजदूरी की दर उस बिन्दु पर संतुलन की स्थिति में होगी, जहाँ श्रम का माग-मूल्य श्रम के पूर्ति मूल्य के बराबर होगा। अतः पूर्ण स्पर्धात्मक श्रम बाजार में मजदूरी की दर की अधिकतम सीमा (जो श्रम की सीमात उत्पन्नता को व्यक्त करती है तथा न्यूनतम सीमा जिनमें नीची मजदूरी पर श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं आया क्योंकि वह श्रमिकों के सामान्य जीवन स्तर को व्यक्त करती है) माग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के संतुलन से निर्धारित होगी।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण :

चित्र सं० 128 में  $OX$  आधार रेखा पर श्रम की इकाइयां तथा  $OY$  लंबी रेखा पर मजदूरी की दर व्यक्त की गई है। विभिन्न मजदूरी दरों पर श्रम की माग-

22 "Thus the wage of labour in a particular industry depends on demand and supply. Demand is shown by the marginal revenue curve of labour to industry. Supply is given by a curve showing at each level of wages what the volume of labour offered will be. Wages are determined by the inter-action of these two curves"

है। श्रम की पूर्ति रेखा  $SS^*$  है। ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को  $P$  बिन्दु पर काटती हैं जो साम्य बिन्दु है तथा जा श्रम की माग तथा पूर्ति की मात्राओं का सन्तुलन-बिन्दु भी कहलाता है। यह बिन्दु ही यह बतलाता है कि  $PQ$  या  $OW$  मजदूरी की दर पर श्रमिकों की माग व पूर्ति  $OQ$  के बराबर होगी। अब यदि यह मान लिया जाय कि मजदूरी की दर  $OW$  से घट कर  $OW_2$  हो जाती है तो श्रमिकों की माग  $W_2B$  के



चित्र सख्या 128

बराबर होगी परन्तु श्रमिकों की पूर्ति घट कर  $W_2N$  के बराबर ही रह जायेगी। कम मजदूरी-दर पर उत्पादक अधिक सख्या में श्रमिकों की नियुक्त करने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन कम दर पर श्रमिक काम करने को तैयार नहीं होंगे। यह स्थिति श्रमिकों की कमी (labour scarcity) की है, क्योंकि माग की मात्रा  $W_2B$  पूर्ति की मात्रा  $W_2N$  से अधिक है। अतः

$$\text{श्रम की कमी} = (W_2B - W_2N) = NB$$

इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर  $OW_1$  हो जाती है तो श्रम की मांग =  $W_1R$  तथा श्रम की पूर्ति =  $W_1A$  होगी। मजदूरी की दर बढ़ाने पर श्रम की माग

\* चित्र सं० 128 में पूर्ति-रेखा  $SS$  प्रारम्भ में तो ऊपर की ओर चढ़ती हुयी है, परन्तु एक सीमा के बाद वह बायीं तरफ खड़ी रेखा  $OY$  की तरफ (बायीं) ओर मुड़ गयी है। इसका कारण यह है कि एक सीमा तक मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर, श्रमिकों की पूर्ति में वृद्धि होगी। परन्तु उस सीमा के पश्चात् आय (मजदूरी) अधिक होने पर, कुछ श्रमिक आराम करना पसन्द करेंगे जिससे श्रम-वाशार में श्रम विशेष की पूर्ति कम हो जायेगी।

( $W_1R$ ) श्रम की पूर्ति ( $W_1A$ ) से कम होगी। मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रमिक से अधिक सत्त्या में श्रमिक कार्य करने के लिए तत्पर होंगे, परन्तु उत्पादक कम से कम सत्त्या में श्रमिकों को नियुक्त करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति श्रम की माग की तुलना में अधिक होगी, जो बेरोजगारी की स्थिति को व्यक्त करती है। अतः

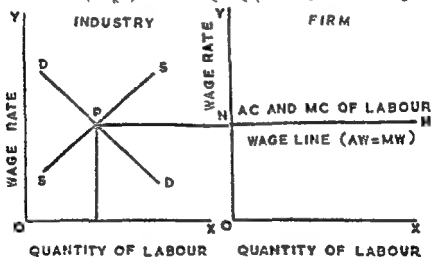
$$\text{बेरोजगारी (Unemployment)} = (W_1R - W_1A) = RA$$

4 पूर्ण स्पर्धा वाले श्रम-बाजार में मजदूरी-निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ मान्यताएँ हैं : (i) श्रम विशेष (labour of a given kind) की माग व पूर्ति में एकाधिकार के तत्त्व विद्यमान नहीं हैं, अर्थात् न तो नियोजक ही (employers) और न श्रमिक ही संगठित होते हैं। वे स्वतन्त्र रूप से श्रम की माग तथा पूर्ति करते हैं। (ii) नियोजकों (employers) की सत्त्या अत्यधिक होती है। उनकी सरस अधिक होने के कारण उत्पादक इकाइयाँ या फर्म बहुत ही छोटी होती हैं और वे अलग अलग श्रम-बाजार में श्रम की कुल पूर्ति के बहुत ही छोटे भाग को प्रयोग में लाती हैं। (iii) एक ही प्रकार के श्रमिकों की सत्त्या भी बहुत अधिक होती है, जो संगठित नहीं होते और स्वतन्त्र होकर अपनी व्यक्तिगत सेवाएँ देवने के लिए तत्पर रहते हैं। (iv) विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के लिए श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता है। (v) श्रम-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होने के साथ ही साथ उत्पादित वस्तुओं के बाजार में भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति पायी जाती है। पूर्ण स्पर्धा की इन मान्यताओं के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को समान मजदूरी प्राप्त होगी। जैसा कि चित्र सं० 128 से स्पष्ट है पूर्ण स्पर्धा वाले श्रम बाजार से सन्तुलन मजदूरी (Equilibrium Wages) ही वह मजदूरी है जो वहाँ स्वेव प्रचलित होगी। सन्तुलन मजदूरी ही मजदूरी तथा रोजगार में सन्तुलन की स्थिति स्थापित करती है।

इसका कारण यह है कि यदि मजदूरी दर बढ़ जाती है तो श्रमिकों की माग कम होने पर कुछ श्रमिक बेकार हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में श्रमिक कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो जायेंगे, जिससे श्रमिकों की माग बढ़ेगी और सभी बेकार श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर घट जाती है, तो श्रमिकों की माग श्रमिकों की पूर्ति से अधिक होगी। इस स्थिति में नियोजकों में अधिक से अधिक सत्त्या में श्रमिकों को नियुक्त करने की स्पर्धा के कारण मजदूरी दर बढ़ेगी और इस बढ़ी हुई मजदूरी-दर पर श्रमिकों की सत्त्या (पूर्ति) बढ़ने से पुनः सन्तुलन की स्थिति स्थापित हो जायेगी। मजदूरी तथा रोजगार में सन्तुलन की स्थिति उस समय तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि श्रम-बाजार की उपर्युक्त मान्यताएँ अपरिवर्तित रहती हैं।

इस सम्बन्ध में उस तथ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक बार सम्पूर्ण उद्योग के लिए मजदूरी निर्धारित कर दिये जाने पर प्रत्येक फर्म या उत्पादक अथवा नियोजक को निर्धारित या दी हुयी मजदूरी स्वीकृत होनी है। चित्र स० 128 में PNR वह मजदूरी है जो उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। यही मजदूरी फर्म के लिए निर्धारित या प्रयुक्त मजदूरी है। फर्म के लिए इसको स्वीकार करने के प्रतिरुद्ध कोई अन्य विकल्प नहीं है। उत्पादन इकाइयों फर्मों या नियोजकों की मर्याद अधिक तथा उनके व्यवसाय का आकार छोटा होने के कारण उनके द्वारा श्रम की कुल पूर्ति का थोड़ा सा ही भाग प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में मजदूरी की दर परिवर्तित रहनी है क्योंकि उनकी मजदूरी मूल्य तथा मजदूरी प्रतिक्रियाओं का श्रम बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन प्रत्येक फर्म द्वारा एक ही हुयी मजदूरी स्वीकार कर लिये जाने पर मजदूरी-रेखा (Wage line) NN

आधार रेखा OX के समानान्तर होती है, जैसा कि चित्र 129 में दिखलाया गया है। मजदूरी रेखा यह स्पष्ट करती है कि श्रम की औसत लागत (मजदूरी उनकी सीमान्त लागत (मजदूरी) के बराबर होती है (Average Cost or Wage of



चित्र सख्या 129

Labour (AW) = Marginal Cost (or Wage of Labour) यह हम मान्यता को स्पष्ट करती है कि पूर्ण स्पर्धा में मजदूरी की दर सीमान्त उत्पादन के मूल्य के बराबर होनी चाहिए।

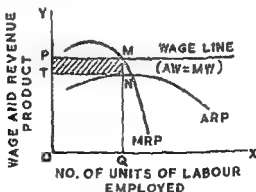
जिस प्रकार पूर्ण प्रति स्पर्धा के अन्तर्गत किसी वस्तु का मूल्य दीर्घ-काल में उत्पादन के औसत एवं सीमान्त लागत के बराबर होती है, उसी प्रकार श्रम का

मूल्य (अथवा श्रम की मजदूरी) पूर्ण प्रति-स्पर्धा की दशाओं में दीर्घ-काल में किसी फर्म के लिए श्रम के श्रौत तथा सीमान्त आय उत्पाद के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना अथवा अपनी हानि को कम से कम करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह उस बिन्दु तक श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता रहेगा जिस बिन्दु पर श्रम की सीमान्त लागत (अर्थात् सीमान्त मजदूरी) श्रम के सीमान्त आय उत्पाद (MRP) के बराबर हो जाती है। यदि फर्म उस बिन्दु के उपरान्त भी श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता है तो श्रम की सीमान्त लागत (सीमान्त मजदूरी) श्रम के MRP से अधिक हो जायेगी और फर्म को हानि होने लगेगी। इसके विपरीत, यदि फर्म उस बिन्दु के पहले ही श्रम को अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग रोक देता है तो श्रम का MRP श्रम की सीमान्त लागत (सीमान्त मजदूरी) से अधिक होगा और ऐसी स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगी। अतः फर्म अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग को उस बिन्दु पर रोक देगा जिस पर श्रम की  $MC = \text{श्रम के MRP}$  फर्म के समुत्पन्न के लिए सीमान्त मजदूरी (MW) का श्रम के सीमान्त आय उत्पाद (MRP) के बराबर होना एक अनिवार्य शर्त है।

**श्रम की श्रौत लागत या श्रौत मजदूरी तथा श्रौत आय उत्पाद का संबंध.**

श्रम की श्रौत मजदूरी तथा उसके श्रौत आय उत्पाद में तीन निम्न प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं।

(1) श्रम के श्रौत आय उत्पाद से श्रौत मजदूरी अधिक होने पर : फर्म को अतिरिक्त श्रम प्रयोग करने पर हानि होगी जैसा कि चित्र 130 प्रदर्शित किया गया है।

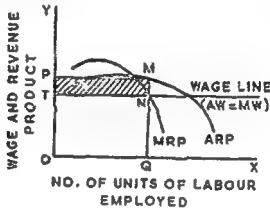


चित्र संख्या 130

चित्र में फर्म उभ समग्र समुत्पन्न की स्थिति में है जबकि वह श्रम को OQ इकाइया प्रयोग में लाती है, क्योंकि रोजगार या प्रयोग के इस स्तर पर सीमान्त

मजदूरी  $MQ$  श्रम के  $MRP (MQ)$  के बराबर है। परन्तु प्रयोग के इस स्तर पर श्रमिक मजदूरी  $MQ$  श्रम के श्रमिक आय उत्पाद  $NQ$  में अधिक है। अतः इस स्थिति में फर्म को श्रम की  $OM$  इकाइयाँ प्रयोग में लाने पर  $PTNM$  के बराबर शुद्ध हानि उठानी पड़ती है।

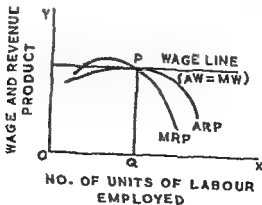
(ii) श्रमिक मजदूरी श्रम के सीमान्त आय उत्पाद से कम होने पर : इस स्थिति में, जैसा कि चित्र सहा 131 में प्रदर्शित किया गया है, फर्म को श्रम की



चित्र सहा 131

$OQ$  इकाइयाँ प्रयोग में लाने पर लाभ प्राप्त होगा। इस चित्र में श्रम का सीमान्त आय उत्पाद  $MQ$  श्रमिक मजदूरी  $NQ$  में  $MN$  मात्रा तक अधिक है। अतः फर्म  $PTNM$  के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है।

(iii) श्रमिक मजदूरी के श्रम के श्रमिक आय उत्पाद के बराबर होने पर : इस स्थिति में फर्म को श्रम का प्रयोग करने पर न लाभ होगा, न हानि। चित्र स०



चित्र सहा 132

132 में श्रम का सीमान्त आय उत्पाद  $PQ =$  श्रमोत्पन्न मजदूरी  $PQ$  के, जबकि फर्म श्रम की  $OQ$  इकाइया प्रयोग में लाता है। अतः फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि।

अल्प काल में फर्म इन तीनों स्थितियों में किसी भी स्थिति से गुजर सकती है। उसे हानि भी हो सकती है, या वह लाभ अर्जित कर सकती है अथवा वह ऐसी स्थिति से भी गुजर सकती है जिसमें उसे न तो लाभ होता है और न हानि ही। परन्तु दीर्घकाल में प्रथम दो स्थितियाँ सम्भव नहीं हैं। केवल तीसरी स्थिति ही सम्भव है जिसमें फर्म को न तो लाभ होता है और न हानि ही।

**प्रालोचना :** इस सिद्धान्त में कई दोष हैं। यह बाजार के वास्तविक वितरण की उपेक्षा करता है, क्योंकि जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, पूर्ण स्पर्धा की सही दशाएँ न तो पूर्णतया पायी हो जाती हैं और न ही विभिन्न श्रम इकाइयों में एकहपता पायी जाती है। कुछ श्रमिक अधिक कुशल होते हैं, तो कुछ श्रमिक कम कुशल, योग्यता तथा कुशलता के आधार पर सभी श्रमिकों में कुछ न कुछ असमानता रहती ही है। इसके अतिरिक्त वेन्स के 'रोजगार सिद्धान्त' के अनुसार श्रम की माग प्राणिक रूप में आय स्तर पर निर्भर है और आय स्तर भी अतः रोजगार स्तर पर निर्भर है। वस्तुतः रोजगार स्तर कई परिवर्तनशील तत्वों (Variables) में से एक ऐसा तत्व है जो श्रम की माग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः मजदूरी निर्धारण में उन विभिन्न परिवर्तनशील तत्वों से ध्यान नहीं किया जा सकता जो रोजगार तथा आय के स्तर को निर्धारित करने हैं।

### अपूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण

(Wages Under Imperfect Competition)

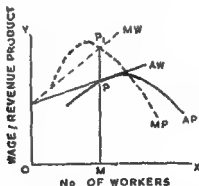
मजदूरी की सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही उचित ठहरता है। परन्तु पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रायः पायी नहीं जाती। शायद ही कुछ ऐसी श्रम बाजार हो जहाँ श्रम की माग करने वाली उत्पादन इकाइयों की संख्या अधिक हो और उनका आकार छोटा हो तथा वे स्वतन्त्र रूप से असंगठित श्रमिकों को नियुक्त करती हो। आजकल उत्पादक इकाइया अधिकतर बड़े आकार की होती हैं अथवा छोटी इकाइया पूर्णतया संगठित होती हैं। श्रमिक भी स्वतन्त्र रूप से श्रम-बाजार में श्रम की पूर्ति नहीं करते। वे भी श्रम संघों (Labour or Trade Unions) के रूप में संगठित होते हैं। वे श्रम सव ही श्रम की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की स्थिति अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति कहलाती है। श्रम-बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

(1) नियोजकों की संख्या बहुत ही कम होती है। नियोजक भी पूर्णतः

संगठित होते हैं। उनमें श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। (ii) नियोजकों या फर्मों का आकार बड़ा होता है। (iii) श्रमिक वर्ग भी संगठित होता है तथा श्रम सघ नियोजकों के सघों से मोदा करने (bargaining) में समर्थ होता है। (iv) श्रमिक में अत्यधिक गतिशीलता नहीं पायी जाती।

इन विशेषताओं में युक्त श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दो स्थितियाँ पायी जाती हैं (i) जब मजदूरी निर्धारण में संगठित नियोजकों की 'सौदा शक्ति' (bargaining power) सबल होती है तब ऐसी स्थिति को केना एकाधिकार की स्थिति (monopsony) कहते हैं (ii) इसके विपरीत जब श्रम सघ की सौदा-शक्ति अधिक सबल होती है और ये श्रम-सघ ही एकाधिकारी की तरह श्रम की पूर्ति नियंत्रित करते हैं, तब ऐसी स्थिति को एकाधिकार की तरह नियंत्रण (monopolistic control) की स्थिति कहा जाता है।

श्रम-बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होने पर सीमान्त मजदूरी तथा औसत मजदूरी की रेखाएँ आसम में नहीं मिलती। (जैसा कि चित्र सं० 133 में  $AW$  तथा  $MW$  रेखाओं से स्पष्ट है।) साम्य या संतुलन की दशाओं (conditions of equilibrium) में सीमान्त मजदूरी तथा सीमान्त उत्पादन  $MP_1$  के बराबर है और औसत मजदूरी व औसत उत्पादन  $MP$  के बराबर है क्योंकि सीमान्त उत्पादन व  $MP$  सीमान्त मजदूरी रेखा  $MW$  को  $P_1$  पर काटता है तथा औसत उत्पादन-



चित्र संख्या 133

वक्र  $AW$  औसत मजदूरी रेखा  $AW$  को  $P$  बिन्दु पर काटता है। आधार रेखा  $OX$  पर  $P_1$  से लम्ब  $PM$  खींचने पर यह ज्ञात होता है कि श्रम की पूर्ति  $OM$  मात्रा के बराबर है।  $OM$  रोजगार-स्तर पर औसत मजदूरी तथा औसत उत्पादन बराबर ( $MP$ ) है, परन्तु सीमान्त मजदूरी तथा सीमान्त मजदूरी उनसे अधिक  $MP_1$  के बराबर है। इससे यह स्पष्ट है कि औसत उत्पादन सीमान्त से कम



है अथवा श्रमन मजदूरी सीमान्त मजदूरी से कम है। नियोजक श्रमिकों को श्रमन मजदूरी से अधिक नहीं देना चाहेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि श्रम की उत्पादकता का मूल्य मजदूरी के बराबर नहीं होगा। जिस सीमा तक उनकी सीमान्त उत्पादकता से कम मजदूरी मिलेगी, उस सीमा तक, यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है। उपर्युक्त चित्र में यदि श्रमिकों को श्रमन मजदूरी  $MP$  दी जा रही हो तो उनका शोषण  $(P_1M - PM) = P_1P$  सीमा तक किया जा रहा है।

### सामूहिक सौदेबाजी-सिद्धांत (Collective Bargaining Theory) :

वर्तमान युग अपूर्णता का युग है। यही कारण है कि पूर्ण स्पर्धा की स्थिति केवल काल्पनिक मानी जाती है। व्यावहारिक जीवन में भी यह देखने को मिलता है कि उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्वयं नियमित नहीं कर सकते। वस्तुतः वस्तुओं के मूल्य बर्तमान से प्रभावित होते रहते हैं। इस आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि श्रम-बाजार में श्रम का मूल्य भी परिवर्तनशील होगा है। श्रम का मूल्य उसी स्थिति में प्रभावित रह सकता है जबकि श्रमिक संगठित हों। सभ्यतः इन मांगों के आधार पर ही श्रम संधि का संगठन किया गया था, जिसका उद्देश्य नियोजकों से सौदेबाजी करके मजदूरी-दर को उनके वर्तमान स्तर से ऊंचा उठाना था। 'सौदेबाजी' शब्द इस तथ्य का संकेत करता है कि 'सौदेबाजी का मिटावा' स्वयं मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत नहीं है, वह केवल दो पक्षों के मध्य संधि को संपादित करके कुछ समय के लिये मजदूरी तय करने में सहायक होता है। यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि 'सौदेबाजी का सिद्धांत श्रमिकों के किसी एक वर्ग-विशेष पर, न कि सम्पूर्ण श्रम-बाजार पर लागू होता है। अतः मजदूरी निर्धारण व स्पर्धात्मकता में श्रम और पूँति के तत्वों का कोई सम्बन्ध नहीं होता। व्यावहारिक रूप में इस सिद्धांत के अन्तर्गत मजदूरी-निर्धारण करने में मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक आर्थिक तथा कई ग्रहण्य तत्वों के आधार पर ही मजदूरी निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार मौखिक मजदूरी दरें तथा रोजगार की दशाएँ श्रम संधि तथा नियोजक संधि के मध्य पारस्परिक सम्भोजी के द्वारा तय की जाती हैं। यह विधि ही 'सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining)' की विधि है। इस विधि से नियोजक को यह लाभ होता है कि उनके प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा मजदूरी में कमी किए जाने की नीति नहीं अपनायी जाती।

### मजदूरी तथा श्रम-संघ (Wages and Trade Unions) :

व्यवहार में प्रतिस्पर्द्धात्मक दशाएँ नहीं पायी जाती तथा श्रम संधि मजदूरी की दरों को प्रभावित करने में सफल होती है। श्रम संधि का मूल लक्ष्य यह है कि

श्रमिकों की मोल करने की क्षमता नियोक्ता की तुलना में सबल हो, ताकि श्रमिकों को उत्पादन का उचित भ्रश और काय की अच्छी दशाएँ प्राप्त हो सकें। अपने साथ के श्रमिकों में किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किए बिना, कोई श्रमिक या निश्चितरूप से अपने नियोक्ता की तुलना में सौदा करने की स्थिति में नहीं रहता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम का उसके सीमांत उत्पादन मूल्य के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है तथा अनुचित मोल करने का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु व्यवहार में इन बातों का आश्वासन नहीं है कि श्रम को उसके सीमांत उत्पादन मूल्य (MVP) के बराबर मजदूरी मिलेगी ही। शायद यह भी संभव नहीं है कि व्यवहार में सीमांत उत्पादन की माप ठीक ठीक की जा सके। साथ ही एक उद्योग से दूसरे उद्योग में श्रमिकों की गतिशीलता की माप में भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं जिनके कारण सीमांत उत्पादन तथा आय में बहुत बड़ी अममानता पायी जाती है। किसी परिस्थिति में यदि सभी नियोक्ता अपने श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादन से कम मजदूरी देने हैं तो पूर्ण गतिशीलता की माप करने में वह मजदूरी अग्रणी सिद्ध होगी। अतः किसी उद्योग में मजदूरी का स्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सम्बन्ध नियोक्ता तथा श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर होगा। यहाँ श्रमिक सघों का मुख्य लक्ष्य इस बात को सुरक्षित करना है कि सामूहिक रूप से श्रमिकों की मोल करने की क्षमता कम से कम नियोक्ता की क्षमता के बराबर हो। वास्तव में श्रम सघ श्रम की मांग व पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर मजदूरी निर्धारण में सहायक होने हैं जिनमें न तो उत्पादकों की अधिक मजदूरी के कारण श्रमिकों को हटाना पड़ और न ही श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी मिले कि वह उनके जीवन-निर्वाह के लिए भी पर्याप्त न हो। इस प्रकार एक तरफ बरोजगारी तथा दूसरी तरफ हड़ताल आदि की सम्भावनाओं का दूर करने में श्रम सघ सहायक होते हैं। बहुत सी परिस्थितियों में श्रम सघों ने पूर्ण सफलता के साथ इन लक्ष्यों को प्राप्त किया है तथा नियोक्ताओं को मजदूरी निर्धारण के लिये सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम को अपनाना पड़ा है ॥

श्रम सघों की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि श्रम की पूर्ति शून्य भी हो सकती है और ऐसा हड़ताल के द्वारा सम्भव है। किन्तु सघों की यह शक्ति इस बात पर निर्भर है कि पूरे उद्योग की श्रम शक्ति का कितना भाग श्रम सघ का सदस्य है, इसके सदस्यों में अनुशासन तथा हड़ताल कितनी है? वित्तीय बाप की मात्रा तथा इसके नेताओं की योग्यता क्या है?

श्रम सघों के काय श्रम सघ मजदूरों की संगठित शक्ति का प्रतीक है। वह उनके व्यक्तित्व का विकास करता है तथा उनकी शक्ति को संगठित करके उन्हें मशक्त बनाता है। वह श्रमिकों के उचित हितों की रक्षा करता है,

उनकी सधर्प शक्ति बढाकर उन्हें नियोजनों से आवश्यक मुविचार्यें दिलाता है। इनके अतिरिक्त मजदूरी निधारण एव वृद्धि में उसके महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी में वृद्धि अपूर्ण प्रतिभागिता में जब श्रमिकों को उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती तथा उनका शापण किया जाता है तब श्रम-संघ अपनी सीमा शक्ति के बत पर मजदूरी-वृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं।

(2) श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि श्रमिकों की उत्पादन समता को बढाने में श्रम-संघ का विशेष स्थान माना जाता है। वे श्रमिकों की काय क्षमता बढाने की दिशा में श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ उत्पादकों एवं नियोजकों को श्रमिकों की कार्य दक्षता में तथा आधुनिकतम तकनीकी विधियों को अपनाने के लिए बाध्य करना है। वह स्वयं भी श्रमिकों की सहाई के लिए कई कल्याणकारी कार्य करता है।

श्रम संघ की शक्ति की सीमाएं श्रमिक संघ चाहे जितनी भी सबल हो, उसके सदस्यों की मजदूरी में वृद्धि एक सीमा तक ही सम्भव है।

(1) बेरोजगारी की स्थिति इसका कारण यह है कि नियामकों के समुदाय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मजदूरी में और वृद्धि हान पर श्रमिकों को नियुक्त करना सामंजस्य नहीं होता। अगर श्रम-संघ इस बिन्दु के यात्र को वृद्धि करने का प्रयत्न करता है तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम संघ को अपनी मांग में परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ हमें अधिक मजदूरी की उत्पादकता का भी स्थान रखना चाहिये।

(ii) अन्य साधनों की प्रतिस्थापना श्रम-संघ को इस तथ्य पर भी ध्यान देना पड़ता है कि किसी उद्योग में श्रम की तुलना में अन्य साधनों की जितने सुविधा-पूर्वक प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मजदूरी में वृद्धि के साथ यह सम्भव है कि उत्पादकता में श्रमिकों को काम पर लगाये, क्योंकि अन्य साधन प्रयोज्य हो सकते हैं। अधिक सीमा तक यह उद्योग से सम्बन्धित इन वैकल्पिक साधनों की पूर्ति की सोच पर निर्भर करेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पूँजी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की है तो यह सम्भव नहीं होगा कि बिना किसी वित्तम्ब तथा मूल्य-परिवर्तन के शोध की श्रम का पूँजी द्वारा प्रतिस्थापन हो सके। उद्योग में प्रतिस्थापन की सोच जितनी ही अधिक होगी मजदूरी की दर वृद्धि कराने में श्रम-संघ की शक्ति उतनी ही कम होगी।

(iii) वस्तु की माग की सोच : श्रम संघ की शक्ति स्वयं वस्तु की माग की सोच पर भी निर्भर करेगी। यदि माग वेलोच है तो उत्पादक मजदूरी की वृद्धि में,

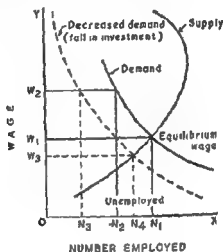
अधिक मूल्य के रूप में, बिना बिज्जी पर बुरा प्रभाव डाले उपभोक्ताओं पर टाल सकता है। इस स्थिति में उत्पादक श्रम-संघ की माग का ज्यादा विरोध भी नहीं करेगा, किन्तु ठीक इसके विपरीत, यदि उत्पादक की वस्तु की माग लोचपूर्ण है तो मूल्य में वृद्धि के साथ ही माना में कमी होगी। अतः उत्पादक मजदूरी में वृद्धि की माग का तीव्र विरोध करेगा।

निष्कर्ष यह है कि चाहे श्रम संघ कितना ही सबल क्यों न हो, एक ऐसा बिन्दु आ जायेगा जिसके बाद मजदूरी में वृद्धि इसके सदस्यों में बेरोजगारी लाये बिना सम्भव नहीं है। संघ का कोई भी उत्तरदायी नेता ऐसा खतरा लेने को तैयार नहीं होगा।

**श्रम संघ तथा सौदेबाजी (Trade unions and Bargaining) :** श्रम संघों के संगठन से, श्रम के नेताओं के अधिकार या शक्ति (monopsonist power) नष्ट हो जाती है या काफी अंशों तक कम हो जाती है। श्रम संघों की शक्ति बढ़ने से एक प्रकार से द्विपक्षीय एकाधिकार (Bilateral monopoly) की स्थिति हो जाती है। श्रम संघ न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी की माग करने हैं। इसी प्रकार मालिक भी एक निश्चित सीमा के ऊपर मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तथा उस सीमा से कम मजदूरी देना चाहते हैं। अतः इन दोनों सीमाओं (श्रम संघ द्वारा माँगी गई न्यूनतम मजदूरी तथा मालिकों द्वारा दी गई अधिकतम मजदूरी) के बीच, सौदेबाजी द्वारा मजदूरी दर का निर्धारण होता है।

श्रम संघों की सौदेबाजी की क्षमता सामान्यतया मालिकों की तुलना में कम होती है क्योंकि (i) श्रमिक सम्पत्तिहीन होते हैं (ii) उनकी गतिशीलता कम होती है तथा (iii) साधनों पर श्रमिकों का अधिकार नहीं होता है। सौदेबाजी की स्थिति पर चित्र स 134 द्वारा प्रकाश पड़ता है। चित्र में पूर्तिवक्र व्यक्तिगत श्रमिक के पूर्ति वक्रों का योग है तथा मांग वक्र व्यक्तिगत फर्मों के सीमांत उत्पादकता वक्रों का योग है।  $OW_1$  साम्य-मजदूरी है। इस मजदूरी पर  $ON_1$  श्रमिक बेरोजगार में हैं। यदि श्रम, माल, मजदूरी, दर को, बदलते,  $OW_2$  करते,  $O$  पर,  $ON_2$  हो जाएगा तथा बेरोजगारी में वृद्धि होगी। कुछ समय पश्चात् यह सम्भव है कि श्रम की पूर्ति कम हो जाए तथा बेरोजगार की मात्रा इतनी कम हो जाए कि मजदूरी के पुनः घटने की सम्भावना ही न रह जाए। श्रम संघ बेरोजगारी को बढ़ावा देने के कारणों में उद्योग में विनियोग बढ़ेगा तथा बाद में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, परन्तु यदि प्रारम्भ में ही श्रम संघ कम मजदूरी पर सहमत हो गए हो तो विनियोग बढ़ने पर वे अधिक मजदूरी के लिए सतर्क रहेंगे।

परन्तु यदि विनियोग घट जाए, जैसा कि चित्र में घटे हुए मांग वक्र द्वारा दर्शाया गया है तो रोजगार घटकर  $ON_3$  हो जाएगा। अधिक बेरोजगारी के कारण मजदूरी घटकर  $OW_3$  के मानपास हो जाएगी। जोकि पहले की साम्य मजदूरी  $OW_1$  से कम होगी।



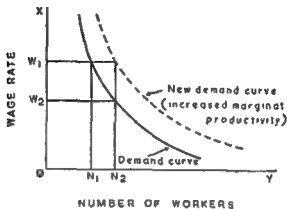
चित्र संख्या 134

इस प्रकार श्रम संचो की सौदेबाजी की क्षमता, मालिकों की तुलना से कम होती है। श्रम की सौदेबाजी की शक्ति केवल 'श्रम बाजार' पर ही नहीं बल्कि मालिकों के वस्तु बाजार' पर भी निर्भर है। यदि मालिक कच्चा माल खरीदने की स्थिति में monopsonist है तथा उत्पादित-वस्तु बेचने की स्थिति में एकाधिकारी (monopolist) है, तो वह कच्चे माल के लिए कम कीमत देकर तथा उपभोक्ताओं से वस्तु की अधिक कामत वसूल कर, बड़ी हुई मजदूरी के प्रभाव को दूर कर सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई मजदूरी में एक वर्ग को लाभ, तथा दूसरे वर्ग को हानि होती है। इस विधि द्वारा मजदूरी-दरों में सामान्यतया वृद्धि नहीं की जा सकती है।

ऊँची मजदूरी की श्रम व्यवस्था (The Economy of high wages)। चित्र सं० 135 द्वारा ऊँची मजदूरी के परिणाम पर प्रकाश पड़ता है। यदि मजदूरी की दर  $OW_2$  है तो  $ON_2$  अधिक काम पर लगाए गए हैं। यदि मजदूरी बढ़ाकर  $OW_1$  कर दी जाए तो काम में लगे हुए श्रमिकों की संख्या घटावी पड़ेगी तथा केवल  $ON_1$  अधिक काम पर लगाए जाएंगे।

परन्तु यह कहा जा सकता है कि मजदूरी ऊँची होने से श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार होगा, इस प्रकार उनकी उपादरना में वृद्धि होगी तथा मांग वक्र

दाहिनी तरफ गिसकेगा इस प्रकार  $OW_1$  साम्य-मजदूरी हो जाएगी तथा इस मजदूरी पर  $ON_2$  श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार मजदूरी बढ़ने पर प्रारम्भ



चित्र सख्या 135

में श्रमिकों की संख्या में कमी होगी है, परन्तु बाद में यह कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने से उनकी मांग बढ़ जाती है।

### प्रश्न व संकेत

1. मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त की विवेचना करिए।

(Ravishankar, B A Final 1965)

[संकेत—मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करने हेतु यथास्थान चित्र देते हुए 'उद्योग' तथा "व्यक्तिगत" 'फर्म' दोनों के सम्बन्ध में मजदूरी के निर्धारण को समझाइये।]

2. मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करिए।

(Raj M A 1964)

[संकेत—मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त को स्पष्ट करिए और उसकी सीमाओं को समझाइये।]

3. 'यदि मजदूरी का निर्धारण श्रम की सीमांत उत्पादकता द्वारा होता है तो श्रमिक संघ अनावश्यक है।' इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

(Raj. M. Com, 1969)

[संकेत—पहले सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण समझाइये तथा बाद में संक्षेप में श्रम-संघों द्वारा मजदूरी को प्रभावित करने की दशाओं का वर्णन करते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी दीजिए।]

# 36

## व्याज ( Interest )

*"Interest is simply a bourgeois device for exploitation"*

—Karl Marx

पूँजी की सेवाओं के बदले में पूँजी के स्वामी को दिए गए पुरस्कार को व्याज कहते हैं। साधारण बाल बाल को भाषा में ऋणी द्वारा मूलधन के अतिरिक्त, धनी को किए गए भुगतान को व्याज कहते हैं। अर्थशास्त्र में इस 'कुल व्याज' कहते हैं। अर्थशास्त्र में व्याज दो प्रकार का माना गया है — 'शुद्ध व्याज' तथा 'कुल व्याज'।

1. शुद्ध या वास्तविक व्याज (Net Interest) : शुद्ध व्याज उस व्याज को कहते हैं जिनमें केवल पूँजी का प्रतिफल सम्मिलित होता है।

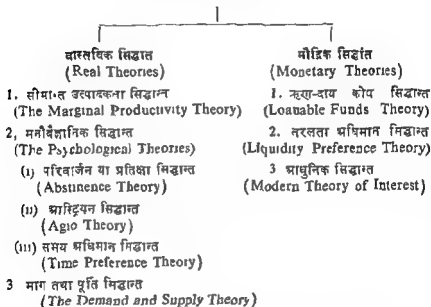
2. कुल व्याज (Gross Interest) : कुल व्याज के अन्तर्गत शुद्ध व्याज, जोखिम उठाने के लिए किया गया भुगतान, धनी के अन्य व्ययों का दाय, तथा धनी की प्रसुविधाओं के बदले किया गया भुगतान सम्मिलित किया जाता है। जब पूँजी-पति पूँजी लगाता है तो उसे कुछ जोखिम वहन करने पड़ते हैं। इस जोखिम के बदले में उसे प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए। मार्शल ने दो प्रकार के जोखिमों का उल्लेख किया है। (i) व्यापारिक जोखिम (Trade Risks) जो जोखिम वस्तुओं का मूल्य गिर जाने या मन्दी के कारण उठाना पड़ता है, उसे व्यापारिक जोखिम कहते हैं। जोखिम का अंश अधिक होने पर व्याज की दर ऊँची होती है। (ii) व्यक्तिगत जोखिम (Personal Risk) इसका सम्बन्ध ऋणी की स्थिति से है; हो सकता है ऋणी ऋण को वापस न करे। अतः इस जोखिम के लिए भी धनी प्रतिफल प्राप्त करना चाहता है। ये दोनों प्रकार के जोखिम व्यक्ति से सम्बन्धित होते हैं, अतः कुल व्याज की दरों में विभिन्नता पाया जाना स्वाभाविक ही है। जोखिम उठाने के अतिरिक्त, ऋण को वशूल करने तथा हिमाव-विताव रखने के लिए भी, ऋण दाता को खर्च करना पड़ता है, अतः वह व्याज के रूप में इन व्ययों को भी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार :

कुल व्याज = जोखिम उठाने का प्रतिफल + ऋण सम्बन्धी व्यय + शुद्ध व्याज

## व्याज निर्धारण के सिद्धान्त (Theories of Interest Determination)

व्याज दर का निर्धारण किम प्रकार किया जाता है ? इसके सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उन सिद्धान्तों को हम सरलता की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं :

### व्याज सिद्धान्तों का वर्गीकरण



व्याज-निर्धारण के वास्तविक सिद्धान्त, व्याज को पूँजी से प्राप्त आय के रूप में देखते हैं। वास्तविक सिद्धान्तों के अन्तर्गत व्याज का सम्बन्ध कतिपय वास्तविक साधन—पूँजी की उत्पादकता, प्रतीक्षा तथा समय अधिमान से जोड़ा गया है। 'वास्तविक सिद्धान्त' व्याज के पुराने सिद्धान्त है। इसके विरुद्ध व्याज निर्धारण के मौद्रिक सिद्धान्त अपेक्षाकृत नवीन हैं। इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत व्याज विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है। अब हम व्याज के उपर्युक्त सिद्धान्तों में से सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त, तथा व्याज सम्बन्धी तीनो मौद्रिक सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे।

### 1. व्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory of Interest)

(1) सिद्धान्त की व्याख्या : यह सिद्धान्त जे० बी० क्लार्क तथा विकस्टेड के विवरण सम्बन्धी सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त पर आधारित है। सर्व प्रथम



लाउडरडेल (Lauderdale) ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया। इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज की दर का विचारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा होता है। पूँजी के प्रयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः पूँजी की मांग उत्पादन वृद्धि के लिए की जाती है। ज्यों ज्यों पूँजी की अधिकाधिक मात्रा संचार ली जाती है, पूँजी का मांग मूल्य कम होता जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में पूँजी का प्रयोग करने से उसकी क्रमागत इकाइयों की उत्पादकता 'सीमान्त उत्पादकता' द्वारा नियंत्रित के अनुसार घटती जाती है। व्याज दर की प्रवृत्ति पूँजी की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होने की होती है। यदि व्याज दर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में कम है तो अधिक पूँजी का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार पूँजी की मांग बढ़ेगी तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कम होगी। अतः व्याज दर तथा सीमान्त उत्पादकता समान हो जाएगी। इसके विपरीत यदि व्याज दर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता से अधिक हो तो कम पूँजी का प्रयोग किया जाएगा। इससे पूँजी की सीमान्त उत्पादकता बढ़ेगी तथा उसकी मांग कम होगी। अतः व्याज दर, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जाएगी अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि साम्य की अवस्था में, दीर्घकाल में, व्याज पूँजी की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा।

पूँजी की मांग . पूँजीगत सम्पत्तियों की मांग क्यों होती है? इसका उत्तर हम प्रकार दिया जा सकता है, "इसकी मांग इसलिए की जाती है कि वे उपयोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं—अर्थात् साधनों की तरह उनकी भी आय उत्पत्ति (revenue product) होती है।" पूँजीगत सम्पत्ति का सीमान्त उत्पादकता बढी जा सकता है। एक उपक्रमी इस बात का अनुमान लगा सकता है कि रोजगार के प्रत्येक स्तर पर उसके कुल भण्डार में कितनी वृद्धि होगी।

पूँजीगत वस्तु की सीमान्त उत्पादकता ज्ञात करने में दो कठिनाइयाँ आती हैं। उपक्रमी को सम्पत्ति (मान लीजिए मशीन) की वर्तमान नहीं, बल्कि भावी उत्पादकता का विषय में अनुमान लगाना पड़ता है। इस भावी उत्पादकता को future yield कह सकते हैं। 1. सम्पत्ति (मशीन को) से सुचारु रूप से काम लेने के लिए बराबर कुछ खर्च करना पड़ता है।

मशीन खरीदते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। मशीन उभी अवस्था में खरीदी जाएगी जबकि मशीन की आय उत्पत्ति (revenue product) कम से कम (1) मशीन की लागत + (2) लागत पर बाजार दर से आने वाले व्याज के बराबर हो। यदि मशीन की आय उत्पत्ति इन दोनों के योग से कम है तो मशीन नहीं खरीदी जाएगी। अतः यह कहा जा सकता है कि एक उपक्रमी जो किसी मशीन को खरीदना चाहता है, सर्व प्रथम वह मशीन से होने वाली भावी आय (Future

yield) पर विचार करना है। भावी प्राप्ति का अनुमान मशीन के कार्य काल या आयु तथा उसमें प्रयत्न करने वाली आय उत्पन्न के आधार पर किया जा सकता है। भावी मानक सम्पूर्ण कार्यकाल की सभी आयों को जोड़ना चाहिये। द्वितीय वह मानक की लागत तथा तृतीय मशीन को खरीदने के लिए उधार की गई रकम पर दिए जाने वाले व्याज का भी ध्यान में रखना।

इसके पश्चात् (1) उपर्युक्त मशीन की विमुक्त भावी प्राप्ति, (Net Future yield), (मशीन का भाग को घटा कर) की तुलना मशीन खरीदने के लिए उधार की गई राशि पर दिए जाने वाले व्याज से करेगा। या (ii) वह मशीन की लागत की तुलना मशीन में प्राप्त होने वाली राशियों की बट्टा कटा हुआ कीमत (Discounted value of its prospective yield) अर्थात् वर्तमान मूल्य (Present Value) से करेगा। इन दोनों ही विधियों द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदी जाए। यदि मशीन की विमुक्त भावी प्राप्ति के कुल योग में से मशीन की लागत घटाने पर जो कुछ शेष बचता है वह मशीन को खरीदने के लिए उधार की गई पूँजी के व्याज से अधिक है तो मशीन खरीदी जाएगी या यदि बट्टा कटी हुई विमुक्त भावी प्राप्ति मशीन की लागत से अधिक है तो भी मशीन खरीदी जाएगी।

इसके विपरीत यदि ध्यान पर दिए जाने वाले व्याज (तथा पूँजी) की मात्रा मशीन की विमुक्त भावी प्राप्ति से अधिक है या मशीन की लागत उससे बड़ा कांति हुई विमुक्त भावी प्राप्ति से अधिक है तो मशीन नहीं खरीदी जाएगी। उपर्युक्त किसी भी परिणाम (Assets) से प्राप्त होने वाले भावी प्रतिफल का अनुमान लगा सकता है। उनके उत्पादन की आशा इनकी किसी भी दी हुई आकांक्षा की जा सकती है ठीक उसी प्रकार से एक दी हुई किस्म की परिणाम का विभिन्न भावों से उद्यम करता अथवा उद्योग का प्राप्त होने वाली आय का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ हम विभिन्न परिणाम का विवरण करते हैं उसका सीमाना उत्पादकता बरूनी जा सकता है जो यह प्रकट करना है कि एक फल की परिणाम के लिए एक एक इकाई और धन देने में उनकी मात्रा में किन्तनी वृद्धि होती है। (स्टानियर तथा डेग) यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि एक परिणाम (मान लेते हैं मशीन) की सीमाना आय उत्पादकता तथा सीमाना भावी प्राप्ति दोनों समान (एक ही) होते हैं। 'भावी प्राप्ति के समय में यह याद रखना चाहिए कि (1) भावी प्राप्ति (Future yield) का निर्धारण उन प्रतिफल द्वारा होता है जो एक अवधि विशेष में प्राप्त होते हैं परन्तु प्रति इकाई समय (Per unit of time) के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रतिफल समान नहीं होते हैं (ii) भावी प्राप्ति का अनुमान पर आधारित होती है तथा उनका सम्बन्ध में लगाए

गए अनुमान गलत सिद्ध हो सकते हैं। (iii) जिन परि सम्पत्तियों का जीवन काल अधिक होता है उन पर जीवन-काल वाली परि सम्पत्तियों की तुलना में, ऊँची दर से बढ़ा काटा जाता है। क्योंकि अधिक जीवनकाल वाली परि सम्पत्ति के लिए अधिक व्याज देना पड़ता है (रकम ज्यादा समय के लिए उधार ली जाती है) अतः विभिन्न जीवन काल वाली परि सम्पत्तियों की सीमान्त उत्पादकताओं या भावी प्राप्तिओं की तुलना नहीं की जाती है, बल्कि बढ़ा काटी हुई सीमान्त उत्पादकताओं अथवा बढ़ा काटी हुई भावी प्राप्तिओं की तुलना की जाती है।

किसी भी परि सम्पत्ति में सम्बन्धित सीमान्त आय उत्पादकता वक्र (MRP) को उसका मांग वक्र या बढ़ा काटी हुई सीमान्त उत्पादकता वक्र कहा जा सकता है। यह वक्र प्रतिकूलों के वर्तमान मूल्य को प्रकट करता है। यह वक्र लगभग सामान्य मांग वक्र की भाँति, बाएँ से दाहिनी ओर झुकता हुआ होता है। एक उपक्रमी, यदि एक प्रकार की मशीनों की सरया में एक से वृद्धि करता है तो उसकी प्राप्ति कम होगी।

यदि बाजार में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति है तो एक उपक्रमी के लिए साधन का पूर्ति वक्र एक क्षैतिज, सरल रेखा (Horizontal Straight line) के रूप में होगा। एक उपक्रमी, साधन की खरीद-मात्रा में उस बिन्दु तक वृद्धि करता जाता है, जिस बिन्दु पर साधन की खरीदी गई अन्तिम इकाई की सीमान्त उत्पादकता (बढ़ा काटने के पश्चात्), उस साधन की लागत के बराबर हो जाती है।

यदि साधन की कीमत दो हुई मान ली जाए तो बाजार दर में कमी होने पर उपक्रमी साधन की अधिक मात्रा खरीदेगा। क्योंकि उधार लिए जाने वाले धन की लागत कम पड़ती है, अतः भावी प्रतिफलों पर कम दर से बढ़ा काटा जाएगा। व्याज दर जितनी ही कम होगी, अन्य बातों के समान रहने पर, साधन की मांग अधिक होती है। अतः साधन का मांग वक्र (अथवा साधन की खरीदने के लिए लिया गया उधार धन सम्बंधी वक्र) नीचे की ओर झुकता हुआ होता है (बाईं से दाहिनी ओर)।

मौद्रिक पूंजी की पूर्ति की दशाएँ : अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि साधनों व सम्पत्तियों की खरीदने के लिए, उधार दी जाने वाली राशि, व्याज दर से किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि यह मान लिया जाए कि सम्पूर्ण बचत, उपक्रमियों को साधन तथा परिसम्पत्तियों की खरीदने के लिए उधार दे दी जाती है। जो लोग उधार देते हैं उन्हें वर्तमान उपभोग का त्याग करना पड़ता है। इस त्याग के बदले उन्हें कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए। उधार देने वाला त्याग के साथ ही साथ जोखिम भी उठाता है (उधार दिए गए धन का लौटना अनिश्चित रहता है)। जोखिम अधिक होने पर उधार देने की तत्परता कम होती है। अतः समस्त

उद्योग के लिए उधार दिये जाने वाले कोष से सम्बन्धित पूर्ति-वक्र बनाया जाए तो ऐसा पूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठना हुआ होगा। अधिक पूँजी उधार देने पर वर्तमान उपयोग का अधिक त्याग करना पड़ता है फलस्वरूप उधार देने वाले अधिक ब्याज लेना चाहते हैं। साथ ही साथ जब अधिक पूँजी की माग होती है तो ऐसे व्यक्तियों से भी उधार लेना पड़ता है जो जातिम की चिंता अधिक करते हैं तथा वे ऊँची ब्याज पर ही उधार देने को तैयार होते हैं।

इस प्रकार ब्याज की वास्तविक दर उधार देय कोषों की नीचे झुकी हुई माग वक्र तथा ऐसे उधार देय कोषों की ऊपर उठती हुई पूर्ति वक्र के कटान बिन्दु (inter section point) पर होता है।

(11) सिद्धान्त की आलोचना (1) एकांगी सिद्धांत ब्याज का सीमान उत्पादकता सिद्धांत एकांगी है। इस सिद्धान्त में सम्पूर्ण ध्यान माग वक्र पर ही केन्द्रित कर दिया गया है तथा पूर्तिपक्ष की उपेक्षा की गई है। ब्याज क्यों लिया जाता है? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मौन है। यह सिद्धान्त पूँजी के पूर्ति मूल्य की उपेक्षा करता है।

(2) केवल पूँजी की उत्पादकता ही ब्याज का कारण नहीं पूँजी की उत्पादकता विभिन्न व्यवसायों में अलग अलग होती है, परन्तु सामान्यतः शुद्ध ब्याज की दर एव होती है। अतः उत्पादकता को ब्याज दर का कारण नहीं माना जा सकता है। ब्याज दर केवल उत्पादकता ही नहीं, बल्कि पूँजी की पूर्ति, धनी नृणा सम्बन्ध तथा भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। उत्पादकता में वृद्धि कर ब्याज दर को ऊँचा नहीं उठाया जा सकता है। इस तथ्य के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। ब्याज वक्र पूँजी की उत्पादकता, प्राचीन काल की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है परन्तु पहले से ब्याज की दरें कम हैं। किशोर ने भी यह मत व्यक्त किया है कि उत्पादकता में वृद्धि कर, ब्याज दर को ऊँचा नहीं उठाया जा सकता है।<sup>1</sup>

(3) उपभोग-सम्बन्धी ऋण : यदि ब्याज पूँजी की उत्पादकता पर निर्भर है तो उपभोग सम्बन्धी ऋणों पर ब्याज क्यों लिया जाता है? ब्याज का सम्बन्ध उत्पादकता में मान लेने पर अनुत्पादक ऋणों पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु यह आलोचना उपयुक्त नहीं है क्योंकि पूँजी की 'अवसर लागत' उत्पादकता का ही प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में वे सभी दोष पाये जाते हैं जो विन-रण के सीमान उत्पादकता सिद्धान्त में पाए जाते हैं।

<sup>1</sup> "To raise the rate of interest by raising the productivity of capital is, therefore, like trying to raise one's self by one's boot traps."  
— Fisher

## 2. प्रतिष्ठित सिद्धान्त या 'माग पूर्ति सिद्धान्त'

(Classical Theory or Demand and Supply Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज दर का निर्धारण 'माग विनियोग की माग' (Demand for Investment) तथा 'बचत की पूर्ति' (Supply of Saving) के सन्तुलन बिन्दु पर होता है। जिस प्रकार मूल्य का निर्धारण माग तथा पूर्ति के सन्तुलन बिन्दु पर होता है, उसी प्रकार व्याज दर का निर्धारण 'विनियोग की माग, तथा 'बचत की पूर्ति' के सन्तुलन बिन्दु पर होता है। मार्शल, पीगू, वालरस आदि अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त के प्रतिपादक मान जाते हैं।

1. पूँजी की पूर्ति : पूँजी की पूर्ति, समाज की बचत की मात्रा पर निर्भर है। पूँजी दुर्लभ है अतः उसका पूर्ति मूल्य होता है। यदि व्याज की दर शून्य है तो भी समाज द्वारा बचत की जाएगी परन्तु इस प्रकार की बचत की मात्रा अल्प होगी। बचत के लिए व्याज का प्रोत्साहन सामान्यतया आवश्यक होता है। सीमांत बचतकर्ता (Marginal Saver) को वर्तमान सुख का त्याग करना पड़ता है, वर्तमान उपयोग को स्थगित करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है अतः उसे इस त्याग के लिए पुरस्कार मिलना आवश्यक है। व्याज दर तथा पूँजी की पूर्ति में कलन सम्बन्ध (Functional Relationship) है। अतः ऊँची व्याज दर पर पूँजी की पूर्ति अधिक होती है तथा कम व्याज दर पर पूँजी की पूर्ति कम होती है। व्याज दर के अतिरिक्त व्यक्ति का दृष्टिकोण, आय स्तर, भविष्य में सुरक्षा की आशा आदि भी पूँजी की पूर्ति को प्रभावित करते हैं।

पूँजी की माग पूँजी की माग, उत्पादकों द्वारा, विनियोजन के लिए की जाती है। उत्पादक अधिक से अधिक लाभप्रद व्यवसाय में पूँजी का विनियोजन करना चाहता है। पूँजी की माग उसकी उत्पादकता के कारण होती है, परन्तु पूँजी की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग करने से, उसकी उत्पादकता, उत्तरोत्तर कम होती जाती है। उत्पादक पूँजी का विनियोजन उस बिन्दु तक करता जाता है जिस पर पूँजी की सीमांत उत्पादकता व्याज दर के बराबर होती है। व्याज दर तथा माग में भी सम्बन्ध है। ऊँची व्याज दर पर उत्पादक पूँजी की कम माग करते हैं तथा कम व्याज दर पर वे पूँजी की अधिक माग करते हैं। पूँजी की माग, पूँजीगत वस्तुओं में विनियोजन के लिए की जाती है इसलिए इसकी माग को विनियोग माग (Investment Demand) भी कहते हैं।

3. व्याज दर का निर्धारण व्याज दर का निर्धारण, उस बिन्दु पर होगा, जिस पर पूँजी की माग तथा पूँजी की पूर्ति में सन्तुलन स्थापित होता है। सन्तुलन व्याज दर का निर्धारण, पूँजी की सीमांत उत्पादकता द्वारा किया जाता है।

यदि किसी समय सन्तुलन ब्याज दर (equilibrium rate of interest), पूँजी की सीमात उत्पादकता से अधिक है तो पूँजी की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा कम होगी अतः ब्याज दर घट्यगी तथा वह सीमात उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत स्थिति में ठाक उल्टी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी तथा ब्याज दर पूँजी की सीमात उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार सन्तुलन की स्थिति में ब्याज दर पूँजी की सीमात उत्पादकता के बराबर होगी तथा इस स्थिति में पूँजी की मांग पूँजी की पूर्ति के बराबर होगी।

4. **आलोचना (1)** इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति है। यदि सभी माघन पूर्ण रोजगार की स्थिति में हैं तो बचत के हेतु प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि ब्याज दिया जाये जिससे बचतकर्ता को वर्तमान उपभोग के त्याग के लिए प्रोत्साहन मिल सक। परन्तु यदि रोजगार मात्र न वर्तमान है तो ब्याज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह धारणा गलत सिद्ध होती है।

(2) सिद्धान्त में आय पर विनियोग के प्रभावों की उपेक्षा की गई है। विनियोग में परिवर्तन होने पर आय स्तर में भी परिवर्तन होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि ब्याज दर पूँजी की सीमात उत्पादकता से कम है तथा पूँजी की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर कम होने के कारण, पूँजी की पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी। अर्थात् निम्न ब्याज दर पर, विनियोग की मात्रा में वृद्धि कठिन हो जाती है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। यदि उत्पादन के लिए, अधिक पूँजी (विनियोग) की मांग की जाती है तो लोगों की आय में वृद्धि होगी जिससे बचत बढ़ेगी। बचत बढ़ने के कारण विनियोग वृद्धि होगी। इसी प्रकार मान लीजिए, ब्याज दर में वृद्धि होती है, इसमें विनियोग कम होगा (विनियोजन कम लाभप्रद हो जाएगा), विनियोग कम होने से रोजगार कम होगा, रोजगार कम होने से आय कम होगी, आय कम होने से बचत कम होगी। अतः ऊँची ब्याज दर, बचत के परिमाण को कम करती है जबकि इस सिद्धान्त में यह कहा गया है कि ऊँची ब्याज दर होने से, बचत के परिमाण में वृद्धि होती है।

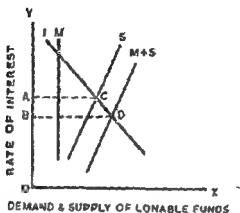
(3) पूँजी की पूर्ति की मात्रा, विनियोग मात्रा से स्वतन्त्र नहीं है (The Supply of Capital is not independent of the investment demand) : विनियोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है, अतः बचत की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। विनियोग में कुछ परिवर्तन होने पर, बचत में किस अनुपात में परिवर्तन होगा ? इसकी जानकारी के लिए ब्याज दर का निर्धारण सर्व प्रथम 'तरलता अधिमान' तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार ब्याज दर का विश्लेषण मौद्रिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

गई बचत का भी अग्र सग्रह करेगे इससे साख बाजार में, पूँजी की पूर्ति में वृद्धि होगी परन्तु यदि व्याज की दर गिरनी है तो लोग वर्तमान निर्वर्त्य आय में से भी सग्रह करना प्रारम्भ करेगे, इस प्रकार बाजार में उपलब्ध 'उधार देय कोष' कम होगा । (ii) बैंक साख (Bank Credit) मुद्रा की पूर्ति बैंक-मुद्रा या साख-मुद्रा से भी प्रभावित होनी है । साख-मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से 'उधारदेय कोष' में वृद्धि होती है । (iv) अन्य तत्व ( Other Factors ) : उपरोक्त तत्वों के अनि रिक्त व्यावसायिक सस्थानों के मूल्य-ह्रास काप, सामान्य-संचित कोष आदि तथा वचन को प्रमाणित करने में सम्बन्धित सरकार की आर्थिक नीतियां, उधारदेय कोष की मात्रा को प्रभावित करती है ।

(2) उधारदेय कोषों की माग उधारदेय कोषों की माग नए विनियोगों तथा नकद राशि या सग्रह की गई राशि के कारण होती है । ऋण की माग उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिए की जा सकती है । अतः उधारदेय कोष की कुल माग इन दोनों से सम्बन्धित मागों पर निर्भर है । ऋण की माग व्याज-दर पर भी निर्भर है कम व्याज दर पर ऋण की माग अधिक होनी है तथा ऊँची व्याज दर पर ऋण की माग कम होती है । मुख्य रूप में उधारदेय कोष की माग चार प्रकार से की जाती है, (i) उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा (ii) सरकार द्वारा (iii) उप-भोक्ताओं द्वारा और (iv) भण्डार के लिए (hoarding)

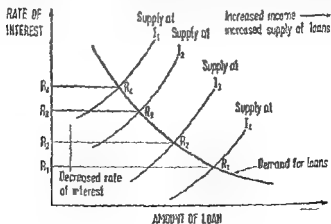
(3) सिद्धांत का स्पष्टीकरण Wickseil द्वारा बतलाए गए इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है । वचन तथा साख मुद्रा का योग (Total) उधार देय कोष की पूर्ति का प्रकट करता है । इस प्रकार उधारदेय कोष की माग तथा उधारदेय कोष की पूर्ति द्वारा व्याज-दर का निर्धारण होता है । साख-मुद्रा की मात्रा, बैंकों की तरलता (Liquidity) पर निर्भर है तथा 'बैंक-साख की मात्रा' व्याज दर द्वारा प्रभावित नहीं होती है (Bank credit is interest inelastic) । इस प्रकार बैंक-साख से सम्बन्धी रेखा व्याज को प्रकट करने वाली रेखा के समान्तर होगी जैसा कि चित्र में M रेखा प्रकट करती है ।

चित्र सं० 136 में OX अक्षर पर उधारदेय कोष की माग तथा पूर्ति और OY पर व्याज की दर प्रदर्शित की गई है । M रेखा मुद्रा को प्रकट करती है । S रेखा, व्याज की विभिन्न दरों पर वचन की प्राप्य-मात्रा को प्रकट करती है । M+S रेखा उधारदेय कोष की कुल मात्रा को प्रकट करती है जो बैंक साख तथा वचन का योग है । I रेखा विनियोग की माग (Investment Demand Schedule) तालिका को प्रकट करती है । व्याज दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होगा, जिसपर S+M तथा I रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं अर्थात् व्याज दर OB होगी ।



चित्र सख्या 136

उधारदेय कोष सिद्धान्त को दूसरी विधि द्वारा भी समझाया जा सकता है। यह सिद्धान्त, यह बतलाता है कि व्याज-दर यह दर है, जो ऋणों की माग तथा पूर्ति को समुचित करती है (equates) चित्र सख्या 137 में, यदि पूर्ति वक्र  $I_1$  की तरह है तो व्याज-दर  $R_4$  होगी। परन्तु पूर्तिवक्र उधार देने वालों की आय पर निर्भर है। एक दी हुई व्याजदर पर, ऊँची आय होने पर ऋण की पूर्ति अधिक होगी। चित्र में  $I_4$  पूर्तिवक्र,  $I_1$  पूर्तिवक्र की अपेक्षा ऊँची आय पर पूर्ति को प्रकट करता है। चित्र से स्पष्ट है कि, आय में वृद्धि के साथ ही साथ व्याज-दर नीचे गिरती है।



चित्र सख्या 137

चित्र से स्पष्ट है कि आय  $I_1$  होने पर  $R_4$  वह व्याज-दर है जो उधारदेय



कोपो की मांग व पूति को सतुलित करती है। इसी प्रकार आय  $I_4$  होने पर,  $R_1$  व्याज दर है।

व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त तथा उधारदेय कोष सिद्धान्त का अन्तर भी, चित्र सख्या 136 द्वारा जाना जा सकता है। प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार व्याज-दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होता जिस पर  $I$  रेखा तथा  $S$  रेखा एक दूसरे को काटती है। अर्थात् व्याज-दर  $OA$  होगी। उधारदेय कोष सिद्धान्त के अनुसार व्याज-दर  $OB$  होगी।

(4) प्रालोचना : विकसेल ने मांग-पक्ष से सम्बन्धित मौद्रिक-शक्तियों की उपेक्षा की है। (1) उधारदेय कोष की मांग के सम्बन्ध में केवल 'विनिर्माण' पर ही ध्यान दिया गया। कोपो की मांग सचय की प्रवृत्ति से भी प्रभावित होती है, विकसेल ने इस तथ्य की उपेक्षा की। (ii) 'साख की मात्रा के परिवर्तन को व्याज-दर प्रभावित नहीं करती' विकसेल की यह मान्यता गहरी नहीं है। वास्तव में बैंक-साख मात्रा व्याज दर से भी प्रभावित होती है।

इन दोषों को करने के लिए, विकसेल के 'उधारदेय-कोष सिद्धान्त' में बाद में संशोधन किए गए। (हम यहां पर उन संशोधनों का उल्लेख नहीं करेंगे, उपर्युक्त विवरण स्नानक तथा ग्रानर्स वक्ताओं के लिए पर्याप्त है।)

(3) सिद्धान्त की समीक्षा - उधारदेय कोष सिद्धान्त व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त में 'अप-संग्रह' तथा 'साख-मुद्रा' की उपेक्षा की गई थी, जिन पर इन सिद्धान्त में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यह सिद्धान्त वास्तविक परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से ध्यान देता है। अतः कुछ अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त को तरलता अधिमान सिद्धान्त में भी अविकल उद्युक्त मानते हैं<sup>4</sup>।

#### 4 तरलता अधिमान सिद्धान्त (The Liquidity Preference Theory)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन J. M. Keynes ने किया। उनके अनुसार व्याज-दर का निर्धारण 'मुद्रा की मात्रा' तथा 'तरलता अधिमान' द्वारा किया जाता है। इन सिद्धान्त का अध्ययन निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(1) व्याज की प्रकृति (2) व्याज की आवश्यकता तथा (3) व्याज-दर का निर्धारण।

<sup>4</sup>, It corresponds more closely to the way in which the business world thinks of the determinants of the rate of interest and because it shows more directly the relation between the marginal efficiency of investment and the rate of interest" *Haley and Ellis, Survey of Contemporary Economics*

## 1 व्याज की प्रकृति (Nature of Interest) -

(1) Keynes के अनुसार विभिन्न वस्तु व्याज दरें (Commodity rates of Interest) पाई जाती हैं तथा 'मुद्रा-व्याज-दर' उनमें से एक है। जिस प्रकार हम, 'मुद्रा-व्याज-दर' की बात करते हैं उसी प्रकार हम 'गेहूँ-व्याज-दर', मछान व्याज दर, की भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आज 10 मन गेहूँ का विनिमय 1 पय के बाद के 11 मन गेहूँ के बदले, किया जा सकता है तो 'गेहूँ-व्याज-दर' 10 प्रतिशत होगा। विभिन्न वस्तु व्याज-दरों को उन्होंने 'Own-rate' कहा है। (2) वस्तु व्याज दरों में व्योप्त विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं के कारण, केन्स के अनुसार तीन हैं, जो विभिन्न सम्पत्तियों, में विभिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं—(i) उत्पाद (Yield or output) (ii) परिवहन सम्बन्धी व्यय (Carrying Cost) तथा (iii) तरलता प्रीमियम (Liquidity Premium)। इन तीनों को क्रमशः  $q$ ,  $c$  तथा  $l$  द्वारा प्रकट किया जा सकता है। किसी वस्तु के स्वामित्व के बदले, एक निश्चित समय में, पुरस्कार की कुछ मात्रा  $q-c+l$  होगी, अर्थात् किसी वस्तु का Own rate of Interest,  $q-c+l$  होगा।

मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों से कुछ पैदा किया जाता है, परन्तु उगम दोष यह है कि परिवहन सम्बन्धी व्यय बहुत करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी तरलता प्रीमियम भी कम होती है। मुद्रा में तरलता प्रीमियम सर्वाधिक होती है तथा इसे ले जाने में भी सामान्यतः कोई व्यय नहीं करना पड़ता, परन्तु इसका 'उत्पाद' शून्य होता है। सम्पत्ति के स्वामियों (Wealth-Owners) की मांग मछान, गेहूँ, मुद्रा या अन्य वस्तुओं में से किसके लिए होगी? यह इस बात पर निर्भर है कि किस वस्तु का  $q-c+l$  अधिकतम है। सतुलन की स्थिति में मछान, गेहूँ आदि का 'माग मूल्य', मुद्रा के सदृश में ऐसा होगा कि विक्रेतों के बीच चुनाव करने में कोई लाभ नहीं होगा। उन सम्पत्तियों का अधिक उत्पादन किया जाएगा, जिनका माग-मूल्य, पूँति मूल्य में अधिक है। उनके उत्पादन में वृद्धि के कारण 'Own rate of Interest' नीचे गिरने, परन्तु यदि मुद्रा की माग बढ़ जाती है तो अधिक मुद्रा का निर्माण नहीं किया जा सकता है मुद्रा की उत्पादन तथा प्रतिस्थापन-लोच शून्य होती है। (Money has zero elasticity of production and substitution) अतः 'मुद्रा व्याज दर' अन्य 'Own rates' की अपेक्षा कम नीचे गिरती है तथा सामान्यतः यह सभी Own-rates से अधिक होती है।

## 2. व्याज की आवश्यकता (Necessity of interest) :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वचत की मात्रा व्याज-दर पर निर्भर करती है, परन्तु केन्स ने इस विचार का खण्डन किया तथा यह कहा कि वचत

समाज की मौद्रिक आय (Money income) तथा 'सीमात उपभोग क्षमता' (Marginal propensity to consume) पर निर्भर करती है। व्याज का वचत से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका प्रमाण यह है कि लाग वचत का मग्नह (hoarding) भी करते हैं, जिस पर उन्हें कोई व्याज नहीं मिलता है। एक व्यक्ति को आय के सम्बन्ध में दो प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं प्रथम का सम्बन्ध 'उपभोग-क्षमता' से है, जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है कि वह आय के किम भाग का उपभोग वर्तमान के लिए करेगा, तथा कौन सा भाग भविष्य के लिए रखेगा? द्वितीय, वह भविष्य के लिए अपनी आय किम रूप में सुरक्षित रखेगा? इसका सम्बन्ध तरलता से है। क्या वह नकद के रूप में अपनी वचत (आय का भाग) को रखना चाहता है? या वह कुछ प्रश को कुछ समय के लिए त्यागने या अन्यत्र विनियोजित करने के लिए तैयार है। केन्स के अनुसार, सामान्यतः लोग अपनी वचन को नकद के रूप में (Liquid form) में रखना चाहते हैं, परन्तु यदि वह अपनी वचन अन्यत्र विनियोजित करने है तो उन्हें 'नग्नता' का त्याग करना पड़ता है अतः व्याज तरलता के त्याग के लिए पुरस्कार है। Keynes के शब्दों में 'व्याज की दर वह प्रीमियम है जो लोगों को अपने धन को संग्रहित मुद्रा के अनिश्चित अन्य किसी रूप में रखने के लिए प्रेरित करने हेतु चुकाया जाता है।'<sup>5</sup>

(तरलता का अभिप्राय मुद्रा का नकद या ऐम रूप में रखने से है, जिसे व्यक्ति तुरन्त नकद रूप में परिवर्तित करा सके। व्यक्ति मुद्रा को 'नकद' या मौद्रा-तिथीय नकदी में परिवर्तनीय रूप में रखना चाहता है। केन्स ने इसे Liquidity Preference कहा है।)

तरलता अभिप्राय के कारण (Motives for Liquidity Preference) : मनुष्य मुद्रा को नकद रूप में निम्नविवित कारणों से रखना चाहता है—

(i) व्यापारिक कार्यों के उद्देश्य (Transaction Motive) : व्यक्ति को नित्य प्रति के कार्यों के लिए-आवश्यक वस्तुएं खरीदन तथा अन्य कारणों से भुगतान करने के लिए नकद मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार व्यापारियों व उद्योगपतियों को प्रतिदिन के सीधों के लिए नकद मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है। इस उद्देश्य के लिए, मुद्रा की मात्रा व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर है।

(ii) पूर्वावधानी या दूरदर्शिता के उद्देश्य से (The Precautionary Motive) : भविष्य की अप्रत्याशी आवश्यकताओं, दायित्वों तथा आकस्मिकताओं के लिए भी नकद मुद्रा अपने पास रखना आवश्यकता होता है।

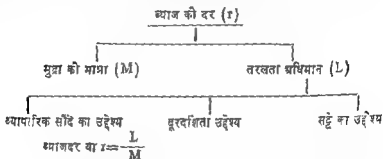
<sup>5</sup> "The rate of interest is the premium which is to be offered to induce people to hold their wealth in some form other than the hoarded money"

(iii) सट्टे के उद्देश्य से (The Speculative Motive) : ऊंची व्याज दर की आशा में भी लोग मुद्रा को अपने पास रखते हैं, जिसे भविष्य में उसका विनियोजन लाभप्रद विनियोगों में किया जा सके। भविष्य में बाजार में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए मुद्रा अपने पास नकद रखी जाती है।<sup>6</sup>

उपरोक्त में से प्रथम व द्वितीय पर व्याज दर का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु तृतीय पर व्याज का पूरा प्रभाव पड़ता है।

### 3 व्याज दर का निर्धारण (Determination of the rate of interest)\*

केस के अनुसार व्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मात्रा (Quantity of money) तथा तरलता अधिमान (Liquidity preference) द्वारा किया जाता है। केस के तरलता अधिमान सिद्धांत को निम्न सारणी प्रकार किया जा सकता है:



व्याज-दर का निर्धारण तरलता अधिमान तथा मुद्रा की पूर्ति (मात्रा) द्वारा होता है। "संतुलन की स्थिति में व्याज-दर मुद्रा की मात्रा तथा व्यक्तियों के तरलता अधिमान के साम्य के बराबर होगी।"

*"At the equilibrium position, the rate of interest will be just at the level necessary to equate the quantity of money in existence with the aggregate amount wanted by people to hold."* —J M Keynes

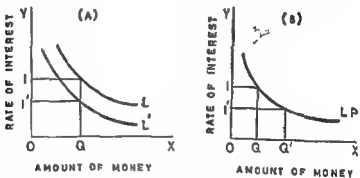
तरलता अधिमान एक फलन-प्रवृत्ति (functional tendency) है जो एक दी हुई व्याज-दर पर, जनता द्वारा की जाने वाली मुद्रा की समग्र-मात्रा को निर्धारित करती है। यदि व्याज दर  $r$ , मुद्रा की मात्रा  $M$  तथा तरलता अधिमान  $L$  है तो  $M=L(r)$  होगा। यदि तरलता अधिमान पूर्ववत् रहे तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर व्याज दर घटेगी तथा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर व्याज-दर बढ़ेगी।

\* "Speculative motive is a motive of earning profit by knowing better the market what the future will bring forth" —J M Keynes

ब्याज-दर तथा तरलता अधिमान में विपरीत सम्बन्ध होता है। ऊँची ब्याज-दर पर तरलता अधिमान घटता है, तथा कम ब्याज-दर पर तरलता अधिमान बढ़ता है। 'तरलता अधिमान' का यह परिवर्तन 'सट्टे के उद्देश्य' से प्रभावित होता है। मुद्रा की माग उपरोक्त तीनों उद्देश्यों पर निर्भर है।

**मुद्रा की पूर्ति** मुद्रा की कुल पूर्ति-मुद्रा तथा बैंक-मुद्रा द्वारा निश्चित होती है। मुद्रा की कुल पूर्ति ब्याज-दर से प्रभावित नहीं होती है।

**रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण** विभिन्न ब्याज-दरों पर, यदि तरलता-अधिमान-वक्र बनाया जाए तो वह सामान्य माग वक्र की भाँति होगा, जो विभिन्न ब्याज दरों पर मुद्रा की माग को प्रदर्शित करेगा। चित्र सं० 138 (A) में OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा तथा OY अक्ष पर ब्याज-दर प्रदर्शित की गई है। L' वक्र विभिन्न ब्याज दरों पर मुद्रा की मागी जाने वाली मात्राओं को प्रकट करता है। OI' ब्याज-



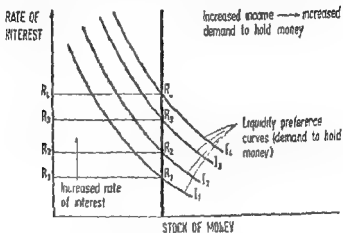
चित्र संख्या 138

दर पर मुद्रा की पूर्ति OQ है। (यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि ब्याज-दर में परिवर्तनों पर ध्यान रखते बिना केन्द्रीय-बैंक तथा सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा (पूर्ति) स्थिर रखती है) L' वक्र यह प्रकट करता है कि यदि ब्याज की दर ऊँची है तो लोग अपने पास कम मुद्रा रखेंगे। यदि तरलता अधिमान में परिवर्तन होता है, अर्थात् लोग प्रत्येक ब्याज-दर पर अधिक मुद्रा रखना चाहते हैं, तो 'तरलता अधिमान वक्र' दाहिनी तरफ ऊपर विभक्त होगा। L वक्र नया तरलता अधिमान वक्र होगा। यदि मुद्रा की पूर्ति पूर्ववत् (OQ) है तो तरलता अधिमान में वृद्धि होने पर ब्याज-दर बढ़ेगी। नई ब्याज-दर OI' हो जाएगी।

उपर्युक्त स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है। वस्तुतः मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस स्थिति को चित्र सं० 138 (B) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हम मान लेते हैं कि समाज का तरलता अधिमान दिया हुआ है जो LP-वक्र

द्वारा प्रदर्शित किया गया है।  $OQ$  मुद्रा की मांग है। व्याज दर  $OI$  है। यदि केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का परिमाण बढ़ाकर  $OQ'$  कर दिया जाता है तो व्याज दर घटकर  $OI'$  हो जाएगी।

दूसरे चित्र द्वारा भी तरलता अधिमान सिद्धान्त को समझा जा सकता है। यह सिद्धान्त यह बतलाता है कि व्याज दर वह दर है जो मुद्रा को रोक रखने की मांग (Demand to hold money) तथा मुद्रा के स्टॉक (Stock of money) को समुलित (Equals) करती है। चित्र सख्या 139 में  $R_1$  व्याज की उस दर



चित्र सख्या 139

को प्रकट करती है जो मुद्रा को रोक रखने की मांग  $I_1$  पर होती है। मुद्रा की रोक रखने की मांग, आय पर निर्भर करती है। अधिक आय पर, लोग अधिक मुद्रा को रोक रखना चाहते हैं। इस तथ्य को उपर्युक्त चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र में  $I_1$  ऊँची आय पर मांग वक्र है ( $I_3$  की तुलना में) इसी प्रकार  $I_3$ ,  $I_1$  की अपेक्षा ऊँची आय के लिए मांग वक्र है। चित्र से स्पष्ट है कि आय बढ़ने पर व्याज-दर ऊँची उठती है।  $I_3$  आय पर व्याज-दर  $I_1$  तथा  $I_2$  आय पर व्याज-दर  $R_1$  है।

सिद्धान्त की विशेषताएँ (1) केन्स का व्याज-सिद्धान्त एक प्रारम्भिक सिद्धान्त (Dynamic Theory) है। यह स्मरणीय है कि केवल व्याज-दर ही लोगों की सट्टे की इच्छा की पूर्ति के लिए पास रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा का निर्दिष्ट नहीं करती। केन्स न इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में व्याज दर में होने वाले परिवर्तनों की अनिश्चितता का ही महत्व है। भविष्य में व्याज-दर में वृद्धि की आशा लोगों को अपने पास अधिक मुद्रा रखने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार भविष्य की अनिश्चितता केन्स के सिद्धान्त का मूल तत्व है, जो प्रारम्भिक दशा का प्रतीक है।

(2) केन्स के अनुसार व्याज दर पूर्णतः मौद्रिक स्थिति (Monetary Phenomenon) से सम्बन्धित है, अतः व्याज-दर पर बैंक व्यवस्था द्वारा नियन्त्रण रखा जा सकता है।

### सिद्धान्त की आलोचना

1 'मुद्रा' का अर्थ अस्पष्ट केन्स ने 'मुद्रा' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। उनके अनुसार साखा मुद्रा भी मुद्रा में सम्मिलित की जानी चाहिए, परन्तु राबर्टसन के साथ हुए विवाद में उन्होंने कहा कि 'साख' को मुद्रा के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

2 सीमांत उत्पादकता की उपेक्षा इस सिद्धान्त में पूँजी की सीमांत उत्पादकता को अनावश्यक माना गया है। केन्स के अनुसार नए विनियोगों के सम्बन्ध में निर्णय साहसी की मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा व्याज की दर द्वारा किया जाता है, परन्तु केन्स इस तथ्य को भूल गए कि पूँजी की उत्पादकता भी साहसी के निर्णय को बहुत प्रभावित करती है।

3 एकांगी सिद्धान्त इस सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु 'तरलता अधिमान' है, परन्तु व्याज के निर्धारण में पूँजी की मांग, पूर्ति, समय अधिमान तथा सीमांत उत्पादकता का भी हाथ रहता है। केन्स ने इन तत्वों की उपेक्षा की है।

4 अमित क्षेत्र इस सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित है। ऐसा समाज जिसमें नकद पैसा नहीं होता है, व्याज-दर का निर्धारण किस प्रकार होगा, इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मौन है।

5 इस सिद्धान्त द्वारा 'दीर्घ कालीन व्याज दर' पर प्रकाश नहीं पड़ता है।

इस आलोचनाओं के होते हुए भी केन्स का सिद्धान्त अधिक तर्कपूर्ण एवं युक्ति मग्न है।

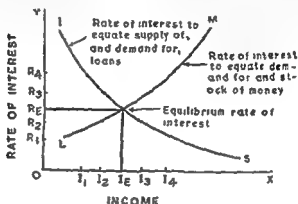
### व्याज दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त

#### 5 (The Modern Theory of the Determination of Rate of Interest)

व्याज के 'उधार देय कोष सिद्धान्त' तथा 'तरलता अधिमान सिद्धान्त'—दोनों द्वारा व्याज-दर का निर्धारण का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता है। इन दोनों सिद्धान्तों में आय के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। व्याज का कोई भी ऐसा सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें आय की उपेक्षा की गई हो। व्याज का आधुनिक सिद्धान्त आय पक्ष पर भी ध्यान देता है तथा यह सिद्धान्त एक प्रकार से उधार देय कोष सिद्धान्त तथा तरलता अधिमान सिद्धान्त का समन्वय है। अब हम आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे।

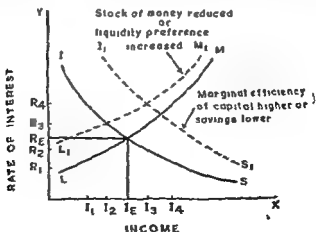
चित्र सं० 140 में  $Is$  वक्र उस व्याज दर का प्रकट करता है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उधार देय कोष की मांग तथा पूर्ति को समतुलित (equates) करता है। (उधार देय कोष सिद्धान्त सम्बन्धी चित्र सं० 137 देखिए)  $LM$  वक्र,

आय के विभिन्न स्तरों पर, उस व्याज दर को प्रकट करता है जो मुद्रा के स्टॉक (Stock of Money) तथा मुद्रा को रखे रखन की मांग (Demand to hold money) को संतुलित करता है। तरलता अधिमान सिद्धान्त सम्बन्धी चित्र सख्या 139 देखिए। जहाँ पर दानो वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर व्याज की



चित्र सख्या 140

वह दर है, जिस पर (i) ऋणों की मांग तथा पूर्ति और (ii) निश्चित की जा सकने वाली आय (Determinable income) पर, मुद्रा को रोके रखन सम्बन्धी मांग (Demand to hold money) और मुद्रा के स्टॉक के बीच संतुलन स्थापित होता है। चित्र सख्या 140 में यह व्याज दर  $R_E$  तथा आय  $I_E$  होगी।



चित्र सख्या 141

चित्र सख्या 141 में IS और LM प्रारम्भिक अवस्था के सूचक हैं।



ब्याज दर  $R_E$  और आय  $I_E$  होगी। निम्नलिखित सम्भावनाओं पर विचार कीजिए—(क) पूँजी की सीमान्त कार्यक्षमता (Marginal Efficiency of Capital) में वृद्धि या वचन की मात्रा में कमी के कारण IS वक्र खिसकर  $I_1S_1$  हो जाएगा तथा ब्याज दर बढ़कर  $R_3$  और आय बढ़कर  $I_4$  हो जाएगी, (ख) IS अपरिवर्तित रहता है परन्तु मुद्रा का स्टाक घट जाता है या तरलता अधिमान (Liquidity Preference) बढ़ जाता है (मुद्रा को रोके रखने की मांग बढ़ जाती है) LM वक्र ऊपर हटकर  $L_1M_1$  हो जाता है। ब्याज दर बढ़कर  $R_3$  हो जाती है, परन्तु आय घटकर  $I_3$  रह जाती है। (ग) दोनों वक्र बदल जाते हैं— LM हटकर  $L_1M_1$  तथा IS हटकर  $I_1S_1$  हो जाती है तो ब्याज दर बढ़कर  $R_4$  और आय  $I_4$  हो जाती है।

इस प्रकार आधुनिक सिद्धान्त आय पर भी विचार करता है तथा इसमें 'उधार देय कोष' तथा 'तरलता अधिमान' सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं।

### प्रश्न व सकेत

- 1 ब्याज का क्या अर्थ है ? ब्याज किस प्रकार निर्धारित होता है ?

(Ravi, B A (F) 1965)

[सकेत 'ब्याज' का आर्थिक आशय स्पष्ट करिए। ब्याज निर्धारण के प्रमुख सिद्धान्तों के नाम लिखिए। अतः में केंस के सिद्धान्त को समझाइये व उसकी आलोचना कीजिए। साथ ही आधुनिक विचार भी संक्षेप में लिखिए।]

- 2 ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धान्त को समझाइये।

(Raj B A 1964, Luck, B A I, 1961)

[सकेत केंस द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को समझाइये। उत्तर में सर्वप्रथम तरलता पसंदगी का आशय व सिद्धान्त का सार लिखिए एवं अतः में उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।]

- 3 ब्याज के उधार देय कोष सिद्धान्त की पूर्ण व्याख्या कीजिए।

## लाभ की प्रकृति ( The Nature of Profit )

*"Profits are the report-card of the past, the incentive gold star for the future, and also the grubstake for your new venture"*

—Samuelson

### 1. लाभ का अर्थ (Meaning of Profit)

उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी या साहसी के कार्य के लिए प्राप्त पुरस्कार को लाभ कहते हैं। परन्तु उद्यमी द्वारा उत्पादन-व्यवस्था के संयोजन (Co-ordination) तथा जोखिम-उठाने (Risk taking) के उत्तरदायित्वों की पूर्ति किए जाने के कारण यह समस्या स्वभावतः सामने आती है कि उद्यमी के उपर्युक्त दोनों कार्यों में से किस कार्य के लिए दिए गए पारितोषिक को लाभ कहा जाय ? इन दोनों बातों में भेद करने का प्रयत्न किया गया है। प्रो० जे० के० मेहता ने इस सम्बन्ध में कहा है कि वास्तविक रूप में शुद्ध लाभ (Net Profit) उद्यमी या साहसी को केवल जोखिम उठाने या अनिश्चितता के कारण ही प्राप्त होता है। उनके अनुसार "शतार्थक सभार की उत्पादन-प्रक्रियाओं में अनिश्चितता का यह तत्त्व त्याग के एक चतुर्थ वर्ग को जन्म देता है। इस वर्ग में जोखिम उठाने तथा अनिश्चितता सहन करने के दो तत्व हैं। इसको लाभ द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।" विलियम फैलनर (William Fellner) ने भी यह कहा है कि साहस का कार्य ही ऐसा कार्य है जिसके लिए लाभ अर्जित किया जाता है। "The entrepreneurial function is the function for which profit is earned" अतः यह स्पष्ट है कि अनिश्चितता के कारण जोखिम का जो मार साहसी (Entrepreneur) द्वारा उठाया जाता है उसके बदले में प्राप्त प्रतिफल 'लाभ' कहलाता है।

### 2. लाभ की धारणा (The Concept of Profit) :

लाभ का उपर्युक्त अर्थ केवल लाभ प्राप्त करने वाले अधिकारी की ओर मकेल करता है। इससे यह बात नहीं होता कि एक उपक्रम की कुल प्राप्तियों (Total

Receipts) में से किम अत्र को लाभ कहा जा सकता है ? इस सवध में टॉजिंग (Tau'sig) का यह वाक्य उल्लेखनीय है : 'लाभ एक मिश्रित तथा विवादास्पद (तय करने वाली) आय है ।' टॉजिंग के इस वाक्य से यह ज्ञान होता है कि 'शुद्ध आर्थिक लाभ' की धारणा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है । टूर्गो (Turgot) का पूँजीपति साहमी (Capitalistic Entrepreneur) स्वामी-प्रबन्धक-साहमी' तीनों ही स्वयं होता था, अतः वह व्याज, मजदूरी तथा जोखिम उठाने के प्रनिफल की तीनों राशियों का स्वयं अधिकारी होता था । परन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और विशेषकर वर्तमान शताब्दी (20वीं) के पूर्वार्द्ध में जे० बी० से की यह धारणा अत्रिक विकसित हुयी है कि उपक्रम का स्वामित्व तथा साहमोद्यम (entrepreneurship) का अस्तित्व उसके प्रबन्धन से सर्वथा अलग है । अतः साहमी-द्यम को प्राप्त आय लाभ की धारणा भी एक भिन्न धारणा मानी जाती है । यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री, जिनमें नाइट (Knight) तथा शूम्पीटर (Schumpeter) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, आर्थिक लाभ उस आय को मानते हैं जो साहमोद्यम को जोखिम उठाने, अनिश्चिन्ता सहन करने तथा नव प्रवर्तन (Innovation) के लिए प्राप्त होती है, परन्तु मार्शल, राबर्टसन तथा कुछ अग्रज अर्थशास्त्री इस विचार को मकुचित मानते हैं । उनके विचार में साहमोद्यमी कुल प्राप्तियों में से समस्त व्ययों को घटाने के पश्चात् शेष का अधिकारी होता है । यह अवशेष लागत अथवा व्यय के ऊपर प्राप्त प्रनिफल का अधिक्य ही वास्तव में उसका लाभ होता है (Profit is excess of returns over outlay or expenditure) । राबर्टसन ने लाभ के इस विस्तृत अर्थ के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है : "इस शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त करना अत्यन्त सुविधाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि उससे ही सम्मिश्रित साधन 'साहस' की सम्मिश्रित आय का अर्थ स्पष्ट होता है ।"<sup>1</sup> अनुरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है लाभ की धारणा में 'अवशेष' नत्व विद्यमान है । विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक लाभ के रूप में इस अवशेष को अलग-अलग परिभाषित किया है । लेफ्टविच (Leftwich) के अनुसार "आर्थिक लाभ फर्म द्वारा व्यय की गयी समस्त उत्पादन लागतों के उपर कुल प्राप्तियों का शुद्ध अवशेष या प्राधिक्य है ।"<sup>2</sup> आर्थिक लाभ की धारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने लेखांकक की लाभ-सम्बन्धी धारणा (Accountant's concept of profit) तथा आर्थिक लाभ की धारणा के अन्तर को इस प्रकार व्यक्त किया है :

<sup>1</sup>. "It seems most convenient to use the word in a comprehensive sense, to denote the composite income of the composite factor 'Enterprise.'  
—Robertson

<sup>2</sup>. "Economic profit is a pure surplus or excess of total receipts over all costs of production incurred by the firm." —Leftwich, R. H.

लेखांकक द्वारा निर्धारित किसी कम्पनी का शुद्ध लाभ या आय } = { उत्पादित वस्तु या वस्तुओं की बिक्री पर कुल प्राप्तियां  
 — (उत्पादन-लागतें तथा वे व्यय जो बाढ़ पर व्याज तथा सम्पत्तियों के ह्रास आदि के रूप में होते हैं)  
 आर्थिक लाभ } = { लेखांकक द्वारा निर्धारित शुद्ध लाभ या आय  
 — (औसत लानाश जो कम्पनी के अराधारियों को दिया गया है)

उपरोक्त सूत्रों में यह स्पष्ट है कि लेखांकक द्वारा निर्धारित लाभ वह सकल लाभ (Gross Profit) है जो श्रम तथा भूमि (कच्चे माल) के मूल्यों की घटाव के बाद बच (अवशेष) रहता है। यदि लेखांकक शुद्ध लाभ (Net Profit) ज्ञात करना चाहता है तो वह उस अवशेष में से पूँजी पर दिए गए व्याज को भी घटा देगा। वस्तुतः लेखांकक का यह शुद्ध लाभ ही आर्थिक लाभ है, क्योंकि कुल प्राप्तियों में से भूमि श्रम तथा पूँजी के मूल्यों का प्रगतान करने के पश्चात् यही अवशेष रहता है। फलतः क अनुसार शुद्ध लाभ ज्ञान करने के लिए हम एक उपक्रम के सकल लाभ में से अनुवर्धित लागत (Contractual Costs) को घटा देना चाहिए, उसके बाद उस शेष में से ह्रास तथा उपक्रमों की पूँजी पर अर्पित शुद्ध व्याज (Imputed pure interest) तथा उपक्रमी द्वारा मजालन तथा प्रदत्त सम्बन्धी श्रम सेवा के लिए अवर्धित मजदूरी (imputed wages) को भी घटा देना चाहिए। इस प्रकार बचा हुआ अवशेष ही शुद्ध आर्थिक लाभ रहा जायेगा।

### 3 कुल एवं शुद्ध लाभ (Gross and Net Profits)

बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वस्तु की बिक्री मूल्य में से मजदूरी तथा कच्चे माल के मूल्य को घटाकर जो राशि शेष रहती है वही लाभ है (Profit is the margin by which selling price exceeds the buying price), किन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा कि इस राशि में अन्य तत्व भी शामिल रहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में लाभ अनिश्चितता के कारण उत्तमी को मिलने वाला पुरस्कार है। इनमें बहुत सी ऐसी परिणाम सम्मिलित हैं जो उत्तमी अन्य साधनों से अलग करता है। अतः स्पष्ट है कि कुल लाभ में से कुछ अन्य तत्वों को अलग करना पड़ता है, जैसे पूँजी का क्षय (wear and tear of capital) होने के कारण उसी मात्रा में पूँजी बनाय रखने के लिए कुल प्राप्ति में से दत्तने मिले कुछ व्यय करना पड़ती है। कुल लाभ में से दूसरा महत्वपूर्ण अंश पूँजी पर दिये गये व्याज की मात्रा है जिसे कुल प्राप्ति में से अलग करना पड़ेगा। यह सम्भव है कि उत्तमी ने स्वयं अपनी पूँजी लगायी हो, फिर भी उसकी कुल प्राप्ति का एक अंश वस्तुतः उसके द्वारा लगायी गयी पूँजी पर व्याज स्वरूप होगी, चाहे इसके लिये स्पष्टतः कोई राशि भरायी न जाती हो।

तोसरा सम्भव तत्व प्रबन्ध में किया गया श्रम है। सार्वजनिक सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों में साधारणतया प्रबन्धक को वेतन मिलता है जिसे मजदूरी के समान ही लागत व्यय का एक अंश माना जाता है। यदि उद्यमी स्वयं प्रबन्धक का कार्य भी करता है तो सम्भव है कि उसे इसके लिये अलग से कोई राशि न मिले, किन्तु कुल प्राप्ति में ये प्रबन्धक के लिए उसका अथवा पारित्यमिक निकाल देना उचित ही होगा। इसी प्रकार स्वयं उद्यमी द्वारा लगायी गयी भूमि के पुरस्कार (लागत) को भी कुल लाभ में से अलग करना पड़ता है।

अतः उम राशि को, जो उत्पादन के मूल्य में से भूमि, श्रम, पूँजी तथा स्वयं उद्यमी द्वारा लगाये गये साधनों का पुरस्कार देने के पश्चात् शेष बच रहता है, शुद्ध लाभ कहते हैं। इसमें से पूँजी के श्रय के लिये भी एक निश्चित माना अलग करनी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि इसके पश्चात् उद्यमी को जो शेष राशि प्राप्त होती है उसे ही लाभ कहेंगे।

#### 4 लाभ के प्रकार (Kinds of Profits)

(i) प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive Profits) : प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में लाभ की प्रवृत्ति समान होने की रहती है। यदि किसी एक उद्योग में लाभ की दर कम तथा दूसरे उद्योग में अधिक है, तो कम लाभ वाले उद्योग में पूँजी और उद्यम निकल कर अधिक लाभ वाले उद्योगों में चले जायेंगे। परिणामस्वरूप जिन उद्योगों में लाभ कम है, वहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी। इस प्रक्रिया के कारण लाभ की दर भी प्रभावित होगी। कम लाभ वाले उद्योग में लाभ बढ़ेगा तथा अधिक लाभ वाले उद्योगों में लाभ घटेगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि विभिन्न उद्योगों में लाभ समान नहीं हो जाता। लाभ के समान होने के लिये हमें इस मान्यता को स्वीकार करना पड़ेगा कि विभिन्न उद्योगों में जोखिम की मात्रा समान है। पुनः लाभ की प्रवृत्ति न्यूनतम होने की रहती है। यदि सभी उद्योगों में अधिक लाभ होता है तो नये उद्यमी तथा पूँजी का प्रवेश होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, मूल्य में ह्रास होगा और लाभ अपने न्यूनतम स्तर पर चला जायेगा। अतः प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत लाभ की प्रवृत्ति सर्वत्र एक समान होने की रहती है।

(ii) एकाधिकार लाभ (Monopoly Profit) . एकाधिकार लाभ की प्राप्ति इस तथ्य में निहित है कि अपनी वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकारी का नियंत्रण होता है तथा वह वस्तु के मूल्य को उम बिन्दु तक भी नहीं गिरने देता जहाँ मूल्य केवल उसके लागत मूल्य के बराबर हो।<sup>3</sup> चूँकि एकाधिकार में पूर्ति का नियंत्रण

<sup>3</sup> "Monopoly profits arise through the ability to control output so that price will not fall to a point where it is only equal to cost."

सम्भव है, अतः एकाधिकारी सदैव वस्तु की कीमत मूल्य से ऊपर रखता है तथा उसे अपनी एकाधिकार-शक्ति के कारण अनाम्य लाभ भी प्राप्त होता है।

एकाधिकार का यह असाधारण (Supra normal) लाभ आर्थिक लगान के समान है। यह स्थानान्तरण-व्यय व ऊपर बचन है। आर्थिक लगान किसी भी ऐसे साधन को मिल सकता है जिसमें कुछ ऐसी विशेषता तथा गुण हैं कि उनकी प्रति बड़ नहीं पानी। एकाधिकारी म वस्तुतः इन प्रकार का गुण मोट्ट है कि वह वस्तु की प्रति को नियन्त्रित कर अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। यदि एकाधिकारी की यह स्थिति स्थायी है तो उद्योगी का लाभ, जो कि सामान्य स्तर से अधिक है कुछ आर्थिक लगान के समान है, किन्तु एकाधिकार शक्ति यदि अस्थायी है तो अनिश्चित राशि को अर्द्ध-लगान (Quasi-rent) कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अतः व्यवहार में शुद्ध लाभ का एकाधिकारिक लाभ के समान ही समझा जाता है।

(iii) अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profits) : अप्रत्याशित लाभ शब्द का प्रयोग केन्स (Keynes) ने अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money, Vol. I' में किया था, किन्तु यहाँ हमारा विवेचन उनके विवेचन से बिल्कुल भिन्न होगा। अप्रत्याशित लाभ एक ऐसा लाभ है जो पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों को समय-समय पर प्राप्त होता है। सामान्य रूप से हम इस अप्रत्याशित लाभ इस कारण कहते हैं कि इस लाभ की प्राप्ति किसी उद्योग के विभिन्न फर्मों को बिना किसी प्रत्याशा (expectation) के जानी रहती है। साथ ही इस लाभ की प्राप्ति के पीछे जो शक्तिशाली कार्य करती है, वे फर्म के निराशा में बिल्कुल नहीं रहती।

अप्रत्याशित लाभ का एक सामान्य स्रोत मूल्य में वृद्धि है। ऐसी मूल्य वृद्धि मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप होती है। जब मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-वृद्धि होती है तो उद्योग या व्यापारी को अपने अपने पक्ष में मूल्य वृद्धि के स्टाक पर विरोध साम प्रत्य होता है क्योंकि इस स्टाक में रखी वस्तु का उत्पादन मुद्रा-स्फीति के पूर्व कम मूल्य पर ही किया गया था।

यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ एक या दो फर्म अपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की आशा कर सकती हैं, वहाँ ऐसे अप्रत्याशित लाभ की आशा सामान्यतः सम्पूर्ण उद्योग नहीं कर सकता। यदि मूल्य की वृद्धि की पूर्ण सीमा सभी फर्मों का ज्ञान हो जाय तो उनका प्रयत्न भी पहले से ही स्टाक जमा करने का होगा जिसकी वृद्धि बड़े मूल्यों पर हो सकेगी, किन्तु उनका इस प्रयत्न के रूप में धर्म तथा कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होगी और अन्ततः वे फर्म ऐसी स्थिति को पहुँच जायेंगी जहाँ उन्हें कोई लाभ प्राप्त न होगा।

अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि क्या इस प्रकार के अप्रत्याशित लाभ को लाभ माना जाये अथवा नहीं? यदि हम लाभ को दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय के ऊपर

प्रोफिट आय मानें, तो यदि मगी नहीं तो अविकलाश में इस प्रकार के लाभ लुप्त हो जायेंगे। दीर्घकाल के अन्वयन सूय में हाम के कारण अप्रत्याशित हानि को लाभ की मात्रा में से घटाना पड़ेगा। चूकि लाभ और हानि दोनों ही अप्रत्याशित हैं, अतः यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे में अधिक होगा।

(iv) सामान्य लाभ (Normal Profits) सामान्य लाभ का विचार मार्शल की देन है। प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm) के पुरस्कार के लाभ को सामान्य लाभ कहते हैं। यह लाभ दीर्घकाल में उस उद्योग में, जहाँ उत्पादन-वृद्धि नियम लागू हो रहा है, प्रति मूल्य में शामिल रहता है। वह फर्म, जो सामान्य लाभ अर्जन करती है, अनुकूलनम फर्म है। इस प्रकार के फर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन—उन्नति या अवनति—नहीं आती। चूकि सामान्य लाभ अनुकूलनम फर्म की उत्पादन लागत में शामिल रहता है, इसलिए इसे हम अनुकूलनम फर्म की आय भी कह सकते हैं।

श्रीमती जोन रॉबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार सामान्य लाभ को लाभ का ऐसा स्तर नहीं माना गया है, जहाँ नयी फर्म न तो प्रवेश करना चाहती है और न पुरानी फर्म बाहर जाती है। असामान्य रूप से अधिक लाभ का तात्पर्य यह है कि नई फर्म प्रवेश करें और नन्वु का उत्पादन बढ़ावें। ठीक इसके विपरीत बहुत ही कम लाभ के कारण फर्म बाहर खली जायेंगी। अतः सामान्य लाभ का वही विशेष उद्योग के सम्बन्ध में ही करना उचित होगा। किन्ती भी उद्योग में प्रवेश करने की कठिनाई उनके लाभ के स्तर पर निर्भर करती है।

(v) शुद्ध लाभ (Pure Profit) : शुद्ध लाभ का विचार क्लार्क (Clark) की देन है। शुद्ध लाभ आय के ऊपर विचार (Surplus over costs) है,<sup>4</sup> जबकि सामान्य लाभ को फर्म के लागत व्यय का एक अंश ही कहा जा सकता है। शुद्ध लाभ अवशिष्ट आय है। क्लार्क के अनुसार यह गणितीय आय है जो स्थिर अर्थ-व्यवस्था में नहीं मिलती, किन्तु लागत-व्यय का जो अर्थ क्लार्क लेते हैं, वह वस्तुतः प्रबन्ध का पारिश्रमिक (Wage of management) है। अतः स्पष्ट है कि जिसे मार्शल असामान्य लाभ कहते हैं, वही क्लार्क के विचार में शुद्ध लाभ है। मार्शल का सामान्य लाभ वस्तुतः क्लार्क के प्रबन्ध के पारिश्रमिक से मिलता जुगता है।

**लाभ सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्त (Theories of Profits) :**

लाभ के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त हैं जिनमें से प्रमुख सिद्धान्त, जोलिन से सम्बन्धित सिद्धान्त, अनिश्चितता सहन करने का सिद्धान्त, योग्यता का

<sup>4</sup> "Pure profit is a return over and above opportunity cost payments"

संगत सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धी सिद्धान्त, नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रमुख हैं। अब हम सत्रों में लाभ के इन विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे।

### 1. लाभ का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory of Profit)

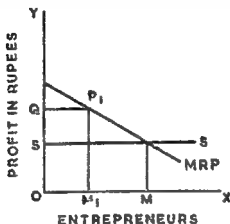
इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि साहसोद्यम योग्यता (Entrepreneurial Ability) भी उत्पादन का एक साधन है। वितरण के सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के अनुसार इस योग्यता का मूल्य, जिसे लाभ कहते हैं, उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार अन्य साधनों का। साहसी व्यवसायी योग्यता अथवा क्षमता की सहायता से जिस अतिरिक्त उत्पत्ति की वृद्धि करता है वह उसकी सीमान्त उत्पादकता कहलाती है। यह प्रतिरिक्त उत्पत्ति उसी समय प्राप्त हो सकती है जब कि उद्योग या साहसी की सहायता की कमी अथवा उसमें एक अतिरिक्त साहसी की वृद्धि कर दी जाय। इस कमी अथवा वृद्धि से उत्पादन-मात्रा में वृद्धि, जितनी कमी या वृद्धि होगी वही साहस की सीमान्त उत्पादकता की माप होगी।

किसी साधन का सीमांत आय उत्पादकता वक्र (MRP), उसका माप वक्र भी होता है। अतः उपक्रमी का MRP वक्र उसका माप वक्र भी होता है। उपक्रमियों की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वे उद्योग में कितना काम सकते हैं अर्थात् उनकी पूर्ति, उनकी आय उत्पादकता पर निर्भर होगी। प्रश्न है उपक्रमी का MRP वक्र किस प्रकार का होगा? भूमि धन, पूँजी आदि साधनों की उत्पादकता या सीमांत आय उत्पादकता, उनकी एक मात्रा बढ़ाकर या घटाकर मरतता से ज्ञात की जा सकती है। परन्तु किसी एक फर्म के सदर्भ में, उपक्रमी की सीमांत आय उत्पादकता ज्ञान नहीं की जा सकती है। क्योंकि फर्म में एक ही उपक्रमी होता है, अतः उसकी मर्यादा घटाने या बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, उद्योग के सदर्भ में उपक्रमियों की उत्पादकता या सीमांत आय उत्पादकता उनकी मर्यादा एक से घटाकर या बढ़ाकर ज्ञात की जा सकती है। इसका स्पष्टीकरण एक रेखा चित्र द्वारा किया जा सकता है।

मान लीजिए एक उद्योग में सभी उपक्रमी एक रूप (Homogeneous) हैं तथा उपक्रम (entrepreneurship) की एकसूत्री भौतिक मात्राओं (homogeneous physical units) द्वारा नापा जा सकता है। जैसा कि चित्र सख्या 138 में OX अक्ष के माध्यमे व्यक्त किया गया है। चित्र में MRP वक्र एक उद्योग में उपक्रमी की सीमांत आय उत्पादकता को प्रकट करता है। यह सामान्य मूल्य वक्र की भाँति है, जो यह प्रकट करता है कि उपक्रमियों की संख्या में वृद्धि करने से उनकी आय (लाभ) घटेगी। SS उनका पूर्ति वक्र है। हम यह मानकर चलते हैं कि सभी उपक्रमी समान



रूप से कुशल हैं, अतः सभी का लाभ बराबर होगा। इन लाभ की मात्रा OS है, जो उपक्रमियों की अवसर लागत (opportunity cost) को प्रकट करती है। यदि लाभ OS से कम है तो उपक्रमी उद्योग छोड़ देगा। अतः OS उपक्रमियों का पूर्ति मूल्य है। चूँकि सभी उपक्रमी समान रूप से कुशल हैं, अतः उनका पूर्ति मूल्य भी समान है। यही कारण है कि उपक्रम का पूर्ति वक्र एक सीधी क्षैतिज रेखा के रूप में



चित्र सख्या 138

है। MRP वक्र तथा SS वक्र एक दूसरे को काटते हैं। OS उद्योग के औसत लाभ को प्रकट करता है। लाभ की यह मात्रा पूर्णस्पर्धा की स्थिति में, दीर्घकाल में पाई जाएगी। OS लाभ पर उपक्रमियों की माग व पूर्ति बराबर है। OS उपक्रमियों की अवसर लागत को प्रकट करता है अतः उद्योग में सभी उपक्रमी 'सामान्य लाभ' अर्जित कर रहे हैं। यह स्थिति दीर्घकाल से सम्बन्धित है।

अल्पकाल में यह संभव है कि कुछ उपक्रमी असामान्य लाभ (Abnormal Profit) अर्जित कर सकते हैं। अल्पकाल में उपक्रमियों की संख्या  $OM_1$  तथा लाभ OQ है। इस प्रकार SQ असामान्य लाभ है। असामान्य लाभ के कारण, दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश होगा तथा यह अधि-लाभ, स्पर्धा के कारण समाप्त हो जाएगा अतः दीर्घकाल में, पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में, सभी फर्म सामान्य लाभ ही अर्जित करनी। दीर्घकाल में सभी फर्मों का लाभ सामान्य होने के कारण निम्नलिखित है।

(1) स्पर्धा के कारण फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत औसत व सीमांत लागत के बराबर होगी (2) फर्मों द्वारा भूमि श्रम पूँजी आदि साधनों को उनकी औसत व सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा। अतः उपक्रमी इन दो कारणों से अधि लाभ नहीं अर्जित कर सकेगा।

अपूर्ण-स्पर्धा के अन्तर्गत उपर्युक्त अग्रामाभ्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। (अल्प-काल तथा दीर्घ काल में भी)।

**आलोचनाएँ :** लाभ का यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। इसके कारण यह है कि शुद्ध लाभ अवशिष्ट आय है अतः वह सीमान्त उत्पादन के बराबर नहीं हो सकता। सम्स्त उत्पादन कार्य में हमी के अस्तित्व पर ही आधारित होता है। अल्प किसी साधन की तरह उसे हटाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त साहसियों की पूर्ति प्रत्यक्ष अल्प होने के कारण उनकी उत्पादकता की सही माप भी सम्भव नहीं है। इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं :

(1) एक फर्म की स्थिति में एक ही साहसी होने पर उस फर्म में साहस की सीमान्त आगम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) की माप सम्भव नहीं है।

(2) एक उद्योग की स्थिति में यद्यपि एक अतिरिक्त साहसी की वृद्धि तो सम्भव है और सम्भवतः गणितीय विधि के द्वारा उससे प्राप्त सीमान्त उत्पादन में वृद्धि का अनुमान भी सम्भव हो सके, फिर भी इस वास्तविक तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सभी साहसी समान योग्यता वाले नहीं होते। साहसियों की योग्यता में विभिन्नता होने के कारण अल्प साधनों की तरह इसमें प्रतिस्थापन का निदान नहीं लागू होता। यही कारण है साहसी की सीमान्त उत्पादकता की माप नहीं की जा सकती।

(3) एकाधिकार की स्थिति में सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार लाभ की गणना करना कठिन होगा, क्योंकि एकाधिकारिक व्यवस्था में साहस की क्षमता में निम्नता स्थापित नहीं की जा सकती।

(4) सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त न तो अप्रत्याशित लाभ की व्याख्या करता है और न ही साहसी की आय के सम्बन्ध में कुशल साहसी के 'योग्यता के लगान' (Rent of ability) के तथ्य को सम्मिलित करता है।

## 2. वाकर का योग्यता-लगान-लाभ-सिद्धान्त

(Walker's Rent Theory of Profit)

लाभ का 'योग्यता लगान सिद्धान्त' अमेरिकी विचारक वाकर (Walker) तथा अन्य अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धान्त 'शुद्ध लाभ' की धारणा पर आधारित है। वाकर के विचार में उद्यमी अपनी सस्था का नायक (Captain) होता है। उसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने की शीघ्रत क्षमता से अधिक क्षमता होती है। सामान्यतः उद्यमी की संगठन कुशलता

तथा योग्यता में अन्तर पाया जाता है। यही कारण है कि योग्यतानुसार साहसियों के भी अनेक वर्ग होते हैं। जो उद्यमी अधिक कुशल होता है, वह प्रबन्ध के लिए पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुछ आधिक्य (Surplus) का अधिकारी होता है। इस आधिक्य का कारण उसका श्रेष्ठ गुण है। अतः बाकर के अनुसार शुद्ध लाम लगान (Rent) के समान ही यह विशेष पुरस्कार है जो केवल श्रेष्ठ उद्यमी को उसकी विशेष योग्यता के कारण प्राप्त होता है।<sup>5</sup> इसी कारण बाकर ने शुद्ध लाम को 'योग्यता का लगान' कहा है, क्योंकि यह उद्यमी की श्रेष्ठ कुशलता का पुरस्कार है, शोषण का फल नहीं है, जैसा कि मार्क्स ने कहा है। इस प्रकार उद्यमी की सकल आय (Gross Income) में से स्वयं की पूँजी, भूमि तथा अपने श्रम के लिए क्रमशः व्यय, लगान तथा मजदूरी घटाने के पश्चात् जो आधिक्य (Surplus) अवशेष रहता है, उसे ही साहसी की योग्यता की शुद्ध आय कहने हैं।

शुद्ध लाम की योग्यता के लगान के रूप में मानने का कारण यह भी है कि (बाकर ने यह माना है कि) भूमि की तरह उत्पादन-क्षेत्र (बाजार) में साहसी की योग्यता की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। कुछ साहसी ऐसी होते हैं जिनकी योग्यता इतनी अधिक नहीं होती कि उनकी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में स्वयं के सामानों के पारिश्रमिक सहित उत्पादन-व्यय से अधिक आय हो सके। ऐसे साहसी सीमांत साहसी कहलाते हैं। जो साहसी सीमांत साहसी की तुलना में अपनी वस्तु को बाजार मूल्य से कम लागत पर उत्पादित करने में अधिक कुशल होता है, उसको निःसन्देह अतिरिक्त लाम प्राप्त होगा। ऐसे श्रेष्ठ साहसी का शुद्ध लाम या योग्यता का लगान उनकी वस्तु के बाजार-मूल्य तथा उनकी लागत के बराबर होगा। साहसी जितना ही अधिक कुशल एवं योग्य होगा, उसके शुद्ध लाम की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यह लाम दीर्घकाल में मोबदार होगा। परन्तु इस प्रकार के लाम की एक विशेषता यह है कि दीर्घकाल में विभिन्न साहसियों को अपने अवसरों तथा अपनी योग्यता को विकसित करने के पूर्ण अवसर उपलब्ध होने हैं। फलस्वरूप श्रेष्ठ साहसी की योग्यता का महत्व क्रमशः संपादन हो जाता है। इसमें शुद्ध लाम या योग्यता का लगान कम होना जाता है और अन्त में शून्य हो जाता है परन्तु अतः प्रति-स्पर्धा में इसके विपरीत स्थिति होती है दीर्घ अवधि में श्रेष्ठ साहसी का शुद्ध लाम अधिक होता है।

अलोचनाएँ . व्यावहारिक रूप से बाकर के विचार की निम्न अलोचनाएँ की जाती हैं :

<sup>5</sup> "The extra gains which any producer or dealer obtains through superior talents for business or superior business arrangement are very much of a kind similar to rent."

(1) लाभ योग्यता लगान नहीं है क्योंकि योग्यता लगान सिद्धान्त छद्मरूप में मजदूरी में विनिम्नता का सिद्धान्त है।<sup>6</sup>

(2) इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि बिना लगान वाली भूमि की तरह लाभ मूल्य में प्रवेश नहीं करता, किन्तु इस प्रकार का तक चलता है। उद्यमी का कुल न कुछ पुरस्कार मूल्य में संशय प्रवेश करता है।

(3) माशल के अनुसार भूमि के लगान के विपरीत, लाभ को सच्चे अर्थ में प्राविश्य नहीं कहा जा सकता। भूमि के सभी टुकड़ों को धनात्मक (positive) या शून्य लगान मिलेगा ही। किसी भी टुकड़े का लगान नकारात्मक (negative) नहीं हो सकता, परन्तु उद्यमी को लाभ न प्राप्त होना या हानि होना सम्भव है।

(4) अत्यधिक लाभ सर्वद्वय ठोठ उद्यम के कारण ही नहीं मिलता। यह अप्रत्याशित लाभ एकाधिकार लाभ या शोपण के फलस्वरूप भी मिल सकता है। लाभ का यह सिद्धान्त अधिक से अधिक लाभ के अन्तर की व्याख्या करता है, लाभ की मूल प्रकृति पर कोई प्रकाश नहीं डालता।

### 3. क्लार्क का गत्यात्मक सिद्धान्त (The Dynamic Theory of Clark)

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो० जे० बी० क्लार्क (Prof J B Clark) के अनुसार लाभ गतिशील अर्थ व्यवस्था में प्राप्त होता है, अतः यह परिवर्तन का परिणाम (result of change) है। उनके विचार में स्थिर अर्थ व्यवस्था (static or stationary society) में लाभ न मिलने का कारण यह है कि उसमें जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन की तकनीकी विधि, उपभोक्ता-आचरण, उनकी रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की विधि भी अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तनों के अभाव के कारण स्थिर अर्थ-व्यवस्था में लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में यह कहा जाता है कि स्पर्धा समस्त लाभों को समाप्त कर देती है (competition is the great killer of all profits)। इसके विपरीत एक गतिशील या गत्यात्मक अर्थ व्यवस्था (Dynamic Society) में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, पूँजी में वृद्धि, उत्पादन के सगठन एवं विधि में परिवर्तन आदि। इसके साथ ही साधन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा उपभोक्ताओं की रुचि बदलती रहती है। इन सभी कारणों से अर्थ-व्यवस्था स्थिर नहीं रहती और उसमें सदा परिवर्तन की प्रवृत्ति रहती है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन क्रिया को व्यवस्थित करने पर ही उत्पादकों को लाभ मिल सकता है। जो उद्योगपति नये परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करता है या नये

<sup>6</sup> "The rent of ability theory of profit is really a theory of differential wage in disguise."

उत्पादन की विविधियों का उपयोग करता है, उसे उस प्रयोग द्वारा लाभ मिलता है, किन्तु जैसे सभी उत्पादक उस नये परिवर्तन के अनुरूप कार्य करने लगते हैं, लाभ लुप्त हो जाता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादक को लाभ की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार लाभ परिवर्तन का परिणाम है और ऐसे परिवर्तन सदैव ही अर्थ-व्यवस्था में होते रहते हैं तथा इन्हीं नये परिवर्तनों के समायोजन के क्रम में लाभ उत्पन्न होता है। लाभ उद्योग को नये सन्तुलन की स्थिति में लाने का पुरस्कार है, भन्ने ही यह पुरस्कार अर्थव्यवस्था में होता है। इस प्रकार लाभ केवल गतिशील परिवर्तनों का ही परिणाम है। यह लाभ उसी समय तक प्राप्त होता है जब तक कि परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है। अतः लाभ एक अर्थव्यवस्था में सत्त्व है जो परिवर्तन की अवधि तक ही प्राप्त हो सकता है। जैसे ही परिवर्तन समाप्त हो जाता है और स्थिति पूर्व-वर्तन हो जाती है, उद्योग को केवल स्थिर या प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थ-व्यवस्था का सामान्य लाभ ही मिलना प्रारम्भ होना जाता है। इसीनिये बलार्क ने लिखा है कि लाभ एक भ्रान्तिजनक शक्ति है, जो उद्योग को प्राप्त होती है, किन्तु वे उसे रोक नहीं सकते। स्पष्ट है लाभ एक गतिशील एवं अस्थायी आय है। वह शीघ्र बदल भी जाता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि गतिशील अर्थ-व्यवस्था में भी लाभ अभी सम्भव है जबकि भविष्य के विषय में ठीक ठीक पूर्वानुमान करना हमारे लिये सम्भव नहीं होता।

**आलोचनाएँ** बलार्क के विचार की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं

(1) यह कहा जाता है कि यह मिथ्या गतिशील परिवर्तनों की उच्च व्याख्या नहीं करता। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनके विषय में पहले से विचार किया जा सकता है और जिनके कारण किसी प्रकार का लाभ भी नहीं मिलता। वास्तव में लाभ उन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही सम्भव हो पाता है जो अनिश्चित हैं तथा जिनके सम्बन्ध में पहले से विचार करना सम्भव नहीं होता। अतः इन दो प्रकार के परिवर्तनों में अन्तर करना आवश्यक है।

(2) यदि किसी परिवर्तन के विषय में सामान्य रूप से आशा की जाती है और यदि लोग उसके अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं तो लाभ की सम्भावना नहीं रह जाती। यदि लोगों की यह सामान्य प्रत्याशा गलत होती है तो लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जो इस प्रकार के परिवर्तन की आशा नहीं रखते थे। इस प्रकार बिना लाभ के भी परिवर्तन सम्भव है।

(3) बिना किसी गतिशील परिवर्तन के अभाव में भी लाभ की प्राप्ति सम्भव है। अतः लाभ को गतिशील परिवर्तन से सम्बन्धित करना केवल अर्द्ध सत्य (half truth) है। अधिक से अधिक इतना कहना पर्याप्त होगा कि भविष्य में होने वाले अज्ञात परिवर्तन ही लाभ को सम्भव बना पाते हैं। इस प्रकार यह सत्य है कि परिवर्तन के कारण लाभ मिलता है, किन्तु सभी प्रकार के परिवर्तन लाभ के जनक नहीं होते।

(4) बलार्क प्रगल्भ कार्य, संयोजन और जोगिम उठाने के कार्यों में कोई भेद नहीं मानते।

#### 4 शूम्पीटर का नव प्रवर्तन-पुरस्कार सिद्धान्त (Schumpeter's Theory of Profit of Innovation)

क्लार्क के विचार से मितना जुलता विचार शूम्पीटर का भी है। शूम्पीटर के अनुसार गतिशील अर्थ-व्यवस्था में नये प्रवर्तनों या आविष्कारों (innovations) के कारण ही लाभ उत्पन्न होता है। इस दृष्टि में ही हम क्लार्क और शूम्पीटर के विचारों में काफी समानता पाते हैं, क्योंकि शूम्पीटर भी नये परिवर्तनों पर ध्यान देते हैं और गतिशील परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, किन्तु शूम्पीटर ने नये परिवर्तनों को क्लार्क के परिवर्तनों से विशेष व्यापक रूप में प्रयोग किया है। शूम्पीटर के नये परिवर्तन से तात्पर्य ऐसे परिवर्तनों से है जिनमें उत्पादन की क्रिया में परिवर्तन होता है और उत्पादन-व्यय में ह्रास होना है जिसके फलस्वरूप लाभ सम्भव हो पाता है। इस प्रकार वे फर्मों को इस नये परिवर्तन को पहले उपयोग में लायेगी, विशेष लाभ प्राप्त कर पायेगी। नये बाजार के मिलने से भी नव-परिवर्तन का लाभ मिलेगा और यह लाभ फर्म को तब तक मिलता रहेगा, जब तक कि उस बाजार में अन्य फर्म प्रतिद्वन्द्वी के रूप में नहीं पहुँच जाती। मन्ते तथा कच्चे मालों की खोज एवं उपयोग के कारण भी फर्मों को प्रारम्भ में नये प्रवर्तन का लाभ मिलेगा। नये प्रवर्तन के माध्यम से प्राप्त ये सभी लाभ अस्थायी होते हैं। ऐसे लाभ तभी तक मजबूत हैं जब तक कि अन्य प्रतिद्वन्द्वी फर्मों उन नये प्रवर्तन का उपयोग नहीं करती। जैसे ही अन्य फर्मों लाभ की आशा में नयी उत्पादन विधि को अपनाती हैं वैसे ही लाभ की मात्रा कम होने लगती है और लाभ क्रमशः कम होता जाता है।

यदि नये प्रवर्तन का सम्बन्ध एकाधिकार से सम्भव है तो लाभ एक लम्बी अवधि तक मिलता रहेगा। नव प्रवर्तन के पेटेंट-अधिकार (Patent Right) के कारण भी लाभ अधिक समय तक मिलता रहेगा। इस प्रकार नये प्रवर्तनों के फल-स्वरूप प्राप्त लाभ को हम आंशिक एकाधिकार की ध्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्रारम्भ में नयी विधि को अपनाने वाली फर्मों की संख्या अल्प होती है।<sup>1</sup> स्पष्ट है, लाभ अस्थायी होता जो नये प्रवर्तनों एवं सुधारों के कारण प्राप्त होता है। यही लाभ अन्य फर्मों द्वारा नये प्रवर्तनों का उपयोग या अनुकरण (imitation) के कारण समाप्त हो जायेगा। अतः यह कहना सत्य है कि लाभ नये प्रवर्तन के कारण मिलता है तथा अनुकरण नुप्त के कारण ही जाता है (Profits are caused by innovation and disappears by imitation)।

<sup>1</sup> "Even the profits of innovation may be classed as profits of potential monopoly since they are dependent upon the smallness of the number of firms that first adopt this innovation." — Meyers

नये प्रवर्तन आर्थिक विकास में महायक होते हैं तथा इस प्रवर्तन के द्वारा लाम की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से लाम नये प्रवर्तन को प्रोत्साहित करता है। यदि नया प्रवर्तन सफल होता है तो लाम की प्राप्ति होगी। स्पष्ट है कि शूम्पीटर के अनुसार लाम नये प्रवर्तन का कारण तथा परिणाम दोनों ही हैं।

आलोचनाएँ शूम्पीटर के विचार की भी आलोचना की जाती है, किन्तु हमें यह ब्याल रखना है कि इन आलोचनाओं का आधार बर्नार्क के सिद्धान्त के ही अनुरूप है, यद्यत् जिन आलोचनाओं का वर्णन बर्नार्क के सिद्धान्त के लिए किया गया है वे ही आलोचनाएँ इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होती हैं।

### 5 हाले का जोखिम उठाने का पुरस्कार सिद्धान्त

(Hawley's Theory of Profit—A Reward For Risk-taking)

उद्यमी का मुख्य कार्य उत्पादन में जोखिम उठाना है। उद्यमी के इसी जातिम उठान के फलस्वरूप लाम प्राप्त होता है। हाले (F B Hawley) ने इसी विचार का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार लाम जोखिम उठाने का पुरस्कार है। उत्पादन के अन्य सभी साधनों का पुरस्कार निश्चित है, क्योंकि लाम मिले या न मिले, उत्पादक को अन्य साधनों का पुरस्कार देना ही पड़ेगा। परन्तु लाम जो उद्यमी का पुरस्कार है अज्ञान और अनिश्चितता का है। यह अनिश्चितता है तथा इसकी प्रकृति अर्थात् अशुभ रूप में है।<sup>8</sup> स्पष्ट है कि लाम वह अवशेष राशि है जिसका पहले में निर्धारण करना सम्भव नहीं है, तथा इसी आय की प्राप्ति के लिए उद्यमी उत्पादन की क्रिया में जोखिम उठाने को तैयार होता है। उद्यमी की आय का आकार जोखिम उठाना ही है। हाले ने इस विचार का वर्णन सन् 1907 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Enterprise and Productive Process" में किया है। उत्पादन-क्रिया में लग रहने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमी को जोखिम उठाने का पुरस्कार मिलता रहे और यह पुरस्कार औसत सामान्य प्राप्ति से अधिक होना चाहिए। चूँकि जोखिम उठाना बड़ा ही कष्टप्रद तथा चिन्ता का विषय है अतः उद्यमी इसे तब तक उठाने को तैयार नहीं होगा, जब तक उसके लिए किसी विशेष पुरस्कार का लोभ न हो। उत्पादन में लगायी गई पूँजी पर औसत सामान्य आय ही यथेष्ट नहीं है, बल्कि जोखिम भेलने का पुरस्कार सामान्य से कुछ विशेष होना चाहिए। चूँकि जोखिम उठाना सरल नहीं है, इसलिए जोखिम उठाने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है।

<sup>8</sup> "The profit of an undertaking or the residue of the product after the claims of land, capital and labour are satisfied, is not the reward of management or co-ordination, but of the risks and responsibilities of the undertaker .....subjects himself to..... this net income being manifestly an undetermined residue, must be a profit."

प्रतियोगिता का क्षेत्र सजीव होने के कारण प्रतियोगिता तीव्र नहीं होती। ऐसी दशा में जो उद्यमी अपने बट्टर जोखिम का भार उठाता है और उससे अपनी सुरक्षा करता है, वही अर्थव्यवस्था में लाभ प्राप्त करता है।

**आलोचनाएँ :** हमें ये विचार की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि लाभ केवल जोखिम उठाने का ही पुरस्कार नहीं है। यह कहना अत्युक्ति होगी कि सम्पूर्ण पुरस्कार जोखिम उठाने के कारण ही मिलता है, फिर भी यह स्थिति रखना चाहिए कि उद्यमी को लाभ जोखिम भरा उठाने के कारण ही नहीं, बल्कि इस कारण भी मिलता है कि वह अपने श्रेष्ठ योग्यता के प्रयत्नों से जोखिम का कम कर देता है जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है। उद्यमी को अपनी कुशलता के कारण बाजार आदि की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान रहता है। वह उनको कम करने के उपाय करके अगले उद्यमी की अपेक्षा विशेष लाभ प्राप्त करता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जोखिमों के निराकरण और कम करने की क्षमता के कारण ही उद्यमी को लाभ मिलता है। वह इसलिए लाभ प्राप्त नहीं करता कि वह उनका भार उठाता है।

वास्तव में लाभ विभिन्न भागों के ऊपर वृद्ध (Surplus over cost) मात्र है और यह सभी प्रकार के जोखिमों के कारण नहीं मिलता। केवल अज्ञात तथा अनिश्चित जोखिमों के कारण ही लाभ उत्पन्न होता है।

## 6. नाइट का अनिश्चितता का सिद्धान्त (Knight's Theory of Uncertainty)

अर्थव्यवस्था में उद्यमी का महत्व तथा उत्तरदायित्व इस तथ्य में निहित है कि वह उत्पादन के विभिन्न माधनों को मिलाकर उत्पादन-उदाई को एक निश्चित स्वरूप देता है, परन्तु इस प्रक्रिया में अनिश्चितता का अंश भी निहित रहता है। भूमि, श्रम तथा पूँजी की पुंति करने वाला इतना ज्ञान पहले से ही रखता है कि दी हुई परिस्थितियों में उसे कितना पारिश्रम या पुरस्कार मिलेगा। ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उत्पादन के इन माधनों के स्वामियों को किसी प्रकार का कोई खतरा उठाना नहीं पड़ता। यह सम्भव है कि निजी पूँजीपति का बाढ़ में पड़ना लगे कि ऋणी (borrower) एक कपटी व्यक्ति है तथा वह ऋण की अदायगी नहीं करेगा। भूमिपति भी बाढ़ या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो सकता है। साथ ही, श्रमिक की बीमारी छूट सकती है जिससे उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, किन्तु ये आपत्तियाँ (वेईमानी, प्राकृतिक आपदाएँ या आर्थिक अन्याय) ऐसी हैं जो दोहरी-बहुत मात्रा में समाज के सभी व्यक्तियों को सहनी पड़ती हैं।

उद्यमी, चाहे वह एक व्यक्ति हो या हज़ारों की संख्या में अंशधारी (Share holders), आय के किसी भी ऐसे स्तर पर निर्भर नहीं रह सकते जिसका आश्वासन दिया जा सके। उद्यमी को एक विशेष प्रकार का खतरा उठाना ही पड़ता है। फलतः



लिए उद्यमी को प्रेरणाम्बुध्न्य लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु इन सतरो के अतिरिक्त सदैव कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती रहनी हैं जो माप में परिवर्तन और तकनीकी विज्ञान आदि को सम्भव बना पाती हैं। इन परिवर्तनों में कोई नमवद्धता (regularity) नहीं होती। इसलिए इनका बीमा नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार के जोखिम अनिश्चित तथा बीमा के अयोग्य (uncertainties and non-insurable risks) होते हैं। ये ऐसे जोखिम होते हैं जिनका बीमा सम्भव नहीं है। फलस्वरूप उद्यमी को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अतः प्रो नाइट Prof Knight लाभ का कारण अनिश्चितता मानते हैं।<sup>१०</sup> प्रो० नाइट ने अपनी पुस्तक "Risk Uncertainty and Profit" जो मई 1921 में प्रकाशित हुई, में अपने लाभ सम्बन्धी इस विचार को पूर्णतया प्रतिपादित किया।

उद्यमी यह चाहता है कि उसके पारितोषण की पूर्ण उचित मात्रा में होनी रहे, अर्थात् सामान्य लाभ (normal profit) मिलता रहे। यह सामान्य लाभ लागत का एक भाग होता है जो एक उद्योग से दूसरे उद्योग के मिला होता है तथा यह मिश्रता अनिश्चितता की मात्रा पर निर्भर करती है। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी माप प्रायः निश्चिन्त रहनी है तथा ऐसे उद्योगों में साधारणतया लाभ कम होता है। ठीक इसके विपरीत किसी नयी वस्तु का भविष्य विन्कुल अनिश्चिन्त होता है। उसे सफलता की आशा के साथ ही असफलता की भी सम्भावना रहती है। अतः ऐसे कार्यों के लिए अत्यधिक लाभ की प्रत्याशा (expectation) का होना आवश्यक है, नाकि उद्यमी उत्पादन की क्रिया में प्रेरित हो सके। इस प्रकार जहाँ कहीं भी अनिश्चितता की मात्रा अधिक होगी उद्यमी को प्रेरित करने के लिए अत्यधिक लाभ का लोभ देना आवश्यक होगा।

आलोचनाएँ : (1) प्रो० नाइट का सिद्धान्त, क्लासिक सिद्धान्त की भाँति, केवल गतिशील परिवर्तनों को ही लाभ का कारण नहीं मानता, क्योंकि जहाँ तक इन परिवर्तनों को जाना जा सकता है, वे विक्रय-मूल्य तथा लागत में अन्तर पैदा नहीं कर सकते।

(2) हानि के समान लाभ का कारण सतरा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञात सतरों के विरुद्ध बीमा किया जा सकता है। अतः लाभ एक विविध जोखिम के कारण प्राप्त होता है जिसकी माप सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि लाभ अनिश्चितता के कारण प्राप्त होता है जो स्वयं गतिशील परिवर्तनों का परिणाम है।

<sup>१०</sup> "It is not dynamic change, not change as such which causes profit, but the divergence of actual conditioning from those which have been expected and on the basis of which business arrangements have been made."

—Prof. Knight.